साँप गंगा in

ब्रेकिंग इंडिया 2.0

राजीव मल्होत्रा

विजया विश्वनाथन

गंगा में सांप

Table of Contents

कॉपीराइट
प्रस्तावना
परिचय
पृष्ठभूमि
चार बड़ी कहानियाँ
कहानी 1: मार्क्सवाद का अमेरिकीकरण
कहानी 2: आलोचनात्मक नस्ल सिद्धांत का भारतीयकरण
कहानी 3: हार्वर्ड विश्वविद्यालय अत्याचार साहित्य का उत्पादन करता है
कहानी 4: नए अभिजात वर्ग द्वारा भारत का विखंडन
वित्तपोषण के उद्देश्य
चाबी छीनना
भाग 1. संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय संस्कृति की वैधता पर बहस
1. संयुक्त राज्य अमेरिका का विघटन
अवलोकन
पुराने वामपंथ की यूरोपीय उत्पत्ति
मार्क्सवाद

मार्क्सवादी आलोचनात्मक सिद्धांत
पश्चात
आलोचनात्मक नस्ल सिद्धांत
अंतर्संबंधता
क्वीर सिद्धांत
वोकवाद का चर्च
उदार कलाएँ हठधर्मी बन जाती हैं
लोकप्रिय वोकवाद
परेशान करने वाली विशेषताएं
विज्ञान, तर्कसंगतता और योग्यतावाद का अस्वीकरण
निष्पक्षता और समानता
कैंसल कल्चर और असहमति का दमन
सक्रियता और टूलबॉक्स
व्यक्तिवाद पर आक्रमण
बराक ओबामा की रंगभेद-मुक्त सोच पर हमला
शैक्षिक युद्धक्षेत्र
पुराने को ध्वस्त करना, लेकिन नए का निर्माण करना न जानना।
वोक का निगमीकरण
2. जाति का अमेरिकीकरण
अवलोकन
भारत में क्रिटिकल रेस थ्योरी का सफर
जाति को वैश्विक नस्लवाद की संरचना माना जाता है
हिंदू धर्म को एक जड़ और दमनकारी व्यवस्था के रूप में खारिज कर दिया गया है।
अन्य जाति व्यवस्थाओं की अनदेखी करना

हिंदू धर्म का विघटन आवश्यक समझा जाता है
3. भारतीय अमेरिकियों की तुलना श्वेत नस्लवादियों से की गई
अवलोकन
भारतीय अमेरिकियों के जातिगत दुर्व्यवहारों से संबंधित अमेरिकी डेटाबेस का संकलन
संयुक्त राज्य अमेरिका में जाति से संबंधित मुकदमे
अमेरिकी प्रौद्योगिकी उद्योग
अमेरिकी कॉलेज और विश्वविद्यालय
अमेरिकी स्थानीय सरकारें
मुद्दे और चुनौतियाँ
दलित सशक्तिकरण आंदोलन का वैश्वीकरण
एक उम्मीद की किरण
4. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में योग्यता प्रणाली पर हमला
अवलोकन
पश्चिमी योग्यतावाद की उत्पत्ति
भारत में कारीगरों और इंजीनियरों को अलग करने का इतिहास
योग्यता को सांस्कृतिक पूंजी का एक रूप माना जाता है
प्रवेश परीक्षाएं जातिगत विशेषाधिकारों को छुपाती हैं
पुरुष प्रधान पूंजीवाद में योग्यता
IIT छात्रों के बीच संस्थागत रिश्तेदारी और ब्रांड विकास को जातिवादी माना जाता है
सिलिकॉन वैली पर हमला
अफ्रो-दलितों से अलग होना
जवाहरलाल नेहरू बनाम नरेंद्र मोदी की राजनीति
सुब्रमणियन के शोध प्रबंध से संबंधित चिंताएँ

5. अफ्रीकी-दलितों का उदय
अवलोकन
येंगडे की मूल ऐतिहासिक मान्यताओं पर सवाल उठाना
अंबेडकर और बौद्ध धर्म का अवसरवादी उपयोग
दलित चिरस्थायी पीड़ित के रूप में
ब्राह्मण पितृसत्ता
जातिगत वैश्वीकरण और चौथी दुनिया
पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए महिलाओं की लड़ाई
आक्रामकता की पुनर्परिभाषा
6. एक प्रतिक्रिया: भारतीय सामाजिक संगठन का इतिहास
परिचय
सात ऐतिहासिक चरण
प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है
वैदिक युग
उपनिषद
भगवद् गीता
The Mahabharata
धर्मशास्त्र
क्या हिंदू धर्म जाति व्यवस्था पर ही केंद्रित है?
हिंदू धर्म की खुली वास्तुकला
हिंदू होने के लिए जाति ही पर्याप्त नहीं है
हिंदू होने के लिए जाति होना आवश्यक नहीं है
वास्तविक व्यवहार में जन्म-आधारित पदानुक्रम के सामने चुनौतियाँ
Shudras and Vanavasis
शूद्र सम्राटों, राजाओं और सैनिकों के रूप में

आर्थिक शक्ति और सामाजिक स्थिति
शूद्रों के बीच अस्पृश्यता
ब्रिटिश शासन से पहले स्वदेशी शिक्षा
दलित हिंदू गौरव
Vanavasis
भक्ति आंदोलन
ब्रिटिश सामाजिक इंजीनियरिंग
ब्रिटिश यह स्वीकार करते हैं कि कोई कठोर जाति व्यवस्था अस्तित्व में नहीं थी।
रिस्ले ने 'जाति = नस्लीय पदानुक्रम' का सिद्धांत थोपा।
'अस्पृश्यता' को आधिकारिक बनाना
भारतीय राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश श्रेणियों को स्वीकार किया
बी.आर. अंबेडकर और दलित आंदोलन
अंबेडकर और जाति
अंबेडकर और इस्लामोफोबिया
अंबेडकर और बौद्ध धर्म
अंबेडकर और साम्यवाद
जाति/जाति के फायदे और नुकसान
तानाशाही के विरुद्ध नियंत्रण और संतुलन
श्रम विभाजन और विशेषज्ञता का हस्तांतरण
जातियों की परस्पर निर्भरता: जजमानी प्रणाली
विकेंद्रीकृत लॉबिंग
पारिस्थितिक भूमिका
आर्थिक सुरक्षा
जातियाँ और अंतर्मुखी स्वभाव: समस्या

जाति व्यवस्था का पतन
भाग II. हार्वर्ड विश्व गुरु और भारतीय अरबपति
7. हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ तीस वर्षों का अनुभव
भारतीय ध्यान प्रणालियों को आत्मसात करने में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की भूमिका
हर्ब बेन्सन
डैनियल गोलेमैन
जॉन काबाट-ज़िन
अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड
स्वामी विवेकानंद और विलियम जेम्स
भारतीय आध्यात्मिकता को पश्चिमी साहित्य में समाहित करना
राल्फ वाल्डो एमर्सन
वॉल्ट व्हिटमैन
हेनरी डेविड थॉरो
टी.एस. एलियट
हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित अत्याचार साहित्य
जन स्वास्थ्य के नाम पर अत्याचार संबंधी साहित्य
वनवासी लोगों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना
खालिस्तानी और कश्मीर अलगाववादी
हिंदी को उर्दू पर मैप करना
प्रारंभिक वर्षों में हार्वर्ड विश्वविद्यालय को भारतीय वित्तपोषण
इन्फिनिटी फाउंडेशन विजिटिंग प्रोफेसरशिप
धीरूभाई अंबानी द्वारा अस्वीकृति
आनंद महिंद्रा ने भी अपनी राय रखी।
Rajat Gupta

सीख सीखी
8. अमेरिका में चीन का ट्रोजन हॉर्स
अवलोकन
चीन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश किया
चीनी वित्तपोषण
चीन अमेरिका में वोकवाद को वित्त पोषित करता है
हार्वर्ड कैनेडी स्कूल का चीन कार्यक्रम
हार्वर्ड के चीन-समर्थक विद्वान
भारत विरोधी और चीन समर्थक धुरी
हार्वर्ड और चीनी सेना
हार्वर्ड और कोविड-19
चीन-ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन संबंध
9. हार्वर्ड विश्वविद्यालय की जांच का महत्व
अवलोकन
हार्वर्ड विश्वविद्यालय का अकादमिक-औद्योगिक परिसर
भारतीयों ने विश्व गुरु राक्षस का निर्माण किया
हार्वर्ड एक अच्छे पुलिस अधिकारी के रूप में
10. डेटाबेस, वर्गीकरण और अभिलेखागार
अवलोकन
वर्गीकरण: भारतीय और पश्चिमी
औपनिवेशीकरण: वर्गीकरण प्रणालियों का टकराव
Kumbh Mela
विभाजन परियोजना
चिकित्सा डेटाबेस
कला और सौंदर्यशास्त्र

अन्य डेटाबेस
बौद्धिक संपदा और राष्ट्रीय सुरक्षा का नुकसान
11. आनंद महिंद्रा और उत्तरआधुनिकतावाद
अवलोकन
होमी के. भाभा, हार्वर्ड के जादूगर
भाभा का उत्तरआधुनिकतावाद
भारतीय फ्रेंचाइजी
हिंदूफोबिया
12. लक्ष्मी मित्तल और सामाजिक न्याय
अवलोकन
हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने भारत में अपना 'दूतावास' स्थापित किया।
राजनीतिक हस्तक्षेप
अमेरिका में जाति का प्रभाव
महिला सशक्तिकरण
गहरी खुदाई
प्रमुख विषय
सामाजिक उद्यमिता
अर्थशास्त्र और विकास
स्वास्थ्य देखभाल
कला और संस्कृति
अन्य विविध परियोजनाएँ
पाकिस्तान के गौरव के विपरीत
13. पिरामल परिवार: हार्वर्ड विश्वविद्यालय का भारत का प्रवेश द्वार
अवलोकन
हार्वर्ड टी.एच. चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में चीन की घुसपैठ

सार्वजनिक स्वास्थ्य में जाति एक परिप्रेक्ष्य के रूप में
भारत पर चान-पिरामल सहयोग
चिंताएँ
14. भारत में मीडिया व्यवस्था पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय का नियंत्रण
अवलोकन
नीमन-पुलित्जर सेंटर एलायंस
नीमन इंस्टीट्यूट और पुलित्जर सेंटर द्वारा समर्थित भारतीय संगठन
केस स्टडी: पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी
शिक्षा के क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने वाली शक्ति के रूप में PARI
केस स्टडी: अमेरिका में हिंदुओं पर हमला
भारत के लिए पुलित्जर सेंटर की वित्तीय सहायता
भारत में नीमन-पुलित्जर मीडिया नेटवर्क
समर्थित मीडिया हाउस
नीमन रिपोर्ट्स
नीमन अनुदान प्राप्तकर्ता, पुरस्कार और फेलोशिप
भारतीय शास्त्रीय ग्रंथों की पुनर्व्याख्या
15. हार्वर्ड कैनेडी स्कूल: भू-राजनीति
अवलोकन
हार्वर्ड के सिपाही भारत के खिलाफ गवाही दे रहे हैं
गलत सूचना युद्ध
भारतीय लोकतंत्र में हस्तक्षेप
महिलाएँ और सार्वजनिक नीति कार्यक्रम
कैर सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स पॉलिसी
अंतर्राष्ट्रीय विकास केंद्र

प्रकाशनों
भारत के अभिजात वर्ग का ब्रेनवॉशिंग
हार्वर्ड विश्वविद्यालय के दोहरे मापदंड
16. हार्वर्ड बिजनेस स्कूल
अवलोकन
व्यवसाय के नजरिए से सामाजिक न्याय
हार्वर्ड और कैंसिल कल्चर
अमेरिकी सिद्धांतों का निर्यात
चीन का व्यावसायिक नेतृत्व
भाग III. क्या भारतीय उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध हैं?
17. भारत की यात्रा के लिए आइवी लीग का मार्ग
18. सऊदी अरब, अमेरिका और भारत के अरबपतियों का गठजोड़
अवलोकन
मानवाधिकारों पर पाखंड
सऊदी अरब द्वारा अमेरिकी संस्थानों को दी जाने वाली धनराशि
मोहम्मद अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब, एमआईटी
भारतीय सहयोगी
अनुसंधान परिणाम
जमील-पॉवर्टी एक्शन लैब की भारत में शाखाएं: वित्तीय प्रबंधन और
अनुसंधान संस्थान और क्रेया विश्वविद्यालय
क्रिया और डेटा माइनिंग
19. अशोका विश्वविद्यालय: हार्वर्ड विश्वविद्यालय का कनिष्ठ भागीदार
अवलोकन
भारत के पारिस्थितिकी तंत्र को तोड़ना: ईंट दर ईंट निर्माण
अशोक: हिंदूफोबिया का एक इनक्यूबेटर

चीन अध्ययन केंद्र
शंघाई मेरिटोक्रेसी कार्यशाला
त्रिवेदी सेंटर फॉर पॉलिटिकल डेटा
त्रिवेदी केंद्र के पीछे के लोग और संस्थाएँ
त्रिवेदी राजनीतिक डेटा केंद्र से प्राप्त परिणाम
द फ्रेंच कनेक्शन: लिया स्पिनर
लिंग और यौनिकता अध्ययन केंद्र
सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन केंद्र
सामाजिक प्रभाव और परोपकार केंद्र
अशोका विश्वविद्यालय की शैक्षणिक साझेदारियाँ
पश्चिमी अकादमिक जगत द्वारा अशोका विश्वविद्यालय को धमकाने का प्रयास
अशोका में छात्रों का वैचारिक प्रशिक्षण
20. अजीम प्रेमजी का मीडिया और शिक्षा पर प्रभाव
अवलोकन
अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय
स्वतंत्र और जनहितैषी मीडिया फाउंडेशन
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की भूमिका
एनईपी के नुकसान – धन, डेटा और प्रतिभा का बहिर्वाह
21. गोदरेज और क्वीयरिंग
अवलोकन
मार्क्सवादी नींव
अमेरिका में क्वीर आंदोलन
ट्रांस-क्वीर और भारत
गोदरेज इंडिया कल्चर लैब

मानव संसाधन नीतियां
अमेरिकी वोकवाद से असहिष्णुता का आयात
22. ओमिडयार नेटवर्क: भारत में ट्रोजन हॉर्स
अवलोकन
पृष्ठभूमि: द अमेरिकन पेरेंट
कर योग्य कंपनियां पारंपरिक कर-मुक्त गैर-लाभकारी संस्थाओं का स्थान ले रही हैं।
ओमिडयार नेटवर्क इंडिया
जोशुआ परियोजना का पुनर्जन्म
ओमिडयार अनुदान हार्वर्ड के मित्तल संस्थान के माध्यम से प्राप्त हुए।
ओमिडयार नेटवर्क इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और बिग डेटा
आर्थिक प्रभाव और नेतृत्व निर्माण
ओमिडयार ने आईडीएफसी इंस्टीट्यूट और आईडीएफसी फाउंडेशन का समर्थन किया।
आईडीएफसी संस्थान की परियोजनाएं
ओमिडयार-चीन गठजोड़
सामाजिक प्रभाव
नीति अनुसंधान और सरकार पर इसका प्रभाव
भारत की संप्रभुता खतरे में है
23. निष्कर्ष: दावोस के देवता और डिजिटल जाति व्यवस्था
दावोस देवतस: क्लाउस श्वाब और विश्व आर्थिक मंच
विघटन प्रक्रिया
व्यक्तियों के लिए नियंत्रण तंत्र के रूप में डिजिटल पहचान
भारतीय व्यवसाय एक नए धर्म के प्रचारक बन रहे हैं
भविष्य के विश्व नेताओं का प्रशिक्षण

दावोस के देवता
स्वीकृतियाँ
ग्रन्थसूची

गंगा में सांप

गंगा में सांप

ब्रेकिंग इंडिया 2.0

Rajiv Malhotra
and
Vijaya Vishwanathan

इन्फिनिटी फाउंडेशन
2022

© इन्फिनिटी फाउंडेशन 2022
2022 में प्रकाशित
इन्फिनिटी फाउंडेशन, 174 नासाउ स्ट्रीट, पीएमबी 400, प्रिंसटन, एनजे 08542
https://infinityfoundation.com/

भारतीय कॉपीराइट नियमों के तहत सभी अधिकार सुरक्षित हैं। आवश्यक शुल्क का भुगतान करने पर, आपको इस ई-पुस्तक के पाठ को स्क्रीन पर देखने और पढ़ने का गैर-अनन्य, गैर-हस्तांतरणीय अधिकार प्राप्त होता है। इन्फिनिटी फाउंडेशन ई-बुक्स की स्पष्ट लिखित अनुमति के बिना, इस पाठ का कोई भी भाग पुनरुत्पादित, प्रसारित, डाउनलोड, डीकंपाइल, रिवर्स-इंजीनियर या किसी भी सूचना भंडारण एवं पुनर्प्राप्ति प्रणाली में किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या यांत्रिक, वर्तमान में ज्ञात हो या भविष्य में आविष्कार किया गया हो, संग्रहीत या उसमें शामिल नहीं किया जा सकता है।
ई-बुक
IFI050v1.0.0
दिनांक: 17-09-2022
ISBN:
निर्माता: श्रीरंगा डिजिटल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
srirangadigital.com

प्रस्तावना

आर. वैद्यनाथन

भारत अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता पर लगातार हो रहे हमलों के दबाव में है। ये हमले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुनियोजित, वित्तपोषित और संचालित हैं और भारत में मौजूद कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए भारतीयों का इस्तेमाल करते हैं, जो एक लोकतंत्र और खुले समाज होने के नाते स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए, जाति व्यवस्था को दुष्परिभाषित रूप से पेश किया जाता है; हालांकि, इसके खिलाफ व्यापक

दुष्प्रचार के कारण भारतीय समाज की संरचना के बारे में बहुत कम जानकारी दी जा रही है।

लगभग बारह वर्ष पूर्व, प्राचीन जाति व्यवस्था के विकृत रूप से दोषपूर्ण बनने और अब एक अंतरराष्ट्रीय गठजोड़ द्वारा इसके शोषण को दर्शाने का एक ठोस प्रयास किया गया था। यह एक अग्रणी कृति और बहुचर्चित पुस्तक थी, जिसका शीर्षक था "ब्रेकिंग इंडिया: वेस्टर्न इंटरवेंशन्स इन द्रविड़ियन एंड दलित फॉल्ट लाइन्स"। इसने एक वैचारिक क्रांति ला दी, क्योंकि पहली बार इस विषय पर स्पष्टता आई थी। "ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेज" शब्द, संपूर्ण ढांचा और शब्दावली, इस क्रांति का हिस्सा बन गए। इसने साक्ष्यों के साथ, भारत के भीतर और बाहर काम कर रही उस जटिल व्यवस्था को समझाया, जो ग्रामीण गरीबों का मस्तिष्क धोकर, उन्हें अपने धर्म में परिवर्तित करके, अंततः सभ्यता के ताने-बाने को नष्ट करने के उद्देश्य से काम कर रही थी। इस कृति के परिणामस्वरूप उत्पन्न सामाजिक आंदोलन ने कई अब तक अज्ञात अवधारणाओं को प्रचलित शब्दावली में शामिल कर दिया। इसने भारत में सोशल मीडिया आइकनों की एक पूरी पीढ़ी को जन्म दिया, जिनका राजनीतिक और सांस्कृतिक विमर्श में अपना-अपना प्रभाव क्षेत्र है। इसने देश में विभिन्न स्तरों पर अनगिनत कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों को जन्म दिया। लेकिन जहाँ एक ओर पहले के भारत तोड़ने वाले बलों की गतिविधियों को लेकर जागरूकता बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर नए भारत तोड़ने वाले बलों से उत्पन्न खतरों में गुणात्मक परिवर्तन और विस्तार हुआ है। 'ब्रेकिंग इंडिया' के मुख्य लेखक राजीव मल्होत्रा और उनकी नई सह-लेखिका विजया विश्वनाथन ने 'स्नेक्स इन द गंगा' में इस स्थिति का विश्लेषण किया है।

यह पुस्तक 'ब्रेकिंग इंडिया' से भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की

'ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस 2.0' (जैसा कि पुस्तक में इन्हें कहा गया है) पर्दे के पीछे से काम कर रही हैं। इन्हें केवल इनके कार्यों की गहन और विस्तृत जांच से ही समझा जा सकता है। हार्वर्ड जैसे प्रतिष्ठित अमेरिकी विश्वविद्यालय इनके प्रभाव में आ चुके हैं, जहां वे भारत को विघटित करने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय के सिद्धांत गढ़ते हैं। और हार्वर्ड भारत में प्रवेश कर चुका है और इसकी प्रमुख संस्थाओं में घुसपैठ कर चुका है। यह पुस्तक भारत में हाल ही में चल रहे सामाजिक संघर्षों के पीछे काम कर रही ताकतों पर प्रकाश डालती है और भविष्य में होने वाले संभावित हमलों का भी अनुमान लगाती है। वैश्विक गठजोड़ों पर इस परिप्रेक्ष्य के बिना, भारतीय बुद्धिजीवी अनुच्छेद 370, नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019, बाबरी मस्जिद, किसान विद्रोह और हाल ही में नूपुर शर्मा कांड तथा अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों पर बढ़ते हमलों के प्रति प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण तक ही सीमित रह जाते हैं, न कि सक्रिय दृष्टिकोण तक।
गंगा में सांप (Snakes in the Ganga) मार्क्सवाद और क्रिटिकल रेस थ्योरी (CRT), जिसे लोकप्रिय रूप से वोकिज़्म के नाम से जाना जाता है, के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और उनके बीच संबंध स्थापित करता है। यह बताता है कि कैसे क्रिटिकल रेस थ्योरी/वोकिज़्म भारत की व्याख्या करने का नवीनतम ढांचा बन गया है। अधिकांश भारतीय इस बात से अनभिज्ञ हैं कि इस ढांचे का उपयोग जाति, मुस्लिम शिकायतों, कश्मीर, लिंग और LGBTQ+ मुद्दों, सांप्रदायिक हिंसा और यहां तक कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ जल, पर्यावरण और विदेश नीति जैसे क्षेत्रों का सूक्ष्मता से विश्लेषण करने के लिए किया जा रहा है। यह विश्लेषण भारत की निंदा करने और उन सामाजिक मुद्दों पर निर्णय सुनाने का आधार बनता है जिन्हें पर्याप्त रूप से समझा नहीं गया है। यह मेरी जानकारी में पहली ऐसी पुस्तक है जो इस नई शक्ति का

इतना विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है। यह क्रिटिकल रेस थ्योरी और पश्चिम में वामपंथियों द्वारा विकसित अन्य सामाजिक सिद्धांतों के विकास पर गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह भारत में इस आंदोलन के प्रसार और विकास पथ का वर्णन करती है।

कई लोग यह जानकर चौंक जाएंगे कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय कुछ प्रमुख अश्वेत अमेरिकियों और महत्वाकांक्षी युवा दलितों के बीच एक चिंताजनक गठबंधन बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जो उन्हें भारत की जाति व्यवस्था को पश्चिमी नस्ल की अवधारणा से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। क्रिटिकल कास्ट थ्योरी और क्रिटिकल दलित थ्योरी के नाम से जाने जाने वाले सिद्धांत इसी ढांचे पर आधारित हैं और हार्वर्ड में इन्हें स्थापित तथ्य के रूप में पढ़ाया जाता है। इस बेबुनियाद तुलना के बावजूद, हार्वर्ड में न तो कोई प्रतिवाद प्रस्तुत किया जाता है और न ही उस पर विचार किया जाता है।

ब्रेकिंग इंडिया ने पहले ही अश्वेत अमेरिकियों को दलितों से और श्वेत अमेरिकियों को ब्राह्मणों से जोड़ने की कुटिल योजना का पर्दाफाश कर दिया था, हालांकि उस समय यह आंदोलन अपने शुरुआती दौर में ही था। आज इसे हाशिए का आंदोलन नहीं माना जा सकता। अमेरिकी टीवी होस्ट ओपरा विन्फ्रे इसका सक्रिय रूप से समर्थन करती हैं और इस विषय पर लिखी गई पुस्तकें न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्टसेलर बन चुकी हैं। हार्वर्ड के विद्वान पूरे अश्वेत आंदोलन को दलित आंदोलन से जोड़ने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। अश्वेत विरासत माह की तरह ही दलित विरासत माह भी मनाया जाता है। अश्वेत जीवन-मरण आंदोलन की तरह ही दलित जीवन-मरण आंदोलन भी चल रहा है। ब्लैक पैंथर पार्टी की तरह ही अब दलित पैंथर्स संगठन भी मौजूद है, और इसी तरह अन्य संगठन भी।

भारत में अमेरिकी प्रणालियों के आयात की गति को देखते हुए, भारतीयों

को अमेरिकी प्रौद्योगिकी क्षेत्र (विशेषकर सिलिकॉन वैली) में किए जा रहे विभाजनकारी जाति सर्वेक्षणों के बारे में चिंतित होना चाहिए। इस सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी का उद्देश्य लोगों के बीच सुलह कराना नहीं है, बल्कि अमेरिकी संगठनों में कार्यरत उच्च जाति के भारतीय कर्मचारियों पर श्वेत वर्चस्ववादियों के समान होने का आरोप लगाने वाले कानूनी मामले तैयार करना है। भारत के उन लोगों पर 'संरक्षित वर्ग' की अमेरिकी कानूनी अवधारणा लागू की जा रही है, जिन्हें पीड़ित के रूप में देखा जा सकता है। परोपकार और विकास के नाम पर, उन्हें भारत के बारे में ऐसी जानकारी जुटाने के लिए भर्ती और प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे हार्वर्ड को अपने पसंदीदा सिद्धांतों का समर्थन करने वाले शोध के लिए एक संग्रह और डेटाबेस बनाने में मदद मिल सके और अत्याचार साहित्य तैयार करने में सहायता मिल सके। ऐसे डेटाबेस का उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिदम को भारत-विरोधी पूर्वाग्रह से ग्रसित करने के लिए भी किया जा रहा है।

भारत से हो रहे भारी मात्रा में प्रतिभा पलायन से अमेरिका को लाभ मिल रहा है, वहीं हार्वर्ड के शिक्षाविदों ने भारतीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) संस्थानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हार्वर्ड के विद्वान इन संस्थानों को ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक ढांचे के रूप में देखते हैं, और इन संस्थानों को भारत में योग्यता-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने का एक और तरीका बताया जा रहा है। उत्कृष्टता के इन संस्थानों को ध्वस्त करके भारत को तोड़ने का यह एक और प्रयास है।

हार्वर्ड की अपार शक्ति के कारण, इस आंदोलन ने भारत की विभाजनकारी पहचान की राजनीति को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। 'सांप गंगा' नामक यह रचना भारत में ब्रिटिश 'सभ्यीकरण' अभियान से

तुलना करती है, जो भारतीयों को नियंत्रित करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति पर आधारित था। संस्कृत को आज भी दमनकारी भाषा बताकर उसकी निंदा की जाती है। हिंदू धर्म को एक प्रमुख लक्ष्य बनाकर उसे नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि इस्लाम को पीड़ित के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, भारतीय परिवार व्यवस्था को अब एक दमनकारी संरचना घोषित कर दिया गया है जो पितृसत्ता और ब्राह्मण विशेषाधिकार को बढ़ावा दे रही है। गुरुओं को भी नहीं बख्शा गया है। भारतीय सभ्यता की नींव को पूरी तरह से नष्ट करने का एक स्पष्ट और सुनियोजित प्रयास चल रहा है।

भारत की राष्ट्र-राज्य के रूप में वैधता, उसके संविधान और उसकी सत्तारूढ़ पार्टी पर हमले करना हार्वर्ड के शोध परियोजनाओं और सम्मेलनों के पसंदीदा विषय हैं। हालाँकि, चीन के प्रति उसका रवैया बिल्कुल विपरीत है। यह पुस्तक दर्शाती है कि कैसे चीन ने अपनी राष्ट्रवादी योजनाओं को आगे बढ़ाने और भारत में पैठ बनाने के लिए हार्वर्ड का चतुराई से इस्तेमाल किया है।

'सांप गंगा में' पुस्तक का एक आकर्षक और मौलिक योगदान हार्वर्ड के व्यापक प्रभाव नेटवर्क का विस्तृत वर्णन है, जो भारत सहित राष्ट्रीय सीमाओं तक फैला हुआ है। यह महत्वपूर्ण कृति स्पष्ट रूप से यह बात सामने रखती है कि भारतीयों की इस धारणा के विपरीत कि भारत विश्व का गुरु है, वास्तव में हार्वर्ड ही गुरु है। यहां तक कि भारतीय सरकार की नीतियां भी इससे प्रभावित होती हैं।

इस जानकारी से हार्वर्ड के कुछ शोध, शिक्षा और प्रचार कार्यों को प्रायोजित करने वाले भारतीय अरबपतियों और बुद्धिजीवियों की भूमिका की और अधिक जांच-पड़ताल करने की प्रेरणा मिलती है। पुस्तक किसी पर दोष नहीं लगाती; लेकिन हमें और अधिक जानने के लिए स्वयं भी

गहराई से छानबीन करनी चाहिए। मुझे अरबपतियों की संलिप्तता सबसे महत्वपूर्ण खुलासा लगी और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे इसे अपने लाभ के लिए एक स्वतंत्र स्रोत के रूप में सही भावना से लें।
गंगा में सांप एक अभूतपूर्व पुस्तक है। मैं देश के प्रति सच्ची चिंता और प्रेम रखने वाले प्रत्येक भारतीय से आग्रह करता हूँ कि वे इस अद्भुत और मौलिक पुस्तक को पढ़ें और भारत को तोड़ने वाली इन ताकतों के खिलाफ एक प्रतिवाद का आयोजन करें। सक्रिय होना प्रतिक्रियात्मक होने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

आर. वैद्यनाथन, वित्त के प्रोफेसर (सेवानिवृत्त), भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर, जून 2022

प्रस्तावना

पीटर बोगोसियन

महज एक दशक में, संयुक्त राज्य अमेरिका के सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों में एक बड़ा बदलाव आया है। विकासवाद बनाम सृजनवाद, ईश्वर का अस्तित्व, या विदेशी भूमि पर अमेरिकी कब्ज़ा जैसे पुराने सांस्कृतिक संघर्षों की बहसें अब लुप्त हो चुकी हैं। इनकी जगह पहचान से जुड़े सवालों ने ले ली है, जैसे 'औरत कौन है?' और ऐतिहासिक शिकायतों से जुड़े सवाल, जैसे 'क्या संयुक्त राज्य अमेरिका को पूर्व गुलामों के अफ्रीकी-अमेरिकी वंशजों को मुआवज़ा देना चाहिए?' ये सवाल जिज्ञासा की सच्ची भावना से नहीं उठाए जाते। बल्कि, इनके पहले से तय जवाब होते हैं और जो कोई भी अलग राय रखता है, उसे न केवल गलत दृष्टिकोण वाला माना जाता है, बल्कि बुरा इंसान समझा जाता है। और एक बार बुरा इंसान घोषित हो जाने पर, ऐसे असहमति जताने वाले को

नौकरी से वंचित करके, समाज से बहिष्कृत करके, सोशल मीडिया पर धमकाकर और पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से बहिष्कार करके दंडित किया जाता है।

इन सवालों के 'सही' जवाबों के पीछे एक नैतिक ढांचा है जो न केवल समर्थन देता है बल्कि ज्ञान की विद्वतापूर्ण स्वीकृति भी प्रदान करता है। नैतिक रूप से प्रचलित निष्कर्षों को वैधता प्रदान करने के लिए अकादमिक साहित्य के संपूर्ण भंडार तैयार किए गए हैं, जो जानबूझकर किसी भी वैकल्पिक दृष्टिकोण को गंभीरता से विचार करने से रोकते हैं। इस तरह के प्रचलित 'विद्वत्ता' में मोटापा अध्ययन, नारीवादी भूगोल, क्वीर अध्ययन आदि शामिल हैं।

कई कारणों से यह आधुनिक सभ्यता के कामकाज के लिए खतरनाक है, जिनमें से प्रमुख यह है कि हम अब अपने शैक्षणिक संस्थानों पर भरोसा नहीं कर सकते कि वे गैर-वैचारिक, स्वतंत्र, साक्ष्य-आधारित ज्ञान के स्रोत उत्पन्न करेंगे जिन पर हम सार्वजनिक नीतियां बनाने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए निर्भर कर सकें। हर उस विश्वविद्यालय के साथ जो वैचारिक रूप से प्रभावित हुआ है, और हर उस पीयर-रिव्यू जर्नल के साथ जिसने आलोचनात्मक सामाजिक न्याय विचारधारा के लिए सत्य का सौदा किया है, हम अपने विश्वासों को उनके निष्कर्षों पर आधारित करते हैं और ऐसे तरीकों से कार्य करते हैं जिन्हें हम अपना विकास मानते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। हम ऐसे कानून बना रहे हैं—और वकीलों की एक नई पीढ़ी को कानून बनाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं—जो ऐतिहासिक मानदंडों से आमूलचूल विचलन की अनुमति देते हैं, उदाहरण के लिए, नाबालिगों के लिए 'लिंग परिवर्तन' सर्जरी (जिसमें छोटी लड़कियों के स्तन और छोटे लड़कों के लिंग को हटाना शामिल है) की अनुमति देना, अक्सर माता-पिता की सहमति के बिना।

हालांकि, इस नैतिक वर्चस्व के साथ एक और भी चिंताजनक बात जुड़ी हुई है: हम असहमति व्यक्त करने की क्षमता और स्वतंत्रता खो रहे हैं। हमारी संज्ञानात्मक स्वतंत्रता—अपने विवेक के अनुसार सोचने की क्षमता —तेजी से कम होती जा रही है। हम अब खुलकर बोल नहीं सकते और प्रचलित रूढ़िवादिता के निर्देशों का पालन करने की मजबूरी के बंधक बन चुके हैं।

हेलेन प्लकरोज़ और जेम्स लिंडसे की बेस्टसेलर पुस्तकें जैसे कि 'सिनिकल थ्योरीज़: हाउ एक्टिविस्ट स्कॉलरशिप मेड एवरीथिंग अबाउट रेस, जेंडर, एंड आइडेंटिटी – एंड व्हाई दिस हार्म्स एवरीबॉडी' और डगलस मरे की 'द मैडनेस ऑफ क्राउड्स: जेंडर, रेस, एंड आइडेंटिटी' ने इन घटनाओं की उत्पत्ति और उनके निरंतर परिणामों को कुशलतापूर्वक समझाया है। 'स्नेक्स इन द गंगा' इन्हीं कृतियों पर आधारित है और बताती है कि यह न केवल पश्चिम में बल्कि भारत में भी कैसे हुआ। यह पुस्तक हमारे संस्थानों के केंद्र में सत्य को रखने और स्वतंत्र रूप से सोचने और खुलकर, ईमानदारी से और निडर होकर बोलने की हमारी क्षमता को बहाल करने का एक सशक्त आह्वान है।

गंगा में सांप (Sneaks in the Ganga) नामक यह पुस्तक अमेरिकी या यूरोपीय दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है, बल्कि इन परस्पर जुड़ी घटनाओं का वैश्विक परिप्रेक्ष्य से विश्लेषण करती है, जिसकी शुरुआत भारत के बारे में अज्ञानता के एक स्पष्ट क्षेत्र पर प्रकाश डालने से होती है। जहां मुख्यधारा के अमेरिका ने आलोचनात्मक सामाजिक न्याय, वोकिज़्म और आलोचनात्मक नस्ल सिद्धांत से जुड़ी समस्याओं को समझना शुरू कर दिया है, वहीं भारत में ऐसा नहीं है। यह पुस्तक इस बात पर प्रकाश डालती है कि आलोचनात्मक नस्ल सिद्धांत और इससे संबंधित अन्य सिद्धांत चुपके से भारत में प्रवेश कर चुके हैं और अधिकांश भारतीयों को

बिना बताए समाज और सरकार के हर पहलू में व्याप्त हो गए हैं। और इस वैचारिक वर्चस्व के साथ, आलोचनात्मक सामाजिक न्याय प्रतिष्ठित भारतीय संस्थानों की वैधता को नष्ट कर रहा है। उदाहरण के लिए, अत्यधिक प्रशंसित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईटीआई) (जिन्हें अमेरिकी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सिलिकॉन वैली के उद्यमियों और कॉर्पोरेट सीईओ का एक बड़ा हिस्सा तैयार करने का गौरव प्राप्त है) को भारतीय मूल के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर द्वारा सामाजिक उत्पीड़न की संरचना घोषित किया गया है (जिस पर अध्याय 4 में चर्चा की गई है)। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) शिक्षा में योग्यता-आधारित व्यवस्था की अवधारणा को दुरुपयोगपूर्ण बताया जा रहा है, और समान अवसर प्रदान करने के बजाय योग्यता की परवाह किए बिना समान परिणाम देने की मांग उठ रही है। इस संदर्भ में, 'सांप गंगा में' नामक रचना भारत की विविध पहचानों के नाजुक संतुलन को देखते हुए इन आक्रामक विचारधाराओं के विनाशकारी परिणामों को दर्शाती है। अमेरिका में प्रचलित वोकवाद (Wokeism) भी गलतफहमियों का कारण बन रहा है। क्रिटिकल रेस थ्योरी जैसे अमेरिकी अकादमिक सिद्धांतों की स्पष्ट समझ न होने के कारण, भारतीय अमेरिकी विदेश नीति के कुछ पहलुओं के लिए सभी अमेरिकियों को दोषी ठहराने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (एक औपचारिक निकाय जो अमेरिकी कांग्रेस को रिपोर्ट करता है) अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भारत को इस्लामोफोबिया के लिए फटकार लगाता है। हालांकि, भारत में अंतर-धार्मिक संबंधों की वास्तविकता कहीं अधिक जटिल है और इसका एक लंबा इतिहास है जिसे किसी भी सूक्ष्म और संतुलित विश्लेषण में ध्यान में रखना आवश्यक है। कई भारतीयों को यह एहसास नहीं है कि इस तरह के वैचारिक पूर्वाग्रह पूरे संयुक्त राज्य

अमेरिका का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और ये तो केवल नई नैतिक रूढ़िवादिता के अकादमिक प्रचार का एक छोटा सा हिस्सा हैं।
वैश्विक स्तर पर वोकवाद के प्रसार में भारत की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, और किसी भी प्रतिवाद को विकसित करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। हालांकि कई अमेरिकी इस बात से अवगत हैं कि भारत सूचना प्रौद्योगिकी कर्मियों का एक बड़ा आपूर्तिकर्ता है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि भारतीय वामपंथी भी आलोचनात्मक सामाजिक न्याय जैसी नवीनतम अमेरिकी वामपंथी विचारधाराओं में प्रशिक्षण के लिए युवा विद्वानों का एक प्रमुख स्रोत है; और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्हें पक्षपातपूर्ण विद्वता और महत्वाकांक्षी सक्रियता के प्रसार के लिए जमीनी स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। 'स्नेक्स इन द गंगा' पुस्तक बताती है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय जैसे अमेरिकी प्रतिष्ठित संस्थान बड़ी संख्या में इन भारतीय वामपंथियों की भर्ती करते हैं, जिन्हें वित्त पोषण और समर्थन दिया जाता है, और इस प्रकार उन्हें ज्ञान कार्यकर्ताओं की वैश्विक वामपंथी सेना के सदस्यों में परिवर्तित किया जाता है।
हालांकि इस तरह की सक्रियता किसी भी देश के लिए खतरनाक है, लेकिन यह शायद भारत जैसे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा करती है, जहां विविध पहचानों का समावेश है और इसलिए सामाजिक अशांति की सबसे अधिक संभावना है। अत:, वैश्विक खतरे से निपटने के लिए वास्तव में खुले विचारों वाले और उदार भारतीय बुद्धिजीवियों को उनके अमेरिकी समकक्षों के करीब लाना आवश्यक है।
गंगा में सांप नामक यह पुस्तक नव-नैतिक रूढ़िवाद के सिद्धांतों को बढ़ावा देने वाले धुर-वामपंथी विद्वानों-कार्यकर्ताओं को भारत द्वारा दी जाने वाली धनराशि का पर्दाफाश करती है। साथ ही, यह इस पेचीदा सवाल को भी उठाती है कि कुछ पूंजीपति अप्रत्यक्ष रूप से नव-मार्क्सवाद को क्यों

बढ़ावा दे रहे हैं।
कभी-कभार ही कोई ऐसी किताब आती है जो किसी सभ्यता की दिशा बदल सकती है। 'सांप गंगा में' ऐसी ही एक किताब है। यह पश्चिम में जन्मी और अन्य संस्कृतियों में निर्यात की गई आलोचनात्मक सामाजिक न्याय की विचारधाराओं और अप्रमाणित नैतिक रूढ़ियों के खतरनाक स्वरूप पर गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। 'सांप गंगा में' ही वह किताब है जो हमें उदारवाद विरोधी विचारधारा का मुकाबला करने, सत्य को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में स्थापित करने और हमारी सभ्यता की दिशा बदलने की सबसे बड़ी उम्मीद देती है।

पीटर बोगोसियन, संस्थापक संकाय फेलो, ऑस्टिन विश्वविद्यालय, जून 2022

परिचय

पृष्ठभूमि

भारत एक बार फिर व्यापक समाजशास्त्रीय सिद्धांतों और उनसे जुड़ी विभिन्न प्रथाओं, सक्रियता, प्रशिक्षित मानव संसाधन और संस्थागत तंत्र को आयात करने की कगार पर है। अतीत में सामाजिक विज्ञान के कई अन्य विदेशी आयातों की तरह, यह आंदोलन भी भारतीय समाज और राजनीति के साथ टकराव की स्थिति में है। फिर भी, भारत के परिप्रेक्ष्य में इस नवीनतम शक्ति का अध्ययन करने का प्रयास बहुत कम हुआ है। इसके विपरीत, सरकार और उद्योग जगत के अभिजात वर्ग इस घुसपैठ में सहभागी हैं। इस कथन को किसी भी प्रकार से आरोप के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि इसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के

एक चेतावनी संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए, जो इस मामले पर आगे की चर्चा की मांग करता है।

आगे की व्याख्या करने से पहले, हमें भारत में आयातित सिद्धांतों और मतों के कारण उत्पन्न सामाजिक-राजनीतिक उथल-पुथल की पिछली लहरों को याद करना आवश्यक है। दक्षिण भारत को परेशान करने वाला बदनाम आर्य/द्रविड़ विभाजन पूरी तरह से यूरोपीय सिद्धांत था जिसे भारत लाया गया और इसे जड़ जमाने में कई पीढ़ियाँ लग गईं। इसके बाद ही हमें एहसास हुआ कि भारत की शैक्षिक, सामाजिक, मीडिया और राजनीतिक संरचना में इसकी जड़ें कितनी गहरी जम चुकी हैं। यह अब दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य द्वारा स्वीकृत सबसे मजबूत प्रतिमानों में से एक है। इस तथ्य के बावजूद कि ऐतिहासिक तथ्य अधिक जटिल और सूक्ष्म हैं, यह सिद्धांत भारत में प्रचलित हो चुका है, और इसका खंडन करने वालों पर ही इसका प्रमाण प्रस्तुत करने का भार है। भारतीय समाजशास्त्र में वर्ण और जाति की अवधारणाएँ बहुत पुरानी, जटिल और परिवर्तनशील थीं। इतिहास के विभिन्न कालखंडों और विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक संरचनाएँ काफी भिन्न थीं। लेकिन पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया विदेशी शब्द 'कास्टा' भारतीय समाज को देखने के यूरोपीय दृष्टिकोण के रूप में 'जाति' के विकास का आधार बना। बाद में, 1871 से ब्रिटिश जनगणना द्वारा इसे आधिकारिक ढाँचे के रूप में अपनाया गया ताकि भारतीय समाज पर उनके नस्लीय सिद्धांतों को लागू किया जा सके। अंग्रेजों ने इस आयातित कठोर प्रणाली के आधार पर नए कानून बनाए और अतीत की लचीली संरचनाओं को प्रतिस्थापित कर दिया। इससे उनकी फूट डालो और राज करो की रणनीति को बल मिला।

आयातित आर्य सिद्धांत की तरह, जाति व्यवस्था के औपनिवेशिक

सिद्धांतों का भी प्रारंभ में सभी वर्गों के भारतीयों और यहाँ तक कि कई ब्रिटिश अधिकारियों ने भी विरोध किया। हालाँकि, धीरे-धीरे भारतीयों ने जाति सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया और अंततः इसे सामान्य संदर्भ के रूप में अपना लिया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, जाति व्यवस्था को कानून में और अधिक सुदृढ़ कर दिया गया, और अब यह विभाजन को बढ़ावा देने वाला एक शक्तिशाली हथियार बन गया है। मार्क्सवाद भी आयात किया गया था, जिससे भारत में कई कम्युनिस्ट दलों का जन्म हुआ, जो सोवियत संघ या चीन से काफी प्रभावित थे। इसके बाद, भारत के मार्क्सवादी बुद्धिजीवियों ने प्राच्यवाद, उत्तर-औपनिवेशिकवाद और अधीनस्थवाद जैसे कई नए अमेरिकी सिद्धांतों को अपनाया। उत्तर-औपनिवेशिकवाद और अधीनस्थवाद के बीच अंतर को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है: उत्तर-औपनिवेशिकवाद ने पूर्वाग्रहों और उत्पीड़न के लिए विदेशी उपनिवेशवादियों को दोषी ठहराया और भारत के मूल निवासियों को उपनिवेशित पीड़ित माना। भारत में यह स्थिति तब बदल गई जब अधीनस्थवाद ने भारत के ब्राह्मणों को उत्पीड़क के रूप में दोषी ठहराना शुरू किया, जबकि उत्पीड़ित पीड़ित निचली जातियां, मुसलमान, महिलाएं और अन्य थे। इससे अल्पसंख्यक राजनीति का उदय हुआ। जहां प्राच्यवाद और उत्तर-औपनिवेशिकवाद ने भारतीयों को विदेशी उपनिवेशवादियों का मुकाबला करने में एकजुट किया, वहीं अधीनस्थवाद भारत को तोड़ने वाली ताकतों का विभाजनकारी आधार बन गया।

इन सभी बौद्धिक प्रणालियों ने सर्वप्रथम अकादमिक जगत में अपनी पैठ बनाई। ये भारतीय इतिहास लेखन, शैक्षिक पाठ्यक्रम और भारत के सिविल सेवकों के प्रशिक्षण तक फैल गईं। भारतीय बुद्धिजीवियों में प्रचलित विदेशी सिद्धांतों को अपनाने का एक विशेष जुनून होता है, और

इसी तरह कई करियर और परंपराएं विकसित होती हैं।
भारतीय बुद्धिजीवियों से शुरू होने वाली बात केवल बुद्धिजीवियों तक ही सीमित नहीं रहती। ऊपर उल्लिखित प्रत्येक आयात को गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के नेटवर्क, विदेशी वित्तपोषण के प्रवाह और बहुराष्ट्रीय राजनीतिक और कानूनी समर्थन द्वारा समर्थित किया जा रहा है। ये तंत्र सुव्यवस्थित और कुशल हैं, और राष्ट्रीय सीमाओं के पार बिजली की गति से काम करते हैं। दुनिया के किसी एक कोने में होने वाली कोई भी घटना पूरे तंत्र में जंगल की आग की तरह फैल जाती है, जिसके जमीनी स्तर पर गंभीर परिणाम होते हैं, यहां तक कि हिंसा भी भड़क सकती है।
आइए अब इस पुस्तक के मूल विषय पर आते हैं। पाठक को यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि क्रिटिकल रेस थ्योरी (सीआरटी) जैसी आदर्शवादी और मानवतावादी अवधारणा का उपयोग सहस्राब्दियों से निर्मित समाज को ध्वस्त करने के लिए किया जा रहा है। हम केवल संयुक्त राज्य अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ क्रिटिकल रेस थ्योरी का उद्गम हुआ और जो सर्वव्यापी हो गई है, बल्कि भारत की भी बात कर रहे हैं, जो विश्व के दूसरे छोर पर स्थित एक ऐसा देश है जिसका इतिहास और सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से अद्वितीय है।
जो पाठक क्रिटिकल रेस थ्योरी से परिचित नहीं हैं, उनकी सुविधा के लिए अध्याय 1 इसके आधार, इतिहास, प्रमुख व्यक्तियों और रणनीतियों की पड़ताल करने के लिए समर्पित है। यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह आंदोलन पीड़ित होने की भावना को भारत को तोड़ने की ताकत के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।
शुरुआत में, जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट करनी होंगी। हमारा ध्यान क्रिटिकल रेस थ्योरी को

अमेरिकी समाज पर लागू करने पर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि इसे भारत के लिए गलत तरीके से अनुकूलित किया गया है और इसके संवेदनशील सामाजिक परिवेश पर जल्दबाजी में लागू किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि भारत के शैक्षणिक संस्थानों में पहले आयातित सिद्धांतों के अनुकूलन के विपरीत, इस मामले में, भारतीयकृत संस्करण भारत के भीतर नहीं, बल्कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय जैसे स्थानों पर तैयार किए जा रहे हैं। और यह काम बड़े पैमाने पर हार्वर्ड में कार्यरत भारतीयों द्वारा किया जा रहा है। इनमें से बड़ी संख्या में भारतीय इस कार्य में शामिल हैं, शीर्ष प्रोफेसरों से लेकर कनिष्ठ विद्वानों और छात्रों तक, सभी भूमिकाएँ निभा रहे हैं।

अंत में, और इस पुस्तक में सबसे अप्रत्याशित निष्कर्ष यह है कि भारतीय अरबपति इस आंदोलन को वित्तपोषित कर रहे हैं, और अपने पारिवारिक नाम और संपर्कों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार का भारतीय समर्थन शामिल है: हार्वर्ड में किए गए शोध से लेकर, हार्वर्ड के उन सम्मेलनों और कार्यक्रमों तक जहाँ इस विषय पर चर्चा होती है, उन प्रशिक्षण सेमिनारों तक जहाँ भारतीय राजनीतिक और व्यावसायिक नेता प्रभावित होते हैं, और भारत में स्थापित उन संगठनों तक जो कच्चा डेटा जुटाने में मदद करते हैं और भारतीय समाज में वैचारिक प्रसार के माध्यम के रूप में कार्य करते हैं।

यह वाकई एक बहुत बड़ी कहानी है। सबसे पहले, पाठक के मन में इस सारी जानकारी को तार्किक और व्यवस्थित तरीके से समझने की क्षमता विकसित करनी होगी। इस शोध प्रबंध के कई पहलू हैं और इसे टुकड़ों में समझने के बजाय समग्र रूप से समझना आवश्यक है। अन्यथा, पाठक कुछ गलत निष्कर्ष निकाल सकता है।

हम इस बहुस्तरीय शोधप्रबंध को एक-एक करके व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत

करना शुरू करेंगे। भारत में आयात किए जा रहे बौद्धिक और सामाजिक-राजनीतिक हथियारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में समझाना होगा। तभी पाठक पूरी तरह समझ पाएंगे कि आयातित पिछली विचारधाराओं की तुलना में इनमें इतना नयापन क्या है।
यह समझाना बेहद ज़रूरी है कि किस तरह अफ़्रीकी अमेरिकियों और दलितों को इस उद्देश्य के लिए एक साथ लाया जा रहा है ताकि अमेरिकी समाज में नस्लवाद की ताज़ा लहरों को भारत तक पहुँचाया जा सके। अमेरिकी व्यवसायों और कैंपस में भारतीय अमेरिकियों की जातिगत जनगणना की जा रही है, और इस तरह तैयार की गई पक्षपातपूर्ण रिपोर्टों का इस्तेमाल भारतीयों के प्रति जनमत को ज़हर देने के लिए किया जा रहा है। इन जनगणनाओं के लिए ज़िम्मेदार वही 'जाति विशेषज्ञ' अचानक सिलिकॉन वैली की विशाल कंपनियों में जातिगत संवेदनशीलता प्रशिक्षण देने वाले कुलीन सलाहकार बन गए हैं, जिससे वहाँ काम करने वाले बड़ी संख्या में भारतीयों को काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। और इसी वजह से अमेरिकी संगठनों में जाति से संबंधित नए कानून और नियम बनाए जा रहे हैं।

चार बड़ी कहानियाँ
यह पुस्तक अमेरिका और भारत दोनों देशों के कई क्षेत्रों में किए गए गहन शोध का परिणाम है। इसे चार अलग-अलग कहानियों में व्यवस्थित किया गया है ताकि पाठक इसकी गहराई को समझ सकें। प्रत्येक कहानी अपने आप में पूर्ण है और एक पूरी पुस्तक बन सकती है। लेकिन इस पुस्तक में निहित महत्वपूर्ण संदेश को समझने के लिए प्रत्येक कहानी को अन्य कहानियों के संदर्भ में देखना आवश्यक है।
इन कहानियों का सारांश नीचे दिया गया है:

किस प्रकार आलोचनात्मक नस्ल सिद्धांत ने पश्चिम में वामपंथी बयानबाजी पर कब्जा कर लिया है, जबकि यह अक्सर ऐसे आदर्शों का समर्थन करता है जो शास्त्रीय उदारवाद के कई मूल घटकों के विपरीत हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने कुछ प्रमुख अश्वेत विद्वानों और प्रतिभाशाली युवा दलित विद्वानों को एक साथ लाकर, 'जाति = नस्ल' की अवधारणा को रेखांकित करते हुए, आलोचनात्मक नस्ल सिद्धांत को आलोचनात्मक जाति सिद्धांत में रूपांतरित किया है। 'ब्रेकिंग इंडिया: वेस्टर्न इंटरवेंशन्स इन द्रविड़ियन एंड दलित फॉल्ट लाइन्स' नामक पुस्तक में उजागर की गई पुरानी अफ्रीकी-दलित विचारधारा के अनुसार, दलित भारत के अश्वेत हैं और ब्राह्मण श्वेत हैं। यह विभाजनकारी धारणा अब नवीनतम समाजशास्त्रीय विचारधारा का रूप ले चुकी है, जो विभाजनकारी पहचान की राजनीति को एक नए स्तर पर ले जाती है। भारत में सभी अमेरिकी नस्ल सिद्धांतों, कानूनी ढाँचों, कार्यकर्ताओं के उपकरणों और संस्थागत नेटवर्कों को लाने का रास्ता खुल गया है। इसलिए आज, अमेरिकी नस्ल-विरोधी आंदोलन भारत की सामाजिक क्रांति को गति प्रदान कर रहे हैं। भारत के सामाजिक अन्याय को दूर करना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन यह व्यापक स्थानांतरण भारत में पीड़ित होने की राजनीति का लाभ उठा रहा है। इसकी तुलना भारत में ब्रिटिश 'सभ्यीकरण' अभियान से की जा सकती है, जो मूल रूप से भारतीयों को नियंत्रित करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति थी। भारत के लिए इसके निहितार्थों को स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है।

हार्वर्ड इस परियोजना का अकादमिक केंद्र बन गया है। यह भारत को ध्वस्त करने के लिए आलोचनात्मक जाति सिद्धांत के उपयोग का समर्थन करने हेतु अत्याचार साहित्य विकसित कर रहा है।

हार्वर्ड तेजी से इस विद्वत्ता और सक्रियता को भारत में निर्यात कर रहा है।

इसने भारतीय उद्योग, सरकार, मीडिया, परोपकार और नागरिक समाज के लगभग हर क्षेत्र में अपनी पैठ बना ली है। भाग 2 और 3 में इसके अनेक ठोस उदाहरण दिए जाएंगे। परोपकार और विकास के दायरे में, अभिजात वर्ग के कार्यकर्ताओं और संस्थानों की एक नई पीढ़ी को मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

ये चारों महत्वपूर्ण कहानियां अपने आप में बेहद अहम हैं। जब इन्हें एक साथ देखा जाता है, तो एक अभूतपूर्व बौद्धिक और सामाजिक क्रांति का खुलासा होता है। नीचे दिया गया चित्र दर्शाता है कि ये कहानियां एक दूसरे से किस प्रकार जुड़ी हुई हैं।

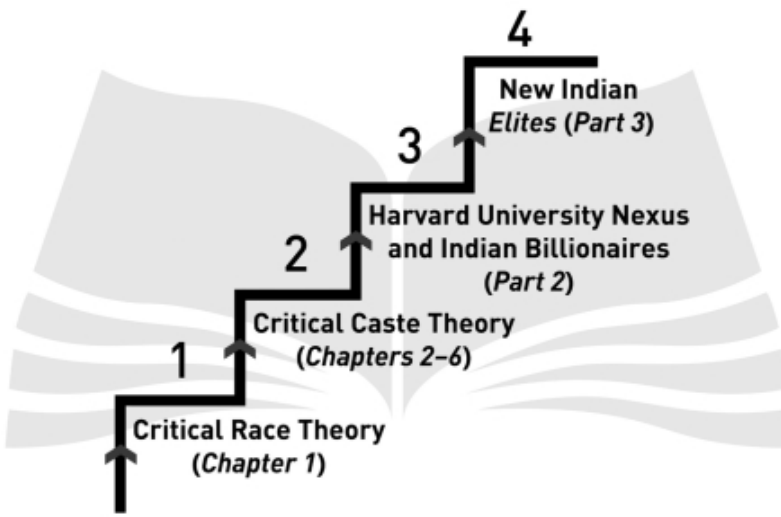

कहानी 1: मार्क्सवाद का अमेरिकीकरण

इस घटनाक्रम को समझने के लिए, हमें यूरोप में मार्क्सवाद के विकास और अमेरिका में इसके आगमन का पता लगाना होगा। यह नया अमेरिकीकृत संस्करण अमेरिका से लेकर दुनिया के बाकी हिस्सों तक,

और भारत पर विनाशकारी प्रभाव डालते हुए, तेजी से फैल रहा है। हालांकि अधिकांश अमेरिकियों ने इतिहास भर में मार्क्सवाद को तिरस्कार की दृष्टि से देखा है, फिर भी मार्क्सवादी विचारधारा अमेरिकी शैक्षणिक संस्थानों, विचारकों और शक्तिशाली गैर-सरकारी संगठनों के मूल में निहित है। इसे मार्क्सवाद नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि इसके नकारात्मक अर्थ हैं; बल्कि, यह व्यवस्थागत नस्लवाद को समाप्त करने के एक शक्तिशाली आंदोलन के भीतर छिपा हुआ है। वास्तव में, यह पुरानी ही बात को नए रूप में प्रस्तुत करने जैसा है। दरअसल, अमेरिका मार्क्सवाद के इस नवीनतम स्वरूप को विकसित करने और प्रचारित करने का वैश्विक केंद्र बन गया है।

हम मार्क्सवाद के कई पहलुओं से सहमत हैं, विशेषकर शोषण के इतिहास के उसके व्यवस्थित विश्लेषण से। लेकिन हम परंपरागत समाजों को ध्वस्त करने के लिए मार्क्सवाद द्वारा अपनाए जा रहे चरम रूपों और इसके विनाशकारी प्रभावों की आलोचना करना चाहते हैं।

क्रिटिकल रेस थ्योरी नामक नया प्रतिमान अच्छे इरादों से शुरू हुआ था – श्वेत अमेरिकियों द्वारा अश्वेत अमेरिकियों पर किए गए अन्याय के खिलाफ लड़ना। लेकिन मार्क्सवाद और उत्तरआधुनिकतावाद के साथ विलय होने के कारण, क्रिटिकल रेस थ्योरी उसी विनाशकारी प्रभाव की ओर खतरनाक रूप से अग्रसर है जो साम्यवाद और अन्य मार्क्सवादी प्रयोगों ने विश्व स्तर पर उत्पन्न किया था। यह कई मार्क्सवादी सिद्धांतों को साझा करता है:

क्रिटिकल रेस थ्योरी मार्क्सवादी द्वंद्ववाद को अपनाती है जिसके अनुसार समाज को उत्पीड़कों और उत्पीड़ितों में विभाजित किया जाना चाहिए। क्योंकि यह सारा विमर्श बुर्जुआ वर्ग (यूरोपीय शासक वर्ग, जिसकी जगह अब श्वेत अमेरिकी ले चुके हैं) द्वारा रचा गया था, इसलिए यह एक

वर्चस्ववादी आख्यान बन गया है जो उत्पीड़क की सेवा करता है। अतः, इसे उखाड़ फेंकने के लिए एक नए प्रति-वर्चस्व का विकास करना आवश्यक है।

मौजूदा स्थापित व्यवस्था (सिद्धांत) पर इतने ज़ोरदार तरीके से हमला करना होगा कि दोनों ही नष्ट हो जाएँ। जब तक पुरानी संरचनाएँ ध्वस्त नहीं हो जातीं, तब तक सभी सामाजिक सुधार केवल पुरानी व्यवस्था को ही कायम रखते हैं। यह संघर्ष हिंसक और बिना किसी समझौते के होना चाहिए। तभी एक नई सामाजिक व्यवस्था का उदय हो सकता है।

सभी सौहार्दपूर्ण वार्ताएँ और व्यवस्था में सुधार के प्रयास त्रुटिपूर्ण हैं क्योंकि वे अंततः पुराने वर्चस्ववादी दृष्टिकोण और उसके नियमों के दायरे में ही सिमट जाते हैं। इसलिए, खुली बातचीत एक बुरा विचार है। वास्तव में, प्रति-वर्चस्व पैदा करने के लिए, यानी पुराने पूर्वाग्रह का जवाब देने के लिए एक नए पक्षपातपूर्ण विमर्श को स्थापित करने के लिए, सोचने और बोलने की स्वतंत्रता को सीमित करना आवश्यक है। यह असहिष्णुता सोवियत तानाशाह स्टालिन की याद दिलाती है। यह क्रिटिकल रेस थ्योरी में कैंसिल कल्चर के रूप में मौजूद है जो अमेरिकी परिसरों और समाज में फैल चुका है।

स्थापित व्यवस्था का विनाश केवल हिंसा के प्रयोग सहित अत्यधिक असहिष्णुता के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है।

अध्याय 1 में आलोचनात्मक नस्ल सिद्धांत की इन सभी विशेषताओं के पर्याप्त प्रमाण दिए जाएंगे जिनकी उत्पत्ति मार्क्सवाद में हुई है।

मार्क्सवाद और क्रिटिकल रेस थ्योरी (CRT) के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह भी है: क्रिटिकल रेस थ्योरी के प्रमुख नेताओं ने तर्कसंगतता, वस्तुनिष्ठ प्रमाण और यहाँ तक कि विज्ञान को भी नकार दिया है। इसका एक उदाहरण लेस्बियन, गे, बाईसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर +

(LGBTQ+) चर्चा में पुरुष-महिला के जैविक लिंग द्वैत को अस्वीकार करना है। 'वास्तविक अनुभव' को अंतिम निर्णय माना जाता है और सभी तर्कसंगत और प्रतिवाद को दबा दिया जाता है। व्यक्तिपरकता को सर्वोपरि माना जाता है जबकि वस्तुनिष्ठता को पितृसत्तात्मक समझा जाता है। जब कोई विरोधी प्रतिवाद करने का प्रयास करता है तो उसे 'कैंसल कल्चर' का प्रयोग किया जाता है। इसके विपरीत, मार्क्सवाद तर्कसंगतता और वैज्ञानिक पद्धति पर अपने ज़ोर देने पर गर्व करता है। हालाँकि जमीनी स्तर पर मार्क्सवादी क्रांतिकारी कट्टरपंथी और विरोधियों के प्रति असहिष्णु थे, लेकिन बुद्धिजीवी तर्कसंगत बहसों में शामिल होते थे।

मार्क्सवाद, उत्तरआधुनिकतावाद और उदारवाद मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किए जाने वाले तीन महत्वपूर्ण सैद्धांतिक ढाँचे हैं। व्यापक रूप से वामपंथी कहलाने वाला वैचारिक समूह इन ढाँचों को आधारशिला के रूप में उपयोग करता है, और विभिन्न संयोजनों के माध्यम से वामपंथी दृष्टिकोणों की एक विस्तृत श्रृंखला को परिभाषित करता है। सभी वामपंथी एक जैसे नहीं होते। कुछ कट्टर मार्क्सवादी होते हैं, कुछ उत्तरआधुनिकतावाद पर अधिक निर्भर होते हैं, कुछ उदारवादी होते हैं जो इन दोनों के केवल हल्के रूपों का उपयोग करते हैं, इत्यादि। गहराई में जाने पर स्थिति और भी जटिल हो जाती है। पता चलता है कि मार्क्सवाद, उत्तरआधुनिकतावाद और उदारवाद भी एकल विचार नहीं हैं, बल्कि प्रत्येक का अपना जटिल इतिहास है और इसके कई उप-समूह हैं। यह पुस्तक वामपंथ के इतिहास और विचारों का विस्तार से अध्ययन करने का इरादा नहीं रखती, क्योंकि यह इसके दायरे से बाहर होगा। इसके बजाय, अध्याय 1 में केवल यह बताया जाएगा कि आलोचनात्मक नस्ल सिद्धांत ने मार्क्सवाद, उत्तरआधुनिकतावाद और उदारवाद, इन तीनों से कुछ तत्व लिए हैं, जबकि इनके कई प्रमुख आधारों को अस्वीकार

किया है।
विडंबना यह है कि अधिकांश पारंपरिक वामपंथी विचारक, जो स्वयं को मार्क्सवाद, उत्तरआधुनिकतावाद और उदारवाद के किसी संयोजन के रूप में परिभाषित करते हैं, इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पाए हैं कि आलोचनात्मक नस्ल सिद्धांत (CRT) उनके मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है। दूसरे शब्दों में, वामपंथी खेमे के भीतर एक गंभीर टकराव चल रहा है। पुरानी वामपंथ को CRT से उभरी नई वामपंथ से चुनौती मिल रही है। आगे दिया गया चित्र यूरोप में वामपंथ के ऐतिहासिक उद्भव को दर्शाता है। 1930 के दशक में, जर्मनी में मार्क्सवाद का एक नया रूप, फ्रैंकफर्ट स्कूल, शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध (1939-45) के दौरान, इसके नेता नाज़ियों से बचने के लिए अमेरिका चले गए। जर्मन दार्शनिक जुर्गन हैबरमास और हर्बर्ट मारक्यूज़ यूरोप से आए युवा नेताओं में शामिल थे और उन्होंने अमेरिकियों की एक नई पीढ़ी को मार्क्सवादी आंदोलन की ओर आकर्षित किया। अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया।
इसी क्रम में, उत्तरआधुनिकतावाद की उत्पत्ति बीसवीं शताब्दी के फ्रांस में हुई, जहाँ प्रमुख विचारकों के माध्यम से इसका अनेक विकास हुआ। अमेरिका में, साहित्यकार गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक ने महत्वपूर्ण फ्रांसीसी विचारकों के अंग्रेजी अनुवादों के माध्यम से इस क्षेत्र में प्रारंभिक योगदान दिया। उत्तरआधुनिकतावाद को अमेरिका तक पहुँचाने में एक अन्य व्यक्ति भारतीय मूल के होमी के. भाभा का भी योगदान रहा, जो अब हार्वर्ड विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। अध्याय 10 में उन्हीं का वर्णन है। मार्क्सवाद और उत्तरआधुनिकतावाद दोनों का यह अमेरिकीकरण महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने अमेरिका को नव वामपंथ का वैश्विक केंद्र बना दिया। बाद में, अमेरिकियों ने आलोचनात्मक नस्ल सिद्धांत को एक गंभीर

विचारधारा के रूप में विकसित किया। अध्याय 1 इसी विषय पर केंद्रित है। यह सिद्धांत इस आधार पर शुरू होता है कि पश्चिमी समाज की मूल संरचना में, जिसमें संस्थाएँ (सरकारी, वित्तीय और कॉर्पोरेट) भी शामिल हैं, व्यवस्थित, अचेतन और व्यापक नस्लवाद अंतर्निहित है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ अल्पसंख्यकों का निरंतर उत्पीड़न होता है। यह सिद्धांत 'नस्लवादी न होने' और 'नस्लवाद-विरोधी होने' के बीच अंतर करता है। 'नस्लवादी न होना' को व्यवस्थित नस्लवाद को उखाड़ फेंकने और समाप्त करने के लिए अपर्याप्त माना जाता है, जबकि 'नस्लवाद-विरोधी' होने में लोगों से अपने पूर्वाग्रहों और मानसिकता को सक्रिय रूप से चुनौती देने और संस्थागत ढाँचों और प्रथाओं पर सवाल उठाने का आह्वान किया जाता है, ताकि एक अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण किया जा सके।

हाल ही में हुए ब्लैक लाइव्स मैटर (बीएलएम) आंदोलन के बाद क्रिटिकल रेस थ्योरी को मुख्यधारा में पहचान मिली, जब अश्वेतों के खिलाफ लंबे समय से चली आ रही पुलिस की बर्बरता इस तरह से सामने आई जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इन घटनाओं ने सीआरटी को मीडिया, स्कूलों और कार्यस्थल में एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बना दिया।

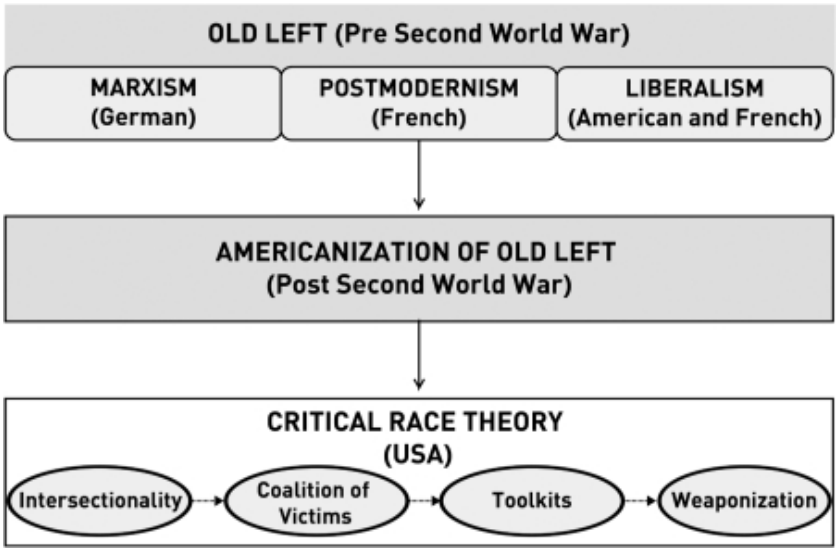

हमारा मानना है कि यद्यपि ये लक्ष्य सराहनीय हैं और जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वे वास्तविक हैं, फिर भी निवारण के कुछ तरीके अंततः समस्याग्रस्त हैं और रचनात्मक होने की तुलना में अधिक विनाशकारी हैं।

क्रिटिकल रेस थ्योरी का एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि अधिकारों के लिए संघर्ष व्यक्तियों द्वारा व्यक्तियों के लिए नहीं, बल्कि समूहों द्वारा अपने सदस्यों के लिए किया जाना चाहिए। यह शास्त्रीय उदारवाद से एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जहाँ अधिकार व्यक्तिगत नागरिकों के रूप में होते हैं, न कि समूह पहचान के रूप में। लेकिन क्रिटिकल रेस थ्योरी में, सामूहिक पहचान की सामाजिक स्थिति उसके सभी सदस्यों के विशेषाधिकार या उत्पीड़न को निर्धारित करती है। यह किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि किसी व्यक्ति की सामूहिक पहचान को समाज में किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है और वह कैसे कार्य करती है।

उदाहरण के तौर पर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा एक कट्टर उदारवादी थे जो पुरानी संस्थागत संरचनाओं को तोड़कर संघर्ष पैदा नहीं करना चाहते थे। वे आधुनिक संस्थाओं के ढांचे के भीतर अश्वेतों के लिए न्याय चाहते थे, न कि उन्हें ध्वस्त करके। ओबामा ऐसी पहचान की राजनीति नहीं खेलना चाहते थे जिससे अश्वेत और श्वेत आपस में भिड़ जाएं। उन्होंने एकता को ही आगे बढ़ने का मार्ग माना और फूट डालने के खिलाफ थे।

अपने सार्वजनिक भाषणों में, ओबामा अक्सर रंगभेद से मुक्ति के माध्यम से सामाजिक एकीकरण की वकालत करते थे; उन्होंने स्पष्ट रूप से यह मानने से इनकार कर दिया कि अमेरिकी समाज और संस्थाएँ अपरिवर्तनीय रूप से नस्लवादी हैं। बेशक, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में, वे शायद इतिहास में अपनी अनूठी स्थिति और श्वेत और अश्वेत नागरिकों के बीच की खाई को पाटने की आवश्यकता से बंधे हुए थे। फिर भी, उन्होंने एक अधिक न्यायपूर्ण और एकजुट देश के निर्माण के लिए लगातार एक विचारशील, रचनात्मक और प्रेरणादायक दृष्टिकोण व्यक्त किया। नस्लभेदी सिद्धांत (क्रिटिकल रेस थ्योरी) की विपरीत स्थिति को समझने और उसका विश्लेषण करने के साथ-साथ उनके इस दृष्टिकोण की सराहना करना आवश्यक है।

रंगभेद से मुक्त होने के मामले में ओबामा का रुख़ शास्त्रीय उदारवाद का प्रतिनिधित्व करता है। उदारवादी आदर्श यह रहा है कि अवसरों में किसी एक नस्ल को दूसरी नस्ल से तरजीह नहीं दी जानी चाहिए और नस्ल के आधार पर भेदभाव के बिना अन्याय को समाप्त किया जाना चाहिए, यानी एक रंगभेद-मुक्त नीति। आलोचनात्मक नस्ल सिद्धांत (क्रिटिकल रेस थ्योरी) का कहना है कि रंगभेद से मुक्त होने की नीति यथास्थिति बनाए रखती है जिसमें अन्याय जारी रहता है। नस्लवाद को खत्म करने के

लिए, विपरीत भेदभाव को अपनाना होगा।
एक और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि उदारवादी समान अवसरों का समर्थन करते हैं, जबकि क्रिटिकल रेस थ्योरी समान परिणामों की मांग करती है। उदारवादी सिद्धांत के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिलने चाहिए और परिणाम योग्यता के आधार पर निर्धारित होते हैं। यह योग्यता-आधारित शासन के अमेरिकी आदर्श के अनुरूप है, जिसका समर्थन ओबामा भी करते हैं। लेकिन क्रिटिकल रेस थ्योरी का कहना है कि समान अवसर प्रणाली में धांधली है क्योंकि इससे असमान परिणाम निकलते हैं। यह दृष्टिकोण इस तथ्य को नजरअंदाज करता है कि व्यक्तिगत क्षमता और भाग्य सहित कई कारक असमान परिणामों में भूमिका निभाते हैं। क्रिटिकल रेस थ्योरी का लक्ष्य 'समानता' है, जिसका अर्थ है समान परिणाम। कॉलेज प्रवेश, कॉर्पोरेट और सरकारी नौकरियों और यहां तक कि गणित परीक्षा परिणामों सहित सभी क्षेत्रों में इसकी मांग की जा रही है।
वस्तुनिष्ठ आधार पर, योग्यता-आधारित व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया जाता है क्योंकि यह समान परिणाम देने में विफल रहती है। विभिन्न पहचानों से प्राप्त अनुभवों की विविधता को अधिक मूल्यवान माना जाता है। कड़ी मेहनत और योग्यता के पारंपरिक विचारों और पुरस्कार की पारंपरिक प्रणालियों पर आलोचनात्मक नस्ल सिद्धांत द्वारा प्रश्नचिह्न लगाया जाता है।
‘संरक्षित वर्ग’ की कानूनी अवधारणा का उपयोग नए प्रकार के पीड़ित समूहों को भर्ती करने के लिए किया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय कानून निम्नलिखित नौ संरक्षित वर्गों को परिभाषित करते हैं और उन्हें भेदभाव या उत्पीड़न से विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं: लिंग (यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान सहित); नस्ल; आयु; विकलांगता; रंग;

पंथ; राष्ट्रीय मूल; धर्म; या आनुवंशिक जानकारी। अमेरिका के अलग-अलग राज्य, राज्य कानून के तहत सुरक्षा के लिए अन्य वर्ग बना सकते हैं, और बनाते भी हैं। क्रिटिकल रेस थ्योरी की रणनीति ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित होने का दावा करने वाले अधिक से अधिक समूहों की पहचान करना और उन्हें एक ऐसे गठबंधन में संगठित करना है जो स्थापित व्यवस्था के खिलाफ लड़ता है। यह असंतुष्ट समूहों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है जिनकी शिकायतें समाज और उसकी संस्थाओं को लगातार तोड़ती रहेंगी।

निम्नलिखित आरेख शास्त्रीय उदारवाद और आलोचनात्मक नस्ल सिद्धांत के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतरों को सूचीबद्ध करता है।

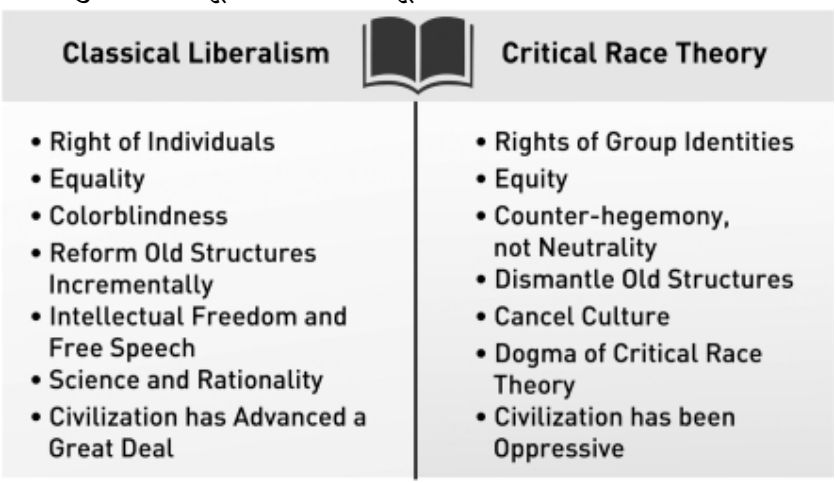

क्रिटिकल रेस थ्योरी नस्लीय भेदभाव के मामले में अश्वेत अमेरिकियों के अनुभवों को विश्व की सभी संस्कृतियों में नस्लवाद और अन्य पूर्वाग्रहों पर लागू होने वाले सार्वभौमिक दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत करती है। हम इससे असहमत हैं। यद्यपि अमेरिका में, उत्पीड़क/उत्पीड़ित का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्वेत/अश्वेत का विभाजन प्रासंगिक है, अन्य संस्कृतियों में परिस्थितियाँ अधिक जटिल और बहुआयामी हो सकती हैं।

उदाहरण के लिए, क्रिटिकल रेस थ्योरी का ढांचा एशियाई अमेरिकियों पर कैसे लागू होगा? क्या वे उत्पीड़क हैं या पीड़ित? उत्पीड़क/पीड़ित की सरल द्विआधारी प्रणाली उस स्थिति से कैसे निपटेगी जहां हिंदुओं जैसे समुदाय को कुछ लोग उत्पीड़क (दलितों के) के रूप में देखते हैं, और अन्य लोग पीड़ित (ऐतिहासिक रूप से मुस्लिम और ईसाई आक्रमणकारियों और उपनिवेशवादियों द्वारा पीड़ित) के रूप में देखते हैं? यह स्थिति तब और भी जटिल हो जाती है जब इस्लाम का बचाव क्रिटिकल रेस थ्योरी में समाहित हो जाता है, जिससे मुसलमानों को अब अश्वेतों की तरह ही व्यवस्थागत पीड़ित के रूप में देखा जाता है।
हार्वर्ड के सबसे प्रभावशाली अश्वेत विद्वानों में से एक, कॉर्नेल वेस्ट, खुले तौर पर सीआरटी के इस तर्क का समर्थन करते हैं कि उत्पीड़ित दलितों की रक्षा के लिए हिंदू धर्म की संरचनाओं को ध्वस्त कर देना चाहिए। लेकिन मुसलमानों, ईसाइयों और पश्चिमी वर्चस्व द्वारा हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के संदर्भ में, यह तर्क दिया जा सकता है कि हिंदू धर्म ही भारतीय मानसिकता को वैश्विक गठजोड़ों द्वारा और अधिक उपनिवेशीकरण से बचा रहा है। इस प्रकार हमारे सामने एक जटिल स्थिति है जिसे केवल उत्पीड़क/उत्पीड़ित के सरलीकृत परिदृश्य में नहीं समेटा जा सकता।
क्या यह तर्क दिया जा सकता है कि वैश्विक उत्पीड़क (अब्राहमिक धर्म और पश्चिमी वामपंथी गठबंधन) स्थानीय उत्पीड़ितों (भारत के भीतर दलितों) को हिंदू धर्म की संरचनाओं को ध्वस्त करने के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भारत एक और सत्ता हथियाने के लिए असुरक्षित हो जाए? यह एक आम रणनीति है जिसे 'मेरे शत्रु का शत्रु मेरा मित्र है' के नाम से जाना जाता है, यानी दलितों को भारत की संप्रभुता के विरुद्ध हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का एक

व्यावहारिक तरीका। भारतीय इतिहास से परिचित लोग इसे आसानी से फूट डालो और राज करो की एक और चाल के रूप में देख सकते हैं।

कहानी 2: आलोचनात्मक नस्ल सिद्धांत का भारतीयकरण
अमेरिका में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह है कि जाति को नस्ल के रूप में परिभाषित किया गया है, जो आलोचनात्मक जाति सिद्धांत के विकास का आधार बन गया है। 'ब्रेकिंग इंडिया' पुस्तक में जिस अफ्रीकी-दलित आंदोलन का जिक्र किया गया है, वह अपने प्रारंभिक चरण में था, लेकिन अब वह परिपक्व होकर एक सशक्त आंदोलन बन चुका है। अध्याय 2, 3, 4 और 5 इस बात पर चर्चा करते हैं कि यह विकास इतनी तेजी से कैसे हुआ। प्रत्येक अध्याय आलोचनात्मक नस्ल सिद्धांत के इस भारतीयकृत संस्करण के एक पहलू पर केंद्रित है और उस पहलू के सबसे महत्वपूर्ण नायक का विश्लेषण करता है।
निम्नलिखित चित्र में इन अध्यायों में चर्चा किए गए चार मुख्य पात्रों को दर्शाया गया है, जिनमें से प्रत्येक का गहन विश्लेषण किया गया है और उनका खंडन प्रस्तुत किया गया है।

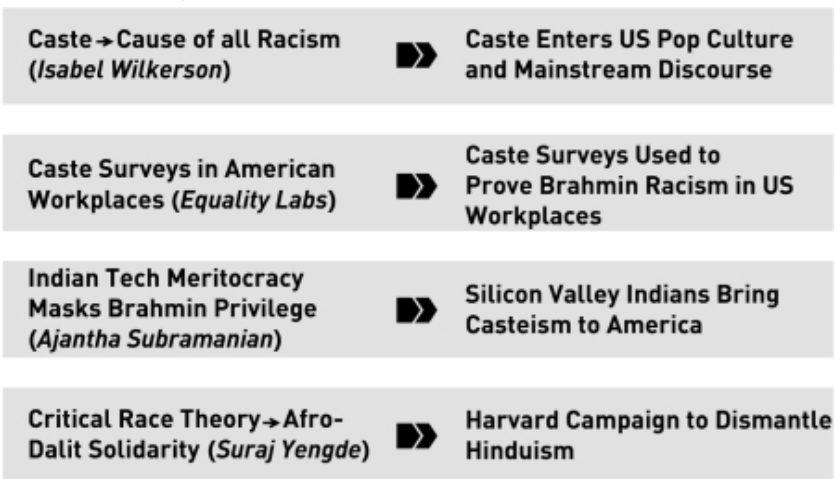

यह कोई मामूली आंदोलन नहीं है। अमेरिकी टीवी होस्ट ओपरा विन्फ्रे ने इसाबेल विल्करसन की किताब, 'कास्ट: द ओरिजिन ऑफ अवर डिसकंटेंट' का सक्रिय रूप से प्रचार किया और इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाया। यह किताब न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्टसेलर बन गई। हार्वर्ड विश्वविद्यालय भी अपने छात्रों के बीच विल्करसन के काम को बढ़ावा देता है। यह किताब आम पाठकों के लिए बेहद अच्छी तरह से लिखी गई है और एक आधिकारिक लहजे में तर्क देती है कि जाति ही वह मूल संरचना है जिसने दुनिया भर में नस्लवाद को जन्म दिया है। अध्याय 2 में हम विल्करसन के सिद्धांत का बिंदुवार विश्लेषण करेंगे, उनके अपने कथनों का हवाला देंगे और अपनी प्रतिक्रियाएँ देंगे।

अध्याय 3 में बताया गया है कि न्यूयॉर्क स्थित इक्वालिटी लैब्स के नेतृत्व में अमेरिका में जाति सर्वेक्षण किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य ब्राह्मण कर्मचारियों द्वारा जातिगत भेदभाव के आरोप में अमेरिकी संगठनों के खिलाफ कानूनी मामले तैयार करना है। अमेरिकी संगठनों पर मंडरा रहे इस कानूनी खतरे के परिणामस्वरूप, जातिवाद को नस्लवाद का एक रूप घोषित करने वाले विभिन्न नए कानून और नियम तेजी से लागू किए जा रहे हैं। कॉर्पोरेट जगत को इस अपराध में शामिल माने जाने का डर सता रहा है, और विशेष रूप से सिलिकॉन वैली में वरिष्ठ प्रबंधन को जातिगत उत्पीड़न के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। ब्राह्मणों को गोरों के बराबर और दलितों को भारत के अश्वेतों के समान चित्रित किया जा रहा है। यह भारतीय अमेरिकियों पर एक हमले में बदल गया है, उन्हें जातिवादी करार दिया जा रहा है, जो श्वेत वर्चस्ववादियों के बराबर हैं।

क्रिटिकल रेस थ्योरी विज्ञान और तर्क पर आधारित योग्यता-आधारित व्यवस्था का विरोध करती है, और इसे श्वेत विशेषाधिकार को बनाए रखने

का एक तरीका मानती है। इस तर्क को हार्वर्ड से शुरू हुए एक आंदोलन में बदल दिया गया है, जिसे प्रोफेसर अजंता सुब्रमणियन ने अपनी प्रभावशाली पुस्तक "द कास्ट ऑफ मेरिट: इंजीनियरिंग एजुकेशन इन इंडिया" के माध्यम से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) पर हमला करते हुए प्रस्तुत किया है। उनका तर्क है कि आईआईटी ने जातिवाद के रूप में नस्लवाद को संस्थागत रूप दिया है, जो अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से दलितों का दमन करता है। अध्याय 4 में इसकी विस्तृत चर्चा की गई है।

हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दलितों के चहेते, सूरज येंगडे, सबसे मुखर और चर्चित अफ्रीकी-दलित हैं। वे हर संस्था में भारतीय समाज की व्याख्या करने के लिए उत्पीड़क/उत्पीड़ित के सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं। अध्याय 5 में ब्राह्मणों, हिंदू धर्म और भारतीय सभ्यता से जुड़ी हर चीज़ पर उनके तीखे हमलों का वर्णन है। उन्होंने पूरे अश्वेत आंदोलन की नकल करते हुए एक दलित आंदोलन खड़ा किया है। दलित विरासत माह उसी तरह मनाया जाता है जैसे अश्वेत विरासत माह। दलित जीवन महत्व आंदोलन उसी तरह है जैसे अश्वेत जीवन महत्व आंदोलन। ब्लैक पैंथर पार्टी की तरह अब दलित पैंथर्स संगठन भी है, और इसी तरह अन्य संगठन भी। येंगडे हार्वर्ड के प्रतिष्ठित कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में वरिष्ठ फेलो हैं।

यद्यपि आलोचनात्मक नस्ल सिद्धांत में नस्ल उत्पीड़न की प्राथमिक श्रेणी है, भारत के संदर्भ में इसका अनुप्रयोग जाति पर आधारित है। हार्वर्ड में येंगडे और अन्य शोधकर्ताओं ने सनसनीखेज और भावनात्मक अत्याचार साहित्य से भरा एक विशाल संग्रह व्यवस्थित रूप से तैयार किया है। जिस प्रकार अमेरिकी कानून के तहत अश्वेत अमेरिकियों को आधिकारिक तौर पर 'संरक्षित वर्ग' घोषित किया गया है, उसी प्रकार दलितों को भी

संरक्षित वर्ग बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि कानूनी कार्रवाई या सार्वजनिक अपमान के डर से अमेरिका में कोई भी दलित नेता के किसी भी कथन पर सवाल नहीं उठा सकता और न ही उसे चुनौती दे सकता है।

क्रिटिकल रेस थ्योरी के अनुसार, उत्पीड़ित समूहों के वास्तविक अनुभव किसी भी वस्तुनिष्ठ प्रमाण या तर्क से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इन अनुभवों की कहानियाँ ही उत्पीड़न की संरचनाओं से लड़ने के लिए प्रति-वर्चस्व विकसित करने का आधार बननी चाहिए। हमारी चिंता यह है कि इन वास्तविक अनुभवों को जांच-पड़ताल, विश्लेषण, आलोचना या खंडन से दूर रखकर समुदायों के बीच दूरी और बढ़ाई जाती है। इससे संघर्ष और बढ़ जाते हैं, बजाय इसके कि लोग चेतना के उच्च स्तर पर एकजुट हों। साथ ही, यह दलितों को उत्कृष्टता प्राप्त करने से रोकता है क्योंकि वे खुद को निरंतर पीड़ित और मुआवजे पर निर्भर समझने लगते हैं।

भारत में क्रिटिकल रेस थ्योरी के दुरुपयोग में, भारतीय सभ्यता का विरोध करने के लिए राजी किए जा सकने वाले किसी भी समूह को उपयोगी सहयोगी माना जाता है और उसे पीड़ित का दर्जा दिया जाता है। दलितों के अलावा, इनमें सबसे महत्वपूर्ण भारतीय मुस्लिम और LGBTQ+ समुदाय हैं। एक बार जब ये पीड़ित पहचानें पुख्ता हो जाती हैं, तो इनका इस्तेमाल संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए हथियार के रूप में किया जाता है और इन्हें हर दिशा में हमले करने के लिए उकसाया जाता है। भारत की सभ्यता के निम्नलिखित पहलुओं को औपचारिक रूप से लक्ष्य के रूप में नामित किया जा रहा है:

संस्कृत: संस्कृत को दमनकारी भाषा घोषित किया जा रहा है। क्रिटिकल रेस थ्योरी का तर्क है कि भाषाओं में 'श्वेत विशेषाधिकार' की संरचनाएं निहित होती हैं, पश्चिम के मामले में, और इसी आधार पर, संस्कृत

निचली जातियों और दलितों के शोषण के एक उपकरण के रूप में ब्राह्मण विशेषाधिकार को कायम रखती है। पुस्तक, 'संस्कृत के लिए लड़ाई: क्या संस्कृत राजनीतिक है या पवित्र, दमनकारी है या मुक्तिदायक, मृत है या जीवित?' ने इस आरोप की व्याख्या की और व्यवस्थित रूप से इसका खंडन किया।

गुरु: चूंकि भारत में श्वेतों के समकक्ष ब्राह्मण हैं, इसलिए सभी गुरुओं को समाज पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का दोषी माना जाता है। गुरुओं की संस्था को श्वेत वर्चस्व के समान समझा जाता है।

देवी-देवता, त्यौहार, तीर्थस्थल, प्रतीकवाद, अनुष्ठान: अतीत की ये सभी संरचनाएँ ब्राह्मण अभिजात वर्ग द्वारा वर्चस्व स्थापित करने के लिए निर्मित की गई थीं। आरोप है कि जानबूझकर इन संरचनाओं में शोषण को जारी रखने के लिए अंतर्निहित तंत्र मौजूद हैं। इसलिए, शोषण के हर उदाहरण की खोज करते हुए ऐसी सभी संरचनाओं पर मुकदमा चलाना महत्वपूर्ण है। खोजी गई सामग्री का उपयोग शोध के लिए एक संग्रह और डेटाबेस बनाने में किया जाता है। अंततः, इसका उद्देश्य इन सभी को ध्वस्त करना है।

वैदिक शास्त्र और इतिहास: वैदिक ग्रंथों और उनसे संबंधित रचनाओं को वर्चस्ववादी माना जाता है। इटली की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक एंटोनियो ग्राम्स्की द्वारा प्रतिपादित मार्क्सवादी सिद्धांत का उपयोग करते हुए, भारतीय परंपराओं पर चर्चा में एक प्रति-वर्चस्व का निर्माण और उसे स्थापित करना आवश्यक है।

पारिवारिक व्यवस्था: पारंपरिक पारिवारिक संरचना पर खुले तौर पर हमला किया जा रहा है, इसे एक ऐसे तंत्र के रूप में देखा जा रहा है जिसके द्वारा माता-पिता दमनकारी व्यवहार को बच्चों तक पहुंचाते हैं, और भारतीय छात्रों को अपने माता-पिता के खिलाफ विद्रोह करने के लिए

प्रोत्साहित किया जा रहा है।
दूसरे शब्दों में कहें तो, इस सिद्धांत के तहत भारत की सफलता में योगदान देने वाली हर चीज का विवेचन और विघटन करना आवश्यक है। अध्याय 2, 3, 4 और 5 में भारतीय समाज पर क्रिटिकल रेस थ्योरी के इस प्रकार के अनुप्रयोग के अनेक उदाहरण दिए गए हैं, जिनमें हार्वर्ड स्थित विद्वान इस शोध और सक्रियता का नेतृत्व कर रहे हैं।
जबकि दलितों और मुसलमानों को क्रिटिकल रेस थ्योरी द्वारा अपना लिया गया है और भारत के खिलाफ इस पहचान के युद्ध में मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया है, वहीं एलजीबीटीक्यू+ समुदाय एक अपेक्षाकृत नया समूह है जिसे पश्चिमी सिद्धांतों का उपयोग करके प्रशिक्षित किया जा रहा है।
सिलिकॉन वैली में कार्यरत भारतीय अमेरिकी सॉफ्टवेयर पेशेवर दीप्ति राव का व्यक्तिगत अनुभव यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्रिटिकल रेस थ्योरी (CRT) की विभाजनकारी प्रकृति पर हमारे शोध प्रबंध के संदर्भ में उनके कथन के महत्व और उनकी अभिव्यक्ति की निडरता को देखते हुए, हम उनका विस्तृत उद्धरण देना चाहते हैं। उन्होंने एक हिंदू समलैंगिक महिला के रूप में हमसे संपर्क किया, जो क्रिटिकल रेस थ्योरी के बढ़ते प्रभाव से निपटने के लिए हिंदू मुख्यधारा से जुड़ने और सहयोग करने में गहरी रुचि रखती थीं। उनका अनुभव इस प्रकार है:
मेरा पालन-पोषण भारत में एक घनिष्ठ परिवार में हुआ। किशोरावस्था के आखिरी दौर में मुझे दूसरी महिलाओं के प्रति आकर्षण महसूस होने लगा, लेकिन समलैंगिक होने के बारे में बात करना वर्जित था। अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करते हुए, मैंने अपने निजी एहसासों को करीबी परिवार के साथ साझा करने का फैसला किया। मेरे माता-पिता ने इसका विरोध किया और इसे एक व्यवहारिक समस्या मानकर

इसका 'समाधान' खोजने की कोशिश की। हिंदू धर्म और वेदांत के ज्ञान ने मुझे महत्वपूर्ण सहारा दिया। मैंने विष्णु सहस्रनाम और हनुमान चालीसा का पाठ किया। मैंने वैदिक विरासत का अध्ययन किया और उसमें विषमलिंगी लोगों के अनेक संदर्भों को पाया। लेकिन आधुनिक हिंदू धर्म की प्रथाएं संकीर्ण थीं और समलैंगिक संबंधों के प्रति असहिष्णु थीं।
कैलिफ़ोर्निया जाने के बाद, मैंने सार्वजनिक रूप से LGBTQ+ समुदाय के सदस्य के रूप में अपनी पहचान ज़ाहिर की, खासकर एशियाई मूल के सदस्यों के एक उपसमूह के साथ। इससे मेरे जीवन में एक खालीपन भर गया क्योंकि एक परिवार के रूप में समान समस्याओं का सामना करने से हमें सुकून और सुरक्षा मिली।
जैसे-जैसे मैं अमेरिकी LGBTQ+ आंदोलन में गहराई से उतरता गया, मैंने देखा कि मेरे इस नए समूह के हिंदू धर्म और भारत के प्रति विरोधी विचार थे। वे हिंदू धर्म को दमनकारी और जातिवादी बताते हुए उसे खत्म करने की पुरजोर वकालत करते थे। वे भारत की सभी समस्याओं का कारण 'ब्राह्मणवादी पितृसत्ता' को मानते थे और भारत की किसी भी सकारात्मक नीति और प्रगति को फासीवादी और राष्ट्रवादी प्रचार बताते थे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि सिलिकॉन वैली की तकनीकी कंपनियों को 'ब्राह्मणों से समस्या' है और उनकी सफलता पूरी तरह से जातिगत विशेषाधिकारों के कारण है। मेरे द्वारा प्रस्तुत किसी भी वैकल्पिक विचार को उन्होंने बेरुखी से खारिज कर दिया। ये लोग मुस्लिम संस्कृति का समर्थन करते थे और इस्लाम के LGBTQ+ विरोधी इतिहास और संरचनात्मक दमन पर कभी चर्चा नहीं करना चाहते थे। यह बेईमानी और कट्टरता है।
मैं दो मुश्किल विकल्पों के बीच फंसी हुई महसूस कर रही थी: एक समलैंगिक होने के नाते भावनात्मक और राजनीतिक समर्थन पाने के

लिए, मुझे अमेरिकी LGBTQ + समुदाय की एक निष्ठावान सदस्य के रूप में सेवा करनी होगी। लेकिन साथ ही, मुझे अपनी धार्मिक विरासत को भी नकारना होगा। मैं इस बात से सहमत हूँ कि आधुनिक युग के लिए हानिकारक, दमनकारी और विभाजनकारी सामाजिक मानदंडों को समाप्त किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे वेदांत बहुत तार्किक लगता है, और गीता में इसके अच्छे समाधान मिलते हैं। दुर्भाग्य से, मेरे LGBTQ + मित्रों ने मुझ पर अपनी हिंदू पहचान को पूरी तरह से त्यागने का दबाव डाला। मुझे दमन महसूस हुआ और शर्म और अपने समर्थन तंत्र को खोने के डर से मैंने अपनी हिंदू पहचान को गुप्त रखा।

अंततः, मैंने यह निर्णय लिया कि मेरी वैदिक विरासत कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, भले ही अब मुझे एक हिंदू होने के नाते उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है!

स्पष्टतः, राव के पास बहुमूल्य अनुभव है और उन्होंने इससे सीखे जाने वाले सबकों पर गहन चिंतन किया है। उन्होंने निम्नलिखित विश्लेषण प्रस्तुत किया है जो हमें अत्यंत प्रभावी लगता है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार विशिष्ट लक्षित संस्कृतियों के विरुद्ध सांस्कृतिक युद्ध छेड़ने के लिए पीड़ित होने की भावना का उपयोग किया जा रहा है:

मैंने अपने इस व्यक्तिगत अनुभव से बहुत कुछ सीखा है। LGBTQ + आंदोलन एक झूठी और बनावटी एकता है क्योंकि इसके विभिन्न वर्गों के यौनिकता पर परस्पर विरोधी विचार हैं। एक लेस्बियन होने के नाते, मुझे अपने नारीत्व पर पूरा भरोसा है और मैं सर्जरी द्वारा लिंग परिवर्तन नहीं करवाना चाहती। लेकिन क्वीर आंदोलन नारी की अवधारणा को ही नकारता है, इसे एक सामाजिक संरचना बताता है जिसे खत्म किया जाना चाहिए। यह कृत्रिम रूप से एकजुट आंदोलन एक ही उत्पीड़क को आरोपित करता है। पश्चिम में यह श्वेत पुरुष हैं, और भारत में इसे ब्राह्मणों

से जोड़ दिया गया है। मुझे लगता है कि विभिन्न संस्कृतियों में कई प्रकार के उत्पीड़न और उत्पीड़क मौजूद हैं। मुसलमानों और फिर यूरोपीय लोगों द्वारा उपनिवेशित हमारे हिंदू इतिहास ने ऐसे घाव छोड़े हैं जिन्हें अन्य समूह नहीं समझ पाते।

मैं इस आंदोलन की कठोर आंतरिक पदानुक्रम प्रणाली को अस्वीकार करता हूँ, जिसमें हम सभी से यह अपेक्षा की जाती है कि हम उच्च पुरोहितों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करें, मानो यह कोई धर्म हो। मैं उस 'कैंसल कल्चर' को भी अस्वीकार करता हूँ जो स्वस्थ समाज की दिशा में मार्ग तलाशने के लिए सभी पृष्ठभूमियों के नेक इरादे वाले लोगों के साथ मिलकर काम करने के बजाय विरोधियों को चुप करा देता है। मैं विशेष रूप से मार्क्सवादी सिद्धांतों से परेशान हूँ जो पहचानों के बीच संघर्ष को अनिवार्य बनाते हैं। मुझे अपनी सभ्यता को नष्ट करने की मांग पसंद नहीं है, खासकर तब जब इन नेताओं को यह पता ही नहीं है कि इसकी जगह क्या स्थापित किया जाए या अराजकता को कैसे रोका जाए।

अंत में, मैं पूरी तरह से समझ सकता हूँ कि अपनी पहचान के कारण हाशिए पर धकेल दिए जाने, उपेक्षित किए जाने या बहिष्कृत किए जाने पर कैसा महसूस होता है। यह अनुभव आपको भावनात्मक रूप से आहत करता है और आपको असुरक्षित बना देता है। यह बड़ी दुर्भावनापूर्ण शक्तियों द्वारा शोषण का उपजाऊ मैदान बन जाता है। दलितों के मामले में यही हुआ। इसकी शुरुआत हिंदू समुदाय के बाकी हिस्सों द्वारा हाशिए पर धकेले जाने से हुई, और वे धर्मांतरण के लिए एकदम सही निशाना बन गए। LGBTQ+ समुदाय से संबंधित भारतीयों का इस्तेमाल क्वीर आंदोलन द्वारा हमारी अपनी सभ्यता के अस्तित्व के खिलाफ राजनीतिक ताकत जुटाने के लिए किया जा रहा है।

हिंदू धर्म के भीतर एक ऐसे आंदोलन की आवश्यकता है जो हिंदू धर्म के

पारंपरिक संसाधनों का उपयोग करते हुए LGBTQ+ लोगों को एकीकृत करे, सामान्य बनाए और उनकी रक्षा करे। यह केवल विभिन्न लिंगों और यौनताओं के प्रति निष्क्रिय 'सहिष्णुता' का मामला नहीं है, बल्कि एक समावेशी आंदोलन है जो समाज में स्थायी परिवर्तन लाए ताकि LGBTQ+ समुदाय के लोग सामान्य विषमलैंगिक सदस्यों के साथ एक एकीकृत समुदाय के रूप में सह-अस्तित्व में रह सकें। इसके लिए संरचनाओं, संस्थानों, नेताओं और संसाधनों की आवश्यकता है। अन्यथा, हम हिंदू न केवल क्रिटिकल रेस थ्योरी आंदोलन के कारण अपने लोगों की एक बड़ी संख्या खो देंगे, बल्कि उन्हें अपनी विरासत के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल होते हुए भी पाएंगे।

अध्याय 1 में यह विस्तार से बताया गया है कि किस प्रकार क्रिटिकल रेस थ्योरी आंदोलन उन सभी समूहों के लिए एक छत्र बन गया है, जिनकी किसी संस्कृति के खिलाफ शिकायतें हैं और जिन्हें वे हमला करने के लिए चुनते हैं।

हम इस सिद्धांत को सिरे से खारिज नहीं करते, लेकिन जब इसे भारत पर लागू किया जाता है, तो अध्याय 2 से 5 तक यह स्पष्ट हो जाता है कि इसके प्रमाण कमजोर हैं और तर्क राजनीतिक बयानबाजी से भरे हुए हैं। आलोचकों को नाम लेकर डराने-धमकाने से स्वतंत्र विचार-विमर्श बाधित हुआ है, जिसके बिना कोई उचित विश्लेषण या समाधान नहीं निकल सकता। क्रिटिकल रेस थ्योरी की अनेक खूबियों का लाभ उठाने के लिए, किसी भी अन्य दार्शनिक प्रणाली के अध्ययन और आलोचना की तरह ही, विश्वविद्यालय स्तर पर सूक्ष्म दृष्टिकोण और गंभीर अध्ययन आवश्यक है। समस्या यह है कि भारतीय समाज पर सीआरटी का अनुप्रयोग झूठ और अतिशयोक्तियों के एक ऐसे पुलिंदे में लिपटा हुआ है जिस पर किसी को भी सवाल उठाने की अनुमति नहीं है।

अध्याय 6 में भारत में जाति के इतिहास से संबंधित विकृतियों का बिंदुवार खंडन किया गया है। यह जातिगत बहस पर एक महत्वपूर्ण स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है।

कहानी 3: हार्वर्ड विश्वविद्यालय अत्याचार साहित्य का उत्पादन करता है
इस पुस्तक की महत्वपूर्ण कहानी यह है कि हार्वर्ड इस तरह के नए 'ब्रेकिंग इंडिया' आंदोलन के लिए एक वैश्विक केंद्र बन गया है।
भाग 2 में हार्वर्ड के तीन प्रमुख केंद्रों का विश्लेषण किया गया है, जिनकी स्थापना आनंद महिंद्रा, लक्ष्मी मित्तल और अजय पीरामल ने अपने-अपने पारिवारिक नामों से की है। इन तीनों ने अपने-अपने पारिवारिक कार्यों के लिए करोड़ों डॉलर का दान दिया है। हालांकि हम इन तीनों को विशिष्ट उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन ये भारत के अध्ययन के लिए हार्वर्ड को दान देने वाले धनी भारतीयों की लंबी सूची का मात्र एक उदाहरण मात्र हैं।
हम यहां किए जा रहे कार्य की प्रकृति और भारत पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पर चर्चा करते हैं। उदाहरणों के साथ, हम यह दर्शाते हैं कि हार्वर्ड मूलतः एक ऐसा एजेंडा निर्धारित कर रहा है जिसमें भारत-विरोधी पूर्वाग्रह भी शामिल हैं। हम इसकी तुलना हार्वर्ड में चीन की उपस्थिति से करते हैं: चीन ने चर्चा को नियंत्रित किया है और इसका उपयोग अपने सुनियोजित राष्ट्रवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया है।
भारत की राष्ट्र-राज्य के रूप में वैधता, उसके संविधान और उसकी सत्तारूढ़ पार्टी पर हमले हार्वर्ड के शोध परियोजनाओं और सम्मेलनों के प्रमुख विषयों में से हैं, जिन्हें अक्सर सामाजिक न्याय की आड़ में छिपाया जाता है। उदाहरण के लिए, भारत द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 में संशोधन करने वाले कानून, नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019

(CAA) और नए कृषि अधिनियम 2020 को लागू करना, विभिन्न 'पीड़ित' समूहों को भड़काने और उन्हें सरकार के खिलाफ गठबंधन बनाने के लिए प्रोत्साहित करने का अवसर बन गया। ऐसे एजेंडे कश्मीर, LGBTQ+ अधिकारों, मुस्लिम शिकायतों जैसे विषयों के अंतर्गत आते हैं। स्वाभाविक रूप से, भारतीय सेना द्वारा विद्रोहियों के खिलाफ की गई कार्रवाई एक आसान निशाना बन जाती है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य, वित्त, उद्यमिता, युवा प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और मीडिया प्रशिक्षण जैसे कई तटस्थ या सकारात्मक विषयों का उपयोग क्रिटिकल रेस थ्योरी में फिट होने वाली पीड़ित पहचानों के उत्पीड़न को उजागर करने के लिए किया जा रहा है। यहां तक कि संस्कृत अध्ययन भी मानवाधिकारों के दृष्टिकोण से यह दावा करता है कि इसके ग्रंथ ब्राह्मण वर्चस्व से प्रेरित हैं और उनमें दलितों, महिलाओं और अन्य लोगों के उत्पीड़न का वर्णन है। हम यह दर्शाते हैं कि भारत में चीन अध्ययन के क्षेत्र का भी इसी तरह से भारतीय संस्कृति के विरुद्ध उपयोग किया जा रहा है।

हार्वर्ड एक वैश्विक केंद्र है जो अमेरिका में अश्वेत/श्वेत इतिहास और कानूनों को नए सिरे से प्रस्तुत करके उन्हें भारत में दलितों/ब्राह्मणों पर लागू करने का प्रयास करता है। इस केंद्र से भारत के विरुद्ध पीड़ित समूहों की सूची लगातार बढ़ती जा रही है। प्रत्येक समूह को भारत के विरुद्ध नकारात्मक तथ्य उजागर करने और जहाँ संभव हो, 'हम/वे' और 'उत्पीड़ित/उत्पीड़क' की भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ग्राम्स्की के प्रति-वर्चस्व निर्माण के सिद्धांत से प्रेरणा लेते हुए, हार्वर्ड के कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर हम भाग 2 में चर्चा करेंगे, जो इस प्रकार के शोध के लिए डेटाबेस और अभिलेखागार तैयार करते हैं।

हार्वर्ड द्वारा इस्लाम और हिंदू धर्म के प्रति अपनाए गए रवैये में स्पष्ट रूप

से दोहरा मापदंड दिखाई देता है। इस्लाम को पीड़ित के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जो सहानुभूति का पात्र है, जबकि हिंदू धर्म को उत्पीड़क के रूप में देखा जाता है जिसे नियंत्रित करने या यहाँ तक कि समाप्त करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर लिखा है: 'संयुक्त राज्य अमेरिका में इस्लामोफोबिया व्यापक रूप से फैल गया है' और इसने इस्लामोफोबिया की निगरानी और उससे लड़ने के लिए कार्यक्रम स्थापित किए हैं। हम निश्चित रूप से सभी धार्मिक कट्टरता के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करते हैं। लेकिन यह केवल कुछ धर्मों की रक्षा के लिए चयनात्मक नहीं होना चाहिए।

यदि हार्वर्ड द्वारा इस्लामोफोबिया की निगरानी और सक्रिय रूप से आलोचना की जा रही है, तो यही दृष्टिकोण हिंदूफोबिया के लिए भी अपनाया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से, स्थिति ठीक इसके विपरीत है: कई मामलों में हार्वर्ड को हिंदूफोबिया को बढ़ावा देते हुए पाया गया है। हिंदुओं की एक याचिका में कहा गया है: 'हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के एक शिक्षाविद ने हाल ही में ट्वीट किया है, "हिंदू भारत के बीमार लोग हैं, उनके धार्मिक ग्रंथ ही उनके दिमाग को प्रशिक्षित करते हैं"'। हिंदू छात्र परिषद द्वारा हार्वर्ड को एक अन्य खुला पत्र भेजा गया था जिसमें शिकायत की गई थी कि हार्वर्ड अपने परिसर में खुलेआम हिंदू-विरोधी भावना का गढ़ बन गया है, और कुछ मामलों में तो इसके संकाय सदस्यों का भी आशीर्वाद प्राप्त है।

हार्वर्ड के राजनीतिक समर्थन से, अमेरिकी कांग्रेस ने एक विधेयक पारित किया जिसमें इस्लामोफोबिया को विश्वव्यापी अपराध घोषित किया गया और सरकार को हर जगह इस्लामोफोबिया के मामलों की पैरवी करने के लिए एक विशेष संगठन बनाने और दोषी पाए जाने वाले देशों पर

अमेरिकी प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया। विडंबना यह है कि अन्य धर्मों को ऐसी कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। इसी बीच, पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 'इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस' पर एक प्रस्ताव पेश किया। इसमें कहा गया कि 'दुनिया के कई हिस्सों में नफरत फैलाने वाले भाषण, भेदभाव और हिंसा बढ़ रही है, जिससे इस्लामी दुनिया में गहरा दुख हो रहा है।' हालांकि फ्रांस चाहता था कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव सभी धर्मों के लिए समावेशी हो, न कि केवल इस्लाम के लिए, और भारत के भी ऐसे ही विचार थे, फिर भी कई मुस्लिम देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसे '15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करने' के निर्णय के साथ पारित किया गया।

हार्वर्ड विशेष रूप से ऐसे डेटाबेस और अभिलेखागार बनाने के लिए जुनूनी प्रतीत होता है जो भारत को तोड़ने वाली ताकतों के लिए रणनीतिक महत्व के होने के साथ-साथ भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा भी हैं। भाग 2 में अल्पसंख्यकों, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों, कमजोर वर्ग के स्वास्थ्य और वित्तीय जानकारी, और हर तरह की सामाजिक जानकारी के संग्रह के कई उदाहरण दिए गए हैं जिनका उपयोग असंतोष पैदा करने के लिए किया जा सकता है।

भाग 2 में कैंसिल कल्चर के ऐसे उदाहरण भी दिए गए हैं जहाँ विरोधियों को व्यवस्थित रूप से बहिष्कृत या अवरुद्ध किया गया है। विपरीत दृष्टिकोण रखने वाले लोगों को उत्पीड़क करार दिया जा सकता है और मुखर आवाजों को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा सकता है। इन सब के गंभीर परिणाम तब सामने आते हैं जब हम यह समझते हैं कि हार्वर्ड भारत के सरकारी संगठनों और उद्योग जगत में गहराई से जुड़ा हुआ है, नीति निर्माण कर रहा है, सिविल सेवकों और कॉर्पोरेट नेताओं को

प्रशिक्षण दे रहा है और शासन के मानक विकसित कर रहा है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किसी भी अन्य विदेशी संस्थान की तुलना में, हार्वर्ड ही अपने अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रभाव के नेटवर्क, वित्तपोषण और ब्रांड नाम का उपयोग करके भारत के युवा नेताओं को सभी क्षेत्रों में आकार दे रहा है।

कहानी 4: नए अभिजात वर्ग द्वारा भारत का विखंडन

पहले चर्चा किए गए सभी घटनाक्रम अंततः भारत को प्रभावित करते हैं। भाग 3 इसी पर केंद्रित है। क्रिटिकल रेस थ्योरी (CRT) का वैश्विक प्रभाव अमेरिका से उत्पन्न हो रहा है, और कई देशों ने इस पर अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया दी है। फ्रांस, जापान, इज़राइल और सिंगापुर अमेरिका के सहयोगी देशों के उदाहरण हैं जिन्होंने CRT से उत्पन्न होने वाले खतरों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। रूस और चीन ने भी इसका कड़ा विरोध किया है, लेकिन यह तो अपेक्षित ही था।

हमारी चिंता यह है कि भारत को अन्य किसी भी प्रमुख देश की तुलना में अधिक तबाही का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसका खंडित समाज क्रिटिकल रेस थ्योरी (CRT) द्वारा समर्थित व्यवधानों के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त है। साथ ही, भारत में बौद्धिक कार्यकर्ताओं का एक मौजूदा तंत्र है जो हार्वर्ड जैसे संस्थानों में CRT के विकास में भाग ले रहा है और साथ ही भारत में कार्यकर्ताओं की एक सेना को प्रशिक्षित करने में मदद कर रहा है। उच्च पदों पर बैठे कई भारतीय अज्ञानता या व्यक्तिगत लाभ के कारण अमेरिका के ऐसे हस्तक्षेपों का स्वागत करते हैं।

पाठकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका स्थित ईरानी अरबपति पियरे मोराद ओमिडयार के स्वामित्व वाले ओमिडयार नेटवर्क ने भारत

भर में निवेश का एक विस्तृत जाल बिछा रखा है, जो हमारे विचार से भारत की संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा है। इसका प्रमाण इसके वैचारिक झुकाव से मिलता है, जो कि सीआरटी-आधारित परियोजनाओं की ओर है। इसके परिष्कृत जनसंपर्क तंत्र ने भारत के उच्च स्तरीय अधिकारियों को यह विश्वास दिला दिया है कि यह परोपकार और विकास कार्यों में लगा हुआ है। यह सच है, लेकिन पूरी सच्चाई कहीं अधिक जटिल है और इसे छिपाकर रखा गया है। ओमिडयार नेटवर्क इंडिया पर एक पूरा अध्याय समर्पित है।

भाग 3 में भारत के कई अन्य संगठनों पर भी चर्चा की गई है जिनकी सामग्री विवादास्पद है। नई दिल्ली के पास स्थित अशोका विश्वविद्यालय एक प्रमुख संस्थान है, जिसे प्रभावशाली भारतीयों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, जो अमेरिकी शैली की उदार कलाओं को लागू करके भारत की मदद करने का दावा करते हैं। इस पर एक पूरा अध्याय समर्पित किया गया है। हम क्रिया विश्वविद्यालय पर भी चर्चा करते हैं, जो इस तरह की गतिविधियों का एक और भारत-आधारित केंद्र है। इसके अलावा, अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब (जे-पाल) (मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी [एमआईटी] में सऊदी अरब द्वारा वित्त पोषित एक पहल जो मानवाधिकारों के मुद्दे पर भारत को लक्षित करती है) सहित कई अन्य संगठनों द्वारा वित्त पोषित गतिविधियाँ भी हैं।

एक दशक पहले लिखी गई पुस्तक 'ब्रेकिंग इंडिया' में उस समय प्रचलित ऐसी ही ताकतों का जिक्र है। लेकिन तब से हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। अब भारत की संप्रभुता को खत्म करने के लिए बिल्कुल नए खिलाड़ी, अलग-अलग तकनीकें और तरीके अपना रहे हैं।

नए खतरे, जिन्हें हम भारत को तबाह करने वाली ताकतें 2.0 कहते हैं, क्रिटिकल रेस थ्योरी पर आधारित हैं, जो पुरानी वामपंथी विचारधाराओं से

बिल्कुल अलग है। अब ध्यान गरीब, अशिक्षित ग्रामीणों को धर्म परिवर्तन कराने पर नहीं, बल्कि शहरी अभिजात वर्ग पर केंद्रित है। लक्ष्य अब भारतीय समाज में हार्वर्ड और अन्य संस्थानों द्वारा अपने वैश्विक प्रभाव नेटवर्क के तहत प्रशिक्षित नेताओं की एक नई पीढ़ी तैयार करना है। हार्वर्ड का नाम और उसके परिष्कृत तरीके, इस क्षेत्र में पैठ बनाने के लिए काफी शक्तिशाली हैं।

निम्नलिखित तालिका इस पुस्तक में वर्णित बलों और पहले बताए गए बलों के बीच अंतर की तुलना करती है।

Caste→Cause of all Racism (*Isabel Wilkerson*)	➡	**Caste Enters US Pop Culture and Mainstream Discourse**
Caste Surveys in American Workplaces (*Equality Labs*)	➡	**Caste Surveys Used to Prove Brahmin Racism in US Workplaces**
Indian Tech Meritocracy Masks Brahmin Privilege (*Ajantha Subramanian*)	➡	**Silicon Valley Indians Bring Casteism to America**
Critical Race Theory→Afro-Dalit Solidarity (*Suraj Yengde*)	➡	**Harvard Campaign to Dismantle Hinduism**

वित्तपोषण के उद्देश्य

इतिहास में, कई अरबपतियों ने मानवता के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और हम इन सराहनीय प्रयासों को मान्यता देना चाहते हैं। हालांकि, कभी-कभी परोपकार के अनपेक्षित परिणाम भी होते हैं। ऐसे परियोजनाओं के वित्तपोषकों के लिए, यह पुस्तक एक सहायक मार्गदर्शिका है जो उनके परोपकार के परिणामों का आलोचनात्मक विश्लेषण करती है। लेखक केवल भारतीय राष्ट्र की स्थिति का गहन

विश्लेषण करते हैं और उन मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं जिन पर शायद ध्यान नहीं दिया गया हो। हमारा मानना है कि इस पुस्तक में उल्लिखित पक्षों ने इन परियोजनाओं को बिना किसी दुर्भावना के शुरू किया था, हालांकि ऐसे प्रयासों के परिणामस्वरूप कुछ अप्रत्यक्ष नुकसान हो सकते हैं जो जोखिम पैदा करते हैं। हम यह भी आशा करते हैं कि इस पुस्तक को सही भावना से पढ़ा जाएगा ताकि भविष्य में परोपकारी निवेशों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

किसी भी निष्पक्ष जांच-पड़ताल की तरह, यह सवाल उठता है कि ये अरबपति हार्वर्ड जैसी जगहों पर ऐसी गतिविधियों को क्यों वित्त पोषित कर रहे हैं। हम कई संभावित कारणों का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि किसी विशेष मामले में कौन सा कारण लागू होता है।

वास्तव में अति-वामपंथी विचारधारा से जुड़ा हुआ है।

इसका एक वैचारिक कारण यह हो सकता है कि हाल के समय में अचानक इतनी संपत्ति अर्जित करने वाले अरबपति या उनके वंशज, जो इसे खर्च कर रहे हैं, वास्तव में आलोचनात्मक जाति सिद्धांत की पूरी अवधारणा से वैचारिक रूप से पूरी तरह सहमत हैं। ऐसे में वे वैचारिक रूप से अति-वामपंथी हैं।

पूरी तस्वीर से अनभिज्ञ

दूसरा संभावित वैचारिक कारण यह हो सकता है कि वे अति-वामपंथियों के इस आलोचनात्मक जाति सिद्धांत को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, लेकिन दलितों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। वे वास्तव में दलितों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने सामाजिक विज्ञान में उनके धन और पारिवारिक नाम का इस्तेमाल करके चल रही गतिविधियों की बारीकियों की जांच नहीं की है। वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि इनमें से कुछ

गतिविधियाँ कितनी खतरनाक हैं। मानवता की मदद करने का उनका भोला-भाला विचार तो है, लेकिन उन्हें पूरी पृष्ठभूमि का ज्ञान नहीं है। और उन्होंने इसमें शामिल सभी पक्षों की ठीक से जांच-पड़ताल भी नहीं की है: अति-वामपंथी विद्वानों के लेख, उनके संगठन और विचारधाराएँ, और भारत को तोड़ने वाली ताकतों के साथ उनके गहरे संबंध।

दूसरे शब्दों में कहें तो, इस श्रेणी में वे लोग शामिल हैं जो जानबूझकर भारत को तोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वे पहली श्रेणी के लोगों की तरह अति-वामपंथी नहीं हैं, बल्कि सोचते हैं कि वे अच्छा काम कर रहे हैं और अनजाने में ही भारत को तोड़ने वाली ताकतों के साथ जुड़ गए हैं।

स्वार्थी

तीसरी संभावना यह है कि धनी लोग हार्वर्ड से मिलने वाली प्रसिद्धि की तलाश में हैं। वे उच्च वर्ग के लोगों के साथ बैठना चाहते हैं, जो समाज के संभ्रांत और प्रतिष्ठित लोगों के बीच अपनी जगह बनाना चाहते हैं। वे दुनिया के अमीर और प्रभावशाली लोगों के बराबर होना चाहते हैं। इसलिए, मूल रूप से इसका उद्देश्य अपनी व्यक्तिगत छवि बनाना और अपनी शान दिखाना है। ग्लैमर के अलावा, वे अपने रिश्तेदारों को हार्वर्ड में छात्र के रूप में या विभिन्न समितियों, बोर्डों और संगठनों में शामिल करवाकर ठोस लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिष्ठित पूर्व छात्र संघ में शामिल होना अपने आप में एक विशेषाधिकार प्राप्त सदस्यता मानी जाती है।

वामपंथ को प्रभावित करना

चौथा कारण यह हो सकता है कि दानदाता अप्रत्यक्ष रूप से अति-वामपंथियों को प्रभावित कर रहा है और बदले में पूंजीवाद और नस्लवाद के खिलाफ लड़ने वाले कार्यकर्ताओं से बख्शा जा रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो, यह परिकल्पना यह दर्शाती है कि कुछ दानदाता अपनी स्वयं की

कमजोरियों से ध्यान हटाने का प्रयास कर रहे हैं।
अति-वामपंथियों ने प्रतिष्ठित शैक्षणिक केंद्रों में सामाजिक विज्ञान पर कब्ज़ा कर लिया है और दलितों, मुसलमानों और हार्वर्ड द्वारा 'संरक्षित समूह' माने जाने वाले अन्य लोगों के लिए गहरे संरचनात्मक बदलावों की मांग के लिए इसका दुरुपयोग किया है। उनके अभियान इन कंपनियों के बोर्ड में बदलाव करके दलितों और LGBTQ+ समुदाय के लोगों को नियुक्त करना चाहते हैं। वे वरिष्ठ प्रबंधन में एक निश्चित प्रतिनिधित्व चाहते हैं और सामाजिक न्याय के आधार पर कुछ प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों को समाप्त करना चाहते हैं। उन्होंने अमेरिका में सिस्को सिस्टम्स जैसी बड़ी कंपनियों के खिलाफ मुकदमेबाजी शुरू कर दी है। पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) आंदोलन भी है जो रेटिंग प्रदान करता है, जिसमें कंपनियों और उनके शीर्ष अधिकारियों के 'सामाजिक आचरण' का मूल्यांकन किया जाता है। इसलिए, हार्वर्ड में शक्तिशाली वामपंथियों को वित्त पोषण करना संरक्षण के बदले रिश्वत देने जैसा हो सकता है। भारतीय अरबपति व्यावसायिक निवेश करते समय विस्तृत जांच-पड़ताल और बातचीत के लिए जाने जाते हैं और हम विनम्रतापूर्वक भारत अध्ययन में निवेश करते समय भी ऐसा ही करने की सलाह देते हैं।

चाबी छीनना
पुस्तक में प्रस्तुत कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:
नया मार्क्सवाद:
अश्वेत अमेरिकियों और दलितों को एकजुट किया गया है और श्वेत अमेरिकियों के खिलाफ युद्ध का दायरा बढ़ाकर ब्राह्मणों को भी निशाना बनाया गया है। अब जाति को अश्वेत अमेरिकियों और दुनिया भर के अन्य

पीड़ित समूहों के खिलाफ नस्लवाद की जड़ माना जाता है। उच्च जाति के भारतीय, भारत के श्वेत माने जाते हैं।

इस नए आंदोलन का अंतिम लक्ष्य वर्तमान विश्व व्यवस्था और उसे समर्थन देने वाली संस्थाओं को ध्वस्त करना है। लेकिन उनके पास एक नई व्यवहार्य विश्व व्यवस्था की दिशा में कोई स्पष्ट मार्ग नहीं है, न ही इस तरह के खतरनाक परिवर्तन को संभालने का आवश्यक अनुभव है।

हमारी चिंता यह है कि क्रिटिकल रेस थ्योरी का इस्तेमाल समाज को ध्वस्त करने के लिए एक हथियार के रूप में किए जाने के बाद, नई सामाजिक व्यवस्था का पुनर्निर्माण उन लोगों द्वारा किया जाएगा जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी नई तकनीकों को नियंत्रित करते हैं।

हमारी पिछली पुस्तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर: 5 बैटलग्राउंड्स, बताती है कि कैसे एआई को अभिजात वर्ग की एक नई नस्ल द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। इसका मार्ग शक्ति और धन के अत्यधिक केंद्रीकरण की ओर अग्रसर है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की याद दिलाता है।

हार्वर्ड विश्वविद्यालय की केंद्रीय भूमिका:

हमारे शोध से पता चलता है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय इस विचारधारा को विकसित करने और इसे सक्रियता के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के साथ-साथ इस नई युद्ध शैली में हजारों लड़ाकों को प्रशिक्षित करने का केंद्र है। हार्वर्ड ने शाखाओं के विशाल नेटवर्क के साथ अपना स्वयं का संघ (समुदाय) विकसित किया है।

भारतीय अरबपति हार्वर्ड में चल रहे 'ब्रेकिंग इंडिया' नामक इस कार्य को सक्रिय रूप से वित्त पोषित करके और इसे जानबूझकर या अनजाने में वैधता प्रदान करके इसका समर्थन कर रहे हैं।

इसका एक संभावित कारण यह है कि इस तरह की फंडिंग से ईएसजी

नामक नई प्रणाली में दानदाताओं की रेटिंग बेहतर होती है, जो अंतरराष्ट्रीय निवेश और वाणिज्यिक अनुबंधों तक उनकी पहुंच निर्धारित करती है। हार्वर्ड को फंडिंग करने से उन्हें प्रतिष्ठित बोर्डों और समितियों में स्थान भी मिलता है। परोपकार की श्रेणी में आने वाला यह उनके द्वारा किए जा सकने वाले सबसे लाभदायक निवेशों में से एक है।

भारतीयों की इस आत्मप्रशंसा वाली धारणा के विपरीत कि भारत विश्व गुरु है, वास्तविकता में हार्वर्ड ही विश्व गुरु है। और भारत विश्व शिष्य है, जिसके अनेक लोग इस व्यवस्था में विश्व कुली और विश्व सिपाही के रूप में सेवा कर रहे हैं।

अन्य देशों से प्रतिक्रिया:

कई अमेरिकी क्रिटिकल रेस थ्योरी और उसके लोकप्रिय सांस्कृतिक रूप, वोकिज़्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि यह समस्या भारत को भी प्रभावित करती है, और कहीं अधिक भयावह तरीके से।

चीन, फ्रांस, जापान, इजराइल, सिंगापुर आदि सहित कुछ देशों ने इस आंदोलन के खिलाफ अभियान शुरू किए हैं।

चीन दोहरी भूमिका निभा रहा है: अपने देश में इस विचारधारा का विरोध करना, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका और भारत जैसे अपने दुश्मनों तक इसे पहुंचाने वालों की मदद करना।

वैदिक प्रणाली पर प्रभाव:

क्रिटिकल रेस थ्योरी का इस्तेमाल वैदिक कथाओं को ध्वस्त करने के लिए किया जा रहा है। इसके पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि भारत में आज मौजूद सभी सामाजिक समस्याएं, जिनमें जाति, लिंग, यौनिकता, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय शामिल हैं, वैदिक संरचनाओं का परिणाम हैं। इसलिए, यह मांग उठ रही है कि हमें वैदिक संरचनाओं को

जीवित नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपने सामने मौजूद सामाजिक संकटों का समाधान करने में विफल रहेंगे। यह सामाजिक न्याय के पैरोकारों से भारतीय सभ्यता की नींव को पूरी तरह से ध्वस्त करने का आह्वान करता है।

हमारा मानना है कि समस्या की जड़ होने के बजाय, वैदिक प्रणाली मानवता के अस्तित्व के लिए आवश्यक अनेक समाधानों की कुंजी है। विडंबना यह है कि हार्वर्ड वैदिक प्रणाली के खजानों – जैसे भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इतिहास, योग, ध्यान, शाकाहार, तत्वमीमांसा और प्रकृति के साथ सामंजस्य – को आत्मसात करने और इन आत्मसात किए गए संस्करणों को अपनी और पश्चिमी देशों की बौद्धिक संपदा के रूप में प्रस्तुत करने में व्यस्त है। हमने ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए भारतीय अरबपतियों से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने समर्थन नहीं दिया। अध्याय 7 में हार्वर्ड द्वारा किए गए कई विशिष्ट आत्मसात्करणों के उदाहरणों पर चर्चा की गई है, जिन्हें हमने पिछले पच्चीस वर्षों में उनके ध्यान में लाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ।

भारत का आत्म-विनाश:

भारत के सत्ताधारी अभिजात वर्ग और तथाकथित 'बुद्धिजीवी' इस सब से काफी हद तक अनभिज्ञ और अचंभित हैं। इसलिए, उनकी ऊर्जा का गलत दिशा में उपयोग हो रहा है, वह बिखरी हुई है और अक्सर प्रतिकूल परिणाम दे रही है।

भारतीय सरकार भी जानबूझकर या अनजाने में मार्क्सवादी क्रांति के इस नवीनतम रूप के प्रति प्रतिबद्ध हो रही है।

वैश्विक वामपंथ में उच्च से निम्नतम स्तर तक बड़ी संख्या में भारतीय कार्यरत हैं। वे मार्क्सवादी क्रांति के इस नवीनतम स्वरूप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वैश्विक वामपंथ राष्ट्रीय सीमाओं से परे सक्रिय है।

‘वोके’ शब्द, अधिक अकादमिक शब्द ‘क्रिटिकल रेस थ्योरी’ का लोकप्रिय पर्याय है। वोके की शुरुआत अश्वेत अमेरिकी समुदाय में जागरूकता फैलाने के साधन के रूप में हुई और इसका अर्थ था सामाजिक वास्तविकताओं के प्रति जागरूक होना। हमारा मानना है कि वोकेवाद लोगों को सकारात्मक रूप से जागरूक करने में सफल रहा है, लेकिन इसकी आगे की सफलता के लिए इसे खुले विचारों वाला बनना होगा, जिसका अर्थ है वाद-विवादों का स्वागत करना।

कुछ उकसावे वाली बातें:

स्वतंत्र विचारक होने के नाते, हम प्रतिशोध या धमकियों के भय के बिना नए विचारों पर मंथन करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, क्या हम इस बात पर विचार कर सकते हैं कि पदानुक्रम न केवल सभी मानव समाजों में, बल्कि जानवरों की सभी प्रजातियों में भी मौजूद है? और जिस प्रकार किसी पशु प्रजाति के सदस्यों में विभिन्न गुणों में व्यक्तिगत भिन्नताएँ, शक्तियाँ और कमजोरियाँ होती हैं, वैसे ही मनुष्यों में भी होती हैं। किसी भी प्रकार की सामाजिक संरचना से भिन्नताओं या पदानुक्रमों को मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए, हमें समान परिणामों तक सीमित हुए बिना न्याय दिलाने के तरीकों का पता लगाना चाहिए।

उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति सर्जन बनने में अधिक सक्षम है जबकि दूसरा माली के रूप में श्रेष्ठ है, तो क्या इन भिन्नताओं के बावजूद उन्हें समान सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान करने का कोई तरीका हो सकता है? यदि परिणाम को सुख के संदर्भ में मापा जाए, तो क्या उन्हें अपने-अपने व्यवसायों में समान सुख प्राप्त हो सकता है? क्या वेदों और बौद्ध धर्म जैसी भारतीय प्रणालियों में पाई जाने वाली तकनीकों का उपयोग करके मानव चेतना को उन्नत करने के लिए एक वैश्विक कार्यक्रम विकसित करना बेहतर विचार होगा?

क्या पुरानी संरचनाओं को ध्वस्त करने से पश्चिमी सार्वभौमिकता के उस दृष्टिकोण को भी चुनौती मिलनी चाहिए जिसमें उपभोक्तावाद को सफलता का मानदंड माना जाता है, और क्या यह प्रतिस्पर्धी लालच और असमान भौतिक परिणामों से उत्पन्न निराशा का मूल कारण है? क्या विरासत कानून अंतर-पीढ़ीगत धन के संकेंद्रण का कारण बन रहे हैं? एक प्रमुख बहस जिसकी आवश्यकता है, वह है हेगेल से शुरू हुई, कार्ल मार्क्स के साथ जारी रही और हाल ही में क्रिटिकल रेस थ्योरी में इसके उपयोग तक पहुँची संपूर्ण द्वंद्वात्मक पद्धति को चुनौती देना। यह संरचना वामपंथी चिंतन की आधारशिला है। एक गंभीर समस्या यह है कि यह प्रचलित सिद्धांत को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांति का आह्वान करती है। लेकिन अन्य सभ्यताओं के वैकल्पिक दृष्टिकोणों का पता लगाने के बारे में क्या? उदाहरण के लिए, यदि हम सिद्धांत और प्रति-सिद्धांत को विपरीत दो बिंदुओं के रूप में देखें, तो वेदांत की शिक्षा दोनों को पार करने और समाहित करने की है। मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक पद्धति के परिणामस्वरूप दो विरोधी अहमों के बीच आपसी विनाश के लिए संघर्ष होता है ताकि एक नया अहम उभर सके, जो उम्मीद है कि बेहतर होगा। लेकिन यह प्रक्रिया मानवता को अहम के स्तर तक सीमित रखती है। इस प्रणाली में उच्च स्तर तक कोई पारगमन नहीं है, जबकि वेदांत और बौद्ध धर्म हमारी चेतना को ऊपर उठाने के लिए व्यावहारिक और सिद्ध तकनीकें प्रदान करते हैं। विडंबना यह है कि पश्चिम में वामपंथियों का एक बड़ा हिस्सा भारत से आयातित कई आध्यात्मिक प्रथाओं, जैसे कि ध्यान, का अभ्यास करता है।

उनकी पद्धतियाँ व्यवस्थित विधियों के माध्यम से चेतना को उन्नत करने के सिद्धांत पर आधारित हैं। पिछले पचास वर्षों में पश्चिम में भारतीय ध्यान प्रणालियों के प्रसार के परिणामस्वरूप, एक व्यापक आंदोलन उभरा

है जो स्वयं को चेतना आंदोलन कहता है। तरह-तरह की पुस्तकें, वीडियो, सेमिनार आदि लोकप्रिय हो रहे हैं जो वेदांत और/या बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण को कुछ हद तक सिखाते हैं: कि केवल चेतना को उन्नत करके ही समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, न कि अहंकार के स्तर पर संघर्ष करके।

गंगा में सांप, कुछ विदेशी संस्थानों के लिए एक रूपक है जो भारत में 'वोकेवाद' के विचारों को थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे भारत की प्राचीन सभ्यतागत संरचना कमजोर हो रही है। यह पुस्तक उन भारतीयों को सूचित करने का इरादा रखती है जो अनजाने में ही ऐसे कार्यों का समर्थन कर रहे हैं, बिना इन परियोजनाओं के अंतिम लक्ष्य को गहराई से समझे। यह पुस्तक लेखकों के उन विदेशी संस्थानों के साथ वर्षों के संवाद का परिणाम है जिन्होंने अक्सर विरोधी विचारों पर बहस को दबाने का प्रयास किया है। पुस्तक का उद्देश्य ऐसे संस्थानों के प्रायोजकों की निंदा करना नहीं है। यह विशुद्ध रूप से बौद्धिक मुद्दों पर स्वस्थ अकादमिक बहस को आमंत्रित करने का एक ईमानदार प्रयास है। यह विद्वानों के कार्यों की आलोचना है, न कि उनके व्यक्तित्व या उन संस्थानों के मालिकों/प्रायोजकों की जहां वे काम करते हैं।

हमें उम्मीद है कि यह पुस्तक इस तरह की बातचीत के द्वार खोलेगी और हम सभी दृष्टिकोणों के गंभीर विचारकों को हमारे विचारों से असहमत होने और आपसी सम्मान के साथ हमसे बहस करने के लिए आमंत्रित करते हैं।

भाग 1. संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय संस्कृति की वैधता पर बहस

1. संयुक्त राज्य अमेरिका का विघटन

अवलोकन

यह अध्याय हार्वर्ड विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों से भारत में आ रही हालिया सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और राजनीतिक उथल-पुथल की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है। इन अवधारणाओं की नींव मार्क्सवाद और उत्तरआधुनिकतावाद पर टिकी है। ये दोनों प्रणालियाँ मुख्यतः यूरोप में उत्पन्न हुईं और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित हुईं, जहाँ इनका उपयोग नवीनतम सामाजिक विज्ञान आंदोलनों को विकसित करने में किया गया है। हालाँकि, मुख्यधारा के अधिकांश लोग वर्तमान लोकप्रिय सामाजिक आंदोलनों में मार्क्सवाद और उत्तरआधुनिकतावाद की उपस्थिति को स्वीकार नहीं करते हैं।

इन दो पूर्व सैद्धांतिक प्रभावों की व्याख्या करना जटिल है क्योंकि समय के साथ दोनों में कई परिवर्तन हुए हैं। यह एक विशाल विषय है, और हम केवल कुछ ही क्षेत्रों का वर्णन कर सकते हैं जो वर्तमान में चर्चित स्थिति के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। हमारा विवरण पूर्ण होने का दावा नहीं करता है और यह केवल इन दोनों प्रणालियों के कुछ विकासों और विशेषताओं को उजागर करता है।

यूरोप की पृष्ठभूमि स्थापित करने के बाद, हम हाल के दशकों की ओर बढ़ते हैं, जिनमें क्रिटिकल रेस थ्योरी (CRT) वर्तमान समय में सबसे प्रभावशाली सिद्धांत के रूप में उभरी। शुरुआत में इसे क्रिटिकल लीगल थ्योरी के रूप में विकसित किया गया था ताकि अमेरिकी कानूनी प्रणाली में व्याप्त नस्लवाद को संबोधित किया जा सके, बाद में इसका विस्तार सभी सामाजिक संस्थानों में व्याप्त नस्लवाद को शामिल करने के लिए किया गया। इसके साथ ही, CRT की कुछ महत्वपूर्ण सैद्धांतिक शाखाओं, जैसे कि इंटरसेक्शनैलिटी और क्वीर थ्योरी, पर भी चर्चा की

जाएगी। ये महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन्होंने अमेरिकी समाज के हर क्षेत्र में CRT के प्रभाव को तेजी से फैलाने में मदद की है।
वोकवाद, क्रिटिकल रेस थ्योरी का लोकप्रिय और मुख्यधारा का सांस्कृतिक रूप है। तर्कसंगतता और विज्ञान की इसकी स्पष्ट अस्वीकृति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन, इसके प्रमुख नेताओं के उद्धरणों के माध्यम से समझाया जाएगा। हम चर्चा करेंगे कि कैसे ये सभी प्रभाव अमेरिकी संस्थानों जैसे सरकार, निजी उद्योग, मीडिया और निश्चित रूप से अकादमिक जगत में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी।
यह अध्याय जीवन विज्ञान क्षेत्र के युवा तकनीकी उद्यमी और रोइवेंट साइंसेज के अध्यक्ष विवेक रामास्वामी के मौलिक विचारों के साथ समाप्त होता है, जो इस प्रश्न का उत्तर देते हैं: कॉर्पोरेट जगत वोकिज़्म को क्यों प्रोत्साहित कर रहा है? कॉर्पोरेट जगत के साथ वोकिज़्म के संबंध पर उनका उत्तेजक शोध प्रबंध सम्मोहक और चौंकाने वाला है।
इस अध्याय में चर्चा की गई नई विचारधारा पिछले दो शताब्दियों में निम्न प्रकार से विकसित हुई है: मार्क्सवाद और उत्तरआधुनिकतावाद (आधार के रूप में) → आलोचनात्मक नस्ल सिद्धांत और उसके सहायक सिद्धांत (नवीनतम उत्पाद) → लोकप्रिय जागरूकतावाद (सामूहिक उपभोग के लिए पैकेजिंग) → सभी संस्थाओं का विघटन (जन आंदोलन)।
यह अध्याय भारत पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करने के लिए आधार तैयार करता है।

पुराने वामपंथ की यूरोपीय उत्पत्ति

मार्क्सवाद

मार्क्सवाद समाज, अर्थशास्त्र और राजनीति के उन सिद्धांतों में से एक है

जिसने पिछली दो शताब्दियों में व्यापक प्रभाव डाला है। इस पर आधारित सामाजिक विज्ञान हाल ही में विकसित होकर आलोचनात्मक नस्ल सिद्धांत (क्रिटिकल रेस थ्योरी) तक पहुँच गए हैं। लेकिन मार्क्सवाद का उदय अचानक नहीं हुआ; इसकी प्रमुख अवधारणाओं की जड़ें इससे भी पहले महान जर्मन विचारक/दार्शनिक जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल तक जाती हैं।

हेगेल को अठारहवीं शताब्दी के अंत और उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में आधुनिक पश्चिमी चिंतन के अग्रदूतों में से एक माना जाता है। उनके महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक इतिहास का दर्शन था। हेगेल का दावा था कि इतिहास एक कारण-कार्य प्रणाली द्वारा संचालित होता है; यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में घटित होने वाली यादृच्छिक और असंबंधित घटनाओं का समूह नहीं है जिनका कोई सामान्य मार्ग, उद्देश्य या दिशा नहीं है। बल्कि, सारा इतिहास कुछ निश्चित प्रतिरूपों का अनुसरण करता है, और उनका दावा था कि उन्होंने इन प्रतिरूपों या नियमों की खोज उसी प्रकार की है जैसे प्राकृतिक वैज्ञानिक प्रकृति के नियमों की खोज करते हैं। हेगेल के इतिहास के मॉडल में, एक अदृश्य शक्ति मानवीय घटनाओं को आगे बढ़ाती है, यही कारण है कि इतिहास में कुछ निश्चित पैटर्न होते हैं और मानवता को एक निश्चित पड़ाव के साथ यात्रा करते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने इस शक्ति को 'वेल्टगेइस्ट' कहा, जिसका अनुवाद अक्सर 'विश्व आत्मा' के रूप में किया जाता है। वेल्टगेइस्ट मोटे तौर पर वैदिक परंपरा में सगुण ब्रह्म या भगवान की अवधारणा के समान है - एक ऐसी शक्ति जो इतिहास को संचालित करती है, या ऋतम् या लय की अवधारणा के समान है जो वास्तविकता के ताने-बाने का मूलभूत आधार है। वैष्णव विचारधारा के अनुसार, एक सर्वोच्च सत्ता इतिहास को एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ाती है। बेशक, यह केवल विचार को समझाने के

लिए एक सादृश्य है और दोनों विचारों में महत्वपूर्ण अंतर हैं।
इस अवधारणा से संबंधित एक और हेगेलियन शब्द है, 'वोल्क्सजिस्ट', जो किसी राष्ट्र की भावना, अर्थात् किसी राष्ट्र की आत्मा या राष्ट्रीय चरित्र को संदर्भित करता है। 'वोल्क्सजिस्ट' उस भावना से मिलती-जुलती है जिसे दीनदयाल उपाध्याय, भारतीय जनसंघ (भारतीय जनता पार्टी [भाजपा] के पूर्ववर्ती दल) के नेता, ने किसी राष्ट्र का 'चित्त' कहा था, यानी वह सार या आधार जो उसके महान आख्यान को संचालित करता है।
तीसरा शब्द, ज़ाइटगाइस्ट, युग की भावना या समय की भावना को संदर्भित करता है; एक अदृश्य शक्ति जो विश्व इतिहास में किसी विशेष युग की विशेषता बताती है। वैदिक संदर्भ में, हम कलियुग नामक एक विशेष युग में जी रहे हैं जो जीवन और समाज की प्रकृति को परिभाषित करता है।
विश्व की भावना एक निश्चित क्रम में विकासवादी चरणों से गुजरती है, जिनसे सभी राष्ट्रों को गुजरना पड़ता है, लेकिन कुछ राष्ट्र दूसरों से आगे होते हैं। हेगेल का एक महत्वपूर्ण दावा यह था कि इन विकासवादी चरणों में पश्चिम अन्य सभी सभ्यताओं से आगे है। इसका तात्पर्य यह है कि पश्चिम आज जिस स्थिति में है, विश्व भावना के प्राकृतिक नियम के अनुसार अन्य राष्ट्रों को भविष्य में उसी तरह बनने का प्रयास करना चाहिए। और जिस तरह अन्य राष्ट्र आज हैं, पश्चिम अतीत में वैसा ही था। हेगेल को अक्सर आधुनिक पश्चिम की अवधारणा का जनक माना जाता है।
इतिहास के इस रेखीय सिद्धांत का प्रयोग हेगेल ने मूल अमेरिकी लोगों के विरुद्ध अत्याचारों को उचित ठहराने के लिए किया, क्योंकि उन्हें असभ्य माना जाता था। उन्होंने अश्वेतों की दासता को भी उचित ठहराया, क्योंकि

उनका मानना था कि वे ऐतिहासिक विकास के इस क्रम में स्वतंत्र रूप से जीने के योग्य नहीं थे। उनके अनुसार, भारत का ब्रिटिश उपनिवेशीकरण वैध था, क्योंकि ब्रिटिश भारत को उसके अपने हित में सभ्य बना रहे थे, ठीक उसी प्रकार जैसे वयस्क बच्चों को अनुशासन सिखाते हैं। दूसरे शब्दों में, उन्होंने विश्व इतिहास के अपने हिस्से के रूप में सभी सभ्यताओं के लिए निर्धारित मानक रेखीय पथ को परिभाषित किया। यही उनका इतिहास दर्शन था।

हेगेल का एक और महत्वपूर्ण विचार जो अत्यंत प्रभावशाली हुआ, वह है 'द्वंद्ववाद'। इसके द्वारा उनका तात्पर्य यह था कि समाज का प्रचलित प्रतिमान, जिसे वे थीसिस कहते थे, एक विरोधी शक्ति को जन्म देता है, जिसे वे एंटी-थीसिस कहते थे। एंटी-थीसिस थीसिस का विरोध करने वाली एक प्रतिक्रिया है। चूंकि इन्हें किसी अन्य तरीके से सुलझाया नहीं जा सकता, इसलिए थीसिस और एंटी-थीसिस का आपस में टकराना अनिवार्य है। यह टकराव अंततः एक संश्लेषण को जन्म देता है, और एक नया प्रतिमान उभरता है; यही नया थीसिस बन जाता है। और इसी प्रकार विश्व भावना का विकास होता है। किसी भी युग या समय में, एक राष्ट्र का एक थीसिस होता है जो उसके समाज के संगठन को परिभाषित करता है। फिर एक एंटी-थीसिस उभरता है जो इसका विरोध करता है। थीसिस और एंटी-थीसिस के बीच टकराव एक संश्लेषण को जन्म देता है जहां एक नया सत्य पाया जाता है, जो पिछले थीसिस और एंटी-थीसिस से कहीं अधिक उच्चतर होता है। विश्व इतिहास इसी प्रकार आगे बढ़ता है। यहां ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रगति के लिए संघर्ष वांछनीय है।

मार्क्स ने अपने सिद्धांत की नींव के रूप में हेगेल के द्वंद्ववाद को अपनाया। लेकिन उन्होंने इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव किया: हेगेल के सिद्धांत में

भौतिक परिवर्तनों को संचालित करने वाली आत्मा के बजाय, मार्क्सवाद में जमीनी भौतिक परिस्थितियाँ ही प्रतिवाद को जन्म देती हैं और सिद्धांत से टकराती हैं। अतः, मार्क्सवाद विशुद्ध रूप से भौतिकवादी कारकों द्वारा ऐतिहासिक कार्य-कारण का सिद्धांत है। यह कार्य-कारण का एक आर्थिक सिद्धांत है, न कि आध्यात्मिक सिद्धांत। यह कहा जा सकता है कि मार्क्स ने इतिहास को संचालित करने वाले कार्य-कारण के रूप में विश्व आत्मा के विचार को हटाकर हेगेल के द्वंद्ववाद को धर्मनिरपेक्ष बना दिया।
मार्क्स के अनुसार, पश्चिम अपने विकास के ऐसे चरण में पहुँच चुका है जहाँ पूंजीपति (बुर्जुआ वर्ग) औद्योगिक उत्पादन के साधनों के स्वामी हैं, और श्रमिक वर्ग (सर्वहारा वर्ग) उनके द्वारा वस्तुओं के उत्पादन में श्रम के रूप में नियोजित हैं। इन दोनों वर्गों के हित निरंतर और परस्पर विरोधी हैं। स्थापित सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था 'सिद्धांत' का प्रतिनिधित्व करती है, और इस व्यवस्था का प्रचार शिक्षा, मीडिया, आधिकारिक नीतियों आदि के माध्यम से किया जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब श्रमिक वर्ग विद्रोह शुरू कर देता है, जो प्रति-सिद्धांत है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मार्क्सवादी विचार में, सिद्धांत और प्रति-सिद्धांत से संश्लेषण प्राप्त करने के लिए दोनों वर्गों के बीच टकराव उत्पन्न करना आवश्यक है। तभी इतिहास में प्रगति हो सकती है।
इसलिए, मार्क्सवाद अनिवार्य रूप से विनाशकारी और हिंसक होता है, क्योंकि केवल प्रतिवाद द्वारा सिद्धांत के विनाश के माध्यम से ही एक नए संश्लेषण की ओर प्रगति हो सकती है। ऐसा कोई पारस्परिक समाधान संभव नहीं है जिसमें दोनों पक्ष शांतिपूर्वक एक-दूसरे को समायोजित कर सकें और सामंजस्य स्थापित कर सकें।

मार्क्सवादी आलोचनात्मक सिद्धांत

हालांकि मार्क्स स्वयं आर्थिक रूप से संपन्न और वंचितों, उत्पीड़क और शोषितों, शासक वर्ग और उसके पीड़ितों पर केंद्रित थे, लेकिन बाद में मार्क्सवाद का विस्तार सत्ता के व्यापक रूपों पर भी किया गया जो केवल आर्थिक नहीं हैं।

मार्क्सवाद के दायरे को विस्तृत करने वाले सबसे प्रभावशाली मार्क्सवादी विचारकों में से एक एंटोनियो फ्रांसिस्को ग्राम्स्की थे, जो इटली की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। उन्हें फासीवादियों द्वारा कैद कर लिया गया था और 1920 के दशक के उत्तरार्ध और 1930 के दशक के आरंभिक वर्षों में लिखी गई उनकी जेल डायरी एक नई मार्क्सवादी विचारधारा का आधार बनी। उनका ध्यान प्रत्यक्ष क्रांति करने के बजाय वैचारिक समस्याओं को पहचानकर उनका समाधान करने पर था। वे पश्चिम के प्रतिवाद के रूप में एक प्रति-वर्चस्व का निर्माण करके पश्चिमी वर्चस्व को ध्वस्त करना चाहते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने के बाद ही वास्तविक क्रांति संभव हो पाएगी।

ग्राम्स्की ने अपने विश्लेषण की शुरुआत इस बात से की कि उनके समय के शोषित मजदूर पूंजीपति वर्ग के खिलाफ विद्रोह नहीं कर रहे थे और उसे उखाड़ फेंक नहीं रहे थे। इस बात ने उन्हें परेशान किया। उनका तर्क था कि प्रभुत्वशाली समूह के खिलाफ विद्रोह करने के बजाय, स्कूलों, चर्चों, अदालतों और मीडिया जैसी संस्थाओं के प्रभाव के कारण मजदूरों ने शासक वर्ग के विश्वासों और मूल्यों को स्वीकार कर लिया था – इस प्रकार उन्होंने मार्क्स के प्रसिद्ध कथन, कि धर्म 'जनता के लिए अफीम' है, को और पुष्ट किया। इसी से प्रेरित होकर ग्राम्स्की ने सांस्कृतिक आधिपत्य की अवधारणा विकसित की। उनके प्रभाव में, मार्क्सवाद लोकप्रिय विमर्श और संस्कृति को बहुत गंभीरता से लेता है। यह संस्कृति और उससे उत्पन्न विमर्श ही है जिसने सर्वहारा वर्ग को अभिजात वर्ग के नियंत्रण में

रखा है। मानसिक/भावनात्मक क्रांति की शुरुआत यहीं से होनी चाहिए, न कि हिंसा के शारीरिक स्तर से।

उनका समाधान था कि सबसे पहले श्रमिकों को उनकी दुर्दशा के बारे में सोचने का तरीका सिखाया जाए। इसके लिए परिवार, राष्ट्र-राज्य, पूंजीवाद और धर्म जैसे मुद्दों के संबंध में पुरानी सोच संरचनाओं को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए एक प्रति-वर्चस्व का निर्माण करना आवश्यक था। तभी एक वास्तविक क्रांति संभव हो सकती थी।[3] बाद में होने वाली हिंसक क्रांति के लिए आधार तैयार करने के लिए विमर्श की क्रांति आवश्यक है।

इसी बीच, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में फ्रैंकफर्ट स्कूल के नाम से जाना जाने वाला एक और जीवंत समूह उभरा, और इसके नेताओं ने 'आलोचनात्मक सिद्धांत' के रूप में प्रसिद्ध विचारधारा को विकसित किया। 1920 के दशक के मध्य से, इसके प्रमुख नेता - मैक्स होर्खाइमर, थियोडोर एडोर्नो और हर्बर्ट मारक्यूज़ - शास्त्रीय मार्क्सवाद से निराश थे। मार्क्सवादियों ने बीसवीं शताब्दी के आरंभ में रूसी क्रांति में अपनी सफलता का जश्न मनाया था, जिसमें लेनिन ने ज़ार निकोलस द्वितीय को उखाड़ फेंकने के लिए किसान विद्रोह का नेतृत्व किया था। लेकिन जर्मनी में, गंभीर आर्थिक मंदी और अभिजात वर्ग के शोषण के बावजूद, ऐसी ही क्रांति की भविष्यवाणियां साकार नहीं हुईं।

रूस की तरह जर्मन जनता ने राज्य के विरुद्ध लामबंदी नहीं की, बल्कि नाज़ी आंदोलन में शामिल हो गई। उन्होंने पूछा कि जर्मनी का सर्वहारा वर्ग रूस के सर्वहारा वर्ग से अलग व्यवहार क्यों कर रहा था? ग्राम्स्की का स्पष्टीकरण यह होगा कि वर्चस्व-विरोधी विमर्श तैयार नहीं किया गया था। फ्रैंकफर्ट स्कूल ने समझाया कि कई बार अभिजात वर्ग कला, लोकप्रिय संस्कृति और मिथकों का उपयोग करके जनता के गुस्से को शांत करके

वास्तव में साम्यवादी क्रांति को रोक सकता है। जनता एक मिथक में जीती है और उनके गुस्से को उनकी पीड़ा से दूर मोड़ा जा सकता है। नाजियों ने यहूदियों और रोमा लोगों को बलि का बकरा बनाकर इस गुस्से को मोड़ने में सफलता प्राप्त की, जिससे रूसी क्रांति जैसी क्रांति को रोका जा सका। दूसरे शब्दों में, वर्चस्ववादी विमर्श का उपयोग नियंत्रण बनाए रखने के लिए किया गया था।

इसलिए, उन्होंने प्रचलित सामाजिक सिद्धांतों को चुनौती देने वाले नए विचारों की खोज की और आलोचनात्मक सिद्धांतों की अवधारणा को सिद्धांतों के एक वर्ग के रूप में प्रस्तुत किया। फ्रैंकफर्ट स्कूल के निदेशक मैक्स होर्खाइमर ने किसी भी सिद्धांत को 'आलोचनात्मक' बताया यदि वह 'मनुष्यों को उन परिस्थितियों से मुक्त करने का प्रयास करता है जो उन्हें गुलाम बनाती हैं'। फ्रैंकफर्ट स्कूल ने पारंपरिक मार्क्सवाद की आर्थिक शक्तियों पर निर्भरता की आलोचना की और समाज में लोकप्रिय संस्कृति की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया। वे घटनाओं का निम्नलिखित क्रम चाहते थे: प्रति-वर्चस्ववादी विमर्श → लोकप्रिय संस्कृति में परिवर्तन → सामाजिक संस्थाओं पर कब्ज़ा → भौतिक क्रांति।

आलोचनात्मक सिद्धांत को ठोस रूप तब मिला जब होर्खाइमर ने 1937 में 'पारंपरिक और आलोचनात्मक सिद्धांत' नामक एक प्रभावशाली घोषणापत्र लिखा। उन्होंने दावा किया कि 'मनुष्य वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता और कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं है'। यह विचार कि सभी सत्य सापेक्ष हैं, फ्रेडरिक नीत्शे और उसके बाद हेगेल के जर्मन विचारों से विरासत में मिला था। इसका तात्पर्य यह है कि सभी प्रवचन विभिन्न सामाजिक शक्तियों द्वारा गढ़े और तथाकथित सत्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। अंतिम सत्य के अभाव में, यह ग्राम्स्की के इस विचार को बल देता है कि जनमानस में स्थापित प्रमुख विचारों को ध्वस्त करने के लिए प्रवचनों का

टकराव होना आवश्यक है।

आलोचनात्मक सिद्धांत को आधुनिक युग के लिए हेगेलियन पुनर्जागरण के रूप में देखा जा सकता है। जहाँ मार्क्स ने आर्थिक शोषण पर आधारित वर्ग संघर्ष पर जोर दिया, वहीं आलोचनात्मक सिद्धांत सांस्कृतिक युद्ध की भूमिका को भी शामिल करते हुए अपने दायरे का विस्तार करता है। फ्रांसीसी मार्क्सवादी पियरे बॉर्डियू ने संस्कृति को पूंजी का एक रूप मानने के सिद्धांत को और विकसित किया। मार्क्सवाद में उनका योगदान संस्कृति और सत्ता के बीच संबंध को स्पष्ट करना था। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग जनता का शोषण करने और अपनी सत्ता की यथास्थिति बनाए रखने के लिए संस्कृति को एक भावनात्मक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। संस्कृति में गहरे और अदृश्य सुरक्षा जाल और भावनात्मक आघात-अवशोषक मौजूद होते हैं। लोग आर्थिक तंगी में भी विद्रोह किए बिना जीवन व्यतीत करते हैं क्योंकि सांस्कृतिक संरचनाएं सत्ता संरचना की रक्षा करती हैं। इस प्रकार, संस्कृति में छिपी हुई संरचनाएं होती हैं जो अभिजात वर्ग को जनता पर सत्ता स्थापित करने में सक्षम बनाती हैं।

आलोचनात्मक सिद्धांतकारों का मानना है कि पूंजीवाद जनता को भौतिकवादी क्रांति से भटकाकर उसे ही कमजोर कर रहा है। पूंजीपति श्रमिक वर्ग में भावनात्मक 'सकारात्मक भावनाएँ' पैदा कर रहे हैं, जिससे उनका ध्यान वास्तविक भौतिक अनुभवों से हट जाता है। संस्कृति पर पूंजीवाद का कब्जा हो चुका है और विज्ञापन उद्योग इसका एक साधन है। लोकप्रिय संस्कृति और विज्ञापन एक सुखदायक मरहम की तरह हैं, जिनका इस्तेमाल सत्ताधारी अभिजात वर्ग जनता का मस्तिष्क धोकर उन्हें शांत करने के लिए करता है। इसका उद्देश्य उनकी ऊर्जा को सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता से दूर करना है। इस प्रकार, उपभोक्तावाद

सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता का शत्रु है।
होर्खाइमर के युवा अनुयायी हर्बर्ट मार्क्यूज़ ने प्रसिद्ध रूप से समझाया कि कैसे पूंजीवाद ने शोषित जनता को मनोवैज्ञानिक रूप से जीत लिया था: यदि मजदूर और उसका मालिक एक ही टेलीविजन कार्यक्रम का आनंद लेते हैं और एक ही रिसॉर्ट में जाते हैं, यदि टाइपिस्ट अपने मालिक की बेटी की तरह ही आकर्षक ढंग से सजी-धजी है, यदि अश्वेत व्यक्ति के पास कैडिलैक कार है, यदि वे सभी एक ही अखबार पढ़ते हैं, तो यह आत्मसातकरण वर्गों के लुप्त होने का संकेत नहीं देता, बल्कि यह दर्शाता है कि स्थापित व्यवस्था को बनाए रखने वाली आवश्यकताएं और संतुष्टियां किस हद तक आम जनता द्वारा साझा की जाती हैं।
इन मार्क्सवादियों ने हॉलीवुड को मुख्य दोषी ठहराया क्योंकि इसने सफलता के झूठे विचार का महिमामंडन किया। पूंजीवाद के मीडिया उद्योग पर नियंत्रण ने इसे अच्छे जीवन के मूल्यों और विचारों को गढ़ने की अनुमति दी। इसी तरह जनता ने यह मानना शुरू कर दिया कि पूंजीवाद ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है, और इसके लिए किसी मार्क्सवादी क्रांति की आवश्यकता नहीं है। मारक्यूज़ ने कहा:
मनोरंजन और सूचना उद्योग का अप्रतिरोध्य उत्पादन अपने साथ कुछ निर्धारित दृष्टिकोण और आदतें, कुछ बौद्धिक और भावनात्मक प्रतिक्रियाएँ लेकर आता है जो उपभोक्ताओं को उत्पादकों से और उत्पादकों के माध्यम से संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था से जोड़ती हैं। ये उत्पाद लोगों को गलत शिक्षा देते हैं और उनका हेरफेर करते हैं; वे एक ऐसी झूठी चेतना को बढ़ावा देते हैं जो अपने झूठ के प्रति अप्रतिरोध्य होती है... इस प्रकार एक आयामी विचार और व्यवहार का एक प्रतिरूप उभरता है।
इस नए मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार, लोकप्रिय मीडिया ने एक नया दृष्टिकोण विकसित किया है जिसके माध्यम से उपभोक्ता समाज में भाग

लेते हैं। उनकी स्वाभाविक और स्वतंत्र इच्छाशक्ति का अपहरण कर लिया गया है। लोगों का वस्तुओं की तरह शोषण किया जा रहा है। वास्तविक संस्कृति का स्थान मनोरंजन उद्योग ने ले लिया है और इसलिए सभी ज्ञान पूंजीपतियों द्वारा आकार दिया जा रहा है।

मार्क्सवाद में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि 1960 और 70 के दशक के शुरुआती नागरिक अधिकार आंदोलन और वियतनाम युद्ध विरोधी आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में सामने आई। मारक्यूज़ अमेरिका में मार्क्सवाद के नवीनतम स्वरूप के एक महत्वपूर्ण चेहरे के रूप में स्थापित हो चुके थे। उन्होंने पाया कि अमेरिकी समाज में वैचारिक अल्पसंख्यकों और बाहरी लोगों का एक ऐसा वर्ग मौजूद है, जिन्हें उनकी शिकायतों को हवा देकर संगठित किया जा सकता है। उन्होंने मूल्यों और संस्कृतियों के प्रदर्शन के माध्यम से अल्पसंख्यकों को यह समझने में मदद की कि अभिजात वर्ग द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। यही वह शुरुआत थी जिसने 'अल्पसंख्यकवाद' आंदोलन को जन्म दिया, जो तब से पूरी दुनिया में फैल चुका है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मार्क्सवाद में केवल दो वर्ग थे: पूंजीपति और सर्वहारा। पूंजीपति एक ही वर्ग था और इसमें कोई अलग अल्पसंख्यक समूह या पहचान नहीं थी जो पीड़ित होने और सत्ता पाने के लिए होड़ कर रही हो। एक पीड़ित वर्ग के स्थान पर कई पीड़ित वर्गों का होना मार्क्सवाद का एक प्रमुख हालिया रूपांतरण है।

आलोचनात्मक सिद्धांत और इसकी सभी शाखाओं और विविधताओं का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी संस्थाओं और मानदंडों पर हमला करके उन्हें ध्वस्त करना था। इसका लक्ष्य स्कूलों द्वारा दी जाने वाली पारंपरिक सोच और जनता की मान्यताओं को बाधित करना था।

मार्क्सवादियों ने साहित्यिक सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया, ताकि ग्रंथों

और अन्य सांस्कृतिक उत्पादों की व्याख्या करके सत्ता की छिपी हुई संरचनाओं को पहचाना जा सके। जब कोई मार्क्सवादी किसी कहानी का विश्लेषण करता है, तो वह उसे समाज में सत्ता की गतिशीलता के प्रतिबिंब के रूप में देखता है और इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि पात्र सत्ता क्रम में अपनी स्थिति के आधार पर कैसे व्यवहार करते हैं। मार्क्सवाद के अनुसार, सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ लेखकों की रचनाओं, उनके द्वारा विकसित पात्रों के प्रकार, उद्धृत उदाहरणों और साहित्यिक कृति में बल दिए गए राजनीतिक विचारों को आकार देती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, सभी साहित्य प्रचलित समाज को प्रतिबिंबित करता है, और साहित्य स्वयं एक सामाजिक संस्था बन जाता है जो एक विशेष विचारधारा का प्रसार करती है।
इस अध्याय में आगे चलकर पाठक को पता चलेगा कि इनमें से कई मार्क्सवादी विचार क्रिटिकल रेस थ्योरी के मूल में समाहित हो गए हैं।

पश्चात
उत्तरआधुनिकतावाद एक बौद्धिक आंदोलन है जिसकी विशेषता वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के प्रति संशयवाद है; इस पर नीत्शे, इमैनुअल कांट, हेगेल और अन्य विद्वानों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह आंदोलन इतिहास, सांस्कृतिक कृतियों और सभी व्यापक कथाओं को उनमें छिपी सत्ता संरचनाओं के सापेक्ष व्याख्यायित करने का प्रयास करता है। विद्वान का कार्य इन छिपी संरचनाओं को खोजना है।
यह एक स्वतंत्र आंदोलन के रूप में शुरू हुआ जिसने यूरोपीय प्रबोधन परियोजना के साथ-साथ आधुनिकता को भी खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें सत्ताधारी अभिजात वर्ग द्वारा निर्मित संरचनाओं के रूप में देखा जाता था।

उत्तरआधुनिकतावाद निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है:
वस्तुनिष्ठ ज्ञान या सार्वभौमिक सत्यों के अस्तित्व के बारे में सामान्य संदेह।
श्रेणियों के बीच की सीमाएं स्वाभाविक रूप से धुंधली मानी जाती हैं और ये महज मनमानी मानवीय परंपराएं हैं।
सभी समाजों में सत्ता संरचनाएं और पदानुक्रम मौजूद होते हैं, और इसी तरह ज्ञान का सृजन होता है।
सभी ज्ञान का निर्माण भाषा के उन खेलों के माध्यम से होता है जो सत्ता से अटूट रूप से जुड़े होते हैं। भाषा स्वयं उन अभिजात वर्ग की शक्ति को समाहित करती है जिन्होंने इसे विकसित किया है। इसलिए, भाषा का प्रयोग हमेशा पक्षपातपूर्ण और दमनकारी होता है।
दूसरे शब्दों में, सत्य के सभी दावे सांस्कृतिक रूप से पक्षपातपूर्ण हैं और अभिजात वर्ग की सामाजिक शक्ति द्वारा निर्मित हैं। इस सिद्धांत का एक परिणाम यह है कि कोई आलोचक वैज्ञानिक प्रमाणों और पद्धति का उपयोग करके किसी भी उत्तर-आधुनिकतावादी कथन के विरुद्ध प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि आलोचना को स्वयं अभिजातवाद की उपज मानकर अस्वीकार कर दिया जाएगा।
उत्तरआधुनिकतावाद अपने संशयवाद को बहुत आगे ले जाता है और मानता है कि सभी बौद्धिक प्रणालियाँ, सिद्धांत और सारगर्भित कथाएँ मात्र सामाजिक रचनाएँ हैं। विज्ञान भी, तर्कसंगत चिंतन की एक प्रणाली के रूप में, ऐसी ही एक सारगर्भित कथा है और किसी वस्तुनिष्ठ वास्तविकता का प्रतिनिधित्व नहीं करती। हम आगे देखेंगे कि कैसे यह विचार आज के आलोचनात्मक नस्ल सिद्धांत में पाई जाने वाली तर्कसंगतता की अवहेलना का कारण बनता है।
फ्रायडियन क्रांति ने एक और महत्वपूर्ण नवाचार प्रस्तुत किया: मन के

एक ऐसे अचेतन स्तर का विचार, जिसके बारे में व्यक्ति स्वयं अनभिज्ञ होता है और जिसे समझने के लिए एक विशेषज्ञ (मनोविश्लेषक) की आवश्यकता होती है। इसने उत्तरआधुनिकतावाद द्वारा सभी मानवीय रचनाओं और गतिविधियों के विखंडन को अचेतन और अदृश्य शक्ति संरचनाओं की खोज में बदल दिया।

दूसरे शब्दों में कहें तो, साहित्य जैसी सभी मानवीय रचनाओं में शक्ति छिपी होती है। उसे खोजना पड़ता है। वामपंथियों ने उत्तरआधुनिकतावाद का उपयोग करके इतिहास और कलाकृतियों का विवेचन करना शुरू किया, ताकि दुर्व्यवहार की संरचनाओं को उजागर किया जा सके। इतिहास पढ़ाते समय, उनका वास्तविक उद्देश्य एक पक्षपातपूर्ण संरचना को उजागर करना होता है।

उनके अनुसार, एक कुशल कला समीक्षक को कलाकार के उस पूर्वाग्रह को उजागर करना चाहिए जो कलाकृति में छिपा रहता है। वह कहेगा कि कलाकृति पुरुषवादी पूर्वाग्रह से ग्रस्त है या विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के अवचेतन पूर्वाग्रह को दर्शाती है, इत्यादि।

प्रारंभ में उत्तरआधुनिकतावाद और मार्क्सवाद के बीच गंभीर टकराव हुआ क्योंकि उत्तरआधुनिकतावाद मार्क्सवाद के मूल वर्ग संघर्ष के सिद्धांत सहित सभी दैवीय अवधारणाओं का विखंडन करता है।

उत्तरआधुनिकतावाद में उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों का विखंडन किया जाता है, जबकि मार्क्सवाद को एक ऐसी पहचान का निर्माण करना आवश्यक लगता है जिसे दलितों के लिए वास्तविक और मूलभूत माना जाए और उन्हें क्रांति के हथियार के रूप में संगठित किया जाए। इसलिए, ये दोनों खेमे परंपरागत रूप से एक-दूसरे के विरोधी रहे हैं।

मार्क्सवाद और उत्तरआधुनिकतावाद को एक साथ लाने के लिए, आलोचनात्मक सिद्धांतकारों ने उत्तरआधुनिकतावाद की दूसरी लहर

विकसित की। पहली लहर ने सभी मेटा नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया था, जबकि दूसरी लहर ने केवल उन्हीं पहचानों और नैरेटिव को ध्वस्त किया जिन्हें दमनकारी माना जाता था। अभिजात वर्ग के नैरेटिव के विपरीत नैरेटिव को अनुमति दी गई और वास्तव में बढ़ावा दिया गया, क्योंकि उत्पीड़ितों को विशेष अधिकार मिलने चाहिए। यह दलितों के अधिकारों की वकालत करने का नया तरीका बन गया, और इसी तरह उत्तरआधुनिकतावाद को मार्क्सवादियों की नैतिक दृष्टि में नया रूप दिया गया।

मार्क्सवाद और उत्तरआधुनिकतावाद के इस मेल ने मार्क्सवाद और उसके सामाजिक विज्ञानों को उत्तरआधुनिकतावाद में समाहित करने का द्वार खोल दिया। इसने उत्पीड़कों और उत्पीड़ितों के विचारों पर अलग-अलग मापदंड और दृष्टिकोण लागू किए। वास्तव में, इस नए स्वरूप ने उत्तरआधुनिकतावाद के संस्थापकों के मूलभूत सिद्धांतों के साथ विश्वासघात किया है।

मार्क्सवाद और उत्तरआधुनिकतावाद की दूसरी लहर के संयोजन का एक प्रमुख अनुप्रयोग उत्तरऔपनिवेशिक अध्ययन के क्षेत्र में हुआ। यह औपनिवेशिक युग के ग्रंथों और अन्य सांस्कृतिक उत्पादों का अध्ययन है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक पाठ में छिपे उपनिवेशवादियों के दमनकारी दृष्टिकोण को उजागर करना है।

गायत्री स्पिवक का 1988 का निबंध, "क्या हाशिए पर रहने वाले लोग बोल सकते हैं?" इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने हाशिए पर रहने वाले लोगों का समर्थन किया, जो चर्चाओं में शामिल न होने के कारण खुद का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। स्पिवक ने फ्रांसीसी दार्शनिक/इतिहासकार जैक्स डेरिडा की उत्तर-आधुनिकतावादी विखंडनात्मक पद्धति को अपनाया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भारत में

बड़ी संख्या में लोग हाशिए पर हैं क्योंकि उन्हें नीतिगत चर्चाओं और उनसे संबंधित विमर्श में भाग लेने की अनुमति नहीं है।

इससे निम्नवर्गीय अध्ययन के लिए व्यापक द्वार खुल गए। भारतीय मार्क्सवादी इतिहासकारों ने निम्नवर्गीय लोगों के अधिकारों की वकालत करने के लिए ग्राम्स्की और फ्रैंकफर्ट स्कूल दोनों के विचारों को तुरंत अपना लिया। इसके परिणामस्वरूप कई ऐसे विद्वान उभरे जो निम्नवर्गीय लोगों की आवाज़ बनने का दावा करते थे। इनमें से अधिकांश विद्वान कुलीन वर्ग से थे, जबकि वे कथित तौर पर निम्नवर्गीय लोगों की आवाज़ बनने का दिखावा करते हुए सत्ता के दलाल की भूमिका निभा रहे थे। सामाजिक विज्ञान में नया विमर्श यह था कि दलितों को अपने इतिहास के निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभाने का अधिकार है क्योंकि इसे अभिजात वर्ग ने लिखा है, और इसलिए विद्वानों को उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। उन्हें पुराने साहित्यिक कार्यों का विखंडन और परिखंडन करके उनकी जगह नए साहित्य और नए इतिहास की रचना करनी चाहिए, जिसमें दलितों की आवाज़ को शामिल किया जाए। वास्तव में, दलित विद्वान ही यह तय करने वाले निर्णायक बन गए कि उत्पीड़न क्या है और दलितों की वास्तविक आवाज़ किसे माना जाना चाहिए। संक्षेप में, वे इस संशोधित सामाजिक संरचना में नए सत्ता दलाल और अभिजात वर्ग बन गए।

निम्नलिखित आरेख मार्क्सवाद, उत्तरआधुनिकतावाद और उत्तरऔपनिवेशिकवाद के संबंध में अब तक के हमारे मुख्य बिंदुओं को दर्शाता है।

इन सबने आलोचनात्मक सिद्धांत के क्षेत्र को व्यापक बनाया है, जो अब उदार कला शिक्षा का केंद्रबिंदु है। यह एक ऐसी कार्यप्रणाली और ढांचा है जो दमनकारी माने जाने वाले प्रमुख आख्यानों को हाशिए पर रखकर

प्रचलित प्रतिमानों को चुनौती देता है। यह प्रमुख आख्यानों को उन व्यापक प्रतीकों, कहानियों, अवधारणाओं, छवियों और विश्वासों के रूप में पहचानता है जो प्रमुख संस्कृति, संस्था या विश्वदृष्टि का निर्माण करते हैं। यह मार्क्सवाद के सिद्धांत के समतुल्य है। प्रति-सिद्धांत को प्रति-आख्यानों के रूप में विकसित किया जाता है ताकि ऐसे मानक चिंतन को चुनौती दी जा सके और शोषितों को मुक्ति दिलाई जा सके।

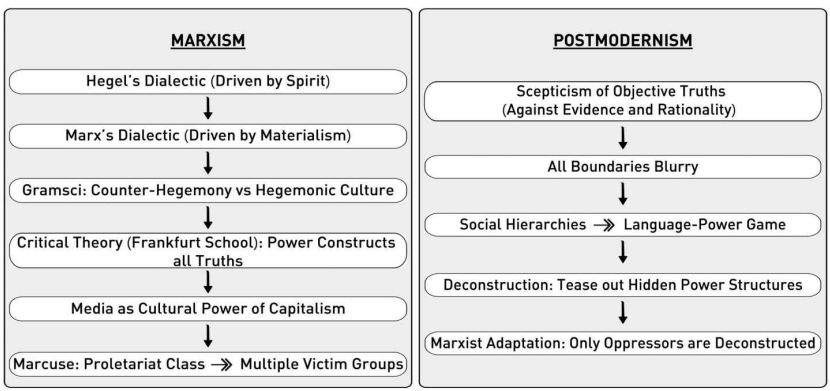

भारतीयों ने इन सिद्धांतों को तुरंत अपना लिया और ब्राह्मणों को उत्पीड़क के रूप में प्रस्तुत किया। भारतीय विद्वान पारंपरिक ग्रंथों में छिपे ब्राह्मणों के संदेशों को उजागर करते हैं, ताकि यह दिखाया जा सके कि वे निचली जातियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और अन्य पीड़ितों पर अत्याचार करते हैं। प्रत्येक संस्कृत ग्रंथ, देवता, गुरु आंदोलन, प्रतीक, अनुष्ठान, त्योहार और भारतीय परंपराओं के अन्य पहलुओं का इन उपकरणों का उपयोग करके विश्लेषण किया जा रहा है ताकि अंतर्निहित उत्पीड़न को उजागर किया जा सके।

यह बताना महत्वपूर्ण है कि यह विखंडन केवल आलोचना पर समाप्त नहीं

होता, जो किसी भी समाज के लिए आत्मनिरीक्षण का एक स्वागत योग्य रूप होगा, बल्कि यह उस चीज की पूर्णतः अस्वीकृति का आह्वान करता है जिसका विखंडन किया जा रहा है, जो अतीत की संरचनाओं के हिंसक विघटन के रूप में क्रांति के लिए मार्क्सवादी आह्वान की याद दिलाता है।

आलोचनात्मक नस्ल सिद्धांत

उपरोक्त घटनाक्रमों की उत्पत्ति अधिकतर यूरोप में हुई, लेकिन इनका प्रभाव अमेरिका में भी देखने को मिला। अमेरिका में घरेलू समाज से संबंधित सबसे पहला महत्वपूर्ण विचार क्रिटिकल लीगल थ्योरी था, जिसने बाद में क्रिटिकल रेस थ्योरी को जन्म दिया।

क्रिटिकल लीगल थ्योरी ने अमेरिकी कानून की संरचना में मौजूद प्रणालीगत पूर्वाग्रह की समस्या का समाधान किया। इसके समर्थकों ने इसे इस प्रकार समझाया:

यह कानून उन लोगों के हितों का समर्थन करता है जो इसे बनाते हैं। … एक ऐसी सत्तागत व्यवस्था जो ऐतिहासिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के पक्ष में है और ऐतिहासिक रूप से वंचित लोगों के विरुद्ध है। … धनी और शक्तिशाली लोग पदानुक्रम में अपना स्थान बनाए रखने के लिए कानून को दमन के एक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं।

इसके नेताओं ने स्वीकार किया कि उनका सिद्धांत फ्रैंकफर्ट स्कूल से काफी प्रभावित है। पहले चर्चा की गई मार्क्सवादी आलोचनात्मक सिद्धांत की तरह, यह भी सामाजिक संरचनाओं को ध्वस्त करने का प्रयास करता है, लेकिन इसका लक्ष्य कानूनी व्यवस्था में सुधार करना है। यह कानून को कानूनों में संहिताबद्ध और न्यायशास्त्र द्वारा संरक्षित सांस्कृतिक वर्चस्व के रूप में देखता है।

क्रिटिकल लीगल थ्योरी पर पहली बड़ी चर्चा 1977 में मैडिसन स्थित विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में हुई थी। कॉर्नेल वेस्ट, एक प्रतिष्ठित अश्वेत अमेरिकी दार्शनिक और कार्यकर्ता, जो अब दलित सक्रियता के समर्थक हार्वर्ड के एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, इसके शुरुआती समर्थकों में से एक थे। आलोचनात्मक विधिक सिद्धांत पर एक और प्रभाव उत्तरआधुनिकतावाद से आया, जिसने व्यक्ति की पहचान से हटकर समूह की पहचान पर ध्यान केंद्रित किया। अब कानूनी अधिकारों की लड़ाई किसी व्यक्ति के बजाय एक समूह की ओर से लड़ी जा रही थी। प्रत्येक समूह की पहचान यह मांग कर सकती थी कि उसे सामूहिक रूप से पीड़ित के रूप में मान्यता दी जाए, न कि उस समय घटित घटनाओं के कारण, बल्कि इतिहास में घटित घटनाओं के कारण। इसका मुख्य उद्देश्य विधिक व्यवस्था की आलोचना करना था, जिसे एक पदानुक्रमित संरचना के रूप में देखा जाता था जो गोरों को कालों पर, पुरुषों को महिलाओं पर, अमीरों को गरीबों पर, इत्यादि को प्रभुत्व जमाने में मदद करती थी।
अगला कदम क्रिटिकल लीगल थ्योरी को क्रिटिकल रेस थ्योरी में विस्तारित करना था, जो यह मानती है कि अमेरिकी जीवन के सभी पहलुओं (केवल कानून ही नहीं) को नस्ल के परिप्रेक्ष्य से देखा जाना चाहिए। यह न केवल सतह पर दिखाई देने वाली गतिविधियों पर लागू होता है, बल्कि उन अदृश्य संरचनाओं पर भी लागू होता है जो इन गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं। और इतिहास को देखे बिना नस्लवाद को नहीं समझा जा सकता। इसलिए, छिपी हुई संरचनाओं को उजागर करने के लिए सतह के नीचे और इन संरचनाओं के इतिहास को देखना आवश्यक है।
हार्वर्ड लॉ स्कूल में स्थायी पद प्राप्त करने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी प्रोफेसर डेरिक बेल जूनियर को 1970 के दशक में विकसित उस सिद्धांत

का जनक माना जाता है, जिसे बाद में क्रिटिकल रेस थ्योरी के नाम से जाना गया। यह आंदोलन शुरू में उत्तरआधुनिकतावाद से अलग रहा क्योंकि इसे अत्यधिक अमूर्त और अव्यावहारिक माना जाता था। जैसा कि पहले बताया गया है, मार्क्सवादियों द्वारा उत्तरआधुनिकतावाद को प्रतिगामी माना जाता था क्योंकि यह अल्पसंख्यक पहचान की उस अवधारणा को भी ध्वस्त कर देता था जिस पर क्रिटिकल रेस थ्योरी की राजनीति आधारित थी। अंततः, 1990 के दशक तक, उत्तरआधुनिकतावाद को मार्क्सवादी ढांचे के भीतर पुनर्परिभाषित किया गया और अब यह आंदोलन का एक महत्वपूर्ण आधार है।

क्रिटिकल रेस थ्योरी की शुरुआत समाज के क्रांतिकारी विश्लेषण से हुई और फिर उसी के आधार पर एक सामाजिक आंदोलन को गति दी। यह सिद्धांत कहता है कि श्वेत विशेषाधिकार की संरचनाएं साहित्य, कला, सामाजिक मानदंडों, नागरिक और आपराधिक कानूनों, संविधान, मोहल्लों में संपत्ति संबंधी प्रथाओं, बैंकिंग में वित्तीय नियमों, ऋण प्राप्त करने वालों आदि हर चीज की नींव हैं। इसमें शिक्षा प्रणाली, मीडिया की संरचनाएं, सरकार की संरचनाएं, निगमों की संरचनाएं और उन्हें चलाने वाले लोग भी शामिल हैं। आधुनिक समाज की ये सभी संस्थागत संरचनाएं व्यवस्थित नस्लवाद को छुपाती हैं।

इस सिद्धांत के व्यापक और दूरगामी प्रभाव को निम्नलिखित सारांश में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

… (सीआरटी) नस्ल को एक ऐसे परिप्रेक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करता है जिसके माध्यम से इसके समर्थक अमेरिकी जीवन के सभी पहलुओं का विश्लेषण करते हैं — … इस दृढ़ता के साथ कि सीआरटी ने अमेरिकी जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित किया है। … (यह) पहचान की राजनीति का आधार है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका को एक ऐसे राष्ट्र के

रूप में पुनर्कल्पना करने का निरंतर प्रयास है जो समूहों द्वारा संचालित है, जिनमें से प्रत्येक समूह पीड़ित होने के विशिष्ट दावे करता है। मनोरंजन के साथ-साथ शिक्षा और कार्यबल क्षेत्रों में भी, सीआरटी अच्छी तरह से स्थापित है, जो व्यक्तिगत मूल्य और प्रतिभा के बजाय त्वचा के रंग के आधार पर निर्णय लेने को प्रभावित करता है। जैसे-जैसे आलोचनात्मक सिद्धांत के विचार रोजमर्रा की जिंदगी में दर्शकों के लिए अधिक परिचित होते जाते हैं, सीआरटी की असहिष्णुता, साथ ही अमेरिकियों के लिए प्रणालीगत नस्लवाद का विचार, 'सामान्य' हो जाता है, जिससे विश्वास पैदा करने वाले और नागरिक सहभागिता को सक्षम बनाने वाले सार्वजनिक और निजी बंधन कमजोर हो जाते हैं।

मूल दावा यह है कि गोरों ने पिछले पाँच सौ वर्षों में अपने दास व्यापार और उपनिवेशीकरण को उचित ठहराने के लिए अश्वेतों की हीनता की धारणा गढ़ी, और ये विचार समाज की गहरी संरचनाओं में समाहित हैं। यहाँ तक कि हमारी भाषा भी इन संरचनाओं को सुदृढ़ करती है।

आधुनिक समाज की संरचनाओं में व्याप्त इस नस्लवादी इतिहास को समझने के बाद क्या किया जाना चाहिए? हेगेल और मार्क्स के द्वंद्ववाद पर आधारित, आलोचनात्मक नस्ल सिद्धांत अपने अनुयायियों से एक प्रतिवाद का निर्माण करने की मांग करता है जो हर प्रकार की पुरानी संरचना से लड़ेगा। इसे आसानी से जमीनी स्तर पर सक्रियता में बदला जा सकता है, जैसे: विश्वविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश और अमेरिकी इतिहास पढ़ाने के तरीके का विरोध करना, संविधान के संस्थापकों को चुनौती देना, इत्यादि। किसी भी चीज को बख्शा नहीं जाना चाहिए। समाज के हर पहलू को उजागर और ध्वस्त किया जाना चाहिए। जो लोग लड़ाई नहीं लड़ते, वे वास्तव में समस्या का हिस्सा हैं। वे अभिजात वर्ग की रक्षा कर रहे हैं। आगे बढ़ने का एकमात्र सही तरीका प्रतिवाद का

समर्थन करना है, जो इन संरचनाओं का विखंडन, विद्रोह, विरोध और उन्हें ध्वस्त करना है।

यह ध्यान देने योग्य है कि एक शताब्दी पूर्व मोहनदास के. गांधी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक, हिंद स्वराज या भारतीय स्वशासन, में भी इसी प्रकार का तर्क दिया गया था: ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था में किसी भी पद पर कार्यरत सभी भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य को बनाए रखने और उसे सुचारू रूप से चलाने में सहायक हैं। इसमें न केवल सेना में कार्यरत भारतीय बल्कि सिविल सेवाओं, शिक्षा आदि क्षेत्रों में कार्यरत भारतीय भी शामिल हैं। गांधी का सत्याग्रह आंदोलन एक प्रकार से इसके विपरीत था, यद्यपि उन्होंने सीधे तौर पर इस ढांचे का उपयोग नहीं किया। सत्याग्रह का उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक समाज में अंतर्निहित ब्रिटिश सिद्धांत को ध्वस्त करने और इस प्रकार उनके साम्राज्य को नष्ट करने के लिए किया गया था।

क्रिटिकल रेस थ्योरी के समर्थकों ने 1960 और 70 के दशक के शुरुआती दौर में नागरिक अधिकार, नस्लीय एकीकरण, सकारात्मक कार्रवाई और समानता के अन्य उपायों के लिए आंदोलन चलाने वाले पुराने उदारवादियों से अलग रुख अपनाया। पारंपरिक उदारवादियों का दृष्टिकोण वंचितों की भौतिक प्रगति पर ज़ोर देना था। लेकिन क्रिटिकल रेस थ्योरी के समर्थकों का दावा है कि नागरिक अधिकार कानून उन पुरानी संरचनाओं पर आधारित हैं जो वास्तव में उत्पीड़न को कायम रखती हैं। उनकी मांग है कि इन संरचनाओं को सहन करने के बजाय उन्हें खत्म किया जाए।

रेवरेंड मार्टिन लूथर किंग जूनियर और अन्य नागरिक अधिकार नेताओं द्वारा समर्थित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत 'रंगभेद रहित दृष्टिकोण' है। यह सिद्धांत कहता है कि सभी व्यक्तियों के साथ रंग या पहचान की परवाह

किए बिना समान व्यवहार किया जाना चाहिए, जिससे सभी को समान अवसर मिल सकें। लेकिन अब इस सिद्धांत को भी चुनौती मिल रही है। पहचान के प्रति तटस्थ और निष्पक्ष रहना अब स्वीकार्य नहीं है; स्थापित संरचनाओं में ऐतिहासिक रूप से अंतर्निहित पूर्वाग्रह हैं जिनका सक्रिय रूप से मुकाबला करना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति केवल तटस्थ होने का दावा करता है (रंगभेद रहित होने का), तो इसे सत्ता छिपाने का मुखौटा माना जाता है। इस अध्याय में आगे हम चर्चा करेंगे कि कैसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रंगभेद रहित दृष्टिकोण का समर्थन किया और कैसे रंगभेद रहित दृष्टिकोण के समर्थकों ने उनका विरोध किया।

पति-पत्नी की जोड़ी और कानून के विद्वान रिचर्ड डेलगाडो और जीन स्टेफेंसिक को क्रिटिकल रेस थ्योरी को उसके वर्तमान स्वरूप में विकसित करने वाले अग्रदूतों में गिना जाता है। वे बताते हैं कि पुरानी उदारवादी सोच को क्यों खारिज किया जाना चाहिए:

आलोचनात्मक नस्ल सिद्धांत उदारवादी व्यवस्था की बुनियाद पर ही सवाल उठाता है, जिसमें समानता सिद्धांत, कानूनी तर्क, ज्ञानोदय का तर्कवाद और संवैधानिक कानून के तटस्थ सिद्धांत शामिल हैं।

कई उदारवादी रंगभेद से मुक्त होकर संवैधानिक कानून के तटस्थ सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं। वे समानता में विश्वास करते हैं, विशेषकर सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार में, चाहे उनका इतिहास या वर्तमान परिस्थितियाँ कुछ भी हों।

ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन की शुरुआत 2013 में अमेरिकी पुलिस द्वारा अश्वेत अमेरिकियों के साथ लंबे समय से हो रही व्यवस्थित क्रूरता और अन्यायपूर्ण व्यवहार के विरोध में हुई थी। लेकिन 2020 में एक श्वेत पुलिसकर्मी द्वारा जॉर्ज फ्लॉयड की जघन्य हत्या और इसी तरह की कई अन्य घटनाओं ने अमेरिका में बड़ी संख्या में अश्वेतों द्वारा झेली जा रही

वास्तविकता के प्रति अमेरिकियों को सचेत कर दिया। इससे क्रिटिकल रेस थ्योरी के प्रति मुख्यधारा में जागरूकता और समर्थन भी बढ़ा। असल में, बीएलएम आंदोलन ने अमेरिकी इतिहास में मार्क्सवाद से प्रेरित किसी भी पिछले आंदोलन की तुलना में कहीं अधिक ज़ोरदार तरीके से क्रिटिकल रेस थ्योरी को बढ़ावा दिया है। अब डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रगतिशील वामपंथ का एक बड़ा हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका को पीड़ित समूहों का राष्ट्र मानता है और पहचान की राजनीति के बदले पारंपरिक उदारवाद और प्रगतिशील लक्ष्यों को त्याग चुका है।

अंतर्संबंधता

अंतर-अंतर्संबंधता, आलोचनात्मक नस्ल सिद्धांत का एक पूरक सिद्धांत है। यह दृष्टिकोण बताता है कि जब कोई व्यक्ति अनेक पहचानों को साझा करता है, तो इन पहचानों के संयोजन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं विशिष्ट होती हैं। आमतौर पर दिया जाने वाला उदाहरण यह है कि अश्वेतों की कुछ समस्याएं होती हैं और महिलाओं की कुछ अलग, लेकिन अश्वेत महिलाओं की समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका समाधान दोनों समूहों द्वारा उचित रूप से नहीं किया जाता। अश्वेत महिलाओं को केवल अश्वेत के रूप में पर्याप्त रूप से नहीं समझा जा सकता क्योंकि अश्वेत संगठन मुख्य रूप से पुरुषों को ही सेवाएं प्रदान करते हैं। न ही अश्वेत महिलाओं को केवल महिला के रूप में पर्याप्त रूप से समझा जा सकता है, क्योंकि अधिकांश महिला समूहों में श्वेत महिलाओं का वर्चस्व होता है। एक अश्वेत महिला को जिन पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है, वे अश्वेत पुरुषों और श्वेत महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले पूर्वाग्रहों से भिन्न होते हैं। इसलिए यह मान लेना सही नहीं होगा कि अश्वेत महिलाओं की देखभाल क्रमशः अश्वेतों और महिलाओं के अधिकारों के लिए चलाए गए अलग-

अलग आंदोलनों द्वारा की गई थी। उनके साथ होने वाला भेदभाव केवल दो अलग-अलग अनुभवों का योग नहीं है। उदाहरण के लिए, जब अश्वेतों के लिए रोजगार के अवसर जुटाए गए, तो वे मुख्य रूप से पुरुषों को मिले। इसी प्रकार, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर जुटाने पर, वे मुख्य रूप से श्वेत महिलाओं को मिले। अश्वेत महिलाओं को न तो अश्वेत आंदोलन से और न ही महिला आंदोलन से लाभ हुआ है। यही कारण है कि अंतर्संबंधता ने अश्वेत महिलाओं को एक अलग और विशिष्ट श्रेणी के रूप में स्थापित करने का आग्रह किया। कोलंबिया लॉ स्कूल की प्रोफेसर किम्बर्ले क्रेंशॉ को अंतर्संबंधता की अवधारणा को प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है।

अंतर्संबंधवाद के समर्थन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब मैरीलैंड विश्वविद्यालय की पेट्रीसिया हिल कॉलिन्स की 1990 की पुस्तक, ब्लैक फेमिनिस्ट थॉट: नॉलेज, कॉन्शियसनेस, एंड द पॉलिटिक्स ऑफ एम्पावरमेंट, ने व्यक्तिगत उदारवाद के विचार के बजाय पहचान की राजनीति की खुलकर वकालत की।[15] सिरमा बिल्गे के साथ कॉलिन्स द्वारा सह-लिखित पुस्तक, अंतर्संबंधवाद में, उन्होंने लिखा:

सामाजिक विभाजन के किसी एक अक्ष, चाहे वह नस्ल हो, लिंग हो या वर्ग, से नहीं, बल्कि अनेक अक्षों से आकारित होता है जो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अंतर्संबंधता एक विश्लेषणात्मक उपकरण के रूप में लोगों को दुनिया और स्वयं की जटिलता को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है।

अंतर्संबंधता की अवधारणा के अनुसार, उत्पीड़क/उत्पीड़ित के संबंधों को केवल नस्ल, लिंग और वर्ग जैसे सामाजिक विभाजन के आधार पर नहीं समझा जा सकता। समाज के वंचित वर्गों पर सत्ता के प्रभाव को व्यक्त करने और उसे वैधता प्रदान करने वाली अनेक सामाजिक शक्तियाँ,

पहचानें और विचारधाराएँ मौजूद हैं। प्राथमिक श्रेणी नस्ल है, जो अन्य पहचानों के साथ मिलकर अनेक पीड़ित पहचानों का निर्माण करती है। हमें याद है कि शास्त्रीय मार्क्सवाद में वर्ग की अवधारणा में सभी प्रकार के शोषित लोग समाहित थे। शोषितों को छोटे-छोटे समूहों में विभाजित न करना महत्वपूर्ण था, क्योंकि ऐसे समूह आपस में लड़ सकते थे और सामूहिक प्रभाव को कमज़ोर कर सकते थे। लेकिन अंतर्संबंधता के कारण, अलग-अलग अल्पसंख्यक पहचानों की सूची में भारी वृद्धि हो रही है। उदाहरण के लिए, नारीवाद कई उप-पहचानों में बँट गया है। अब नारीवादी विचारधारा के कई समूह हैं जो स्वयं को उदार नारीवादी, नव-उदार नारीवादी, मार्क्सवादी नारीवादी, समाजवादी नारीवादी, कट्टरपंथी सांस्कृतिक नारीवादी, कट्टरपंथी समलैंगिक नारीवादी, कट्टरपंथी स्वतंत्रतावादी नारीवादी, मनोविश्लेषणात्मक नारीवादी, स्त्रीवादी, ईसाई नारीवादी, यहूदी नारीवादी, इस्लामी नारीवादी, भारतीय नारीवादी आदि कहते हैं। ये विभिन्न समूह अक्सर एक-दूसरे पर हमला करते रहते हैं। विभिन्न पहचानों को मिलाकर अंतर्संबंधी समूहों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाई जा सकती है, जिससे हाशिए पर मानी जाने वाली और विशेष व्यवहार की आवश्यकता वाली पहचानों की संख्या में वृद्धि होती है। इस बदलाव ने पहचान की राजनीति के द्वार खोल दिए हैं क्योंकि पीड़ित पहचानों की संख्या में वृद्धि हुई है। अकादमिक क्षेत्रों में अब आलोचनात्मक शिकायत अध्ययन, आलोचनात्मक लिंग अध्ययन, आलोचनात्मक यौनिकता अध्ययन, आलोचनात्मक मोटापा अध्ययन और आलोचनात्मक जाति अध्ययन शामिल हैं।

अमेरिका और अन्य देशों में मुसलमानों ने खुद को पीड़ित के रूप में प्रस्तुत करने के लिए 'क्रिटिकल इस्लामोफोबिया स्टडीज' नामक एक अभियान शुरू किया है। इससे डेमोक्रेटिक पार्टी में इस्लामी लॉबी को

भारत के खिलाफ कुछ नए और साहसिक कदम उठाने की प्रेरणा मिली है। उनकी एक सफलता यह रही है कि उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस में एक विधेयक पेश किया है जो विश्व स्तर पर इस्लामोफोबिया को अवैध घोषित करता है और अमेरिकी विदेश विभाग को प्रत्येक देश में इस्लामोफोबिया की निगरानी के लिए एक विशेष समूह गठित करने का निर्देश देता है। यदि किसी देश में इस्लामोफोबिया पाया जाता है, तो उस पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की जाएगी।

यह विधेयक अमेरिकी कांग्रेस में लगभग सभी डेमोक्रेट सांसदों के समर्थन से पारित हो गया। इसके बाद इसे अमेरिकी सीनेट में चर्चा के लिए पेश किया गया। हमने एक खुले पत्र के माध्यम से इस विधेयक का विरोध किया। अब तक यह विधेयक अमेरिकी सीनेट में आगे नहीं बढ़ पाया है, लेकिन इसे वापस भी नहीं लिया गया है। अमेरिकी कांग्रेस में इस तरह के विधेयक की तत्काल सफलता इस बात का प्रमाण है कि कुछ विशिष्ट पहचानों को पीड़ितों के रूप में एकजुट करके और उनका इस्तेमाल पारंपरिक उदारवाद को उखाड़ फेंकने के लिए एक हथियार के रूप में करने का यह आंदोलन कितना सफल रहा है।

पीड़ितों की विभिन्न पहचानों को उत्पीड़न के एक पदानुक्रम में संगठित किया जा रहा है। इस पदानुक्रम में निचले स्थानों पर स्थित लोगों को 'संरक्षित वर्ग' कहा जाता है, जो उन्हें विभिन्न कानूनों के तहत भेदभाव से सुरक्षा के मामले में विशेष दर्जा प्रदान करता है।

आलोचकों द्वारा उठाया जा रहा प्रश्न यह है कि वैध पीड़ित पहचानों को परिभाषित करने का अधिकार किसे है, और संरक्षित वर्गों की सूची किस आधार पर निर्धारित की जाएगी? वर्तमान वास्तविकता यह दर्शाती है कि पीड़ित अधिकारों के इस सामाजिक खेल में सबसे मुखर, सबसे आक्रामक और सबसे संगठित कार्यकर्ता ही विजयी होते हैं। यह पूरी तरह

से एक राजनीतिक मामला है जो क्रिटिकल रेस थ्योरी पर चर्चा को नियंत्रित करने वालों के हाथों में है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि कश्मीरी पंडितों, पाकिस्तान से शरणार्थी बने पंजाबी हिंदुओं, भारत में निर्वासित तिब्बतियों आदि के लिए पीड़ित होने की कोई विशेष अंतर्विभागीय श्रेणियां उपलब्ध नहीं हैं।

इस आंदोलन का राजनीतिक लक्ष्य अंतर्संबंधता का उपयोग करके कई हाशिए पर पड़ी पहचानों की पहचान करना और फिर उन्हें एक साथ जोड़कर विशेषाधिकार प्राप्त अभिजात वर्ग के तथाकथित उत्पीड़न को उखाड़ फेंकना है।

हम इस बात को समझते हैं कि विभिन्न पहचानों द्वारा झेली गई क्रूरताओं की गहरी ऐतिहासिक संरचनाएं हैं और उन्हें उजागर करना और समाप्त करना आवश्यक है। हालांकि, कई विसंगतियां और विरोधाभास हैं जिन पर लोगों को खुलकर चर्चा करने में सक्षम होना चाहिए। उदाहरण के लिए:

प्रिंसटन के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री एंगस डेटन बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों में अमेरिका में श्वेत अमेरिकियों को मानसिक स्वास्थ्य, व्यसन, आत्महत्या, रोजगार हानि, कम जीवनकाल आदि के मामले में अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक कष्ट झेलना पड़ा है। सभी श्वेतों को उत्पीड़क करार देने के बजाय, क्या हाशिए पर रहने वाले श्वेतों को समाज की संरचनाओं के शिकार के रूप में शामिल करना उचित होगा?

योग्यता के बावजूद, हार्वर्ड जैसे कुछ प्रतिष्ठित कॉलेजों में एशियाई और यहूदी छात्रों का प्रवेश पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि उन्हें श्वेतों की तरह ही विशेषाधिकार प्राप्त समूह माना जाता है। अमेरिकी कॉलेज और अन्य संस्थान विभिन्न एशियाई समुदायों की सहमति के बिना ही एशियाई लोगों को नस्लीय आधार पर परिभाषित करने की मनमानी कर रहे हैं।

मैरीलैंड विश्वविद्यालय ने प्रथम वर्ष के प्रवेश के लिए अपनी नस्लीय श्रेणियां निर्धारित की हैं। इसमें एशियाई छात्रों को श्वेत छात्रों के साथ रखा गया है। ये श्रेणियां हैं: 'एशियाई छात्रों को छोड़कर अन्य अश्वेत छात्र' और 'श्वेत या एशियाई छात्र'।

अमेरिकी खेलों में एशियाई लोगों का प्रतिनिधित्व कम है जबकि अश्वेत लोगों का प्रतिनिधित्व अधिक है। इसका कारण यह है कि अश्वेत लोग बास्केटबॉल और अमेरिकी फुटबॉल जैसे खेलों के लिए शारीरिक रूप से श्रेष्ठ होते हैं। क्या हमें इसे 'अश्वेत विशेषाधिकार' और अश्वेतों द्वारा 'संरचनात्मक नस्लवाद' कहना चाहिए और एशियाई लोगों को शोषित घोषित करना चाहिए? अन्यथा, यदि हम इस बात का जश्न मनाते हैं कि अश्वेत लोगों का शरीर खेलों के लिए उपयुक्त और अधिक मजबूत होता है, तो उसी अनुपात में एशियाई लोगों का गणित में बेहतर होना समस्या क्यों है? विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) के क्षेत्र में योग्यता को अभिजात वर्ग का विशेषाधिकार माना जा रहा है और भारतीयों पर इस संबंध में श्वेत विशेषाधिकार का लाभ उठाने का आरोप लगाया जा रहा है। यही अध्याय 4 का मुख्य बिंदु है।

सबसे बड़ी समस्या यह है कि श्वेत लोगों के उदय से हजारों साल पहले से ही नस्लवाद और सामाजिक अन्याय मौजूद था। और नस्लवाद केवल श्वेत लोगों के कारण ही नहीं होता। उदाहरण के लिए, अफ़्रीकी और अन्य सभी संस्कृतियों का भी एक ऐसा इतिहास रहा है जिसमें समूह पहचानों ने एक-दूसरे का शोषण और उत्पीड़न किया है। अफ़्रीकी लोग आपस में ही दास प्रथा का पालन करते थे, जिसका श्वेत लोगों के साथ उनके संघर्ष से कोई संबंध नहीं था। अफ़्रीकी उत्पीड़क भी थे और उत्पीड़ित भी। अरबों में भी आपस में उत्पीड़क और उत्पीड़ित थे, और मुस्लिम राज्यों में भी दास प्रथा थी। यूरोप में ऐसे श्वेत लोग भी थे जो अन्य श्वेत लोगों के

गुलाम थे। प्राचीन यूनानियों के पास गुलाम थे। प्राचीन रोमनों के पास भी थे, और चीनियों के पास भी। और न ही सभी श्वेत लोग अनिवार्य रूप से शोषक या विशेषाधिकार प्राप्त हैं।

इसके अलावा, भारतीय अमेरिकी आलोचनात्मक नस्ल सिद्धांत के लिए एक दुविधा प्रस्तुत करते हैं: क्या वे उत्पीड़ित हैं क्योंकि उन्होंने यूरोपीय और मुस्लिम आक्रमणकारियों के संयुक्त शासन के तहत लंबे समय तक उपनिवेशीकरण झेला है? या क्या वे अमेरिका में अपनी शैक्षिक और आर्थिक सफलता के कारण विशेषाधिकार का आनंद ले रहे हैं? स्पष्ट रूप से, आलोचनात्मक नस्ल सिद्धांत का आधार बहुत सरल है क्योंकि इसने मार्क्सवाद से उत्पीड़क/उत्पीड़ित का द्विआधारी दृष्टिकोण अपनाया है। यही सवाल ईसाइयों के बारे में भी पूछा जा सकता है। ऐतिहासिक रूप से, ईसाई धर्म का सभी महाद्वीपों के मूल निवासियों पर अत्याचार का एक भयावह इतिहास रहा है। पोप ने चर्च द्वारा अतीत में किए गए अत्याचारों के लिए कई मूल निवासियों से माफी मांगी है। क्या क्रिटिकल रेस थ्योरी के सिद्धांतों के अनुसार ईसाई संरचनाओं (जो चर्च के संपूर्ण संस्थागत तंत्र के समान हैं) को भंग कर देना चाहिए? या क्या ईसाइयों को कुछ देशों में उन कानूनों का शिकार माना जाना चाहिए जो उनके धर्म प्रचार करने की क्षमता को सीमित करते हैं?

अंतर-विभागीय ढांचे के भीतर अल्पसंख्यक दर्जा हासिल करने की होड़ लगी हुई है। जिस तरह मुसलमान इस्लामोफोबिया को गैरकानूनी घोषित करवाना चाहते हैं, उसी तरह ईसाई नेता भी विविधता आंदोलन के तहत अपना अधिकार जताने के लिए आगे आए हैं। इस विचार के एक अच्छे प्रतिनिधि इंटेल के सीईओ पैट गेलसिंगर हैं। उनका कहना है कि कॉर्पोरेट जगत में खुले तौर पर अपनी ईसाई पहचान को प्रदर्शित करना स्वागत योग्य है। कार्यस्थल पर विविधता के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने इसका

समर्थन किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि इसमें उनके जैसे व्यक्ति का सम्मान करना भी शामिल होना चाहिए, जो एक खुले ईसाई हैं और अपने काम को अंततः 'ईश्वर का सम्मान' करने के रूप में वर्णित करते हैं। इस तरह कोई व्यक्ति 'कार्यस्थल पर अपना संपूर्ण व्यक्तित्व प्रस्तुत कर सकता है', यह कहते हुए: 'मैं एक ईसाई हूँ। अगर मैं कार्यस्थल पर अपने ईसाई विश्वास को व्यक्त नहीं कर सकता, तो वह एक विविध कार्यस्थल नहीं है।' हिंदू समुदाय ने अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में इस तरह से अपनी पहचान नहीं बनाई है।

क्वीर सिद्धांत

हालांकि क्वीर थ्योरी की शुरुआत LGBTQ+ समुदाय में अलग से हुई थी, लेकिन यह क्रिटिकल रेस थ्योरी के साथ तेजी से जुड़ गई है क्योंकि दोनों ही उत्पीड़ित माने जाने वाले लोगों से संबंधित हैं। इन दोनों को मिलाकर एक व्यापक सिद्धांत बनाना इसे और भी अधिक शक्तिशाली बनाता है।

सभी श्रेणियों को समाप्त करना

क्वीर थ्योरी को अक्सर यौनिकता तक ही सीमित समझ लिया जाता है। हालांकि, क्वीर थ्योरी के प्रवर्तकों ने इसे कहीं अधिक गहरा अर्थ दिया। उनके अनुसार, क्वीर का अर्थ है वह जो सभी श्रेणियों से परे हो। इसका प्रयोग मुख्य रूप से लिंग, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, विषमलैंगिकता, समलैंगिकता आदि की प्रचलित परिभाषाओं को चुनौती देने के लिए किया जाता है। लेकिन व्यापक रूप से, क्वीर एक ऐसा विश्वदृष्टिकोण है जो सभी श्रेणियों को चुनौती देता है क्योंकि श्रेणियां द्वंद्वों, या विपरीत युग्मों पर आधारित होती हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि वेदांत में भी श्रेणियों और विपरीत युग्मों का ऐसा ही विखंडन मिलता है, और बौद्ध विचारक नागार्जुन के बौद्ध

धर्म संबंधी कार्यों में भी यही बात झलकती है।
क्वीर थ्योरी, द्विआधारी श्रेणियों की आलोचना को सत्ता के एक सामाजिक सिद्धांत में बदल देती है। यह कहती है कि स्थिर परिभाषाएँ और श्रेणियाँ दमनकारी होती हैं क्योंकि इन्हें बनाने वाले ही प्रभुत्वशाली वर्ग थे। भाषा सहित सभी मानवीय उत्पाद सामाजिक संरचनाएँ हैं जिनमें पूर्वाग्रह और दमन अंतर्निहित होते हैं। दमन इन श्रेणियों के इतिहास और उपयोग में अंतर्निहित है, भले ही यह सतह के नीचे छिपा रहे। और इस तथ्य को पहचानना ही आपको एक क्वीर कार्यकर्ता बनाता है।
क्वीर सिद्धांत सीधे तौर पर उत्तरआधुनिकतावाद से उत्पन्न हुआ है और इसलिए जीव विज्ञान पर आधारित किसी भी वस्तुनिष्ठ लिंग या यौन श्रेणियों के प्रति घोर संशयवादी है। क्वीरवादी पुरुष और स्त्री की श्रेणियों के साथ-साथ सीधे, समलैंगिक, समलैंगिक महिला आदि होने की श्रेणियों को भी अस्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि किसी व्यक्ति का शारीरिक रूप से पुरुष या स्त्री होना अपरिहार्य है, लिंग परिवर्तनशील है और किसी व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक यौन झुकाव सामाजिक रूप से निर्मित होता है। जिसे हम सामान्य और स्वाभाविक मानते हैं, वह भ्रामक है; प्रमुख संस्कृति ने हमें इन श्रेणियों को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार करने के लिए मस्तिष्क में घोल दिया है। हमने उत्पीड़न की श्रेणियों को आत्मसात कर लिया है और उन्हें स्वाभाविक मान लिया है। इसलिए, ऐसी सभी श्रेणियों को समाप्त कर देना चाहिए।
क्वीर थ्योरी का कहना है कि पुरुष-महिला, मर्दाना-स्त्री और विषमलिंगी-समलैंगिक जैसी श्रेणियां उत्पीड़क की सेवा करती हैं, इसलिए जब हम इनका उपयोग करते हैं तो हम भी उत्पीड़न में भागीदार होते हैं। यह सिद्धांत चाहता है कि हम इन द्विआधारी श्रेणियों को हटा दें और सभी यौन सीमाओं को तरल और लचीला मानें। इसका मानना है कि कोई व्यक्ति

एक ही समय में मर्दाना और स्त्री, विषमलिंगी और समलैंगिक आदि हो सकता है। और वास्तव में, ऐसी अनगिनत श्रेणियां हैं जो परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली चीजों को आपस में मिलाती हैं। आइए इस पर गहराई से विचार करें।

यह सिद्धांत 1980 के दशक के मध्य में उभरा, और इसके तीन प्रमुख संस्थापक गेल रुबिन, जूडिथ बटलर और ईव कोसोफ़स्की सेडविक थे। रुबिन ने 1984 में 'थिंकिंग सेक्स: नोट्स फॉर ए रेडिकल थ्योरी ऑफ सेक्सुअल पॉलिटिक्स' नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने यौन या कामुकता के किसी भी जैविक आधार पर घोर संदेह व्यक्त किया। वह यौन अनिवार्यतावाद को खारिज करती हैं, जिसे वह 'यह विचार कि यौन संबंध एक प्राकृतिक शक्ति है जो सामाजिक जीवन से पहले मौजूद होती है' के रूप में परिभाषित करती हैं। उनका कहना है: 'जब तक कामुकता को मुख्य रूप से एक जैविक घटना या व्यक्तिगत मनोविज्ञान के एक पहलू के रूप में समझा जाता है, तब तक यह राजनीतिक विश्लेषण से परे है।'

इन सिद्धांतकारों में जूडिथ बटलर सबसे प्रभावशाली हैं। वे फ्रांसीसी नारीवाद से प्रभावित हैं और लिंग को पूरी तरह से सामाजिक रूप से निर्मित मानती हैं। वे 'लिंग प्रदर्शनशीलता' शब्द का प्रयोग करती हैं, जिसका अर्थ है कि लोगों को रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का निर्वाह करना सिखाया जाता है। अपनी प्रमुख पुस्तक 'बॉडीज़ दैट मैटर: ऑन द डिस्करसिव लिमिट्स ऑफ़ सेक्स' में वे लिंग प्रदर्शनशीलता को 'विमर्श की पुनरावृत्ति शक्ति के रूप में परिभाषित करती हैं जो उस घटना को उत्पन्न करती है जिसे वह नियंत्रित और सीमित करती है'। दूसरे शब्दों में, जिस तरह से हम व्यवहार करते हैं, बात करते हैं और एक-दूसरे से व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, वह समाज द्वारा परिभाषित इन लिंग

भूमिकाओं का प्रदर्शन है।
बटलर अपनी दूसरी पुस्तक, जेंडर ट्रबल: फेमिनिज्म एंड द सबवर्जन ऑफ आइडेंटिटी में, इस बात को और स्पष्ट करती हैं कि लैंगिक भूमिकाएँ सामाजिकरण के माध्यम से जानबूझकर या अनजाने में सिखाई और सीखी जाती हैं, कार्यों, व्यवहार, तौर-तरीकों, अपेक्षाओं आदि के एक समूह के रूप में। अंततः, लोग इन भूमिकाओं को स्वतः ही निभाने लगते हैं। ये भूमिकाएँ आंतरिक रूप से स्थापित हो जाती हैं और लोगों को इस बात का एहसास भी नहीं होता कि वे इन्हें निभा रहे हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे मंच पर निभाई गई भूमिकाएँ अभिनेता की आत्म-छवि बन जाती हैं।
उनका मानना है कि लोग जन्म से ही स्वयं को पुरुष या स्त्री, सीधे या समलैंगिक के रूप में नहीं जानते, इसलिए ऐसी कोई जन्मजात या प्राकृतिक विशेषताएँ नहीं होतीं; ये बाद में समाज द्वारा निर्मित होती हैं। इन भूमिकाओं को निभाकर लोग यह भ्रम पैदा करते हैं कि ये भूमिकाएँ वास्तविक और स्वाभाविक रूप से सार्थक हैं। यही उनका उत्पीड़न है, और इसके लिए समाज ही जिम्मेदार है।
परिणामस्वरूप, ऐसे द्विआधारी शब्दों का प्रयोग करने वाला हर व्यक्ति उत्पीड़क है क्योंकि वह इन अवधारणाओं में निहित संरचनाओं को सुदृढ़ कर रहा है। बटलर का कहना है कि लैंगिक पहचान की अवधारणा एक 'विचारधारा' है जिसे उजागर और ध्वस्त किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि समस्या लैंगिक श्रेणियों और संबंधों का वस्तुकरण है, और अनजाने में लोग इसे दोहराते रहते हैं और इस प्रकार उत्पीड़न के इस रूप को मजबूत करते हैं।
ईव कोसोफ़स्की सेडविक क्वीर थ्योरी की तीसरी अग्रणी हैं। वे इन श्रेणियों को तोड़कर उन्हें असंगत और अंततः अराजक बनाने की वकालत

करती हैं। सेडविक की पुस्तक, 'एपिस्टेमोलॉजी ऑफ़ द क्लोसेट', में उन्होंने फ्रांसीसी दार्शनिक मिशेल फ़ूको के उत्तर-आधुनिकतावाद के दृष्टिकोण को लिया और उसे कामुकता पर लागू किया। उनके अनुसार, यौन द्वंद्व सभी सामाजिक द्वंद्वों की नींव हैं। अन्य अग्रदूतों की तरह, वे समलैंगिक, समलैंगिक महिला, उभयलिंगी आदि जैसी स्थिर श्रेणियों के विरुद्ध हैं।

इन तीनों प्रश्नवादियों के अनुसार, इनमें से कोई भी श्रेणी किसी व्यक्ति में स्थायी नहीं होती, बल्कि एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ में निरंतर बदलती रहती है। इसलिए, ऐसी श्रेणियों को स्थिर मानकर उनका उपयोग करना अपने आप में दमनकारी है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि क्वीर थ्योरी से पहले, उदार नारीवाद और LGBTQ+ सक्रियता ने यौन श्रेणियों को स्पष्ट सीमाओं वाली सुस्पष्ट संस्थाओं के रूप में माना था; उनका आंदोलन इन श्रेणियों के लोगों के प्रति पूर्वाग्रहों को बदलने के लिए था। लेकिन क्वीर थ्योरी इन श्रेणियों की वैधता का विरोध करती है और मानती है कि इन्हें समानता प्रदान करने से ये सामान्य हो जाती हैं और इनका दमनकारी स्वरूप बढ़ जाता है।

प्रश्नवादी विचारधारा के समर्थकों की एक अन्य रणनीति श्रेणियों को भ्रामक, अव्यवस्थित, अतार्किक और अतार्किक बनाकर उन्हें अप्रासंगिक बनाना है। जब ये सिद्धांतकार किसी विषय पर प्रश्न उठाने की बात करते हैं, तो उनका तात्पर्य उस विषय के भीतर सभी द्विआधारी श्रेणियों की सीमाओं को धुंधला करना होता है।

हम ऊपर प्रस्तुत क्वीर सिद्धांतकारों के विचारों से सहमत हैं। हालांकि, बात यहीं खत्म नहीं होती। क्वीर सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि उनके खिलाफ तर्क देना असंभव है क्योंकि वे वैज्ञानिक और

तर्कसंगत श्रेणियों का उपयोग करने वाले किसी भी विरोधी को सिरे से खारिज कर देते हैं। इसलिए, उनका प्रवचन किसी चर्च के हठधर्मिता जैसा है, और साक्ष्य-आधारित तर्क का उपयोग करके उनकी थीसिस को चुनौती देना ईशनिंदा है। हम असहमत हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते हैं। किसी भी चर्चा को अंतिम घोषित करके आगे के विकास के लिए बंद नहीं किया जाना चाहिए।

ऐसे सिद्धांत प्रकृति को वस्तुनिष्ठ रूप से समझने के विज्ञान के दावे को खारिज करते हैं, क्योंकि प्रकृति के बारे में सभी ज्ञान मानव सामाजिक निर्माण का परिणाम है। प्रश्नवादियों ने बचपन की मासूमियत की धारणा को भी ध्वस्त कर दिया है, इसे माता-पिता द्वारा अपने श्वेत वर्चस्व के पूर्वाग्रहों को कायम रखने के लिए किया गया एक सामाजिक निर्माण बताया है।

इस सिद्धांत को उलट कर देखें तो क्या हम कह सकते हैं कि पीड़ित की पहचान भी सामाजिक रूप से निर्मित होती है? यदि बचपन की मासूमियत जैसी कोई चीज नहीं है, तो क्या हम यह भी कह सकते हैं कि पीड़ित जैसी कोई चीज भी नहीं है? यह बचपन से निभाई जाने वाली एक भूमिका है जिसे समाज ने मजबूत किया है। हम इस प्रश्न के उत्तर पर कोई पक्ष नहीं लेते, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे प्रश्नों पर खुलकर चर्चा हो।

वेदांत के साथ तुलना

क्वीर थ्योरी की तुलना वेदांत और बौद्ध धर्म से करना रोचक है, क्योंकि दोनों ही धर्म भाषाई श्रेणियों को हमारी संज्ञानात्मक दुनिया के सापेक्ष मानते हैं। श्रेणियों को अहंकार की संज्ञानात्मक प्रणाली द्वारा निर्मित माना जाता है। जिस सापेक्षिक क्षेत्र में हम रहते हैं, वह लौकिक/अनुभवजन्य क्षेत्र है। परमार्थिक या निरपेक्ष वास्तविकता सभी श्रेणियों से परे है। इस

अर्थ में, क्वीर थ्योरी जो दावा कर रही है, उसे भारतीय चिंतन में बहुत पहले ही विस्तार से समझाया जा चुका है।

एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि वेदांत में, अभिधारणा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर होती है, जबकि क्वीर थ्योरी में यह सामाजिक कारणों से उत्पन्न होती है। एक अन्य अंतर यह है कि वेदांत व्यक्ति को अहंकार से ऊपर उठकर श्रेणियों से परे जाने के लिए कहता है, जबकि क्वीर थ्योरी एक सामाजिक समूह के अहंकार को दूसरे समूह के अहंकार से लड़ने के लिए प्रेरित करती है। क्वीर सिद्धांत के अनुयायी पहचान के विभिन्न समूहों के बीच टकराव चाहते हैं। इसलिए, क्वीर सिद्धांत के अनुयायियों का वांछित परिणाम अहंकार से परे नहीं, बल्कि अहंकार के भीतर ही होता है।

दूसरा अंतर यह है कि वेदांत के अनुसार, अहंकार की वैचारिक श्रेणियों से ऊपर उठने पर व्यक्ति अद्वैत चेतना की अवस्था का अनुभव करता है, जबकि क्वीर थ्योरी किसी उच्चतर चेतना अवस्था के अस्तित्व पर आधारित नहीं है। क्वीर थ्योरी सामाजिक उत्पीड़न से मुक्ति तो चाहती है, लेकिन व्यक्ति के अहंकार से मुक्ति दिलाने के लिए कुछ नहीं करती। वास्तव में, क्वीर थ्योरी, क्रिटिकल रेस थ्योरी के अन्य सिद्धांतों की तरह, पीड़ित की पहचान के अहंकार को बढ़ावा देती है और उसके क्रोध को दूसरों के विरुद्ध निर्देशित करती है।

क्वीर थ्योरी, क्रिटिकल रेस थ्योरी के साथ इस मान्यता में जुड़ी हुई है कि भाषा का स्वरूप पश्चिमी उपनिवेशवाद के इतिहास से प्रभावित है, जिससे सभी भाषाई श्रेणियां दमनकारी बन जाती हैं। यह धारणा बनाई जा रही है कि सभी भाषाओं को उपनिवेशवादियों ने आकार दिया है। यह बात अंग्रेजी भाषा के संदर्भ में सच हो सकती है, लेकिन संस्कृत श्रेणियों में लोगों पर इस तरह की शक्ति का प्रदर्शन नहीं होता। वास्तव में, संस्कृत मुक्तिदायक है, दमनकारी नहीं। एक ही तर्क सभी भाषाओं और उनकी

भाषाई संरचनाओं पर लागू नहीं किया जा सकता। संस्कृत भाषी लोग विश्व विजेता या उत्पीड़क नहीं थे। यह एक गंभीर मुद्दा है। क्रिटिकल रेस थ्योरी का उपयोग संस्कृत को ब्राह्मणों द्वारा प्रयुक्त दमनकारी भाषा के रूप में आरोपित करने के लिए किया जा रहा है, और यह दावा ब्राह्मणों को भारत के श्वेत और दलितों को भारत के अश्वेत के रूप में वर्गीकृत करके किया जा रहा है।

दिलचस्प बात यह है कि क्वीर थ्योरी के समर्थन में, वैदिक प्रणाली में ईश्वर को अक्सर आधा पुरुष और आधा स्त्री के रूप में दर्शाया गया है, और देवत्व की समझ में भी पुरुषत्व और स्त्रीत्व की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। इसलिए, क्वीर सिद्धांत के समर्थकों की बात को भारतीय परंपरा में पहले से ही सम्मान दिया जा चुका है।

लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि भारतीय परंपरा ने लौकिक और इन श्रेणियों के व्यावहारिक उपयोग को अस्वीकार नहीं किया। यह केवल इतना कहती है कि कोई भी श्रेणी अंतिम और निरपेक्ष नहीं है। फिर भी, हमें सांसारिक/व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए इन्हें बनाए रखना चाहिए, साथ ही यह भी जानना चाहिए कि परमार्थिक क्षेत्र में ये श्रेणियां पार हो जाती हैं।

सामने दिया गया आरेख दर्शाता है कि कैसे मार्क्सवाद, उत्तरआधुनिकतावाद और उत्तरऔपनिवेशिक सिद्धांत (जो मुख्यतः अमेरिका के बाहर के समाजों के लिए विकसित किए गए थे) को अमेरिकी समाज के लिए आलोचनात्मक नस्ल सिद्धांत के निर्माण में शामिल किया गया है। दूसरे शब्दों में, अमेरिका में मौजूद अश्वेत/श्वेत नस्लवाद की वास्तविकताओं को इन पूर्व सिद्धांतों के साथ मिलाकर नवीनतम सामाजिक सिद्धांत का निर्माण किया गया है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं।

वोकवाद का चर्च

उदार कलाएँ हठधर्मी बन जाती हैं

उदार कला शिक्षा का घोषित लक्ष्य छात्रों को जटिल और विविध विचारों को समझने, अमूर्त चिंतन में संलग्न होने और खुले मन से विरोधी मतों पर विचार करने में सक्षम बनाना है। शिक्षक को छात्रों को अनेक दृष्टिकोणों से सैद्धांतिक आधार प्रदान करना चाहिए और उन्हें आपस में और शिक्षकों के साथ जुड़ने तथा पारस्परिक सम्मान के साथ विरोधियों से बहस करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसी शिक्षा उन्हें मान्यताओं, धारणाओं और परंपराओं को चुनौती देने में सक्षम बनाएगी।

व्यवहार में, उदार शिक्षा बिल्कुल विपरीत हो गई है। छात्रों को अब स्वयं सोचने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें शिक्षक की विशिष्ट विचारधारा और सामाजिक न्याय की नैतिकता सिखाई जाती है। शैक्षणिक संस्थान खुले चिंतन और वैकल्पिक दृष्टिकोणों के लिए आश्रय स्थल नहीं रह गए हैं। रूढ़िवादी विचारक एलन ब्लूम ने अपनी प्रभावशाली पुस्तक, "द क्लोजिंग ऑफ द अमेरिकन माइंड: हाउ हायर एजुकेशन हैज़ फेल्ड डेमोक्रेसी एंड इम्पावरिश्ड द सोल्स ऑफ टुडेज़ स्टूडेंट्स" में अमेरिकी विश्वविद्यालयों पर सिद्धांत के रूप में हठधर्मिता फैलाने और विद्वत्ता के वेश में शिक्षा का प्रचार करने का आरोप लगाते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा था।

विडंबना यह है कि समाज को सत्ता संरचनाओं से मुक्त करने के नाम पर, शिक्षाविदों ने स्वयं एक विशाल सत्ता संरचना का निर्माण कर लिया है। चूंकि पुरानी संरचनाओं को बाधा माना जाता है, इसलिए उन्हें ध्वस्त किया

जाना है। इसमें न केवल धर्म, राष्ट्र-राज्य और पारंपरिक मूल्यों जैसी संरचनाओं को समाप्त करना शामिल है, बल्कि वस्तुनिष्ठता, तर्कसंगतता और योग्यता-आधारित व्यवस्था को भी समाप्त करना शामिल है।

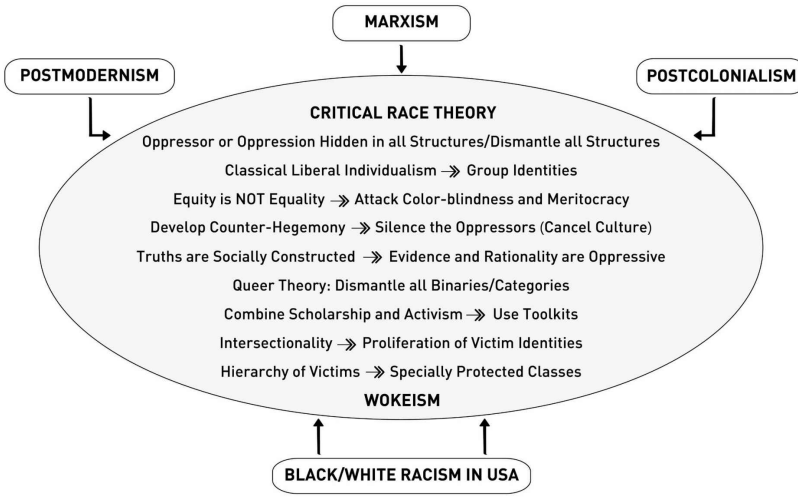

वास्तविक विज्ञान परिकल्पनाओं को तैयार करने और उन्हें अनुभवजन्य परीक्षण, वाद-विवाद, खंडन और मिथ्याकरण के अधीन करने पर आधारित है। हालांकि, सामाजिक विज्ञान अक्सर तथ्यों और नैतिक मूल्यों के बीच की सीमाओं को धुंधला कर देते हैं। समाज में सामाजिक विज्ञानों की शक्ति कठोर विज्ञानों की तरह सिद्धांत गढ़ने की उनकी क्षमता से नहीं, बल्कि समाजों को कमजोर करने की उनकी क्षमता से आती है। इसके अलावा, उदार कलाओं के वैश्वीकरण का उपनिवेशीकरण पर प्रभाव पड़ा है। सही मायने में उदार होने के लिए, प्रत्येक समाज को अपनी सांस्कृतिक नींव पर आधारित अपनी विषयवस्तु विकसित करनी चाहिए और वैश्विक समरूपता का विरोध करना चाहिए। लेकिन अमेरिकी विद्वानों, संस्थानों, सिद्धांतों और वित्तपोषण स्रोतों के प्रभुत्व ने स्थानीय संस्कृतियों को कमजोर कर दिया है। अकादमिक रैंकिंग और वैश्विक मूल्यांकन

सूचकांकों की प्रणाली भी पश्चिम द्वारा नियंत्रित है और स्थानीय उत्कृष्टता को कमज़ोर करती है।
हम सामाजिक विज्ञान, मानविकी और उदार कला शब्दों का परस्पर उपयोग करते हैं क्योंकि इन विषयों के बीच अंतर-अनुशासनात्मक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक आंदोलन चल रहा है।

लोकप्रिय वोकवाद
'वोके' शब्द अश्वेत संस्कृति में पहले से ही प्रचलित था, लेकिन एक श्वेत पुलिसकर्मी द्वारा जॉर्ज फ्लॉयड (एक अश्वेत व्यक्ति) की हत्या के बाद यह मुख्यधारा में आ गया। 'वोके होना' एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ है क्रिटिकल रेस थ्योरी के ढांचे के अनुसार सामाजिक अन्याय के प्रति जागरूक होना। इसका मतलब है समाज को नियंत्रित करने वाली सभी अदृश्य शक्ति संरचनाओं से लड़ना। हम 'वोकेवाद' और 'क्रिटिकल रेस थ्योरी' शब्दों का परस्पर उपयोग करेंगे; क्रिटिकल रेस थ्योरी अधिक औपचारिक अकादमिक प्रणाली है, जबकि वोकेवाद इसका लोकप्रिय, अनौपचारिक रूप है।
हालांकि हम उत्पीड़ितों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और उनकी मदद करने वाले आंदोलनों का समर्थन करते हैं, फिर भी हम क्रिटिकल रेस थ्योरी द्वारा सुझाए गए कई तरीकों से असहमत हैं। हमारा मानना है कि कार्यकर्ता नेता सताए गए निर्दोष स्वतंत्र विचारक नहीं हैं, बल्कि सेंसरशिप, कैंसिल कल्चर और अपने नवस्थापित धर्म के आक्रामक प्रचार के समर्थक हैं। उदाहरण के लिए, हम वोकिज़्म के इस आधार से असहमत हैं कि तर्कसंगतता एक समस्या है क्योंकि चतुर, उच्च-वर्गीय अभिजात वर्ग इसका शोषण के हथियार के रूप में उपयोग कर रहा है। यह आंदोलन रचनात्मक जुड़ाव में रुचि नहीं रखता। यह अभिव्यक्ति की

स्वतंत्रता, बहस, चर्चा, चुनौती, साक्ष्य आदि के लिए खुला नहीं है। इस अध्याय के अगले भाग में इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

वोकिज़्म के सिद्धांतों को एक नए प्रकार के चर्च से संबंधित हठधर्मिता के रूप में देखना तर्कसंगत है। वोकिज़्म के कट्टरपंथी वे निरंकुश शासक हैं जो यह तय करते हैं कि कौन वंचित है और किसे विशेष व्यवहार का हकदार माना जाए। यह एक शक्तिशाली नई संस्था है जिसके अपने ही ईशनिंदा के विचार हैं। असहमति जताने वालों पर बेरहमी से हमला किया जाता है। असहमति की कोई गुंजाइश नहीं है।

'वोके' विचारधारा समूहवाद और कबीलेवाद का एक रूप है, जो समाज को 'हम/वे' के संदर्भ में देखती है और अपने विरोधियों के खिलाफ एक पूर्ण युद्ध छेड़ देती है।

नीचे दी गई तालिका इस आंदोलन और कुछ चर्चों की सैद्धांतिक संरचना के बीच कुछ समानताओं को दर्शाती है।

Church of Christianity	Church of Wokeism
• Adam and Eve's Original Sin	• White Ancestors' Construction of Oppressive Structures
• Sin Built into the Very Act of Reproduction	• Racism Built into all Structures Including Language, Knowledge, Institutions
• Everyone is a Born Sinner	• Every White Person (Mapped also to Brahmins) is a Born Oppressor
• Bible as Dogma	• Critical Race Theory as Dogma
• Evidence that Contradicts is the Work of the Devil	• Evidence that Contradicts is Caused by Racist Structures
• Church Appoints High Priests	• Self-appointed Authorities with Absolute Power
• No Free Speech. Dissenters are Heretics	• No Free Speech. Dissenters are Racists
• Infidels can only be Saved by Confession	• Oppressors by Birth can only be Saved by Confession of Guilt and Unconditional Submission

विवेक रामास्वामी, जिन्होंने 'वोके इंक: हाउ लिबरल एक्टिविस्ट्स आर सीजिंग कंट्रोल ऑफ कॉर्पोरेट अमेरिका' नामक पुस्तक लिखी है, ने वोकवाद का अध्ययन किया है। एक संगठित धर्म से उनकी तुलना रोचक है:

विविधता एक कला का शब्द बन गई है, एक प्रतीक बन गई है, इतनी शक्तिशाली कि यह प्रतीक अब उस चीज़ से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है जिसका प्रतिनिधित्व करने के लिए इसे बनाया गया था। जागरूकता सच्ची विविधता, विचारों की विविधता का बलिदान करती है, ताकि नस्ल और लिंग जैसे सतही विविधता के प्रतीक फल-फूल सकें। कहानी में ईसा मसीह की तरह, विचारों की सच्ची विविधता अब विविधता के चर्च के लिए खतरा बन गई है।

जागरूकता का कहना है कि श्वेत वर्चस्ववादियों द्वारा निर्मित संरचनाओं में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति जन्मजात नस्लवादी बन जाता है, ठीक उसी तरह जैसे चर्च हर किसी से यह स्वीकार करने की मांग करता है कि वे जन्मजात पापी हैं:

जागरूकता नई रूढ़िवादिता है, नया धर्म है, जो धर्मनिरपेक्ष आवरण में खुद को छुपाता है। चूंकि इसके अनुयायी किसी अलौकिक शक्ति के बजाय पहचान की धर्मनिरपेक्ष शक्तियों की पूजा करते हैं, इसलिए विविधता के चर्च के लिए कार्यस्थल में घुसपैठ करना बहुत आसान हो जाता है।

एक अन्य आलोचक, जोशुआ मिशेल, इस बात को विस्तार से बताते हैं:

अमेरिका ने अपना धर्म नहीं खोया है। ... उसने अपने धर्म को राजनीति के क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया है। ... पहचान की राजनीति, राजनीति को रूपांतरित करती है। यह राजनीति को बलि चढ़ाने के धार्मिक स्थल में बदल देती है। ... परमेश्वर के निर्दोष मेमने के बलिदान के बिना ईसाई धर्म का अस्तित्व नहीं होता। मसीह, बलि का बकरा, अशुद्धों को शुद्ध

करता है—संसार के पापों को अपने ऊपर लेकर। बलि के बकरे के शुद्धिकरण से, जिनके लिए वह बलि का चढ़ावा है, वे स्वयं को शुद्ध करते हैं। पहचान की राजनीति, व्यक्तियों के बजाय समूहों के लिए इस शुद्धिकरण का एक राजनीतिक संस्करण है। पहचान की राजनीति के संदर्भ में बलि का बकरा श्वेत विषमलैंगिक पुरुष है, जो यदि शुद्ध हो जाए, तो माना जाता है कि वह अन्य सभी समुदायों की पवित्रता को बहाल और पुष्ट करेगा। वह अपराधी है; अन्य सभी—महिलाएं, अश्वेत, हिस्पैनिक, एलजीबीटीक्यू—के पापों को बलि के बकरे द्वारा ढक दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे बलि का बकरा बने मसीह ने आदम की सभी संतानों के पापों को ढक दिया था।

पहचान की राजनीति में लिप्त लोग अपने भीतर से बाहर की अशुद्धता को दूर करके मुक्ति की तलाश करते हैं। श्वेत विषमलैंगिक पुरुष उनकी नज़र में पहला अशुद्ध अपराधी है; लेकिन पहचान की राजनीति में लिप्त लोगों की निर्दोषता एक अपराधी के बलिदान से ही खरीदी जा सकती है, इसलिए एक बार जब वह अपराधी शुद्ध हो जाता है, तो दूसरा अपराधी ढूंढना पड़ता है। [28]

जिस प्रकार आदम और हव्वा ने वह मूल पाप किया जिसने तब से लेकर आज तक सभी को प्रभावित किया है, उसी प्रकार व्यवस्थागत नस्लवाद राष्ट्र निर्माण में शामिल संस्थापकों और अन्य सभी लोगों का मूल पाप है। व्यक्तिगत योग्यता संरचनात्मक मूल पाप के आगे फीकी पड़ जाती है। यह विश्वासों की एक ऐसी प्रणाली है जो एक अविभाज्य इकाई के रूप में खड़ी है और व्यक्ति के अस्तित्व के सभी पहलुओं को छूती है। आपको सबूतों पर विचार करने और अपनी पसंद के अनुसार 'वोकेनेस' के कुछ हिस्सों को चुनने की अनुमति नहीं है। ... ईसाई धर्म और इस्लाम की तरह, 'वोकेनेस' एक ऐसी विश्वास प्रणाली प्रदान करने का दावा करती है

जो हर चीज की व्याख्या करती है, और यह अपने अनुयायियों को अपनी पसंद के अनुसार चुनने की अनुमति नहीं देती है। ... 'वोकेनेस' आदेश देती है, सुझाव नहीं। ... आपको थोड़ा 'वोके' होने की अनुमति नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे ईसाई अपने पांच पसंदीदा आदेशों का पालन नहीं कर सकते। [...] यह वह संरचना है जिसका उपयोग वे ब्रह्मांड को समझने के लिए करते हैं। जहां एक 'वोके' न होने वाला व्यक्ति सामान्य अंतःक्रियाओं को देखता है, वहीं 'वोकेनेस' का अनुयायी सूक्ष्म आक्रामकता देखता है। जैसे एक ईसाई सृष्टि में ईश्वर का हाथ देखता है, वैसे ही 'वोके' व्यक्ति हर जगह पहचान-आधारित शक्ति संबंधों का मार्गदर्शक हाथ देखता है।
संगठित ईसाई धर्म से एक और समानता जो हमें मिलती है, वह है पीड़ित होने की भावना का उपयोग। वोकिज़्म ने इसे मार्क्सवाद के फ्रैंकफर्ट स्कूल से विरासत में लिया, जिसके नेताओं ने 'अधीनस्थ' नामक एक नए वर्ग को 'उत्पीड़ित' के रूप में परिभाषित किया। यह एक नए प्रकार का सर्वहारा वर्ग था जिसे सांस्कृतिक शक्ति से वंचित लोगों के रूप में परिभाषित किया गया था। इस सांस्कृतिक वर्चस्व के कई नाम और रूप हैं: नारीवादी इसे पितृसत्ता कहते हैं; यौन अल्पसंख्यक इसे विषमलैंगिकता कहते हैं, और नस्लीय अल्पसंख्यक इसे श्वेत वर्चस्व कहते हैं।
शोषित समुदाय के रूप में हकदार होने का मुख्य मानदंड पीड़ा है। सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखने का आदर्श तरीका पीड़ित बनना या पीड़ित का प्रतिनिधित्व करना है। इसे निम्नलिखित रूप से समझाया गया है:
पीड़ित की राजनीति... एक तरह से पश्चिमी दुनिया में ईसाई विचारों और रीति-रिवाजों का अवशेष है, जहाँ पारंपरिक धार्मिक शिक्षा या प्रशिक्षण का अभाव है। पीड़ित राजनीति का आधार दुख सहने वाले सेवक के प्रति भक्ति का दर्पण प्रतिबिंब है। ईसाई धर्म की तरह ही सामाजिक न्याय की

राजनीति में भी: आदिम पीड़ित के घाव मानव स्वभाव और समाज की टूटी हुई स्थिति की गवाही देते हैं। ईसाइयों के लिए, क्रूस एक प्रकार का सिंहासन है, और कांटों का ताज अधिकार का प्रतीक बन जाता है। ईसाई धर्म का विरोधाभास यह है कि प्रभु राजा के रूप में शासन करते हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं को पीड़ित के रूप में अर्पित किया।
इस पीड़ित को सामाजिक व्यवस्था के केंद्र में रखकर, चाहे अनुष्ठान के माध्यम से हो या उपदेश के माध्यम से, समस्त मानवता के उद्धार की शुरुआत होती है। श्रद्धालु अपने पापों के उन प्रभावों को स्वीकार करते हैं जिनसे पीड़ित का भाग्य तय हुआ। इस अनुष्ठान का उद्देश्य इसे देखने वालों को नैतिक शिक्षा देना और प्रेरित करना है, तथा उन्हें उद्धार के प्रयास में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह अपने अनुयायियों को एक ऐसी दानव विद्या भी प्रदान कर सकता है जो दुनिया को अदृश्य उत्पीड़कों और यातना देने वालों से भर देती है, जिससे वे अति संवेदनशील और भयभीत हो जाते हैं।
राजनीतिक शब्दावली इस बारे में है कि कौन संरक्षित वर्ग होने का हकदार है और योग्यता की परवाह किए बिना उन्हें क्या प्राप्त करने का अधिकार है।
कुल मिलाकर, ग्राम्स्की से लेकर मारक्यूज़ तक मार्क्सवादी प्रभाव ने वोक आंदोलन में असहमति के प्रति असहिष्णुता को बढ़ावा दिया है। इससे मध्ययुगीन चर्च द्वारा विधर्मियों पर किए गए अत्याचारों की याद आती है। जो व्यक्ति बौद्धिक चिंतन की तलाश में इन वातावरणों में प्रवेश करता है, उसे चुपचाप बैठने और सुनने के लिए कहा जाता है। यह चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान सुसमाचार पढ़े जाने के समय की चुप्पी के समान है। यदि आप तर्कसंगत प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप पर विधर्म का आरोप लगाया जाता है। पहचान की राजनीति की मांग है कि उत्पीड़क पापी होने के नाते

प्रायश्चित करें, अन्यथा उन्हें अपने पूर्वजों के पापों के लिए अनंत काल तक दंडित किया जाना चाहिए। विडंबना यह है कि किसी व्यक्ति को उत्पीड़क मानने का यह जन्म-आधारित निर्धारण है।
जब कुछ शोषित लोग क्रिटिकल रेस थ्योरी क्रांति में शामिल न होने का फैसला करते हैं, तो उन पर अपने उत्पीड़कों की विचारधाराओं को अपनाने का आरोप लगाया जाता है और इसलिए उन्हें कठोर पुनर्शिक्षा शिविरों में भेजने की आवश्यकता बताई जाती है। यह चर्च द्वारा शैतान के प्रभाव में होने के आरोपी लोगों से बुरी आत्माओं को निकालने के लिए जांच आयोग चलाने की इच्छा के समान है।

परेशान करने वाली विशेषताएं
यद्यपि हम व्यवस्थागत नस्लवाद की समस्याओं और उन्हें समाप्त करने के लिए उभर रहे आंदोलनों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, फिर भी इसके मुख्य सिद्धांतों का विश्लेषण करना और खुले मन से इस पर बहस करना महत्वपूर्ण है। यह खंड कुछ ऐसे मुद्दों को प्रस्तुत करता है जिन पर रचनात्मक बहसों में विचार-विमर्श नहीं किया गया है।

विज्ञान, तर्कसंगतता और योग्यतावाद का अस्वीकरण
यह नया आंदोलन विज्ञान और तर्कसंगतता को श्वेत-प्रभुत्व वाली संस्कृति की उपज मानता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एक प्रभाव मार्क्सवाद के फ्रैंकफर्ट स्कूल से था, जिसके दार्शनिकों ने कहा था कि 'एक सच्चा ज्ञानमीमांसा ज्ञान के प्रति आसक्ति को समाप्त करना चाहिए, जो कि नीत्शे के अनुसार, अमूर्त व्यवस्थापन की ओर ले जाता है।' उन्होंने वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक सत्यों को अस्वीकार कर दिया।

इसलिए सत्य का निर्माण राजनीतिक संघर्षों से होता है; एक समूह के अहंकार दूसरे समूह के अहंकार से लड़ते हैं। परिणाम उन्हीं के द्वारा तय किए जाते हैं जिनकी आवाज़ बुलंद होती है, जिनके पास अधिक शक्ति और हिंसा होती है, और जिनका संगठन बेहतर होता है।

तर्कसंगतता और योग्यता को नकारने का एक अन्य दृष्टिकोण शोध न्याय का सिद्धांत है। यह सिद्धांत कहता है कि विज्ञान, तर्क, अनुभववाद, वस्तुनिष्ठता, सार्वभौमिकता आदि सभी व्यक्तिगत भावनात्मक अनुभव और पारंपरिक कथाओं की तुलना में अतिरंजित हैं। समाजशास्त्री और लेखक एंड्रयू जोलिवेट ने शोध न्याय को एक ऐसे ढांचे के रूप में परिभाषित किया है जो 'सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और अनुभवात्मक सहित ज्ञान के विभिन्न रूपों को समान शक्ति और वैधता प्रदान करता है...'। यह सिद्धांत मांग करता है कि विज्ञान और वस्तुनिष्ठ तर्क को कम महत्व दिया जाए जबकि भावनाएं, व्यक्तिपरक अनुभव और व्यक्ति की व्यक्तिगत कथाएं प्राथमिकता प्राप्त करें।

इस विषय पर हम भारतीय मार्क्सवादी विद्वान मीरा नंदा से सहमत हैं, जो इस बात को स्वीकार नहीं करतीं कि विज्ञान और तर्क को केवल पश्चिमी अवधारणा मानकर उन पर हमला किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि ऐसा दृष्टिकोण भारत की उन परंपराओं के प्रति अन्यायपूर्ण है, जहाँ पश्चिमी ज्ञानोदय से बहुत पहले से ही विज्ञान और तर्क का मजबूत स्थान रहा है। नंदा कहती हैं, 'यदि हम वस्तुनिष्ठता की बुनियाद ही पश्चिम को सौंप देते हैं, तो क्या हम तर्कहीन भावनात्मक कथाओं की पुरानी रूढ़ियों की ओर वापस नहीं लौट रहे हैं?' उनके अनुसार, ऐसे सिद्धांत भारत को विज्ञान और तर्क का उपयोग करके प्रगति करने से रोकते हैं, क्योंकि इन्हें पश्चिम का क्षेत्र मान लिया गया है। उनका यह भी मानना है कि भारतीयों को तर्कहीन और अंधविश्वासी कहना अपमानजनक है।

तर्कहीनता की इस लहर के कारण STEM शिक्षा की भी आलोचना हो रही है। 'इंजीनियरिंग और सामाजिक न्याय: इंजीनियरों, प्रौद्योगिकी और समाज पर संश्लेषण व्याख्यान' नामक पुस्तक में यह सुझाव दिया गया है: 'सत्य को वस्तुनिष्ठ और निरपेक्ष मानने के दृष्टिकोण से परे जाना ही इंजीनियरिंग शिक्षा में सबसे मौलिक परिवर्तन है जिसकी हमें आवश्यकता है।' एक अन्य शोधपत्र में कहा गया है: 'मैं वस्तुओं, सत्यों और ज्ञान के विरुद्ध एक ऐसे आंदोलन का समर्थन करता हूँ जो मूलभूत सिद्धांतों द्वारा निर्देशित विश्व में रहने के तरीके की ओर अग्रसर हो।'

विज्ञान और तर्कसंगतता की वस्तुनिष्ठता को नकारने की एक समस्या यह है कि ऐसा समाज चीन जैसे उन देशों से पिछड़ जाएगा जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तत्पर हैं। साथ ही, इस तरह के तर्कहीन रवैये से समाज में आंतरिक विभाजन पैदा होगा, जिसके परिणामस्वरूप लोग चीन जैसी विदेशी शक्ति के अधीन हो जाएंगे।

क्रिटिकल रेस थ्योरी की प्रमुख समर्थकों में से एक, रॉबिन डिएन्जेलो का मानना है कि वैज्ञानिक पद्धति, सटीकता और कड़ी मेहनत, ये सभी 'श्वेतता की पहचान' हैं। उनका मानना है कि योग्यतावाद श्वेत विशेषाधिकार को सही ठहराने के लिए गढ़ा गया एक श्वेत मिथक है। उनका मानना है कि नीतियों का मूल्यांकन तर्कसंगतता के आधार पर नहीं, बल्कि इस आधार पर किया जाना चाहिए कि क्या उनसे अल्पसंख्यकों को लाभ हुआ है। क्रिटिकल रेस थ्योरी, कड़ी मेहनत और योग्यता को परिणामों को निर्धारित करने वाले वास्तविक कारक के रूप में नकारती है और विजेताओं को संरचनात्मक नस्लवाद का परिणाम मानती है।

हम इस बात पर प्रकाश डालना चाहते हैं कि किसी समुदाय के प्रत्यक्ष अनुभवों को वस्तुनिष्ठ, तर्कसंगत और साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोणों की

तुलना में कहीं अधिक महत्व दिया जाता है। पिछले कई दशकों से, हिंदू धर्म के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोण को लेकर अमेरिकी शिक्षा जगत के साथ हमारी कई बार बहस हुई है। हमने कई विषयों पर अपने पक्ष को साबित करने के लिए तथ्य, ठोस प्रमाण और तर्क प्रस्तुत किए। हर बार हमें इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि हमारे पास 'शैक्षणिक योग्यता' नहीं है और हमारे दावों को 'सहकर्मी समीक्षा' द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। जब हमने कहा कि हम परंपरा के अंतर्मुखी सदस्य होने के नाते अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं, तो हमारा उपहास किया गया और हिंदू होने के नाते बोलने के हमारे अधिकार से वंचित कर दिया गया। हालांकि, अश्वेतों को व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उनकी गवाही को शैक्षणिक निष्कर्षों से ऊपर माना जाता है।
हमें बताया जाता है कि अंतर यह है कि अश्वेत लोग पीड़ित हैं; ग्राम्स्की और मारक्यूज़ के अनुसार, यह उन्हें एक संरक्षित वर्ग के विशेष अधिकारों का हकदार बनाता है। वहीं, हिंदू और परोक्ष रूप से अधिकांश भारतीय उत्पीड़क माने जाते हैं - यह सब हिंदू-विरोधी और भारत-विघटनकारी ताकतों के आरोपों पर आधारित है। यह दोहरे मापदंड को उचित ठहराता है।

निष्पक्षता और समानता
यहां एक महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दा समता और निष्पक्षता के बीच का अंतर है। समता का अर्थ है सभी को समान अवसर मिलना। निष्पक्षता का अर्थ है समान परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों के स्तर को पुनर्वितरित करना।
उदारवाद के पूर्ववर्ती स्वरूप में यह सिद्धांत प्रचलित था कि प्रत्येक व्यक्ति

को अपनी समूह पहचान से स्वतंत्र समान अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। नया सिद्धांत पहचान की राजनीति पर आधारित है: नस्ल, लिंग, यौन अभिविन्यास, लैंगिक पहचान, राष्ट्रीयता और धर्म पर आधारित प्रत्येक समूह पहचान जीवन का अनुभव अलग-अलग तरीके से करती है; और उनकी शक्ति की असमानता की भरपाई उन्हें असमान अधिकार देकर की जानी चाहिए।

परिणामस्वरूप, कार्यालयों और परिसरों में विविधता की अवधारणा अब विचारों की विविधता को नहीं, बल्कि पहचानों की विविधता को संदर्भित करती है। चूंकि विभिन्न समूह अलग-अलग तरीकों से ज्ञान का उत्पादन करते हैं, इसलिए यह सिद्धांत है कि आवश्यक विविधता में विभिन्न पहचानों के दृष्टिकोण प्रतिबिंबित होने चाहिए। लेकिन कुछ पहचानों ने दूसरों पर प्रभुत्व जमाया है और उन्हें दबाया है तथा विशेषाधिकार की संरचनाएं बनाई हैं; इसलिए, अधिक न्यायसंगत वातावरण बनाने के लिए इन दमनकारी पहचानों को सीमित करना आवश्यक है।

समानता का यह दृष्टिकोण उस सिद्धांत के विपरीत है जिस पर संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण हुआ था, यानी योग्यता के आधार पर मेहनती और नियमों का पालन करने वाले लोगों को ही लाभ मिलता है। मूल विचार यह था कि मध्यम वर्ग अपनी योग्यता के अनुसार धन सृजित करता है। अब इस विचार को पूरी तरह से नकार दिया गया है।

योग्यता को नकारने की यह प्रवृत्ति हार्वर्ड जैसे संस्थानों में भी समस्याएँ पैदा करती है, जहाँ प्रवेश नीतियाँ आधिकारिक तौर पर एशियाई लोगों के साथ भेदभाव करती हैं। उन्होंने एशियाई लोगों के प्रवेश पर सीमा लगाने के लिए तर्क प्रस्तुत किए हैं।

एक और समस्या यह है कि यद्यपि क्रिटिकल रेस थ्योरी पदानुक्रमित संरचनाओं से लड़ना चाहती है, फिर भी यह स्वयं एक सरलीकृत प्रणाली

है क्योंकि यह संरचनाओं में शामिल कारकों की बहुलता और जटिलता पर विचार करने में विफल रहती है। सभी पहचानों को उत्पीड़क या उत्पीड़ित के रूप में एक द्विआधारी प्रणाली में बहुत सरलता से वर्गीकृत किया जाता है। लेकिन एक व्यक्ति कई पहचानों को धारण करता है। एक ही व्यक्ति एक साथ पिता, पति, नियोक्ता, भारतीय, हिंदू, दार्शनिक, वैज्ञानिक, तर्कशील, राजनीतिक रूप से गलत, शिव और देवी का उपासक, ध्यान करने वाला, पशु प्रेमी, संगीत, भोजन और फैशन का प्रेमी, किसी विशेष शहर का निवासी, किसी विशेष विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र, किसी विशेष भाषा का वक्ता आदि हो सकता है। वही व्यक्ति एक संदर्भ में प्रभावशाली या यहां तक कि उत्पीड़क हो सकता है और फिर भी दूसरे संदर्भ में उत्पीड़ित हो सकता है।

इसके अलावा, क्रिटिकल रेस थ्योरी हजारों वर्षों से विभिन्न संदर्भों में व्याप्त हर सामाजिक बुराई को एक ही कारण का परिणाम बताती है। यह हास्यास्पद है। न ही यह समाधान को निष्पक्ष और समान तरीके से लागू करती है। उदाहरण के लिए, क्या मुस्लिम नायकों द्वारा जीते गए देशों (जैसे भारत) में निर्मित स्मारकों को उसी तरह ध्वस्त कर देना चाहिए जैसे अमेरिका में पुराने गुलाम मालिकों की मूर्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है? क्या अंग्रेजी भाषा को उत्पीड़क की भाषा मानकर समाप्त कर देना चाहिए? स्पष्ट है कि क्रिटिकल रेस थ्योरी को सार्वभौमिक बनाना आसान नहीं है।

हम यह मानकर नहीं चल सकते कि किसी विशेष पहचान के सभी सदस्य किसी मानक संहिता के अनुसार एक समान व्यवहार करते हैं। कुछ सदस्य अपने निर्धारित व्यवहारों से हटकर भी व्यवहार करते हैं। मानवीय गुण व्यक्तिगत होते हैं और किसी विशेष पहचान के सभी सदस्यों के लिए निश्चित नहीं होते। यही प्रकृति में विविधता का सिद्धांत भी है। यह वृक्षों,

पौधों, जानवरों और वास्तव में समस्त जीवन की विशिष्टता पर लागू होता है।

कैंसल कल्चर और असहमति का दमन

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हर्बर्ट मारक्यूज़ फ्रैंकफर्ट स्कूल के प्रमुख नेताओं में से एक थे जो यूरोप से अमेरिका चले गए और मार्क्सवाद को अटलांटिक पार लाने में मदद की। 1968 में, उन्होंने लिखा कि समाज को केवल शोषित समूहों के विचारों को ही स्वीकार करना चाहिए और रूढ़िवादी विचारों को दबा देना चाहिए। उन्होंने लिखा कि नागरिक अधिकार एक शून्य-योग खेल होना चाहिए: शोषितों को अधिकार देने के लिए, उन्हें उत्पीड़कों से छीनना होगा।

जिन लोगों के पास नागरिक अधिकार नहीं हैं, उनके द्वारा इन अधिकारों का प्रयोग करने का अर्थ है उन लोगों से इन अधिकारों को छीन लेना जो इनके प्रयोग में बाधा डालते हैं, और पृथ्वी के शापितों की मुक्ति का अर्थ है न केवल उनके पुराने बल्कि उनके नए आकाओं का भी दमन करना... प्रतिगामी आंदोलनों के सक्रिय होने से पहले ही उनसे सहिष्णुता छीन लेना; विचार, मत और शब्द के प्रति भी असहिष्णुता, और अंततः विपरीत दिशा में असहिष्णुता, अर्थात् स्वघोषित रूढ़िवादियों, राजनीतिक दक्षिणपंथियों के प्रति असहिष्णुता— ये लोकतंत्र विरोधी धारणाएँ लोकतांत्रिक समाज के वास्तविक विकास को दर्शाती हैं जिसने सार्वभौमिक सहिष्णुता के आधार को नष्ट कर दिया है। (जोर दिया गया)

यह एक प्रकार की प्रतिशोधात्मक व्यवस्था है। इस प्रकार की सोच का मूल उद्देश्य पश्चिमी सार्वभौमिकता की परंपराओं को ध्वस्त करना और ग्राम्स्की द्वारा प्रस्तावित उत्पीड़ितों के प्रति-वर्चस्व की स्थापना करना था। उदारवादी विचारधारा, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समाज का

आधार मानती है, अब खारिज की जा रही है। लागू की जा रही विचारधारा छात्रों को अमेरिकी परिसरों में प्रोफेसरों, अतिथि वक्ताओं और यहां तक कि अन्य छात्रों पर भी चिल्लाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसे 'सांस्कृतिक वर्चस्व' को 'प्रति-वर्चस्व' से बदलने का एक वैध तरीका माना जा रहा है। क्रिटिकल रेस थ्योरी के समर्थक अपना रुख स्पष्ट करते हैं: ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ के प्रति प्रतिबद्ध होना एक तटस्थ सिद्धांत प्रतीत हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए, यह घोषणा करना कि ‘मैं केकेके और 2लाइव क्रू दोनों को समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देने के लिए प्रतिबद्ध हूं’ एक गैर-तटस्थ मूल्य निर्णय है, जो यह दावा करता है कि घृणास्पद बातें कहने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े उत्पीड़न, कलंक और अपमान से मुक्त होने की स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है।

यही आज के उदार कला विश्वविद्यालयों में प्रचलित 'कैंसल कल्चर' का वैचारिक आधार है। यह इस आंदोलन के नेताओं को यह तय करने का अधिकार देता है कि उत्पीड़क और उत्पीड़ित कौन हैं, और उसी आधार पर यह तय करने का अधिकार देता है कि किसकी अभिव्यक्ति को अवरुद्ध किया जाना चाहिए।

रॉबिन डिएन्जेलो के 2011 के शोध पत्र (जो बाद में 2020 में 'व्हाइट फ्रैजिलिटी' नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ) ने श्वेत लोगों के नस्ल संबंधी मुद्दों पर रक्षात्मक रवैये को दर्शाने के लिए 'श्वेत नाजुकता' शब्द को लोकप्रिय बनाया। उनका मानना है कि नस्ल संबंधी मुद्दों पर चर्चा से बचने के कारण, जब यह विषय उठाया जाता है तो वे भावनात्मक रूप से 'कमजोर' हो जाते हैं, और उनकी प्रतिक्रियाएँ टालमटोल भरी और प्रतिकूल होती हैं। उनकी इस निष्क्रियता का परिणाम यह है कि 'नस्लीय संतुलन' श्वेत विशेषाधिकारों के पक्ष में बना रहता है। वह श्वेत नाजुकता

को इस प्रकार परिभाषित करती हैं:

… एक ऐसी स्थिति जिसमें नस्लीय तनाव की न्यूनतम मात्रा भी असहनीय हो जाती है, जिससे कई तरह की रक्षात्मक प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न होती हैं। … इनमें क्रोध, भय और अपराधबोध जैसी भावनाओं का बाहरी प्रदर्शन, और तर्क-वितर्क, मौन रहना और तनाव उत्पन्न करने वाली स्थिति से दूर चले जाना जैसे व्यवहार शामिल हैं। ये व्यवहार, बदले में, श्वेत नस्लीय संतुलन को पुनः स्थापित करने का कार्य करते हैं।[40]

उनकी किताब 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स की नंबर एक बेस्टसेलर बनी। कॉर्पोरेट जगत और विश्वविद्यालय डिएन्जेलो के ग्राहक हैं, जो विविधता प्रशिक्षण के लिए उनकी सेवाओं पर लाखों खर्च करते हैं। वे अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए व्यक्तिगत किस्सों और अपने स्वयं के अनुभवों पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं। वे इस बारे में साहसिक दावे करती हैं कि श्वेत लोग नस्लवादी कहे जाने पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। ये प्रतिक्रियाएँ उन्हें आश्वस्त करती हैं कि वे वास्तव में नस्लवादी हैं। केवल उनके सिद्धांत के प्रति उनका पूर्ण समर्पण ही उन्हें संतुष्ट करेगा। वे चाहती हैं कि उनके बड़ी संख्या में अनुयायी उनके विचारों पर सवाल उठाने वाले किसी भी व्यक्ति की निंदा करें। संक्षेप में, यदि आप असहमत हैं तो रॉबिन डिएन्जेलो सार्थक बातचीत या संवाद के सभी द्वार बंद कर देती हैं। अपने द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण से देखते हुए, वह कहती है कि यदि आप उन लोगों को खत्म करने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं जिनका वह विरोध करती है, तो आप नस्लवादी हैं:

सामाजिक न्याय के प्रति एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण विशिष्ट सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यों को संदर्भित करता है जो यह स्वीकार करते हैं कि समाज नस्ल, वर्ग, लिंग, यौनिकता और क्षमता सहित सामाजिक समूहों के आधार पर महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से स्तरीकृत (अर्थात् विभाजित और असमान)

है। [...] हममें से प्रत्येक के पास यह विकल्प है कि हम इन अन्यायपूर्ण प्रणालियों को बाधित करने और समाप्त करने के लिए काम करेंगे या उन्हें अनदेखा करके उनके अस्तित्व का समर्थन करेंगे। कोई तटस्थ मार्ग नहीं है; अन्याय के विरुद्ध कार्रवाई न करने का चुनाव करना अन्याय को स्वीकार करने के समान है।

उनके अनुसार विज्ञान भी व्यक्तिपरक है:

सभी ज्ञान एक विशिष्ट दृष्टिकोण से पढ़ाया जाता है; प्रमुख ज्ञान की शक्ति काफी हद तक उसके तटस्थ और सार्वभौमिक रूप में प्रस्तुत किए जाने पर निर्भर करती है। ज्ञान की अवधारणा को पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ, तटस्थ और मानवीय हितों से परे न होने के रूप में समझने के लिए, प्राकृतिक जगत के खोजे जा सकने वाले नियमों (जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम) और सामाजिक रूप से निर्मित ज्ञान के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। सामाजिक रूप से निर्मित से हमारा तात्पर्य यह है कि मनुष्यों द्वारा समझा जाने वाला सभी ज्ञान मानव समाजों की विचारधाराओं, भाषा, विश्वासों और रीति-रिवाजों द्वारा निर्मित होता है। यहां तक कि विज्ञान का क्षेत्र भी व्यक्तिपरक है।

वह कहती हैं कि चूंकि प्रभुत्वशाली समूह द्वारा किया जाने वाला उत्पीड़न संस्थागत रूप ले चुका है, इसलिए 'प्रभुत्वशाली समूह के किसी भी सदस्य को अल्पसंख्यक समूह के किसी सदस्य को उत्पीड़ित करने के लिए कुछ भी विशिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है।' मात्र श्वेत होना (और भारतीय संदर्भ में ब्राह्मण होना) ही नस्लवादी माने जाने के लिए पर्याप्त है।

हम संरचनात्मक पूर्वाग्रहों के उनके विश्लेषण के अधिकांश पहलुओं से सहमत हैं, लेकिन इस बात से असहमत हैं कि जो कोई भी उनसे बहस करता है या उनके विचारों पर सवाल उठाता है, उसे नस्लवादी करार दिया

जाना चाहिए। किसी भी श्वेत व्यक्ति द्वारा असहमति जताना उनके अनुसार 'आंतरिक वर्चस्व' को दर्शाता है। संक्षेप में, नस्ल को लेकर उनका सिद्धांत एक नए धर्म का सिद्धांत बन जाता है, जिसमें वे स्वयं को परम पैगंबर मानती हैं। सभी असहमति जताने वालों को ईशनिंदा करने वाला करार दिया जाना चाहिए।

यदि कोई शैक्षिक कार्यक्रम सीधे तौर पर नस्लवाद और श्वेतों को मिलने वाले विशेषाधिकारों को संबोधित करता है, तो श्वेतों की सामान्य प्रतिक्रियाओं में क्रोध, अलगाव, भावनात्मक अक्षमता, अपराधबोध, तर्क-वितर्क और संज्ञानात्मक असंगति शामिल होती हैं (ये सभी प्रशिक्षकों पर नस्लवाद को सीधे संबोधित करने से बचने का दबाव बढ़ाती हैं)। तथाकथित प्रगतिशील श्वेत लोग यह कहकर खुद को अलग-थलग कर सकते हैं कि उन्हें इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्होंने 'इस विषय पर पहले ही कक्षा ले ली है' या 'वे इसे पहले से जानते हैं'। नस्लवाद-विरोधी शिक्षा प्रयासों में इन प्रतिक्रियाओं को अक्सर आंतरिक वर्चस्व की चुनौती के प्रतिरोध के रूप में देखा जाता है। ... इन्हें नस्लीय अलगाव से उत्पन्न कमज़ोर मनोसामाजिक सहनशक्ति के परिणाम के रूप में भी समझना उपयोगी हो सकता है।

कक्षा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दमन की वकालत करने वाले विद्वान-कार्यकर्ताओं का एक और अच्छा उदाहरण टोरंटो विश्वविद्यालय से पीएचडी प्राप्त बारबरा एप्पलबाउम हैं। वह कक्षा में प्रश्न उठाने की कोशिश कर रहे एक छात्र के बारे में लिखती हैं: 'उसे अपनी असहमति व्यक्त करने की अनुमति देना और उसकी मान्यताओं को चुनौती देने में समय व्यतीत करना अक्सर हाशिए पर पड़े छात्रों के लिए नुकसानदायक साबित होता है, जिनके अनुभवों को, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से, उसके दावों द्वारा खारिज कर दिया जाता है।'

इसका अर्थ यह है कि अब छात्रों को असहमति व्यक्त करने की अनुमति देना खतरनाक माना जाता है। यदि प्रतिवाद की अनुमति दी जाती है, तो शिक्षक द्वारा निर्धारित सिद्धांत कमजोर पड़ सकता है और उन शोषितों के मन में संदेह पैदा कर सकता है जिन्हें वे बचाने का प्रयास कर रहे हैं।
एप्पलबाउम का तर्क है कि 'भाषा हमारे लिए एक वैचारिक ढांचा प्रदान करके हमारी वास्तविकता का निर्माण करती है, जिससे अर्थ प्राप्त होता है।' भाषा में व्यक्त कोई भी वैचारिक ढांचा या तर्क स्वयं ही त्रुटिपूर्ण होगा और उस भाषा में अंतर्निहित वर्चस्व को कायम रखेगा। चूंकि भाषा के अलावा तर्क करने का कोई अन्य तरीका नहीं है, इसलिए व्यावहारिक परिणाम यह है कि हमें इन सिद्धांतों को चुनौती नहीं देनी चाहिए।
इसी प्रकार, लेखिका एलिसन बेली का तर्क है कि जो कोई भी उनके जैसे लोगों से असहमत होता है, वह 'ज्ञान संबंधी हिंसा' कर सकता है:
'विशेषाधिकार-संरक्षण करने वाले ज्ञान संबंधी विरोध को आलोचनात्मक जुड़ाव के रूप में मानना इसे वैधता प्रदान करता है और इसे अधिक स्वतंत्र रूप से प्रसारित होने देता है; जैसा कि मैं बाद में तर्क दूंगी, यह उत्पीड़ित समूहों के प्रति ज्ञान संबंधी हिंसा कर सकता है।'

सक्रियता और टूलबॉक्स
एक नया चलन शिक्षण को विशुद्ध रूप से शैक्षिक होने के बजाय अत्यधिक निर्देशात्मक और सक्रियतावादी बना रहा है। विद्वत्ता और सक्रियता के बीच की सीमाएँ धुंधली होती जा रही हैं। शिक्षण राजनीति से अविभाज्य हो गया है। संकाय सदस्य अब खुले तौर पर घोषणा कर सकते हैं कि वे कार्यकर्ता हैं और उनके कॉलेज पाठ्यक्रम में उनकी अपनी विचारधारा का शिक्षण शामिल है। असहमति प्रतिबंधित है। यह किसी चर्च के कक्षागृह या मदरसे जैसा है।

शिक्षा के इस राजनीतिकरण वाले स्वरूप की समर्थक, कार्यकर्ता-विद्वान सैंड्रा ग्रे लिखती हैं:

शैक्षणिक नागरिक होने का एक हिस्सा यह भी है कि हम अपने छात्रों को और अधिक करने और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। ... शिक्षाविदों को अपने सामान्य कामकाजी जीवन के हिस्से के रूप में गठबंधन और संबंध बनाने की आवश्यकता है, और कभी-कभी तो राजनीतिक वकालत संगठनों के सदस्य बनने की भी आवश्यकता होती है।

2018 में, कार्यकर्ता-विद्वानों के एक समूह ने निबंधों का एक संकलन तैयार किया, जिसका शीर्षक था "सड़कों पर उतरना: वकालत में विद्वत्ता की भूमिका और विद्वत्ता में वकालत"। यह एक महत्वपूर्ण कदम है: हालांकि कई विद्वान कार्यकर्ता भी रहे हैं, लेकिन अब ये भूमिकाएँ अलग-अलग नहीं बल्कि आपस में जुड़ गई हैं। विद्वान खुले तौर पर अपनी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए अपने शोध का उपयोग कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान वस्तुनिष्ठता को हुआ है, जो परंपरागत रूप से अकादमिक शोध की पहचान रही है।

सक्रियतावाद और विद्वत्ता के इस घालमेल ने कक्षा में हर तरह की विचारधारा और राजनीति को लाने का रास्ता खोल दिया है। शिक्षक के राजनीतिक मुद्दे, उनकी नैतिक मान्यताएं, उनके पसंदीदा उत्पाद आदि, इन सभी को छात्रों पर थोपना जायज़ समझा जाता है, जो एक तरह से बंधक श्रोता हैं और असहमति व्यक्त करने का उनके पास कोई विकल्प नहीं है।

सक्रियता में अधिक लोगों को आकर्षित करने के लिए, कुछ जटिल सिद्धांतों को सरल 'तरीके' वाले दृष्टिकोणों से बदलना आवश्यक हो गया है। विद्वान-कार्यकर्ता और सांस्कृतिक इतिहासकार मैरी पूवे ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित किया

है जिसे वे 'टूलबॉक्स अप्रोच' कहती हैं, जिससे सामाजिक आंदोलन अकादमिक कम और सक्रियतावादी अधिक बन गया है। जटिल विचारों को सरल, आसानी से व्यक्त किए जाने वाले और संक्षिप्त शब्दों में ढाला गया है, जिनका उपयोग एक हथियार के रूप में किया जा सकता है। इससे बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को मार्क्सवाद, उत्तरआधुनिकतावाद, आलोचनात्मक नस्ल सिद्धांत, अंतर्संबंधता, क्वीर सिद्धांत आदि जैसे जटिल विषयों के विचारों और इतिहास को समझे बिना ही सक्रियता में शामिल होने का अवसर मिला है।

आजकल ऐसे नारीवादियों, नस्लवाद-विरोधी कार्यकर्ताओं और LGBTQ + कार्यकर्ताओं से मिलना आम बात हो गई है जिन्हें ऊपर बताए गए सिद्धांतों की कोई समझ नहीं होती, जबकि उनका प्रचार उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित होता है। उनके विचारों में उत्पीड़क/उत्पीड़ित, प्रभुत्वशाली/हाशिए पर पड़े जैसे शब्द और समाज का सांस्कृतिक रूप से निर्मित होना, पहचानों के टकराव से उत्पन्न होने वाली बयानबाजी शामिल होती है। वे ऐसे जटिल शब्दों का प्रयोग करते हैं जिन्हें वे पूरी तरह से समझते नहीं हैं। जो अनुयायी बिना सोचे-समझे इस विचारधारा में शामिल हो जाते हैं, वे पूछताछ किए जाने पर अपने विचारों का बुद्धिमानी से बचाव करने में असमर्थ होते हैं। अंततः, दमन की पुरानी संरचनाओं की जगह नई संरचनाएं ले रही हैं जो वास्तव में मुक्तिदायक नहीं हैं।

उत्तरआधुनिकतावादी दृष्टिकोण, जिसके अनुसार सामाजिक वास्तविकता का निर्माण प्रमुख विचारों द्वारा होता है, अब इस मांग में तब्दील हो गया है कि शोषितों की वाणी को शोषकों की वाणी पर सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिए। इसने उस पूर्व उदारवादी दृष्टिकोण को ध्वस्त कर दिया है जिसके अनुसार 'विचारों के बाज़ार' में बुरे विचार स्वतः ही बेहतर विचारों से पराजित हो जाते हैं। उदारवाद में एक बड़ा बदलाव यह है कि स्वतंत्र

चिंतन की जगह यह हठधर्मिता ले रही है कि केवल एक विशेष विचारधारा ही स्वीकार्य है, और यह विचारधारा पहचान की राजनीति की विचारधारा है।

व्यक्तिगत भावनाओं को व्यक्त करने की स्वतंत्रता देने के लिए, इस आंदोलन के नेता छात्रों को अपने व्यक्तिगत अनुभवों को एक राजनीतिक ढांचे में व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। स्नातक होने तक, वे नए सिद्धांतों से इस कदर प्रभावित हो चुके होते हैं कि उनकी आलोचनात्मक सोच की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसलिए हम लोगों को मुक्त करने के लिए संरचनाओं को नहीं हटा रहे हैं; हम केवल एक ढांचे को दूसरे से बदल रहे हैं।

यह मान लिया गया है कि विश्वसनीय ज्ञान बिना प्रमाण, तर्क या पूछताछ के प्राप्त किया जा सकता है। यह ज्ञान केवल हाशिए पर पड़े समूहों के रूप में नामित लोगों के अनुभवों को सुनकर प्राप्त किया जा सकता है, और यह पदनाम इस चर्च के अधिकारियों द्वारा तय किया गया है और इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। चूंकि केवल वास्तविक अनुभव ही मान्य हैं, इसलिए सभी पारंपरिक और आधिकारिक ग्रंथों को त्याग देना चाहिए क्योंकि उनमें दमनकारी भाषा का प्रयोग किया गया है।

व्यक्तिवाद पर आक्रमण

हाल तक उदारवाद की प्रमुख विशेषता प्रत्येक नागरिक के लिए समान व्यक्तिगत अधिकारों का सिद्धांत था। फ्रांस एक लोकतांत्रिक देश का उदाहरण है जहाँ वोकवाद के साथ टकराव तीव्र हो गया है। आइए, शास्त्रीय उदारवाद के पतन जैसे व्यापक विषय को समझने के लिए फ्रांस पर चर्चा करें।

फ्रांसीसी गणतंत्रवाद के नाम से जानी जाने वाली राजनीतिक विचारधारा

की उत्पत्ति फ्रांसीसी क्रांति (1789-99) में हुई और यह फ्रांसीसी वृहद कथा का मूल आधार बनी। यह व्यवस्था एक प्रकार का सामाजिक अनुबंध है जिसमें प्रत्येक नागरिक का राज्य के साथ सीधा संबंध होता है। अल्पसंख्यकों के संरक्षण के प्रति फ्रांस का दृष्टिकोण यह है कि सभी समान हैं और उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। यही उनका सार्वभौमिक अधिकारों का सिद्धांत है।

दूसरी ओर, क्रिटिकल रेस थ्योरी और इंटरसेक्शनैलिटी समूह पहचान के अधिकारों का समर्थन करते हैं। सीआरटी के अनुसार, समाज में व्यक्तिगत अधिकार वाले व्यक्ति नहीं होते। इसमें समूह पहचान शामिल होती है और उन लोगों को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए जो समाज के बाकी हिस्सों द्वारा उत्पीड़ित होने का दावा करते हैं। वोक विचारक दावा करते हैं कि नस्ल, धर्म, लिंग और यौनिकता लोगों को विभिन्न प्रकार के जीवन अनुभव प्रदान करते हैं और इसलिए सार्वजनिक नीतियों को समूहों के बीच अंतर करना चाहिए। वोकवाद फ्रांस के सार्वभौमिकतावाद को अभिजात्यवाद से ग्रस्त और परिवर्तन का विरोध करने का बहाना मानता है।

ये दोनों विश्वदृष्टिकोण एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं और अभी तक इनका कोई ऐसा समाधान नहीं निकला है जिससे दोनों पक्षों को फायदा हो।

फ्रांसीसी सरकार के एक थिंकटैंक के सदस्य ने कहा: 'वोकेवाद लोगों को नियंत्रित करने के लिए उन्हें समूहों में बांटता है। यह कहता है कि तुम मेरे समूह से संबंधित हो, और मेरे समूह के नेता तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें कैसा व्यवहार करना है। यह फ्रांसीसी मानसिकता के बिल्कुल विपरीत है।'

एक अन्य 'वोके' विरोधी कार्यकर्ता इसे फ्रांसीसी उदारवाद के संस्थापक सिद्धांतों के खिलाफ एक पूर्ण युद्ध के रूप में वर्णित करता है:

हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ किसी भी विषय पर खुलकर बोलने की स्वतंत्रता को स्वाभाविक माना जाता है। जब अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कहते हैं कि फलां विषय पर बात करना मना है, तो लोग तुरंत इसे सेंसरशिप कहते हैं, और हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते।
राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने क्रिटिकल रेस थ्योरी की आलोचना की है क्योंकि यह व्यक्तिवाद को कमजोर करती है, जो फ्रांसीसी गणराज्य की विचारधारा का मूल आधार है। यह सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जिसे राज्य से समान अधिकार प्राप्त हैं, और समूह राज्य और व्यक्तिगत नागरिकों के बीच मध्यस्थ नहीं हैं। क्रिटिकल रेस थ्योरी और इंटरसेक्शनैलिटी का दावा है कि समूह आंदोलनों के नेताओं को अपने-अपने सदस्यों की ओर से उनके अधिकारों के लिए बातचीत करनी चाहिए।
फ्रांस में मुसलमानों ने अपनी सामूहिक पहचान के लिए पीड़ित होने का दावा करने के लिए क्रिटिकल रेस थ्योरी को अपनाया है। 2020 में एक भाषण के दौरान, राष्ट्रपति मैक्रोन ने अपने देश के सामाजिक ताने-बाने में व्याप्त अराजकता और धीरे-धीरे बढ़ते कट्टरपंथ पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने इस्लाम को विशेष रूप से निशाना बनाया और फ्रांसीसी आबादी के बीच अलगाववादी पहचान पैदा करने के लिए इसकी आलोचना की।
मैं सभी धर्मों और नास्तिकों सहित प्रत्येक नागरिक से गणतंत्र के सभी कानूनों का पूर्णतया पालन करने का आग्रह करता हूँ। और इस कट्टरपंथी इस्लामवाद में – चूंकि यही मूल मुद्दा है, तो आइए इस पर चर्चा करें और इसका नाम लें – गणतंत्र के कानूनों का उल्लंघन करने और एक समानांतर व्यवस्था स्थापित करने, अन्य मूल्यों को स्थापित करने, समाज को संगठित करने का एक ऐसा तरीका विकसित करने की घोषित, प्रचारित इच्छा, एक व्यवस्थित तरीका है, जो प्रारंभ में अलगाववादी है,

लेकिन जिसका अंतिम लक्ष्य गणतंत्र पर पूर्णतः कब्जा करना है। और यह धीरे-धीरे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और ईशनिंदा के अधिकार के हनन में परिणत हो रहा है, और हमें गुप्त रूप से कट्टरपंथी बना रहा है।

उन्होंने समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए बाहरी प्रभावों को दोषी ठहराया और कुछ लोगों के नाम भी बताए:

बाहरी प्रभावों और राजनीतिक शक्तियों तथा निजी संगठनों द्वारा संगठित व्यवस्था ने इन सबसे कट्टरपंथी रूपों को बढ़ावा दिया है। ... हमने इसे देश और विदेश दोनों जगह होने दिया है। वहाबवाद, सलाफवाद, मुस्लिम ब्रदरहुड – इनमें से कई अभिव्यक्तियाँ शुरू में कुछ लोगों के लिए शांतिपूर्ण थीं। उनका विमर्श धीरे-धीरे बिगड़ता चला गया। वे स्वयं कट्टरपंथी बन गए हैं। उन्होंने अलगाव के संदेश, एक राजनीतिक परियोजना, लैंगिक समानता के खंडन में कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया है... और बाहरी वित्तपोषण, बाहर से किए गए दुष्प्रचार के माध्यम से, वे हमारे देश के केंद्र तक पहुँच गए हैं।

फ्रांस की तरह ही, क्रिटिकल रेस थ्योरी का दृष्टिकोण अमेरिका को व्यक्तियों के एक राष्ट्र के रूप में नहीं, बल्कि पीड़ितों के विभिन्न समूहों के एकीकरण के रूप में पुनर्कल्पित करना है। मारक्यूज़ इन्हीं समूहगत पहचानों को उत्प्रेरित करना चाहते थे, ताकि उत्पीड़ित जनसमूह अपने अधिकारों की मांग कर सकें।

अमेरिकी जनगणना नई पहचानें गढ़कर पहचान की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। उदाहरण के लिए, 'रंगभेद का शिकार लोग' श्रेणी पर विचार करें। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि कई हिस्पैनिक लोग खुद को 'रंगभेद का शिकार लोग' कहलाना नहीं चाहते और अमेरिकी मुख्यधारा में घुलमिल जाना पसंद करते हैं। नस्लीय आधार पर वर्गीकृत होने के बजाय,

वे कड़ी मेहनत के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं। 1871 से शुरू हुई ब्रिटिश जनगणनाओं से एक कड़वा सबक सीखा जा सकता है। यह एक ऐसा निरंतर अभियान था जिसने भारतीय समाज की आत्म-छवि को विकृत कर दिया, जिससे विभाजनकारी जाति व्यवस्था का उदय हुआ। हाशिए पर पड़े समूह के सभी सदस्यों के विचार एक जैसे माने जाते हैं और उनकी आवाज़ का प्रतिनिधित्व उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्हें कार्यकर्ता घोषित किया गया है। अन्य लोगों को आमंत्रित नहीं किया जाता, या उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है, या उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण और प्रशिक्षण लेने को कहा जाता है कि वे नियमों का पालन करें। अंततः, केवल उन्हीं लोगों को प्रामाणिक माना जाता है जो उनसे सहमत होते हैं। सब कुछ एक शून्य-योग राजनीतिक खेल में बदल जाता है जिसमें आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता उत्पीड़कों को एक पूर्ण युद्ध में पराजित करना है।

बराक ओबामा की रंगभेद-मुक्त सोच पर हमला

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने एक प्रसिद्ध चुनावी भाषण में कहा था, 'कोई अश्वेत अमेरिका या श्वेत अमेरिका, एशियाई अमेरिका या लैटिनो अमेरिका नहीं है; केवल संयुक्त राज्य अमेरिका है।' अब वोकवादियों द्वारा इसकी आलोचना की जा रही है। उनका मानना है कि ओबामा का दृष्टिकोण नस्लीय असमानता की समस्या का समाधान नहीं कर सकता। वोकवाद नस्लीय समस्याओं के लिए संरचनात्मक समाधान की मांग करता है, भले ही ये समाधान विपरीत नस्लवाद में तब्दील हो जाएं।

नस्ल संबंधी समस्या के प्रति ओबामा के दृष्टिकोण की आलोचना रंगभेद-मुक्ति के रूप में की जा रही है। रंगभेद-मुक्त समाज वह होता है जिसमें

नस्ल-तटस्थ सरकारी नीतियां होती हैं जो नस्लीय समानता के लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए किसी भी रूप में भेदभाव को अस्वीकार करती हैं। रंगभेद-मुक्ति ही रेवरेंड मार्टिन लूथर किंग जूनियर और रॉबर्ट कैनेडी के नागरिक अधिकार आंदोलन और 1950 और 60 के दशक के संबंधित भेदभाव-विरोधी आंदोलनों की नींव थी।

दूसरे शब्दों में, ओबामा के दृष्टिकोण में, उदाहरण के लिए, गोरों के खिलाफ पूर्वाग्रह को वैध बनाकर अश्वेतों के खिलाफ पूर्वाग्रह से नहीं लड़ा जा सकता। यह अवधारणा अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स जूनियर के उस मत का आधार बनी जब उन्होंने कहा: 'नस्ल के आधार पर भेदभाव को रोकने का तरीका नस्ल के आधार पर भेदभाव करना बंद करना है।'59[59] रंग-अंधा दृष्टिकोण का मूल अर्थ यह है कि सरकार को एक समान अवसर प्रदान करना चाहिए जिसमें व्यक्तियों को अपने परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और योग्यता अर्जित करनी चाहिए।

कई लोगों को इस बात पर अविश्वास है कि क्रिटिकल रेस थ्योरी विपरीत भेदभाव की मांग करती है। लेकिन अतीत के भेदभावों को दूर करने के लिए विपरीत नस्लवाद की यह विचारधारा आंदोलन के प्रमुख समर्थकों द्वारा स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई है। उदाहरण के लिए, न्यूयॉर्क टाइम्स के नंबर एक बेस्टसेलर लेखक और नेशनल बुक अवार्ड विजेता, इबराम एक्स. केंडी ने प्रसिद्ध रूप से कहा है:

अतीत में हुए भेदभाव का एकमात्र उपाय वर्तमान भेदभाव है।
वर्तमान भेदभाव का एकमात्र उपाय भविष्य भेदभाव है।[60]

यह तो सामाजिक न्याय का एक ऐसा रूप है जिसमें 'जैसे को तैसा' किया जाता है!

ओबामा ने अश्वेत समाज में मौजूद कुछ ऐसे पूर्वाग्रहों को निडरता से

उजागर किया जो उनकी प्रगति के लिए हानिकारक हैं। वे अश्वेतों को जवाबदेह ठहराना चाहते थे और उनकी स्थिति सुधारने के लिए उन्हें जिम्मेदार बनाना चाहते थे। उन्होंने बताया कि उनके घरों में 'बहुत ज़्यादा टेलीविजन' है। उन्हें यह नहीं पता कि गेम बॉक्स कब बंद करना है या बच्चों को कब सुलाना है। उन्होंने अपने साथी अफ्रीकी अमेरिकियों की अत्यधिक 'विषाक्त पदार्थों' के सेवन और 'शैक्षिक उपलब्धि पर ज़ोर न देने' के लिए आलोचना की। उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता कि उन्हें किसने सिखाया कि पढ़ना-लिखना और क्रियाओं का सही रूप धारण करना श्वेतों का काम है।'

उन्होंने ‘अपने पिताओं से अधिक अपेक्षाएँ रखकर और अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताकर अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेने’ के महत्व पर भी बल दिया और अश्वेत समाज में ‘दो माता-पिता वाले परिवारों’ की कमी की आलोचना की। उन्होंने उन लोगों की निंदा की जो यह मानने से इनकार करते हैं कि ये मूल्य उनकी दुर्दशा में किस प्रकार योगदान दे रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा:

नागरिक अधिकार आंदोलन केवल उत्पीड़क के विरुद्ध लड़ाई नहीं थी; यह हममें से प्रत्येक के भीतर मौजूद उत्पीड़क के विरुद्ध भी लड़ाई थी।

जब ओबामा से विशेष रूप से अश्वेतों को निशाना बनाने के उनके इरादों के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया:

मैं एक अश्वेत व्यक्ति हूँ जो बिना पिता के पला-बढ़ा और मैं जानता हूँ कि इसकी मुझे कितनी कीमत चुकानी पड़ी। मेरे पास इस चक्र को तोड़ने की क्षमता है, मेरी बेटियाँ बेहतर स्थिति में हैं। इस विषय पर चर्चा करने का मतलब यह नहीं है कि मैं प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की आवश्यकता, रोजगार प्रशिक्षण की आवश्यकता, बुनियादी ढांचे में अधिक निवेश की आवश्यकता, या निम्न आय वाले समुदायों में रोजगार की आवश्यकता के

बारे में अपनी चर्चा को नकार रहा हूँ।
वह अश्वेत समुदाय की समस्याओं और सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता, दोनों विषयों पर बात करना चाहते थे। यह कार्रवाई 'वर्ग' पर आधारित होनी थी, न कि 'नस्ल' पर, इसलिए मुआवज़ा/उपचार केवल अश्वेतों के लिए ही आरक्षित नहीं होना था। उनकी रंगभेद-मुक्त सोच के अनुरूप, पीड़ित श्वेतों सहित अन्य योग्य व्यक्तियों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए था।
ओबामा के उस दृष्टिकोण की कई आलोचनाएँ हैं जो नस्लीय समस्याओं को सुलझाने के लिए फूट के बजाय राष्ट्रीय एकता पर ध्यान केंद्रित करता है। कई अश्वेतों के लिए रंगभेद से मुक्त होना एक बुरा सौदा लग सकता है क्योंकि आलोचना को स्वीकार करना और अपनी आदतों को बदलना कठिन होता है। दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना भी मुश्किल होता है, खासकर तब जब उन्हें उत्पीड़कों के समूह के रूप में देखा जाए।
मुख्य आशंका यह है कि रंगभेद को अनदेखा करने से संरचनात्मक समस्याओं के कारण होने वाले अंतर्निहित नस्लीय भेदभाव की अनदेखी हो जाती है। अपनी पुस्तक, "नस्लवादियों के बिना नस्लवाद: रंगभेद रहित नस्लवाद और अमेरिका में नस्लीय असमानता की निरंतरता" में, एडुआर्डो बोनिला-सिल्वा इस दृष्टिकोण पर विचार करते हैं:
नस्ल आज भी सामाजिक परिणामों को प्रभावित करती है (जैसे कि श्रम बाजार, धन, शिक्षा, पुलिस के साथ बातचीत और रोजमर्रा के अनुभवों में), और इसे अनदेखा करके—या रंगभेद को नजरअंदाज करके—हम नस्लीय असमानता की व्यवस्था को कायम रखने और मजबूत करने में मदद करते हैं।
उनके अनुसार, रंगभेद रहित नीति ही नस्ल के मुद्दे पर ओबामा द्वारा हासिल की गई प्रगति की कमी के लिए जिम्मेदार है, यह एक ऐसा विषय

है जिसे उनकी सामाजिक नीतियों में लक्षित नहीं किया गया है और सार्वजनिक रूप से इस पर लगभग कभी चर्चा नहीं की गई है।
एक अन्य प्रकाशन में, बोनिला-सिल्वा और उनके सह-लेखक डेविड डायट्रिच बताते हैं कि 'बराक ओबामा का चुनाव अमेरिका के "नस्ल-मुक्त" देश बनने का उदाहरण नहीं है।' बल्कि, 'एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में ओबामा की लोकप्रियता और नस्ल पर उनका राजनीतिक रुख और व्यक्तित्व रंगभेद-मुक्त नस्लवाद के अनुरूप है।' वे शिकायत करते हैं कि 'ओबामा प्रशासन के तहत, रंगभेद-मुक्त नस्लवाद की जड़ें अमेरिकी राजनीति की गहराई में और भी गहरी पहुँच जाएँगी।'
वे श्वेत और अश्वेत दोनों ही वर्गों के लोगों के बीच ओबामा की व्यापक लोकप्रियता को एक राजनीतिक मास्टरस्ट्रोक के रूप में देखते हैं क्योंकि वह सभी पक्षों को वही बताते हैं जो वे सुनना पसंद करते हैं:
ओबामा अश्वेत और श्वेत लोगों के लिए विशेष रूप से अलग-अलग अर्थों वाला प्रतीक बन गए हैं। गैर-श्वेत लोगों के लिए, ओबामा एक ऐसे अमेरिका की संभावनाओं का प्रतीक बन गए, जिसकी वे अधिक समतावादी बनने की आशा करते थे। अश्वेतों के लिए, एक अश्वेत राष्ट्रपति होने की संभावना एक समुदाय के रूप में उनकी ऐतिहासिक आकांक्षाओं का प्रतीक बन गई, 'एक अधूरा सपना, जो अब साकार हो गया है'। अश्वेतों की पुरानी पीढ़ियों के लिए, जो मरने से पहले नस्लीय समानता देखने के लिए बेताब थे, और रीगन के बाद की पीढ़ी के कई अश्वेतों और अल्पसंख्यकों के लिए, जिन्होंने अपने जीवनकाल में नस्लीय प्रगति बहुत कम देखी है, ओबामा नागरिक अधिकार आंदोलन के नए मसीहा बन गए। इसके विपरीत, श्वेतों के लिए ओबामा का प्रतीकात्मक अर्थ इस विश्वास के अनुरूप था कि अमेरिका वास्तव में एक रंगभेद-मुक्त राष्ट्र है। श्वेतों के लिए ओबामा जल्दी ही ओपरा या टाइगर वुड्स जैसी

हस्ती बन गए, एक अश्वेत व्यक्ति जिसने अपने अश्वेत होने की पहचान को पार करके राष्ट्रीय नायक का दर्जा हासिल कर लिया। इस प्रकार, श्वेत लोगों और विश्वभर के अन्य समर्थकों के लिए, ओबामा 'संभावनाओं' का भी प्रतिनिधित्व करते थे, होरेशियो अल्गर की पौराणिक कथा के अमेरिकी वादे का कि "चाहे शुरुआत कितनी भी साधारण हो, या ओवरकोट कितना भी फटा हुआ हो, एक बार अमेरिका के तट पर पहुँचने के बाद कोई भी कुछ भी हासिल कर सकता है"।

क्रिटिकल रेस थ्योरी के समर्थक अश्वेतों का तर्क है कि ओबामा की सफलता का कारण यह था कि उन्होंने अपनी अश्वेत पहचान को अपनाने के बजाय उसे त्याग दिया या कम महत्व दिया। संक्षेप में, ओबामा ने हीनता की स्थिति को स्वीकार किया और यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया होता, तो राजनीतिक परिणाम भिन्न हो सकते थे।

ओबामा की लोकप्रियता का एक कारण उनकी नस्ल-भेद से परे (नस्लीय भेदभाव से ऊपर) छवि और राजनीति को अपनाना भी था। उन्होंने नागरिक अधिकार आंदोलन के अधिकांश नेताओं, अपने पादरी (जो अश्वेत समुदाय से थे और खुलेआम नस्लवादी थे), अपने चर्च और उन सभी लोगों से दूरी बना ली, जो उन्हें 'बहुत अश्वेत' या 'बहुत राजनीतिक' दिखाते थे। ओबामा के चुनाव प्रचार अभियान में मिशेल ओबामा की छवि को भी इस तरह बदला गया कि श्वेत मतदाताओं के लिए वे कम अश्वेत, कम सशक्त और अधिक श्वेत महिला जैसी लगें। उनके श्वेत समर्थकों के लिए, ओबामा पहले 'अश्वेत' नेता थे जिनका समर्थन करने में उन्हें सहजता महसूस हुई क्योंकि उन्होंने नस्लवाद के बारे में बात नहीं की; क्योंकि वे उन्हें बार-बार याद दिलाते रहे कि वे आधे श्वेत हैं; क्योंकि वे बहुत 'स्पष्टवादी' थे या - सीनेटर बिडेन के शब्दों में, जिसे बाद में कार्ल रोव ने भी दोहराया - ओबामा 'पहले मुख्यधारा के अफ्रीकी अमेरिकी थे जो

स्पष्टवादी, बुद्धिमान, स्वच्छ और आकर्षक व्यक्तित्व वाले थे'। इसके अलावा, जेसी जैक्सन और अल शार्प्टन जैसे अश्वेत नेताओं के विपरीत, उन्होंने उन्हें देश में नस्लीय स्थिति के लिए दोषी महसूस नहीं कराया। इसके विपरीत, ओबामा ने एकता का उपदेश दिया।

ओबामा के प्रति निष्पक्षता बरतते हुए, यह कहना उचित होगा कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि रंगभेद पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वे चाहते थे कि सभी अमेरिकी इसके लिए प्रयास करें। वे चाहते थे कि लोग तुरंत कठिन व्यक्तिगत बदलाव करें और संरचनात्मक बदलावों का इंतजार न करें। अश्वेत समुदाय के कई सदस्यों द्वारा रंगभेद के समर्थन से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपनी बात प्रभावी ढंग से रखी।

यह स्वीकार करना होगा कि ओबामा की जीत ने नस्लीय विमर्श में एक नया अध्याय शुरू किया, जिसने अश्वेतों और श्वेतों को आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाया। लेकिन इस जुड़ाव को क्रिटिकल रेस थ्योरी के समर्थकों द्वारा एक समस्या के रूप में देखा जाता है। उनमें से कुछ की एक प्रमुख पुस्तक में ओबामा के राष्ट्रपति पद पर निम्नलिखित प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है:

बराक ओबामा की ऐतिहासिक जीत के बाद, अमेरिकी नस्लीय विमर्श में एक नया केंद्र उभर कर आया, जिसे नस्ल को लेकर ध्रुवीकरण करने वाले और प्रतिगामी विवादों के एक व्यावहारिक विकल्प के रूप में देखा गया। इस वैचारिक बदलाव का रंगभेद-मुक्त विचारधारा के विरुद्ध संघर्ष पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। चुनाव की पूर्व संध्या पर, नस्लीय न्याय के पैरोकारों पर कानूनी और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में रंगभेद-मुक्त विजय के मद्देनजर नस्ल-जागरूक विमर्श के अवशेषों को छोड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा था। नस्ल-मुक्त विचारधारा के उदय ने नस्लीय न्याय विमर्श के क्षरण को और गहरा कर दिया। अमेरिकी परिदृश्य में नस्ल-मुक्त विचारधारा के

उत्साहपूर्ण आगमन के पीछे एक रूढ़िवादी लहर थी जिसने नस्लीय न्याय समर्थकों को एक ऐसे विमर्श में खींच लिया जिसने एक विकृत असमान यथास्थिति को वैधता प्रदान की। नस्ल-मुक्त विचारधारा की संभावना का एक राजनीतिक विजय होना, जिसके बारे में नस्लीय न्याय के कुछ ही हितधारकों ने कभी सोचा होगा, नागरिक अधिकार इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है।

किम्बर्ले विलियम्स क्रेंशॉ ओबामा द्वारा रंगभेद-मुक्त दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के तरीके से चिंतित हैं, उनका कहना है कि 'बराक ओबामा के समर्थन से उत्तर-नस्लवाद अमेरिकी राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आ गया, और इसके साथ ही रंगभेद-मुक्ति को नस्लीय ज्ञानोदय से और नस्लीय न्याय की वकालत को शिकायत की राजनीति से जोड़ने की एक लंबे समय से चली आ रही रूढ़िवादी परियोजना भी आगे बढ़ गई।' उनका कहना है कि समस्या रंगभेद-मुक्ति में है क्योंकि यह एक रूढ़िवादी परियोजना है और इसलिए, यह कोई समाधान नहीं दे सकती।

कोलंबिया विश्वविद्यालय की संकाय सदस्य मार्सेल मेंटर ने संक्षेप में बताया कि रंगभेद एक समस्या क्यों है:

जब हम कहते हैं कि हम नस्लीय भेदभाव नहीं करते, तो हम अश्वेत और भूरे रंग के लोगों को अनदेखा कर देते हैं और उनके अनुभवों, जीवन और पीड़ाओं को निरर्थक और मौन बना देते हैं। हम संपूर्ण सच्चाइयों को दबा देते हैं और पूरे अमेरिका में लोगों के एक बहुत ही वास्तविक और दर्दनाक इतिहास को छिपा देते हैं।

नागरिक अधिकार आंदोलन के दृष्टिकोण में क्रमिक, चरणबद्ध प्रगति पर जोर दिया गया था। लेकिन क्रिटिकल रेस थ्योरी मौजूदा व्यवस्था की नींव को ही तुरंत ध्वस्त करना चाहती है; इसे फिर से गढ़ने के सभी प्रयासों को पुरानी संरचनाओं के अस्तित्व का समर्थन करने के बराबर माना जाता है।

वे समानता, कानूनी तर्क और संवैधानिक कानून, प्रबोधन और तर्कसंगतता को पूरी तरह से नकारते हैं।

शैक्षिक युद्धक्षेत्र

अमेरिकी विश्वविद्यालय परिसर क्रिटिकल रेस थ्योरी के विरोध का केंद्र बन गए हैं। यहीं पर कट्टरता और असहिष्णुता चरम पर है। वक्ताओं और यहां तक कि विश्वविद्यालय अध्यक्षों को भी कार्यकर्ताओं द्वारा चुप करा दिए जाने की घटनाएं आम हैं, कार्यकर्ता डेस्क पर खड़े होकर तब तक चिल्लाते रहते हैं जब तक पुलिस को हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता। जो लोग इस आंदोलन की तानाशाही का विरोध करते हैं, उन्हें उपहास, सार्वजनिक अपमान, बहिष्कार या यहां तक कि बर्खास्तगी का सामना करना पड़ता है। अध्ययनों से पता चला है कि अमेरिकी परिसरों में क्रिटिकल रेस थ्योरी का विरोध करने वाले एक तिहाई छात्रों और विद्वानों को उनके विचारों के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की धमकी दी गई है, और इसका विरोध करने वाले सत्तर प्रतिशत शिक्षाविदों ने अपने साथियों के बीच शत्रुतापूर्ण माहौल की सूचना दी है।

अमेरिका में बालवाड़ी से लेकर बारहवीं कक्षा तक के स्कूली विषयों जैसे सामाजिक अध्ययन, इतिहास और नागरिक शास्त्र में 'वोके' (जागरूकता से प्रेरित) विषयों को शामिल करने का चलन बढ़ रहा है। इससे अभिभावकों की ओर से भारी विरोध उत्पन्न हुआ है, जो शिकायत करते हैं कि यह सामग्री शिक्षकों और छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे विषयों से विचलित करती है, जो करियर बनाने और अमेरिकी सपने को साकार करने का अवसर प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, कैलिफ़ोर्निया एक ऐसा पाठ्यक्रम लागू करने की योजना बना रहा है जिसमें अंतर-संबंधीता पर एक पूरा खंड समर्पित

होगा। वर्जीनिया के फेयरफैक्स काउंटी पब्लिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने जिला कर्मचारियों के सामने बोलने के लिए एक सामाजिक न्याय सलाहकार को बीस हजार डॉलर का भुगतान किया। मैरीलैंड के मॉन्टगोमरी काउंटी का स्कूल बोर्ड 'नस्लवाद-विरोधी ऑडिट' करने के लिए एक सलाहकार पर लगभग पांच लाख डॉलर खर्च करने की योजना बना रहा है।
ओहियो राज्य अपने स्कूल बोर्ड को क्रिटिकल रेस थ्योरी पर प्रशिक्षण दे रहा है और शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले सभी राज्य कर्मचारियों और ठेकेदारों के लिए भी प्रशिक्षण अनिवार्य कर रहा है। नए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में सक्रियता के ऐसे तरीके अपनाए जा रहे हैं जो वस्तुनिष्ठ ज्ञान और ऐतिहासिक तथ्यों के बजाय व्यक्तिगत अनुभवों को प्राथमिकता देते हैं। यह सब तब हो रहा है जब वर्षों के शोध से पता चलता है कि अल्पसंख्यक छात्र अभी भी मुख्य विषयों में अपने साथियों से पीछे हैं। शिक्षाविदों की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग आधे अमेरिकी सरकार की तीनों शाखाओं के नाम भी नहीं बता सकते। फिर भी, यह शिक्षण पद्धति सक्रियता को बढ़ावा देती है, जबकि अधिकांश छात्र परिपक्व निर्णय लेने और जिम्मेदारी से कार्य करने में असमर्थ हैं।
अमेरिकी इतिहास को अतीत के अन्यायों के कालक्रम और क्षतिपूर्ति न्याय के रूप में अपेक्षित विभिन्न प्रकार के अधिकारों के रूप में पुनर्लिखित किया जा रहा है।

पुराने को ध्वस्त करना, लेकिन नए का निर्माण करना न जानना।
राष्ट्र-राज्य, स्थापित व्यवस्था के विरुद्ध अनेक पीड़ित पहचानों के इस नवीनतम द्वंद्व का संभावित शिकार है। जो कभी सकारात्मक नागरिक उत्तरदायित्व की भावना हुआ करती थी, वह अब व्यवधान की पुकार में तब्दील हो रही है, जिसमें कभी-कभी हिंसक क्रांति भी शामिल है।

हमें अब्राहम लिंकन के इस कथन को याद रखना चाहिए: 'कोई भी शिकायत भीड़ द्वारा कानून बनाकर हल करने योग्य नहीं है'। इसके अलावा, हमें 'स्वतंत्रता के गौरवशाली ताने-बाने को संविधान और कानूनों के प्रति आदर' पर टिकाना चाहिए। संविधान के तहत उचित प्रक्रिया को बनाए रखने की इन मूलभूत अवधारणाओं को ध्वस्त करना अनुचित है। क्रिटिकल रेस थ्योरी का अंतिम लक्ष्य मौजूदा संरचनाओं को ध्वस्त करना है क्योंकि उन्होंने ऐतिहासिक रूप से बहुत उत्पीड़न और अन्याय को जन्म दिया है, और वादा यह है कि कुछ नया, लेकिन अभी तक अपरिभाषित, उनकी जगह लेगा और न्याय लाएगा। हालाँकि, हमें इसी तरह के व्यवधानों के इतिहास पर गौर करना चाहिए:

रूसी क्रांति, जिसने साम्यवाद की स्थापना की, पुराने ढाँचों को ध्वस्त करने की परियोजना को भी अंजाम दे रही थी। वह प्रयोग विफल रहा, जबकि पश्चिमी यूरोप ने पुराने ढाँचों के भीतर ही अपना विकास जारी रखा और कहीं बेहतर प्रदर्शन किया।

इसी प्रकार, ईरान में पश्चिमी प्रभाव के तहत निर्मित धर्मनिरपेक्ष ढाँचों को ध्वस्त करने के लिए एक क्रांति हुई। इनके स्थान पर इस्लामी ढाँचे स्थापित किए गए, जिससे आतंकवाद का उदय हुआ, न कि एक बेहतर समाज का निर्माण।

अमेरिका ने इस्लामी तानाशाही को खत्म करने और उनकी जगह लोकतंत्र स्थापित करने की उम्मीद में हस्तक्षेप किया। लेकिन वह प्रयास भी विफल रहा।

चीन की माओवादी क्रांति ने नए सिरे से शुरुआत करने के नाम पर उसके पारंपरिक ताने-बाने को नष्ट कर दिया, लेकिन नया चीन सामाजिक न्याय का उपयुक्त उदाहरण नहीं है।

पुरानी संरचनाओं को पूरी तरह से ध्वस्त करने के हर मामले में, नतीजा

एक ऐसी गड़बड़ी ही निकला जिसने पहले से भी कहीं अधिक अन्याय को जन्म दिया। तो, इस बात का क्या प्रमाण है कि पुरानी संरचनाओं को तोड़ने के लिए क्रिटिकल रेस थ्योरी की क्रांति बेहतर परिणाम लाएगी?

वोक का निगमीकरण

अमेरिका के कार्यस्थलों में क्रिटिकल रेस थ्योरी (CRT) प्रशिक्षण कार्यशालाओं और सेमिनारों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। प्रबंधन पर CRT के समर्थकों द्वारा तैयार की गई आधिकारिक नीतियों को अपनाने का दबाव है। ये प्रशिक्षण सत्र 1920 के दशक में ग्राम्स्की द्वारा यूरोपीय श्रमिकों के लिए अनुशंसित ब्रेनवाशिंग सत्रों की तर्ज पर तैयार किए गए हैं - इनका उद्देश्य 'सांस्कृतिक वर्चस्व' के स्थान पर 'प्रति-वर्चस्व' का विमर्श तैयार करना था।

इस तरह के दुष्प्रचार का एक प्रसिद्ध उदाहरण 2020 में स्मिथसोनियन संस्थान के राष्ट्रीय अफ्रीकी अमेरिकी इतिहास और संस्कृति संग्रहालय में देखने को मिला। संग्रहालय के प्रशिक्षण कार्यक्रम में इस धारणा की आलोचना की गई कि कड़ी मेहनत और वस्तुनिष्ठ एवं तर्कसंगत चिंतन ही सफलता की कुंजी है। इसमें समझाया गया कि ये गुण 'श्वेत वर्चस्व वाली संस्कृति' से संबंधित हैं। इस तरह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तेजी से फैल रहे हैं।

मानव संसाधन (एचआर) विभागों पर महंगे 'वोके' सलाहकारों का दबाव रहता है, और अगर वे इसका विरोध करते हैं, तो उन पर नस्लवादी होने का आरोप लगने का खतरा रहता है। मानव संसाधन प्रबंधन सोसायटी (एसएचआरएम), जो एचआर पेशेवरों की पैरवी करने वाली संस्था है, कॉर्पोरेट एचआर पेशेवरों को इस तरह के प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए

राजी करने में एक प्रमुख भूमिका निभा रही है। यह कार्यस्थल में सामाजिक न्याय लाने के बहाने क्रिटिकल रेस थ्योरी का उपयोग करते हुए विविधता प्रशिक्षण प्रदान करती है। एसएचआरएम का काफी प्रभाव है, जिसके सदस्यों में 165 देशों के 300,000 से अधिक मानव संसाधन पेशेवर और व्यावसायिक अधिकारी शामिल हैं, और इसकी नीतियां और विचारधाराएं दुनिया भर में 11.5 करोड़ श्रमिकों को प्रभावित करती हैं। क्रिटिकल रेस थ्योरी की एक शीर्ष सलाहकार, रॉबिन डिएन्जेलो, खूब पैसा कमाती हैं। वे भाषण देने के लिए लाखों डॉलर फीस लेती हैं। वे स्पष्ट रूप से कहती हैं: 'यह पुस्तक निःसंकोच पहचान की राजनीति पर आधारित है।' विडंबना यह है कि डिएन्जेलो मुक्त उद्यम की घोर विरोधी हैं, फिर भी कॉरपोरेट जगत उनसे इतना डरता है कि उन्हें काम पर रखता है।

एक अन्य उदाहरण क्रिटिकल रेस थ्योरी के अगुआ इब्रम एक्स. केंडी हैं, जिनकी पुस्तक, हाउ टू बी एन एंटी-रेसिस्ट, पूंजीवाद की निंदा करती है: 'पूंजीवाद मूलतः नस्लवादी है; नस्लवाद मूलतः पूंजीवादी है। इनका जन्म एक ही अप्राकृतिक कारणों से हुआ है, और एक दिन ये एक ही अप्राकृतिक कारणों से समाप्त हो जाएंगे।' फिर भी सबसे बड़ी कंपनियां उनके साथ खड़ी दिखना चाहती हैं।

क्रिटिकल रेस थ्योरी ने लिबरल आर्ट्स कॉलेजों से नियुक्त स्नातकों के माध्यम से कार्यस्थल में भी अपनी पैठ बना ली है, जो इस प्रभाव को साथ लाते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उन एल्गोरिदम में भी अंतर्निहित है जो यह निर्धारित करते हैं कि सोशल मीडिया पर खातों और संदेशों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है।

विवेक रामास्वामी ने एक सशक्त तर्क प्रस्तुत किया है कि कॉर्पोरेट जगत

में प्रचलित जागरूकतावाद किसी अंधेरे पहलू को छिपाने का एक तरीका है। वे लिखते हैं: 'कॉर्पोरेट अमेरिका के शीर्ष पदों पर एक नई अदृश्य शक्ति सक्रिय है', एक ऐसी शक्ति जो 'हमारे समय का सबसे बड़ा घोटाला है - एक ऐसा घोटाला जो न केवल आपका पैसा बल्कि आपकी आवाज और आपकी पहचान भी छीन लेता है'।

रामास्वामी ने कॉर्पोरेट जगत में चल रहे उस धोखे का पर्दाफाश किया है, जिसमें 'लाभ और सत्ता के अलावा किसी और चीज़ की परवाह करने का दिखावा किया जाता है, ताकि इन दोनों को और अधिक हासिल किया जा सके'। दूसरे शब्दों में, धनी और लालची उद्योगपति भलाई करने का दिखावा करते हैं, लेकिन यह समाज के हर पहलू पर अपनी शक्ति फैलाने का एक तरीका है। उनका कहना है कि उद्योगपति प्रगतिशील दिखने वाली परोपकारी नीतियों का उपयोग केवल अपनी सत्ता के दुरुपयोग से ध्यान हटाने के लिए एक चाल के रूप में कर रहे हैं।

इन नए 'जागरूक' मूल्यों को अपनाकर, अमेरिका के व्यापारिक नेताओं को विधर्म से संत बनने का एक पीढ़ी में एक बार मिलने वाला अवसर मिला। निगम अब उत्पीड़क नहीं रहे। इसके बजाय, यदि निगम शक्ति का सही ढंग से प्रयोग किया जाए, तो यह वास्तव में उन नए शक्तिहीन वर्गों को सशक्त बना सकती है जो दुष्ट निगमों के हाथों नहीं, बल्कि सीधे-सादे श्वेत पुरुषों के हाथों पीड़ित थे - वे वास्तविक अपराधी जिन्होंने न केवल निगमों के जन्म से, बल्कि आधुनिक मानव इतिहास के दौरान अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था।

वह लिखते हैं कि बड़ी-बड़ी कंपनियाँ अपने लालच की संस्कृति को छिपाने के लिए वोकवाद का सहारा ले रही हैं। महंगे विविधता सलाहकारों को नियुक्त करके, वे श्वेत पुरुषों के खिलाफ आक्रोश को मोड़कर अपने पूंजीवाद को बचा रही हैं। यह कंपनियों और वोकवाद के बीच एक

अवसरवादी गठबंधन है।

कॉरपोरेशनों ने कभी भी 'वोकेनेस' को सचमुच में पसंद नहीं किया, भले ही उन्होंने इसे अपनाया और पूंजीवाद के साथ जोड़ दिया। उनका इरादा हमेशा इसका इस्तेमाल करना था। लेकिन 'वोकेनेस' ने भी कभी पूंजीवाद को सचमुच में पसंद नहीं किया। पूंजीवाद में मौलिक रूप से 'वोके' जैसा कुछ नहीं था, कोई स्वाभाविक अनुकूलता नहीं थी। जब कॉरपोरेशनों ने यह घोषणा करना शुरू किया कि 'वोकेनेस' और पूंजीवाद अविभाज्य हैं और इस संदेश को फैलाने में मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति को पैसा और प्रतिष्ठा देने लगे, तो दोनों पक्षों ने इस प्रस्ताव को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नहीं थी, बल्कि इसलिए कि यह लाभदायक था। [...]

इस सौदेबाजी से 'वोकेनेस' को जो सबसे बड़ा फायदा मिला, वह यह था कि उसे हर बड़ी कंपनी को अपने संदेश को दुनिया भर में फैलाने के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल करने का मौका मिल गया। कंपनियों ने सिर्फ पैसा ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने वोकेनेस को एक ऐसा मेगाफोन देने का वादा किया जिससे उसका संदेश तेजी से प्रसारित हो सके और मुख्यधारा में आ सके। वोकेनेस को व्यापार जगत की सर्वमान्य विचारधारा बनाकर, उन्होंने इसे हर जगह सर्वमान्य विचारधारा बनाने का वादा किया। बदले में, कंपनियों को वोकेनेस की नैतिक श्रेष्ठता का आवरण ओढ़ने का मौका मिल गया। यह एक धूर्ततापूर्ण समझौता था।

रामास्वामी के पाखंड के आरोप का सारांश यह है: 'एक निगम जागरूक लोगों को धन और प्रभाव प्रदान करता है, और बदले में वे निगम को अपनी कुकर्मों को छिपाने के लिए जागरूकता की नैतिक श्रेष्ठता का आवरण प्रदान करते हैं।' परोपकार का यह आवरण पारंपरिक जनसंपर्क की तुलना में निवेश पर बेहतर प्रतिफल देता है।

इस तरह अति धनाढ्य लोग नैतिक आचरण के नियमों का अपहरण कर रहे हैं, जो परंपरागत रूप से व्यवसाय संचालन के दायरे से बाहर रहे हैं। विचारों का बाज़ार मुख्य रूप से समान अवसर प्रदान करने वाले व्यक्तिगत प्रतिभागियों के लिए था, न कि पहचान की राजनीति के लिए। लेकिन अब हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट शक्ति सार्वजनिक बहस की कठोरता को दरकिनार करते हुए समाज पर अपने विचार थोप रही है। बड़ी कंपनियाँ अपने सामाजिक मूल्यों के आधार पर यह तय कर रही हैं कि वे निवेश और व्यावसायिक लेन-देन के लिए किसे प्राथमिकता देंगी। रामास्वामी के अनुसार, समस्या यह है कि 'जब कंपनियाँ नैतिक नियम बनाने के लिए अपनी व्यावसायिक बाज़ार शक्ति का उपयोग करती हैं, तो वे प्रभावी रूप से कम धन वाले लोगों को हमारे लोकतंत्र में समान रूप से अपनी बात रखने से रोकती हैं।'

रामास्वामी का तर्क है कि सीमित देयता वाली कंपनी मुक्त उद्यम के लिए आविष्कृत एक शक्तिशाली उपकरण थी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि सीमित देयता प्राप्त करने के बदले में, निगमों ने स्वयं को वाणिज्य तक ही सीमित रखा और सरकार के लिए निर्धारित भूमिकाओं में विस्तार नहीं किया। यह अलगाव अतीत में ईस्ट इंडिया कंपनी और आज के गूगल जैसी कंपनियों के उदय से समाज की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। लेकिन अब पूंजीवाद की संस्थाओं को वोकवाद के प्रसार और कार्यान्वयन के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और निगम वोक सक्रियता का उपयोग अपनी व्यावसायिक सीमाओं से परे जाकर समाज और सरकारों पर शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक माध्यम के रूप में कर रहे हैं।

यदि जागरूक पूंजीपति वाणिज्य से परे जाकर सामाजिक नैतिकता को भी नियंत्रित करना चाहते हैं, तो कॉर्पोरेट कानून में सीमित देयता प्रावधानों

को समाप्त कर देना चाहिए, ताकि वे अपने कार्यों के लिए सामाजिक जिम्मेदारी और जवाबदेही स्वयं वहन करें। वर्तमान में, सीमित देयता की कॉर्पोरेट सुरक्षा का दुरुपयोग सामाजिक सक्रियता के नाम पर किया जा रहा है। सरकारें सामाजिक नीति का संचालन करती हैं और लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से जवाबदेह होती हैं। निगम आम जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते, बल्कि केवल अपने शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह होते हैं, और यही कारण है कि उनकी सामाजिक सक्रियता शक्ति का अनुचित विस्तार है। एक अधिक न्यायसंगत दृष्टिकोण यह होगा कि सीमित देयता सुरक्षा के दायरे को कम किया जाए और उनकी सामाजिक सक्रियता को इस सुरक्षा से बाहर रखा जाए।

भारतीय सामाजिक सिद्धांत ने अनेक क्षेत्रों में सत्ता के अत्यधिक केंद्रीकरण की इस समस्या का समाधान किया। इसके लिए विभिन्न वर्णों (सामाजिक पूंजी के रूपों) के बीच पृथक्करण आवश्यक था। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि व्यवसाय (वैश्य वर्ण) संसाधनों के अधिकतम उपयोग द्वारा लाभ पर ध्यान केंद्रित करें, जबकि बुद्धिजीवी और अध्यात्मवादी (ब्राह्मण वर्ण) नैतिक मुद्दों पर नेतृत्व करें और सरकारें (क्षत्रिय वर्ण) जनता को सामाजिक लाभ पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करें।

'हितधारक पूंजीवाद' का नया विचार इन सीमाओं को चुनौती देता है और निजी निगमों को व्यापक रूप से मानवता के सामाजिक हितों को निर्धारित करने की अनुमति देता है। जिस प्रकार भारतीय संविधान सरकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने से रोकता है, उसी प्रकार बड़े व्यवसायों को भी सार्वजनिक चर्चा में हस्तक्षेप करने से रोका जाना चाहिए। यह नस्ल, लिंग, धर्म और राष्ट्रीय मूल जैसी 'संरक्षित श्रेणियों' की सूची का विस्तार करके और उसमें राजनीतिक विचारधारा को भी शामिल करके प्राप्त किया जा सकता है।

पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) आंदोलन, जो व्यापार जगत में व्यापक रूप से फैल रहा है, कंपनियों को उनके आचरण के आधार पर इन तीनों मापदंडों पर रेटिंग देता है। किसी फर्म को मिलने वाला निवेश उसके ESG रेटिंग पर निर्भर कर सकता है। लेकिन एक वाजिब सवाल यह उठता है कि किसी कंपनी के ESG स्कोर को निर्धारित करने के मानदंड कौन तय करता है और किस आधार पर? वर्तमान में, ESG शराब, जुआ, तंबाकू और हथियारों जैसे 'हानिकारक उद्योगों' से परहेज करता है। लेकिन मांस उद्योग और फार्मा उद्योग द्वारा परीक्षण के लिए जानवरों के उपयोग का क्या?
ईएसजी का आधार सराहनीय है, लेकिन यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अच्छी सामाजिक नीति के निर्माण में विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व हो। क्रिटिकल रेस थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि अश्वेतों और अन्य अंतरजातीय पहचानों के विचारों को किसी भी तर्कसंगत या तार्किक तर्क से ऊपर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तो इसी तर्क के आधार पर, हम ईएसजी के मानकों को तैयार करने में विविध मूल्य प्रणालियों को क्यों शामिल नहीं कर सकते?

2. जाति का अमेरिकीकरण

अवलोकन
भारतीय वामपंथियों की मदद से संयुक्त राज्य अमेरिका में एक सशक्त आंदोलन विकसित हुआ है, जिसका उद्देश्य जाति को विश्व इतिहास में नस्लवाद की सार्वभौमिक संरचना के रूप में स्थापित करना है। इस

सिद्धांत के परिणामस्वरूप एक नई पहचान गढ़ी गई है, जिसे पीड़ितता के केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे आमतौर पर अफ्रीकी-दलित पहचान के रूप में जाना जाता है।

ब्रेकिंग इंडिया नामक पुस्तक में अफ्रीकी-दलित आंदोलन का परिचय इस प्रकार दिया गया है:

1990 के दशक में, प्रिंसटन विश्वविद्यालय के एक अफ्रीकी-अमेरिकी विद्वान ने मुझे अनौपचारिक रूप से बताया कि वे भारत से लौटे हैं, जहाँ वे 'अफ्रो-दलित परियोजना' के साथ काम कर रहे थे। मैंने पाया कि यह अमेरिकी-संचालित और वित्तपोषित परियोजना अंतर-जातीय/वर्णीय अंतःक्रियाओं और दलित आंदोलन को अमेरिकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखती है। अफ्रो-दलित परियोजना दलितों को भारत के 'काले' और गैर-दलितों को भारत के 'गोरे' के रूप में चित्रित करने का प्रयास करती है... लेकिन यह जाति को नस्ल के रूप में देखने का एक गलत समीकरण है। यद्यपि आधुनिक जाति संरचनाओं और अंतर्संबंधों में दलितों के प्रति लंबे समय से पूर्वाग्रह रहा है, दलितों का अनुभव अमेरिका में अफ्रीकी दासता के अनुभव से बहुत कम मिलता-जुलता है।

एक दशक से भी अधिक समय पहले प्रकाशित होने के बाद से इस पुस्तक ने व्यापक प्रभाव डाला और अनेक प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न कीं। अमेरिका में और भारत में, जहाँ अफ्रीकी-दलित आंदोलन का स्वरूप समान है, काफी प्रगति हुई है और यह कहीं अधिक कपटपूर्ण रूप ले चुका है। उभरती हुई अफ्रीकी-दलित पहचान का आधार यह सिद्धांत है कि जाति ही नस्ल है। हम इस सिद्धांत और अमेरिकी मुख्यधारा पर इसके प्रभाव पर चर्चा करेंगे।

इस अध्याय में निम्नलिखित बातों की व्याख्या की गई है:

जैसा कि पहले बताया गया है, क्रिटिकल रेस थ्योरी को भारतीय समाज पर लागू किया गया है। सिद्धांत रूप में इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जैसा कि हम आगे समझाएंगे, यह विश्लेषण घटिया, पूर्वाग्रहों से भरा हुआ है और इससे गलत और खतरनाक निष्कर्ष निकले हैं।
हाल ही में बेस्टसेलर रही इसाबेल विल्करसन की किताब 'कास्ट: द ओरिजिन ऑफ आवर डिसकंटेंट्स' पर चर्चा की गई है ताकि इस विषय की नींव रखी जा सके। इसमें प्रस्तुत सिद्धांत को अमेरिका में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है और यह इस बात का पुख्ता सबूत है कि नस्ल, जाति की गहरी जड़ों वाली घटना का परिणाम है। वास्तव में, जाति को वह आधारभूत संरचना माना जाता है जिस पर नस्लवाद काम करता है। इसलिए, नस्लवाद-विरोधी आंदोलन को स्वयं को जाति-विरोधी आंदोलन के रूप में पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, 'ब्रेकिंग इंडिया' में चर्चा की गई अफ्रीकी-दलित परियोजना अब कहीं अधिक आक्रामक हो गई है, क्योंकि जो पहले अलग-अलग और स्वतंत्र आंदोलन थे - भारत में जाति से जूझ रहे दलित और अमेरिका में नस्लवाद से जूझ रहे अश्वेत - अब एक वैश्विक आंदोलन में विलीन हो गए हैं।

भारत में क्रिटिकल रेस थ्योरी का सफर
इस पुस्तक का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर केंद्रित है कि किस प्रकार क्रिटिकल रेस थ्योरी को भारतीय समाज पर लागू किया जा रहा है और भारत में आक्रामक रूप से निर्यात किया जा रहा है। भारतीय वामपंथ ने मार्क्सवाद और उत्तरआधुनिकतावाद से उत्पन्न सभी पूर्व पश्चिमी सामाजिक विचारों (जैसे उत्तरऔपनिवेशिक अध्ययन, सबाल्टर्न अध्ययन आदि) को पूरी तरह से आयात कर लिया है, और अब उनका नवीनतम जुनून क्रिटिकल रेस थ्योरी का भारतीयकरण करना है।

क्रिटिकल रेस थ्योरी (CRT) के कई विचार भारत में धीरे-धीरे, अनौपचारिक रूप से और चुपके से पेश किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय और भारत में उसके नेटवर्क की बदौलत, क्रिटिकल रेस थ्योरी की पूरी कार्यप्रणाली को भारत में स्थानांतरित करने के लिए एक औपचारिक आंदोलन भी चल रहा है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

सिद्धांत

इसका उपयोग कुछ समूहों को कट्टरपंथी बनाने के लिए किया जाता है।

सक्रियता के लिए उपकरण किट

पीड़ितों की पहचान का विकास और सुदृढ़ीकरण

हार्वर्ड में विभिन्न स्तरों पर पहले से ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

हार्वर्ड भारत के धनी व्यक्तियों से धनराशि की व्यवस्था करने के साथ-साथ कानूनी और राजनीतिक सहायता प्रदान करके अमेरिका से भी समर्थन प्रदान करता है।

यह व्यापक नेटवर्क एक शीर्ष-स्तरीय आंदोलन है, जो पहले के उन 'ब्रेकिंग इंडिया' आंदोलनों से बिल्कुल अलग है जो जमीनी स्तर पर घुसपैठ कर रहे थे। इस नए 'ब्रेकिंग इंडिया' आंदोलन का उद्देश्य भारत के सभी संस्थानों में, जिनमें सरकार, उद्योग, शिक्षाविद और गैर सरकारी संगठन शामिल हैं, एक विशिष्ट नेतृत्व स्थापित करना है। इसका विस्तृत विवरण भाग 2 में दिया जाएगा, इसीलिए हम हार्वर्ड को विश्व गुरु कहते हैं जो भारत में शाखाओं (ब्रांचों) के विशाल नेटवर्क से युक्त अपना संघ बना रहा है।

निम्नलिखित आरेख भारत में क्रिटिकल रेस थ्योरी के आयात से जुड़ी समस्याओं को दर्शाता है। भाग 2 और 3 में इन विषयों पर विस्तार से

चर्चा की गई है।

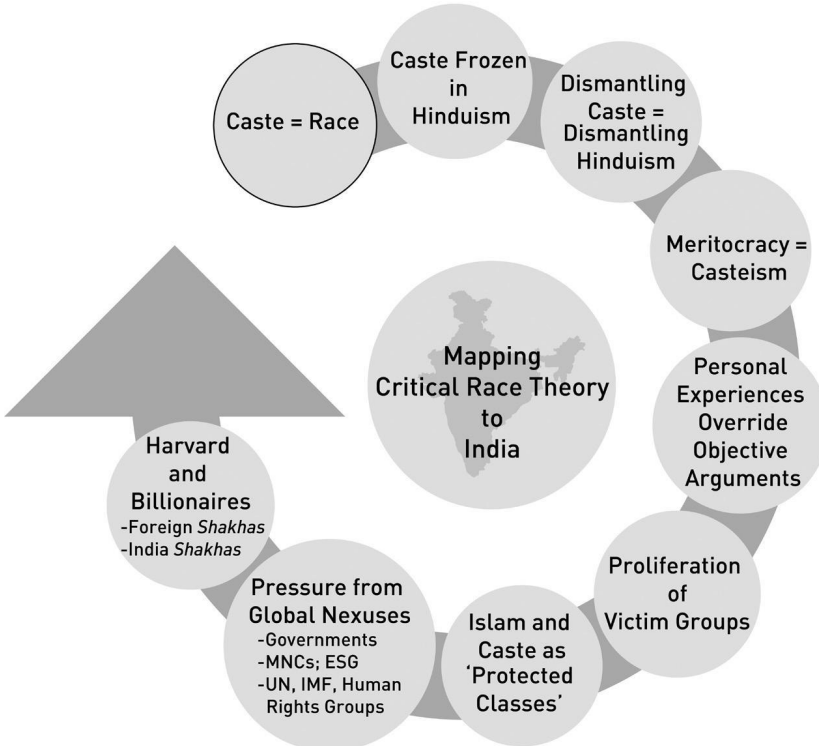

ऊपर से शुरू करते हुए दक्षिणावर्त दिशा में आगे बढ़ने पर, आरेख के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

जाति की सामाजिक संरचना को नस्ल की जैविक विशेषताओं के बराबर माना जाता है।

हिंदू धर्म में जाति को एक अपरिहार्य अंग के रूप में माना जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में जाति व्यवस्था को नजरअंदाज किया जाता है।

दावा यह है कि चूंकि जाति व्यवस्था हिंदू धर्म का एक अपरिहार्य हिस्सा है, इसलिए इसे खत्म करना तभी संभव है जब हिंदू धर्म को ही खत्म कर दिया जाए।

योग्यता-आधारित व्यवस्था को जातिगत संरचनाओं का उत्पाद और

इसलिए उसका एक हिस्सा माना जाता है।
चूंकि सभी वस्तुनिष्ठता संरचनात्मक विशेषाधिकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित होती है, इसलिए कहा जाता है कि वस्तुनिष्ठ तर्कों को व्यक्तिगत अनुभवों से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। केवल पीड़ित के रूप में पहचाने गए समूहों को ही वैध व्यक्तिगत अनुभव रखने वाला माना जाता है।
अनेक ऐतिहासिक अभिलेखों के विपरीत, इस्लाम को पीड़ित समुदाय माना जाता है। इसलिए, इसे 'संरक्षित वर्ग' का दर्जा प्राप्त करने का अधिकार है।
सरकारों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने ईएसजी कार्यक्रमों के माध्यम से और संयुक्त राष्ट्र तथा मानवाधिकार संगठनों जैसे अंतरराष्ट्रीय समूहों को शामिल करते हुए वैश्विक गठजोड़ का इस्तेमाल भारत पर इन ढांचों को स्वीकार करने के लिए दबाव डालने के लिए किया जाता है।
हार्वर्ड भारत और विदेशों में अपने विशाल और प्रभावशाली नेटवर्क के माध्यम से इस कथा को गढ़ने और प्रसारित करने में केंद्रीय भूमिका निभा रहा है।
हम पाठकों को याद दिलाना चाहते हैं कि क्रिटिकल रेस थ्योरी का अंतिम लक्ष्य उन सभी संरचनाओं को ध्वस्त करना है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़कों के रूप में ब्रांडेड लोगों द्वारा बनाया गया था। उन संरचनाओं के भीतर काम करना, उनमें संशोधन करना या उनके पूर्वाग्रहों को दूर करने का प्रयास उत्पीड़कों द्वारा अपने वर्चस्व की यथास्थिति को बनाए रखने की एक चाल के रूप में स्पष्ट रूप से और मुखरता से विरोध किया जाना चाहिए।
भारत के संदर्भ में, इसका अंतिम लक्ष्य वैदिक/हिंदू विरासत की सभी संरचनाओं, ग्रंथों, देवी-देवताओं, प्रतीकों, अनुष्ठानों, त्योहारों, रीति-रिवाजों, गुरुओं और संस्थाओं को नष्ट करना है। इसके अतिरिक्त, भारत

की प्रौद्योगिकी शिक्षा, विशेष रूप से IIT, निशाने पर आ गई है क्योंकि, जैसा कि हम अध्याय 4 में देखेंगे, हार्वर्ड के विद्वानों ने इसे योग्यतावाद का गढ़ घोषित किया है, और योग्यतावाद को ब्राह्मणों द्वारा स्थापित जातिवाद की संरचना बताया गया है।

एक बार फिर, संदेह दूर करने के लिए, हम दलितों जैसे विभिन्न समुदायों के विरुद्ध अत्याचारों और उनके निवारण की अनिवार्यता से इनकार नहीं कर रहे हैं। हम इन सभी समुदायों के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखते हैं। लेकिन हम वैदिक संरचनाओं के पूर्णतः विघटन के विरुद्ध हैं और आधुनिक समय के अनुकूल अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण को प्राथमिकता देते हैं। अध्याय 6 में हम जिन प्रतिवादों का विस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे, उनमें से एक यह है कि वर्ण (जिसे मोटे तौर पर जाति के समान माना जाता है) एकसमान रूप से अपमानजनक या स्थिर नहीं रहा है, बल्कि (क) यह एक सकारात्मक शक्ति भी रहा है; और (ख) अतीत में कई बार इसे भीतर से सफलतापूर्वक संशोधित किया गया है। इसलिए, हम हिंदू धर्म के पूर्णतः विघटन की मांग करने वाले तर्कों को अस्वीकार करते हैं। नीचे दी गई तालिका में क्रिटिकल रेस थ्योरी के विभिन्न दृष्टिकोणों और हमारी प्रतिक्रियाओं का सारांश दिया गया है।

Position of Critical Race Theorists and Afro-Dalits	Our Position
✓ Dalits and Lower Castes Suffer Serious Biases Alongwith Many Other Groups	Agree
✓ Problems can be Deep and Systemic, not Superficial	Agree
✗ All Victims of Social Grievances Must be Unified Using Intersectionality	Disagree. Each Grievance has its Own Contexts, Causes, and Remedies. Cannot Club them all as One Anti-thesis
✗ Zero-sum Hegelian Dialectic Needed to Defeat Opponents; no Room to Collaborate	Disagree. The Ego Level that Created the Problem Cannot Solve it. Dialectic will only Create more Violence. Need to Raise the Level of Individual Consciousness
✗ Caste Problems Caused by Hinduism and Cannot be Solved within Hinduism	Disagree. Caste as Practiced Today is Neither Necessary nor Sufficient in Hinduism
✗ Free Speech of Opponents Must be Denied, and Dissidents Attacked as Racists	Disagree. Must Avoid Creating a New Religion with Dogma, High Priests, Blasphemy Laws
✗ Wokeism Must be Spread Across All Civil Society Using Intimidation	Disagree. Need Honest and Fair Approaches

इस प्रकार की सामाजिक समस्याएं हर सभ्यता में मौजूद रही हैं और वास्तव में आज भी मौजूद हैं। वैदिक परंपरा ने अक्सर इन समस्याओं का समाधान किया है, जिसके परिणामस्वरूप बड़े सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, जिनका स्पष्टीकरण प्रमाणों के साथ दिया जाएगा। अतः प्रश्न यह उठता है कि क्या बाहरी हस्तक्षेप आवश्यक है और क्या यह सर्वोत्तम समाधान होगा?

दूसरी ओर, एक सभ्यता या राष्ट्र द्वारा दूसरे के आंतरिक सामाजिक मुद्दों में बाहरी हस्तक्षेप का इतिहास बेहद दुखद रहा है। उदाहरण के लिए, जब

विजय प्राप्त करने वालों ने उत्तरी अमेरिकी मूल निवासियों पर विजय प्राप्त की, तो अक्सर इसे इस आधार पर उचित ठहराया गया कि मूल निवासी मानव बलि जैसे अपराध करते थे, लेकिन इस विजय का परिणाम उनका नरसंहार हुआ। अफ़्रीकी लोगों के साथ यूरोपीय लोगों द्वारा किए गए व्यवहार में भी यही पैटर्न देखने को मिलता है। जब अमेरिका ने कैलिफ़ोर्निया, टेक्सास, न्यू मैक्सिको और नेवादा राज्यों पर कब्ज़ा करने के लिए मेक्सिको पर आक्रमण किया, तो असली मकसद केवल विस्तारवाद था क्योंकि उन ज़मीनों पर तेल की खोज हुई थी। लेकिन अमेरिकी कांग्रेस में इस आक्रमण को उचित ठहराने के लिए जो कारण बताया गया वह यह था कि मेक्सिकन लोग अपनी महिलाओं और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, और इसके लिए बहुत सारे सबूत गढ़े गए और उन्हें अत्याचार साहित्य के रूप में प्रस्तुत किया गया।
'पीली पत्रकारिता' शब्द का प्रयोग समाचार पत्रों की उस शैली के लिए किया जाता था जिसमें तथ्यों के बजाय सनसनीखेज खबरों पर जोर दिया जाता था और जिसका इस्तेमाल अमेरिकियों की भावनाओं को भड़काकर उन्हें अन्य देशों पर आक्रमण करने के लिए उकसाने के लिए किया जाता था। यह शब्द 1890 के दशक के मध्य में जोसेफ पुलित्जर के न्यूयॉर्क वर्ल्ड और विलियम रैंडोल्फ हर्स्ट के द न्यूयॉर्क जर्नल के बीच समाचार पत्रों की होड़ में सनसनीखेज पत्रकारिता को दर्शाने के लिए गढ़ा गया था। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में अपने चरम पर, यह उन कई कारकों में से एक था जिसने अमेरिका को क्यूबा और फिलीपींस में युद्ध में धकेलने में मदद की, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण हुआ।

जाति को वैश्विक नस्लवाद की संरचना माना जाता है
तीन शताब्दियों से अधिक समय तक चले औपनिवेशिक काल के दौरान,

वर्ण (संस्कृत शब्द जिसका अंग्रेजी में अनुवाद संभव नहीं है) का अंग्रेजों द्वारा प्रशासन की सुगमता और अपने उपनिवेश पर प्रभुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से गलत अनुवाद करते हुए इसे 'जाति' के रूप में वर्णित किया गया। इससे भी बुरी बात यह है कि भारतीय संविधान ने बाद में जाति की इस नई पदानुक्रमित संरचना को वैधता प्रदान की, जो आधुनिक वोट बैंक की राजनीति और भारतीय लोकतंत्र की नींव बन गई। जाति का लंबा और जटिल इतिहास अध्याय 6 का विषय है।

जाति की अवधारणा को और भी गलत तरीके से समझा गया है, इस बार अमेरिकी संदर्भ में, अश्वेत/श्वेत नस्लीय राजनीति के संदर्भ में। गलत व्याख्या करने वालों की सूची में हाल ही में शामिल हुई हैं पुलित्जर पुरस्कार विजेता अफ्रीकी-अमेरिकी पत्रकार और लेखिका इसाबेल विल्करसन। विल्करसन 'जाति' शब्द का प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेतों और श्वेतों के बीच नस्लीय तनाव को दर्शाने के लिए करती हैं। जाति को नस्ल के बराबर मानने का यह नया विचार सामाजिक न्याय आंदोलन के अग्रभाग में अमेरिकी शब्दावली में प्रवेश कर गया है। इसलिए, हम जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं, वह दोहरी विकृति है जिसे इस प्रकार दर्शाया जा सकता है: वर्ण → जाति → नस्ल।

विल्करसन का मूल सिद्धांत यह है कि भारत की सामाजिक संरचना 'विश्व की मूल जाति व्यवस्था' है, जो कई समाजों की सतह के नीचे गहराई में निहित है और अमेरिका और भारत दोनों में नस्लवाद का कारण बनती है। वह जाति को 'मानवीय मूल्यों की एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था के रूप में परिभाषित करती हैं, जो समाज में एक कृत्रिम पदानुक्रम का निर्माण करती है'; वह इसे नस्ल से जोड़ती हैं, यह कहते हुए कि नस्ल उस अंतर्निहित संरचना का उपकरण है जिसे जाति कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, जाति वह आधार है जिस पर नस्ल एक उपकरण के रूप में कार्य

करती है। निम्नलिखित चित्र उनके सिद्धांत के व्यापक विस्तार को दर्शाता है।

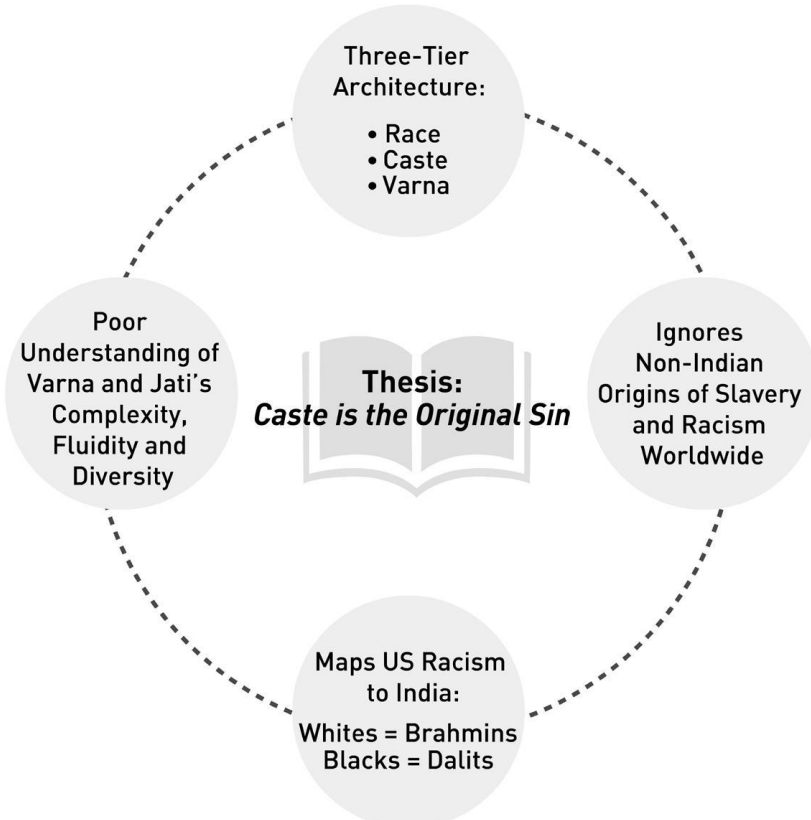

इस शोध प्रबंध ने विल्करसन को अमेरिका में एक सार्वजनिक बुद्धिजीवी के रूप में प्रसिद्धि दिलाई और नस्लवाद पर चल रही चर्चा को नई दिशा दी। ओपरा विन्फ्रे ने अपने बुक क्लब के माध्यम से विल्करसन की पुस्तक की बिक्री को बढ़ावा दिया, जबकि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे 'एक तत्काल अमेरिकी क्लासिक' कहा। मुख्यधारा मीडिया और अमेरिकी विचारकों में उनकी बेस्टसेलर पुस्तक की लोकप्रियता ने जाति को एक नया अर्थ दिया है, जिससे यह एक आम शब्द बन गया है। हालांकि, जैसा कि हम आगे

विस्तार से बताएंगे, यह तो पूरे भारत में इसके दूरगामी प्रभावों की बस शुरुआत है!

हालांकि, जाति को नस्ल के बराबर मानने का यह पहला मामला नहीं है। 2001 में, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में नस्ल पर संयुक्त राष्ट्र के एक सम्मेलन के दौरान, भारतीय सरकार को एक प्रस्ताव का विरोध करना पड़ा जिसमें जाति को नस्लवाद का एक रूप बताया गया था। इस्तेमाल किए गए तर्कों में से एक यह आम (लेकिन झूठा) बयानबाजी थी कि 'देवदासियों को मंदिर परिसर में ही हिंदू देवी-देवताओं के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिदिन बलात्कार का खतरा रहता है'। सरकार इस खंड को अंतिम प्रस्ताव से हटवाने में सफल रही।

लेकिन पहले के उदाहरणों में, जाति को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मौजूद कई अन्य प्रकार के नस्लवाद के साथ-साथ एक प्रकार के नस्लवाद के रूप में देखा जाता था। इन सभी रूपों का आपस में समतुल्य संबंध था; कोई भी प्राथमिक या दूसरों का कारण नहीं था। हालाँकि, जाति को नस्लवाद के रूप में प्रस्तुत करने के इस नवीनतम दावे में कुछ मौलिक रूप से नया और भिन्न है: इस नए सिद्धांत में, जाति नस्लवाद का मूल पाप है और वैश्विक स्तर पर नस्लवाद का कारण रही है। जाति शब्द को केवल एक रूपक या उपमा के रूप में नहीं अपनाया गया है, बल्कि एक कारण-कार्य सिद्धांत के रूप में अपनाया गया है जिसके अनुसार जाति हर जगह पाए जाने वाले नस्लवाद का कारण है। हम विल्करसन के सिद्धांत और उस पर आधारित नए आंदोलन की व्याख्या करेंगे।

त्वचा के रंग को अक्सर जाति का सूचक माना जाता है। भारत में अक्सर यह धारणा प्रचलित है कि निम्न जाति के लोग सांवले रंग के होते हैं और उच्च जाति के लोग गोरे रंग के। इसका उपयोग जाति को नस्ल से जोड़ने के लिए किया जाता है। विल्करसन अपने एक भारतीय साक्षात्कारकर्ता

के हवाले से कहती हैं कि भारत में 'त्वचा के रंग को लेकर जुनून' और 'सांवले रंग के भारतीयों के प्रति नफरत' है। हालांकि, सच्चाई यह है कि जाति (नस्ल के विपरीत) शारीरिक बनावट से निर्धारित नहीं होती। यह उन कई गलत धारणाओं में से एक है जो वह नस्ल के प्रति सजग अमेरिकियों को लुभाने के लिए फैलाती हैं, क्योंकि अमेरिका में अश्वेत होना शारीरिक बनावट पर आधारित है।

दरअसल, कृष्ण, काली और दुर्गा जैसे अधिकांश हिंदू देवी-देवता सांवले रंग के हैं, इस तथ्य का भजनों में हमेशा महिमामंडन किया जाता है। विल्करसन एक ओर तो हिंदू धर्म को नस्लवाद का कारण बताती हैं, वहीं दूसरी ओर इस तथ्य को नज़रअंदाज़ कर देती हैं कि अधिकांश हिंदू देवी-देवता सांवले रंग के हैं, जो उनके सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। इसके अलावा, भारत की प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में सांवले और गोरे रंग के व्यक्तियों के चित्र बने हैं, जिनमें सांवले रंग के लोगों को अक्सर कीमती वस्त्र और आभूषण पहने दिखाया गया है, जबकि गोरे रंग के सेवक उनके नौकर प्रतीत होते हैं। ये गुफा चित्र इस्लामी युग से पहले (सातवीं शताब्दी) के हैं और इस्लामी शासकों द्वारा अछूते रहे क्योंकि ये सदियों तक जनता की नज़रों से छिपे रहे, जब तक कि अंग्रेजों ने इन्हें खोजा नहीं। ऐसे कई उदाहरण हैं जो यह साबित करते हैं कि त्वचा के रंग को जातिगत स्थिति का पूर्ण मापदंड मानना जोखिम भरा है, और विल्करसन का ऐसा प्रयास अमेरिका में अश्वेतों की भावनाओं को भड़काने के उनके उद्देश्य को दर्शाता है।

इसके विपरीत तर्क भी दिया जा सकता है: भारतीय समाज में गोरे रंग के प्रति समकालीन वरीयता अरब, ईरान और तुर्की के आक्रमणकारियों का परिणाम थी, जो अपने साथ गोरी त्वचा को सौंदर्य के प्रतीक के रूप में लेकर आए थे। इस्लामी और फिर यूरोपीय उपनिवेशवाद ने भारतीय

सौंदर्यशास्त्र को जिस हद तक आकार दिया, और ये दोनों प्रकार के उपनिवेशवाद एक हजार वर्षों से अधिक समय तक चले, इस सिद्धांत पर संदेह करना आवश्यक है कि भारत की 'मूल' जाति व्यवस्था ने काले रंग के लोगों की स्थिति को निम्न स्तर पर पहुँचाया।

विल्करसन ने अमेरिका में जातिगत भेदभाव के उदाहरण जिम क्रो युग से दिए हैं, जो देश के इतिहास का एक बेहद नस्लवादी दौर था। जिम क्रो कोई व्यक्ति नहीं था, बल्कि उन्नीसवीं सदी के एक लोकप्रिय गीत पर आधारित एक उपनाम था, जो अफ्रीकी अमेरिकियों को रूढ़िबद्ध तरीके से पेश करता था। 'जिम क्रो' नस्लीय उत्पीड़न और अलगाव की उस व्यवस्था का प्रतीक बन गया जिसे अमेरिकी सरकार ने आधिकारिक तौर पर मान्यता दी थी। 'जिम क्रो कानून' 1877 से लेकर 1950 और 60 के दशक में नागरिक अधिकार आंदोलन तक लागू रहे। विल्करसन का यह दावा कि जातिगत उत्पीड़न भी इसी तरह का था, क्योंकि इसका अर्थ है कि इसे सरकारों द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी, गलत है। भारत में ब्रिटिश शासन को छोड़कर, किसी भी प्रकार के जाति-आधारित उत्पीड़न को लागू करना आधिकारिक सरकारी नीति नहीं थी। सामाजिक प्रथाओं और सरकारी कानूनों में अंतर होता है, जिसे विल्करसन समझने में चूक गए हैं।

विल्करसन ने बिल्कुल सही कहा है कि किसी समस्या का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक आप प्लास्टर और वॉलपेपर की ऊपरी सतह से परे न देखें। इसके लिए सामाजिक समस्या को गहराई से समझने की आवश्यकता है, और वह अपने शोध प्रबंध को अमेरिकी नस्ल मुद्दे के एक्स-रे के रूप में प्रस्तुत करती हैं। वह कहती हैं कि जिस प्रकार पुराने घरों में एक गहरी संरचना होती है जो उस क्षेत्र को छुपाती है जहां असली समस्या छिपी होती है, उसी प्रकार अमेरिकी समाज में भी जाति व्यवस्था

एक अदृश्य कंकाल की तरह है जो नस्लवाद के संचालन का केंद्र है। उनका शोध प्रबंध यह है कि जाति अमेरिकी समाज के विभाजन और आंतरिक संघर्षों का आधार है। एक भौतिक इमारत के उदाहरण का उपयोग करते हुए, विल्करसन जाति को स्टड और जॉइस्ट की इंजीनियरिंग संरचना कहती हैं जो एक भौतिक इमारत को सहारा देती है लेकिन आम लोगों द्वारा देखी नहीं जा सकती; केवल एक इंजीनियरिंग विशेषज्ञ ही हमें इसकी व्याख्या कर सकता है। वह अमेरिकी लोगों को जाति की व्याख्या करने में विशेषज्ञ हैं। वह लिखती हैं:

जाति हमारे विभाजनों का आधार है। यह मानवीय पदानुक्रम की संरचना है, हमारे मामले में, 400 साल पुरानी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अवचेतन निर्देशों का एक कोड है। जाति को देखना किसी देश के एक्स-रे को प्रकाश में देखने जैसा है। जाति व्यवस्था एक कृत्रिम संरचना है, मानवीय मूल्यों का एक निश्चित और अंतर्निहित क्रम है जो वंश और अक्सर अपरिवर्तनीय व्यवसायों के आधार पर एक समूह की कथित श्रेष्ठता को दूसरे समूहों की कथित हीनता के विरुद्ध स्थापित करता है। ये व्यवसाय सैद्धांतिक रूप से तटस्थ प्रतीत होते हैं, लेकिन उस पदानुक्रम में जीवन और मृत्यु का अर्थ निर्धारित करते हैं जो उस प्रमुख जाति का पक्ष लेता है जिसके पूर्वजों ने इसे नामित किया था। जाति व्यवस्था कठोर, अक्सर मनमानी सीमाओं का उपयोग करके क्रमबद्ध समूहों को अलग-अलग, एक दूसरे से विशिष्ट और उनके निर्धारित स्थानों पर रखती है।

एक और सशक्त उपमा जो वह देती हैं, वह शरीर के डीएनए से संबंधित है: 'जिस प्रकार डीएनए कोशिका विकास के लिए निर्देश संहिता है, उसी प्रकार जाति अमेरिका में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अंतःक्रियाओं के लिए उसके गर्भकाल से ही संचालन प्रणाली है।'

उनके अनुसार, जाति और नस्ल के बीच संबंध सरल और सीधा है: जाति

ही नस्लभेद का व्याकरण है। वह लिखती हैं:
जाति व्यवस्था मानव विभाजन के लिए एक साधन के रूप में जाति-आधारित व्यवस्था का आधार बनती है। यदि हमें मनुष्यों को जाति की भाषा में देखना सिखाया गया है, तो जाति वह अंतर्निहित व्याकरण है जिसे हम बचपन में, अपनी मातृभाषा सीखते समय, आत्मसात करते हैं। जाति, व्याकरण की तरह, न केवल हमारे बोलने के तरीके का, बल्कि सूचना को संसाधित करने के तरीके का भी एक अदृश्य मार्गदर्शक बन जाती है; वे स्वतःस्फूर्त गणनाएँ जो बिना सोचे-समझे वाक्य में समाहित हो जाती हैं। प्रत्येक लेबल के पीछे सदियों का इतिहास और मान्यताओं एवं मूल्यों का निर्धारण छिपा होता है।
दिलचस्प बात यह है कि वह नस्ल को लचीला और जाति को कठोर मानती हैं। इसलिए, जाति ही असली समस्या है: 'जाति हड्डियाँ हैं, नस्ल त्वचा। जाति स्थिर और कठोर है। नस्ल परिवर्तनशील और सतही है, जो समय-समय पर अमेरिका में प्रभुत्वशाली वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए पुनर्परिभाषित होती रहती है।' वह कहती हैं कि जाति हमें सदियों से बंदी बनाकर रखे हुए है: 'हम सभी सदियों पुराने एक मौन युद्ध में पैदा होते हैं, उन टीमों में शामिल होते हैं जिन्हें हमने खुद नहीं चुना है।'
यहां तक कि जब वह संक्षेप में यह स्वीकार करती है कि बाइबिल में नस्लवादी विचार हैं, तब भी वह इस बात पर जोर देती है कि बाइबिल में वर्णित नस्लवाद जाति की पूर्व-मौजूद धारणा पर आधारित था जो बाइबिल से पहले शुरू हुई थी।
विल्करसन ने भारत में दलितों के साथ समय बिताया, जो डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अनुयायी थे। डॉ. अंबेडकर एक अग्रणी बुद्धिजीवी और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहीं से उन्होंने भारत में जाति व्यवस्था और अमेरिका में नस्ल

व्यवस्था के बीच समानताओं की एक व्यवस्थित सूची विकसित करना शुरू किया। इसी कार्य के परिणामस्वरूप उनकी हालिया पुस्तक बेस्टसेलर बनी।

वह अंबेडकर को अपना नायक मानती हैं और उन्हें अमेरिकी कार्यकर्ता और बैपटिस्ट पादरी, रेवरेंड मार्टिन लूथर किंग जूनियर के भारतीय समकक्ष के रूप में संदर्भित करती हैं। वह अंबेडकर और जाने-माने अफ्रीकी अमेरिकी बुद्धिजीवी डब्ल्यू.ई.बी. डु बोइस के बीच हुई बातचीत का हवाला देती हैं। अंबेडकर ने डु बोइस को लिखा, 'भारत में अछूतों की स्थिति और अमेरिका में नीग्रो लोगों की स्थिति में बहुत समानता है।' डु बोइस ने अंबेडकर को जवाब में भारत के अछूतों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की।

यह सब सच है, लेकिन कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। विल्करसन की किताब में जिस बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ किया गया है, वह है किंग जूनियर द्वारा मोहनदास गांधी के प्रति व्यक्त की गई उनकी स्पष्ट कृतज्ञता। किंग जूनियर गांधी के प्रति श्रद्धा रखते थे, जैसा कि राजनीतिक कार्यकर्ता रेव. जेसी जैक्सन और उनके कई पूर्ववर्ती और गुरु भी रखते थे। यदि उन्होंने अफ्रीकी-अमेरिकी आंदोलन के इतिहास में इसका उल्लेख किया होता, तो उन्हें आधुनिक जातिगत भेदभावों से लड़ते हुए भी गांधी के वर्ण व्यवस्था के समर्थन पर चर्चा करनी पड़ती। उस चर्चा के लिए उन्हें कहीं अधिक सूक्ष्म समझ की आवश्यकता होती। ऐसा विश्लेषण उन्हें जाति की जटिलताओं में उलझा देता, जिससे उनके लिए अपने पाठकों की अनभिज्ञ भावनाओं को भड़काने वाले व्यापक बयान देना मुश्किल हो जाता।

सच तो यह है कि किंग जूनियर गांधी जी से प्रेरित होकर 1954 में अपना नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया था। इसके अलावा, बीसवीं सदी

के पूरे अफ्रीकी अमेरिकी संघर्ष को उसके शुरुआती नेताओं ने गांधीवादी आंदोलन के रूप में वर्गीकृत किया था, जिसमें गांधी जी के सत्याग्रह या शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा के विचारों का उपयोग किया गया था। कई प्रमुख अफ्रीकी अमेरिकी गांधी जी के आंदोलन का अध्ययन करने और उससे सीखने के लिए भारत गए थे। विल्करसन जाति को एक विशेष तरीके से परिभाषित करके हिंदू धर्म पर चुनिंदा हमला कर रहे हैं, जबकि आधुनिक नस्लवाद और अन्य पूर्वाग्रह प्रणालियों से निपटने के लिए हिंदू धर्म की क्षमता को पूरी तरह से अनदेखा कर रहे हैं।

भारतीय विचारों को अफ्रीकी अमेरिकियों द्वारा आत्मसात करने की प्रक्रिया दो चरणों में हुई। पहला चरण बीसवीं शताब्दी में था, जब भारतीय संस्कृति को अश्वेतों को मुक्ति दिलाने वाले संसाधन के रूप में देखा गया और गांधीजी को इस प्रक्रिया का अग्रणी विचारक माना गया। दूसरा चरण बीसवीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ, जब भारतीय संस्कृति को जाति व्यवस्था के कारण नस्लवाद का कारण बनने वाली एक अभिशाप के रूप में देखा जाने लगा।

विल्करसन का कहना है कि अमेरिका में जाति-आधारित नस्लवाद के अनुभव से पहले, अश्वेत लोगों जैसी कोई पहचान नहीं थी, क्योंकि उनकी पहचान अफ्रीका में उनके विशेष कबीले तक ही सीमित थी। इसी तरह, श्वेत लोगों जैसी कोई पहचान नहीं थी, क्योंकि वे खुद को आयरिश, इतालवी, जर्मन, फ्रांसीसी आदि मानते थे, और जाति व्यवस्था के कारण ही अमेरिका में 'श्वेत' कहलाए। हालांकि, नस्लवाद के अमेरिकी इतिहास का सिद्धांत देते हुए, वह पंद्रहवीं-सोलहवीं शताब्दी के खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस की भूमिका को नजरअंदाज करती हैं, जिन्होंने अपने ईसाई पूर्वाग्रहों के कारण मूल अमेरिकियों को अमानवीय समझा। वह लिखती हैं: 'अमेरिकी जाति व्यवस्था की शुरुआत 1619 की गर्मियों में

वर्जीनिया कॉलोनी में पहले अफ्रीकियों के आगमन के बाद के वर्षों में हुई।' उनके विश्लेषण में, उस पूर्व काल को वह महत्व नहीं दिया गया है जिसके वह हकदार है, जब पोप के आशीर्वाद से स्पेनिश विजेताओं ने मूल अमेरिकियों पर सबसे अकल्पनीय अत्याचार किए थे।

अंतर्विवाह प्रथा को लेकर उनकी चिंता जायज़ है, जिसका अर्थ है जन्म आधारित समुदाय के भीतर ही विवाह सीमित करना। बीसवीं शताब्दी के आरंभिक सुजननवाद आंदोलन में शामिल हुए कई अमेरिकियों की वे आलोचना भी उचित ही करती हैं, जिनमें आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उद्योगपति हेनरी फोर्ड और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शिक्षाविद एवं अध्यक्ष चार्ल्स विलियम एलियट शामिल हैं। लेकिन सुजननवाद के प्रस्तावों के लिए प्रसिद्ध अमेरिकी नस्लवादी मैडिसन ग्रांट का हवाला देकर वे सुजननवाद को जाति से गलत तरीके से जोड़ती हैं; वे ग्रांट को जाति पर अपने विषय-विशेषज्ञों में से एक के रूप में इस्तेमाल करती हैं। इससे जाति व्यवस्था सुजननवाद की परियोजना जैसी प्रतीत होती है।

विल्करसन कहती हैं कि भारत में उच्च जातियाँ अपने रक्त की शुद्धता को बनाए रखना चाहती थीं, और यह आज तक कायम है। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि भारत के सभी वर्गों के कई समुदाय अपनी विशिष्ट पहचान, रीति-रिवाजों और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए अंतर्विवाह प्रथा को चुनते हैं।

विल्करसन को शायद इस ऐतिहासिक तथ्य की जानकारी नहीं है कि उच्च जातियाँ भी भारतीय ही थीं, न कि विदेशी विजेता। भारतीय इतिहास में अफ़्रीकियों को किसी अन्य महाद्वीप (और इसलिए एक अलग नस्ल) से लाकर गुलामी में धकेलने का कोई उदाहरण नहीं मिलता, सिवाय मुस्लिम शासनकाल के, जैसा कि इस अध्याय में आगे बताया गया है। उनकी पुस्तक किस्सों और उन लोगों के उद्धरणों से भरी है जिन्हें प्रामाणिक

विद्वान माना जाता है, और हिंदू दृष्टिकोण से कोई प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि कई हिंदू बुद्धिजीवियों ने जाति के बारे में उनके द्वारा दिए गए कथनों पर विस्तार से लिखा है और उनका खंडन किया है।

उनकी पुस्तक अमेरिका का वर्णन करने और नस्ल के साथ समानताएं दिखाने के लिए जाति का चयनात्मक रूप से प्रयोग करती है। वह भारत से लिए गए कुछ उदाहरणों को अमेरिका में अश्वेतों के अनुभवों के साथ जोड़कर प्रस्तुत करती हैं। उदाहरण के लिए, वह श्वेत अमेरिकी नस्लवाद को 'प्रमुख जाति', 'सत्ताधारी बहुसंख्यक जाति' या 'उच्च जाति' जैसे शब्दों से संदर्भित करती हैं। अमेरिका में एशियाई और लातिनो लोगों को 'मध्यम जाति' कहा जाता है, जबकि अफ्रीकी अमेरिकियों को 'अधीनस्थ जाति', 'निम्नतम जाति', 'निचली जाति' और 'अपमानित जाति' के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह भारतीय और अमेरिकी इतिहास की तुलना करने का एक सरलीकृत तरीका है।

विल्करसन का कहना है कि अमेरिका और भारत दोनों पर आर्यों ने विजय प्राप्त की थी, एक ने अटलांटिक महासागर पार किया था जबकि दूसरे ने उत्तर से पहाड़ों को पार करते हुए भारत में प्रवेश किया था। वे वैश्विक जाति व्यवस्था के जनक हैं, जिसे वे अपने साथ हर जगह ले गए। उनका कहना है कि लोकतंत्र ने दोनों देशों में जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ नहीं गिराया है। इतिहास और परिणामों में इतने मूलभूत अंतरों के बावजूद, दोनों देशों में जाति व्यवस्था एक गहरी संरचना के रूप में मौजूद है। दूसरे शब्दों में, उनके अनुसार आर्यों की सामाजिक पदानुक्रम की संरचनाएं हर जगह के समाजों में समाहित हो गईं।

वह लिखती हैं:

दोनों देशों की सामाजिक व्यवस्थाएँ अत्यंत भिन्न हैं। फिर भी, मानो एक

ही निर्देश पुस्तिका का अनुसरण करते हुए, जिसे उनकी विशिष्ट संस्कृतियों के अनुरूप ढाला गया हो, दोनों देशों ने कठोर सीमा रेखाएँ और प्रोटोकॉल बनाए रखने के समान तरीके अपनाए। दोनों देशों ने अपनी प्रमुख जातियों को निम्न मानी जाने वाली जातियों से अलग, पृथक और ऊपर रखा। दोनों देशों ने अपने मूल निवासियों - भारत में आदिवासियों और संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल अमेरिकियों - को दूरस्थ क्षेत्रों में और समाज के अनदेखे हाशिये पर निर्वासित कर दिया। दोनों देशों ने सबसे निचले समूहों - भारत में दलितों और संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकियों - को सबसे निचले पायदान पर जकड़ने के लिए कानूनों का एक जाल बनाया, और उन्हें वहीं रखने के लिए आतंक और बल का प्रयोग किया।

और आगे विस्तार से बताते हैं:

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत क्रमशः मानव इतिहास के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र बन गए, दोनों ही अपनी-अपनी संस्कृतियों के पवित्र ग्रंथों के अध्ययन पर आधारित जाति व्यवस्था पर टिके हुए थे। दोनों ही देशों में अधीनस्थ जातियों को सबसे निचले पायदान पर रखा गया था, जिन्हें अतीत के पापों के कारण उनके अपमान का पात्र माना जाता था।

हिटलर के जर्मनी से जुड़े नाज़ीवाद के लिए भी जाति व्यवस्था को ही दोषी ठहराया जाता है, क्योंकि विल्करसन आर्य आक्रमण सिद्धांत को सत्य मानते हैं। लेकिन विज्ञान, भाषाविज्ञान, पुरातत्व और कला इतिहास के प्रमाणों के आधार पर इस सिद्धांत को खारिज कर दिया गया है। अगले पृष्ठ पर दिया गया चित्र विल्करसन के सिद्धांत के आधार को दर्शाता है। यूरोपीय संस्कृतियों में नस्लीय भेदभाव के कारण के रूप में चर्च की गहरी संरचनाओं को वह पूरी तरह से अनदेखा करती हैं। नाज़ीवाद के उदय की

व्याख्या करते हुए, वह चर्च और ईसाई-पूर्व यूरोपीय संरचनाओं की भूमिका को नज़रअंदाज़ करती हैं जिनका भारत या वैदिक विचार से कोई संबंध नहीं था। वह इस बात को पूरी तरह से अनदेखा करती हैं कि कैसे उत्पीड़ित यहूदियों को भारत में एक नया घर मिला; स्पष्ट रूप से, यह उनके शोध प्रबंध के अनुरूप नहीं है। विल्करसन पश्चिमी समाज में निहित गुलामी, नरसंहार, नस्लवाद, सुजननशास्त्र आदि के अन्य कारणों से ध्यान भटकाती हैं। संक्षेप में, वह पश्चिमी नस्लवाद को एक विदेशी और एशियाई चीज़ के रूप में सामान्यीकृत करती हैं।

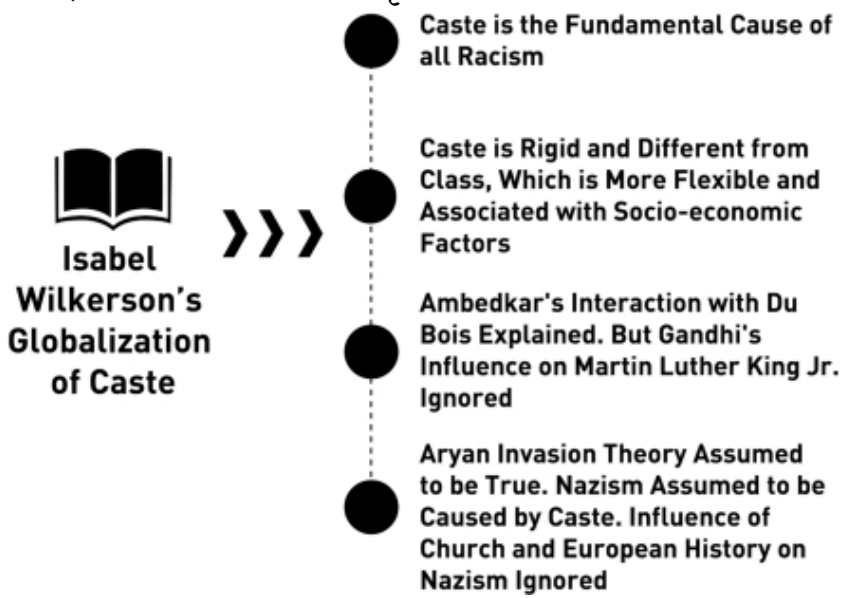

हिंदू धर्म को एक जड़ और दमनकारी व्यवस्था के रूप में खारिज कर दिया गया है।

ऐसे निर्णायक निष्कर्षों में वर्ण व्यवस्था के परिवर्तनशील इतिहास को नजरअंदाज किया जा रहा है, जो न केवल समय के साथ बल्कि विभिन्न समुदायों की विविधता में भी दिखाई देता है। विल्करसन ऐसा प्रतीत

कराती हैं मानो हिंदू सामाजिक संरचना कोई स्थायी चीज हो, ठीक उसी तरह जैसे इब्राहीमी धर्मों को एक ही ग्रंथ में स्थिर कर दिया गया हो। वह मानती हैं कि सामाजिक मानदंड समय के साथ और सभी हिंदू क्षेत्रों में समान रूप से लागू किए गए हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है।

उदाहरण के लिए, भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इतिहास दर्शाता है कि धातु विज्ञान, वस्त्र विज्ञान, कृषि और अन्य क्षेत्रों में भारत की कई अभूतपूर्व उपलब्धियाँ उन समुदायों द्वारा हासिल की गईं जिन्हें वर्तमान में निम्न जाति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के कारण संरचनात्मक बदलाव हुए, जिससे कुछ व्यवसायों का अवमूल्यन हुआ। व्यवसायों में विविधता थी और कुछ ऐसे व्यवसाय जिन्हें अब अधीनस्थ और निम्न जाति का माना जाता है, वास्तव में उस समय प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। भारतीय इतिहास के विभिन्न कालखंडों में जातिगत समीकरणों की प्रकृति भिन्न-भिन्न रही।

विल्करसन ने भारतीय जनसमूह के सभी वर्गों की औपनिवेशिक और इस्लामी काल से पूर्व की समृद्धि को नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने एक हजार वर्षों के उपनिवेशवाद के प्रभाव पर भी पर्याप्त विचार नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप एक ऐसी संस्कृति का निर्माण हुआ है जो अभी तक पूरी तरह से उपनिवेशवाद से मुक्त नहीं हो पाई है। यह अनुभव अन्य किसी भी प्रमुख सभ्यता की तुलना में हिंदू सभ्यता के लिए अद्वितीय है क्योंकि न तो ईसाई और न ही इस्लामी समाजों को इतने लंबे समय तक इतने गहन रूप से उपनिवेशित किया गया था। प्राचीन वैदिक संस्कृति की निंदा करने के बजाय हमें इन विभिन्न प्रकार के उपनिवेशवाद के प्रभावों का अध्ययन करना चाहिए। विल्करसन की पुस्तक में जातिगत गतिशीलता का इस प्रकार का सूक्ष्म विश्लेषण, संदर्भ और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य नहीं मिलता है।

विल्करसन भारत के भीतर से उत्पन्न सामाजिक समस्याओं के समाधानों को स्वीकार करने में विफल रहती हैं। वह उन विभिन्न धार्मिक व्यवस्थाओं की पूरी तरह से अनदेखी करती हैं जो समाज को सही राह पर लाने के एक तरीके के रूप में अस्तित्व में आईं। वह इस तथ्य को भी अनदेखा करती हैं कि भारत के कुछ महानतम ऋषि, जिन्हें आज भी सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, जैसे वाल्मीकि, जिनके नाम पर रामायण का श्रेय दिया जाता है, समाज के सबसे निचले तबके से थे।

एक अधिक संतुलित दृष्टिकोण यह स्वीकार करता है कि अर्थव्यवस्थाएँ कभी स्थिर नहीं होतीं और किसी समुदाय की आर्थिक स्थिति निश्चित नहीं होती। विभिन्न व्यवसायों की सापेक्षिक वित्तीय स्थिति में उतार-चढ़ाव होता रहता है। बाज़ार की परिस्थितियाँ, राजनीति और अन्य कारक बदलते रहते हैं, और सत्ता संरचनाएँ गतिशील होती हैं।

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भी जातिगत समीकरण अलग-अलग रहे हैं। उत्तर भारत की स्थिति दक्षिण भारत से भिन्न है। कैरिबियाई देशों में हिंदुओं की जातिगत संरचना भारत जैसी नहीं है; वहां सभी जातियों के हिंदुओं को बंधुआ मजदूरी के बहाने कैरिबियाई देशों में लाकर गुलाम बनाया गया था। विल्करसन इस विषय पर मौन हैं। अमेरिका और कनाडा में हिंदू अपने नए देशों में सामाजिक रूप से ढल गए हैं, फिर भी वे हिंदू बने हुए हैं। हांगकांग जैसे देशों में हिंदू प्रवासी भी बहुत भिन्न हैं। इसलिए, हिंदू धर्म एक समान, समरूप समाज नहीं है।

विल्करसन की एक और खामी यह है कि वे ब्राह्मणों और क्षत्रियों पर लागू होने वाले कठोर वर्ण प्रतिबंधों से अनभिज्ञ प्रतीत होती हैं, जो निचली जातियों पर लागू नहीं होते। धन संचय और भौतिक सुखों के उपभोग के मामलों में निचली जातियों को ब्राह्मणों की तुलना में अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। वर्ण व्यवस्था में चार अलग-अलग वर्णों के अनुरूप चार अलग-

अलग पदानुक्रम हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना उत्तरदायित्व और अधिकार क्रम है। उदाहरण के लिए,

ब्राह्मण केवल औपचारिक ग्रंथों के विषय-विशेषज्ञ होने और अनुष्ठान संपन्न करने के अधिकार के मामले में सर्वोच्च स्थान पर हैं। उन्हें भौतिक संपत्ति रखने की मनाही है, और अधिकांश भौतिक समृद्धि अन्य जातियों द्वारा अर्जित और उपभोग की जाती थी। इसलिए, उनसे गरीब रहने का आग्रह किया जाता था।

क्षत्रियों के पास राजनीतिक शक्ति होती है, वे सेना, दरबारों में सेवा करते हैं और न्यायाधीश एवं राजा भी बनते हैं। उनका उद्देश्य आर्थिक पूंजी पर नियंत्रण करना नहीं है।

व्यापार और वाणिज्य में वैश्यों का दबदबा है, जो आधुनिक पूंजीपतियों के समकक्ष है। लेकिन उन्हें राजनीति में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।

शूद्रों को शारीरिक और व्यावहारिक कौशल में निपुणता प्राप्त थी। इसमें शल्य चिकित्सा, कला, कृषि आदि क्षेत्र शामिल हैं। शूद्रों ने अतीत के कुछ युगों में काफी समृद्धि प्राप्त की और यहाँ तक कि शूद्र शासकों का एक वंश भी अस्तित्व में था।

आधुनिक कार्यस्थल में अधिकांश ब्राह्मण शास्त्रों में वर्णित उन आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं जो उन्हें धन संचय करने या राजनीतिक सत्ता धारण करने से रोकते हैं। उनकी पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, ब्राह्मणों को प्रौद्योगिकी उद्यमी या धनी पूंजीपति नहीं बनना चाहिए, न ही उन्हें राजनीति में प्रवेश करने की अनुमति है। इसी प्रकार, उद्योगपतियों (वैश्य होने के नाते) को राजनीति में प्रवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं। क्षत्रिय होने का दावा करने वालों को पूंजी बाजार में निवेश करने की अनुमति नहीं है। वर्ण व्यवस्था ध्वस्त हो गई है क्योंकि प्रत्येक वर्ण के अधिकारों और विशेषाधिकारों की सीमाओं का उल्लंघन हुआ है।

पारंपरिक सुरक्षा उपायों के इन उल्लंघनों ने उन समस्याओं को जन्म दिया है जिनकी आलोचना की जा रही है।

स्पष्टतः, विशेषाधिकारों का कोई एकसमान और रैखिक क्रम नहीं था। चारों वर्ण एक-दूसरे के समानांतर और पूरक थे, जिनमें अलग-अलग आंतरिक पदानुक्रम थे। वर्णों को व्यावसायिक विशिष्टताओं के रूप में बेहतर समझा जा सकता है जो प्रारंभ में व्यक्तिगत गुणों और योग्यता पर आधारित थीं। बाद में, यह सामाजिक पूंजी के एक वंशानुगत रूप में परिवर्तित हो गया। इन सभी विसंगतियों की आलोचना, बहस और नए सूत्रीकरण प्रस्तावित करना सबके लिए जायज़ है।

प्रत्येक वर्ण के लिए निर्धारित अलग-अलग नियमों के विपरीत, श्वेत अमेरिकी ऐसे किसी भी नियम से बंधे नहीं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में, विभिन्न प्रकार की सामाजिक पूंजी को अलग-अलग वर्गों में विभाजित नहीं किया गया है। श्वेतों ने एक ही समरूप पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। इसलिए, ब्राह्मणों को श्वेतों के साथ जोड़ना हास्यास्पद और स्वार्थपूर्ण भी है, क्योंकि यह पश्चिमी समाज में व्याप्त सभी सामाजिक बुराइयों का दोष विदेशियों पर मढ़ने का प्रयास करता है, जिससे पश्चिमी सार्वभौमिकता को विश्व के लिए एक आदर्श के रूप में मजबूत किया जा सके। अमेरिकी अश्वेतों और श्वेतों के बीच विभाजन को भारतीयों को दोषी ठहराकर समझाया जा रहा है।

विल्करसन ब्राह्मणों और गोरों की तुलना करते हुए कहती हैं कि उन्हें सामान्यता, सुंदरता आदि का सर्वोच्च मानक माना जाता है। हालांकि अमेरिका में गोरों के मामले में यह बात सच हो सकती है क्योंकि उन्हें उन गुणों से युक्त माना जाता है जिन्हें सभी गैर-गोरों को प्राप्त करने की आकांक्षा रखनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों के मामले में यह बात सच नहीं है। वह लिखती हैं:

जाति व्यवस्था में, प्रमुख जाति को सूर्य के समान माना जाता है जिसके चारों ओर अन्य सभी जातियाँ घूमती हैं, और इसे सामान्यता, बुद्धि, सौंदर्य के मानक के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके आधार पर अन्य सभी जातियों का मूल्यांकन किया जाता है, और उन्हें प्रमुख जाति से मनोवैज्ञानिक निकटता के आधार पर अवरोही क्रम में रखा जाता है। ब्राह्मणों के गुण ही सर्वोपरि नहीं हैं, और न ही सभी जातियों को उन्हें पाने की आकांक्षा रखनी चाहिए। नाट्यशास्त्र नामक भारतीय पद्धति में भी, जो कला प्रदर्शन पर आधारित एक ग्रंथ है और जिसमें सौंदर्य की अवधारणा का भी विस्तृत वर्णन है, यह संकेत मिलता है कि ब्राह्मण सबसे सुंदर और शूद्र सबसे कम सुंदर हैं।

विल्करसन को इस बात का एहसास नहीं है कि भारतीय लोग, भले ही गरीब हों, अपने विशिष्ट समुदाय पर गर्व करते हैं। यह एक ऐसी पहचान है जिसका सांस्कृतिक महत्व है: त्यौहार, परंपराएं, खान-पान और विशिष्ट ग्राम देवी-देवता। यही भारतीय विविधता की समृद्धि है। स्वस्थ विविधता और भेदभावपूर्ण अंतर में सूक्ष्म अंतर है; बाद वाले का विरोध किया जाना चाहिए, न कि पहले वाले का। पश्चिमी देशों की एकरूप संस्कृति के विपरीत, भारतीय संस्कृति विरोधाभासों पर आधारित है। इसका अर्थ यह नहीं है कि एक समुदाय श्रेष्ठ है और दूसरा हीन, बल्कि यह है कि दोनों पक्षों में असुविधा या चिंता पैदा होने के बावजूद, मतभेदों को पहचानना, उनकी सराहना करना और उन्हें स्वीकार करना आवश्यक है।

वर्ण व्यवस्था को अप्रचलित बताकर उसकी आलोचना की जा सकती है क्योंकि आज प्रौद्योगिकी कई पुराने व्यवसायों की जगह ले चुकी है, या कम से कम उन्हें बाधित कर रही है, और अब उन्हें अलग-अलग समुदायों में रखना संभव नहीं है। वास्तव में, आजकल 'सफलता' को सभी प्रकार की पूंजी (सामाजिक, धन और बौद्धिक) के संचय के रूप में देखा जाता

है, जिसके लिए बहुवर्णीय योग्यता आवश्यक है। उदाहरण के लिए, एक व्यवसायी (वैश्य) जिसके पास वैज्ञानिक योग्यता (ब्राह्मण) भी हो, अक्सर सफलता के शिखर पर पाया जाता है - जैसा कि एलोन मस्क, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, लैरी पेज आदि के उदाहरणों में देखा जा सकता है।

वर्ण एक ऐसी अवधारणा है जिसे संस्कृत संदर्भ से अलग करके किसी अन्य ढांचे में समाहित करने पर सबसे जटिल और गलत समझा जाता है। जाति की बात करें तो, इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, न ही जमीनी स्तर पर एकसमान कार्यप्रणालियाँ हैं, और न ही उन भारतीयों के बीच कोई आम समझ है जो इससे प्रभावित प्रतीत होते हैं। इसे गलत तरीके से शक्ति और उत्पीड़न के एक कठोर पिरामिड के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें समय, स्थान या किसी अन्य संदर्भ के अनुसार कोई भिन्नता नहीं है, और न ही परंपरा के भीतर से परिवर्तन की कोई गुंजाइश या लचीलापन है।

अन्य जाति व्यवस्थाओं की अनदेखी करना

विल्करसन एक महत्वपूर्ण बिंदु को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं कि मुसलमानों के आगमन से पहले भारत में दास प्रथा नहीं थी। (प्राचीन ग्रंथों में दास प्रथा का आरोप दास शब्द के गलत अनुवाद पर आधारित है, जिसमें दास को दास, शूद्र को दास, क्षत्रिय को सामंती शासक आदि के रूप में अनुवादित किया गया है।) मुस्लिम शासन के दौरान भारत में दास प्रथा की शुरुआत हुई, इसका प्रमाण 2013 में न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में अफ्रीकी-अमेरिकी विद्वानों द्वारा आयोजित एक प्रमुख प्रदर्शनी में मिलता है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे अफ्रीकियों को गुलाम बनाकर भारत लाया गया, कैसे उनमें से कई बाद में भारतीय समाज में घुलमिल

गए, और कैसे कुछ अपने दम पर स्थानीय नेता और शासक बन गए। अकादमिक कृतियों में इस्लामी शासन के दौरान हिंदुओं की व्यापक दासता का भी वर्णन मिलता है। भारतीयों को नियमित रूप से मध्य एशिया के दास बाज़ारों में ले जाया जाता था और बेचा जाता था, जहाँ पुरुषों के मामले में श्रम के मूल्य और महिलाओं के मामले में उम्र और रूप-रंग के आधार पर कीमतें तय होती थीं। अंततः, कई पीढ़ियों के बाद, कुछ बचे हुए लोग यूरोप के विभिन्न हिस्सों में पहुँचने में कामयाब रहे, जहाँ वे बहिष्कृत हो गए और यूरोप के रोमा लोग (जिन्हें अपमानजनक रूप से जिप्सी कहा जाता था) के रूप में जाने गए। यूरोप में कई शताब्दियों तक चले उत्पीड़न के दौरान उनकी भयावह कहानी जारी रही। इसका अंत नाज़ियों के गैस चैंबरों में हुआ - वे मारे गए लाखों लोगों में शामिल थे, हालाँकि उन्हें 'होलोकॉस्ट' के पीड़ितों में शामिल नहीं किया गया है। ('होलोकॉस्ट' शब्द केवल यहूदी पीड़ितों के लिए आरक्षित है।) ये यूरोप के दलित हैं, जो सदियों से ईसाई उत्पीड़न का परिणाम हैं। विल्करसन द्वारा अनदेखा किया गया एक और असुविधाजनक तथ्य दक्षिण एशिया में प्रचलित मुस्लिम जाति व्यवस्था है। अशरफ जाति सर्वोच्च जाति है और पैगंबर मुहम्मद, अन्य अरब सरदारों, तुर्कों या फारसियों की वंशज होने का दावा करती है। अजलाफ भारतीय मूल के लोग हैं जो इस्लामी आक्रमणों द्वारा परिवर्तित हुए; अर्ज़ल मुसलमानों में सबसे निचली जाति है। उर्दू शब्द 'कौम' जाति को संदर्भित करता है और पाकिस्तान में वैवाहिक विज्ञापनों में इसका आमतौर पर उल्लेख किया जाता है। सैद्धांतिक रूप से, इस्लाम में जाति व्यवस्था निषिद्ध है, इसलिए कौम की राजनीतिक रूप से सही व्याख्या जातीयता या समान विरासत वाले समुदाय के रूप में की जाती है। ऐसे समुदाय भी हैं जो खुद को दलित मुस्लिम के रूप में पहचानते हैं। अध्याय 6 में मुस्लिम जाति

व्यवस्था पर अंबेडकर के लेखन की चर्चा की गई है, और विल्करसन इसे अनदेखा करती हैं, जबकि वह उन्हें अपना आदर्श मानती हैं।
विश्व भर में व्याप्त विभिन्न प्रकार के भेदभावों पर चर्चा करते हुए और उन्हें भारत की जाति व्यवस्था से जोड़ते हुए, विल्करसन ईसाई-पूर्व और ईसाई दोनों ही यूरोपीय समाजों में मौजूद जाति व्यवस्थाओं की गहराई से पड़ताल करने में विफल रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से यूरोपीय समाज बंद, अंतर्विवाही सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुसार स्तरीकृत थे, जिनमें कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, बुर्जुआ वर्ग और किसान वर्ग जैसे समूह शामिल थे। ब्रिटिश शाही परिवार में भी एक जाति व्यवस्था मौजूद है जिसमें जन्मजात विशेषाधिकार और एक निश्चित प्रकार की सुनिश्चित व्यावसायिक पदानुक्रम शामिल है; साथ ही, अन्य यूरोपीय शाही परिवारों के सदस्यों से ही विवाह करने का दबाव भी रहता है, हालांकि व्यवहार में अक्सर इसका उल्लंघन किया जाता है।
विल्करसन द्वारा इतिहास के एक विशेष रूप से काले अध्याय को नजरअंदाज किया गया है, जो भारत में चर्च के निर्माण का वह इतिहास है जो पंद्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध और सोलहवीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पुर्तगालियों के आगमन से शुरू हुई विजयों पर आधारित है। चर्च को यह समर्थन ब्रिटिश काल में भी जारी रहा जब ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार ने चर्च को बड़ी मात्रा में प्रमुख भूमि अनुदान के रूप में दी। यही कारण है कि भारत भर के शहरों में असंख्य कब्रिस्तान, युवा ईसाई संघ, चर्च और ईसाई मिशनरी स्कूल सबसे प्रतिष्ठित स्थानों पर स्थित हैं। यद्यपि भारत की जनसंख्या में ईसाइयों की संख्या तीन प्रतिशत से भी कम है, फिर भी चर्च और अन्य ईसाई संस्थानों के पास जनसंख्या के प्रतिशत से कहीं अधिक मूल्य की अचल संपत्ति है। इसके अलावा, उनके पास उन शैक्षणिक संस्थानों का असमान स्वामित्व है जो भारी राजस्व उत्पन्न करते

हैं और हिंदू जनता पर राजनीतिक और सामाजिक दमनकारी शक्ति का आनंद लेने में सहायक होते हैं।

एक ऐसे घनी आबादी वाले देश में जहाँ शिक्षा की मांग आपूर्ति से कहीं अधिक है, कुछ ईसाई शिक्षण संस्थान कमजोर परिवारों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के बदले में उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करते हैं। प्रलोभन यह है कि धर्मांतरण करने पर शिक्षा शुल्क माफ कर दिया जाता है, जो अन्यथा औसत परिवार के लिए अत्यधिक होता है। वित्तीय, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से अत्यधिक प्रभावशाली ये विद्यालय औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों द्वारा कब्जा की गई भूमि का उपयोग करके स्थापित किए गए थे। क्रिटिकल रेस थ्योरी का मुख्य आह्वान उत्पीड़कों द्वारा निर्मित सभी संरचनाओं को ध्वस्त करना है। भारत में इस तरह के किसी भी प्रयास में चर्च को भी शामिल करना होगा।

मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं पर किए गए अत्याचारों के लिए एक समानांतर तर्क भी दिया जाता है। यह तर्क अतीत के आक्रमणकारियों से संबंधित है और इसका आज के भारतीय मुसलमानों के अच्छे या बुरे होने से कोई लेना-देना नहीं है। उनमें से अधिकांश सभ्य लोग हैं। समानांतर तर्क उत्तर भारत में भव्य मुस्लिम स्मारकों, विशाल कब्रिस्तानों, मस्जिदों, मदरसों और इस्लामी काल में निर्मित अन्य निर्माणों के लिए उपयोग की गई अत्यधिक भूमि से संबंधित है, जिन्हें कभी-कभी हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। मुस्लिम शासकों ने गैर-मुसलमानों पर जज़्या कर भी लगाया, जिसके कारण कई हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करना पड़ा क्योंकि वे इसे चुकाने में असमर्थ थे।

विल्करसन की किताब में प्रतीकवाद पर एक पूरा अध्याय है, जिसमें वह वर्जीनिया के चार्लोट्सविले में 2017 में हुए दंगों को जायज़ ठहराती हैं, जिनमें अतीत के श्वेत गुलाम मालिकों की मूर्तियों को गिराया गया था। वह

बताती हैं कि यह कृत्य उन अश्वेतों द्वारा पूरी तरह से जायज़ था जो अपने अतीत के उत्पीड़न के प्रतीकों से छुटकारा पाना चाहते थे। यह उनके लिए भारत के साथ तुलना करने का एक अच्छा अवसर था, जैसा कि उन्होंने अपनी पूरी किताब में अन्य बिंदुओं पर किया है। लेकिन वह इस मुद्दे पर पूरी तरह से चुप हैं। उन्हें इस तथ्य का उल्लेख करना चाहिए था कि भारत में, सदियों के उत्पीड़न का प्रतीक मुस्लिम स्मारक मुस्लिम शासकों द्वारा स्वयं को सम्मानित करने के लिए बनवाए गए थे।

उनकी खामोशी का कारण दोहरा मापदंड छुपाना है। जब हिंदू अपने पवित्र स्थलों और पुरानी इस्लामी औपनिवेशिक संरचनाओं को वापस लेने की मांग करते हैं, तो उन पर सिर्फ इसलिए अपराध का आरोप लगाया जाता है क्योंकि वे अपना हक चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर, जब अश्वेत लोग स्मारकों पर कब्जा कर लेते हैं और श्वेतों द्वारा निर्मित उन संरचनाओं को ध्वस्त कर देते हैं जो उनके उत्पीड़न का प्रतीक हैं, तो इसे अपराध नहीं, बल्कि एक उचित प्रतिक्रिया माना जाता है।

इस असमान दृष्टिकोण का कारण यह है कि भारत में, वर्तमान अल्पसंख्यक (मुस्लिम और ईसाई) अपने उन पूर्वजों द्वारा प्राप्त संरचनात्मक विशेषाधिकारों को विरासत में प्राप्त कर चुके हैं जिन्होंने हिंदू बहुसंख्यक समुदाय पर शासन किया था। फिर भी, कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि वे विशेषाधिकार प्राप्त समुदाय हैं।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक जाति व्यवस्था मौजूद है, जिसके कई सदस्य विल्करसन के सहकर्मी विशेषाधिकार प्राप्त सदस्य हैं। वास्तव में, जाति जैसी व्यवस्थाएं विश्व भर की सभी संस्कृतियों में मौजूद रही हैं और आज भी जारी हैं। स्पेनिश जाति व्यवस्था, अफ्रीकी देशों में विभिन्न प्रकार की जाति व्यवस्थाएं, अमेरिकी जाति व्यवस्था, पाकिस्तान की जाति व्यवस्था और यहां तक कि चीन और

जापान की जाति व्यवस्थाओं के बारे में भी काफी जानकारी उपलब्ध है। इनमें से कोई भी बात भारत या अन्य जगहों पर जाति-आधारित पूर्वाग्रहों को उचित नहीं ठहराती है, लेकिन किसी बीमारी का सही निदान एक व्यवहार्य उपचार योजना विकसित करने की दिशा में आवश्यक पहला कदम है।

हिंदू धर्म का विघटन आवश्यक समझा जाता है

इस तरह के लेखों में अक्सर देखा जाता है कि विल्करसन कर्म (कार्य, कर्म, पुण्य) प्रणाली को जातिगत दुर्व्यवहारों को कायम रखने का मुख्य कारण मानती हैं। उनका कहना है कि कर्म सिद्धांत निम्न जाति के लोगों को दंडित करने को उचित ठहराता है।

भारतीय जाति व्यवस्था को स्थिर और इसमें रहने वालों द्वारा निर्विवाद माना जाता है, क्योंकि यह धर्म और हिंदू पुनर्जन्म की मान्यता से बंधी है। हिंदू मान्यता के अनुसार, व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगता है और जन्म के बाद अपनी जाति के नियमों का जितना अधिक पालन करता है, अगले जन्म में उसका स्थान उतना ही ऊंचा होता है। कुछ पर्यवेक्षकों का कहना है कि यही बात भारतीय जाति व्यवस्था को अन्य सभी से अलग करती है: कि सबसे निचली जाति के लोग अपने भाग्य को स्वीकार करते हैं, कि यह अटल और अपरिवर्तनीय है; दलित अपने देवताओं द्वारा निर्धारित कर्मों का फल भोगते हैं और बिना किसी शिकायत के अपना निम्न कार्य करते हैं, क्योंकि वे इससे अधिक की आकांक्षा नहीं रखते। जीवित रहने के लिए, अधीनस्थ जाति के कुछ लोग यह सीख लेते हैं और मान लेते हैं कि प्रतिरोध व्यर्थ है।

उनका मानना है कि यह कुछ वैसा ही है जैसा गुलाम अफ्रीकियों की दुर्दशा को तर्कसंगत ठहराया गया था, और दोनों ही मामलों में इस

मूलभूत सत्य की अनदेखी की गई है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र होना चाहते हैं। कर्म सिद्धांत को जातिगत दुर्व्यवहार के कारण से जोड़कर, वे हिंदू धर्म को ध्वस्त करने के तर्कों का आधार तैयार करती हैं।

विल्करसन जाति संबंधी कुछ स्थापित सिद्धांतों का उल्लेख करते हैं, जिनमें प्रमुख पश्चिमी विद्वानों के सिद्धांत भी शामिल हैं, कि जाति एक प्रकार का वर्ग है जिसमें संपूर्ण व्यवस्था को ध्वस्त किए बिना पूर्वाग्रहों को दूर किया जा सकता है। ऐसा दृष्टिकोण निम्न वर्गों के लिए बेहतर आर्थिक और सामाजिक अवसर सृजित करके जातिगत पूर्वाग्रहों को दूर करने की संभावनाओं के लिए खुला है। कई मानवीय परियोजनाएं हैं जिनमें सभी जातियों के लोग कम भाग्यशाली लोगों की मदद के लिए एकजुट होते हैं, और यह प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है।

लेकिन इन विचारों को संक्षेप में स्वीकार करने के बाद, वह दृढ़ता से दावा करती है कि जाति मूल रूप से वर्ग से भिन्न है:

जाति की स्थिर प्रकृति ही इसे वर्ग से अलग करती है, जिससे इसकी अक्सर तुलना की जाती है। वर्ग समाज में किसी व्यक्ति की स्थिति का एक बिल्कुल अलग मापक है, जो शिक्षा के स्तर, आय और व्यवसाय के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक स्थिति से उत्पन्न होने वाली विशेषताओं, जैसे उच्चारण, रुचि और शिष्टाचार, द्वारा निर्धारित होता है। इन्हें कड़ी मेहनत और सूझबूझ से प्राप्त किया जा सकता है या गलत निर्णयों या विपत्ति के कारण खोया जा सकता है। यदि आप अपने कर्मों से इससे बाहर निकल सकते हैं, तो यह वर्ग है, जाति नहीं।

उसके मन में इस बात को पुख्ता करने वाली बात यह है कि वह दृढ़ता से मानती है कि जाति व्यवस्था स्थायी है और किसी भी नीति या सामाजिक उपाय से इसे सुधारा नहीं जा सकता। इस निष्कर्ष का तात्पर्य यह है कि निचली जातियों के उद्धार के लिए हिंदू धर्म को समाप्त करना आवश्यक

है।

विल्करसन सरलीकरण के जाल में फंस जाती हैं। वह 'जाति → नस्लवाद' को सामाजिक दुर्व्यवहारों के एक ही, सर्वव्यापी और सार्वभौमिक कारण के रूप में चित्रित करना चाहती हैं। एक अधिक सुसंगत विश्लेषण में सामाजिक पूर्वाग्रहों के कई कारणों पर विचार किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, क्या पुरुषत्व भी सामाजिक पूर्वाग्रह का एक कारण हो सकता है? यदि ऐसा है, तो इसका भारत-विशिष्ट जातिगत मुद्दों से कोई संबंध नहीं होगा।

विल्करसन एक हिंदू पुरुष द्वारा अपने जनेऊ (ब्राह्मणों द्वारा पहना जाने वाला पवित्र धागा) को त्यागने के कार्य को जाति-विरोधी संकेत के रूप में सराहती हैं। वह इसे जाति का सशक्त त्याग कहती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार क्रिटिकल रेस थ्योरी सभी से अपने नस्लवाद-विरोधी होने का प्रमाण देने की मांग करती है, उसी प्रकार हिंदुओं पर भी अपने प्रतीकों, परंपराओं, रीति-रिवाजों, ग्रंथों, त्योहारों और अनुष्ठानों को त्यागने का दबाव डाला जाना चाहिए ताकि वे जागरूक (वोके) बन सकें। लेकिन उन्होंने अपने अश्वेत समुदाय से यह नहीं कहा है कि वे नस्लवाद-विरोधी होने का प्रदर्शन करने के लिए चर्च छोड़ दें और ईसाई धर्म का त्याग कर दें।

उनकी पुस्तक के जवाब में, हम निम्नलिखित नैतिक प्रश्न उठाते हैं: क्या ऐसे आलोचक जाति व्यवस्था को दोष देने में हद से आगे बढ़ रहे हैं और परिणामस्वरूप, सभी दुर्व्यवहारों को हिंदू धर्म से अविभाज्य मानकर हिंदू धर्म को ही समाप्त करना आवश्यक समझते हैं? क्या कोई इसी तरह का रुख अपनाएगा कि कैथोलिक चर्च में यौन शोषण के कारण कैथोलिक धर्म को ही समाप्त कर देना चाहिए? या इस्लाम में दुर्व्यवहार के कारण इस्लाम को ही समाप्त कर देना चाहिए? या अफ्रीका में अफ्रीकी लोगों के

बीच नस्लवाद और जातिवाद के दुर्व्यवहार के कारण, क्या सभी अश्वेत संस्कृति को ही समाप्त करने की मांग करनी चाहिए?
एक ओर, विल्करसन किसी भी समूह को अमानवीय बनाने को लेकर बेहद चिंतित हैं, क्योंकि इससे उस समूह के सदस्यों को सिर्फ इसलिए नुकसान पहुंचाना आसान हो जाता है क्योंकि वे उस समूह से संबंधित हैं। लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि उनका काम उन्हीं ताकतों को बढ़ावा दे रहा है जो हिंदुओं को अमानवीय बना रही हैं। यह तेजी से हो रहा है और हिंदुओं को एक असहाय समुदाय में बदल रहा है, जिन्हें सिर्फ इसलिए निष्पक्ष व्यवहार का हकदार नहीं समझा जाता क्योंकि उन पर हिंसक और उत्पीड़क होने का आरोप लगाया जाता है। वह समूहवादी सोच के गुलाम बनने का विरोध करती हैं, फिर भी हिंदू धर्म के खिलाफ समूहवादी सोच ही उनके काम का मुख्य कारण है। वह नियंत्रण स्थापित करने के लिए उत्पीड़न के इस्तेमाल के खिलाफ भी हैं, लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं देतीं कि कैंपस में हिंदुओं का अकादमिक उत्पीड़न वास्तव में उसी उत्पीड़न का एक रूप है।
अंततः, हिंदू धर्म को भंग करने की मांग करने वाला पूरा आंदोलन योग, ध्यान, शाकाहार, पर्यावरण संरक्षण आदि के माध्यम से अमेरिकी चेतना को ऊपर उठाने में हिंदुओं के योगदान को नजरअंदाज करता है। यह तर्क दिया जा सकता है कि इन समस्याओं का समाधान केवल उच्च स्तर की चेतना से ही संभव है, न कि आज प्रचलित निम्न स्तर की चेतना से। समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान उन्हें पार करके और एक उच्च दृष्टिकोण से देखना है। हिंदू मत 'तत्त्वम् असि', यानी कि सभी मूल रूप से दिव्य हैं और कोई भी शाश्वत पापी नहीं है, और 'वसुधैव कुटुंबकम', यानी कि सभी जीव एक ही परिवार हैं, मानव जाति की सहायता के लिए अंतर्निहित संसाधनों के उदाहरण हैं। विल्करसन भक्ति आंदोलन को

नजरअंदाज करते हैं, जो एक ऐसा भक्तिमय आंदोलन था जिसने पूरे भारत में जातिगत सीमाओं को मिटा दिया। यह एक आंतरिक विकास था जिसने सामाजिक बाधाओं को पार किया।
अध्याय 6 में भारतीय सामाजिक संरचनाओं और इतिहास के बारे में उनकी गलतफहमियों का अधिक विस्तृत जवाब दिया गया है।

3. भारतीय अमेरिकियों की तुलना श्वेत नस्लवादियों से की गई

अवलोकन
इस अध्याय में विस्तार से बताया गया है कि भारतीय अमेरिकी समुदाय के प्रति गहरी ईर्ष्या से प्रेरित पक्षपातपूर्ण शोध किस प्रकार अमेरिकी कार्यस्थलों में अराजकता पैदा कर रहा है, जहाँ बड़ी संख्या में कर्मचारी भारतीय मूल के हैं। इसमें निम्नलिखित बातों का स्पष्टीकरण दिया गया है:
अमेरिकी सक्रियता का एक नया अमेरिकी तंत्र उभरा है जो अमेरिका में जाति पर डेटा एकत्र कर रहा है - जिसमें उद्योग, विश्वविद्यालय और सरकार शामिल हैं - और कानूनों और नीतियों को बदलने के लिए पैरवी कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप जाति को अमेरिका के कानूनों के तहत औपचारिक रूप से नस्लवाद के एक रूप के रूप में मान्यता मिल जाएगी। थेनमोझी सौंदराजन द्वारा संचालित संस्था इक्वालिटी लैब्स, भारतीयों के खिलाफ चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियान का केंद्र है। वह अपनी दलित पहचान का इस्तेमाल करती है और श्वेत अमेरिकियों को अपराधबोध दिलाने के लिए खुद को पीड़ित के रूप में पेश करती है। उनकी संस्था गैर-

लाभकारी संस्था के रूप में पंजीकृत नहीं है क्योंकि ऐसा करने पर उसे अपने धन के स्रोतों और उपयोगों का खुलासा सार्वजनिक रूप से करना होगा।

इसका प्रमुख उत्पाद अमेरिकी कार्यस्थल में जाति व्यवस्था पर एक रिपोर्ट है। इसमें इस्तेमाल की गई कार्यप्रणाली में कई गंभीर खामियां थीं। इसी विषय पर प्रतिष्ठित शोध संगठनों द्वारा प्रकाशित कम से कम दो अन्य रिपोर्टों ने इसके निष्कर्षों से असहमति जताई है।

इक्वालिटी लैब्स ने नस्लभेद के आरोपों को दर्ज कराने के लिए अमेरिकी नस्लवाद विरोधी कानूनों का इस्तेमाल करते हुए महत्वपूर्ण कानूनी और नीतिगत जीत हासिल की है। इसके कार्यों के भारतीय अमेरिकियों और दुनिया भर के हिंदुओं के साथ-साथ अमेरिका, भारत और विश्व भर की संस्थागत संरचनाओं पर भी विनाशकारी परिणाम होंगे।

पश्चिमी विश्वविद्यालयों और वामपंथी संगठनों में दलित नेतृत्व का सुनियोजित पोषण चल रहा है, जिसे बाद में भारत में निर्यात किया जाता है। जैसा कि हम भाग 2 में देखेंगे, हार्वर्ड विश्वविद्यालय इसका मुख्य केंद्र है। यह अमेरिकी केंद्रित तंत्र भारतीय संस्थानों में गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुका है।

इक्वालिटी लैब्स ने अमेरिका स्थित उन संगठनों का गठबंधन बनाया है जो भारत-विरोधी रुख अपनाते हैं। इसने सनसनीखेज खबरों और सुनियोजित अभियान का इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी संगठनों के बीच जाति व्यवस्था पर एक विश्वसनीय संस्था के रूप में अपनी पहचान बनाई है। यह नियोक्ताओं से भारतीय कर्मचारियों की जाति जनगणना कराने की मांग करता है, ताकि कर्मचारियों में जातिवाद को खत्म किया जा सके। इस तरह की जनगणना और प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं इक्वालिटी लैब्स की आय का एक प्रमुख स्रोत बन गई हैं।

ऐसा लगता है कि इक्वालिटी लैब्स यह मानकर चलती है कि जब तक निर्दोष साबित न हो जाए, हर भारतीय और हिंदू जातिवाद का दोषी है। अमेरिका में किसी अन्य राष्ट्रीय मूल या धर्म को इस तरह से निशाना बनाकर व्यवहार नहीं किया गया है।
जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हम जाति आधारित भेदभाव सहित किसी भी प्रकार के भेदभाव को लेकर बेहद चिंतित हैं। जब भी कोई वैध मामला हो, उसका निपटारा कानूनी माध्यमों से किया जाना चाहिए। लेकिन हम अतिशयोक्ति, मिथ्याकरण, दोषारोपण के सरलीकृत सिद्धांतों, अत्यधिक पीड़ित होने की भावना, विभाजनकारी दृष्टिकोण आदि का विरोध करते हैं।

भारतीय अमेरिकियों के जातिगत दुर्व्यवहारों से संबंधित अमेरिकी डेटाबेस का संकलन
अमेरिका स्थित इक्वालिटी लैब्स समूह स्वयं को दलित 'शक्ति निर्माण' संगठन के रूप में वर्णित करता है। दक्षिण एशियाई प्रवासी समुदाय के बीच अमेरिका में व्यापक जातिगत भेदभाव का आरोप लगाने वाली एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद यह अचानक प्रसिद्ध हो गया। प्रगतिशील पश्चिमी दर्शकों को प्रभावित करने वाले प्रभावी संदेशों के माध्यम से, संगठन ने कई सरकारी, शैक्षणिक और कॉर्पोरेट संस्थानों को भारतीय अमेरिकियों, विशेष रूप से हिंदुओं के संबंध में अपने विचारों और नीतिगत सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए सफलतापूर्वक राजी कर लिया है। 2016 में, इसे अपना पहला अनुदान प्राप्त हुआ और इसने अमेरिका में जाति पर अपने प्रमुख सर्वेक्षण के लिए प्रतिक्रियाएँ एकत्र करना शुरू किया।
इक्वालिटी लैब्स की संस्थापक और प्रमुख प्रेरक शक्ति, थेनमोझी

साउंडराजन का जन्म कैलिफोर्निया में हुआ था। उनके पिता एक हृदयरोग विशेषज्ञ थे और भारत के तमिलनाडु से आकर यहाँ बसे थे। उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले और दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स से शिक्षा प्राप्त की। वे एमआईटी ओपन डॉक्यूमेंट्री लैब से भी जुड़ी रही हैं, जो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 'कहानीकारों, प्रौद्योगिकीविदों और विद्वानों को एक साथ लाकर वृत्तचित्र के नए रूपों का अन्वेषण करता है'। ब्लैक हिस्ट्री मंथ की तर्ज पर उन्होंने दलित हिस्ट्री मंथ की शुरुआत की है।

सौंदराजन के तरीकों में मीडिया सक्रियता, मुकदमेबाजी और विविधता एवं समावेशन से संबंधित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शामिल हैं। इक्वालिटी लैब्स की वेबसाइट बताती है कि उसका मिशन है...

जातिगत भेदभाव, इस्लामोफोबिया, श्वेत वर्चस्व और धार्मिक असहिष्णुता के उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए सामुदायिक अनुसंधान, राजनीतिक आधार निर्माण, संस्कृति-परिवर्तनकारी कला और डिजिटल सुरक्षा का उपयोग किया जाता है। इन विधियों के माध्यम से, हम समुदायों को उत्पीड़न की दीर्घकालिक प्रणालियों में नए हस्तक्षेप करने और अपने अधिकारों की वकालत करने के लिए व्यावहारिक उपकरण प्रदान करते हैं।

इक्वालिटी लैब्स को राजनीतिक क्षेत्र में काफी प्रभाव दिलाने वाली इसकी प्रमुख उपलब्धि 2018 की रिपोर्ट, 'कास्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स' थी। बावन पृष्ठों की इस रिपोर्ट ने अमेरिका, भारत और यहां तक कि चीन में भी मीडिया में तुरंत व्यापक कवरेज हासिल की। इसके कुछ प्रमुख दावों में अमेरिका में रहने वाले दलितों से संबंधित निम्नलिखित चौंकाने वाले आंकड़े शामिल थे:

67 प्रतिशत लोगों ने अपने कार्यस्थलों पर अनुचित व्यवहार की शिकायत

की।
बीस प्रतिशत लोगों को अपने कार्यस्थल पर जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा।
चालीस प्रतिशत लोगों को जाति के आधार पर प्रेम संबंधों में अस्वीकृति का सामना करना पड़ा।
पच्चीस प्रतिशत लोगों को जाति से संबंधित मौखिक या शारीरिक हमले का सामना करना पड़ा।
पाठकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि ये सर्वेक्षण और रिपोर्ट अमेरिका में रहने वाले दलितों से संबंधित हैं, न कि भारत से। कार्यप्रणाली में खामियों और अंतर्निहित पूर्वाग्रहों को लेकर कई मुद्दे उठाए गए हैं, जो निष्कर्षों की विश्वसनीयता को कम करते हैं। उदाहरण के लिए:
अमेरिकी जनगणना में दलितों को कभी भी एक श्रेणी के रूप में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए अमेरिका में दलितों की संख्या का अनुमान लगाना असंभव है।
गैर-भारतीयों द्वारा नस्लवाद के कारण कार्यस्थल पर किए जाने वाले अनुचित व्यवहार और विशिष्ट जाति-आधारित भेदभाव के बीच कोई अंतर नहीं किया गया।
यह सर्वेक्षण इक्वालिटी लैब्स के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके द्वारा चुने गए लोगों को वितरित किया गया था और यह व्यापक भारतीय अमेरिकी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। शायद इसी कारण लगभग तीस प्रतिशत उत्तरदाताओं ने खुद को गैर-विषमलिंगी (जिन्हें आगे उभयलिंगी, समलैंगिक, सर्वलिंगी और क्वीर में वर्गीकृत किया गया है) बताया। ये आंकड़े सांख्यिकीय रूप से पक्षपाती प्रतीत होते हैं।
इक्वालिटी लैब्स ने अपने स्वयं के व्यक्तिपरक मानदंडों का उपयोग करते हुए, जिन्हें कभी भी पारदर्शी रूप से प्रकट नहीं किया गया है, बीस

प्रतिशत प्रतिक्रियाओं को 'अतिवादी या अतार्किक' होने के कारण पूरी तरह से खारिज कर दिया।
इसमें यह भी स्वीकार किया गया कि कोई वैज्ञानिक रूप से मान्य सांख्यिकीय नमूनाकरण नहीं था। उदाहरण के लिए, रिपोर्ट की गई जाति संबद्धता का कोई बाहरी सत्यापन नहीं था (और स्वयं को किसी एक 'जाति' के रूप में पहचानने के लिए कोई सुसंगत रूप से लागू कार्यप्रणाली नहीं थी)।[6]
इस रिपोर्ट के परिणामों की तुलना भारत के बाहर प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा किए गए जाति-संबंधी दो अन्य सर्वेक्षणों से की जानी चाहिए। इनमें से एक सर्वेक्षण भारतीय अमेरिकी समुदाय में जाति पर 2021 में कार्नेगी एंडोमेंट द्वारा जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय और पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय (यूपेन) के सहयोग से किया गया था। रिपोर्ट में इक्वालिटी लैब्स के निष्कर्षों में किए गए दावों के संबंध में निम्नलिखित बातें कही गई हैं:
इक्वालिटी लैब्स द्वारा किए गए इस अध्ययन में उत्तरदाताओं की भर्ती के लिए गैर-प्रतिनिधि स्नोबॉल सैंपलिंग पद्धति का उपयोग किया गया। … जिन उत्तरदाताओं ने अपनी जातिगत पहचान का खुलासा नहीं किया, उन्हें डेटा सेट से हटा दिया गया। … यह नमूना दक्षिण एशियाई अमेरिकी आबादी का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करता है और जाति के बारे में दृढ़ विचार रखने वालों के पक्ष में झुकाव पैदा कर सकता है। भारत में जातिगत भेदभाव का अस्तित्व निर्विवाद है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी सटीक सीमा और तीव्रता पर विवाद हो सकता है।
कार्नेगी एंडोमेंट की रिपोर्ट में पाया गया कि अमेरिका में रहने वाले लगभग 42 लाख भारतीय मूल के लोगों में से अधिकांश किसी भी जाति समूह से व्यक्तिगत रूप से संबंधित नहीं हैं, और केवल 1% हिंदुओं ने दलित या

अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित होने की बात कही। पांच प्रतिशत से भी कम दलितों ने जाति आधारित भेदभाव का सामना करने की बात कही। जाति आधारित भेदभाव का दावा करने वालों में से एक बड़ी संख्या ने कहा कि उन्हें गैर-भारतीयों के हाथों ऐसे भेदभाव का सामना करना पड़ा। यह सब इक्वालिटी लैब्स के निष्कर्षों का खंडन करता है और उन्हें कमजोर करता है।

ब्रिटेन में जातिगत भेदभाव पर किया गया दूसरा, कहीं अधिक विस्तृत सर्वेक्षण, राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया था। उनकी 121 पृष्ठों की रिपोर्ट में कहा गया है कि 'ब्रिटेन में जाति व्यवस्था मौजूद है: इस पर कोई विवाद नहीं है', लेकिन साथ ही यह भी स्वीकार किया गया है कि ब्रिटेन में जातिगत भेदभाव की सीमा का पता लगाने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण की आवश्यकता होगी जिसमें जटिलताएं, संसाधन और समय-सीमा शामिल होगी जो उनके अध्ययन के दायरे से बाहर है। यह विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि ब्रिटिश आबादी को जाति के आधार पर विभाजित नहीं किया गया है और इसलिए यह विश्वसनीय डेटा उपलब्ध नहीं है कि कौन किस जाति से संबंधित है।

स्पष्ट खामियों, पूर्वाग्रहों और निष्कर्षों की व्यापक प्रकृति के बावजूद, इक्वालिटी लैब्स की रिपोर्ट को न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, बीबीसी, एनपीआर, ब्लूमबर्ग और अन्य प्रमुख प्रकाशनों में व्यापक कवरेज मिली। इन मीडिया संस्थानों ने रिपोर्ट के निष्कर्षों को अचूक सत्य मानकर उनका समर्थन करने से पहले उचित जांच-पड़ताल करने की जहमत नहीं उठाई। हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल के अश्वेत समुदाय से ताल्लुक रखने वाले पूर्व प्रोफेसर कॉर्नेल वेस्ट जैसे कई बुद्धिजीवियों ने भी इस रिपोर्ट का समर्थन किया, जबकि एक विद्वान के रूप में अपने साथियों के कार्यों की समीक्षा

करते समय विषय पर किसी भी प्रतिवाद पर विचार करना आवश्यक होता है। मीडिया ने अपने साक्षात्कारों और चर्चाओं में हिंदू धर्म के विशेषज्ञों को आमंत्रित करने की जहमत भी नहीं उठाई।

अमेरिकी कांग्रेस की भारतीय अमेरिकी डेमोक्रेट सदस्य प्रमिला जयपाल ने इक्वालिटी लैब्स को काफी बढ़ावा दिया। 2019 में, उन्होंने इक्वालिटी लैब्स, साउथ एशियन अमेरिकन्स लीडिंग टुगेदर और एपीआई छाया के साथ मिलकर जाति पर एक कांग्रेसी ब्रीफिंग का आयोजन किया। जयपाल ने अमेरिकी कांग्रेस के एक अन्य डेमोक्रेट सदस्य रो (रोहित) खन्ना के साथ मिलकर 2021 में इक्वालिटी लैब्स के साथ साझेदारी की और बी.आर. अंबेडकर की स्मृति में एक प्रस्ताव पेश किया। हम चाहते हैं कि दुनिया अंबेडकर का सम्मान करे, लेकिन इसे एजेंडा-चालित औसत दर्जे की रिपोर्टों से भ्रमित नहीं होना चाहिए।

इक्वालिटी लैब्स एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में पंजीकृत नहीं है, जिसके तहत वित्तीय जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य हो या अमेरिका में राजनीतिक प्रचारकों पर लागू होने वाले कड़े प्रतिबंधों का पालन करना पड़े। ऐसा लगता है कि यह जनता से अपनी वित्तीय जानकारी छिपाने की एक चालाकी भरी चाल है।

लेकिन अप्रत्यक्ष सूत्रों से पुष्टि होती है कि ओमिडयार नेटवर्क से जुड़े वामपंथी गैर-लाभकारी संगठनों से इसे भरपूर वित्तीय सहायता मिलती है। यह दक्षिण एशियाई कार्यकर्ता संगठनों के एक व्यापक गठबंधन के हिस्से के रूप में काम करता है जो इसके संदेशों को फैलाने में मदद करते हैं। नीचे दिया गया आरेख इक्वालिटी लैब्स के प्रचार को फैलाने में मदद करने वाले कुछ संगठनों को दर्शाता है।

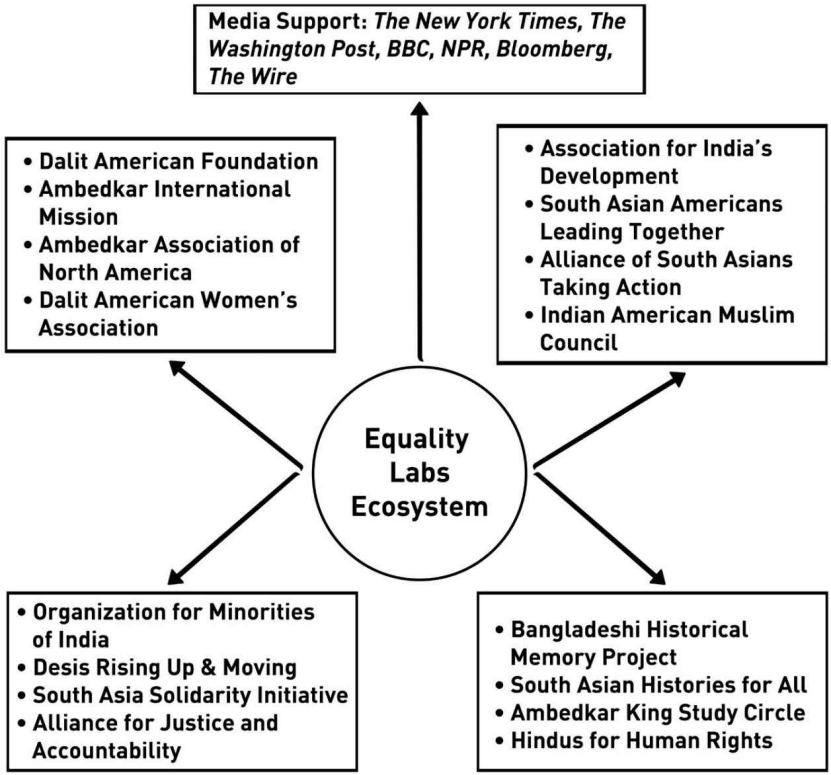

इनमें से कुछ संगठन रटगर्स विश्वविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर ऑड्रे ट्रुश्के और उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों, जैसे कि 2021 में आयोजित 'वैश्विक हिंदुत्व विघटन सम्मेलन' से भी जुड़े थे। 'दोषमुक्ति, राज्य हिंसा, अश्वेत-विरोधी भावना, जातिगत भेदभाव और धार्मिक असहिष्णुता के खिलाफ लड़ाई' के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए, सौंदराजन को प्रतिष्ठित रोड्स ट्रस्ट द्वारा 'अटलांटिक फेलोशिप' से सम्मानित किया गया था।

इक्वालिटी लैब्स को आलोक वैद्य-मेनन जैसे दूसरी पीढ़ी के भारतीय अमेरिकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ब्राउन गर्ल मैगज़ीन जैसे प्रकाशनों से विशेष समर्थन प्राप्त करने में सफलता मिली है। इसकी

सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण इसके संदेशों की परिष्कृत गुणवत्ता है, जो विशेष रूप से गैर-भारतीयों जैसे विशिष्ट दर्शकों के लिए तैयार किए गए हैं। जाति, हिंदू धर्म और भारतीय अमेरिकी समुदाय पर इसके विचार संकुचित, घृणास्पद, त्रुटिपूर्ण और हास्यास्पद भी हैं। फिर भी, इन्हें इस तरह से चतुराई से प्रस्तुत किया गया है कि प्रगतिशील अमेरिकी इन्हें समझ सकें और इनसे जुड़ाव महसूस कर सकें। इसके लिए पश्चिमी संदर्भ में नस्ल से जुड़े परिचित विचारों और कथाओं को हिंदू धर्म और भारत पर लागू किया गया है।

उदाहरण के लिए, 2018 में भारत यात्रा के दौरान, ट्विटर के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जैक डोर्सी ने महिला पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और लेखकों के एक समूह के साथ 'ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को ध्वस्त करो' वाक्यांश वाला इक्वालिटी लैब्स का पोस्टर पकड़े हुए तस्वीर खिंचवाई। इक्वालिटी लैब्स के प्रायोजक इसे राजनीतिक रूप से सही शब्दों में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी मुख्यधारा का सामाजिक न्याय संगठन बताते हैं।

एक और सफलता का कारक इक्वालिटी लैब्स का आक्रामक नेतृत्व है, जो अश्वेत आंदोलन के साथ अपने तालमेल का उपयोग करते हुए आगे बढ़ रहा है। 2017 में, साउथ एशियन हिस्ट्रीज़ फॉर ऑल की सह-संस्थापक के रूप में, सौंदराजन ने अश्वेत और दलित कार्यकर्ताओं को संगठित किया ताकि वे इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में भारत और हिंदू धर्म के चित्रण के संबंध में कैलिफोर्निया राज्य शिक्षा बोर्ड की सुनवाई में गवाही दे सकें। बताया जाता है कि वह सुबह साढ़े छह बजे से कतार में इंतजार कर रहे सैकड़ों माता-पिता और बच्चों को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थीं। कैलिफोर्निया शिक्षा विभाग के सुरक्षा कर्मियों को अंततः उन्हें और उनके साथी कार्यकर्ताओं को उपद्रवी और

आक्रामक व्यवहार के लिए बाहर निकालना पड़ा। सौंदराजन ने इन घटनाओं को अलग तरह से वर्णित किया है, उनका दावा है कि कैलिफोर्निया सरकार के अधिकारियों ने उन्हें 'दलित अमेरिकी होने' के कारण चार बार बाहर निकाला।

संयुक्त राज्य अमेरिका में जाति से संबंधित मुकदमे
अमेरिका में तीन प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें इक्वालिटी लैब्स और इसके सहयोगी संगठनों के अनुसंधान और पैरवी गतिविधियों ने हलचल मचाना शुरू कर दिया है: कॉरपोरेट जगत, विश्वविद्यालय और कॉलेज परिसर, और स्थानीय सरकारें। इन्हें सामने दिए गए आरेख में दर्शाए गए प्रमुख उदाहरणों के साथ स्पष्ट किया जाएगा।

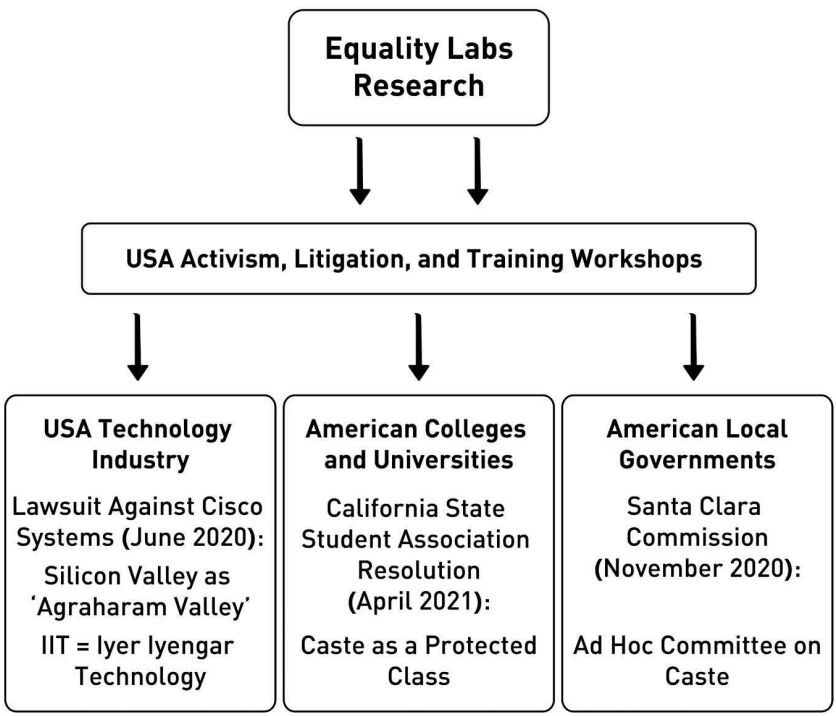

अमेरिकी प्रौद्योगिकी उद्योग

इक्वालिटी लैब्स की 2018 की रिपोर्ट ने भारतीय और हिंदू अमेरिकियों, विशेष रूप से कैलिफोर्निया में, को निशाना बनाने वाले मुकदमों की नींव रखी। जून 2020 में, कैलिफोर्निया के निष्पक्ष रोजगार और आवास विभाग ने एक गुमनाम 'भारतीय दलित' की ओर से कथित जातिगत भेदभाव के लिए सिस्को सिस्टम्स के खिलाफ मुकदमा दायर किया। एजेंसी ने दावा किया कि सिस्को में 'दक्षिण एशियाई भारतीय' कर्मचारियों की संख्या अधिक थी और उसने 'सबसे गहरे रंग की जाति' के दलित कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने में लापरवाही बरती, ताकि उन्हें 'कठोर हिंदू धार्मिक और सामाजिक पदानुक्रम' लागू करने वाले सहकर्मियों द्वारा भेदभाव और उत्पीड़न का सामना न करना पड़े। शिकायत में कहा गया कि सिस्को अपने कार्यस्थल में 'जातिगत स्थिति, धार्मिक शुद्धता और सामाजिक बहिष्कार से जुड़ी असमानताओं' को रोकने में विफल रहा। इसके समर्थन में सबूत इक्वालिटी लैब्स द्वारा प्रदान किए गए थे। इसने सिस्को पर यह भी आरोप लगाया कि उसके जातिगत दुर्व्यवहार करने वाले आईआईटी से आए थे, जो सौंदराजन के अनुसार, 'जातिवादी सोच, प्रक्रियाओं और नीतियों के लिए कुख्यात' है।[20] इसने शिकायत की कि: उच्च जाति के छात्र और शिक्षक जो उन शैक्षणिक संस्थानों (जैसे आईआईटी) में बेहद शत्रुतापूर्ण संस्कृति का निर्माण करते हैं, वे आगे चलकर सिलिकॉन वैली की तकनीकी कंपनियों में जातिवादी पूर्व छात्र नेटवर्क बनाते हैं। ये कंपनियां अक्सर "आंतरिक रेफरल" नामक प्रक्रिया के माध्यम से भर्तियां करती हैं... यह मूल रूप से जातिगत नेटवर्किंग है, ... जो अक्सर एक ही जाति के लोगों को भर्ती करती है, इसलिए कई कंपनियों के पूरे विभाग अक्सर केवल उच्च जाति के प्रबंधकों से बने होते

हैं।
इसलिए, सौंदराजन कंपनियों को 'जातिगत रूप से सक्षम' बनाना चाहती हैं। वह सिस्को मामले को वैश्विक महत्व का मानती हैं और उनका मानना है कि इसका भारत पर अमेरिका से भी अधिक प्रभाव पड़ेगा।
सिस्को ने जवाब दिया कि उसने मामले की पूरी तरह से जांच की और जाति आधारित भेदभाव का कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि सिस्को अपना बचाव कर रही है, लेकिन उसके मानव संसाधन उपाध्यक्ष ने एक सार्वजनिक पोस्ट में आलोचकों को शांत करने की कोशिश शुरू कर दी है: हालांकि भारतीय समाज में जाति शब्द का प्रयोग अक्सर भेदभाव को दर्शाने के लिए किया जाता है, लेकिन यह अवधारणा वंशानुगत विशेषताओं पर आधारित कई प्रकार के भेदभावों को समझने में उपयोगी है। इसाबेल विल्करसन, जिनकी पुस्तक 'वार्मथ ऑफ अदर सन्स' ने मुझे अमेरिका में अश्वेत-विरोधी नस्लवाद की कपटपूर्ण प्रकृति को समझने में मदद की, ने इस अवधारणा को अमेरिकी नस्लवाद पर लागू करते हुए एक शानदार नई पुस्तक लिखी है, जिसका शीर्षक है 'कास्ट: द ओरिजिन ऑफ आवर डिसकंटेंट्स'।
अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर (एआईसी) ने इस मामले में एमिकस क्यूरी का दर्जा मांगा, और अंबेडकर किंग स्टडी सर्कल और हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स भी इसमें शामिल हो गए। एआईसी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील जॉन रशिंग ने द वायर को बताया:
जाति भी नस्ल और रंगभेद का एक रूप है, और कैलिफोर्निया में इन दोनों को गैरकानूनी घोषित किया गया है। ... सभी दलित दक्षिण एशियाई हैं, और कैलिफोर्निया में नस्ल के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना गैरकानूनी है। ... यदि शिकायतकर्ता दक्षिण एशियाई न होकर किसी अन्य नस्ल का होता, तो उसे जातिगत भेदभाव का सामना नहीं करना

पड़ता।

द वॉशिंगटन पोस्ट में छपे एक लेख में अमेरिका में उच्च जाति के कर्मचारियों पर निम्न जाति के कर्मचारियों की भर्ती रोकने के लिए एकजुट होने का आरोप लगाया गया है। इक्वालिटी लैब्स के हवाले से कहा गया है कि गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम जैसी तकनीकी कंपनियों में दलितों को 'अपमानजनक टिप्पणियों, चुटकुलों, बदमाशी, भेदभावपूर्ण भर्ती प्रक्रियाओं, सहकर्मी समीक्षाओं में पक्षपात और यौन उत्पीड़न' का सामना करना पड़ा है। इन सभी कंपनियों ने अपनी भर्ती या पदोन्नति नीतियों में जातिगत भेदभाव के आरोपों से इनकार किया है।

हार्वर्ड और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के दो प्रतिष्ठित भारतीय अमेरिकी शिक्षाविदों ने इस मामले को न्यूयॉर्क टाइम्स में उठाया। उन्होंने सिस्को और बीएपीएस (अमेरिका के सबसे बड़े हिंदू संगठनों में से एक) के खिलाफ दायर मुकदमों का इस्तेमाल अमेरिकी कानून के तहत जाति को अपराध घोषित करने के लिए पैरवी करने के लिए किया। उन्होंने कहा, 'जाति को संरक्षित श्रेणी बनाना अमेरिका में जाति की समस्या के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।' इसका अर्थ है कि कानून के तहत जाति को नस्लवाद के समान कानूनी दर्जा देना।

एक अन्य लेख में आरोप लगाया गया है: ‘दलित और अन्य हाशिए पर पड़ी जातियों के छात्रों को अक्सर उनकी त्वचा के रंग, उनके पहनावे और यहां तक कि उपनामों को लेकर भी उपहास का सामना करना पड़ता है, जिन्हें अक्सर जातिगत पहचान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।’ इसमें इक्वालिटी लैब्स की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया है कि निम्न जाति के छात्रों को अमेरिकी परिसरों में ‘सूक्ष्म आक्रामकता’ का सामना करना पड़ता है। इक्वालिटी लैब्स सिलिकॉन वैली को

‘आग्रहारम घाटी’ कहती है (आग्रहारम एक प्राचीन कृषि अनुदान है जो ब्राह्मणों को अपनी परंपराओं का पालन करने के लिए राजपरिवार द्वारा दिया गया था)। उन्होंने IIT को ‘अय्यर अयंगर टेक्नोलॉजी’ का उपनाम दिया है, अय्यर और अयंगर ब्राह्मणों के आम नाम हैं।

अमेरिका भर में हर दिन दर्ज होने वाले रोजगार भेदभाव के मामलों की भारी संख्या को देखते हुए, जिन्हें इस तरह की या बिल्कुल भी तवज्जो नहीं मिलती, इस स्तर की मीडिया कवरेज बेहद असामान्य है। इक्वालिटी लैब्स तकनीकी जगत में जाति को लेकर चर्चाओं को हवा देने में उत्प्रेरक का काम कर रही है, जिससे भारतीय और हिंदू रक्षात्मक स्थिति में आ गए हैं। इस तरह की मीडिया सक्रियता का उद्देश्य अमेरिका में एच-1बी वर्क वीजा के लिए जाति-आधारित कोटा लागू करने के लिए पैरवी करना भी है, जिससे योग्यता को मानदंड के रूप में प्रतिस्थापित किया जा सके। हम इस बात से इनकार नहीं करते कि अमेरिकी कार्यस्थलों में जाति आधारित भेदभाव के कुछ मामले हो सकते हैं। इन्हें व्यापक रूप से लागू कानूनों और कॉर्पोरेट नीतियों के माध्यम से दूर किया जा सकता है, और किया जाना चाहिए। इक्वालिटी लैब्स के प्रस्ताव में समस्या यह है कि जाति एकमात्र संरक्षित श्रेणी बन जाएगी जो एक विशिष्ट धर्म (हिंदू धर्म), एक देश (भारत) और एक नस्लीय समूह (भारतीय अमेरिकी) को उत्पीड़क के रूप में अलग करती है। उदाहरण के लिए, नस्ल, लिंग, यौन अभिविन्यास आदि जैसी अन्य संरक्षित श्रेणियां इस बात से तटस्थ हैं कि अपराधी कौन हो सकता है और पीड़ित कौन (जैसे, एक महिला किसी पुरुष का यौन उत्पीड़न कर सकती है)। यहां, हिंदुओं और भारतीयों को एकमात्र उत्पीड़क श्रेणी के रूप में अलग किया जा रहा है। यह अन्य सभी श्रेणियों के विपरीत, लोगों के एक विशेष वर्ग को दानव के रूप में चित्रित करता है। उदाहरण के लिए, 'काफिर' के लिए कोई समकक्ष संरक्षित

श्रेणी नहीं है, जबकि इस्लाम को उत्पीड़क के रूप में नामित किया गया है।

इसके अलावा, ऐसे माहौल में जहां लोगों से उनकी नस्लीय, यौन, धार्मिक और अन्य संबद्धताओं का खुलासा करने की मांग करना अनुचित और गैरकानूनी है, वहां जातिगत भेदभाव की निगरानी के लिए जातिगत संबद्धताओं का खुलासा करने की मांग करना उचित नहीं होगा (खासकर तब जब अमेरिका में अधिकांश हिंदू खुद को किसी भी जाति से नहीं जोड़ते)। क्या होगा यदि एक ब्राह्मण महिला किसी निचली जाति के व्यक्ति या किसी श्वेत व्यक्ति से शादी करती है? पारंपरिक हिंदू धर्म में, जन्म जाति को जीवनसाथी की जाति में बदल दिया जाता है; क्या जातिगत भेदभाव से संबंधित कॉर्पोरेट नीतियां इसका समर्थन करेंगी?

इक्वालिटी लैब्स और उससे जुड़े कार्यकर्ताओं के मीडिया तंत्र ने सिस्को मुकदमे का इस्तेमाल सिलिकॉन वैली की अन्य तकनीकी कंपनियों पर दबाव बनाने के लिए शुरू कर दिया है। उनका संदेश यह है कि सिस्को ने उच्च जाति के भारतीय हिंदू पृष्ठभूमि से बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त किया है, जो एक प्रतिगामी और कठोर हिंदू सामाजिक पदानुक्रम का पालन करते हैं। सिस्को को इस बात की जानकारी होनी चाहिए थी कि ऐसे कर्मचारियों में जातिगत भेदभाव मौजूद होगा, और उसे जाति-विरोधी प्रशिक्षण देना चाहिए था और अपनी कॉर्पोरेट मानव संसाधन नीतियों में जाति को शामिल करना चाहिए था।

इक्वालिटी लैब्स ने कई अमेरिकी तकनीकी कंपनियों में जाति-आधारित भेदभाव के मामलों की जानकारी जुटाने का आह्वान किया है, जो भारतीयों को शर्मिंदा करने के लिए एक डराने वाला माहौल बना रहा है। इससे मानव संसाधन विभाग भी भ्रमित हैं क्योंकि उन्हें दो ऐसे भारतीय समूह दिखाई देते हैं जो दिखने में एक जैसे हैं और जिनके नाम भी मिलते-

जुलते हैं। विविधता और समावेशन विभाग के कर्मचारियों को भी इसमें शामिल होना पड़ रहा है; वे इन अत्यधिक पूर्वाग्रही और नकारात्मक रूढ़ियों से परेशान हैं। कार्यकर्ता कॉर्पोरेट प्रबंधन से मांग कर रहे हैं कि वे जाति को नस्लीय पूर्वाग्रह के मुद्दे के रूप में गहराई से समझें।

चूंकि अमेरिकी उद्योग इस विषय पर बात करने में असहज महसूस करता है, इसलिए इक्वालिटी लैब्स और इसके सहयोगी संगठन राजनीतिक रूप से सही होने और हमलों से सुरक्षित रहने के लिए 'जातिगत योग्यता प्रशिक्षण' प्रदान कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, इसके कार्यकर्ताओं की टीम बड़ी अमेरिकी कंपनियों को प्रशिक्षित करती है और इस तरह उन्हें जातिगत भेदभाव के आरोपों से बचाती है। इस प्रकार इक्वालिटी लैब्स ने अपने लिए एक फलता-फूलता व्यवसाय खड़ा कर लिया है।

2020 में, अमेरिकी कंपनियों ने नस्लीय समानता के प्रयासों के लिए पैंतीस अरब डॉलर देने का वादा किया। विविधता, समता और समावेशन के क्षेत्र में कई सलाहकारों का कहना है कि 2020 की गर्मियों का समय उनके करियर का अब तक का सबसे व्यस्त दौर था। यह कोविड-19 और जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के विरोध प्रदर्शनों का मिलाजुला प्रभाव था। कंपनियां अक्सर विविधता पर अपना रुख स्पष्ट करके मुकदमों के जोखिम को कम करती हैं। वे विविधता, समानता और समावेशन (DEI) प्रशिक्षण के लिए बजट आवंटित करके ऐसा करती हैं।

दर्जनों कंपनियों और संस्थानों ने शर्मनाक गलतियों या एकरूपता वाले बोर्डों और कार्यस्थलों के खुलासे से उत्पन्न विवादों को टालने के लिए हाई-प्रोफाइल पहल शुरू की हैं या किसी अश्वेत व्यक्ति को प्रमुख पद पर नियुक्त किया है।

हमें माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और अन्य कंपनियों के अमेरिकी मुख्यालयों में काम करने वाले भारतीयों से पता चला है कि उन्हें इन 'जातिगत

संवेदनशीलता प्रशिक्षण' कार्यशालाओं में भाग लेना अनिवार्य है। उनका मानना है कि इन कार्यशालाओं की सामग्री सनसनीखेज, एकतरफा और घोर अपमानजनक है। लेकिन 'जातिवादी', 'नस्लवादी' आदि करार दिए जाने के डर से कोई भी खुलकर नहीं बोलता।

ऐसे मुकदमों और डराने-धमकाने की रणनीति का असर उन कंपनियों पर दूरगामी होने की संभावना है जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय कर्मचारी कार्यरत हैं। कार्यस्थल पर भेदभाव को रोकने और उस पर नज़र रखने के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के समान रोजगार अवसर आयोग (यूनाइटेड स्टेट्स इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन) के तहत सौ से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को कर्मचारियों की जाति/नस्ल, लिंग, नौकरी की श्रेणी और वेतन से संबंधित जनसांख्यिकीय डेटा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राज्य स्तर पर भी इसी तरह की आवश्यकताएं मौजूद हैं। एक बार जब जाति को नस्ल के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है और ऐसे कानूनों के तहत स्पष्ट रूप से शामिल कर लिया जाता है, तो कंपनियों को जनगणना करानी होगी और अपने भारतीय और हिंदू कर्मचारियों को जाति के आधार पर आधिकारिक रूप से वर्गीकृत करना होगा।

विचित्र तथ्य यह है कि अमेरिकी कंपनियों के मानव संसाधन विभाग, नागरिक अधिकार प्रवर्तन एजेंसियां और अदालतें एक ही अप्रमाणित रिपोर्ट के आधार पर अंधाधुंध कार्रवाई करने में जुट गई हैं। उचित सावधानी की यह कमी इक्वालिटी लैब्स के एजेंडे के प्रति सहानुभूति रखने वालों के लिए भी खतरे की घंटी बजा देनी चाहिए।

अमेरिकी कॉलेज और विश्वविद्यालय

तकनीकी उद्योग की तरह ही, अमेरिकी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के परिसरों में भी बड़ी संख्या में भारतीय छात्र रहते हैं। कुछ परिसरों में,

जाति को हाल ही में एक 'संरक्षित वर्ग' घोषित किया गया है, जो एक औपचारिक शब्द है और जिसके कानूनी परिणाम होते हैं। अमेरिकी संघीय और राज्य कानूनों के तहत, संरक्षित वर्ग उन लोगों का समूह है जिनमें कोई समान विशेषता होती है और जिन्हें उस विशेषता के आधार पर रोजगार में भेदभाव से कानूनी रूप से सुरक्षा प्राप्त होती है। संघीय संरक्षित वर्गों में नस्ल, त्वचा का रंग, धर्म या पंथ, राष्ट्रीय मूल या वंश, लिंग (जिसमें लिंग, गर्भावस्था, यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान शामिल हैं), आयु, शारीरिक या मानसिक विकलांगता आदि शामिल हैं। कार्यकर्ता इस सूची में जाति को शामिल करवाने के लिए पैरवी कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, अमेरिका के सभी प्रकार के प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों की जाति का डेटा संकलित करना शुरू कर देंगे, जिसका व्यावहारिक अर्थ है भारतीय मूल के लोगों की प्रोफाइलिंग करना और यह साबित करने के लिए इस डेटा की रिपोर्ट करना कि वे जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। इससे निश्चित रूप से 'जाति विशेषज्ञों' के लिए प्रतिष्ठानों को परामर्श देने का रास्ता खुल जाएगा।

हमने अमेरिकी शिक्षा जगत, विशेषकर दक्षिण एशियाई अध्ययन विभागों में व्याप्त हिंदू-विरोधी भावना के बारे में विस्तार से लिखा है। उच्च जाति के भारतीयों को उत्पीड़क के रूप में चित्रित करने का यह कदम, जिससे उन्हें अपनी पहचान के लिए अपराधबोध महसूस करना पड़े, हिंदू-विरोधी भावना से लड़ने के लिए पिछले पच्चीस वर्षों में किए गए सभी प्रयासों को निष्फल कर देगा। हिंदू छात्र और संकाय सदस्य नस्लवादी करार दिए जाने के डर से अपनी पहचान छिपाएंगे या उसके लिए क्षमा याचना करेंगे।

मैसाचुसेट्स स्थित ब्रैंडिस विश्वविद्यालय ने अब अपनी भेदभाव-विरोधी और उत्पीड़न-विरोधी नीति में जाति को शामिल कर लिया है, जैसा कि

कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, डेविस ने भी किया है। कई अन्य परिसर अपनी आधिकारिक भेदभाव-विरोधी नीतियों में जाति को शामिल करने के विभिन्न चरणों में हैं। विश्वविद्यालय अधिकारी कुछ छात्र और संकाय कार्यकर्ताओं के दबाव के कारण यह कदम उठा रहे हैं। वर्तमान में, कैलिफोर्निया राज्य में तेईस परिसरों वाले कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी सिस्टम में जाति पर विचार किया जा रहा है। अप्रैल 2021 में, कैलिफोर्निया स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें जाति को एक संरक्षित वर्ग के रूप में शामिल करने की मांग की गई और न्यासी बोर्ड को अपनी नीतियों को अद्यतन करने और जाति की बेहतर समझ के लिए संसाधन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। यह किसी भी राज्यव्यापी विश्वविद्यालय प्रणाली में अपनी तरह का पहला प्रस्ताव था। इसमें जाति को 'एक ऐसी दमनकारी संरचना के रूप में वर्णित किया गया है जो दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोगों को प्रभावित करती है', और कहा गया है कि इस व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शामिल हैं, और वे लोग भी शामिल हैं जो जाति व्यवस्था से पूरी तरह बाहर हैं (अर्थात दलित)।[36]

इक्वालिटी लैब्स की रिपोर्ट और सिस्को मामले का हवाला देते हुए प्रस्ताव में कहा गया है:

जबकि: जातिगत स्थिति से जुड़ी ये सभी असमानताएं दक्षिण एशियाई अमेरिकी संस्थानों और अमेरिकी मुख्यधारा के उन संस्थानों में गहराई से समा गई हैं, जिनमें दक्षिण एशियाई आप्रवासियों की अच्छी खासी आबादी है, और जातिगत सामाजिक पहचान के कुछ कारक उपनाम, परिवार द्वारा मांसाहार, उनके मूल देश में भूमि स्वामित्व, वे किससे विवाह करना चाहते हैं या प्रेम संबंध रखना चाहते हैं, और क्या उन्हें अपने पूजा स्थल और समुदाय में बाहर निकलने की अनुमति है, आदि हैं;[37]

इस प्रस्ताव में इक्वालिटी लैब्स के निर्देशों का अनुपालन करने का भी स्पष्ट आह्वान किया गया था:
जबकि: भेदभाव-विरोधी नीति में जाति को शामिल करने से कैल पॉली और बड़े सीएसयू अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन इक्वालिटी लैब्स की सिफारिशों के अनुरूप हो जाएंगे; [38]
और अंत में यह निष्कर्ष निकलता है:
अतः यह संकल्प लिया जाता है: कैलिफ़ोर्निया पॉलीटेक्निक विश्वविद्यालय और पूरे कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय में भर्ती के दौरान जाति को एक संरक्षित श्रेणी के रूप में शामिल करने के साथ-साथ जातिगत योग्यता प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए।
सिस्को मामले की तरह ही, इस तरह की शब्दावली यह सवाल खड़ा करती है कि आखिर कौन यह तय करेगा कि किसी हिंदू का शाकाहारी भोजन या उसी जाति के व्यक्ति से विवाह जातिगत भेदभाव है या नहीं। क्या भारतीय मूल के छात्रों और शिक्षकों को किसी विश्वविद्यालय द्वारा इक्वालिटी लैब्स के निर्देशों को इतनी बेशर्मी से लागू करने और अपनी नीतियों को बनाने के लिए उसके 'प्रशिक्षण' का उपयोग करने के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार होगा? क्या जाति की जटिलताओं की बहुत कम जानकारी रखने वाले विश्वविद्यालय प्रशासकों द्वारा हिंदुओं को स्पष्ट रूप से निशाना बनाना भेदभावपूर्ण है?

अमेरिकी स्थानीय सरकारें

अमेरिका में काउंटी स्तर की सरकारों में भी जाति ने राजनीति में अचानक प्रवेश कर लिया है। उदाहरण के लिए, सिलिकॉन वैली के केंद्र में स्थित सांता क्लारा काउंटी को एक प्रस्ताव भेजा गया। यहीं पर कई बड़ी तकनीकी कंपनियां स्थित हैं जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय मूल के

कर्मचारी काम करते हैं। इसलिए, सनसनी फैलाने के उद्देश्य से इस क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में चुना गया है।
सार्वजनिक अभिलेखों के अनुसार, सौंदराजन ने नवंबर 2020 में सांता क्लारा काउंटी आयोग के साथ मुलाकात की और उन्हें सर्वसम्मति से एक तदर्थ समिति के गठन को मंजूरी देने के लिए राजी कर लिया।
इक्वालिटी लैब्स की थेनमोझी सौंदराजन ने जाति व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जाति व्यवस्था के पदानुक्रम और आधुनिक विश्व में जाति व्यवस्था से संबंधित जानकारी प्रदान की। साथ ही, उन्होंने दक्षिण एशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापक रूप से फैले जातिगत भेदभाव के बारे में भी बताया। सुश्री सौंदराजन ने कार्यस्थल, शिक्षण संस्थानों और रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत भेदभाव के कृत्यों का वर्णन किया।
अध्यक्ष बोरेन ने इस मुद्दे पर जागरूकता लाने के लिए सुश्री सौंदराजन की सराहना की। आयुक्त चायकिन के एक प्रश्न के उत्तर में, सुश्री सौंदराजन ने कहा कि इक्वालिटी लैब्स का उद्देश्य जाति को संरक्षित श्रेणी के रूप में स्थापित करना है, न कि जाति व्यवस्था को संरक्षित श्रेणी बनाना, और उन्होंने मुद्दों को संबोधित करने और जनता को अपनी कहानियाँ साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु एक सार्वजनिक मंच में रुचि व्यक्त की।
जाति को एक मुद्दे के रूप में औपचारिक रूप से आगे बढ़ाने पर समीक्षा शुरू हुई, जिससे जातिगत भेदभाव को रोकने और उस पर नज़र रखने के लिए नीतियां बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। स्थानीय भारतीय समुदाय भी इसमें शामिल हुआ और एक सार्वजनिक मंच में भाग लिया जहां आमंत्रित 'विशेषज्ञों' ने आयोग के निर्णय को सूचित करने में मदद करने के लिए अपने विचार व्यक्त किए।

हालांकि देखने में यह तदर्थ समिति एक निष्पक्ष स्वयंसेवी निकाय लग रही थी, लेकिन इसके उपाध्यक्ष, सांता क्लारा विश्वविद्यालय में संचार के एसोसिएट प्रोफेसर जस्टिन बोरेन ने सार्वजनिक बैठक का लिंक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने इक्वालिटी लैब्स, दलित विमेन फाइट, सांसद रो खन्ना, ऐश कालरा और रॉब (रॉबर्ट एंड्रेस) बोंटा (कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल) के अकाउंट को टैग किया। खन्ना और कालरा दोनों ही डेमोक्रेटिक पार्टी के वामपंथी धड़े और सीनेटर बर्नी सैंडर्स के जाने-माने समर्थक हैं। वैकल्पिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी व्यक्ति को इसमें शामिल नहीं किया गया था।

सार्वजनिक सुनवाई के दौरान, उपाध्यक्ष बोरन और अध्यक्ष ब्रायन फ्रेंज़ेन ने हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों को बार-बार बाधित किया। उन्होंने एक दलित प्रतिनिधि को, जो खुद को एक गर्वित हिंदू बता रहा था, यह कहकर चुप करा दिया कि इक्वालिटी लैब्स की उसकी आलोचना उस पर 'हमला' करने के बराबर है। दूसरी ओर, आयोग ने इक्वालिटी लैब्स को काफी छूट दी, और यहाँ तक कि एक ऐसे व्यक्ति को भी अनुमति दी जो 'जातिगत विशेषाधिकार' का दावा कर रहा था और जिसके पास अंदरूनी जानकारी थी, कि वह उच्च जाति के लोगों पर निम्न जातियों के प्रति 'हिंसक दमनकारी' होने का आरोप लगाए।

आमंत्रित ‘विशेषज्ञों’ में कई गुमनाम व्यक्ति शामिल थे, जिनमें से एक को ‘एच-1बी वीज़ा और जाति विशेषज्ञ’ बताया गया; दूसरे की पहचान केवल ‘पाकिस्तानी दलित प्रोफेसर’ के रूप में की गई; और एक अन्य ने स्वयं को ‘दलित क्वीर नॉन-बाइनरी’ बताया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान की प्रोफेसर अजंता सुब्रमणियन भी आमंत्रित वक्ता थीं। उन्होंने इन ‘विशेषज्ञों’ की गुमनामी को यह कहकर उचित ठहराया कि ‘इस मंच पर गुमनाम रूप से गवाही देने वाले दलितों की संख्या इस बात का प्रमाण

है कि जातिगत कलंक और भेद खुलने का डर अमेरिका में भी उनका पीछा कर रहा है।' सुब्रमणियन ने अमेरिका में जाति पर व्यवस्थित डेटा संग्रह की वकालत की क्योंकि इसका उपयोग शैक्षणिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को जातिगत भेदभाव से निपटने के लिए 'संस्थागत तंत्र' स्थापित करने के लिए बाध्य करने के लिए किया जा सकता है। हार्वर्ड में उनके कार्य पर अगले अध्याय में चर्चा की गई है, और उनका अत्यधिक पूर्वाग्रह स्पष्ट रूप से सामने आता है।

इक्वालिटी लैब्स और संबंधित संगठनों ने अपने पक्ष में गवाही देने के लिए काफी संख्या में लोगों को जुटाया, जिनमें कई दूसरी पीढ़ी के भारतीय अमेरिकी भी शामिल थे, जिन्होंने 'जातिगत विशेषाधिकार' प्राप्त होने के लिए माफी मांगी और अपने परिवारों और समुदायों में कथित रूप से व्याप्त जातिवाद, अश्वेत-विरोधी भावना, इस्लामोफोबिया और गैसलाइटिंग की निंदा की। कई गैर-दक्षिण एशियाई लोगों ने भी इक्वालिटी लैब्स के पक्ष में गवाही दी।

अंबेडकर किंग स्टडी सर्कल ने पहले सत्र के बाद निम्नलिखित प्रेस विज्ञप्ति जारी की:

सबसे तीखी टिप्पणियों में से एक उस वक्ता की थी जिसने तर्क दिया कि जिस प्रकार वह, एक श्वेत अमेरिकी महिला होने के नाते, गैर-श्वेत लोगों के नस्लवाद के अनुभवों को परिभाषित या खंडित करने की स्थिति में नहीं है, उसी प्रकार उच्च जातियों के सदस्य भी जातिगत भेदभाव के अस्तित्व से इनकार करने की स्थिति में नहीं हैं। उनकी यह टिप्पणी स्पष्ट रूप से उन कई उच्च जाति के वक्ताओं के जवाब में थी जिन्होंने दलित और बहुजन वक्ताओं पर अपनी कहानियों को मनगढ़ंत बताने का बार-बार आरोप लगाया था।

गवाही देने के लिए प्रतीक्षा कर रहे आम लोगों की संख्या आयोग की

अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी और सत्र लगभग आठ घंटे तक चला। दूसरी बैठक आयोजित की गई जिसमें आयोग ने अपनी कार्य योजना में जातिगत मुद्दे को शामिल करने के संबंध में अंतिम निर्णय को स्थगित कर दिया। अध्यक्ष फ्रेंज़ेन ने स्वीकार किया कि यह मुद्दा उनके प्रारंभिक अनुमान से कहीं अधिक जटिल था। फिर भी, सांता क्लारा काउंटी की वेबसाइट पर कार्यवाही का दस्तावेजीकरण अभी भी इक्वालिटी लैब्स और उसके सहयोगियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री पर आधारित है। हिंदू अमेरिकी समुदाय के सदस्यों द्वारा भेजे गए कई पत्र भी मौजूद हैं। आयोग की वेबसाइट पर सूचीबद्ध एक विशेष रूप से उल्लेखनीय दस्तावेज़ नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल (एनएएसीपी) द्वारा पारित एक प्रस्ताव है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे पुराने और सबसे सम्मानित नागरिक अधिकार संगठनों में से एक है। इसकी शुरुआत रेवरेंड मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा स्वयं को 'अछूत' के रूप में पहचानने के उल्लेख से होती है।

इस प्रस्ताव में हिंदू समूहों के खिलाफ लगाए गए निम्नलिखित आरोप निराधार और विशेष रूप से कठोर हैं:

जबकि जाति की किसी भी आलोचना को हिंदुत्ववादी समूहों द्वारा हिंदू धर्म पर हमले के रूप में निंदा का पात्र बनाया जाता है। सिस्को जाति भेदभाव मुकदमे में, एक हिंदुत्ववादी समूह ने कैलिफोर्निया सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की कि जाति भेदभाव का आरोप निष्पक्ष रोजगार और आवास विभाग द्वारा हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता और अधिकारों में हस्तक्षेप है। कैलिफोर्निया में पाठ्यपुस्तक के मुद्दे पर हिंदू दक्षिणपंथी समूहों ने अमेरिका में जाति प्रथा के खंडन के लिए बच्चों सहित हजारों लोगों को लामबंद किया; और

कार्यस्थल पर जातिगत भेदभाव का प्रचलन दक्षिण एशियाई लोगों द्वारा

अपने दैनिक जीवन में किए जाने वाले जातिगत भेदभाव का ही विस्तार है; बड़े कॉरपोरेट संस्थानों में भर्ती और बर्खास्तगी के पदों पर आसीन विशेषाधिकार प्राप्त जातियां धनबल और सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों को नियंत्रित करती हैं तथा सार्वजनिक पदों तक उनकी पहुंच होती है; जिससे दलित और भी अधिक असुरक्षित हो जाते हैं।

शक्तिशाली NAACP द्वारा पारित और पूरे अमेरिका में कानूनी कार्यवाही में इस्तेमाल किया जाने वाला ऐसा आधिकारिक प्रस्ताव अमेरिका में हिंदुओं के लिए संभावित रूप से खतरनाक है। विशेष रूप से, हिंदू धर्म और 'हिंदुत्व' को इस कथित भेदभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यह ईसाई धर्म पर गुलामी और रंगभेद का आरोप लगाने और किसी व्यक्ति के ईसाई परंपराओं के पालन को उसकी नस्लवादी प्रवृत्ति का मापदंड बनाने के समान है। हिंदू धर्म को छोड़कर दुनिया के किसी भी अन्य प्रमुख धार्मिक परंपरा के साथ ऐसा करने की हिम्मत कोई नहीं करेगा।

मुद्दे और चुनौतियाँ

सभी कानूनी मामलों और प्रस्तावों/संकल्पों में इक्वालिटी लैब्स अग्रणी भूमिका निभा रही है। यह छात्रों और विद्वानों के बीच अपनी मजबूत उपस्थिति का उपयोग एक कठोर जाति व्यवस्था के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए कर रही है, जिसका दोषी हिंदू धर्म है। इसके आरोपों के अनुसार, जाति एक आपराधिक प्रकार की हिंदू धार्मिक प्रथा है। निम्न जातियों को सांवली त्वचा वाला और उच्च जातियों को गोरी त्वचा वाला बताया जाता है, ताकि अमेरिका की अश्वेत/श्वेत नस्लीय राजनीति की

भावनाओं का फायदा उठाया जा सके।

सभी मामलों में मीडिया कवरेज का एक ही दृष्टिकोण है और वही विशेषज्ञ एक साक्षात्कार से दूसरे साक्षात्कार में बार-बार सामने आते हैं। इसका मतलब है कि पूरे भारतीय अमेरिकी समुदाय को नस्लवादी करार दिया जा रहा है और उन्हें अति-वामपंथी आंदोलन द्वारा हमला किए जाने योग्य माना जा रहा है। कंपनियों और विश्वविद्यालयों पर भारतीयों को एक बोझ के रूप में देखने का दबाव डाला जा रहा है। इससे उनकी भर्ती और पेशेवर उन्नति प्रभावित हो सकती है और कार्यस्थल पर उनके आपसी संबंधों में असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है।

ये सभी मामले हिंदू धर्म को जन्मजात रूप से कट्टर और दमनकारी बताकर दायर किए गए हैं। लेकिन अमेरिकी संविधान राज्य के किसी भी अंग को धार्मिक सिद्धांतों के मामलों में हस्तक्षेप करने से रोकता है, और सरकार को किसी व्यक्ति के धर्म को परिभाषित करने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा, प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों और दायित्वों को जानने का अधिकार है, और उल्लंघन संबंधी किसी भी नोटिस में स्पष्ट रूप से यह बताया जाना चाहिए कि कानून का उल्लंघन कैसे हो रहा है। ऐसे कानून और उनका प्रवर्तन व्यक्तिपरक, मनमाना, सुनी-सुनाई बातों पर आधारित आदि नहीं हो सकते। सच्चाई यह है कि यदि आप भारतीयों के एक यादृच्छिक समूह से पूछें कि जाति का अर्थ क्या है, तो अलग-अलग उत्तर सामने आएंगे। एक औपचारिक, व्यापक रूप से स्वीकृत परिभाषा के बिना, जाति मुकदमेबाजी का कारण कैसे बन सकती है? यदि परिभाषा पर आम सहमति भी हो, तो भी कंपनियों या विश्वविद्यालयों के लिए किसी व्यक्ति की जाति का निर्धारण करना चुनौतीपूर्ण होगा। यह निराधार धारणा है कि भारतीय मूल का हिंदू व्यक्ति अनिवार्य रूप से अपनी पहचान जाति के आधार पर बनाता है और जाति व्यवस्था के

सिद्धांत के अनुसार भेदभाव करता है। क्या भारतीय नामों वाले लोगों को भी जाति प्रमाण पत्र रखना आवश्यक होगा? यदि यह नियम हिंदुओं पर लागू होता है, तो अन्य जातीय या अल्पसंख्यक समूहों और अन्य राष्ट्रीय मूल के लोगों पर क्यों नहीं? एक और मुद्दा यह है कि कई हिंदू अपनी जाति के बारे में कुछ नहीं जानते, जैसे कि वे जिनके पूर्वज गुयाना, त्रिनिदाद, बहामास आदि में बंधुआ मजदूर के रूप में आए थे। अमेरिका में दूसरी और तीसरी पीढ़ी के हिंदू अप्रवासी, मिश्रित नस्ल के विवाह से जन्मे लोग, और श्वेत हिंदू या अश्वेत हिंदू - इनमें से अधिकांश अपनी जाति के बारे में अनभिज्ञ हैं।

इससे अमेरिकी संविधान के तहत गारंटीकृत समान संरक्षण की चुनौतियां सामने आती हैं, क्योंकि ये कार्यकर्ता एक ऐसा वर्ग बनाना चाहते हैं जो कानून की नजर में संदिग्ध होगा, और इसलिए भी क्योंकि नीतियों का एक विशेष समूह केवल उन्हीं पर लागू होगा।

भारतीय अमेरिकियों के लिए विशेष चिंता के विषय निम्नलिखित मुद्दे हैं: कार्यस्थल पर भेदभाव से जुड़े किसी मामले में, एक अमेरिकी कॉर्पोरेट मानव संसाधन अधिकारी, न्यायाधीश या जूरी किस प्रकार पूर्वाग्रह रख सकते हैं? क्या व्यवसाय भारतीय मूल के कर्मचारियों से उनकी जाति बताने को कहेंगे? क्या वे भारतीय सरकार के आधिकारिक जाति वर्गीकरण को अपनाएंगे? क्या वे यह मान लेंगे कि एक मराठी ब्राह्मण को तेलुगु रेड्डी पर उसी तरह का वर्चस्व प्राप्त जातिगत विशेषाधिकार है, जिस तरह गोरों को अश्वेतों पर है? क्या भेदभाव की शिकायत में एक गुजराती पटेल के शाकाहारी भोजन को जातिवाद का सबूत माना जाएगा? क्या हिंदुओं के लिए आत्मरक्षा करना कठिन हो जाने के कारण वे खुलेआम घृणास्पद भाषणों का शिकार बन जाएंगे? क्या अमेरिकी स्कूलों में हिंदू छात्रों के साथ होने वाली बदमाशी की घटनाएं और भी बदतर हो जाएंगी?

क्या कॉलेजों में यहूदी छात्रों द्वारा कोषेर रसोई की मांग करना उचित होगा, लेकिन हिंदू छात्रों द्वारा शाकाहारी भोजन की मांग को जातिवादी माना जाएगा?
इन मुद्दों को अमेरिकी कानूनों के तहत अमेरिकी मुद्दों के रूप में संबोधित किया जाना चाहिए (भले ही काल्पनिक रूप से, भारत सरकार वास्तव में 'फासीवादी' हो), क्योंकि हिंदू अमेरिकियों को भी धार्मिक स्वतंत्रता का समान अधिकार प्राप्त है।

दलित सशक्तिकरण आंदोलन का वैश्वीकरण
2014 के एक साक्षात्कार में, थेनमोझी सौंदराजन ने बताया कि हालाँकि उन्होंने स्नातक की पढ़ाई के दौरान खुद को दलित के रूप में सार्वजनिक किया, लेकिन पाँचवीं कक्षा में उन्हें पता चला कि भोपाल रासायनिक त्रासदी (1984 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र में हुई गैस रिसाव) ने अछूत नामक एक समूह को प्रभावित किया था, और तभी उनके माता-पिता ने उन्हें उनके वंश के बारे में बताया। एक अन्य साक्षात्कार में उन्होंने दावा किया कि दक्षिणी कैलिफोर्निया में रहने वाले भारतीय अमेरिकी उन्हें अपने घरों में आयोजित पार्टियों में अपने मुख्य बर्तनों और छुरी-कांटे का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देते थे। उनका कहना है कि उनका परिवार जाति व्यवस्था से बचने के लिए भारत छोड़कर आया था, और जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी दलित पहचान की घोषणा की, तो उन्हें उच्च जाति के भारतीय प्रोफेसरों द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया और उन्हें जान से मारने की धमकियाँ भी मिलीं। सौंदराजन को एक नेता के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिसका प्रमाण उन्हें मिले पुरस्कारों की विशाल संख्या से मिलता है।
उनके काम को प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका डायवर्सिटी प्रोग्राम,

म्यूजियम ऑफ कंटेम्परेरी आर्ट, रॉबर्ट राउशेनबर्ग फाउंडेशन, चिकन एंड एग फाउंडेशन, एनेनबर्ग इनोवेशन सेंटर, स्लैमडांस, एमआईटी सेंटर फॉर न्यू मीडिया स्टडीज, सोरबोन, द सोर्स मैगजीन, उत्ने रीडर, नेशनल सेंटर फॉर द ह्यूमैनिटीज, नेशनल साइंस फाउंडेशन, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजिल्स और अल्फ्रेड पी. स्लोअन फाउंडेशन द्वारा मान्यता प्राप्त है।

इक्वालिटी लैब्स खुद को अंबेडकरवादी शक्ति-निर्माण संगठन के रूप में वर्णित करता है, जो अपने संदेशों और राजनीतिक गतिविधियों में एक विशिष्ट भारतीय धार्मिक और राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ-साथ समकालीन अमेरिकी सामाजिक न्याय का प्रतिनिधित्व करता है। इसके जमीनी स्तर के एजेंडे में हिंदू आस्था और पहचान की विभिन्न अभिव्यक्तियों को लक्षित करना शामिल है। उदाहरण के लिए, "हम होली को ना क्यों कहते हैं? जातिवाद को चुनौती देने के लिए एक मार्गदर्शिका" शीर्षक वाले एक ब्लॉग में, इसने होली के त्योहार की कड़ी आलोचना की, क्योंकि इसका कथित संबंध 'एक आदिवासी राजा के हिंसक तख्तापलट', होलिका (एक दलित) की हत्या और 'औपनिवेशिक' ब्राह्मणों द्वारा जातिगत उत्पीड़न और आदिवासी लोगों की परंपराओं के हाशिए पर धकेलने से था। इसका आह्वान था:

स्वयं इसका जश्न मनाने से बचें और इसके हिंसक इतिहास को भगवा रंग में रंगने के सांस्कृतिक प्रयासों का विरोध करें... भोजन के दौरान कहानी का बहुजन संस्करण साझा करें। लोगों को भारत के इतिहास पर ब्राह्मणवादी नियंत्रण के बारे में शिक्षित करें और इसे भाजपा, हिंदू फासीवाद और उच्च जाति के सत्ता नेटवर्क के उदय से जोड़ें। ... जिस प्रकार प्रगतिशील अमेरिकी स्वदेशी प्रतिरोध का सम्मान करने के लिए थैंक्सगिविंग नहीं मनाते, उसी प्रकार सत्ता निर्माण के तरीकों के बारे में

सोचें और जाति उन्मूलन के प्रयासों का समर्थन करें। साथ में भोजन करें, दलित और बहुजन इतिहास पढ़ें और उन नेताओं का सम्मान करें जो उच्च जाति और ब्राह्मण परिवारों से नहीं हैं।

इसने आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों सहित कई हाशिए पर पड़े समुदायों में आजमाई गई राजनीतिक लामबंदी रणनीतियों को तेजी से अपनाया है। इक्वालिटी लैब्स का ध्यान स्थायी पेशेवर संगठनों का जमीनी स्तर का नेटवर्क बनाने और विरोध प्रदर्शनों, सार्वजनिक मंचों में भागीदारी, मीडिया से संपर्क और कानून निर्माण के माध्यम से प्रत्यक्ष कार्रवाई के लिए लोगों को संगठित करने पर केंद्रित है।

पांच वर्षों के भीतर, इसने भारतीय और हिंदू अमेरिकियों को एक सफल अमेरिकी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में पेश करने वाली प्रचलित धारणाओं को सफलतापूर्वक नया रूप दिया है। इसने जो नई धारणा व्यापक रूप से स्थापित की है, वह यह है कि समुदाय की सफलता का कारण उनके धार्मिक जुड़ाव के कारण उनमें निहित प्रतिगामी और भेदभावपूर्ण प्रथाएं हैं। इस प्रकार, नया नारा यह है: भारतीय जहां भी जाते हैं, वे अपने साथ जाति ले जाते हैं।

इक्वलिटी लैब्स ने मुख्यधारा के दानदाताओं के साथ-साथ सरकार, शिक्षा जगत और निगमों के निर्णयकर्ताओं को लक्षित करते हुए अत्याचारों से संबंधित अत्यंत प्रभावशाली साहित्य तैयार किया है। इसमें समानांतर रूप से कई अभियान चलाने की क्षमता है जो मीडिया का प्रभावी ढंग से उपयोग करके सार्वजनिक दृष्टिकोण को निर्धारित करते हैं। अभिजात्य मीडिया, शिक्षा जगत और उच्च स्तरीय नीति निर्माताओं के द्वार उनके लिए खुल गए हैं। बीएपीएस के खिलाफ उनकी सुनियोजित कानूनी कार्रवाई के परिणामस्वरूप, हिंदू अमेरिकी आबादी, अमेरिकी उद्योग और राजनीति में अपनी शक्तिशाली स्थिति के दावों के बावजूद, रक्षात्मक

स्थिति में आ गई है और जनता की नजरों में संदिग्ध बन गई है। हम अपराधों के मामलों में न्याय दिलाने का समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि बीएपीएस ने श्रम कानूनों का उल्लंघन किया है, तो उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। लेकिन इससे पूरे समुदाय को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे अमेरिका में मुसलमानों, अश्वेतों या ईसाइयों द्वारा किए गए अपराधों के परिणामस्वरूप उन पहचानों को इस तरह से कलंकित नहीं किया जाता है।

हिंदू-विरोधी भावना की अवधारणा को भी चुनौती दी जा रही है क्योंकि हिंदुओं को उनके उत्पीड़ित दलित साथी अमेरिकियों के खिलाफ आपराधिक शत्रुता के अपराधियों के रूप में कलंकित किया जा रहा है। जैसा कि पहले चर्चा किए गए कानूनी मामलों से स्पष्ट है, सुस्थापित व्यक्तियों की बड़ी हिंदू आबादी की उपस्थिति से अधिकारियों और प्रशासकों की इक्वालिटी लैब्स को समर्थन देने की इच्छा पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता।

इक्वालिटी लैब्स की सक्रियता झूठे आरोपों से भरी हुई है। उदाहरण के लिए, 2020 में, डार्टमाउथ कॉलेज की एक छात्रा ने तीन हिंदू प्रोफेसरों पर मुस्लिम होने के कारण उसे परेशान करने का आरोप लगाया। उसने यह भी कहा कि 'उसे लगता है कि हिंदुओं को मुसलमानों को प्रताड़ित होते देखना अच्छा लगता है'।

महा हसन अलशावी ने आगे आरोप लगाया कि प्रोफेसर प्रसाद जयंती 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)' नामक एक मुस्लिम विरोधी संगठन के सदस्य थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने एक स्नातक छात्रा को उनके धर्म के बारे में पूछताछ करने का निर्देश दिया था। जहां तक प्रतिवादी जयंती के मुस्लिम विरोधी संगठन के सदस्य होने की रिपोर्ट का सवाल है, इस आरोप का समर्थन करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं

थी।
दुर्भाग्यवश, अमेरिका में ऐसा कोई तुलनीय भारतीय जमीनी संगठन नहीं है जो कॉरपोरेट जगत, सरकार, विश्वविद्यालय और मीडिया में कार्यरत भारतीय अमेरिकियों के लिए लगातार इसी तरह की गतिविधियाँ चला रहा हो। इसे समस्याओं पर केवल प्रतिक्रिया देने के बजाय सक्रिय और निरंतर बने रहने की आवश्यकता होगी। इसे उच्चतम अमेरिकी मानकों के अनुरूप पेशेवर होना होगा और मुद्दों को अमेरिकी भाषा में प्रस्तुत करना होगा।

एक उम्मीद की किरण
इक्वालिटी लैब्स के काम में शायद एक सकारात्मक पहलू भी है। अंततः, यह हिंदू को अपने लिए लड़ने पर मजबूर करता है क्योंकि लड़ाई व्यक्तिगत होती जा रही है। यह लड़ाई हर हिंदू के कार्यस्थल, घर और परिवार में प्रवेश कर रही है, और वे अब तक की तरह असहज परिस्थितियों से भाग नहीं सकते।
लेकिन इससे भी अधिक उत्साहजनक बात यह है कि थेनमोझी सौंदराजन के विचारों में हाल ही में एक बदलाव आया है। उन्होंने बौद्ध ध्यान (अर्थात विपश्यना, जिसे अब माइंडफुलनेस के रूप में नया नाम दिया गया है) के उपयोग की वकालत करना शुरू कर दिया है।
वह विशेष रूप से रूथ किंग के काम से प्रभावित हैं, जो एक अश्वेत ध्यान शिक्षिका और कई पुस्तकों की लेखिका हैं, जिनमें "नस्लवाद का मूल भाव बदलना" भी शामिल है। [51] यह एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, और इस मुद्दे से जुड़े सभी लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए। इस पुस्तक में हमने कई बार भारत में विकसित विभिन्न ध्यान प्रणालियों के माध्यम से प्राप्त चेतना के स्तर को बढ़ाने की वकालत की है। केवल सामान्य अहंकार से ऊपर के स्तर से ही, जिसे रूथ किंग 'अंदर से बाहर'

कहती हैं, मानवता जाति और अन्य पहचानों की भयानक सीमाओं को पार कर सकती है। हमें आशा है कि थेनमोझी सौंदराजन वास्तव में चेतना को बढ़ाने के मार्ग पर चल रही हैं और हम सभी हितधारकों के हित में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहयोग का स्वागत करते हैं।

4. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में योग्यता प्रणाली पर हमला

अवलोकन
हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मानवविज्ञान की प्रोफेसर अजंता सुब्रमणियन ने 'द कास्ट ऑफ मेरिट: इंजीनियरिंग एजुकेशन इन इंडिया' नामक एक चर्चित पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जातिगत विशेषाधिकारों को बढ़ावा देने और उन्हें कायम रखने वाली फैक्ट्रियां हैं। वे शिक्षा जगत में प्रभावशाली हैं और हार्वर्ड स्थित मित्तल फैमिली इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जहां वे 'बिल्डिंग नेशंस, ब्रेकिंग कम्युनिटीज: द लोकैलिटी ऑफ कास्ट वायलेंस इन कॉलोनियल नॉर्थ इंडिया' जैसे सेमिनारों की अध्यक्षता करती हैं। वे हार्वर्ड में मेहरा फैमिली प्रोफेसर ऑफ साउथ एशियन स्टडीज भी हैं।
इस अध्याय में निम्नलिखित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है:
उनके शोध प्रबंध का एक मूलभूत विचार श्वेत अमेरिकी अभिजात्यवाद को भारत की उच्च जातियों से जोड़ना है। वे अपनी पुस्तक की शुरुआत में ही यह बात स्पष्ट कर देती हैं: 'उच्च जाति के सुदृढ़ीकरण को समझने के लिए, मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेतता के निर्माण पर हुए शोध का

सहारा लिया है।'

सुब्रमणियन आलोचनात्मक सिद्धांत का प्रयोग करते हुए अपना वैचारिक ढांचा विकसित करती हैं, जिसमें वह मानती हैं कि ब्राह्मण सांस्कृतिक पूंजीपति हैं और आईआईटी उनके द्वारा अधिक उच्च जाति के इंजीनियरों के उत्पादन का तंत्र हैं। इस सांस्कृतिक पूंजी को योग्यता के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है क्योंकि यह वस्तुनिष्ठ, स्वायत्त और वास्तविक प्रकार की क्षमता प्रतीत होती है। वह योग्यतावाद को एक आवरण के रूप में खारिज करती हैं जिसके पीछे ब्राह्मणों का विशेषाधिकार अपनी सर्वोच्चता को कायम रखता है।

उनके विशेष निशाने पर आईआईटी और उनके पूर्व छात्र हैं। वह उन पर सिलिकॉन वैली और अन्य जगहों पर आने वाली निचली जातियों के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाती हैं।

मुख्य बात यह है कि भले ही कोई IITian निष्पक्ष हो, फिर भी वह उसे संस्थागत संरचना से लाभ उठाने और इस प्रकार इसके दुर्व्यवहार को कायम रखने और मजबूत करने का दोषी मानती है। उनके अनुसार, IIT अपनी संरचना के कारण ही जातिगत विशेषाधिकारों को स्थापित करते हैं, चाहे कोई ब्राह्मण छात्र आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से हो या कोई निम्न जाति का छात्र आर्थिक रूप से सशक्त और सुशिक्षित परिवार से हो। अध्याय 1 में क्रिटिकल रेस थ्योरी के केंद्र बिंदु को समूह पहचानों के टकराव पर बताया गया है, न कि व्यक्तिवाद पर।

सुब्रमणियन ने पियरे बॉर्डियू के उस प्रसिद्ध कथन का हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रतिष्ठित परीक्षाएं और उच्च शिक्षा प्रणाली पुरानी सामाजिक व्यवस्थाओं के पुनरुत्पादन की गारंटी देती हैं। इस कथन का हवाला देते हुए, वह यह साबित करना चाहती हैं कि IIT की परीक्षा और पाठ्यक्रम भारत में जातिगत व्यवस्थाओं को पुनर्जीवित कर रहे हैं।

लेकिन वह परीक्षा या पाठ्यक्रम में जातिवाद का कोई ठोस प्रमाण नहीं देतीं। वह केवल स्वयं को 'पीड़ित' बताने वाले लोगों के कई व्यक्तिगत किस्से सुनाती हैं।

सुब्रमणियन आईआईटी की संस्थागत संरचना को भंग करने और इस दमन से शोषित निम्न वर्गों को मुक्त करने की वकालत करती हैं। उनका व्यापक सक्रियतावाद सामाजिक इंजीनियरिंग को बढ़ावा देना है, जो राजनीतिक वोट बैंक और कानून के साथ-साथ विविधता के लिए कॉर्पोरेट नीतियों को भी प्रभावित करता है।

उनका रवैया निचली जातियों के प्रति तिरस्कारपूर्ण है, जिससे यह संकेत मिलता है कि उनमें योग्यता की कमी है और किसी भी प्रकार की योग्यता प्रणाली उनके खिलाफ एक साजिश है। उनका मूल भाव यह है कि समान अवसर मिलने पर भी निचली जातियां योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकतीं।

वह इस बात को नजरअंदाज करती है कि अमेरिका में भारतीय प्रवासियों की प्रौद्योगिकी-प्रधान संरचना जातिगत विशेषाधिकार के कारण नहीं है, बल्कि यह उसकी आप्रवासन नीति का परिणाम है जो योग्यता और समाज में योगदान देने वालों को प्राथमिकता देती है।

सुसंगत रहने के लिए, सुब्रमणियन को अन्य प्रकार के अभिजात वर्गीय पदानुक्रमों को भी लक्षित करना होगा, जैसे कि भारतीय मुसलमानों के सामाजिक संगठन, जवाहरलाल नेहरू की समाजवादी संरचनाएं, हार्वर्ड के बिजनेस-मेडिकल-और कैनेडी स्कूल के पूर्व छात्र नेटवर्क।

जैसा कि हम आगे बताएंगे, जाति पर उनके विचार सरलीकरण, अति सरलीकरण और अपने दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए साक्ष्यों के चयनात्मक उपयोग से भरे हुए हैं।

हमें उनके काम से यह आपत्ति है कि यह भारत में सांप्रदायिकता,

विभाजन और राष्ट्र-विरोधी भावना को बढ़ावा देता है। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई फूट डालो और राज करो की नीति को हार्वर्ड के प्रोफेसरों द्वारा संचालित अंतरजातीय पहचान युद्धों के रूप में फिर से दोहराया जा रहा है।

पश्चिमी योग्यतावाद की उत्पत्ति

प्रारंभ में, हम सुब्रमणियन के इस विचार से असहमत हैं कि आधुनिक योग्यता-आधारित व्यवस्था के लिए किसी प्रकार से भारतीय जाति व्यवस्था को दोषी ठहराया जा सकता है। पश्चिम में योग्यता-आधारित व्यवस्था का विचार प्रारंभिक यहूदी-ईसाई धर्म से जुड़ा है, जिसमें यह मान्यता है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है और बुरे लोगों के साथ बुरा होता है। हम इस धार्मिक सिद्धांत को बाइबिल आधारित योग्यता-आधारित व्यवस्था कह सकते हैं। इसे सर्वशक्तिमान और सर्व-कल्याणकारी ईश्वर द्वारा स्थापित किया गया था। हर सौभाग्य एक पुरस्कार है और हर दुर्भाग्य एक दंड।

सदियों बाद प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन आया। जर्मन समाजशास्त्री और राजनीतिक अर्थशास्त्री मैक्स वेबर के अनुसार, इसके परिणामस्वरूप प्रोटेस्टेंट कार्य नीति का उदय हुआ। अपनी उल्लेखनीय पुस्तक, "प्रोटेस्टेंट नैतिकता और पूंजीवाद की भावना" में, वेबर ने एक समाजशास्त्रीय और आर्थिक सिद्धांत प्रस्तुत किया कि प्रोटेस्टेंट धर्म के मूल्य परिश्रम, अनुशासन और मितव्ययिता को जन्म देते हैं, जो आधुनिक पूंजीवाद की नींव बने। इसने प्रोटेस्टेंटों (विशेषकर सोलहवीं शताब्दी के धर्मशास्त्री जॉन कैल्विन के अनुयायियों) को धन संचय करने के लिए प्रोत्साहित किया, और उनमें से कई ने अपनी भौतिक सफलता को ईश्वर से प्राप्त शाश्वत मुक्ति का संकेत माना।

अमेरिका में, यह विचार और विकसित हुआ कि स्वतंत्र, वैश्वीकृत बाजार

लोगों को उनकी प्रतिभा और पहल के अनुरूप पुरस्कृत करते हैं। चूंकि सफलता के लिए ऐसे गुण नैतिक होना आवश्यक नहीं था, इसलिए तकनीकी योग्यता-आधारित प्रणाली का जन्म हुआ।

धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का प्रतिपादन अर्थशास्त्र के जनक माने जाने वाले एडम स्मिथ ने अपनी 1776 की पुस्तक 'द वेल्थ ऑफ नेशंस' में किया था। तब से, अर्थशास्त्रियों ने इस अवधारणा को बढ़ावा दिया है कि अपने स्वार्थों का पालन करने से समाज के लिए सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। इस विचारधारा ने मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा को सीमित संसाधनों के आवंटन का सबसे कुशल तरीका बताया। हर कोई सीमित वस्तुओं और सीमित संख्या में नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, और इनका आवंटन उपभोक्ताओं और श्रमिकों की क्षमता (या योग्यता) के आधार पर होता है।

पश्चिम में योग्यतावाद की ऐतिहासिक उत्पत्ति और विकास को निम्नलिखित कालक्रम के रूप में दर्शाया जा सकता है: बाइबिल आधारित योग्यतावाद → प्रोटेस्टेंट नैतिकता → आधुनिक पूंजीवाद → तकनीकी योग्यतावाद → एडम स्मिथ।

हाल ही में, अमेरिका पर योग्यता को अत्यधिक महत्व देने का आरोप लगाया गया है। उदाहरण के लिए, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में राजनीतिक दर्शन के प्रोफेसर माइकल जे. सैंडेल ने अपनी हालिया पुस्तक, "द टायरेनी ऑफ मेरिट: व्हाट्स बिकम ऑफ द कॉमन गुड?" में लिखा है कि उनके अपने छात्र आश्वस्त हैं कि उनकी सफलता पूरी तरह से योग्यता के कारण है, जबकि उनमें से दो-तिहाई उच्च आय वर्ग से हैं।

अनेक लेखकों ने योग्यता-आधारित व्यवस्था की कमियों को उजागर किया है और इसके लिए कई कारण बताए हैं। लेकिन अजंता सुब्रमण्यम से पहले किसी ने भी हिंदू जाति को मुख्य दोषी नहीं ठहराया। ऊपर संक्षेप

में वर्णित पश्चिमी योग्यता-आधारित व्यवस्था का इतिहास सुब्रमण्यम द्वारा हिंदुओं पर 'योग्यता' के आधार पर किए गए हमले की तार्किक निरर्थकता को दर्शाता है, जबकि उनके हमले का असली निशाना तो स्वयं पश्चिमी व्यवस्था ही है।

भारत में कारीगरों और इंजीनियरों को अलग करने का इतिहास
अब हम सुब्रमणियन के उस शोध प्रबंध का सारांश प्रस्तुत करेंगे जिसे उन्होंने भारत में तकनीकी प्रशिक्षण के अपने ऐतिहासिक विश्लेषण के आधार पर तैयार किया है।
यह सर्वमान्य है कि परंपरागत रूप से भारत में तकनीकी ज्ञान निम्न जातियों के कारीगरों के अधिकार क्षेत्र में था। धर्मपाल की रचनाओं और इन्फिनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित 'भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इतिहास' श्रृंखला जैसी कई कृतियों में इसका प्रमाण मिलता है।
अंग्रेजों ने इन सब बातों को बदल दिया क्योंकि तकनीकी शिक्षा और अभ्यास राज्य की सत्ता और आर्थिक विकास का अभिन्न अंग बन गए, और उन्होंने इसे उच्च जाति का दर्जा दिया। सुब्रमणियन इस बदलाव के इतिहास का पता लगाते हैं, जिसका चरम बिंदु ब्राह्मणों का इंजीनियरिंग पेशे पर नियंत्रण था। इंजीनियरिंग का उदय औपनिवेशिक प्रथाओं पर आधारित था, जिन्होंने निम्न जाति को उच्च जाति से, शारीरिक श्रम को बौद्धिक श्रम से, और कारीगरी को पेशेवर नौकरियों से अलग किया।
उनके शोध के इस भाग में विवाद की गुंजाइश बहुत कम है। 1813 के ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम में भारतीयों के बीच विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया था, और कंपनी के निदेशकों ने निर्णय लिया कि सामाजिक अभिजात वर्ग के लिए शिक्षा की मौजूदा संस्थागत संरचनाएं यथावत रहेंगी। निर्णायक मोड़ 1823 में आया जब सामाजिक

और धार्मिक सुधारों पर काम करने वाले ब्रह्म समाज के संस्थापक राम मोहन रॉय ने बंगाल के गवर्नर-जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा। रॉय ने कलकत्ता (अब कोलकाता) में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित करने के ब्रिटिश प्रस्ताव की आलोचना की और सरकार से आग्रह किया कि इसके बजाय उन्हें 'अधिक उदार और प्रबुद्ध शिक्षा प्रणाली' को बढ़ावा देना चाहिए। उनका तात्पर्य ब्रिटेन से भारत में वैज्ञानिक चिंतन के हस्तांतरण के लिए अंग्रेजी भाषा की शिक्षा प्रणाली से था। ऐसा करके, रॉय वास्तव में भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंग्रेजीकरण को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने वाले पहले व्यक्ति बन गए।

आरंभ में, अंग्रेजों ने रॉय की बात पर ध्यान नहीं दिया और संस्कृत आधारित शिक्षा जारी रही। लेकिन बाद में, ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों ने रॉय के इस विचार को अपना लिया कि हिंदू ज्ञान पढ़ाना एक मूलभूत त्रुटि है क्योंकि यह निरर्थक और अनुपयोगी है। इससे ब्रिटिश संसद में दो गुटों के बीच बहस छिड़ गई, एक गुट संस्कृत शिक्षा का समर्थक था और दूसरा अंग्रेज़ी शिक्षा का। 1835 में, यह बहस इतिहासकार लॉर्ड थॉमस मैकाले के भारतीय शिक्षा पर प्रसिद्ध लेख में परिणत हुई, जिसके परिणामस्वरूप अंततः भारत की शिक्षा प्रणाली में संस्कृत के स्थान पर अंग्रेज़ी का प्रचलन हुआ। इस क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए मैकाले की बहुत आलोचना की गई है, लेकिन अक्सर यह बात भुला दी जाती है कि मैकाले द्वारा इस विचार को अपनाने से एक दशक पहले ही राम मोहन रॉय ने इस प्रक्रिया को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

इस प्रकार, पारंपरिक शिक्षण प्रणाली की जगह कानून, चिकित्सा और सिविल इंजीनियरिंग में ब्रिटिश प्रशिक्षण ने ले ली। रुड़की में सिविल इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना 1847 में आधुनिक भारत के

पहले इंजीनियरिंग महाविद्यालय के रूप में हुई थी। अंग्रेजों ने अपनी विशिष्ट विभाजनकारी नीति को जारी रखते हुए यह प्रचार किया कि इंजीनियरिंग में व्यावहारिक कार्य आवश्यक है, और इसलिए उच्च जाति के लोग ऐसे कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

उन्होंने एक पदानुक्रमित समाज की अपनी परिकल्पना के अनुरूप, इस विषय को दो-स्तरीय प्रणाली में विभाजित किया। शीर्ष स्तर के लिए, उन्होंने सैद्धांतिक प्रकृति के व्यावसायिक इंजीनियरिंग कार्यक्रम बनाए जो सामाजिक प्रतिष्ठा और अच्छे वेतन वाली नौकरियों का वादा करते थे। इसे एक प्रतिष्ठित, उच्च-स्तरीय पेशे और ब्राह्मणों के लिए कुलीन समाज में प्रवेश करने के मार्ग के रूप में प्रचारित किया गया। इसके परिणामस्वरूप भारतीय महाविद्यालय-शिक्षित इंजीनियरों का एक समूह तैयार हुआ, जिसमें मुख्य रूप से उच्च जाति के ब्राह्मण शामिल थे। दूसरा स्तर उन कारीगरों के लिए बनाया गया जो निम्न जातियों से थे, ताकि उन्हें आधुनिक औद्योगिक विनिर्माण पद्धतियों से प्रशिक्षित किया जा सके। कुछ ब्रिटिश अधिकारियों ने इस कदम का विरोध किया, जबकि अन्य इसके पक्ष में थे। लॉर्ड कर्ज़न, जो 1899-1905 तक भारत के ब्रिटिश वायसराय रहे, जैसे विरोधियों का कहना था कि आधुनिक उद्योग पश्चिमी संस्कृति की नकल है, जबकि भारत के लिए नीतियां पारंपरिक रीति-रिवाजों के प्रति वफादार होनी चाहिए। कई ब्रिटिश अधिकारी औद्योगिक वस्तुओं के निर्माता के रूप में निचली जातियों के कारीगरों को बढ़ावा देना चाहते थे। अंततः दो-स्तरीय दृष्टिकोण को भारतीय जाति व्यवस्था के अनुकूल मानते हुए इस बहस का समाधान किया गया। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ तक, इंजीनियरिंग एक कुलीन वर्ग का क्षेत्र बन गया था, जो ब्रिटिश श्वेत लोगों और कुलीन ब्राह्मणों के बीच संचालित होता था, जबकि निचली जातियां व्यावहारिक कार्य करती थीं।

इस तरह शिल्प कौशल और इंजीनियरिंग एक दूसरे से बिलकुल अलग हो गए, इंजीनियरिंग को उच्च वर्ग का और उच्च जाति के लिए उपयुक्त माना जाने लगा। इंजीनियरिंग शारीरिक श्रम से अलग हो गई, जिसे निचली जातियों के लिए छोड़ दिया गया।

सुब्रमणियन विस्तार से बताते हैं:

19वीं शताब्दी के मध्य से 20वीं शताब्दी के मध्य तक तकनीकी ज्ञान का विकास संघ से राज्य, कारखाने से कक्षा और निम्न जाति से उच्च जाति की ओर बदलाव का दौर रहा है। ये बदलाव साम्राज्यवादी स्तर पर कई प्रक्रियाओं से प्रभावित थे: 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश राजशाही को सत्ता का हस्तांतरण, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंतर-साम्राज्यवादी औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, औपनिवेशिक शासन की लागत को कम करने के प्रयास और अल्पविकास की राष्ट्रवादी आलोचनाएँ।

इस बदलाव ने ब्रिटिश-भारतीय इंजीनियर की पहचान को औपनिवेशिक अभिजात वर्ग के सदस्य के रूप में स्थापित कर दिया, जो उपनिवेश की पदानुक्रम का प्रतीक था। प्रारंभ में, इसका अर्थ नस्लीय विशिष्टता था। लेकिन दोहरे दबावों - इंग्लैंड द्वारा उपनिवेशवाद को 'कम खर्च में' करने के दबाव और ब्रिटेन पर अल्पविकास का आरोप लगाने वाले राष्ट्रवादियों के दबाव - ने नस्लीय बाधाओं को दूर किया और उच्च जातियों को इंजीनियरिंग सेवा में प्रवेश करने का अवसर मिला।

तकनीकी शिक्षा का दो दिशाओं में विकास जातिगत भेदों से प्रभावित था और बदले में, इन भेदों को और भी मजबूत करता था। स्वतंत्रता के आगमन तक, तकनीकी ज्ञान की स्थिति में परिवर्तन आ चुका था; जहाँ इंजीनियरिंग अब उच्च जाति के बौद्धिक आकांक्षाओं का विषय बन गई थी, जो राष्ट्र निर्माण से गहराई से जुड़ी हुई थी, वहीं कारीगरी को एक प्रकार के अकुशल श्रम के रूप में देखा जाने लगा था, जिसे आर्थिक

विकास के लिए बहुत कम उपयोगी माना जाता था।
आगे दिया गया विवरण सुब्रमणियन द्वारा IITs के विकास के इतिहास की व्याख्या का सारांश है। उनके अनुसार, औद्योगिक शिक्षा और कॉलेज इंजीनियरिंग की दो धाराएँ अलग-अलग दिशाओं में चली गईं। तकनीकी कौशल और ज्ञान का समृद्ध इतिहास रखने वाली निचली जातियों को दरकिनार कर उच्च जाति के इंजीनियरिंग क्षेत्र में धकेल दिया गया। इस प्रकार इंजीनियरिंग एक वैचारिक ज्ञान के अनुशासन के रूप में विकसित हुई, जिसमें निचली जातियाँ पीछे छूट गईं।
ब्राह्मण मध्यस्थों ने यह धारणा बनाने में अहम भूमिका निभाई कि ब्राह्मण जन्मजात रूप से अधिक ज्ञानी और नेतृत्व के लिए अभिप्रेत होते हैं। औपनिवेशिक भारत में अधिकांश इंजीनियर उच्च वर्ग से थे। उनमें से बड़ी संख्या में लोग शारीरिक श्रम से घृणा करते थे, फिर भी उन्होंने इंजीनियरिंग को अपनाया क्योंकि इसे ईस्ट इंडिया कंपनी से निकटता के साथ वैचारिक ज्ञान का एक उच्च-स्तरीय पेशा माना जाता था। इससे औपनिवेशिक सिविल सेवाओं और अन्य विशेषाधिकारों तक पहुंचने का त्वरित मार्ग प्रशस्त होता था।
जब जर्मनी ने IIT मद्रास की स्थापना में मदद की पेशकश की, तो IIT में दो-स्तरीय प्रणाली को खत्म करने के लिए एक संक्षिप्त संघर्ष हुआ। जर्मनों ने बताया कि उनके कम से कम आधे तकनीशियन लघु उद्योगों और हस्तशिल्प से आते थे, न कि बड़े पैमाने की परियोजनाओं से। इसलिए, IIT मद्रास ने हस्तकला में व्यावहारिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। लेकिन, सुब्रमणियन के अनुसार, जर्मनों को भारतीयों का रवैया निराशाजनक लगा क्योंकि वे शिल्पकला को उपेक्षित मानते थे। इसका कारण यह था कि औपनिवेशिक काल में, उस समय की प्रशासनिक इकाई, मद्रास प्रेसीडेंसी ने तकनीकी शिक्षा को इस तरह से लागू किया था

जिससे सामाजिक ऊँच-नीच और मजबूत हुई। सुब्रमणियन कहते हैं कि 1921 तक, मद्रास में इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों में लगभग चौहत्तर प्रतिशत ब्राह्मण थे, जबकि उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या केवल तीन प्रतिशत थी।
उनका कहना है कि 1970 के दशक तक, आईआईटी मद्रास में स्थापित व्यावहारिक शिक्षा का जर्मन मॉडल कमजोर पड़ने लगा, जिसका आंशिक कारण आईआईटी के छात्रों का अमेरिका में बड़े पैमाने पर पलायन था, जहाँ इंजीनियरिंग सिद्धांत की अधिक मांग थी। समय के साथ, इससे आईआईटी के छात्र इंजीनियरिंग के मूल पदों से हटकर शिक्षा जगत, प्रबंधन और निजी क्षेत्र की ओर रुख करने लगे।
जातिगत पदानुक्रम में स्तरीकरण तब और भी मजबूत हो गया जब आईआईटी ने कंप्यूटर विज्ञान जैसे सैद्धांतिक क्षेत्रों में खुद को अलग पहचान दिलाने का फैसला किया।
सुब्रमणियन द्वारा ऊपर संक्षेप में दिए गए ऐतिहासिक विवरण के अधिकांश भाग से हम सहमत हैं। अब हम उनके इस तर्क पर विचार करते हैं कि उच्च जातियाँ योग्यता की आड़ में चतुराई से अपने जातिगत विशेषाधिकारों को छुपाती हैं।

योग्यता को सांस्कृतिक पूंजी का एक रूप माना जाता है

अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए, वह फ्रांसीसी मार्क्सवादी और समाजशास्त्री पियरे बॉर्डियू द्वारा प्रतिपादित सांस्कृतिक पूंजी के विचारों का सहारा लेती हैं और उन्हें भारतीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और गणित (एसटीईएम) शिक्षा के संदर्भ में लागू करती हैं। बॉर्डियू विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक पूंजी के सिद्धांत के माध्यम से मार्क्सवाद को व्यापक रूप देने के लिए प्रसिद्ध हुए। मार्क्सवाद की आर्थिक पूंजी की अवधारणा के

अलावा, सांस्कृतिक पूंजी भी होती है, जिसे बॉर्डियू 'समाज के भीतर वैध संस्कृति से परिचित होना' के रूप में परिभाषित करते हैं। यह पूंजी 'उच्च संस्कृति' मानी जाने वाली चीजों को संचित करने से संबंधित है और इसमें किसी सामाजिक समूह के सदस्यों द्वारा अर्जित कौशल, शिक्षा, मानदंड और व्यवहार शामिल हैं जो उन्हें दूसरों पर लाभ प्रदान करते हैं। शासक वर्ग के मानदंडों के अनुसार सुसंस्कृत माना जाना एक प्रकार की पूंजी बन जाती है जिसका उपयोग किया जा सकता है।

बोर्डियू ने सांस्कृतिक पूंजी के तीन प्रकारों की पहचान की है:

ए. शारीरिक पूंजी: किसी व्यक्ति के शरीर में शारीरिक रूप से अंतर्निहित विशेष प्रतिभाएं, जैसे गाना गाना, एक विशेष उच्चारण होना, गणित जानना या कोई खेल खेलना।

बी. वस्तुनिष्ठ पूंजी: व्यक्ति से भौतिक रूप से अलग, जैसे कि व्यक्ति द्वारा निर्मित बौद्धिक संपदा, लेकिन जिसका अपना अलग अस्तित्व होता है और जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है।

सी. संस्थागत पूंजी: सांस्कृतिक पूंजी के उत्पादन और पुनरुत्पादन के साधन, जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, हॉलीवुड, अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) प्रयोगशालाएं।

सांस्कृतिक पूंजी का मूल्य समाज के अनुसार अलग-अलग होता है। एक समाज में जिसका बहुत महत्व हो, वही मूल्य दूसरे समाज में कम या नगण्य भी हो सकता है। सांस्कृतिक पूंजी का संचय सामाजिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। व्यक्ति प्रमाण-पत्र, प्रतिष्ठा, संबंध और नेटवर्किंग संपर्क जैसी सांस्कृतिक संपत्तियों का संचय कर सकता है। किसी व्यक्ति का पारिवारिक इतिहास और सामाजिक वर्ग भी सांस्कृतिक पूंजी का अभिन्न अंग हैं।

जहां 'ए' प्रकार की सांस्कृतिक पूंजी किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित

नहीं की जा सकती, वहीं 'बी' प्रकार की पूंजी अन्य प्रकार की पूंजी की तरह हस्तांतरित की जा सकती है। यह सत्ता को धारण करने और हस्तांतरित करने तथा सामाजिक पदानुक्रम को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। 'सी' प्रकार की सांस्कृतिक पूंजी के एकाधिकार की संभावना कहीं अधिक होती है क्योंकि इसका स्वामी संचित सांस्कृतिक पूंजी का उत्पादन और वितरण नियंत्रित कर सकता है।

हमारी वर्तमान चर्चा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षणिक योग्यताएं सांस्कृतिक पूंजी का एक रूप हैं।

सुब्रमणियन का मुख्य बिंदु यह दावा है कि:

आईआईटी में प्राप्त शैक्षणिक योग्यताएं एक प्रकार की सांस्कृतिक पूंजी हैं, जिसके पूंजीपति उच्च जातियां हैं; और

इस प्रकार की पूंजी को योग्यता माना जाता है क्योंकि यह वस्तुनिष्ठ, स्वायत्त और एक वास्तविक प्रकार की क्षमता प्रतीत होती है।

संक्षेप में, सुब्रमणियन भारत में इंजीनियरिंग शिक्षा के इतिहास का उपयोग यह दावा करने के लिए करती हैं कि यह एक प्रकार की सांस्कृतिक पूंजी बन गई है। और योग्यता जाति-आधारित विशेषाधिकारों को छिपाने और प्रतिस्थापित करने के लिए एक सार्वजनिक पहचान चिह्न के रूप में कार्य करती है। भारत भर में उच्च जातियाँ योग्यता को एक सामूहिक जातिगत विशेषता के रूप में अपनाती हैं ताकि वे निम्न जातियों से खुद को अलग कर सकें। वह जोर देकर कहती हैं कि इस प्रकार, योग्यता जातिगत पहचान का वस्तुकरण करने का एक तरीका बन गई है। उनका दावा है कि योग्यता का दुरुपयोग उच्च जाति की पूंजीवादी व्यवस्था को कायम रखने की साजिश है। यही कारण है कि आईआईटी के छात्र एकजुट होकर समतावादी समाज के उदय को रोकने का प्रयास करते हैं,

क्योंकि इससे उनके सांस्कृतिक पूंजीगत लाभ समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने इस संस्थागत ढांचे को ध्वस्त करने और इस सांस्कृतिक पूंजी द्वारा शोषित निम्न वर्गों को मुक्त कराने का दायित्व अपने कंधों पर लिया है। सुब्रमणियन कहती हैं कि ब्राह्मण प्रौद्योगिकी समुदाय अपनी सफलता को सांस्कृतिक पूंजी के रूप में प्रस्तुत करना पसंद करता है, जो शिक्षा के प्रति आनुवंशिक झुकाव और उद्यमशीलता की पूर्वनिर्धारित क्षमता पर आधारित है। वह बताती हैं कि पहले के अभिजात वर्ग के विपरीत, जिनकी पूंजी अचल भूमि के रूप में थी, योग्यता, जातिगत विशेषाधिकार और प्रतिष्ठित संबद्धता पर आधारित अभिजात वर्ग का नया रूप अत्यधिक गतिशील और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विपणन योग्य है। इसलिए योग्यता ही नई मुद्रा है। IIT केंद्रीय बैंकों के समान हैं और इस मुद्रा को छापते हैं। जिस प्रकार लोग आर्थिक पूंजी के लिए युद्ध करते हैं, उसी प्रकार सांस्कृतिक पूंजी को भी चुनौती दी जा सकती है। उनका दावा है कि जब निचली जातियों ने संस्थागत संरचनाओं को धमकाने के लिए वोट बैंक की राजनीति का इस्तेमाल किया, तो उच्च जातियों ने आगे रहने के लिए योग्यता पर और भी अधिक भरोसा करना शुरू कर दिया।
लोकतंत्र – एक विचारधारा और राजनीतिक दावे करने के लिए संरचनाओं के एक समूह के रूप में – हाशिए पर रहने वाले लोगों की राजनीति को यथास्थिति को चुनौती देने के लिए एक आधार प्रदान करता है। परिणामस्वरूप, असमानता की संरचनाएं स्वतः पुनरुत्पादित नहीं होतीं। बल्कि, उच्च जाति द्वारा योग्यता का दावा करना, निम्न जाति के दावे के विरुद्ध चल रहे राजनीतिक दांव-पेच के युद्ध का प्रतीक है।
हम उनके शोध प्रबंध को समझते हैं, लेकिन निम्नलिखित मुद्दों को उठाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, हम इसी तरह का तर्क देते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में। हमने पहले भी यह तर्क दिया है कि 'आलोचनात्मक

सिद्धांतों' का निर्माण, और सामान्य रूप से सामाजिक विज्ञान के सिद्धांत, स्वयं ही विशेषाधिकारों की एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें छिपी हुई संरचनाएं हैं। यह तर्क लगभग दो दशक पहले एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक बहस - पीयर-रिव्यू कार्टेल - के दौरान दिया गया था। हमने यह तर्क दिया था कि सुब्रमण्यम जैसे विद्वान उदार कलाओं में सांस्कृतिक पूंजीपति हैं क्योंकि उनकी संस्थागत स्थिति उन्हें ऐसे विशेष विशेषाधिकार देती है जिनके वे हकदार नहीं हैं। उस बहस का निम्नलिखित अंश इस बिंदु को संक्षेप में प्रस्तुत करता है:

सहकर्मी समीक्षा प्रक्रिया की प्रकृति एक ज्ञान उत्पादन गिरोह का निर्माण कर रही है जो पश्चिमी अकादमिक जगत को ज्ञान उत्पादन के साधनों पर नव-औपनिवेशिक नियंत्रण प्रदान करती है। अभिजात वर्ग के गिरोह से बाहर की किसी भी आलोचना को (विशेषकर यदि उसे पर्याप्त गंभीर खतरा माना जाए) सहकर्मी समीक्षा को रामबाण बताकर दरकिनार कर दिया जाता है। पश्चिमी नियंत्रित उदार कला बौद्धिक तंत्र के सबसे प्रिय मिथकों में से एक यह है कि उसकी सहकर्मी समीक्षा एक निष्पक्ष प्रणाली है। उनकी विद्वत्ता पर हमारी आलोचनाओं को अवैध माना जाता है क्योंकि उनके लेखन की सहकर्मी समीक्षा हो चुकी है। ... हमारी सभी प्रतिक्रियाओं को उन पर 'हमला' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, न कि निष्पक्ष आलोचना के रूप में, क्योंकि ये सहकर्मी समीक्षा गिरोह के भीतर से नहीं आती हैं। ... जिन्हें उनके अकादमिक संघ द्वारा लाइसेंस प्राप्त नहीं है, उन्हें उनके विचारों के विरुद्ध तर्क देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, और निश्चित रूप से समान भागीदार के रूप में तो बिल्कुल नहीं। यह रवैया अकादमिक चर्चा में एक बड़ी समस्या का हिस्सा है, विशेषकर मानवशास्त्र, समाजशास्त्र और धर्म के अध्ययन में, जहाँ यह मान लिया जाता है कि (i) गैर-अकादमिक व्यक्ति को केवल एक जानकार

सूचनादाता के रूप में ही देखा जा सकता है, और (ii) जानकार सूचनादाता को पलटवार नहीं करना चाहिए। इससे औसत दर्जे के विद्वानों को एकजुट होने और 'हम विद्वान' और 'आप अज्ञानी उपभोक्ता' के बीच विभाजन को उजागर करने का अवसर मिलता है। स्पष्ट रूप से, सहकर्मी-समीक्षा प्रक्रिया ने अत्यधिक प्रतीकात्मक महत्व प्राप्त कर लिया है। अकादमिक जगत की यह खामी इसे अत्यंत आवश्यक आत्म-चिंतन से रोकती है।

दरअसल, कई शिक्षाविदों का मानना है कि अकादमिक जगत में किसी प्रभावशाली संरक्षक के बिना, केवल योग्यता के बल पर प्रकाशन करना और आगे बढ़ना मुश्किल है। मानविकी और उदार कलाओं में 'अकादमिक सत्य' अक्सर निरर्थक बातों, झूठे सबूतों और राजनीतिक एवं भावनात्मक रूप से आवेशित बयानबाजी का एक मुखौटा होता है। मार्क्सवाद के समय से ही, आलोचनात्मक सिद्धांत राजनीतिक विचारधाराओं से घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहा है। उच्च शिक्षा स्वीकृत सिद्धांतों के भंडार से चुनकर या उन्हें मिलाकर किसी भी उद्देश्य के लिए एक कृत्रिम तर्क तैयार करना सिखाती है।

उदार कलाओं के समर्थक गर्व से दावा करते हैं कि वे अब साहित्य, कला या संस्कृति का अध्ययन स्वयं में नहीं करते; बल्कि, ये उपयुक्त 'सिद्धांतों' के माध्यम से संसाधित किए जाने वाले 'विषय' हैं। इससे विशिष्ट 'सिद्धांतों' का वैधीकरण और प्रचार एक गंभीर मुद्दा बन जाता है क्योंकि जो सिद्धांतों को नियंत्रित करता है, वही विमर्श को नियंत्रित करता है। इससे निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं: बाज़ार में उपलब्ध सिद्धांतों में से कौन से सिद्धांत विद्वतापूर्ण उपयोग के लिए स्वीकृत टूलबॉक्स में शामिल होंगे, यह तय करने की शक्ति किसके पास है और किस अधिकार से है? लोकप्रियता (प्रचलन, धन और शक्तिशाली समर्थन के कारण) किस हद

तक प्रमुख मानदंड है? क्या यह एक दुष्चक्र का संकेत देता है, जिसमें बुद्धिजीवियों के समरूप समूह द्वारा किसी सिद्धांत का उपयोग उस सिद्धांत को बढ़ावा देता है और उसे बाज़ार में हिस्सेदारी हासिल करने में मदद करता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें योग्यता के अनुरूप मूल्य नहीं दिया जाता? अकादमिक कार्टेल, किसी भी ट्रेड यूनियन की तरह, यह तय करता है कि किन सिद्धांतों को स्वीकृति दी जाएगी।

इससे यह बात स्पष्ट होती है कि सुब्रमणियन का अपना हार्वर्ड विश्वविद्यालय भी निम्नलिखित बातों का दोषी है: प्रमाणपत्र प्रदान करके और अपने नाम के बल पर ही, यह अपने छात्रों और शिक्षकों को दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पूंजी में से एक प्रदान करता है। यह विश्वविद्यालय भी इसे योग्यता मात्र बताता है। उदाहरण के लिए, प्रतिष्ठित हार्वर्ड बिजनेस स्कूल कार्यक्रम यह दावा करता है कि इसके कुलीन पूर्व छात्रों के माध्यम से मिलने वाला नेटवर्किंग नेटवर्क इसके स्नातकों के लिए जीवन भर की सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक है। जब छात्र हार्वर्ड में प्रवेश करते हैं, तो वे एक ऐसे वैश्विक नेटवर्किंग क्लब का हिस्सा बन जाते हैं जो एक-दूसरे का ख्याल रखता है। हार्वर्ड के उच्चवर्गीय समुदाय की सदस्यता निश्चित रूप से अभिजात्य वर्ग के लिए है।

हार्वर्ड में सांस्कृतिक पूंजी के निर्माण के कई अन्य संस्थागत तंत्रों को गिनाया जा सकता है: गुट द्वारा नियंत्रित प्रतिष्ठित पीयर-रिव्यू पत्रिकाएँ; विश्वसनीयता का अनुचित लाभ उठाने के लिए सुब्रमणियन द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की तरह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का उपयोग; और स्थायी पद प्राप्त करने की अत्यधिक राजनीतिक प्रक्रिया। भाग 2 भारत के विरुद्ध सांस्कृतिक पूंजी विकास के गठजोड़ के रूप में हार्वर्ड की अनेक संस्थाओं को उजागर करने के लिए समर्पित है।

सुब्रमणियन हार्वर्ड द्वारा योग्यता पर दिए जाने वाले बल को एक प्रकार का छिपा हुआ पूर्वाग्रह मानती हैं। उनका सुझाव है कि छात्रों का 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व' होना चाहिए और प्रवेश प्रक्रिया 'समाज का दर्पण' होनी चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि ये बदलाव हार्वर्ड की पूंजी को और बढ़ा देंगे। वास्तव में, इससे हार्वर्ड के अभिजात वर्ग को शक्ति मिलेगी, क्योंकि वे हाशिए पर पड़े लोगों को चुनकर प्रवेश देंगे और फिर उन्हें अपने पसंदीदा सिद्धांतों से प्रभावित करेंगे। क्या इन सब का विश्लेषण करने के लिए एक आलोचनात्मक हार्वर्ड सिद्धांत की आवश्यकता है?

अमेरिकी संस्थानों का इतिहास वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने का रहा है। अमेरिकी आव्रजन कानून कला, विज्ञान, शिक्षा, व्यवसाय के साथ-साथ उच्च उपाधि प्राप्त उत्कृष्ट प्रोफेसरों और शोधकर्ताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। सुब्रमणियन इन सभी क्षेत्रों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व लाने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन क्या वह हार्वर्ड और अन्य सभी प्रमुख अमेरिकी खेलों की टीमों में भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग करेंगी? क्या वह ओलंपिक खेलों, ऑस्कर, नोबेल पुरस्कार और अन्य पुरस्कारों जैसे सभी प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में मुकदमा चलाकर उन्हें योग्यता के स्थान पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व लागू करने के लिए मजबूर करेंगी ताकि समाज का प्रतिबिंब प्रदर्शित हो सके?

सुब्रमणियन द्वारा उपेक्षित सांस्कृतिक पूंजीवाद की एक अन्य व्यापक प्रणाली यह है कि दक्षिण एशिया में मुसलमान अपने समाज में मूल्यवान माने जाने वाले सांस्कृतिक गुणों को अपनाकर इस्लाम की सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ते हैं। इसमें दाढ़ी बढ़ाना, सही उच्चारण के साथ उर्दू बोलना, हलाल प्रथाओं को बढ़ावा देना, शारीरिक हावभाव और व्यवहार में अति-पुरुषत्व का प्रदर्शन करना आदि शामिल हैं। ये मुसलमानों की अशरफ

जाति, यानी उनकी सर्वोच्च जाति की पहचान हैं। ऐसे विषय सुब्रमणियन के लिए राजनीतिक रूप से अनुचित होंगे, जो आमतौर पर अपने विचारों को उत्तेजक तरीके से व्यक्त करती हैं। उन्हें अध्याय 6 में संक्षेप में वर्णित मुस्लिम अभिजात्यवाद पर अंबेडकर की आलोचना पर ध्यान देना चाहिए।

प्रवेश परीक्षाएं जातिगत विशेषाधिकारों को छुपाती हैं

भारत के युवाओं द्वारा आईआईटी में प्रवेश परीक्षा को आधुनिक योग्यता प्रणाली का सबसे मानक, वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मापक माना जाता है। लेकिन सुब्रमणियन का कहना है कि अंतर्निहित सामाजिक और सांस्कृतिक पूंजी संरचनाओं को पर्याप्त रूप से ध्वस्त नहीं किया गया है। उनका मानना है कि आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक कारक हैं जो इस परीक्षा को निचली जातियों के लिए अनुचित बनाते हैं। इसलिए, वे इंजीनियरिंग पेशे में सफल नहीं हो पाते हैं।

वह इस बात को साबित करने के लिए कोई ठोस उदाहरण या तर्क नहीं दे पाती कि परीक्षा कुछ जातियों को दूसरों से अधिक विशेषाधिकार देती है। वह केवल स्वयं को 'पीड़ित' बताने वाले लोगों के कई साक्षात्कारों का हवाला देती है और उनमें से कुछ चुनिंदा किस्से चुनकर अपने सिद्धांत का समर्थन करती है। वह बार-बार दावा करती है कि वह दलितों की आवाज़ है, उनकी वाणी है। लेकिन यह मानवविज्ञान का एक आम तरीका है और इस तरह की कार्यप्रणाली में कुछ भी वैज्ञानिक नहीं है।

सुब्रमणियन का तर्क खोखला है क्योंकि वह केवल बॉर्डियू के कथन का हवाला देती हैं, जिन्होंने कहा था कि प्रतिष्ठित परीक्षाएं और उच्च शिक्षा प्रणाली पुरानी सामाजिक व्यवस्थाओं के पुनरुत्पादन की गारंटी देती हैं। फिर वह यह मानकर चलती हैं कि बॉर्डियू के दृष्टिकोण से भारत को देखते हुए उन्होंने यह साबित कर दिया है कि IIT परीक्षा और पाठ्यक्रम भारत

में भी जातिगत व्यवस्थाओं को पुनर्जीवित कर रहे हैं। उनका रवैया निचली जातियों के प्रति तिरस्कारपूर्ण है, जिसका अर्थ है कि उनमें योग्यता की कमी है और किसी भी प्रकार की योग्यता प्रणाली उनके विरुद्ध एक षड्यंत्र है। उनका मूल तात्पर्य यह है कि निचली जातियां समान अवसर मिलने पर भी योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकतीं।

एक मजबूत तर्क यह होगा कि निचली जातियों को प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से तैयार नहीं किया गया क्योंकि ब्रिटिश काल में आम जनता के लिए कोई सार्वभौमिक शिक्षा नीति नहीं थी। यह स्थिति स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू (स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री) और इंदिरा गांधी (भारत की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली प्रधानमंत्री) के नेतृत्व में भी जारी रही। इसलिए, जब ये युवा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का प्रयास करते हैं, तब तक वे पहले से ही पिछड़ चुके होते हैं। यह उपनिवेशवाद और उसके बाद नेहरू युग में जारी रहे अभिजात्यवाद के कारण उत्पन्न एक धर्मनिरपेक्ष समस्या है।

सुब्रमणियन भारत की उच्च स्तरीय सरकारी सेवाओं में उम्मीदवारों को प्रवेश देने वाली संघ लोक सेवा आयोग (यूएन) परीक्षा की भी आलोचना करती हैं, उनका आरोप है कि इसमें अभिजात्यवादी संरचनाएं शामिल हैं। हालांकि, इस परीक्षा में सामाजिक विज्ञान का भी व्यापक महत्व है, और भारत में पढ़ाया जाने वाला सामाजिक विज्ञान पूरी तरह से पश्चिम से आयातित है। उन्हीं की और हार्वर्ड जैसे संस्थानों में उनके जैसी अन्य विद्वानों की, जो स्वयं पश्चिमी सामाजिक विज्ञान की उपज हैं, ने भारत में इन अभिजात्यवादी संरचनाओं का निर्माण किया है।

प्रवेश परीक्षाओं का विरोध करने का मूल कारण क्रिटिकल रेस थ्योरी के उस सिद्धांत को अपनाना है जो समानता के बजाय निष्पक्षता को प्राथमिकता देता है। जैसा कि अध्याय 1 में बताया गया है, इसका अर्थ है

समान अवसरों के बजाय समान परिणामों की वकालत करना। इस दृष्टिकोण में वंचित छात्रों को बेहतर ढंग से तैयार करने और उन्हें सर्वश्रेष्ठ छात्रों के बराबर प्रदर्शन करने में मदद करने के लिए संस्थानों को तैयार करने पर कम जोर दिया जाता है। इसमें यह अंतर्निहित धारणा है कि वंचित लोग सीखने में असमर्थ हैं, और इसलिए परिणामों को समाज की संरचना के अनुरूप संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए। उनके अनुसार, एक निष्पक्ष प्रवेश नीति मुख्य रूप से प्रत्येक छात्र के इतिहास और पहचान पर केंद्रित होगी और किसी विशेष क्षेत्र में उनकी योग्यता पर विचार नहीं करेगी।

पुरुष प्रधान पूंजीवाद में योग्यता

सुब्रमणियन के प्रमुख आरोपों में से एक यह है कि IIT के अधिकांश छात्र पुरुष हैं। वह आगे दावा करती हैं कि परिसरों में पुरुषों के बीच घनिष्ठ संबंध हिंदू परिवार के भीतर पुरुष संबंधों द्वारा पूर्वनिर्धारित थे। दूसरे शब्दों में, परिवारों में हिंदू पुरुष प्रधान व्यवस्था इंजीनियरिंग पेशे में मर्दाना गुण लाती है। हालांकि, ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि अमेरिका में भी STEM शिक्षा पुरुष प्रधान है और इसलिए यह केवल हिंदू समाजों तक ही सीमित नहीं है। हमारा मानना है कि STEM को सभी लिंगों और पहचानों के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कुछ समूहों के खराब प्रदर्शन का समाधान किसी सुविधाजनक बलि का बकरा बनाने के गलत निदान पर आधारित नहीं होना चाहिए। सुब्रमणियन इस तथ्य को भी नजरअंदाज करती हैं कि भारत STEM शिक्षा में विश्व में सबसे अधिक महिलाएँ पैदा करता है।

IIT छात्रों के बीच संस्थागत रिश्तेदारी और ब्रांड विकास को जातिवादी

माना जाता है

सुब्रमणियन को यह बात असामान्य लगती है कि आईआईटी के छात्र एक-दूसरे का समर्थन करते हैं और उन्हें इस बात से परेशानी होती है कि उनका ब्रांड एक प्रकार की सांस्कृतिक पूंजी बन रहा है।

उच्च जाति के बहुसंख्यक IIT छात्रों के बीच संस्थागत संबंध एक और भी अधिक शक्तिशाली पूंजी का रूप ले चुका है। प्रवासी IIT छात्र अपने प्रभावी संबंधों को बनाए रखने और मजबूत करने तथा IIT की प्रतिष्ठा को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त ब्रांड बनाने के प्रयासों में अग्रणी रहे हैं। इस ब्रांडिंग के अधिकांश कार्य सिलिकॉन वैली में रहने वाले IIT छात्रों द्वारा संचालित किए गए हैं, जिनके लिए उद्यमशीलता की सफलता ने स्वयं-निर्मित व्यक्ति होने की उनकी भावना को और भी मजबूत किया है। हालांकि, अपने सदस्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना प्रत्येक विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ का मूल स्वभाव है। वह इस संबंध में आईआईटी की सफलता से असंतुष्ट हैं:

सिलिकॉन वैली के IITian भारतीय तकनीकी पेशेवरों को वैश्विक स्तर पर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में तुरंत पहचान दिलाने के लिए पेशेवर नेटवर्किंग और छवि निर्माण में अग्रणी रहे हैं। उनके संबद्धता और अनुभव का नेटवर्क भारतीय तकनीकी योग्यता के आधार को और मजबूत करता है, जबकि जातिगत पहचान लगभग गायब हो जाती है।

यह स्पष्ट नहीं है कि जाति का इस तथ्य से क्या संबंध है कि आईआईटी के पूर्व छात्र, अन्य सभी पूर्व छात्रों की तरह, अपना प्रचार करते हैं, अपनी छवि बनाते हैं और वैश्विक स्तर पर एक-दूसरे की मदद करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अन्य संस्थानों में होता है। नेटवर्किंग किसी भी छात्र समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ और आकांक्षा है; एक अमूर्त लाभ। यह किसी भी आधुनिक शिक्षा प्रणाली की अंतर्निहित विशेषता है और इस तरह की

किसी भी आलोचना का दोष पश्चिमी शिक्षा प्रणाली पर ही है, न कि चुनिंदा रूप से भारतीयों या हिंदुओं पर।

सुब्रमणियन ने 1992 में सिलिकॉन वैली में मुख्य रूप से IIT के छात्रों द्वारा स्थापित समूह, टीआईई (द इंडस एंटरप्रेन्योर्स) पर भी कटाक्ष किया है। द इंडस एंटरप्रेन्योर्स का विस्तार विश्व स्तर पर कई देशों में शाखाओं के साथ हुआ है। यह तकनीकी उद्यमियों, वेंचर कैपिटलिस्टों, कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच नेटवर्किंग के लिए एक गैर-लाभकारी संगठन है। ऐसे संगठन व्यवसाय, चिकित्सा, आतिथ्य उद्योग, कानूनी पेशे और यहां तक कि मानव विज्ञान (जो उनका अपना क्षेत्र है) में भी मौजूद हैं। अगर भारतीयों ने प्रौद्योगिकीविदों के लिए विश्व का प्रमुख पेशेवर संघ बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है।

सुब्रमणियन इस बात से भी चिंतित हैं कि कई भारतीय सिलिकॉन वैली की कंपनियों के मालिक हैं और एंजेल निवेशक हैं जो समान पृष्ठभूमि वाले लोगों को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन यह सभी पेशों में एक आम चलन है: लोग किसी न किसी पहचान के आधार पर एक ही विश्वविद्यालय, गांव या अन्य संबद्धता वाले लोगों को प्राथमिकता देते हैं। वास्तव में, विविधता के समर्थक अल्पसंख्यक समुदायों को ऐसे औपचारिक और अनौपचारिक नेटवर्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि श्वेत अभिजात वर्ग के पारंपरिक नेटवर्कों पर एकाधिकार को तोड़ा जा सके। टीआईई जैसे संगठनों से जुड़ना और निचली जातियों को इसी तरह के नेटवर्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना परस्पर विरोधी नहीं हैं।

उन्हें इस बात से और भी ज़्यादा ठेस पहुँचती है कि सिलिकॉन वैली के IIT छात्रों ने पैन-IIT एलुमनाई एसोसिएशन बनाया है, जो दुनिया भर में फैल चुका है। वह मानती हैं कि यह हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल नेटवर्क के समान है, लेकिन वह न तो हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल नेटवर्क की और न ही

हार्वर्ड कैनेडी स्कूल ऑफ़ गवर्नमेंट नेटवर्क की इतनी कड़ी आलोचना करती हैं। उन पर हमला करना उनके आइवी लीग करियर के लिए जोखिम भरा हो सकता है।

उनके निशाने पर कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने IIT ब्रांड को बढ़ावा दिया है। इनमें विनोद खोसला, प्रसिद्ध वेंचर कैपिटलिस्ट और सन माइक्रोसिस्टम्स के सह-संस्थापक, एन.आर. नारायण मूर्ति, इंफोसिस के संस्थापक और कई अन्य शामिल हैं। वह बताती हैं कि अमेरिका के पूर्व और वर्तमान राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और जो बाइडेन ने भी IIT के छात्रों की प्रशंसा की है, साथ ही बिल गेट्स (माइक्रोसॉफ्ट के), जेफ बेजोस (अमेज़ॅन के) और नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने भी। वह IIT की सफलता से नाराज हैं: 'इस बयानबाजी के शोरगुल में IIT के निर्माण में निहित वंशानुगत जातिगत पूंजी और राज्य संरक्षण के स्वरूप खो गए हैं।'

अमेरिका में रहने वाला पटेल समुदाय होटल व्यवसाय में एक-दूसरे की मदद करने के लिए जाना जाता है। न्यू जर्सी में सिख समुदाय के पास अधिकांश पेट्रोल पंप हैं; वे एक-दूसरे को प्रशिक्षण देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और व्यवसाय में आने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। इसी तरह, कोरियाई समुदाय के पास अधिकांश लॉन्ड्री हैं। यह अमेरिकी समाज की एक सच्चाई है: जब लोग किसी देश से पलायन करते हैं, तो वे एक साथ रहते हैं और किसी विशेष क्षेत्र में पेशेवर रूप से विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं। इसी तरह, आईआईटी स्नातकों का एक-दूसरे का समर्थन करना कोई असामान्य बात नहीं है, भले ही कुछ कारणों से वे सिद्ध योग्यता प्राप्त तमिल ब्राह्मण हों। सुब्रमणियन इसे 'संस्थागत रिश्तेदारी' कहते हैं और इसे दुनिया भर के नियोक्ताओं के बीच आईआईटी को अधिक आकर्षक बनाने के लिए ब्राह्मणों की साजिश मानते हैं। सच्चाई यह है कि भारत का आउटसोर्सिंग उद्योग अपने लोगों का विपणन करना

चाहता है, और अपने ग्राहकों के सामने एक सकारात्मक छवि प्रस्तुत करना एक अच्छी व्यावसायिक रणनीति है।

सुब्रमणियन का कहना है कि IIT के छात्रों के साथ भारत के क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों की तुलना में बहुत अलग व्यवहार किया जाता है, जो समाज के निचले तबके के छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं। उनके लिए यह एक चिंता का विषय है कि IIT को योग्यता का मानक माना जाता है। वह बताती हैं कि गांधीजी की विचारधारा के कई अनुयायियों ने शुरू में IIT को अभिजात्य वर्ग का संस्थान माना था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा भी विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ क्योंकि वह अभिजात्य वर्ग का संस्थान था और सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना उच्चतम स्तर की प्रतिभाओं को चुनता था।

उनकी चिंता का एक और विषय प्रवासी उद्यमियों की सफलता है, क्योंकि यह भारतीयों के लिए गर्व का विषय बन गया है। उनका कहना है कि सिलिकॉन वैली में IIT के छात्र खुद को 'नवउदारवादी पूंजीपति' समझने लगे हैं। लेकिन यह उस वैश्विक पूंजीवादी समाज का मूल स्वभाव है जिसमें हम रहते हैं; यह मुक्त उद्यम की प्रकृति और संरचना है और इसका ब्राह्मण होने, IIT के छात्र होने या जाति से कोई लेना-देना नहीं है।

वह भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के अल्पविकास और भारत में स्थित इंजीनियरों की कम उपलब्धि की आलोचना करने वाले IIT छात्रों से नाराज़ हैं। लेकिन भारतीय इंजीनियरों की आलोचना करने का एकमात्र अधिकार उन्हीं को क्यों होना चाहिए? इस समस्या पर अन्य लोग अपना शोध क्यों नहीं विकसित कर सकते? वास्तव में, भारत में इंजीनियरिंग शिक्षा संबंधी नीतियों की सिफारिश करने के लिए IIT छात्र एक मानवविज्ञानी से कहीं अधिक योग्य हैं।

हमने भी भारत की उन नीतियों की आलोचना की है जिनमें वह अपने इंजीनियरों का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा तरीका अलग है: हमारी आलोचना यह है कि भारत मूल रूप से अपने इंजीनियरों को कच्चे श्रम के रूप में बेच रहा है और कुछ अरबपतियों को और भी अमीर बना रहा है, जबकि उत्पादित तकनीक एक विदेशी ग्राहक की है जो बाद में इसे भारत को लाइसेंस पर दे देता है।
उनके संपूर्ण लेखन में भारतीय अमेरिकी प्रौद्योगिकीविदों की उपलब्धियों के प्रति उनकी अवमानना स्पष्ट रूप से झलकती है।

सिलिकॉन वैली पर हमला
सुब्रमणियन का लक्ष्य नस्लीय तनाव के संवेदनशील अमेरिकी परिदृश्य में दरार पैदा करना है, जिसके लिए वह एक अल्पसंख्यक समूह को दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहती हैं। वह लिखती हैं:
… संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसे लोग जो वास्तव में IIT की प्रतिष्ठा बढ़ाने और तकनीकी रूप से उन्नत भारतीय की छवि गढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वे भारत की राजनीति में भी सक्रिय हैं। वे भारत में कुछ खास तरह के उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हैं, कभी IIT के माध्यम से, तो अक्सर अन्य तरीकों से… उनमें से कुछ सलाहकार हैं… और वे वास्तव में आर्थिक और कानूनी परिवर्तन के कुछ ऐसे रूपों में निवेशित हैं जो अधिक निर्बाध विदेशी निवेश और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के अधिक उदारीकरण की अनुमति देते हैं। यह एक ऐसी परियोजना है जिसका ध्यान विशेष रूप से अमेरिका पर केंद्रित है, लेकिन इसका एक अंतरराष्ट्रीय आयाम भी है। आदर्श अल्पसंख्यक होने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आप असाधारण हैं और… अन्य कम सफल अल्पसंख्यकों के लिए एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

... आपकी सफलता को अन्य अल्पसंख्यकों के मुकाबले इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि एशियाई अमेरिकियों को प्राप्त होने वाली जाति और वर्ग पूंजी के रूपों को पूरी तरह से छिपा दिया जाता है।
वह इक्वालिटी लैब्स की प्रबल समर्थक हैं, जिसने जातिगत भेदभाव के आरोपों को लेकर सिस्को के खिलाफ हालिया मामले को तैयार करने में मदद की। वह लिखती हैं कि 'जाति एक गतिशील श्रेणी है' और सामाजिक और सांस्कृतिक पूंजी के रूप में जातिगत विशेषाधिकार एक 'स्थानांतरणीय पूंजी' है जिसे भारतीय अमेरिका लेकर आए हैं।
वह अमेरिकी कॉरपोरेट जगत में जाति व्यवस्था के जीवित रहने के बारे में खुलकर अपनी राय व्यक्त करती हैं, और क्रिटिकल रेस थ्योरी की प्रतिध्वनि करते हुए कहती हैं कि सभी जातियों के प्रति तटस्थता की नीति जातिगत विशेषाधिकार की रक्षा करती है।
यह कोई संयोग नहीं है कि दक्षिण एशियाई-अमेरिकी लोगों का एक बड़ा हिस्सा विशेषाधिकार प्राप्त जातिगत पृष्ठभूमि से आता है। ... यदि कोई जातिगत पहचान को नहीं मानता, तब भी वह जातिगत विशेषाधिकार का लाभार्थी होता है। इसलिए जाति यहाँ है, रही है और रहेगी। अतः हमें वास्तव में इसका सामना करना होगा, न कि यह दिखावा करना कि यह अस्तित्वहीन है।
विडंबना यह है कि भारत में आरक्षण नीतियों के कारण उच्च जाति के कई लोग पश्चिमी देशों में प्रवास कर चुके हैं, क्योंकि इन नीतियों के चलते अन्य जातियों और पृष्ठभूमियों की तुलना में उनके लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाना बहुत कठिन हो गया है। लेखिका का कहना है कि उच्च जाति के भारतीय प्रवासियों की सफलता उनकी अपनी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि भारत से हस्तांतरित सामाजिक पूंजी के रूप में जाति की सफलता का परिणाम है। वह भारतीय अमेरिकियों पर इस उच्च जाति

पूंजी को संरक्षित रखने का आरोप लगाती हैं, लेकिन इस तथ्य को स्वीकार करने में विफल रहती हैं कि अधिकांश भारतीय अमेरिकी स्वयं को किसी विशेष जाति से नहीं जोड़ते और अक्सर दूसरी जाति में विवाह करते हैं। यदि किसी आम भारतीय अमेरिकी से उनकी जाति पूछी जाए, तो कई मामलों में उनके पास कोई जवाब नहीं होगा।

आईआईटी मद्रास में उद्यमिता प्रकोष्ठ होने पर गर्व करने के बजाय, वह इस समूह की आलोचना करती हैं कि इसने 130 स्टार्टअप स्थापित करने और 250 इंटर्नशिप सृजित करने का श्रेय लिया है। उन्हें चिंता है कि प्रवासी भारतीयों और स्वदेश के बीच ये सहयोग इस बात का प्रमाण है कि आईआईटी के छात्रों और अन्य भारतीयों ने सिलिकॉन वैली के योग्यता-आधारित मॉडल को अपना लिया है। भारतीयों की सफलता के हर संकेत और उदाहरण को वह निम्न जातियों के विरुद्ध एक षड्यंत्र के रूप में देखती हैं। यहां तक कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और रघुराम राजन (आईएमएफ के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर) भी आईआईटी की प्रशंसा करने वालों में शामिल हैं, और इसलिए वे भी इस जातिगत षड्यंत्र का हिस्सा हैं।

'सिस्को मामला एक खतरा है क्योंकि यह प्रवासी भारतीयों को कम सुरक्षित बनाता है,' वह कहती हैं, और बताती हैं कि यह एक निर्णायक मोड़ क्यों बनना चाहिए:

सिस्को मामला... उच्च जाति के भेदभाव और दबी हुई जातियों के हाशिए पर धकेलने के व्यापक पैटर्न को दर्शाता है।... अमेरिका में जातिवाद आज भी सक्रिय है, भले ही अधिकांश अमेरिकियों को यह दिखाई न देता हो। भारतीय संस्थानों, जैसे कि IIT, के पूर्व छात्र अपने जातिगत पूर्वाग्रहों को अमेरिकी तकनीकी क्षेत्र में ले आए हैं, जहाँ वे एक बार फिर अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। IIT से

स्नातक दलित इंजीनियर को "आरक्षित श्रेणी" का छात्र बताकर, उसके उच्च जाति के आकाओं ने अपनी जातिवादी सोच को व्यक्त किया कि उसने IIT में अवैध रूप से प्रवेश लिया था, वह बौद्धिक रूप से हीन था और सिस्को में नौकरी के योग्य नहीं था, और उसे उसकी औकात दिखानी ज़रूरी थी। इसके अलावा, उन्होंने इस प्रकार निर्धनता का भाव दिखाया क्योंकि अमेरिका में जाति को कानूनी रूप से लाभ या हानि का आधार नहीं माना जाता है। जाति के आधार पर भेदभाव करने की इसी निर्धनता को सिस्को मामला समाप्त करने का वादा करता है।
वह आगे दावा करती है कि,
भारत में मौजूद वंश-आधारित भेदभाव के कई रूप – अस्पृश्यता की प्रथा से लेकर कार्यस्थल और सामाजिक जीवन में भेदभाव तक – अमेरिका में भी देखने को मिलते हैं।
सिस्को मामले से यह उम्मीद जगती है कि ऐसी नीतियों को अकादमिक और तकनीकी क्षेत्रों में व्यापक रूप से लागू किया जा सकता है। अमेरिकी गैर-भेदभाव नीतियों में जाति को शामिल करने से प्रभावशाली जातियों द्वारा प्राप्त की जाने वाली दंडमुक्ति की भावना पर अंकुश लगेगा और शोषित जाति के छात्रों और कर्मचारियों को भेदभाव के खिलाफ खुलकर बोलने में मदद मिलेगी। लेकिन जातिगत भेदभाव को अधिक व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए, अमेरिकी संस्थानों को अपने छात्रों या कर्मचारियों की जातिगत पृष्ठभूमि को पहचानने और परिसर में सामाजिक मेलजोल की निगरानी करने से कहीं आगे जाना चाहिए।
विदेशी ठेकेदारों और विक्रेताओं को काम पर रखने वाली कंपनियां अक्सर यह अपेक्षा करती हैं कि वे अपने देश की मानक नीतियों और प्रोटोकॉल का पालन करें। इसका अर्थ यह है कि अमेरिका में अपनाई जाने वाली जाति-संबंधी नीतियां भारतीय ठेकेदार कंपनियों और विक्रेताओं पर भी

लागू हो सकती हैं। इसका भारतीयों पर और व्यापक रूप से प्रौद्योगिकी उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।

सुब्रमणियन चाहते हैं कि सिस्को और इसी तरह के अन्य मामलों के परिणामस्वरूप जाति को अमेरिकी नस्लवाद के समान एक घटना के रूप में गहराई से जांचा जाए। नस्ल की तरह ही, जातिगत पूर्वाग्रह संस्थागत संरचनाओं में अंतर्निहित है जो जातिगत विशेषाधिकार को पुन: उत्पन्न करना जारी रखते हैं।

संरक्षित श्रेणी भेदभाव के अनुभवों को संबोधित करने के लिए एक कानूनी आधार प्रदान करती है। ... जाति पर अधिक व्यापक डेटा संग्रह की अनुमति देता है क्योंकि यह एक अच्छी तरह से समझी जाने वाली श्रेणी नहीं है ... और इससे यह धारणा नहीं बनेगी कि दक्षिण एशियाई किसी तरह पिछड़े या गैर-आधुनिक हैं। अमेरिका एक नस्लीय समाज है। यह ... हर तरह की रेखाओं के साथ विभाजित है। और जाति उन्हीं रूपों में से एक है ... और यह ऐसी श्रेणी नहीं है जिसे नस्ल या वर्ग तक सीमित किया जा सके। इसका अपना तर्क और कुछ प्रकार के प्रतिरूप हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ... जाति नस्ल से अधिक शर्मनाक नहीं है। ये दोनों वंश-आधारित भेदभाव की संरचनाएं हैं जो पूरी तरह से आधुनिक हैं। इन श्रेणियों में कुछ भी पुरातन नहीं है, जब वे केवल पूर्व-आधुनिक या पूर्व-औपनिवेशिक या औपनिवेशिक अतीत के अवशेष नहीं हैं। (वे) ... विवाह, शिक्षा और अन्य माध्यमों से रोजमर्रा के जुड़ाव के रूपों के माध्यम से पुनरुत्पादित होते हैं।

सुब्रमणियन अपने इस बयान को आईआईटी की आलोचना के संदर्भ में रखती हैं, जबकि वास्तव में अधिकांश आईआईटी छात्र इसे गर्व की बात मानते हैं:

IIT के छात्रों ने भारत में उद्यमिता की भावना को बढ़ावा दिया और

पूंजीपतियों की एक नई पीढ़ी को तैयार किया, जिन्होंने देश को समाजवाद की बेड़ियों से मुक्त कराया। प्रवासी उद्यमिता के चलते, IIT ब्रांड भारत का ब्रांड बन गया। यह प्रवासी उदारवादी विचारधारा देश के उद्धार का भार अमेरिका में रहने वाले IIT छात्रों के हाथों में सौंपती है। वह चाहती हैं कि उन्हीं की तरह मानवविज्ञानी और समाज वैज्ञानिक दबे-कुचले लोगों तक नई विचारधारा पहुंचाएं और उन्हें इस बात का मलाल है कि उनके समूह की तुलना में IIT के छात्रों ने अधिक सफलता हासिल की है। उन्हें इस बात से भी परेशानी है कि IIT के छात्रों ने खुद को पीड़ित कहलाने से इनकार किया है।

भारत की विकास स्थिति को ब्रांड मूल्य के बराबर मानकर, यह विकास की सामाजिक, राजनीतिक और यहाँ तक कि नैतिक जटिलता को बाजार मूल्य तक सीमित कर देता है। ... निवेश आकर्षित करने और धन संचय करने की क्षमता ही सामाजिक मूल्य और बौद्धिक योग्यता का सर्वोपरि सूचकांक बन जाती है।

यह सच है कि संरचनात्मक सामाजिक-आर्थिक कारक उन संसाधनों तक पहुँच के असमान स्तरों का कारण बनते हैं जो किसी व्यक्ति को सफल और योग्य बनाते हैं। इन मुद्दों का समाधान करना नितांत आवश्यक है। हालाँकि, सुब्रमणियन के तर्क में जो बात कुटिल है, वह यह है कि 'योग्यता' की अवधारणा को ही अमान्य ठहराया जा रहा है। किसी भी प्रकार के भेदभाव को षड्यंत्र और संरचनात्मक अभिजात्यवाद का परिणाम बताया जाता है। इसका स्वाभाविक परिणाम यह निकलता है कि योग्यता-आधारित व्यवस्था का कोई वैध अस्तित्व ही नहीं है। इस तरह के हमले का निशाना पूंजीवाद और स्वतंत्र विचार हैं; यह विशुद्ध रूप से सर्वाधिकारवादी साम्यवाद है जो नस्लवाद-विरोधी और जातिवाद-विरोधी के वेश में घुसपैठ कर रहा है।

अफ्रो-दलितों से अलग होना

सुब्रमणियन उच्च जाति = श्वेत लोगों के वर्गीकरण को लेकर स्पष्ट हैं, लेकिन वह निम्न जाति = अश्वेत लोगों को उसी हद तक समतुल्य नहीं मानना चाहतीं, जिस हद तक इसाबेल विल्करसन और सूरज येंगडे (हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के, जिनकी चर्चा अगले अध्याय में की गई है) ऐसा करना चाहते हैं।

वह विल्करसन के इस विचार से असहमत हैं कि जाति एक ऐसी स्थिर और स्थायी संरचना है जिसमें नस्लवाद सार्वभौमिक रूप से व्याप्त है। विल्करसन के सिद्धांत से उनकी मुख्य आपत्ति यह है कि सुब्रमणियन जाति को भारत के इतिहास की एक विशिष्ट अवधारणा मानते हैं, न कि ऐसी कोई चीज़ जिसे निकालकर संदर्भ से अलग करके कहीं और स्थापित किया जा सके। यह विदेशी उपनिवेशवाद और पूंजीवाद के अनूठे अनुभव के साथ-साथ आंतरिक विकास का एक उप-उत्पाद है।

विल्करसन से एक और अंतर यह है कि सुब्रमणियन पिछली दो शताब्दियों के सामाजिक संघर्षों को नजरअंदाज नहीं करना चाहतीं। उनका तर्क है कि भारत में जाति और अमेरिका में नस्ल दोनों में काफी बदलाव आए हैं, और प्रत्येक व्यवस्था के भीतर बहुत अधिक तरलता और गतिशीलता है। जाति का सामाजिक और राजनीतिक जीवन कहीं अधिक जटिल है, और वह जाति और नस्ल की सरल तुलना का विरोध करती हैं।

लेकिन हम इस बात का अनुमान लगाने से खुद को रोक नहीं सकते कि उनके बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है: सुब्रमणियन अमेरिकी अकादमिक जगत में जाति पर होने वाली चर्चा पर अपना अधिकार जमाना चाहती हैं। विल्करसन की उनकी आलोचना से यह संकेत मिलता है कि वे नस्ल संबंधी आलोचना का अधिकार विल्करसन, जो एक अश्वेत

विद्वान हैं, को सौंपने के लिए तैयार हैं, ताकि जाति को केवल भारतीय अवधारणा के रूप में स्थापित किया जा सके। उन्हें अपने तर्क को विल्करसन के व्यापक रूप से प्रचलित सिद्धांत से अलग रखना होगा, ताकि वे अकादमिक विशेषज्ञ के रूप में अपना वर्चस्व स्थापित कर सकें।

जवाहरलाल नेहरू बनाम नरेंद्र मोदी की राजनीति

1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित राष्ट्र निर्माण का सपना देखा। इसीलिए, उन्होंने IITs के साथ-साथ विदेशी सहायता से बड़े पैमाने पर इस्पात संयंत्रों और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं के विचार को बहुत महत्व दिया। सुब्रमणियन नेहरू की इस बात के लिए आलोचना करती हैं कि इन नए इंजीनियरिंग कॉलेजों को जातिगत राजनीति से दूर रखा गया, जिससे जातिगत ऊँच-नीच को बढ़ावा मिला। नेहरू ने तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सेवा भाव से ब्राह्मणवादी बताया था। उनका मानना है कि इससे वैज्ञानिक की अभिजात वर्ग की छवि और मजबूत हुई और भौतिक और व्यावहारिक पहलू कम विशेषाधिकार प्राप्त, निम्न जातियों के अधिकार क्षेत्र में आ गए। उनके अनुसार, नेहरू ने IITs को दो-स्तरीय इंजीनियरिंग प्रणाली का हिस्सा बनाकर यूरोप की नकल की।

लेकिन वह इसके मूल कारण को नजरअंदाज कर देती हैं: नेहरू और इंदिरा गांधी ने जमीनी स्तर पर जन शिक्षा की उपेक्षा की, जिसके कारण उच्च शिक्षा में वर्तमान स्तरीकरण उत्पन्न हुआ है। नियोजित अर्थव्यवस्था के मॉडल के रूप में नेहरू का राज्य समाजवाद भी अभिजात्य वर्ग को लक्षित करता था, लेकिन सुब्रमणियन ने इसका पर्याप्त विश्लेषण नहीं किया है।

नरेंद्र मोदी के प्रति सुब्रमणियन का रुख नेहरू के प्रति उनके शांत विचारों

की तुलना में कहीं अधिक शत्रुतापूर्ण है। वह मोदी की सभी उपलब्धियों को निरंकुश बताकर सिरे से खारिज कर देती हैं।

नरेंद्र मोदी के उदय ने IIT छात्रों की आत्म-निर्माण की परियोजनाओं में एक और बदलाव ला दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह बदलाव IIT छात्रों द्वारा भाजपा के नवउदारवादी पूंजीवाद के समर्थन में सबसे स्पष्ट रूप से देखा गया है। … मोदी की सत्तावादी लोकलुभावनवाद शैली को संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत दोनों में समर्थन मिला है। … IIT परिसरों में सांस्कृतिक राष्ट्रवादी राजनीति में वृद्धि इसका स्पष्ट प्रमाण है। भारत के भीतर उच्च जातिवाद की इस नवीनतम अभिव्यक्ति और योग्यता के लिए उच्च जाति के दावों और उत्थान के लिए निम्न जाति के दावों के बीच चल रहे द्वंद्व पर इसके प्रभावों का विश्लेषण हम निष्कर्ष में करेंगे।

वह इस तथ्य को आसानी से नजरअंदाज कर देती हैं कि मोदी की चुनावी जीत (2014 और 2019 दोनों में) काफी हद तक निचली जातियों से मिले व्यापक समर्थन के कारण हुई थी। यह विडंबना है कि आईआईटी अभिजात्यवाद के उनके कथित इतिहास को स्वीकार करने के बाद भी, वह अंततः सत्ताधारी भाजपा को दोषी ठहराती हैं।

उन्हें इस बात से परेशानी है कि IIT के प्रवक्ता ने प्रौद्योगिकीविदों और पूंजीपतियों के खिलाफ मोदी की नीतियों की प्रशंसा की है। उन्होंने इस बात पर उनकी आलोचना की है कि IIT भारत में राज्य समाजवाद के विपरीत प्रकाश की किरण रहे हैं। उनका यह कथन कि अमेरिका में जाकर बसे IIT छात्रों ने स्व-निर्मित उद्यमी बनकर खूब तरक्की की, जबकि भारत में रह गए छात्र पिछड़ गए, अमेरिका के चरित्र को दर्शाता है। चाहे चीन, जापान, जर्मनी, रूस, पोलैंड या कहीं और से आए अप्रवासी हों, अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ लोग योग्यता और मुक्त उद्यम के आधार

पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस लोकाचार का हिंदू धर्म या भारतीय ब्राह्मणों के किसी भी प्रकार के जातिगत विशेषाधिकार से कोई संबंध नहीं है।
फिर भी, उनका कहना है कि भारत में 'हिंदू राष्ट्रवादियों' के चुनाव से जातिगत सत्ता को मजबूती मिली है, जो प्रवासी भारतीयों में भी दिखाई देती है। इसका कारण यह बताया गया है कि मोदी जातिवादी हैं (भले ही वे उच्च जाति समुदाय से संबंध नहीं रखते) और उच्च जाति के विशेषाधिकारों का समर्थन कर रहे हैं। वे लिखती हैं:
अन्य बहुसंख्यक राष्ट्रवादों की तरह, हिंदू राष्ट्रवाद का भी लंबे समय से उच्च जाति के मध्यम वर्ग में एक सामाजिक आधार रहा है। अधिकांश IITian इन दोनों वर्गों का एक आदर्श संयोजन हैं, जो उच्च जाति के मध्यम वर्ग के सदस्यों से उभरकर पूंजीवादी वर्ग का हिस्सा बने हैं, और जिनका प्रभाव मातृभूमि और प्रवासी दोनों में फैला हुआ है।
सुब्रमणियन हालांकि, इस बात का कोई प्रमाण नहीं देतीं कि मोदी सरकार की कौन सी नीतियां निम्न जाति विरोधी हैं। इसके विपरीत, बुनियादी ढांचे, रोजगार विकास और कई सामाजिक कार्यक्रम अल्पसंख्यकों और निम्न जातियों के हित में रहे हैं। एक अच्छे विद्वान को भारत में विभिन्न राजनीतिक सरकारों के दौरान निम्न जातियों की प्रगति की तथ्यात्मक तुलना करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा लगता है कि सुब्रमणियन के काम का दायरा इससे परे है। वास्तव में, अपनी पुस्तक के निष्कर्ष में, वह पिछली कांग्रेस सरकार की गरीबी कम करने और दलितों को अधिकार दिलाने में की गई महान उपलब्धियों की एक सूची बनाती हैं; लेकिन अपने व्यापक सामान्यीकरणों का समर्थन करने के लिए कोई सांख्यिकीय तुलना प्रस्तुत नहीं करतीं।
वह आईआईटी को ऐसे संस्थानों के रूप में चित्रित करती हैं जो अमीरों से गरीबों को धन के पुनर्वितरण को रोकते हैं और उच्च और निम्न जाति के

काम के अलगाव को बनाए रखते हैं।
मानसिक और शारीरिक, प्रतिभावान और प्रशिक्षित, सामान्य और आरक्षित, प्रवासी और मातृभूमि, तथा अधिनायकवाद और निम्न जाति के अधिकारों की राजनीति के बीच क्रमिक विभाजन रेखाओं में, हम उन गतिशील और निरंतर पैंतरेबाज़ी के रूपों को देखते हैं जिनके माध्यम से उच्च जाति-त्व में निहित अधिकारपूर्ण निवेश को व्यक्त और सुरक्षित किया जाता है।

सुब्रमणियन के शोध प्रबंध से संबंधित चिंताएँ
आगे दिया गया आरेख सुब्रमणियन के सिद्धांत, उससे उत्पन्न सक्रियता और भारत को तोड़ने के प्रयासों में लगे बलों पर उसके प्रभाव का सारांश प्रस्तुत करता है।
सुब्रमणियन जाति को आर्थिक वर्ग की तरह मानने के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि इससे जातिगत भेदभाव आर्थिक विकास के माध्यम से दूर हो जाएगा। उनका मानना है कि जाति एक स्थायी दीर्घकालिक संरचना है, और वे इस संरचना पर आधारित हर चीज को ध्वस्त करना चाहती हैं। प्रतिस्पर्धी वैश्वीकरण के इस युग में हमें उनका यह दृष्टिकोण अदूरदर्शी और खतरनाक लगता है। वे राष्ट्र निर्माण और सभी समुदायों के उत्थान में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) शिक्षा के व्यापक प्रभावों का विश्लेषण करने में विफल रही हैं।
सुब्रमणियन आईआईटी में प्रवेश पाने के लिए आवश्यक कड़ी मेहनत को पूरी तरह से अनदेखा करती हैं, जिसके कारण हजारों छात्रों की सफलता की कहानियां सामने आती हैं। वास्तव में, उनका तर्क है कि योग्यता-आधारित परिणामों का बचाव करना ही जातिगत विशेषाधिकार का एक रूप है। जैसा कि हमने अध्याय 1 में देखा, यह संकीर्ण मानसिकता सीधे

तौर पर क्रिटिकल रेस थ्योरी से ली गई है, जो उनके दृष्टिकोण के विरुद्ध किसी भी तर्कसंगत बहस के द्वार बंद कर देती है।

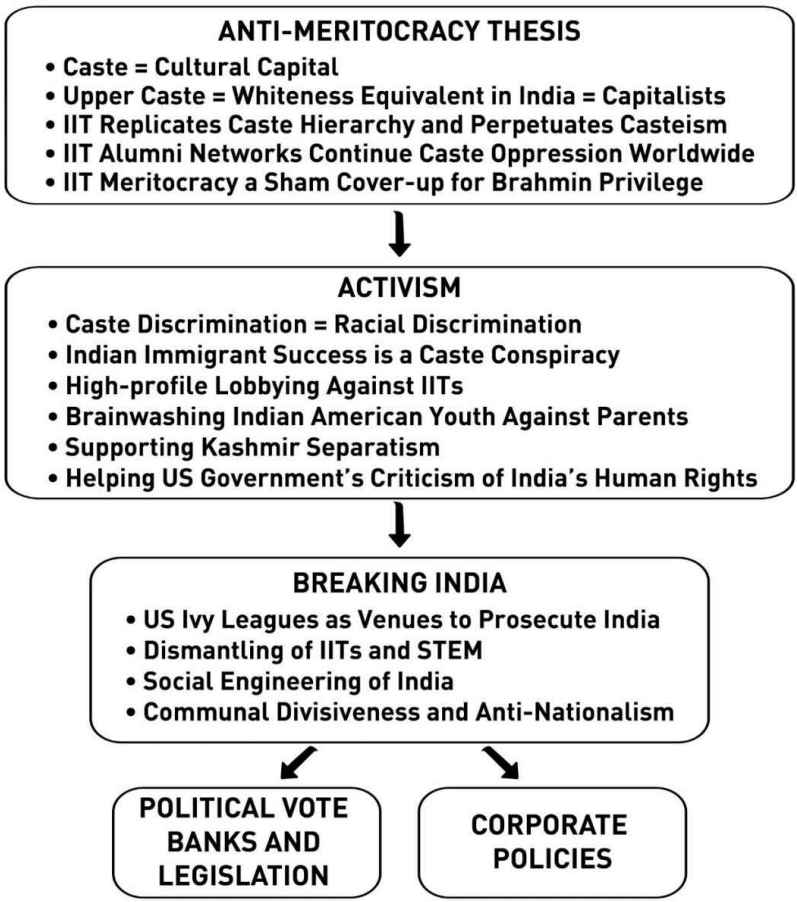

उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि अमेरिकी विश्वविद्यालयों के दक्षिण एशियाई अध्ययन विभागों में हिंदू-विरोधी रवैया प्रचलित है, जिससे हिंदू छात्र अन्य धर्मों के छात्रों की तुलना में मनोवैज्ञानिक रूप से पिछड़ जाते हैं। स्थिति को और भी बदतर बनाने के लिए, अजंता सुब्रमणियन और सूरज येंगडे जैसे कुछ शिक्षाविद विश्वविद्यालयों में युवा भारतीयों का मस्तिष्क इस तरह से भर रहे हैं कि वे अपने माता-पिता को

जातिवादी होने के कारण तिरस्कार की दृष्टि से देखें। वे इस तथ्य को नजरअंदाज करती हैं कि भारतीय माता-पिता के लिए अपने बच्चों की कॉलेज शिक्षा के लिए अपनी जीवन भर की बचत का निवेश करना आम बात है, जो लाखों डॉलर तक पहुंच सकता है। वे भारतीय-अमेरिकी युवाओं का मस्तिष्क इस तरह से भरकर विद्रोह करने के लिए उकसाना चाहती हैं, जिसे वे अपने परिवार का जातिगत विशेषाधिकार मानती हैं। दक्षिण एशियाई युवाओं की एक पीढ़ी सामाजिक न्याय के अन्य आंदोलनों के साथ एकजुट होकर काम करती है। विशेषाधिकार के बारे में सोचने में एक झिझक है। विशेष रूप से अमेरिका में जन्मे दक्षिण एशियाई लोगों में जाति के प्रति अज्ञानता है क्योंकि उन्हें उन संरचनात्मक परिस्थितियों के बारे में नहीं बताया गया है जिनके कारण उनके परिवार प्रवास कर सके और सफल हो सके। दक्षिण एशियाई लोग अपने वर्ग विशेषाधिकार से अवगत हैं और नस्लीय अल्पसंख्यक स्थिति और उच्च मध्यम वर्ग की स्थिति के अंतर्संबंध के बारे में सोचने के तरीके को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन कहानी का जातिगत आयाम अक्सर अनदेखा रह जाता है। श्वेत न होने को संरचनात्मक विशेषाधिकार की कमी से न जोड़ें। दक्षिण एशियाई अमेरिकियों के लिए यह महत्वपूर्ण है, यदि वे सामाजिक न्याय की लड़ाई में प्रभावी सहयोगी बनना चाहते हैं।

अमेरिका में जाति व्यवस्था की कार्यप्रणाली और नस्लीय एवं जातिगत विशेषाधिकारों के बीच समानता को समझने के लिए तत्पर रहें। दक्षिण एशियाई देशों में अल्पसंख्यक होने की तुलना में अमेरिका में अल्पसंख्यक होने का क्या अर्थ है, इस पर विचार करना महत्वपूर्ण है। भारत में इस समय एक सत्तावादी, कुछ लोग इसे फासीवादी सरकार कहेंगे, सत्ता में है और प्रवासी दक्षिण एशियाई लोगों के बीच इसे व्यापक समर्थन प्राप्त है। इसलिए यदि आप सामाजिक न्याय आंदोलनों के साथ जुड़ना चाहते हैं,

तो यह महत्वपूर्ण है कि आप न केवल यहाँ बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उपमहाद्वीप में अल्पसंख्यकों और शोषित जातियों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाएं। और अपने पैतृक देश में बहुसंख्यकवादी परियोजना का समर्थन करने के जाल में न फंसें, इसे अपनी नस्लीय, राष्ट्रीय या धार्मिक पहचान का विस्तार न समझें।

वह इस तथ्य को नज़रअंदाज़ करती हैं कि उच्च शिक्षित तकनीकी पेशेवरों का अमेरिका आना और प्रतिष्ठित पदों पर आसीन होना, भारतीय जातिगत विशेषाधिकार का परिणाम नहीं बल्कि योग्यता आधारित अमेरिकी आप्रवासन नीतियों से जुड़ा है। यदि अमेरिका किसानों, बढ़ई या राजमिस्त्री को प्राथमिकता दे, तो निश्चित रूप से कई लोग पलायन कर जाएंगे। यदि बिना किसी प्रतिबंध के आवागमन के द्वार खोल दिए जाएं, तो पलायन करने वाले लोगों की विविधता बहुत अधिक होगी।

सुब्रमणियन एक प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जो IITs पर जातिगत विशेषाधिकार को बढ़ावा देने का आरोप लगाती हैं। उनका तर्क है कि विशेषाधिकार प्राप्त जातिगत पृष्ठभूमि वाले भारतीयों ने अमेरिका में जातिवाद को जन्म दिया है, और जातिगत भेदभाव के खिलाफ अमेरिका में हाल ही में दायर मुकदमे तो बस हिमबर्ग का एक छोटा सा हिस्सा हैं। वह लिखती हैं कि,

अमेरिका में रहने वाले अधिकांश दक्षिण एशियाई लोग विशेषाधिकार प्राप्त जातिगत पृष्ठभूमि से आते हैं, और जाति उनके लिए एक प्रकार की पूंजी रही है जिसका लाभ वे प्रवास के अवसरों का फायदा उठाने के साथ-साथ अमेरिका में कुछ आर्थिक और व्यावसायिक सफलताएं प्राप्त करने में भी उठा पाए हैं।

अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, वह IIT छात्रों के खिलाफ सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी आधार पर अभियान चला रही हैं।

उन्होंने खुद को एक ऐसे प्रमुख अपराधी के रूप में स्थापित किया है जो हर उस मंच पर IIT को बदनाम करने के लिए दृढ़ संकल्पित है जहां उन्हें आमंत्रित किया जा सकता है। लेकिन उनके इस प्रयास में इस बात की कोई आत्म-जागरूकता नहीं है कि सांप्रदायिक हिंसा और विभाजन को बढ़ावा देकर वह भारत को तोड़ने वाली ताकतों की मदद कर रही हैं।
असली सवाल यह है कि क्या अमेरिकी उच्च शिक्षा संस्थान भारतीय समाज पर मुकदमा चलाने, भारत की नीतियों को निर्धारित करने और कठोर भू-राजनीतिक दबाव डालने के लिए उपयुक्त मंच हैं? क्या मानवाधिकारों के उल्लंघन के अपने ही रिकॉर्ड को देखते हुए, चाहे वह घरेलू स्तर पर हो या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अमेरिका के पास इस तरह के हस्तक्षेप करने का नैतिक अधिकार है? क्या घरेलू प्रकृति के ऐतिहासिक मुद्दों को सुलझाने में अमेरिका का विश्व के अन्य हिस्सों में कोई सफल इतिहास रहा है?
इससे मध्य पूर्व में मानवाधिकार उल्लंघन के अमेरिकी आरोपों की याद आती है, जिसके कारण सैन्य तैनाती हुई थी। लेकिन बाद में यह साबित हुआ कि यह तेल पर कब्ज़ा करने की इच्छा से प्रेरित था। सामाजिक वैज्ञानिकों का अमेरिका के घिनौने हस्तक्षेपों में मोहरा बनने का एक कुख्यात इतिहास रहा है, और उनके द्वारा तैयार किए गए अत्याचार साहित्य का उपयोग अतीत में आक्रामकता और विजय के आपराधिक कृत्यों को उचित ठहराने के लिए किया गया है।
ये प्रचलित विचार भारत में आयात किए जा रहे हैं ताकि पहले से ही जर्जर शिक्षा व्यवस्था को और भी ध्वस्त किया जा सके। हार्वर्ड स्थित मित्तल संस्थान न केवल सुब्रमणियन की छात्रवृत्ति का समर्थन करता है, बल्कि भारत में योग्यता की भूमिका और परिभाषा का अध्ययन करने के लिए सेमिनार भी आयोजित करता है। जहां चीन विज्ञान, प्रौद्योगिकी,

इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में शीर्ष विद्वानों की एक पीढ़ी तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, वहीं ये प्रगतिशील विचार भारत में भी पनप रहे हैं, जिसमें अजंता सुब्रमणियन जैसे हमारे अपने अरबपतियों और शिक्षाविदों का भी योगदान है।

उत्तरआधुनिकतावाद ने सामाजिक विज्ञान और मानविकी को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग (एसटीईएम) के कठोर विज्ञानों में धीरे-धीरे प्रवेश करने में सहायता की है, जिससे राजनीति, समाजशास्त्र और मानवशास्त्र का समावेश हुआ है। यह विश्वव्यापी स्तर पर हो रहा है। उदाहरण के लिए, कनाडा में, भारतीय मूल के पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक और रसायन विज्ञान के प्रोफेसर, पतंजलि कम्भमपति को संघीय सरकार के दो अनुदानों से वंचित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा था, 'हम कौशल और आपसी हितों के आधार पर सबसे योग्य लोगों को नियुक्त करेंगे।' कनाडा की प्राकृतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान परिषद ने उनके 450,000 डॉलर के अनुदान आवेदन को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि 'आवेदन में समानता, विविधता और समावेशन संबंधी विचार अपर्याप्त माने गए।' आवेदन को नौकरशाही स्तर पर ही खारिज कर दिया गया, इससे पहले कि यह उस चरण तक पहुँच पाता जहाँ अन्य वैज्ञानिक उनके प्रस्ताव की समीक्षा कर सकें।

हमने इस बात पर चर्चा की है कि जाति को अमेरिकी शैली के नस्लवाद के पर्याय के रूप में देखा जाने लगा है, अमेरिका में भारतीयों द्वारा जातिगत पूर्वाग्रह को उजागर करने के लिए डेटाबेस संकलित किए जा रहे हैं, अमेरिकी कार्यस्थलों में जातिगत दुर्व्यवहार के आरोप में कानूनी कार्रवाई की जा रही है, और IIT को नस्लवादी संगठन बताकर उन पर हमले किए जा रहे हैं। अगला अध्याय अमेरिका स्थित एक प्रमुख दलित कार्यकर्ता का विश्लेषण करता है, जिन्होंने इन सभी तत्वों को एकीकृत

करते हुए दलित आंदोलन को अश्वेत अमेरिकी आंदोलन के साथ जोड़ दिया है।

5. अफ्रीकी-दलितों का उदय

अवलोकन
सूरज येंगडे ने अमेरिकी संदर्भ में नस्लवाद के मूल दायरे से परे क्रिटिकल रेस थ्योरी का विस्तार करने के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में वरिष्ठ फेलो, हार्वर्ड के अफ्रीकी अमेरिकी अध्ययन विभाग में रिसर्च एसोसिएट, हचिन्स सेंटर फॉर अफ्रीकन एंड अफ्रीकन अमेरिकन रिसर्च में फेलो हैं और हार्वर्ड में ही संस्थागत नस्लवाद-विरोधी और जवाबदेही पहल की संस्थापक टीम के सदस्य हैं। येंगडे विपुल, तीक्ष्ण बुद्धि वाले, साहसी और स्पष्टवादी हैं, साथ ही उनमें स्वाभाविक हास्य और आकर्षण है जो उन्हें एक आकर्षक सार्वजनिक बुद्धिजीवी बनाता है। हम उन्हें इस विमर्श के भविष्य में एक अग्रणी के रूप में गंभीरता से लेते हैं। हम उनके उद्देश्य से सहमत हैं, लेकिन उनके कार्यों में गंभीर कमियों की ओर भी ध्यान दिलाते हैं।
वह अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकियों पर होने वाले हर अत्याचार की तुलना भारत में उसी तरह की घटना से करने के मिशन पर हैं। जब अमेरिकी पुलिस की बर्बरता से संबंधित जॉर्ज फ्लॉयड की घटना सामने आई, तो येंगडे ने तुरंत लिखा:
ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी को भी स्पष्ट समानताओं पर ध्यान देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे जबरदस्ती इस सादृश्य को चर्चाओं में शामिल

करना पड़ा। एक टीवी बहस में एक पैनलिस्ट ने कहा कि यह अमेरिका केंद्रित चर्चा है और इसलिए भारत के जातिगत मुद्दों को उठाना ध्यान भटकाने वाला होगा।

अमेरिकी मीडिया उन्हें अफ्रीकी-दलित परियोजना का समर्थन करने और इसे वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए उनकी सराहना कर रहा है:

येंगडे ने अश्वेत सक्रियता से अपने व्यक्तिगत जुड़ाव के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि उनके पिता दलित पैंथर्स के सदस्य थे, जो ब्लैक पैंथर पार्टी से प्रेरित एक संगठन है और जाति व्यवस्था का विरोध करने के लिए काम करता है।

'जाति सभी समस्याओं की जड़ है' येन्गडे का मूल मंत्र है, और वे हर अवसर पर इसका जोरदार जाप करते हैं।[4] और यह बात न केवल भारत में, बल्कि विश्व भर में उन पर लागू होती है: 'जाति स्पष्ट रूप से भूगोल से परे है और एक परजीवी की तरह स्थानीय प्रथाओं पर पलकर नए रूप धारण कर लेती है।'[5]

अमेरिका में अश्वेत आंदोलन के ढांचे का इस्तेमाल दलित इतिहास माह, दलित जीवन मायने रखता है और दलित पैंथर्स जैसे आंदोलनों को जन्म देने के लिए किया गया है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट है: 'बोस्टन क्षेत्र में, "दलित और अश्वेत जीवन मायने रखता है" आंदोलन दलित और अश्वेत कार्यकर्ताओं की युवा पीढ़ी की नवगठित, पुनर्जीवित एकजुटता का प्रमाण है।' यहां तक कि कॉर्नेल वेस्ट की प्रसिद्ध पुस्तक 'रेस मैटर्स' का शीर्षक भी येंगडे ने अपनी पुस्तक 'कास्ट मैटर्स' लिखने के लिए उधार लिया है। हमने पहले भी पीयूष 'बॉबी' जिंदल जैसे भारतीयों की आलोचना की है जो अमेरिकी दक्षिणपंथी संगठनों की सदस्यता का लाभ उठाने के लिए खुद को गोरा दिखाने का दिखावा करते हैं। क्या सूरज येंगडे उनका अश्वेत समकक्ष है? उन्होंने अपने बालों को अफ्रीकी समुदायों की पारंपरिक शैली

में बदल लिया है और एक नए प्रकार का दलित विमर्श गढ़ा है जो क्रिटिकल रेस थ्योरी के अनुरूप है। इस प्रक्रिया में, येंगडे भारतीय अरबपतियों द्वारा प्रायोजित हार्वर्ड के थिंक टैंकों के चहेते बन गए हैं। येंगडे का सबसे प्रबल जुनून ब्राह्मणों को जातिगत अत्याचारों के लिए पूरी तरह से दोषी ठहराना रहा है; दलितों और अन्य लोगों की दुर्दशा में योगदान देने वाले अन्य सभी कारकों को वे अनदेखा करते हैं। उनका कहना है कि जाति और उससे जुड़े सभी अत्याचारों के वैचारिक, धार्मिक और सामाजिक कारण हिंदू धर्म में निहित हैं। उनका कहना है कि कठोर जाति व्यवस्था हिंदू धर्म के मूल में समाहित है और इस व्यवस्था ने अपने लंबे इतिहास में करोड़ों निर्दोष लोगों की जान ली है। वास्तव में, यह समाज के सभी स्तरों पर और हर व्यक्ति के निजी जीवन में इतनी गहराई से समाई हुई है कि केवल अन्याय के प्रति अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण और कार्यों को बदलकर इसका समाधान करना असंभव है।

और चूंकि हिंदू धर्म से अन्याय को अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए परंपरा के संरक्षक ब्राह्मणों पर प्रहार करना और हिंदू धर्म को ध्वस्त करना आवश्यक है, जो उन्हें दमन की शक्ति प्रदान करता है। परिवर्तन के लिए इन संरचनाओं को पूर्णतः ध्वस्त करना अनिवार्य है। और यह वैश्विक स्तर पर होना चाहिए। और येंगडे के विचार में, जब तक यह हासिल नहीं हो जाता, सभी प्रगतिशील आंदोलन अपर्याप्त रहेंगे।

इसलिए, अजंता सुब्रमणियन के मत के समान, 'समान अवसर' जैसी पहलों के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था में सुधार के सभी प्रयास विफल होंगे क्योंकि गहरी संरचनाएं असमान परिणामों को पुन: उत्पन्न करती रहती हैं। और जो लोग स्थापित संस्थाओं के भीतर सुधारों का समर्थन करते हैं, वे केवल समस्या को और बढ़ा रहे हैं। चाहे उनके इरादे कितने भी अच्छे क्यों न हों, उन्हें भी जातिवादी कहकर निंदा की जानी चाहिए।

दूसरे शब्दों में, येंगडे विश्व की वर्तमान सामाजिक व्यवस्था से कोई समझौता नहीं करते क्योंकि उनका कहना है कि इसमें जाति अंतर्निहित है।

येंगडे का सिद्धांत मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक सिद्धांत पर आधारित है: प्रत्येक सिद्धांत का उसके प्रति-सिद्धांत द्वारा पूर्णतः परस्पर-विनाश के युद्ध में विरोध किया जाना चाहिए। सिद्धांत और प्रति-सिद्धांत के बीच टकराव के मलबे से एक नए प्रकार का संश्लेषण उभरेगा; यह संश्लेषण अगला सिद्धांत बनेगा। यह नया सिद्धांत फिर से एक प्रति-सिद्धांत और एक नए संघर्ष को जन्म देगा। यह प्रक्रिया जारी रहेगी, जैसा कि अध्याय 1 में समझाया गया है। नीचे दिया गया आरेख इस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है।

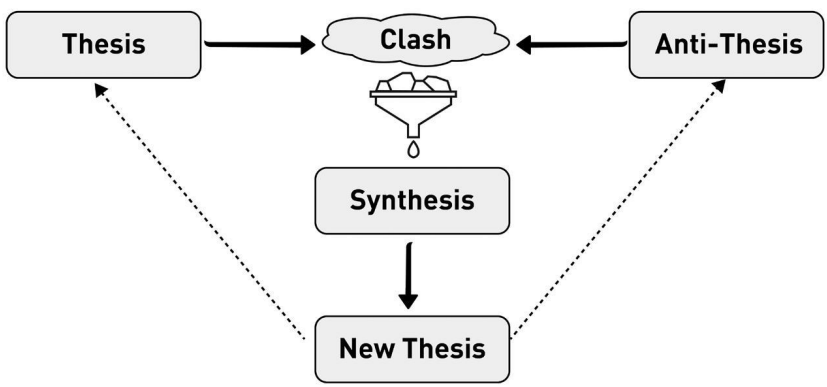

इसलिए, प्रगति के लिए स्थापित संरचनाओं और उन्हें ध्वस्त करने के उद्देश्य से गठित विरोधी ताकतों के बीच निरंतर संघर्षों की एक श्रृंखला आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, व्यवस्था के पूर्ण पतन के लिए एक व्यापक युद्ध ही आगे बढ़ने का एकमात्र व्यवहार्य मार्ग है।

जब येंगडे सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए मार्क्सवाद का प्रयोग करते हैं, तो उनका तर्क स्पष्ट होता है: हिंदू धर्म ही वह संस्थागत व्यवस्था है जो इसके लिए जिम्मेदार है और इसलिए, मुख्य दोषी है; ब्राह्मण इसे

नियंत्रित कर रहे हैं; और जाति वह साधन है जिसका उपयोग मानवता को दबाने के लिए किया जा रहा है। अतः, उनके जीवन का उद्देश्य एक ऐसी क्रांति शुरू करना है जो ब्राह्मणों, हिंदू धर्म और जाति को एक व्यापक युद्ध में पराजित करने के लिए उनके विरुद्ध खड़ी हो।

उनकी बातों में काफी सच्चाई है। हमारी उनसे असहमति इस बात से है कि वे संशयवादियों द्वारा उठाए गए गंभीर सवालों को खारिज कर देते हैं। वे उन्हें जातिवादी बताकर खारिज कर देते हैं, जिससे सार्थक बहसें रुक जाती हैं। उनके अनुसार, ब्राह्मणों के लिए एकमात्र नेक काम यही है कि वे उनकी विचारधारा को पूरी तरह स्वीकार कर लें, समाज के प्रति अपने पापों को स्वीकार करें, असहमत परिवार के सदस्यों से नाता तोड़ लें और वैश्विक 'चौथी दुनिया' आंदोलन शुरू करने के उनके अभियान का समर्थन करें। हमें वे कट्टरपंथी और महत्वाकांक्षा में अंधे लगते हैं।

अंबेडकर से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने खुद को उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। उनका मानना है कि वे वहीं से आगे बढ़ रहे हैं जहां से ऐतिहासिक अंबेडकर ने छोड़ा था।

उपरोक्त सारांश येंगडे के विचारों को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से है, ताकि हम उचित जांच-पड़ताल कर एक निष्पक्ष मूल्यांकन विकसित कर सकें। हम यह दोहराना चाहेंगे कि हम उनके तर्कों और सुझाए गए समाधानों से असहमत होने के बावजूद, उनके मुद्दे को गंभीरता से लेते हैं।

हमारा विश्लेषण उनके कार्यों को पढ़ने और अमेरिका, भारत और अन्य जगहों पर दिए गए उनके भाषणों के ढेरों वीडियो देखने पर आधारित है। हम उनके काम के प्रति अपनी समग्र प्रतिक्रिया को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं:

उनके तथ्यात्मक दावों और विश्लेषण में गंभीर खामियां हैं। वे कई सामाजिक बुराइयों के विश्लेषण में अत्यधिक सरलीकरण का सहारा लेते

हैं; वे बार-बार गंभीर तथ्यात्मक गलतियां करते हैं, और उन मुद्दों की बारीकियों को समझने में विफल रहते हैं जो व्यक्तिपरक, विवादास्पद या वास्तविकता के कई पहलुओं वाले होते हैं।
वह अपने कई दावों के समर्थन में सीमित साक्ष्य प्रस्तुत करता है।
उनकी अंतर्निहित शून्य-योग द्वंद्वात्मक पद्धति में कई समस्याएं हैं, जो सामाजिक संघर्ष को अधिकतम करने के लिए बनाई गई है। यह मूल रूप से उस बौद्ध मार्ग के विपरीत है जिसका वे अनुसरण करने का दावा करते हैं।

येंगडे की मूल ऐतिहासिक मान्यताओं पर सवाल उठाना
येंगडे के कई दावे पूरी तरह से झूठे या अतिरंजित आधारों पर आधारित हैं। अक्सर, उनके खिलाफ ठोस प्रतिवाद भी मौजूद होते हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। यह चिंताजनक है कि वे अक्सर गैर-जिम्मेदाराना बयान देकर बच निकलते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि उन्हें प्रायोजित और बढ़ावा देने वाले शिक्षाविद उनके काम की उचित समीक्षा में रुचि नहीं रखते हैं। आइए कुछ उदाहरणों पर गौर करें।
बिना किसी विश्वसनीय प्रमाण का हवाला दिए, येंगडे यह बेबुनियाद बयान देते हैं कि आर्यों नामक एक विदेशी जाति ने कई सहस्राब्दियों पहले भारत पर आक्रमण किया था और अपने साथ जाति व्यवस्था की समस्या लेकर आए थे। बिना किसी सहायक आंकड़े और विश्लेषण के, वे हमें इस 'विदेशी आक्रमण' पर विश्वास दिलाना चाहते हैं, जिसके बारे में वे कहते हैं, 'यह तो अब सिद्ध हो चुका है'। उनका दावा है कि आनुवंशिक प्रमाणों ने इस आर्य आक्रमण सिद्धांत को निर्णायक रूप से सिद्ध कर दिया है।
तथ्य बिल्कुल अलग हैं:
आर्यन आक्रमण सिद्धांत औपनिवेशिक युग के दौरान गढ़ी गई एक

परिकल्पना थी जो यूरोपीय हितों की पूर्ति करती थी और वास्तव में यह उस प्रकार का नस्लवादी और साम्राज्यवादी सिद्धांत था जिसका उन्हें समर्थन करने के बजाय खंडन करना चाहिए था।
इस पर कभी भी किसी प्रकार की अकादमिक जांच-पड़ताल नहीं की गई। हाल के दशकों में, पुरातत्व, भाषाविज्ञान, भौगोलिक चिह्नों, आनुवंशिकी आदि कई विषयों से प्राप्त साक्ष्यों का उपयोग करके इस सिद्धांत का पूरी तरह से खंडन किया गया है।
आनुवंशिक साक्ष्य भारत भर में काफी हद तक आंतरिक एकता की ओर इशारा करते हैं।
वे उन स्थापित शोधों का भी खंडन करते हैं जो यह दर्शाते हैं कि अंग्रेजों ने अपनी जनगणनाओं के माध्यम से एक गतिशील जाति संरचना को औपचारिक कानूनी व्यवस्था में स्थिर कर दिया था। उनका मुख्य तर्क यह है कि अंग्रेजों ने भारत पर केवल नब्बे वर्षों तक शासन किया था, इसलिए उनका प्रभाव सीमित था। वे यह भूल जाते हैं कि ब्रिटिश राजशाही द्वारा भारत पर 90 वर्षों तक शासन करने से पहले, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 258 वर्षों तक शासन किया था। ब्रिटिश युग, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से लेकर 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक, लगभग 350 वर्षों की अवधि तक फैला हुआ था।
येंगडे ने अंग्रेजों और पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों, मुसलमानों, मंगोलों आदि जैसे विभिन्न आक्रमणकारियों द्वारा भारतीयों की पराजय का एक सरलीकृत स्पष्टीकरण दिया है। उनका सिद्धांत यह है कि उच्च जातियों ने निम्न जातियों को हथियार उठाने से इसलिए रोका क्योंकि वे उन पर नियंत्रण रखना चाहते थे। वास्तव में, वे कहते हैं, ब्राह्मणों ने विदेशी आक्रमणकारियों के साथ मिलीभगत की जबकि शूद्र देश की रक्षा करना चाहते थे। निम्न जातियाँ भारत के प्रति वफादार थीं, लेकिन उच्च जातियों

ने राष्ट्र के साथ विश्वासघात किया। 'दलित खतरे में पड़ गए और उन्हें गुलाम बनाकर कहीं फेंक दिया गया', जबकि उच्च जातियाँ उपनिवेशवादियों के साथ मिल गईं।

लेकिन सच्चाई यह है कि परिस्थितियाँ कहीं अधिक जटिल थीं। यद्यपि कई अभिजात वर्ग मुस्लिम और ब्रिटिश आक्रमणकारियों के साथ चिंताजनक रूप से मिलीभगत करते थे, वहीं औपनिवेशिक काल के दौरान व्यापक प्रतिरोध और स्वशासन के लिए संघर्ष भी हुए, जिसके कारण अंततः भारत को स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता प्राप्त हुई।

उनका एक और बेतुका दावा यह है कि हिंदू धर्म उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक अस्तित्व में ही नहीं था। उनका मानना है कि हिंदू धर्म 'ब्राह्मणों को एकजुट करने का एक राजनीतिक आह्वान था, जब उन्हें लगा कि उनके विशेषाधिकार छिन रहे हैं'। यह दावा हिंदू-विरोधी अक्सर करते हैं, लेकिन इसमें एक अंतर्निहित विरोधाभास है: एक ओर तो हिंदू धर्म को प्राचीन काल में जाति व्यवस्था के निर्माण का दोषी ठहराया जाता है, और दूसरी ओर यह दावा किया जाता है कि हिंदू धर्म हाल के समय तक अस्तित्व में ही नहीं था!

साथ ही, हमें यह भी मानना होगा कि इतिहास के बारे में उनके कई विचार सत्य हैं। उनका यह तर्क बिल्कुल सही है कि मंगल पांडे को 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत का श्रेय गलत तरीके से दिया जाता है, जबकि असली नायक मातादीन भंगी नामक एक दलित थे, जिन्होंने मंगल पांडे को प्रेरित किया था। उनका यह कथन भी सही है कि गांधी ने जाति व्यवस्था को समाप्त करने के बजाय आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाया। इसी कारण येंगडे उन्हें 'नया आधुनिक राजनीतिक मनु' कहते हैं।

इसके अलावा, येंगडे की प्रशंसा करते हुए यह भी कहा जा सकता है कि

उन्होंने अंबेडकर के इस दावे को स्वीकार किया है कि वेदों में जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं है, और बाद में हुए परिवर्तन ने इसे जन्म आधारित बना दिया। इससे उन्हें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए था, न कि सारा दोष हिंदू धर्म पर मढ़ना चाहिए था। इस महत्वपूर्ण बिंदु का लापरवाही से उल्लेख करने के बाद, वे तुरंत 'धूर्त ब्राह्मणों और उनकी संतानों' पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं।
इस विषय पर उनका समग्र दृष्टिकोण असंगत है। कभी वे कहते हैं कि जाति व्यवस्था आर्यों द्वारा भारत पर आक्रमण करने के दौरान लाई गई थी। फिर वे कहते हैं कि यह वेदों में नहीं थी और बाद में ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई थी। और फिर वे दावा करते हैं कि 'यह कोई संयोग नहीं है कि आर्यों को भारत के हिंदू कानूनों और उसकी क्रूर जाति व्यवस्था में आध्यात्मिक मातृभूमि मिली', जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदू कानून और क्रूर जाति व्यवस्था आर्यों से पहले से मौजूद थे।
इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि वह परिस्थितियों और श्रोताओं के अनुसार कहानी को तोड़-मरोड़ कर पेश करने के लिए तैयार है, जबकि लगातार हिंदू धर्म और ब्राह्मणों की विषाक्तता के बारे में एक ही बात दोहराता रहता है।

अंबेडकर और बौद्ध धर्म का अवसरवादी उपयोग
येंगडे खुद को अंबेडकर आंदोलन का मशालवाहक मानते हैं। लेकिन वे अंबेडकर की भावनाओं को जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं और अपने एजेंडे के अनुरूप अंबेडकर आंदोलन के उद्देश्यों को नए सिरे से परिभाषित करते हैं। अंबेडकर सर्वप्रथम एक भारतीय राष्ट्रवादी थे और उन्होंने गर्व से स्वयं को ऐसा घोषित किया था। इसलिए, युवावस्था और संवेदनशीलता के बावजूद, वे अमेरिका और यूरोप द्वारा दिए गए भौतिकवादी प्रलोभनों

को नजरअंदाज करने में सक्षम थे। उन्होंने विदेशी संस्थानों या धर्मों पर निर्भर न रहने का विकल्प चुना और विदेश में अध्ययन करने के बाद, सब कुछ त्याग कर अपनी मातृभूमि लौट आए। येंगडे में हमें ऐसे विचार देखने को नहीं मिलते।

हम इस बात पर सवाल उठाते हैं कि येंगडे भारत की अखंडता और संप्रभुता को कितना महत्व देते हैं। हार्वर्ड को अपना आधार बनाकर उन्होंने खुद को भारतीय हितों के खिलाफ काम करने के लिए तैयार कर लिया है। और इस ऊंचे पद पर बैठकर वे सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनकी प्राथमिकताएं (और निष्ठाएं) भारत से बाहर प्रतीत होती हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने अंबेडकर से बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया है। अंबेडकर का सबसे अमिट प्रभाव यह था कि उन्होंने दलित पहचान को अपनाया, जो जातिगत भेदभाव के बिना सभी दलित लोगों को समाहित करने वाला एक समूह है। अंबेडकर ने भारतीयों के ईसाई धर्म या इस्लाम में धर्मांतरण का पुरजोर विरोध किया। ईसाई धर्म और इस्लाम दोनों में मौजूद खामियों को उजागर करने वाले उनके लेख सर्वविदित हैं, जिन पर अगले अध्याय में चर्चा की जाएगी।

हाल ही में येंगडे और एक थेरवाद बौद्ध भिक्षु के बीच हुई चर्चा में, मेज़बान ने उनसे पूछा कि अंबेडकर ने बौद्ध धर्म कैसे अपनाया। येंगडे ने जवाब दिया कि अंबेडकर को 'बुद्ध से अधिक प्रेरक कुछ नहीं मिला'। यह पूरी सच्चाई नहीं है। येंगडे जिस बात का ज़िक्र नहीं करना चाहते, वह यह है कि अंबेडकर ने उपलब्ध सभी धार्मिक विकल्पों का विस्तृत और व्यवस्थित मूल्यांकन किया था, और बौद्ध धर्म अपनाने से पहले उन्होंने ईसाई धर्म और इस्लाम दोनों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया था। येंगडे ने अंबेडकर की 'अन्य धर्मों' के प्रति असुविधा का अस्पष्ट रूप से उल्लेख किया है, लेकिन कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं दिया है। उनका

कहना है, 'अगर अंबेडकर बुद्ध धर्म के अलावा किसी और धर्म में चले जाते, तो कई युद्ध छिड़ जाते।' मानो अंबेडकर ने ऐसा न करने के अपने कारण स्पष्ट न किए हों। यह अनदेखी संभवतः येंगडे के उस एजेंडे से प्रेरित है जिसके तहत वे किसी भी कीमत पर हिंदू धर्म को नीचा दिखाना चाहते हैं, भले ही इसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन अंबेडकर के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध हों। इस परिप्रेक्ष्य में देखने पर, हिंदुओं और बौद्धों पर मुसलमानों द्वारा किए गए अत्याचारों को नजरअंदाज करना समझ में आता है। वे जातिगत मुद्दों के लिए ब्राह्मणों को दोषी ठहराने के लिए उत्सुक हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम और ईसाई समाजों में भी।
जातिगत अत्याचारों के समाधान के रूप में अंबेडकर का विचार था कि दलितों को बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए। यह बात अंबेडकर के विश्वदृष्टिकोण और सामाजिक सक्रियता का केंद्रबिंदु है। इसलिए, दलितों के नए नेता के रूप में येंगडे का बौद्ध धर्म से संबंध विशेष महत्व रखता है और इसका गहन अध्ययन आवश्यक है।
बौद्ध भिक्षु के साथ उनकी बातचीत से कुछ आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टियाँ प्राप्त होती हैं। पूरे साक्षात्कार के दौरान, भिक्षु अपने प्रश्नों में बहुत सीधे रहते हैं; वे कई बार येंगडे को कठिन परिस्थितियों में डालते हैं ताकि बौद्ध धर्म के बारे में उनकी समझ की सीमा का पता चल सके। वे येंगडे की सतही जानकारी को उजागर करने के लिए पर्याप्त विनम्र हैं, लेकिन फिर भी यह सतही जानकारी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, मेजबान उनके इस दावे के आधार पर प्रश्न करते हैं कि दलित मूल रूप से बौद्ध थे। येंगडे का स्पष्टीकरण इस प्रकार है:
जब बुद्ध भारत की चेतना में आए, तो वे वैदिक जाति व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए क्योंकि बुद्ध ने जाति व्यवस्था के ताश के पत्तों के महल को ही ध्वस्त कर दिया। बुद्ध ने यह प्रस्ताव रखा कि कई

जनजातियाँ, जिन्हें अंततः अछूत घोषित किया गया था, धम्म का हिस्सा बन जाएँ और धम्म का हिस्सा होने के कारण, धम्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों की बार-बार हत्याएँ की गईं। स्वयं बुद्ध पर भी कई शारीरिक और आध्यात्मिक हमले हुए।

यह जवाब अस्पष्ट लगता है और येंगडे के इस दावे का कोई ठोस सबूत नहीं देता कि दलित मूल रूप से बौद्ध थे। बाद में, उसी साक्षात्कार में वे कहते हैं, 'अंबेडकर जन्म से हिंदू हैं और एक निम्न जाति के अछूत हिंदू हैं', इस प्रकार दलितों के मूल रूप से बौद्ध होने के अपने पहले के दावे का खंडन करते हैं।

'दलित हिंदू नहीं हैं' इस बात को पुष्ट करने के लिए येंगडे दलितों को विभिन्न प्रकार की विशेषताएँ देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि दलित एक समरूप समूह बिल्कुल नहीं हैं। दलित नामक एकीकृत पहचान की धारणा अन्याय के विरुद्ध राजनीतिक उद्देश्य से सभी हाशिए पर पड़े समुदायों को एकजुट करने के लिए हाल ही में गढ़ी गई है। लेकिन हिंदू धर्म पर आक्रमण करने के उद्देश्य से उनकी संस्कृतियों को समरूप बनाने का प्रयास उनकी बहुलता का उल्लंघन है। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि यह सर्वविदित है कि भाषा, इतिहास, भौगोलिक निकटता, आध्यात्मिक परंपराओं, संस्कृति या व्यावसायिक स्थिति के मामले में उनमें कभी भी आंतरिक एकता नहीं रही है।

यह विडंबनापूर्ण है कि इस तरह का समरूपीकरण का रवैया उदारवादी अकादमिक जगत से आता है जो विविधता का इतनी धूमधाम से समर्थन करता है।

जब येंगडे ने हार्वर्ड में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मेजबानी की, तो उन्होंने अपने अतिथि से यह कहलवाया, 'आदिवासी (स्वदेशी लोग) कभी हिंदू नहीं थे। हमारे सभी रीति-रिवाज और परंपराएं हिंदुओं से

बिल्कुल अलग हैं।' यह साबित करने के लिए कि वे हिंदू नहीं हैं, एक कारण यह बताया गया कि आदिवासी प्रकृति पूजक हैं। लेकिन हिंदू भी तो प्रकृति पूजक हैं! सूर्य देव की अनेक रूपों में पूजा की जाती है। वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी देवताओं के ही रूप हैं। पवित्र पर्वत और नदियाँ हैं। पीपल का वृक्ष पवित्र है। प्रकृति और हिंदू धर्म अविभाज्य हैं।

येंगडे का कहना है कि हिंदुओं ने बुद्ध को नौवां अवतार, भगवान विष्णु का पुनर्जन्म कहकर आत्मसात कर लिया, और ऐसा बुद्ध को हिंदुओं के अधीन और गौण बनाने के लिए किया गया था। येंगडे को यह जानना चाहिए कि अवतार एक संस्कृत शब्द है जो ईश्वर/सर्वोच्च सत्ता के प्रकटीकरण को संदर्भित करता है, और बुद्ध को अवतार कहना किसी भी तरह से उन्हें गौण या अपमानित करना नहीं माना जा सकता। साथ ही, कई संप्रदाय (परंपराएं) अवतारों की आधिकारिक सूची में बुद्ध के स्थान को आवश्यक रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रति हिंदू प्रतिक्रिया और स्वीकृति में येंगडे के अनुमान से कहीं अधिक सूक्ष्मता है। इस तरह का सतही व्यंग्य गंभीर विद्वता नहीं है।

वह हिंदुओं के हाथों बौद्धों के उत्पीड़न का उपदेश देता है। वह 'बुद्ध, बौद्धों और उनके धम्म के नरसंहार, बार-बार हुए नरसंहारों' का जिक्र करता है। वह आचार्य आदि शंकराचार्य, जिन्हें हिंदू सबसे महान वैदिक विद्वानों और अग्रणी आध्यात्मिक नेताओं में से एक मानते हैं, का सबसे अपमानजनक ढंग से उल्लेख करता है। वह ट्वीट करता है: 'यह बदसूरत सिर वाला कूड़ेदान - शंकराचार्य इस तरह के अपराधों के लिए जिम्मेदार है।' वह शंकराचार्य पर हत्या का आरोप लगाता है: 'आदि शंकराचार्य के आक्रमण के दौरान कई भिक्षुओं की हत्या की गई।' 'बुद्ध को इस धरती से मिटाने के लिए आक्रमण और हमले किए गए।' और निश्चित रूप से, वह अपने इन बेतुके दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं देता है।

अंबेडकर के विचारों को दोहराते हुए, वे कहते हैं कि हिंदुओं ने बौद्ध मंदिरों और विहारों को अपवित्र किया, और तथाकथित ब्राह्मणवादी आक्रमणकारियों द्वारा भिक्षुओं का सामूहिक नरसंहार किया गया। वे यह उल्लेख करना भूल जाते हैं कि बौद्ध स्मारकों को मुस्लिम आक्रमणकारियों और शासकों द्वारा नष्ट किया गया था। शंकराचार्य ने केवल वैदिक विचार का प्रचार किया जो अनेकों को प्रेरित करता है। यद्यपि उन्होंने बौद्ध विचारों और सिद्धांतों को चुनौती दी, उन्होंने ऐसा कठोर, खुले और स्वतंत्र विचार-विमर्श के माध्यम से किया - हिंसा के माध्यम से नहीं। यही सच्चे सत्य की खोज के लिए बौद्धिक वाद-विवाद की भारतीय परंपरा थी। भारत में बौद्ध संगठनों का उन्मूलन हिंदुओं द्वारा नहीं बल्कि विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा किया गया था। हिंदू और बौद्धों के बीच सामान्यतः शांतिपूर्ण संबंध रहे।

येंगडे ने घोषणा की है कि भारतीयों को बौद्ध धर्म में पुनः परिवर्तित करने के अंबेडकर के कार्य को आगे बढ़ाना उनका दायित्व है। वे बौद्ध धर्म की सच्ची भावना को दर्शाते हैं जब वे कहते हैं कि अपने उत्पीड़क को धर्म में परिवर्तित करना व्यापक संघ की संगति बनाने का एक अच्छा तरीका है। यदि येंगडे वास्तव में बौद्ध धर्म की आध्यात्मिकता को विश्वव्यापी स्तर पर फैलाना चाहते हैं, तो हम उनका पूरा समर्थन करेंगे। ऐसे आंदोलन में शामिल होना एक अद्भुत अनुभव होगा।

लेकिन जैसा कि हम अब देखेंगे, हार्वर्ड में रहते हुए उनकी सक्रियता बौद्ध सिद्धांतों के साथ शायद ही मेल खाती है: मार्क्सवादी द्वंद्ववाद बौद्ध मार्ग के साथ असंगत है! और यह बात अंबेडकर ने कही थी, जैसा कि हम अध्याय 6 में देखेंगे।

बुद्ध की प्रमुख शिक्षा में दो भाग शामिल थे: निदान और समाधान: बुद्ध ने अपने प्रसिद्ध चार आर्य सत्यों में मानव स्थिति का विश्लेषण किया

है। यह सूक्ष्म, गहन और परिष्कृत अंतर्दृष्टि है और येंगडे के उस क्रोधपूर्ण और विभाजनकारी सिद्धांत से बिल्कुल भिन्न है जो हिंदुओं को सभी सामाजिक समस्याओं का कारण बताता है। येंगडे चार आर्य सत्यों के परिप्रेक्ष्य से दुख की प्रकृति और उस दुख को दूर करने के साधनों को नहीं समझते हैं। इसलिए, वे बौद्ध धर्म का सतही रूप से उपयोग कर रहे हैं, केवल अपने सांस्कृतिक लाभ को छिपाने के लिए। उनकी समझ उनके अहंकार के स्तर से है, जबकि बौद्ध धर्म अहंकार का विखंडन करके चेतना की उच्च अवस्था को प्राप्त करता है।

बुद्ध के समाधान को आमतौर पर अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। यह मार्ग अहंकार से ऊपर उठकर स्वयं की चेतना के स्तर को उन्नत करने और फिर दूसरों को भी ऐसा करने में सहायता करने पर केंद्रित है। यह मार्क्सवादी द्वंद्ववाद के बिल्कुल विपरीत है, जो अन्य अहंकारों से संघर्ष करने का आह्वान करता है। येंगडे अहंकार के स्तर पर कार्य कर रहे हैं, जो प्रतिद्वंद्वी को नीचा दिखाकर सत्ता के लिए संघर्ष करने से प्रेरित है। उनका मार्ग बौद्ध धर्म के विपरीत एक क्रांति का आह्वान है। बुद्ध हमें अंतर्मन ले जाकर समस्या और समाधान दोनों को समझाते हैं। उनका मूलमंत्र यह है कि बेहतर मनुष्य एक बेहतर और अधिक जिम्मेदार समाज का निर्माण करेंगे। दूसरी ओर, येंगडे समस्या और समाधान दोनों को बाह्य रूप देते हैं। विडंबना यह है कि उनका सिद्धांत बौद्ध धर्म से मेल खाता है, जबकि उनका प्रतिवाद बौद्ध धर्म से टकराव पैदा करने के लिए बनाया गया है। जैसे-जैसे बातचीत बौद्ध धर्म की ओर बढ़ती है, येंगडे का बौद्ध होने का दावा झूठा साबित होने लगता है। विपश्यना (जिसे आम तौर पर ध्यान कहा जाता है) के साथ अपने संबंध को समझाने का उनका तरीका संतोषजनक नहीं है। आखिरकार, विपश्यना बुद्ध द्वारा सिखाई गई ध्यान की तकनीक है जो अब एक विश्वव्यापी आंदोलन है और बौद्धों के लिए

मूलभूत अभ्यास मानी जाती है।
लेकिन जब मेजबान ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने विपश्यना की है, तो वे असहज दिखे और धीरे से बोले: 'मैंने तीन साल पहले दस दिन का एक कोर्स किया था।' उनका अनुभव फलदायी नहीं रहा। उन्होंने कहा: 'ये शिक्षक हमेशा कहते हैं कि अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहो। मैं आलसी था और अभ्यास नहीं कर रहा था।'
ध्यान का अभ्यास करने वाला कोई भी व्यक्ति यह जानकर आश्चर्यचकित रह जाएगा कि वह इस साधना को कितना तुच्छ समझता है, जब वह स्वीकार करता है कि ध्यान करते समय, 'मेरे मन में यह विचार आया कि मेरे मुँह में बहुत अधिक लार है'। वह कहता है कि उसे ध्यान में विरक्ति करना और ध्यान कर पाना 'कठिन' लगा। वह निष्कर्ष निकालता है कि वह एक वर्ष से अधिक समय से विपश्यना करने के बारे में सोच रहा है। स्पष्ट रूप से, वह न तो ध्यान करने वाला है और न ही उसने बौद्ध परंपरा के अनुसार विपश्यना को उचित सम्मान दिया है।
ध्यान न करने वाला बौद्ध होना एक विरोधाभास है। यह आत्म-विरोधाभास है, क्योंकि जब तक व्यक्ति अहंकार के स्तर पर चेतना से संघर्ष करता रहता है, तब तक मुक्ति की ओर कोई सच्ची प्रगति संभव नहीं है। बौद्ध दृष्टिकोण से देखा जाए तो, येंगडे एक पहचान को जकड़ रहा है, अपने विरोधियों पर क्रोध प्रकट कर रहा है और पहचानों के बीच युद्ध का आह्वान कर रहा है। यह बौद्ध धर्म के मार्ग के विरुद्ध है।
इसके अलावा, वे यह गलत बयान देते हैं कि 'धम्म एक मौखिक परंपरा थी। इसे कभी लिखा नहीं गया।' तथ्य यह है कि मूल रूप से यह मौखिक था, लेकिन फिर पाली में लिखा गया, और उसके बाद संस्कृत में अनुवादित हुआ जहाँ इसे औपचारिक रूप दिया गया और व्यापक रूप से विकसित किया गया। वे इस तथ्य से अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं कि बौद्ध धर्म

ने अपने ग्रंथों को संस्कृत में लिखने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि संस्कृत में कठोरता का वह मानक मौजूद था जो किसी अन्य भाषा में उपलब्ध नहीं था। संस्कृत को दिया गया यह महत्व बौद्ध धर्म के इतिहासकारों को भलीभांति ज्ञात है।

इसके अलावा, वे कहते हैं: 'अंबेडकर द्वारा बुद्ध को अपना गुरु कहना, उस आत्मीयता से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।' लेकिन निश्चित रूप से उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि बौद्ध धर्म का एक मूल सिद्धांत किसी भी व्यक्तित्व को देवत्व प्रदान करने से बचना है।

अंततः, येंगडे साक्षात्कार में स्वीकार करते हैं: 'मैं बौद्ध धर्म का पालन नहीं करता। मैं शायद साल में एक बार मंदिर जाता हूँ। और मुझे यह भी नहीं पता कि मंदिर जाने के बाद क्या करना है।' दूसरे शब्दों में, बौद्ध होने का उनका दावा एक छल है। बौद्ध धर्म से उनका संबंध अन्य उद्देश्यों से प्रेरित प्रतीत होता है। और यह समझना आसान है कि अंबेडकर के उत्तराधिकारी के रूप में खुद को स्थापित करना हार्वर्ड में उनके करियर को कैसे आगे बढ़ाएगा।

वह अंबेडकर के उस सपने को साकार करना चाहते हैं जिसमें विभिन्न बौद्ध देशों का एक राजनीतिक संघ बनाने की बात कही गई थी, यानी एक ऐसा राजनीतिक गुट जो एक-दूसरे की रक्षा करे। लेकिन इस वैश्विक बौद्ध आंदोलन और एकीकरण को हासिल करने का उनका तरीका दलित पैंथर्स को बढ़ावा देना है, जिनके बारे में उनका कहना है कि वे अमेरिका के ब्लैक पैंथर्स की तरह हैं। उनका दावा है कि दलित पैंथर्स बौद्ध हैं और दलितों ने कभी हिंसा नहीं भड़काई। हालांकि वे अन्य समूहों के प्रति अधिक सहानुभूति विकसित करने की वकालत करते हैं, लेकिन व्यवहार में यह दलित पैंथर्स के उस आक्रामक मार्ग से भिन्न है जिसका वे स्वयं प्रतिनिधित्व करते हैं।

दलित चिरस्थायी पीड़ित के रूप में

येंगडे जाति पर आलोचनात्मक नस्ल सिद्धांत लागू करते हैं और जिसे वे आलोचनात्मक दलित सिद्धांत कहते हैं, उसे विकसित कर रहे हैं, जो पूर्वाग्रहों के गहरे कारणों की पड़ताल करके पूर्ववर्ती सिद्धांत को प्रतिस्थापित करेगा। इस संदर्भ में दलितों को चिरस्थायी पीड़ित के रूप में येंगडे की व्याख्या को समझना आवश्यक है।

क्रिटिकल रेस थ्योरी का मानना है कि श्वेत अमेरिकियों को प्राप्त विशेषाधिकार अमेरिकी संस्थागत संरचनाओं में इतनी गहराई से समाए हुए हैं कि ये पूर्वाग्रह अचेतन रूप से भी काम करते हैं। इसी तरह निम्न वर्ग का उत्पीड़न एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है। येंगडे ने इसी विचार को जाति पर लागू किया है। उनके विश्लेषण में ब्राह्मण श्वेत अमेरिकियों के समान हैं और दलित तथा अन्य निम्न जातियाँ अश्वेत अमेरिकियों के समान हैं। निम्नलिखित कथन उनके विचारों को स्पष्ट करते हैं:

जो संसाधन किसी ब्राह्मण के पास हैं, वे योग्यता के बल पर अर्जित नहीं किए गए हैं। वे लूटपाट और गुंडागर्दी से प्राप्त किए गए हैं।

कोई आपसे आपके पूर्वजों के पापों का प्रायश्चित करने के लिए नहीं कह रहा है। ... कई मायनों में, यथास्थिति बनाए रखकर और अधिकांश आबादी को परेशान करके आप अपने पूर्वजों के कर्मों का फल भोग रहे हैं।

दूसरे शब्दों में कहें तो, ब्राह्मण 'गुंडों' ने अपनी योग्यता के बल पर विशेषाधिकार अर्जित नहीं किए, बल्कि लूटपाट करके उन्हें जमा किया। इस तर्क का आधार यह है कि आज के ब्राह्मण केवल अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित समाज की उन संरचनाओं का लाभ उठा रहे हैं, जिनका उद्देश्य

विशेषाधिकारों को आगे बढ़ाना है। 'जनसंख्या के बहुमत' से उनका तात्पर्य दलितों से है, और उन्हें ब्राह्मणों द्वारा 'उत्पीड़ित' किया जा रहा है जो अपने विशेषाधिकारों को कायम रखते हैं।

निम्नलिखित अनुच्छेद उनके सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट करते हैं। वे ब्राह्मण जो अतीत की इन शोषणकारी संरचनाओं को स्वीकार करने में विफल रहते हैं और दलितों की मदद करने का दिखावा करने के लिए संरक्षणवादी कार्य करते रहते हैं, वे शोषण को बढ़ावा दे रहे हैं। वे भी 'जातिवादी व्यवस्था' का हिस्सा हैं।

जब तक हम आपके आस-पास मौजूद उन संरचनाओं को नहीं पहचानते, तब तक आप जातिवादी व्यवस्था का हिस्सा बने रहेंगे क्योंकि आपने अपने परोपकारी और दानशील तरीकों से धीरे-धीरे जातिवाद को बढ़ावा देने में बहुत सूक्ष्मता से योगदान दिया है।

इसलिए, जिसे हम परंपरा कहते हैं, वह स्वयं एक शोषणकारी संरचना है, जिसमें इसके सभी त्योहार और मूल्य शामिल हैं:

परंपरा जैसी कोई चीज नहीं होती। हमने इसे अपने मूल्यों को प्रदर्शित करने और त्योहारों जैसी चीजों को बाकी बहुसंख्यक लोगों पर थोपने के लिए बनाया है, और ये सब 'परंपरा' का हिस्सा बन जाते हैं।

वह नहीं चाहते कि लोग यह सोचें कि सकारात्मक कार्रवाई या कोटा प्रणाली दलितों पर कोई एहसान है। उनके अनुसार, दलितों ने समाज में उत्पादक भूमिका निभाई है जिसके लिए उन्हें उचित मुआवजे से वंचित रखा गया है। इसलिए, शैक्षिक सब्सिडी केवल उन्हें उनका हक वापस देना है।

दलित वास्तव में अपनी शिक्षा का खर्च स्वयं उठा रहे हैं। क्योंकि वे एक निश्चित आर्थिक योगदान देते हैं, जो राज्य के खजाने में जाता है और फिर राज्य उन्हें बदले में कुछ देता है। इस मामले में, कई बार राज्य उन्हें बदले

में कुछ नहीं देता। ... मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे देखें कि दलित हर साल राज्य के खजाने में कितना योगदान देते हैं और बदले में उन्हें कितना मिलता है।

अगले अध्याय में इतिहास के विभिन्न कालखंडों के दौरान दलितों के योगदान और आर्थिक स्थितियों की व्याख्या की जाएगी।

एक और मुद्दा जिस पर हमें आपत्ति है, वह येंगडे के वर्ग संबंधी दृष्टिकोण से संबंधित है। हालांकि हम दलितों और निचली जातियों की दुर्दशा के प्रति सहानुभूति रखते हैं, लेकिन जब वे इस बात पर जोर देते हैं कि जाति वर्ग के समान नहीं है, तो हमें यह बात समस्याग्रस्त लगती है। वर्ग को शिक्षा और आर्थिक सुधारों के माध्यम से बदला जा सकता है, जबकि जाति स्थायी होती है। वे लिखते हैं कि यह अंतर कर्म के सिद्धांत के कारण है।

जाति वर्ग से श्रेष्ठ है। ...श्रम शास्त्रों में वर्णित कर्म सिद्धांत से जुड़ा है, इसलिए इस संदर्भ में वे "अपना प्रायश्चित कर रहे हैं"। भारत में वर्गीय लोग मूल रूप से पूंजी के स्वामी ब्राह्मण और बनिया समूह हैं।

उनका कहना है कि पूंजी ब्राह्मणों और बनिया (व्यापारी) समूहों के स्वामित्व में है। दलितों और निचली जाति के लोगों को पूंजी से वंचित रखा जाता है क्योंकि कर्म सिद्धांत का इस्तेमाल यह दावा करने के लिए किया जाता है कि उनके पिछले जन्मों के बुरे कर्मों के कारण उन्हें निम्न स्थिति में जन्म लेना पड़ा। इसलिए, उनकी दुर्दशा को 'प्रायश्चित' के रूप में समझाया जाता है। जन्म आधारित भेदभाव का यह आध्यात्मिक औचित्य इसे वर्ग से अलग बनाता है, और इसलिए इसे जड़ से मिटाना असंभव है।

उनका कहना है कि इस दुर्व्यवहार का पैमाना भयावह है। वे कुछ आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, जिनमें कुछ संख्याएँ गंभीर अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होती हैं, ताकि उनकी बात को सनसनीखेज बनाया जा सके।

भारत में जातिवाद 1.35 अरब लोगों को प्रभावित करता है। यह 1 अरब लोगों को बुरी तरह प्रभावित करता है। यह 80 करोड़ लोगों को बुरी तरह प्रभावित करता है। यह 5 करोड़ लोगों की मानवीय गरिमा को गुलाम बनाता है। यह 3 करोड़ भारतीय अछूतों के लिए विनाश, लूटपाट, श्रम, गुलामी, बंधन, अनगिनत बलात्कार, नरसंहार, आगजनी, कारावास, पुलिस बर्बरता और नैतिक मूल्यों के हनन का प्रतीक है।

'भारत शायद एकमात्र ऐसा देश है जहाँ रंगभेद युग के गुलाम मौजूद हैं,' वह दावा करता है। उसके द्वारा उद्धृत आँकड़े, यदि सत्य मान लिए जाएँ, तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारत मानवाधिकारों के मामले में विश्व का सबसे बुरा दुःस्वप्न है।

2006 से 2016 के बीच दलितों के खिलाफ लगभग पांच लाख अत्याचार किए गए। यह एक ऐसा नरसंहार है जिसे हमने अपनी आँखों के सामने देखा है, फिर भी यह कोई नई घटना नहीं है। यह स्वतंत्रता के युग से ही होता आ रहा है, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर क्रूर नरसंहारों के साथ, फिर भी दलितों ने गृहयुद्ध नहीं छेड़ा है। उनके पास ऐसा करने के सभी कारण हैं।

दलितों के खिलाफ होने वाली यह सारी हिंसा 'हिंदू धार्मिक व्यवस्था' के नाम पर आती है। उनका कहना है:

हिंदू धार्मिक व्यवस्था द्वारा बहिष्कृत किए गए लोग, जिन्हें नीच, अपवित्र, जीवन के अयोग्य माना जाता था, ऐसे प्राणी जिनकी सार्वजनिक उपस्थिति मात्र से पूरे समुदाय पर हिंसा का प्रकोप मच जाता था।

अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए उन्होंने जिन तथ्यों का इस्तेमाल किया है, उनमें से कई स्पष्ट रूप से गलत हैं। उनका यह कहना गलत है कि भारत से उच्च जाति के लोग अमेरिका आकर अल्पसंख्यक होने के नाते आरक्षण का लाभ उठाते हैं। उनका यह कथन भी गलत है कि अमेरिकी

आरक्षण से उच्च जाति के भारतीयों को प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने में मदद मिलती है।

भारत में आरक्षण का विरोध करने वाले कई लोग यहाँ [अर्थात अमेरिका में] आरक्षण के लिए कतार में लग जाते हैं ताकि उन्हें आइवी लीग स्कूलों और अन्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश और अन्य नौकरियाँ मिल सकें, और यह बहुत ही विडंबनापूर्ण है।

येंगडे को अमेरिका में सकारात्मक कार्रवाई की नीति की गलत समझ है: आप विविधता कोटा के लिए आवेदन क्यों कर रहे हैं जो कि आरक्षण है? आप पदोन्नति चाहते हैं, आप जोर-शोर से चिल्लाते हैं कि 'मैं अश्वेत हूं, मैं भारतीय हूं, मुझे तरक्की नहीं मिलती क्योंकि श्वेत लोग हावी हैं' और फिर आप पदोन्नति चाहते हैं। तो, उन्हें यहां आरक्षण के आधार पर पदोन्नति मिलती है। उन्हें यहां आरक्षण के आधार पर नौकरी मिलती है, उन्हें यहां आरक्षण के आधार पर प्रवेश मिलता है, फिर भी वे यही बात भारत पर लागू होते हुए नहीं देखते।

अमेरिका में आज प्रचलित सकारात्मक कार्रवाई और भारत में लागू आरक्षण नीतियों में अंतर है। परंपरागत रूप से, अमेरिका ने कोटा का विरोध किया है; लेकिन अब संस्थानों की जवाबदेही तय करने के लिए मापदंड निर्धारित करने की मांग करने वालों के दबाव के कारण अमेरिका पर दबाव बढ़ रहा है। फिर भी, अमेरिका में कोटा या आरक्षण का व्यापक उपयोग उस तरह से नहीं देखा जाता है जिस तरह से भारत में इसे आक्रामक रूप से लागू किया जाता है।

येंगडे की यह शिकायत बिल्कुल सही है कि भारत की आधुनिक शिक्षा प्रणाली बेहद अपर्याप्त रही है – 'भारत की 85% आबादी को शिक्षा से वंचित रखा गया, और इसके अलावा, शेष 10% को अपूर्ण शिक्षा मिली, पूर्ण शिक्षा नहीं।' इससे आबादी का एक बड़ा हिस्सा उपयोगी काम करने

और जीविका कमाने में असमर्थ हो गया। यहाँ धर्मपाल के लेखन का उल्लेख करना आवश्यक है, जिन्होंने दर्शाया है कि 1800 के दशक के मध्य तक, भारतीय जनता को उनके व्यवसायों के अनुरूप अच्छी शिक्षा मिल रही थी। ये आँकड़े ब्रिटिश सर्वेक्षणों में अच्छी तरह से दर्ज हैं और अगले अध्याय में इनकी चर्चा की गई है।

इसके बाद, शिक्षा पर ब्रिटिश नियंत्रण के चलते अंग्रेज़ी संस्कृति से प्रभावित भारतीयों का एक वर्ग तैयार हुआ जो ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था में निम्न स्तर के प्रशासनिक कार्यों के लिए उपयुक्त था। भारत के बड़े उद्योग (जैसे कपड़ा और इस्पात) ध्वस्त हो गए और ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति ने उन पर कब्ज़ा कर लिया। विश्व की सबसे बड़ी निर्यात अर्थव्यवस्था होने से भारत मात्र ब्रिटिश वस्तुओं का उपभोक्ता बनकर रह गया। येंगडे इन सब बातों पर मौन हैं।

आर्थिक उत्पीड़न के अलावा, येंगडे बताते हैं कि दलितों को अपमान का भी सामना करना पड़ता है। उन पर चुप रहने और उच्च जातियों का सामना न करने का दबाव रहता है। उनका मानना है कि दलितों का डिज़ाइनर कपड़े पहनना, घुड़सवारी करना या यहाँ तक कि मूंछें रखना भी भारत में अस्वीकार्य है। वे आगे कहते हैं कि हार्वर्ड में उनकी उच्च उपलब्धि को कुछ लोग घृणित मानते हैं।

येंगडे कहते हैं कि भारत में दलितों को पहचान और वोट बैंक की राजनीति के लिए दोषी ठहराया जा रहा है, जबकि उच्च जातियां भी उनका शोषण कर रही हैं: 'क्या आपको नहीं लगता कि ब्राह्मण, ठाकुर, मराठा और बनिया पहचान की राजनीति का हिस्सा हैं? वे हैं। तो आइए जातिगत राजनीति पर भी यही नजरिया लागू करें।' वे सही कह रहे हैं। पहचान और वोट बैंक की राजनीति भारतीय लोकतंत्र में एक आम बात बन गई है और यही विखंडन और विभाजन की ओर बढ़ने का सबसे बड़ा

कारण है। कोई भी समुदाय इससे ऊपर नहीं उठ पाया है; और एक-दूसरे को दोषी ठहराना रचनात्मक नहीं है।

येंगडे मार्क्सवादी द्वंद्ववाद के नजरिए से देखते हैं, इसलिए उनके लिए यह एक शून्य-योग का खेल है। ब्राह्मणों की निंदा की जानी चाहिए और उन्हें सत्ता से बेदखल किया जाना चाहिए ताकि उनकी संरचनाएं ध्वस्त हो सकें। जब तक ऐसा नहीं होता, दलित स्वतंत्र नहीं हो सकते।

विभिन्न कंपनियों के सीईओ और बोर्ड सदस्यों में से 44% ब्राह्मण हैं। हमें इस पर सवाल उठाने की जरूरत है कि आखिर कैसे एक अल्पसंख्यक समुदाय इतना अधिक प्रभाव और शक्ति रखता है।

आखिर ऐसा क्यों है कि केवल ब्राह्मण ही धनी मंदिरों में पुजारी बने रहते हैं और शोषित धन की इतनी बड़ी मात्रा पर विराजमान रहते हैं? यह तो श्रमिक वर्ग, किसानों का धन है जिस पर वे विराजमान हैं।

पहला आंकड़ा इस मायने में सही है कि शीर्ष कॉर्पोरेट पदों पर ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व अधिक है; इस पर बहस हो सकती है कि क्या यह पूरी तरह से योग्यता पर आधारित है या इसमें उनके विशेषाधिकार और प्रभाव का भी योगदान है। लेकिन दूसरा दावा गलत है। भारत भर में बड़ी संख्या में मंदिरों का संचालन गैर-ब्राह्मण पुजारी करते हैं। मंदिरों की संपत्ति की बात करें तो, इसका अधिकांश हिस्सा सरकार के हाथों में है क्योंकि बड़े हिंदू मंदिरों के कोष पर सरकार का नियंत्रण है। यह हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है: चर्चों, मस्जिदों और गुरुद्वारों के विपरीत, हिंदू मंदिर अंग्रेजों द्वारा हिंदुओं के खिलाफ लागू किए गए भेदभावपूर्ण कानूनों के बाद से ही सरकार द्वारा संचालित होते रहे हैं, जिन्हें कभी निरस्त नहीं किया गया है।

उनका यह कथन भी गलत है कि आरक्षण के मामले में 'आपके ब्राह्मण साथी आपकी सीटें ले रहे हैं। दलित या आदिवासी आपकी सीटें नहीं ले

रहे हैं।' दलितों और निचली जातियों के लिए कोटा वास्तव में अधिक है और यह बहस का विषय है।

उपरोक्त कथन में सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसमें उसी प्रकार की यहूदी-विरोधी मानसिकता का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण यहूदियों को कई क्षेत्रों से खदेड़ दिया गया था, जब उन पर यह आरोप लगाया गया था कि वे एक समृद्ध अल्पसंख्यक हैं जो जर्मनी के गरीब मूल निवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं। ब्राह्मणों के प्रति इस प्रकार का दुष्प्रचार अत्यंत खतरनाक है।

येंगडे का उत्पीड़न का विश्लेषण इस घोषणा के साथ समाप्त होता है कि ब्राह्मण अपराधी हैं। वे कहते हैं:

अगर कोई समुदाय बार-बार अपराध करता है, तो आप उस समुदाय को क्या कहेंगे? ...अफ्रीकी-अमेरिकी संघर्ष में, उन्हें सीधे-सीधे श्वेत वर्चस्ववादी कहा जाता है। ...बताइए, हम उन्हें 'ब्राह्मण वर्चस्ववादी' कब कहेंगे? ...मेरे नज़रिए से ये अपराधी जातियाँ हैं। मैं इन्हें किसी और तरह से नहीं पहचानूँगा; इन्होंने मेरे समुदाय पर अपराध किया है, और ये मेरे लिए अपराधी हैं। अगर ठाकुरों ने अपराध किया है, तो वे मेरे लिए अपराधी जाति हैं। अब उन्हें कलंक मिटाने और मेरी नज़र में बने रहने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी।

वह ब्राह्मणों को अपराधी जाति के रूप में बदनाम करना चाहता है। उसने बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया है कि ब्राह्मणों को ही निशाना बनाया जाना चाहिए, दूसरों को नहीं, यहाँ तक कि अन्य उच्च जातियों को भी नहीं। हिंदू धर्म पर हमला करने का उसका तरीका इस प्रकार है:

ब्राह्मण शास्त्र जाति व्यवस्था को मान्यता देते हैं। उनका दावा है कि ऋग्वेद का एक भजन, पुरुष सूक्त, 'इस महापुरुष, ब्रह्मा की पवित्र आत्मा' है और इसने जन्म के अनुसार संसार को व्यवस्थित किया है।

दमन के सभी रूप इसी पदानुक्रमिक संरचना पर आधारित हैं, जिसमें ब्राह्मण सर्वोच्च स्थान पर बने रहते हैं। सभी पितृसत्तात्मक व्यवस्था ब्राह्मणवादी है, और यह न केवल महिलाओं बल्कि गरीबों को भी गुलाम बनाती है।

ब्राह्मण अपनी सर्वोच्च स्थिति को बरकरार रखने के लिए सभी तरीकों और रचनात्मक विचारों का उपयोग करेंगे।

उनसे यह सवाल किया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के नाम से जाने जाने वाले समुदायों को क्यों दोषी नहीं ठहराया जाता, जबकि दलितों के खिलाफ हिंसा की कई घटनाएं ओबीसी द्वारा ही की जाती हैं। वे केवल ब्राह्मणों को ही क्यों निशाना बनाते हैं? उनका जवाब पूरी तरह से ब्राह्मण-विरोधी है।

ओबीसी हिंसा के लिए ज़िम्मेदार हैं, लेकिन वे एक ढाँचे के तहत हिंसा थोप रहे हैं। जाति के बिना, ओबीसी इंसान हैं, ब्राह्मण इंसान हैं, दलित इंसान हैं। जाति के साथ कोई ब्राह्मण बन जाता है, कोई ओबीसी बन जाता है। ओबीसी मूल रूप से ब्राह्मणवाद की सेवक जातियाँ हैं जहाँ वे सेवा करना पसंद करते हैं क्योंकि यह ढाँचा उन्हें सतही श्रेष्ठता प्रदान करता है। यदि कोई ओबीसी अपराध कर रहा है, तो इसका कारण यह है कि उससे ऊपर का कोई व्यक्ति उस हिंसा को अंजाम देने का अधिकार दे रहा है, और इसके लिए उसे आध्यात्मिक, राजनीतिक और विभिन्न तरीकों से मुआवजा दिया जाता है, जैसा कि हम आज के भारत में देखते हैं।

इसका अर्थ यह है कि ब्राह्मण उन अपराधों के लिए भी जिम्मेदार हैं जो दूसरों द्वारा किए गए हैं क्योंकि उनके द्वारा कथित तौर पर स्थापित जाति व्यवस्था ही तीसरे पक्ष द्वारा किए गए सभी अपराधों का कारण बन रही है।

वह जिससे बात कर रहा होता है, उसके अनुसार विरोधाभासी बयान देता है। उदाहरण के लिए, एक ओर वह कहता है, 'दलित कोई दबी हुई श्रेणी नहीं है... यह उत्पीड़क को चुनौती देना नहीं है।' लेकिन वास्तव में, जैसा कि पिछले पृष्ठों में दर्शाया गया है, वह न केवल उत्पीड़क को चुनौती दे रहा है, बल्कि ब्राह्मणों के खिलाफ सबसे घिनौने प्रकार का प्रतिगामी भेदभाव भी कर रहा है। और तो और, वह कई झूठे आरोप, अतिरंजित और एकतरफा दावे कर रहा है।

येंगडे दलितों के लिए मुआवजे की आवश्यकता का दावा करने के लिए अश्वेत अमेरिकियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा और तर्क को उधार लेते हैं:

क्षतिपूर्ति एक ऐसा तरीका है जिससे उत्पीड़क को यह बताया जा सकता है कि आप भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब यदि आप नुकसान पहुंचाना जारी रखते हैं, तो आपको और अधिक क्षतिपूर्ति करनी होगी। यह केवल भौतिक लाभ नहीं है, बल्कि सबसे पहले यह स्वीकार करना है कि हां, हमने दलितों की हत्याओं और बलात्कारों से लाभ उठाया है और आज भी लाभ उठा रहे हैं।

वह चाहते हैं कि भारतीय यह स्वीकार करें कि प्रमुख राज्यों में खेतों में काम करने वाले अधिकांश दलित भूमिहीन हैं और 'उनकी भूमिहीनता सामंती व्यवस्था में मौजूद उत्पीड़क जातियों को हिंसा करने का अवसर देती है'। उनके अनुसार, आगे का रास्ता यह होगा कि उच्च जातियां 'अपने विशेषाधिकारों का त्याग करें। हजारों वर्षों से आपके पास जो भी जमीन है, उसे दान कर दें और उसका पुनर्वितरण करें'।

दिलचस्प बात यह है कि उपरोक्त चर्चा में एक पैनलिस्ट ने बताया कि भारतीय संविधान में अतीत में हुए अत्याचारों के लिए मुआवजे का प्रावधान है (अंबेडकर की बदौलत), जबकि अमेरिकी संविधान में ऐसा

नहीं है। लेकिन वह इस तरह के तर्क को समझने में असमर्थ हैं। पश्चिमी संस्थानों के समर्थन से, येंगडे का मानना है कि भारतीय करदाताओं को सिपाहियों की एक बड़ी सेना तैयार करने में और भी अधिक खर्च करना चाहिए। जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए, वह मांग करते हैं: दलितों और आदिवासी छात्रों के लिए निर्धारित निधि से प्रति सेमेस्टर 10,000 छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों में भेजना एक अच्छा विचार होगा। दलितों को भौतिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाएं।

वह दलितों को बड़े पैमाने पर धन का वितरण चाहता है:

भारत में लगभग 70 प्रतिशत दलित मजदूर भूमिहीन हैं। यदि उन्हें भूमि दी जाए, तो वे उसकी अच्छी देखभाल करेंगे और अधिक उपज देंगे। और मेरे विचार से यह भूमि के राष्ट्रीयकरण से ही संभव हो सकता है। एक बार ऐसा हो जाने पर, हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जो कम से कम समानता की ओर थोड़ा सा प्रयास करेगा। सकारात्मक कार्रवाई मात्र एक नीति है, हमें अपनी संस्थाओं का लोकतंत्रीकरण करने के लिए और भी आक्रामक नीतियों की आवश्यकता होगी।

दलितों के अधिकारों के लिए वे जिस तत्परता से आवाज़ उठाते हैं, उसके बावजूद उनकी सफलताओं का वे स्वागत नहीं करते। अमेरिका में आयोजित एक पैनल चर्चा के दौरान, कुछ पैनलिस्टों ने सुझाव दिया कि अमेरिकी बिजनेस स्कूल दलितों को सामाजिक उन्नति के लिए आवश्यक कौशल सिखा सकते हैं, जो भारत लौटने पर उनके लिए सहायक होंगे। इससे येंगडे असहज हो गए, विशेष रूप से तब जब एक पैनलिस्ट ने उल्लेख किया कि भारत में एक दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स है जो दलित उद्यमियों को पूंजी उपलब्ध कराता है। येंगडे ने तुरंत घोषणा की कि दलित उद्यमियों के समूह का प्रमुख 'आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) के

दक्षिणपंथी हेरफेर का शिकार' है और दलितों का प्रतिनिधित्व करने देना खतरनाक है। वे इस 'ब्राह्मणवादी वर्चस्व' की स्थापना के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराते हैं और दलितों की सहायता के लिए उनके द्वारा की गई किसी भी पहल की निंदा करते हैं।

स्पष्ट रूप से, येंगडे उन दलितों को प्राथमिकता देते हैं जिन्हें वे 'पीड़ित' के रूप में पेश कर सकें, न कि उन दलितों को जिन्होंने योग्यता और उद्यमशीलता के बल पर व्यवस्था में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ी हैं। जातिगत असमानताओं पर भारत द्वारा की गई सभी प्रगति को वे अपने विभाजनकारी भाषणों से नकारते हैं। राम नाथ कोविंद, जिन्होंने जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया, एक दलित हैं। इसके अलावा, वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू स्वयं संथाल हैं, जो तथाकथित अनुसूचित जनजातियों में से एक हैं। येंगडे दलितों, विशेषकर महिलाओं को स्वच्छ जल, स्वच्छता, मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं, आवास आदि जैसी जीवन की आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में हुई अभूतपूर्व प्रगति को भी नजरअंदाज करते हैं।

उन्होंने अन्यत्र लिखा है:

दक्षिणपंथी अंबेडकर को अपना बताकर अपना दावा करना चाहते हैं क्योंकि दलित ब्राह्मणवादी विचारधारा के लिए एक संभावित चुनौती हैं। अगर दक्षिणपंथी उनसे लड़ नहीं सकते, तो वे उन्हें आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। दक्षिणपंथियों ने अपने दुश्मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया है क्योंकि वे दलितों के मुखर अधिकारों को दबा नहीं सकते।

दूसरे शब्दों में कहें तो, हिंदू ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जो उन्हें स्वीकार्य हो। उनके अनुसार, किसी भी समाधान के लिए हिंदू धर्म का पूर्ण और अंतिम विघटन ही आवश्यक शर्त प्रतीत होती है।

वह प्रतिस्पर्धी दलित नेताओं को बर्दाश्त नहीं करते, विशेषकर उन नेताओं को जो दलितों के आर्थिक जीवन को रचनात्मक तरीकों से बेहतर बनाना चाहते हैं। और यदि कोई उच्च जाति का विद्वान दलितों पर चर्चा करता है, तो सहानुभूति जताते हुए भी, वह अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं। उनका तर्क है: 'गैर-दलितों द्वारा किए गए दलित अध्ययनों की अधिक गहन जांच की आवश्यकता है।'

ब्राह्मण पितृसत्ता

येंगडे का कहना है कि आर्य पुरुष अकेले घोड़ों पर सवार होकर आए थे, उनके साथ कोई महिला नहीं थी। परिणामस्वरूप, 'आर्य आक्रमण महिलाओं के अलगाव पर आधारित था, और यहाँ महिलाओं को समान नहीं माना जाता था।' ब्राह्मणों ने आर्य परंपराओं को जारी रखा, जिससे सारी समस्याएँ उत्पन्न हुईं। यह हास्यास्पद है और भारत के बारे में बुनियादी जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसे स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन 'हार्वर्ड' का दर्जा मिलने के कारण येंगडे इस तरह की बेतुकी बातों से बच निकलते हैं।

येंगडे का एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को हिंदू नियमों से वैधता मिलती है जो ब्राह्मणों को सर्वोच्च दर्जा प्रदान करते हैं। यह एक ऐसी अनकही समस्या है जो हम सभी के भीतर व्याप्त है। ... ब्राह्मणवाद पितृसत्ता के बराबर है और पितृसत्ता ब्राह्मणवाद के बराबर है। इनमें कोई अंतर नहीं है। वे समझाते हैं:

यदि महिलाओं और दलितों का दमन नहीं किया जाता, तो जातिवादी समाज कार्य नहीं कर सकता। जातिवादी समाज की ऑक्सीजन दलितों और महिलाओं की मृत्यु है।[64] इसका मूल वेदों में मिलता है: 'ऋग्वेद काल में, महिलाएं पहली दास थीं।'[65]

और हिंदू धर्म क्या है? उनका कहना है कि यह महज ब्राह्मण पितृसत्ता की अभिव्यक्ति है:

जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो हम ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को छिपा लेते हैं। यदि आपको हिंदू धर्म के बारे में बात करनी ही है, तो ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को शुरुआती बिंदु के रूप में लेना ही होगा। इसी आधार पर विभिन्न हिंदू धर्मों की सभ्यताएँ निर्मित हुई हैं।

उनका कहना है कि ब्राह्मणों का मूल स्वभाव ही पुरुष को स्त्री-विरोधी बनाना है। बचपन से ही लड़कों को एक शक्तिशाली पुरुष बनने की शिक्षा दी जाती है। जो पुरुष न हो, उसे समाज के लिए अभिशाप माना जाता है। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पाँच संस्थाओं के माध्यम से समाज पर थोपी जाती है: परिवार, माता-पिता, विवाह, प्रजनन और महिलाओं पर यौन नियंत्रण। उनका कहना है कि ब्राह्मणवादी विशेषाधिकार को उजागर करने के किसी भी प्रयास का विरोध किया जाता है।[70] सुशिक्षित और आत्मविश्वासी महिलाओं को खतरा माना जाता है।

एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी महिला ब्राह्मणवादी (sic) वैदिक व्यवस्था के लिए परमाणु बम के समान है।

उच्च वर्ग की ब्राह्मण महिलाओं को ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को स्वीकार करने के लिए विवश किया जाता था। 'यदि वह विरोध करती, तो उसे जाकर अपने पति की जलती हुई चिता में कूदना पड़ता था।' विरोध करने का अर्थ था स्वयं पर यातना सहना।

ब्राह्मणों द्वारा स्त्री की रक्षा करने का बहाना उसकी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि उसकी हर गतिविधि पर नज़र रखने के लिए होता है। उनका कहना है कि स्त्री को निगरानी में रखा जाता है और उस पर पहरा दिया जाता है ताकि वह ऐसे बच्चे पैदा न कर सके जो जाति व्यवस्था के अनुरूप न हों। सती प्रथा और विधवापन जैसी प्रथाएँ भी स्त्री को नियंत्रित करने के लिए

ही बनाई गई थीं। यही कारण है कि विधवा को अपना सिर मुंडवाना पड़ता है, एक विशेष प्रकार की साड़ी पहननी पड़ती है और समाज से बहिष्कृत होकर जीना पड़ता है। 'जब तक वह जीवित रहती है, उसका जीवन नरक बन जाता है।'

उनका कहना है कि महिलाओं को अज्ञानी और असुरक्षित बनाए रखने के लिए उन्हें वेदों तक पहुंच से वंचित रखा जाता है।

मनुस्मृति एक प्रभावी सिद्धांत प्रस्तुत करती है कि महिलाएं वेदों तक पहुंच नहीं सकतीं क्योंकि वे जन्म से पापी हैं और यहीं अध्याय समाप्त हो जाता है। ... यह एक अत्यंत विषमलैंगिक, यौन-प्रधान प्रवचन बन जाता है जो महिलाओं की स्वायत्तता की स्वतंत्रता को सीमित करता है।

ब्राह्मण प्रधान समाज कई महिलाओं की हत्याओं का कारण बनता है, न केवल दलित महिलाओं की, बल्कि सभी महिलाओं की:

अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी करता था, तो संभावना यही रहती थी कि उसने पहली पत्नी की हत्या कर दी हो। और इन हत्याओं को आत्महत्या का नाम दे दिया जाता था - खाना बनाते समय जल गई या कुएं से पानी भरने गई और पैर फिसल गया। ... केवल दलितों की ही बात नहीं, पतियों द्वारा की गई किसी भी महिला की हत्या को प्राकृतिक आपदा या थकान के कारण आत्महत्या बता दिया जाता था।

येंगडे का मानना है कि स्त्री का चरम सुख पुरुष की चरम सुख शक्ति के लिए खतरा है। वास्तव में, जो कोई भी स्त्री की यौन इच्छाओं और शरीर की स्वतंत्रता को दबाता है, वह ब्राह्मणवादी पितृसत्ता में भागीदार है, चाहे वह किसी भी लिंग, जाति, वर्ग या धर्म का हो। स्त्री को असहाय महसूस कराने के लिए, उनका कहना है कि भारतीय पुरुषों ने यह अनिवार्यता बनाई कि पत्नी को अगले सात जन्मों तक उन्हें अपने पति के रूप में चाहना चाहिए। येंगडे के पुनर्जन्म के कर्म सिद्धांत की समझ के अनुसार

यह आवश्यक है।
उनका तर्क है कि जातिगत पदानुक्रम को बनाए रखने के लिए, महिलाओं की भूमिका केवल प्रजनन इकाई तक सीमित है; वे जातिगत शुद्धता को बनाए रखने के लिए बनी फैक्ट्रियां हैं। उनका दावा है कि मनुस्मृति, रामायण और अन्य तथाकथित आध्यात्मिक ग्रंथों में वर्णित दंडों और कानूनों के माध्यम से इसे लागू किया गया है। येंगडे कहते हैं कि मनुस्मृति देश का कानून बन गया। इसने महिलाओं को पशुओं के समान स्तर पर ला दिया।
इसीलिए अंबेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि यदि यह नया देश महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं दे सकता, तो मैं किसी भी ऐसी चीज का हिस्सा बनने से इनकार करता हूं जो सदियों पुराने मानदंडों को दोहराती हो।
येंगडे परिवार व्यवस्था को जातिगत दुर्व्यवहार को संरक्षित करने वाली एक कुटिल संरचना के रूप में भी आलोचना करती हैं। 'एकविवाही परिवार के ढांचे से बाहर काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को वेश्या माना जाता है'।
जब कोई किसी विशेष भारतीय परिवार में जन्म लेता है जो किसी विशेष धर्म का पालन करता है, तो वास्तव में वह एक ऐसे परिवार में जन्म लेता है जो व्यवहार को निर्धारित करता है। सर्वनाम पहले से ही तय होते हैं, और एक महिला की भूमिका पहले से ही निर्धारित होती है। आप उन नियमों और मानदंडों को तोड़ नहीं सकते और यदि आप चुनौती देते हैं, तो आपको कटु वाणी वाली महिला माना जाता है।
यह शोषणकारी व्यवस्था स्वतः ही कायम रहती है क्योंकि माता-पिता इसे सिखाते हैं और युवाओं को उनकी स्वतंत्र पसंद से वंचित करते हैं।
अमेरिका में रहने वाले भारतीय प्रवासी माता-पिता यह तय करते हैं कि

उनके बच्चे किन लोगों के साथ उठें-बैठें और किस तरह की जीवनशैली अपनाएं। उनका मानना है कि 'माता-पिता प्रभावी रूप से अपने बच्चों के लिए जातिगत पुलिस बन जाते हैं।'

जब माता-पिता अपने बच्चों की मदद करते हैं, तो वे जातिगत विशेषाधिकार का दुरुपयोग कर रहे होते हैं और अपराधियों को जन्म दे रहे होते हैं, वे कहते हैं। येंगडे भारतीय युवाओं से अपने माता-पिता को अस्वीकार करने और जातिवाद, पितृसत्ता, समलैंगिकता-विरोधी भावना, ट्रांसजेंडर-विरोधी भावना, विदेशियों से नफरत और भारतीय संस्कृति में निहित अन्य सभी प्रकार के अमानवीय मूल्यों से छुटकारा पाने की अपील करते हैं। वे कहते हैं:

माता-पिता ही पहले जातिवादी शिक्षक होते हैं। वे अपने बच्चे के मन को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब युवा मुझसे पूछते हैं कि जाति से कैसे छुटकारा पाया जाए, तो मैं उन्हें अपने जातिवादी माता-पिता से संबंध तोड़ने की सलाह देता हूं।

इसलिए, वह न केवल सामाजिक व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहता है, बल्कि परिवारों को तोड़ना और पारिवारिक संरचनाओं को नष्ट करना भी चाहता है। इस तरह का आंदोलन क्रांति भी नहीं है; यह सरासर विनाश है और सांस्कृतिक नरसंहार के समान है। वह अन्य धर्मों में मौजूद इसी तरह की समस्याओं के लिए ब्राह्मणों को दोषी ठहराता है। उसका कहना है कि ब्राह्मणों का प्रभाव इतना गंभीर रहा है कि ये समस्याएं इस्लाम और ईसाई धर्म सहित सभी धर्मों में समाहित हो गईं।

येंगडे का मानना है कि विवाह माता-पिता द्वारा 'यौन बाजार' में सौदेबाजी करने का एक तरीका है। बच्चों को विवाह के लिए तैयार किया जाता है। विवाह का यह अति-पूंजीवादी उत्सव इतना व्यापक है कि लोग उस विशेष दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। यही कारण है कि भारत में एक

महिला को संतान न होने पर ससुराल वालों और कुछ मामलों में माता-पिता द्वारा भी प्रताड़ित किया जाता है। उसे भगवान से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करनी पड़ती है। ब्राह्मण पितृसत्ता उच्च जाति के पुरुषों में इस सारी चिंता का कारण बनती है और उन्हें निम्न जाति के पुरुषों और सभी महिलाओं को नियंत्रित करने के लिए विवश करती है।

उनका दावा है कि मनुस्मृति में परिवारों को जाति की शुद्धता बनाए रखने की आवश्यकता थी और कई मामलों में, उन्हें आपस में ही विवाह करना और संतान उत्पन्न करना पड़ता था। मनु ने महिलाओं को मात्र संपत्ति बना दिया, मानो वे गुलाम हों जिनका लेन-देन किया जा सके। येंगडे के अनुसार, क्योंकि स्त्री को पशु के समान माना जाता है, यह हिंसा को बढ़ावा देता है और 'इसीलिए हर हफ्ते 21 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होता है'।

महिलाओं की इस दयनीय स्थिति को देखते हुए, अन्य सभी परियोजनाओं को दरकिनार कर देना चाहिए और मुख्य लक्ष्य महिलाओं को 'ब्राह्मणवादी हिंसा' से मुक्त कराना होना चाहिए। लेकिन केवल वही और उनका आंदोलन ही इस मुक्ति के कार्य को अंजाम देने में सक्षम हैं। उच्च जाति की महिला विद्वान जो ऐसे मुद्दों में शामिल होती हैं, वह आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है; वह उन पर अपने पुरुषों की रक्षा के लिए पश्चिम से नारीवादी सिद्धांत चुराने का आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि वे अपने चारों ओर फैले ब्राह्मणवादी पितृसत्ता पर शायद ही कभी ध्यान देती हैं, क्योंकि यह रोजमर्रा के कार्यों में सामान्य हो गया है।

येंगडे महिलाओं के मुद्दों पर इस्लाम के दमनकारी भूमिका को भी अनदेखा करते हैं या कम आंकते हैं। वे महिलाओं के साथ इस्लाम के संरचनात्मक व्यवहार, बहुविवाह और निकाह सहित विवाह की प्रथाओं, हलाल और मुस्लिम पुरुषों द्वारा खुलेआम प्रदर्शित और गर्वित अति-

पुरुषत्व के मामले में इस्लाम को खुली छूट देते हैं। ऐसा भी प्रतीत नहीं होता कि वे अपने अश्वेत अमेरिकी सहयोगियों को यह बताने में सहज हैं कि अफ्रीकी समाजों के इतिहास में महिलाओं के दमन और अंतर-जातीय हिंसा की अनेक संरचनाएं शामिल हैं।

येंगडे के तीखे हमले में ब्राह्मणों पर दलित और आदिवासी महिलाओं की हत्या का जश्न मनाने के लिए मिथक गढ़ने का आरोप लगाया गया है। होली का त्योहार इसका एक उदाहरण है। उनके अनुसार, यह होलिका की कहानी को दर्शाता है, जो एक आदिवासी महिला है जिसे हिंदू ग्रंथों में दलितों की तरह असुर या राक्षस के रूप में चित्रित किया गया है। उनका कहना है कि ये ग्रंथ उच्च जाति के लोगों को देवता के रूप में दर्शाते हैं, जबकि हिंदू उत्पीड़न के खिलाफ विरोध करने वालों को राक्षस माना जाता है। यही होली को असुर की मृत्यु के उत्सव के रूप में मनाने का मिथक है। येंगडे ने ये सब बिना किसी सबूत के दावा किया है।

एक और सिद्धांत जो उन्होंने सीधे मिशनरी प्रचार से लिया है, वह यह है कि मंदिर की देवदासियाँ यौन दासियाँ थीं। उनके अनुसार, हिंदू पुजारी लगातार यौन संबंध बनाने की कोशिश करते थे, और इसलिए उन्होंने देवदासी नामक यौन दासता की एक व्यवस्था बनाई। उनके अनुसार, देव का अर्थ भगवान और दासी का अर्थ भगवान की महिला दासी है। उनका दावा है कि ब्राह्मणों को भगवान के समान माना जाता है, और दलितों को गुलाम बनाकर उनकी पाँच-छह साल की बच्चियों को भगवान की सेवा के बहाने मंदिरों में दासी बनने के लिए भेजा जाता है। उनके अनुसार, यह एक जबरन प्रथा थी। यह मूल रूप से महिलाओं का लगातार बलात्कार करने और उन्हें हिंदू देवताओं के मनोरंजन के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की एक व्यवस्था थी, जिसके बदले में देवता आशीर्वाद देते थे। यही कारण है कि उनका दावा है कि हिंदू दलित महिलाओं को नग्न अवस्था में

घुमाते हैं या उनसे पुरुषों को प्रसन्न करने वाले सभी प्रकार के कार्य करवाते हैं। लेकिन उनके अनुसार, उच्च जाति के पुरुष किसी उच्च जाति की महिला द्वारा दलित पुरुष के बलात्कार को सहन नहीं कर सकते, क्योंकि वे अपनी मर्दानगी को लेकर असुरक्षित हैं।
नीचे दिया गया आरेख हिंदू धर्म को समाप्त करने के येंगडे के अडिग रुख के पीछे की मुख्य मान्यताओं को दर्शाता है।

Suraj Yengde's Formula for Attacking Hinduism

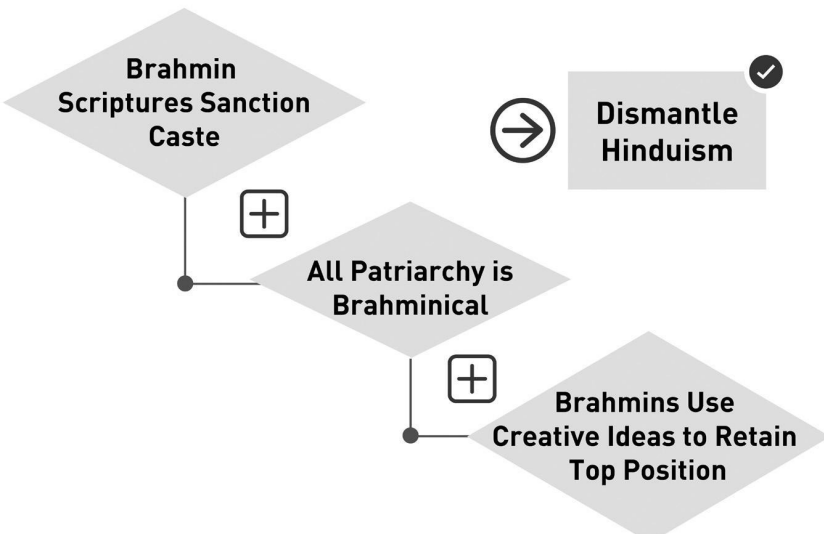

जातिगत वैश्वीकरण और चौथी दुनिया
येंगडे बताते हैं कि अमेरिका में भारतीय मूल के चार लाख लोग रहते हैं, जिनमें लगभग दो लाख भारतीय छात्र शामिल हैं। कुशल श्रम बल के लिए एच-1बी वीजा प्राप्त करने में भारतीय शीर्ष पर हैं। इसके अलावा, बड़ी संख्या में भारतीयों को ग्रीन कार्ड मिल रहा है या वे अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं। वे सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, कमला हैरिस,

बॉबी जिंदल आदि जैसे कई प्रभावशाली लोगों का जिक्र करते हैं। वे कहते हैं कि अमेरिका को यह नहीं पता है, और वे उन्हें यह समझाना चाहते हैं, कि वे अपने साथ जातिगत संरचनाएं लेकर आते हैं।

येंगडे का अमेरिका में भारतीय प्रवासियों के बारे में स्पष्ट और सुस्पष्ट दृष्टिकोण है, और वे उनकी सफलता का श्रेय उनकी जातिगत अभिजात्यता और श्वेत अमेरिकियों से निकटता को देते हैं।

अमेरिका में भारतीय मूल के इतने सारे लोग इतनी तरक्की क्यों कर रहे हैं? ... कई बड़े उद्योगों के दिग्गज दक्षिण एशिया के भारतीय मूल के लोग हैं। इतने सारे भारतीय डॉक्टर या दंत चिकित्सक अमेरिकी बीमारियों का इलाज क्यों करते हैं? और संस्कृति, साहित्य और मीडिया उद्योगों में भी इतने सारे भारतीय लोग क्यों हैं? आखिर वह कौन सा रहस्य है जो इसे संभव बनाता है? इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें जातिगत परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता है। अमेरिकी सपने के शिखर पर बैठे कई भारतीय मुख्य रूप से भारतीय समाज की प्रभावशाली जातियों से आते हैं। उनका पालन-पोषण, तौर-तरीके, कुशलता, सोचने का तरीका और गर्व जताने का तरीका, संस्कृति में विश्वास, प्रभावशाली दमनकारी स्थिति, निम्नतम जाति के श्रम तक आसान पहुंच और 'आगे बढ़कर जीतने' का आत्मविश्वास, ये सभी गुण अमेरिकी धरती पर उनके 'रिश्तेदारों' में भी पाए जाते हैं। भारतीयों का अमेरिका आना प्रभावशाली जातियों की घर वापसी है। कई भारतीय जो मानवीय मूल्यों से ऊपर श्रेष्ठता, घृणा और लाभ की राजनीति में लिप्त हैं, उन्हें रिपब्लिकन पार्टी में स्वाभाविक स्थान मिलता है।

विडंबना यह है कि कई भारतीय अमेरिकी वास्तव में उदारवादी हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी और प्रगतिशील विचारों का असमान रूप से समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि भारतीय प्रवासी जातिगत उत्पीड़न के अपने

गंदे काले रहस्य को हाथियों और योग की आकर्षक छवियों के पीछे छिपा रहे हैं, जबकि जाति को चर्चा के विषय के रूप में दरकिनार कर रहे हैं। वे समझाते हैं:

जब लोग भारत छोड़कर जाते हैं और एक तरह से भारत के राजदूत बन जाते हैं, तो वे भारत को सड़कों पर हाथियों, योग, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं की घिसी-पिटी छवि के रूप में बढ़ावा देते हैं। ... भारत में होने वाली हर चीज़ का मूल तत्व होने के बावजूद, जाति का मुद्दा उठाया या उस पर सवाल उठाए जाने का कोई आसार नहीं दिखता। ज़्यादातर समय, जाति को पूर्वी दृष्टिकोण से देखा जाता है और इसे श्रम विभाजन के भारत के अपने रचनात्मक तरीके के रूप में समझा जाता है। यह अपने वास्तविक स्वरूप में सामने नहीं आती - यानी जातिगत भेदभाव के रूप में।

नवउदारवाद इसके लिए जिम्मेदार कारकों में से एक है क्योंकि यह वैश्विक अभिजात वर्ग को अपना शोषण जारी रखने में सक्षम बनाता है। वैश्विक बहुपक्षीय संस्थानों द्वारा शोषण की गहरी संरचनाओं से निपटा नहीं गया है।

विश्व बैंक और आईएमएफ अपनी शोषणकारी नीतियां थोपते हैं, यही कारण है कि प्रत्येक देश का अभिजात वर्ग निर्लज्जतापूर्वक और व्यापक आक्रामकता के साथ सत्ता पर काबिज रहता है। जाति, सामाजिक नियमों की तरह, समाज में अंतर्निहित सांस्कृतिक संस्थाओं के माध्यम से समाजों पर हावी रहती है। इस प्रकार, संरचना और संस्कृतियां समाजों पर हावी रहती हैं, जिन्हें पश्चिमी मानवाधिकार व्यवस्था में आसानी से पवित्र मानकर रखा गया है, और इसके द्वारा उत्पन्न उत्पीड़न को नजरअंदाज किया गया है।

उनके अनुसार समस्या यह है कि भारत ने स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र के लिए

उचित दिशा निर्धारित करने का सुनहरा अवसर खो दिया। अंग्रेजों की जगह लेने वाले अभिजात वर्ग वे भारतीय थे जिनका अंग्रेजों से घनिष्ठ संबंध था, और

...जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे संस्थानों में पढ़े थे, जो अमेरिका गए थे। ये वे लोग थे जो परंपरागत रूप से सत्ता के पदों पर आसीन थे, जैसे भारत में ब्राह्मण समुदाय या बनिया समुदाय। गांधी और नेहरू ब्राह्मण-बनिया प्रतिनिधित्व के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। जब अंग्रेजों ने शासन छोड़ा, तो इन कुलीन भारतीय समुदायों ने उनसे सत्ता की बागडोर संभाली। यही कारण है कि हम आज भी अशांति देखते हैं।

हालांकि उनकी बातों में काफी सच्चाई है, फिर भी येंगडे अमेरिकी प्रतिस्पर्धा के चरम पर भारतीय अमेरिकियों की उपलब्धियों का श्रेय किसी भी तरह से देने से इनकार करते हैं। वे उनकी उपलब्धियों को भारत में मिले 'वंशानुगत' जातिगत विशेषाधिकार का नाम देकर उनका महत्व कम आंकते हैं, जो अमेरिका, जर्मनी और अन्य जगहों पर श्वेत विशेषाधिकार के समान है।

उच्च जाति से होने के वंशानुगत गुण व्यक्ति को फलने-फूलने के लिए आवश्यक गुण प्रदान करते हैं। उच्च जाति का आप्रवासी, भले ही गरीब हो, फिर भी जाति-पूंजीवादी प्रतिस्पर्धा के इस कुटिल युग में आवश्यक सांस्कृतिक गुणों, सामाजिक विश्वास निर्माण और सामाजिक एवं व्यावसायिक तकनीकों से लाभान्वित होता है। ... उच्च जाति के आप्रवासी समूह अमेरिका में फलते-फूलते और उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। अमेरिकी समाज में ऐसे अलिखित नियम हैं जो जातिवाद का समर्थन और उसे मान्यता देने वाले समूहों के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देते हैं। उच्च जातियों के लिए जातिवादी समाज की नींव को न हिलाना आसान है, जो निम्नतम समूह को अछूत और अदृश्य बनाने पर आधारित है। प्रत्येक

उच्च-मध्यम वर्गीय, गैर-अमेरिकी लहजे वाले परिवार में ... कोई भी अमेरिकी जाति व्यवस्था की वैधता में उच्च जातियों के अटूट विश्वास को देख सकता है। वे कड़ी मेहनत और योग्यता-आधारित उन्नति के मूल्यों को दृढ़ता से धारण करते हैं, और निम्नतम जातियों को आलसी और अयोग्य बताकर उनका अपमान करते हैं। कुछ दशकों से अधिक समय तक महत्वपूर्ण उपस्थिति के अभाव में, उच्च जाति के अप्रवासी अन्य समाजों के अपने बिछड़े हुए रिश्तेदारों—आर्यन जर्मनी, श्वेत अमेरिका या ब्राह्मण भारत—के साथ गठबंधन कर लेते हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि आर्यों को भारत के हिंदू कानूनों और इसकी क्रूर जाति व्यवस्था में एक आध्यात्मिक मातृभूमि मिली।

दूसरे शब्दों में, वे समझाते हैं, 'जाति उतनी ही अमेरिकी है जितनी श्वेत वर्चस्व।' यह वही जाति व्यवस्था है जो विभिन्न देशों में अपनाई गई है। येंगडे बताते हैं कि 1800 के दशक में भी कुछ विद्वानों ने जाति को केवल हिंदू समाज तक सीमित न रखकर एक वैश्विक सामाजिक घटना के रूप में समझाया था। लेकिन विभिन्न देशों के सभी बहिष्कृत लोगों को एकजुट करने के लिए कोई वैश्विक आंदोलन संभव नहीं हो सका। अगली शताब्दी में, अंबेडकर ने भी कई देशों के बहिष्कृत लोगों से संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन इस पहल से कोई स्थायी परिणाम नहीं निकला। वे बताते हैं कि हाल ही में कुछ अंतर-राष्ट्रीय बैठकें हुई हैं जिनमें वे सामूहिक कार्रवाई के नेता के रूप में उभर रहे हैं।

उनके लिए आगे का रास्ता परोपकारियों को यह समझाने में है कि हार्वर्ड को दुनिया भर के निम्न जाति के विचारकों को एकजुट करने का केंद्र बनाया जाए। वे खेद व्यक्त करते हैं कि हार्वर्ड में अभी तक उनकी मुलाकात नाइजीरिया, जापान, सेनेगल, माली, मॉरिटानिया, केन्या, सोमालिया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, पूर्वी और पश्चिमी यूरोप, नेपाल,

पाकिस्तान, श्रीलंका, इज़राइल, अफगानिस्तान आदि देशों के उत्पीड़ित लोगों से नहीं हुई है।
उनका कहना है कि उनकी अगली परियोजना दुनिया भर में उन समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना है जिन्हें हजारों वर्षों से हाशिए पर रखा गया है। शासक वर्ग मौजूदा ढाँचे को बरकरार रखने के लिए सकारात्मक कार्रवाई जैसे आंशिक समाधानों का उपयोग करते हैं। इसमें बदलाव होना चाहिए।
मैं एक चौथी दुनिया, एक विचार-मंथन मंच, एक ऐसी अवधारणा की कल्पना कर रहा हूँ जो पहली, दूसरी और तीसरी दुनिया से परे है। यह चौथी दुनिया उन लोगों को भी समाहित करती है जिन्होंने तीसरी दुनिया की परियोजना में कभी भाग नहीं लिया क्योंकि वह एक विशेष प्रकार के अभिजात्यवाद को बढ़ावा देती है। इन हाशिए पर पड़े लोगों को आमंत्रित किया जाएगा कि वे आपस में बातचीत करें और इस बारे में सोचें कि वे दुनिया में कैसे जीना चाहते हैं, खुद को कैसे देखना चाहते हैं। वर्तमान में, संसाधनों की अनुपलब्धता और पहुँच की कमी के कारण, वे एक-दूसरे से बात नहीं कर सकते।
वह हार्वर्ड में ऐसा व्यक्ति बनना चाहता है जो 'चौथी दुनिया' के दबे-कुचले लोगों को एकजुट करे:
घोर गरीबी और प्रतिनिधित्व की कमी के कारण, दुनिया के कई अछूत आज भी अपने समाजों में मुख्यधारा की धारणाओं को चुनौती देने में असमर्थ हैं। अपनी यात्राओं और शोध के माध्यम से, मैंने यह भी पाया कि उत्तर-औपनिवेशिक विद्वत्ता और सक्रियता मूल समाजों के अभिजात वर्ग द्वारा अपने द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न को छिपाने और जनता का ध्यान बाहरी 'अन्य' - मरणासन्न औपनिवेशिक राज्य - की ओर मोड़ने की एक और रणनीति थी।

विश्वभर में एक ऐसा वर्ग मौजूद है जिसे हम 'चौथी दुनिया' कह सकते हैं, जहां मानवाधिकारों और सामाजिक एवं आर्थिक न्याय से संबंधित प्रमुख चर्चाओं और बहसों से उपेक्षित लोग रहते हैं। आज इन वंचित समूहों की पहचान करना और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता नेटवर्क स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है।

चौथी दुनिया के लिए एक थिंकटैंक बनाने का उनका दृष्टिकोण महत्वाकांक्षी है और इस पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है: मुख्यधारा की धारणाओं को चुनौती देने के उद्देश्य से समर्पित एक संगठन, एक फोर्थ वर्ल्ड थिंक-टैंक, इस लक्ष्य को पूरा कर सकता है। यह दुनिया भर के सबसे कमजोर समूहों को हाशिए पर धकेले जाने के अपने अनुभवों पर चर्चा करने और उन्हें साझा करने तथा भेदभाव और उत्पीड़न से लड़ने के तरीके सीखने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। यह एकजुटता के कार्य को जमीनी स्तर तक ले जाएगा और दुनिया भर के वंचित समूहों के बीच ज्ञान और सक्रियता की संरचनाओं के निर्माण में मदद करेगा। उत्पीड़ित जातियों को विश्व के भविष्य के लिए एक सामूहिक समतावादी दृष्टिकोण विकसित करने के लिए एक मंच पर आने की आवश्यकता है। एक साथ आना और सामूहिक रूप से काम करना ही एकमात्र तरीका है जिससे हम उत्पीड़न के बंधनों को तोड़ सकते हैं।

विश्वभर में कई मंचों पर, येंगडे इस तरह के संगठन को वित्त पोषण प्रदान करने के लिए अपनी दलीलें दे रहे हैं, और बार-बार पूछते हैं: 'क्या विश्वविद्यालय अमेरिका और दुनिया भर में जाति पर शोध को वित्त पोषित करेंगे?'

हालांकि हार्वर्ड एक विशिष्ट संस्थान है, फिर भी उन्हें यह एक उपयोगी आधार लगता है क्योंकि यहाँ उनकी मुलाकात अन्य देशों के समान पृष्ठभूमि वाले बुद्धिजीवियों से होती है। ‘मानवता के प्रति उनका प्रेम आशा

का सच्चा प्रमाण है। उन्होंने वास्तव में समुदाय के साथ मिलकर काम किया है, और उनकी विद्वत्ता अत्याधुनिक है। जब मैं इन प्रोफेसरों से बात करता हूँ, तो हम वास्तव में उस दायरे से बाहर होते हैं।' वे वंचित समुदायों के अन्य लोगों के लिए एक उदाहरण स्थापित करना चाहते हैं।

मैं लोगों को हार्वर्ड में होने के अनुभव के बारे में बताना चाहता हूँ और उन्हें आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हार्वर्ड में आने वाली अगली पीढ़ी सामाजिक रूप से जागरूक, व्यावहारिक रूप से जानकार और विशेष रूप से न केवल विद्वता से बल्कि उन संरचनाओं को बदलने की इच्छा से भी लैस होगी जिनसे वे अब तक जूझते रहे हैं।

येंगडे अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकी अकादमिक जगत में अपनी पैठ बना रहे हैं और इसका उपयोग जाति के इतिहास पर आधारित साहित्य का एक संग्रह तैयार करने के लिए करना चाहते हैं। यह एक मानक संदर्भ पुस्तकालय बन जाएगा और अमेरिकी अकादमिक जगत के समर्थन से उनके विश्वदृष्टिकोण को वैधता प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एक रिपोर्ट में कहा गया है:

येंगडे ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे 1820 के दशक से चली आ रही वैश्विक साहित्य की समृद्ध परंपरा को पुनर्जीवित करेंगे, जिसमें अश्वेत और दलित लोगों पर अत्याचार करने वाली व्यवस्थाओं का इतिहास दर्ज है। उन्होंने कहा, "मैं भविष्य के लिए एक संग्रह बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं।" उन्होंने जेम्स मैक्यून स्मिथ, फ्रेडरिक डगलस और चार्ल्स समनर को अमेरिकी ऐतिहासिक हस्तियों के रूप में उद्धृत किया जिन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई थी। येंगडे ने कहा कि डगलस ने यह स्वीकार किया था कि गुलामी ने सीधे तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय जाति व्यवस्था को जन्म दिया था।

इस तरह की वैश्विक स्तर की अभिलेखीय परियोजना से अश्वेत अमेरिकियों की दलित विद्वानों, जैसे कि उनके द्वारा पढ़े जाने की आवश्यकता पूरी होगी। उनका कहना है कि जब तक वे ऐसा नहीं करेंगे, तब तक वे जाति को नहीं समझ पाएंगे और इस प्रकार अमेरिकी नस्लवाद को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे।

उदाहरण के लिए, वे बताते हैं कि ब्लैक पैंथर्स दलितों से अनभिज्ञ थे, और इसीलिए अश्वेत अमेरिकियों को शिक्षित करने के लिए उनका अश्वेत-दलित आंदोलन आवश्यक है। अज्ञानता का एक और उदाहरण वे इस ओर इशारा करते हैं कि अश्वेत अमेरिकी कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति के रूप में मनाते हैं, जबकि उन्हें यह पता होना चाहिए कि वह आधी ब्राह्मण हैं। आगे बढ़ने का रास्ता दलित अभिलेखागार बनाना है ताकि आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित किया जा सके, और वे इस वैश्विक परियोजना की देखरेख करना चाहते हैं।

वह ऐसे आंदोलनों के नकारात्मक प्रभाव पर विचार नहीं करता जो स्थानीय समुदायों में आवश्यक मुद्दों पर ध्यान देने की क्षमता को बुरी तरह से कम कर सकते हैं, जबकि इन मुद्दों का समाधान स्थानीय स्तर पर ही संभव है। उत्पीड़न और पीड़ित होने की भावना को इस तरह सामान्यीकृत करने से मुद्दों का इतना अधिक महत्व कम हो जाएगा और बलि का बकरा बनाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा कि कोई भी उन विशिष्ट मुद्दों को गंभीरता से नहीं सुलझाएगा जिन पर रचनात्मक लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए काम करने की आवश्यकता है। इसके बजाय, लोग केवल दुनिया की नाइंसाफी का रोड़ा रोएंगे और एक ऐसी क्रांति का आह्वान करेंगे जो कभी होगी ही नहीं। इस प्रक्रिया में, वह एक मसीहा की तरह व्यवहार करने लगेगा और समाज को सहारा देने वाली पारंपरिक संस्थाएं कमजोर या नष्ट हो जाएंगी। यह खतरनाक और विनाशकारी है।

येंगडे भारत को तोड़ने वाली ताकतों की कई प्रचार गतिविधियों को भी मजबूत कर रहे हैं। जाति से जुड़े मामलों में अलगाववादी सोच रखने वाले सिख अब तक अनुपस्थित रहे हैं। लेकिन वे उन्हें अपने बड़े गठबंधन में शामिल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, वे चेतना नामक एक कनाडाई संगठन में अक्सर अतिथि के रूप में जाते हैं, जिसका संचालन मुख्य रूप से सिखों द्वारा किया जाता है। चेतना स्वयं को इस प्रकार वर्णित करती है:
इसकी स्थापना 1999 में वैश्विक स्तर पर जाति-आधारित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्राथमिक उद्देश्य से की गई थी। यह संवादों, चर्चाओं, प्रस्तुतियों और सेमिनारों के माध्यम से जातिविहीन, सम्मानजनक और समावेशी समुदायों के निर्माण के लाभों को बढ़ावा देता है। चेतना के सदस्य भारत में मानवाधिकारों के महारथी बाबासाहेब डॉ. बी. आर. अंबेडकर से प्रेरणा लेते हैं। इसका डॉ. हरि शर्मा फाउंडेशन, साइमन फ्रेजर विश्वविद्यालय (एसएफयू) के मानविकी संस्थान और ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय (यूबीसी) के विभिन्न विभागों के साथ मजबूत सहयोग है। इस सहयोग ने 2016 से डॉ. अंबेडकर स्मृति व्याख्यानों का आयोजन और संचालन किया है।
तीसरे विश्व परियोजना और अधीनस्थ परियोजना जैसे पूर्व आंदोलनों से परिचित पाठक यह सोचेंगे कि इस चौथे विश्व परियोजना में नया और अलग क्या है। ऐसा लगता है कि अब दुनिया के दबे-कुचले लोगों के बीच बेहतर समन्वय है और नेताओं की एक नई पीढ़ी सामने आई है, इसीलिए इस परियोजना को नया नाम दिया गया है। लेकिन शिकायतों का मूल स्वरूप वही है।

पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए महिलाओं की लड़ाई

येंगडे को दलितों के हिमायतियों के बीच बाज़ार हिस्सेदारी के लिए आंतरिक संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। इक्वालिटी लैब्स की थेनमोझी साउंडराराजन, हार्वर्ड के दलितों के सर्वोपरि नेता सूरज येंगडे को उन्हीं के गढ़ में चुनौती देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने हार्वर्ड को कुछ अन्य विश्वविद्यालयों की तरह जाति को 'संरक्षित श्रेणी' के रूप में शामिल करने के लिए मना कर उन्हें मात दे दी है।

आउटलुक इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, येंगडे ने इक्वालिटी लैब्स पर अपने कठिन परिश्रम का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है: 'हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के वरिष्ठ फेलो और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दलितों की सबसे प्रभावशाली आवाज डॉ. सूरज येंगडे ने कहा कि उन्हें इस बारे में सूचित नहीं किया गया था।' येंगडे स्पष्ट रूप से नाराज थे: 'हार्वर्ड परिसर में एकमात्र गर्वित अंबेडकरवादी को आप कैसे बाहर कर सकते हैं, जो लंबे समय से सक्रिय है और जाति-संवेदनशील नीतियों के लिए पैरवी कर रहा है?' उन्होंने हार्वर्ड के इस कदम को 'सवर्णों और शातिर गैर सरकारी संगठनों (संभवत: इक्वालिटी लैब्स का जिक्र करते हुए) द्वारा अमेरिका में अंबेडकरवादियों के कठिन परिश्रम का दुरुपयोग करने का एक क्लासिक मामला' बताया।

सौंदराजन और येंगडे उत्पीड़ितों के बीच एक-दूसरे से होड़ कर रही हैं। दोनों ही दलितों के अधिकारों के लिए काम करने वाले उस छोटे से उद्योग में शीर्ष स्थान हासिल करने की होड़ में हैं, जो पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वालों को भारी अनुदान और परामर्श शुल्क प्रदान करता है।

हार्वर्ड द्वारा लिए गए इस निर्णय से जो असली मुद्दा उठता है, वह यह है कि यदि दलितों पर हो रहा अत्याचार परिसर में इतना महत्वपूर्ण मुद्दा था, तो इसके मुखर समर्थक सूरज येंगडे को हार्वर्ड के बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा क्यों दरकिनार कर दिया गया?

आक्रामकता की पुनर्परिभाषा

येंगडे के शब्दों, विचारों और गतिविधियों में एक प्रकार की हिंसा झलकती है, जो मानवाधिकारों, सामाजिक समावेश और उत्थान के नाम पर आक्रामकता और विनाश को जायज़ ठहराने वाले एक नए वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करती प्रतीत होती है। चाहे अपनाई गई रणनीति कितनी भी छलपूर्ण हो या झूठ का प्रदर्शन कितना भी बेशर्मी भरा हो, यह समान विचारधारा वाले लोगों को आकर्षित करता है। और इस समूह के कई लोगों के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए कोई भी तरीका जायज़ है।

6. एक प्रतिक्रिया: भारतीय सामाजिक संगठन का इतिहास

परिचय

पूर्ववर्ती अध्यायों में जाति व्यवस्था पर आलोचनात्मक नस्ल सिद्धांत के अनुप्रयोग और भारत को तोड़ने वाली शक्ति के रूप में इसके रूपांतरण का परिचय दिया गया था। यह अध्याय इन मुद्दों और हमारी प्रतिक्रियाओं को समेकित करता है और कहीं अधिक विस्तृत एवं व्यवस्थित विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

इसका उद्देश्य भारतीय सामाजिक संगठन के इतिहास पर एक स्वतंत्र प्रस्तुति के रूप में भी कार्य करना है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, फिर भी हमें कोई ऐसा व्यापक अध्ययन नहीं मिला है जो क्रिटिकल रेस थ्योरी के समर्थकों द्वारा किए गए दावों की विस्तृत श्रृंखला का जवाब दे सके। यह अध्याय इस जटिल विषय पर संतुलित चर्चा के लिए साक्ष्य-

आधारित दावे प्रस्तुत करके इस कमी को पूरा करने का प्रयास करता है। हमारा उद्देश्य एक सर्वांगीण स्वस्थ बहस को आमंत्रित करना है।

इस विषय पर गलतफहमियों का एक कारण वर्ण और जाति शब्दों का लगातार गलत अनुवाद करके उन्हें जाति के रूप में देखना है। जाति की शब्दावली और अवधारणा यूरोपियों द्वारा आयात की गई थी और उनके मन में इसका अर्थ नस्लों का एक पदानुक्रम था। परिणामस्वरूप, इस ढांचे का उपयोग वर्ण और जाति को शोषणकारी व्यवस्थाओं के रूप में चित्रित करने के लिए किया जाने लगा। वर्ण व्यवस्था की तुलना पश्चिम में प्रचलित दास प्रथा या दासता जैसी व्यवस्थाओं से भी की जाने लगी। इस प्रकार वर्ण और जाति को भारत की वर्तमान कई सामाजिक समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया गया।

हम वर्तमान समय के संदर्भ में जाति शब्द का प्रयोग करेंगे और यूरोपीय सामाजिक अभिनिर्माण से पहले के कालखंडों के लिए वर्ण-जाति शब्द का प्रयोग करेंगे, जिसने एक गतिशील व्यवस्था को जाति में परिवर्तित कर स्थिर कर दिया।

भारतीय समाज की रूपरेखा तैयार करने में इस त्रुटि का गंभीर परिणाम निम्नलिखित है: हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में वर्ण और जाति का व्यापक रूप से उल्लेख होने के कारण, विद्वानों ने तीन प्रमुख गलतियाँ की हैं: भारत की सामाजिक संरचना को पिछले हजारों वर्षों से और भारतीय सामाजिक समूहों की विविधता में स्थिर माना जाता रहा है।

आज की तमाम सामाजिक समस्याओं का दोष प्राचीन काल की उत्पत्ति पर मढ़ दिया गया है। भारतीय समाज को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए वैदिक या हिंदू धर्म को जिम्मेदार ठहराया गया है।

भारत के लंबे इतिहास में एक बार नहीं बल्कि बार-बार घटी भीषण

उथल-पुथल को नजरअंदाज कर दिया गया है या उनके प्रभाव को ध्यान में रखे बिना ही उन पर पर्दा डाल दिया गया है।

वर्ण जाति को नस्लवाद के रूप में चित्रित करना हिंदू धर्म को भंग करने के राजनीतिक आंदोलनों में एक शक्तिशाली हथियार बन गया है। यदि नस्लवाद हिंदू धर्म से अविभाज्य है - जैसा कि दावा किया जाता है - तो एक समझदार व्यक्ति के रूप में, हम सभी को मिलकर हिंदू धर्म को ही समाप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि समाज को इस बुराई से मुक्ति मिल सके।

इस चर्चा में बहुत कुछ दांव पर लगा है। इसलिए, प्राचीन काल से लेकर अब तक भारतीय सामाजिक गतिशीलता की प्रकृति को ठीक से समझना महत्वपूर्ण है। यह अध्याय बताता है कि कैसे पारंपरिक भारतीय समाज विभिन्न कालों और विभिन्न प्रभावों के तहत विकसित हुआ, और यह विकास नवीनतम सामाजिक निर्माण तक जारी है।

यह उल्लेखनीय है कि पूर्व के पश्चिमी मानवविज्ञानी और दार्शनिकों ने भारत की वर्ण-जाति संरचनाओं के बारे में सकारात्मक मत व्यक्त किए थे। उनमें से कई ने लिखा कि अनेक आक्रमणों, अकाल, क्रांतियों, सामाजिक उथल-पुथल और विदेशी धर्मों के आक्रमणकारियों द्वारा विजय के बावजूद भारत के अस्तित्व का कारण काफी हद तक ये लचीली सामाजिक संरचनाएं थीं। यह बताया गया कि वर्ण-जाति ने हिंदुओं को इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के आक्रामक अभियानों का विरोध करने में भी सक्षम बनाया। उदाहरण के लिए, उन्नीसवीं सदी के फ्रांसीसी मिशनरी अब्बे डुबोइस, जिन्होंने भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे, ने स्वीकार किया कि वर्ण-जाति व्यवस्था भारत को बर्बरता से बचाने के लिए जिम्मेदार थी। उन्होंने कहा कि इसने एक जिम्मेदार सरकार प्रदान की, निरंकुशता को

रोका और विदेशी शासन के अधीन भी स्वदेशी कला और संस्कृति को संरक्षित रखा।

वर्ण और जाति के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक विभिन्न विविध सामाजिक समूहों को एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत करना रहा है जिसमें समुदाय सहयोग करते हैं, लेन-देन करते हैं, बातचीत करते हैं, विकसित होते हैं और अनुकूलन करते हैं। इससे सदियों तक गांवों को स्थिरता मिली और उन्हें स्वतंत्र और आत्मनिर्भर इकाइयों के रूप में कार्य करने में सहायता मिली। इसने प्रत्येक जातीय, सामाजिक, धार्मिक या व्यावसायिक समूह को अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखते हुए सामाजिक समग्रता के एक भाग के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाया। वर्ण या जाति के धनी सदस्य गरीब सदस्यों की सहायता करते थे और उन्हें आवश्यक सुरक्षा प्रदान करते थे। इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का अभाव भी हुआ, जो कई समाजों में कमजोरों के शोषण का मूल कारण है। एक स्वस्थ समाज को कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता होती है, और वर्ण व्यक्तियों की प्राकृतिक विविधता पर आधारित श्रम विभाजन था। यह भारत की विविधता में स्पष्ट है जो आज भी काफी हद तक संरक्षित है: भाषाओं, देवी-देवताओं और पूजा-पाठ के तरीकों, खान-पान की आदतों, संस्कृति, मूल्य प्रणालियों, परिवार और जीवन शैली में।

इन वर्णनों के विपरीत, प्राचीन वर्ण-जाति व्यवस्था को वर्तमान में शूद्रों और वर्ण व्यवस्था से बाहर माने जाने वाले लोगों के शोषण की जाति व्यवस्था के रूप में चित्रित किया जाता है। हालांकि, जैसा कि हम आगे समझाएंगे, ऐतिहासिक प्रमाण इस तरह की एकतरफा तस्वीर पेश नहीं करते हैं।

आज जाति को लेकर चल रही बड़ी बहस निम्नलिखित प्रश्नों के इर्द-गिर्द

घूमती है:
क्या हिंदू धर्म के लिए जाति एक आवश्यक शर्त है – यानी, क्या हिंदू होने के लिए जाति से बचा जा सकता है?
क्या हिंदू धर्म के लिए जाति एक पर्याप्त शर्त है – यानी, क्या जाति का पालन करने से व्यक्ति स्वतः ही हिंदू बन जाता है?
क्या वर्ण-जाति व्यवस्था का कोई ऐसा रूप है जो आधुनिक लोकतंत्र और पूंजीवाद के अनुकूल हो, या ये दोनों मूल रूप से एक दूसरे के विपरीत हैं? दूसरे शब्दों में, क्या हिंदू को पश्चिम में आत्मसात होने के लिए जाति व्यवस्था को त्यागना होगा, या क्या वर्ण-जाति को इस प्रकार संशोधित किया जा सकता है कि वह भारत की अपनी सामाजिक व्यवस्था के रूप में कार्य करे, जिसमें व्यक्तिगत स्तर पर स्वतंत्रता हो?
क्या प्राचीन वैदिक समाज में जाति व्यवस्था मौजूद थी? भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का प्रवेश कब और क्यों हुआ? सदियों से जाति व्यवस्था का विकास कैसे हुआ और इसके क्या कारण थे?
क्या जातिगत भेदभाव इतना लचीला है कि शिक्षा और आर्थिक उन्नति से इसका समाधान हो सके, या यह जन्म-आधारित और स्थिर है, जो कि अधिक मजबूत और पार पाना कठिन है? और जन्म-आधारित जाति व्यवस्था के अभाव में, क्या पश्चिमी समाजों ने व्यापक वर्ग और धन असमानताओं को दूर करने में सफलता प्राप्त की है? क्या पश्चिम इस समस्या के समाधान के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जन्म-आधारित धन उत्तराधिकार को समाप्त करने के लिए तैयार होगा?
क्या जाति व्यवस्था केवल अपमानजनक है, या केवल सकारात्मक है, या इसमें अच्छे और बुरे दोनों गुण मौजूद हैं?
आज जातिगत उत्पीड़न कितना गंभीर है? इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं और प्रगति रिपोर्ट क्या है?

पश्चिम में कार्यरत दलित कार्यकर्ता कौन हैं? उनकी स्थिति क्या है, उन्हें कौन समर्थन देता है और वैश्विक स्तर पर उनका वर्तमान प्रभाव क्या है?
जैसा कि हम देखेंगे, भारतीय समाज अत्यंत विविधतापूर्ण, गतिशील और निरंतर विकसित होता रहा है। किसी एक ढांचे को समय के साथ लगातार लागू नहीं किया जा सकता है, और एक निश्चित और मानक दृष्टिकोण मान लेना भ्रामक है।
आधुनिक जाति और सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन करने वाले विद्वान आमतौर पर धर्मशास्त्रों नामक विशाल ग्रंथों को अपने मुख्य ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं, जिनमें जाति संरचनाओं को संहिताबद्ध किया गया था। ये ग्रंथ कई लेखकों द्वारा कई शताब्दियों की अवधि में लिखे गए थे। आइए धर्मशास्त्रों में कही गई बातों पर एक संक्षिप्त नज़र डालें।
धर्मशास्त्रों का सबसे व्यापक अध्ययन संस्कृत विद्वान पी.वी. केन ने अपने बहु-खंडीय ग्रंथ 'धर्मशास्त्रों का इतिहास' में किया था, जो लगभग आधी सदी पहले प्रकाशित हुआ था। उनके शोध से प्राप्त कुछ प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:
आज जिसे जाति व्यवस्था कहा जाता है, उसकी उत्पत्ति का श्रेय किसी एक स्रोत को देना असंभव है। भारत में सामाजिक संरचनाओं को आकार देने और उनमें बदलाव लाने में अनेक प्रवाहों और जटिल अंतःक्रियाओं का योगदान रहा है।
आज की प्रचलित जाति व्यवस्था और प्राचीन एवं मध्यकालीन धर्मशास्त्रों में वर्ण-जाति के बारे में प्रचलित अवधारणाओं में बहुत बड़ा अंतर है।
धर्मशास्त्रों में कई कथन लाक्षणिक और प्रतीकात्मक हैं, और कई श्लोक रहस्यमय हैं।
विभिन्न ग्रंथों के बीच ही नहीं, बल्कि कभी-कभी एक ही ग्रंथ के भीतर

भी विरोधाभास पाए जाते हैं। यह समस्या इस तथ्य से और भी बढ़ जाती है कि संस्कृत शब्दों के अक्सर कई अर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए, वर्ण का अर्थ 'रंग' भी हो सकता है, लेकिन हाल ही में विद्वानों द्वारा नस्लीय व्याख्या शुरू करने तक इसका प्रयोग लोगों के त्वचा के रंग को निर्दिष्ट करने के लिए नहीं किया जाता था।

धर्मशास्त्रों की समझ में पश्चिमी और आधुनिक भारतीय विद्वानों द्वारा भी कई तथ्यात्मक त्रुटियां की गई हैं।

इस बात के बहुत कम प्रमाण हैं कि धर्मशास्त्रों में वर्णित अधिकांश नियमों और आदेशों को हिंदू शासकों द्वारा कभी लागू किया गया था, हालांकि इन ग्रंथों का हवाला कभी-कभी व्यक्तियों के बीच होने वाली बहसों में दिया जाता था। इनका उपयोग संदर्भ ग्रंथ के रूप में तब किया जाता था जब किसी को अपने पक्ष का समर्थन करने के लिए यह उपयुक्त लगता था, लेकिन इन्हें लागू करने योग्य या अंतिम अधिकार नहीं माना जाता था। ये ग्रंथ मुख्यतः अनुष्ठानिक प्रथाओं से संबंधित हैं और इनके उल्लंघन के ब्रह्मांडीय परिणामों का वर्णन करते हैं।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय सामाजिक समूहों को स्पष्ट सीमाओं वाली सटीक श्रेणियों में परिभाषित करना कठिन है। मामला तब और भी जटिल हो जाता है जब हम यह विचार करते हैं कि धर्मशास्त्र हिंदू धर्म के कई आध्यात्मिक ग्रंथों में से केवल एक है। वास्तव में, हिंदू धर्म का पालन करने के लिए धर्मशास्त्रों का अध्ययन अनिवार्य नहीं है। आइए भारतीय आध्यात्मिकता का व्यापक परिप्रेक्ष्य देखें:

हिंदू धर्म का पालन करने के लिए धर्म का पालन करना आवश्यक है।

भारतीय परंपराएं अब्राहमिक धर्मों की तरह 'एक ग्रंथ' प्रणाली पर आधारित नहीं हैं। इसमें अनेक ग्रंथों का संग्रह है जो कई स्रोतों से लिए गए हैं।

भारत में उच्च स्तर की शिक्षा का अर्थ था कि यहाँ हमेशा अनेक मत और विचार मौजूद रहते थे, जो आपस में तर्क-वितर्क करते रहते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि बौद्धिक कृतियों का विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय विकसित हुआ। इस प्रकार की ज्ञान प्रणाली में एकसमान विचार और उनका अनिवार्य कार्यान्वयन संभव नहीं था। प्रचलित आम सहमति के विरुद्ध अनेक आंदोलन हुए और स्थापित सत्ता को चुनौती देने के लिए नए विचार और समूह उभरे। अपनी उत्पत्ति से ही, हिंदू धर्म एक ऐसी परंपरा रही है जो ज्ञान के प्रसार और वंशानुक्रम पर आधारित है। वैदिक परंपरा से अनेक शाखाएँ निकलीं, जिनमें विविध दृष्टिकोण, परंपराएँ और विचारधाराएँ थीं। इससे एक ऐसी खुली संरचना का निर्माण होता है जो सुधार और विकास की गुंजाइश प्रदान करती है, जिससे प्रत्येक विचारधारा का हिंदू अपने आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे उपयुक्त स्थान पा सकता है।

विरोधियों के पवित्र ग्रंथों को जलाने या पूर्व ग्रंथों को विधर्म या ईशनिंदा घोषित करने की कोई परंपरा नहीं थी। इसीलिए पवित्र ग्रंथों और प्रथाओं का प्रसार हुआ, जो कभी-कभी देखने में भिन्न या विरोधाभासी प्रतीत होते हैं, लेकिन फिर भी एक ही वैदिक विश्वदृष्टि में निहित हैं।

हिंदू धर्म के विभिन्न ग्रंथों में धर्मशास्त्रों का उपयोग हिंदुओं के दैनिक जीवन में नहीं होता है। अनुयायी वेद, उपनिषद, भगवद् गीता, इतिहास और पुराणों का अध्ययन करते हैं। ऐसा कोई हिंदू मिलना दुर्लभ है जो प्रतिदिन सुबह धर्मशास्त्रों का अध्ययन करके अपने दिन का मार्गदर्शन लेता हो। दूसरी ओर, कई हिंदू प्रतिदिन गीता, रामायण पढ़ते हैं, वैदिक मंत्रों का जाप करते हैं या उपनिषदों के तत्वमीमांसा पर चिंतन करते हैं। अधिकांश हिंदू घरों में गीता, रामायण, उपनिषद या श्रीमद् भागवतम् रखी जाती हैं, लेकिन धर्मशास्त्र लगभग न के बराबर ही रखी जाती हैं। यदि

विभिन्न हिंदू ग्रंथों की प्रतियों को देखने वाले हिंदुओं की संख्या का सर्वेक्षण किया जाए, तो धर्मशास्त्र अन्य सभी ग्रंथों की तुलना में सबसे नीचे स्थान पर होंगे।

यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि घोर निंदा झेलने वाले धर्मशास्त्रों को गुरु परंपरा के माध्यम से संशोधित किया गया था, इसलिए उनका अब्राहमिक कानूनों के समान कोई कट्टर प्रभाव नहीं था। अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों ने धर्मशास्त्रों का सहारा लेकर 'जेंटू कानून' नामक ग्रंथ संकलित किया ('जेंटू' बाइबिल में 'गैर-यहूदी' लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अपमानजनक शब्द है)। बाद में, इसे 'हिंदू कानून' से प्रतिस्थापित किया गया, जिसका नेतृत्व सर विलियम जोन्स ने किया, जिन्होंने स्वयं को पंडित विलियम जोन्स कहा। इसका उद्देश्य बंगाल में अंग्रेजों द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी मामलों के निपटारे के लिए एक 'मानक कानून' निर्धारित करना था, जहाँ वे मुख्य न्यायाधीश थे। परंपरागत रूप से, सामाजिक सिद्धांतों की व्याख्या और उन पर निर्णय देने का अधिकार रखने वाली कोई केंद्रीकृत चर्च जैसी संरचना नहीं थी। विवादों का निपटारा अत्यधिक प्रासंगिक परिस्थितियों और संबंधित व्यक्तियों पर आधारित होता था।

कर्म सिद्धांत कहता है कि न्याय करने वाली एक सार्वभौमिक दैवीय शक्ति है। यह इब्राहीमी धर्मों में ईश्वर के आदेशों से भिन्न है, जिनमें मनुष्यों से ईश्वर के आदेशों का पालन करने का आग्रह किया जाता है। हिंदू शासक व्यक्तियों के आध्यात्मिक अनुपालन या उल्लंघन के प्रति उदासीन थे, और उनका विधि अधिकार क्षेत्र केवल सांसारिक मामलों तक ही सीमित था। उनका ध्यान स्वयं पर केंद्रित था, न कि धार्मिक उत्साह के नाम पर आत्माओं का दोहन करने पर। इसलिए, कोई भी हिंदू शासक ऐसा नहीं था जिसने धर्म को उपनिवेश बनाने का आधार बनाया हो।

अंततः, धर्मशास्त्रों में जो कहा गया है, वह लोगों के व्यवहार से संबंधित मानवशास्त्रीय प्रमाणों से मेल नहीं खाता। धर्मशास्त्र भारतीय और विदेशी अभिलेखों सहित सभी प्रकार के अनुभवजन्य प्रमाणों के आधार पर जमीनी हकीकत का वर्णन करते हैं। इससे पता चलता है कि ये ग्रंथ समाज द्वारा अपनाए गए तरीके के अनुसार वर्णनात्मक थे, न कि निर्देशात्मक।

क्योंकि इन मामलों पर कोई मानक संस्थागत 'कानून' नहीं है, इसलिए अनेक लिखित कथन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक व्यक्ति द्वारा अपनाई जाने वाली हर प्रथा के लिए, दूसरे लोग अलग-अलग प्रथाओं का पालन करते हैं। समाज से जुड़े सवालों के अक्सर 'हाँ' और 'ना' दोनों ही जवाब होते हैं।

इसलिए, कोई एक ऐसी 'जाति व्यवस्था' नहीं थी जिसे सदियों से या भारत की विशाल भौगोलिक विविधता और समुदायों में समान रूप से लागू किया जा सके। भारतीय समाज को अक्सर एक ही 'जाति' व्यवस्था के नजरिए से देखा जाता है, जिससे विरोधाभास उत्पन्न होते हैं। 'जाति व्यवस्था' शब्द भी भ्रामक है क्योंकि यह एक ऐसे ढांचे का सुझाव देता है जिसे लगातार और सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है।

भारतीय सभ्यता के कई अन्य पहलुओं की तरह, जातियाँ भी सामाजिक संगठन की एक खुली संरचना की तरह थीं जिसमें कई प्रकार के समुदाय विद्यमान थे, अनुकूलित होते थे, दूसरों को आत्मसात करते थे या दूसरों द्वारा आत्मसात हो जाते थे, और कई मामलों में, लुप्त हो जाते थे।

पश्चिमी देशों में सरल ढाँचों को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए जाति की ऐसी सूक्ष्म समझ को बहुत अव्यवस्थित और जटिल माना जाता है, और यही इस विषय पर शोध की समस्या का मूल है। हालाँकि, समय के साथ भारतीय समाज की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित सामान्य कथन

कहे जा सकते हैं:
जनता के सामाजिक जीवन की गरिमा, समृद्धि और जीवंतता के संदर्भ में, अच्छे और बुरे दौर थे, अच्छे और बुरे क्षेत्र थे, अच्छे और बुरे उदाहरण थे। कुल मिलाकर, पश्चिमी दुनिया में किसी भी समय प्रचलित प्रथाओं की तुलना में, भारतीय समाज अत्यधिक उन्नत, गतिशील, लचीला और समृद्ध था, और आम तौर पर प्रचलित रूढ़ियों के विपरीत पिछड़ा या दमनकारी होने से बहुत दूर था।
स्थापित सामाजिक मानदंडों को लगातार चुनौती मिलती रही, जिनमें साधारण और विनम्र व्यक्तियों द्वारा अग्रणी आध्यात्मिक विशेषज्ञों को चुनौती देना भी शामिल था। कई स्वदेशी सामाजिक सुधार आंदोलनों ने महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। इस विकास के लिए किसी भी प्रकार के विदेशी या बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

सात ऐतिहासिक चरण
हमने भारतीय सामाजिक इतिहास को निम्नलिखित सात अवधियों में व्यवस्थित किया है, जिन्हें चर्चा के उद्देश्य से एक ढीले-ढाले, अनौपचारिक कालक्रम के रूप में प्रस्तावित किया गया है।
प्रारंभिक वैदिक
उत्तर वैदिक और इतिहासिक
धर्मशास्त्र (जो 2 से ओवरलैप करते हैं)
मुस्लिम शासन
यूरोपीय औपनिवेशिक शासन
पोस्ट-आजादी
भूमंडलीकरण
इन अवधियों को किसी सटीक विशेषताओं या समयसीमा द्वारा

परिभाषित नहीं किया गया है, न ही ये परस्पर अनन्य हैं। ये आंशिक रूप से अतिव्यापी हैं और प्रत्येक में दूसरे के कुछ गुण समाहित हैं। आगे दी गई मुख्य विशेषताएं केवल उदाहरण के तौर पर हैं और इनका उद्देश्य किसी भी बिंदु पर एकसमान प्रणाली का सरलीकृत चित्र प्रस्तुत करना नहीं है।

आइए, भारतीय समाज के संगठनात्मक स्वरूप में उसके इतिहास के दौरान हुए परिवर्तनों को समझने और उनकी सराहना करने के लिए, इन सातों कालों पर संक्षेप में नज़र डालें।

प्रारंभिक ऋग्वेद काल में हमें शिल्पकार, किसान, पुजारी और योद्धा मिलते हैं; समाज मूलतः समतावादी था। लोगों के गहरे, संस्थागत और पदानुक्रमित वर्गीकरण का कोई प्रमाण नहीं मिलता। महिलाएं और शूद्र भी वैदिक भजन और अन्य महत्वपूर्ण रचनाएँ कर रहे थे।

उत्तर वैदिक और ऐतिहासिक काल में भी वर्ण की अवधारणा अपने प्रारंभिक रूप में थी और जन्म पर सख्ती से निर्भर नहीं थी। धातुकर्मी, रथ निर्माता और बढ़ई जैसे कारीगर जन्म से ही व्यवसायिक जाति नहीं थे। महाभारत में कहा गया है कि कोई व्यक्ति केवल जन्म से ही ब्राह्मण नहीं बनता, बल्कि आचरण से भी बनता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य माता से जन्म ले सकता है। वर्णों की सापेक्ष स्थिति के संबंध में भी कुछ अस्पष्टता थी और ये एक दूसरे से परिवर्तनशील रूप से संबंधित थे।

सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य (शासनकाल लगभग 321-297 ईसा पूर्व) के समय भारत आए यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने दावा किया कि भारत में दास प्रथा अज्ञात थी, कोई भारतीय दास अस्तित्व में नहीं था और सभी भारतीय स्वतंत्र थे। यूनानी लेखक शूद्रों को सोदराई कहते हैं और उन्हें मैसिडोनिया के राजा सिकंदर (326 ईसा पूर्व) के समय उत्तर-पश्चिम

भारत का एक महत्वपूर्ण समुदाय बताते हैं। यह आधुनिक विद्वानों द्वारा प्रस्तुत इस मत के विपरीत है कि शूद्र और दलित वैदिक काल से ही दास रहे हैं।

प्राचीन ग्रंथों में जाति को काफी हद तक नजरअंदाज किया गया था और यह एक बाद की अवधारणा प्रतीत होती है। प्रारंभ में, जाति का सामान्य अर्थ एक ऐसा रिश्तेदारी समूह था जिसके लोग एक ही व्यवसाय और एक जैसी जीवनशैली अपनाते थे। वर्ण व्यवस्था के भीतर यह जाति संरचना ईसा पूर्व कुछ शताब्दियों में विकसित हुई प्रतीत होती है। बाद में ही ये संरचनाएं अधिक औपचारिक रूप धारण कर पाईं।

मनुस्मृति में बताया गया है कि जातियों की उत्पत्ति विभिन्न वर्णों के बीच अंतर्विवाह से हुई। इससे पता चलता है कि विभिन्न वर्णों के बीच अंतर्विवाह होते थे। इस प्रकार, मनुस्मृति में इकसठ जातियों का उल्लेख है और ब्रह्मवैवर्त पुराण में सौ से अधिक जातियों का उल्लेख है। कौटिल्य (जो दार्शनिक चाणक्य के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं), जिन्होंने अर्थशास्त्र की ख्याति लिखी है, ने भी कम से कम पंद्रह जातियों का उल्लेख किया है जो विभिन्न वर्णों के बीच विवाहों का परिणाम थीं। मौर्योत्तर काल (187 ईसा पूर्व-320 ईस्वी) के दौरान विभिन्न वर्णों के बीच अंतर्विवाह होते रहे और जातियाँ नई जातियों को जन्म देती रहीं।

जातियों की उत्पत्ति समुदायों के भौगोलिक स्थानांतरण पर भी आधारित हो सकती है। ऐसे प्रवासों ने लोगों को अपनी पिछली पहचान और नए पेशे को मिलाकर स्वयं को पुनर्परिभाषित करने का अवसर दिया। इस स्थानांतरण में उनका वर्ण भी बदल सकता है। पूरे भारत में ऐसे प्रवासी समूहों के अनेक उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण के लिए, ब्राह्मणों में ऐसे प्रवासों के कारण दक्षिण में वदमा, आंध्र द्रविड़ और मुलुकनाडु जैसी अनेक जातियाँ उत्पन्न हुईं। पश्चिम में सौराष्ट्र से आए ब्राह्मणों का एक

समूह दक्षिण में मदुरै में कारीगर बन गया और स्वयं को 'सौराष्ट्र जाति' कहता है, लेकिन इसे तमिल ब्राह्मणों ने स्वीकार नहीं किया है। तमिलनाडु की कोंगू गौड़ा (वेल्लाल) जाति पूर्व में बंगाल से आए प्रवासी हैं।
धर्मशास्त्रों में वर्णित अपद-धर्म (संकट के समय का धर्म) का सिद्धांत वर्णों के निर्धारित व्यवसायों में सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को उजागर करता है। इससे यह प्रमाण मिलता है कि चारों वर्णों के लिए विभिन्न व्यवसायों के लिखित निर्देशों का अक्सर व्यवहार में पालन नहीं किया जाता था।
इस प्रकार, मनुस्मृति में उल्लेख है कि संकट के समय में, लोग अपने पारंपरिक व्यवसायों को छोड़कर अन्य वर्णों और जातियों के व्यवसायों को अपनाने लगे। यह प्रमाणित है कि लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने पेशे बदलते थे। बौद्ध ग्रंथों में भी यह बताया गया है कि कोई जाति किसी विशेष व्यवसाय से सख्ती से बंधी नहीं थी। हमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ एक क्षत्रिय योद्धा एक साथ कुम्हार, टोकरी बनाने वाला, सरकंडा बनाने वाला, माला बनाने वाला आदि का काम करता था; और एक वैश्य रसोइया बिना किसी सामाजिक विरोध या प्रतिष्ठा की हानि के दर्जी या कुम्हार का काम करता था। गुप्त काल (चौथी शताब्दी ईस्वी से छठी शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध तक) और उत्तर-गुप्त काल में जातियों का और अधिक प्रसार हुआ। यह भी उल्लेखनीय है कि शूद्रों में अन्य वर्णों की तुलना में उनकी जातियों के भीतर कहीं अधिक आंतरिक विभाजन थे।
उदाहरण के तौर पर, कुछ मध्यकालीन शिलालेखों से पता चलता है कि विभिन्न दान-पुण्य संस्थाओं की स्थापना करने वाले बहुत कम दानदाताओं ने स्वयं को अपने वर्ण या जाति के आधार पर वर्णित किया था। इसके बजाय, शिलालेखों में केवल उनके और उनके माता-पिता के नाम ही दिए

गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस काल में वर्ण और जाति किसी व्यक्ति की पहचान के सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं थे।
मुस्लिम आक्रमणों के साथ हालात पूरी तरह बदल गए। मुस्लिम काल में शहरों, व्यापार और कृषि का पतन हुआ। भारतीय जनता की प्रगति रुक गई और वे असहाय, गतिहीन और गरीब हो गए। निराशा का यह वातावरण आर्थिक उद्यम, व्यापार या औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं था। कई बार तो कृषि भी मुश्किल से ही चल पाती थी। बहुत से लोगों के लिए एकमात्र उम्मीद जीवित रहना ही थी। जातियाँ कम उद्यमशील थीं और उन्होंने अपने वंशानुगत व्यवसायों को ही स्थिर कर लिया और अंतर्विवाह को अपना लिया।
मुगल शासकों ने जनता का निर्दयतापूर्वक शोषण किया और इससे आर्थिक असमानताएँ उत्पन्न हुईं। शाहजहाँ के शासनकाल (1628-58) के दौरान, कुल राजस्व का 37 प्रतिशत 68 राजकुमारों और अमीरों को और शेष 25 प्रतिशत 587 अधिकारियों को आवंटित किया गया था। इसका अर्थ यह है कि साम्राज्य के कुल राजस्व का लगभग 62 प्रतिशत केवल 655 व्यक्तियों को दिया गया था। अकबर के शासनकाल (1556-1605) के दौरान आय का वितरण और भी अधिक असमान हो गया, जब शीर्ष पच्चीस व्यक्तियों ने कुल राजस्व का तीस प्रतिशत से अधिक हिस्सा ले लिया।
मुगल काल में अपनाई गई भव्य जीवनशैली और स्मारक आक्रमण और लूटपाट पर आधारित थे, न कि नए निवेश, शिक्षा या विकास गतिविधियों पर। उन्होंने दुनिया की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में से एक पर कब्जा कर लिया था और कुछ शताब्दियों तक विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत किया। वहीं दूसरी ओर, यूरोप विश्व का एक पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण अपने 'अंधकार युग' में था, लेकिन अचानक ही वह बाकी सभी देशों से

आगे निकल गया।

मुगलों ने जबरन वसूली, कराधान या प्रत्यक्ष ज़ब्ती के माध्यम से लगभग सभी अतिरिक्त धन पर कब्जा कर लिया। धन का एक बड़ा हिस्सा अनुत्पादक विलासिता में परिवर्तित हो गया। इसके परिणामस्वरूप बार-बार और विनाशकारी अकाल पड़े। इन कारकों ने आर्थिक गतिशीलता को बाधित किया। कारीगरों और व्यापारियों की गतिशीलता कम हो गई। व्यवसाय वंशानुगत हो गए। विवाह और भोजन साझा करने के मामलों में जाति व्यवस्था अधिक कठोर हो गई और अवसरवादिता और सामाजिक स्तरीकरण में विलीन हो गई। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि मुस्लिम काल में, जाति समूह अस्तित्व के लिए रक्षात्मक हो गए और सामाजिक गतिशीलता में भारी गिरावट आई।

सोलहवीं शताब्दी में जब पुर्तगाली भारत आए, तो उन्होंने पाया कि समाज (हिंदू और मुस्लिम दोनों) विभिन्न व्यावसायिक जातियों में संगठित था। उन्होंने इन्हें 'कास्ता' कहा, जिसका अर्थ है जनजाति, गोत्र या नस्ल। किसी भी भारतीय भाषा में 'जाति' शब्द का कोई सटीक पर्याय नहीं है। धीरे-धीरे, 'जाति' शब्द को जातियों के पर्याय के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। ब्रिटिश शासन के दौरान, जातियों को औपचारिक 'जाति व्यवस्था' के रूप में पुनः परिभाषित किया गया।

औपनिवेशिक काल में भी भारतीयों की पहचान जटिल और बहुआयामी थी। परिस्थिति के अनुसार, कोई एक पहचान प्रमुख हो सकती थी। इसलिए, जब औपनिवेशिक जनगणनाओं में जातिगत संबद्धताओं का पता लगाने का प्रयास किया गया, तो प्राप्त उत्तरों में अंतर्विवाही समूहों या व्यवसायों को दर्शाने वाले नामों से लेकर उपाधियों और उपनामों तक की विविधता पाई गई। कोई एक ऐसी श्रेणी नहीं थी जिससे लोग सार्वभौमिक रूप से संबद्धता का दावा करते हों, जो पश्चिमी 'जाति' की अवधारणा के

अनुरूप हो।

ब्रिटिश जनगणना अधिकारियों ने इस बात पर अपनी निराशा व्यक्त की है कि कई भारतीयों को अपनी जाति का ज्ञान नहीं था, और कई मामलों में उन्हें जनगणना प्रपत्र भरने के लिए प्रशिक्षित करना पड़ा। औपनिवेशिक वर्गीकरण प्रणाली यह मानती थी कि जातियाँ सुस्पष्ट मानक इकाइयाँ हैं जिनके सदस्यों की गणना की जा सकती है और उनकी विशेषताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। ऐसी जनगणनाओं के माध्यम से बड़ी मात्रा में डेटा एकत्रित किया गया था, और इसे सार्थक प्रारूपों में ढालना आवश्यक था। औपनिवेशिक अधिकारियों ने आपस में विचार-विमर्श किया और इस विरोधाभास को हल करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार किया। वर्गीकरण की इस प्रणाली ने उन्हें अपने औपनिवेशिक शासन के दौरान इन समूहों को अधीन करने में मदद की। उन्होंने जानबूझकर कुछ जातियों को 'अपराधी' करार दिया और उनके विरुद्ध नरसंहार किया।

जाति पर किए गए सभी आधुनिक समाजशास्त्रीय अध्ययन इन्हीं मनमानी औपनिवेशिक अवधारणाओं का उपयोग करते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद, लोकतांत्रिक व्यवस्था ने जातियों को वोट बैंक में बदल दिया, जिनका राजनेताओं द्वारा अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए लगातार दुरुपयोग किया जाता रहा है।

वैश्वीकरण के इस युग में हालात एक बार फिर बदल रहे हैं। आज जब भोजन या कोई भी उत्पाद डिलीवर होता है, तो कौन जानेगा, या जानने की परवाह करेगा कि व्यक्ति की जाति या लिंग क्या है? वस्तुओं और सेवाओं का मुक्त आदान-प्रदान बाजार प्रतिस्पर्धा और योग्यता पर आधारित है, और पुराने सामाजिक वर्गीकरणों की कोई परवाह नहीं करता। जन्म से संबंधित कारकों की परवाह किए बिना, व्यक्ति काम कर

सकता है, वेतन पा सकता है, अपने करियर में आगे बढ़ सकता है और सामाजिक रूप से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकता है। दक्षता और अनुकूलन ही सफलता के प्रमुख कारक हैं, जो बाकी सभी चीजों से ऊपर हैं।

पूंजीवाद जाति व्यवस्था को अप्रचलित बना रहा है, लेकिन यह समाज को संरचनात्मक पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं करता। नई गतिशीलता चुनौतियां और अवसर दोनों लेकर आती है। तेजी से शहरीकरण हो रहे भारत में एकमात्र बची हुई जाति व्यवस्था सरकार द्वारा लोगों को दी गई औपचारिक पहचानों द्वारा लागू की गई है। यही भारत का अभिशाप है: इसके संविधान में निहित जन्मजात दोष। यही जहरीली पहचान की राजनीति को हवा देता है।

हिंदू सामाजिक संरचना के विकास के कालानुक्रमिक क्रम को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है: वर्ण → जाति → वर्ग → राजनीतिक वोट बैंक → वैश्विक जातिगत संघर्ष। अगले पृष्ठ पर दिया गया चित्र भारतीय सामाजिक संरचनाओं के विकासवादी इतिहास को दर्शाता है।

मेटावर्स कई संपत्तियों को आभासी बनाकर और उनके भौतिक स्वरूप को कम महत्व देकर और भी आगे बढ़ता है। सवाल यह है कि क्या वैश्विक स्तर पर एक बिलकुल नई तरह की 'मेटावर्स जाति व्यवस्था' उभर कर सामने आएगी, और उसकी विशेषताएं क्या होंगी।

आगे दी गई तालिका सात अवधियों में रुझानों को व्यवस्थित करती है जो इस बात का उदाहरण हैं कि कैसे वर्ण जाति में, जाति जाति में और अब वोट बैंक में परिवर्तित हो गया।

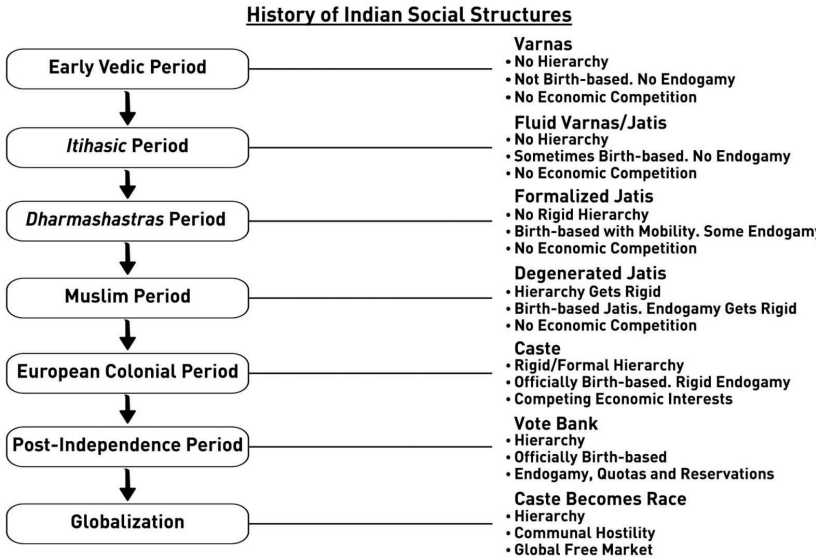

PERIODS	1 Early Vedic	2 Late Vedic & *Itihasic*	3 *Dharma-shastras*	4 Muslim Period	5 European Colonial	6 Post-Independence	7 Globalization
Key character	Varna	Fluid Jati/ Varna structures	Formalized jati	Jati degeneration and abuse	Caste	Vote bank	Critical Caste Theory
Hierarchy	No	No	Multiple hierarchies and privileges	Hierarchy becomes stronger	Rigid and formal hierarchy	Yes	Yes
Birth-based	No	Not always	Yes, but mobility possible	Yes	Officially birth-based	Officially birth-based	Equated with race
Competing economic interests	No	No	No	No	Yes	Quotas; competition	Global free market
Communal hostility	No	No	No	Sometimes	Yes	Yes	Yes
Endogamy	No	No	Yes, but flexible	Yes	Yes	Yes	Yes
Untouchability	No	No	Little	Yes	Yes	Yes. But illegal	Cancel Culture
Top-down power (as opposed to lateral peer groups)	No	No	No	Yes	Yes	Yes. Lobbying	Globalized
Political groupings	No	No	No	No	No	Yes. Communalism	Global social justice

तालिका हमारी चर्चा का सारांश प्रस्तुत करती है और भारत के इतिहास में वर्ण, जाति और वर्ग की विभिन्न विशेषताओं को सूचीबद्ध करती है। यह देखा जा सकता है कि वर्ण, जाति और वर्ग को वर्तमान में एक दूसरे

के समान मानकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जाती है। हम तालिका के प्रमुख बिंदुओं पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। (प्रारंभिक काल में पदानुक्रम के अभाव को स्पष्ट करना आवश्यक है। वास्तव में, अनुष्ठान करने के विशिष्ट संदर्भ में पदानुक्रम मौजूद था, हालांकि व्यापक सामाजिक अर्थ में नहीं।)

प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है
अब हम साक्ष्य के स्रोतों के रूप में प्रमुख प्राचीन ग्रंथों की जांच करेंगे।

वैदिक युग
चार वर्णों का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के दो श्लोकों में मिलता है। इसमें चार सामाजिक समूहों का जिक्र है: ब्राह्मण, राजन्य (क्षत्रिय के स्थान पर), वैश्य और शूद्र, लेकिन वर्ण शब्द का उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित दो श्लोकों ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है क्योंकि इनका अक्सर यह दावा करने के लिए उपयोग किया जाता है कि वेद शूद्रों के साथ भेदभाव करते हैं और उन्हें ईश्वर के चरणों के समान मानते हैं।
जब देवताओं ने पुरुष को विभाजित किया, तो उन्होंने उसे कितने भागों में काटा? उसका मुख क्या था? उसकी भुजाएँ क्या थीं? उसकी जांघें और पैर किन वस्तुओं के नाम से जाने जाते हैं?
ब्राह्मण उसका मुख था; राजा (क्षत्रिय) उसकी भुजाएँ बना; वैश्य उसकी जांघें थीं; शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुआ।
बी.आर. अंबेडकर और कई अन्य विद्वानों ने इन छंदों को बाद में जोड़ा गया माना। इसी संदर्भ में, प्रसिद्ध सामाजिक वैज्ञानिक आर.एस. शर्मा ने लिखा:
इससे यह स्पष्ट है कि शूद्र एक सामाजिक वर्ग के रूप में अथर्ववेद काल

के अंत में ही प्रकट होते हैं [कालानुक्रमिक रूप से वेदों में अंतिम], जब उनकी उत्पत्ति का पुरुष सूक्त संस्करण ऋग्वेद के दसवें खंड में शामिल किया गया होगा।

इनके समय चाहे जो भी हों, ये श्लोक जन्म-आधारित और पदानुक्रमित व्यवस्था का समर्थन नहीं करते। बल्कि, ये समाज को एक जैविक इकाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे एक एकीकृत व्यक्ति के कई अंग होते हैं। इसका उद्देश्य उन विभिन्न पहलुओं के बीच मनोवैज्ञानिक अंतर्संबंधों और निर्भरताओं को उजागर करना है जो एक अभिन्न एकता का निर्माण करते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों की तरह ही इनमें भी परस्पर निर्भरता है। एक स्वस्थ शरीर में अंगों के बीच कोई संघर्ष या शोषक/शोषित का कोई शोषणकारी पदानुक्रम नहीं होता। शरीर के विभिन्न अंग एक सामान्य संरचना, अर्थात् डीएनए, द्वारा अभिन्न रूप से एकीकृत होते हैं।

कोई भी व्यक्ति अपने पैरों को सिर्फ इसलिए कमतर नहीं आंकना चाहेगा क्योंकि वे शारीरिक रूप से 'नीचे' हैं। शारीरिक रूप से नीचे होने का अर्थ कम महत्व होना नहीं है। इसके अलावा, ब्रह्मांडीय व्यक्ति को अक्सर क्षैतिज रूप से लेटे हुए दर्शाया जाता है, ऐसे में कोई 'ऊपरी' या 'निचला' भाग नहीं होता।

बृहदारण्यक उपनिषद में विभिन्न ऋतुओं को समझाने के लिए मानव शरीर का स्पष्ट रूप से रूपक के रूप में प्रयोग किया गया है, जिसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से कुछ ऋतुओं को दूसरों की तुलना में 'निम्न और हीन' के रूप में वर्गीकृत करना नहीं है। यह शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग करके नक्षत्रों, बादलों, रेत, नदियों, पहाड़ों, पेड़ों और पौधों का प्रतिनिधित्व करते हुए ब्रह्मांड का वर्णन भी करता है। प्राचीन ग्रंथों में शरीर को विविध तत्वों की जैविक एकता के रूपक के रूप में प्रयोग किया गया

है।
इसके अलावा, इन श्लोकों में कोई निर्देशात्मक बात नहीं है। ये केवल यह दर्शाते हैं कि समाज के विभिन्न अंग अपनी-अपनी भूमिकाओं में किस प्रकार विशिष्ट होते हैं। इस प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग एकता में अंतर्निहित विविधता को समझाने के लिए किया जाता था। दुर्भाग्यवश, हिंदू समाज को दमनकारी पदानुक्रम के रूप में चित्रित करने के जुनून में डूबे पश्चिमी विद्वान दावा करते हैं कि शूद्रों को पैरों के समान माना जाता था, इसलिए उन्हें बाकी प्राणियों से हीन समझा जाता था।
मैकगिल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरविंद शर्मा ने इन श्लोकों की एक और व्याख्या प्रस्तुत की है: प्रत्येक व्यक्ति को विविध क्षेत्रों में दक्षता हासिल करने और उन्हें एकीकृत करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों का निर्वाह करने में सक्षम होना चाहिए: शारीरिक और मानसिक कार्य, समुदाय का प्रबंधन या शासन, आवश्यकता पड़ने पर सैन्य सेवा प्रदान करना, व्यावसायिक गतिविधियाँ और अन्य पेशेवर कार्य। वे लिखते हैं: 'विचार यह है कि सभी वर्ण प्रत्येक व्यक्ति में समाहित हैं, न कि प्रत्येक व्यक्ति किसी एक वर्ण में समाहित है।' हम इसे समाज पर भी लागू कर सकते हैं और कह सकते हैं: जिस प्रकार पुरुष, ब्रह्मांडीय व्यक्ति, अनेक विशिष्टताओं को एकीकृत करता है, उसी प्रकार हमारे समाज को भी सभी क्षमताओं में सामंजस्य और अनुकूलन स्थापित करना चाहिए।
संक्षेप में, ऋग्वेद सभी मनुष्यों की समानता पर बल देता है: 'कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई हीन नहीं। सभी भाई-भाई हैं और समृद्धि की ओर अग्रसर हैं।'

उपनिषद
उपनिषदों का संपूर्ण तत्वमीमांसा सभी मनुष्यों, जीवित प्राणियों और

वास्तव में समस्त अस्तित्व की परम एकता पर जोर देता है।
इसके अतिरिक्त, वज्रसूचिका नामक उपनिषद पूरी तरह से जन्म आधारित सामाजिक पहचान का खंडन करने पर केंद्रित है। यह संक्षिप्त है, जिसमें केवल नौ छोटे अनुच्छेद हैं, और एस. राधाकृष्णन ने इसे अपनी पुस्तक, द प्रिंसिपल उपनिषद में शामिल किया है। अद्वैत वेदांत पर आधारित सीधे बिंदु-दर-बिंदु कथन देने के बाद, यह सभी को सर्वोच्च सत्ता का ध्यान करने और मन से सभी भेदों और अहंकार को दूर करने का आह्वान करता है। वज्रसूचिका इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ती कि सामाजिक भेदभाव उपनिषदों के विश्वदृष्टिकोण के विपरीत है।

भगवद् गीता
हिंदू धर्म में धर्मशास्त्रों की तुलना में गीता कहीं अधिक प्रासंगिक और प्रभावशाली है। धर्मशास्त्रों और गीता के बीच जहां भी मतभेद होता है, गीता को ही प्राथमिकता दी जाती है। आइए वर्ण व्यवस्था पर गीता के दृष्टिकोण का अध्ययन करें।
गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वर्ण जन्म पर आधारित नहीं है। इसका मुख्य उद्धरण वह है जहाँ कृष्ण कहते हैं: 'चार वर्णों की रचना मैंने चरित्र और व्यवसाय के आधार पर की है।' (गीता 4.13) कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इनकी रचना गुणों (स्वभाविक योग्यता, चरित्र) और कर्म के आधार पर हुई है। वर्णों के चार भागों में विभाजन के आधार के रूप में जन्म का कोई उल्लेख नहीं है।
महाभारत युद्ध में, कुछ ऐसे व्यक्ति भी शामिल हुए जो जन्म से क्षत्रिय नहीं थे, उन्होंने भी अपने स्वभाव के अनुसार युद्ध में भाग लिया। कृष्ण ने पांडव अर्जुन को स्वधर्म का पालन करने का ज्ञान दिया, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी योग्यता और गुणों का अनुसरण करना चाहिए। यह

समाज के सर्वोत्तम हित में संसाधनों के अधिकतम उपयोग का एक तरीका है।
गीता वेदांत के उस सिद्धांत की व्याख्या करती है कि प्रत्येक प्राणी में दैवीयता विद्यमान है। कृष्ण कहते हैं: 'जो मुझे सभी वस्तुओं में देखता है और सभी वस्तुओं को मुझमें देखता है, वह कभी मुझसे विमुख नहीं होता। और न ही मैं उससे कभी विमुख होता हूँ।' (गीता 6.30) और इसके बाद एक श्लोक कहता है: 'जो दूसरों के सुख-दुख का आकलन उसी मापदंड से करता है जिस मापदंड से वह स्वयं का करता है, वही योगी सर्वोच्च है।' (गीता 6.32)
सोलहवें अध्याय में कृष्ण उन गुणों की सूची देते हैं जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं। इनमें अहिंसा, सत्य, सभी के प्रति करुणा, क्रोध और घृणा का अभाव, निस्वार्थ भाव से दान और सेवा करना, क्षमा और नम्रता शामिल हैं। (गीता 16.1-3) इनमें से कोई भी गुण जन्म पर आधारित नहीं है।
कृष्ण का जीवन स्वयं सभी वर्णों की अभिव्यक्ति है। उनका पालन-पोषण ग्वालों वाले एक वैश्य परिवार में हुआ। उन्होंने द्वारका पर क्षत्रिय के रूप में शासन किया। उन्होंने शूद्र होते हुए अर्जुन के सारथी की भूमिका स्वीकार की और ब्राह्मण होते हुए गीता का उपदेश दिया।

The Mahabharata

महाभारत में उल्लेख है कि सत्य युग (जो प्रथम और सर्वोत्कृष्ट युग माना जाता है) में मनुष्यों का केवल एक ही वर्ण था - विवस्वत मनु की संतानों का वर्ण। पुराणों और अन्य हिंदू धर्मग्रंथों में भी उस काल में अलग-अलग सामाजिक श्रेणियों का कोई प्रमाण नहीं मिलता है।
महाभारत इस बात पर जोर देता है कि चरित्र जन्म से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

उच्च कुल में जन्म लेना चरित्रहीन व्यक्ति का प्रमाण नहीं हो सकता। परन्तु अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति निम्न कुल में जन्म लेने के बावजूद भी अपनी विशिष्टता साबित कर सकते हैं। (महाभारत, उद्योग पर्व, अध्याय 34.41)

जो शूद्र सदा संयम, सत्य और धर्म में लीन रहता है, मैं उसे ब्राह्मण मानता हूँ। आचरण से ही व्यक्ति द्विज होता है। (महाभारत, वन पर्व, अध्याय 216.14-15)

कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद में, जब अर्जुन ने विशेष रूप से पूछा कि वर्ण का निर्धारण कैसे होता है, तो कृष्ण ने उत्तर दिया: 'जन्म इसका कारण नहीं है, मेरे मित्र; यह सद्गुण हैं, जो कल्याण का कारण हैं। व्रत का पालन करने वाला चांडाल (अछूत) भी देवताओं द्वारा ब्राह्मण माना जाता है।'

कर्ण को सारथी का पुत्र होने के कारण एक समारोह में भाग लेने से प्रतिबंधित किए जाने की प्रसिद्ध कहानी यह दर्शाती है कि उस समाज में वर्ण से संबंधित जाति की भावना मौजूद थी। हालांकि, इससे भी अधिक रोचक बात यह है कि उन्हें एक राज्य का सिंहासन दिया जाता है, जिससे उनके वर्ण में परिवर्तन होता है, जो उस लचीले ढांचे में संभव था।

समाजशास्त्री दीपांकर गुप्ता लिखते हैं:

वैदिक काल के बहुत बाद, यहाँ तक कि मौर्य साम्राज्य के बाद भी, अस्पृश्यता की अवधारणा अस्तित्व में आई। शतपथ ब्राह्मण में, मुखिया को आम आदमी के साथ एक ही बर्तन में भोजन करने की सलाह दी गई है। ऋग्वेद में भी अछूतों का कोई उल्लेख नहीं है। लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी में ही अछूतों का वर्ग और अस्पृश्यता की अवधारणा स्पष्ट हुई, उदाहरण के लिए अपस्तम्भ धर्मसूत्र में। [25]

अंबेडकर शूद्रों के प्रति पूर्वाग्रह की उत्पत्ति पर अनुमान लगाते हैं। उनका

कहना है कि कुछ ब्राह्मणों को (मध्ययुग में) शूद्र राजाओं द्वारा अपमानित और प्रताड़ित किया गया था और प्रतिशोध के रूप में उन्होंने उपनयन या जनेऊ संस्कार करना बंद कर दिया। इसी कारण शूद्र चौथे वर्ण बन गए क्योंकि उनके धार्मिक विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया गया था। एक अन्य सिद्धांत जो वे प्रस्तावित करते हैं वह यह है कि अस्पृश्यता बौद्ध प्रभाव के अंतर्गत शुरू हुई जब हिंदुओं ने पशु बलि और गोमांस खाना छोड़ दिया, और जो हिंदू गोमांस खाते रहे उन्हें अछूत माना गया।
इस सिद्धांत पर उनके रुख के बावजूद, अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत हैं कि जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था वैदिक काल के बाद और अस्पृश्यता बौद्ध धर्म के बाद अस्तित्व में आई।
अरविंद शर्मा यह भी बताते हैं कि कई ऋषि गैर-ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। वे वाल्मीकि (रामायण के रचयिता), व्यास (महाभारत के रचयिता और वेदों के संकलक) और यहाँ तक कि महान ऋषि वशिष्ठ का उदाहरण देते हैं। ये सभी निम्नतम वर्ग में जन्मे थे। कालिदास, जिन्हें संस्कृत के सबसे महान कवि के रूप में सम्मानित किया जाता है, एक साधारण और साधारण परिवार से आए थे।

धर्मशास्त्र

धर्मशास्त्रों को अक्सर जाति व्यवस्था और हर तरह के अत्याचारों का समर्थन करने वाले ग्रंथों के रूप में चित्रित किया जाता है। लेकिन इन ग्रंथों को कभी भी बाइबिल या कुरान की तरह पूर्ण सत्य नहीं माना गया। ऐसा कोई भी कानून नहीं था जो लोगों को किसी भी धर्मशास्त्र या उसके किसी भी श्लोक को अस्वीकार करने से रोकता हो। और जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, धर्मशास्त्रों को कभी भी वेदों और उपनिषदों जैसे अन्य ग्रंथों के समान दर्जा प्राप्त नहीं था। इन सब बातों को देखते हुए,

विद्वान धर्मशास्त्रों के कुछ अलग-थलग श्लोकों का हवाला देकर और उन्हें अटूट 'हिंदू कानून' के रूप में स्थापित करके हिंदू धर्म के स्वरूप को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? धर्मशास्त्रों की श्रेणी में आने वाले विशाल साहित्य में भी जातियों की संख्या और स्वरूप पर एकमत नहीं है, और स्वयं अंबेडकर इसके विपरीत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

हालाँकि प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था को सिद्ध करने के लिए मनुस्मृति को सबसे आसानी से उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, फिर भी यह अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है: यदि कोई आचरण नियम दुखदायी हो या लोगों में आक्रोश पैदा करे तो उसका त्याग कर देना चाहिए। (मनु 4:176) दूसरे शब्दों में, यह स्वयं में सुधार करने वाली ग्रंथ है और यह स्वयं को पूर्ण और स्थायी रूप से स्थिर होने का दावा नहीं करती।

व्यापक रूप से कहें तो, मनुस्मृति के अध्याय 2 के पहले श्लोक में धर्म की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: 'वही सच्चा धर्म है जिसका पालन बुद्धिमान, भले और वासना एवं द्वेष से मुक्त लोग करते हैं, और जो हृदय को भाता है।' गांधी जी अक्सर अपने प्रवचनों में इस श्लोक का उद्धरण देते थे। इसका तात्पर्य यह है कि यदि वासना एवं द्वेष से मुक्त बुद्धिमान और भले लोग जन्म आधारित जाति व्यवस्था को अस्वीकार कर दें, तो मनुस्मृति के अनुसार, इस व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है। किसी पैगंबर के आने, चमत्कारों से स्वयं को सिद्ध करने और फिर शिक्षाओं में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वह यह है कि धर्मशास्त्र ब्राह्मणों पर सबसे कठोर प्रतिबंध लगाते हैं। उनसे उच्चतम मानकों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है और उनकी गतिविधियों पर कठोर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। यह उस आम दावे के

बिल्कुल विपरीत है कि धर्मशास्त्र ग्रंथ ब्राह्मणों का पक्ष लेते थे और शूद्रों के साथ भेदभाव करते थे। इसलिए, धर्मशास्त्रों के अनुसार, ब्राह्मण का जीवन अधिक कठिन और सख्त था। ब्राह्मणों को कठोर आचार संहिता का पालन करना आवश्यक था।

एक ब्राह्मण को अपना जीवनयापन करने के लिए ऐसा आजीविका का तरीका अपनाना आवश्यक था जिससे जीवों को कम से कम या बिल्कुल भी नुकसान न पहुंचे।

वह केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक न्यूनतम धन ही एकत्रित कर सका, और वह भी कुछ विशिष्ट गतिविधियों के माध्यम से जो केवल उसी के लिए आवश्यक थीं।

ब्राह्मणों के लिए दंड अधिक कठोर थे। चोरी के मामलों में, शूद्रों पर चोरी की गई राशि का 8 गुना, वैश्यों पर 16 गुना, क्षत्रियों पर 32 गुना और ब्राह्मणों पर 64 गुना से लेकर 128 गुना तक का जुर्माना लगाया जाता था। इसका कारण यह बताया जाता था कि ब्राह्मणों से उच्चतम स्तर की जीवनशैली अपनाने की अपेक्षा की जाती थी।

ब्राह्मणों को मांस, लाख या नमक बेचकर धन कमाने की मनाही थी। और यदि कोई ब्राह्मण तीन दिन तक दूध बेचता, तो वह शूद्र बन जाता। मनु ने सलाह दी है कि जो ब्राह्मण शिल्पकार का काम करते हैं, उन्हें शूद्र माना जाना चाहिए।

धर्मशास्त्रों में ब्राह्मणों और क्षत्रियों को उधार पर ब्याज लेने से मना किया गया है। ग्यारहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम विद्वान अल-बिरूनी ने अपनी कृति किताब-उल-हिंद (लगभग 1030 ईस्वी) में लिखा है कि भारतीय समाज में सूदखोरी या ब्याज पर पैसा उधार देना केवल शूद्रों को ही अनुमत था और अन्य सभी वर्णों के लिए निषिद्ध था। धर्मशास्त्रों में यह भी कहा गया है कि ब्राह्मण को हथियार को अपने हाथों

में नहीं लेना चाहिए, भले ही वह केवल उसकी जांच करने के लिए ही क्यों न हो।
ब्राह्मणों को यह सिखाया गया था कि वे प्रशंसा पाने से उसी प्रकार बचें जैसे कोई जहर से बचता है।
विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, ब्राह्मणों को शूद्रों से उपहार की अपेक्षा करने की अनुमति नहीं थी।
आधुनिक विद्वान धर्मशास्त्रों, विशेषकर मनुस्मृति पर, अस्पृश्यता प्रथा को मान्यता देने का झूठा आरोप लगाते हैं। हम इसके विपरीत प्रमाण प्रस्तुत करते हैं।
इन ग्रंथों में कहा गया है कि कुछ अस्वीकृत व्यवसायों (शिकार, मांस काटना आदि) में लगे लोग अछूत बन जाते थे। ये ग्रंथ केवल कुछ विशेष व्यवसायों को करने के आधार पर ही किसी को अछूत की श्रेणी में रखते हैं। कुछ व्यवसायों को आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग में अपवित्र माना जाता था, और इन अपवित्र गतिविधियों में लगे व्यक्तियों से संपर्क न करने पर जोर दिया गया था। ये प्रतिबंध आध्यात्मिक स्वच्छता की भावना के कारण थे, न कि घृणा या किसी प्रकार के जातीय पूर्वाग्रह के कारण।
शोक की अवस्था में किसी के घनिष्ठ मित्र को भी कई दिनों तक स्पर्श नहीं किया जाता था, क्योंकि मृत शरीर में मृतक के संस्कार (कर्मों के निशान) निहित होते हैं।
अस्पृश्यता कई अलग-अलग कारणों से भी उत्पन्न हुई, जिनका किसी विशेष वर्ण में जन्म से कोई संबंध नहीं था। कुछ लोग गंभीर अपराध करने के कारण बहिष्कृत हो गए।
छुआछी प्रथा की शुरुआत धार्मिक शुद्धता बनाए रखने के एक तरीके के रूप में हुई थी। उदाहरण के लिए, कई परिवारों में सदियों से चली आ रही एक विशेष परंपरा होती है, जिसमें परिवार के सदस्य अनुष्ठान पूरा होने

तक उस सदस्य को स्पर्श नहीं करते जिसे अनुष्ठान का प्रभारी नियुक्त किया गया है। यहां तक कि अनुष्ठान के लिए पहने जाने वाले वस्त्र भी अलग से धोए जाते हैं और दूसरों द्वारा छुए नहीं जाते। शारीरिक संपर्क पर लागू धार्मिक नियमों के कारण इसे परिवार के भीतर भी 'छूछी प्रथा' के रूप में देखा जा सकता है।

आम धारणा के विपरीत, धर्मशास्त्रों में शूद्रों के साथ हर प्रकार के शारीरिक संपर्क को अपवित्र नहीं माना गया है। उदाहरण के लिए, वैदिक ऋषि अत्रि और देवता बृहस्पति, दोनों ने कहा है कि मंदिरों, धार्मिक जुलूसों, विवाहों, यज्ञों या त्योहारों में किसी भी प्रकार के संपर्क से कोई अपवित्रता नहीं होती है।

एक और आम तौर पर प्रचलित गलत धारणा यह है कि वर्ण हमेशा अंतर्विवाही थे। लेकिन बौधायन धर्मसूत्र ब्राह्मणों और शूद्रों के बीच विवाह की अनुमति देता है।

आम धारणाओं के विपरीत, प्राचीन वैदिक ग्रंथ इस बात की गवाही देते हैं कि शूद्र वैदिक अनुष्ठान करते थे: [44]

ऋग्वेद में सभी सामाजिक वर्गों के पाँच ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख है जिन्होंने अग्नि के लिए अनुष्ठान किए।

कुछ वैदिक ग्रंथों के लेखक शूद्र भी थे। उदाहरण के लिए, ऐतरेय ब्राह्मण के लेखक शूद्र थे।

छान्दोग्य उपनिषद में उल्लेख है कि राजा जनश्रुति को शूद्र ऋषि द्वारा प्राण और वायु का ज्ञान दिया गया था।

रामायण में उल्लेख है कि अयोध्या के लोग वेदों के ज्ञाता थे।

अर्थशास्त्र लगभग सभी स्वदेशी समुदायों को आर्य मानता है, जिनमें शूद्र और अधिकांश निम्न-वर्गीय समुदाय शामिल हैं।

अत्रि संहिता में शूद्र, निषाद, चांडाल और म्लेच्छ को ब्राह्मण मूल का माना

गया है। धर्मशास्त्रों में भी शूद्रों के लिए विभिन्न संस्कार निर्धारित किए गए हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि वे हिंदू समाज का अभिन्न अंग थे।
हिंदू धर्म के मूल ग्रंथों के उपरोक्त विश्लेषण से पता चलता है कि आधुनिक विद्वत्ता अविश्वसनीय और सरलीकृत रही है और इस पर सवाल उठाए जाने चाहिए।

क्या हिंदू धर्म जाति व्यवस्था पर ही केंद्रित है?
यह खंड उन आरोपों के जवाब में और अधिक ऐतिहासिक तर्क प्रस्तुत करता है कि जाति हमेशा से हिंदू धर्म से अविभाज्य रही है और यह एक ऐसी बुराई है जो केवल इसी धर्म में पाई जाती है और किसी अन्य धर्म में नहीं।

हिंदू धर्म की खुली वास्तुकला
यह आम तौर पर आरोप लगाया जाता है कि हिंदू धर्म से जुड़े कई वर्जनाओं, प्रतिबंधों और पूर्वाग्रहों को हिंदू धर्म के मूल ग्रंथों और आधिकारिक संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त है। लेकिन हिंदू धर्म धर्मशास्त्रों द्वारा परिभाषित या सर्वमान्य नहीं है; जैसा कि हमने देखा, धर्मशास्त्रों में भी विभिन्न मत हैं जो कभी-कभी एक-दूसरे के विपरीत होते हैं। न ही तीन प्रख्यात आचार्यों (आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य) या असंख्य लोकप्रिय संतों और आंदोलनों द्वारा दी गई व्याख्याएं ही एकमात्र ऐसी व्याख्याएं हैं जिन्हें सभी हिंदुओं को स्वीकार करना चाहिए। हिंदू धर्म के प्रत्येक ग्रंथ, उदाहरण और सामाजिक आंदोलन का उनके योगदान के लिए उसी प्रकार सम्मान किया जाना चाहिए जिस प्रकार हम

इतिहास के विभिन्न प्रमुख वैज्ञानिकों का सम्मान करते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी पूर्ण या अंतिम नहीं है।
हिंदू धर्म एक खुली संरचना है जो मार्गदर्शन प्रदान करने वाले ग्रंथों का एक विशाल भंडार प्रस्तुत करती है, और यही कारण है कि इसमें अनेक विकल्प मौजूद हैं। प्रत्येक हिंदू अपनी पसंद के अनुसार आध्यात्मिक व्याख्या, मार्गदर्शन के लिए गुरु (या गुरु का अभाव), इष्ट देवता (विशेष देवता), अनुष्ठान, त्योहार, तीर्थ स्थल और जीवनशैली का चयन कर सकता है, और करता भी है।
विकल्पों के इस भंडार से, विभिन्न व्यक्ति और समूह प्रणाली एकीकरणकर्ता के रूप में उभरते हैं और अलग-अलग प्रकार के लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाले विशिष्ट व्यवस्थित समाधान तैयार करते हैं। ऐसे कई तैयार 'हिंदू मार्ग' मौजूद हैं, जिनमें से प्रत्येक एक स्टार्टअप और सार्वजनिक पेशकश की तरह है, जो आध्यात्मिक बाजार में सफल हो भी सकते हैं और नहीं भी।

हिंदू होने के लिए जाति ही पर्याप्त नहीं है
यदि जाति हिंदू होने की पर्याप्त शर्त होती, तो जाति का पालन करने वाला हर व्यक्ति हिंदू होता, जिसमें ईसाई, मुस्लिम या अन्य गैर-हिंदू धर्मों के अनुयायी भी शामिल होते। लेकिन वास्तविकता यह है कि जाति, और यहाँ तक कि अस्पृश्यता भी, गैर-हिंदू भारतीयों में बहुत आम है।
यहां तक कि उन अछूतों में भी, जिनके नेता खुद को गैर-हिंदू बताते हैं, जातिगत ऊँच-नीच और अशुद्धता का एक क्रम मौजूद है। उदाहरण के लिए, भंगियों (सफाईकर्मियों) को महारों (कृषि मजदूरों) से अधिक अशुद्ध माना जाता है। यदि जाति व्यवस्था उन्हें स्वतः ही हिंदू बना देती, तो उन्हें स्वयं को गैर-हिंदू नहीं कहना चाहिए था।

कुछ लिंगायत स्वयं को गैर-हिंदू मानते हैं क्योंकि वे वेदों और वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते, फिर भी जाति और रीति-रिवाजों का पालन करते हैं। बसवेश्वर कर्नाटक में भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे और उनके अनुयायी वीरशैव या लिंगायत कहलाते हैं। वे सामाजिक भेदभाव के घोर विरोधी थे, फिर भी अपने अनुयायियों के बीच जाति व्यवस्था को रोकने में असफल रहे।

बौद्ध धर्म और वर्ण

बुद्ध को अक्सर वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध एक समाज सुधारक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और बौद्ध धर्म को उच्च वर्णों के प्रभुत्व के विरुद्ध शूद्रों के विद्रोह के रूप में समझाया जाता है। हालांकि, बौद्ध ग्रंथ एक अलग ही वास्तविकता प्रकट करते हैं। बुद्ध एक क्षत्रिय थे जिन्होंने वर्ण व्यवस्था का तब विरोध किया जब वह ब्राह्मणों के हित में थी, लेकिन तब नहीं जब वह क्षत्रियों के हित में थी। बुद्ध अंतर्विवाह (अपने वर्ण के भीतर विवाह) और सहभोज (केवल अपने वर्ण के लोगों के साथ भोजन करना) में भी विश्वास रखते थे - कम से कम जहाँ तक उनके अपने क्षत्रिय वर्ण का संबंध था।

वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध बौद्ध आलोचना बाद में आई और यह कोई नई या क्रांतिकारी बात नहीं थी। यह कई पूर्ववर्ती और समकालीन धार्मिक संप्रदायों द्वारा साझा की गई थी। वैदिक समाज के प्रबुद्ध और उदार वर्गों में भी जन्म के बजाय कर्मों पर समान बल दिया गया था। छान्दोग्य उपनिषद (IV.4) कहता है कि अच्छे आचरण से ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण बनता है।

इसके अलावा, बौद्ध धर्म के अधिकांश बुद्धिजीवी स्वयं ब्राह्मण थे। बौद्ध संघ की बौद्धिक शक्ति को विद्वान ब्राह्मणों के नियमित प्रवेश द्वारा बनाए रखा गया था। आरंभ से ही, ब्राह्मण अनुयायी बौद्ध धर्म के आधार स्तंभ

के रूप में कार्य करते रहे हैं।
आरंभिक काल में जो लोग गंभीर बौद्ध धर्म के अनुयायी बने, उन्होंने अपने गृहस्थी त्याग दिए और मठों में भिक्षु बन गए। जब कोई बुद्ध का अनुयायी गृहस्थ रहता था, तब भी वह अपने पुराने वर्ण बोध या कर्तव्य का त्याग नहीं करता था। अंबेडकर के अनुसार भी, बौद्ध धर्म में उन लोगों के लिए कोई अलग धम्म दीक्षा नहीं थी जो धम्म में दीक्षित होना चाहते थे लेकिन संघ में भिक्षु नहीं बनना चाहते थे। यही कारण है कि अंबेडकर ने गृहस्थों के लिए अपनी स्वयं की धम्म दीक्षा समारोह की शुरुआत की। अतः बौद्ध धर्म के इतिहास में, गृहस्थ समुदाय ने कभी भी एक अलग और विशिष्ट 'बौद्ध' पहचान का दर्जा प्राप्त नहीं किया।
पी.वी. केन और एस. राधाकृष्णन जैसे विद्वानों का मत है कि बुद्ध स्वयं यह नहीं मानते थे कि वे एक नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं।
कई भारतीयों को विष्णु और बुद्ध की पूजा में, या शिव और अवलोकितेश्वर की पूजा में, या पार्वती और तारा की पूजा में कोई अंतर नहीं दिखता था।
भारत में मुस्लिम जातियाँ
भारतीय मुसलमानों में जातिगत पूर्वाग्रहों के प्रबल प्रमाण मौजूद हैं। मध्यकालीन भारत के प्रारंभिक मुस्लिम इतिहासकारों जैसे मिन्हाज-ए-सिराज जुजानी और जियाउद्दीन बरानी (तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी ईस्वी) ने इस्लाम धर्म अपनाने वाले भारतीयों को नीचा दिखाया। बरानी का मानना था कि सुल्तानों को सरकारी सेवा में केवल उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए जो जन्म से कुलीन पृष्ठभूमि के हों। उन्होंने सलाह दी कि निम्न जाति के हिंदू धर्मान्तरित लोगों के बच्चों को मदरसों में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि यह शिक्षा उन्हें सरकारी नौकरियों के लिए योग्य बना देगी। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन (शासनकाल 1266-87

ईस्वी) ने राज्य सेवा के लिए कुलीन जन्म को एक अनिवार्य शर्त बना दिया और निम्न जाति के धर्मान्तरित लोगों को सरकारी पदों के लिए अस्वीकार कर दिया।

यह भी उल्लेखनीय है कि जब सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो उसने निम्न जाति के मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था।

वर्तमान भारतीय मुस्लिम आबादी का भारी बहुमत (पचहत्तर प्रतिशत) दलित मुस्लिम कहलाता है। जाति और अस्पृश्यता दक्षिण एशिया में मुसलमानों के लिए एक जीती-जागती सच्चाई है, और यह समुदाय का सबसे छिपा हुआ रहस्य है। कई अध्ययनों में दावा किया गया है कि मुस्लिम समूहों में 'पवित्रता और अपवित्रता'; 'स्वच्छ और अपवित्र जातियाँ' जैसी अवधारणाएँ निश्चित रूप से मौजूद हैं। 2009 के एक अध्ययन में पाया गया कि किसी भी प्रमुख मुस्लिम संगठन में एक भी 'दलित मुस्लिम' नेता नहीं था, जिन पर मुख्य रूप से उच्च जाति के मुसलमानों का वर्चस्व था।

उत्तर प्रदेश के चौदह जिलों में सात हजार दलित मुस्लिम परिवारों पर किए गए 2015 के एक अन्य अध्ययन में, कई लोगों ने बताया कि मुस्लिम दावतों में उन्हें अलग बैठाया जाता है। उत्तरदाताओं ने यह भी पुष्टि की कि वे उच्च जाति के मुसलमानों के बाद ही भोजन करते हैं। कई लोगों ने बताया कि उन्हें अलग थालियों में खाना परोसा जाता है। लगभग आठ प्रतिशत ने बताया कि उनके बच्चों को कक्षाओं में और स्कूल के दोपहर के भोजन के दौरान भी अलग पंक्तियों में बैठाया जाता है। इसी तरह, उनमें से कम से कम एक तिहाई ने कहा कि उन्हें अपने मृतकों को उच्च जाति के मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाने की अनुमति नहीं है। उन्हें कहीं और जाने के लिए कहा जाता है या मुख्य मैदान का एक कोना दिया

जाता है।
यह उल्लेखनीय है कि जब दलित मुस्लिम उत्तरदाताओं से उच्च जाति के मुस्लिम और हिंदू घरों में अपने अनुभवों को साझा करने का अनुरोध किया गया, तो उनमें से लगभग तेरह प्रतिशत ने मुस्लिम घरों में अलग-अलग बर्तनों में भोजन/पानी प्राप्त करने की सूचना दी, जबकि हिंदू घरों के मामले में यह अनुपात लगभग छियालीस प्रतिशत था।
इस अध्याय के बाद के एक खंड में बी.आर. अंबेडकर द्वारा मुस्लिम जातिगत दुर्व्यवहारों की तीखी आलोचना दी गई है।
जाति और ईसाई धर्म
2003 में, पोप जॉन पॉल द्वितीय ने तमिलनाडु के बिशपों को संबोधित करते हुए भारत में कैथोलिक चर्च में जातिगत भेदभाव की आलोचना की। उन्होंने कहा: 'चर्च का यह दायित्व है कि वह निरंतर हृदय परिवर्तन के लिए कार्य करे, सभी लोगों को यह समझने में मदद करे कि प्रत्येक मनुष्य ईश्वर की संतान, मसीह का भाई या बहन है, और इसलिए हमारे अपने परिवार का सदस्य है।' उनके इस आह्वान के बावजूद, आज भी समाचार पत्रों में ऐसे विज्ञापन देखने को मिलते हैं जिनमें ईसाई 'कैथोलिक ब्राह्मण' जीवनसाथी की तलाश करते हैं।
दलितक्रिश्चियंस डॉट कॉम वेबसाइट एक सक्रिय आंदोलन को समर्पित है जो चर्च से जातिगत भेदभाव को समाप्त करने और इस पाखंड से खुद को मुक्त करने की मांग करती है। यह वेबसाइट भारतीय ईसाइयों के बीच जाति और अस्पृश्यता के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है।
अपने समुदाय में जातिगत भेदभाव को लेकर कई वर्षों तक इनकार करने के बाद, भारत में चर्च ने अंततः आंतरिक भेदभाव को स्वीकार किया और अपने ईसाई दलितों और निचली जातियों के लिए नौकरियों और शिक्षा में विशेष कोटा की मांग शुरू कर दी।

अमेरिका में रहने वाले भारतीय ईसाइयों के बीच भी, केरल की जातियों और तमिल जातियों के लिए अलग-अलग चर्च हैं।

हिंदू होने के लिए जाति होना आवश्यक नहीं है
कई हिंदू जाति व्यवस्था का पालन नहीं करते, इसलिए हिंदू होने के लिए जाति कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। उदाहरण के लिए, हिंदू कई पीढ़ियों से सूरीनाम, मॉरीशस, बाली, फिजी और भारत के बाहर अन्य स्थानों पर बसे हुए हैं। वे कट्टर हिंदू हैं, लेकिन जाति व्यवस्था का पालन नहीं करते। उनमें से कई तो अपनी जाति जानते भी नहीं हैं, क्योंकि उनके पूर्वज एक सदी से भी अधिक समय पहले गिरमिटिया मजदूर के रूप में भारत छोड़कर चले गए थे और उनका अपने पूर्वजों से संपर्क टूट गया था। वे सभी प्रकार के हिंदुओं से स्वतंत्र रूप से विवाह करते हैं और साथ में भोजन करने या पूजा स्थलों को साझा करने पर कोई रोक नहीं है। (दूसरी ओर, मारवाड़ी और पटेल जैसी कुछ प्रवासी जातियों ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखी है।)
उपरोक्त तथ्य सिद्ध करते हैं: हिंदू होने के लिए जाति न तो अनिवार्य शर्त है और न ही पर्याप्त शर्त। जाति व्यवस्था का पालन किए बिना भी कोई हिंदू हो सकता है; इसके विपरीत, हिंदू हुए बिना भी जाति व्यवस्था का पालन किया जा सकता है।

वास्तविक व्यवहार में जन्म-आधारित पदानुक्रम के सामने चुनौतियाँ
अनेक प्रसिद्ध घटनाएँ दर्शाती हैं कि हिंदू धर्म के उच्चतम वर्गों को भी जन्म के आधार पर भेदभाव करने पर चुनौती दी गई है। इसका एक उदाहरण आदि शंकराचार्य का है: उन्होंने एक चांडाल को अपने रास्ते से हटने के लिए कहा, जिसने उनके इस व्यवहार पर सवाल उठाया कि क्या यह

उनके दर्शन के अनुरूप है। तब शंकराचार्य ने गुरु के समक्ष प्रणाम किया, अपने अद्वैत दर्शन को दोहराया और श्लोकों का एक प्रसिद्ध पाठ किया। पहले श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर को जानता है, चाहे उसकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, वही उसका गुरु है। कई महत्वपूर्ण आधुनिक गुरु जन्म से ब्राह्मण नहीं रहे हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, इस्कॉन के श्री प्रभुपाद और स्वामी चिन्मयानंद।

जातिगत नियमों की व्याख्या या उन्हें लागू करने वाली कोई केंद्रीय संस्था न होने के कारण, आम नागरिकों के लिए इस तरह की चुनौतियाँ और आवागमन स्वैच्छिक थे। समुदाय की स्थिति के इस स्वतंत्र निर्धारण के कारण, कई जातियों की रैंकिंग विवाद का विषय थी। कई जातियाँ दूसरों से श्रेष्ठ होने का दावा करती थीं। कुछ जातियाँ पवित्रता के नियमों का पालन करके या जनेऊद समारोह और कुछ पूजा-पाठ करके ऐसा करती थीं। कई मामलों में, जिन्हें शूद्र माना जाता था, वे स्वयं को क्षत्रिय समझते थे।

जाति व्यवस्था पर अपने कार्यों के लिए प्रसिद्ध मानवविज्ञानी और समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवासन ने इसे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कहा। यह एक ऐसा माध्यम था जिसके द्वारा संपूर्ण समूह अपनी जातिगत स्थिति में सुधार कर सकते थे, क्योंकि अंतिम निर्णय लेने के लिए कोई चर्च जैसी सत्ता नहीं थी। केवल अंग्रेजों ने ही आधिकारिक जाति कानून बनाए और उन्हें लागू किया।

Shudras and Vanavasis

यह खंड शूद्रों के बारे में विद्वानों द्वारा फैलाई गई उन कई गलत धारणाओं का खंडन करता है जिनमें कहा गया है कि प्राचीन वैदिक काल से ही शूद्र

गुलाम और शोषित रहे हैं। बेशक, हर तरह के अत्याचार के खिलाफ लड़ना जरूरी है, लेकिन यह सबसे अच्छा तरीका है तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित सटीक दृष्टिकोण अपनाना। गलत निदान हमेशा नुकसानदायक होता है और गलत समाधानों की ओर ले जाता है। यह बात विशेष रूप से तब सच होती है जब पहचान की राजनीति शामिल हो।

शूद्र सम्राटों, राजाओं और सैनिकों के रूप में

यह स्पष्ट है कि वर्ण व्यवस्था जन्म से ही स्थिर और अपरिवर्तनीय नहीं थी। यद्यपि प्राचीन भारत में व्यवसाय अक्सर माता-पिता के वर्ण के अनुरूप होता था, महान महाकाव्यों, बौद्ध जातक कथाओं और हिंदू एवं बौद्ध साहित्य में वर्णित शिल्पों की सूचियों से यह सिद्ध होता है कि एक वर्ण या जाति में जन्मा व्यक्ति यदि अपनी वंशानुगत भूमिका निभाने में असमर्थ हो या अपनी रुचि या प्रतिभा के कारण किसी अन्य वर्ण या जाति की ओर आकर्षित हो तो वह दूसरे वर्ण या जाति में जा सकता था।

वास्तव में, वैदिक काल में शूद्रों को राजाओं और सम्राटों के पदों पर आसीन देखा जा सकता है। कुछ दलित विद्वानों का दावा है कि शूद्र भारत की गैर-आर्य मूल निवासी जाति थे, जिन्हें आक्रमणकारी आर्यों ने जीत कर गुलाम बना लिया था। हालांकि, अंबेडकर इस सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज करते हैं और जोर देते हैं कि शूद्र, अन्य सभी भारतीयों की तरह, मूल निवासी थे। वे आगे पुष्टि करते हैं कि प्राचीन भारत के कुछ सबसे प्रख्यात और शक्तिशाली राजा शूद्र थे। महाभारत में एक शूद्र राजा द्वारा यज्ञों के संचालन का उल्लेख है। अंबेडकर इस राजा की पहचान ऋग्वेद में वर्णित सुदास से करते हैं।

अंबेडकर के इस विचार की पुष्टि अन्य ऐतिहासिक प्रमाणों से भी होती है: चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत के नंदा वंश के शासक हिंदू, जैन

और बौद्ध धर्मग्रंथों के अनुसार शूद्र थे। इसका अर्थ है कि उत्तरी भारत के महान सम्राट महापद्म नंदा शूद्र थे।
इसी प्रकार, भारत के अगले महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी शूद्र थे। मौर्य साम्राज्य भारत का अब तक का सबसे विशाल साम्राज्य था, और पहली बार एक केंद्रीकृत सरकार के अधीन अखिल भारतीय राष्ट्रीयता की स्थापना हुई। यह उल्लेखनीय है कि ऐसे साम्राज्य का मुखिया एक शूद्र था।
बाद में, गुप्त काल के दौरान सौराष्ट्र, अवंती, अर्बुदा और मालवा क्षेत्रों में शूद्र राजाओं का शासन था।
बौद्ध धर्मग्रंथों के अनुसार, शक्तिशाली पाल वंश, जिसने आठवीं शताब्दी के मध्य से ग्यारहवीं शताब्दी तक लगभग चार सौ वर्षों तक बंगाल और पूर्वी भारत के अन्य भागों पर शासन किया, शूद्र मूल का था। बौद्ध ग्रंथ मंजुश्री-मूल-कल्प में कहा गया है कि पाल वंश के संस्थापक गोपाल (750-1160 ईस्वी) शूद्र थे। पाल वंश के सम्राट बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे, और उनके ताम्रपत्र शिलालेख बुद्ध की स्तुति से शुरू होते हैं।
मध्यकालीन भारत में, तेलुगु भाषी आंध्र क्षेत्र पर शासन करने वाले काकतीय वंश के सम्राटों (लगभग 1163-1323 ईस्वी) ने अपने शिलालेखों में स्वयं को शूद्र घोषित किया। मध्यकालीन आंध्र समाज की एक विशेषता यह थी कि कई प्रमुख योद्धा परिवार स्वयं को क्षत्रिय होने का दावा नहीं करते थे, बल्कि गर्व से भगवान ब्रह्मा के चरणों से वंशज होने का उल्लेख करते हुए अपने शूद्र होने की घोषणा करते थे।
मध्यकालीन आंध्र में शूद्रों के पास वास्तविक राजनीतिक शक्ति का उच्चतम स्तर था।
शूद्र राजा हमेशा स्वयं को हिंदू समाज का अभिन्न अंग मानते थे। प्राचीन भारत में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिससे यह संकेत मिले कि उन्होंने

कभी स्वयं को इसके विपरीत माना हो।
आंध्र प्रदेश के प्रमुख प्रोलय नायक के एक महत्वपूर्ण संस्कृत शिलालेख में 1329 में मुसलमानों से एक बड़े क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए शूद्रों द्वारा किए गए आंदोलन का उल्लेख है।
फिर शूद्र जाति के मुसुमुरी परिवार के मुखिया प्रोलाया का उदय हुआ। उनकी शक्ति का सामना न कर पाने के कारण यवन अपने किले छोड़कर अज्ञात स्थानों पर भाग गए। उन्होंने अग्रहार भूमि ब्राह्मणों को वापस सौंप दी और वैदिक यज्ञों को पुनः स्थापित किया। उन्होंने तरुष्कों के आवागमन से आंध्र प्रदेश में फैली अपवित्रता को यज्ञ की अग्नि से निकलने वाले घी के धुएँ से दूर किया।
एक अन्य उदाहरण तब सामने आया जब 1320 में एक महार (अंबेडकर का समुदाय) ने इस्लाम से हिंदू धर्म में पुनः परिवर्तित होकर हिंदू शासन की स्थापना की। अरविंद शर्मा का मानना है कि इससे यह संकेत मिलता है कि महार स्वयं को हिंदू धर्म के अंतर्गत मानते थे।
यह मान लेना उचित नहीं होगा कि केवल कुछ भाग्यशाली शूद्र ही शासक बने जबकि आम जनता हाशिए पर जीवन व्यतीत करती रही। वैदिक काल और उसके बाद के काल में शूद्र वर्ण ने समग्र रूप से सामाजिक-राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राज्य के शासन तथा सेना में उच्च पदों पर उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा।
अश्वमेध यज्ञ के दौरान, शूद्रों ने विश्व विजय अभियान पर भेजे गए घोड़े की रक्षा के लिए सशस्त्र रक्षकों के रूप में कार्य किया।
800 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व की अवधि के दौरान, शूद्रों को रत्निन कहलाने वाले लगभग एक दर्जन 'राज्य के उच्च पदाधिकारियों' के प्रतिष्ठित निकाय में स्थान प्राप्त हुआ। [80]
महाभारत में यह भी अनुशंसा की गई है कि राजा को सलाह देने के लिए

आठ मंत्रियों का एक दल होना चाहिए, जिसमें चार ब्राह्मण और तीन शूद्र शामिल हों। इसमें यह भी उल्लेख है कि हस्तिनापुर के राजा के रूप में युधिष्ठिर के भव्य राज्याभिषेक में शूद्रों को आमंत्रित किया गया था।
उत्तर मध्यकालीन युग में, हम पाते हैं कि शूद्रों को पराक्रमी योद्धा छत्रपति शिवाजी (शासनकाल 1674-80) की सेना और भारत के अन्य शासकों की सेना में सैनिकों के रूप में आम तौर पर नियुक्त किया जाता था। इनमें से कई रामोशी, महार और मांग जैसी तथाकथित अछूत जातियों से संबंधित थे।
यह परंपरा ब्रिटिश भारत में भी जारी रही और सैनिकों ने इसे अपनी पूर्ववर्ती क्षत्रिय परंपरा की निरंतरता के रूप में देखा। आज भी, भारतीय सेना में एक महार रेजिमेंट है जिसने दो सेना प्रमुख दिए हैं, कई युद्ध सम्मान जीते हैं और देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, परम वीर चक्र प्राप्त किया है। कई दलित समुदाय वर्तमान में क्षत्रिय वंश का दावा करते हैं और अक्सर उनके क्षत्रिय नाम होते हैं, जिसकी पुष्टि भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण द्वारा की गई है। पूरे भारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां दलित स्वयं को क्षत्रिय मानते हैं।
महार सैनिक मराठों और अन्य शासकों के प्रति अपनी सैन्य सेवा में विशेष रूप से निष्ठावान थे। हिंदू पेशवाओं ने भी शाही परिवार की महिलाओं की सुरक्षा के लिए महारों को नियुक्त किया था। मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा मराठा राजकुमार संभाजी की हत्या के बाद, संभाजी के पुत्र ने सिधनक महार को मराठा राज्य की सेवा के लिए एक स्वतंत्र महार पलटन गठित करने के लिए सम्मानित किया।

आर्थिक शक्ति और सामाजिक स्थिति

शूद्रों को हमेशा असहाय और गरीब के रूप में चित्रित किए जाने के

विपरीत, अभिलेख दर्शाते हैं कि वे वैदिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। वेदों में उनसे जुड़े कई प्रकार के तकनीकी शिल्पों और उद्योगों का उल्लेख है। पी.वी. केन ने 62 विभिन्न शूद्र उद्योगों का उल्लेख किया है जिनमें चमड़ा उद्योग, धातु विज्ञान और वस्त्र उद्योग शामिल हैं, जिनका स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण उन्हीं के पास था। दूसरे शब्दों में, वे स्वरोजगार करते थे, न कि श्रमिक।

शूद्र कारीगरों और शिल्पकारों को बड़े शिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाता था और वेदों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राजा का कर्तव्य ऐसे संस्थानों का निर्माण करना है। ऋग्वेद के कई मंत्रों में कहा गया है कि राजा को शिल्पकारों और शिल्पकारों की रक्षा और सहायता भी करनी चाहिए।

ब्राह्मणों और क्षत्रियों का शूद्रों के अधीन काम करना असामान्य नहीं था। केरल में कई आयुर्वेदिक चिकित्सक और संस्कृत विद्वान शूद्र एझवा समुदाय से संबंधित थे। उदाहरण के लिए, इट्टी अचूदान सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध के एक प्रतिष्ठित एझवा जड़ी-बूटी विशेषज्ञ थे, जिनका कथन प्रसिद्ध पुस्तक 'हॉर्टस मालाबारिकस' के आरंभ में मिलता है। पौधों के औषधीय गुणों पर यह वनस्पति विज्ञान संबंधी ग्रंथ यूरोपियों के वनस्पति विज्ञान के ज्ञान के सबसे प्रारंभिक स्रोतों में से एक माना जाता है। यह 1678 और 1703 के बीच एम्स्टर्डम से बारह खंडों में प्रकाशित हुआ था।

प्राचीन काल में, शूद्र और वैश्य जो एक ही आर्थिक क्षेत्र में मिलकर काम करते थे, उन्हें सामूहिक रूप से सुद्रार्यों कहा जाता था। अनेक शिलालेखों से पता चलता है कि ये संघ बैंकों की तरह भी कार्य करते थे, जनता से ब्याज पर जमा राशि प्राप्त करते थे और उधारकर्ताओं को धन उधार देते थे।

विधिकार मेधातिथि की मनुस्मृति पर टीका कहती है कि शूद्र व्याकरण और अन्य विज्ञानों का शिक्षण करते हैं, जिसका उल्लेख बृहद्धर्म पुराण में भी मिलता है। आपस्तम्भ धर्मसूत्र कहता है कि स्त्री और शूद्रों में परंपरागत रूप से विद्यमान विद्या या ज्ञान अथर्ववेद का पूरक है।
याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति और विष्णु स्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथ यह सिद्ध करते हैं कि शूद्र कारीगरों और शिल्पकारों के संघ राज्य व्यवस्था का हिस्सा थे और उन्हें उच्च सम्मान प्राप्त था। ये संघ देश के न्यायिक न्यायाधिकरणों का भी हिस्सा थे। गौतम धर्मशास्त्र में उल्लेख है कि उन्हें अपने कानून बनाने का अधिकार था जिनका राजा सम्मान करता था। पूरे लिखित इतिहास में, इन संघों को सामाजिक रूप से उच्च स्थान प्राप्त था। वास्तव में, प्राचीन भारत में शूद्र संघों ने काफी आर्थिक समृद्धि का आनंद लिया।
उत्तरी भाग में बारहवीं शताब्दी तक गिल्ड प्रणाली कार्यरत रही, जिसके बाद मुस्लिम आक्रमणों ने गिल्डों को गतिहीन और जड़ बना दिया, जिसके परिणामस्वरूप उनका पतन और उपविभाजन हुआ।
उस समय के धनी वर्ग का हिस्सा होने के नाते, उन्होंने बड़े दान भी किए। इसका प्रमाण अनेक शिलालेखों में मिलता है जिनमें शूद्रों को परोपकारी बताया गया है। छठी से तीसरी शताब्दी के जैन आगम, जिनमें महावीर की शिक्षाएँ शामिल हैं, शूद्रों की आर्थिक समृद्धि और उनके प्रति सामाजिक सम्मान का चित्र प्रस्तुत करते हैं। सातवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत आने वाले चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने शूद्रों को कृषक वर्ग के रूप में उल्लेख किया है।
अगले पृष्ठ पर दिया गया चित्र परंपरागत भारतीय समाज में शूद्रों द्वारा निभाई गई बहुआयामी भूमिका को दर्शाता है।

शूद्रों के बीच अस्पृश्यता

आम तौर पर यह माना जाता है कि छुआछीपी का अभ्यास केवल उच्च वर्णों द्वारा शूद्रों और दलितों के उत्पीड़न के रूप में किया जाता था। हालांकि, छुआछीपी इन समुदायों में भी मौजूद थी और ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म अपनाने के बाद भी बनी रही। इस बात के प्रमाण हैं कि ईसा युग की शुरुआत तक, अछूतों ने स्वयं एक जाति व्यवस्था विकसित कर ली थी और उनके अपने अछूत थे। इस प्रकार, मनु ने उल्लेख किया है कि चांडाल और निषाद (जो एक निम्न जाति थी) के मिश्रित विवाह से जन्मे अंत्यवासयिन को चांडाल भी तिरस्कृत करते थे। इसी प्रकार, लगभग प्रत्येक अछूत समूह यह महसूस करता था कि दूसरा समूह उनसे नीचा है। आज भी, प्रत्येक क्षेत्र में अनुसूचित जातियों में एक ऐसी पदानुक्रमिक व्यवस्था है जो कुछ समुदायों से पानी और फल के आदान-प्रदान को प्रतिबंधित करती है। उदाहरण के लिए, दक्षिण भारत में, एक माला, मदिगा को अछूत मानता है, और दोनों के लिए, एक थोटी अछूत है। इसी प्रकार उत्तर भारत में, एक मेघवाल के लिए, एक रेगर अछूत है, और दोनों के लिए, एक भंगी अछूत है। इसी तरह, आदि द्रविड़, धोबी, माला और मदिगा समुदायों से भोजन और पानी स्वीकार नहीं करते हैं। विडंबना यह है कि कई अनुसूचित जातियां (छियानवे प्रतिशत) वर्तमान में अंतर्विवाही हैं।

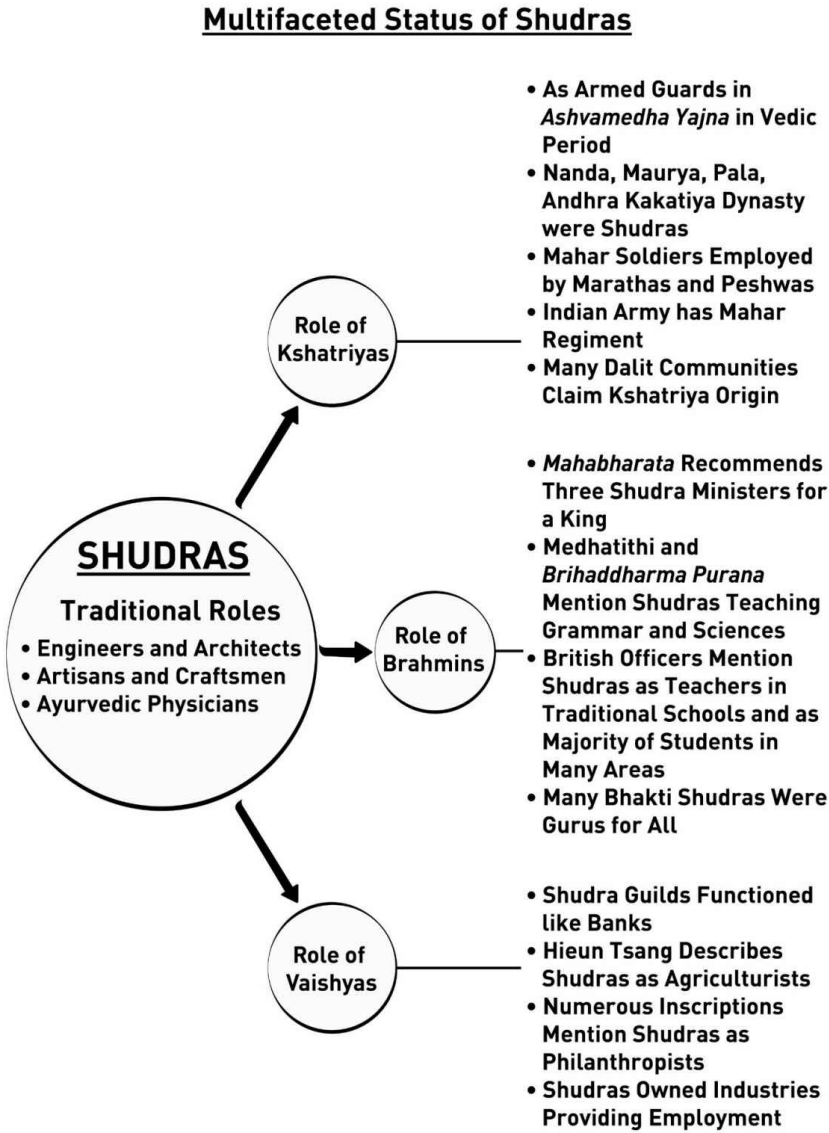

ब्रिटिश शासन से पहले स्वदेशी शिक्षा

कुछ विद्वान वर्तमान में यह दावा करते हैं कि शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं दिया गया। इन सिद्धांतों के अनुसार, इसी भेदभाव के

कारण शूद्र निरक्षरता में डूबे रहे। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि भारत में शिक्षा, चाहे प्राचीन काल में हो या ब्रिटिश शासन तक, ब्राह्मणों और क्षत्रियों का विशेषाधिकार थी। इस मत के अनुसार, शूद्रों को मुक्ति तभी मिली जब अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की और उन्हें समान अवसर प्रदान किए। हालांकि, सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है।

गांधी जी के सबसे निष्ठावान अनुयायियों में गिने जाने वाले विद्वान धर्मपाल ने भारत से संबंधित आधिकारिक अभिलेखों का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड में काफी समय व्यतीत किया। उनका उद्देश्य ब्रिटिश अभिलेखों के अनुसार औपनिवेशिक काल से पहले की भारतीय स्वदेशी शिक्षा की स्थिति पर एक अभिलेख तैयार करना था। उनकी पुस्तकें एक महत्वपूर्ण संदर्भ स्रोत हैं जो प्रख्यात इतिहासकारों द्वारा किए गए कई झूठे दावों का खंडन करती हैं।

धर्मपाल लिखते हैं:

मद्रास प्रेसीडेंसी और बंगाल-बिहार के आंकड़े एक तरह का खुलासा प्रस्तुत करते हैं। ये आंकड़े शिक्षकों और छात्रों की पृष्ठभूमि को उजागर करते हैं। यह पिछले 100 वर्षों या उससे अधिक समय से चली आ रही विभिन्न विद्वानों की धारणाओं के बिल्कुल विपरीत है, जिनमें यह माना जाता था कि भारत में किसी भी प्रकार की शिक्षा, हाल के दशकों तक, हिंदुओं में मुख्य रूप से द्विज और मुसलमानों में शासक वर्ग तक ही सीमित थी। जो वास्तविक स्थिति सामने आई है, वह इससे भिन्न थी, बल्कि इसके बिल्कुल विपरीत थी, कम से कम हिंदुओं के बीच, मद्रास प्रेसीडेंसी के जिलों (और विशेष रूप से तमिल भाषी क्षेत्रों में) और बिहार के दोनों जिलों में। इन क्षेत्रों में मौजूद हजारों स्कूलों में शूद्र कहलाने वाले समूह और उनसे नीचे मानी जाने वाली जातियां ही प्रमुख थीं।

दूसरे शब्दों में कहें तो, शूद्रों और अन्य निम्न सामाजिक वर्गों के समुदायों को पारंपरिक भारतीय शिक्षा तक अच्छी पहुँच प्राप्त थी। धर्मपाल ने भारत की स्वदेशी शिक्षा प्रणाली पर ब्रिटिश सर्वेक्षणों का उपयोग करते हुए सटीक आँकड़े प्रस्तुत किए हैं। अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका में 1825 में मद्रास प्रेसीडेंसी के उनके निष्कर्षों का सारांश दिया गया है।

Community Profile of Boys Undergoing Instruction in Schools and at Home in the District of Madras, ca.1825

	Brahmins	Vaisyas	Sudras	Other Castes	Hindus	Muslims	Total
Instructed in Schools	410	853	3,678	447	5,370	153	5,523
% of Total	*7.42*	*15.12*	*66.59*	*8.09*	*97.23*	*2.77*	
Instructed at Home	7,586	6,132	7,589	3,449	24,756	1,690	26,446
% of Total	*28.68*	*23.19*	*28.70*	*13.04*	*93.61*	*6.39*	
Total	**7,996**	**6,967**	**11,267**	**3,896**	**30,126**	**1,843**	**31,969**

स्रोत: धरमपाल, द ब्यूटीफुल ट्री

स्पष्टत:, विद्यालयों में शूद्रों का प्रतिशत (66.59) अन्य सभी वर्णों के कुल प्रतिशत से अधिक है। साथ ही, घर की तुलना में विद्यालयों में अधिक शूद्रों को शिक्षा प्राप्त हुई, जो औपचारिक शिक्षा तक आसान पहुँच को दर्शाता है।

इसी प्रकार, धर्मपाल बताते हैं कि मलयालम भाषी मालाबार में, शूद्र और अन्य ऐसी जातियाँ स्कूली छात्रों का लगभग चौवन प्रतिशत थीं। कन्नड़ भाषी बेल्लारी में, ब्राह्मण और वैश्य छात्रों का अनुपात तैंतीस प्रतिशत था, जबकि शूद्र और अन्य निम्न वर्गों के छात्र स्कूली छात्रों का तिरसठ प्रतिशत थे। उड़िया भाषी गंजाम में भी स्थिति समान थी: ब्राह्मण और वैश्य छात्रों का अनुपात 35.6 प्रतिशत था, और निम्न वर्गों के छात्र लगभग 63.5 प्रतिशत थे। अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका मद्रास प्रेसीडेंसी

के विभिन्न क्षेत्रों में स्वदेशी स्कूलों में छात्रों के वर्णवार विभाजन का प्रतिशत दर्शाती है।

यह प्रवृत्ति केवल प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा तक ही सीमित नहीं थी। मद्रास प्रेसीडेंसी के सर्वेक्षणों के अनुसार, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा का अभ्यास करने वाले लोग विभिन्न जातियों से संबंधित थे। ब्रिटिश चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार, उनमें से नाई जाति के लोग सर्वश्रेष्ठ शल्य चिकित्सक थे। खगोल विज्ञान एक और विषय था जिसमें अधिकांश छात्र शूद्र थे।

धर्मपाल के निष्कर्षों का समर्थन इस तथ्य से होता है कि ब्रिटिश प्रशासक थॉमस मुनरो ने 1822 में मद्रास प्रेसीडेंसी में स्वदेशी भारतीय शिक्षा के अपने सर्वेक्षण में स्पष्ट रूप से कहा था कि ऐसा कोई संकेत नहीं है कि शूद्र होने के कारण बच्चों को स्थानीय भाषा के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने से रोका गया हो। [120]

Community Profile of Boys Studying in the Indigenous Schools, ca.1825

Linguistic Region		Brahmins	Vaisyas	Sudras	Other Castes	Hindus	Muslims
Odiya	Students	808	243	1,001	886	2,938	27
	% of Total	*27.25*	*8.20*	*33.76*	*29.88*	*99.09*	*0.91*
Telugu	Students	13,893	7,676	10,076	4,755	36,521	1,639
	% of Total	*36.41*	*20.12*	*26.40*	*12.46*	*95.70*	*4.30*
Kannada	Students	1,233	1,004	3,296	1,332	6,865	329
	% of Total	*17.14*	*13.96*	*45.82*	*18.52*	*95.43*	*4.57*
Malayalam	Students	2,230	84	3,697	2,756	8,767	3,196
	% of Total	*18.64*	*0.70*	*30.90*	*23.04*	*73.28*	*26.72*
Tamil	Students	11,557	4,442	57,873	13,196	87,437	5,453
	% of Total	*12.44*	*4.78*	*62.30*	*14.21*	*94.13*	*5.87*
Presidency Total	Students	29,721	13,449	75,943	22,925	1,42,528	10,644
	% of Total	*19.40*	*8.78*	*49.58*	*14.97*	*93.05*	*6.95*

स्रोत: धरमपाल, द ब्यूटीफुल ट्री

शूद्र न केवल छात्रों में प्रमुख थे बल्कि शिक्षकों का भी एक बड़ा हिस्सा थे। ब्रिटिश विद्वान विलियम वार्ड ने बंगाल के स्वदेशी विद्यालयों के अपने

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक विवरण में कहा है कि विद्यालयों में शिक्षक आम तौर पर शूद्र होते थे और कभी-कभार ब्राह्मण होते थे। [121]

दलित हिंदू गौरव

कुछ आधुनिक विद्वान दावा करते हैं कि शूद्र और दलित हिंदू नहीं हैं। यह समाज को बांटने और खंडित करने के एजेंडे को बढ़ावा देता है। हालांकि, यदि हम भारत सरकार द्वारा किए गए विभिन्न जनसंख्या जनगणना रिपोर्टों और व्यापक सर्वेक्षणों को देखें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि शूद्रों और दलितों का एक बड़ा बहुमत गर्व से खुद को हिंदू मानता है।

भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण द्वारा अपने विशाल 'भारत के लोग' परियोजना (1985-92) के अंतर्गत किए गए अध्ययन को एक विश्वसनीय संदर्भ के रूप में लिया जा सकता है। इसका उद्देश्य भारत के सभी समुदायों की मानववैज्ञानिक रूपरेखा प्रस्तुत करना था। रिपोर्ट में कई रोचक तथ्य सामने आते हैं:

अनुसूचित जाति समुदाय के 96.9 प्रतिशत लोगों ने स्वयं को हिंदू बताया।

दक्षिण कैरोलिना के 79.8 प्रतिशत समुदाय जल संसाधनों को अन्य समुदायों के साथ साझा करते हैं और 67 प्रतिशत समुदाय श्मशान घाटों को अन्य समुदायों के साथ साझा करते हैं।

उनमें से 91 प्रतिशत लोग अन्य समुदायों के समान ही धार्मिक स्थलों पर जाते हैं।

अनुसूचित जाति समुदायों के 91 प्रतिशत लोग पारंपरिक हिंदू त्योहारों और उत्सवों में भाग लेते हैं, और इनमें से 17.6 प्रतिशत लोगों की इन त्योहारों में विशेष भूमिका होती है।

इसके अलावा, अंबेडकर ने भौतिक मानवशास्त्रीय आंकड़ों का उपयोग

करते हुए विशेष रूप से यह तर्क दिया कि महाराष्ट्र में महारों और कुछ ब्राह्मण समूहों तथा उत्तर प्रदेश में चमारों और ब्राह्मणों के बीच कोई जातीय अंतर नहीं था।

कई शोधकर्ताओं ने यह भी बताया है कि क्षेत्रों के बीच आनुवंशिक अंतर किसी दिए गए क्षेत्र की जातियों के बीच भिन्नताओं से अधिक हैं।

भारत में तीन सबसे बड़े दलित या अनुसूचित जाति समुदायों - चमार, आदि द्रविड़ और पासी - के धार्मिक जीवन के बारे में पुख्ता सबूत मौजूद हैं। इनसे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वे स्वयं को हिंदू मानते रहे हैं।

चमार भारत का सबसे बड़ा अनुसूचित जाति या दलित समुदाय है और लगभग सभी उत्तरी राज्यों में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में इन्हें रैदासी के नाम से जाना जाता है क्योंकि वे स्वयं को हिंदू वैष्णव संत रैदास के आध्यात्मिक वंशज मानते हैं। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में उनके विवाह वैदिक परंपरा के अनुसार संपन्न होते हैं और रैदास के अलावा वे हिंदू देवी-देवताओं की भी पूजा करते हैं। हरियाणा में भी, रैदास के अनुयायी जिन्हें जाटव कहा जाता है, साथ ही संत कबीर के अनुयायी जिन्हें जुलाहा कहा जाता है, लक्ष्मी और काली की पूजा करते हैं। वे अपने जन्म, विवाह और मृत्यु के अनुष्ठानों के लिए ब्राह्मणों की सहायता लेते हैं। दुर्गा पूजा और होली उनके प्रमुख त्योहार हैं।

आदि द्रविड़ भारत का दूसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जाति समुदाय है। वे स्वयं को हिंदू मानते हैं, हिंदू तीर्थ स्थलों पर जाते हैं और हिंदू त्योहार मनाते हैं। कर्नाटक में, वे दुर्गाम्मा, रेणुका, परशुराम, लक्ष्मी, वेंकटरमण आदि हिंदू देवी-देवताओं की पूजा करते हैं। आंध्र प्रदेश में, वे हिंदू धर्म का पालन करते हैं और दिवाली, दशहरा, गणेश चतुर्थी, पोंगल आदि त्योहार मनाते हैं।

भारत में तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति या दलित समुदाय, पासी,

इस पौराणिक कथा में विश्वास रखती है कि वे ऋषि परशुराम के पसीने (हिंदी में पसीना, इसलिए उनका नाम पासी पड़ा) से उत्पन्न हुए थे ताकि गायों को मारे जाने से बचाया जा सके। वे कई उत्तरी राज्यों में फैले हुए हैं और हनुमान, देवी और अन्य देवी-देवताओं की पूजा करते हैं, साथ ही काशी, प्रयाग, हरिद्वार, वृंदावन और नैमिषारण्य जैसे पवित्र हिंदू केंद्रों की तीर्थयात्रा करते हैं। आमतौर पर, उनके प्रमुख अनुष्ठानों में एक ब्राह्मण ही मुख्य भूमिका निभाता है। पासी अन्य जातियों के साथ कुओं, जल संसाधनों और धार्मिक स्थलों को साझा करते हैं और उनके साथ पारंपरिक त्योहारों में भाग लेते हैं। नीचे दिया गया चित्र भारत के कुछ दलित समुदायों की क्षेत्रीय स्थिति की झलक दिखाता है।

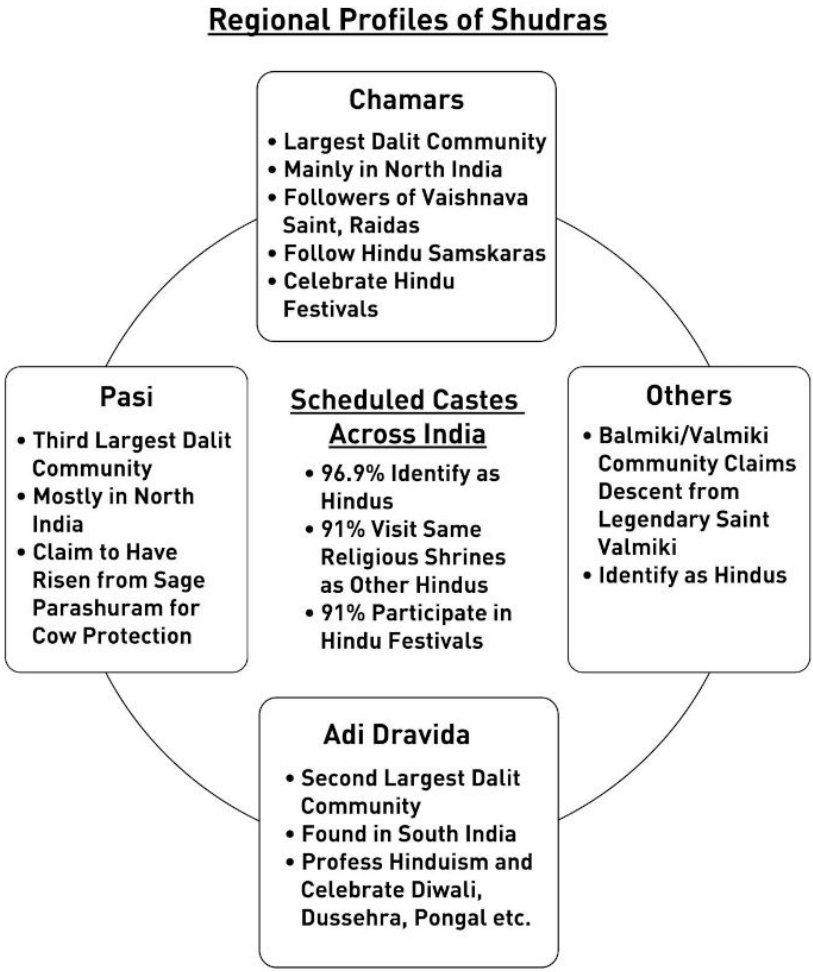

उनकी अपनी पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, मध्यकाल तक पासी उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में शासन करते थे। उनकी कुछ उपजातियाँ, जैसे राजपसी, राजपूतों से अपनी उत्पत्ति का दावा करती हैं।

हमें यह बताना आवश्यक है कि ब्रिटिश-पूर्व काल में घरों में शौचालय न होने के कारण हाथ से मैला ढोने का कोई चलन नहीं था। दलितों के लिए हाथ से मैला ढोने की प्रथा ब्रिटिशों की देन थी, जो उस समय लंदन में प्रचलित मैला ढोने की प्रथाओं पर आधारित थी। भंगी, मेहतर और अन्य

जातियों जैसे समुदाय ब्रिटिश शासन के दौरान मैला ढोने के काम से जुड़ गए। अब इन्हें सामूहिक रूप से बाल्मीकि/वाल्मीकि कहा जाता है और ये पौराणिक हिंदू संत वाल्मीकि से अपनी उत्पत्ति का दावा करते हैं। वे स्वयं को हिंदू भी मानते हैं।

Vanavasis

आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ है मूल निवासी। सभी भारतीयों को आदिवासी कहा जाना चाहिए, लेकिन अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नस्लीय नीतियों के तहत केवल कुछ समुदायों को ही स्वदेशी और बाकी को विदेशी आक्रमणकारी माना गया। 'आदिवासी' शब्द भी त्रुटिपूर्ण है क्योंकि यह अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के उन मूल निवासियों की याद दिलाता है जिन्हें विदेशी जातियों ने अधीन कर लिया था, और इस शब्दावली का उपयोग गैर-आदिवासियों को किसी विदेशी जाति के रूप में मानने के लिए किया गया है। भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कुछ लोगों के लिए 'स्वदेशी लोग' शब्द के प्रयोग का भी विरोध किया है क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि बाकी भारतीय विदेशी हैं।
हम ‘वनवासी’ शब्द का प्रयोग उन समुदायों के लिए करेंगे जो परंपरागत रूप से वन में निवास करते हैं, यह स्पष्ट करते हुए कि भिन्न भौगोलिक स्थिति किसी भिन्न नस्ल को नहीं दर्शाती है। हालांकि, सरकारी आंकड़ों के संदर्भ में हम भ्रम से बचने के लिए आधिकारिक शब्द ‘अनुसूचित जनजाति’ का ही प्रयोग करेंगे।
दलितों की तरह ही, आजकल कई दावे किए जाते हैं कि वनवासी हमेशा से गैर-हिंदू थे। हालांकि, 1931 के एक ब्रिटिश जनगणना अधीक्षक ने कहा कि उनके प्रांतों में वनवासी हिंदू रीति-रिवाजों का पालन करते थे, हिंदू जुलूसों में भाग लेते थे और हिंदू देवी-देवताओं की पूजा करते थे।

उन्होंने यह भी बताया कि अक्सर उन्हें अन्य हिंदुओं से अलग पहचानना मुश्किल होता था और वे खुद को हिंदू ही कहते थे।
हाल ही में, 'पीपल ऑफ इंडिया' परियोजना के अनुसार, विभिन्न अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अधिकांश लोगों ने स्वयं को हिंदू के रूप में पहचाना। उन्होंने सर्वेक्षणों में दिए गए अन्य विकल्पों, जैसे कि स्वदेशी जनजातीय धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम आदि के बजाय हिंदू धर्म को चुना। 1981 की जनगणना में, कुल अनुसूचित जनजाति आबादी का 87.05 प्रतिशत लोगों ने स्वयं को हिंदू के रूप में वर्गीकृत किया।
भारत में चार सबसे बड़े वनवासी समुदाय गोंड, भील, संथाल और मीना हैं।
संख्या के हिसाब से गोंड भारत की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, जो मध्य भारत के कई राज्यों में फैले विशाल भौगोलिक क्षेत्र में रहती है। वे एक समय राजनीतिक रूप से शक्तिशाली थे और मध्यकाल में उन्होंने चार अलग-अलग राज्यों पर शासन किया था। उनकी पौराणिक कथाओं के अनुसार, उनके पूर्वजों को भगवान शिव और माता पार्वती ने गोद लिया और उनका पालन-पोषण किया। वे हिंदू देवी-देवताओं की पूजा करते हैं और होली, दिवाली, दशहरा, राखी और संक्रांति जैसे सभी प्रमुख हिंदू त्योहार मनाते हैं।
भारत की दूसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति भील समुदाय है, जो दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र में फैली हुई है। वे भीली भाषा बोलते हैं, जो संस्कृत परिवार से संबंधित है। वे गुजरात का सबसे बड़ा वनवासी समुदाय हैं। लगभग सभी भील स्वयं को हिंदू मानते हैं और होली, दिवाली, नवरात्रि, राखी आदि त्योहार मनाते हैं। ऐतिहासिक रूप से, भीलों ने कई राजपूत सरदारों के राज्याभिषेक समारोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मीना राजस्थान की सबसे बड़ी और भारत की चौथी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। वे विष्णु के मीन अवतार से अपनी उत्पत्ति का पता लगाते हैं, इसीलिए उनका नाम मीना पड़ा। भगवान शिव उनके सर्वोच्च देवता हैं और वे हनुमान, सीता-राम और राधा-कृष्ण की भी पूजा करते हैं। 1961 और 1971 की जनगणना में, शत प्रतिशत मीना समुदाय ने स्वयं को हिंदू के रूप में दर्ज कराया था।

शूद्रों की तरह, कई वनवासी समुदायों ने प्रौद्योगिकीविदों और इंजीनियरों के रूप में हिंदू समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश की अगरिया जनजाति (नाम आग से लिया गया है) पारंपरिक रूप से लोहार और लोहे को गलाने और लोहे की वस्तुएं बनाने में विशेषज्ञ थे।

मुंडा समुदाय के लोग मध्य और उत्तरपूर्वी राज्यों में निवास करते हैं। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानी बीरसा मुंडा इसी समुदाय से थे। वे एक ब्राह्मण से प्रभावित थे जिन्हें वे अपना गुरु मानते थे। उन्होंने हिंदू महाकाव्यों का अध्ययन किया और उनके पौराणिक नायकों से प्रेरित हुए। भक्ति का पाठ करने वाले एक वैष्णव संत से मिलने के बाद वे शाकाहारी बन गए। बीरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों और जमींदारों तथा ब्रिटिश प्रशासकों के अत्याचारों के विरुद्ध भी आवाज उठाई। कई वनवासी समुदाय क्षत्रिय वंश के होने का दावा करते हैं।

यह उल्लेखनीय है कि ईसाई मिशनरियों द्वारा लंबे समय तक चलाए गए आक्रामक धर्मांतरण अभियानों के बावजूद, पूर्वोत्तर भारत की कई अनुसूचित जनजातियाँ स्वयं को बड़ी संख्या में हिंदू बताती हैं। उदाहरण के लिए, असम की ब्रह्मपुत्र घाटी की सबसे बड़ी जनजाति बोडो-कचारी में, 1971 की जनगणना में पंचानवे प्रतिशत लोगों ने स्वयं को हिंदू बताया था। वे वैष्णव मठों और मंदिरों के पवित्र तीर्थस्थलों में भी दर्शन

करते हैं।
असम की कचारी होजाई अनुसूचित जनजाति बोडो भाषाई समूह से संबंधित है, जो बच्चे का नामकरण और जनेऊ संस्कार जैसे प्रमुख हिंदू अनुष्ठानों का पालन करती है। वे शाक्त परंपरा से संबंधित हैं और खुद को क्षत्रिय मानते हैं। 1971 की जनगणना के अनुसार, होजाई समुदाय के सभी लोग हिंदू धर्म के अनुयायी थे। एक अन्य बोडो समुदाय कचारी बर्मन है और 1961 और 1971 की जनगणना के अनुसार, उन सभी ने स्वयं को हिंदू के रूप में वर्गीकृत किया था।

भक्ति आंदोलन
हिंदू धर्म के ढांचे के भीतर जातीय भेदभाव और विभाजन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए भक्ति आंदोलन सबसे प्रमुख आंदोलन था। पूरे भारत में इसका नेतृत्व तथाकथित निम्न जातियों में जन्मे कई संत कवियों ने किया, जिनमें महिला संत भी शामिल थीं।
भक्ति (जिसका व्यापक अर्थ है समर्पण) हमेशा से हिंदू धर्म का अभिन्न अंग रही है। उपनिषद, भगवद् गीता, महाभारत, रामायण और पुराणों में भक्ति की शिक्षाएं समाहित हैं। छठी शताब्दी ईस्वी में तमिलनाडु में शैव और वैष्णव संतों द्वारा इस प्राचीन परंपरा को व्यापक रूप से पुनर्जीवित किया गया। बारहवीं शताब्दी में कर्नाटक में, इसने जातिगत एकाधिकार के दावों के विरुद्ध आवाज उठाई, यहाँ तक कि ब्राह्मण की पुत्री का विवाह अछूत के पुत्र से कराने तक का मार्ग प्रशस्त किया।
भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म को एक जनमानस आंदोलन के रूप में लोकतांत्रिक बनाया। इसके अनुयायियों ने इस बात पर जोर दिया कि आध्यात्मिक ज्ञान के लिए केवल पुस्तकी ज्ञान ही आवश्यक नहीं है।

इससे वेदों तक एकाधिकार का दावा करने वालों का अधिकार प्रभावी रूप से कम हो गया, क्योंकि अब वेद ही एकमात्र मार्ग नहीं रह गए थे। हालांकि, यह कहना गलत होगा कि भक्ति ने वेदों के विरुद्ध विद्रोह किया; सच्चाई यह है कि इसकी शिक्षाएं वैदिक हैं। वास्तव में, कई महत्वपूर्ण भक्ति संतों ने वैदिक ग्रंथों पर टीकाएँ लिखीं और उनके अध्ययन की वकालत की।

भक्ति आंदोलन विविध था और पूरे भारत में फैला हुआ था। उत्तर भारत में कबीर, कर्नाटक में शिशुनाला शरीफ और महाराष्ट्र में शिरडी साई बाबा, ये सभी जन्म से मुस्लिम थे, लेकिन हिंदू धर्म में अत्यधिक पूजनीय भक्ति संत थे। महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन भी इसी तरह का था, जिसमें ब्राह्मणों के साथ-साथ निम्न जाति के श्रमिक वर्ग के लोग भी शामिल थे।

कुछ आधुनिक दावों के विपरीत कि शूद्रों ने कभी स्वयं को हिंदू नहीं माना, शूद्र पृष्ठभूमि से कई प्रभावशाली भक्ति संत हुए। हम कुछ प्रमुख उदाहरणों पर नज़र डालेंगे।

उत्तर में रविदास और कबीर

स्वामी रामानंदचार्य एक प्रभावशाली वैष्णव संत थे, जो जन्म से ब्राह्मण थे और उन्होंने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रसार किया। उनके बारह प्रमुख शिष्य थे, जिनमें से कई शूद्र थे जैसे संत रविदास, संत कबीर और संत सैन।

रविदास ने भक्ति का प्रसार करने के लिए पूरे उत्तर भारत की यात्रा की और विष्णु को समर्पित गहन भजन लिखे। रविदास की ख्याति दूर-दूर तक फैल गई। सोलहवीं शताब्दी की प्रसिद्ध महिला मीराबाई ने काशी में उनसे मिलने का उल्लेख किया है और उन्हें अपना गुरु माना है। संत रविदास ने अपने कई भक्ति गीतों में कहा है कि यद्यपि वे शूद्र जाति के चमार से

संबंध रखते हैं, वाराणसी के ब्राह्मण उनके समक्ष अत्यंत आदर से प्रणाम करते हैं।

पंद्रहवीं शताब्दी के कवि और संत कबीर, रामानंदचार्य के एक अन्य प्रभावशाली शिष्य थे। उनका जन्म वाराणसी में शूद्र समुदाय के बुनकर परिवार में हुआ था। वे भक्ति कवियों में सबसे प्रसिद्ध हैं और जनता के बीच उनके बहुत से अनुयायी हैं। उनके दोहे, या दो पंक्तियों की कविताएँ, विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना से ओतप्रोत हैं, जिन्हें वे राम या हरि कहते हैं, और भारतीय समाज के सभी वर्गों द्वारा, उनके वर्ण या जाति की परवाह किए बिना, लोकप्रिय रूप से गाए जाते हैं।

महाराष्ट्र के हिंदू संत

महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय (तेरहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध और चौदहवीं शताब्दी के आरंभिक काल) के संत कवि चोखामेला ने अपनी रचनाओं में उल्लेख किया है कि वे महार जाति से संबंध रखते थे, जिसे निम्नतम जाति माना जाता है। उन्होंने विष्णु और वेदों की स्तुति में अनेक भक्ति गीत रचे। उनके संप्रदाय के अन्य संत जैसे नामदेव, तुकाराम, गोरा कुम्भार, सावंत माली भी निम्न जातियों से संबंधित थे।

वारी तीर्थयात्रा महाराष्ट्र की एक जीवंत परंपरा है जिसमें भक्त वरकरी परंपरा के दो प्रमुख संतों - ब्राह्मण ज्ञानेश्वर और शूद्र तुकाराम - के नामों से प्रेरित मंत्रों का जाप करते हुए पैदल यात्रा करते हैं। यह इस परंपरा में ब्राह्मणों और शूद्रों की एकता को दर्शाता है। तुकाराम वैदिक परंपरा के प्रबल अनुयायी थे और उनके एक गीत में कहा गया है कि वेदों और पुराणों पर अविश्वास करने वाले व्यक्ति की ओर देखना भी नहीं चाहिए।
169

दक्षिण के हिंदू शूद्र संत

तमिल शैव धर्म के तिरसठ संत, जिन्हें नयनमार कहा जाता है, शूद्रों सहित

सभी वर्णों से संबंधित थे। इसी प्रकार, तमिल वैष्णव अलवर धर्म के बारह संतों में से कुछ शूद्र थे।

दलितों को मुख्यधारा समाज में एकीकृत करने वाले व्यापक सामाजिक आंदोलनों में केरल के एझवा और तमिलनाडु के नादार प्रमुख थे। औपनिवेशिक शासन के अधीन होने के बावजूद, दोनों ने हिंदू ढांचे के भीतर ही अपने सामाजिक परिवर्तन हासिल किए।

एझवा समुदाय के मामले में, नारायण गुरु एक शक्तिशाली नेता थे जिन्होंने उनकी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाया। जब एझवा समुदाय को भेदभाव का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने नए हिंदू मंदिरों का निर्माण और अभिषेक किया जहाँ दलित और गैर-दलित एक साथ प्रार्थना करते थे। उन्होंने आदि शंकराचार्य के दर्शन का प्रचार किया और इसे विश्व के लिए एक उत्कृष्ट योगदान बताया। उन्होंने दलितों को हिंदू अनुष्ठान करने और हिंदू दर्शन पढ़ाने के लिए पुरोहित के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए वैदिक विद्यालयों की स्थापना की। एक शिक्षाविद् के रूप में, नारायण गुरु ने सभी समुदायों के लिए धर्मनिरपेक्ष विद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना की और उनके कई महत्वपूर्ण शिष्य ब्राह्मण थे।

उन्होंने एझवा समुदाय से आगे बढ़कर अन्य दलितों को भी अपने साथ जोड़ा, ताकि उन्हें पेशेवर करियर बनाने के लिए शिक्षित किया जा सके। उनका कार्यक्रम दलितों के सर्वांगीण विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम था, जिसमें उनके बीच वित्तीय ऋण प्रणाली का विकास भी शामिल था।

नारायण गुरु ने अपने शिक्षकों को अन्य जातियों के साथ सद्भाव का उपदेश देने का प्रशिक्षण दिया और उन्हें उच्च जातियों का समर्थन प्राप्त था। दलितों को प्रमुख मंदिरों में प्रवेश दिलाने की मांग को लेकर सभी जातियों के संयुक्त जुलूस निकाले गए। गांधी और उन्होंने मिलकर इन

सुधारों को मुख्यधारा में लाने के लिए काम किया।
नादर समुदाय के पास नारायण गुरु जैसा कोई करिश्माई नेता नहीं था, फिर भी वे अपने धर्मनिरपेक्ष नेताओं के नेतृत्व में फले-फूले। उनके मामले में, यह मुख्य रूप से शिक्षा और रोजगार कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से संभव हुआ। उन्होंने मैत्रीपूर्ण ऋण समझौतों और अनौपचारिक रोजगार एजेंसियों के माध्यम से एक-दूसरे की मदद की, साथ ही स्वयं को संस्कृतनिष्ठ बनाया।
नादर समुदाय उद्योग जगत में आर्थिक रूप से शक्तिशाली बन गया। आधुनिक विद्वानों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि इस समुदाय में भारत के कुछ सबसे धनी उद्योगपति शामिल हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजीज के संस्थापक शिव नादर इसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले एक अरबपति उद्योगपति हैं। उनकी सफलता से कई सबक सीखे जा सकते हैं। उनका दृष्टिकोण हार्वर्ड विश्वविद्यालय के सूरज येंगडे के दृष्टिकोण से बिल्कुल विपरीत था। उनका लक्ष्य अपने पीड़ित होने की जागरूकता फैलाने या सरकार और समाज से विरोध प्रदर्शन करने और मांगें रखने के लिए उग्रवादी संगठन बनाना नहीं था।
बल्कि, उन्होंने अपनी उन्नति के लिए रचनात्मक पहल की स्थापना की। उदाहरण के लिए:
उन्होंने अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राजी कर लिया।
उन्होंने व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जिससे सदस्यों को अपने पारंपरिक व्यवसायों से बाहर काम करने की योग्यता प्राप्त हुई।
उन्होंने अपने सदस्यों को उन स्थानों पर स्थानांतरित होने में मदद की जहां नौकरियां उपलब्ध थीं।
उन्होंने अपने समुदाय में नशे की लत से लड़ाई लड़ी।

साथी नाडारों की देखभाल विस्तारित परिवार की तरह की जाती थी। यह उपलब्धि समाज के अन्य वर्गों के प्रति शत्रुतापूर्ण रुख अपनाए बिना हासिल की गई। सफलता अन्य समुदायों पर हमला करने के बजाय उनके साथ मिलकर काम करने के परिणामस्वरूप मिली।
आधुनिक हिंदू धर्म में कई ऐसे आंदोलन हुए हैं जिन्होंने अनुयायियों के नैतिक ताने-बाने और आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध बनाने में योगदान दिया है। स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो और अन्य विद्वानों के अनुसार, आधुनिक हिंदू धर्म ने जाति व्यवस्था को नकार दिया है। इसी प्रकार, ब्रह्मकुमारी, इस्कॉन, श्री सत्य साई बाबा और माता अमृतानानंदमयी के नेतृत्व वाले समूहों ने यह सिद्ध किया है कि हिंदू धर्म जाति व्यवस्था के बिना भी फल-फूल सकता है और उसे किसी बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

ब्रिटिश सामाजिक इंजीनियरिंग

ब्रिटिश यह स्वीकार करते हैं कि कोई कठोर जाति व्यवस्था अस्तित्व में नहीं थी।
ग्लासगो विश्वविद्यालय के मानवविज्ञानी प्रोफेसर साइमन चार्स्ले बताते हैं कि 1871 से 1901 तक की जनगणनाओं में भी अंग्रेजों ने भारतीय समाज को जातिगत ढांचे में ढालने का प्रयास किया। यह देखते हुए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी, भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति के 250 वर्षों बाद भी यही स्थिति बनी हुई है। चार्स्ले का विवरण इस प्रकार शुरू होता है:
जब सर हर्बर्ट रिस्ले 1901 की भारत जनगणना के आयुक्त बने, तो उन्होंने इसके दायरे में पूरे उपमहाद्वीप में जातियों के वर्गीकरण और

श्रेणीकरण का एक भव्य प्रयोग करने का निश्चय किया। ... जनगणना में अक्सर अलग-अलग जातियों की पहचान करने में भी कठिनाई आती थी और कुछ जनगणना क्षेत्रों में तो यह प्रक्रिया इस कारण विफल हो जाती थी कि जातियों के वर्गीकरण का कोई सार्थक तरीका खोजना असंभव था, जिससे विवादों का बवंडर खड़ा न हो जाए, जैसा कि 1871 की मद्रास जनगणना के आयुक्त ने कहा था। आयुक्त अपनी रिपोर्टों में अक्सर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जातियों की सूची प्रदान करने से अधिक किसी महत्वाकांक्षा से पीछे हट जाते थे। यह स्पष्ट था कि ... पूरे देश में वर्गीकरण में एकरूपता की आशा नहीं की जा सकती थी। इसलिए, रिस्ले की योजना प्रत्येक प्रांत, प्रेसीडेंसी, रियासत के प्रत्येक जनगणना आयुक्त को एक मानक योजना भेजने की थी, जिसमें उन्हें स्थानीय प्रयोज्यता पर विचार करने और आवश्यकतानुसार संशोधन प्रस्तावित करने के लिए 'स्थानीय सज्जनों' की समितियाँ गठित करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

इसका अर्थ यह है कि 'अलग-अलग जातियों की पहचान करना भी मुश्किल था'। 'उनका कोई सार्थक वर्गीकरण करना असंभव था'। जातियों के अध्ययन के कई दशकों के प्रयासों के बाद भी, 'देश भर में वर्गीकरण में एकरूपता की उम्मीद नहीं की जा सकती थी'। इससे पता चलता है कि दो शताब्दियों से अधिक समय तक भारत का गहन अध्ययन करने और कई भारतीय राजाओं, विद्वानों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से परामर्श करने के बावजूद, अंग्रेज जाति व्यवस्था के बारे में अनभिज्ञ थे। 'जाति व्यवस्था' पर विशेषज्ञ होने का दावा करने वाले प्रत्येक वर्तमान विद्वान को इन ब्रिटिश विवरणों का विनम्रतापूर्वक अध्ययन करना चाहिए।

जनगणना परियोजना की शुरुआत से ही, ब्रिटिश अधिकारियों ने मानचित्रण के लिए चुनी जा रही भारतीय समुदायों के साथ-साथ

जनगणना करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों के प्रतिरोध की सूचना दी। एक लगातार चुनौती वास्तविक जीवन में 'जातियों' की स्पष्ट सीमाएँ और परिभाषाएँ निर्धारित करना था। यह मुद्दा जनगणना अधिकारियों की आधिकारिक रिपोर्टों में अच्छी तरह से दर्ज है।

समस्या एक गहरे सभ्यतागत संघर्ष की थी। अंग्रेजों को जातियों की सरल, मानक परिभाषाओं की आवश्यकता थी जो परस्पर अनन्य और स्पष्ट रूप से सीमांकित हों। लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग थी। भारतीय समाज उस तरह से काम नहीं करता था जैसा अंग्रेज देखना चाहते थे। ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल ने भी स्वीकार किया कि धर्मशास्त्रों जैसे ग्रंथों में वर्णित बातों के बजाय वास्तविक जीवन में प्रचलित रीति-रिवाज और प्रथाएं 'हिंदुओं के लिए कानून' का बेहतर स्रोत थीं। [177]

धरमपाल ने ब्रिटिश पुस्तकालयों में कई वर्ष बिताने के बाद यह निष्कर्ष निकाला:

अंग्रेजों के लिए जाति एक बड़ी बाधा थी, एक घोर बुराई थी, इसलिए नहीं कि वे जातिविहीनता या गैर-पदानुक्रमित व्यवस्था में विश्वास करते थे, बल्कि इसलिए कि यह भारतीय समाज को तोड़ने के उनके रास्ते में खड़ी थी। जाति ने भारतीय समाज के विखंडन की प्रक्रिया में बाधा डाली और विजय एवं शासन को और अधिक कठिन बना दिया। भारतीय समाज को जातियों में संगठित करने के विरुद्ध वर्तमान आक्रोश और सैद्धांतिक सूत्र, चाहे आज जाति का औचित्य हो या न हो, ब्रिटिश शासन से ही शुरू होता है।

लॉर्ड रिस्ले द्वारा पदानुक्रमित ढांचा थोपने से पहले, विभिन्न यूरोपीय विचारक भारतीय समाज को अपनी कल्पना में समेटने और उसके विशाल आकार, विविधता और गहराई को समझने के लिए विभिन्न प्रकार की वैचारिक योजनाओं पर विचार कर रहे थे। उदाहरण के लिए, 1871 में

मद्रास प्रेसीडेंसी में जनगणना कार्यों का पर्यवेक्षण करने वाले डब्ल्यू.आर. कॉर्निश ने लिखा: 'क्या कभी ऐसा कोई काल था जिसमें हिंदू चार वर्गों में विभाजित थे, यह अत्यंत संदिग्ध है।' इसी प्रकार, 1871 की बिहार जनगणना पर एक रिपोर्ट लिखने वाले सी.एफ. मैग्राथ ने लिखा कि 'अब मनु द्वारा कथित रूप से किए गए चार जातियों के अर्थहीन विभाजन को त्याग देना चाहिए।'

कैम्ब्रिज की मानवविज्ञानी सुसान बेली लिखती हैं:

औपनिवेशिक काल के काफी समय तक, उपमहाद्वीप का अधिकांश भाग उन लोगों से आबाद था जिनके लिए जातिगत औपचारिक भेद का महत्व सीमित था, यहाँ तक कि तथाकथित हिंदू बहुल क्षेत्रों में भी... जिन संस्थाओं और मान्यताओं को अब अक्सर पारंपरिक जाति के तत्व के रूप में वर्णित किया जाता है, वे 18वीं शताब्दी के आरंभ में ही आकार ले रही थीं।

अंग्रेजों द्वारा गठित विभिन्न समितियों और आयुक्तों ने अनेक प्रकार की व्याख्याएँ प्रस्तुत कीं और अक्सर बिना किसी पदानुक्रम के जातियों की एक सरल सूची का सहारा लिया। उदाहरण के लिए, बड़ौदा में, जनगणना संचालन के प्रभारी अधीक्षक ने कहा कि रिस्ले की शब्दावली 'बिल्कुल विचित्र' थी क्योंकि उनके प्रांत में 'इस तरह के स्पष्ट भेद नहीं हैं'। उन्होंने बिना किसी पदानुक्रम के जातियों की वर्णानुक्रमिक सूची का सहारा लिया।

रिस्ले के दृढ़ संकल्प के बावजूद, वे भारत भर में अपने अधिकारियों के बीच एक समान वर्गीकरण पर सहमति प्राप्त करने में असफल रहे। भारत के एक प्रांत में लागू सभी वर्गीकरण योजनाओं को अन्य प्रांतों में अस्वीकार कर दिया गया। अनुभवी और जानकार अधिकारियों, भारतीय और यूरोपीय दोनों से शिकायतें प्राप्त हुईं। चार्स्ले बताते हैं: 'एक के बाद

एक जनगणना आयुक्त विभिन्न आधारों पर बने समूहों के बीच कोई व्यवस्था स्थापित करने के लिए संघर्ष करते रहे।'

यह दिलचस्प बात है कि भारत के जनगणना आयुक्त ने बंगाल से शिकायत की थी कि 'अज्ञानी वर्गों को जाति का अर्थ बहुत कम पता होता है और वे या तो अपना व्यवसाय, या अपनी उपजाति, या अपना गोत्र, या फिर कोई ऐसा नाम बताते हैं जिससे वे अपने साथी ग्रामीणों के बीच जाने जाते हैं।'

लेकिन धीरे-धीरे, बीसवीं शताब्दी तक, बार-बार होने वाली जनगणनाओं और अजनबियों द्वारा उनके दरवाजे पर आकर उनकी जाति की पहचान करने के तरीके के बारे में लगातार पूछताछ के कारण, भारतीय समुदाय के नेता ऐसे उपयुक्त उत्तर देने के लिए प्रशिक्षित हो गए जो अंग्रेजों को स्वीकार्य हों।

किसी समुदाय को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाना चाहिए, इस विषय पर व्यापक साहित्य का विकास हुआ। जनगणना करने वालों द्वारा 'निम्न' मानी जाने वाली कई जातियों ने तर्क दिया कि वे उच्च जातियाँ थीं। श्रेणियों को लेकर तीखी बहस हुई। जातियों को परस्पर अनन्य मानने का एक प्रमुख आधार यह था कि वे अंतर्विवाह का अभ्यास करती थीं, लेकिन यह भी समान रूप से लागू नहीं होता था। विवाह साथी के रूप में कौन योग्य होगा, यह निर्धारित करने वाले प्रमुख कारकों में जन्म स्थान, व्यवसाय, भाषा और विभिन्न संयोजन शामिल थे। अंतर्विवाह भी सार्वभौमिक नहीं था क्योंकि कई बहिर्विवाही समूह भी थे, अर्थात् वे जो अपने समुदाय से बाहर विवाह करते थे। जातिगत सीमाएँ अक्सर कई अपवादों और संदर्भों के साथ पारगम्य थीं।

रिस्ले ने ‘जाति = नस्लीय पदानुक्रम’ का सिद्धांत थोपा।

अंततः, पश्चिमी नस्ल सिद्धांत के ढांचे को मानक के रूप में अपनाया गया और रिस्ले ने भारत की विविधता को जबरदस्ती उसमें फिट करने का फैसला किया। इस प्रकार, आधी सदी तक फैले कई जनगणनाओं के दौरान हुए प्रयोगों और त्रुटियों के माध्यम से काल्पनिक जाति व्यवस्था का उदय हुआ।

पेंसिल्वेनिया के टेम्पल विश्वविद्यालय में भूगोल, शहरी और वैश्विक अध्ययन के प्रोफेसर संजय चक्रवर्ती ने औपनिवेशिक एजेंडा का सारांश प्रस्तुत किया है, जिसे आज विद्वानों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है:

उन्नीसवीं शताब्दी के लगभग कालखंड के दौरान, उपनिवेशवादियों ने सुविधा के अनुसार श्रेणियों का उपयोग करते हुए भारतीय सामाजिक पहचानों का निर्माण या सृजन किया। यह ब्रिटिश भारतीय सरकार के अपने हितों की पूर्ति के लिए किया गया था - मुख्य रूप से एक ऐसे एकल समाज का निर्माण करना जिसमें एक समान कानून हो और जिसका आसानी से शासन किया जा सके। धर्मों और सामाजिक पहचानों की एक बहुत बड़ी, जटिल और क्षेत्रीय रूप से विविध प्रणाली को इस हद तक सरलीकृत किया गया कि शायद विश्व इतिहास में इसका कोई समानांतर उदाहरण नहीं है, पूरी तरह से नई श्रेणियां और पदानुक्रम बनाए गए, असंगत या बेमेल भागों को एक साथ मिला दिया गया, नई सीमाएं बनाई गईं और लचीली सीमाओं को और कठोर बना दिया गया।

परिणामस्वरूप बनी श्रेणीबद्ध व्यवस्था अगले सवा शताब्दी में कठोर हो गई, क्योंकि गढ़ी गई श्रेणियां वास्तविक अधिकारों से जुड़ गईं। ब्रिटिश भारत में धर्म-आधारित निर्वाचक मंडल और स्वतंत्र भारत में जाति-आधारित आरक्षण ने अस्पष्ट श्रेणियों को ठोस रूप दिया। एक श्रेणी से संबंधित होने के बजाय दूसरी श्रेणी से संबंधित होने के वास्तविक और

भौतिक परिणाम सामने आने लगे।

‘अस्पृश्यता’ को आधिकारिक बनाना

ब्रिटिश विशेषज्ञों के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती यह तय करना था कि वर्ण चार हैं या पाँच। सुप्रसिद्ध चार वर्ण श्रेणियों के अलावा, रिस्ले ने पाँचवीं श्रेणी का प्रस्ताव रखा जिसे उन्होंने 'ऐसी जातियाँ जिनके स्पर्श से गंगाजल भी दूषित हो जाता है' के रूप में परिभाषित किया।

लेकिन रिस्ले का मानदंड, जिसके अनुसार ब्राह्मणों द्वारा अछूतों के हाथों से पानी न पीने की अनिच्छा से उनका निर्धारण होता था, सर्वव्यापी नहीं था। शारीरिक पृथक्करण के मानदंड कहीं अधिक जटिल थे। कुछ ही जनगणना प्रबंधक रिस्ले के पाँचवें वर्ण के सुझाव को अपनाना चाहते थे क्योंकि उनकी परिभाषा को ठोस परिस्थितियों में लागू करना अत्यंत व्यक्तिपरक और राय का विषय था।

लेकिन धीरे-धीरे यह विचार प्रचलित हो गया। राजस्थान में, दो ब्रिटिश जनगणना अधीक्षकों ने पहली बार लिखित रूप में 'अछूत' शब्द का प्रयोग किया। हालांकि, अन्य लोगों ने बताया कि चार वर्ण प्रणाली में इन समूहों को शूद्रों के अंतर्गत शामिल किया गया था और अछूत जैसी कोई श्रेणी नहीं थी। जमीनी स्तर पर प्राप्त साक्ष्य एक प्रांत से दूसरे प्रांत और एक जनगणना अधिकारी से दूसरे जनगणना अधिकारी के अनुसार भिन्न थे। चार और पांच वर्ण प्रणाली, दोनों को प्रारंभ में अलग-अलग स्थानों पर अपनाया गया था।

इसके बाद रिस्ले ने नस्लीय सिद्धांत लागू करके समस्या का समाधान करने का निर्णय लिया। उन्होंने शुरुआत की।

उन्होंने कथित नस्लीय संरचना के आधार पर 'क्षेत्रों' को अलग-अलग वर्गीकृत किया, जिनमें कुछ हद तक एकरूपता की उम्मीद की जा सकती

थी। उत्तर-पश्चिम, जो आज भारत और पाकिस्तान में विभाजित है, को उन्होंने 'इंडो-आर्यन क्षेत्र' घोषित किया, जिसमें राजस्थान के दो जनगणना प्रभाग, पंजाब और कश्मीर शामिल थे। हालाँकि पंजाब की रिपोर्ट से उन्हें कोई समर्थन नहीं मिला और कश्मीर की रिपोर्ट से भी बहुत कम, उन्होंने राजस्थान की दो रिपोर्टों से संकेत लिया और इसी मामूली आधार पर उन्होंने उस क्षेत्र के लिए एक एकीकृत वर्गीकरण स्थापित किया जिसमें 'श्रेणी VII: अछूत जातियाँ' शामिल थी। ऐसा कोई शब्द उनके किसी अन्य क्षेत्र में शामिल नहीं किया जा सका। इस प्रतिकूल शुरुआत से, जो एक सफल पहल से कहीं अधिक एक अस्वीकृति का प्रतिनिधित्व करती थी, आधुनिक भारत में एक महत्वपूर्ण शब्द का सफर शुरू हुआ।
इस प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के तहत, ब्रिटिश अधिकारी बिना किसी वस्तुनिष्ठ जाँच-पड़ताल के अपने मनपसंद सिद्धांतों का प्रयोग और प्रचार कर सकते थे। एक उद्यमी अधिकारी ने उस समय प्रचलित नस्लीय सिद्धांत का उपयोग करते हुए अपनी खुद की श्रेणियाँ बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने ब्राह्मणों को 'मुख्य रूप से आर्य या उनके समकक्ष' के रूप में परिभाषित किया; उन्होंने 'मिश्रित जातियाँ' नामक एक श्रेणी बनाई; दूसरी 'आदिवासी जनजातियाँ और खानाबदोश जातियाँ'; और अंत में, 'अशुद्ध जातियाँ'।

भारतीय राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश श्रेणियों को स्वीकार किया
यह मुद्दा भारतीय राष्ट्रवादियों के बीच बहस का विषय बन गया, जो आम तौर पर अंग्रेजी भाषी अभिजात वर्ग के सदस्य थे। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार देखा था और इसी संवेदनशीलता को वे भारत में निम्न जातियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में लेकर आए। 1903 में, शिक्षाविद और कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने

दलित वर्गों के उत्थान के लिए एक प्रस्ताव पेश किया।
'अछूत' शब्द अभी मुख्यधारा में प्रचलित नहीं हुआ था, और इस अवधारणा को 'पिछड़े वर्ग' के रूप में व्यक्त किया जा रहा था। 1877 में प्रकाशित बॉम्बे गजेटियर के पहले खंडों में 'पिछड़ी जातियाँ' शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन 1879-80 के बाद के खंडों में 'वर्ग' शब्द का प्रयोग होने लगा और यही शब्द सुधारवादी आंदोलन का मुख्य आधार बन गया। 1906 में बॉम्बे में, 1909 में मद्रास में और उत्तर भारत में आर्य समाज ने भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया। दशक के अंत तक, दलित वर्गों के उत्थान पर लेख पूरे भारत के समाचार पत्रों में प्रकाशित होने लगे थे।
इसी समय बड़ौदा के महाराजा और गुजरात के प्रगतिशील शासक सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने समुदायों के वर्गीकरण के तरीके पर गहरा प्रभाव डालना शुरू किया। उन्होंने दलित वर्गों के उत्थान के आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रमुख कार्यकर्ताओं, सुधारकों और लेखकों को भी प्रोत्साहित किया। इनमें स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय, थियोसोफिस्ट नेता एनी बेसंत और प्रसिद्ध बौद्ध विचारक अनागरिका धर्मपाल प्रमुख थे।
महाराजा ने 'पिछड़े वर्ग' शब्द के बजाय 'अस्पृश्यता' शब्द को प्राथमिकता दी। उनकी प्रतिष्ठा को देखते हुए, उनके द्वारा चुने गए इस शब्द ने चर्चा को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने कहा कि 'भारत के प्रांतों, जातियों और समुदायों में समय के साथ बदलाव आया है, जिसके कारण यह समस्या भी बदलती रही है।' धीरे-धीरे, महाराजा के शब्द 'अस्पृश्यता' की जगह 'अस्पृश्यता' शब्द का प्रयोग होने लगा। महाराजा की अध्यक्षता में, 1918 में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन ने 'अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी घोषणापत्र' जारी किया।

1920 के दशक तक, यह शब्द ब्रिटिश लेखन में व्यापक रूप से प्रचलित हो गया था, लेकिन गांधी जी संकोच करते थे। कभी-कभी वे 'तथाकथित अछूत' या 'दबे हुए वर्ग' जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे। 1931 में, उन्होंने एक बदलाव की घोषणा की और निर्णय लिया कि 'हरिजन' (ईश्वर का सेवक) शब्द अधिक उपयुक्त है।

अंबेडकर की आवाज़ बहुत महत्वपूर्ण थी, जो स्वयं बॉम्बे प्रेसीडेंसी से महार समुदाय से थे और एक ऐसा समुदाय थे जिन पर 'अछूत' शब्द निश्चित रूप से लागू होता था। महार कभी एक विशाल और व्यापक कृषि समुदाय थे जो ज़मींदार थे, लेकिन बाद में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण भूमिहीन मज़दूर बन गए। जब वे 1924 में अमेरिका और ब्रिटेन में अपनी विधिक शिक्षा पूरी करके भारत लौटे, तब तक अंबेडकर 'अछूत' शब्द का प्रयोग करने लगे थे। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अछूत 'भारत के राष्ट्रीय जीवन का एक अलग हिस्सा' हैं और उन्होंने स्वयं को उनका प्रवक्ता नियुक्त किया।

जब अस्पृश्यता लाखों लोगों की पहचान बन गई, तो इसके 'अन्य' को नाम देने की आवश्यकता महसूस हुई। प्रारंभ में, 'जातिगत हिंदू' शब्द का प्रयोग किया गया, यहाँ तक कि अंबेडकर ने भी 1930 में इसका प्रयोग किया था। लेकिन बाद में उन्होंने इसे त्याग दिया और 'हिंदू' को 'अन्य' के रूप में अपनाया, जिससे अछूतों को बहिष्कृत हिंदुओं के बजाय गैर-हिंदू घोषित किया गया। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था जिसके दूरगामी परिणाम हुए।

अंबेडकर ने तर्क दिया कि अछूत मूल रूप से हिंदुओं से भिन्न थे, और उन्होंने इस बात का लाभ उठाकर एक अलग और विशिष्ट पहचान पर जोर दिया। स्वतंत्र भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष और पहले न्याय मंत्री के रूप में, वे अछूत पहचान को दृढ़ता से स्थापित करने के

लिए जिम्मेदार थे।[192] नीचे दिया गया चित्र दर्शाता है कि ब्रिटिश काल के दौरान अस्पृश्यता एक औपचारिक श्रेणी कैसे बन गई।

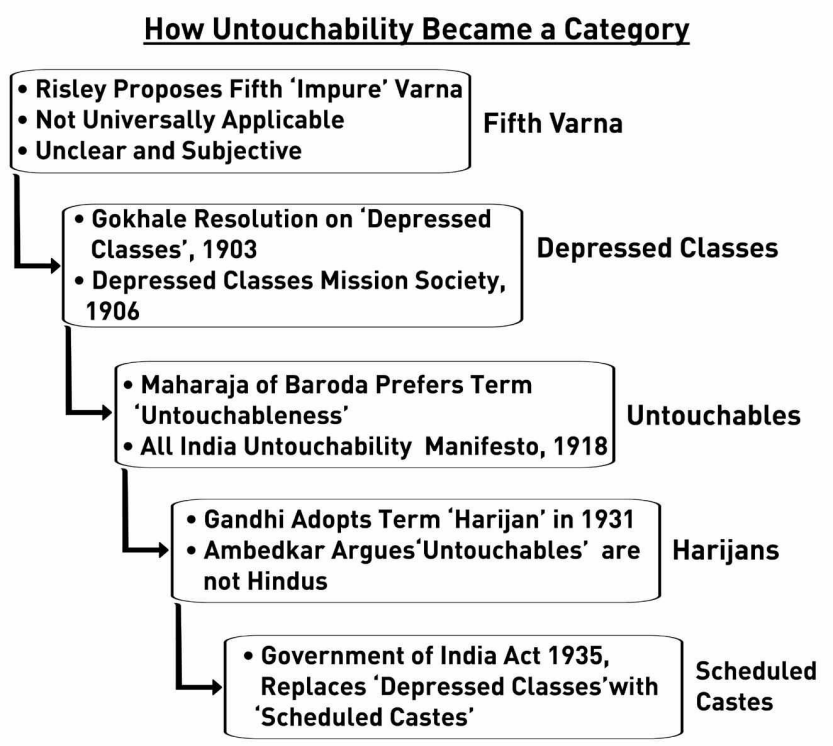

विद्वानों ने अस्पृश्यता को एक मानक श्रेणी के रूप में, न केवल एक शब्द के रूप में बल्कि स्वयं श्रेणी के रूप में भी, कई समस्याओं की पहचान की है:

यह एक अखिल भारतीय समरूप जातीयता स्थापित करता है, जबकि वास्तव में प्रत्येक क्षेत्र के सबसे निचले तबके के समुदाय अपने इतिहास, रीति-रिवाजों, उच्च जातियों के साथ संबंधों और आंतरिक सामाजिक-राजनीतिक संगठन में एक दूसरे से भिन्न हैं। चार्स्ले के अनुसार, समस्या यह है कि यह 'स्थानीय विविधता को छुपाता है और क्षेत्रों के बीच एक ऐसी एकरूपता स्थापित करता है जो वास्तविकता से कहीं अधिक स्पष्ट

है। यह भारतीय समाज को समझने की समस्या को सरल बना देता है, लेकिन इसके एक प्रमुख और विश्लेषणात्मक रूप से महत्वपूर्ण लक्षण: विविधता को समझने की आवश्यकता को नजरअंदाज कर देता है।'
किसी विशेष क्षेत्र के भीतर भी, यह शब्द कई समुदायों को समाहित करता है जिन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान को सावधानीपूर्वक संरक्षित रखा है। उदाहरण के लिए, इस अछूत समूह के भीतर प्रत्येक जाति स्वयं को एक विशिष्ट प्रथम पूर्वज मानती है, जो पहचान के महत्वपूर्ण रूप से भिन्न ऐतिहासिक स्रोतों की ओर इशारा करता है।
विभिन्न अछूत समुदायों के बीच तनाव रहा है। गांधी जी अक्सर उनके बीच मौजूद पूर्वाग्रहों के लिए उनकी आलोचना करते थे।
अशुद्धता की अवधारणा (परिभाषित मानदंड) भी इतनी जटिल है कि इसे इस समरूप वर्गीकरण में समाहित नहीं किया जा सकता है।
यह अपने सभी सदस्यों पर पीड़ित/उत्पीड़क की दोहरी मानसिकता थोपता है, जबकि वास्तव में प्रत्येक समुदाय की सामाजिक कहानी अलग होती है। यह हर समुदाय को वंचित महसूस कराता है, जिन्हें खुद को पीड़ित समझना चाहिए और अन्य जातियों के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाना चाहिए।
चार्स्ले का मानना है कि अस्पृश्यता की श्रेणी भारत की सामाजिक वास्तविकता पर थोपा गया एक कृत्रिम मुद्दा था। वे कहते हैं:
इस प्रकार, "अस्पृश्यता" ने विविधता और भिन्नता को दबा दिया और एक समान और अत्यंत सरलीकृत संरचना स्थापित की जिसके आधार पर भारतीय समाज को समझा जाना था। इस अवधारणात्मक विकास का सकारात्मक व्यावहारिक महत्व बहुत अधिक था, लेकिन सकारात्मक पहलुओं पर विचार करने से पहले इसके नकारात्मक पहलू को अच्छी तरह समझना आवश्यक है। बीसवीं शताब्दी के अंत के साथ-साथ वर्तमान

घटनाक्रमों के संदर्भ में यही नकारात्मक पहलू तेजी से प्रासंगिक होता जा रहा है।

लेकिन "अस्पृश्यता" न केवल विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों और निरंतरताओं पर एक विराम लगाती है, बल्कि ... इसके द्वारा निर्मित विभाजन के नीचे छिपी हर सकारात्मक चीज़ को भी छिपा देती है। ... "अस्पृश्य" शब्द उन लोगों के कार्यों या व्यक्तित्व को नहीं दर्शाता, बल्कि केवल दूसरों द्वारा उनके साथ किए जाने वाले नकारात्मक व्यवहार को दर्शाता है: उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाता है। ... उन्हें कारीगरों, किसानों या व्यापारियों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, न ही उनके धार्मिक योगदानों के संदर्भ में, बल्कि अस्पृश्यता के उस अपरिभाषित, अस्पष्ट और निश्चित रूप से अवमूल्यनकारी गुण के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, 'पिछड़ी जातियाँ' शब्द को 'अनुसूचित जातियाँ' से बदल दिया गया। यह बात समझ से परे थी कि जहाँ दक्षिण में यह स्थिति थी, वहीं उत्तर में स्थिति भिन्न थी। कई विशेषज्ञों का मानना था कि देश के बड़े हिस्से में अछूत एक अलग समूह नहीं थे। नीचे दिया गया चित्र दर्शाता है कि कैसे ब्रिटिश सामाजिक इंजीनियरिंग ने आधुनिक जाति व्यवस्था को जन्म दिया।

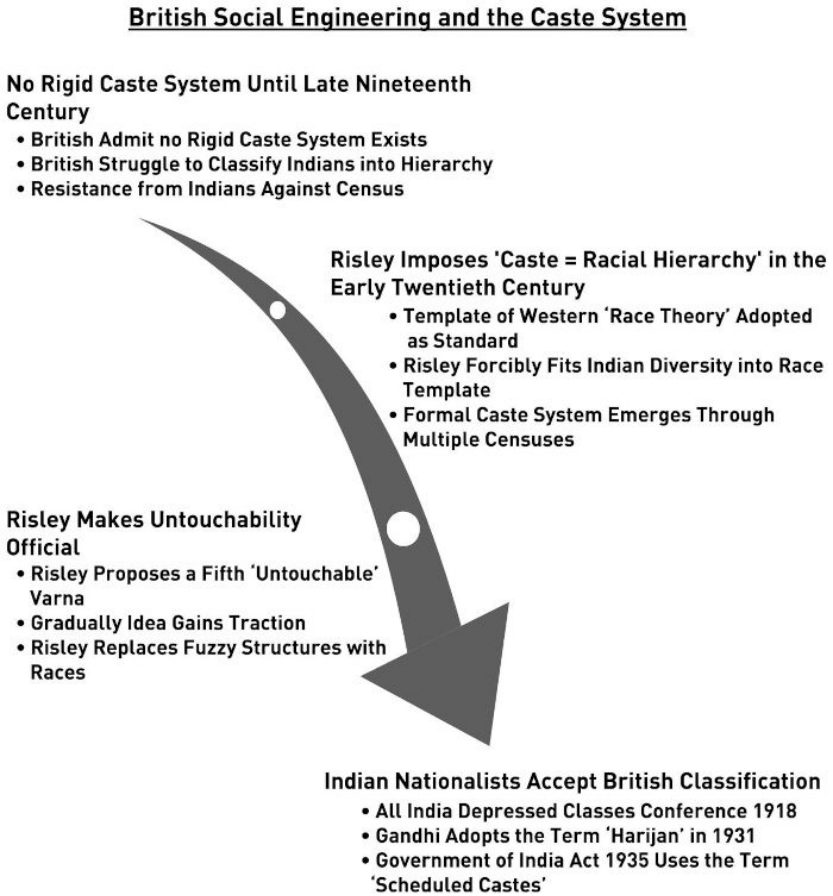

अनुसूचित जाति व्यवस्था का निर्माण इस प्रकार हुआ: पहले इसके शब्दों पर चर्चा हुई, फिर ब्रिटिश जनगणनाओं द्वारा इसे औपचारिक रूप दिया गया, और बाद में भारतीय राष्ट्रवादियों और सुधारकों ने इसे अपनाया। अंततः, जो शुरू में एक सैद्धांतिक ढांचा था, वह जमीनी स्तर पर ठोस रूप ले लिया। इसे प्राचीन वैदिक समाज की विशेषताओं को परिभाषित करने के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया।
चार्स्ले कहते हैं:

जाति एक कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त समूह बन जाती है जिससे हर कोई या तो स्पष्ट रूप से संबंधित होता है या नहीं। राज्य द्वारा आवंटित लाभ और विशेषाधिकार प्राप्त जातियों के लिए, सदस्यता साबित करने और दावों को मान्य करने के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
... पिछली शताब्दियों में समाज के जो विभाजन कहीं अधिक अव्यवस्थित, कम एकरूप और अधिक अस्पष्ट थे, उनमें एक परिवर्तन हासिल किया गया है, जिसे हमने शताब्दी के प्रारंभ में रिस्ले के महान प्रयोग के परिणामों में स्पष्ट रूप से देखा था।
वर्तमान में यह बहस चल रही है कि क्या अछूत उस जाति व्यवस्था को दोहराते हैं या अस्वीकार करते हैं जो उन्हें कमतर आंकती है, और यह इस बात का उदाहरण है कि इस श्रेणी की प्रकृति को गलत समझने से एक अवास्तविक समस्या उत्पन्न होने का खतरा है।
... यह अवधारणा एक श्रेणी स्थापित करती है जिसे पदानुक्रमित रूप से व्यवस्थित समाज के सबसे निचले स्तर के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन व्यवहार में यह आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से अलग-अलग स्थिति वाली विभिन्न जातियों को फंसाकर उन्हें एक समान मानती है।

बी.आर. अंबेडकर और दलित आंदोलन

बी.आर. अंबेडकर के विचारों का विश्लेषण किए बिना जाति पर कोई भी चर्चा अधूरी है। वे एक महान बुद्धिजीवी थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान राजनीति में कदम रखा। अंबेडकर ने प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक जॉन ड्यूवी के मार्गदर्शन में कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया

और महार जाति से होने के कारण, उन्होंने सभी निचली जातियों के अधिकारों की वकालत की, जिसमें राष्ट्रवादी संघर्ष में अपने हिंदू साथियों से भी मुकाबला करना शामिल था।
हम इस पुस्तक से संबंधित चार विषयों पर अंबेडकर के प्रमुख विचारों का विश्लेषण करते हैं। नीचे दी गई तालिका में अंबेडकर की उन चार प्रमुख रचनाओं की सूची दी गई है जिनका हमने अध्ययन किया है। प्रत्येक रचना पर अलग-अलग चर्चा की गई है।

Ambedkar's Major Works	Main Theme
Annihilation of Caste[200]	Severe criticism of caste abuses and Hinduism
Pakistan: The Partition of India[201]	Harsh attack on Islam
The Buddha and His Dhamma[202]	Explanation of his new interpretation of Buddhism
Buddha or Karl Marx?[203]	Argument on why Buddhism is superior to Communism

तालिका के अंदर फुटनोट चिह्न ,200 , 201 , 202 , 203

अंबेडकर और जाति
अंबेडकर और गांधी के बीच जटिल संबंध थे। मतभेद का मुख्य कारण जातिगत भेदभाव था। दोनों इस बात से सहमत थे कि निचली जातियों और अछूतों के साथ घोर दुर्व्यवहार और अमानवीय भेदभाव होता है, लेकिन समस्या के समाधान को लेकर उनके विचार मौलिक रूप से भिन्न थे। गांधी जाति को हिंदू धर्म का अभिन्न अंग मानते हुए उसमें संशोधन करना चाहते थे ताकि इससे जुड़े अत्याचारों को दूर किया जा सके। वहीं, अंबेडकर जाति व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते थे। गांधी दलितों को हरिजन कहते थे और हिंदुओं को यह सिखाने के लिए अथक प्रयास करते थे कि वे दलितों को सम्मानपूर्वक स्वीकार करें। अंबेडकर का

मानना था कि दलितों को 'समायोजित' करने का यह एक दिखावटी तरीका था और इससे अत्याचारी संरचनाओं को पूरी तरह से समाप्त करने की दिशा में पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए।

अंबेडकर और गांधी के बीच एक महत्वपूर्ण बहस में अंबेडकर का जाति व्यवस्था पर सबसे सीधा और स्पष्ट बयान शामिल है। इस बयान की पृष्ठभूमि अपने आप में रोचक है। एक हिंदू सुधारवादी समूह ने अंबेडकर को 1936 में अपने वार्षिक सम्मेलन में जाति व्यवस्था पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया था। अंबेडकर ने उन्हें छपाई और वितरण के लिए अपने मसौदे की एक अग्रिम प्रति भेजी। आयोजकों को कई अंशों से आपत्ति हुई क्योंकि वे हिंदू धर्म की आलोचना कर रहे थे और उन्होंने उन्हें हटाने का अनुरोध किया। अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। आयोजकों ने अचानक उनका भाषण रद्द कर दिया।

अंबेडकर ने अपने भाषण को 'जाति का नाश' शीर्षक से एक निबंध के रूप में स्वतंत्र रूप से प्रकाशित किया। यह संभव है (हालांकि यह सिद्ध नहीं हुआ है) कि उन्होंने प्रकाशित संस्करण में हिंदू धर्म के विरुद्ध और भी कठोर टिप्पणियां कीं ताकि वे उन हिंदू नेताओं की संकीर्ण मानसिकता पर अपना क्रोध व्यक्त कर सकें जिनका वे सामना कर रहे थे। यह निबंध एक महत्वपूर्ण घटना बन गया जिसने भारतीय राष्ट्रवादियों के बीच एक जीवंत बहस को जन्म दिया।

गांधी ने अंबेडकर के निबंध का उत्तर लिखकर अपनी पत्रिका हरिजन में प्रकाशित किया। अंबेडकर ने भी गांधी को जवाब देते हुए उनके हरिजन लेख की बिंदुवार आलोचना की।

अपने विश्लेषण के लिए हमने अंबेडकर के निबंध को व्यापक विषयों में पुनर्गठित किया है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हमारे विचार उनके विचारों से मेल खाते हैं और वैश्विक वामपंथियों के आज के दावों का खंडन करते हैं।

उदाहरण के लिए, वे जातियों को अलग-अलग नस्लें मानने के पश्चिमी दृष्टिकोण को खारिज करते हुए लिखते हैं: 'यह मानना कि जातिगत भेद वास्तव में नस्लगत भेद हैं, और विभिन्न जातियों को कई अलग-अलग नस्लों की तरह मानना, तथ्यों का घोर विकृति है।' वे बाद में इसी निबंध में इस विचार को दोहराते हैं: 'जाति व्यवस्था नस्लीय विभाजन नहीं करती। जाति व्यवस्था एक ही नस्ल के लोगों का सामाजिक विभाजन है।' यह आज के दलित विद्वानों से एक बड़ा मतभेद है जो इस बात पर जोर देते हैं कि दलित अन्य हिंदुओं से एक अलग नस्ल हैं। यह अफ्रीकी-दलित आंदोलन की एक मूलभूत खामी है जो दलितों को अश्वेतों के साथ मिला देती है।

अंबेडकर कहते हैं कि भारत के एक क्षेत्र के अछूत दूसरे क्षेत्र के अछूतों से भिन्न हैं। इसलिए, उन्हें एक ही नस्ल के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। वे लिखते हैं: 'बंगाल के अछूतों और मद्रास के अछूतों में क्या नस्लीय समानता है?' उनका तात्पर्य यह है कि यद्यपि अछूत एक ही नस्ल के भीतर एक सामाजिक विभाजन हैं, वे एक समरूप समूह नहीं हैं।

यह महत्वपूर्ण बयान उनके द्वारा जाति के आधार पर हिंदू धर्म को अस्वीकार करने के बाद आया है। इस अस्वीकृति के बावजूद, उनका मानना है कि उपनिषद स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के एक नए सिद्धांत का आधार बन सकते हैं।

वह लिखते हैं:

आपको अपने धर्म को एक नया सैद्धांतिक आधार देना होगा—ऐसा आधार जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के अनुरूप हो; संक्षेप में, लोकतंत्र के अनुरूप हो। मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ। लेकिन मुझे बताया गया है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के अनुरूप धार्मिक सिद्धांतों के लिए आपको विदेशी स्रोतों से उधार लेने की आवश्यकता नहीं

होगी, और आप ऐसे सिद्धांतों के लिए उपनिषदों से प्रेरणा ले सकते हैं। यद्यपि वे इस निबंध का उपयोग हिंदू धर्म से अपने विमुख होने की घोषणा करने के लिए करते हैं, वे हिंदुओं के प्रति द्वेष के बजाय सद्भाव बनाए रखना चाहते हैं। वे लिखते हैं: 'भले ही मैं आपके समुदाय से अलग हो जाऊं, मैं आपके आंदोलन को सक्रिय सहानुभूति के साथ देखता रहूंगा, और आपको मेरी सहायता यथासंभव मिलती रहेगी। आपका कार्य एक राष्ट्रीय मुद्दा है।'

हालांकि, उनका मूल संदेश हिंदू ग्रंथों और प्रथाओं का कड़ा विरोध करता है। समग्र आकलन को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है: 'आप जिस भी दिशा में मुड़ें, जाति ही वह राक्षस है जो आपके रास्ते में बाधा बनेगी। आप राजनीतिक सुधार या आर्थिक सुधार तब तक नहीं कर सकते जब तक आप इस राक्षस को नष्ट नहीं कर देते।'

जाति व्यवस्था पर अंबेडकर की स्पष्ट और तार्किक आलोचना प्रभावशाली है। उन्होंने अपने तर्क को निम्नलिखित तीक्ष्ण कथनों में विभाजित किया है। हम उनके विचारों को मुख्यतः उनके अपने शब्दों में और कुछ भावार्थों के साथ संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं: [211]

श्रमिकों के बीच विभाजन: जाति केवल श्रम का विभाजन नहीं है। यह श्रमिकों का भी विभाजन है... यह एक पदानुक्रम है जिसमें श्रमिकों के वर्गों को एक दूसरे के ऊपर श्रेणीबद्ध किया जाता है।

व्यक्तिगत प्रतिभा का अपर्याप्त आर्थिक उपयोग: जाति व्यवस्था समाज को प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग करने से रोकती है क्योंकि यह माता-पिता की सामाजिक स्थिति के आधार पर व्यक्तियों को पहले से ही कार्य सौंप देती है। उद्योगों में बदलाव के कारण नए व्यवसायों को अपनाने के लिए गतिशीलता की आवश्यकता होती है, जबकि जाति व्यवस्था श्रमिक को कृत्रिम रूप से स्थिर कर देती है। श्रम विभाजन भी

स्वतंत्र चुनाव, व्यक्तिगत भावना और प्राथमिकताओं पर आधारित नहीं है। यह 'नियति के सिद्धांत' पर आधारित है। परिणामस्वरूप, 'जाति व्यवस्था आर्थिक दक्षता का परिणाम नहीं देती'।

हिंदुओं में विखंडन: जाति व्यवस्था हिंदुओं को एकजुट नहीं कर रही, बल्कि उन्हें विखंडित रख रही है। 'जाति व्यवस्था सामूहिक गतिविधियों में बाधा डालती है; और सामूहिक गतिविधियों में बाधा डालकर इसने हिंदुओं को एक एकीकृत जीवन और आत्म-चेतना वाले समाज बनने से रोक दिया है।' इसका एक परिणाम यह है कि 'जाति हिंदू धर्म को एक धर्म प्रचारक बनने से रोकती है।' दूसरे शब्दों में, एक व्यापक हिंदू या भारतीय वृत्तांत के बजाय, अलग-अलग जाति-विशिष्ट वृत्तांत प्रचलित हैं। अंततः, निष्ठा मुख्य रूप से अपनी जाति के प्रति होती है। 'यह असामाजिक भावना, अपने हितों की रक्षा करने की यह भावना, विभिन्न जातियों के एक-दूसरे से अलगाव में उतनी ही प्रमुख विशेषता है जितनी कि राष्ट्रों के अलगाव में। ... इसलिए, हिंदू केवल जातियों का समूह नहीं हैं, बल्कि कई युद्धरत समूह हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने लिए और अपने स्वार्थी आदर्शों के लिए जी रहा है।'

बड़े उद्देश्यों के प्रति उदासीनता: 'उदासीनता जाति व्यवस्था का परिणाम है, जिसने अच्छे उद्देश्य के लिए भी संगठन और सहयोग को असंभव बना दिया है।' इसके परिणामस्वरूप, 'जाति हिंदुओं को आपसी सहयोग, विश्वास और भाईचारे से वंचित करती है।' वास्तव में, स्थिति इसके विपरीत है। एक-दूसरे की मदद करने के बजाय, 'उच्च जातियों ने निम्न जातियों को दबाए रखने की साजिश रची है।'

सुधारों में बाधा: जातिगत विशेषाधिकारों का आनंद लेने वाले लोग इसकी संरचनाओं को बनाए रखना चाहते हैं और सुधारों को रोकना चाहते हैं। 'रूढ़िवादियों के हाथों में जाति सुधारकों को सताने और सभी सुधारों को

समाप्त करने का एक शक्तिशाली हथियार रही है।'
स्पष्ट रूप से कहें तो, हमें यह विश्लेषण सत्य, ईमानदार और साहसिक लगता है। यह एक ऐसी चुनौती थी जिसे 1935 में हिंदू सुधारवादियों को अंबेडकर को आमंत्रित न करने के बजाय सुनना, उस पर बहस करना और विचार करना चाहिए था। वास्तविक सुधार का एक बेहतरीन अवसर हाथ से निकल गया। हम समय को पीछे नहीं ले जा सकते और यह निर्धारित नहीं कर सकते कि यदि हिंदू नेता इतने रक्षात्मक न होकर अंबेडकर के साथ मिलकर विभिन्न परिवर्तनों पर विचार-विमर्श करते तो भारत का भविष्य अलग होता या नहीं।
अंबेडकर फिर जातिगत समस्याओं के समाधान पर चर्चा करते हैं। वे कहते हैं: 'मेरा आदर्श एक ऐसा समाज होगा जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित हो।' यह 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से मिलता-जुलता है। विडंबना यह है कि उनके अनुयायियों ने आज इस आंदोलन को पहचान की राजनीति और आलोचनात्मक नस्ल सिद्धांत में बदल दिया है, जबकि फ्रांसीसी क्रांति ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों पर जोर दिया था। संबंध प्रत्येक नागरिक और राज्य के बीच व्यक्तिगत रूप से होना चाहिए, जिसमें कोई समूह पहचान नागरिकों और राज्य के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य न करे। इस बिंदु पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने आलोचनात्मक नस्ल सिद्धांत के खिलाफ अपने हालिया अभियान में जोर दिया है, जैसा कि अध्याय 1 में बताया गया है।
अंबेडकर पूछते हैं: तो फिर, ऐसा होने से क्या रोकता है? सभी जातियों को एक साथ लाने के लिए अंतर्जातीय भोजन करना पहले से ही प्रचलित था, लेकिन उन्हें यह अपर्याप्त लगता है। वे अंतर्जातीय विवाह चाहते हैं जो आवश्यक परिवर्तन लाएंगे।

अंतर्विवाह से जातिवाद की भावना और चेतना का नाश नहीं हुआ है। मेरा मानना है कि इसका वास्तविक उपाय अंतर्विवाह ही है। रक्त का मिलन ही अपनेपन और रिश्तेदारी की भावना पैदा कर सकता है, और जब तक यह रिश्तेदारी, अपनेपन की भावना सर्वोपरि नहीं हो जाती, जाति द्वारा उत्पन्न अलगाववादी भावना—परदेसी होने की भावना—समाप्त नहीं होगी।

अब वे हिंदू धर्म को आवश्यक सुधारों में बाधक कारक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हिंदू धर्म के विरुद्ध उनका निर्णय बेहद कठोर है:

जाति व्यवस्था का आंतरिक सुधार लगभग असंभव है। जाति का आधार दैवीय है। इसलिए आपको जाति से जुड़ी पवित्रता और दैवीयता को नष्ट करना होगा। अंततः, इसका अर्थ है कि आपको शास्त्रों और वेदों के अधिकार को नष्ट करना होगा।

हिंदू धर्म पर अपने हमले को विस्तार से बताते हुए, वे हिंदू धर्म के बारे में अपनी समझ स्पष्ट करते हैं। आइए पहले उनके कथनों को उद्धृत करें, फिर अपनी प्रतिक्रिया दें। हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या वे वास्तव में हिंदू धर्म को व्यापक रूप से समझते हैं।

हिंदू धर्म क्या है? क्या यह सिद्धांतों का समूह है, या नियमों की संहिता? वेदों और स्मृतियों में वर्णित हिंदू धर्म, यज्ञ, सामाजिक, राजनीतिक और स्वच्छता संबंधी नियमों और विनियमों का एक मिश्रित संग्रह मात्र है। हिंदुओं द्वारा धर्म कहलाने वाला यह समूह आदेशों और निषेधों का एक विशाल संग्रह मात्र है। आध्यात्मिक सिद्धांतों के अर्थ में, जो वास्तव में सार्वभौमिक हों, सभी जातियों, सभी देशों और सभी समयों पर लागू हों, ऐसा धर्म इनमें नहीं पाया जाता; और यदि पाया भी जाता है, तो वह किसी हिंदू के जीवन का मार्गदर्शक नहीं होता। एक हिंदू के लिए, धर्म का अर्थ है आदेश और निषेध।

यह हिंदू धर्म का एक संकुचित दृष्टिकोण है। अंबेडकर इसे केवल हठधर्मी नियमों का एक समूह मानते हैं, जिसमें आध्यात्मिकता का कोई अंश नहीं है। इस कथन में वे विभिन्न आयामों पर विचार नहीं करते, जैसे कि:
उपनिषदों में निहित गहन दर्शन।
योग और ध्यान की ऐसी शारीरिक-मानसिक साधनाएँ जिनमें जाति के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस विषय पर अनेक शास्त्र मौजूद हैं।
संपूर्ण तंत्र प्रणाली जन्म-आधारित किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार से मुक्त है और पूरी तरह से प्रत्येक साधक के नियंत्रण में है।
भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म के भीतर से हुए उन सफल आंदोलनों का एक उदाहरण था, जिन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए द्वार खोले। ऐसे कई आंदोलन हुए जिन्होंने उन 'नियमों' का उल्लंघन किया, जिनसे अंबेडकर को स्वाभाविक रूप से चिंता हुई।
हिंदू धर्म की इस संकीर्ण समझ के आधार पर, वह आगे चलकर निम्नलिखित घोषणा करता है:
इसलिए, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि ऐसे धर्म का नाश होना चाहिए, और मैं कहता हूँ कि ऐसे धर्म के नाश के लिए काम करने में कुछ भी अधार्मिक नहीं है। ... यह आपका कर्तव्य है कि आप इस नकाब को उतार फेंकें, इस कानून को धर्म का नाम देकर फैलाई गई गलत धारणा को दूर करें। ... उन्हें जो बताया जाता है कि धर्म है, वह धर्म नहीं है, बल्कि वास्तव में कानून है, आप इसके संशोधन या उन्मूलन का आग्रह करने की स्थिति में होंगे।
हमें आश्चर्य होता है कि क्या अंबेडकर ग्रीक ग्रंथों पर भी यही तर्क लागू करेंगे। आखिर, अरस्तू तो दास प्रथा के कट्टर समर्थक थे। प्लेटो और अरस्तू दोनों ने ही शिशुहत्या का समर्थन किया था। यदि अंबेडकर यही मानदंड लागू करते, तो ग्रीक ग्रंथों के साथ-साथ हेगेल से लेकर लगभग

सभी प्रमुख यूरोपीय प्रबुद्ध विचारकों पर भी प्रतिबंध लगाना पड़ता। क्या हमें प्रबुद्ध विचारकों से सीखना बंद कर देना चाहिए? इसके अलावा, अमेरिकी संस्थापक पिता भी उन सिद्धांतों और प्रथाओं के दोषी थे जिन्हें आज मानवाधिकारों का उल्लंघन माना जाता है और यहाँ तक कि अपराध की श्रेणी में रखा जाता है।

हम इस चर्चा को बाइबल तक ले जा सकते हैं, जिसमें गुलामी से लेकर बलात्कार तक की क्रूरताओं की कोई कमी नहीं है। अंबेडकर द्वारा एक विशाल परंपरा को समाप्त करने की मांग, क्योंकि उसमें आपत्तिजनक सामग्री भी शामिल है, उन्हें यहूदी-ईसाई धर्म को पूरी तरह से समाप्त करने की भी ऐसी ही मांग करने के लिए बाध्य करती है।

हाल ही में, आइंस्टीन की डायरियों से पता चला है कि उन्होंने चीनियों के खिलाफ नस्लीय टिप्पणियां की थीं। क्या भौतिक विज्ञानी इस आधार पर उनके सभी सिद्धांतों को खारिज करना चाहेंगे?

हम इस बात से सहमत हैं कि हिंदू ग्रंथों का आधुनिक समय के अनुसार अध्ययन किया जाना चाहिए और चुनिंदा रूप से अपनाया जाना चाहिए। जहां आवश्यक हो, वहां गलतफहमियों से बचने के लिए नई व्याख्या, यहां तक कि पुनर्लेखन भी किया जाना चाहिए। स्मृतियों में स्वयं इस दृष्टिकोण का समर्थन किया गया है। उदाहरण के लिए, मनुस्मृति 4.176 अपने क्रियान्वयन में लचीलेपन की वकालत करती है। यह स्पष्ट रूप से कहती है: यदि धर्म के किसी विशेष पहलू की जनता द्वारा निंदा की जाती है, तो व्यक्ति को उसका त्याग कर देना चाहिए। यह तथ्य कि अनेक स्मृतियां सदियों से लिखी गईं और अक्सर परस्पर विरोधी विचार प्रस्तुत करती थीं, धर्म के अनुकूलन की लचीलता का प्रमाण है और यह अब्राहमिक ग्रंथों की तरह एक बंद किताब नहीं है। कई मुख्यधारा के हिंदू संगठनों, जिनमें आर्य समाज एक प्रमुख उदाहरण है, ने आधुनिक समय के अनुरूप मनुस्मृति

को संशोधित और पुनर्व्याख्यायित किया है।
अंबेडकर हिंदुओं को हिंदू धर्म में सुधार के लिए ठोस सुझाव देते हैं। वे इस 'सुधार' के लिए आवश्यक 'मुख्य बिंदुओं' की सूची बनाते हैं। पहला बिंदु पुस्तकों को जलाने और उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की पुरानी अब्राहमिक परंपरा का एक चरम रूप है। यह अंबेडकर के उदारवादी विचारों के विपरीत है और उनके द्वारा अपनाए गए बौद्ध धर्म से पूरी तरह अलग है। वे कहते हैं:
हिंदू धर्म की एक ही मानक पुस्तक होनी चाहिए, जो सभी हिंदुओं को स्वीकार्य और सभी हिंदुओं द्वारा मान्यता प्राप्त हो। इसका अर्थ यह है कि हिंदू धर्म की अन्य सभी पुस्तकें, जैसे वेद, शास्त्र और पुराण, जिन्हें पवित्र और प्रामाणिक माना जाता है, कानून द्वारा अमान्य हो जानी चाहिए, और इन पुस्तकों में निहित किसी भी धार्मिक या सामाजिक सिद्धांत का प्रचार दंडनीय होना चाहिए।
यह एक बुरा सुझाव है। वास्तव में, कोई भी बौद्ध अंबेडकर द्वारा एक को छोड़कर सभी बौद्ध पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाने जैसे हस्तक्षेप की सराहना नहीं करेगा।
हिंदू सुधार के लिए उनका दूसरा प्रस्ताव पुरोहित प्रथा को समाप्त करना या पुजारी बनने के लिए वंशानुगत मानदंड को हटाना है। सच्चाई यह है कि पुरोहितों के चयन को लेकर मंदिरों में कई परंपराएं प्रचलित हैं, जिनमें जन्म से ही निम्न जाति के पुजारी का चयन करने की परंपरा भी शामिल है। लेकिन अंबेडकर फिर अति कर देते हैं और चाहते हैं कि राज्य पुरोहित प्रथा को उसी तरह नियंत्रित करे जैसे वह सरकारी कर्मचारियों को प्रमाणित करता है। वे कहते हैं, 'कानून द्वारा यह प्रावधान होना चाहिए कि कोई भी हिंदू तब तक पुजारी बनने का हकदार नहीं होगा जब तक वह राज्य द्वारा निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न कर ले।' वास्तव में, वे चाहते हैं कि

सरकारी लाइसेंस के बिना पुजारी के रूप में कार्य करना दंडनीय अपराध हो। प्रत्येक पुजारी 'राज्य का सेवक होना चाहिए'। राज्य को पुरोहितों की संख्या सीमित करनी चाहिए ताकि यह मनमानी व्यवस्था न बन जाए।
जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, गांधी ने अंबेडकर के इस तीखे लेख का जवाब देते हुए जाति व्यवस्था का बचाव किया और उसमें सीमित सुधार की इच्छा व्यक्त की। वे चाहते थे कि बुनियादी संरचनाएं बनी रहें, लेकिन हरिजन समुदाय के प्रति कोई पूर्वाग्रह न हो। इससे अंबेडकर संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने पलटवार करते हुए कहा:
महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हरिजन में जाति विषय पर दिए गए मेरे भाषण का उल्लेख करके मुझे जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं उनका अत्यंत आभारी हूं। ... इस भाषण को प्रकाशित करने का मेरा उद्देश्य हिंदुओं को चिंतन करने और अपनी स्थिति का आकलन करने के लिए प्रेरित करना था।
उनका मानना था कि जाति व्यवस्था ने हिंदुओं को बर्बाद कर दिया है और वर्ण व्यवस्था 'एक ऐसे बर्तन की तरह है जिसमें से पानी रिसता रहता है' और जो अंततः एक अत्याचारी जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत अत्यंत आवश्यक थे। इसके लिए यह आवश्यक था कि 'जाति और वर्ण व्यवस्था के पीछे छिपी धार्मिक पवित्रता की भावना को नष्ट किया जाए'। इसलिए, 'शास्त्रों के दैवीय अधिकार' को त्यागना होगा। किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं था।

अंबेडकर और इस्लामोफोबिया
अंबेडकर और गांधी के बीच मतभेद का एक और प्रमुख क्षेत्र इस्लाम था। गांधी ने मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की और भारत के बाहर

उनके वैश्विक एजेंडे का समर्थन भी किया। दूसरी ओर, अंबेडकर इस्लाम और ईसाई धर्म दोनों को भारतीयों के लिए खतरनाक विकल्प मानते थे क्योंकि उन्हें डर था कि इससे भारतीय समाज का ताना-बाना टूट जाएगा। अंबेडकर द्वारा हिंदू धर्म को अस्वीकार करना सर्वविदित है, लेकिन यह गलत धारणा है कि वे इस्लाम के प्रति सकारात्मक या कम से कम तटस्थ थे। आज यह गलत धारणा वैश्विक वामपंथ के इस्लाम के साथ रणनीतिक गठबंधन का समर्थन करने के लिए बनाई गई है। दलित आंदोलन अब अमेरिका में अश्वेतों और विश्व भर के मुसलमानों के साथ जुड़ा हुआ है और मार्क्सवाद के नए रूपों पर आधारित हो गया है, जिन पर हमने विभिन्न प्रकार के आलोचनात्मक सिद्धांतों के रूप में चर्चा की थी। इस्लाम की आलोचनाओं को रोकने के लिए दुनिया भर में किए जा रहे प्रयासों को देखते हुए, अंबेडकर के उस विचार का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जिसे आज इस्लाम विरोधी माना जा सकता है। वे लिखते हैं कि हिंदू समाज की सामाजिक समस्याओं पर व्यापक रूप से चर्चा तो होती है, लेकिन इस्लाम की इस तरह खुलकर आलोचना न होना उन्हें घोर पाखंड लगता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए, उन्होंने अपनी लगभग पाँच सौ पृष्ठों की पुस्तक 'पाकिस्तान: भारत का विभाजन' में इस्लाम की बिंदुवार आलोचना करने के लिए काफी स्थान समर्पित किया है। उनकी दृढ़ता, स्पष्टवादिता और निर्भीकता उल्लेखनीय है, और यह आश्चर्यजनक है कि इस्लाम की उनकी स्पष्ट और कठोर निंदा के बावजूद, उनके इस कार्य पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। हम उनके विचारों को विस्तार से उद्धृत करेंगे क्योंकि इस विषय पर उनके विचारों को दबाया जा रहा है।

वह अपने तीखे विश्लेषण की शुरुआत यह कहकर करते हैं: 'कोई यह सवाल पूछ सकता है कि क्या कोई ऐसी सामाजिक बुराई है जो हिंदुओं में

पाई जाती है और मुसलमानों में नहीं पाई जाती?' फिर वह कहते हैं, 'बाल विवाह को ही ले लीजिए', और आंकड़ों की एक तालिका का उपयोग करते हुए वह यह तर्क देते हैं कि इस्लाम इस बुराई से हिंदू धर्म की तुलना में कहीं अधिक पीड़ित है।

उनका अगला विषय महिलाओं की स्थिति है। वे कहते हैं, 'मुस्लिम महिला दुनिया की सबसे असहाय व्यक्ति है।' यहाँ वे एक मुस्लिम नेता का हवाला देते हुए विस्तार से बताते हैं: 'इस्लाम ने उस पर हीनता की मुहर लगा दी है और उन सामाजिक रीति-रिवाजों को धार्मिक स्वीकृति दे दी है जिन्होंने उसे आत्म-अभिव्यक्ति और व्यक्तित्व के विकास के पूर्ण अवसर से वंचित कर दिया है।' उनका लंबा विश्लेषण इस निष्कर्ष के साथ समाप्त होता है: 'बहुविवाह और रखैल प्रथा की बड़ी और अनेक बुराइयों को, और विशेष रूप से एक मुस्लिम महिला के लिए इसके दुख के स्रोत को, शब्दों में पर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता।'

फिर वह इस्लाम में गुलामी का मुद्दा उठाता है और लिखता है:

इस्लाम भाईचारे की बात करता है। सभी का मानना है कि इस्लाम गुलामी और जाति-भेद से मुक्त होना चाहिए। गुलामी के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यह अब कानून द्वारा समाप्त कर दी गई है। लेकिन जब तक यह प्रथा प्रचलित थी, इसका अधिकांश समर्थन इस्लाम और इस्लामी देशों से प्राप्त होता था। कुरान में गुलामों के साथ न्यायपूर्ण और मानवीय व्यवहार के संबंध में पैगंबर द्वारा दिए गए निर्देश प्रशंसनीय हैं, लेकिन इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस अभिशाप को समाप्त करने का समर्थन करता हो।

स्पष्ट है कि पैगंबर गुलामी को सहन करते थे और केवल यही चाहते थे कि गुलामों के साथ दुर्व्यवहार न हो।

इसके बाद वे बताते हैं कि इस्लाम में आज भी भयावह जाति व्यवस्था

मौजूद है। इसे समझाने के लिए वे जनगणना के आंकड़े और अन्य स्रोतों का हवाला देते हैं। इस्लाम ने अपने अधिकांश लोगों को निम्न जाति और यहां तक कि अछूत के रूप में वर्गीकृत किया है।

मुसलमान स्वयं दो मुख्य सामाजिक वर्गों को मान्यता देते हैं: (1) अशरफ या शरफ और (2) अजलाफ। अशरफ का अर्थ है 'कुलीन' और इसमें विदेशियों के सभी निर्विवाद वंशज और उच्च जाति के हिंदू धर्मान्तरित लोग शामिल हैं। अन्य सभी मुसलमान, जिनमें व्यावसायिक समूह और निम्न वर्ग के सभी धर्मान्तरित लोग शामिल हैं, अपमानजनक शब्दों 'अजलाफ', 'दुष्ट' या 'नीच लोग' से जाने जाते हैं: उन्हें कमीना या इतर, 'नीच' या रसील भी कहा जाता है, जो रिजाल का बिगड़ा हुआ रूप है, जिसका अर्थ है 'बेकार'। कुछ स्थानों पर एक तीसरा वर्ग भी माना जाता है, जिसे अर्ज़ल या 'सबसे नीच' कहा जाता है। कोई भी अन्य मुसलमान उनसे मेलजोल नहीं रखता और उन्हें सार्वजनिक कब्रिस्तान का उपयोग करने के लिए मस्जिद में प्रवेश करने की मनाही है।

इसके बाद वे अशरफ, अजलाफ और अर्जल जातियों का विस्तार से वर्णन करते हुए उनमें शामिल उप-जातियों के नाम बताते हैं। उदाहरण के लिए, सईद, शेख, पठान और मुगल सबसे उच्च जाति में आते हैं। अधिकांश मुसलमान निचली जातियों से संबंधित हैं। अंत में, वे उन समुदायों के नाम बताते हैं जिन्हें इस्लाम में अछूत माना जाता है।

वे विशेष रूप से पर्दा प्रथा से परेशान हैं: 'वास्तव में, मुसलमानों में हिंदुओं की सभी सामाजिक बुराइयाँ हैं और कुछ और भी। वह कुछ और मुस्लिम महिलाओं के लिए अनिवार्य पर्दा प्रथा है।' वे लिखते हैं:

पर्दा प्रथा के परिणामस्वरूप, मुस्लिम महिलाओं का अलगाव हो जाता है। महिलाओं को बाहरी कमरों, बरामदों या बगीचों में जाने की अनुमति नहीं होती; उनके कमरे घर के पिछवाड़े में होते हैं। ... जवान और बूढ़ी, सभी

एक ही कमरे में बंद रहती हैं। उनकी उपस्थिति में कोई पुरुष नौकर काम नहीं कर सकता। एक महिला को केवल अपने बेटों, भाइयों, पिता, चाचाओं और पति से मिलने की अनुमति होती है, या किसी अन्य करीबी रिश्तेदार से जिसे भरोसेमंद पद दिया गया हो। वह नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद तक नहीं जा सकती और जब भी उसे बाहर जाना हो, उसे बुर्का पहनना पड़ता है। सड़कों पर बुर्का पहने महिलाओं का चलना भारत में सबसे भयावह दृश्यों में से एक है। इस तरह के अलगाव का मुस्लिम महिलाओं के शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ना तय है। वे अक्सर एनीमिया, तपेदिक और पायरिया से पीड़ित होती हैं। उनके शरीर विकृत हो जाते हैं, उनकी पीठ झुक जाती है, हड्डियां बाहर निकल आती हैं, हाथ-पैर टेढ़े हो जाते हैं। पसलियों, जोड़ों और लगभग सभी हड्डियों में दर्द होता है। उनमें अक्सर दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इस श्रोणि विकृति का परिणाम प्रसव के समय असमय मृत्यु होता है।

पर्दा प्रथा मुस्लिम महिलाओं को मानसिक और नैतिक पोषण से वंचित कर देती है। स्वस्थ सामाजिक जीवन से वंचित होने के कारण, नैतिक पतन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग-थलग रहने के कारण, वे अपना ध्यान छोटी-मोटी पारिवारिक कलह में लगाती हैं, ... उनका दृष्टिकोण संकीर्ण और सीमित हो जाता है। वे अन्य समुदायों की अपनी बहनों से पीछे रह जाती हैं, किसी भी बाहरी गतिविधि में भाग नहीं ले पातीं और दासतापूर्ण मानसिकता और हीन भावना से ग्रस्त हो जाती हैं। उनमें ज्ञान की कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि उन्हें घर की चारदीवारी के बाहर किसी भी चीज़ में रुचि न लेने की शिक्षा दी जाती है। विशेष रूप से पर्दा प्रथा का पालन करने वाली महिलाएं असहाय, डरपोक और जीवन में किसी भी संघर्ष के लिए अयोग्य हो जाती हैं। अंबेडकर का कहना है कि मुस्लिम पुरुषों की अनैतिकता का कारण पर्दा

प्रथा है, क्योंकि इन पुरुषों का महिलाओं के साथ सामान्य सामाजिक संपर्क नहीं होता। उनके अनुसार, अलगाव अस्वस्थ प्रवृत्तियों और यौन अतिचारों को जन्म देता है।

परदे के शारीरिक और बौद्धिक प्रभाव नैतिक मूल्यों पर पड़ने वाले इसके प्रभावों के मुकाबले कुछ भी नहीं हैं। परदे की उत्पत्ति स्पष्ट रूप से दोनों लिंगों में यौन इच्छाओं के प्रति गहरी जड़ें जमाए संदेह में निहित है और इसका उद्देश्य लिंगों को अलग करके उन्हें नियंत्रित करना है। ... परदे ने मुस्लिम पुरुषों के नैतिक मूल्यों को बुरी तरह प्रभावित किया है। ... एक मुस्लिम का अपने घर की महिलाओं के अलावा किसी अन्य महिला से कोई संपर्क नहीं होता। यहां तक कि उनके साथ भी उसका संपर्क केवल कभी-कभार बातचीत तक ही सीमित रहता है। पुरुषों के लिए, बच्चों या वृद्ध महिलाओं को छोड़कर, किसी भी महिला के साथ कोई संगति या मेलजोल नहीं होता। यह अलगाव ... पुरुषों के नैतिक मूल्यों पर निश्चित रूप से बुरे प्रभाव डालता है। यह कहने के लिए किसी मनोविश्लेषक की आवश्यकता नहीं है कि एक सामाजिक व्यवस्था जो दोनों लिंगों के बीच सभी संपर्कों को काट देती है, यौन अतिचार और अप्राकृतिक तथा अन्य विकृत आदतों और तरीकों की ओर अस्वस्थ प्रवृत्ति को जन्म देती है।

उनका दावा है कि यह अलगाव मुसलमानों और अन्य लोगों के बीच भेदभाव को भी जन्म देता है। इसके अलावा, यह मुसलमानों को राष्ट्र की व्यापक राजनीति और सामाजिक कल्याण के प्रति उदासीन बना देता है: 'पर्दा प्रथा के बुरे परिणाम केवल मुस्लिम समुदाय तक ही सीमित नहीं हैं। यह हिंदुओं और मुसलमानों के सामाजिक अलगाव के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में सार्वजनिक जीवन के लिए अभिशाप है।'

अंबेडकर ने आगे मुसलमानों पर आरोप लगाया कि उनमें तुच्छ और स्वार्थी मामलों से परे राजनीतिक संवेदनशीलता का अभाव है:

मुसलमानों को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उनकी सर्वोपरि रुचि धर्म में होती है। यह बात उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए मुस्लिम मतदाताओं द्वारा रखी जाने वाली शर्तों और नियमों से स्पष्ट होती है... उम्मीदवार के कार्यक्रम की जांच-परख करना उन्हें कोई परवाह नहीं होती। ... उम्मीदवार को मस्जिद के पुराने दीयों को अपने खर्च पर नए दीयों से बदलना चाहिए, फटे हुए पुराने कालीन को नए कालीन से ढकना चाहिए, या जर्जर हो चुकी मस्जिद की मरम्मत करानी चाहिए। ... मुस्लिम मतदाता तब भी संतुष्ट हो जाते हैं जब उम्मीदवार भव्य भोज देने को तैयार हो जाता है, और कुछ मामलों में तब भी जब वह एक-एक वोट के लिए वोट खरीदने को तैयार हो जाता है। मुसलमानों के लिए चुनाव केवल पैसे का मामला है, और सामाजिक कार्यक्रम का मुद्दा बहुत कम ही होता है...। मुस्लिम राजनीति विशुद्ध धर्मनिरपेक्ष जीवन श्रेणियों, जैसे अमीर और गरीब, पूंजीपति और मजदूर, जमींदार और किरायेदार, पुजारी और आम आदमी, तर्क और अंधविश्वास के बीच के अंतरों पर ध्यान नहीं देती। यह मूलतः धार्मिक है और केवल एक ही अंतर को मान्यता देती है, अर्थात् हिंदू और मुसलमान के बीच का अंतर। जीवन की धर्मनिरपेक्ष श्रेणियों में से किसी का भी मुस्लिम समुदाय की राजनीति में कोई स्थान नहीं है; और यदि उन्हें स्थान मिल भी जाता है—और मिलना ही चाहिए, क्योंकि वे अप्रतिरोध्य हैं—तो वे मुस्लिम राजनीतिक जगत के एकमात्र मार्गदर्शक सिद्धांत, अर्थात् धर्म के अधीन हो जाते हैं।

उनका कहना है कि सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि मुसलमानों को जगाने और उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए किसी भी तरह के सामाजिक आंदोलन का पूरी तरह से अभाव है।

लेकिन इससे भी कहीं अधिक चिंताजनक बात यह है कि भारत के मुसलमानों में सामाजिक सुधार का कोई संगठित आंदोलन नहीं है जो इन

बुराइयों को जड़ से खत्म कर सके। हिंदुओं में भी सामाजिक बुराइयाँ हैं। लेकिन उनमें एक राहत देने वाली बात यह है कि उनमें से कुछ इन बुराइयों के अस्तित्व से अवगत हैं, और कुछ इनके निवारण के लिए सक्रिय रूप से आंदोलन कर रहे हैं। मुसलमान... इन बुराइयों को नहीं समझते, और इसलिए इनके निवारण के लिए आंदोलन नहीं करते। ...वे अपनी मौजूदा प्रथाओं में किसी भी बदलाव का विरोध करते हैं। ...मुसलमानों ने 1930 में केंद्रीय विधानसभा में लाए गए बाल विवाह विधेयक का विरोध किया, जिसके तहत लड़की के विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़के के विवाह की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी, इस आधार पर कि यह मुस्लिम धार्मिक कानून के विरुद्ध था।

और गहराई से समझाते हुए, अंबेडकर मुस्लिम कानून के मूल सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं, जिसके अनुसार दुनिया को मुसलमानों द्वारा शासित देशों और गैर-मुसलमानों, यानी काफिरों द्वारा शासित देशों में विभाजित किया गया है। ऐसी व्यवस्था में सच्ची लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। मुस्लिम धार्मिक कानून के अनुसार, दुनिया दो भागों में बंटी है: दार-उल-इस्लाम (इस्लाम का निवास स्थान) और दार-उल-हर्ब (युद्ध का निवास स्थान)। कोई देश दार-उल-इस्लाम तब कहलाता है जब उस पर मुसलमानों का शासन हो। कोई देश दार-उल-हर्ब तब कहलाता है जब मुसलमान उसमें निवास तो करते हैं लेकिन शासक नहीं होते। मुस्लिम धार्मिक कानून के अनुसार, भारत हिंदुओं और मुसलमानों की साझा मातृभूमि नहीं हो सकता। यह मुसलमानों की भूमि हो सकती है, लेकिन यह 'हिंदुओं और मुसलमानों के समान रूप से रहने' की भूमि नहीं हो सकती। इसके अलावा, यह मुसलमानों की भूमि तभी हो सकती है जब इस पर मुसलमानों का शासन हो। जिस क्षण यह भूमि किसी गैर-मुस्लिम शक्ति के अधीन हो जाती है, यह मुसलमानों की भूमि नहीं रह जाती।

दार-उल-इस्लाम होने के बजाय, यह दार-उल-हर्ब बन जाती है।
उनका कहना है कि जब मुस्लिम शासित देश गैर-मुस्लिम देशों को हराने में असमर्थ होते हैं, तो वे 'इस्लामी जिहाद की चरमपंथी अवधारणा' का सहारा लेते हैं। वे इसे इस प्रकार संक्षेप में बताते हैं:
मुस्लिम कानून में जिहाद (धर्मयुद्ध) नामक एक और आदेश है... इसके अनुसार, "किसी मुस्लिम शासक का यह कर्तव्य है कि वह इस्लाम के शासन का विस्तार करे जब तक कि पूरी दुनिया इसके अधीन न आ जाए। ... तकनीकी रूप से, सक्षम मुस्लिम शासक का यह कर्तव्य है कि वह दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करे।" और जिस प्रकार भारत में मुसलमानों द्वारा हिजरत का सहारा लेने के उदाहरण मिलते हैं, उसी प्रकार जिहाद की घोषणा करने में भी उनके संकोच न करने के उदाहरण भी मिलते हैं।
देश के प्रति एक मुसलमान की निष्ठा और इस्लाम के प्रति उसकी निष्ठा के मुद्दे पर, अंबेडकर संभावित दोहरेपन को उजागर करते हैं:
... एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, वह इस्लाम का वह सिद्धांत है जो कहता है कि किसी ऐसे देश में जो मुस्लिम शासन के अधीन नहीं है, जहाँ कहीं भी मुस्लिम कानून और उस देश के कानून के बीच टकराव हो, मुस्लिम कानून को ही सर्वोपरि माना जाएगा, और एक मुसलमान को मुस्लिम कानून का पालन करने और उस देश के कानून का उल्लंघन करने का औचित्य होगा... कुरान के अनुसार, एक मुसलमान को, चाहे वह नागरिक हो या सैनिक, चाहे वह मुस्लिम शासन के अधीन हो या गैर-मुस्लिम शासन के अधीन, केवल ईश्वर, उसके पैगंबर और मुसलमानों में से सत्ता में बैठे लोगों के प्रति निष्ठा रखने का आदेश दिया गया है...
हिंदू इस्लाम धर्म को नहीं मानते, इसलिए उन्हें काफ़िर माना जाता है। इस

कारण मुसलमान उन्हें सम्मान के पात्र नहीं मानते। परिणामस्वरूप, हिंदुओं के नेतृत्व वाली कोई भी सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या नहीं, मुसलमानों को स्वीकार्य नहीं हो सकती।

मुसलमानों के लिए हिंदू काफ़िर है। काफ़िर सम्मान के योग्य नहीं है। वह नीच कुल का और अधिकारहीन है। इसीलिए काफ़िर द्वारा शासित देश मुसलमान के लिए दारुल हर्ब है। ... यह साबित करने के लिए और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती कि मुसलमान हिंदू सरकार का पालन नहीं करेंगे। सरकार के अधिकार का पालन करने के लिए प्रेरित करने वाली आदर और सहानुभूति की मूलभूत भावनाएँ स्वाभाविक रूप से मौजूद नहीं होतीं। लेकिन यदि प्रमाण की आवश्यकता हो, तो उसकी कोई कमी नहीं है। यह इतना प्रचुर मात्रा में है कि समस्या यह है कि क्या प्रस्तुत किया जाए और क्या नहीं... खिलाफत आंदोलन के दौरान, जब हिंदू मुसलमानों की मदद के लिए इतना कुछ कर रहे थे, तब भी मुसलमान यह नहीं भूले कि उनकी तुलना में हिंदू एक नीच और हीन जाति हैं।

मुख्यधारा में प्रचलित आम राय के विपरीत, अंबेडकर को विश्वास है कि इस्लाम अत्यधिक विभाजनकारी और कबीलेवादी है:

कहा जाता है कि हिंदू धर्म लोगों को बांटता है और इसके विपरीत, इस्लाम लोगों को एकजुट करता है। यह केवल आधा सच है। क्योंकि इस्लाम जितना लोगों को जोड़ता है, उतना ही उन्हें विभाजित भी करता है। इस्लाम एक घनिष्ठ संगठन है और मुसलमानों और गैर-मुसलमानों के बीच जो अंतर यह करता है, वह बहुत ही वास्तविक, बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही अलगाव पैदा करने वाला अंतर है। इस्लाम का भाईचारा मानवता का सार्वभौमिक भाईचारा नहीं है। यह केवल मुसलमानों के लिए मुसलमानों का भाईचारा है। भाईचारा तो है, लेकिन इसका लाभ केवल

उस संगठन के सदस्यों तक ही सीमित है। जो लोग इससे बाहर हैं, उनके लिए केवल तिरस्कार और शत्रुता ही है।

इस्लाम की भयावहता के इस तरह के विश्लेषण के कई पन्नों के बाद, अंबेडकर आश्चर्य करते हैं, 'मुसलमान सामाजिक सुधार का विरोध क्यों करते हैं?' इसका उत्तर देने के लिए, वे पहले उन कारणों पर गौर करते हैं जो विश्व भर के मुसलमानों को पिछड़ा हुआ मानते हैं। वे कहते हैं कि मुसलमानों को विश्व स्तर पर 'एक अप्रगतिशील लोग' घोषित किया गया है। इस्लाम ने उन्हें 'उनकी जन्मजात बर्बरता में जकड़ रखा है... यह एक स्थिर अवस्था में है, निष्क्रिय और अभेद्य। यह अपरिवर्तनीय है; और राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक परिवर्तनों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।' वे विज्ञान के प्रति मुसलमानों की घृणा पर फ्रांसीसी प्राच्यविद् जोसेफ रेनन का हवाला देते हैं।

मुसलमान की सबसे विशिष्ट विशेषता विज्ञान के प्रति उसकी घृणा है, उसका यह दृढ़ विश्वास है कि अनुसंधान व्यर्थ, तुच्छ और लगभग अधार्मिक है—प्राकृतिक विज्ञान, क्योंकि वे ईश्वर के साथ प्रतिद्वंद्विता करने के प्रयास हैं।

अंबेडकर भारत में विशेष रूप से इस स्थिति का गहराई से विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकालते हैं कि मुसलमान स्वयं को हिंदुओं का विरोधी मानते हैं। उन्हें लगातार हिंदुओं से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है: 'उनकी सारी ऊर्जा हिंदुओं के विरुद्ध पदों और सीटों के लिए निरंतर संघर्ष में लगी रहती है, जिसमें सामाजिक सुधार से संबंधित प्रश्नों के लिए न तो समय है, न विचार है और न ही गुंजाइश है।' वे कहते हैं कि मुसलमान सामाजिक न्याय के लिए हिंदुओं के साथ सहयोग नहीं करना चाहते, भले ही दोनों पक्षों का हित एक समान हो।

उदाहरण के लिए, उनका मानना है कि गरीब मुसलमान, सभी धर्मों के

अमीरों से लड़ने के लिए गरीब हिंदुओं के साथ एकजुट नहीं होते, क्योंकि वे किसी अमीर मुस्लिम जमींदार से लड़ना नहीं चाहते। मुसलमानों में भाईचारा हर तरह के सामाजिक न्याय से ऊपर है। यह इस बात से स्पष्ट है कि मुसलमान हिंदू शासित राज्यों के खिलाफ आंदोलन करते हैं, लेकिन मुस्लिम शासित राज्यों के खिलाफ नहीं, जबकि मुद्दा बिल्कुल एक जैसा होता है। वे लिखते हैं:

मुसलमानों के लिए सबसे अहम मुद्दा लोकतंत्र नहीं है। बल्कि यह है कि बहुसंख्यक शासन वाला लोकतंत्र हिंदुओं के खिलाफ उनके संघर्ष में मुसलमानों को कैसे प्रभावित करेगा। क्या इससे उन्हें मजबूती मिलेगी या कमजोरी? अगर लोकतंत्र उन्हें कमजोर करता है, तो वे लोकतंत्र को नहीं अपनाएंगे। वे मुस्लिम राज्यों में भ्रष्ट व्यवस्था को जारी रखना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि हिंदू प्रजा पर मुस्लिम शासक की पकड़ कमजोर हो। मुस्लिम समुदाय में राजनीतिक और सामाजिक गतिरोध का केवल एक ही कारण है। मुसलमान सोचते हैं कि हिंदू और मुसलमानों को निरंतर संघर्ष करना होगा।

अंबेडकर गांधी को भी नहीं छोड़ते, जिन्हें वे मुसलमानों की रक्षा करने और अपने सिद्धांतों का उल्लंघन करने के लिए पाखंडी मानते हैं: 'उन्होंने [गांधी ने] मुसलमानों को कभी जवाबदेह नहीं ठहराया, जबकि वे हिंदुओं के खिलाफ जघन्य अपराध करने के दोषी थे।' अंबेडकर भारत में मुसलमानों द्वारा हिंदुओं की हत्याओं की निंदा करते हैं और इस बात से चिंतित हैं कि गांधी ऐसे व्यवहार की आलोचना करने में विफल रहे।

श्री गांधी हिंसा के हर कृत्य की निंदा करने में अत्यंत सतर्क रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस को, उसकी इच्छा के विरुद्ध भी, इसकी निंदा करने के लिए बाध्य किया है। लेकिन श्री गांधी ने कभी भी हिंदुओं की ऐसी हत्याओं का विरोध नहीं किया। मुसलमानों ने ही नहीं, बल्कि श्री गांधी ने भी प्रमुख

मुस्लिम नेताओं से इनकी निंदा करने का आह्वान नहीं किया। वे इन मामलों पर मौन रहे हैं।

अंबेडकर ने हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों द्वारा किए गए कुख्यात दंगों के बारे में लिखा है:

मालाबार में मोपलाओं द्वारा हिंदुओं के विरुद्ध किए गए रक्तरंजित अत्याचार अवर्णनीय थे। पूरे दक्षिण भारत में, हर विचारधारा के हिंदुओं के बीच भय की लहर फैल गई थी, जो तब और तीव्र हो गई जब कुछ खिलाफत नेताओं ने इस प्रकार गुमराह होकर प्रस्ताव पारित कर दिए कि 'धर्म की खातिर लड़ रहे मोपलाओं को बधाई'।

इन तमाम भयावहताओं के बावजूद, गांधी ने उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें 'बहादुर, ईश्वर से डरने वाले मोपला' बताया जो 'अपने धर्म के लिए और धार्मिक तरीके से लड़ रहे थे'।

इस्लाम पर अंबेडकर के व्यापक लेखन का कोई भी निष्पक्ष अध्ययन यह पाएगा कि आज विश्व स्तर पर लागू किए जा रहे मानदंडों के अनुसार वे इस्लाम विरोधी थे।

अंबेडकर और बौद्ध धर्म

अंबेडकर ने 'बुद्ध और उनका धम्म' नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने बौद्ध धर्म की अपनी व्याख्या को स्पष्ट रूप से समझाया है। प्रस्तावना में, उन्होंने उन बातों को स्पष्ट किया है जिन्हें वे प्रचलित व्याख्याओं में अस्वीकार करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहलू जिसे वे अस्वीकार करते हैं, वह बुद्ध की शिक्षाओं का मूल तत्व है: चार आर्य सत्य। अंबेडकर लिखते हैं:

आर्यों के चार सत्य गैर-बौद्धों के लिए बौद्ध धर्म के उपदेशों को स्वीकार करने में एक बड़ी बाधा हैं। क्योंकि ये चार आर्य सत्य मनुष्य में आशा का

अभाव पैदा करते हैं और बुद्ध के उपदेशों को निराशावाद का उपदेश बना देते हैं। क्या ये मूल उपदेशों का हिस्सा हैं या भिक्षुओं द्वारा बाद में जोड़े गए हैं?

पुनर्जन्म की अवधारणा को अस्वीकार करने में उनके विचार विरोधाभासों से भरे हैं। एक ओर तो वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म जैसी कोई बात नहीं है, वहीं दूसरी ओर वे कहते हैं कि बुद्ध एक बोधिसत्व थे, जो पुनर्जन्म पर आधारित एक अवधारणा है, जिसे वे इस प्रकार समझाते हैं:

ज्ञान प्राप्ति से पहले गौतम केवल बोधिसत्व थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध बने। बोधिसत्व कौन और क्या होता है? बोधिसत्व वह व्यक्ति होता है जो बुद्ध बनने की आकांक्षा रखता है। बोधिसत्व बुद्ध कैसे बनता है? बोधिसत्व को लगातार दस जन्मों तक बोधिसत्व रहना पड़ता है। अपने दसवें जन्म में वे धर्ममेघ बनते हैं। बोधिसत्व को बुद्ध की अनंत दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है।

वह विशेष रूप से वर्णन करते हैं कि बोधिसत्व ने दसवें जन्म में बुद्ध बनने से पहले अपने पिछले नौ जन्मों में क्या-क्या उपलब्धियां हासिल कीं। इस विरोधाभास का कारण स्पष्ट है: चूंकि अंबेडकर हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा से खुद को अलग रखना चाहते थे, इसलिए वे बौद्ध धर्म से भी इसे हटाना चाहते थे, जिसे उन्होंने स्वयं अपनाया था। असल समस्या यह है कि स्वयं बुद्ध कहते हैं कि उन्हें अपने अनेक पूर्व जन्म याद हैं। दलाई लामा और बोधिसत्व की संपूर्ण परंपरा पुनर्जन्म पर आधारित है।

हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के बारे में अंबेडकर की समझ गलत है: हिंदू धर्म में परम आत्मा (आत्मन) की अवधारणा है, और वह आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। इसलिए, पुनर्जन्म आत्मा का नहीं होता। पुनर्जन्म लेने वाली सत्ता जीवात्मा है, जो आत्मा का शारीरिक

रूप है, और आत्मा से भिन्न है।
बौद्ध धर्म में चेतना की एक धारा है जिसमें क्षणिक अवस्थाएँ समाहित हैं और कोई स्थायी आत्मा या आधार नहीं है। आत्मा का अनुभव एक भ्रम है। ऐसी कोई 'सत्ता' नहीं है जो पुनर्जन्म लेती हो, लेकिन पुनर्जन्म एक प्रक्रिया है। कर्म चेतना पर संस्कार या वासना नामक छाप छोड़ते हैं। संस्कार की ऊर्जा एक बीज के समान है जो फल नामक प्रभाव उत्पन्न करती है। शरीर की मृत्यु के बाद, अपूर्ण संस्कार नए शरीर के पुनर्जन्म का आधार बनते हैं। लेकिन ऐसी कोई आत्मा नहीं है जो पुनर्जन्म लेती हो।
एक धर्म (हिंदू धर्म) में परम आत्मा का अस्तित्व है, लेकिन वह जन्म लेने या मरने वाली शक्ति नहीं है। दूसरे धर्म (बौद्ध धर्म) में कोई परम आत्मा नहीं है। इसलिए, दोनों में से कोई भी धर्म यह नहीं मानता कि कोई परम आत्मा पुनर्जन्म लेती है।
इसी प्रकार, हिंदू धर्म में कर्म की अवधारणा को लेकर अंबेडकर की समझ भी गलत है। उनका कहना है कि हिंदू धर्म में कर्म की अवधारणा 'आत्मा' पर आधारित है, जबकि आत्मा एक अब्राहमिक अवधारणा है, इसलिए इससे भ्रम उत्पन्न होता है। यद्यपि बौद्ध धर्म में कर्म अर्जित करने वाली कोई सत्ता नहीं है, फिर भी यह कहता है कि संस्कार या वासनाएं कर्म के वे निशान हैं जो परिणामों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अतः बौद्ध धर्म कर्म को नकारता नहीं है।
अंबेडकर और मानक बौद्ध धर्म के बीच एक और गंभीर मतभेद ध्यान के प्रति उनके दृष्टिकोण को लेकर है। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग सभी बौद्धों के लिए निर्धारित विधि है। इस मार्ग के सातवें और आठवें चरण क्रमशः सजगता और ध्यान हैं। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ, सतिपट्ठान सूत्र और विशुद्धिमग्ग, बुद्ध द्वारा स्वयं के ज्ञानोदय के लिए अभ्यास की गई कई

व्यवस्थित ध्यान तकनीकों पर जोर देते हैं। बुद्ध की संपूर्ण शिक्षा यह है कि ये सार्वभौमिक मार्ग हैं जो सभी के लिए उपलब्ध हैं, और वे केवल वही सिखा रहे हैं जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया है, और कुछ नहीं।
लेकिन अंबेडकर बौद्ध धर्म की अपनी व्याख्या में ध्यान को नजरअंदाज करते हैं या उस पर कम जोर देते हैं। उनके लिए, ध्यान केवल शिक्षा और मानसिक विकास का एक साधन मात्र है। किसी भी गंभीर बौद्ध के लिए, ध्यान मानसिक गतिविधि से पूरी तरह अलग है, और यदि ध्यान को तुच्छ समझा जाए तो बौद्ध धर्म का पूरा आधार ही खो जाता है।
बौद्ध धर्म के इन मूल सिद्धांतों को त्यागकर, उन्होंने एक नया संस्करण तैयार किया। अक्टूबर 1956 में बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अंबेडकर ने हिंदू धर्म के साथ-साथ थेरवाद और महायान बौद्ध धर्म को भी औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अपनी मृत्यु से लगभग छह सप्ताह पहले अपने स्वयं के नवयान बौद्ध धर्म की शुरुआत की। इस नए आंदोलन में शामिल होने के लिए उनके अनुयायियों के औपचारिक शपथ समारोह में बाईस प्रतिज्ञाएँ शामिल थीं। यद्यपि उनमें से एक प्रतिज्ञा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का नाममात्र उल्लेख करती है, लेकिन उसमें ध्यान का कोई जिक्र नहीं है।
संक्षेप में, अंबेडकर ने बौद्ध धर्म का धर्मनिरपेक्षीकरण किया है और इसके आध्यात्मिक आयाम को जड़ से उखाड़ फेंका है:
वह निर्वाण या ज्ञानोदय की पारंपरिक अवधारणा को कुछ हद तक अलौकिक और पलायनवादी मानकर खारिज कर देते हैं।
उनका मानना है कि ध्यान अभ्यास में बहुत अधिक समय व्यतीत करना गैरजिम्मेदाराना है क्योंकि इससे व्यक्ति सामाजिक संबंधों से दूर हो जाता है।
वे निर्वाण को आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं बल्कि एक सामाजिक

अवधारणा मानते हैं, जो सद्भाव और न्याय पर आधारित समाज को संदर्भित करती है। अंबेडकर का लक्ष्य बौद्ध धर्म को सामाजिक न्याय की व्यवस्था में परिवर्तित करना था। वे चाहते थे कि उनके द्वारा निर्मित बौद्ध धर्म में लोकतंत्र को बढ़ावा मिले और अछूतों और अन्य समुदायों को न्याय मिले।

हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अंबेडकर आध्यात्मिकता को व्यर्थ नहीं मानते थे। वे केवल उस अस्पृश्यता को दूर करने का प्रयास कर रहे थे जो उनके अनुसार हिंदू दर्शन में निहित थी। उनकी समस्या इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि बौद्ध धर्म के कई सिद्धांत हिंदू धर्म के समान थे, जिसके कारण उनके लिए बिना बदलाव के बौद्ध धर्म को अपनाना असंभव था।

उनके अनुयायियों ने उनके आंदोलन की तुलना उस बौद्ध धर्म से करने का प्रयास किया है जिसे दिवंगत वियतनामी भिक्षु थिच न्हाट हान पश्चिम में लेकर आए थे। पश्चिमी लोग इसे 'सक्रिय बौद्ध धर्म' कहते हैं क्योंकि यह समाज और पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के प्रति मानवीय चेतना को जागृत करने के लिए ध्यान और अन्य अभ्यासों का उपयोग करता है। फिर यह बौद्ध नैतिकता और ध्यान के अभ्यास से प्राप्त अंतर्दृष्टि को सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के माध्यम से दुख और अन्याय को कम करने में लागू करता है। इसमें अहिंसा, भौतिकवाद से अनासक्ति, पशु और प्रकृति की रक्षा और शांति स्थापना पर विशेष बल दिया जाता है। लेकिन यह तुलना कठिन है क्योंकि अंबेडकर के बौद्ध धर्म में ध्यान शामिल नहीं है, जबकि थिच न्हाट हान के बौद्ध धर्म की शुरुआत यहीं से होती है। परिणामस्वरूप, अंबेडकर का बौद्ध धर्म विशुद्ध रूप से राजनीतिक है।

धर्मनिरपेक्ष बौद्ध धर्म का समर्थन करने के बावजूद, अंबेडकर धर्मनिरपेक्षता

के विरोधी होने का दावा करते थे; वे धर्म को ही अपना आधार बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा: 'जो लोग धर्म के महत्व को नकारते हैं, वे यह समझने में विफल रहते हैं कि विशुद्ध धर्मनिरपेक्ष आदर्श की तुलना में धार्मिक आदर्श में कितनी अधिक शक्ति और मान्यता निहित है।' 1954 में अखिल भारतीय रेडियो के एक प्रसारण में उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष आदेशों को तोड़ा जा सकता है, जबकि धर्म का सभी को सम्मान करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यद्यपि उनके आंदोलन ने बौद्ध धर्म के प्रमुख आध्यात्मिक तत्वों को हटाकर इसे विशुद्ध रूप से सामाजिक न्याय आंदोलन में बदल दिया, अंबेडकर इसे धर्म का नाम देना चाहते थे ताकि इसे वह पवित्रता प्राप्त हो सके जो धर्म, और विशेष रूप से बौद्ध धर्म को प्राप्त है।

ईसाई धर्म और इस्लाम के संबंध में उन्होंने कहा:

धर्म परिवर्तन के देश पर पड़ने वाले परिणामों को ध्यान में रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस्लाम या ईसाई धर्म में धर्मांतरण से दलित वर्गों का राष्ट्रीय अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यदि वे इस्लाम अपनाते हैं, तो मुसलमानों की संख्या दोगुनी हो जाएगी...और मुस्लिम वर्चस्व का खतरा भी वास्तविक हो जाएगा। यदि वे ईसाई धर्म अपनाते हैं...तो इससे देश पर ब्रिटेन की पकड़ और मजबूत हो जाएगी।

उन्होंने बौद्ध धर्म को भारत के लिए सबसे कम हानिकारक मार्ग बताया, क्योंकि वे बौद्ध धर्म को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग मानते थे। उनका उद्देश्य सरल था। अंबेडकर एक कट्टर भारतीय राष्ट्रवादी थे और भारतीय संस्कृति के लिए लाभकारी धर्म का समर्थन करने को अपनी प्राथमिकता मानते थे। उनकी सोच को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

	Hinduism	Christianity	Islam	Buddhism
Good for India's unity	Yes	No	No	Yes
Good for overcoming caste abuse	No	N/A	No	Yes

अंबेडकर और साम्यवाद

अंबेडकर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अध्ययनों में से एक बुद्ध और कार्ल मार्क्स की तुलना थी। बाद में इसे "बुद्ध या कार्ल मार्क्स?" नामक एक छोटी पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। वे यह कहकर शुरुआत करते हैं कि दोनों प्रणालियाँ संपत्ति के निजी स्वामित्व का विरोध करती हैं क्योंकि इससे दुख और पीड़ा होती है। दोनों में अंतर केवल उपयोग की जाने वाली विधियों में है।

इसके बाद वे उनकी पद्धतियों का विश्लेषण करते हैं और बताते हैं कि बौद्ध धर्म मार्क्सवाद से श्रेष्ठ क्यों है। मुख्य अंतर यह है कि बुद्ध पहले व्यक्ति के नैतिक स्वभाव में आंतरिक परिवर्तन लाना चाहते थे और उसे स्वेच्छा से अपने मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहते थे, जबकि साम्यवाद हिंसा का उपयोग करता है और तानाशाही थोपता है। वे लिखते हैं:

बुद्ध द्वारा अपनाए गए साधन थे किसी व्यक्ति के नैतिक स्वभाव को बदलकर उसे स्वेच्छा से मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना।

साम्यवादियों द्वारा अपनाए गए साधन भी उतने ही स्पष्ट, संक्षिप्त और त्वरित हैं। वे हैं (1) हिंसा और (2) सर्वहारा वर्ग की तानाशाही।

साम्यवादी कहते हैं कि साम्यवाद की स्थापना के केवल दो ही साधन हैं। पहला है हिंसा। मौजूदा व्यवस्था को तोड़ने के लिए इसके अलावा कोई और साधन पर्याप्त नहीं है। दूसरा है सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। नई

व्यवस्था को जारी रखने के लिए इसके अलावा कोई और साधन पर्याप्त नहीं है। अब बुद्ध और कार्ल मार्क्स के बीच समानताएं और अंतर स्पष्ट हो गए हैं। अंतर साधनों के बारे में हैं। लक्ष्य दोनों का एक ही है।

अंबेडकर कहते हैं कि अपने नेक उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश में कम्युनिस्टों ने अन्य मूल्यवान चीजों को नष्ट कर दिया। वे पूछते हैं, 'क्या वे मालिक की जान लिए बिना संपत्ति नहीं छीन सकते थे?' इसलिए अंततः उन्होंने बुद्ध के स्वैच्छिक दृष्टिकोण को कम्युनिज्म के बल प्रयोग से श्रेष्ठ माना।

वे कहते हैं कि महत्वपूर्ण अंतर बाह्य बल प्रयोग (साम्यवाद में) और व्यक्ति के आंतरिक रूपांतरण (बौद्ध धर्म में) के बीच है: 'किसी को बलपूर्वक शासन और नैतिक मूल्यों के आधार पर शासन में से किसी एक को चुनना होगा।' वे बुद्ध के एक उपदेश का उदाहरण देते हुए धार्मिक शासन और बलपूर्वक शासन के बीच अंतर स्पष्ट करते हैं। रूसी साम्यवादी क्रांति का उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि उनके द्वारा प्राप्त परिवर्तन बल प्रयोग के बिना कायम नहीं रह सकते। बल प्रयोग बंद होने पर अराजकता फैल जाएगी।

यह शायद नैतिक बल के विफल होने और क्रूर बल के उसके स्थान पर आने की स्थिति का सबसे सटीक चित्रण है। बुद्ध की इच्छा थी कि प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक रूप से इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह स्वयं धर्म के राज्य का रक्षक बन सके।

उनका कहना है कि बल प्रयोग समाप्त होने के बाद केवल धर्म ही परिवर्तन को कायम रख सकता है। वे रूसियों को एक सबक देते हैं: 'ऐसा प्रतीत होता है कि रूसी बल प्रयोग समाप्त होने के बाद साम्यवाद को कायम रखने के लिए बौद्ध धर्म को अंतिम सहायता के रूप में नहीं देख रहे हैं।'

उनके लिए तानाशाही समस्याग्रस्त थी क्योंकि इसे बनाए रखने के लिए निरंतर बल प्रयोग की आवश्यकता होती थी। बुद्ध ने इसका विरोध किया: 'तानाशाही के संबंध में बुद्ध का कोई मत नहीं था। वे एक लोकतांत्रिक व्यक्ति के रूप में पैदा हुए और एक लोकतांत्रिक व्यक्ति के रूप में ही उनकी मृत्यु हुई।' लोकतंत्र का लाभ स्पष्ट है: 'संसदीय सरकार में आपका कर्तव्य और अधिकार दोनों होते हैं; कानून का पालन करने का कर्तव्य और उसकी आलोचना करने का अधिकार। तानाशाही में आपका केवल पालन करने का कर्तव्य होता है, लेकिन उसकी आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं होता।'

तानाशाही केवल अल्पकालिक रूप से ही एक सुरक्षित लोकतंत्र स्थापित करने के लिए अच्छी हो सकती है। 'तानाशाही अपना काम पूरा करने के बाद, लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं और पत्थरों को हटाने के बाद और लोकतंत्र के मार्ग को सुरक्षित बनाने के बाद, स्वयं को क्यों न समाप्त कर दे?' उन्होंने स्थायी तानाशाही को अनुचित माना क्योंकि यह आध्यात्मिक मूल्यों को नष्ट कर देती है: 'मानवता केवल आर्थिक मूल्यों को ही नहीं चाहती, बल्कि वह आध्यात्मिक मूल्यों को भी संरक्षित रखना चाहती है। स्थायी तानाशाही ने आध्यात्मिक मूल्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है।'

अंबेडकर को इस बात पर गर्व है कि रूसियों द्वारा साम्यवाद लाने से हजारों साल पहले, बुद्ध ने अपने संघ में इसे छोटे पैमाने पर लागू कर दिया था, और वह भी बल प्रयोग या तानाशाही का सहारा लिए बिना।

रूसी अपने साम्यवाद पर गर्व करते हैं। लेकिन वे भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि बुद्ध ने संघ के संदर्भ में साम्यवाद की स्थापना तानाशाही के बिना की। ... यह बहुत छोटे पैमाने पर साम्यवाद था,

लेकिन ... यह तानाशाही के बिना था, एक चमत्कार जिसे लेनिन करने में असफल रहे। बुद्ध की विधि भिन्न थी। उनकी विधि मनुष्य के मन को बदलना था: उसके स्वभाव को बदलना था: ताकि मनुष्य जो भी करे, वह स्वेच्छा से बिना बल या दबाव के करे। उनका मुख्य साधन ... उनका धम्म और उनके धम्म का निरंतर प्रचार था। बुद्ध का मार्ग लोगों को वह करने के लिए मजबूर करना नहीं था जो उन्हें पसंद नहीं था, भले ही वह उनके लिए अच्छा था। उनका मार्ग मनुष्य के स्वभाव को बदलना था ताकि वे स्वेच्छा से वह करें जो वे अन्यथा नहीं करते।

उनका आदर्श समाज वह होगा जो फ्रांसीसी क्रांति की आकांक्षाओं को पूरा करे, लेकिन जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य करें:

समाज एक नई नींव रखने का प्रयास कर रहा है जिसे फ्रांसीसी क्रांति ने तीन शब्दों में संक्षेप में व्यक्त किया था: बंधुत्व, स्वतंत्रता और समानता। इस नारे के कारण फ्रांसीसी क्रांति का स्वागत किया गया था। लेकिन यह समानता लाने में विफल रही। हम रूसी क्रांति का स्वागत करते हैं क्योंकि इसका उद्देश्य समानता लाना है। लेकिन समानता लाने के प्रयास में समाज बंधुत्व या स्वतंत्रता का बलिदान नहीं कर सकता। बंधुत्व या स्वतंत्रता के बिना समानता का कोई मूल्य नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये तीनों एक साथ तभी रह सकते हैं जब कोई बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करे।

संक्षेप में कहें तो, साम्यवाद और फ्रांसीसी क्रांति दोनों के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग बुद्ध के मार्ग से होकर गुजरता है। दोनों ही अपने घोषित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हुए, लेकिन बुद्ध ने उन्हें बहुत पहले ही प्राप्त कर लिया था।

जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, अंबेडकर के तर्क में समस्या यह है कि उन्होंने बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को पहले ही अस्वीकार कर दिया है,

जिनमें ध्यान भी शामिल है। बौद्ध धर्म के अनुसार, पहले व्यक्ति को गहन आंतरिक परिवर्तन से गुजरना चाहिए और उसके बाद ही समाज की सहायता के लिए बाहरी भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन अंबेडकर बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्यों और इसकी अनुशंसित ध्यान पद्धतियों को स्वीकार नहीं करते हैं।

संक्षेप में, अंबेडकर बुद्ध और मार्क्स के बीच फंसे हुए हैं, और किसी भी विचारधारा का पूरी तरह से पालन करने में असमर्थ हैं। एक ओर, बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म से उनके गंभीर मतभेद हैं। ये मतभेद बौद्ध धर्म के मूलभूत तत्वमीमांसा (जैसे पुनर्जन्म और कर्म) और इसकी ध्यान प्रणालियों दोनों से संबंधित हैं। दूसरी ओर, वे मार्क्सवाद के विरुद्ध तर्क देने के लिए बौद्ध धर्म और इसके आध्यात्मिक रूपांतरण का उपयोग करना चाहते हैं।

इसलिए, वे मार्क्सवाद के विरुद्ध अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए बौद्ध धर्म की अपनी पुनर्परिभाषित परिभाषा का सहारा लेते हैं। समस्या यह है कि वे बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों या प्रथाओं से सहमत हुए बिना ही उसका समाधान प्रस्तुत करते हैं।

यह एक गंभीर त्रुटि है: वे किस आधार पर दावा करते हैं कि ऐसी विधि कारगर होगी? क्या यह सच नहीं है कि अंबेडकर के बौद्ध धर्म के प्राथमिक शिक्षक पुस्तकें थीं, न कि परंपरा के अनुसार कोई जीवित गुरु? वे पारंपरिक अर्थों में बौद्ध नहीं थे, जिन्हें किसी गुरु ने ध्यान और अन्य साधनाओं में दीक्षित किया हो। क्या अंबेडकर ने बुद्ध द्वारा निर्धारित ध्यान के मार्ग को दरकिनार करते हुए आध्यात्मिक परिवर्तन प्राप्त किया है? यदि अंबेडकर के नवनिर्मित बौद्ध धर्म को गंभीरता से लिया जाए, न कि केवल अटकलों के रूप में, तो उन्हें इसे वास्तविक अनुभव पर आधारित करना होगा। 'बुद्ध और उनका धम्म' में उन्होंने सही ही कहा है कि बौद्ध

धर्म जो कुछ भी सिखाता है, वह व्यवहार में सिद्ध अनुभवों पर आधारित है। बुद्ध ने केवल वही सिखाया जो उन्होंने अपने व्यक्तिगत आंतरिक अनुभव से जाना था। यही मानदंड अंबेडकर की नई प्रणाली पर भी लागू होना चाहिए। वे केवल वही सिखा सकते हैं जो उन्होंने स्वयं प्राप्त किया है। लेकिन अंबेडकर ने कभी भी यह दावा नहीं किया कि उन्होंने अपनी नई पद्धतियों का उपयोग आध्यात्मिक परिवर्तन प्राप्त करने के लिए किया है।

उनकी पद्धति में बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक साधनों को नकार दिया गया, जबकि सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को व्यवहार में कभी प्रदर्शित नहीं किया गया, यहाँ तक कि एक छोटे प्रायोगिक समूह में भी नहीं। फिर भी, वे बुद्ध की पद्धति को अस्वीकार करते हुए अपनी पद्धति को अपना लेते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे अधिक समय तक जीवित नहीं रहे, क्योंकि इससे उन्हें बुद्ध की तरह अपने विचारों को अनुभवजन्य परिणामों के आधार पर स्थापित करने का अवसर मिलता।

भौतिक स्तर पर तमाम उपलब्धियों के बावजूद, मानवजाति आज भी अहंकार से प्रेरित है, और मुख्यतः स्वार्थ, लोभ, वासना, शारीरिक इच्छाओं आदि से ग्रस्त जनजातीय अहंकार से। दूसरे शब्दों में, ठीक उन्हीं मानसिक विकारों से जिनसे बुद्ध ने अपने अनुयायियों को छुटकारा पाने के लिए कहा था। बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत यह है कि हमारी समस्याओं का समाधान मन के इस स्तर पर संभव नहीं है। आवश्यकता है अहंकार से परे आध्यात्मिक विकास की।

विडंबना यह है कि अंबेडकर की प्रशंसा करने वाले अनेक लोग बुद्ध की पद्धति का अभ्यास करने और अपनी चेतना को विकसित करने के लिए वास्तव में प्रतिबद्ध नहीं हैं, जबकि इससे वे समाज की बेहतर सेवा करने में सक्षम हो सकते हैं। इसके बजाय, वे इस गंभीर आंतरिक साधना को

दरकिनार करते हुए राजनीतिक, सामाजिक या अन्य प्रकार की सत्ता की लालसा रखते हैं, और यह सब बौद्ध होने के आड़ में करते हैं। नीचे दिया गया चित्र अंबेडकर के दर्शन का सार प्रस्तुत करता है।

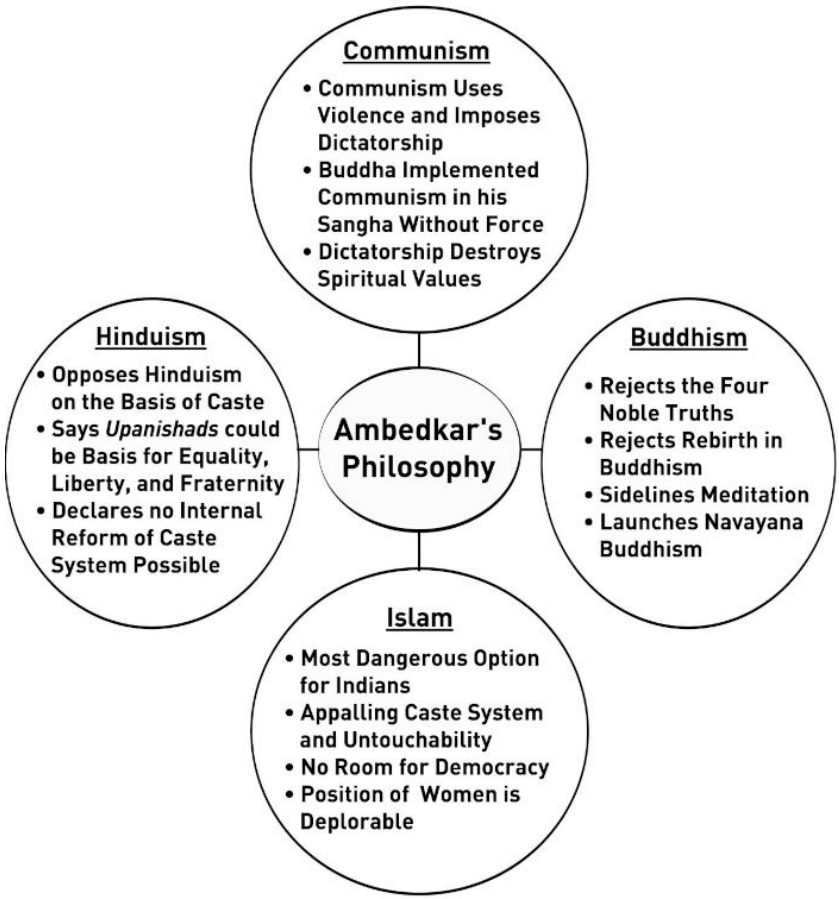

जाति/जाति के फायदे और नुकसान[255]

इस अंतिम भाग में, हम जाति व्यवस्था का समग्र मूल्यांकन प्रस्तुत करते हैं। ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन ने कहा था कि लगभग 1800 तक

भारत विश्व का सबसे समृद्ध देश था, उस समय तक ब्रिटिशों ने भारत की आर्थिक शक्ति को आक्रामक रूप से नष्ट करना शुरू कर दिया था। इतनी लंबी अवधि की अपार समृद्धि इस धारणा से मेल नहीं खाती कि जाति व्यवस्था ने प्राचीन काल से ही भारत को आर्थिक रूप से पिछड़ा बना दिया था। आइए इस व्यवस्था के प्रमुख लाभों और हानियों का संतुलित विश्लेषण करें।

तानाशाही के विरुद्ध नियंत्रण और संतुलन

जाति व्यवस्था एक विकेंद्रीकृत स्वशासन प्रणाली थी जिसमें कई अर्ध-स्वायत्त सामाजिक समूह अपने-अपने सदस्यों को सेवाएं प्रदान करते थे। यही कारण है कि भारत में भाषाओं, रीति-रिवाजों, आध्यात्मिक प्रथाओं, लोक कलाओं और संस्कृति की विविधता विश्व के किसी भी अन्य देश से कहीं अधिक है।

जब तक जातियाँ अपनी स्थानीय परंपराओं के आधार पर कार्य करती रहीं, तब तक यह संरचना केंद्रीकृत नियंत्रण की आवश्यकता के बिना एक विशाल और विविधतापूर्ण समाज को बनाए रखने में सक्षम थी। इसने किसी भी वर्ण या सामाजिक पूंजी में सत्ता के केंद्रीकरण को रोका। अंग्रेजों ने इसे ध्वस्त कर दिया क्योंकि उनके हित अलग थे और उन्हें ऊपर से नीचे तक औपनिवेशिक नियंत्रण की आवश्यकता थी।

ब्राह्मणों के मामले में, धर्मशास्त्र अनुष्ठानिक स्थिति और भौतिक शक्ति के बीच स्पष्ट विभाजन करते हैं। ब्राह्मणों को अनुष्ठानिक अधिकार का प्रयोग करना होता है, और इसे उनका अनिवार्य दायित्व माना जाता है। समाज के प्रति उनका कर्तव्य ज्ञान की खोज करना और वैदिक परंपरा का संरक्षण करना है। यह कोई 'विशेषाधिकार' नहीं है क्योंकि ब्राह्मणों को न तो राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने की अनुमति है और न ही धन संचय करने

की। ब्राह्मण को दान या मुआवज़ा मांगने की अनुमति नहीं है और वे केवल अपनी आजीविका के लिए आवश्यक भौतिक वस्तुएँ ही प्राप्त कर सकते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार, अपनी जीविका के लिए आवश्यक धन से अधिक संचय करना पतन का कारण बनता है। 256

क्षत्रियों के मामले में, उनका कर्तव्य (विशेषकर राजाओं का) कानून-व्यवस्था बनाए रखना, धर्म की रक्षा करना और जनता की सुरक्षा करना है। उन्हें कोई निरंकुश या तानाशाही शक्ति नहीं दी गई है। उनका कर्तव्य अपने मंत्रियों से परामर्श करना, जनता की बात सुनना और उनकी शिकायतों का समाधान करना है। मंत्रिमंडल में शूद्रों सहित समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल थे।

धर्मशास्त्रों में यह प्रावधान भी है कि यदि कोई राजा धर्म का पालन करने या जनता और उनकी संपत्ति की रक्षा करने में विफल रहता है, तो उसके मंत्री जनता के समर्थन से उसे पद से हटा सकते हैं। यद्यपि व्यवहार में यह कहना संभव नहीं है कि शासन व्यवस्था पूर्ण थी, फिर भी यह महत्वपूर्ण है कि उस समय जीवंत विचार-विमर्श होता था और राजनीतिक चिंतन एक काल से दूसरे काल तक विकसित होता रहा।

ब्रिटिश शासन के दौरान, कई विकेंद्रीकृत कार्यों को ब्रिटिशों द्वारा प्रशिक्षित और नियुक्त सिविल सेवकों के अधीन समेकित कर दिया गया। इन ब्रिटिश नियुक्तियों के दो मुख्य उद्देश्य थे: एक ओर, वे अत्यधिक कर वसूलते थे, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के सबसे धनी देशों में से एक से सबसे गरीब देशों में से एक बन गई। दूसरी ओर, औपनिवेशिक सिविल व्यवस्था पुलिस, अदालतों और सेना के माध्यम से नियंत्रण बनाए रखने का काम करती थी - ये सभी एक जटिल शासन प्रणाली के तहत ब्रिटिशों के प्रति जवाबदेह थे।

ब्रिटिशों ने यह निर्धारित करने वाले कानून बनाकर अर्थव्यवस्था को

नियंत्रित किया कि कौन किस विशेष आर्थिक गतिविधि में शामिल हो सकता है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को भी नियंत्रित किया; संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं पर आधारित देशी शिक्षा को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा लागू कर दी गई, जिसकी शिक्षण विधियाँ और पठन सामग्री लंदन में बैठे लोगों द्वारा निर्धारित की जाती थीं। उन्होंने हिंदू मंदिरों और उनके दैनिक प्रशासन पर औपनिवेशिक नियंत्रण जैसे विभिन्न कानूनों के माध्यम से धार्मिक जीवन को भी नियंत्रित किया (जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है)। सरकारी अधिकारियों ने भौतिक पर्यावरण को नियंत्रित किया, जिसमें ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति की आपूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की परियोजनाएँ शामिल थीं।

श्रम विभाजन और विशेषज्ञता का हस्तांतरण

हमने देखा है कि प्रारंभिक सामाजिक गतिशीलता और वर्ण एवं जाति व्यवस्था की लचीली प्रणाली कैसे लुप्त हो गई। उस समय आज की तरह सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, और बच्चे बचपन से ही अपने माता-पिता से कौशल और ज्ञान प्राप्त करते थे। धीरे-धीरे भाई-भतीजावाद हावी हो गया और योग्यता आधारित वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। व्यवसाय परिवारों से जुड़ गए और गतिशीलता कम हो गई।

शिलालेखीय अभिलेखों से पता चलता है कि कई पेशेवर जातियाँ धनी और सुव्यवस्थित थीं, और गण के नाम से जाने जाने वाले मजबूत पेशेवर संघ उभरे। शूद्र सामाजिक रूप से उन्नति कर राजा भी बन सकते थे; सिवाय इसके कि उन्हें ब्राह्मणों के लिए आरक्षित अनुष्ठान करने की अनुमति नहीं थी।

जबकि वैश्यों और शूद्रों के पास पेशेवर संघ या संघ थे, ब्राह्मणों के पास चर्च जैसी कोई संस्था नहीं थी जिसमें आर्कबिशप, बिशप आदि का पदानुक्रम होता है। यह इस दावे का खंडन करता है कि ब्राह्मणों ने 'जाति व्यवस्था' लागू की थी। वास्तव में, उनके पास किसी भी चीज़ को लागू करने के लिए कोई संगठनात्मक तंत्र नहीं था। सत्ता के ये सभी साधन गैर-ब्राह्मणों के हाथों में होने के कारण, उनके लिए नियंत्रण स्थापित करना असंभव था।
ब्राह्मणों की शक्ति का मूल कारण यह था कि वे किसी अनुष्ठान को करने से इनकार कर सकते थे और अपना ज्ञान दूसरों को देने से मना कर सकते थे। यह शक्ति का एक नकारात्मक रूप था, न कि दूसरों पर शक्ति का प्रदर्शन करने का कोई सकारात्मक तरीका।

जातियों की परस्पर निर्भरता: जजमानी प्रणाली
भारतीय गांवों में जातियां हमेशा से आर्थिक रूप से एक-दूसरे पर निर्भर रही हैं और कोई भी जाति गांव के बाकी पारिस्थितिकी तंत्र के बिना आत्मनिर्भर नहीं थी। इसका कारण यह था कि किसी भी जाति का गांव के सभी संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं था। अधिकांश ग्रामीण अपनी जाति के पारंपरिक व्यावसायिक विशेषज्ञता का अनुसरण करते थे। इस विशेषज्ञता के कारण सेवाओं का स्वस्थ आदान-प्रदान होता था। जातियों के बीच संबंध संविदात्मक, व्यक्तिगत या अस्थायी नहीं थे, बल्कि दीर्घकालिक आपसी विश्वास पर आधारित थे।
यह जजमानी प्रणाली है, जो पारंपरिक व्यावसायिक दायित्वों पर आधारित है और आज भी ग्रामीण भारत में कुछ हद तक प्रचलित है। यह अंतर-जाति पारस्परिकता की प्रणाली थी। प्रत्येक जाति ग्राम जीवन में एक विशिष्ट भूमिका निभाती है। इस भूमिका में आर्थिक, सामाजिक और

नैतिक कार्य शामिल हैं, और इसमें सामाजिक सहयोग के साथ-साथ आर्थिक आदान-प्रदान भी शामिल है। नीचे दिया गया उदाहरण दर्शाता है कि जजमानी प्रणाली कैसे कार्य करती है:

बच्चे के जन्म के उत्सव में, ब्राह्मण नामकरण संस्कार संपन्न कराते हैं, सुनार नवजात शिशु के लिए सोने के आभूषण प्रदान करते हैं, धोबी गंदे कपड़े धोते हैं, नाई संदेशवाहक होते हैं, बढ़ई बच्चे को समारोह के लिए रखने हेतु लकड़ी का पट्टा प्रदान करते हैं, लोहार लोहे की चूड़ी प्रदान करते हैं, कुम्हार पकी हुई सब्जियां और पीने का पानी रखने के लिए कुल्हड़ प्रदान करते हैं, पासी भोजन करने के लिए पत्तल प्रदान करते हैं, और भंगी उत्सव के बाद स्थान की सफाई करते हैं। सभी सहायकों को भोजन, धन और वस्त्रों का उपहार प्राप्त होता है, जो आंशिक रूप से रीति-रिवाज, आंशिक रूप से जजमान के प्रभाव और आंशिक रूप से प्राप्तकर्ता की विनती पर निर्भर करता है।

जजमानी व्यवस्था में भूमिकाओं और मानदंडों का एक ऐसा जाल समाहित है जो सांस्कृतिक मूल्यों द्वारा व्यवस्थित रूप से एकीकृत, वैध और समर्थित है। यह व्यवस्था जातियों के श्रम विभाजन और आर्थिक अंतर-निर्भरता को बनाए रखती है। अधिकांश क्षेत्रों में पारंपरिक भुगतान फसल कटाई के दौरान किया जाता है; प्रत्येक भूमिधारक किसान नए उत्पादित अनाज को विभिन्न जातियों में वितरित करता है। अतिरिक्त भुगतान घर के लिए भूमि, पशुओं के चरने के लिए क्षेत्र, लकड़ी और गोबर का ईंधन, औजारों के लिए ऋण आदि के रूप में भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त, भूमिधारक किसान समारोहों के अवसर पर कपड़े और उपहार देता है और आपात स्थिति में ऋण भी दे सकता है।

उदाहरण के लिए, ग्राम अधिकारी या सामुदायिक सेवक (जैसे चौकीदार) पूरे गाँव के साथ जजमानी संबंध बनाए रखते हैं। इस प्रकार, चौकीदार के

परिवार को गाँव के प्रत्येक भूस्वामी किसान के परिवार से फसल कटाई के समय अंशदान प्राप्त होता है। ग्राम सेवकों को गाँव की भूमि का कर-मुक्त उपयोग करने का अधिकार भी हो सकता है। ऐसे परिवारों को गाँव के किसी विशेष भाग में रहने वाले सभी लोगों की सेवा करने का अधिकार होता है।

विकेंद्रीकृत लॉबिंग

जातियों ने राजा के हस्तक्षेप के बिना अपने आंतरिक मामलों के निपटारे के लिए अपनी पंचायतें (जाति-विशिष्ट शासन प्रणाली) विकसित कीं। यह कई विवादों को आंतरिक रूप से निपटाने का एक कुशल और किफायती तरीका था। इससे स्थानीय स्थिरता भी आई क्योंकि राजा के स्तर पर आक्रमणों और उथल-पुथल के बावजूद, ग्राम स्तर पर स्थानीय जीवन सुचारू रूप से चलता रहा। यह एक विकेन्द्रीकृत कल्याणकारी व्यवस्था थी और कुछ मायनों में लोकतंत्र के समान थी। यही कारण है कि हिंदू धर्म जमीनी स्तर पर लंबे समय तक कायम रहा है।

धीरे-धीरे जातियाँ अधिक आत्मनिर्भर और सुदृढ़ होती गईं। पंचायतों ने जाति की एकता और शक्ति बनाए रखने के लिए अंतर्विवाह को लागू किया। वे किसी गंभीर अपराध के लिए किसी को निर्वासन में भेज सकते थे, जिसे घोर अपमान माना जाता था।

आधुनिक युग में, कई जातियाँ मिलकर बड़े जाति समूह बन गई हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी राजनीतिक लॉबी है जो मुख्यधारा के समाज या केंद्र सरकार के साथ बातचीत करती है। ये जाति समूह मुख्य रूप से राजनीतिक वोट बैंक हैं और इनके पारंपरिक कार्यों का अधिकांश हिस्सा समाप्त हो चुका है।

पारिस्थितिक भूमिका

जाति समूहों ने अपने पेशेवर दायरे तय करने के लिए आपसी समझ बनाई थी। केवल मछुआरा जाति ही मछली पकड़ने जाती थी, केवल किसान जाति ही कृषि करती थी, और केवल चमार जाति को ही मृत पशु की खाल का अधिकार था। मछुआरों में भी कई जातियाँ थीं, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट प्रकार की मछली पकड़ने में माहिर थी। समय के साथ, जाति पंचायतों ने अत्यधिक मछली पकड़ने से रोकने के लिए नियम बनाए, उदाहरण के लिए, जिससे मछलियों के भंडार को नष्ट होने से बचाया जा सके। कुछ जातियों पर पूरे गाँव के हित के लिए पवित्र उपवनों के संरक्षण का दायित्व भी था।

इस प्रकार, जाति व्यवस्था ने प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा को कम किया और अत्यधिक दोहन को रोका। किसी विशेष जाति की आंतरिक विशेषज्ञता ने विशिष्ट कौशलों में दक्षता के कुशल अंतर-पीढ़ीगत प्रवाह को सुनिश्चित किया। किसी विशेष पेशे के लिए आवश्यक संसाधन मुक्त बाजार प्रणाली में खुली प्रतिस्पर्धा की तुलना में बेहतर संरक्षित थे। जातियों के बीच व्यावसायिक क्षेत्रों की सीमाएँ प्रतिद्वंद्विता को सीमित करने का एक साधन थीं।

सकारात्मक पक्ष यह था कि समाजों और प्रकृति के बीच एक सामंजस्यपूर्ण और स्थिर संतुलन बना हुआ था। नकारात्मक पक्ष यह था कि प्रतिस्पर्धा के कारण यह संतुलन गतिरोध और नवाचार की कमी में तब्दील हो गया।

आर्थिक सुरक्षा

फसल कटाई पूरी होते ही, गाँव के कारीगरों, नाइयों, धोबों, कृषि श्रमिकों आदि द्वारा दी गई सेवाओं के लिए वार्षिक भुगतान, चाहे वह वस्तु के रूप

में हो या नकद, करने की एक प्रणाली विकसित हुई। भुगतान की यह प्रणाली उत्पादन की मात्रा पर आधारित नहीं थी, बल्कि इस सिद्धांत पर आधारित थी कि जमींदारों को स्थानीय ग्राम श्रमिकों का ध्यान रखना चाहिए और इसमें विशेष परिस्थितियों और कठिनाइयों के लिए किए गए खर्च भी शामिल थे। यह एक संरक्षक-आश्रित संबंध में परिवर्तित हो गया, जिसमें जमींदारों का अन्य श्रमिक वर्ग के परिवारों पर प्रभुत्व स्थापित हो गया। स्वाभाविक रूप से, किसी भी विषम परिस्थिति की तरह, यहाँ भी हर प्रकार के दुर्व्यवहार और अत्याचार होते थे। सद्भाव टूटकर संघर्षों में बदल जाता था। इस प्रकार के तनाव किसी वेदों से उत्पन्न 'बुरे ब्राह्मण षड्यंत्र' या ऐसी किसी बात के कारण नहीं थे। यह स्थानीय स्तर पर परस्पर विरोधी हितों के बीच का वर्ग संघर्ष मात्र था।
यद्यपि आर्थिक प्रणाली स्थानीय संसाधनों और मांगों के उपयोग को अनुकूलित कर सकती थी, लेकिन बड़े पैमाने पर उत्पादन और व्यापार के सामने यह उप-इष्टतम थी।

जातियाँ और अंतर्मुखी स्वभाव: समस्या
जाति-आधारित सामाजिक व्यवस्था के कई लाभ थे। समुदाय एक-दूसरे के साथ अत्यधिक हस्तक्षेप किए बिना स्वायत्त रूप से अपने मामलों का प्रबंधन करने पर ध्यान केंद्रित करते थे। आर्थिक क्षेत्र और सीमाओं का स्पष्ट सीमांकन था। प्रत्येक जाति के अपने नेता, रीति-रिवाज, देवी-देवता, अनुष्ठान और त्यौहार, कानून और विवादों के निपटारे की व्यवस्था थी। बाहरी लोगों के प्रति उनका रवैया था, 'मैं अपने काम से काम रखूँ और तुम अपने काम से काम रखो'। यह भारत की अपार विविधता का एक प्रमुख कारण था, क्योंकि हजारों विशिष्ट संस्कृतियाँ अलग-अलग और काफी हद तक पृथक समूहों में विकसित हुईं। इसने सामंजस्य को भी

बढ़ावा दिया, क्योंकि जातियाँ एक-दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति नहीं रखती थीं।

साथ ही, अपनी जाति की सीमाओं से परे व्यापक मामलों में यह अरुचि बाहरी लोगों के प्रति उदासीनता में भी परिवर्तित हो गई। अंबेडकर ने इस बिंदु की भी आलोचना की: 'उदासीनता जाति व्यवस्था का परिणाम है, जिसने अच्छे उद्देश्य के लिए भी संगठन और सहयोग को असंभव बना दिया है।' चूंकि अन्यत्र जो कुछ भी हो रहा था, उससे व्यक्ति के स्वार्थी हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, इसलिए बाहरी घटनाओं पर नजर रखने का कोई खास कारण नहीं था।

दुर्भाग्यवश, भारत की अलगाववादी नीति के कारण बाहरी खतरों को समझने में वह आसानी से पिछड़ सकता था। यद्यपि आक्रमणकारियों की कई लहरें भारत के अन्य भागों में प्रवेश कर तबाही मचा चुकी थीं, फिर भी उस समय के धनी और शक्तिशाली राज्यों ने आक्रमणकारियों के क्षेत्रों में विद्वानों को भेजकर उनका अध्ययन कराने का कोई प्रयास नहीं किया, अर्थात् परंपरा के अनुसार पूर्व-पक्ष यानी विरोधियों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करने का प्रयास नहीं किया। इसलिए, भारत और उसके लोगों को बाहरी लोगों ने बेहतर समझा, न कि इसके विपरीत।

विदेशी शत्रु से लड़ने के लिए भारतीय शासकों के एकजुट होने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। लेकिन ये उदाहरण अधिकतर तब सामने आते थे जब शत्रु पहले से ही आक्रमण के द्वार पर आ चुका होता था। वे शत्रुओं को रोकने और यहाँ तक कि उन पर विजय प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से एकजुट नहीं होते थे। भारतीयों में विजय प्राप्त करने वाले शासकों जैसी विस्तारवादी मानसिकता का अभाव था, वे अपने स्थानीय मामलों में ही संतुष्ट रहते थे। इसलिए, भारतीयों ने बड़े पैमाने पर टीम निर्माण कौशल विकसित नहीं किया, जैसा कि उदाहरण के लिए रोमनों ने अपने विदेशी

अभियानों और साम्राज्यवादी शासन के दौरान किया था।
कुछ लोग कहेंगे कि भारतीय परंपराएँ स्थानीय राजाओं और समुदायों को बड़े उद्देश्यों के लिए एकजुट होने के लिए अनुकूल नहीं बनातीं, लेकिन हम इससे असहमत हैं। महाभारत में कृष्ण उस दूरदर्शी व्यक्ति का उदाहरण हैं जो धर्म के लिए लड़ने के लिए अनेक भिन्न-भिन्न समूहों को एक साथ लाते हैं। यदि ऊपर वर्णित जातिगत विभाजन वांछनीय होता, तो कृष्ण विभिन्न नेताओं को एकजुट करने का प्रयास नहीं करते। इसलिए, यह बहाना कि भारतीयों का विखंडित होना उच्च आध्यात्मिकता का प्रतीक है, केवल एक बहाना है। जब व्यक्तिगत स्वार्थ दांव पर होते हैं, तो भारतीय समुदाय एकजुट होते हैं, तो उन परिस्थितियों में सामूहिक रूप से कार्य क्यों न करें जो स्वार्थ से प्रेरित नहीं हैं। अन्यथा, भारतीयों को बचाने के लिए मदर टेरेसा जैसी किसी महान हस्ती की आवश्यकता होगी क्योंकि उनके साथी भारतीय आवश्यकता के समय सामाजिक जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं।
यह अंतर्मुखी एकाग्रता वेदांत की शिक्षाओं के अनुरूप है। दुर्भाग्यवश, इसने जीवन के आनंद को अधिकतम करने के बजाय जीवन से अपेक्षाओं को कम करने की ओर भी अग्रसर किया है। भारतीय परंपराएं चाहती हैं कि हम भौतिक सुख-सुविधाओं का आनंद लें, बशर्ते यह धार्मिक तरीके से किया जाए और धार्मिक नियमों का उल्लंघन न हो।
निष्कर्षत:, हमारा मानना है कि भारतीय मानसिकता पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव जातिगत विखंडन और अंतर्मुखता का अंतर्मन रहा है। यह सामाजिक व्यवस्थाओं को समय और नवीनतम तकनीकों के अनुरूप अद्यतन करने का एक और कारण है।

जाति व्यवस्था का पतन

सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल के कारण इस व्यवस्था की मूल संरचना में व्यवधान उत्पन्न हुआ और वह कमजोर पड़ गई। समय के साथ, वर्ण से जाति व्यवस्था बनी, जो बाद में जाति में परिवर्तित हो गई। जाति व्यवस्था अब लगभग समाप्त हो चुकी है, लेकिन इसका भूत आज भी भारत को त्रस्त करता है।

आधुनिक लोकतंत्र और सामाजिक गतिशीलता का परिणाम एक नई तरह की व्यवस्था है जो मुख्य रूप से वोट बैंक और संसाधन आवंटन के लिए पैरवी पर आधारित है। सार्वजनिक शिक्षा और रोजगार गतिशीलता ने युवा पीढ़ी की अपने माता-पिता के पदचिन्हों पर चलने की रुचि को कम कर दिया है। प्रौद्योगिकी और आर्थिक रुझानों ने पुराने मॉडलों को अप्रचलित कर दिया है।

व्यवहार में परंपरागत वर्ण व्यवस्था का बहुत कम अंश ही शेष रह गया है। जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और दलित लोग शायद ही कभी परंपरा द्वारा निर्धारित भूमिकाओं तक सीमित रह पाते हैं। जन्म से ही भेदभाव न करने वाला हर व्यक्ति अपनी इच्छानुसार और बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम किसी भी पेशे में स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकता है।

कई पुराने पेशे लुप्त हो गए हैं, और कुछ सबसे आशाजनक पेशे वे हैं जो पहले अस्तित्व में ही नहीं थे। चमड़े के काम जैसे कुछ पहले 'गंदे' माने जाने वाले पेशे अब अरबों डॉलर के वैश्विक उद्योग बन गए हैं, जिन्हें अति-धनी उद्योगपति चलाते हैं। तकनीक के कारण पुराने सामाजिक बंधन और कलंक कम हो गए हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में किसी आलीशान बार में कोई संभ्रांत ग्राहक पेय का ऑर्डर देता है, तो उसे बारटेंडर की जाति/वर्ण से कोई लेना-देना नहीं होता।

दुर्भाग्यवश, पहचान से संबंधित पुरानी शब्दावली आज भी प्रचलन में है,

जबकि संदर्भ पूरी तरह से भिन्न हैं। इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। लोग सोचते हैं कि आज का ब्राह्मण प्राचीन ब्राह्मण के समान है और इसलिए उसकी सभी कमियों का दोष वेदों पर है।

हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति, उसका अस्तित्व और उसका विघटन हिंदू धर्म से स्वतंत्र रहा है। यह हमेशा से ही एक विशुद्ध सामाजिक घटना रही है जो मुख्य रूप से हिंदू समाज में घटित हुई। मनुस्मृति सहित धर्मशास्त्र उस समय और स्थान की सामाजिक वास्तविकता का वर्णन करते थे, न कि कोई नियम बनाते थे। मनुस्मृति (IV.176) स्पष्ट रूप से कहती है कि यदि कोई नियम दुःख और आक्रोश का कारण बनता है तो उसे अस्वीकार कर देना चाहिए।

जाति व्यवस्था का पतन हिंदू धर्म के अस्तित्व के लिए कोई खतरा नहीं है। हिंदू धर्म एक बरगद के वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें, तने और शाखाएँ अनेक प्रकार की होती हैं, और कोई एक बिंदु ऐसा नहीं है जहाँ से यह पूरी तरह से समाप्त हो जाए। इसलिए, जो लोग हिंदू धर्म का पालन नहीं करते, वे भी पूर्णतः हिंदू होने में सक्षम हैं।

भाग II. हार्वर्ड विश्व गुरु और भारतीय अरबपति

7. हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ तीस वर्षों का अनुभव

भाग 1 में, हमने चर्चा की कि कैसे आलोचनात्मक नस्ल सिद्धांत (क्रिटिकल रेस थ्योरी) की उत्पत्ति अमेरिका में हुई, जिसमें मार्क्सवाद और उत्तरआधुनिकतावाद के यूरोपीय सिद्धांतों को अश्वेतों और अन्य

पीड़ित समुदायों पर होने वाले सामाजिक उत्पीड़न पर लागू किया गया। आलोचनात्मक नस्ल सिद्धांत का लक्ष्य वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को सहारा देने वाली मूलभूत संरचनाओं को ध्वस्त करना है।

हमने यह भी समझाया कि जाति को नस्ल से जोड़कर भारतीय समाज पर क्रिटिकल रेस थ्योरी कैसे लागू की जा रही है। अमेरिका के चार प्रमुख नेताओं के कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिनमें से एक अश्वेत महिला थीं और अन्य तीन अमेरिका में रहने वाले भारतीय थे।

इसाबेल विल्करसन एक अश्वेत लेखिका हैं जिनके कार्यों ने इस विचार को फैलाया है कि जाति ही नस्लवाद की मूलभूत संरचना है।

थेनमोझी साउंडराजन अमेरिका में रहने वाले भारतीयों द्वारा जातिगत पूर्वाग्रहों का सर्वेक्षण करने, इस साक्ष्य का उपयोग करके मुकदमे दायर करने, जाति को नस्लवाद के समकक्ष घोषित करने के लिए कानूनी और नीतिगत परिवर्तनों के लिए पैरवी करने और अमेरिकी कॉरपोरेट जगत में जाति व्यवस्था पर प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण संगठन की स्थापना के लिए जिम्मेदार हैं।

हार्वर्ड की प्रोफेसर अजंता सुब्रमणियन ने एक ऐसी किताब लिखी है जिसने सिलिकॉन वैली में रहने वाले भारतीयों को झकझोर दिया है। इस किताब में उन्होंने आईआईटी को संस्थागत जातिगत उत्पीड़न का एक रूप बताया है। हमें इस किताब से पहले किसी ऐसे व्यक्ति की जानकारी नहीं है जिसने उनके तर्क का विस्तार से विश्लेषण किया हो और व्यापक जवाब दिया हो।

हमने जिस चौथे व्यक्ति को चुना है, वह हैं सूरज येंगडे, जो प्रतिष्ठित हार्वर्ड कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में वरिष्ठ फेलो हैं। वे हिंदू-विरोधी भावना का खुलकर और बिना किसी समझौते के समर्थन करने वाले प्रतीक बन गए हैं।

हमने अध्याय 6 को जाति के इतिहास और प्रकृति तथा हिंदू धर्म से इसके संबंध पर एक प्रतिवाद प्रस्तुत करने के लिए भी समर्पित किया है।
भाग 2 में, हम इस बात का गहराई से विश्लेषण करेंगे कि भारतीय समाज पर यह विमर्श कैसे विकसित हो रहा है, भारतीय विद्वानों को कैसे प्रशिक्षित किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं का उत्पादन कैसे हो रहा है, और बदले में इसे भारत में कैसे निर्यात किया जा रहा है।
हार्वर्ड विश्वविद्यालय इस कार्य का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ इस कार्य को संचालित करने वाली कई शाखाएँ हैं, जो विश्वविद्यालय के विभिन्न स्कूलों और केंद्रों में फैली हुई हैं। यह उस आश्चर्यजनक खोज का एक हिस्सा है जिसे हम प्रस्तुत करेंगे।
दूसरा, और भी चौंकाने वाला पहलू यह है कि हार्वर्ड में इस काम को वित्त पोषित करने और बढ़ावा देने में भारतीय अरबपतियों द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका है।
लेकिन इस गहन अध्ययन की पृष्ठभूमि तैयार करने से पहले, हम हार्वर्ड के साथ अपने तीस वर्षों के संबंधों के बारे में विस्तार से बताएंगे। इन अरबपतियों के आने से बहुत पहले ही हमने हार्वर्ड में कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और अतिथि प्रोफेसरों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। हमने हार्वर्ड में प्रकाशित हो रहे शोध कार्यों का अध्ययन किया है, समीक्षाएँ लिखी हैं, इसके संकाय सदस्यों के साथ वाद-विवाद किया है और भारत तथा हिंदू धर्म से संबंधित इसकी गतिविधियों पर नज़र रखी है। यह अध्याय उपयोगी पृष्ठभूमि जानकारी प्रदान करेगा और विषय की पृष्ठभूमि तैयार करेगा।
सन् 1994 में लेखकों में से एक, राजीव मल्होत्रा द्वारा इन्फिनिटी फाउंडेशन की स्थापना के तुरंत बाद, उन्होंने भारत के चित्रण के संबंध में अमेरिकी उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ व्यापक संपर्क स्थापित किया।

भारत के अध्ययन में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के महत्व को देखते हुए, इस संपर्क में हार्वर्ड विश्वविद्यालय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। हमारी आशा रचनात्मक सहयोग की थी। उस समय, अमेरिका में कोई अन्य संगठन भारत की सभ्यता से संबंधित विशिष्ट अकादमिक कार्यों को वित्तपोषित या प्रायोजित नहीं कर रहा था। हमारा खुले दिल से स्वागत किया गया और हमें अग्रणी के रूप में सराहा गया। यह अध्याय एक ऐसे उतार-चढ़ाव भरे रिश्ते का वर्णन करता है जो कई चरणों से गुजरा।
लगभग वर्ष 2000 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। यह घटना हार्वर्ड के हिंदू धर्म के अध्ययन के अग्रणी प्रोफेसरों में से एक जॉन कारमैन की सेवानिवृत्ति पार्टी थी। उनकी विशेषज्ञता बारहवीं शताब्दी के हिंदू दार्शनिक और धर्मशास्त्री रामानुजाचार्य के कार्यों में थी, और पश्चिमी शिक्षाविदों द्वारा उनके लेखन को इस विषय पर अंतिम सत्य माना जाता था। कारमैन ने वसुधा नारायणन सहित कई महत्वपूर्ण विद्वानों को प्रशिक्षित किया था, जो बाद में अमेरिकन एकेडमी ऑफ रिलीजन की अध्यक्ष बनीं, जो एक अत्यंत प्रतिष्ठित पद है। एक मिलनसार और स्पष्टवादी व्यक्ति, कारमैन की अंतर्दृष्टि ने इन्फिनिटी फाउंडेशन के शुरुआती वर्षों में हम पर गहरा प्रभाव डाला।
राजीव मल्होत्रा पार्टी में मौजूद थे, जिसके बाद कारमन वाशिंगटन डी.सी. के लिए रवाना होने वाले थे। मल्होत्रा का प्रिंसटन स्थित घर रास्ते में ही पड़ता था, इसलिए दोनों ने साथ यात्रा करने का फैसला किया। इससे उन्हें कुछ घंटे आराम से बिताने का मौका मिला और दोनों ने कई मुद्दों पर चर्चा की। अकादमिक पूर्वाग्रहों और मल्होत्रा द्वारा वर्णित 'जाति, गाय, करी' से जुड़े रूढ़िवादी विचारों के बारे में हमारी चिंताओं को कारमन ने ध्यान से सुना। उन्होंने इन्फिनिटी फाउंडेशन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ परियोजनाओं का सुझाव भी दिया।

कारमैन ने कहा कि वह भारत लौटकर दक्षिण में अपने परिवार द्वारा स्थापित चर्च में रहने की योजना बना रहे हैं, जिसका उद्देश्य धर्म प्रचार कार्य करना है। यह अप्रत्याशित नहीं था क्योंकि हिंदू धर्म के कई हार्वर्ड विद्वान दोहरा रुख अपनाते हैं: अपने अकादमिक कार्य में वस्तुनिष्ठ और तटस्थ होने का दावा करते हैं, लेकिन निजी तौर पर आक्रामक एजेंडा पालते हैं जो उनकी इस तटस्थता के विपरीत है।

सबसे प्रभावशाली बात तो उनकी आखिरी बात थी, जब ट्रेन प्रिंसटन के पास पहुँच रही थी। कारमैन ने कुछ इस तरह कहा: अमेरिका में भारतीय समुदाय की सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक उनके बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली हैं और अमेरिकी अभिजात वर्ग में शामिल होंगे।

फिर उन्होंने कहा: 'उनकी विरासत के बारे में उनके विचारों को हम अकादमी में ही पाल-पोस रहे हैं। उनके माता-पिता अपने करियर बनाने में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें इन मामलों में मार्गदर्शन देने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है, और वे हमें ही शिक्षक और गुरु मानते हैं।'

इस बयान का मल्होत्रा पर गहरा असर हुआ। इन्फिनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित हार्वर्ड परियोजनाओं की निगरानी के दौरान वे कई वर्षों से हार्वर्ड के शैक्षणिक पूर्वाग्रहों के अपने अनुभव पर विचार कर रहे थे। अब चीजें स्पष्ट होने लगीं। उन्हें समझ आने लगा कि कारमन कितने सही थे। अमेरिकी कॉलेजों में भारतीय छात्रों का पालन-पोषण अमेरिकी उच्च शिक्षा प्रणाली द्वारा किया जा रहा है। हाई स्कूल के बाद जब बच्चे अपने माता-पिता के घर से बाहर निकलते हैं, अपनी व्यक्तिगत पहचान और व्यक्तित्व विकसित करते हैं, तो यह परिवर्तन अमेरिकी कॉलेजों में स्नातक की पढ़ाई के दौरान होता है। इसके बाद, मल्होत्रा ने हार्वर्ड के अधिकारियों के समक्ष शैक्षणिक पूर्वाग्रहों के मुद्दे को और अधिक मुखरता से उठाना शुरू कर दिया।

जिन पहले क्षेत्रों में हमने हार्वर्ड का ध्यान आकर्षित किया, उनमें से एक था भारतीय सभ्यता का पश्चिम में आत्मसात होना, जिसमें इस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभ्यता के आत्मसात होने की अवधारणा पर हमारे कई पूर्व लेखों में चर्चा की गई है, और अब हम हार्वर्ड से संबंधित ठोस उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। हार्वर्ड में व्यवहार में हमने जो दूसरा पैटर्न पाया, वह था भारतीय परंपराओं का अपमान। ये दोनों बौद्धिक आंदोलन एक दूसरे को पोषित करते रहे:

हार्वर्ड द्वारा भारतीय परंपराओं को जितना अधिक अपमानित किया गया, उतना ही अधिक विद्वानों को बिना श्रेय दिए उनसे सामग्री लेने का प्रोत्साहन मिला। आख़िरकार, एक पिछड़ी परंपरा/संस्कृति महान योगदानों के स्रोत के रूप में सम्मान के योग्य नहीं थी। जब हमने उन अमेरिकियों का सामना किया जो इस परंपरा को मौलिक रूप से प्रस्तुत करके इसे आत्मसात कर रहे थे, तो उनका अक्सर यह बचाव होता था कि वे उस परंपरा से खुद को दूर रखना चाहते हैं जो अपनी महिलाओं को जलाती है, अपनी निचली जातियों और मुसलमानों को मार डालती है। इसके विपरीत, एक बार अपने खजाने खो जाने पर, यह परंपरा आदिम प्रथाओं, विचित्रताओं, खतरनाक गुरुओं और देवी-देवताओं से भरी एक खोखली खोल की तरह प्रतीत होती है। ईसाई विजेताओं ने अमेरिका के मूल निवासियों को ठीक इसी तरह चित्रित किया था; इस वर्णन का उपयोग उनकी भूमि और धन पर कब्जा करने को उचित ठहराने के लिए किया गया था। हालांकि, अन्य मूल संस्कृतियों के प्रति क्षतिपूर्ति और क्षमा याचना के प्रयास प्रतीत होते हैं, लेकिन भारत के प्रति पश्चिमी शिक्षा जगत का रवैया स्पष्ट रूप से हिंदू-विरोधी बना हुआ है।

दूसरे शब्दों में, किसी परंपरा का दानव-विज्ञान उसके मूल स्वरूप को आत्मसात करने, उसे नीचा दिखाने या मिटाने का औचित्य सिद्ध करने का

एक तरीका है। हम हार्वर्ड में घटी इन दोनों प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। विभिन्न विभागों के साथ अपने जुड़ाव के माध्यम से, हमने इन्हीं विषयों पर शोध और चर्चाओं को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा।
क्रिटिकल रेस थ्योरी के ढांचे के संदर्भ में, आत्मसात करने का तात्पर्य यह है कि परंपराओं को किसी भी उपयोगिता से रहित माना जाता है। इसकी समस्याओं पर जोर दिया जाता है और इसलिए यह तर्क देना आसान हो जाता है कि इसकी संरचनाओं को दमनकारी मानकर समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन यदि सकारात्मक योगदानों को स्वीकार किया जाता है, तो वे पारंपरिक संरचनाओं के लिए एक मजबूत बचाव के रूप में कार्य करते हैं।
आखिर, हिंदू धर्म को खत्म करने के वैश्विक आंदोलन (जो अब क्रिटिकल रेस थ्योरी की बदौलत चल रहा है) को कैसे सही ठहराया जा सकता है, जबकि यही परंपरा योग, ध्यान प्रणालियों, पर्यावरण नारीवाद और आधुनिक उदारवाद में समाहित कई अन्य पहलुओं की जननी है? इसकी मूल संरचनाओं को पूरी तरह से नष्ट करने का एकमात्र तरीका इसके इतिहास से सभी सकारात्मक योगदानों को हटाना है। और यही प्रक्रिया है, जैसा कि हम आगे देखेंगे।

भारतीय ध्यान प्रणालियों को आत्मसात करने में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की भूमिका

1970 से 1980 का दशक अमेरिकी समाज के लिए परिवर्तन का दशक था, जब भारतीय योग, ध्यान और चिकित्सा विज्ञान प्रणालियों की व्यापक रूप से खोज हुई। ये प्रणालियाँ पहले ही अमेरिका पहुँच चुकी थीं, लेकिन इस दशक में जनता द्वारा इन्हें व्यापक रूप से अपनाया गया और इन प्राचीन प्रणालियों की वैधता की गंभीर वैज्ञानिक जाँच-पड़ताल की

गई।

महर्षि महेश योगी की ट्रान्सेंडेंटल मेडिटेशन™ (टीएम) पद्धति का अभ्यास करने वाले मल्होत्रा को पता चला कि हार्वर्ड के एक प्रभावशाली चिकित्सा शोधकर्ता, हर्ब (हर्बर्ट) बेन्सन ने बिना किसी स्वीकृति के इस तकनीक को अपना लिया था और इसे अपनी खोज बता दिया था। इसी बात ने मल्होत्रा को अमेरिका में भारतीय आध्यात्मिक और अन्य परंपराओं के आत्मसात्करण की प्रक्रिया का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पाया कि यह आत्मसात्करण बड़े पैमाने पर हो रहा था और हार्वर्ड इस गतिविधि का एक प्रमुख केंद्र था।

बोस्टन के तीन व्यक्तियों ने वैज्ञानिक अन्वेषकों के रूप में निर्णायक भूमिका निभाई: हर्ब बेन्सन, डैनियल गोलेमैन और जॉन काबाट-ज़िन। पहले दो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में थे, जबकि काबाट-ज़िन पास के मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय में थे और हार्वर्ड से उनके घनिष्ठ संबंध थे। तीनों ने भारतीय गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया था और तीनों ने मिलकर काम किया।

बेन्सन के मामले में, उन्होंने महर्षि योगी की ट्रान्सेंडेंटल मेडिटेशन तकनीक को आत्मसात किया और इसे रिलैक्सेशन रिस्पांस नाम दिया।

गोलेमैन के करियर को तब उड़ान मिली जब उन्होंने मनोविज्ञान के भारतीय मॉडलों का उपयोग करते हुए अपनी सुपरहिट पुस्तक, इमोशनल इंटेलिजेंस लिखी।

कबैट-ज़िन ने विपश्यना, जिसे ध्यान के सबसे प्राचीन रूपों में से एक माना जाता है, भारतीय शिक्षक एस.एन. गोयनका से पूर्ण आभार और कृतज्ञता के साथ सीखी और इसे अपनी विशिष्ट माइंडफुलनेस मेडिटेशन में बदल दिया, जिसे उन्होंने माइंडफुलनेस-बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन (एमबीएसआर) के रूप में स्थापित किया।

इन तीनों व्यक्तियों की शब्दावली शीघ्र ही अमेरिकी भाषा का अभिन्न अंग बन गई और उनके सिद्धांतों को उनके द्वारा किए गए अग्रणी वैज्ञानिक आविष्कारों के रूप में देखा जाने लगा। समय के साथ, इनमें से प्रत्येक सिद्धांत एक वैश्विक आंदोलन में तब्दील हो गया, जिसे कंपनियों और आम जनता को सिखाया जाने लगा।

माल्होत्रा भारतीय ज्ञान के अमेरिकी वैज्ञानिक समुदाय और मुख्यधारा समाज में समाहित होने के इतिहास पर एक बहु-खंडीय श्रृंखला पर काम कर रहे हैं। इस अध्याय में, हम बेन्सन, गोलेमैन और काबाट-ज़िन द्वारा निभाई गई भूमिका का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे।

माल्होत्रा ने अपने यू-टर्न सिद्धांत में जिस पैटर्न का उल्लेख किया है, उसी के अनुसार, तीनों ने हिंदू और बौद्ध स्रोतों और आध्यात्मिक शिक्षकों के साथ अपने संबंधों में निम्नलिखित चरणों का सामना किया:

आरंभ में, उन्होंने सीधे भारतीय स्रोतों से सीखा और उनसे अत्यंत प्रभावित हुए। गोलेमैन और काबाट-ज़िन के मामले में, इस ज्ञान को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया गया। हालाँकि, बेन्सन के मामले में, वे अधिक चतुर थे क्योंकि उन्होंने इस तथ्य को छुपाया कि वे टीएम ध्यानियों पर शोध कर रहे थे और अपने शोध निष्कर्षों को पूरी तरह से मौलिक बताकर प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित किया।

तीनों ने भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का गहन अध्ययन किया, जिसमें सैद्धांतिक ज्ञान के साथ-साथ ध्यानियों पर प्रयोगशाला प्रयोग करके उनके चिकित्सीय प्रभावों का अध्ययन करना भी शामिल था। उन्होंने कई शोध पत्र प्रकाशित किए और अमेरिकी सरकार एवं शैक्षणिक संस्थानों से उन्हें पर्याप्त आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। इस नए क्षेत्र की खोज से अमेरिकी वैज्ञानिक समुदाय में काफी उत्साह था। भारत को महत्व का केंद्र माना जाता था और उसे ज्ञान के विशाल भंडार के रूप में देखा जाता था।

उन्होंने शुरू में पश्चिमी वैज्ञानिकों के सामने खुद को उन भारतीय प्रणालियों के अनुवादक और समर्थक के रूप में प्रस्तुत किया, जिन्हें उन्होंने 'खोजा' था और जिन्हें वे अपने साथियों के ध्यान में लाना चाहते थे। उन्होंने भारतीय प्रणालियों को सार्थक और विश्वसनीय तरीके से प्रस्तुत करने के लिए पश्चिमी मनोवैज्ञानिक और चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया। शुरुआत में, उन्होंने इन प्रणालियों को 'भारतीय' कहना जारी रखा, क्योंकि इससे वे कहीं अधिक विश्वसनीय लगती थीं।
धीरे-धीरे, उनके प्रकाशित कार्यों में भारतीय प्रणालियों और शिक्षकों का उल्लेख कम होता गया; पहले इसे उनकी मुख्य 'खोज' के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन बाद में यह उल्लेख मात्र रह गया। जिन्हें पहले 'वैदिक' या 'हिंदू' परंपराएँ कहा जाता था, उन्हें अधिकतर 'बौद्ध', फिर 'एशियाई' और अंततः 'पूर्वी परंपराएँ' कहा जाने लगा।
साथ ही, अन्य विश्व धर्मों (मुख्यतः यहूदी धर्म, ईसाई रहस्यवाद और सूफीवाद) का उल्लेख उनके ग्रंथों में समान प्रथाओं वाले धर्मों के रूप में किया गया, लेकिन वे उतने व्यापक रूप से ज्ञात, प्रचलित या विस्तृत रूप से वर्णित नहीं थे। दूसरे शब्दों में, वैदिक प्रणालियों की अद्वितीय और मूल्यवान बौद्धिक संपदा को व्यवस्थित रूप से कमज़ोर कर दिया गया और उसे 'सामान्य आध्यात्मिक ज्ञान' में परिवर्तित कर दिया गया।
अंततः, 1980 के दशक तक, इस ज्ञान को अमेरिकियों द्वारा विकसित ज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया, जिन्होंने विभिन्न ट्रेडमार्क, मालिकाना शब्दावली विकसित की और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए बड़े संस्थानों की स्थापना की।
1990 के दशक के मध्य में, जब मल्होत्रा ने इस विषय पर शोध करना शुरू किया, तो उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से कई बार संपर्क किया ताकि वे शोध परियोजनाओं, सम्मेलनों, व्याख्यानों और पाठ्यक्रमों के माध्यम

से इन घटनाओं के भारतीय संबंधों का पता लगाने के लिए उन्हें मना सकें। इन्फिनिटी फाउंडेशन इस इतिहास को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रायोजक, वित्तपोषित और हर संभव भूमिका निभाना चाहता था। लेकिन इनमें से कुछ भी साकार नहीं हुआ। हार्वर्ड के एक विभाग ने एक के बाद एक अपनी अरुचि के लिए कई तरह के कारण बताए। कुछ ने यह जताने का नाटक किया कि उन्हें किसी भी भारतीय प्रभाव की जानकारी नहीं है। कुछ ने कहा कि यह अतीत की बात है और हमें भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए, जबकि कुछ का मानना था कि भारतीय परंपराएं इतनी महान हैं कि उन्हें इस तरह की छोटी-मोटी मान्यता की आवश्यकता नहीं है।
सबसे परेशान करने वाला तर्क यह था कि यह आध्यात्मिक-वैज्ञानिक ज्ञान पश्चिमी संस्थानों में अधिक सुरक्षित और उपयोगी है क्योंकि भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों के कारण इसे ऐसे ज्ञान का संरक्षक मानना उचित नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो, भारत पिछड़ा हुआ है और इन ज्ञान के खजानों का मालिक होने के योग्य नहीं है, जबकि पश्चिम, मानवता का उद्धारकर्ता होने के नाते, इस ज्ञान का उपयोग करने में अधिक जिम्मेदार होगा।
उस काल का इतिहास लिखने वाले कम से कम एक पश्चिमी लेखक ने नस्लवादी पहलुओं के बारे में खुलकर बात की थी:
हम इस स्थिति में नस्ल के संभावित प्रभाव को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते... महर्षि एक सांवली त्वचा वाले भारतीय व्यक्ति थे जिनकी बड़ी दाढ़ी और लंबे, कुछ हद तक बिखरे हुए बाल कंधों से आगे तक लटके रहते थे, और वे आम तौर पर योग वस्त्रों में हिंदू प्रार्थना माला धारण किए दिखाई देते थे। ... टीएम के प्रति प्रतिक्रिया अक्सर महर्षि पर लागू 'पूर्वी भिक्षुओं' की रूढ़ियों से प्रभावित होती थी, जो इस आंदोलन का प्रतिष्ठित चेहरा थे। जॉन काबाट-ज़िन, एमबीएसआर का चेहरा, एक साफ दाढ़ी

वाले श्वेत अमेरिकी डॉक्टर हैं जिनके छोटे बाल और बिना फ्रेम का चश्मा है, और वे व्यावसायिक पोशाक में अपने उपदेश देते हैं।
भारत से पश्चिम तक ज्ञान के ऐसे दर्जनों हस्तांतरणों का वर्णन भारतीय परंपराओं के आत्मसात पर आधारित हमारी पुस्तक श्रृंखला में किया गया है। हार्वर्ड पर आधारित इस खंड में, हम ऊपर वर्णित तीनों व्यक्तियों का संक्षिप्त परिचय देंगे।

हर्ब बेन्सन
1960 के दशक में, जब महर्षि की टीएम तकनीक अमेरिका के नव-युग आंदोलन में तेज़ी से फैल गई, तो उन्होंने अपने युवा शिष्य, जो एक मेडिकल छात्र थे, रॉबर्ट कीथ वालेस से टीएम के प्रभावों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने और परिणामों को प्रकाशित करने के लिए कहा। इस शोध पर पहला शोधपत्र वालेस ने अकेले लेखक के रूप में 1970 में साइंस पत्रिका में प्रकाशित किया। उन्होंने इस शोध पर पीएचडी की और 1971 में अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी में इसके परिणाम प्रकाशित किए।
तब से, वालेस का महर्षि के आंदोलन के साथ घनिष्ठ और अटूट संबंध रहा है। वे महर्षि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष बने और उन्होंने अमेरिका में पहले महर्षि आयुर्वेद क्लीनिक की स्थापना की। 1975 तक, महर्षि के अमेरिकी संगठन के 370 केंद्र थे और हर महीने 30,000 लोग ट्रान्सेंडेंटल मेडिटेशन सीखने के लिए पंजीकरण करा रहे थे।
इस बीच, हर्ब बेन्सन हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक प्रतिष्ठित हृदय रोग विशेषज्ञ थे, लेकिन ध्यान के क्षेत्र में उनका कोई पूर्व शोध प्रकाशन नहीं था। वास्तव में, उनके प्रारंभिक प्रकाशनों को तंबाकू अनुसंधान परिषद से

वित्त पोषण प्राप्त हुआ था, जो 1953 में तंबाकू उद्योग द्वारा सिगरेट पीने से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं पर वैज्ञानिक अध्ययनों को वित्त पोषित करने के लिए स्थापित एक पहल थी। यह पहल कानूनी कारणों से 1998 में बंद कर दी गई थी।

जब बेन्सन को मानव शरीर क्रिया विज्ञान पर ट्रान्सेंडेंटल मेडिटेशन के प्रभावों के बारे में पता चला, तो उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि यह एक बहुत बड़ा अवसर है। उन्होंने शुरुआती दिनों में महर्षि योगी से व्यक्तिगत रूप से कई बार मुलाकात की ताकि उनकी शिक्षाओं को गहराई से समझ सकें। बेन्सन की पत्नी ने भी ट्रान्सेंडेंटल मेडिटेशन सीखा और अभ्यासी बन गईं।

बेन्सन ने ध्यान अनुसंधान में सहयोग करने के लिए वालेस से संपर्क किया। हार्वर्ड के प्रोफेसर के रूप में बेन्सन के प्रभाव को देखते हुए वालेस के लिए यह प्रस्ताव आकर्षक था। चूंकि वालेस अपना पहला शोध पत्र प्रकाशित कर चुके थे और पीएचडी पूरी कर चुके थे, इसलिए उन्होंने हार्वर्ड में अपना शोध जारी रखने के लिए बेन्सन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दिलचस्प बात यह है कि बेन्सन ने वालेस को अपनी पीएचडी थीसिस अलग से प्रकाशित करने से रोकने की कोशिश की और सुझाव दिया कि वे इसे संयुक्त रूप से प्रकाशित करें। लेकिन महर्षि ने वालेस को आगे बढ़ने के लिए कहा। शुरू से ही, बेन्सन किसी न किसी तरह से इस शोध पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे।

वॉलेस और बेन्सन का एक संयुक्त शोध पत्र 1971 में साइंटिफिक अमेरिकन (SciAm) में प्रकाशित हुआ था। यह पूरी तरह से वॉलेस का काम था और बेन्सन का योगदान केवल इतना था कि उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके पत्रिका को उन निष्कर्षों को प्रकाशित करने के लिए राजी किया, जिन्हें उस समय चिकित्सा जगत में विवादास्पद माना जाता

था। वास्तव में, वॉलेस के पीएचडी शोध प्रबंध से कई आंकड़े और डेटा इस सह-लिखित शोध पत्र में शामिल हैं। 1971 में, एमआईटी में ध्यान पर एक वैज्ञानिक सम्मेलन में, महर्षि, बेन्सन और वॉलेस ने भाषण दिए। अब तक, वॉलेस को यह उम्मीद थी कि एक ईमानदार सहयोग होगा जिसमें महर्षि ज्ञान लाएंगे और बेन्सन हार्वर्ड के प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे।

लेकिन एक अहम मोड़ आया। हार्वर्ड में बेन्सन के वरिष्ठ अधिकारियों को चिंता होने लगी कि महर्षि से उनके संबंध हार्वर्ड को बदनामी दिला सकते हैं, क्योंकि ध्यान का विषय हिप्पी संस्कृति के हिस्से के रूप में चर्चा में था और इसलिए इसे नशा करने वालों से जोड़ा जा रहा था। लेखक और मनोवैज्ञानिक टिमोथी लेरी और अन्य लोगों को नशा करने के आरोप में हार्वर्ड से निष्कासित कर दिया गया था और संस्थान अपनी प्रतिष्ठा बचाना चाहता था। मीडिया अक्सर नशा और ध्यान को एक ही श्रेणी में रखता था। इसके अलावा, 'पूर्वी रहस्यवाद' से जुड़ी किसी भी चीज़ को अकादमिक मान्यता प्राप्त नहीं थी।

बेन्सन का सपना नोबेल पुरस्कार जीतना था और वह जानते थे कि टीएम पर उनके इन निष्कर्षों के दूरगामी परिणाम होंगे। इसलिए, उनके लिए महर्षि से दूरी बनाए रखना महत्वपूर्ण हो गया।

ध्यान के वैज्ञानिक प्रभावों को प्रमाणित करने के बाद, बेन्सन ने आंदोलन से नाता तोड़ लिया। उन्होंने वालेस के बिना ही अपना शोध पत्र प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने पूरी सामग्री को अपनी मौलिक रचना के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने महर्षि के अनुयायियों द्वारा किए गए पूर्व शोध की नकल करने के लिए अपने ही विषयों का उपयोग करके उसी अध्ययन को दोहराया था, लेकिन इसे मौलिक होने का दिखावा किया। परिणामस्वरूप, वालेस बेन्सन से अलग

हो गए।
बेन्सन ने 1975 में अपनी ट्रेडमार्क तकनीक को 'द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स' नामक एक बेहद लोकप्रिय पुस्तक में प्रस्तुत किया। मौलिकता का दावा इस एक विचार पर आधारित था कि उन्होंने महर्षि के मंत्र को 'एक' शब्द से बदल दिया था। उन्होंने दावा किया कि इससे यह तकनीक सामान्य हो गई और किसी विशेष धर्म या संस्कृति तक सीमित नहीं रही।
ट्रान्सेंडेंटल मेडिटेशन और रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स के बीच समानताएं इतनी स्पष्ट और प्रत्यक्ष हैं कि इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बेन्सन कहते हैं कि सभी ध्यान प्रणालियों में चार सामान्य विशेषताएं होती हैं जो उन्हें चिकित्सकीय रूप से प्रभावी बनाती हैं: शांत वातावरण; एक मानसिक उपकरण; निष्क्रिय मनोवृत्ति; और मांसपेशियों में तनाव कम होना/आरामदायक स्थिति। हालांकि, उन्होंने किसी भी वैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से यह साबित नहीं किया कि ये चारों विशेषताएं वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक या पर्याप्त हैं। उन्होंने बस इन आवश्यकताओं को दोहराया क्योंकि महर्षि ने ट्रान्सेंडेंटल मेडिटेशन को इसी तरह समझाया था।
यह ध्यान देने योग्य है कि बेन्सन विश्राम प्रतिक्रिया को एक 'गैर-पंथिक' तकनीक के रूप में वर्णित करते हैं और यह दावा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते कि यह विशेषता टीएम और योग से भिन्न है। प्रतिष्ठित पत्रिका लैंसेट में वे लिखते हैं: 'विश्राम प्रतिक्रिया को एक गैर-पंथिक, सरल मनोवैज्ञानिक तकनीक या योगिक, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष तकनीकों द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है।' यह उस समय अमेरिका में प्रचलित 'पूर्वी पंथों' के भय का लाभ उठाने की एक चतुर रणनीति थी। इस प्रकार का भय फैलाना उन्हें अपने दावों को वैज्ञानिक और मंत्र जैसे सभी पंथिक तत्वों से रहित साबित करने में सहायक रहा।

इस तरह की युक्तियों ने उनके प्रकाशन करियर को आगे बढ़ाने में मदद की, चाहे वह गंभीर अकादमिक चिकित्सा पत्रिकाओं में हो या लोकप्रिय पुस्तकों में, जिनमें उन्होंने चिकित्सा शब्दों में मन-शरीर संबंध के भारतीय सिद्धांतों की व्याख्या की।

बेन्सन ने अपनी विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग करते हुए ध्यान की इसी तकनीक पर और भी पुस्तकें लिखीं, जिनकी चालीस मिलियन प्रतियां बिकीं। उनका लेखन धीरे-धीरे ईसाई धर्म की ओर अग्रसर होता गया। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से संबद्ध होकर उन्होंने माइंड-बॉडी मेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो व्यवहार चिकित्सा के क्षेत्र में एक लाभकारी अनुसंधान और प्रशिक्षण पहल थी। भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से इसे अलग करके, उनका माइंड-बॉडी इंस्टीट्यूट हाई स्कूलों में अपनी ट्रेडमार्क तकनीक को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने में कामयाब रहा। संस्थान ने स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए 'बेन्सन विधि' के सभी पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए। इसने अपने मॉडल को अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं को फ्रेंचाइज़ किया और आम जनता के लिए शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किए।

उनके चिकित्सा अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य प्राचीन भारतीय प्रणालियों के प्रभावों को प्रमाणित करना और उनकी व्याख्या करना था, जिन्हें उन्होंने अपनी विशेष पद्धति 'रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स' के रूप में वैज्ञानिक और तकनीकी भाषा में प्रस्तुत किया। उदाहरण के लिए, टीएम तकनीक द्वारा प्रदान की जाने वाली गहरी विश्राम अवस्था को उन्होंने 'पैरासिम्पेथेटिक सक्रियण की हाइपोमेटाबोलिक अवस्था' नाम दिया। अपने प्रभाव, वित्तीय स्रोतों और जॉन टेम्पलटन फाउंडेशन (जिन्हें उन्होंने बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल किया) जैसे ईसाई संस्थानों के प्रायोजन के बल पर, वे महर्षि के विशिष्ट भारतीय विचारों को अपनी बेंसन पद्धति के रूप में पुनः स्थापित

करने में सफल रहे। वे भारतीय मन विज्ञान की उपलब्धियों को पश्चिमी ढाँचे और स्वामित्व में लाने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गए।
बेन्सन ने तिब्बती बौद्ध धर्म के विचारों को अपनी ध्यान प्रणाली में शामिल करने के इरादे से भारत की यात्रा की, ताकि वह टीएम से अलग दिखे। 1980 में, जब बेन्सन और वालेस भारत में मिले, तो बेन्सन ने यह जताने की कोशिश की कि उसने कोई गलती नहीं की है, बल्कि इसके विपरीत दावा किया कि उसने महर्षि के विचारों को लोकप्रिय बनाकर भारतीय आध्यात्मिकता में योगदान दिया है। बेन्सन द्वारा साहित्यिक चोरी के बारे में महर्षि से कई बार पूछा गया; उन्हें इसकी जानकारी थी, लेकिन वे चाहते थे कि वालेस और अन्य लोग इसे नज़रअंदाज़ कर दें और मामले को आधिकारिक तौर पर आगे न बढ़ाएं।
बेन्सन के तीस-पृष्ठ के जीवनी-डेटा में दर्जनों 'मौलिक' शोध प्रकाशनों, प्रतिष्ठित संबद्धताओं और उनकी विभिन्न प्रमुख उपलब्धियों को सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन यह तकनीकी शब्दावली को सावधानीपूर्वक इस तरह से संशोधित करता है कि उनका सारा काम 'पश्चिमी' विज्ञान के रूप में दिखाई दे।
अकादमिक जगत के साथ-साथ मुख्यधारा के अमेरिकी मीडिया ने भी ध्यान विज्ञान की खोज का पूरा श्रेय बेन्सन को दिया। महर्षि की ट्रान्सेंडेंटल मेडिटेशन में इसके योगदान का ज़िक्र शायद ही कभी किया गया। वास्तव में, बेन्सन को 'ध्यान को रहस्यमुक्त करने' का श्रेय दिया गया, क्योंकि उन्होंने उन मंत्रों को हटा दिया जो कई यहूदी-ईसाई अमेरिकियों को भयभीत करते थे। उन्होंने हार्वर्ड में इन तकनीकों को बेचकर खूब धन कमाया और एक शानदार करियर बनाया, लेकिन उन्होंने न तो इन प्रथाओं की भारतीय उत्पत्ति को स्वीकार किया और न ही चेतना की उच्च अवस्थाओं की व्याख्या करने वाले संस्कृत आधारित सिद्धांतों

और ज्ञानमीमांसाओं को।
यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि राजीव मल्होत्रा ने हार्वर्ड के अधिकारियों को अपने विद्वानों के दावों और जिन भारतीय स्रोतों से उन्होंने जानकारी ली थी, उनके बीच संबंधों पर चर्चा करने के लिए मनाने का भरसक प्रयास किया। हालांकि, हार्वर्ड ने इस मुद्दे को उठाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।

डैनियल गोलेमैन
डेनियल गोलेमैन अब एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित मनोवैज्ञानिक हैं, कई बेस्टसेलिंग पुस्तकों के लेखक हैं जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस: व्हाई इट कैन मैटर मोर दैन आईक्यू, और साइकोलॉजी टुडे के पूर्व मुख्य संपादक हैं।
लेकिन उनकी कहानी 1960 के दशक में बर्कले में स्नातक की पढ़ाई के दौरान शुरू होती है, जब उन्हें भारतीय ध्यान प्रणालियों में रुचि हुई। हार्वर्ड में अपने पीएचडी शोध और प्री-डॉक्टोरल फेलोशिप के लिए वे ध्यान का अध्ययन करने भारत गए। वहां उनकी मुलाकात रिचर्ड एल्पर्ट से हुई, जिन्हें मतिभ्रम पैदा करने वाली दवा एलएसडी के प्रयोगों के कारण हार्वर्ड से निकाल दिया गया था। एल्पर्ट भारत गए और गुरु नीम करोली बाबा के शिष्य बन गए और अपना नाम बदलकर राम दास रख लिया। राम दास, जिनका हाल ही में निधन हुआ, हार्वर्ड से अपने जुड़ाव के लिए जाने जाते थे और वे भक्ति आंदोलन को अमेरिका लाने वाले व्यक्ति थे, जो नए युग/हिप्पी युग के प्रतीक बन गए।
बाद में गोलेमैन पोस्ट-डॉक्टोरल अनुदान के तहत भारत लौट आए। उन्होंने भी नीम करोली बाबा के साथ काफी समय बिताया और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं का व्यापक अध्ययन किया, सिद्धांत और व्यवहार

दोनों ही दृष्टियों से। 1971 में हार्वर्ड में डॉक्टरेट छात्र के रूप में उनके पहले शोध पत्रों में से एक भारतीय ध्यान पर था, जिसमें उन्होंने भारतीय ग्रंथों में 'चेतना की पांचवीं अवस्था' के बारे में कही गई बातों का वर्णन किया है।

पीछे मुड़कर देखते हुए, गोलेमैन याद करते हैं कि जब वे इन विचारों को अमेरिका लेकर आए थे, तब योग 'बहुत ही अनोखा' था और ध्यान के बारे में 'लगभग कोई जानता ही नहीं था'। वे कहते हैं कि उन्होंने 'अस्तित्व के रूपांतरण' की भारतीय अवधारणा को खोजा, जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मुझे बहुत दिलचस्प लगी। इसलिए, मैंने वह फैलोशिप हासिल की और भारत के लिए रवाना हो गया। वे बताते हैं कि उन्होंने भारत से क्या सीखा:

बौद्ध धर्म के केंद्र में एक मनोवैज्ञानिक प्रणाली थी... जो पश्चिमी मनोविज्ञान में पूरी तरह से अज्ञात थी। मैंने इसके बारे में लिखना शुरू किया, और जिस तरह से यह मन के साथ काम करती थी, जिस तरह से यह मन को रूपांतरित करने के तरीकों की कल्पना करती थी... ध्यान इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। पश्चिमी मनोविज्ञान यह नहीं समझता था कि... ध्यान मन को रूपांतरित करता है, और अब हम जानते हैं, मस्तिष्क को भी। 1970 के दशक में किसी ने भी न्यूरोप्लास्टिसिटी शब्द नहीं सुना था... बार-बार के अनुभव मस्तिष्क की संरचना और कार्य को बदलते हैं, यह बौद्ध मनोविज्ञान में निहित था और पश्चिमी मनोविज्ञान में अज्ञात था।... आप मन को इस हद तक रूपांतरित कर सकते थे कि... आपकी आंतरिक भावनात्मक स्थिति बाहरी परिस्थितियों के वश में नहीं होती थी, बल्कि एक निरंतर, समभाव वाली, दयालुता से भरी अवस्था होती थी। यह अकल्पनीय था।... मैं कहूंगा कि 2010 के दशक के मनोवैज्ञानिक इस पर समग्र रूप से उतना ध्यान नहीं देते हैं।

वह बेन्सन (जो उस समय हार्वर्ड संकाय में सुस्थापित थे) के साथ महर्षि की ट्रान्सेंडेंटल मेडिटेशन का अभ्यास करने वाले ध्यानियों पर शोध करने के अपने अनुभव का वर्णन करते हैं। वह इस अभ्यास के साथ-साथ इसके लाभों के नैदानिक निष्कर्षों का भी विस्तार से वर्णन करते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक समुदाय में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। वह लिखते हैं कि पिछले तीन वर्षों में उन्होंने कई ध्यान तकनीकों का प्रयास किया था, और यह कि,

महर्षि महेश योगी द्वारा सिखाई गई ट्रान्सेंडेंटल मेडिटेशन (पारलौकिक ध्यान) वह पद्धति है जिसका मैंने सबसे लंबे समय तक अभ्यास किया है, जिसके सैद्धांतिक ज्ञान से मैं सबसे अच्छी तरह परिचित हूँ, और जिसके बारे में मैं यहाँ परिकल्पना कर रहा हूँ। ट्रान्सेंडेंटल मेडिटेशन (टीएम), अमेरिका में सिखाई जाने वाली अधिकांश योग प्रणालियों की तरह, अपनी जड़ें उस परंपरा से जोड़ती है जिसका पतंजलि का योग सूत्र उत्कृष्ट उदाहरण है।

गोलेमैन आगे कहते हैं: 'मेरी परिकल्पनाएँ टीएम के अनुभव से उत्पन्न हुई हैं, लेकिन इन्हें सामान्य रूप से ध्यान के संदर्भ में तैयार किया गया है, इस आशा के साथ कि इनका परीक्षण विभिन्न प्रणालियों पर किया जाएगा।' वे महर्षि के एक प्रसिद्ध और लंबे समय से अनुयायी रहे कीथ वालेस (जिनकी चर्चा ऊपर की गई है) द्वारा ध्यान के वैज्ञानिक अध्ययन में किए जा रहे अग्रणी शोध कार्य को भी स्वीकार करते हैं। वे निष्कर्ष निकालते हैं: 'मुझे यह कहना होगा कि यह लेख उस प्रक्रिया के वर्णन की मात्र शुरुआत है जिसके द्वारा ध्यान करने वाला व्यक्ति पाँचवीं अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और न ही यह उस अवस्था का पूर्ण वर्णन करता है...'

गोलेमैन ने जल्द ही अपने विश्लेषण का विस्तार बौद्ध ध्यान तक किया।

1972 में, उन्होंने वैदिक और बौद्ध दोनों स्रोतों का हवाला देते हुए और उनकी शिक्षाओं और ध्यान प्रणालियों की तुलना करते हुए दो प्रभावशाली शोध पत्र लिखे। उन्होंने भक्ति और हरे कृष्ण आंदोलनों पर सकारात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चर्चा की। उन्होंने स्वामी विवेकानंद और उनके अमेरिकी शिष्य क्रिस्टोफर इशरवुड का हवाला दिया और भक्ति की तुलना राज योग से की, जो मन को नियंत्रित करने की एक तकनीक है। भारतीय प्रणालियों के उनके सर्वेक्षण में श्री अरबिंदो का इंटीग्रल योग (कई तकनीकों का संयोजन), प्रसिद्ध दार्शनिक जे. कृष्णमूर्ति का ध्यान, पतंजलि का योग सूत्र और ऋषि रमण महर्षि की शिक्षाएं शामिल हैं। गोलेमैन ने वैदिक और बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान का व्यापक सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त किया और उन्हें बिना किसी लाग-लपेट या छिपाव के धार्मिक परंपराओं के रूप में समझाया। फिर उन्होंने सिद्ध योग के संस्थापक स्वामी मुक्तानंद पर चर्चा की, जो अमेरिका में पहले से ही बहुत लोकप्रिय थे, और कुंडलिनी योग, तंत्र और तिब्बती तंत्र के बीच तुलना की। उनके कार्यों में संस्कृत शब्दों की एक विस्तृत शब्दावली शामिल थी, जिसका उन्होंने भारतीय साहित्य की व्याख्या करने के लिए भरपूर उपयोग किया। ये लेख पश्चिम में ध्यान के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से किए गए सबसे गहन प्रारंभिक सर्वेक्षणों में से थे, जिनमें लगभग एक दर्जन विभिन्न भारतीय प्रणालियों का उल्लेख किया गया था। यद्यपि सूफी और ईसाई रहस्यवाद का भी उल्लेख किया गया था, लेकिन ये बहुत संक्षिप्त थे और अध्ययन का नब्बे प्रतिशत हिस्सा हिंदू और बौद्ध प्रणालियों पर केंद्रित था।[14] अपने प्रारंभिक प्रकाशनों में, गोलेमैन ने मुख्य रूप से भारतीय स्रोतों, जैसे महर्षि महेश योगी और श्री अरबिंदो, और भारतीय स्रोतों पर लगभग पूर्णतः प्रशिक्षित विद्वानों, जैसे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक चार्ल्स टार्ट, जिन्होंने भारतीय योग प्रणालियों का अध्ययन किया था, आदि का हवाला दिया।

1975 तक, गोलेमैन अपने भारतीय ज्ञान को बौद्ध अभिधर्म या ग्रंथों के ढांचे पर ढाल रहे थे, जिसमें उन्होंने पर्याप्त संस्कृत शब्दावली का उपयोग किया।

आत्मविश्वास और मान्यता प्राप्त करने के बाद, गोलेमैन ने प्रतिष्ठित मनोचिकित्सा वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशन शुरू किया। यह शोध लोकप्रिय हुआ और इसने मन विज्ञान के क्षेत्र को जन्म दिया। विडंबना यह है कि इस क्षेत्र से भारतीय स्रोतों के संदर्भ लगभग पूरी तरह से मिटा दिए गए हैं, जबकि अमेरिकी विचारकों और वैज्ञानिकों की एक पूरी पीढ़ी भारतीय स्रोतों से ही पोषित हुई है।

धीरे-धीरे, उन्होंने और उनके साक्षात्कारकर्ताओं ने वैदिक स्रोतों को छोड़ना शुरू कर दिया और बौद्ध स्रोतों का हवाला देना शुरू कर दिया। गोलेमैन ने अभिधर्म प्रणाली को चेतना की अवस्थाओं के सबसे व्यापक और विस्तृत पारंपरिक मनोविज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। 1976 तक, वे इस ज्ञान को अधिक धर्मनिरपेक्ष शब्दों में 'मानसिक स्वास्थ्य के लिए एशियाई दृष्टिकोण' के रूप में संदर्भित करने लगे और इसे प्रतिष्ठित मुख्यधारा के वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित करने लगे।

उनकी 1977 में प्रकाशित पुस्तक, 'द वैराइटीज़ ऑफ़ द मेडिटेटिव एक्सपीरियंस', 'द मेडिटेटिव माइंड' शीर्षक से पुनर्प्रकाशित होने पर उनकी पहली बेस्टसेलर बनी। इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय पद्धतियों से जो कुछ सीखा है, उसे पश्चिमी ढांचे में ढाला है, लेकिन इस स्तर पर भारतीय स्रोतों को छिपाया नहीं है। एक पश्चिमी जीवनीकार लिखते हैं: 'जैसा कि मनोविज्ञान में हाल ही में पीएचडी प्राप्त करने वाले व्यक्ति से अपेक्षित है, प्राचीन स्रोत सामग्री को लगातार मनोवैज्ञानिक शब्दों में प्रस्तुत किया गया है।' पुस्तक की प्रस्तावना राम दास ने लिखी है। पहला संस्करण नीम करोली बाबा और भगवान हनुमान को समर्पित था। पेंगुइन द्वारा इसका

नया संस्करण प्रकाशित किया गया, जो उनकी पहली न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर बनी।

1980 के दशक के मध्य तक, गोलेमैन ध्यान पर सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक बन गए थे, जो द न्यूयॉर्क टाइम्स में नियमित रूप से लेख लिखते थे और अमेरिकियों को मन विज्ञान की अपनी नई प्रणाली के बारे में शिक्षित करते थे। वास्तव में, यह प्रणाली भारतीय स्रोतों से प्राप्त ज्ञान का ही पुनर्कथन थी।

कभी-कभी उन्होंने अपने भारतीय स्रोतों को स्वीकार किया है, लेकिन मुख्य रूप से उन्होंने स्वयं को बौद्ध स्रोतों तक ही सीमित रखा है। उदाहरण के लिए, वे अभिधर्म तत्वमीमांसा को मनोविज्ञान के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानते हैं।

... मैंने एक वैकल्पिक मनोवैज्ञानिक प्रणाली की खोज की। ... अभिधर्म, जो मन के इस मॉडल के लिए संस्कृत शब्द है। फिर मैंने मनोविज्ञान पत्रिकाओं में इसके बारे में लिखना शुरू किया, हालांकि बहुत ही कम प्रसिद्ध मनोविज्ञान पत्रिकाओं में, क्योंकि केवल वही इसमें रुचि रखते थे। ... पश्चिमी मनोविज्ञान को यह जानकारी देना महत्वपूर्ण था क्योंकि ... इसने ... मानव होने की संभावनाओं के क्षितिज को विस्तृत किया। ... यदि मनोविज्ञान किसी चीज़ के बारे में है, तो वह मन और उसकी ऊपरी सीमाओं के बारे में है; हम किन सबसे बुरी जगहों पर जा सकते हैं, किन सबसे अच्छी जगहों पर जा सकते हैं? और इसने कुछ ऐसी बेहतरीन जगहों का वर्णन किया जिनके बारे में हमने अभी तक नहीं सुना था...

गोलेमैन दलाई लामा के करीबी रहे और अपनी पुस्तकों के लिए प्रस्तावना और प्रशंसा पत्र लिखने के लिए अक्सर उनकी मदद लेते थे। उनकी 1995 में प्रकाशित पुस्तक, 'इमोशनल इंटेलिजेंस', अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेस्टसेलर बनी और चालीस भाषाओं में अनुवादित हुई। यह एक प्रतिष्ठित

पुस्तक है जिसका उपयोग निगम प्रबंधन और नेतृत्व के पाठों के लिए करते हैं।
विडंबना यह है कि जब उन्हें भारत की शीर्ष बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा आमंत्रित किया जाता है, तो इस तथ्य की शायद ही कभी सराहना की जाती है कि वे भारतीय ज्ञान का पुनर्विक्रय कर रहे हैं, सिवाय इसके कि वे कभी भारत की यात्रा कर चुके हैं और वहाँ से कुछ प्रेरणाएँ प्राप्त कर सकते थे। गोलेमैन अब दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी नई और मौलिक वैज्ञानिक खोजों से भारतीय परंपरा को पीछे छोड़ दिया है।
गोलेमैन भारतीय प्रणालियों का वैज्ञानिक पद्धति से व्यवस्थित परीक्षण करने और उनकी विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मूल परंपरा का अस्तित्व ही नष्ट हो जाए। उदाहरण के लिए, जब प्राचीन ग्रीस से ज्ञान ग्रहण किया जाता है, तो उसे विधिवत स्वीकार किया जाता है, और यही मानक भारतीय ज्ञान के मामले में भी लागू होना चाहिए। इस प्रकार की स्वीकृति ज्ञान प्रणाली को उसके मूल स्वरूप में जीवित रखती है ताकि वह हमें और समृद्ध कर सके।

जॉन काबाट-ज़िन
हालांकि जॉन काबाट-ज़िन औपचारिक रूप से हार्वर्ड से जुड़े नहीं हैं, फिर भी उन्हें यहां शामिल किया गया है क्योंकि उन्होंने संस्थान में अन्य लोगों के साथ मिलकर काम किया है और वहां उनका प्रभाव स्पष्ट है।
1960 के दशक के उत्तरार्ध में, जब काबाट-ज़िन एमआईटी में आणविक जीव विज्ञान में पीएचडी कर रहे थे, तब उन्होंने ज़ेन ध्यान पर एक व्याख्यान में भाग लिया। उन्होंने प्रमुख बौद्ध शिक्षकों से और बोस्टन के इनसाइट मेडिटेशन सेंटर में ध्यान का अध्ययन शुरू किया, जहाँ वे बाद में

एक शिक्षक बन गए। 1979 तक, उनके पास तेरह वर्षों का प्रशिक्षण और अभ्यास था, और दो सप्ताह के ध्यान साधना सत्र के दौरान, उनका दावा है कि उन्हें एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई: जीवन में उनका 'कर्मिक दायित्व' बौद्ध धर्म से प्राप्त शिक्षाओं को अमेरिकियों को दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं और तनाव से निपटने में मदद करने के लिए लागू करना होगा। इस मिशन को पूरा करने के लिए, उन्होंने मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय के मेडिकल स्कूल (जिसे अब यूमास चान मेडिकल स्कूल के नाम से जाना जाता है) को माइंडफुलनेस-बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन क्लिनिक स्थापित करने की अनुमति देने के लिए राजी किया।
कबैट-ज़िन ने ध्यान को इस तरह से प्रस्तुत और विपणन किया कि उन्हें अपार सफलता मिली। उनका कहना है कि इस तकनीक को माइंडफुलनेस नाम देने का निर्णय सोच-समझकर लिया गया था, क्योंकि वे अपने उत्पाद को स्पष्ट रूप से 'बौद्ध' या विदेशी के रूप में पेश नहीं करना चाहते थे। 1970 के दशक में, उन्होंने महसूस किया कि औसत अमेरिकी ध्यान को हिप्पियों, न्यू एजर्स, आज़ाद ख्यालों वाले लोगों और अन्य प्रतिसंस्कृति से अलग-थलग पड़े लोगों से जुड़ा मानते थे। उन्होंने बहुत पहले ही अमेरिकियों के बीच इस सांस्कृतिक बाधा और पूर्वाग्रह को दूर करने के महत्व को समझ लिया था। उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र के माध्यम से मुख्यधारा के बाज़ार को लक्षित करने का निर्णय लिया।
उन्होंने माइंडफुलनेस-बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन (MBSR) नामक ब्रांड को औपचारिक रूप से ट्रेडमार्क कराया। उनका कहना है कि समाधि, ध्यान, विपश्यना या प्राणायाम जैसे शब्दों की तुलना में MBSR शब्द बहुत कॉर्पोरेट लगता है। और इसे ज्ञानोदय कहने के बजाय तनाव प्रबंधन कहना अधिक उपयुक्त था। उन्होंने प्राचीन भारतीय तकनीकों को 'बॉडी स्कैनिंग' और 'गाइडेड मेडिटेशन' जैसे नामों से नया रूप दिया। काबाट-ज़िन कहते

हैं: 'मैंने इसे संरचित करने और इसके बारे में बात करने के ऐसे तरीके खोजने में बहुत मेहनत की जिससे इसे बौद्ध धर्म, न्यू एज, पूर्वी रहस्यवाद या सरासर निरर्थक के रूप में देखे जाने का जोखिम यथासंभव कम हो सके।'

उन्होंने बुद्ध द्वारा स्वयं सिखाई गई प्राचीन विपश्यना पद्धति की व्यावसायिक फ्रेंचाइजी देकर लाखों कमाए हैं। हालांकि, काबट-ज़िन इस तकनीक को अपनी हालिया खोज के रूप में प्रचारित करते हैं। उन्होंने अपने काम को हिंदू और बौद्ध परंपराओं से अलग कर लिया है और इसे पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष विज्ञान के रूप में स्थापित किया है, जिसमें वे स्वयं को खोजकर्ता बताते हैं। इस क्षेत्र के अन्य विद्वानों से चर्चा करते समय, वे अपनी पद्धतियों की 'एशियाई' उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं, जिसे वे तीन घटकों का संयोजन बताते हैं: (1) विपश्यना, बौद्ध धर्म का एक थेरवाद रूप; (2) ज़ेन अभ्यास; और (3) हठ योग, एक प्रकार का योग जो अधिक शारीरिक है। हालांकि ये स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक उत्पत्ति वाली भारतीय प्रणालियाँ हैं, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग उनके दावों की नैदानिक प्रकृति को कमजोर करता है।

एक और शानदार कदम था यूमास मेडिकल स्कूल में चिकित्सा, स्वास्थ्य देखभाल और समाज में ध्यान केंद्रित करने के लिए केंद्र की स्थापना करना। इससे उन्हें चिकित्सा अनुसंधान क्षेत्र में सक्रिय रहने का अवसर मिला। इससे काबाट-ज़िन को उन अन्य पश्चिमी विद्वानों की तुलना में अपार विश्वसनीयता प्राप्त हुई जो स्वयं को भारतीय गुरुओं की तरह प्रस्तुत कर रहे थे। उन्होंने उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, दीर्घकालिक दर्द, चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम और सिरदर्द जैसी विभिन्न स्थितियों के उपचार में प्रभावकारिता साबित करने के लिए एक के बाद एक कई सफल नैदानिक परीक्षण किए।

अमेरिकी चिकित्सा जगत के अलावा, उन्हें विशेष कार्यक्रम विकसित करने के लिए अमेरिकी सेना से भी धनराशि मिलने लगी। अमेरिकी सेना ने युद्धक्षेत्र में लड़ाकों की 'परिचालनात्मक प्रभावशीलता' में सुधार के लिए एमबीएसआर का उपयोग किया है। उन्हें कुछ सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों से भी अनुसंधान के लिए अनुदान प्राप्त हुए। दलाई लामा के साथ दीर्घकालिक घनिष्ठ संबंध बनाए रखना भी एक और बुद्धिमत्तापूर्ण कदम है क्योंकि इससे उन्हें आध्यात्मिक हलकों में प्रामाणिकता का दावा करने में मदद मिलती है और उनके खुलेआम नकल करने के लिए होने वाली आलोचना से बचाव होता है। वे वर्जीनिया स्थित माइंड एंड लाइफ इंस्टीट्यूट के बोर्ड में हैं, जो दलाई लामा और प्रमुख पश्चिमी वैज्ञानिकों के बीच सार्वजनिक संवादों का आयोजन करने वाला संगठन है।
उनकी सबसे बड़ी सफलता 1993 में मिली जब उनके काम को पीबीएस टेलीविजन श्रृंखला, हीलिंग एंड द माइंड विद बिल मोयर्स में प्रमुखता से दिखाया गया। इससे वे अमेरिकी ध्यान आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक के रूप में घर-घर में ख्यातिप्राप्त हो गए।
जॉन काबाट-ज़िन की फ्रैंचाइज़ी ने बड़ी संख्या में चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवरों, कॉर्पोरेट अधिकारियों और अन्य लोगों को प्रशिक्षित किया है। इसने तीस देशों में नैदानिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सैकड़ों फ्रैंचाइज़ी स्थापित की हैं और लाखों रोगियों की मदद की है। बौद्ध ध्यान के लाभ सर्वविदित हैं, सिवाय इसके कि इसे बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं माना जाता। अब वे इतने प्रसिद्ध हो गए हैं कि बौद्ध भी उनकी आलोचना नहीं कर सकते। वे निडर होकर कहते हैं कि ध्यान में कुछ भी विशेष रूप से बौद्ध नहीं है, कि 'ध्यान पर बौद्धों का कोई अधिकार नहीं है', इत्यादि।
निजी बातचीत में, काबाट-ज़िन भारत के प्रति अपने ऋण का सम्मानपूर्वक उल्लेख करते हैं और स्वीकार करते हैं कि उन्होंने ये

प्रणालियाँ बीस वर्षों की अवधि में भारतीय स्रोतों से सीखीं। लेकिन उनके कई केंद्रों के शिक्षक तब शर्मिंदा हो जाते हैं जब हम उन्हें बताते हैं कि अपनी शुरुआती किताबों में उन्होंने अपनी विधियों को विपश्यना कहा था, क्योंकि इससे उन्हें अपनी शिक्षाओं की विश्वसनीयता स्थापित करने में मदद मिली थी। माइंडफुलनेस के अधिकांश शिक्षक यह सब सुनना नहीं चाहते। भारत, विशेषकर हिंदू धर्म से किसी भी प्रकार का संबंध, नकारात्मक जुड़ाव के रूप में देखा जाता है जो एमबीएसआर के बाज़ार मूल्य को कम करता है। कुछ शिक्षक तब क्रोधित हो जाते हैं जब उन्हें समझाया जाता है कि ये भारतीय तकनीकें हैं जिन्हें पश्चिमी बाज़ारों के लिए नए रूप में प्रस्तुत किया गया है।

कई बौद्ध विद्वानों और डेविड लॉय जैसे अमेरिकी ज़ेन शिक्षक पारंपरिक शिक्षकों ने कबात-ज़िन द्वारा विपश्यना को एक विपणन योग्य सेवा में तब्दील करने के तरीके की आलोचना की है। और अब, वह इस खेल में अकेले खिलाड़ी नहीं हैं। अमेरिकी माइंडफुलनेस उद्योग ने माइंडफुलनेस शिक्षकों को प्रमाणित करने के लिए गलाकाट प्रतिस्पर्धा के एक नए दौर में प्रवेश किया है, हालांकि यह लालच बौद्ध मूल्यों के विपरीत है। उदाहरण के लिए, इंटरनेशनल माइंडफुलनेस टीचर्स एसोसिएशन एक प्रतिस्पर्धी संगठन है जो व्यावसायिक उद्यम की तरह काम करता है। इसकी एक सेवा के तहत 22,500 डॉलर खर्च करके उन जगहों की यात्रा कराई जाती है जिन्हें यह 'हमारे ग्रह के सात चक्र' होने का दावा करता है। एक अन्य पेशकश में वरिष्ठ कॉर्पोरेट प्रबंधकों को माइंडफुलनेस का प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिदिन बारह हजार डॉलर का परामर्श शुल्क लिया जाता है। संगठन आठ सौ डॉलर के वार्षिक शुल्क पर सदस्य बन सकते हैं। मान्यता के लिए शुल्क, इसके लोगो के उपयोग के लिए लाइसेंस शुल्क आदि भी हैं। एक अन्य प्रतिद्वंद्वी, विजडम लैब्स, दावा

करता है कि उसने फोर्ड मोटर कंपनी के प्रबंधकों को माइंडफुलनेस प्रशिक्षण बेचा है। यह ऐसी बिक्री रणनीतियाँ सिखाता है जो इसके फ्रेंचाइजी को व्यावसायिक सौदे हासिल करने में मदद करती हैं। विजडम लैब्स का दावा है, 'यह सब ब्रांडिंग और पोजिशनिंग के बारे में है।'
लेकिन जॉन काबाट-ज़िन का ब्रांड, माइंडफुलनेस-बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन, निर्विवाद रूप से इस क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ है। इसके आठ सप्ताह के कार्यक्रम को पच्चीस हज़ार से अधिक लोग पूरा कर चुके हैं और लगभग एक हज़ार प्रमाणित प्रशिक्षक/शिक्षक इसे सिखाते हैं। साथ ही, यह विश्व भर के छह सौ से अधिक क्लीनिकों में पढ़ाया जाता है। यह एक प्रकार की पिरामिड योजना है जिसमें एक छात्र आगे बढ़कर अन्य इच्छुक लोगों का प्रशिक्षक बन सकता है।
जॉन काबाट-ज़िन ने नए प्रवेशकों के लिए बाधाएँ खड़ी कर दी हैं। शिक्षकों के उनके प्रमाणीकरण की प्रतिष्ठा कहीं अधिक है। और उन्होंने निगमों, स्कूलों, सरकार और सेना जैसे नए बाजारों की लगातार पहचान की है।
भारतीय विचार को पश्चिमी दर्शन और मनोविज्ञान में समाहित करना
ध्यान के अलावा, पश्चिमी मनोविज्ञान भी भारत से गहराई से प्रभावित रहा है, लेकिन शिक्षाविदों द्वारा इसे सावधानीपूर्वक छिपाया गया है। इन पहलुओं के महत्व को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ उदाहरण देंगे।

अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड
अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध और बीसवीं सदी के आरंभिक काल के एक प्रसिद्ध ब्रिटिश गणितज्ञ थे, जिन्होंने विज्ञान के दर्शन में अमिट योगदान दिया। उनके सबसे प्रशंसित शिष्य, प्रभावशाली दार्शनिक बर्ट्रेंड रसेल और व्हाइटहेड ने कई परियोजनाओं पर सहयोग

किया। 1924 में, व्हाइटहेड हार्वर्ड विश्वविद्यालय चले गए, जहाँ उन्होंने अपनी आध्यात्मिक प्रणाली विकसित की, जिसे उन्होंने 'जीवों का दर्शन' कहा, जो वर्तमान में प्रक्रिया दर्शन के नाम से जाना जाता है।
व्हाइटहेड का भारतीय दर्शन प्रणालियों से व्यापक परिचय था और उन्होंने सकारात्मक टिप्पणियाँ की हैं, जैसे कि 'व्यवहारिक तत्वमीमांसा के इतिहास में बौद्ध धर्म सबसे विशाल उदाहरण है'। कुछ विद्वानों ने बौद्ध धर्म और व्हाइटहेड के प्रक्रिया दर्शन के केंद्रीय सिद्धांतों के बीच समानता पर भी टिप्पणी की है। उदाहरण के लिए, प्रख्यात अमेरिकी धर्मशास्त्री चार्ल्स हार्टशोर्न ने कहा: 'व्हाइटहेड की विचार शैली, उल्लेखनीय रूप से, प्राचीन बौद्ध धर्म की याद दिलाती है...।'
दुर्भाग्यवश, पश्चिमी राष्ट्रवाद ने अधिकांश टिप्पणीकारों और यहाँ तक कि पश्चिमी बौद्ध विद्वानों को भी उनके विचारों में निहित बौद्ध धर्म को कमतर आंकने के लिए प्रेरित किया है। वे यह जताना चाहते हैं कि ये उनके द्वारा वैज्ञानिक सोच का उपयोग करके की गई स्वतंत्र खोजें थीं, जो कि जिसे सरसरी तौर पर 'भारतीय रहस्यवाद' कहकर खारिज कर दिया जाता है, उसमें मौजूद नहीं हो सकती थीं।
हालांकि, एक बहुत ही पुख्ता सबूत है जो उनके साहित्यिक चोरी की ओर इशारा करता है: व्हाइटहेड के प्रक्रिया दर्शन के सिद्धांत ऐसे हैं कि उन्हें मात्र विश्लेषणात्मक तर्क और वैज्ञानिक अवलोकनों से प्राप्त नहीं किया जा सकता था, इसके लिए ध्यानमग्न मन की उन्नत अवस्थाओं (जो बौद्ध धर्म में आवश्यक हैं) की आवश्यकता होती है, जिन्हें प्राप्त करने का दावा व्हाइटहेड ने नहीं किया था। व्हाइटहेड की प्रणाली के कुछ आधार सामान्य मानसिक अवस्थाओं में जानना असंभव है, जिससे साहित्यिक चोरी की संभावना बढ़ जाती है।
आगामी पुस्तक परियोजना में, राजीव मल्होत्रा ने विस्तार से बताया है कि

मौलिक बौद्ध धर्म और व्हाइटहेड के प्रक्रिया दर्शन के केंद्रीय विचारों के बीच कम से कम दस विशिष्ट अभिसरण बिंदु हैं।

जर्मन-बौद्ध विद्वान न्यानापोनिका थेरा बताते हैं कि व्हाइटहेड द्वारा प्रस्तावित मुख्य अंतर्दृष्टि केवल ध्यान की उन्नत अवस्था से ही प्राप्त की जा सकती है, न कि केवल बौद्धिक तर्क से। वे दावा करते हैं कि व्हाइटहेड के दावों को 'आत्मनिरीक्षण ध्यान में अप्रशिक्षित मन द्वारा प्रत्यक्ष और अलग से नहीं देखा जा सकता', और आगे कहते हैं:

जैसे पानी की एक बूंद के सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म जीव केवल सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई देते हैं, वैसे ही मन जगत में होने वाली अत्यंत अल्पकालिक प्रक्रियाओं को भी सूक्ष्म मानसिक परीक्षण की सहायता से ही समझा जा सकता है, और यह केवल ध्यान साधना के फलस्वरूप ही प्राप्त होता है। केवल वही आत्मनिरीक्षणात्मक सजगता या ध्यान (सत्ती) जो ध्यानमग्न अवस्था में उच्च स्तर की आंतरिक स्थिरता, शुद्धता और दृढ़ता (उपेक्खा-सती-परिशुद्धि) प्राप्त कर चुकी हो, ऐसी सूक्ष्म मानसिक सूक्ष्मता के लिए आवश्यक तीक्ष्णता, सूक्ष्मता और त्वरित संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया प्रदान कर सकती है। इसके बिना... शोध के साधन के रूप में केवल विभिन्न खंडित विचार क्षणों की श्रृंखलाओं के बीच तुलना से निष्कर्ष निकालने का मार्ग ही खुला रहेगा।

क्षणिक अनुभवों की गहरी समझ प्राप्त करने के लिए एक उन्नत ध्यानमग्न मन आवश्यक है, जिसके आधार पर व्हाइटहेड ऐसी घटनाओं की संबंधपरक संरचना को समझ सकते थे। केवल अनुमान लगाने की प्रक्रिया ध्यानमग्न अंतर्दृष्टि को पूरक कर सकती है और उसे व्यक्त करने में मदद कर सकती है, लेकिन वह स्वयं क्षणिकता के सूक्ष्म जगत में प्रवेश नहीं कर सकती।

बौद्ध धर्म में समझ के तीन चरण माने जाते हैं: (1) अध्ययन से प्राप्त

ज्ञान; (2) चिंतन से प्राप्त ज्ञान; और (3) ध्यान से प्राप्त ज्ञान। व्हाइटहेड की चर्चाएँ पूरी तरह से पहले दो चरणों तक ही सीमित हैं, और उन्होंने कभी भी तीसरे चरण को प्राप्त करने का दावा नहीं किया। व्हाइटहेड द्वारा उपयोग की जाने वाली विशुद्ध रूप से अनुमानित (आगमनात्मक) विधि से तो वह जिसे वे 'श्रेणीबद्ध योजना' या 'अस्तित्व की श्रेणियाँ' कहते हैं, उसे भी प्रकट नहीं किया जा सकता।

तो फिर, उन्होंने ये अंतर्दृष्टियाँ स्वयं कैसे विकसित की होंगी? व्हाइटहेड द्वारा 'वास्तविक सत्ताओं' या 'वास्तविक अवसरों' के रूप में वर्णित चीज़ों और बौद्ध सिद्धांतों के बीच समानताएँ इतनी गहरी हैं कि उन्हें महज संयोग नहीं माना जा सकता।

यह ध्यान देने योग्य है कि कैम्ब्रिज में व्हाइटहेड के परिवेश में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचलन था। कई प्रमुख बुद्धिजीवी इससे बहुत प्रभावित थे। व्हाइटहेड और रसेल बौद्ध धर्म के गहन अध्येता थे, जो ब्रिटेन में प्रचलित बौद्धिक चलन था। हार्वर्ड में भी, व्हाइटहेड के कार्यकाल के दौरान बौद्ध अध्ययन की परंपरा दृढ़ता से स्थापित हुई थी। बर्ट्रेंड रसेल भी बौद्ध धर्म के प्रति उनके समान ही उच्च सम्मान रखते थे।

व्हाइटहेड का अपने विचारों की उत्पत्ति का श्रेय पूरी तरह से पश्चिमी स्रोतों को देना आश्चर्यजनक है। हालांकि उनके द्वारा उद्धृत पश्चिमी उदाहरण बेहद कमजोर हैं, वहीं बौद्ध धर्म के वे सिद्धांत जिनसे उनका सिद्धांत निकला है, स्पष्ट और अत्यंत विस्तृत हैं। उनके तर्क तभी सबसे सशक्त और स्पष्ट होते हैं जब उन्हें बौद्ध मॉडलों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है; लेकिन जब वे अटकलबाजी करने लगते हैं और शब्दावली एवं संरचना दोनों में मौलिक दिखने का प्रयास करते हैं, तो वे अस्पष्ट और भ्रामक हो जाते हैं। बौद्ध धर्म का कोई भी जानकार व्यक्ति पश्चिमी दार्शनिकों को अपने सैद्धांतिक पूर्ववर्ती बताने के उनके प्रयासों को अत्यंत अविश्वसनीय

पाएगा।
व्हाइटहेड ने प्रक्रिया पर ईश्वर को आरोपित करके अपने सिद्धांत को ईसाई धर्म के अनुकूल बनाया। बौद्ध दृष्टिकोण से, यह अनावश्यक और असंगत दोनों है। बौद्ध धर्म को विज्ञान के दर्शन के रूप में और फिर ईसाई धर्म के अनुकूल धर्मशास्त्र के रूप में अपनाना ईसाई धर्मशास्त्रियों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया। पियरे टेइलहार्ड डी चारडिन, चार्ल्स हार्टशोर्न, जॉन बी. कॉब, कार्ल रहनर सहित कई लोगों ने प्रक्रिया धर्मशास्त्र के रूप में जाने जाने वाले एक विचित्र मिश्रण को आगे बढ़ाना शुरू किया।
अब इसे मुख्यधारा की ईसाई धर्मशास्त्र माना जाता है और इसके भारतीय मूल की ओर इशारा करने का कड़ा विरोध किया जाता है, लगभग सेंसरशिप की हद तक। उदार ईसाई हलकों में प्रोसेस थियोलॉजी को दी जा रही महत्ता के कारण, जिसमें व्हाइटहेड को अग्रणी विचारक के रूप में स्थापित किया गया है, हार्वर्ड ने बौद्ध धर्म के इस पूर्णतः अनुकरण के हमारे दावों की जांच में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है।

स्वामी विवेकानंद और विलियम जेम्स
यह सर्वविदित है कि 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद की ऐतिहासिक सभा में एक अभूतपूर्व भाषण दिया था। उस युग के प्रख्यात अमेरिकियों पर विवेकानंद के प्रभाव का पर्याप्त शोध और प्रकाशन नहीं हुआ है। उन्होंने न्यू इंग्लैंड में नवविचार आंदोलन को व्याख्यान दिए और ध्यान का शिक्षण दिया तथा अमेरिका के कई हिस्सों में वेदांत समाजों की स्थापना की, जिन्होंने उस समय के बौद्धिक अभिजात वर्ग में अपनी पैठ बनाई।
जिस बात पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता, वह यह है कि उन्हें दर्शनशास्त्र विभाग के प्रमुख, प्रख्यात दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक

विलियम जेम्स के विशेष अतिथि के रूप में कई बार हार्वर्ड में आमंत्रित किया गया था। वास्तव में, कई बार विवेकानंद जेम्स के घर में ही ठहरे थे, जहाँ जेम्स ने हार्वर्ड में विवेकानंद के प्रसिद्ध सेमिनारों की मेजबानी की थी, जिनमें कई प्रमुख बुद्धिजीवी शामिल हुए थे।

पश्चिम में विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। लेकिन जिस बात का अक्सर जिक्र नहीं होता, वह यह है कि उन्होंने विवेकानंद के संपर्क में रहकर सांख्य दर्शन का गहन ज्ञान प्राप्त किया, जो भारतीय दर्शन की वह शाखा है जो मन के सिद्धांत से संबंधित है। उन्होंने हार्वर्ड में महत्वपूर्ण बौद्ध विद्वानों से भी परामर्श लिया और नागार्जुन द्वारा स्थापित मध्यमक बौद्ध धर्म के साथ-साथ अभिधर्म का भी अध्ययन किया।

जेम्स वेदांत से परिचित हुए और उन्होंने अपनी लोकप्रिय पुस्तक, 'धार्मिक अनुभव की विविधताएँ' में उपनिषदों और अन्य भारतीय ग्रंथों का उल्लेख किया। उन्होंने भारतीय परंपराओं की गहनता और प्रामाणिकता को स्वीकार किया, योग का अभ्यास करने का प्रयास किया और महसूस किया कि गुरु का होना महत्वपूर्ण है।

राजीव मल्होत्रा ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक विज्ञान, मन विज्ञान, धार्मिक अध्ययन और इतिहास के शोधकर्ताओं को विवेकानंद के अमेरिका पर प्रभाव से संबंधित परियोजनाओं में रुचि लेने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया। दुर्भाग्यवश, हार्वर्ड ने केवल दिखावटी समर्थन दिया और इन महत्वपूर्ण विषयों को नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा।

भारतीय आध्यात्मिकता को पश्चिमी साहित्य में समाहित करना

1990 के दशक में, मल्होत्रा ने यह भी पाया कि हार्वर्ड से जुड़े कई प्रख्यात अमेरिकी लेखक वास्तव में भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से गहराई से प्रभावित थे। स्वाभाविक रूप से, उन्होंने इन तथ्यों को हार्वर्ड के लोगों के ध्यान में लाया, ताकि वे इस विषय पर चर्चा के लिए कार्यक्रम आयोजित करने में रुचि लें। हम कुछ प्रमुख उदाहरण देंगे - बोस्टन क्षेत्र में स्थित ट्रांसेंडेंटलिस्ट और नोबेल पुरस्कार विजेता कवि टी.एस. एलियट।

राल्फ वाल्डो एमर्सन

राल्फ वाल्डो एमर्सन को ट्रांसेंडेंटलिस्ट आंदोलन के संस्थापक और 1800 के दशक में यूनिटेरियन समुदाय के एक महत्वपूर्ण विचारक के रूप में जाना जाता है। हालांकि अपने प्रारंभिक वर्षों में वे एक धर्मनिष्ठ ईसाई थे, लेकिन हिंदू ग्रंथों, विशेष रूप से भगवद गीता, वेदों और उपनिषदों के गहन अध्ययन के बाद उनके जीवन में एक गहरा परिवर्तन आया। उनका यह परिवर्तन प्रभावशाली था: उपनिषदों के इस कथन ने कि उनका अपना अंतर्मन ही अंततः ईश्वर है, उन्हें यूनिटेरियन चर्च से नाता तोड़ने और चर्च के पादरी पद से इस्तीफा देने के लिए प्रेरित किया।

1824 में एमर्सन को हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल (एचडीएस) में दाखिला मिला और फिर उन्हें सर्वोच्च शैक्षणिक सम्मान, फी बीटा कप्पा सोसाइटी में शामिल किया गया। हार्वर्ड में अपने व्याख्यानों और लेखन के लिए वे प्रसिद्ध हुए। लेकिन भारतीय प्रभाव से प्रभावित होकर जब 1838 में उन्हें एचडीएस में दीक्षांत भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया, तो उनके व्याख्यान ने विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से और दृढ़ता से यीशु से जुड़े चमत्कारों और यीशु के ईश्वर होने के दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने ईसाई धर्म की कड़ी आलोचना करते हुए इसे घुटन भरा, यीशु के ऐतिहासिक अस्तित्व के प्रति जुनूनी और बौद्धिक योग्यता से

रहित बताया। उनकी टिप्पणियों से हार्वर्ड के विद्वान और आम प्रोटेस्टेंट समुदाय में आक्रोश फैल गया। उन्हें नास्तिक और विधर्मी घोषित कर दिया गया। अगले तीस वर्षों तक उन्हें हार्वर्ड में बोलने से प्रतिबंधित कर दिया गया।

2003 में, हार्वर्ड ने एमर्सन की द्विशताब्दी को एक भव्य आयोजन के रूप में मनाया, जिसमें उनके जीवन पर कई व्याख्यान और उनकी कृतियों की एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। हालाँकि, उन्होंने 1838 में दिए गए उनके व्याख्यान की शर्मनाक घटना पर चर्चा करने से पूरी तरह परहेज किया।

हमने आयोजकों को पत्र लिखकर कहा कि एमर्सन के हिंदू धर्म पर लिखे लेखों को शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। तभी इन्फिनिटी फाउंडेशन ने प्रोफेसर रॉबर्ट सी. गॉर्डन को इस विषय पर एक पुस्तक लिखने के लिए प्रायोजित किया। "एमर्सन एंड द लाइट ऑफ इंडिया: एन इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री" 2008 में प्रकाशित हुई, जिसमें इन भारतीय प्रभावों का विस्तृत विवरण दिया गया है। हार्वर्ड ने इस पर चर्चा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।

वॉल्ट व्हिटमैन

दूसरे सबसे प्रसिद्ध ट्रान्सेंडेंटलिस्ट, जिनका जीवन और कार्य अमेरिकी बौद्धिक इतिहास का अभिन्न अंग बन गए, वाल्ट व्हिटमैन थे, जिन्हें अमेरिका का राष्ट्रीय कवि और उन्नीसवीं सदी के महानतम कवियों में से एक माना जाता है। एक बार फिर, मुक्ति, वास्तविकता के स्वरूप और वेदों और उपनिषदों में पाई जाने वाली शिक्षाओं के बारे में उनके विचारों में उल्लेखनीय समानताएं हैं।

एमर्सन ने एक बार मशहूर टिप्पणी की थी कि व्हिटमैन की 'लीव्स ऑफ

ग्रास' 'भगवद गीता और द न्यूयॉर्क हेराल्ड' का मिश्रण थी। व्हिटमैन ने खुद कहा था कि उन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध रचना लिखने की तैयारी में 'प्राचीन हिंदू कविता' के साथ-साथ कुछ पश्चिमी रचनाओं का भी अध्ययन किया था।

व्हिटमैन की भारत से प्रेरित प्रमुख कविताओं में से एक, 'द स्लीपर्स' में, वे उपनिषद का सार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि सभी सत्ताएँ ब्रह्म के ही रूप हैं:

मैं अभिनेता हूँ, अभिनेत्री हूँ, मतदाता हूँ, राजनीतिज्ञ हूँ, प्रवासी और निर्वासित हूँ, वह अपराधी हूँ जो कटघरे में खड़ा था, वह जो प्रसिद्ध रहा है, और वह जो आज के बाद प्रसिद्ध होगा, हकलाने वाला हूँ, सुगठित व्यक्ति हूँ, कमजोर या दुर्बल व्यक्ति हूँ।

... मैं वो हूं जिसने खुद को सजाया और उम्मीद से अपने बालों को समेटा, मेरा बेवफा प्रेमी आ गया है, और अंधेरा हो चुका है।

इसकी तुलना भगवद् गीता (9.16, 18-19) में कृष्ण द्वारा कही गई बातों से करें:

मैं अनुष्ठानिक क्रिया हूँ, मैं बलिदान हूँ, मैं पूर्वजों को दी जाने वाली आहुति हूँ, मैं औषधीय जड़ी बूटी हूँ, मैं पवित्र भजन हूँ, मैं पिघला हुआ मक्खन भी हूँ, मैं अग्नि हूँ, और मैं भेंट हूँ।

मैं ही लक्ष्य हूँ, मैं ही पालनहार हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही साक्षी हूँ, मैं ही निवास स्थान हूँ, मैं ही शरणस्थल हूँ और मैं ही मित्र हूँ। मैं ही उत्पत्ति और अंत हूँ, मैं ही आधार हूँ, मैं ही विश्राम स्थान हूँ और मैं ही अविनाशी बीज हूँ।

...मैं अमरता भी हूँ और मृत्यु भी; मैं अस्तित्व भी हूँ और गैर-अस्तित्व भी, हे अर्जुन।

अपनी रचना 'पैसेज टू इंडिया' में व्हिटमैन कहते हैं कि उनकी यात्रा केवल

'भूमि और समुद्रों' तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 'आदिम विचार... वापस, ज्ञान के जन्मस्थान तक, निर्दोष अंतर्ज्ञान तक' है।
उन्हें उपनिषदों के उस विचार की गहरी समझ प्राप्त हुई जिसमें उनके गहरे आत्म का परम सत्य से मिलन बताया गया था। इसी समझ के कारण उन्होंने अमेरिकी मानदंडों से हटकर एक अपरंपरागत जीवनशैली अपनाई – एक ऐसी जीवनशैली जिसमें भटकना, एकांतवास और अपने समय की राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना शामिल था।

हेनरी डेविड थॉरो

थोरो 1800 के दशक के अमेरिका के अग्रणी प्रकृतिवादियों, कवियों और दार्शनिकों में से एक थे। वे एमर्सन और व्हिटमैन के साथ मिलकर ट्रांसेंडेंटलिस्ट आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। प्राकृतिक इतिहास और पर्यावरण पर उनके लेखन का अमिट प्रभाव रहा है।
अन्य दो आध्यात्मिक नेताओं की तरह, थोरो भी भारत की आध्यात्मिक विरासत से गहराई से प्रभावित थे। एमर्सन के घर में दो साल रहने के दौरान ही उन्होंने वैदिक ग्रंथों और महाभारत एवं मनुस्मृति के यूरोपीय अनुवादित ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया। उन्होंने अपनी डायरियों में इन ग्रंथों के बारे में अत्यंत प्रेरणा के साथ लिखा। बाद में एक मित्र ने उन्हें हिंदू धर्म पर इक्कीस पुस्तकों का संग्रह भेजा, जिसे थोरो ने जीवन भर संजोकर रखा। उन्होंने बड़े स्नेह से लिखा कि उन्होंने 'इन अनमोल ग्रंथों' को अपने हाथों से बनाए एक नए म्यान में रखा है। इन्हें पढ़ने के बाद उन्होंने एक मित्र को लिखा: 'मैं इनमें से कई ग्रंथों से परिचित हूँ और जानता हूँ कि इन्हें कितना महत्व देना चाहिए। मैं आपको यह सूचना उसी प्रकार भेज रहा हूँ जैसे किसी बच्चे के जन्म की सूचना देता हूँ।'
उन्होंने फ्रांसीसी से अंग्रेजी में एक कृति, 'सात ब्राह्मणों का पुनर्जन्म' का

अनुवाद किया और इसे योग के दर्शन के रूप में पढ़ा, जिसे उन्होंने स्पष्ट रूप से हिंदू साधना की एक तपस्वी प्रणाली के रूप में देखा। एक मित्र को लिखे पत्र में उन्होंने लिखा:

ध्यान में लीन योगी सृष्टि में अपना योगदान देता है: वह दिव्य सुगंध का अनुभव करता है, अद्भुत बातें सुनता है। दिव्य रूप उसे बिना विचलित किए उसके भीतर से गुजरते हैं, और अपनी स्वाभाविक प्रकृति से जुड़कर वह मूल पदार्थ को सजीव करते हुए आगे बढ़ता है। कुछ हद तक, और कभी-कभार, मैं भी एक योगी हूँ।

उनकी डायरी का एक अन्य अंश कहता है: 'कोई व्यक्ति अपने निजी इतिहास में हिंदू धर्म की जड़ खोज सकता है, जब वह दिन या रात के मौन अंतरालों में, कभी-कभी कठोर संतुष्टि के साथ स्वयं पर वैसी ही तपस्या करता है।'

कुल मिलाकर, उस युग के इतिहासकारों का मानना है कि थोरो हिंदू धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म से अधिक प्रभावित थे। लेकिन उनके लेखन में दोनों का प्रभाव दिखता है, और इसी प्रभाव ने उन्हें प्रकृति में गहरे अर्थ खोजने के लिए प्रेरित किया। एक रहस्यवादी के रूप में, वे स्वयं को एक योगी के समान मानते थे।

हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्वान प्रोफेसर यूजीन टेलर, जो मन विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी थे और भारतीय प्रभावों के बारे में लिखने में भी रुचि रखते थे, ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की:

हेनरी डेविड थोरो के सविनय अवज्ञा संबंधी विचार हिंदू धर्मग्रंथों में ध्यान, योग और अहिंसा के अध्ययन से उत्पन्न हुए थे।

यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथन है क्योंकि थोरो के सविनय अवज्ञा संबंधी लेखन ने बाद में गांधी को प्रभावित किया, जबकि आम धारणा यह है कि यह एक अमेरिकी विचार था जो बाद में गांधी तक पहुंचा। टेलर का

कहना है कि यह एक प्राचीन भारतीय विचार था जिसे थोरो ने पश्चिम में आत्मसात किया और गांधी के माध्यम से इसे वापस भारत में पहुंचाया। थोरो की आध्यात्मिक अनुभूति पर आधारित पुस्तक में भारतीय परंपराओं के साथ उनके गहरे संबंधों पर स्पष्ट रूप से चर्चा की गई है।
विडंबना यह है कि हार्वर्ड ने थोरो की भारतीय प्रेरणाओं को नकार दिया है। चूंकि वे हार्वर्ड के छात्र थे (1833-7), इसलिए 2017 में उनकी जन्म शताब्दी वहीं मनाई गई थी। हार्वर्ड गजट ने लिखा: 'हार्वर्ड ने थोरो को गहराई से प्रभावित किया और उन्हें वह बनाने में मदद की जो वे थे...।' 'द हार्वर्ड इन थोरो' नामक लेख में थोरो में निहित भारतीयता का कोई उल्लेख नहीं है।

टी.एस. एलियट
टी.एस. एलियट, जिन्हें बीसवीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी कवि माना जाता है, हार्वर्ड में अध्ययन के दौरान संस्कृत और पतंजलि सूत्र जैसे हिंदू ग्रंथों का गहन अध्ययन कर रहे थे। कई वर्षों के इस अध्ययन ने उनके चिंतन में गहरा परिवर्तन लाया और उन्होंने कहा था कि 'इन ग्रंथों की सूक्ष्मता के सामने अधिकांश महान यूरोपीय दार्शनिक स्कूली बच्चों जैसे लगते हैं।'
उन्होंने उपनिषद, भगवद् गीता, वेद और कई अन्य ग्रंथों का अध्ययन किया, और विद्वानों का मानना है कि ये ग्रंथ उनकी कुछ बेहतरीन रचनाओं के लिए प्रेरणास्रोत थे, जिनमें 'द वेस्ट लैंड' से लेकर नाटक और 'फोर क्वार्टेट्स' तक शामिल हैं। हिंदू क्लासिक्स ने न केवल पहले से प्रचलित विचारों की पुष्टि की, बल्कि स्थापित दृष्टिकोणों को भी महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रदान कीं।
यद्यपि एलियट को भारतीय दर्शन का गहन और व्यापक ज्ञान था, फिर भी

आज के अंग्रेजी साहित्य विभागों में इस प्रभाव का उल्लेख शायद ही कभी मिलता है, और उनकी कविता को गहराई से समझने के लिए इसका विश्लेषण तो और भी कम होता है। आधुनिक अमेरिकी विचार और साहित्य के ऐतिहासिक विकास पर कॉलेज के पाठ्यक्रमों में केवल ग्रीक और यूरोपीय प्रभावों को ही शामिल किया जाता है, और कुछ अफ्रीकी और उत्तर-आधुनिकतावादी तृतीय विश्व के लेखकों को बहुसांस्कृतिक बनाने के लिए इसमें जोड़ दिया जाता है। एलियट जैसे प्रतिष्ठित अमेरिकी विचारकों पर किसी भी प्रकार के भारतीय प्रभाव का कोई निशान नहीं मिलता।

एलियट इस बात से जूझ रहे थे कि भारत से आने वाले ऐसे आध्यात्मिक प्रभावों को उनके अमेरिकी समकालीन विधर्मी मानते थे। उन्होंने लिखा कि यदि वे भारतीय विचारों को पूरी तरह अपना लेते, तो वे अमेरिकी संस्कृति, परिवार, देश, समुदाय और यहाँ तक कि स्थापित अमेरिकी काव्य परंपरा से भी कट जाते। भारतीय परंपरा को अपनाना मूल रूप से पश्चिमी हर चीज़ को नकारने के समान था। वहीं दूसरी ओर, संस्कृत ग्रंथों की ओर उनका आकर्षण इतना प्रबल और अनवरत था कि उसे रोकना असंभव था।

अंततः उन्होंने इस आंतरिक संघर्ष का समाधान कर लिया। उन्होंने वैदिक विचारधारा में अत्यधिक डूबने से बचने के लिए अपने ईसाई धर्म में लौटने का निर्णय लिया। हालाँकि, वे इस खतरे के बिना संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन भी जारी रखना चाहते थे। इसलिए, उन्होंने हार्वर्ड समुदाय की उपस्थिति में सार्वजनिक रूप से (दूसरी बार) बपतिस्मा लिया। इस कार्य के माध्यम से अपनी ईसाई पहचान को सुरक्षित करने के बाद, उन्होंने संस्कृत का अध्ययन जारी रखा, लेकिन अब पहले की तरह बपतिस्मा लिए बिना, बल्कि एक निश्चित दूरी बनाए रखते हुए।

जब मल्होत्रा की मुलाकात प्रो. क्लियो केर्न्स से हुई, जिन्होंने टी.एस. एलियट के हिंदू धर्म के आजीवन अध्ययन पर अपना डॉक्टरेट शोध प्रबंध लिखा था, तो दोनों के बीच तुरंत एक गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। इन्फिनिटी फाउंडेशन ने उन्हें विभिन्न परियोजनाओं के लिए एक शोधार्थी के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की और उनकी पुस्तक, 'टी.एस. एलियट एंड इंडिक ट्रेडिशन्स इन इंडिया' प्रकाशित की, ताकि एलियट की रचनाओं के प्रशंसक युवा भारतीय यह समझ सकें कि उन्होंने अपनी प्रशंसित कविताओं के लिए संस्कृत ग्रंथों का गहन अध्ययन किया था। लेकिन हार्वर्ड को इस शोध को आगे बढ़ाने में रुचि दिलाने के सभी प्रयास व्यर्थ गए।

पिछले तीस वर्षों से, हार्वर्ड के धार्मिक अध्ययन, बिजनेस स्कूल, सामाजिक विज्ञान, मेडिकल स्कूल या मनोविज्ञान विभागों को इन्हें भारतीय योगदान के रूप में प्रदर्शित करने के लिए मनाने के हमारे प्रयास विफल रहे हैं।

हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित अत्याचार साहित्य

इनफिनिटी फाउंडेशन की हार्वर्ड और भारत के संबंधों से जुड़ी दूसरी बड़ी खोज और भी चौंकाने वाली थी। हमने पाया कि यह संस्थान भारत पर अत्याचार संबंधी साहित्य तैयार करने का एक प्रमुख केंद्र है। इस शब्द का तात्पर्य उस साहित्य से है जो अमेरिकी किसी अन्य संस्कृति के बारे में लिखते हैं और उन्हें अपने ही लोगों पर अत्याचार करने वाले बर्बर के रूप में चित्रित करते हैं। यह साहित्य मानवाधिकार उल्लंघन के सिद्धांतों को विकसित करने के लिए एक संग्रह बन जाता है, जिनका उपयोग लक्षित समाजों पर आरोप लगाने के लिए किया जाता है। किसी न किसी स्तर

पर, ऐसे सिद्धांतों को राजनीतिक अभियानों में हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि उन समाजों में घुसपैठ की जा सके या किसी तरह हस्तक्षेप किया जा सके, और खुद को सामाजिक न्याय दिलाने वाले उद्धारकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया जा सके।

जन स्वास्थ्य के नाम पर अत्याचार संबंधी साहित्य
हार्वर्ड में जन स्वास्थ्य के नाम पर भारत पर इतने व्यापक साहित्य का संकलन, संपादन और साझाकरण देखकर हम दंग रह गए। हार्वर्ड स्कूल फॉर पब्लिक हेल्थ (एचएसपीएच), जिसका नाम बाद में बदलकर हार्वर्ड टी.एच. चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ कर दिया गया, में भारत पर कई मंच आयोजित किए जाते थे। 1990 के दशक से लेकर कुछ वर्ष पूर्व तक इन मंचों की पूरी सूची में निम्नलिखित शामिल थे:
बाल विवाह
महिलाओं के खिलाफ अपराध
दहेज
भ्रूणहत्या
लड़की
इंजेक्शन/गर्भनिरोधक
सती
आदिवासियों
उपरोक्त प्रत्येक विषय के अंतर्गत, होम पेज https://www.hsph.harvard.edu/ पर विस्तृत वेबसाइटें उपलब्ध थीं। वे वेबसाइटें अब मौजूद नहीं हैं, लेकिन हमारे पास उनकी सामग्री के बड़े हिस्से के स्क्रीनशॉट हैं। उनमें लेख, शोधार्थियों के संपर्क विवरण, अनुसंधान के लिए संसाधन सामग्री, भारत में कानूनी मामले आदि

शामिल थे।
दिलचस्प बात यह भी है कि दक्षिण एशिया के अलावा हार्वर्ड में इसी तरह का संग्रह रखने वाला एकमात्र अन्य क्षेत्र अफ्रीका था। चीन पर ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था।
जब हार्वर्ड भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य में मदद करने का दावा करता है, तो ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि वह डेंगू, मलेरिया या अन्य व्यापक उष्णकटिबंधीय बीमारियों के इलाज के लिए धन देगा। या फिर भारत के चिकित्सा पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देगा, जो इलाज के लिए विदेशी मरीजों को लाता है। लेकिन इन वेबसाइटों पर गंभीर बीमारियों के इलाज, पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने, भारत की सुविधाओं और उपकरणों में सुधार करने या मौलिक दवाओं की खोज को प्रोत्साहित करने के बारे में कुछ भी नहीं था। सारा ध्यान केवल सामाजिक दुर्व्यवहारों और अत्याचारों से संबंधित साहित्य पर था। हमें यह उम्मीद नहीं थी कि हार्वर्ड भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए गंदगी खोदने में इतना मशगूल होगा।
भारत के प्रति खुलेआम भेदभाव को कम से कम कुछ हद तक सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए 2005 से छिपाना शुरू किया गया। उसी समय हार्वर्ड ने भारतीय दानदाताओं से धन जुटाने का फैसला किया।

वनवासी लोगों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना
1990 के दशक के उत्तरार्ध में, इन्फिनिटी फाउंडेशन ने हार्वर्ड के विद्वानों के साथ बातचीत शुरू की। इसके फलस्वरूप फाउंडेशन ने हार्वर्ड इंडोलॉजी राउंड टेबल्स की एक श्रृंखला के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की, जिसका नेतृत्व जर्मन-अमेरिकी इंडोलॉजिस्ट माइकल विट्ज़ेल ने किया। इस अनुदान के तहत, विभिन्न देशों के विद्वानों को प्राचीन भारतीय

इतिहास और पुरातत्व से संबंधित विशिष्ट परियोजनाओं पर एक साथ काम करने के लिए प्रतिवर्ष हार्वर्ड में आमंत्रित किया जाता था। हम कई प्रख्यात विद्वानों से मिले, उनके शोध के बारे में प्रत्यक्ष रूप से जाना, अकादमिक अनुसंधान की राजनीति को समझा और अंततः अपने शोध के माध्यम से उन्हें जवाब देने में सक्षम हुए। यह पूर्व-पक्ष (विरोधी दृष्टिकोणों का व्यवस्थित अध्ययन) का एक महत्वपूर्ण शिक्षण अनुभव था।

हमें जो एक महत्वपूर्ण बात पता चली, वह थी हार्वर्ड की मुंडा भाषाओं के अध्ययन में गहरी रुचि। यह भाषाओं का एक परिवार है जो मध्य भारत के कई हिस्सों के साथ-साथ दक्षिण पूर्व एशिया में, ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों तक बोली जाती है। इस विषय पर एक प्रारंभिक शोध पत्र इन्फिनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित मध्य और दक्षिण एशिया के प्रागैतिहासिक काल पर तीसरे हार्वर्ड गोलमेज सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। इस शोध को सिंधु घाटी के शिलालेखों और प्रारंभिक वैदिक काल की मूल भाषा से मुंडा या ऑस्ट्रोएशियाई संबंध का पता लगाने में सहायक के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

हमें पता चला कि इस शोधपत्र के पीछे हार्वर्ड में एक ढांचा विकसित किया जा रहा था। इसके परिणाम बेहद गंभीर थे। शोधपत्र में कहा गया था कि पश्चिमी भारतविदों द्वारा माना जाने वाला आर्य/द्रविड़ विभाजन अधूरा है, क्योंकि न तो आर्य और न ही द्रविड़ भारत के 'मूल निवासी' थे। इनसे पहले मुंडा जनजातियाँ यहाँ बसी थीं। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी भी उसी प्राचीन परिवार का हिस्सा हैं, जो इन भूमियों पर बसने वाले सबसे पहले एशियाई थे।

इस सिद्धांत के अनुसार, जिस प्रकार आर्यों ने द्रविड़ लोगों को जीत कर दक्षिण भारत में धकेल दिया, उसी प्रकार द्रविड़ भी पश्चिम भारत से आए पूर्व विजेता थे जिन्होंने भारत के मुंडाओं पर आक्रमण कर उन्हें अपने

अधीन कर लिया।
दूसरे शब्दों में कहें तो, भारत के नस्लीय इतिहास की दो नहीं, बल्कि तीन परतें हैं। सबसे पहले और प्राचीन निवासी मुंडा थे, जो अब सबसे निचले पायदान पर हैं। फिर द्रविड़ आए और उन्होंने मुंडाओं को हराकर उनका दमन किया। और अंत में आर्य आए, जिन्होंने मुंडाओं और द्रविड़ दोनों का दमन किया और वे सबसे ऊपर हैं।
इन विद्वानों से सावधानीपूर्वक पूछताछ करने पर मल्होत्रा को यह स्पष्ट हो गया कि वे मध्य भारत में नवजात माओवादी आंदोलन को भारत के विरुद्ध अलगाववाद भड़काने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते थे। इन अध्ययनों का मुख्य उद्देश्य मुंडा भाषाओं को संस्कृत और तमिल से पूर्णतः भिन्न बताना था, और उन्हें शेष भारत से संस्कृति और धर्म में अंतर दर्शाने का आधार बनाना था। रणनीति यह थी कि हिंदू धर्म और जिसे वे 'संस्कृतिकृत संस्कृति' कहते थे, उससे अधिकतम भिन्नताओं को उजागर किया जाए। मुंडा पहचान को स्पष्ट रूप से 'उप-राष्ट्रवाद' के रूप में प्रस्तुत किया गया। उन्हें आर्यों और द्रविड़ों दोनों के उत्पीड़न के शिकार निम्न वर्ग के लोगों के रूप में चित्रित किया गया। इस परिदृश्य में भारत विदेशी आर्यों और द्रविड़ों द्वारा निर्मित एक अवैध राष्ट्र है जो मूल निवासियों पर अत्याचार करता है।
आज ये तीनों स्तर अपने-अपने सामाजिक समूहों में परिवर्तित हो गए हैं। भारत के सामाजिक स्तरों का मानचित्रण इस प्रकार किया जा रहा है:
आर्य → ब्राह्मण
द्रविड़ → निचली जातियाँ
मुंडा → आदिवासी/आदिवासी → दलित
यह मुंडा भाषा या लोगों के प्रति किसी वास्तविक प्रेम से प्रेरित नहीं था, बल्कि अंग्रेजों और विभिन्न मिशनरियों द्वारा एक शताब्दी पहले शुरू की

गई विखंडन परियोजना को जारी रखने के लिए था। एक बार जब एक अलग उप-राष्ट्रवाद की नींव पड़ जाती है, तो कुछ लोगों को उत्पीड़क के रूप में बदनाम करने के लिए अत्याचार साहित्य की एक बड़ी मात्रा को इसमें शामिल कर लिया जाता है। यह एक घातक मिश्रण में बदल जाता है। इसके परिणाम हमारे सामने हैं।
मालहोत्रा द्वारा भारतीयों को सचेत करने के प्रयास – सरकारी अधिकारियों, गुरुओं, शिक्षाविदों, राजनेताओं – विफल रहे क्योंकि यह महज एक और षड्यंत्र सिद्धांत प्रतीत होता है। हालांकि, इस सिद्धांत का परिणाम वर्तमान में दलित आंदोलन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जिसका उद्देश्य वनवासियों को 'आदिवासी' के रूप में सशक्त बनाना और उन्हें शेष भारत से अलग पहचान देना है।

खालिस्तानी और कश्मीर अलगाववादी
वर्ष 2000 तक, अमेरिका में रहने वाले काफी संख्या में भारतीयों को यह एहसास होने लगा था कि इन्फिनिटी फाउंडेशन के पास हार्वर्ड और इसी तरह के संस्थानों के साथ भारत से संबंधित मामलों पर काम करने का विशेष अनुभव है। इसी दौरान न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्यदूत (2002-5) प्रमथेश रथ ने राजीव मल्होत्रा से संपर्क किया, उनके घर गए और उन्हें दूतावास में आमंत्रित किया। इन सबका उद्देश्य अमेरिकी विश्वविद्यालयों, मीडिया और स्कूलों में भारत अध्ययन की स्थिति को समझने के लिए उनसे परामर्श करना था। वे इस विषय में रुचि दिखाने वाले पहले भारतीय थे, जो उच्च पद पर थे।
रथ द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में से एक न्यूयॉर्क दूतावास में राजीव मल्होत्रा द्वारा आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी थी, जिसमें प्रभावशाली आमंत्रितों के एक चुनिंदा समूह ने भाग लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि

मल्होत्रा द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर वे सहमत होंगे। लेकिन प्रतिक्रिया बिल्कुल विपरीत रही। उपस्थित लोगों में कई ऐसे भी थे जिन्हें भारत का मित्र माना जाता था, लेकिन जब उन्हें भारत पर होने वाली चर्चा की असहज स्थिति के बारे में बताया गया, तो वे रक्षात्मक हो गए और अकादमिक जगत के साथ एकजुट हो गए। यह प्रमथेश रथ के लिए एक चेतावनी थी।

कुछ सप्ताह बाद, रथ ने मल्होत्रा को फोन किया और बताया कि वह अपनी लिमोसिन में हार्वर्ड जा रहे हैं, जहाँ वह भारत पर एक सम्मेलन में मुख्य अतिथि हैं। उन्होंने मल्होत्रा से भाषण के लिए कुछ सुझाव मांगे। मल्होत्रा यह जानना चाहते थे कि उन्हें किन लोगों के साथ मंच साझा करना होगा। रथ ने सूची को ध्यान से देखे बिना ही नाम पढ़ दिए। तभी मल्होत्रा ने उन्हें बताया कि सूची में कश्मीर के जाने-माने अलगाववादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी विद्वान और भारतीय अति वामपंथी शामिल हैं। जब रथ को उनके बारे में पता चला, तो वह समझ गया कि उसे फंसाया जा रहा है। यह घटना हार्वर्ड में उसके लिए घात लगाकर किए गए हमले की तरह थी। उसने तुरंत न्यूयॉर्क लौटने और हार्वर्ड की अपनी यात्रा रद्द करने का फैसला किया। यह चौंकाने वाली बात थी कि भारत के पास (और अभी भी) इतने महत्वपूर्ण स्थान पर बैठे अपने विरोधियों की निगरानी और जासूसी करने के लिए कोई प्रभावी अनुसंधान शाखा नहीं थी। हार्वर्ड द्वारा प्रायोजित भारत तोड़ने वाली ताकतों के साथ ऐसी ही कई मुठभेड़ों में से यह एक थी।

हिंदी को उर्दू पर मैप करना

हार्वर्ड के साथ अपने अनुभवों के दौरान, हमने पाया कि उनके हिंदी पाठ्यक्रम में वास्तव में हिंदी नहीं बल्कि उर्दू पढ़ाई जा रही थी, जिसे

भारत-मुस्लिम अध्ययन के विद्वान अली एस. असानी पढ़ा रहे थे। इन पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले छात्रों ने इन्फिनिटी फाउंडेशन को बताया कि असानी पहले ही दिन यह बात स्पष्ट कर देते थे कि चाहे किसी ने हिंदी में दाखिला लिया हो या उर्दू में, सभी को एक ही चीज़ सीखने को मिलेगी क्योंकि दोनों भाषाओं में अंतर नगण्य है।

जैसे-जैसे पाठ्यक्रम आगे बढ़ता गया, वे धीरे-धीरे हिंदी को हीन और उर्दू को श्रेष्ठ भाषा के रूप में प्रस्तुत करने लगे। पठन सामग्री, प्रदर्शित फिल्में और सांस्कृतिक कार्यक्रम, सभी में उर्दू को सौंदर्य की भाषा के रूप में दर्शाया जाता था। युवा और आसानी से प्रभावित होने वाले भारतीय छात्र उन्हें पिता तुल्य मानते थे, जो उन्हें अपने घर पर पार्टियों और समारोहों के लिए आमंत्रित करते थे। असानी एक प्रसिद्ध मुस्लिम धर्म प्रचारक हैं जो विश्व मुस्लिम कांग्रेस जैसे मंचों पर इस्लाम की बहुलता और मानवाधिकारों का जोरदार समर्थन करते हैं।

वह जानबूझकर हिंदी पाठ के लिए ऐसे असाइनमेंट चुनते थे जिनमें हिंदू महिलाएं अपनी संस्कृति पर विलाप करती हों, निम्न जाति और गरीब लोग अपना गुस्सा जाहिर करते हों, इत्यादि। दूसरे शब्दों में, हिंदी सामग्री आम तौर पर नकारात्मक होती थी, जबकि उर्दू सामग्री सकारात्मक होती थी और उसमें रोचक और मनोरंजक मुद्दों पर चर्चा होती थी।

पाठ्यक्रम के दौरान, कभी-कभी वे कहते थे कि हिंदी बहुत जटिल है, और उर्दू सीखना ही काफी है। हिंदी-उर्दू पाठ्यक्रम के पहले स्तर के बाद, श्रृंखला के प्रत्येक अगले पाठ्यक्रम में उर्दू पर अधिक और हिंदी पर कम ध्यान दिया जाता था। जब तक छात्र विभिन्न 'हिंदी' पाठ्यक्रम पूरे करते, तब तक वे हिंदी से नफरत करने लगते थे और उर्दू से प्यार करने लगते थे।

फिर हमने हार्वर्ड के हिंदी-उर्दू शिक्षण के विश्लेषण को समुदाय में

फैलाया। कई अभिभावक आक्रोशित हो गए। एक गुजराती व्यापारी ने हार्वर्ड की अनुमति से एक निजी शिक्षक को उचित हिंदी पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए प्रायोजित किया। अधिकांश भारतीय छात्र उस पाठ्यक्रम में चले गए और असानी ने खुद को उपेक्षित महसूस किया। उन्होंने सुगाता बोस जैसे लोगों की मदद से राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया और प्रतिस्पर्धी हिंदी पाठ्यक्रम को रद्द करवा दिया।
असानी हिंदी को उर्दू में समाहित करने और हिंदी को उसकी अपनी सुंदरता, साहित्य और विचारों वाली एक स्वतंत्र भाषा के रूप में कमजोर करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहे हैं। यह घटना लगभग बीस वर्ष पहले घटी थी और यह उन विवादों में से एक थी जो इन्फिनिटी फाउंडेशन ने हार्वर्ड के साथ छेड़े थे।

प्रारंभिक वर्षों में हार्वर्ड विश्वविद्यालय को भारतीय वित्तपोषण

इन्फिनिटी फाउंडेशन विजिटिंग प्रोफेसरशिप
शैक्षणिक पूर्वाग्रह की समस्याओं को दूर करने के लिए इन्फिनिटी फाउंडेशन का प्रारंभिक दृष्टिकोण हार्वर्ड जैसे संस्थानों को वित्त पोषित करना था, इस उम्मीद में कि वे अपना दृष्टिकोण बदलेंगे। फाउंडेशन ने हार्वर्ड के संस्कृत और भारतीय अध्ययन विभाग को अनुदान दिया, जिसका उद्देश्य एक अतिथि प्रोफेसर को दो ऐसे विषयों को पढ़ाने के लिए लाना था जिन्हें हम उपेक्षित महसूस कर रहे थे:
पश्चिमी सभ्यता में भारत के योगदान को अपर्याप्त रूप से मान्यता दी गई है।
पश्चिमी अकादमिक जगत में हिंदू धर्म के साथ होने वाला अनुचित

व्यवहार, अर्थात् हिंदू-विरोधी भावना।
पहले व्यक्ति थे कनाडा के मैकगिल विश्वविद्यालय में हिंदू धर्म के विख्यात विद्वान प्रोफेसर अरविंद शर्मा। हार्वर्ड में हमारा संपर्क जाने-माने भारतविद् माइकल विट्ज़ेल से था, जिनके साथ हमारी कई बहसें और मतभेद हुए, लेकिन उस समय उनके साथ हमारा सम्मानजनक सहयोगात्मक संबंध भी था। विट्ज़ेल ने हमें गोपनीय रूप से बताया था कि कुछ संकाय सदस्य हमारी योजनाओं का निश्चित रूप से विरोध करेंगे।
सच्चे उदारवादियों की तरह इन विषयों को हिंदू धर्म के 'अंदरूनी' दृष्टिकोण के रूप में पहचानने के बजाय, इस तरह के पाठ्यक्रम के शुरू होने से पहले ही इसके विचार पर कड़ा हमला किया गया। कुछ खबरों के अनुसार, तीन प्रभावशाली संकाय सदस्यों की एक टीम ने अधिकारियों से पाठ्यक्रम रद्द करवाने की कोशिश की। हालांकि, हार्वर्ड की ओर से अतिथि प्रोफेसरशिप के मेजबान विट्ज़ेल ने शर्मा के पाठ्यक्रमों का बचाव किया। इस प्रकार, वे पाठ्यक्रम रद्द करवाने में असफल रहे।
अगले वर्ष, 2002 में, संस्कृत विद्वान और भारतविज्ञानी तथा ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के एशियाई अध्ययन विभाग के प्रोफेसर एमेरिटस अशोक अकलुजकर हार्वर्ड में इन्फिनिटी फाउंडेशन के दूसरे अतिथि प्रोफेसर बने। उन्होंने विवादास्पद विषयों में न पड़ने का निर्णय लिया। उनकी पत्नी विद्युत अकलुजकर, जो स्वयं भी एक संस्कृत विद्वान थीं, को भी हार्वर्ड में व्याख्याता के पद पर नियुक्त किया गया। अपने शिक्षण और शोध के अलावा, उन्होंने संगमनी: भारत अध्ययन सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें संस्कृत परंपरा का एक दुर्लभ और प्रामाणिक चित्रण प्रस्तुत किया गया। हमारा एक लक्ष्य न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टोनी ब्रुक के भाषाविज्ञानी प्रोफेसर एस.एन. श्रीधर पर ध्यान केंद्रित करना था, ताकि हम वहां नियोजित किए जा रहे एशिया केंद्र के प्रमुख के

रूप में उनकी नियुक्ति का समर्थन कर सकें।
इन्फिनिटी फाउंडेशन ने समुदाय को यह बताना शुरू किया कि अमेरिका में दक्षिण एशियाई अध्ययन, इंडोलॉजी कहे जाने वाले विषय की जगह ले रहे हैं; यह भारत के संस्कृत-आधारित अध्ययनों से सामाजिक विज्ञानों की ओर बदलाव को दर्शाता है, इसीलिए वामपंथी दृष्टिकोण का उपयोग किया जा रहा है। हालाँकि, चीन के मामले में, इसे अन्य पड़ोसी देशों के साथ 'पूर्वी एशिया' में शामिल नहीं किया गया, बल्कि इसे चीन के रूप में एक अलग पहचान दी गई। भारत को आठ दक्षिण एशियाई देशों में से एक के रूप में शामिल करने से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य देशों को निर्णय लेने में समान प्रतिनिधित्व और अधिकार की मांग करने का मौका मिल रहा था, जिसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा था। कार्यक्रमों को इंडिक स्टडीज या इंडिया स्टडीज नाम देने के हमारे अभियान का शिक्षाविदों ने विरोध किया।

धीरूभाई अंबानी द्वारा अस्वीकृति
2000 के दशक के आरंभ में, स्वर्गीय ऋषि कुमार मिश्रा और उनकी पत्नी रेणुकाजी ने प्रिंसटन स्थित इन्फिनिटी फाउंडेशन के कार्यालय का दौरा किया। मिश्रा, स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी के विशेष सलाहकार और अंबानी द्वारा स्थापित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक थे। उन्होंने हार्वर्ड जैसे संस्थानों के प्रति हमारे विरोध के बारे में सुना था और विशेष रूप से यह जानना चाहते थे कि अंबानी द्वारा हार्वर्ड में प्रोफेसरों के पदों के लिए वित्तीय सहायता देने के अनुरोध पर क्या किया जाए। आखिरकार, हार्वर्ड की प्रतिष्ठा को देखते हुए, हमारे लिए इसके विरुद्ध व्यवस्थित रूप से तर्क देना असामान्य बात थी। इस दंपति ने हार्वर्ड के संबंध में हमारी चिंताओं को सुनने के लिए इन्फिनिटी फाउंडेशन में एक सप्ताहांत

बिताया।

इन्फिनिटी फाउंडेशन ने छह विद्वानों को आमंत्रित किया जो अमेरिका में दक्षिण एशियाई अध्ययन की स्थिति का अध्ययन करने वाली उसकी टीम का हिस्सा थे। मिश्रा के लिए ये प्रस्तुतियाँ चौंकाने वाली थीं, क्योंकि उन्हें हार्वर्ड और इसी तरह के संस्थानों में भारत-विरोधी झुकावों के बारे में कभी जानकारी नहीं थी। एक प्रस्तुति में बताया गया कि हार्वर्ड चीन का अध्ययन बड़े सम्मान के साथ करता है, जबकि भारत को मानवाधिकारों के नज़रिए से देखा जाता है - जाति, महिलाओं पर अत्याचार, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार आदि। अन्य प्रस्तुतियाँ आर्यन आक्रमण सिद्धांत जैसे विशिष्ट पूर्वाग्रहों के बारे में थीं। इसका परिणाम यह हुआ कि लौटने पर मिश्रा ने धीरूभाई अंबानी को सलाह दी कि जब तक हार्वर्ड भारत के प्रति अपना रुख नहीं बदलता, तब तक उसे एक भी डॉलर न दें। हमारी टीम ने दिखाया कि चीन को एक गंभीर सभ्यता के रूप में देखा जाता है। इसका एक कारण यह है कि चीन का अध्ययन मुख्य रूप से मंदारिन भाषा में होता है, जबकि भारत का अध्ययन अंग्रेजी में होता है। इसके अलावा, चीन पश्चिमी विद्वानों के लिए वीजा नियमों को इस तरह नियंत्रित करता है कि वह उन लोगों को ब्लैकलिस्ट कर देता है जिन्हें वह आपत्तिजनक मानता है, जबकि भारत खुला है और बिना किसी निगरानी के सबका स्वागत करता है, और किए गए शोध का कोई विश्लेषण नहीं करता। वास्तव में, भारतीय इसे एक प्रशंसा के रूप में लेते हैं जब पश्चिमी लोग उनका अध्ययन करते हैं, मानो वे उपेक्षित होने की हीन भावना से ग्रस्त हों।

इन्फिनिटी फाउंडेशन के हस्तक्षेप से हार्वर्ड के धनी भारतीयों से चंदा जुटाने के अभियान पर अस्थायी रूप से रोक लग गई। इसके बाद हुई घटनाओं की गहमागहमी में, जब हार्वर्ड भारतीय उद्योग से धन जुटाने के

लिए अभियान चला रहा था, इन्फिनिटी फाउंडेशन संभावित दानदाताओं को हतोत्साहित करने में सफल रहा। लेकिन इन सब बातों ने फाउंडेशन को हार्वर्ड की नज़रों में ला दिया। लगभग उसी समय, इन्फिनिटी फाउंडेशन ने हार्वर्ड में आयोजित इंडोलॉजी राउंड टेबल की अपनी वार्षिक प्रायोजन भी समाप्त कर दी।

हार्वर्ड में प्रसिद्धि पाने और श्वेत अमेरिकी अभिजात वर्ग के प्रतिष्ठित लोगों के साथ भोजन करने का आकर्षण भारतीयों के लिए इतना प्रबल है कि वे इसका विरोध नहीं कर पाते। अधिकांश धनी भारतीयों के लिए असली सफलता तब होती है जब उन्हें मान्यता मिलती है और श्वेत अभिजात वर्ग के साथ उच्च स्तरीय भोज में स्थान मिलता है। सदियों से भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के बाद, पश्चिम इस कमजोरी को भली-भांति जानता है और इसका भरपूर फायदा उठाता है। सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दियों में इसी ज्ञान का उपयोग करके उन्होंने एक के बाद एक राजाओं का शासन, नियंत्रण और पतन किया। अंग्रेजों ने धनी भारतीय बच्चों को कैम्ब्रिज ले जाना, उनके साथ पोलो खेलना, श्वेत महिलाओं से मेलजोल रखना सीखा – ताकि वे अन्य भारतीयों की उपस्थिति में मानद श्वेतों के रूप में खुद को सम्मानित महसूस कर सकें। स्वतंत्रता के बाद, अंग्रेजों की जगह अमेरिकियों ने ले ली, इसीलिए हार्वर्ड जैसे स्थानों का रणनीतिक महत्व बढ़ गया।

आनंद महिंद्रा ने भी अपनी राय रखी।

एक दिन इन्फिनिटी फाउंडेशन को एक प्रमुख भारतीय का फोन आया कि भारतीय उद्योगपति आनंद महिंद्रा को हार्वर्ड संस्थान में शामिल करने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने मुंबई स्थित अपने मुख्यालय में फाउंडेशन को कार्यालय स्थान उपलब्ध कराया है। मल्होत्रा ने महिंद्रा से

व्यक्तिगत रूप से मिलने का समय लिया और उन्हें एक अत्यंत सभ्य, विनम्र और खुले विचारों वाला कार्यकारी पाया। उन्होंने उनकी चिंताओं को ध्यान से सुना। वे उन मुद्दों से अनभिज्ञ थे जो स्पष्ट रूप से उन्हें परेशान कर रहे थे। लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हार्वर्ड ने उनकी पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी, इसलिए वे हार्वर्ड के प्रति बहुत ऋणी हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए यह ऋण चुकाने का समय है, इससे अधिक कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि चिंता न करें, क्योंकि वे केवल बहुत छोटी राशि, जैसे कि एक बार में बीस हजार डॉलर, दे रहे हैं, और वह भी भारतीय छात्रों को शोधार्थी के रूप में आने के लिए।

महिंद्रा हार्वर्ड के संबंध में इन आपत्तियों को समझना चाहते थे ताकि वे इन्हें आगे पहुंचा सकें और सुनिश्चित कर सकें कि हार्वर्ड अपना दृष्टिकोण बदल ले। कुछ दिनों बाद, महिंद्रा के सुझाव पर, मल्होत्रा ने हार्वर्ड के सुगाता बोस से संक्षिप्त फोन पर बातचीत की, जो धन जुटाने के लिए ब्रांड एंबेसडर के रूप में भारत आए हुए थे। मल्होत्रा ने सुगाता बोस की उन रचनाओं की सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी जिनमें मुगल-पूर्व भारत को असभ्य बताया गया है, इस्लामी उपनिवेशवादियों को आलोचनाओं से छूट दी गई है, और एक अर्ध-इस्लामी सभ्यता (जिसे 'धर्मनिरपेक्षता' के रूप में प्रस्तुत किया गया है) के तहत एकीकृत दक्षिण एशिया की वापसी को बढ़ावा दिया गया है। यह सब, उनकी मित्र और सह-लेखिका, आयशा जलाल ने हार्वर्ड जैसे संस्थानों में दक्षिण एशिया के मुख्य पाठ्यक्रम में कुशलतापूर्वक शामिल करवा दिया था। (जलाल, हालांकि हार्वर्ड संकाय में नहीं थीं, लेकिन मल्होत्रा द्वारा इस विचित्र विसंगति की ओर ध्यान दिलाने तक उनके दक्षिण एशिया कार्यक्रम की समिति में थीं, और फिर उन्होंने अचानक वह भूमिका छोड़ दी।) बोस सौहार्दपूर्ण और स्पष्टवादी थे और मल्होत्रा से बाद में बातचीत जारी रखने

के लिए सहमत हुए - जो कभी नहीं हो सकी।
जैसा कि हम आगे के अध्याय में देखेंगे, आनंद महिंद्रा ने बाद में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मानविकी केंद्र के लिए दस मिलियन डॉलर दान किए, जिसका नाम बाद में उनके नाम पर रखा गया। एक सीधे-सादे और विवादरहित व्यक्ति, महिंद्रा ने इस बात से कभी इनकार नहीं किया।

Rajat Gupta

लगभग 2005 में, इन्फिनिटी फाउंडेशन के राजीव मल्होत्रा और कृष्णन रामास्वामी, रजत गुप्ता (उस समय मैकिन्से के प्रबंध निदेशक) से कई घंटों की निजी मुलाकात के लिए गए। फाउंडेशन ने समझाया कि भारतीय परोपकारियों द्वारा अमेरिकी विश्वविद्यालयों को धन देने से पहले, उनके जैसे लोगों को यह जांच-पड़ताल करनी चाहिए कि किसी विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम ने क्या परिणाम दिए हैं और यह परोपकारी की भारत के प्रति धारणा से कितना मेल खाता है। हमने तर्क दिया कि कोई भी प्रबंधन सलाहकार उचित जांच-पड़ताल किए बिना अपने ग्राहक को किसी भी उद्यम में निवेश करने का प्रस्ताव नहीं देता है।
इस बात ने गुप्ता को प्रभावित किया। मल्होत्रा और रामास्वामी ने बताया कि इन्फिनिटी फाउंडेशन ही एकमात्र ऐसा संगठन था जिसने अमेरिका में दक्षिण एशियाई अध्ययन का इस तरह का निष्पक्ष विश्लेषण करने का प्रयास किया था। उन्होंने बताया कि चीनी सरकार और उनके निजी दानदाता पश्चिम में चीन अध्ययन की स्थिति पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कोई उद्योग विश्लेषक किसी उद्योग के लिए करता है, और यह रिपोर्ट उन्हें मार्गदर्शन देती है कि कहां और कैसे निवेश करना है। इससे चीन को किसी भी कार्यक्रम का मूल्यांकन करने और विषय के बारे में जानकारी के आधार पर बातचीत करने का आधार

मिलता है।
गुप्ता ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उन्होंने इस बारे में इस तरह से नहीं सोचा था। उन्होंने कहा कि भारत अध्ययन से जुड़े लोग अच्छे और सभ्य हैं। मल्होत्रा ने जवाब दिया कि किसी व्यावसायिक निवेश का मूल्यांकन करते समय, उचित जांच-पड़ताल इस बात पर आधारित नहीं होती कि प्रबंधन टीम व्यक्तिगत स्तर पर 'अच्छे लोग' या सभ्य हैं या नहीं, बल्कि पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ मानदंडों और साक्ष्यों पर आधारित होती है। उन्होंने पूछा कि क्या गुप्ता या उनकी जानकारी में किसी और ने पिछले पचास वर्षों में भारत अध्ययन विभागों के लेखों का अध्ययन किया है, ताकि वे स्थिति का भारतीय परिप्रेक्ष्य से मूल्यांकन कर सकें। इसका उत्तर आज भी वही है, नहीं, उन्होंने नहीं किया है!

सीख सीखी
भारत विज्ञान और भारत के प्रति हार्वर्ड के रुख की गहन जांच के परिणामस्वरूप, फाउंडेशन ने हार्वर्ड से प्रकाशित शोध की सार्वजनिक रूप से आलोचना करना शुरू कर दिया। 2002 में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब मल्होत्रा को हार्वर्ड के वार्षिक अमेरिकन एकेडमी ऑफ रिलीजन सम्मेलन में हिंदू धर्म के शीर्ष विद्वानों के साथ बहस करने के लिए आमंत्रित किया गया। यह वेंडी डोनिगर और राजीव मल्होत्रा के गुटों के बीच एक टकराव था। हार्वर्ड ने डोनिगर गुट का समर्थन करने का फैसला किया। डोनिगर के छात्र जेफरी कृपाल और सारा काल्डवेल को हार्वर्ड में प्रतिष्ठित पद मिले, जिनका उपयोग उन्होंने मल्होत्रा की आलोचनाओं के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान शुरू करने के लिए किया। हार्वर्ड के गुट के पूर्ण समर्थन से एक बहुआयामी हमला शुरू किया गया:

दार्शनिक मार्था नुसबॉम ने "द क्लैश विद इन" नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने अमेरिका में रहने वाले उन हिंदू विचारकों का वर्णन किया जिन्हें वह निशाना बनाना चाहती थीं, और राजीव मल्होत्रा को मुख्य व्यक्ति के रूप में नामित किया गया था।

जैक हॉली, जो उसी खेमे का एक और साथी था, ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक परियोजना शुरू की, जिसमें छात्रों की टीमों को विशिष्ट हिंदू संगठनों में भेजा गया ताकि उनके खिलाफ़ ऐसी जानकारी जुटाई जा सके जिसका इस्तेमाल उन्हें बेनकाब करने के लिए किया जा सके। जिन पांच समूहों को निशाना बनाया गया उनमें से एक इन्फिनिटी फाउंडेशन था। अन्य संगठनों में स्वामी दयानंद सरस्वती का अर्श विद्या गुरुकुलम भी शामिल था, जहां बाद में एफबीआई ने उनकी गतिविधियों के बारे में पूछताछ करने के लिए दौरा किया।

इस हमले का एक और पहलू पॉल कोर्टराइट द्वारा किया गया था, जिसे राजीव मल्होत्रा ने भगवान गणेश पर उनके हिंदू विरोधी लेखन के लिए बेनकाब किया था, जिसने अमेरिका भर में अपने कैंपस दौरों के दौरान सार्वजनिक रूप से कहा था कि उसने एफबीआई को रिपोर्ट किया था कि कुछ 'हिंदू चरमपंथी' उस पर हमला कर रहे थे।

तब से लेकर अब तक, भारतीय सरकार और भारतीय अरबपतियों ने दक्षिण एशिया के अध्ययन के लिए हार्वर्ड को भारी धनराशि दी है – जिसमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारें दोनों शामिल हैं। फिर भी, भारत का अध्ययन करने वाले इस 'उद्योग' की स्थिति पर कोई भी सरकारी या स्वतंत्र रिपोर्ट नहीं है, जिसमें विभिन्न विषयों – धार्मिक अध्ययन, इतिहास, मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मानवाधिकार और महिला अध्ययन आदि – के कई हजार पूर्णकालिक विद्वान शामिल हैं। दूसरी ओर, अकादमिक जगत में

चीन अध्ययन चीन के हाथों में सुरक्षित है, और पश्चिमी विद्वानों को बाहरी लोगों के रूप में रखा गया है जो प्रवेश पाने के लिए तरस रहे हैं।
हिंदू कार्यकर्ताओं की कोई भी प्रतिक्रिया सतही होने और दिखावटीपन को प्राथमिकता देने के कारण कोई खास असर नहीं डाल पाई है। याचिकाएँ जारी करना या विरोधियों को गुस्से भरे पत्र लिखना बेकार है। वे इस प्रक्रिया की गहरी बारीकियों को समझने में नाकाम रहे हैं। किसी मरीज की बीमारी से लड़ने के लिए तख्तियाँ लेकर नारे लगाना और कीटाणुओं के खिलाफ बोलना काफी नहीं है! डॉक्टर को बीमारी की कार्यप्रणाली को समझना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि कहाँ और कैसे हस्तक्षेप करना है। लेकिन एक आलसी, अयोग्य व्यक्ति (भले ही उसकी मंशा अच्छी हो) यह सब सीखने के लिए मेडिकल स्कूल नहीं जाएगा और फिर बीमारी को हराने के लिए तैयार नहीं होगा। वह बहुत जल्दी में रहता है, अक्सर उसमें योग्यता की कमी होती है, और वह जनता के बीच अपनी छवि बनाना चाहता है। और इसीलिए वह अस्पताल के बाहर खड़े होकर कीटाणुओं के खिलाफ नारे लगाता है। यह एक अजीब तुलना लग सकती है, लेकिन अगर आप भारतीय कार्यकर्ताओं के काम को ध्यान से देखें, तो उनमें से कई इस तस्वीर में फिट बैठते हैं।

8. अमेरिका में चीन का ट्रोजन हॉर्स

अवलोकन
पश्चिमी शिक्षा जगत में भारत की नाजुक स्थिति को शायद चीन के साथ तुलना करके सबसे अच्छी तरह समझाया जा सकता है, जिसने भी

शुरुआत में पिछड़ने के बावजूद कुशलतापूर्वक खुद को मजबूत स्थिति में पहुँचाया। इस अध्याय में, हम हार्वर्ड में चीन की स्थिति पर एक संक्षिप्त नज़र डालेंगे। हम दिखाएंगे कि कैसे चीनी अरबपति अपनी सरकार के साथ मिलकर रणनीति और कौशल का उपयोग करते हुए हार्वर्ड के कार्यक्रमों को चीन के हितों की ओर ले जाते हैं। यह विरोधाभासों का एक महत्वपूर्ण अध्ययन है जो भारत के सामने मौजूद गंभीर स्थिति को समझने में सहायक होता है।

हमारे समय का एक प्रमुख घटनाक्रम चीन द्वारा अपनी तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन करना है, उदाहरण के लिए, हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण और अमेरिकी विमानवाहक पोतों के मॉडल पर लक्ष्य अभ्यास। इससे चीन एक महाशक्ति बनने की राह पर अग्रसर हो गया है। चीन की स्थिति में बदलाव के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि उसे अब पश्चिमी देशों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत, पश्चिमी व्यवसायों को चीनी बाजार तक पहुंच की आवश्यकता है और उन्होंने यह भी दिखाया है कि यदि आवश्यक हुआ तो वे समझौता करने को भी तैयार हैं। पश्चिमी व्यापार जगत के नेताओं के व्यवहार पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) का ही नियंत्रण है। चीनी बुद्धिजीवियों में यह धारणा है कि अब शेष विश्व के लिए एक शक्तिशाली चीन की विश्वदृष्टि और संस्कृति को अपनाना आवश्यक हो गया है। लेकिन यह सब रातोंरात नहीं हुआ। और हार्वर्ड विश्वविद्यालय का उपयोग चीन ने अमेरिकी जनमत को प्रभावित करने की अपनी सुनियोजित रणनीति के तहत किया है।

अमेरिकी विश्वविद्यालयों के कामकाज का अध्ययन करने के बाद, चीनियों ने पाया कि वे अपने धनदाताओं और विचारधाराओं के हितों की पूर्ति के लिए व्यावसायिक संगठनों की तरह संचालित होते हैं। विशेष रूप से हार्वर्ड, अपने बहुराष्ट्रीय नेटवर्क और दुनिया भर के स्कूलों, कंपनियों,

थिंक टैंकों, जनता और सरकारों पर प्रभाव के मामले में अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में कहीं अधिक योगदान दे सकता है। यह अध्याय विस्तार से बताता है कि चीनी वित्त पोषण ने प्रभाव के इन सभी क्षेत्रों से संबंधित निम्नलिखित विशिष्ट लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया है:
हार्वर्ड में, चीनी सरकार के दृष्टिकोण को कभी-कभी चीन पर एकमात्र प्रासंगिक दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। चीन में मानवाधिकारों के हनन का अध्ययन शायद ही कभी किया जाता है और वास्तव में उन्हें छिपाया गया है। लेकिन हार्वर्ड नियमित रूप से ऐसे मुद्दों पर भारत की आलोचना करता है। अमेरिका-चीन सम्मेलनों ने भी चीन की छवि को बेहतर बनाने में योगदान दिया है।
हार्वर्ड चीन के विकास में सहायक प्रौद्योगिकी पर चीनी छात्रों और सरकारी अधिकारियों को शिक्षित करना जारी रखे हुए है। इससे चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। लेकिन हार्वर्ड चीन को मानविकी और सामाजिक विज्ञान के विषय में व्याख्यान नहीं देता है।
चीन ने हार्वर्ड में वोकवाद को वित्त पोषित किया है और हार्वर्ड नेटवर्क का उपयोग करके अमेरिका में इसका प्रसार किया है। इससे अमेरिकी जीवन के हर पहलू में पैठ बनाने में मदद मिली है।
हार्वर्ड और अन्य अमेरिकी विश्वविद्यालयों के चीनी सरकार और सेना के साथ घनिष्ठ संबंध हैं और उन्हें उनसे धनराशि प्राप्त होती रही है। चीन को सैन्य प्रौद्योगिकी प्रदान करने वाले अमेरिकी विश्वविद्यालय भारत के लिए चिंता का विषय होने चाहिए।
अमेरिकी थिंकटैंक और मीडिया के प्रतिनिधियों को मंचों में भाग लेने के लिए चीन में आमंत्रित किया जाता है, जिससे चीन के प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होती है।
आगामी अध्यायों में इन सभी बातों की तुलना हार्वर्ड द्वारा भारत के प्रति

किए गए व्यवहार से की जाएगी।

चीन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश किया
हार्वर्ड में चीन का प्रवेश नाटकीय रहा है। मई 1996 में हांगकांग की व्यवसायी नीना कुंग ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश किया।
बालों की चोटी बांधने वाली वह महिला बिना बुलाए हार्वर्ड यार्ड में आ गई। उनके पास वह विचार था जिसे रॉबर्ट डी. ब्लैकविल, जो कैनेडी स्कूल के लिए रूस और चीन कार्यक्रम चलाते हैं [बाद में भारत में अमेरिकी राजदूत बने], 'हार्वर्ड द्वारा अमेरिकी और चीनी अभिजात वर्ग के बीच संवाद को बढ़ावा देने का विचार' बताते हैं।
हार्वर्ड में कुंग की मुलाकात जिन लोगों से हुई, उन्होंने उन्हें हार्वर्ड के कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के डीन जोसेफ एस. नाइ जूनियर से मिलवाया। वह अपनी योजना प्रस्तुत करने के लिए उनके कार्यालय गईं। 33 लाख डॉलर की संपत्ति के साथ वह उस समय दुनिया की सबसे धनी महिलाओं में से एक थीं। बीजिंग में उनके उच्च स्तरीय संपर्क थे और उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ पहले ही घनिष्ठ संबंध बना लिए थे, क्योंकि वह उनके चुनाव प्रचार के लिए धन जुटाने में शामिल थीं।
कुंग द्वारा हार्वर्ड को दिया गया शुरुआती सात मिलियन डॉलर का दान चीन द्वारा निर्धारित शर्तों पर एक लंबे सहयोग की शुरुआत मात्र था। रॉबर्ट डी. ब्लैकविल के अनुसार, हार्वर्ड केनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में उनके कार्यक्रम को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के शीर्ष अधिकारियों से आश्चर्यजनक रूप से शीघ्र स्वीकृति मिली। उन्होंने समझाया: 'हम यहां 20-25 साल के युवाओं से नहीं निपट रहे हैं। ये वरिष्ठ चीनी सैन्य अधिकारी और सिविल सेवक हैं। वे बहुत गंभीर लोग हैं। वे कोई भी काम लापरवाही से नहीं करते।' वास्तव में, तब से हार्वर्ड में चीन द्वारा किया

गया कोई भी काम लापरवाही से नहीं हुआ है। यहां तक कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग का हार्वर्ड के साथ घनिष्ठ संबंध भी 2012 में उनकी बेटी के वहां रहते हुए कुशलतापूर्वक विकसित किया गया था।

पिछले पच्चीस वर्षों में, चीन ने हार्वर्ड में एक दीर्घकालिक रणनीति अपनाई है जिसके लिए दूरदर्शिता, निरंतरता, कार्यान्वयन के बारीक पहलुओं पर ध्यान देने के साथ-साथ अल्पकालिक कठिनाइयों को सहने की सहनशीलता की आवश्यकता होती है। चीन ने पश्चिम के साथ बड़े ही चालाकीपूर्ण और सुनियोजित तरीके से संबंध स्थापित किए। हाल तक, प्रत्येक अमेरिकी प्रशासन को यह विश्वास था कि वह चीन को मुक्त उद्यम और बहुपक्षीय संस्थानों की वैश्विक प्रणाली में एक प्रमुख मित्र के रूप में विकसित करने में मदद कर रहा है। इसके विपरीत, यह तर्क कि वह अपने सबसे बड़े दुश्मन को बढ़ावा दे रहा है और उसे मजबूत बना रहा है, को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया।

लेकिन चीन के बारे में बाकी सब चीजों की तरह, पश्चिमी शिक्षाविदों के साथ उसका रिश्ता भी जटिल और विरोधाभासी है। यह अपने नागरिकों के लिए दुनिया के सबसे सशक्त राष्ट्रवादी विचारों में से एक का निर्माण कर रहा है, जबकि तिब्बत, शिनजियांग और हांगकांग में भयानक मानवाधिकार उल्लंघन कर रहा है। इसी वजह से इसने वामपंथी सामाजिक विज्ञान के उन प्रचलित सिद्धांतों को सिरे से खारिज कर दिया है जिन्हें पश्चिम पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है। चीन की एक उल्लेखनीय उपलब्धि हार्वर्ड विश्वविद्यालय को अपने साथ जोड़ना है, जबकि हार्वर्ड बौद्धिक वामपंथ का गढ़ है। इस जुड़ाव के परिणामस्वरूप, हार्वर्ड के विद्वानों ने स्वीकार किया है कि चीन के साथ बातचीत करते समय उनके सामाजिक न्याय के विचार स्वीकार्य नहीं हैं।

आगे के अध्यायों में हार्वर्ड और भारत की विभिन्न संस्थाओं – सरकार,

उद्योग, मीडिया और शिक्षा – के बीच के जटिल संबंधों पर चर्चा की जाएगी। इन अध्यायों को समझने के लिए, पाठक को यह समझना आवश्यक है कि चीन का हार्वर्ड के साथ एक बिल्कुल अलग तरह का रिश्ता है। इस संस्था के साथ चीन का व्यवहार उसके प्रति अपार विश्वास दर्शाता है और उसने प्रभाव खरीदने के अपने नापाक एजेंडे को साकार करने के लिए भारी संसाधन लगाए हैं। इसे 'तीव्र शक्ति' कहा गया है और यह मात्र सौम्य शक्ति से कहीं अधिक व्यापक है। चीन की रणनीति दीर्घकालिक है और उसके तरीके दबावपूर्ण, अपारदर्शी और कठोर हैं। सच कहें तो, हार्वर्ड में भारत की तुलना में चीन की कहीं अधिक मजबूत स्थिति देखकर हमें आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन हमें एक कहीं अधिक चिंताजनक बात पता चली: हार्वर्ड में चीन की पैठ उसके लिए भारत में प्रभाव और तोड़फोड़ के जरिए घुसपैठ करने का एक रास्ता भी है।
हाल ही में अमेरिका को इस बात का एहसास होना शुरू हुआ है कि उसके सर्वश्रेष्ठ संस्थान चीनी धन से प्रभावित हो चुके हैं। 2019 में प्रकाशित हूवर इंस्टीट्यूशन की एक रिपोर्ट में अमेरिकी थिंकटैंक, मीडिया और शैक्षणिक संस्थानों में चीनी घुसपैठ को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गई थीं। इस घुसपैठ का केंद्र हार्वर्ड कैनेडी स्कूल है, जहां चीन अपने सुनियोजित एजेंडे को अभूतपूर्व पैमाने पर लागू करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अमेरिकी बुद्धिजीवियों को नियुक्त करता है।
हार्वर्ड के चीन जनवादी गणराज्य (सीसीपी) के साथ संबंध गहरे, व्यापक और पुराने हैं। अब इसे अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा है, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, यह भारत के लिए भी खतरा है। यह अध्याय इस बात को उजागर करेगा कि चीन के साथ हार्वर्ड की घनिष्ठता लोकतंत्र, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के उस रक्षक के रूप में उसकी छवि का उल्लंघन करती है, जिसे वह दुनिया, और विशेष

रूप से भारत के सामने प्रस्तुत करता है। दुर्भाग्य से, भारतीय अभिजात वर्ग इस बात से अनभिज्ञ है, और इसके विपरीत, भारत को न केवल पश्चिम बल्कि चीन के प्रति भी असुरक्षित बनाने में भागीदार है।

हार्वर्ड में चीन के प्रभाव का उदाहरण तेंग बियाओ की कहानी से मिलता है, जो एक चीनी असंतुष्ट और कार्यकर्ता थे और 'स्कॉलर्स एट रिस्क' कार्यक्रम के माध्यम से हार्वर्ड आने के लिए अपने देश से भाग गए थे। हार्वर्ड पहुँचने पर, बियाओ को अपने देश की आलोचना करने की पूरी स्वतंत्रता की उम्मीद थी; आखिरकार, यही वह कारण था जिसके लिए वे चीन से भागे थे। इसलिए, उन्होंने हांगकांग के साथी असंतुष्टों के साथ हार्वर्ड में एक चर्चा का आयोजन किया, जिनका चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) की आलोचना करने का एक साझा इतिहास था। लेकिन बियाओ की घोर निराशा के लिए, हार्वर्ड लॉ स्कूल के एसोसिएट डीन ने उन्हें यह कहते हुए कार्यक्रम रद्द करने का आदेश दिया कि इससे विश्वविद्यालय को 'शर्मिंदगी' होगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने और मानवाधिकारों के लिए खड़े होने का यही हाल है! हार्वर्ड क्रिमसन की एक रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है:

… तेंग के कार्यक्रम का रद्द होना … इस बात को उजागर करता है कि विश्वविद्यालय सीसीपी की पहुँच से अछूता नहीं है। … यह इस बात की याद दिलाता है कि हार्वर्ड का चीन के साथ संबंध शून्य में नहीं है। भले ही उच्च शिक्षा कभी-कभी अंतरराष्ट्रीय संवाद और अनौपचारिक आलोचना के लिए एक वैकल्पिक मंच प्रदान करती है, विश्वविद्यालय राज्य और शिक्षा जगत, राजनीति और सत्य के परस्पर विरोधी हितों से पूरी तरह बच नहीं सकता है।

हार्वर्ड को चीन से भारी मात्रा में धन प्राप्त होने की कई रिपोर्टें सामने आई हैं, जो इस बात का संकेत देती हैं कि संस्थान में व्याप्त भ्रष्टाचार और

लालच ने चीन को उच्च पदों पर बैठने का मौका दिया है, जहाँ से वे सभी निर्णय ले रहे हैं। हार्वर्ड के बुद्धिजीवियों को प्रभावित करने की यह रणनीति कई दशकों से सुनियोजित तरीके से अपनाई जा रही है।
चीन के राजनीतिक रुख को पश्चिम के अनुकूल तरीके से प्रस्तुत करने के लिए विद्वानों को धनराशि दी जाती है; फिर इन कथनों को विद्वानों की विश्वसनीयता और मीडिया नेटवर्क तक उनकी पहुंच का उपयोग करके व्यापक रूप से प्रचारित किया जाता है। वास्तव में, हार्वर्ड ने अमेरिकी अभिजात वर्ग के व्यापक वर्ग को लक्षित करते हुए, सीसीपी के एक महत्वपूर्ण जनसंपर्क अंग के रूप में कार्य किया है।
आगे के अध्यायों में हम विस्तार से बताएंगे कि हार्वर्ड किस प्रकार लगातार और व्यापक रूप से मानवाधिकारों के मुद्दे पर भारत पर हमला करता है और लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करने के लिए उसकी निंदा करता है। दूसरी ओर, चीन समर्थक विद्वान चीन के मामले में इन्हीं मुद्दों पर अपना नियंत्रण रखते हैं और इन चिंताओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के सभी प्रयासों को दबा देते हैं। उदाहरण के लिए, भारत पर अपनी चर्चाओं के विपरीत:
हमें ऐसा नहीं लगता कि हार्वर्ड चीन में लोकतंत्र समर्थक असंतुष्टों को उजागर करने के लिए सम्मेलनों और सेमिनारों का आयोजन करने में जल्दबाजी करेगा।
हार्वर्ड विश्वविद्यालय तिब्बती स्वतंत्रता, हांगकांग में लोकतंत्र आंदोलन, ताइवान की स्वतंत्रता, चीन द्वारा सामाजिक ऋण प्रणाली के माध्यम से अपने नागरिकों की निगरानी, चीन द्वारा मंगोलियाई संस्कृति और भाषा पर की जा रही कार्रवाई या उइघुर मुसलमानों के मानवाधिकार संकट जैसे मुद्दों पर गहराई से विचार नहीं करता है।
इसमें उन समस्याओं पर चर्चा नहीं की गई है जैसे कि प्रसिद्ध चीनी

नागरिकों का अचानक गायब हो जाना और फिर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए दोबारा सामने आना।
हार्वर्ड, चीनी सरकार द्वारा जैक मा (अलीबाबा समूह के अरबपति संस्थापक) को अत्यधिक सफल और मुखर होने के कारण चुप कराने और उन पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों पर चुप्पी साधे हुए है।
इस बात पर कोई चर्चा नहीं हो रही है कि चीन में एक सफल स्कूल ट्यूशन कंपनी को रातोंरात गैर-लाभकारी संस्था बनने के लिए कैसे मजबूर होना पड़ा।

Harvard Praises China	• Harvard President Lawrence S. Bacow tells Xi Jinping it is 'Admirable that the Chinese Government Attaches Great Importance to Higher Education and Makes Huge Efforts in this Regard' • Confirmed Harvard will Continue Exchanges and Cooperation with Chinese Educational and Scientific Research Institutions*
Harvard Silent or Muted	• Tibet, Dalai Lama • Inner Mongolian Language/Culture • Pro-Democracy Movement in Hong Kong • Taiwanese Independence • Uyghur Muslims • Disappearance of Dissident Citizens
Harvard Helps China	• Training CCP Fellows that Run Uyghur Detention Camps • Social Credit System • Propaganda for CCP • Chinese Geopolitical Interests in India • Solving China's Environmental, Logistics, and Infrastructure Problems

सारणी के अंदर फुटनोट चिह्न ,*
विशेष रूप से हार्वर्ड का इतिहास स्वार्थ को सर्वोपरि रखने का रहा है: इसने दक्षिण अफ़्रीकी रंगभेद का समर्थन तब भी किया जब अन्य संस्थान अपना निवेश वापस ले रहे थे और परिसर में विरोध प्रदर्शनों के बावजूद

भी। हालाँकि, चीन के साथ इसके संबंध को जो बात अलग बनाती है, वह है हार्वर्ड द्वारा चीनी शासन का सक्रिय समर्थन। यहाँ तक कि द हार्वर्ड क्रिमसन भी हार्वर्ड की बुनियादी मानवीय शालीनता की कमी के लिए आलोचना करता है।

फिर भी चीन के प्रति उसका रवैया— अपने कार्यों में इतने घृणित शासन का मौन समर्थन, प्रचारवादी संस्थानों की प्रशंसा करने के लिए अपने प्रभावशाली ब्रांड का उपयोग करने की तत्परता, मानवीय आपदा के मुख्य निष्पादकों के साथ मेलजोल— हमारे इतिहास पर एक विशेष रूप से शर्मनाक धब्बा है, बुनियादी मानवीय शालीनता के प्रति चिंताजनक उपेक्षा है।

अमेरिकी विश्वविद्यालय चीनी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के परिणामों को भलीभांति समझते हैं। उदाहरण के लिए, जब कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन डिएगो (यूसीएसडी) ने दलाई लामा को अपने परिसर में आमंत्रित किया, तो इससे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) नाराज हो गई। परिसर में कई चीनी छात्र तिब्बत पर सीसीपी के रुख का समर्थन करने और दलाई लामा की यात्रा का विरोध करने के लिए संगठित हुए।

यूसीएसडी में पढ़ने वाले कई विदेशी चीनी छात्र दलाई लामा को विश्व सद्भाव के दूत के रूप में नहीं, बल्कि चीन को विभाजित करने के इच्छुक अलगाववादी और अपने देश के सामंती अतीत के प्रतीक के रूप में देखते हैं। यह दृष्टिकोण चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा प्रचारित किया जाता है, जो अपनी सीमाओं के भीतर तिब्बत और दलाई लामा के बारे में, साथ ही 1989 के तियानमेन स्क्वायर नरसंहार और ताइवान के साथ संबंधों के बारे में क्या कहा जा सकता है और क्या नहीं, इस पर कड़ा नियंत्रण रखती है।

"क्या चीन दलाई लामा की मेजबानी करने के लिए एक अमेरिकी

विश्वविद्यालय को दंडित कर रहा है?" शीर्षक वाले एक लेख में उन परिणामों का वर्णन किया गया है जिनका सामना यूसीएसडी को करना पड़ा, जब चीन ने अन्य उपायों के साथ-साथ उसके आगंतुक विद्वानों के वीजा पर रोक लगा दी। यह एक स्पष्ट संदेश देने का तरीका था कि चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए। हार्वर्ड ने इस नीति का सावधानीपूर्वक पालन किया है।

हार्वर्ड के फेयरबैंक सेंटर फॉर चाइनीज स्टडीज ने पिछले दो दशकों में तिब्बत पर कई सम्मेलन आयोजित किए हैं जो चीनी हितों के अनुरूप तो हैं, लेकिन तिब्बतियों को इनसे कोई ठोस लाभ नहीं मिला। इन मंचों की संरचना, मुद्दों की रूपरेखा और संचालन के संदर्भ में तिब्बती वक्ताओं को सीमित रखा गया था। दूसरी ओर, इन मंचों ने मानवाधिकारों के सभी हनन के लिए चीनी सरकार के आधिकारिक रुख को बिना किसी पश्चाताप या शर्म के प्रस्तुत किया। उदाहरण के लिए, वक्ताओं में से एक बीजिंग में संयुक्त मोर्चा कार्य विभाग के राष्ट्रीयता और धर्म ब्यूरो के प्रमुख झू शियाओमिंग थे, जो चीन की तिब्बत नीति के आंतरिक प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। उनका रुख था:

मेरा मानना है कि वार्ता में मुख्य रूप से इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि दलाई लामा और उनके अनुयायी स्वतंत्रता की अपनी मांग कैसे छोड़ें, अलगाववादी गतिविधियां बंद करें और मातृभूमि के एकीकरण तथा राष्ट्रीय एकता और प्रगति में योगदान दें, न कि तिब्बत की कानूनी और राजनीतिक स्थिति से संबंधित प्रश्न पर। तिब्बत चीन का अभिन्न अंग है। अमेरिकी कांग्रेस चीनी सरकार से दलाई लामा के साथ किन प्रश्नों पर वार्ता करने की अपेक्षा करती है? तिब्बत की स्थिति, 'उच्च-स्तरीय स्वायत्तता', या अन्य प्रश्न? ये सभी प्रश्न वार्ता योग्य नहीं हैं।

झू शियाओमिंग ने तो यहाँ तक दावा किया है कि चीनी शासन के अधीन

तिब्बत प्रगति और मानव विकास का एक ऐसा आदर्श था जो तिब्बती स्वशासन के तहत कभी नहीं देखा गया। दूसरे शब्दों में, तिब्बत पर चीन का कब्ज़ा उसके अपने लाभ के लिए था। चूंकि चीनी सेना तिब्बती पक्ष से संख्या में कहीं अधिक थी, इसलिए तिब्बत की चीन से स्वायत्तता या चीन के भीतर एक अलग राज्य के रूप में उसके अस्तित्व से संबंधित सभी सवालों को टालना, झूठा बताकर खारिज करना या अनदेखा करना आसान था। तिब्बत में हान चीनी लोगों द्वारा किए गए मानवाधिकारों के व्यापक उल्लंघन और तिब्बती संस्कृति के विनाश पर कोई चर्चा नहीं हुई। बेशक, हार्वर्ड ने कभी भी चीन के भीतर हाशिए पर रहने वाले लोगों की पहचान गढ़ने या वहाँ की महिलाओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन का अध्ययन करने का प्रयास नहीं किया, जैसा कि उसने भारत के मामले में किया है। न ही इन अपराधों के लिए चीनी संस्कृति या सभ्यता को दोषी ठहराना आवश्यक समझा गया है, जिस तरह भारत में सभी गलतियों को किसी न किसी रूप में उसकी प्राचीन संस्कृति से जोड़ा जाता है।

हार्वर्ड कैनेडी स्कूल दो सीसीपी अधिकारियों, एर्केन तुनियाज़ और याओ निंग को प्रशिक्षित करने के लिए कुख्यात है, जो उइघुर मुस्लिम नजरबंदी शिविरों की देखरेख करते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के स्नातकों ने '2017 से नौ नजरबंदी केंद्रों का निर्माण या विस्तार किया है'।

शिनजियांग में लगभग 10 लाख जातीय अल्पसंख्यक लोगों के लिए चीन के नजरबंदी शिविरों की देखरेख में शामिल दो अधिकारियों ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रतिष्ठित फैलोशिप पर अध्ययन किया है...

ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के अनुसार, याओ निंग, जो एक स्थानीय कम्युनिस्ट पार्टी सचिव हैं और जिन्हें इस वर्ष बीजिंग द्वारा

शिनजियांग में उनके काम के लिए सम्मानित किया गया था, ने 2010 और 2011 के बीच हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ऐश सेंटर फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड इनोवेशन में एशिया फेलो के रूप में अध्ययन किया था। क्षेत्रीय अध्यक्ष एर्केन तुनियाज़ ने 2012 में ऐश सेंटर में न्यू वर्ल्ड फेलो के रूप में कुछ महीने बिताए। शिनजियांग के अध्यक्ष, पार्टी सचिव चेन क्वांगुओ के बाद क्षेत्रीय सर्वोच्च अधिकारी हैं। तुनियाज़ ने शिनजियांग के नजरबंदी शिविरों का बचाव करते हुए उन्हें "आतंकवाद-विरोधी और कट्टरपंथ-विरोधी उपाय" बताया। 2012 में प्रकाशित एक लेख में, ऐश सेंटर ने कहा कि तुनियाज़ और हार्वर्ड में उनके एक सहयोगी का शोध "उनके पेशेवर करियर को दिशा देने और नवाचार और लोकतांत्रिक शासन पर सेंटर के शोध कार्यों को समृद्ध करने का वादा करता है।"

36 वर्षीय याओ ने चीन के सिंघुआ विश्वविद्यालय में लोक नीति में पीएचडी के हिस्से के रूप में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। … उन्होंने शिनजियांग के काशगर प्रान्त में काम किया, पहले येंगिशेहर काउंटी में… जहाँ मुख्य रूप से उइघुर आबादी रहती है, और फिर मरालबेशी काउंटी में, एस्पी (ASPI) की रिपोर्ट में कहा गया है। 2019 की शुरुआत में, याओ निंग को मरालबेशी काउंटी का पार्टी सचिव नियुक्त किया गया… जहाँ ASPI के शोधकर्ताओं ने 2017 के बाद से निर्मित या विस्तारित नौ नजरबंदी सुविधाओं की पहचान की है," रिपोर्ट में आगे कहा गया है।

हार्वर्ड के रॉय और लीला ऐश सेंटर फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड इनोवेशन का दावा है कि चीनी प्रतिभागियों के लिए उसके प्रशिक्षण और फेलोशिप कार्यक्रमों में, उम्मीदवारों को बीजिंग स्थित अमेरिकी दूतावास द्वारा पूरी तरह से जांच-पड़ताल के बाद ही स्वीकार किया जाता है। फिर भी, मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के रिकॉर्ड वाले चीनी अधिकारी किसी

तरह इस जांच-पड़ताल से बच निकलते हैं, जबकि अमेरिकी सरकार ने खुले तौर पर बीजिंग पर शिनजियांग को 'खुली जेल' में बदलने का आरोप लगाया है।

ऐश सेंटर ने अपने कार्यक्रम में दो चीनी फेलो के साथ अपने संबंधों का प्रदर्शन करते हुए कहा कि वे उसके द्वारा चयनित 'न्यू वर्ल्ड फेलो' में शामिल हैं। हार्वर्ड का कहना है कि उसने उन्हें लाया है।

सरकारी अधिकारियों, नीति निर्माताओं और होनहार नए नेताओं की एक बड़ी संख्या को प्रासंगिक अनुसंधान में अपने कौशल को और बेहतर बनाने और अपनी क्षमता को व्यापक बनाने के लिए यह कार्यक्रम उपलब्ध है... यह फैलोशिप कार्यक्रम न केवल चीनी पीढ़ी को प्रासंगिक शैक्षणिक और सरकारी अनुभव प्रदान करता है, बल्कि यह भविष्य में सहयोग और ज्ञान साझा करने के लिए अमेरिका और चीन के बीच एक सेतु का काम भी करता है।

विडंबना और विडंबना के एक दिलचस्प मोड़ में, एर्केन तुनियाज़, जिन्हें हार्वर्ड ने 'अमेरिका-चीन संबंधों को जोड़ने' के लिए प्रशिक्षित किया था, बाद में अमेरिकी वित्त विभाग की विशेष रूप से नामित नागरिकों (एसडीएन) की सूची में डाल दिया गया। एसडीएन विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय के तहत अमेरिका द्वारा बनाए रखी गई एक ब्लैकलिस्ट है।

विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) लक्षित देशों के स्वामित्व या नियंत्रण वाले या उनके लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों और कंपनियों की सूची प्रकाशित करता है। यह उन व्यक्तियों, समूहों और संस्थाओं को भी सूचीबद्ध करता है, जैसे कि आतंकवादी और मादक पदार्थों के तस्कर, जिन्हें गैर-देश-विशिष्ट कार्यक्रमों के तहत नामित किया गया है। सामूहिक रूप से, ऐसे व्यक्तियों और कंपनियों को "विशेष रूप से नामित नागरिक"

या "एसडीएन" कहा जाता है। उनकी संपत्तियों को अवरुद्ध कर दिया जाता है और अमेरिकी नागरिकों को आमतौर पर उनके साथ लेन-देन करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

तुनियाज़ की संपत्ति अब अमेरिका में फ्रीज कर दी गई है, और हार्वर्ड सहित हर अमेरिकी संस्थान को उसके साथ लेन-देन करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

हार्वर्ड ने चीन को नाराज़ करने के डर से ऐसे हार्वर्ड फेलो से खुद को अलग करने के लिए कोई बयान तक जारी नहीं किया। यह उस तरीके के बिल्कुल विपरीत है जिस तरह हार्वर्ड के विद्वान और कई कार्यक्रम और आयोजन नियमित रूप से भारत पर हमले करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हार्वर्ड में भारत पर सबसे पसंदीदा विषयों में नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA) की आलोचना, कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना, हिंदू राष्ट्रवाद, जातिगत दुर्व्यवहार, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार आदि शामिल हैं। हार्वर्ड ने नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनने से पहले ही ब्लैकलिस्ट कर दिया था और भारतीय अदालतों द्वारा दोषमुक्त किए जाने के बावजूद भी, मानवाधिकारों के हर संभव उल्लंघन के लिए उन पर और उनकी पार्टी, भाजपा पर व्यक्तिगत रूप से हमला करना जारी रखा है।

हार्वर्ड का एक और पाखंड यह है कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थक होने का दावा करता है, और इसी तर्क का इस्तेमाल उसने भारतीय अर्थशास्त्र के प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी को बर्खास्त करने के लिए किया। हार्वर्ड की शिकायत उनके इस बयान पर थी कि भारत के मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। छात्रों में स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देने के लिए हार्वर्ड में इस विषय पर बहस होनी चाहिए थी। आखिर, भारतीय मुसलमान अपने पूर्वजों को मध्य पूर्व के विदेशी आक्रमणकारी कहना

पसंद नहीं करते। इसलिए, उनके पूर्वज भारत के मूल निवासी यानी हिंदू ही तो हो सकते हैं?
हम हार्वर्ड के चीन के सामने आत्मसमर्पण का समर्थन नहीं करते, लेकिन हम यह बताना चाहते हैं कि भारत को यह सीखना होगा कि खेल कैसे खेला जाता है। एक ऐसा मध्य मार्ग खोजना होगा जो स्वार्थ और शैक्षणिक स्वतंत्रता के संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखे।

चीनी वित्तपोषण
चीन, राज्य-नियंत्रित संस्थाओं और निजी व्यवसायों के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से अमेरिकी संस्थानों को वित्त पोषित करता है। उदाहरण के लिए, ऐश सेंटर के दानदाताओं में से एक चाइना सदर्न पावर ग्रिड कंपनी लिमिटेड है, जो पूरी तरह से चीनी सरकार के स्वामित्व, संचालन और वित्त पोषित है, और जिसका प्रबंधन 'चीन की केंद्रीय सरकार द्वारा सीधे नियुक्त' किया जाता है।
इसके अलावा, न्यू वर्ल्ड चाइना एंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट नामक एक चीनी कंपनी से भी दान प्राप्त हुआ है, जिसके बोर्ड में लगभग सभी सदस्य सीसीपी के सदस्य हैं। उदाहरण के लिए, इसके अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक, चेंग कार-शुन, सीसीपी के राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन के स्थायी समिति सदस्य के रूप में कार्य कर चुके हैं।
इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हार्वर्ड को चीन से प्राप्त लाखों डॉलर के विदेशी उपहारों का खुलासा न करने के कारण अमेरिकी न्याय विभाग की निगरानी में रखा गया। और दुर्भाग्य से, यह एकमात्र अमेरिकी संस्थान नहीं है जो चीनी प्रभाव में विकसित हो रहा है।
अमेरिकी शिक्षा विभाग के अनुसार, 2013 से चीनी निधियों को स्वीकार करने वाले शीर्ष तीन अमेरिकी विश्वविद्यालय हार्वर्ड विश्वविद्यालय, दक्षिणी

कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय हैं। स्टैनफोर्ड भी चीन के साथ एक बड़ा सहयोगी है। अमेरिकी सरकार प्रमुख अमेरिकी संस्थानों में चीन की घुसपैठ की गहराई और व्यापकता को लेकर चिंतित है।

शिक्षा विभाग के महाधिवक्ता रुबिनस्टीन ने रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष, सीनेटर रॉब पोर्टमैन (रिपब्लिकन-ओहियो) को लिखे पत्र में कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिकी शिक्षा प्रणाली में 'रणनीतिक रूप से निवेश' करती है और 'चीन के कुल खर्च की सटीक या पूर्ण जानकारी जनता के पास नहीं है क्योंकि चीन से दान स्वीकार करने वाले लगभग 70% कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने इसकी रिपोर्ट नहीं दी है।' पत्र में यह भी कहा गया है कि चीनी धन के साथ 'ऐसी शर्तें जुड़ी होती हैं जो शैक्षणिक स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकती हैं।'

अमेरिकी शिक्षण संस्थानों में चीन की घुसपैठ की जांच के लिए, शिक्षा विभाग ने विदेशी धन की जानकारी न देने के आरोप में हार्वर्ड और येल विश्वविद्यालयों के खिलाफ जांच शुरू की है। इन जांचों में अन्य संदिग्ध गतिविधियों का भी खुलासा हुआ है। उदाहरण के लिए, हार्वर्ड के रसायन विज्ञान और रासायनिक जीवविज्ञान विभाग के अध्यक्ष चार्ल्स एम. लिबर को विदेशी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की भर्ती के लिए चीनी सरकार के एक कार्यक्रम से अपने संबंधों के बारे में अमेरिकी रक्षा विभाग को "झूठे, मनगढ़ंत और धोखाधड़ी वाले बयान" देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। नैनो विज्ञान पर केंद्रित एक समूह का नेतृत्व करने वाले लिबर ने विश्वविद्यालय की जानकारी के बिना चीन के वुहान शहर में एक शोध प्रयोगशाला स्थापित की थी।

ये जांचें एक व्यापक जांच का हिस्सा हैं, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 6.5 अरब डॉलर की पहले से अज्ञात विदेशी धनराशि का खुलासा हुआ

है, जिसमें से अधिकांश चीन, सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात से आई है। जांच के दायरे में आने वाले अन्य विश्वविद्यालयों में जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय, टेक्सास ए एंड एम विश्वविद्यालय, कॉर्नेल विश्वविद्यालय, रटगर्स विश्वविद्यालय, एमआईटी और मैरीलैंड विश्वविद्यालय शामिल हैं। अमेरिकी अधिकारी अमेरिकी कॉलेजों में आने वाले चीनी छात्रों पर भी सख्ती बरत रहे हैं।

चीन अमेरिका में वोकवाद को वित्त पोषित करता है
विदेशी तानाशाह अक्सर ऐसे तंत्रों के माध्यम से निगमों को वित्त पोषित करते हैं जो देखने में भले ही हानिरहित लगें। रामास्वामी कहते हैं कि 'विदेशी तानाशाह जागरूक निगमों की नैतिक प्रतिष्ठा का उपयोग अपने स्वयं के उत्पीड़न को छिपाने और वैश्विक मंच पर संयुक्त राज्य अमेरिका की नैतिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं।' इसका एक अच्छा उदाहरण यह है कि सीसीपी अन्य देशों में जागरूकवाद को प्रोत्साहित करती है लेकिन अपने देश में इस पर प्रतिबंध लगाती है। रामास्वामी बताते हैं:
चीनी बाज़ार के संरक्षक के रूप में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए निगमों को अपने मूल्यों को विदेशों में फैलाने के लिए प्रेरित करती है। यह काम वह केवल जागृत पूंजीवाद के उदय के माध्यम से करती है - डिज्नी, मैरियट, एप्पल या एनबीए जैसी कंपनियां संयुक्त राज्य अमेरिका में "प्रणालीगत नस्लवाद" और ट्रांसफोबिया जैसे अन्याय के खिलाफ अपना नैतिक आक्रोश व्यक्त करती हैं, जबकि चीन में यातना शिविरों, धार्मिक अल्पसंख्यकों के जबरन बंध्याकरण और निर्दोष नागरिकों की पिटाई जैसे मानवाधिकारों के हनन पर पूरी तरह से चुप रहती हैं।

विदेशी सत्तावादी राष्ट्र अमेरिका के नए हितधारक मॉडल की कमजोरियों को अमेरिका से कहीं बेहतर समझते हैं और हितधारक के रूप में अपनी स्थिति का निर्दयतापूर्वक लाभ उठाकर चुनिंदा मुद्दों का निर्धारण करते हैं, जिनका समर्थन जागरूक पूंजीपति करते हैं। एनबीए अपने सभी कोर्ट पर "ब्लैक लाइव्स मैटर" का नारा लगा सकता है क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी को इस संदेश से कोई खतरा नहीं है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी एनबीए या उसके किसी भी कर्मचारी को हांगकांग, ताइवान या उइगरों के समर्थन में एक शब्द भी बोलने की अनुमति नहीं देगी।

तिब्बत को उन वर्जित विषयों की सूची में शामिल किया जा सकता है जो हाल तक चीन विरोधी आंदोलनों के केंद्र में थे। लेकिन ऐसा लगता है कि चीन अमेरिका में उन आवाजों को दबाने में सफल रहा है। इससे पता चलता है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अमेरिकी और अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने दीर्घकालिक संदेश फैलाने के लिए किस प्रकार सफलतापूर्वक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया है। रामास्वामी संक्षेप में कहते हैं कि 'अमेरिका में जागरूक पूंजीपति विदेशों में अपने तानाशाह मित्रों के साथ मिलकर पैसा कमाते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे वे अपने देश में दुनिया को बचा रहे हों।'

वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक लेख के अनुसार, चीन के एक नए कानून ने हार्वर्ड और प्रिंसटन सहित अमेरिका के शीर्ष विश्वविद्यालयों को उन पाठ्यक्रमों पर चेतावनी लेबल लगाने के लिए बाध्य कर दिया है जिनमें चीन द्वारा संवेदनशील माने जाने वाली कोई भी सामग्री शामिल है। यह एक लंबी सूची है जिसे चीन लगातार बढ़ाता रहता है। 'इसके जवाब में, चीनी राजनीति का अध्ययन कर रहे प्रिंसटन के छात्रों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपने असाइनमेंट पर अपने असली नामों के बजाय गुप्त कोड का उपयोग करना शुरू कर दिया है।'

रामास्वामी कहते हैं: 'वही कंपनियां जिन्होंने उपभोक्ताओं की प्रौद्योगिकी तक पहुंच में सुधार किया है और उसकी कीमतें कम की हैं, वही कंपनियां विचारों के बाजार में विकल्पों को सीमित कर रही हैं और वैचारिक असहमति की "कीमत" बढ़ा रही हैं।' वे इसे 'विचार-निर्धारण' कहते हैं और उनका मानना है कि मूल्य-निर्धारण से लड़ने के लिए बनाए गए एंटीट्रस्ट कानूनों का विस्तार करके विचार-निर्धारण को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए।
यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चीन ने अमेरिकी परिसरों में अमेरिका को गेमिंग के माध्यम से प्रभावित किया है और चीन के गहरे जड़े जमाए जाल को हटाना न तो त्वरित होगा और न ही आसान।

हार्वर्ड कैनेडी स्कूल का चीन कार्यक्रम
हार्वर्ड कैनेडी स्कूल ने चीनी हितों की बेहतर सेवा करने के लिए अपने बहुआयामी चीन कार्यक्रम में संशोधन किया है। पहले के कुछ चीन संबंधी कार्यक्रम, जिन्हें रद्द कर दिया गया है, चीनी नौकरशाहों को शासन, नेतृत्व, संकट प्रबंधन और स्थिरता में प्रशिक्षण देने से संबंधित थे। ये कार्यक्रम एचकेएस वेबसाइट पर 'पिछली परियोजनाओं' के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं।

China's Carrots	China's Sticks
Strategic Funding	Block Access to China, Libraries, and Archives
Scholars Bought Out	Deny Visas to Scholars
Soft Lobbying	Close Joint Ventures that Give US Universities Access to China
Foreign Thinktanks, Institutions, Government, and Universities Bought Out	Use US Business Leaders that are Dependent on Chinese Markets to Put Pressure on Harvard

नए प्रोजेक्ट इस बात का प्रमाण हैं कि चीन एक मजबूत, विवेकपूर्ण और केंद्रित रणनीति अपनाते हुए हार्वर्ड का उपयोग अपने रणनीतिक हितों को पूरा करने के लिए कर रहा है, न कि इसके विपरीत। प्रोजेक्ट के विवरण से यह स्पष्ट है कि चीन ही सब कुछ नियंत्रित कर रहा है और हार्वर्ड से निम्नलिखित अपेक्षाएं लेकर वह पूरी तरह स्पष्ट है:
चीन को विश्व का अग्रणी प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तक बनाएं
चीन की प्राथमिकताओं के अनुसार उसकी पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करें।
चीन की रसद और बुनियादी ढांचे में मदद करना, जैसे कि चीन की सामाजिक ऋण प्रणाली को सुव्यवस्थित करना।
शिक्षा प्रणाली के बुनियादी ढांचे के लिए परोपकार निधि की सुविधा प्रदान करना
यह दर्शाकर कि चीनी जनता अपनी सरकार का समर्थन करती है और साम्यवाद चीन के उत्थान के लिए एक शानदार व्यवस्था रही है, चीन के प्रचार तंत्र का विस्तार बनें।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चीन इन लक्ष्यों में से प्रत्येक को परिभाषित करता है और उनकी सफलता की निगरानी के लिए मानदंड प्रदान करता है।
अमेरिका में चीन के प्रचार तंत्र के काम करने का एक अच्छा उदाहरण हांगकांग राज्य की चीन ग्लोबल फिलैंथ्रोपी इंस्टीट्यूट (सीजीपीआई) के साथ साझेदारी करके ग्लोबल लीडर्स इन फिलैंथ्रोपी प्रोग्राम की शुरुआत करना है। सीजीपीआई एक चीनी गैर-सरकारी संगठन है, सिवाय इसके कि इसके बोर्ड में दो प्रमुख विदेशी दानदाता हैं: माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और रे (रेमंड थॉमस) डेलियो। डेलियो दुनिया की सबसे बड़ी हेज

फंड फर्म, ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के अरबपति संस्थापक हैं। उनके समर्थन के बदले में, चीनी सरकार ने डेलियो को चीन में संस्थागत और उच्च निवल मूल्य वाले निवेशकों को निवेश उत्पाद बेचने की अनुमति दी। सीएनबीसी के एक साक्षात्कार के दौरान, डेलियो से पूछा गया कि वे चीनी नजरबंदी शिविरों में बंद उइगरों के मानवाधिकार उल्लंघन को कैसे संतुलित करते हैं। उन्होंने यह कहते हुए प्रश्न को टाल दिया कि वे 'इस तरह के मामलों के विशेषज्ञ नहीं हो सकते'। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका में भी सामाजिक न्याय से जुड़े कई मुद्दे हैं और वे राजनीति में नहीं पड़ना चाहते। उन्होंने कहा कि उनका काम 'नियमों का पालन करना' है।

मैं संयुक्त राज्य अमेरिका को देखता हूँ और कहता हूँ, 'अच्छा, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या चल रहा है और क्या मुझे अपने मानवाधिकार मुद्दों और अन्य चीजों के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में निवेश नहीं करना चाहिए?' मैं कोई राजनीतिक तुलना करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं मूल रूप से नियमों का पालन करने, यह समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है और सही ढंग से निवेश करूँ।

सीएनबीसी के होस्ट ने डैलियो की इस गलत तुलना पर आपत्ति जताते हुए कहा कि भले ही अमेरिका परिपूर्ण न हो, लेकिन उसकी स्थिति की तुलना चीन से नहीं की जा सकती, जहां सरकार लोगों को गायब कर देती है। डैलियो ने जवाब दिया कि जहां अमेरिका व्यक्तियों और व्यक्तिवाद का देश है, वहीं चीन में सरकार "परिवार का ही एक हिस्सा है... एक शीर्ष-प्रधान देश होने के नाते, वे एक सख्त अभिभावक की तरह व्यवहार करते हैं।"

डलियो द्वारा उइघुर मानवाधिकार अत्याचारों को चीन के 'सख्त अभिभावक' की तरह व्यवहार करने के रूप में समझाकर खारिज करना

हांगकांग स्वास्थ्य सेवा संस्थान (एचकेएस) को रास आता है। एचकेएस 'डलियो फैलोशिप' के लिए धन प्राप्त करने में पूरी तरह से सहज है, जिसके तहत चीनी छात्र एचकेएस के चीन कार्यक्रम में अध्ययन करने आते हैं। इन फैलोशिप से चीन विरोधी उम्मीदवारों को बाहर कर दिया जाता है।

डालियो के स्वयं सीसीपी से घनिष्ठ संबंध हैं:

डैलियो वास्तव में चीन में कामकाज के तरीकों के बारे में गहन ज्ञान रखते हैं। उन्होंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वांग किशान को अपना "व्यक्तिगत नायक" बताया है। अपनी 2017 की पुस्तक, प्रिंसिपल्स में, डैलियो ने स्वीकार किया, "जब भी मैं वांग से बात करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ब्रह्मांड के नियमों को खोलने वाले एकीकृत कोड को समझने के करीब पहुँच रहा हूँ।"

चीनी सरकार ने उन शिक्षाविदों, विद्वानों और व्यापारियों को पुरस्कृत करने के लिए एक 'श्वेत सूची' बनाई है जो अमेरिका-चीन संबंधों के बारे में सकारात्मक बोलते हैं और चीन द्वारा मानवाधिकारों के हनन को अनदेखा करते हैं। उन्हें संपर्क, बहु-प्रवेश वीजा और अन्य लाभ दिए जाते हैं।

वाशिंगटन डीसी स्थित एक रेडियो स्टेशन को चीन ने अपने प्रचार को प्रसारित करने के लिए लाखों डॉलर का भुगतान किया है। चीन की नज़र में अच्छा बने रहने के लिए, कई अमेरिकी कंपनियों ने चीनी हितों के विरुद्ध अपने उल्लंघनों के लिए औपचारिक रूप से माफी मांगी है।

यह विडंबना ही है कि अमेरिकी व्यवसायी चीन को खुश करने और उसकी 'व्हाइटलिस्ट' में शामिल होने के लिए इतनी कोशिशें करते हैं, जबकि चीन का अमेरिकी बौद्धिक संपदा की चोरी का लंबा इतिहास रहा है। 2020 में, अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया और सुरक्षा केंद्र के तत्कालीन निदेशक विलियम इवानिना ने कहा था कि 'चीनी बौद्धिक संपदा चोरी से अमेरिकी

कंपनियों को सालाना 300 अरब डॉलर से 600 अरब डॉलर का नुकसान होता है।' उन्होंने जिस एफबीआई रिपोर्ट का हवाला दिया था, उसमें कहा गया था कि चीनी बौद्धिक संपदा का खतरा एफबीआई के लिए सबसे बड़ी कानून प्रवर्तन चुनौती है। इसकी पुष्टि करते हुए, सीएनबीसी के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि पांच में से एक अमेरिकी कंपनी ने दावा किया कि पिछले वर्ष चीन ने उनकी बौद्धिक संपदा चुराई थी।

हार्वर्ड विश्वविद्यालय भारत को परोपकार के पश्चिमी तौर-तरीकों पर व्याख्यान देता है, लेकिन चीन के मामले में स्थिति बिल्कुल उलट है। एचकेएस चाइना फिलैंथ्रोपी प्रोजेक्ट 'परोपकारी दान के पूर्व उदाहरणों और मॉडलों' पर शोध करता है, ऐसे मॉडलों का उपयोग करते हुए जिनमें, एचकेएस के अनुसार, 'चीन के साथ वैचारिक, संस्थागत, सामाजिक और राजनीतिक समानताएं हैं, लेकिन जिनका अभी तक पर्याप्त अध्ययन नहीं किया गया है'। यह एचकेएस कार्यक्रम रूस और पूर्वी यूरोप जैसे पूर्व-कम्युनिस्ट/समाजवादी देशों का अध्ययन करता है ताकि सीसीपी के लोकाचार और दृष्टिकोण के अनुरूप समाधान सुझाए जा सकें।

... हम विश्व के उन क्षेत्रों के विद्वानों और विशेषज्ञों को एक साथ लाते हैं जिनकी चीन से स्पष्ट वैचारिक, संस्थागत, सामाजिक और राजनीतिक समानताएँ हैं, लेकिन जिन पर कम अध्ययन हुआ है। रूस और पूर्वी यूरोप संक्रमणकालीन राजनीतिक अर्थव्यवस्थाएँ हैं जो चीन के साथ राजनीतिक और संस्थागत आधारों के कुछ पहलुओं को साझा करती हैं, और यह समझने में सहायक होती हैं कि परोपकारी गतिविधियाँ राज्य द्वारा कैसे आकार लेती हैं और उसके साथ कैसे परस्पर क्रिया करती हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में चीनी लोगों की परोपकारी प्रथाएँ चीन के साथ सांस्कृतिक समानता वाले भौगोलिक क्षेत्रों में शिक्षाप्रद अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। इस

परियोजना में चीन पर भी महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित किया गया है - चीन किन परंपराओं से प्रेरणा लेता है और परोपकार के विकास को सीमित करने में राज्य/समाज की गतिशीलता के कौन से उदाहरण आज भी चीन में मौजूद हैं? इससे ... संगोष्ठियों, नीतिगत संक्षिप्त विवरणों, विद्वानों के लेखों की एक श्रृंखला तैयार होगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे की फेलोशिप सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

2013 के बाद से, हार्वर्ड चीन सम्मेलन मुख्य रूप से अमेरिका-चीन संबंधों पर केंद्रित रहे हैं, ताकि यह दिखाया जा सके कि चीन विश्व मंच पर एक प्रमुख महाशक्ति के रूप में परिपक्व हो चुका है। तकनीकी लाभ का एक व्यावहारिक प्रोजेक्ट बे एरिया डेवलपमेंट एंड इनोवेशन रिसर्च प्रोजेक्ट है, जिसे चाइनीज एसोसिएशन ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी स्टडीज के लिए चलाया जा रहा है। इसका लक्ष्य तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने वाले वास्तविक स्मार्ट शहरों के कारकों का अध्ययन करके, चीनी ग्राहक को नवाचार के लिए एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद करना है जिसकी उनमें कमी है।

इस परियोजना के अंतर्गत शेन्ज़ेन खाड़ी क्षेत्र के विकास के ऐतिहासिक अनुभवों का अध्ययन किया जाएगा; मैसाचुसेट्स खाड़ी क्षेत्र सहित विभिन्न खाड़ी क्षेत्र विकास मॉडलों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा; और चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और संबंधित वैश्विक खाड़ी क्षेत्रों के बीच खाड़ी क्षेत्र विकास के क्षेत्र में अनुसंधान आधार को मजबूत किया जाएगा। ...ऐश सेंटर क्षेत्रीय विकास और सार्वजनिक क्षेत्र के नवाचार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न खाड़ी क्षेत्र क्षेत्रों के विद्वानों और विशेषज्ञों को एक साथ लाने हेतु कई वैश्विक खाड़ी क्षेत्र मंचों का आयोजन करेगा।

एचकेएस में एक अन्य परियोजना का विषय चीन और वैश्वीकरण है, जो

राजनीति से हटकर चीन में विकास और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है। एचकेएस ऐश सेंटर विभिन्न कार्यक्रमों के तहत चीनी नागरिकों को कार्यकारी शिक्षा प्रदान करता है:

चाइना लीडर्स इन फाइनेंस प्रोग्राम चीन के बैंकिंग क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए दो सप्ताह का कार्यक्रम है: 'कार्यक्रम में शामिल कौशल में वार्ता, कॉर्पोरेट रणनीति, 21वीं सदी की प्रतिभाओं को आकर्षित करना और नवाचार को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।'

डैलियो फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित एक्जीक्यूटिव लीडर्स इन फिलैंथ्रोपी प्रोग्राम का उद्देश्य नेताओं को प्रभावी सार्वजनिक मूल्य संगठनों के निर्माण में मदद करना है।

शंघाई का दो सप्ताह का कार्यकारी प्रबंधन कार्यक्रम नगर निगम एजेंसियों के अधिकारियों को 'रणनीति, नेतृत्व, सेवा वितरण प्रबंधन, शहरी नियोजन और विकास, संकट प्रबंधन और सामाजिक नीति' सिखाने का लक्ष्य रखता है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में प्रचलित है।

इन सभी गतिविधियों में सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यकों, मानवाधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि जैसे मुद्दों से निपटने से सावधानीपूर्वक बचा जाता है।

चीनी सरकार और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से करीबी संबंध रखने वाले व्यापारियों द्वारा अमेरिकी विश्वविद्यालयों में भेजे जाने वाले धन पर गहन नज़र रखी जा रही है। हूवर इंस्टीट्यूशन की एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि चीन-संयुक्त राज्य विनिमय फाउंडेशन (CUSEF) कई अमेरिकी शैक्षणिक संस्थानों, थिंक टैंकों और गैर-लाभकारी संगठनों को वित्त पोषित करता है। हांगकांग विश्वविद्यालय (HKS) की CUSEF के साथ साझेदारी है, जिसका उद्देश्य नीति अनुसंधान, मीडिया कवरेज और

विनिमय कार्यक्रमों के माध्यम से अमेरिकी विश्वविद्यालयों को लक्षित करके प्रभाव खरीदना और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रचार फैलाना है। CUSEF और HKS दोनों ने कई शोध परियोजनाओं में सहयोग भी किया है।

CUSEF साझेदारी के तहत, HKS छात्रों के प्रतिनिधिमंडलों को चीन में सभी खर्चों का भुगतान किए गए दौरों पर भेजता है:

सीयूएसईएफ की स्थापना 2008 में हांगकांग के पूर्व मुख्य कार्यकारी और व्यापारिक दिग्गज तुंग ची ह्वा (सी.एच. तुंग) की पहल पर हुई थी, जो अभी भी फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। तुंग चीनी पीपुल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस (सीपीपीसीसी) के उपाध्यक्ष भी हैं, जो चीन का सर्वोच्च स्तरीय "संयुक्त मोर्चा" संगठन है, और उन्होंने अक्टूबर 2017 में कम्युनिस्ट पार्टी के 19वें कांग्रेस में भाग लिया था। इसके अलावा, फाउंडेशन के आधिकारिक सलाहकारों में चीन स्थित सदस्यों की संख्या और चीनी सरकारी निकायों के साथ फाउंडेशन के सहज संबंध, फाउंडेशन के इस दावे को झूठा साबित करते हैं कि यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और पीआरसी सरकार से स्वतंत्र है। सीयूएसईएफ अमेरिकियों को लक्षित करके कई कार्यक्रम चलाता है जिन्हें सटीक रूप से "प्रभाव-प्राप्ति गतिविधियों" के रूप में वर्णित किया जा सकता है; इस प्रकार, इसने विदेशी एजेंट पंजीकरण अधिनियम (एफएआरए) के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका में पंजीकरण कराया है। इसकी पैरवी गतिविधियों में पत्रकारों और संपादकों, थिंक टैंक विशेषज्ञों और शहर और राज्य के अधिकारियों सहित उन प्रतिनिधिमंडलों के लिए चीन के सभी खर्चों सहित यात्राओं का प्रायोजन करना शामिल है, जिन्हें फाउंडेशन की वेबसाइट "विचारक नेता" कहती है। (जोर दिया गया)

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों और सरकारी थिंक टैंकों, स्कूलों

और प्रभावशाली समूहों से मुलाकात के अलावा, (एचकेएस) प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने खुलासा किया कि उन्होंने हुआवेई सुविधाओं का दौरा भी किया है। सीयूएसईएफ के ब्रोशर में (एचकेएस) प्रतिनिधिमंडल की तस्वीरें हैं, जिनमें छात्रों को सरकारी पेकिंग विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के एक पूर्व मेजर जनरल द्वारा व्याख्यान देते हुए दिखाया गया है।

एचकेएस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारतीय मूल के संजय सेठ ने किया, जिन्होंने चीन यात्रा के बारे में शानदार रिपोर्ट दी: 'सीयूएसईएफ के प्रचार ब्रोशर में छात्रों के प्रशंसापत्र भी शामिल हैं, जिनमें से कुछ चीन की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि यह एक ऐसा देश है जिसने अविश्वसनीय प्रगति की है।' सेठ ने कहा:

प्रतिनिधिमंडल को आशा है कि इस यात्रा के माध्यम से वे चीन के विकास की अपनी समझ को और गहरा करेंगे और अमेरिका और चीन के लोगों के बीच मित्रता को गहरा करने और द्विपक्षीय युवा आदान-प्रदान को बढ़ाने के लिए सकारात्मक प्रयास करने के लिए तत्पर हैं।

द नेशनल पल्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी न्याय विभाग के विदेशी एजेंट पंजीकरण अधिनियम के दस्तावेजों से पता चला है कि ‘स्थापित मीडिया संस्थानों और चीन-संयुक्त राज्य अमेरिका एक्सचेंज फाउंडेशन (CUSEF) के बीच एक दशक से अधिक पुराना संबंध है’। लेख का शीर्षक था, “सभी प्रमुख पश्चिमी मीडिया संस्थान चीनी कम्युनिस्ट प्रचार मोर्चे से ‘निजी रात्रिभोज’ और ‘प्रायोजित यात्राएं’ लेते हैं”। इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, सीएनएन, रॉयटर्स, एबीसी न्यूज, द इकोनॉमिस्ट, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, एजेंस फ्रांस-प्रेस, टाइम पत्रिका, लॉस एंजिल्स टाइम्स, द हिल, बीबीसी और द अटलांटिक के साथ-साथ अधिकांश अन्य प्रसिद्ध प्रिंट मीडिया और टीवी संस्थानों की

संलिप्तता का उल्लेख किया गया है। एक निजी चीनी लॉबी ने CUSEF अधिकारियों के साथ रात्रिभोज और बैठकें आयोजित कीं और चीन के बारे में दुष्प्रचार फैलाने के उद्देश्य से प्रसिद्ध मीडिया संस्थानों के लिए चीन की 'परिचयात्मक यात्राओं' का आयोजन किया।

एक्सियोस द्वारा उजागर की गई 2011 की एफएआरए फाइलिंग में सीयूएसईएफ और अमेरिकी लॉबिंग फर्म बीएलजे के बीच हुए समझौते का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसमें बताया गया है कि सीयूएसईएफ ने चीन के संबंध में "मीडिया, प्रमुख प्रभावशाली व्यक्तियों, जनमत नेताओं और आम जनता के बीच सकारात्मक संदेशों का प्रभावी प्रसार" कैसे किया।

इस मामले में पीछे न रहने के लिए, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू भी 2015 में चीन की यात्रा में शामिल हुआ, जो दर्शाता है कि संस्था की साख संदिग्ध है।

भारतीय सरकार और भारतीय अरबपतियों के विपरीत, चीन और उसके कारोबारी नेता अपने अमेरिकी साझेदारों के साथ सख्त बातचीत करते हैं। उनकी मांगें स्पष्ट और सटीक होती हैं, और कई अमेरिकी संस्थान भारी मुनाफे के बदले में उनकी मांगों को मान लेते हैं। नीचे एक और ठोस उदाहरण दिया गया है:

वॉशिंगटन डीसी के एक प्रमुख विश्वविद्यालय से एक चीनी विश्वविद्यालय ने संपर्क किया और चीनी विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में चीनी अध्ययन केंद्र स्थापित करने के लिए 500,000 डॉलर के वार्षिक अनुदान का प्रस्ताव रखा। चीनी पक्ष की तीन मुख्य शर्तें थीं: (1) चीनी अधिकारियों और अन्य आगंतुकों को नियमित भाषणों के लिए सार्वजनिक मंच उपलब्ध कराए जाएंगे; (2) चीनी भागीदार विश्वविद्यालय के संकाय अमेरिकी विश्वविद्यालय परिसर में चीन से संबंधित पाठ्यक्रम पढ़ा सकेंगे;

और (3) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में नए चीनी अध्ययन पाठ्यक्रम जोड़े जाएंगे।
स्पष्ट रूप से, चीन दुनिया को अपने दृष्टिकोण से शिक्षित करना चाहता है और आइवी लीग को भारत की तरह आलोचनात्मक दृष्टिकोण लिखने नहीं देना चाहता। इसे हासिल करने के लिए, उसने हार्वर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित किया है और सहयोग की शर्तों को निर्धारित करने में सक्षम रहा है। भारत के मामले में, हम दिखाएंगे कि हार्वर्ड ने अरबपतियों का इस्तेमाल करके कार्यक्रमों के एक नेटवर्क के माध्यम से देश में पैठ बनाई है, जो अमेरिका और भारत दोनों में तेजी से फैल रहा है।

हार्वर्ड के चीन-समर्थक विद्वान
चीन का कठोर शासन, जो उसके नागरिकों की बुनियादी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है, कोई रहस्य नहीं है। हालांकि, वह अपने मूल्यों, भाषा और संस्कृति को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की महत्वाकांक्षा रखता है। और हार्वर्ड के विद्वान चीन के इस दृष्टिकोण को वैधता प्रदान करने में सहायक हैं। इसका एक रोचक उदाहरण हार्वर्ड के रॉय और लीला ऐश सेंटर द्वारा किया गया एक सर्वेक्षण है, जो चीन की कम्युनिस्ट व्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है; इस सर्वेक्षण में निष्कर्ष निकाला गया कि सीसीपी को अपने नागरिकों का भारी समर्थन प्राप्त है।
जुलाई 2020 की रिपोर्ट "सीसीपी के लचीलेपन को समझना: समय के साथ चीनी जनमत का सर्वेक्षण" में दावा किया गया है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) "पहले की तरह ही मजबूत है" और "जन विद्रोह के किसी भी आसन्न खतरे में नहीं है।"
यह सर्वेक्षण होराइजन रिसर्च कंसल्टेंसी ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया

था, जो एक पूर्व उच्च पदस्थ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अधिकारी द्वारा संचालित एक चीनी कंपनी है। हालांकि, संदेह से बचने के लिए, हार्वर्ड ने अपनी शोध रिपोर्ट में होराइजन का नाम गुप्त रखा। विदेश नीति विशेषज्ञों ने रिपोर्ट के निष्कर्षों की प्रामाणिकता पर संदेह व्यक्त किया है।
हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ऐश सेंटर फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस से संबद्ध विद्वानों द्वारा किए गए इस अध्ययन में 2003 से 2016 के बीच चीनी केंद्रीय सरकार और उसके निचले स्तरों की सरकारों के प्रति जनता की स्वीकृति का विश्लेषण किया गया। ... इस 13 वर्षों की अवधि में सरकार के सभी स्तरों के प्रति जनता की स्वीकृति में वृद्धि हुई है। शोधकर्ताओं ने अपने निष्कर्ष 2019 के अंत में एक अकादमिक पत्रिका में और फिर जुलाई 2020 में एक "पॉलिसी ब्रीफ" के रूप में प्रकाशित किए।
होराइजन रिसर्च के साथ शोधकर्ताओं के संबंधों को छिपाने के अलावा, हार्वर्ड की रिपोर्टों में इस संभावना पर चर्चा नहीं की गई कि उत्तरदाता राजनीतिक सवालों के ईमानदार जवाब देने में कम सहज महसूस कर सकते हैं। एईआई के विद्वान कूपर ने कहा कि इन अध्ययनों में सर्वेक्षण डेटा पर राजनीतिक दबाव के संभावित प्रभाव का उल्लेख किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि चीन में सर्वेक्षण करने में कोई बुराई है, बशर्ते आप स्पष्ट रूप से बताएं कि किन परिस्थितियों में किससे सर्वेक्षण किया गया और इस तथ्य को नोट करें कि वे सटीक जवाब देने में स्वतंत्र महसूस नहीं कर रहे होंगे।" "लेकिन अगर उन्होंने वह डेटा प्रस्तुत नहीं किया, तो मुझे लगता है कि यह समस्याग्रस्त है।"
अध्ययन के लेखकों में से एक, एडवर्ड कनिंघम को चाइना सदर्न पावर ग्रिड कंपनी से 2.3 मिलियन डॉलर और चीन स्थित अरबों डॉलर की प्रबंधन कंपनी तियानफू ग्रुप से 3.9 मिलियन डॉलर प्राप्त हुए।[69] हितों के टकराव को सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया है, लेकिन हार्वर्ड

बदलाव के प्रति अपने विरोध पर अडिग है।

इस प्रकार के वित्तीय संबंध ऐश सेंटर की उस सरकार पर निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट करने की क्षमता पर सवाल उठाते हैं, जो कई व्यावसायिक सौदों में नियंत्रण रखती है जिनमें सेंटर के प्रमुख शोधकर्ता शामिल प्रतीत होते हैं। हार्वर्ड रॉय और लीला ऐश सेंटर फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड इनोवेशन के निदेशक प्रोफेसर एंथोनी साइच, होराइजन रिसर्च के साथ काम करने वाले इस अध्ययन में शामिल एक अन्य शोधकर्ता थे। साइच को चीनी सरकार से कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और वे चीन समर्थक लॉबी समूह, नेशनल कमेटी ऑन यूनाइटेड स्टेट्स-चाइना रिलेशंस के ट्रस्टी हैं। इस तरह के हितों के टकराव व्यापक रूप से मौजूद हैं। यह चीन द्वारा चीन समर्थक विद्वानों को सफलतापूर्वक तैयार करने का भी प्रमाण है।

चीन द्वारा वित्त पोषित कई शोधकर्ताओं की तरह, साइच चीन के प्रति अत्यधिक सहानुभूति रखते हैं और उसके घोर मानवाधिकार उल्लंघनों को उजागर करने से कतराते हैं, दबाव डालने की तो बात ही दूर है। जहाँ हार्वर्ड भारत को बहुत कठोर दृष्टि से देखता है, वहीं चीन को पिछले तीन दशकों में मानवाधिकारों के क्षेत्र में हुई प्रगति के लिए लगातार सराहा जाता है। मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय के आधार पर उसका कभी भी निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं किया जाता, बल्कि उसकी प्रगति की प्रशंसा की जाती है। चीन द्वारा वित्त पोषित शोध शिक्षाविदों को अधिक नरम और समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। साइच खुले तौर पर चीन के समर्थक हैं और अमेरिकियों से चीन के पहले और अधिक मजबूत होने तक धैर्य रखने और फिर उसके अधिक खुले होने की उम्मीद करने का आग्रह करते हैं।

… हम चीन को कई स्तरों पर गलत समझते हैं। पहली बात तो यह है कि वे वास्तव में अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं हैं, जैसा कि अक्सर उन्हें

बताया जाता है। ... जैसे-जैसे उनकी अर्थव्यवस्था अधिक विकसित होती जाएगी, जैसे-जैसे शहरी मध्यम वर्ग का विकास होगा, वैसे-वैसे राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ-साथ आर्थिक स्वतंत्रता की भी मांग बढ़ेगी, जो चीन में सुधारों का परिणाम है। ... वे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीन आज से 30 साल पहले की तुलना में कहीं अधिक स्वतंत्र और रहने के लिए आसान जगह है।

भारत विरोधी और चीन समर्थक धुरी

यह दर्शाने के लिए कि हार्वर्ड का चीन समर्थक रुख अक्सर उसके भारत विरोधी रुख से मेल खाता है, हम हार्वर्ड के बेहद प्रभावशाली प्रोफेसर निकोलस बर्न्स का उदाहरण लेते हैं।

बर्न्स के सीसीपी से घनिष्ठ संबंध तब विकसित हुए जब उन्होंने एक कंसल्टिंग फर्म के लिए काम किया जो अमेरिका में सीसीपी के लॉबिंग नेटवर्क का हिस्सा थी। उनकी आलोचना इस रूप में की गई है कि वे चीन के बहुत करीब हैं।

निक बर्न्स एक परामर्श फर्म के पूर्व सलाहकार हैं, जिसमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारी कार्यरत हैं, वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम के बोर्ड सदस्य हैं जो चीन की सेना के साथ सहयोग करता है, और वे चीनी सरकारी मीडिया आउटलेट्स के लिए भी लिखते हैं।

बर्न्स ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के रक्षा सचिव बिल कोहेन द्वारा स्थापित कोहेन ग्रुप में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्य किया। कोहेन ग्रुप पूर्व सीसीपी अधिकारियों के साथ घनिष्ठ रूप से काम करने के लिए जाना जाता है और वाशिंगटन डी.सी. स्थित विभिन्न चीन लॉबिंग समूहों में सक्रिय है। इस समूह ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा शिनजियांग में उइगरों के खिलाफ मानवाधिकारों के हनन के लिए प्रतिबंधित एक संस्था

को भी सलाह दी है।
कोहेन ग्रुप की चाइना प्रैक्टिस का दावा है कि यह 'दुनिया भर की प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों और चीनी उद्यमों के बीच रचनात्मक जुड़ाव और सहयोग को बढ़ावा देती है' और 'विदेशों में उच्च गुणवत्ता वाले निवेश में लगी चीनी कंपनियों का समर्थन करती है'। चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए, कोहेन ग्रुप के बीजिंग और तियानजिन में एक दशक से अधिक समय से दो कार्यालय हैं। बर्न्स चीन के सरकारी मीडिया आउटलेट्स, जिनमें चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क भी शामिल है, पर भी दिखाई दे चुके हैं।
बर्न्स हांगकांग राज्य के रॉबर्ट और रेनी बेलफर सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के बोर्ड में हैं, जिसने सीसीपी सरकार और सैन्य अधिकारियों के साथ साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किए हैं।
समूह ने काल्पनिक साइबर परिदृश्यों का अभिनय किया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हुआवेई, हथियार नियंत्रण ढांचे आदि से संबंधित संवेदनशील तकनीकी मामलों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने एक काल्पनिक साइबर परिदृश्य के माध्यम से यह चर्चा की कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर तीसरे पक्ष के साइबर हमले की स्थिति में उनकी संबंधित सरकारें और कंपनियां क्या करेंगी। कार्य समूह ने बौद्धिक संपदा की चोरी, आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा और डार्क वेब पर मैलवेयर के प्रसार को नियंत्रित करने पर भी चर्चा की।
बर्न्स का महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि वर्तमान बाइडन प्रशासन ने उन्हें चीन में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है। अपने नए पद पर रहते हुए यह देखना दिलचस्प होगा कि बर्न्स चीन में उइघुर मानवाधिकार संकट से कैसे निपटते हैं। वर्षों से उनका रवैया चीन के प्रति बेहद सहानुभूतिपूर्ण रहा है। 2020 में एस्पेन इंस्टीट्यूट के एक कार्यक्रम में चीन के संदर्भ में

बर्न्स ने कहा था, 'हम उन्हें दुश्मन के रूप में नहीं देख सकते क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत है।'
लेकिन भारत की गलतियों को उजागर करने में उन्हें कोई झिझक नहीं है। 2020 में "भारत पर, अमेरिका को और अधिक व्यापक सोच रखनी चाहिए" शीर्षक वाले एक लेख में उन्होंने लिखा: "भारत को उन लोगों पर लगाम लगाने की सलाह दी जाती है जो अक्सर घृणित हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडा अपनाते हैं, जिससे देश की बड़ी मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी को नुकसान होता है।"
स्पष्ट है कि हार्वर्ड कैनेडी स्कूल अपने विभिन्न केंद्रों के साथ भारत के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए अच्छी स्थिति में है। उदाहरण के लिए, निकोलस बर्न्स द्वारा 2020 में कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को अपने 'फ्यूचर ऑफ डिप्लोमेसी प्रोजेक्ट' में आमंत्रित करने से यह बात स्पष्ट होती है। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में, भोले-भाले और संवेदनशील गांधी ने बर्न्स के सामने भारतीय लोकतंत्र के प्रति अपनी शिकायतें खुलकर रखीं। हार्वर्ड को खुश करने के लिए, गांधी ने यह कहकर समर्थन मांगा कि भारत की विपक्षी पार्टियों को लोकतांत्रिक तरीके से काम करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने शिकायत की कि आरएसएस और भाजपा भारत के लोकतंत्र का अपहरण कर रहे हैं।
गांधी ने बर्न्स से अमेरिकी हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि भारत में व्याप्त सत्ता के ऐसे दुरुपयोग पर अमेरिका चुप क्यों है: 'मुझे अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान से कुछ भी सुनने को नहीं मिलता। यदि आप "लोकतंत्रों की साझेदारी" की बात कर रहे हैं, तो यहां जो कुछ हो रहा है उस पर आपका क्या विचार है?' उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए अमेरिकी हस्तक्षेप का आह्वान किया।
मेरा दृढ़ विश्वास है कि अमेरिका एक गहन विचार है, स्वतंत्रता का विचार,

जिस तरह से यह आपके संविधान में समाहित है, यह एक बहुत शक्तिशाली विचार है। लेकिन आपको उस विचार की रक्षा करनी होगी। और यही असली सवाल है।

सुनियोजित बातचीत जारी रहने के दौरान, बर्न्स ने अमेरिका में अश्वेत अमेरिकियों पर हो रहे उत्पीड़न का जिक्र किया और फिर गांधी को भारत में मुसलमानों के साथ हो रहे दमनकारी व्यवहार पर टिप्पणी करने के लिए प्रेरित किया।

मुझे भारत में मुसलमानों के दमन हेतु सरकार और अन्य संस्थाओं की नीतियों पर चिंता है। ...हम दोनों ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के भीतर लगभग अस्तित्वगत चुनौतियों से जूझ रहे हैं, और जब तक हम इन चुनौतियों पर काबू नहीं पा लेते, तब तक हमारी बाह्य नीतियों में सफलता सीमित रहेगी। क्या आप सहमत हैं? क्या आप असहमत हैं?

गांधी ने कूटनीतिक ढंग से कहा कि बर्न्स द्वारा पहले उल्लेखित 'हिंदू राष्ट्रवाद' को हिंदू धर्म के साथ नहीं मिलाना चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने वही बात कही जो उनके मेजबान सुनना चाहते थे, और बताया कि भारतीय सरकार का रुख यह है कि...

यह उन सभी के खिलाफ है जो असहमत हैं, इसलिए यह दलितों के खिलाफ है, यह आदिवासियों के खिलाफ है, यह मुसलमानों के खिलाफ है, यह सिखों के खिलाफ है, यह उन सभी के खिलाफ है जो इस विचार का विरोध करते हैं कि भारत में किसी के पास पूर्ण सत्ता है। इससे हमारे देश के लिए एक गंभीर समस्या उत्पन्न होने वाली है।

गांधी ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से नरेंद्र मोदी सरकार की आर्थिक विफलताओं का अध्ययन करने का भी आग्रह किया है। उन्होंने बाद में ट्वीट किया: 'विफलताओं पर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के भविष्य के केस स्टडी: 1. कोविड-19, 2. नोटबंदी, 3. जीएसटी कार्यान्वयन'।

यह घटना दर्शाती है कि हार्वर्ड किस प्रकार भू-राजनीतिक मुद्दों में पक्षपात करता है और भारत एवं चीन के साथ व्यवहार में दोहरा मापदंड अपनाता है। हार्वर्ड के विद्वानों ने क्रिटिकल रेस थ्योरी (CRT) का उपयोग करके इस 'हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडा' को ध्वस्त करने के लिए एक विशाल तंत्र का निर्माण और संचालन किया है। यद्यपि CRT का लक्ष्य दमनकारी सभी संरचनाओं को ध्वस्त करना है, यह उल्लेखनीय है कि हार्वर्ड ने CCP की संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए ऐसा कोई आंदोलन शुरू नहीं किया है, जबकि CCP का दमनकारी इतिहास सुस्थापित है।

हार्वर्ड और चीनी सेना

हार्वर्ड के चीन की सेना से घनिष्ठ संबंध भारत के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। इस संबंध में एनबीसी न्यूज़ की एक खोजी रिपोर्ट जानकारीपूर्ण है; यह दर्शाती है कि कैसे अमेरिकी विश्वविद्यालय उन चीनी स्कूलों से संबंध बनाए रखते हैं जो चीन के सैन्य निर्माण का समर्थन करते हैं। एक अन्य रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीनी सेना से जुड़े कम से कम अस्सी-आठ मिलियन डॉलर साझेदारी के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से अमेरिकी कॉलेजों तक पहुंचे हैं। उदाहरण के लिए, 2020 के चाइना फोरम के प्रायोजकों में से एक चाइना टेलीकॉम था, जिसे अमेरिकी रक्षा विभाग ने चीनी सैन्य सहयोगी के रूप में पहचाना है। एक अन्य प्रायोजक सरकारी मीडिया आउटलेट चाइना सेंट्रल टेलीविजन नेटवर्क, चाइना डेली और शिन्हुआ न्यूज़ थे। इसके अलावा:

हार्वर्ड विश्वविद्यालय का वार्षिक चाइना फोरम – जो राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक खतरे के बावजूद अमेरिका-चीन संबंधों को और मजबूत करने की वकालत करता है – टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस और टेनसेंट के साथ-साथ चीनी सैन्य सहयोगी हुआवेई और चाइना टेलीकॉम सहित कई

(सीसीपी) से जुड़े संगठनों के साथ सहयोग करता है।
2021 में, एक स्वतंत्र रिपोर्ट ने खुलासा किया कि हार्वर्ड और अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ने चीनी रक्षा और परमाणु कार्यक्रम के लिए प्रौद्योगिकियों को विकसित करने हेतु चीनी सेना और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) दोनों के साथ सहयोग किया था। हार्वर्ड टी.एच. चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, जहां पिरामल सेंटर फॉर पब्लिक हेल्थ स्थित है, की सात चीनी विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी है।
हार्वर्ड विश्वविद्यालय के टी.एच. चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने सात चीनी विश्वविद्यालयों के साथ एक स्वास्थ्य साझेदारी चलाई है, जिसका उद्देश्य अकादमिक आदान-प्रदान करना और चीनी कार्यक्रम प्रतिभागियों को चीनी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार के लिए एजेंट के रूप में कार्य करने का प्रशिक्षण देना है। हार्वर्ड के इस समूह में शामिल कम से कम छह विश्वविद्यालयों में गंभीर सुरक्षा जोखिम हैं, क्योंकि वे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की ओर से किए जा रहे अन्य शोधों से जुड़े हुए हैं। तीन विश्वविद्यालय—सिचुआन विश्वविद्यालय, शीआन जियाओतोंग विश्वविद्यालय और सिंघुआ विश्वविद्यालय—चीनी रक्षा, जिसमें चीनी परमाणु कार्यक्रम भी शामिल है, के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास में सहयोग करते हैं। इन तीनों का चीनी साइबर जासूसी गतिविधियों से संबंध है।
प्रोजेक्ट 2049 इंस्टीट्यूट में चीन नीति के वरिष्ठ निदेशक इयान ईस्टन ने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा में कुलीन विश्वविद्यालय अनजाने में एक नया मोर्चा खोल रहे हैं: स्वास्थ्य सेवा। … इससे चीन और अमेरिका दोनों में मरीजों की गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है। ईस्टन ने कहा, “हो सकता है कि आपको चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) में दिलचस्पी न हो, लेकिन सीसीपी को आपमें दिलचस्पी है।

वह आपका सारा व्यक्तिगत और निजी डेटा इकट्ठा करना चाहती है। वह आपके डेटा का इस्तेमाल आपके, आपके मूल्यों और आपकी जीवनशैली के खिलाफ करना चाहती है।" उन्होंने आगे कहा, "ऐसा होने का खतरा बहुत वास्तविक है। चिकित्सा के प्रति सीसीपी के दृष्टिकोण में कुछ भी सौम्य या मानवतावादी नहीं है, और वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी उद्योग के उसके शोषण की कड़ी निंदा की जानी चाहिए।"
पिरामल हार्वर्ड (और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से चीनियों) को भारत में प्रवेश का मार्ग प्रदान कर रहा है। पिरामल की इस पहल को अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, गोदरेज, टाटा ट्रस्ट्स, नरोत्तम शेखसरिया फाउंडेशन और भारत के अन्य बड़े खिलाड़ियों का भी समर्थन प्राप्त है। एक खुला प्रश्न यह है कि क्या यह अप्रत्यक्ष पहुंच चीनियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य को भारतीयों के खिलाफ एक ट्रोजन हॉर्स में बदलने की अनुमति देती है?

हार्वर्ड और कोविड-19
कोविड-19 महामारी से निपटने के दौरान हार्वर्ड की कथा को नियंत्रित करने की शक्ति और हांगकांग केनेडी स्कूल के चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से घनिष्ठ संबंध स्पष्ट हो गए। 2020 के अंत में, चीनी चिकित्सक और वायरोलॉजिस्ट डॉ. ली-मेंग यान ने एक अध्ययन प्रकाशित किया जिसमें दावा किया गया कि कोविड-19 को चीनी सरकार की एक अनुसंधान प्रयोगशाला में बनाया गया था। व्हिसलब्लोअर बनने के बाद यान हांगकांग छोड़कर अमेरिका भाग गईं। हार्वर्ड के शोरेनस्टीन सेंटर ऑन मीडिया, पॉलिटिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी ने यान के काम को गलत सूचना बताते हुए उसे बदनाम करने के लिए एक रिपोर्ट प्रकाशित की। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल mediamanipulation.org नामक एक पहल चलाता है जिसमें कहा गया है: 'यान रिपोर्ट विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया गया एक

भ्रामक लेख है, जो झूठा दावा करता है कि नोवेल कोरोनावायरस एक चीनी प्रयोगशाला में बनाया गया था।' हालांकि, हार्वर्ड रिपोर्ट में जिन संदर्भों का इस्तेमाल किया गया है, वे चीनी सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों से आते हैं।

शोरेनस्टीन सेंटर के विश्लेषण में यान के काम को गलत साबित करने के लिए जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है... इसमें कई ऐसे अध्ययनों का उल्लेख है जिन्हें सीसीपी से वित्तीय सहायता मिली है। सेंटर एमआईटी की एक रिपोर्ट का भी हवाला देता है जिसमें डॉ. रॉबर्ट गैलो को इसके पहले शोधकर्ता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। गैलो को चीनी विज्ञान अकादमी के सरकारी विश्वविद्यालय से पुरस्कार मिला था... वे ग्लोबल वैक्सीन नेटवर्क के सह-संस्थापक भी हैं, जिसकी कम्युनिस्ट चीन में कई सक्रिय शाखाएं हैं। सीसीपी से इतने मजबूत संबंधों को देखते हुए, डॉ. यान के विश्लेषण को अमान्य साबित करने के लिए इन अध्ययनों का हवाला देना अनैतिक है।

इसके अलावा, शोरेनस्टीन सेंटर में कई सीसीपी से जुड़े फेलो होने का भी खुलासा हुआ था:

स्टीवन डोंग सिंघुआ विश्वविद्यालय के वैश्विक पत्रकारिता संस्थान के पूर्व निदेशक थे, जहाँ से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शिक्षा प्राप्त की थी। डीन ने मार्क्सवादी पत्रकारिता को 'सही राजनीतिक दिशा' बताया है। डोंग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समाजवाद अकादमी में राजनीतिक संचार के प्रोफेसर भी हैं और उन्होंने बीस हजार से अधिक वरिष्ठ चीनी अधिकारियों को व्याख्यान दिए हैं।

झेंग्रांग हू ने चीन की राज्य परिषद के पत्रकारिता और संचार अनुशासन मूल्यांकन समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्हें चीन की राज्य

परिषद द्वारा एक विशेष सरकारी पुरस्कार और एक क्रॉस-सेंचुरी उत्कृष्ट कार्मिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
ली शिगुआंग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी समर्थित प्रचार माध्यम शिन्हुआ के पूर्व वरिष्ठ संपादक थे। वे सिंघुआ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और चीनी विदेश मंत्रालय की सार्वजनिक कूटनीति सलाहकार समिति के सदस्य हैं।
सीसीपी और हार्वर्ड के बीच (शोरेनस्टीन सेंटर के माध्यम से) गहरा संबंध है:
शोरेनस्टीन सेंटर ने हार्वर्ड के ऐश सेंटर के साथ मिलकर कम से कम 10 कार्यक्रम आयोजित किए हैं। ऐश सेंटर ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी और उसके स्वामित्व वाली कंपनियों से लाखों डॉलर लिए हैं और ऐसे अध्ययन प्रकाशित किए हैं जिन्हें चीनी सरकारी मीडिया आउटलेट्स ने लोकप्रिय बनाया है, जिनमें दावा किया गया है कि सरकार को रिकॉर्ड स्तर का समर्थन प्राप्त है। इन कार्यक्रमों में "फर्जी खबरों का मुकाबला: अनुसंधान और कार्रवाई के लिए एक एजेंडा", "चीन से रिपोर्टिंग: न्यूयॉर्क टाइम्स के संवाददाता डेविड बारबोजा के साथ बातचीत" और "चीन में मीडिया की राजनीति: अधिनायकवाद के तहत सत्ता का तात्कालिक उपयोग" शामिल हैं।
2021 में, हार्वर्ड ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस को हार्वर्ड टी.एच. चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के दीक्षांत समारोह में विशिष्ट वक्ता के रूप में आमंत्रित किया। घेब्रेयेसस ने उस समय चल रहे कोविड-19 के दौरान चीन को दोषसिद्धि से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे WHO का चेहरा थे, जिस पर महामारी के शुरुआती दिनों में चीन की भूमिका को छिपाने के लिए झूठ बोलने, षड्यंत्र सिद्धांतों को बढ़ावा देने और गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया गया था। चैन स्कूल ने घेब्रेयेसस की 'महान अंतर्दृष्टि और

राजनीतिक नेतृत्व' की सराहना की और उन्हें 'WHO के इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर विश्वास बहाल करने के लिए सही व्यक्ति' बताया। इसके परिणामस्वरूप एक सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई:

हार्वर्ड द्वारा टेड्रोस को आमंत्रित करने के फैसले से विदेशी राष्ट्रों और अमेरिकी विश्वविद्यालयों के बीच मौजूदा संबंधों पर सवाल उठते हैं, जिनमें से दर्जनों विश्वविद्यालयों ने पिछले साल चीन से मिले दान का खुलासा नहीं किया था। शिक्षा विभाग ने येल और हार्वर्ड की जांच की... क्योंकि उन्होंने रूस, सऊदी अरब, ईरान और चीन सहित विदेशी राष्ट्रों से मिले 375 मिलियन डॉलर के अनुदान का खुलासा नहीं किया था। 2014 में, हार्वर्ड के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का नाम बदलकर टी.एच. चान के नाम पर रखा गया, जो एक चीनी व्यवसायी और हार्वर्ड के स्नातक थे, जिनके बेटों ने स्कूल को 350 मिलियन डॉलर का दान दिया था, जो हार्वर्ड को अब तक मिला सबसे बड़ा दान है।

इसकी तुलना भारत द्वारा कोविड-19 संकट से निपटने के तरीके से करें, जिसकी हार्वर्ड ने केवल आलोचना और संशय ही व्यक्त किया है। उदाहरण के लिए, हार्वर्ड चान इंडिया रिसर्च सेंटर के निदेशक के. विश्वनाथ और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में चिकित्सा की प्रोफेसर लुईस इवर्स ने भारत में नेतृत्व की कमी, गंगा में मिले शवों और मौतों की कम रिपोर्टिंग के बारे में बात की।

गंगा नदी में शव बहकर आ रहे हैं। यह एक बेहद भयावह और दुखद स्थिति है। और सर्दियों के बाद से हालात और भी बदतर हो गए हैं। मैं राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर समन्वय और नेतृत्व की बात कर रहा हूँ, जहाँ आप इन दिशा-निर्देशों को विकसित कर रहे हैं, चाहे वह नैदानिक स्तर पर हो या सार्वजनिक स्वास्थ्य स्तर पर, नीतियों का विकास, कार्यान्वयन, प्रवर्तन संबंधी मुद्दों को एक एकीकृत तरीके से संभालना

और राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उचित जानकारी प्रदान करना। और अब इस तरह के नेतृत्व की वास्तव में आवश्यकता है। और ऐसा लगता है कि यह मौजूद ही नहीं है।

चीन-ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन संबंध

उस समय केंद्रीय खुफिया एजेंसी (सीआईए) के निदेशक विलियम बर्न्स ने अमेरिकियों को चीन द्वारा किए जा रहे आक्रामक प्रचार प्रयासों के बारे में चेतावनी दी थी। इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए, ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन, कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, विल्सन सेंटर, एशिया सोसाइटी और अन्य प्रमुख अमेरिकी थिंकटैंक के कई विद्वानों ने चाइना पब्लिक डिप्लोमेसी एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो वाशिंगटन फ्री बीकन की एक रिपोर्ट के अनुसार सीसीपी का एक संगठन है।[98] इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है:

एशिया सोसाइटी के वैश्विक सह-अध्यक्ष और ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन के चाइना सेंटर के नामधारी जॉन एल. थॉर्नटन इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता हैं, साथ ही स्टेट लेजिस्लेटिव लीडर्स फाउंडेशन के अध्यक्ष स्टीफन लैकिस भी मुख्य वक्ता हैं। ब्रूकिंग्स क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव के डैनियल विक्टर और पैसिफिक काउंसिल ऑन इंटरनेशनल पॉलिसी के जेरोल्ड ग्रीन भी पैनलिस्ट के रूप में सूचीबद्ध हैं।

एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, ब्रूकिंग्स चीनी प्रभाव में बुरी तरह से फंसा हुआ है। इस और अन्य अमेरिकी थिंकटैंकों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) से संबंधों के कारण भारी आलोचना का सामना करना पड़ा है। ब्रूकिंग्स बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के मानद अध्यक्ष जॉन एल. थॉर्नटन 2016 से सिल्क रोड फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। यह

कम्युनिस्ट पार्टी समर्थित एक कोष है जो बेल्ट एंड रोड पहल के लिए परियोजनाएं विकसित करता है, जिसे अमेरिकी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानती है। वे चीन के कन्फ्यूशियस संस्थानों से भी जुड़े हुए हैं, जिनका कथित तौर पर बीजिंग द्वारा अमेरिकी स्कूलों में प्रचार-प्रसार के लिए उपयोग किया जाता है। ब्रूकिंग्स के जॉन एल. थॉर्नटन चाइना सेंटर के विद्वानों ने बेल्ट एंड रोड और कन्फ्यूशियस संस्थानों का बचाव किया है, लेकिन यह खुलासा नहीं किया है कि थॉर्नटन उन संगठनों में कार्यरत हैं जो इन पहलों का समर्थन करते हैं।
हार्वर्ड और अमेरिकी संघीय सरकार के बीच शीर्ष विद्वानों के आदान-प्रदान के कारण इसे गंभीर माना जाता है:
एक प्रमुख पारदर्शिता निगरानी समूह का कहना है कि ब्रूकिंग्स जैसे थिंक टैंक अपनी सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने की क्षमता के कारण विदेशी प्रस्तावों के प्रति संवेदनशील हैं। कम से कम 17 ब्रूकिंग्स विद्वान बाइडेन प्रशासन में शामिल हो चुके हैं। ब्रूकिंग्स के पूर्व चीन फेलो रश दोशी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के चीन पोर्टफोलियो के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।
ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन की 2017 की एक रिपोर्ट, जिसका शीर्षक "सुरक्षित शहर नवाचार के लाभ और सर्वोत्तम प्रथाएं" था, ब्राउन विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डॉ. डैरेल वेस्ट द्वारा लिखी गई थी। इस रिपोर्ट में वेस्ट ने नैरोबी और लिजियांग (चीन) में पुलिसिंग के लिए (हुआवेई की) तकनीक के उपयोग के लाभों की प्रशंसा की है। हालांकि, ब्रूकिंग्स में इस अध्ययन को प्रायोजित करने वाली हुआवेई के साथ वेस्ट के संबंधों का खुलासा नहीं किया गया, जिससे ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन पर गंभीर सवाल उठते हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने कहा कि डॉ. वेस्ट ने इस बात का उल्लेख नहीं किया था कि

या तो विवादित चीनी दूरसंचार कंपनी हुआवेई ने दोनों शहरों के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान की, या हुआवेई सेफ सिटी उपकरणों के दुनिया के अग्रणी विक्रेताओं में से एक है, जिसे कंपनी पुलिसिंग और निगरानी में सुधार के लिए "अत्याधुनिक" सुरक्षा के रूप में वर्णित करती है।
वाशिंगटन पोस्ट ने यह भी उल्लेख किया है कि जुलाई 2016 और जून 2018 के बीच, हुआवेई ने फ्यूचरवेई टेक्नोलॉजीज, इंक. के माध्यम से ब्रूकिंग्स को कम से कम 300,000 डॉलर का दान दिया, जो हुआवेई की अमेरिका स्थित सहायक कंपनी है।
लेकिन वेस्ट के हुआवेई के साथ संबंध उनकी विद्वत्ता की स्वतंत्रता पर सवाल उठाते हैं और अमेरिका के अग्रणी थिंक टैंकों में से एक पर चीन के प्रभाव का एक चिंताजनक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। [104]
अगर ब्रूकिंग्स चीनी प्रभाव में है, तो भारत में स्थापित उस संस्था के मकसद पर सवाल उठते हैं, जहां कई शीर्ष भारतीय अभिजात वर्ग के बच्चे वरिष्ठ पदों पर कार्यरत हैं। क्या वे पश्चिमी सूट पहने और अमेरिकी लहजे में बात करने वाले सीसीपी के मुखपत्र हैं? उनका असली मकसद क्या है? ब्रूकिंग्स की कार्यप्रणाली के बारे में भारतीयों को कितनी जानकारी है? भारतीय अभिजात वर्ग के रिश्तेदारों और बच्चों के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा किस हद तक खतरे में है? ये ऐसे गंभीर प्रश्न हैं जिनका भारत को समाधान ढूंढना होगा।
अमेरिकी संस्थानों में सेंध लगाने और अमेरिकी अभिजात वर्ग को खरीदकर अपने नियंत्रण में लेने पर चीन का ध्यान केंद्रित करना वांछित परिणाम प्राप्त करता प्रतीत होता है। अमेरिकी विश्वविद्यालय प्रणाली में पैठ बनाने के लिए चीन के तीन लक्ष्य हैं।
अमेरिकी नेतृत्व की अगली पीढ़ी को प्रभावित करना और यह तय करना कि हमारे उभरते नेता चीन को किस नजरिए से देखते हैं।

चीनी छात्रों को ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के लिए अमेरिकी विश्वविद्यालयों में भेजें और फिर उन्हें वापस चीन ले जाएं।
विशेषकर स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड जैसे प्रमुख अनुसंधान विश्वविद्यालयों की अनुसंधान प्रयोगशालाओं से संवेदनशील जानकारी एकत्र करें।
डेली वायर की डॉक्यूमेंट्री में रिपोर्ट किया गया है कि विश्वविद्यालय के अध्यक्ष चीनी धन के प्रवाह से अवगत हैं, लेकिन वे इस बारे में चुप रहने की कोशिश करते हैं:
यदि आप 1,000,000 डॉलर या उससे अधिक का दान करते हैं, तो आप 'प्रभाव' के बारे में सोच रहे हैं; आप स्कूल को वह पढ़ाने के लिए प्रभावित करना चाहते हैं जो आप खुद पढ़ना चाहते हैं; आप शोध अनुदान देना चाहते हैं जो आपको यह समझने में मदद करे कि अमेरिकी क्या अध्ययन कर रहे हैं; आपको अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिलाए। चीनी दान से इस बात पर प्रभाव पड़ता है कि प्रोफेसर चीन के बारे में कैसे पढ़ाते हैं, वे उस क्षेत्र - ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया और अन्य - के बारे में कैसे पढ़ाते हैं। यह अमेरिकी छात्रों के चीन के प्रति दृष्टिकोण को आकार देता है। ... चीनी घुसपैठ अमेरिकी सहयोग का परिणाम है, अमेरिकी लालच का परिणाम है।
भारत में चीनी घुसपैठ के संबंध में, भारत में लॉ एंड सोसाइटी एलायंस द्वारा प्रकाशित "मैपिंग चाइनीज फुटप्रिंट्स एंड इन्फ्लुएंस ऑपरेशन इन इंडिया" शीर्षक वाली 76 पृष्ठों की एक रिपोर्ट है।

9. हार्वर्ड विश्वविद्यालय की जांच का महत्व

अवलोकन

उन्नीसवीं सदी के फ्रांसीसी राजनयिक और दार्शनिक, एलेक्सिस डी टॉकविले को 'मन का साम्राज्य' वाक्यांश का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है, जब उन्होंने लिखा था:

मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों को अंग्रेज़ लोगों के उस हिस्से के रूप में देखता हूँ जिसे नई दुनिया के अनछुए इलाकों का अन्वेषण करने का कार्य सौंपा गया है; जबकि राष्ट्र का शेष भाग, अधिक अवकाश का आनंद लेते हुए और जीवन की नीरसता से कम परेशान होकर, अपनी ऊर्जा चिंतन में लगा सकता है और बौद्धिक साम्राज्य को सभी दिशाओं में विस्तारित कर सकता है। इसलिए अमेरिकियों की स्थिति बिल्कुल असाधारण है...[1]

द्वितीय विश्व युद्ध (1939-45) के बाद अमेरिकी साम्राज्य के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया गया था, जब दिवंगत ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक विशाल सभा को संबोधित किया था। उन्होंने समझाया कि ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के लिए पश्चिम को अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए एक अलग दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता थी। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था: 'भविष्य के साम्राज्य मन के साम्राज्य हैं।'

यह अध्याय दर्शाता है कि हार्वर्ड के प्रोफेसर किस प्रकार एक गुट की तरह व्यवहार करते हैं, जो भारत के बारे में एक विशेष दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए सभी असहमतिपूर्ण आवाजों को दबा देते हैं। वास्तव में, हार्वर्ड ब्रिटिश युग के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की भूमिका निभा रहा है, और भारत पर वैसा ही प्रभाव डाल रहा है जैसा ऑक्सफोर्ड ने डाला था। भारतीय साहित्य का अध्ययन करने और उसका अनुवाद करने वाले हार्वर्ड के विद्वानों का उद्देश्य मार्क्सवादी व्याख्याओं को प्रस्तुत करके भारतीयों की

आत्म-पहचान को प्रभावित करना और पहचान की राजनीति को बढ़ावा देना है।
भारत सरकार का हार्वर्ड के प्रति दृष्टिकोण भी भोला रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसने उचित जांच-पड़ताल नहीं की है। इसके परिणामस्वरूप नीति निर्माण, हार्वर्ड को बढ़ावा देने और उसे भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट देने में महंगी गलतियां हुई हैं। देश के भीतर लोगों और संस्थानों का निर्माण करना सस्ता होता और भारत के अपने हितों के अनुरूप भी होता।

हार्वर्ड विश्वविद्यालय का अकादमिक-औद्योगिक परिसर
आज, अमेरिकी कॉलेज केवल बौद्धिक साम्राज्य ही नहीं हैं, बल्कि व्यवसाय की तरह चलाए जाते हैं, जो पैसा कमाते हैं और अपने ब्रांड का प्रबंधन करते हैं। छात्रों को कॉलेज की खेल टीमों में खेलने के लिए भर्ती किया जाता है, जिससे उन्हें टिकट बिक्री और टीवी प्रसारण अधिकारों से लाखों डॉलर की कमाई होती है। पूर्व छात्र टीमों का समर्थन करने के लिए विश्वविद्यालयों को दान देना पसंद करते हैं। प्रवेश में उन खिलाड़ियों के लिए अलिखित 'कोटा' है, जिन्हें मुश्किल से ही कोई शिक्षा मिलती है। कॉलेज खेल सामग्री और ब्रांडेड कॉलेज परिधान बेचकर भी पैसा कमाते हैं। खेल कोटा के अलावा, हार्वर्ड जैसे कई कॉलेज विरासत प्रवेश के रूप में हार्वर्ड से पारिवारिक संबंध रखने वाले छात्रों को लगभग 35 प्रतिशत सीटें देते हैं। नियमित छात्र इस ब्रांड का हिस्सा बनने के लिए भारी शुल्क का भुगतान करते हैं। अधिकांश छात्र भारी कर्ज के साथ स्नातक होते हैं। अमेरिका में छात्र ऋण संकट के स्तर पर है, जहां 43 मिलियन छात्रों द्वारा लिए गए कुल संघीय ऋण 1.5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है। इसके अलावा, अमेरिकी कॉलेज विचारधाराओं के प्रसार और वितरण के

केंद्र के रूप में काम करते हैं, जहाँ छात्रों का एक समूह विचारधाराओं को ग्रहण करता है। यह तब स्वीकार्य होता जब विचारों की विविधता को खुलकर पनपने का समान अवसर मिलता। लेकिन, जैसा कि हम इस पुस्तक में दर्शा रहे हैं, वास्तविकता इससे बहुत अलग है: संकाय एक ट्रेड यूनियन की तरह काम करते हैं, जिसमें वैचारिक रूप से समान विचारधारा वाले सदस्य एक-दूसरे का समर्थन करते हैं और आलोचकों और विरोधियों को बाहर रखने के लिए एकजुट हो जाते हैं। विविधता का यह चलन जैविक विविधता (नस्ल, लिंग आदि) पर केंद्रित है, लेकिन विचारों की विविधता के प्रति असहिष्णु है।

भाग 2 के आगामी अध्यायों में अमेरिकी विश्वविद्यालयों, भारतीय अरबपतियों, भारतीय सरकार और अन्य विभिन्न हितधारकों के बीच होने वाली अंत:क्रियाओं और ऐसे सहयोगों के जोखिम भरे परिणामों को दर्शाया जाएगा। इनमें से कुछ सहयोगी शायद उत्पन्न हो रहे परिणामों से अनभिज्ञ हों।

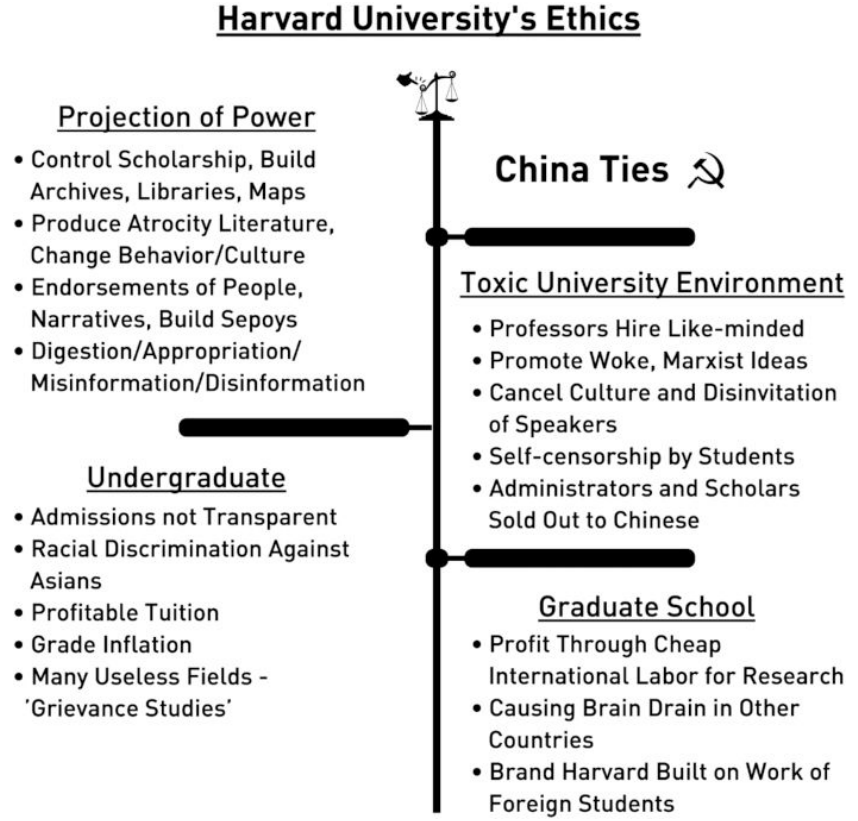

हमने अपनी बात साबित करने के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय पर ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि विश्व मंच पर इसका बहुत प्रभाव है। हार्वर्ड में जो शुरू होता है, वह वहीं तक सीमित नहीं रहता। यह हर जगह बौद्धिक और नीतिगत संस्थानों में गहराई तक फैलता है। विश्व गुरु शब्द का अर्थ है विश्व का गुरु। इसे जानबूझकर हार्वर्ड पर लागू किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय अभिजात वर्ग में यह दावा करना चलन में है कि भारत विश्व गुरु है। हमारा तर्क यह है कि भारत शिष्य की तरह है, जबकि हार्वर्ड वैश्विक गुरु है। ऊपर दिया गया चित्र हार्वर्ड विश्वविद्यालय की नैतिकता का वर्णन करता है।

हम अनुदान, कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों और उनके शोध कार्यों, और हार्वर्ड

द्वारा उत्पन्न वैचारिक पूर्वाग्रहों पर चर्चा करेंगे। हम भारतीय गैर-सरकारी संगठनों, संस्थानों और मीडिया के साथ हार्वर्ड के संबंधों का भी गहन विश्लेषण करेंगे, जो हार्वर्ड के प्रभाव को बढ़ाते और मजबूत करते हैं। यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये संबंध भारत के हितों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। अपने विशाल धन और प्रभाव के बल पर, हार्वर्ड ने भारतीय सरकार और नागरिक समाज में पैठ बना ली है; यह भारतीयों से संबंधित संवेदनशील डेटा एकत्र कर रहा है; इसे भारतीय अरबपतियों का समर्थन प्राप्त है; और यह भारतीय नीतियों की भावी दिशा और भारत पर होने वाली चर्चा को निर्धारित कर रहा है। आगामी अध्यायों में प्रस्तुत साक्ष्यों के अंबार से यह बात स्पष्ट हो जाएगी।

अगले पृष्ठ पर दी गई आकृति भारत पर चर्चा के विकास और प्रसार में हार्वर्ड को केंद्रीय भूमिका निभाने वाले संस्थान के रूप में दर्शाती है। इसके तत्वों को संक्षेप में समझाया गया है:

सबसे भीतरी वृत्त में उन सिद्धांतों को दर्शाया गया है जो इस वृत्त में प्रयुक्त हैं, जिनमें मार्क्सवाद आधारशिला के रूप में कार्य करता है। इन पर भाग 1 में चर्चा की गई थी।

सैद्धांतिक ढांचे के चारों ओर एक बॉक्स है जो हार्वर्ड के विभिन्न स्कूलों और केंद्रों को दर्शाता है जो इन सिद्धांतों में योगदान देते हैं और इनसे प्रेरणा लेते हैं।

बाहर की ओर इंगित तीर इन केंद्रों के माध्यम से हार्वर्ड द्वारा डाले गए प्रभाव को दर्शाते हैं। हार्वर्ड से प्रत्यक्ष रूप से या उसके सहयोग और वितरण चैनलों के नेटवर्क के माध्यम से भारत पर अनेकों प्रभाव पड़ते हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि जिसे हम 'ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस 2.0' कहते हैं, उसे और भी ताकत मिली। यह हमारी एक दशक पहले प्रकाशित पुस्तक 'ब्रेकिंग इंडिया' का संदर्भ है, जिसने पहली बार इस घटनाक्रम पर

व्यापक ध्यान आकर्षित किया था। तब से, भारत के खिलाफ काम कर रही ताकतों में बदलाव आया है और पूरी तरह से नई ताकतें उभर कर सामने आई हैं जिन्होंने युद्ध को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है।

भारतीयों ने विश्व गुरु राक्षस का निर्माण किया

2008 में, भारत सरकार ने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को सम्मानित करने के लिए हार्वर्ड को भारतीय करदाताओं के 45 लाख डॉलर दिए। हार्वर्ड गजट ने रिपोर्ट किया:

भारत सरकार ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय को भारतीय स्नातक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु 45 लाख डॉलर का दान दिया है। यह दान हार्वर्ड में अर्थशास्त्र और दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर तथा थॉमस डब्ल्यू. लैमोंट विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अमर्त्य सेन की उपलब्धियों और विश्व भर में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के लिए उनके कार्यों को मान्यता देता है। साथ ही, यह दान हार्वर्ड के दक्षिण एशिया अध्ययन केंद्र के रूप में हार्वर्ड को स्थापित करने की दिशा में हार्वर्ड की दक्षिण एशिया पहल के कार्यों को भी मान्यता देता है।

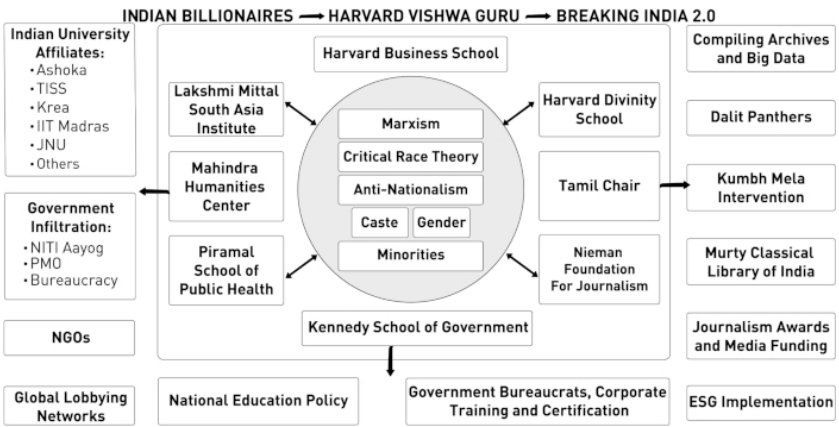

अमेरिका में भारत के तत्कालीन राजदूत रोनेन सेन ने इस समझौते को

संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा, “मुझे खुशी है कि हार्वर्ड ने प्रोफेसर अमर्त्य सेन की 75वीं जयंती पर इस उपहार को स्वीकार किया है, जो भारत के महान सपूत और विश्व के अग्रणी समकालीन विचारकों में से एक हैं।” उन्होंने आगे विश्वविद्यालय के भारत पर किए जा रहे प्रभावशाली शोध की प्रशंसा की, जिसे भारत से प्राप्त इस उपहार से और भी व्यापक बनाने का इरादा था।

यह वही रोनेन सेन हैं जिन्होंने आधिकारिक पद पर रहते हुए, अपने नेतृत्व वाले भारतीय वाणिज्य दूतावास की नौकरशाही को दरकिनार करते हुए, मॉर्मन मिशनरियों को अवैध रूप से भारतीय वीजा जारी किए थे। इसके लिए उन्हें यूटा से अमेरिकी सीनेटर गॉर्डन स्मिथ द्वारा सराहा गया था, जिसका खुलासा लीक हुए वीडियो से हुआ।

8 फरवरी 2009 को रिकॉर्ड किए गए "मॉर्मन लीक्स" शीर्षक वाले एक लीक हुए वीडियो में, तत्कालीन अमेरिकी सीनेटर गॉर्डन स्मिथ ने रोनेन सेन पर भारत में मॉर्मन चर्च के सदस्यों के लिए वीजा बढ़ाने का दबाव डाला। स्मिथ मॉर्मन चर्च के आजीवन सदस्य हैं। वे बताते हैं कि कैसे अमेरिकी सीनेट में मौजूद धर्मनिष्ठ मॉर्मन भारत में मॉर्मन चर्च को पहुँच और प्रभाव प्रदान करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कैसे सेन और उन्होंने भारतीय नौकरशाही से बचने के लिए एक तरह का समझौता किया था। सेन ने सीधे तौर पर 200 मॉर्मन वीजा को प्रभावित किया। स्मिथ ने सुझाव दिया कि इसी तरह अन्य मॉर्मन सीनेटरों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये लीक हुए वीडियो 2007 से 2012 के बीच शूट किए गए थे।

मातृभूमि के प्रति इस 'सेवा' के लिए रोनेन सेन को 2012 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।

2010 से पहले, हार्वर्ड को किसी विदेशी दाता से मिला अब तक का

सबसे बड़ा दान टाटा कंपनीज़, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा दिया गया पचास मिलियन डॉलर का था। इसके बदले में, हार्वर्ड ने अपनी एक इमारत का नाम 'टाटा हॉल' रखने पर सहमति जताई।[8] इसकी पश्चिमी विद्वानों सहित कई लोगों ने आलोचना की। आलोचकों ने कहा कि विशेष कर-मुक्त स्थिति को देखते हुए, टाटा भारत को आयकर से वंचित कर रहा था और दुनिया के सबसे समृद्ध विश्वविद्यालय को 103 वर्षों में अपना सबसे बड़ा दान दे रहा था। टाटा ट्रस्ट्स द्वारा 2010 में प्रतिष्ठित (एचबीएस) को दिए गए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के उपहार की जांच शुरू हो गई है... भारत से सार्वजनिक धन के दुनिया के सबसे विशेषाधिकार प्राप्त और धनी लोगों की ओर "स्पष्ट रूप से गलत तरीके से निर्देशित" होने पर सवाल उठ रहे हैं। इंटरलिंक कैपिटल स्ट्रैटेजीज के प्रबंध निदेशक एलन बियर्ड ने... द डेली कॉलर में सवाल उठाया, "अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक... सबसे जरूरतमंदों से अपना खजाना कैसे छीन सकता है? और व्यापार प्रबंधन का इतना सम्मानित संस्थान सुशासन के हर सिद्धांत के खिलाफ जाने वाले संदिग्ध धन को स्वीकार करने की विडंबनाओं के प्रति इतना अंधा कैसे हो सकता है?"

"...अगर भारतीय सरकार की जांच में यह निष्कर्ष निकलता है कि गरीब भारतीयों से धन लेकर अमीर पश्चिमी लोगों को नहीं भेजा जाना चाहिए था, तो टाटा का यह दान जनसंपर्क के लिहाज से एक बड़ी आपदा साबित हो सकता है," बियर्ड ने कहा। ... (उन्होंने) भारत से आई मीडिया रिपोर्टों का हवाला दिया... कि इस दान की भारतीय सरकार द्वारा जांच की जा रही है। ... भारत की लोक लेखा समिति (PAC) की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर उप-समिति की दो मुख्य चिंताएं हैं – पहली, यह दान टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा के निजी कोष से नहीं,

बल्कि एक भारतीय परोपकारी संगठन टाटा ट्रस्ट्स से सीधे आया था; दूसरी, इस दान ने धर्मार्थ ट्रस्टों से प्राप्त दान की कर-मुक्त स्थिति का अनुचित लाभ उठाया।"

"हार्वर्ड बिजनेस स्कूल (एचबीएस) में टाटा हॉल का नामकरण, यदि सच है, तो यह बेहद चिंताजनक और नैतिक रूप से निंदनीय है," बियर्ड ने लिखा। भारतीय सरकार की उप-समिति ने कहा है कि "(हार्वर्ड के) टाटा हॉल का निर्माण न तो दान था और न ही कोई अंतरराष्ट्रीय कल्याणकारी कार्य जिसमें भारत की रुचि थी," बल्कि यह "विभिन्न टाटा ट्रस्टों के एक/कुछ न्यासियों के व्यक्तिगत हितों को बढ़ावा देने" के लिए था। बियर्ड ने कहा कि भारत में सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट का उद्देश्य देश के गरीब और वंचित लोगों का भला करना है।

उन्होंने कहा, '... सार्वजनिक धन का स्पष्ट रूप से दुरुपयोग हुआ है...'। बियर्ड ने 'अब संदिग्ध हो चुके इस लेन-देन' में एचबीएस के डीन नितिन नोहरिया की 'स्पष्ट भूमिका' पर भी सवाल उठाया और कहा कि सितंबर 2013 में टाटा हॉल के निर्माण के पूरा होने से तीन महीने पहले, नोहरिया को टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस के बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था।

2003 में, हार्वर्ड ने दक्षिण एशिया के अध्ययन के लिए एक छोटी सी पहल शुरू की थी, जिसे दक्षिण एशिया पहल कहा जाता था। हालाँकि, टाटा के इस दान ने एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, क्योंकि इसने कई अन्य भारतीय अरबपतियों को हार्वर्ड के जादुई प्रभाव में आने के लिए प्रोत्साहित किया।

2017 में, विश्व की सबसे बड़ी इस्पात कंपनी के मालिक भारतीय अरबपति लक्ष्मी मित्तल ने पच्चीस मिलियन डॉलर का दान देकर इस पहल को और बढ़ावा दिया। हार्वर्ड ने इस पहल का नाम उनके नाम पर

रखकर इसे और मजबूत किया और इस तरह लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान की स्थापना हुई। टाटा से मिले इस दान के तुरंत बाद, तरुण खन्ना हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर से पदोन्नत होकर दक्षिण एशिया पहल के प्रमुख बने और अब हार्वर्ड में मित्तल संस्थान के प्रमुख हैं। वे अटल इनोवेशन मिशन के आयोग सदस्य हैं, जिसका प्रचार 'नीति आयोग द्वारा देश भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एक प्रमुख पहल' के रूप में किया जाता है। वे भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर विकास समिति के सह-अध्यक्ष भी हैं। इस प्रकार, खन्ना दोनों क्षेत्रों में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं।

भारत में हार्वर्ड की पैठ तब और भी गहरी हो गई जब सरकार ने 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) लागू की। यह अमेरिकी सामाजिक विज्ञान और मानविकी के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों के लिए एक बड़ा अवसर साबित हुआ। नई नीति के तहत अमेरिकी विश्वविद्यालय भारत में सभी आकार के भारतीय दानदाताओं से धन जुटाने के उद्देश्य से सीधे ट्रस्ट स्थापित कर सकते हैं। इस नीति का लाभ उठाते हुए हार्वर्ड ने तुरंत दिल्ली में एक कार्यालय स्थापित किया। अब भारत में इसे कर-मुक्त दर्जा प्राप्त है, और भारतीय व्यवसायी, गैर-सरकारी संगठन और परोपकारी संस्थाएं भारत में हार्वर्ड को दान देने पर कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। दरअसल, नई नीति ने पश्चिमी संस्थानों को उनके अपने देशों में भी सामाजिक हेरफेर के उनके पिछले रिकॉर्ड की जांच किए बिना ही आमंत्रित कर लिया है। आगे के अध्यायों में भारत की नीतियों और सभ्यतागत वृत्तांत पर हार्वर्ड के शोध के विनाशकारी परिणामों और भावी पीढ़ियों के मस्तिष्क को प्रभावित करने के प्रभावों को दर्शाया जाएगा।

हार्वर्ड एक अच्छे पुलिस अधिकारी के रूप में

जब उत्तरी अमेरिका में यूरोपीय बसने वाले मूल अमेरिकियों की ज़मीनें हथिया रहे थे, तब कुछ श्वेत व्यक्तियों (जिन्हें 'अच्छे पुलिसकर्मी' कहा जाता था) ने हस्तक्षेप करके उनकी मदद की। उन्होंने मूल निवासियों की दुर्दशा को समझा, उनके लिए लड़ाई लड़ी और यहाँ तक कि सत्ता में बैठे श्वेत लोगों के साथ बातचीत में उनका प्रतिनिधित्व भी किया। शुरुआत में, इन अच्छे पुलिसकर्मियों ने मूल निवासियों का दिल और विश्वास जीत लिया। लेकिन अंततः उन्होंने मूल निवासियों को धोखा दिया और बुरे पुलिसकर्मियों के साथ मिल गए। मूल निवासियों की हालत उससे भी बदतर हो गई, अगर उन्होंने खुद का प्रतिनिधित्व किया होता और इन मध्यस्थों पर भरोसा न किया होता। अच्छे पुलिसकर्मी या तो यह कहकर अपना दोषमुक्त कर लेते थे कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की और असफल रहे; या फिर वे पाला बदलने के बहाने के रूप में मूल निवासियों पर मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाते थे।

अंततः, मूल निवासियों के लिए यह एक बुरा विचार साबित हुआ कि उन्होंने इन श्वेत लोगों को श्वेत सत्ता प्रतिष्ठान के साथ व्यवहार करने में मध्यस्थ और मददगार के रूप में काम करने दिया। विशेष रूप से 1820 और 1930 के दशक के उत्तरार्ध में, सातवें अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन के शासनकाल के दौरान, इस तरह की स्थिति के अनेक उदाहरण देखने को मिले। मूल निवासियों ने अपनी ज़मीनें खो दीं और सांस्कृतिक एवं शारीरिक नरसंहार का सामना किया। समस्या यह थी कि मूल निवासी अपना नेतृत्व विकसित करने में विफल रहे और मददगारों और उनकी उदारता पर निर्भर हो गए।

यही स्थिति अश्वेत अमेरिकियों के मामले में भी दोहराई गई। अमेरिकी इतिहास में पुनर्निर्माण काल (1865-77) के बाद, अश्वेतों ने भी वही

सबक सीखा: अपने हितों की रक्षा के लिए श्वेत नेतृत्व पर निर्भर रहना एक रणनीतिक गलती थी। तभी अश्वेतों ने श्वेतों के मार्गदर्शन से मुक्त होकर अपने स्वयं के नेताओं को विकसित करने का निर्णय लिया और स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हुए अपने स्वयं के समाधान और नीतियां तैयार कीं।

भारत की मदद करने के नाम पर हार्वर्ड का खुद को एक आदर्श पुलिस अधिकारी के रूप में स्थापित करना एक समस्या है। यह भारत के जटिल मुद्दों में दखल देना, रणनीतिक डेटाबेस पर नियंत्रण करना और मुद्दों को अपने हिसाब से ढालना पसंद करता है। ऊपर वर्णित अमेरिकी सीमांत और हार्वर्ड में अंतर यह है कि हार्वर्ड अपने मार्गदर्शन में भारतीयों को आदर्श पुलिस अधिकारी बनने का प्रशिक्षण देता है। यह भावी नेताओं को भारत की आवाज़ बनने के लिए तैयार करता है और फिर उनके पूरे करियर में उन्हें स्थापित और समर्थन देता है। अंततः इससे भारतीय समाज के एक के बाद एक पहलुओं पर औपनिवेशिक नियंत्रण स्थापित हो जाता है। यह कुछ वैसा ही है जैसा अंग्रेजों ने पूरे भारत में जमींदारों का एक नेटवर्क बनाया था, जिन्हें जनता पर शासन करने में मदद के बदले अंग्रेजों से समर्थन प्राप्त होता था।

हार्वर्ड के पाठ्यक्रमों, सेमिनारों और अनुदानों में दी जाने वाली बहुत सी सामग्री भारत के विकास के लिए उपयोगी प्रतीत हो सकती है। हालांकि, मुद्दा उन अन्य प्रभावों का है जो युवा दिमागों पर धीरे-धीरे असर डालते हैं। जैसा कि अगले अध्यायों में दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट होता है, भारत ने अपने भावी नेताओं की विचारधाराओं, संबद्धताओं, निष्ठाओं और समग्र पहचान की भावना को विकसित करने का कार्य हार्वर्ड को सौंप दिया है। लेकिन क्या हार्वर्ड को भारत लाने की इस जल्दबाजी में इसके व्यापक प्रभावों पर विचार किया गया है? चीन ने बिल्कुल अलग दृष्टिकोण

अपनाया है। यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) से संबंधित रणनीतिक प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अमेरिकी ज्ञान को वापस ला रहा है, और विशेष रूप से अमेरिका से चीन में आयात किए जा रहे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों में इसकी कोई रुचि नहीं है। वास्तव में, जहाँ चीन अपनी सीमाओं के भीतर अमेरिकी 'वोकेवाद' को अस्वीकार करता है, वहीं वह अमेरिकी समाज पर प्रहार करने के लिए 'वोकेवाद' का उपयोग एक आक्रामक हथियार के रूप में करता है; चीन, सीसीपी द्वारा वित्त पोषित चाइना ग्लोबल टेलीविज़न नेटवर्क का उपयोग करके अमेरिकी बच्चों को लक्षित करते हुए अंग्रेजी में वीडियो प्रसारित करके अमेरिका में क्रिटिकल रेस थ्योरी को बढ़ावा दे रहा है।

हार्वर्ड की भारत परियोजनाओं को अलग-थलग करके देखना एक गलती होगी। ये उस विशाल पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं जिसका खुलासा यह पुस्तक करती है। ऐसी सैकड़ों परियोजनाएं और कुछ हज़ार वर्तमान और भावी विद्वान भारत के पारंपरिक भव्य आख्यान को ध्वस्त करने और उसकी जगह एक नया आख्यान स्थापित करने में लगे हुए हैं, जो भारतीय संप्रभुता के कई मूलभूत सिद्धांतों और विशेष रूप से इसकी वैदिक नींव को नकारता है।

एक तरह से यह कहा जा सकता है कि यह हार्वर्ड द्वारा तैयार किया गया भारत का एक भव्य वृत्तांत है जिसे मुख्यधारा के रूप में विकसित और सामान्यीकृत किया जा रहा है, और यह सब भारतीय धन, इस उद्देश्य के लिए नियुक्त भारतीय प्रतिभाओं और भारतीयों को मध्यस्थों और वितरण चैनलों के रूप में उपयोग करके भारत और दुनिया भर के लोगों तक इस वृत्तांत को पहुंचाने के माध्यम से किया जा रहा है।

हम यह साबित करेंगे कि हार्वर्ड ने एक उच्चस्तरीय बौद्धिक समुदाय

विकसित किया है, जिसके पास सशक्त संसाधन हैं और इसे नई दिल्ली और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में स्थापित किया है। यह ढांचा भारतीय विद्वानों के हार्वर्ड तक पहुंचने के लिए एक मजबूत माध्यम का काम करता है। और हार्वर्ड अपनी ब्रांड वैल्यू के कारण ही इस क्षेत्र का संरक्षक बन पाया है।

परिणामस्वरूप, भारत स्थित केंद्रों के अपने पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से, हार्वर्ड सार्वजनिक स्वास्थ्य, व्यवसाय, सामाजिक विज्ञान, भारत विज्ञान, इतिहास, मानविकी और सरकार के क्षेत्रों में भारत-विशिष्ट ज्ञान का भंडार बना रहा है, जिसे अत्याचार साहित्य तैयार करने, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने और भारत को और कमजोर करने के लिए रणनीतिक रूप से तैनात किया जा सकता है।

सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 ने विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भारत में प्रवेश के द्वार खोल दिए हैं: वे भारत में बेझिझक अपनी शाखाएँ स्थापित कर सकते हैं। यह घुसपैठ सार्वजनिक है और इसे भारत सरकार का पूर्ण समर्थन प्राप्त है।

विडंबना यह है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। हार्वर्ड वही भूमिका निभा रहा है जो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ऑक्सफोर्ड ने निभाई थी। ऑक्सफोर्ड भारत पर शासन करने के लिए औपनिवेशिक नेताओं को प्रशिक्षित करने में अधिक पारदर्शी था। लेकिन हार्वर्ड की कार्यप्रणाली चालाकी भरी और इतनी स्पष्ट नहीं है, और इसकी गतिविधियों के विवरण को समझने और संकलित करने के लिए गहन शोध की आवश्यकता है। भारत विद्या का जन्म यूरोप में हुआ और शास्त्रों के संदेश को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। इस बार, हार्वर्ड ही इसका दोषी है। निम्नलिखित तालिका ब्रिटिश शासन के लिए ऑक्सफोर्ड की भूमिका और अमेरिकियों के लिए हार्वर्ड की भूमिका के बीच कुछ प्रमुख अंतरों को दर्शाती है।

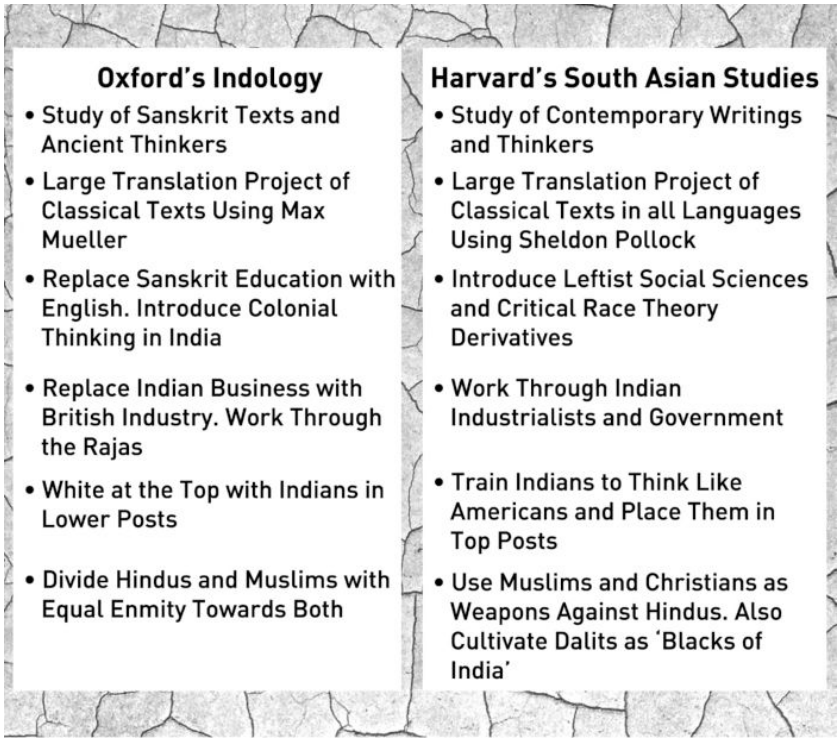

अगर हार्वर्ड को दान में मिलने वाली करोड़ों डॉलर की रकम भारत में निवेश की जाए, तो भारत अपनी शिक्षण क्षमताओं को बढ़ा सकता है और अपने संस्थानों को मजबूत कर सकता है। हार्वर्ड के हर एक स्कॉलर को मिलने वाली धनराशि के बदले भारत में बीस स्कॉलरों को धनराशि दी जा सकती है। भारतीय विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को शिक्षित कर सकते हैं और भविष्य की अर्थव्यवस्था में नए योगदानकर्ताओं को लाने के लिए मजबूत संस्थान बनाने में मदद कर सकते हैं। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा में क्षमता निर्माण समय की मांग है और यह कार्य कहाँ किया जाता है, यह महत्वपूर्ण है।

भारत का अध्ययन करने के लिए पश्चिमी विद्वानों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला वैचारिक दृष्टिकोण गलत है। भारत में हार्वर्ड का प्रभाव जितना

बढ़ता जाएगा, भारतीय खुद को उसी नजरिए से देखने लगेंगे। जब किसी सभ्यता के लोग खुद को अपने तरीके से परिभाषित नहीं कर पाते, तो वह सभ्यता फलना-फूलना बंद कर देती है। भारत को भारत अध्ययन की देखरेख उसी तरह करनी चाहिए, जैसे चीन चीन अध्ययन को नियंत्रित करता है। तभी भारत गलत व्याख्याओं से बच सकता है और अपने ही लोगों को अपने हितों के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल होने से रोक सकता है। हम पहले ही देख चुके हैं कि पश्चिम द्वारा भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर दशकों के शोध का नतीजा हिंदू धर्म को ही खत्म करने की मांग करने वाले निष्कर्षों में परिणत हुआ है।

भारत के इतिहास को हार्वर्ड को सौंपना भारत के लिए दोहरी मार है। इसका कारण यह है कि हार्वर्ड न केवल भारत पर अत्याचारों से संबंधित साहित्य तैयार करता है, बल्कि इसकी लोकप्रियता भी इसे उच्च स्तर की विश्वसनीयता प्रदान करती है। यह अपने इस ब्रांड का लाभ उठाकर भारतीय विचारकों और राजनेताओं को अपने साथ जोड़ रहा है और भारतीय कॉरपोरेट जगत के नेताओं और नौकरशाहों को प्रमाणन प्रदान कर रहा है। परिणामस्वरूप, हार्वर्ड द्वारा भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य, मानवाधिकार, अल्पसंख्यकों, जाति और महिलाओं से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण रिपोर्ट का विरोध करना राजनीतिक रूप से कठिन हो गया है।

10. डेटाबेस, वर्गीकरण और अभिलेखागार

अवलोकन

ब्रिटिश शासन के दौरान, भारत से ब्रिटेन में ज्ञान का काफी आदान-प्रदान

हुआ, जो ब्रिटिश ज्ञान के रूप में आत्मसात हो गया। इस आदान-प्रदान के प्रमाण बिखरे हुए हैं, लेकिन ठोस हैं और विवरणों को संकलित करने के लिए व्यापक शोध की आवश्यकता है। वनस्पति विज्ञान, गणित, धातु विज्ञान, वस्त्र विज्ञान, भाषा विज्ञान और चिकित्सा जैसे क्षेत्र इसके सुस्थापित उदाहरण हैं। प्रत्येक विशिष्ट क्षेत्र में, ब्रिटिश पहले भारत में एक संगठन स्थापित करते थे ताकि भारतीय विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम किया जा सके और उनसे सीखा जा सके। इसमें भारतीयों की बौद्धिक संपदा की नकल करना और फिर उसमें सुधार करना शामिल था। धीरे-धीरे, और चरणों में, भारतीय ज्ञान की यह नकल ब्रिटेन में स्थानांतरित हो गई। अंततः, भारतीय उद्योग या अनुशासन को बंद कर दिया गया, जिसमें अक्सर कठोर तरीके अपनाए जाते थे, जिनमें भारतीय संस्कृति को आदिम और अपमानजनक बताकर आरोप लगाना भी शामिल था।

हाल के समय में, भारतीय विचारों का अमेरिकी आत्मसातकरण भी इसी तरह हुआ है। अमेरिका स्थित अवेदा, त्वचा की देखभाल और सौंदर्य के लिए आयुर्वेदिक तकनीकों और सूत्रों के व्यवस्थित हस्तांतरण का एक अच्छा उदाहरण है। इसके परिणामस्वरूप दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति-आधारित सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड विकसित हुआ। इसकी मूल कंपनी, एस्टी लॉडर कंपनीज़ ने भारत से जड़ी-बूटियों की खेती को अमेरिका और अन्य जगहों पर अपने खेतों में स्थानांतरित करते हुए अरबों डॉलर का मुनाफा कमाया।

इरादे अक्सर अच्छे होते हैं, और विदेशी शोधकर्ताओं द्वारा भारतीय ज्ञान के अध्ययन से भारत को लाभ भी हो सकता है। हालांकि, बौद्धिक संपदा के उचित बंटवारे के लिए शुरू से ही कानूनी अनुबंध न होने पर, इस बात की पूरी संभावना है कि पश्चिमी पक्ष को फायदा होगा और भारत विदेशी प्रौद्योगिकी के केवल उपभोक्ता के रूप में ही रह जाएगा।

आज के समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता में एल्गोरिदम को प्रशिक्षित करने के लिए डेटाबेस के रूप में घरेलू ज्ञान का उपयोग कहीं अधिक गंभीर मुद्दा है। इसके निहितार्थ महज आर्थिक मूल्य से कहीं अधिक व्यापक हैं। किसी अन्य देश के बारे में डेटाबेस और ज्ञान रखने की शक्ति को समझना महत्वपूर्ण है। पुस्तक, "कृत्रिम बुद्धिमत्ता और शक्ति का भविष्य", उन राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों को दर्शाती है जिनका सामना भारत को करना पड़ रहा है क्योंकि विदेशी संस्थाएं विभिन्न रूपों में उसके डेटाबेस का दुरुपयोग कर रही हैं।

वर्गीकरण: भारतीय और पश्चिमी

परंपरागत भारतीय चिंतन में अनेक संगठनात्मक सिद्धांत व्याप्त हैं जिन्हें वर्गीकरण के रूप में समझा जा सकता है: ब्रह्मांड विज्ञान और तत्वमीमांसा, भाषा विज्ञान, नृत्य, संगीत, वनस्पति विज्ञान, सामाजिक संरचनाएँ, योग, गणित, चिकित्सा आदि। अग्रणी भारतीय विचारकों ने किसी विषय पर बड़ी मात्रा में जानकारी संकलित और व्यवस्थित की तथा विश्व को समझने के लिए वैदिक आधार का उपयोग किया। इसके परिणामस्वरूप अनेक वर्गीकरणों का निर्माण हुआ जो भारतीय सभ्यता के व्याकरण और सारगर्भित वृत्तांतों के रूप में कार्य करते हैं।

वैदिक सभ्यता को एक खुली संरचना के रूप में देखा जा सकता है जो विशिष्ट वर्गीकरणों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं को अभिव्यक्त करती है। आधुनिक शब्दावली में, यह कहा जा सकता है कि भारतीय सभ्यता में अनेक क्षेत्र-विशिष्ट डेटाबेस शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की एक सुस्पष्ट संरचना है। ये सभी संरचनाएं और ज्ञान प्रणालियां वेदों की सार-संरचना का अनुसरण करती हैं।

पाणिनी और मनु की रचनाओं में इसके दो प्रमुख उदाहरण मिलते हैं।

व्याकरणविद् पाणिनी की अष्टाध्यायी में उन्होंने भारत भर में अपने समय के दौरान विभिन्न भाषाओं की विशेषताओं का संकलन करके भाषा की कार्यप्रणाली का वर्णन किया है। इन भाषाओं का विश्लेषण करके उन्होंने भाषा परिवार के वाक्यविन्यास और अर्थशास्त्र में मौजूद प्रतिरूपों और सिद्धांतों की खोज की।

इस प्रकार के व्याकरण के नियम वर्णनात्मक या निर्देशात्मक हो सकते हैं। वर्णनात्मक नियम केवल यह बताते हैं कि कोई चीज़ कैसे कार्य करती है, वह कैसे होती है, चाहे उसका कारण कुछ भी हो। गुरुत्वाकर्षण जैसा है वैसा ही है, और कोई भी भौतिक विज्ञानी यह नहीं बता सकता कि यह ऐसा क्यों है, या यह किसी विशेष तरीके से होना चाहिए या नहीं। भौतिकी और सभी आधुनिक विज्ञान का कार्य विशुद्ध रूप से वर्णनात्मक है। दूसरी ओर, निर्देशात्मक नियम यह निर्दिष्ट करते हैं कि व्यवहार कैसा होना चाहिए, जैसे कि किसी राजा द्वारा स्थापित कानून या संविधान जिसका नागरिकों को पालन करना चाहिए। निर्देशात्मक नियम मानव निर्मित हैं, इसलिए वे कृत्रिम और मनमाने हो सकते हैं।

एक अनुभवजन्य वैज्ञानिक प्राकृतिक घटनाओं (जैसे गुरुत्वाकर्षण या प्रकाश) के प्रतिरूपों का अवलोकन करता है और उन्हें प्रकृति द्वारा पालन किए जाने वाले 'नियमों' की एक प्रणाली के रूप में प्रतिरूपित करता है। ये नियम 'भौतिकी के नियम' कहलाते हैं और प्रकृति के कार्य करने के तरीके का वर्णन करते हैं। इन्हें 'नियम' इसलिए कहा जाता है क्योंकि पश्चिमी विचार उन धर्मों से उत्पन्न हुए हैं जहाँ ईश्वर को नियम निर्माता के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने प्रकृति द्वारा पालन किए जाने वाले इन निर्देशात्मक नियमों को बनाया है। यहूदी-ईसाई धर्म प्रकृति के व्यवहार को ईश्वर का निर्देश मानता है; मनुष्य इन व्यवहार प्रतिरूपों की खोज करते हैं और इसलिए, मानवीय दृष्टिकोण से ये वर्णनात्मक हैं। प्रकृति वैज्ञानिक से

स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, और विज्ञान केवल इसके प्रतिरूपों को उजागर करता है और उन्हें प्रकृति द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों के रूप में प्रस्तुत करता है।

इसी प्रकार, पाणिनी का व्याकरण विभिन्न भाषाओं के कार्य करने के तरीके को दर्शाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पाणिनी ने भाषाओं का आविष्कार नहीं किया और न ही उनके लिए व्याकरण स्थापित किया। बल्कि, वे उनसे पहले से ही विद्यमान थीं, ठीक वैसे ही जैसे प्राकृतिक घटनाएँ उन नियमों की खोज करने वाले वैज्ञानिक से पहले से विद्यमान होती हैं।

हालांकि, पाणिनी द्वारा खोजे जाने के बाद, उनके व्याकरण के नियम एक निर्देशात्मक कार्य भी करने लगे: विद्वानों ने इन नियमों को अपनाया और उनका पालन करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उनके व्याकरण का उपयोग करके अन्य भाषाओं को औपचारिक रूप भी दिया। दूसरे शब्दों में, पाणिनी के व्याकरण का उपयोग उन भाषाओं को पुनर्गठित करने के लिए किया गया है जो पहले इन नियमों का पालन नहीं कर रही थीं। इसके उदाहरण भारत में प्रारंभिक शताब्दियों में मिलते हैं। हाल ही में, यूरोप द्वारा पाणिनी के व्याकरण की खोज के बाद, यूरोपीय व्याकरणों को उन्नत करने के लिए तीव्र प्रयास किए गए। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्गीकरण किसी ज्ञान क्षेत्र, इस मामले में, प्राकृतिक भाषाओं के विकास में बहुत शक्तिशाली प्रभाव डालते हैं। वे विमर्श को एक निश्चित दिशा में निर्देशित करने का कार्य करते हैं।

भारत में सामाजिक आचरण पर संकलित और टीकाकार मनुस्मृति एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण का दूसरा प्रमुख उदाहरण है। मनु स्पष्ट करते हैं कि ये वे रीति-रिवाज हैं जिनका पालन लोग करते हैं; वे यह नहीं कहते कि ये सार्वभौमिक रूप से लागू किए जाने वाले नियमों का एक मानक समूह हैं।

वास्तव में, वे यह स्पष्ट करते हैं कि उत्तर के रीति-रिवाज दक्षिण के रीति-रिवाजों से भिन्न हैं, एक स्थानीय समुदाय से दूसरे स्थानीय समुदाय में भिन्न हैं, इतिहास के एक काल से दूसरे काल में भिन्न हैं, समाज के एक वर्ग या एक सामाजिक संदर्भ से दूसरे में भिन्न हैं। मनु प्रत्येक युग और प्रत्येक संदर्भ के लिए ऐसे ग्रंथों (जिन्हें स्मृति कहा जाता है) को अनुकूलित और पुनर्लेखन करने की वकालत करते हैं। मनुस्मृति सामाजिक संगठन के बारे में ऐसे ग्रंथों के संपूर्ण परिवार, जिसे धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है, का एक प्रमुख उदाहरण है।

यह एक विवादास्पद विषय है कि धर्मशास्त्र निर्देशात्मक बन गए थे या नहीं, और यदि बने थे, तो किस हद तक, किस समयावधि में और कहाँ। निर्देशात्मक होने पर, ऐसे नियमों को न्यायालयों और राजाओं द्वारा कानून के रूप में लागू किया जाता था। अन्यथा, ऐसे नियम किसी उच्च सत्ता के बल पर नहीं, बल्कि समाज के अपने विवेक पर आधारित रीति-रिवाजों का विशुद्ध वर्णनात्मक विवरण होते थे। इस पुस्तक के भाग 1 में इन स्मृतियों पर विस्तार से चर्चा की गई है।

ये दोनों उदाहरण – भाषाओं को व्याकरण में संकलित और विश्लेषित करना और सामाजिक प्रतिरूपों का अध्ययन करना और उन्हें धर्मशास्त्रों के रूप में समझाना – पहले से मौजूद घटनाओं के अनुभवजन्य डेटाबेस बनाने और उन्हें समझने के लिए एक सैद्धांतिक ढांचा प्रदान करने के उदाहरण हैं।

इस वर्गीकरण सूची में अन्य क्षेत्रों को भी आसानी से जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए, नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कलाओं और सौंदर्यशास्त्र का सिद्धांत है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में स्वदेशी डेटाबेस विकसित करने वालों और भारत को समझने के लिए उनके गहन वर्गीकरणों की कोई कमी नहीं थी।

पश्चिम ने भी अपनी-अपनी वर्गीकरण प्रणालियाँ विकसित की हैं। सभी प्राकृतिक विज्ञान – भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान आदि – प्रकृति के व्यवहार को समझने के लिए व्यवस्थित नियम विकसित करने में पश्चिम की महान उपलब्धियाँ हैं।

हमारी आलोचनाएँ पश्चिमी वर्गीकरण के अन्य क्षेत्रों से संबंधित हैं: मानविकी और सामाजिक विज्ञान, जो सामाजिक व्यवहार के नियमों के व्यवस्थित विकास से जुड़े हैं। इन्हें 'विज्ञान' कहकर, मानव व्यवहार के पश्चिमी सिद्धांतकारों ने विभिन्न विषयों पर अनुभवजन्य डेटा संकलित किया और सिद्धांत विकसित किए, जो कई मायनों में भौतिकविदों के कार्य करने के तरीके से मिलते-जुलते हैं। इन क्षेत्रों में अर्थशास्त्र, राजनीति, संस्कृति, समाजशास्त्र, इतिहास और मनोविज्ञान शामिल हैं। हालांकि, सैद्धांतिक रूप से इन सामाजिक विज्ञानों/मानविकी को प्राकृतिक विज्ञानों के समान ही विज्ञान के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन व्यवहार में इस समानता के साथ गंभीर समस्याएं हैं।

पहली बात तो यह है कि मानव व्यवहार को निर्जीव वस्तुओं की तरह प्रतिरूपित नहीं किया जा सकता क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र इच्छाशक्ति और चुनाव का प्रयोग करते हैं, और समय के साथ उनमें परिवर्तन आ सकता है, जिससे उनके व्यवहार की भविष्यवाणी करना कठिन हो जाता है। यह अंतर सर्वविदित और स्वीकृत है।

दूसरे, प्राकृतिक विज्ञानों में, प्रयोगकर्ता की मनस्थिति, धारणाएँ, विश्वास प्रणालियाँ, पूर्वाग्रह, पक्षपात और उद्देश्य परिणाम में कम महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि माप स्वयं वस्तुनिष्ठ होता है, भले ही व्याख्या वस्तुनिष्ठ न हो। सामाजिक विज्ञानों के संदर्भ में यह सत्य नहीं है।

तीसरा अंतर जो सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता की कमी का कारण बनता है, वह स्पष्ट रूप से समझा नहीं गया है और इस पुस्तक के लिए

बहुत महत्वपूर्ण है: पश्चिम ने हाल की शताब्दियों में अपनी कठोर शक्ति के लाभों के माध्यम से दुनिया को उपनिवेशित किया, और ऐसा करने में उसने अपनी सोच और इसलिए, अपने वर्गीकरणों को दूसरों पर थोपा। पुस्तक, 'बीइंग डिफरेंट: एन इंडियन चैलेंज टू वेस्टर्न यूनिवर्सलिज्म', में 'पश्चिमी सार्वभौमिकता' शब्द का प्रयोग पश्चिम के सीमित अनुभवों को पूर्ण और सार्वभौमिक नियमों के समूह में परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करने के लिए किया गया है, जो वर्णनात्मक और निर्देशात्मक दोनों हैं। पश्चिमी सार्वभौमिकता यूरोप की ऐतिहासिक घटनाओं से उत्पन्न मूल्यों और विश्वासों पर आधारित है। यह मानती है कि वे अनुभव सार्वभौमिक हैं, और इसलिए, पश्चिमी दर्शन, नैतिकता, सामाजिक विज्ञान और इतिहास उपयुक्त टेम्पलेट हैं जिनमें अन्य सभी सभ्यताओं को समाहित किया जा सकता है।

क्योंकि पश्चिमी सभ्यता को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, इसलिए गैर-पश्चिमी सभ्यताएँ केवल पूर्व की उत्पत्ति (जैसे 'हमारा अतीत') या उन क्षेत्रों के रूप में प्रासंगिक हैं जहाँ पश्चिम कार्य करता है ('हमारा सभ्यता निर्माण अभियान') या पश्चिमी हितों के लिए खतरे ('हमारी सीमाएँ') के रूप में। अन्य संस्कृतियों के अनूठे हित और पहचान का कोई विशेष महत्व नहीं है।

वास्तव में, सामाजिक विज्ञानों का अधिकांश विकास यूरोप द्वारा विश्व के उपनिवेशीकरण के दौरान हुआ, और इसका उद्देश्य उपनिवेशीकरण के एक उपकरण के रूप में कार्य करना था। मानवविज्ञानी, समाजशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक वैज्ञानिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक उपनिवेशवादियों के साथ मिलकर काम करते थे, और कई मामलों में उनके द्वारा नियोजित भी थे। उनका काम गैर-यूरोपीय लोगों को समझने के लिए विभिन्न वर्गीकरणों का निर्माण करना था, जिसका स्पष्ट उद्देश्य

उन्हें हराना, उन पर शासन करना, उन्हें नियंत्रित करना और कई मामलों में अंततः उनका विनाश करना था।

इसलिए, पश्चिमी सार्वभौमिकतावाद आम तौर पर पश्चिम की श्रेष्ठता को मानता है, और इसके सामाजिक सिद्धांत दूसरों को नीचा दिखाने की विषाक्तता से दूषित हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि सभी पश्चिमी सामाजिक विचार त्रुटिपूर्ण या हानिकारक हैं और उन्हें पूरी तरह से खारिज कर देना चाहिए। बल्कि, इसका तात्पर्य यह है कि इसके प्रत्येक दावे की गंभीरतापूर्वक जांच-पड़ताल किए बिना इसे बिना सोचे-समझे स्वीकार नहीं करना चाहिए। पश्चिमी सामाजिक विज्ञान के कई पहलू उन देशों में लागू होते हैं, लेकिन जब उन्हें वैश्विक स्तर पर लागू किया जाता है तो हिंसा का कारण बनते हैं।

पश्चिमी सामाजिक विज्ञानों की एक गंभीर समस्या यह है कि वे निर्देशात्मक हो गए हैं: पहले औपनिवेशिक काल में, और हाल ही में, जिसे वैश्वीकरण कहा जाता है उसके एक भाग के रूप में। वैश्वीकरण कई मायनों में विश्व का पश्चिमीकरण बन गया है। इस्लामी देशों और चीन से हाल ही में हुए विरोध को पश्चिमी सार्वभौमिकता के अत्यधिक शक्तिशाली हो जाने के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। पश्चिमी विचारों को जबरदस्ती थोपने के रूप में शुरू हुआ यह सिलसिला अब सामान्य हो गया है और इसे अचेतन रूप से 'वैज्ञानिक' के रूप में स्वीकार किया जाता है। इन सिद्धांतों को संकलित करने और उन्हें विश्व स्तर पर लागू करने वाली पश्चिमी संस्थाओं की शक्ति को देखते हुए, सामाजिक सिद्धांतकारों में विनम्रता की कमी दिखाई देती है, जिनमें विशेष रूप से गैर-पश्चिमी देशों से नियुक्त किए गए और पश्चिमी संस्थाओं की सेवा में लाए गए अश्वेत लोग शामिल हैं।

इस अध्याय में हम कई उदाहरणों के माध्यम से निम्नलिखित प्रक्रियाओं

को क्रियान्वित होते हुए दिखाएंगे:
डेटाबेस, अभिलेखागार और वर्गीकरण → मानक पश्चिमी ढाँचे → विश्व स्तर पर अपनाए गए और अभिजात वर्ग द्वारा नियंत्रित सार्वभौमिकता

औपनिवेशीकरण: वर्गीकरण प्रणालियों का टकराव
दो सभ्यताओं के बीच टकराव में, उनकी वर्गीकरण प्रणालियों में स्वाभाविक रूप से मतभेद उत्पन्न होता है। कठोर शक्ति से प्रबल पक्ष, पराजित या पराजित पक्ष की वर्गीकरण प्रणाली का भविष्य भी निर्धारित कर सकता है, और इस प्रकार उसकी सौम्य शक्ति को भी नियंत्रित कर सकता है।
कई मामलों में, पराजित पक्ष के सभी ज्ञान को मिटाने के लिए पुस्तकों को जला दिया गया, ताकि आने वाली पीढ़ियों का मस्तिष्क परिवर्तन करके उन्हें विजयी पक्ष की वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार पाला-पोसा जा सके। यूरोपियों ने अमेरिका और अफ्रीका में ऐसा किया, और चीन आज तिब्बत, शिनजियांग और हांगकांग में ऐसा कर रहा है। भारत के मुस्लिम विजेताओं और शासकों ने भी बड़े पैमाने पर पुस्तकों का विनाश किया, लेकिन उनकी मुख्य रुचि त्वरित धन उगाहने में थी।
पश्चिमी रणनीति कहीं अधिक परिष्कृत है। वे उपनिवेशित ज्ञान के उन हिस्सों को अपना लेते हैं जो उन्हें उपयोगी लगते हैं। इसे वे अपने हिसाब से नया रूप देते हैं और एक नई ज्ञान प्रणाली के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिस पर उनका अपना अधिकार होता है। यदि वे यह स्वीकार कर लें कि उनकी बौद्धिक प्रणालियों में उपनिवेशित लोगों से उधार लिए गए प्रमुख तत्व शामिल हैं, तो इससे पराजित पक्ष को मनोवैज्ञानिक रूप से शक्ति मिलेगी, जिससे उन पर शासन करना कठिन हो जाएगा। उपनिवेशवादियों और उपनिवेशितों के बीच सत्ता की विषमता वैज्ञानिक विचारों और

संस्कृतियों के इतिहास को पूरी तरह से मनगढ़ंत बनाने की अनुमति देती है। यही वर्गीकरणों का टकराव है।

सभ्यताओं के टकराव का परिणाम आम तौर पर वही होता है जिसे हमने पहले 'पाचन' के रूप में वर्णित किया है। यह तब होता है जब एक आक्रामक, शिकारी संस्कृति एक कमजोर संस्कृति को टुकड़ों में बांट देती है और उनमें से उन हिस्सों को चुन लेती है जिन पर वह अपना अधिकार जमाना चाहती है। ये हथियाए गए तत्व शिकारी की अपनी भाषा और सामाजिक संरचनाओं के इतिहास और प्रतिमानों में समाहित हो जाते हैं, जिससे मूल परंपरा का बहुत कम निशान बचता है। इस प्रकार लूटी गई सभ्यता अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक पूंजी से क्षीण हो जाती है। अंततः, क्षीण हो चुकी सभ्यता एक मृत संस्कृति के रूप में संग्रहालय में प्रवेश करती है, और शक्तिशाली सभ्यता के लिए कोई खतरा नहीं रह जाती। पाचन के बाद जो बचता है वह अपशिष्ट पदार्थ होता है जिसे हटाकर नष्ट कर दिया जाता है। शक्तिशाली पक्ष अपनी अवधारणाओं, सौंदर्यशास्त्र, भाषा, प्रतिमानों, ऐतिहासिक ढांचे और दर्शन को थोप देता है, और उन्हें सार्वभौमिक विश्वदृष्टि के रूप में स्थापित करता है। साथ ही, कमजोर संस्कृति की छवियां, प्रतीक, इतिहास और भाषाएं विकृत हो जाती हैं।

सरल शब्दों में कहें तो, पाचन एक सभ्यता को दूसरी सभ्यता के ढांचे में ढालने का एक तरीका है। पचाई गई सभ्यता अपने वर्गीकरणों पर नियंत्रण खो देती है और परिणामस्वरूप उसके सदस्य मानसिक रूप से गुलाम बन जाते हैं। जब कोई वर्गीकरण/ढांचा पश्चिम द्वारा हथिया लिया जाता है और उसे अपने एजेंडे के अनुरूप ढाल दिया जाता है, तो हम इसकी आलोचना पाचन की क्रिया, एक प्रकार की हिंसा के रूप में करते हैं। उपनिवेशित लोग अपने भौतिक और अनुभवात्मक क्षेत्र में अपना

रास्ता खो देते हैं क्योंकि उनके अनुभव पश्चिमी सार्वभौमिकता की आद्य-संरचना में पुनर्परिभाषित हो जाते हैं।

पश्चिमी देश दूसरों की सभ्यताओं को आत्मसात करने में अत्यंत कुशल होते हैं, और इसी कारण वे अन्य सभ्यताओं को अपने संदर्भ बिंदुओं में ढालकर उन पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। अंततः, पश्चिमी विशेषज्ञ और उनके मार्गदर्शन में प्रशिक्षित गैर-पश्चिमी लोग उस सभ्यता के विषय-विशेषज्ञ बन जाते हैं। उन्हें उस सभ्यता पर टिप्पणी करने, नीतिगत सुझाव देने और अंततः उन नीतियों को लागू करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

इस पुस्तक में उजागर की गई एक प्रमुख समस्या यह है कि अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देश, भारत से संबंधित अपने सामाजिक विज्ञान वर्गीकरणों में फिट होने वाले महत्वपूर्ण डेटाबेस और अभिलेखागारों के निर्माण पर नियंत्रण रखते हैं। इसने ज्ञान के हर क्षेत्र पर अपना प्रभाव जमा लिया है। जिन विभिन्न परियोजनाओं की हम आलोचना करते हैं, वे इसी विषय पर आधारित हैं, जैसे कुंभ मेले का मानचित्रण, भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य का मानचित्रण, जाति की पुनर्व्याख्या करके उसे अमेरिका में नस्लवाद के रूप में प्रस्तुत करना, और पश्चिमी देशों में लैंगिक संघर्ष के परिप्रेक्ष्य से भारत में लैंगिक डेटाबेस का निर्माण करना।

भारत के पुनः उपनिवेशीकरण की संभावना के प्रति इस पुस्तक की चेतावनी को समझने के लिए उपनिवेशवाद के इतिहास को बेहतर ढंग से समझना आवश्यक है। ब्रिटिश उपनिवेशवादी भारतीय समाज के बारे में कुछ विशेष प्रकार की जानकारी एकत्रित करने में अग्रणी थे। यह जानकारी भारत की शिक्षा प्रणाली, कृषि प्रणाली, सामाजिक स्तरीकरण, शासन प्रणाली, भाषा विज्ञान आदि से संबंधित थी। यह ज्ञान उनके साम्राज्य निर्माण की परियोजना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और केंद्रीय

बन गया।

ब्रिटिशों की रणनीति हर तरह के नक्शे बनाना थी – एक 'नक्शा' एक तरह का डेटाबेस होता था। राजनीतिक वैज्ञानिक बेनेडिक्ट एंडरसन ने यूरोपीय साम्राज्यों के निर्माण में इस तरह के नक्शा बनाने की भूमिका का दस्तावेजीकरण किया। उनकी पुस्तक, 'इमैजिन्ड कम्युनिटीज: रिफ्लेक्शंस ऑन द ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म', 1980 के दशक से एक क्लासिक बन गई है और उत्तर-औपनिवेशिक अध्ययन, इंडोलॉजी और दक्षिण एशियाई अध्ययन में व्यापक रूप से पढ़ाई जाती है। यह बताती है कि कैसे समुदाय उनके बारे में बनाए गए नक्शों से आकार लेते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवादी भूगोल, जनसंख्या, धार्मिक प्रथाओं, सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं का मानचित्रण (डेटाबेस को व्यवस्थित करने के व्यापक अर्थ में) करने के प्रति जुनूनी थे, जिसका उद्देश्य बेहतर बातचीत और नियंत्रण के लिए एक खाका तैयार करना था। इसी तरह का मानचित्रण पहले उत्तरी अमेरिका में यूरोपीय बसने वालों द्वारा किया गया था, जिसने मूल निवासियों के खिलाफ उनके व्यवस्थित आक्रमण में मदद की थी।

इस प्रकार का मानचित्र निर्माण आज भी जारी है: जिला और ग्राम स्तर पर भारत के कुछ बेहतरीन सामाजिक-धार्मिक डेटाबेस वे हैं जिन्हें हाल ही में चर्च और केंद्रीय खुफिया एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। एंडरसन द्वारा वर्णित औपनिवेशिक मानचित्र निर्माण परियोजना और हार्वर्ड जैसे अमेरिकी प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा भारत पर किए जा रहे वर्तमान शोध में एक विचित्र समानता है। यह इस पुस्तक के मुख्य विचार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और हम एंडरसन के इस प्रभावशाली कार्य में लिखे गए अंशों का सारांश प्रस्तुत करने के लिए कुछ स्थान समर्पित करेंगे।

एंडरसन ने भारत से संबंधित हर तरह के डेटा को इकट्ठा करने और उसे सिद्धांतों, ढाँचों, नीतियों आदि में बदलने के औपनिवेशिक जुनून का विस्तृत वर्णन किया। उनका एक उद्देश्य उपयोगी लगने वाली हर चीज की नकल करना और उसे अपनी बौद्धिक संपदा घोषित करना था। इससे चिकित्सा, कृषि, वनस्पति विज्ञान, वस्त्र, भाषा विज्ञान, धातु विज्ञान आदि क्षेत्रों में यूरोपीय ज्ञान के विस्तार में मदद मिली।

दूसरा, अधिक भयावह लक्ष्य, भारतीय मानसिकता का पूर्वानुमान लगाने और उसे नियंत्रित करने का तरीका समझना था। इसका उपयोग परिस्थिति के अनुसार भारतीय समाज की सहायता करने या उसे कमजोर करने के लिए किया जाता था। पश्चिमी सार्वभौमिकता में भारतीय ज्ञान को शामिल करना रचनात्मक उद्देश्यों के लिए था, जबकि भारतीय समाज को कमजोर करना विनाशकारी उद्देश्यों के लिए था।

एंडरसन बताते हैं कि यूरोपीय लोगों द्वारा अपने औपनिवेशिक परिसंपत्तियों, यानी क्षेत्र और निवासियों, को दर्ज करने की परियोजना को तीन संस्थानों - जनगणना, मानचित्र और संग्रहालय - के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था। इन संस्थानों को यांत्रिक पुनरुत्पादन की नई तकनीकों के उपयोग से लाभ हुआ। एंडरसन कहते हैं,

इन सबने मिलकर औपनिवेशिक राज्य द्वारा अपने प्रभुत्व की कल्पना करने के तरीके को गहराई से आकार दिया—जिसमें उसके द्वारा शासित मनुष्यों की प्रकृति, उसके क्षेत्र का भूगोल और उसकी वंशावली की वैधता शामिल थी।

जनगणनाएँ बहुत बड़े पैमाने पर किए जाने वाले कार्य थे, जिन्होंने अंततः समाज को उसके सामाजिक पदानुक्रम में प्रत्येक व्यक्ति के स्थान को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वर्गीकरण के प्रकार से रूपांतरित कर दिया। जनगणना करने वालों में सटीकता के प्रति अटूट

लगन थी, और इसकी विशालता और कठोरता ने इसे अत्यधिक विश्वसनीयता प्रदान की। देशी शासकों द्वारा की गई पिछली जनगणनाएँ केवल कर संग्रह के उद्देश्य से थीं और उन्होंने सामाजिक श्रेणियों के नए प्रकारों को प्रस्तुत नहीं किया था। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से आगे की क्रमिक जनगणनाओं में श्रेणियों को पुनर्परिभाषित करने के तरीके में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देते हैं: समूहों को लगातार समूहीकृत, असंबद्ध, पुनर्संयोजित, मिश्रित और पुनर्व्यवस्थित किया गया।
औपनिवेशिक काल के आगे बढ़ने के साथ, जनगणना श्रेणियाँ अधिक स्पष्ट रूप से नस्लीय होती गईं, जबकि धार्मिक पहचान धीरे-धीरे प्राथमिक जनगणना वर्गीकरण के रूप में लुप्त हो गई। अध्याय 6 में जमीनी स्तर पर सामाजिक वास्तविकता को विकृत करने में ब्रिटिश जनगणना की भूमिका पर चर्चा की गई है।
सन् 1730 के दशक में कालमापी के आविष्कार से मानचित्र निर्माण में एक बड़ी छलांग लगी, जिससे देशांतरों की सटीक गणना संभव हो सकी। संपूर्ण विश्व को एक समतल ज्यामितीय ग्रिड पर दर्शाया जा सकता था। इस खाली टेम्पलेट में उपनिवेशवादियों द्वारा चुने गए अनुभवजन्य आंकड़ों को डाला जा सकता था। इससे पहले, जो मानचित्र मौजूद थे वे ब्रह्मांड विज्ञान पर आधारित काल्पनिक मानचित्र थे। उदाहरण के लिए, एक बौद्ध मानचित्र में स्वर्ग और नरक तथा उनके बीच के पृथ्वी लोक को दर्शाया जा सकता था। एक विशुद्ध धर्मनिरपेक्ष मानचित्र में सैन्य अभियानों और जहाजों के आरेख हो सकते थे। लेकिन ब्रिटिश मानचित्र अक्षांश और देशांतरों के साथ संदर्भ-मुक्त संख्याओं का उपयोग करके भूगोल को दर्शाते थे।
मानचित्र और जनगणना के अंतर्संबंध ने एक बिल्कुल नई तरह की शक्ति का सृजन किया। जनगणना से प्राप्त जनसांख्यिकीय आंकड़ों को

मानचित्रों में शामिल किया गया, जिससे वे केवल स्थलीय होने के बजाय राजनीतिक उपकरण बन गए। मानचित्र संबंधी संदर्भों के आधार पर चर्चा को नया स्वरूप दिया गया। पारंपरिक संदर्भ बिंदु पवित्र स्थलों, नदियों, समुद्रों, पहाड़ों, समुदायों, धर्मों और भाषाओं के संदर्भ में थे। नए प्रकार का मानचित्र इन सभी से अलग हो गया और व्यक्ति की भौतिक वास्तविकता का एक नया अमूर्त रूप बन गया।

मानचित्र किसी वस्तु का प्रतिनिधित्व करने वाला मॉडल नहीं था, बल्कि वह वस्तु का वास्तविक मॉडल था जिसका वह प्रतिनिधित्व करने का दावा करता था। यह पृथ्वी की सतह पर अनुमानों को मूर्त रूप देने का एक वास्तविक साधन बन गया था। मानचित्रण की अवधारणा वह प्रतिमान थी जिसके अंतर्गत प्रशासनिक और सैन्य दोनों अभियान कार्य करते थे और उसकी सेवा करते थे।

मुद्रण तकनीक की सहायता से भूगोल को दर्शाने का नया तरीका और भी व्यापक हो गया। शासकों ने अपनी सुविधानुसार मानव पदानुक्रम, इतिहास और संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए नए मानचित्रों को सावधानीपूर्वक सामग्री से भर दिया। राजनीतिक-जीवनी संबंधी वृत्तांतों के रूप में कार्य करने वाले मानचित्रों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। परिणामस्वरूप, मूल निवासियों के लिए अपनी दुनिया को समझने का एक बिल्कुल नया तरीका सामने आया।

तीसरी संस्था – संग्रहालय – यूरोप के लिए स्वाभाविक है क्योंकि यूरोपीय इतिहास निरंतरता की एक कहानी है जिसमें प्रत्येक युग अतीत की संस्कृतियों को नष्ट करने के लिए हिंसा से चिह्नित है। संग्रहालयों में संग्रहित वस्तुएं मृत अतीत से संबंधित होती हैं और वर्तमान समाज उन्हें 'उन लोगों' से जुड़ी वस्तु के रूप में देख सकता है। अपने अतीत से अलग-थलग होने की यह धारणा उन लोगों तक पहुंचाई गई जिन पर यूरोपियों ने

विजय प्राप्त की। यह एक प्रकार की हिंसा थी क्योंकि गैर-पश्चिमी लोगों में आमतौर पर अपने अतीत को अपने वर्तमान जीवन से अलग होने की वैसी भावना नहीं होती थी।

उदाहरण के लिए, किसी जीवित देवता की पूजा-अर्चना के अनुष्ठान उसी तरह से नहीं किए जा सकते, जब उसका मंदिर किसी संग्रहालय या पुरातत्व संस्थान द्वारा प्रबंधित 'पुरातत्व स्थल' में परिवर्तित हो जाता है। संग्रहालय में रखी देवता की प्रतिमा मात्र एक प्रतिमा रह जाती है, वह जीवित व्यक्ति नहीं जो कभी हुआ करता था। इस प्रकार संग्रहालयों और पुरातत्व ने 'मृत अतीत' और जीवित परंपरा को परिभाषित करने में एक साथ काम किया। उपनिवेशवादियों ने यह तय किया कि मूल निवासियों के अतीत के किन पहलुओं को उनके जीवित वर्तमान के विपरीत उनकी प्राचीनता के रूप में वर्गीकृत करके 'नष्ट' किया जा सकता है।

साथ ही, उपनिवेशवादियों ने स्थानीय लोगों को अपनी उदारता और नेक इरादों का आड़ देने के लिए पुरातात्विक जीर्णोद्धार की विशाल परियोजनाओं को प्रायोजित किया, जबकि वैज्ञानिक विकास की आड़ में उन्होंने अपने पूर्वाग्रहों को छिपाए रखा। पुनर्निर्मित स्मारकों में अक्सर प्रगतिशील पश्चिम के प्रतीकों को मूल निवासियों की आदिम अवस्था के साथ मिलाकर दिखाया जाता था। किसी उपनिवेश की प्राचीनता का दस्तावेजीकरण उपनिवेशवादियों की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करने का एक दिखावटी तरीका बन गया। इस प्रकार उपनिवेशित सभ्यताओं को संग्रहालय में संरक्षित किया जा सकता था और एक धर्मनिरपेक्ष औपनिवेशिक राज्य के प्रतीक के रूप में स्थापित किया जा सकता था। जनगणना, मानचित्र और संग्रहालयों जैसी तीन प्रमुख संस्थाओं के अलावा, हम बड़े पैमाने पर अनुवाद परियोजनाओं को एक और उद्यम के रूप में जोड़ सकते हैं जो बौद्धिक और भावनात्मक विजय का एक रूप है।

एंडरसन बताते हैं कि कैसे इन परियोजनाओं ने स्थानीय लोगों के बाहरी स्थानों के बारे में उनके विचारों को फिर से परिभाषित किया:
जनगणना, मानचित्र और संग्रहालय एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं और औपनिवेशिक काल के उत्तरार्ध में राज्य की अपने क्षेत्र के बारे में सोचने की शैली को उजागर करते हैं। इस सोच का मूल तत्व एक समग्र वर्गीकरण ढांचा था, जिसे राज्य के वास्तविक या काल्पनिक नियंत्रण में आने वाली किसी भी चीज़ पर असीमित लचीलेपन के साथ लागू किया जा सकता था: लोग, क्षेत्र, धर्म, भाषाएँ, उत्पाद, स्मारक इत्यादि।
पश्चिम द्वारा विकसित एक अन्य वर्गीकरण प्रणाली भारत के सामाजिक संगठन के लिए जातिगत ढांचा है। जैसा कि भाग 1 में चर्चा की गई है, इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। हालांकि इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने की थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी यह जारी रहा और अब एक राजनीतिक पहचान के रूप में और भी अधिक कठोर हो गया है। क्रिटिकल रेस थ्योरी का उपयोग करके इसे एक बार फिर से क्रिटिकल कास्ट थ्योरी के रूप में रूपांतरित किया जा रहा है।
संस्कृत नॉन-ट्रांसलेटेबल्स: द इंपॉर्टेंस ऑफ संस्कृतनाइजिंग इंग्लिश नामक पुस्तक में बताया गया है कि कैसे कुछ संस्कृत शब्दों का अंग्रेजी में अनुवाद करने से उनके अर्थ विकृत हो गए हैं और इस प्रक्रिया में एक पराया विश्वदृष्टिकोण थोप दिया गया है।
अभिजात्यवादी ढाँचे, विशेषकर विदेशी गठजोड़ों द्वारा नियंत्रित ढाँचे, अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। स्थापित संदर्भों का उपयोग करके इनका हवाला देने वालों को प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ऐसे ढाँचों की वैधता को अचूक सत्य मान लिया जाता है। जो कोई भी इससे असहमत होने का साहस करता है, उसे कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ता है, जैसा कि सोशल मीडिया पर विवादास्पद विचार

रखने वालों और प्लेटफ़ॉर्म पर संचालित पक्षपाती एल्गोरिदम का सामना करने वालों के लिए स्पष्ट है। ऐसी ज्ञान प्रणाली एक प्रतिध्वनि कक्ष की तरह बन जाती है क्योंकि नया डेटा केवल उसी ढाँचे में फिट बैठता है। ब्रिटिश काल में नौवहन, खगोल विज्ञान, सर्वेक्षण, फोटोग्राफी और मुद्रण जैसी समकालीन तकनीकों के प्रयोग से भारत की छवि में नाटकीय परिवर्तन आया। इसी प्रकार, आज हार्वर्ड जैसे संस्थानों में भारत के जो नए ज्ञान-मानचित्र बनाए जा रहे हैं, उनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, आभासी और संवर्धित वास्तविकता आदि की नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। सूचना का उपयोग उपनिवेशीकरण के लिए अब कहीं अधिक शक्तिशाली और जटिल तरीके से किया जा सकता है।

उदाहरण के लिए, जैसा कि हम बाद के एक अध्याय में विस्तार से बताएंगे, हार्वर्ड में मित्तल संस्थान द्वारा विकसित किया जा रहा आधुनिक अकादमिक अभिलेखागार एक मानचित्र, जनगणना, संग्रहालय, सामाजिक संगठन और बहुत कुछ का डिजिटल समकक्ष है, खासकर जैसे-जैसे मेटावर्स विकसित होता है और हमारा अनुभव अधिक डिजिटल होता जाता है।

आगे के अध्यायों में यह दिखाया जाएगा कि हार्वर्ड के विभिन्न केंद्र और परियोजनाएँ, जिन्हें विडंबनावश भारतीय अरबपतियों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, भारतीय समाज, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, संघर्षों, सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं, आर्थिक समस्याओं, विकास समस्याओं, जमीनी स्तर के उद्यमशीलता, शैक्षिक नीतियों आदि पर डेटाबेस विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। ये डेटाबेस एआई एल्गोरिदम को प्रशिक्षित करने के लिए अत्यंत शक्तिशाली बन जाएंगे। और यह उपनिवेशवाद की अगली पीढ़ी को जन्म देगा।

यह दृष्टिकोण नीति निर्माण और उस पर होने वाली बहसों, सरकारों और निगमों के मूल्यांकन और व्यक्तियों के एक प्रकार के डिजिटल जाति-व्यवस्था में संगठित होने के तरीके को आकार देगा, जो उनके करियर और जीवनशैली को प्रभावित करेगा। यह प्रभाव नागरिक समाज के सभी पहलुओं में व्याप्त होगा, और भविष्य का निर्माण मुख्य रूप से अमेरिकियों द्वारा विकसित सिद्धांतों में निहित आधारों, निष्कर्षों और पूर्वाग्रहों पर होगा।

संपत्तियों का संग्रह करना और उन्हें 'लेबलिंग' के माध्यम से मेटावर्स में स्थान देना, लोगों, स्थानों और वस्तुओं पर कब्जा करने और उन्हें उपनिवेश बनाने का एक रणनीतिक कार्य है। अंग्रेजों ने इसे 'सभ्यता मिशन' कहा, जिसमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने एक रणनीतिक भूमिका निभाई। पुस्तक 'ऑक्सफोर्ड एंड एम्पायर' इस रणनीति का उपयोग करते हुए बौद्धिक स्तर पर साम्राज्य निर्माण में इसकी भूमिका का दस्तावेजीकरण करती है। भारतीय अभिजात वर्ग ने इसे भारत को एक महान ब्रिटिश उपहार के रूप में स्वीकार किया। इसी प्रकार, आज के भारतीय भी हार्वर्ड द्वारा अपने समाज के बारे में उनकी सोच में लाए गए अमेरिकीकरण से विस्मित हैं।

ब्रिटिश काल में, भारत के बारे में जानकारी का उपयोग ब्रिटिश नेताओं को भारत का प्रबंधन करने के लिए प्रशिक्षित करने में किया गया था। इन युवा ब्रिटिश पुरुषों को फिर भारत भेजा गया, जहाँ उन्होंने बदले में, कनिष्ठ भारतीय सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया, जिससे उनकी सोच उपनिवेशवादियों के अनुरूप हो गई। ये देशी 'द्विभाषी बुद्धिजीवी वर्ग', अर्थात् वे देशी जो उपनिवेशवादियों की भाषा, मुहावरे और विचारधारा में प्रशिक्षित होते हैं, उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और नए अभिजात वर्ग का हिस्सा बन जाते हैं।

हमारे अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि हार्वर्ड जैसे अमेरिकी अभिजात्य विश्वविद्यालयों ने एक तरह से अंग्रेजों की राह पकड़ ली है। अतीत में अंग्रेजों की तरह ही, आज अमेरिकियों ने भी प्रतिभाशाली भारतीयों को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सफलतापूर्वक अपने साथ मिला लिया है। बड़ा अंतर यह है कि अंग्रेज भारतीयों को केवल कनिष्ठ पदों पर नियुक्त करते थे, जबकि अमेरिकियों ने भारतीयों को अपने उद्यमों में उच्चतम स्तर तक सफलतापूर्वक शामिल कर लिया है।
इस तरह की अमेरिकी मानचित्र-निर्माण और डेटाबेस निर्माण प्रक्रिया बेहद खतरनाक है। ये डेटाबेस ग्रामीणों के जीवन में, सूक्ष्म वित्तपोषण में, सामाजिक मुद्दों के साथ अंतर्संबंध में और ऊपर उल्लिखित अन्य क्षेत्रों में अति-स्थानीय स्तर पर घटित हो रही घटनाओं का वास्तविक समय का स्नैपशॉट हैं। भारत को हार्वर्ड के नियंत्रण में मौजूद समग्र मेटा-नैरेटिव और ढांचे में समाहित किया जा रहा है।
यह पुस्तक इस बात का खुलासा करती है कि यह सब कैसे हो रहा है। इसलिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।

Kumbh Mela

पहले चर्चा किया गया एक प्रमुख उदाहरण हार्वर्ड की वह व्यापक निगरानी परियोजना है, जिसके तहत कुंभ मेले जैसे आयोजनों के दौरान वीडियो, छवियों, सामाजिक जनसांख्यिकी, रक्त के नमूनों और लोगों की आवाजाही के माध्यम से डेटा एकत्र किया जाता है। यह एक विशाल डेटाबेस निर्माण कार्य है जिसमें भारत के हर कोने से लगभग एक करोड़ लोगों की जानकारी शामिल है, जो हर समुदाय और हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। हार्वर्ड अपने इस कार्य को कुंभ मेले की 'मैपिंग' कहता है। इस पैमाने का डेटाबेस निर्माण विश्व में कहीं भी बेजोड़ है और

इसे भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अकादमिक अनुसंधान की आड़ में अंजाम दिया गया है।

इस तरह की गतिविधियाँ आम भारतीयों की निजता का उल्लंघन करती हैं और भारत के प्रस्तावित डेटा संरक्षण कानूनों के विपरीत हैं। एकत्रित जानकारी का उपयोग भारतीय समाज की कमजोरियों और विभाजन रेखाओं का पता लगाने, एल्गोरिदम को प्रशिक्षित करने, जातीय, भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच संघर्षों का फायदा उठाने वाले हिंदू विरोधी आंदोलनों को बढ़ावा देने और सामान्य तौर पर भारत की संप्रभुता में हस्तक्षेप करने के लिए किया जाता है।

जब हार्वर्ड स्थित लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान ने हार्वर्ड कुंभ मेला परियोजना की शुरुआत की, तो भारतीयों को गर्व महसूस हुआ। आखिरकार, इससे उनकी विरासत को वैश्विक महत्व मिला। हालांकि, गौर करने पर पता चला कि इस परियोजना ने मेले को एक विदेशी पर्यटन के रूप में पेश करके उसका महत्व कम कर दिया; इसके उद्देश्य को विकृत और धर्मनिरपेक्ष बना दिया; जानकारी का दुरुपयोग किया गया; भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा करने वाले साहित्य के लिए जानकारी का दोहन किया गया; और ईसाई प्रचारकों और इस्लामी समूहों की घुसपैठ के लिए कानूनी रास्ते खोल दिए गए। और जैसा कि पहले बताया गया है, ये सभी जांचें प्रासंगिक भारतीय संदर्भों पर उचित विचार किए बिना, यूरोपीय-केंद्रित दृष्टिकोण से की गईं।

हार्वर्ड की कुंभ मेला परियोजना टीम के आधिकारिक वीडियो में प्रोफेसर डायना एक ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने अनजाने में ही छिपे हुए एजेंडे का खुलासा कर दिया, जब उन्होंने कहा कि उन्हें मेले में नारीवादी गैर सरकारी संगठनों की उपस्थिति की कमी खल रही है। ठीक इसी तरह फोर्ड फाउंडेशन ने कई दशक पहले भारत में अपना हस्तक्षेप शुरू किया

था: भारत में कई नारीवादी गैर सरकारी संगठनों को प्रशिक्षण, वित्तपोषण और सशक्तिकरण प्रदान करके, और फिर उनका उपयोग भारतीय समाज के बारे में अत्याचार साहित्य फैलाने के लिए किया, साथ ही भारतीय युवाओं की एक पूरी पीढ़ी को पश्चिमी सामाजिक सिद्धांतों में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित किया। लक्ष्य भारत की प्रतिभाशाली युवा महिलाओं को भारत में महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न का अध्ययन करने के लिए लगातार प्रोत्साहित करके पश्चिमी नारीवाद को लोकप्रिय बनाना था। हम निश्चित रूप से लैंगिक मुद्दों का अध्ययन और समाधान चाहते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि इसके लाभ और हानियों पर सावधानीपूर्वक विचार किए बिना पश्चिमी नारीवाद के मॉडलों का अंधाधुंध आयात अवांछनीय है। हमारा मानना है कि हार्वर्ड के विद्वान मेले को एक पवित्र हिंदू आयोजन के रूप में मानने के बजाय, नीचे उल्लिखित असहज मुद्दों की खोज के लिए एक खुली यात्रा के रूप में इसका उपयोग करने में अधिक रुचि रखते थे:
क्या मेले में पुरुषों का वर्चस्व है? क्या साध्वियों को साधुओं के समान अधिकार प्राप्त हैं?
क्या इस आयोजन में महिलाओं का शोषण हो रहा है?
क्या वहां बलात्कार और उत्पीड़न होते हैं? क्या वहां तांत्रिक यौन समारोह होते हैं?
क्या दलितों पर अत्याचार हो रहा है?
क्या हिंदू समूहों में LGBTQ+ का समान प्रतिनिधित्व है?
क्या दक्षिण और उत्तरपूर्वी क्षेत्रों के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है?
परियोजना के शोधकर्ता मूलत: मेले को उन घिसे-पिटे विषयों में ढाल रहे थे जिनका उपयोग भारत को लक्षित करने वाली हजारों मानवविज्ञान और सामाजिक विज्ञान परियोजनाओं में किया जाता है। इसका बाहरी स्वरूप

विविधता अध्ययन के रूप में प्रस्तुत करना और मेले की सुविधाओं में जाति और लिंग असमानताओं की खोज करना था। इस व्यापक रणनीति में दहेज, सती प्रथा, मूर्तिपूजा, कुछ नग्न साधुओं द्वारा कथित तौर पर मानव मांस खाने आदि जैसे मुद्दों पर अकादमिक शोध प्रबंध, खोजी पत्रकारिता और टेलीविजन वृत्तचित्र तैयार करना शामिल था। इस प्रक्रिया में, मेले का मूल पवित्र उद्देश्य समाप्त हो गया और यह एक ऐसे तमाशे में तब्दील हो गया जिसका एकमात्र उद्देश्य इस तरह के एजेंडा-आधारित शोध को बढ़ावा देना था।

हजारों वर्षों से भारत की विविधता आपसी सद्भाव और सम्मान के साथ सह-अस्तित्व में रही है, लेकिन यह परियोजना हार्वर्ड को आधुनिकीकरण के नाम पर इसमें हस्तक्षेप करने और इसे बाधित करने का अधिकार देगी, जिससे कुछ भारतीय गैर-सरकारी संगठनों को और बढ़ावा मिलेगा। विभिन्न गुटों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक समूह मेले का राजनीतिकरण करने के लिए इस मुहिम में शामिल हो जाएंगे। एक बार शुरू होने पर, यह प्रवृत्ति अपने आप ही फैलती जाएगी और विभिन्न समूहों के बीच संघर्षों को हवा देगी।

हमें आशंका थी कि यह मेला विदेशी, 'असभ्य और खतरनाक' लोगों का एक विशाल अनछुआ क्षेत्र बन सकता है। यह बहुत खुला है और रोमांच, प्रसिद्धि और धन की तलाश में पश्चिमी लोगों के लिए अपार अवसर प्रदान करता है।

शोधकर्ताओं के लिए, यह विदेशी और कामुक चीजों की खोज का एक और मानवशास्त्रीय क्षेत्र मात्र है। इसका एक तात्कालिक प्रभाव कुंभ मेले में बड़े पैमाने पर कंडोम वितरण की मांग के रूप में सामने आया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस सनसनीखेज खबर को हवा दी और विदेशी मीडिया ने भी तुरंत इस खबर को उठा लिया।

हार्वर्ड की टीम द्वारा तैयार की गई किसी भी सामग्री में कुंभ मेले में संपन्न हो रहे यज्ञ (सृष्टि और संतुलन की ब्रह्मांडीय प्रक्रिया) के आध्यात्मिक अर्थ पर चर्चा नहीं की गई है। जब उन्होंने मेले के पीछे के 'मिथक' पर चर्चा की, तो उसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी किसी अनोखी, आदिम और काल्पनिक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया। उनमें ऋतम (ब्रह्मांडीय व्यवस्था) और यज्ञ के आध्यात्मिक पहलुओं और संसार में उनके प्रकटीकरण को समझने के लिए आध्यात्मिक विशेषज्ञता और रुचि का अभाव है। इस गहन अंतर्दृष्टि का अभाव इसलिए है क्योंकि परियोजना के शीर्ष नेतृत्व में श्रद्धा (आध्यात्मिक दृष्टिकोण) का अभाव है।

हार्वर्ड कुंभ मेला टीम के एक ब्लॉग में बताया गया है: 'इस समूह के शोध का एक प्रमुख परिणाम यह था कि कुंभ मेले में कई लोगों ने इस उत्सव के दौरान होने वाले प्रदूषण को लेकर चिंता व्यक्त की।' मेले से होने वाले प्रदूषण पर आगे और शोध होना तय है। जिस तरह दिवाली, गणेश उत्सव और अन्य हिंदू त्योहारों को पर्यावरण के लिए हानिकारक माना जाता है, उसी तरह कुंभ मेले को भी पुरानी और हानिकारक प्रथाओं की सूची में शामिल किया जाएगा। हमने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि हार्वर्ड और अन्य संस्थानों के छात्र पहले से ही 'पर्यावरणीय मुद्दों' का अध्ययन कर रहे हैं ताकि हिंदू धर्म की समस्याओं, जैसे अस्थि विसर्जन, शवदाह और अन्य सदियों पुरानी स्थापित रस्मों को उजागर किया जा सके।

एक उद्यमी अमेरिकी विद्वान ने शेखी बघारी कि उसने गंगा नदी के किनारे पतंग उड़ाने की परंपरा में भाग लिया क्योंकि इससे उसे अपनी पतंग पर एक वीडियो कैमरा छिपाने और उसे फिल्मांकन के लिए ड्रोन में बदलने का मौका मिला। कल्पना कीजिए कि उसने अपने संग्रह के लिए कितने सनसनीखेज और आपत्तिजनक वीडियो फुटेज का खजाना इकट्ठा किया होगा!

ईसाई मिशनरियों ने मेले में घुसपैठ करके धर्म प्रचार करने की कोशिश की है। इस पर किसी भी तरह की रोक को मिशनरी पश्चिमी और भारतीय संस्थानों की मदद से चुनौती दे सकते हैं। पहले से ही यह तर्क प्रचलित है कि मेले, गंगा नदी या किसी भी अन्य सार्वजनिक स्थान पर किसी का स्वामित्व नहीं है, इसलिए हर किसी को अपनी इच्छानुसार भाग लेने का समान अधिकार है। मिशनरी अच्छे मेहमान बनकर, साम (मित्रता) और दान (दान) का इस्तेमाल करते हुए प्रवेश करने में माहिर हैं। वे निस्संदेह ग्रामीणों को प्रभावित करने के लिए बहुत सारी मुफ्त चीजें लाएंगे, जो मेले में आने वाले लोगों का एक बड़ा हिस्सा हैं। हार्वर्ड का बहुलवाद प्रोजेक्ट भोले-भाले हिंदू नेताओं को 'हिंदू सहिष्णुता' की प्रशंसा करके आसानी से शांत कर लेता है, जिससे उनमें गर्व की भावना पैदा होती है। इस प्रकार के डेटा से किए जाने वाले परिष्कृत विश्लेषणों के उदाहरण के रूप में, हम तरुण खन्ना के नेतृत्व वाली एक टीम द्वारा 2016 में प्रकाशित एक शोध पत्र का उल्लेख करते हैं। इस शोध पत्र में कहा गया है कि उन्होंने कुंभ मेले में एक टेलीफोन कंपनी से मोबाइल फोन डेटा (फोन कॉल और टेक्स्ट संदेश दोनों सहित) प्राप्त किया। इस डेटा का उपयोग समरूपता के विस्तृत अध्ययन के लिए किया गया, जो एक ऐसा शब्द है जो किसी समूह में व्यक्तियों के व्यवहार को संदर्भित करता है जिसमें कुछ व्यक्ति उनसे मिलते-जुलते होते हैं और अन्य भिन्न माने जाते हैं। समानता/भिन्नता के मानदंड जाति, धर्म, भाषा, लिंग, समाज के वर्ग आदि पर आधारित हो सकते हैं। इस प्रकार का अध्ययन इन समूहों के भारतीयों के उन लोगों के प्रति व्यवहार का मॉडल प्रस्तुत करता है जिन्हें भिन्न माना जाता है।

इस शोधपत्र में कहा गया है: 'इन संचार संबंधी जानकारियों से कम से कम यह पता चलता है कि किसने किससे, कब और कितनी देर तक

संपर्क किया।' उन्होंने जिस डेटासेट का उपयोग किया, उसमें 146 मिलियन टेक्स्ट मैसेज और 245 मिलियन फोन कॉल का रिकॉर्ड था, कुल मिलाकर 390 मिलियन संचार घटनाएं दर्ज थीं। मेले में लगे कुल 207 मोबाइल फोन टावरों से यह डेटा एकत्र किया गया और प्रत्येक टावर के अक्षांश और देशांतर को मिलाकर मेले के मैदान का एक स्थानिक मानचित्र तैयार किया गया।

इस शोधपत्र में आगे कहा गया है कि कुंभ मेले ने भीड़-भाड़ वाले विशाल परिवेश में व्यक्तिगत स्तर पर ऐसे व्यवहार का अध्ययन करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया। टीम ने तेईस राज्यों के प्रतिभागियों का अध्ययन किया और प्रत्येक राज्य और सामाजिक समूह के लिए अलग-अलग निष्कर्ष निकाले। उनके अनुमान के अनुसार, उनके विश्लेषण में शामिल तीन महीने की अवधि के दौरान 61 मिलियन लोगों ने मेले में भाग लिया।

रिपोर्ट में विभिन्न समूहों में सामूहिक निर्णय लेने की प्रवृत्ति (झुंड में रहने की प्रवृत्ति) की संभावना पर निष्कर्ष दिए गए हैं। इसमें भाषाई मूल, जातीय समूह और पूर्व-स्थापित सामाजिक बंधन एवं सीमाएँ जैसे कारकों का अध्ययन किया गया, साथ ही 'सहयोगी समरूपता' का मापन भी किया गया। शोधकर्ताओं ने बताया कि ऐसे अध्ययन किसी समूह की 'मानव भगदड़' जैसी स्थितियों के प्रति संवेदनशीलता का अनुमान लगा सकते हैं। समरूपता के मापन से कुछ लोगों के 'अलगाव' की प्रवृत्ति का भी पता चल सकता है।

मेले में भाग लेने वाले अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में कम जनसंख्या वाले राज्यों की तुलना में समरूपता का स्तर कम था। रिपोर्ट में इसका कारण यह बताया गया है कि यह इस बात का माप है कि विभिन्न पृष्ठभूमि के भारतीयों को अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोगों के प्रति कितना

सहज या असहज महसूस होता है।
इस शोध में से कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं है, और हार्वर्ड के लिए इस तरह की गतिविधियाँ करना उचित है क्योंकि उसे हर कदम पर भारतीय अधिकारियों से सहायता मिली है। हार्वर्ड ने कई भारतीय अभिजात वर्ग को अपने ब्रांड के साथ प्रतिष्ठित जुड़ाव का प्रस्ताव देकर आसानी से उनका समर्थन प्राप्त कर लिया। हार्वर्ड की परियोजना पर आधारित खूबसूरत ढंग से प्रस्तुत पुस्तक, जिसका शीर्षक 'कुंभ मेला: क्षणभंगुर मेगासिटी का मानचित्रण' है, का विमोचन बड़े धूमधाम से किया गया।
न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी के प्रायोजन से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
नई दिल्ली में इस कार्यक्रम का शुभारंभ भारत के स्वतंत्रता दिवस के ठीक बाद, भव्य ओबेरॉय होटल में किया गया। उनका समर्थन हासिल करने के लिए, तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने हार्वर्ड के साथ अपने जुड़ाव के लिए आभार व्यक्त किया, जिससे अंतरराष्ट्रीय मीडिया की उपस्थिति में उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को बल मिला।
अगले दिन, मित्तल इंस्टीट्यूट ने मुंबई के प्रतिष्ठित छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय में एशिया सोसाइटी इंडिया सेंटर और हार्वर्ड क्लब ऑफ मुंबई के साथ साझेदारी में आयोजित पांच लॉन्च की श्रृंखला में दूसरे लॉन्च की मेजबानी की।
हार्वर्ड के प्रतिष्ठित मित्तल संस्थान ने इस परियोजना को अंतर्विषयक परियोजना बताया है, जिसमें कई विभाग शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अलग उद्देश्य है। इनमें शहरी नियोजन, रसद, सार्वजनिक स्वास्थ्य, धार्मिक अध्ययन, व्यवसाय विद्यालय, मानव विज्ञान, डिजाइन विद्यालय

आदि शामिल थे। इनमें से प्रत्येक विभाग का दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष था और वे केवल अध्ययन के लिए रोचक नमूनों की तलाश में थे।
कुंभ मेला डेटाबेस का लाभ उठाते हुए, हार्वर्ड ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अपना विस्तार किया है। जनस्वास्थ्य परियोजना के नाम से जानी जाने वाली यह पहल, हार्वर्ड के अपने टी.एच. चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ सहित कई भागीदारों के सहयोग से चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य मेले में तीर्थयात्रियों, साधुओं और सुरक्षा बलों के स्वास्थ्य की व्यापक जांच करना है। रिपोर्ट में बताया गया है:
यह परियोजना टीम द्वारा इलाहाबाद में 2013 के कुंभ मेले में किए गए शोध पर आधारित है, जहाँ उन्होंने शुरू में iPads पर अपने रोग निगरानी उपकरण का परीक्षण किया था। ... 2015 जनस्वास्थ्य परियोजना का मुख्य आधार एक अद्वितीय इंटरैक्टिव दृश्य विश्लेषणात्मक उपकरण ("डैशबोर्ड") है जो स्वास्थ्य अधिकारियों को वास्तविक समय में महत्वपूर्ण रोग निगरानी डेटा प्रदान करता है। पहले ही दिन, डैशबोर्ड ने मेले में तीर्थयात्रियों की सेवा कर रहे 30 से अधिक स्थायी और मोबाइल स्वास्थ्य क्लीनिकों में सरकार द्वारा जारी टैबलेट उपकरणों पर दर्ज 2,000 से अधिक मुलाकातों को ट्रैक किया था। यह वास्तविक समय रोग निगरानी कार्यक्रम अपने पैमाने में अभूतपूर्व है। इस सभी समृद्ध डेटा का उपयोग करके, योजनाकार आयु, स्थान, लिंग, रोग और रोग आवृत्ति के आधार पर संगठित रोगियों का डेटा वास्तविक समय में देख सकते हैं।
हार्वर्ड का मानना है कि इस तरह के डेटा में पारंपरिक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को दरकिनार करते हुए भारतीय समाज में चुनौतियों का सामना कर रहे शरणार्थियों और अल्पसंख्यक समुदायों की मदद करने की अपार क्षमता है। उसने घोषणा की कि अगला चरण मॉडलिंग से समाधान सुझाने और फिर सामाजिक-राजनीतिक हस्तक्षेप करने की ओर बढ़ेगा।

भारतीय अरबपतियों द्वारा दिए गए अनुदान के कारण अन्य संभ्रांत भारतीय और कुछ भोले-भाले पारंपरिक हिंदू भी मेले को समझने के लिए हार्वर्ड के तौर-तरीकों को अपना लेते हैं। इस प्रकार, दोहरी संस्कृति वाले भारतीयों का उपयोग हार्वर्ड के विश्वदृष्टिकोण को फैलाने के लिए किया जाता है।

इस प्रकार के किसी भी डेटाबेस और संग्रह के निर्माण का लक्ष्य ऑनलाइन खोज इंजनों को भारत से संबंधित हार्वर्ड के दृष्टिकोण को मानक दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करना है। हार्वर्ड और उसके सहयोगियों द्वारा विकसित टूलकिट और डैशबोर्ड इस प्रकार जनता के लिए अपनी विरासत तक पहुँचने के मानक और उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके बन जाएँगे।

कई साल पहले, इन्फिनिटी फाउंडेशन ने हार्वर्ड द्वारा कुंभ मेले की निगरानी पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसमें चेतावनी दी गई थी कि यह उतना हानिरहित प्रोजेक्ट नहीं है जितना दिखता है, क्योंकि यह भारत के हर कोने से लगभग एक करोड़ लोगों का सामाजिक-जनसांख्यिकीय, डीएनए और मनोवैज्ञानिक डेटा संकलित कर रहा था। यह डेटा हार्वर्ड के मशीन लर्निंग सिस्टम को सामाजिक और राजनीतिक विभाजन की पहचान करने में भी मदद कर रहा है, जिसका अंततः मानवाधिकारों के नाम पर दुरुपयोग किया जा सकता है।

हमारी रिपोर्ट, जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में छपी थी, भारत के कई राज्यों की राजधानियों के साथ-साथ शैक्षणिक, मीडिया और नागरिक समाज के अन्य संस्थानों में व्यापक रूप से वितरित की गई। विभिन्न कुंभ मेलों में वरिष्ठ नेताओं को इसकी लाखों प्रतियां बांटी गईं, जिससे भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई।

2017 में, जब योगी आदित्यनाथ भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश

के मुख्यमंत्री बने, तो राजीव मल्होत्रा ने उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर रिपोर्ट प्रस्तुत की और ऐसे विदेशी प्रोजेक्टों की जांच का अनुरोध किया। लेकिन भारत की केंद्र या राज्य सरकारों ने कोई कार्रवाई नहीं की। दरअसल, कई महीनों बाद एक चौंकाने वाली प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई जिसमें बताया गया कि योगी आदित्यनाथ ने कुंभ मेले में डेटा इकट्ठा करने के लिए विशेष रूप से कई विदेशी शोध एजेंसियों (हार्वर्ड सहित) को आमंत्रित किया था। विडंबना यह है कि विदेशी संस्थानों को पूरी तरह से बिना किसी निगरानी के निगरानी करने का खुला रास्ता मिल गया। हालांकि, ऐसा लगता है कि हार्वर्ड को बेनकाब करने के लिए इस विषय पर हमारे लगातार लेखन और भाषण का अंततः असर हुआ है। हार्वर्ड के तरुण खन्ना ने चुपचाप बयान दिया है कि मित्तल इंस्टीट्यूट की कुंभ मेले की जांच करने की अब कोई योजना नहीं है। हालांकि, यह देखना बाकी है कि क्या हार्वर्ड ने अपनी प्रत्यक्ष संलिप्तता उजागर होने के बाद इस परियोजना को अपने साझेदारों के नेटवर्क को आउटसोर्स कर दिया है।

विभाजन परियोजना

हार्वर्ड की अपनी व्याख्या के साथ एक रणनीतिक डेटाबेस संग्रह बनाने का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण विभाजन परियोजना है। इसे मित्तल संस्थान द्वारा वित्त पोषित किया गया है और हार्वर्ड में जन स्वास्थ्य और मानवाधिकार केंद्र की निदेशक प्रोफेसर जेनिफर लीनिंग इसका नेतृत्व कर रही हैं। वह एक दशक से अधिक समय से इस परियोजना पर काम कर रही हैं और भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के विभाजन काल से संबंधित सामग्रियों का सबसे व्यापक संग्रह बनाने की योजना बना रही हैं। इसमें जनता और मीडिया के साथ-साथ सरकारी स्रोतों की आवाज़ें भी शामिल होंगी। यह एक दीर्घकालिक परियोजना है जिसमें कई संकाय

सदस्य शामिल हैं। इसका उद्देश्य विभाजन काल से कहीं आगे बढ़कर ब्रिटिश भारत के संपूर्ण कालखंड को कवर करना है।
मानवाधिकार और अंतरराष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ लीनिंग, अभिलेखागार की व्याख्या, वर्गीकरण और उस तक पहुंच की निगरानी करेंगे।
तरुण खन्ना ने कहा कि पार्टीशन प्रोजेक्ट इस बात को दर्शाता है कि मित्तल के दक्षिण एशिया संस्थान का मूल उद्देश्य क्या है: दक्षिण एशिया के विद्वानों के साथ-साथ हार्वर्ड के शोधकर्ताओं और छात्रों सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों के विद्वानों को एक साथ लाकर अत्यधिक महत्व के विषय पर समग्र नियंत्रण हासिल करना।
इस दिशा में किए जा रहे कार्यों के एक उदाहरण के रूप में, हार्वर्ड के एक छात्र ने दिवंगत मिल्खा सिंह (जिन्हें लोकप्रिय रूप से 'फ्लाइंग सिख' कहा जाता था) का साक्षात्कार लिया, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ एथलीटों में से एक थे। छात्र अक्षय वीर, मित्तल संस्थान में विभाजन के राजदूत हैं और उन पचपन छात्रों में से एक हैं जो 'लुकिंग बैक, इन्फॉर्मिंग द फ्यूचर - द 1947 पार्टीशन ब्रिटिश इंडिया: इम्प्लिकेशन्स ऑफ मास डिसलोकेशन्स अक्रॉस जियोग्राफीज' नामक परियोजना पर काम कर रहे हैं। विभाजन परियोजना के इस भाग में छात्र विभाजन के पीड़ितों से मौखिक कहानियाँ एकत्र कर रहे हैं और उनका दस्तावेजीकरण कर रहे हैं। मित्तल संस्थान का कहना है कि वह 'अल्प प्रतिनिधित्व वाली आवाजों', अर्थात् महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों के मौखिक इतिहास पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है।
उनका दावा है कि उन्होंने तीन वर्षों की अवधि में बचे हुए लोगों के 2300 से अधिक वृत्तांत एकत्र किए हैं। हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ डिज़ाइन 1947 के विभाजन के दौरान हुए विस्थापन की गहरी समझ विकसित करने में लगा हुआ है। मित्तल संस्थान द्वारा भारत और पाकिस्तान से कई

आगंतुकों को धार्मिक विस्थापनों का दस्तावेजीकरण करने के लिए फेलोशिप दी जा रही हैं। संस्थान लिंग और विभाजन जैसे विषयों पर सेमिनारों की एक श्रृंखला आयोजित करता है।

इस प्रकार का संग्रह किसी विशेष कालखंड का प्रामाणिक ऐतिहासिक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए बनाया जाता है। इसका अर्थ यह है कि ब्रिटिश भारत का सबसे व्यापक संग्रह हार्वर्ड के पास होगा। भविष्य में इस विषय पर शोध करने के इच्छुक सभी विद्वानों को हार्वर्ड से संपर्क करके इस संग्रह तक पहुँच का अनुरोध करना होगा। भारत से प्राप्त बिखरी हुई सामग्री को मित्तल परिवार से प्राप्त धनराशि से हार्वर्ड द्वारा संकलित और संग्रहित किया जाएगा।

यह कुछ वैसा ही है जैसे औपनिवेशिक काल के भारतीय विद्या के अभिलेखागारों पर हीडलबर्ग, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के विश्वविद्यालयों का नियंत्रण है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है! वैदिक ज्ञान प्रणालियों पर भारत की दुर्लभ पांडुलिपियाँ अभी भी पश्चिमी पुस्तकालयों और अभिलेखागारों के पास हैं, और भारतीय विद्वानों को उन तक पहुँचने के लिए भारी शुल्क देना पड़ता है। भारतीय अभिलेखीय सामग्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भारत से बाहर है, और सरकार को हार्वर्ड जैसे संस्थानों के हाथों में और अधिक सामग्री सौंपने के बजाय उसे वापस लाने पर ध्यान देना चाहिए।

ब्रिटिश भारत के अभिलेखागार का स्वामित्व जिसके पास भी होगा, उसके पास उस काल के इतिहास लेखन के प्राथमिक स्रोत होंगे और अप्रत्यक्ष रूप से, भारत के व्यापक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी। यह शोध भारत में भारतीय विद्वानों के साथ आसानी से किया जा सकता है। इससे एक आंतरिक दृष्टिकोण प्राप्त होगा, जिससे सामाजिक विज्ञान के लिए एक भारतीय स्वदेशी मॉडल विकसित होगा। भारतीय

सभ्यतागत मूल्यों के अनुरूप भारतीय समाज के मॉडलों पर शोध, पुनर्निर्माण और अद्यतन करने की आवश्यकता है।

चिकित्सा डेटाबेस

हार्वर्ड की महत्वाकांक्षाएं भारत के संवेदनशील स्वास्थ्य डेटाबेस को हासिल करने तक ही सीमित नहीं हैं। इसका उद्देश्य संपूर्ण सॉफ्टवेयर और डेटा संग्रह तंत्र विकसित करना और इसे भारत में संचालित करना भी है। यह इंडिया डिजिटल हेल्थ नेटवर्क है, जिसका नेतृत्व हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और बेथ इज़राइल डिकॉनेस मेडिकल सेंटर में आपातकालीन चिकित्सा के सहायक प्रोफेसर और हार्वर्ड टी.एच. चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में वैश्विक स्वास्थ्य और जनसंख्या के सहायक प्रोफेसर, प्रो. सचित बलसारी कर रहे हैं। इस परियोजना को अनुसंधान और नीति सहयोग के रूप में वर्णित किया गया है और इसका लक्ष्य है: एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई)-सक्षम स्वास्थ्य विनिमय पारिस्थितिकी तंत्र का विकास, भारत के डिजिटल स्वास्थ्य सूचना वास्तुकला को आकार देने के लिए नीतिगत अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने का प्रयास करता है। इस प्रस्ताव को नीति आयोग ने अपने राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्टैक के दृष्टिकोण पत्र में और भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट में अपनाया और कार्यान्वित किया है। प्रमुख योगदानों में शामिल हैं: क) व्यक्तिगत स्वास्थ्य डेटा की सुवाह्यता को अनिवार्य करते हुए "मशीन-पठनीय" शब्द का समावेश, जो भारत में स्वास्थ्य डेटा अंतरसंचालनीयता के लिए आधार तैयार करता है; ख) अस्पताल-आधारित इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड के विपरीत, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड की अवधारणा, जो भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का संगठनात्मक आधार है; और

ग) राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एनडीएचएम) में नियामक सैंडबॉक्स का समावेश, जो नियंत्रित परीक्षण वातावरण हैं जिनमें मौजूदा नियमों को अस्थायी रूप से शिथिल किया जा सकता है ताकि नई तकनीकों के लिए प्रयोग की अनुमति मिल सके।

हार्वर्ड की परियोजना में एक ऐसे टूलकिट का विकास और स्थापना शामिल है जिसे वह 'प्राथमिक देखभाल स्तर पर आवश्यक दस्तावेज़ीकरण, कर्मियों और संसाधनों की पहचान' करने वाला बताता है। यह इस टूलकिट के रणनीतिक महत्व के बारे में बढ़-चढ़कर बताता है: हम स्वास्थ्य डेटा के डिजिटलीकरण के लिए प्रदाता-संचालित, रोगी-केंद्रित डिज़ाइन प्रक्रिया विकसित कर रहे हैं, जिसके द्वारा डॉक्टर और प्रशासक आसानी से उपयोग में आसान अनुकूलित समाधानों को शीघ्रता से लागू कर सकते हैं जो डेटा को अन्य प्रणालियों से सुरक्षित रूप से स्थानांतरित कर सकते हैं।

इस परियोजना में उनका साझेदार टाटा ट्रस्ट्स है, जो इस टूलकिट का संचालन करेगा और डेटाबेस संकलित करेगा, जिसे हार्वर्ड के साथ साझा किया जाएगा। भारत और हार्वर्ड के कंप्यूटर वैज्ञानिक, मेडिकल इन्फॉर्मेटिशियन, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, डेटा वैज्ञानिक और नीति निर्माता तकनीकी और नीतिगत सहायता प्रदान करते हैं। हार्वर्ड और टाटा ने अन्य प्रतिष्ठित भारतीय अनुसंधान संस्थानों को भी इसमें शामिल किया है। इसके बाद, मित्तल इंस्टीट्यूट ने हार्वर्ड की ओर से इस डेटाबेस संकलन परियोजना को और आगे बढ़ाया। हार्वर्ड और भारतीय संस्थाओं के बीच कई सेमिनार आयोजित किए गए और सहयोग को बढ़ावा दिया गया, जिनमें मित्तल की अहम भूमिका रही है। उदाहरण के लिए, रेडक्लिफ इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी के साथ आयोजित निम्नलिखित संयुक्त सेमिनार का वर्णन इसकी वार्षिक रिपोर्ट में किया गया है:

रेडक्लिफ इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडीज द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य सूचना आदान-प्रदान संगोष्ठी में चिकित्सा, कंप्यूटर विज्ञान, बिग डेटा, सार्वजनिक नीति और कानून के विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया ताकि स्वास्थ्य सूचना आदान-प्रदान में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए एक शोध और नीतिगत एजेंडा की पहचान की जा सके।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 'भारत में स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं का भंडारण अत्यंत विविध है' लेकिन बिखरा हुआ, अव्यवस्थित और पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। इसमें मित्तल की मदद से हार्वर्ड के लिए मौजूद अवसर को समझाया गया है:

भारत में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के आंकड़ों की व्यापक अनुपलब्धता वाला यह खंडित पारिस्थितिकी तंत्र एक प्रभावी आदान-प्रदान प्रणाली के निर्माण में एक बड़ी चुनौती पेश करता है, वहीं हाल ही में मोबाइल नेटवर्क और ब्रॉडबैंड की व्यापक उपलब्धता महंगे पारंपरिक प्रणालियों से मुक्त साहसिक और नवीन समाधानों के लिए एक नया अवसर प्रदान करती है।

प्रोजेक्ट प्रकाश जैसी कई नेक पहलें भी हैं। यह हार्वर्ड के पास बोस्टन में स्थित एक स्वतंत्र गैर-लाभकारी संस्था है जो भारत के गरीबों में दृष्टिहीनता के उपचार में उत्कृष्ट सहायता प्रदान करती है। भला ऐसे नेक आंदोलन की आलोचना कौन कर सकता है? यह लोगों को दृष्टिहीनता के इलाज के लिए उपलब्ध सबसे उन्नत उपचार प्रदान करता है।

हालांकि, यह एक महत्वाकांक्षी डिजिटल डेटाबेस भी तैयार कर रहा है; एक केंद्रीकृत भंडार जो 'बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए सबसे अधिक आवश्यक चिकित्सा और पुनर्वास संसाधनों के प्रकारों के संबंध में नीतियां बनाने के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करेगा'। यह 'वैज्ञानिकों और उद्योग भागीदारों को मोबाइल और क्लाउड-आधारित समाधान विकसित करने के लिए एक प्रोटोटाइपिंग वातावरण प्रदान करने हेतु क्षेत्रीय डिजिटल

स्वास्थ्य नवाचार केंद्र' विकसित कर रहा है, साथ ही नई तकनीकों के लिए डेटा एकत्र करने हेतु परीक्षण प्रयोगशालाएं भी स्थापित कर रहा है। इस परियोजना को टाटा ट्रस्ट्स द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है, जबकि मित्तल संस्थान इसके कार्यों का प्रदर्शन और संचालन करता है।

सवाल यह है: ऐसे डेटाबेस और प्रौद्योगिकियों का स्वामित्व, नियंत्रण और उपयोग कौन करेगा? क्या भारत एक बार फिर अमेरिकी उदारता पर निर्भर उपभोक्ता राष्ट्र बन जाएगा? क्या यह बौद्धिक संपदा और डेटाबेस का अनजाने में/अनजाने में हुआ हस्तांतरण हो सकता है?

भारतीय आयुर्वेदिक शोधकर्ताओं का एक नेटवर्क बनाने और आनुवंशिकी के क्षेत्र में उनके ज्ञान को हार्वर्ड के समकक्षों तक पहुंचाने के लिए नियमित आदान-प्रदान का आयोजन भी किया जाता है। हार्वर्ड के मित्तल संस्थान के नई दिल्ली कार्यालय ने 'माइटोकॉन्ड्रियल विकार, बांझपन, लिंग निर्धारण, फोरेंसिक आनुवंशिकी और आयुर्वेद प्रकृति के आनुवंशिक आधार' जैसे विषयों पर आदान-प्रदान को सुगम बनाया है।

भारत की समृद्ध जैव विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा को अनजाने में हार्वर्ड के हाथों में सौंपने वाली एक और संवेदनशील परियोजना लद्दाख नन एसोसिएशन के साथ सहयोग है। इस पारिस्थितिक और सांस्कृतिक प्रलेखन परियोजना को 'लद्दाख नन एसोसिएशन डिजिटल सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट' नाम दिया गया है। इसका घोषित लक्ष्य है:

पौधों और उनके औषधीय उपयोगों का रिकॉर्ड बनाने के साथ-साथ संरक्षण और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में काम करने वाली भिक्षुणियों के अनुभवों को रिकॉर्ड करना और डिजिटल रूप से संग्रहीत करना। उन्होंने (विद्वान लुईस) तीन सप्ताह के सहयोगात्मक कार्यक्रम में आभासी साक्षात्कारों और भिक्षुणियों द्वारा ली गई तस्वीरों के माध्यम से अपना शोध किया। ... (लुईस) एक डिजिटल संग्रह की नींव विकसित करेंगी

जो लद्दाख के लुप्तप्राय औषधीय पौधों और उनके उपयोगों का दस्तावेजीकरण कर सके, साथ ही तिब्बती बौद्ध भिक्षुणियों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और संरक्षण नेतृत्व का एक विकसित रिकॉर्ड प्रदान कर सके।[36]

'संरक्षण', 'लुप्तप्राय' और 'स्वास्थ्य सेवा' जैसे शब्दों का चतुराईपूर्ण प्रयोग देखिए। भला ऐसे मुद्दों का समर्थन कौन नहीं करेगा! और यह सब लद्दाख की बौद्ध भिक्षुणियों के सम्मान में किया जा रहा है।

एक अन्य अनुदान भारतीय कृषि में दलहन फसलों पर शोध करने के लिए है, जो 'भारतीय कृषि विरासत, भारत से वनस्पति संग्रह का इतिहास और जैव विविधता के शासन' पर डेटाबेस बनाने के हिस्से के रूप में है।

उपरोक्त उदाहरणों के अलावा, मित्तल संस्थान सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों और सुधारों के प्रति अमेरिकी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए भी काफी काम प्रायोजित करता है। कोविड-19 महामारी ने इसे भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन में अपनी पैठ बनाने और अपना प्रभाव फैलाने का एक नया अवसर प्रदान किया है। स्वाभाविक रूप से, सार्वजनिक स्वास्थ्य सामाजिक न्याय और आलोचनात्मक सिद्धांतों को लाने और भारत के भीतर अमेरिकी मूल्यों और समर्थन के साथ नेताओं को स्थापित करने का एक बेहतरीन माध्यम भी है।

कला और सौंदर्यशास्त्र

मित्तल संस्थान के संस्कृति संरक्षण कार्यक्रम ने कला और संग्रहालय की कलाकृतियों का एक रोचक डेटाबेस विकसित किया है। हार्वर्ड के संकाय और छात्र भारत में संरक्षण और जीर्णोद्धार प्रथाओं का अध्ययन करने के लिए मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय जैसे संग्रहालयों का दौरा करते हैं। संस्थान ने संरक्षण विज्ञान, प्रशिक्षण और अनुसंधान पर

एक आभासी कार्यशाला का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य 'एक आभासी मंच का निर्माण करना है जो संग्रहालयों और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संस्थानों को एक साथ लाकर सहयोग करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम बनाए, जिससे संग्रहालयों और क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक व्यवहार्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हो सके'।

इसका मतलब यह है कि हार्वर्ड संग्रहालय की सभी डिजिटल संपत्तियों को रखने वाले क्लाउड सिस्टम को नियंत्रित करेगा, जिनका मेटावर्स में अपार महत्व होगा और साथ ही भविष्य के एल्गोरिदम को प्रशिक्षित करने के लिए बिग डेटा भी उपलब्ध होगा।

मित्तल इंस्टीट्यूट की कार्यकारी निदेशक, मीना हेवेट ने भारत में संरक्षण विज्ञान की स्थिति का अध्ययन करने के लिए लखनऊ स्थित भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट (INTACH) की संरक्षण प्रयोगशाला का भी दौरा किया – पांडुलिपियों से लेकर पशु खाल तक – ताकि कला संग्राहकों के लिए उपलब्ध वर्तमान संरक्षण सेवाओं की समझ विकसित हो सके।

इसी तरह की एक परियोजना है 'इतिहास में रंगों का मानचित्रण'। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य 'रंगों पर नई जानकारी को संकलित और व्यवस्थित करना तथा इन रंगों को ऐतिहासिक संदर्भ में रखना' है। यह एशियाटिक सोसाइटी, उदयपुर संग्रहालय और छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के सहयोग से एशियाई चित्रों में पाए जाने वाले अनूठे रंगों के वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है।

एक अन्य अनुदान इस बात को समझने के लिए दिया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार चित्रकला शैली को 'भारतीय पहचान के निर्माण और उसे कायम रखने के एक उपकरण' के रूप में विकसित किया

और इसका उपयोग 'कलाकृतियों के भीतर एक अंग्रेज़ीकृत भारतीय पहचान' के निर्माण के लिए किया तथा किस प्रकार इसने 'औपनिवेशिक दृष्टिकोण से भारतीय पहचान प्रस्तुत की'। हमारा मानना है कि यह शोध भारतीयों की पहचान को एक बार फिर से परिभाषित करने में उपयोगी होगा, लेकिन इस बार इसे अंग्रेज़ीकृत करने के बजाय अधिक अमेरिकीकृत बनाया जाएगा।

अन्य डेटाबेस

कुछ शोध परियोजनाएं भारत में उन लोगों की सूचियां संकलित करती हैं जिनका इस्तेमाल भविष्य में भारत के खिलाफ हथियार के रूप में किया जा सकता है। ऐसी ही एक परियोजना में भारत में यौन हिंसा के खिलाफ काम करने वाले नारीवादी संगठनों की सूची दी गई है।

एक अन्य संकाय अनुदान मध्यम आकार के भारतीय शहरों पर एक एटलस विकसित करने के लिए था। यह एक डेटाबेस है जिसका उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए किया जाएगा कि 'नई जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक विकास और संभावित अवसंरचना निवेश किस दिशा में निर्देशित होंगे'। इसका एक अन्य पहलू ऐसे कई शहरों के 'राजनीतिक, सामाजिक और स्थानिक पहलुओं का गहन अध्ययन' करना है। भारत में कई शहरी योजनाकार इन परियोजनाओं के प्रति आकर्षित हुए हैं।

‘सीड्स फॉर चेंज प्रोग्राम’ को धनराशि दी गई है, जिसका उद्देश्य निगमों, निवेशकों और गैर-सरकारी संगठनों के लिए एक डिजिटल डैशबोर्ड टूल विकसित करना और उसका रखरखाव करना है, जो मानवाधिकारों के हनन और राजनीतिक जोखिमों की निगरानी करना चाहते हैं। ‘यह टूल समाचार, सोशल मीडिया डेटा और राजनीतिक-आर्थिक सूचकांकों को एकत्रित करके उपयोगकर्ता को उनकी जटिल आपूर्ति श्रृंखलाओं और

निवेशों में व्यवधानों और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों की समझ प्रदान करता है।’

बौद्धिक संपदा और राष्ट्रीय सुरक्षा का नुकसान

सबसे चिंताजनक मुद्दा यह है कि भारतीयों से संबंधित व्यक्तिगत डेटा और उससे जुड़ी हर चीज़ को चुराकर पश्चिमी ढाँचों में ढाला जा रहा है और परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले नए सिद्धांतों को विकास के नाम पर भारत में निर्यात किया जा रहा है। यह डेटा भारतीयों की बौद्धिक संपदा है। और इसका दुरुपयोग गुप्त रूप से, बिना किसी पारदर्शिता के, इसके इच्छित उपयोगों के संबंध में किया जा रहा है।

यद्यपि आरंभ में इसके कुछ सकारात्मक लाभ प्रतीत हो सकते हैं, इतिहास गवाह है कि सभ्यता निर्माण अभियान उपनिवेशवादियों का उपनिवेशित लोगों पर नियंत्रण मजबूत करने के उद्देश्य से चलाए जाते हैं। उपनिवेशित लोगों का इतिहास और संस्कृति असंगति में सिमट जाती है, और उपनिवेशवादी उस व्यापक ढांचे को नियंत्रित करते हैं जो इसे समझने में सहायक होता है।

हार्वर्ड जैसी विदेशी संस्थाओं के हाथों में महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और अन्य सभी प्रकार की जानकारियाँ होने से सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं को विकसित करने की क्षमता खतरे में पड़ जाती है। भारत की सबसे संवेदनशील कमजोरियों से संबंधित संवेदनशील आंकड़ों से लैस हार्वर्ड, कानूनों को बदलने और बाहरी आक्रमणकारियों, चाहे वे मिशनरी हों, आर्थिक ताकतें हों या राजनीतिक विरोधी हों, की मदद करने के लिए खुलेआम दबाव का सहारा ले सकता है। यह देश को अस्थिर करने के लिए पहचान की राजनीति और सामाजिक अशांति को बढ़ावा दे सकता है। यह लोगों की

प्रतिस्पर्धात्मक संभावनाओं को नुकसान पहुँचाने के लिए औसत दर्जे को बढ़ावा दे सकता है। यह अधिक लोगों को लुभाने के लिए विभिन्न प्रकार के लाभ बाँट सकता है। यह आक्रमणकारियों को संत और पीड़ितों को उत्पीड़क के रूप में प्रस्तुत करने के लिए इतिहास को फिर से लिख सकता है।

चूंकि इसका ब्रांड धन आकर्षित करता है और इस तरह के धन के लिए कर छूट उपलब्ध कराने हेतु कानून निर्माण को सफलतापूर्वक प्रभावित कर चुका है, इसलिए यह लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को दरकिनार करने और नागरिक समाज पर वास्तविक प्रभाव स्थापित करने की स्थिति में आ सकता है।

यह संभव है कि भारत अनजाने में अपने नागरिकों की संपत्तियों की रक्षा करने में विफल हो रहा है। और वह नीति-निर्माण का काम हार्वर्ड विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों के लोगों को सौंप रहा है।

11. आनंद महिंद्रा और उत्तरआधुनिकतावाद

अवलोकन

अगले कुछ अध्यायों में, हम हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विभिन्न केंद्रों में चल रही और भारतीय अरबपतियों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का साहित्यिक सर्वेक्षण करेंगे। हम जिन स्रोत सामग्रियों का उपयोग करेंगे, वे मुख्य रूप से स्वयं विद्वानों के लेखन या व्याख्यान, साथ ही उनके संस्थानों की रिपोर्ट और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मीडिया हैं।

इनमें से कई विषय प्रशंसनीय और अध्ययन के योग्य हैं। हमारा यह भी कहना नहीं है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय और इन केंद्रों को इस प्रकार के शोध कार्य करने का कोई अधिकार या आधिपत्य नहीं है। हमारी आलोचना केवल उन मुद्दों पर चिंता व्यक्त करती है जहां इन अध्ययनों का भारत के भविष्य और संप्रभुता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। सार्वजनिक नीति, संवेदनशील सामाजिक-आर्थिक मुद्दों की समझ, राष्ट्र के विकास के लिए प्राथमिकताओं और उद्देश्यों का निर्धारण, और अनुसंधान एवं विकास से संबंधित कुछ मूलभूत कार्य हैं जो समाज को आकार देने के लिए आवश्यक हैं। इन्हें स्वदेशी स्तर पर विकसित किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यह वह कार्य है जिसे भारत को स्वयं, भारत के लिए और भारतीयों के लिए करना चाहिए। यह एक ऐसी मूलभूत क्षमता है जिसे कई कारणों से आउटसोर्स नहीं किया जा सकता, विशेषकर विदेशी संस्थानों को।

पहली बात तो यह है कि बौद्धिक पूंजी और उसे आगे बढ़ाने की क्षमता न होने के कारण भारत विदेशी शक्तियों पर निर्भर हो जाएगा और उनके नियंत्रण में आ जाएगा। रूस को ही उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे एक प्रमुख विश्व शक्ति भी रातोंरात विश्व मंच से इस हद तक अलग-थलग पड़ सकती है कि उसे बुनियादी वित्तीय ढांचे और विश्व व्यापार प्रणालियों तक पहुंच से वंचित कर दिया जाए, जिन्हें अब तक सार्वभौमिक माना जाता था।

दूसरे, इन बाहरी पक्षों द्वारा निकाला और इस्तेमाल किया जा रहा डेटा सही मायने में भारत के नागरिकों का है। इस डेटा का उपयोग समाज के कामकाज को समझने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु किया जा सकता है और इसी प्रक्रिया का उपयोग अवांछित हस्तक्षेपों, जैसे कि जन-भड़काने और सामाजिक हेरफेर आदि के प्रभाव की निगरानी के लिए

भी किया जा सकता है। कई देश डेटा गोपनीयता कानून लागू करते हैं जो अपने नागरिकों से प्राप्त डेटा पर संप्रभुता का दावा करते हैं। लेकिन भारतीय डेटा को समाज की मदद करने के बहाने छल-कपट से हथियाया जा रहा है और इस प्रक्रिया में जांच से बचा जा रहा है।

तीसरा, संवेदनशील सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक सुधार परियोजनाओं की सफलता के लिए, उन्हें लोगों के सांस्कृतिक संदर्भ और मानदंडों के अनुरूप होना आवश्यक है। हमने देखा है कि पश्चिमी प्रणालियों के अनुसार गठित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण रवांडा में नरसंहार का सामना कर रहे लोगों और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का सामना कर रहे लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में विफल रहे हैं। दोनों ही मामलों में, बाहरी रूप से थोपी गई प्रणालियों को अस्वीकार कर दिया गया, चाहे उनकी मंशा कितनी भी अच्छी क्यों न रही हो, और प्रतिशोधात्मक न्याय के बजाय सुलह की दिशा में उन्मुख कम औपचारिक तंत्रों को प्राथमिकता दी गई। अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने की यह क्षमता एक स्वस्थ, कार्यात्मक और लचीले समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने नागरिकों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील हो सके।

चौथा, हिंदू धर्म और भारत के प्रति अंतर्निहित पूर्वाग्रह है, जिन्हें आदिम, बर्बर और प्रतिगामी माना जाता है। यह औपनिवेशिक काल की पुरानी रूढ़ियों का पुनरावलोकन है, जिन्होंने ईसाई धर्म और पश्चिमी तौर-तरीकों का प्रचार करने के लिए अत्याचार साहित्य का इस्तेमाल किया। अब इसे और भी कपटपूर्ण तरीके से मार्क्सवादी दृष्टिकोण के साथ जोड़ दिया गया है, जो क्रांति और हिंसक टकराव को भड़काने का प्रयास करता है, जिसके लिए देशी प्रणालियों को पूरी तरह से ध्वस्त करके एक 'विरोधी' विचारधारा उत्पन्न करना आवश्यक है। यह रचनात्मक, व्यावहारिक समस्या समाधान को दरकिनार करते हुए, बलि का बकरा बनाने और

असहमति एवं विभाजन फैलाने को बढ़ावा देता है।
दूसरे शब्दों में कहें तो, ये परियोजनाएँ हमेशा हानिरहित और नेक इरादे वाली नहीं होतीं। इनके पीछे एक अंतर्निहित ढाँचागत एजेंडा है जो भारत की मूल परंपराओं, प्रथाओं, संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों को नष्ट करने और उनकी जगह पश्चिमी सार्वभौमिकता या अब्राहमिक धर्म के विचारों को स्थापित करने के लिए पूरी लगन से काम कर रहा है।
इन अध्यायों में हम इन मामलों पर चीन द्वारा अपनाए गए वैकल्पिक दृष्टिकोण का वर्णन करेंगे। हम चीनी दृष्टिकोण को पूरी तरह अपनाने की वकालत नहीं कर रहे हैं। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विद्वता की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि जब विचारों और विषयों में संतुलन, सम्मानजनक और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण, और बारीकियों की समझ न हो, तो ये आदर्श अर्थहीन हो जाते हैं। इन पहलों को वित्तपोषित करने वालों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए और अपने धन के उपयोग पर अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करने चाहिए।
यह अध्याय विशेष रूप से हार्वर्ड स्थित महिंद्रा ह्यूमैनिटीज सेंटर से संबंधित है और दर्शाता है कि कैसे इसका उपयोग (इसके उद्योगपति दानदाता की जानकारी के बिना भी) भारत को विश्व की सबसे प्राचीन जीवित परंपराओं में से एक और इसलिए अपने आप में अध्ययन योग्य देश के रूप में उसकी प्रतिष्ठा को कमज़ोर करने के लिए किया गया है। यह बताता है कि कैसे हार्वर्ड ने केंद्र के प्रमुख के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया है जो इस सभ्यता के प्रति अपने शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, जबकि उनके साथियों ने उनकी विद्वत्ता पर सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मुद्दा उत्तर आधुनिकतावाद का वह दृष्टिकोण है जिसके माध्यम से भारत का अध्ययन किया जा रहा है। अध्याय 1 में इस दृष्टिकोण से संबंधित मुद्दों पर एक भारतीय परिप्रेक्ष्य से चर्चा की गई है।

2010 में, महिंद्रा एंड महिंद्रा के अरबपति मालिक आनंद महिंद्रा ने हार्वर्ड को दस मिलियन डॉलर दान किए, जिसके जवाब में हार्वर्ड ने अपने मानविकी केंद्र का नाम महिंद्रा मानविकी केंद्र रखकर उन्हें धन्यवाद दिया। महिंद्रा ने कहा था:

कला, संस्कृति, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में वैश्विक चिंतन में भारत के योगदान की बौद्धिक विरासत का हिस्सा होने पर मुझे गर्व है। मैं व्यवसाय के मूल मूल्य प्रस्ताव में सामाजिक और मानवतावादी सरोकारों को शामिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं और कार्यस्थल और कार्यस्थल पर अपने साथियों और सहकर्मियों के अपार समर्थन से ऐसा करने का प्रयास किया है।

महिंद्रा का सराहनीय लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संस्कृतियों और विषयों के बीच विचारों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना है। इसके फलस्वरूप, हार्वर्ड ने उन्हें विश्वविद्यालय संसाधन समिति, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एशिया सेंटर की सलाहकार समिति, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन सलाहकार बोर्ड और एशिया-प्रशांत सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया है। उन्होंने एचबीएस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की सह-स्थापना की और 2008 में एचबीएस पूर्व छात्र उपलब्धि पुरस्कार प्राप्त किया।

हार्वर्ड क्रिमसन ने रिपोर्ट किया: 'यह हार्वर्ड के इतिहास में केवल मानविकी के लिए दिया गया सबसे बड़ा दान था।' प्रो. तरुण खन्ना ने इस दान को संभव बनाया और एक गरीब देश से एक अमीर देश में धन प्रवाह को सांस्कृतिक रूढ़ियों को तोड़ने के तरीके के रूप में उचित ठहराया।

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बिजनेस स्कूल और ह्यूमैनिटीज सेंटर द्वारा इन दान का सदुपयोग होने के साथ-साथ, ये भारत और दक्षिण एशिया में एक ऐसी जागरूकता की लहर पैदा कर सकते हैं जो सौभाग्यशाली लोगों को अच्छे संस्थानों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करेगी... इस तरह

का अंतर्राष्ट्रीय परोपकार—जिसमें पैसा एक अपेक्षाकृत अविकसित देश से अधिक विकसित देश की ओर जाता है—सांस्कृतिक रूढ़ियों को तोड़ने में मदद करेगा...

महिंद्रा ने होमी के. भाभा को केंद्र के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए जाने का समर्थन करते हुए कहा कि महिंद्रा का नाम, निदेशक के नाम के साथ मिलकर, केंद्र को 'भारत की विरासत और कला एवं मानविकी में इसके समकालीन योगदान का प्रतीक' बना देगा। भाभा ने भी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि 'अमेरिका में कोई अन्य मानविकी केंद्र ऐसा नहीं है जिसका नाम ही उसके वैश्विक स्वरूप को दर्शाता हो।'

भाभा अकादमिक जगत में सबसे प्रभावशाली उत्तरऔपनिवेशिक और उत्तरआधुनिकतावादी विद्वानों में से एक थे, और भारतीय वामपंथियों द्वारा सराहे जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित विद्वानों में गिने जाते थे। मानविकी, और विशेष रूप से आलोचनात्मक सिद्धांतों में उनकी प्रतिष्ठा को देखते हुए, महिंद्रा मानविकी केंद्र पर उनका गहरा प्रभाव रहा है। इसलिए, भाभा की स्थिति और बौद्धिक योगदान को स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है। यह पृष्ठभूमि हार्वर्ड के भारत के प्रति दृष्टिकोण को आकार देने में उत्तरआधुनिकतावाद की भूमिका को समझने में भी सहायक होगी। उत्तरआधुनिकतावाद न केवल भारत के विखंडन के लिए आधार प्रदान करता है, बल्कि आलोचनात्मक नस्ल सिद्धांत जैसे विभिन्न प्रचलित सामाजिक विज्ञान सिद्धांतों का भी समर्थन करता है।

जब भाभा को पहली बार हार्वर्ड लाया गया, तो उनकी नियुक्ति को एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखा गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि 'इस शरद ऋतु में शिकागो विश्वविद्यालय से होमी के. भाभा का अधिग्रहण एक बड़ी सफलता माना जाता है, मानो सैमी सोसा बोस्टन रेड सॉक्स में शामिल हो गए हों।' भारतीय सरकार ने भाभा को प्रतिष्ठित पद्म भूषण से

सम्मानित किया है। उन्होंने कई प्रतिष्ठित समितियों में अपनी सेवाएं दी हैं, जैसे कि इंफोसिस पुरस्कार के लिए मानविकी जूरी।

होमी के. भाभा, हार्वर्ड के जादूगर

नव नियुक्त प्रमुख भाभा ने महिंद्रा द्वारा दिए गए उपहार की प्रशंसा की: कला और मानविकी के सार्वभौमिक उपयोग के लिए विश्व स्तर पर प्रतिबद्ध संस्थानों को ऐसे परोपकारी दान दिए जाएंगे। मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता, राष्ट्र केवल अपनी वार्षिक विकास दर से ही अपना नाम और प्रतिष्ठा नहीं बनाते। सही मायने में वैश्विक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, आपको दिखना होगा, संस्कृति और मानवीय मूल्यों का प्रतिनिधित्व करना होगा, और मुझे लगता है कि यही आनंद के दान की विशेष विशेषता है... हार्वर्ड में मानविकी केंद्र, जिसका मैं निर्देशन करता हूं, एक केंद्र मात्र नहीं है, बल्कि यह विश्वविद्यालय के चौराहे पर स्थित है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि मानविकी का केंद्रीय महत्व तथ्यों की व्याख्या करना सिखाना है। उन्होंने कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यवसाय, कला, साहित्य और धर्म की सभी जानकारी तब तक बेकार है जब तक उसकी सही व्याख्या न की जाए। हम उनके नीचे दिए गए सामान्य कथन से सहमत हैं:

यदि आपके पास मानवतावादी विषय नहीं हैं, जो नैतिकता, सदाचार, मानव जीवन और उसकी प्रगति, समानता, निष्पक्षता और न्याय, सहानुभूति, अल्पसंख्यकों के अधिकारों आदि पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और वित्तीय क्षेत्र में मूल्यों का एक मजबूत ढांचा नहीं होगा। मानविकी एक ऐसा ढांचा तैयार करती है जो ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों को एक साथ आने की अनुमति देता है। मानविकी का एक और महत्वपूर्ण योगदान है। सूचनाओं और तथ्यों का अंबार लगा

हुआ है। सूचना ज्ञान में कैसे परिवर्तित होती है, यह व्याख्या की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। मैं इन तथ्यों को क्यों देख रहा हूँ? मुझ पर इतनी सारी जानकारी क्यों डाली जा रही है? मैं मूल्यवान और महत्वपूर्ण को अनुपयोगी से कैसे अलग करता हूँ? इन सभी के लिए व्याख्या की आवश्यकता है। मानविकी, साहित्य, कला इतिहास, दर्शनशास्त्र, धर्मशास्त्र या धर्मग्रंथों का अध्ययन व्याख्या और सूचना के मूल्यांकन से संबंधित है। और यह एक ऐसी बात है जिसके बारे में लोग अक्सर प्रेस से बात नहीं करना चाहते। प्रेस पूछेगा कि व्याख्या क्या है, इसके परिणाम क्या हैं, इससे क्या लाभ होता है। व्याख्या का बाजार मूल्य क्या है? शून्य। लेकिन व्याख्या के बिना, आप बाजार में हस्तक्षेप करना, निर्णय लेना नहीं समझ पाएंगे। ... ऐसे युग में जहां हर तरफ से सूचनाओं की बौछार हो रही है, वहीं व्याख्या ही सूचनाओं को ज्ञान में परिवर्तित करती है।

हालांकि, मुख्य मुद्दा यह है: किसकी व्याख्या का उपयोग किया जाए? किस सभ्यता के परिप्रेक्ष्य से? मानविकी में 'सार्वभौमिक' व्याख्यात्मक परिप्रेक्ष्य जैसी कोई चीज नहीं है। भारतीय चिंतन में भी, और पश्चिमी चिंतन में भी यही स्थिति है। हालांकि, किसी सभ्यता के परिप्रेक्ष्यों में महत्वपूर्ण समानताएं होती हैं जो एक सुसंगत विश्वदृष्टि का निर्माण करती हैं। पश्चिमी विश्वदृष्टि भारतीय विश्वदृष्टि से काफी भिन्न है।

भाभा एक प्रसिद्ध उत्तरआधुनिकतावादी विद्वान हैं जिन्होंने अपने पूरे करियर में पश्चिमी विचार की इस शैली का समर्थन किया है और इसका उपयोग भारत को एक राष्ट्र के रूप में, वैदिक विचार को एक प्रणाली के रूप में और अन्य भारतीय चीजों की वैधता को विखंडित करने और खंडन करने के लिए किया है। हमारे निम्नलिखित विश्लेषण से जो सबसे महत्वपूर्ण बात उभर कर आती है वह यह है कि भाभा भारत में मानविकी

के अमेरिकीकरण पर जोर देते हैं।
एक दशक से भी पहले, हार्वर्ड के प्रोफेसर माइकल विट्ज़ेल ने हमें बताया था कि वामपंथी समूह इंडोलॉजी विभाग को दक्षिण एशियाई अध्ययन विभाग में बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने इन्फिनिटी फाउंडेशन को दक्षिण एशियाई अध्ययन के नए चार्टर को प्रभावित करने में मदद करने की पेशकश की, बशर्ते हम इसे बड़े पैमाने पर वित्त पोषित कर सकें और वे अपनी सेवानिवृत्ति से पहले कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ सुनिश्चित कर सकें। हमें उनकी ईमानदारी और प्रस्ताव पर पूरा भरोसा था, लेकिन हम आवश्यक धनराशि जुटाने में असफल रहे।
जैसे-जैसे साल बीतते गए, विट्ज़ेल की चेतावनियाँ सच साबित हुईं। हार्वर्ड के नए दक्षिण एशिया कार्यक्रम पिछले कई दशकों से चले आ रहे इंडोलॉजी से लगातार दूर होते गए। 2010 तक, निम्नलिखित घोषणा की गई:
संस्कृत और भारतीय अध्ययन विभाग ने दक्षिण एशियाई अध्ययन विभाग के रूप में अधिक अंत:विषयक दृष्टिकोण अपनाने की योजना बनाई है। संस्कृत के प्रोफेसर माइकल ई. जे. विट्ज़ेल के अनुसार, विभाग अपने वर्तमान संकाय को आठ से बढ़ाकर 15 करने के लिए मानव विज्ञान, इतिहास, धर्म, लोककथा और पौराणिक कथा, संगीत और पुरातत्व जैसे अन्य विभागों से ज्ञान प्राप्त करेगा।

भाभा का उत्तरआधुनिकतावाद
यह कहना उचित होगा कि श्वेत उदारवादी अकादमिक हलकों में भाभा के अपने ही साथियों के बीच भी उनकी आलोचना होती है। वे उनकी जानबूझकर अपनाई गई अस्पष्टता, रहस्यवाद और अनिश्चितता की रणनीति की आलोचना करते हैं। यह सुनिश्चित करना कि बहुत कम लोग

ही उन्हें समझ सकें, एक शानदार रणनीति है क्योंकि जो बात समझना कठिन हो उसे चुनौती देना असंभव है।
दिलचस्प बात यह है कि 1998 में, फिलॉसफी एंड लिटरेचर पत्रिका ने भाभा को अपनी बैड राइटिंग प्रतियोगिता में दूसरा पुरस्कार दिया। यह एक निरर्थक अकादमिक प्रकाशन को उजागर करने का एक तरीका है। यह पुरस्कार 'विद्वानों की पुस्तकों और लेखों में पाए जाने वाले सबसे शैलीगत रूप से निंदनीय अंशों से खराब लेखन का जश्न मनाता है'। भाभा को उनकी व्यापक रूप से प्रशंसित पुस्तक, द लोकेशन ऑफ कल्चर में निम्नलिखित वाक्य के लिए पुरस्कार दिया गया था:
यदि कुछ समय के लिए, इच्छा की छल को अनुशासन के उपयोग के लिए परिकलित किया जा सकता है, तो जल्द ही अपराधबोध, औचित्य, छद्म-वैज्ञानिक सिद्धांत, अंधविश्वास, नकली प्राधिकार और वर्गीकरण की पुनरावृत्ति को विभाजन के एक प्रवचन की अशांति को औपचारिक रूप से "सामान्य" बनाने के हताश प्रयास के रूप में देखा जा सकता है जो इसकी अभिव्यंजक पद्धति के तर्कसंगत, प्रबुद्ध दावों का उल्लंघन करता है।
जब भाभा को हार्वर्ड संकाय में नियुक्त किया गया, तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्रोफेसर एमेरिटस मार्जोरी पेरलोफ ने 'निराशा' व्यक्त करते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि 'उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है'। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में मीडिया अध्ययन के प्रोफेसर मार्क क्रिस्पिन मिलर ने भी उनके काम की आलोचना करते हुए कहा: 'अंततः यह तर्क दिया जा सकता है कि नवशब्दों और लैटिन से प्रेरित प्रचलित शब्दों के अलावा इसमें कोई अर्थ नहीं है। ज्यादातर समय मुझे समझ नहीं आता कि वे क्या कह रहे हैं।' एक अन्य पश्चिमी आलोचक ने भाभा की सबसे चर्चित पुस्तक को 'घनी, आडंबरपूर्ण गद्य शैली' बताया है, जो 'उन मानवतावादियों में आम हो गई

है जो वैज्ञानिकों से खुद को हीन समझते हैं।' अन्य लोग बताते हैं कि वे अपने विचारों की तुच्छता को गूढ़ उत्तर-संरचनावादी शब्दावली के पीछे छिपाते हैं। उन्हें अनुचित प्रसिद्धि मिलती है, जबकि इसमें कोई शोध-प्रबंध, कोई तर्क या कोई प्रमाण नहीं है। वे सामान्य कथनों का प्रयोग करके विद्वत्ता का दिखावा करते हैं, जो पाठक की संज्ञानात्मक क्षमताओं को अभिभूत कर देते हैं। जटिल वाक्य संरचनाओं और कुछ ऊंचे-ऊंचे उद्धरणों का उपयोग करते हुए, वे एक ऐसे धोखेबाज विक्रेता की तरह हैं जो आपको एक शोध-प्रबंध बेच रहा है।

प्रख्यात उदारवादी शिक्षाविद और अपनी पुस्तक "व्हाइट मिथोलॉजीज़: राइटिंग हिस्ट्री एंड द वेस्ट" के लिए प्रसिद्ध रॉबर्ट यंग, भाभा की एक वैचारिक योजना से दूसरी वैचारिक योजना पर बार-बार जाने की आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि भाभा के किसी भी विचार को अनुभवजन्य साक्ष्य या ठोस तर्क द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, और वे बिना किसी औचित्य के एक विचार से दूसरे विचार पर बेतरतीब और असंतुलित रूप से जाने से विचलित हैं।

हर बार भाभा इस शाश्वत वर्णन के माध्यम से यह संकेत देते प्रतीत होते हैं कि विचाराधीन अवधारणा स्वयं औपनिवेशिक विमर्श की स्थिति का निर्माण करती है और सभी ऐतिहासिक कालों और संदर्भों के लिए मान्य होगी – इसलिए जब इसे बाद में अगली अवधारणा से प्रतिस्थापित किया जाता है तो यह कुछ हद तक आश्चर्यजनक लगता है... स्वाभाविक रूप से, विभिन्न अवधारणाएँ अलग-अलग महत्व उत्पन्न करती हैं – लेकिन उनके बीच संबंध की किसी भी अभिव्यक्ति का अभाव चिंताजनक बना रहता है।

यंग आगे कहते हैं कि भाभा का 'सैद्धांतिक अराजकतावाद' और 'सुसंगत मेटाभाषा' का अभाव उनकी शैली को समझ से परे बना देता है। किसी ने

एक बार चुटकी लेते हुए कहा था: 'क्या होमी भाभा समझते हैं कि वे क्या लिखते हैं?' कहावत है, अगर आप प्रतिभा से प्रभावित नहीं कर सकते, तो बकवास से उन्हें उलझा दें!

यह हमें उत्तरआधुनिकतावादी मिशेल फौको और दार्शनिक जॉन सियरल के बीच हुए संवाद की याद दिलाता है, जिसमें फौको ने ऐसी अस्पष्ट भाषा के प्रयोग को उचित ठहराया था जिसे कोई नहीं समझ पाएगा। ऐसा माना जाता है कि फौको ने सियरल से कहा था कि उन्होंने एक गूढ़ और अभेद्य शैली में इसलिए लिखा क्योंकि 'फ्रांसीसी दार्शनिकों द्वारा गंभीरता से लिए जाने के लिए किसी के लेखन का 25 प्रतिशत हिस्सा समझ से परे निरर्थक होना आवश्यक है'।

उत्तरआधुनिकतावाद ऐसे शोधों से भरा पड़ा है। वास्तव में, इसके विद्वान उत्तरआधुनिकतावाद की परिभाषा को लेकर भी आपस में सहमत नहीं हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि इसके विद्वानों द्वारा सर्वमान्य एक सिद्धांत यह है कि निरपेक्ष सत्य और वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के सभी विचारों को अस्वीकार कर देना चाहिए। इसने उत्तरआधुनिकतावाद को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में स्थापित कर दिया है जहाँ केवल एक ही कारक पर निर्भर करते हुए कुछ भी हो सकता है: क्या किसी के सिद्धांत और दावे उन समकक्षों के समूह द्वारा स्वीकार किए जाते हैं जिनके पास प्रत्येक दावे के भाग्य का निर्धारण करने की शक्ति है। यहाँ किसी भी प्रकार के प्रमाण या तार्किक प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है।

इस संदर्भ में एक चर्चित विवाद तब सामने आया जब न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ एलन सोकल ने जानबूझकर निरर्थक शब्दों से भरा एक लेख लिखा। इसमें दावा किया गया था कि क्वांटम गुरुत्वाकर्षण प्रकृति में उत्तर-आधुनिकतावादी है, और उन्होंने अपने लेख में उत्तर-आधुनिकतावादियों द्वारा पसंद किए जाने वाले

मुहावरों का इस्तेमाल किया। उन्होंने 'सीमाओं का उल्लंघन', 'विखंडन', 'प्रमुख विचारधाराएं और सत्ता संबंध', 'स्व-संदर्भित', 'प्रति-वर्चस्ववादी', 'हाशिए पर स्थित समुदाय' आदि जैसे प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया। दूसरे शब्दों में, भौतिकी ने अंततः यह निष्कर्ष निकाला कि वास्तविकता पूरी तरह से एक सामाजिक रचना है। सोकल ने यह लेख उत्तर-आधुनिकतावाद की दो सबसे प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में से एक, ड्यूक यूनिवर्सिटी प्रेस की 'सोशल टेक्स्ट' को भेजा। इसे स्वीकार कर लिया गया। फिर उन्होंने खुलासा किया कि यह सब एक धोखा था और इसके बारे में उत्तर-आधुनिकतावाद की दूसरी लोकप्रिय पत्रिका, 'लिंगुआ फ्रांका' में लिखा। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य यह प्रदर्शित करना था कि उत्तर-आधुनिकतावाद के सबसे सम्मानित संपादक भी ऐसी चीज को नहीं पहचान सकते जो पूरी तरह से बेतुकी और हास्यास्पद हो!

भारत में द हिंदू को दिए गए 2005 के एक साक्षात्कार में, भाभा अपने आलोचकों से नाराज़ थे और उन्होंने कहा कि उन जैसे दार्शनिक को 'आम आदमी की आम भाषा' का उपयोग करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि वैज्ञानिकों को तकनीकी भाषा के उपयोग के लिए छूट दी जाती है जो आम पाठकों को तुरंत समझ में नहीं आती है। यह एक घमंडी बयान है जिसमें वह दावा करता है कि वह खुद को 'दार्शनिक' घोषित करके अतार्किक तुलनाओं में बोल और लिख सकता है। हालांकि, इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि वह खुद की तुलना उन वैज्ञानिकों से करता है जो तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करते हैं। उसे यह जानना चाहिए कि विज्ञान में प्रयुक्त तकनीकी शब्द सटीक परिभाषाओं के अधीन होते हैं, स्पष्ट होते हैं और व्यापक बहस के बाद वैज्ञानिक समुदाय द्वारा स्वीकार किए जाते हैं; निरर्थक बातें उत्तर-आधुनिकतावाद की विशेषता वाली अस्पष्टता के आवरण में नहीं छिप

सकतीं।
इसके अलावा, वैज्ञानिक दावों की निरंतर स्वतंत्र अनुभवजन्य जांच और तार्किक छानबीन की जाती है, जिसका बौद्धिक स्तर उत्तरआधुनिकतावाद में पाए जाने वाले स्तर से कहीं अधिक होता है। एक बार पाठक किसी वैज्ञानिक शब्द को समझ लेता है, तो पाठ पूरी तरह स्पष्ट और असंदिग्ध हो जाता है, जबकि भाभा के उत्तरआधुनिकतावादी अहंकार के मामले में, उनके साथी उत्तरआधुनिकतावादी भी यह समझाने या समझने में असमर्थ हैं कि वे क्या कहना चाह रहे हैं।
इस पद्धति के पीछे उनका मकसद क्या हो सकता है? हमारा मानना है कि भाभा हार्वर्ड के प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए चालाकी से और सोची-समझी रणनीति अपना रहे हैं, जिसके तहत वे बेतुकी बातें फैलाकर पाठक के मन में संज्ञानात्मक असंगति पैदा कर रहे हैं। और एक बार जब पाठक की तर्कशक्ति इस तरह टूट जाती है, तो निरर्थक बातें भी ज्ञान का रूप ले लेती हैं और पाठक को वांछित वैचारिक स्थिति की ओर मोड़ा जा सकता है। इसमें एक तरह से 'पाइड पाइपर' (जादूगर) उनका मार्गदर्शन कर सकता है।
पाठकों को उनके कार्यों को समझने में जितनी अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, भाभा की प्रतिष्ठा एक मौलिक विचारक के रूप में उतनी ही बढ़ती गई है। वास्तव में, कई विद्वानों का मानना है कि उनकी निरर्थकता ही उन्हें अद्भुत बनाती है। लेकिन अस्पष्टता और अपठनीयता का उपयोग एक छलावा है, न कि कोई प्रतिभा का चमत्कार।
दूसरी ओर, कई उदारवादी विचारकों ने अपने लेखन में स्पष्टता दिखाई है। उदाहरण के लिए, फ्रांसीसी-पश्चिमी भारतीय विचारक फ्रांत्ज़ फैनन एक प्रख्यात उत्तर-औपनिवेशिक विद्वान थे जिनकी शैली निरर्थक बातों से मुक्त थी और इसीलिए उनका काम पाठकों के लिए सुलभ था।

भाभा पर यूरोपीय विचारकों, विशेष रूप से जैक्स लाकान, मिशेल फौकॉल्ट, सिगमंड फ्रायड और जैक्स डेरिडा की छाप, जितनी अधिक कोई उन्हें समझने की कोशिश करता है, उतनी ही स्पष्ट होती जाती है। भाभा के वे मूलभूत सिद्धांत क्या हैं जिन पर उनकी सारी प्रसिद्धि टिकी है? हमने उन्हें समझने में दो दशक बिताए हैं और नीचे हम अपनी क्षमता के अनुसार उनका संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं। हम उनके चार मुख्य विचारों को अत्यंत सकारात्मक ढंग से समझाएंगे और उन्हें सुसंगत और एकीकृत रूप से प्रस्तुत करेंगे ताकि उन्हें संदेह का लाभ मिल सके।
संकरता या संकरण: यह एक जटिल तरीका है जिससे भाभा कई संस्कृतियों के तत्वों को अपनाने की प्रक्रिया को संदर्भित करते हैं, जिसे आमतौर पर बहुसंस्कृतिवाद के रूप में जाना जाता है।
दुविधा: सरल शब्दों में कहें तो, इसका अर्थ यह है कि उपनिवेशवाद उपनिवेशित व्यक्ति की पहचान में एक विभाजन पैदा करता है। एक ओर, उसके पास उपनिवेशक द्वारा दी गई पहचान होती है, लेकिन साथ ही, वह अपनी मूल पहचान का एक हिस्सा भी बरकरार रखता है।
तीसरा क्षेत्र: यह दो परस्पर विरोधी पहचानों के बीच का मानसिक क्षेत्र है, जो दुविधा के कारण उत्पन्न होता है। यह संस्कृति की ऐतिहासिक पहचान की हमारी धारणा को चुनौती देता है, जो एक समरूप, एकीकृत शक्ति के रूप में, मूल अतीत द्वारा प्रमाणित और जनता की राष्ट्रीय परंपरा में जीवित रखी गई है। यहीं पर अपनी मूल संस्कृति के बारे में मौलिकता और शुद्धता के पदानुक्रमित दावे टूट जाते हैं और अपनी संस्कृति के बारे में नए कथन विकसित होते हैं। भाभा का मानना है कि संस्कृति के बारे में कुछ भी सुस्पष्ट नहीं है क्योंकि संस्कृति के सभी तत्वों को अलग किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है और विखंडित किया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक को फिर अपने उद्देश्य के अनुरूप ढाला जा

सकता है। यहां तक कि इसके इतिहास को भी वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार पुनर्लिखित किया जा सकता है।

अनुकरण: यह उनके संपूर्ण सिद्धांत का चरमोत्कर्ष है। यह उपनिवेशित लोगों द्वारा उपनिवेशवादियों की संस्कृति की नकल करने को संदर्भित करता है। इसका परिणाम प्रतिरोध का एक रूप है। 'अनुकरण का प्रभाव छलावरण है... यह पृष्ठभूमि के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रश्न नहीं है, बल्कि एक मिश्रित पृष्ठभूमि के विरुद्ध सामंजस्य स्थापित करने का प्रश्न है।' क्योंकि संकरण कभी भी उपनिवेशवादी की पूर्ण प्रतिकृति नहीं होता, इसलिए यह मूल उपनिवेशित संस्कृति के अवशेषों को बरकरार रखता है जो प्रतिरोध के एक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं।

भाभा जिसे संकरता कहते हैं, वह इस तथ्य को नज़रअंदाज़ करता है कि जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को उपनिवेशित करती है, तो सत्ता की विषमता के कारण एक सभ्यता का दूसरी सभ्यता द्वारा आत्मसात हो जाना जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। वह यह भी चाहते हैं कि हम बिना किसी ठोस तर्क के यह मान लें कि उपनिवेशित संस्कृति द्वारा उपनिवेशक की नकल करना हर मामले में प्रतिरोध का एक रूप है जो उपनिवेशवाद को कमजोर करता है। उनका कहना है कि यह प्रतिरोध उत्पीड़क और उत्पीड़ित के बीच आदान-प्रदान की सीमा को सीमित करता है।

लेकिन भाभा इस तथ्य को नज़रअंदाज़ करते हैं कि अंतर-सांस्कृतिक लेन-देन अनेक प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए, राजीव मल्होत्रा द्वारा प्रतिपादित यू-टर्न सिद्धांत उस यात्रा का विस्तृत वर्णन है जिसके द्वारा उपनिवेशक, उपनिवेशित सभ्यता का अनुभव करता है। इस यात्रा के दौरान, वह पराई संस्कृति को अपनी संस्कृति के रूप में अपना लेता है। यह सिद्धांत प्रक्रिया के पाँचों चरणों में कार्यरत विभिन्न शक्तियों और उनसे उत्पन्न होने वाले विभिन्न परिणामों की विस्तृत व्याख्या करता है।

यह उन दो सभ्यताओं पर ऐसे यू-टर्न के समग्र प्रभाव को भी स्पष्ट करता है जो इस मुठभेड़ में शामिल होती हैं।

उत्तरआधुनिकतावाद को खतरनाक बनाने वाली बात यह है कि यह किसी भी सिद्धांत को प्रमाणों से सिद्ध करने के दायित्व को समाप्त कर देता है। यह सत्य को सापेक्ष बना देता है और उसे पहचान की राजनीति में बदल देता है। सभी सत्य-दावों को अभिजात वर्ग द्वारा सत्ता के खेल के रूप में खारिज कर दिया जाता है। हालांकि कुछ शोधों में यह बात सच है, लेकिन उत्तरआधुनिकतावादी अति कर देते हैं। वे प्राकृतिक विज्ञान, गणित आदि सहित सभी ज्ञान को अभिजात वर्ग के हाथों में सत्ता के परिणाम के रूप में विखंडित कर देते हैं। इससे उत्तरआधुनिकतावाद 'वोकेवाद' का समर्थक बन जाता है क्योंकि राजनीतिक शुद्धता, अनुभवजन्य प्रमाण और तार्किक व्याख्या की आवश्यकता को दरकिनार कर देती है।

देवदत्त पट्टानाइक इस शैली का एक प्रमुख उदाहरण हैं और वैदिक शास्त्रों को सापेक्षिक रूप देने के कारण विवादों में घिरे रहे हैं। उदाहरण के लिए, वे भगवद गीता की सभी पिछली व्याख्याओं को खारिज करते हैं और अपनी 'मेरी गीता' को ही मान्य व्याख्या मानते हैं। यह सच है कि यह परंपरा चुनौतियों और नए विचारों से फलती-फूलती है। लेकिन इस परंपरा के भीतर व्याख्या के कुछ सुस्पष्ट सिद्धांत भी हैं।

भारतीय ग्रंथों का उत्तरआधुनिकतावादी विखंडन उनके महत्वहीनकरण, गलत अनुवाद और खंडित होने की ओर ले जाता है, जिनका संदर्भ से बाहर मनमाने ढंग से उपयोग और दुरुपयोग किया जा सकता है। भाभा जिस संकरता की प्रशंसा करते हैं, वही गैर-पश्चिमी सभ्यताओं को पश्चिम के गर्भ में समाहित करने का कारण बनती है।

यह आश्चर्य की बात नहीं है कि भाभा प्रसिद्ध कर्नाटक गायक टी.एम. कृष्णा जैसे लोगों का समर्थन करते हैं, जिनका प्रमुख कार्य भारतीय

शास्त्रीय संगीत को भाभा द्वारा 'हाइब्रिड' कहे जाने वाले रूपों में समाहित करने को बढ़ावा देना है। महिंद्रा ह्यूमैनिटीज सेंटर में दिए गए एक व्याख्यान के दौरान इस बात पर प्रकाश डाला गया।

उत्तरआधुनिकतावाद के बारे में हमारा मत यह है कि यह वेदांत और बौद्ध धर्म से अनेक विचार ग्रहण करता है, और इस पर अनेक अकादमिक लेखों में चर्चा हो चुकी है। हालांकि, ये उधार विकृत हो जाते हैं, जैसा कि अक्सर तब होता है जब ज्ञान एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता में समाहित हो जाता है। उत्तरआधुनिकतावाद और भारतीय ज्ञान प्रणालियाँ दोनों ही हमारी इंद्रियों द्वारा अनुभव की जाने वाली सामान्य वास्तविकता का विखंडन करती हैं। भारतीय प्रणालियाँ ऐसा उच्चतर चेतना अवस्था में एक उच्चतर वास्तविकता को प्रकट करने के उद्देश्य से करती हैं, जिसे मोक्ष, निर्वाण आदि के नाम से जाना जाता है। दूसरी ओर, उत्तरआधुनिकतावाद ऐसी किसी उच्चतर चेतना अवस्था को नहीं मानता।

तो, सामान्य वास्तविकता के उत्तर-आधुनिकतावादी विखंडन से क्या निष्कर्ष निकलता है और इससे क्या हासिल होता है? यह एक गंभीर प्रश्न है जिस पर उत्तर-आधुनिकतावादी चर्चा नहीं करते। वेदांत और उत्तर-आधुनिकतावाद दोनों ही हमारे सांसारिक ज्ञान से मुक्ति पाना चाहते हैं, लेकिन उत्तर-आधुनिकतावाद में इस सामान्य चेतना से परे की किसी भी प्रकार की तत्वमीमांसा का अभाव है। इसका कारण यह है कि उत्तर-आधुनिकतावाद का जन्म एक राजनीतिक साधन के रूप में हुआ था, जिसका उद्देश्य सत्ता और प्रभुत्व का परिणाम माने जाने वाले सभी वृहद आख्यानों का विरोध करके यूरोपीय अन्याय का विरोध करना था। और इसलिए, यह पूरा आंदोलन राजनीतिक स्तर पर ही अटका रहा और आध्यात्मिक रूप से कभी आगे नहीं बढ़ पाया।

भारतीय फ्रेंचाइजी

भाभा दो संस्कृतियों के बीच संतुलन बनाने वाले एक चतुर मध्यस्थ हैं। उन्होंने भारतीयों को यह विश्वास दिलाने की कला में महारत हासिल कर ली है कि वे उनके लिए नवीनतम अमेरिकी साहित्यिक सिद्धांत लेकर आए हैं, और साथ ही साथ खुद को अमेरिकियों के सामने भारत की प्रामाणिक आवाज के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

वे तीसरी दुनिया में एक प्रमुख अमेरिकी बुद्धिजीवी के रूप में जाने जाते हैं। अंग्रेजी भाषा पर उनकी महारत उन्हें अलंकृत और चंचल शब्दों से भारतीयों को मंत्रमुग्ध करने में सक्षम बनाती है। आलोचनात्मक सिद्धांत के गढ़ की रक्षा करने वाले भारतीय चौकीदार या संरक्षक उन्हें एक महान हस्ती मानते हैं। इस संगठन के वरिष्ठ सदस्य कनिष्ठ अंग्रेजी ऑनर्स के छात्रों के बीच उनकी रचनाओं का प्रचार करने के लिए अधिकृत पुरोहित हैं। भारत में संगठन संचालक उन्हें अंतर-सांस्कृतिक मध्यस्थ के रूप में अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए प्रस्तुत करते हैं।

भारत में पैदा हुई यह बनावटी लोकप्रियता अमेरिका में श्वेत उदारवादियों को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उन्हें लगता है कि वह साम्राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है और पलटवार कर रहा है। इससे श्वेत लोगों का अपराधबोध कम हो जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अमेरिकी अकादमिक जगत अपने नस्लवाद का समाधान कर रहा है। भारतीय युवाओं को सबसे अधिक नुकसान पहुँचाने का तरीका उन्हें और अधिक भ्रम और मूर्खता की ओर धकेलना है। उत्तरआधुनिकतावाद किसी भी जनमानस के आत्मसम्मान को नष्ट करने का एक भयानक हथियार है। अमेरिका एक ऐसा व्यावहारिक समाज है जिसके पास ऐसी बेतुकी बातों के लिए समय नहीं है। इसलिए, अमेरिका में भाभा का कोई व्यावहारिक महत्व नहीं था और न ही अमेरिकी सरकार और मुख्यधारा के कॉरपोरेट

जगत ने उन्हें एक गंभीर विचारक के रूप में मान्यता दी। कई दशकों तक, उनका महत्व मुख्य रूप से तृतीय विश्व अध्ययन के अकादमिक दायरे तक ही सीमित रहा। फिर, एक दिन, उनकी वैधता अकादमिक दायरे से बाहर फैल गई। इसी समय आनंद महिंद्रा ने होमी के. भाभा को एक छोटे से अकादमिक दायरे से बाहर निकालकर भारत पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणीकार के रूप में स्थापित किया, जिन्होंने नीति निर्माताओं और आम जनता को प्रभावित किया।

हिंदूफोबिया

भाभा भारत में हिंदू धर्म और राष्ट्रवाद के घोर आलोचक रहे हैं। उनका कहना है: ‘इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदुत्व जैसे कुछ सांस्कृतिक, धार्मिक और नैतिक विचारों को लोगों के सामने एक राष्ट्रीय समुदाय के निर्माण के मंच के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।’

उनका मानना है कि जहां भाजपा विदेशों में एक बेहद वैश्विक छवि पेश करती है, वहीं भारत में यह संकीर्ण सोच वाली है और देश के भीतर कुछ परंपराओं, संस्कृतियों और समुदायों को कमजोर करने में लगी हुई है। देश और विदेश में अपनाए गए इस वैचारिक विरोधाभास से वे लगातार परेशान रहते हैं।

भाभा ने डोनाल्ड ट्रम्प के नारे 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' (MAGA) से इसकी तुलना की है। उनका दावा है कि भारत में भी इसी तरह का लोकलुभावन राष्ट्रवाद जीवित है, और 'खतरनाक बात यह है कि जो लोग इससे सहमत नहीं हैं, उन्हें निष्पक्ष और स्वतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर नहीं दिया जाता। उन्हें रूढ़िबद्ध करके बलि का बकरा बनाया जाता है।' इस तरह के दमन का विरोध करने के लिए, भाभा चाहते हैं कि भारतीय विदेशी संगठनों के साथ एकजुटता दिखाएं।

उन्होंने उन भारतीय लेखकों का समर्थन किया जिन्होंने कथित अधिकारों और स्वतंत्रता के दमन के खिलाफ विरोध के वैध तरीके के रूप में सरकार को अपने साहित्य अकादमी पुरस्कार (साहित्यिक विद्वता के लिए) लौटा दिए।

जब नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया, तो भाभा ने कुलपति को पत्र लिखकर इसकी आलोचना करते हुए इसे 'असहमति का अपराधीकरण' बताया। विडंबना यह है कि उन्होंने 'विभिन्न विचारों के साथ जुड़ने' का आह्वान किया, जबकि उनके प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय ने अपने गुट से असहमत लोगों को बार-बार इस बात से वंचित रखा है।

भाभा ने अक्सर यह धारणा फैलाई है कि भारत 'हिंदू राष्ट्रवाद' और 'बहुसंख्यक सत्तावाद' की ओर बढ़ रहा है और अल्पसंख्यकों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। एक साक्षात्कार में उनका निम्नलिखित बयान इसी दृष्टिकोण का एक उदाहरण है:

आज भारत में लोकतांत्रिक संवाद की बजाय राजनीतिक उपदेशात्मकता को बढ़ावा देने का चलन है। देशभक्ति या लोकलुभावनवाद के नाम पर भारत की मिश्रित और समन्वित संस्कृति के एक तत्व - उदाहरण के लिए हिंदुत्व - का सहारा लेना, संस्कृतियों, विश्वासों और समुदायों के बीच उस सूक्ष्म संतुलन को बिगाड़ता है जो भारत की उस अद्भुतता का प्रतीक है जो कभी भारत था और जो एक बार फिर भारत की अद्भुतता बन सकता है। हमारा संविधान समानता का एक उत्कृष्ट साधन है जिसमें व्यापक राष्ट्रीय हित के हिस्से के रूप में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए नियंत्रण और संतुलन मौजूद हैं। जब राज्य बहुसंख्यकवादी धमकी और बहिष्कार के हथकंडे अपनाता है और अंधाधुंध रूप से "भीतरी शत्रु" - दलितों,

ईसाइयों, मुसलमानों, एलजीबीटी समुदाय, गैर सरकारी संगठनों आदि - के खिलाफ कार्रवाई करता है, तो लोकतांत्रिक भागीदारी सत्तावादी भय से ढक जाती है।

वह गलत धारणा रखते हैं कि हिंदू सभ्यता उन चीजों को वैधता प्रदान करती है जिन्हें वे 'जातीय शुद्धता की काल्पनिक वापसी; एक बंद सांस्कृतिक समरूपता; एक गहन रूप से विनियमित कामुकता; क्षेत्रीय संप्रभुता की एक चारदीवारी वाली असुरक्षा' कहते हैं। भाभा का राष्ट्र का आदर्श निम्नवर्गीय विखंडन पर आधारित है जहाँ सभी मूल्य अनिश्चित हैं। वे लगातार हिंदुत्ववादियों पर किसी प्राचीन समरूप भारत में लौटने की इच्छा रखने का आरोप लगाते हैं।

उनकी और अन्य उत्तरआधुनिकतावादियों की समस्या यह है कि वे यह गलत धारणा रखते हैं कि हिंदू धर्म एकरूपता चाहता है। जैसा कि 'बीइंग डिफरेंट' और 'इंद्राज़ नेट' नामक दो पुस्तकों में विस्तार से बताया गया है, वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। हिंदू धर्म एक खुला ढांचा है और यह विचारों, पूजा विधियों, देवी-देवताओं, वंशों, आध्यात्मिक ढांचों आदि की विविधता का समर्थन करता है। हिंदू धर्म भिन्नता के प्रति पारस्परिक सम्मान के माध्यम से विविधता को बढ़ावा देता है।

महिंद्रा सेंटर द्वारा प्रचारित वैचारिक झुकाव के एक उदाहरण के रूप में, आइए हम उस कार्यक्रम पर गौर करें जिसे सेंटर ने हार्वर्ड के रेडक्लिफ इंस्टीट्यूट की दुर्बा मित्रा द्वारा लिखित 'इंडियन सेक्स लाइफ' नामक एक रोचक पुस्तक के विमोचन के लिए प्रायोजित किया था। यह पुस्तक भारत में कामुकता के अध्ययन के लिए जाति के उपयोग पर केंद्रित है, जिसमें वेश्यावृत्ति पर विशेष जोर दिया गया है। यह लेखिका की मौलिक अंतर्दृष्टि और औपनिवेशिक काल के साहित्य की समीक्षा पर आधारित एक रोचक कृति है। हालांकि, इसमें पूर्वाग्रह झलकता है, क्योंकि लेखिका पूरी तरह

से पश्चिमी और पश्चिमी लोगों द्वारा प्रशिक्षित भारतीयों के द्वितीयक स्रोतों पर निर्भर हैं जो हिंदू जाति को रूढ़िवादी रूप में प्रस्तुत करते हैं। वह विलियम जोन्स, लेवी स्ट्रॉस, डेविड एमिल दुर्खीम और अन्य के जातिगत विचारों का हवाला देती हैं, और हिंदू परंपरा के भीतर के स्रोतों का संदर्भ नहीं देती हैं। उदाहरण के लिए, धर्मशास्त्र और इतिहास में वेश्याओं के कई संदर्भ हैं जो अधिकतर पूर्वाग्रह रहित हैं, और उनके जीवन की व्याख्या करने के लिए पश्चिमी कृतियों के बजाय इनका उपयोग किया जा सकता है।

एक अन्य पद्धतिगत समस्या यह है कि यद्यपि मित्रा यह स्वीकार करती हैं कि उर्दू और फ़ारसी लेखों में भी इसी प्रकार की घटनाओं का वर्णन मिलता है, फिर भी वे उनकी गहराई से पड़ताल नहीं करतीं। केवल 'हिंदू जाति' का अध्ययन किया गया है, और केवल उच्च जाति के हिंदू पुरुषों को ही समस्या के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऐसे विद्वान से अपेक्षित ही है कि उनकी व्याख्याओं में 'अभिजात्यवादी', 'राष्ट्रवादी', 'स्त्री-द्वेषी', 'पितृसत्तात्मक', 'बहुसंख्यकवादी' आदि जैसे शब्दों का भरपूर प्रयोग किया गया है।

मित्रा एक सदी पहले के दो लेखों की तुलना करती हैं: एक मुस्लिम महिला द्वारा लिखित और एक हिंदू पुरुष द्वारा लिखित। मुस्लिम महिला के वृत्तांत में एक ऐसे सपने का वर्णन है जिसमें भविष्य में भारतीय महिलाएं सार्वजनिक जीवन में प्रभुत्व जमाती हैं, प्रौद्योगिकी में नवाचार करती हैं और शासन-प्रशासन संभालती हैं, जबकि पुरुष घर में एकांत में रहते हैं। वह इसकी तुलना एक उच्च जाति के हिंदू पुरुष द्वारा लिखित दूसरे वृत्तांत से करती हैं, जिसमें वह 'एक उपदेशात्मक वैज्ञानिक ग्रंथ में महिलाओं की बेलगाम कामुकता के परिणामस्वरूप उच्च जाति के हिंदू समाज के पतन' का वर्णन करती हैं। हिंदू पुरुष को पितृसत्ता के उस

रूढ़िवादी प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है जो मुखर महिलाओं से छुटकारा पाना चाहता है। वह ऐसे मीम्स फैलाना चाहती हैं जिनमें मुस्लिम पुरुष को आदर्श दिखाया जाए जबकि हिंदू पुरुष को 'उच्च जाति के हिंदू अभिजात वर्ग' के रूप में वर्णित किया जाए, जो 'हिंदू एकविवाह' के माध्यम से 'बहुसंख्यक पितृसत्तात्मक नियंत्रण' रखता है। इस तरह की पहचान की राजनीति ने उन्हें हार्वर्ड में लोकप्रिय बना दिया है।

मित्रा ने ट्विटर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ट्विटर पर 'हिंदू दक्षिणपंथी पुरुषों की एक बहुत ही अच्छी महिला-विरोधी सेना' मौजूद है, जो 'एक ऐसी रणनीति का हिस्सा है जो शुरुआत से ही हिंदू राष्ट्रवाद का हिस्सा रही है'।

पैनलिस्टों की टिप्पणियों में दृष्टिकोणों की कोई विविधता नहीं दिखती। वे इस पुस्तक को आलोचनात्मक सामाजिक सिद्धांत, बौद्धिक इतिहास और ज्ञान के समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में समर्थन देते हैं। एक अन्य उदाहरण महिंद्रा ह्यूमैनिटीज सेंटर द्वारा महिंद्रा सेंटर के पर्यावरण फोरम के तहत प्रसेनजीत दुआरा को दिया गया समर्थन है। दुआरा चीन के एक जाने-माने विद्वान और चीनी अध्ययन संस्थान के सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं। लॉ सोसाइटी फाउंडेशन की एक हालिया रिपोर्ट में इस संस्थान को

लुटियंस थिंक टैंक, जो चीनी अध्ययन के लिए समर्पित है और खुद को एक 'तटस्थ' शोध संगठन के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, वास्तव में भारत में चीन समर्थक भावनाएं भड़काने का आक्रामक प्रयास कर रहा है। खबरों के अनुसार, संदिग्ध अध्ययनों और विश्लेषणों के माध्यम से यह कम्युनिस्ट चीन को सकारात्मक रूप में चित्रित करने का प्रयास करता है और इसने बीजिंग के विस्तारवादी एजेंडे या मानवाधिकारों के हनन पर कभी चिंता नहीं जताई है - यहां तक कि भारतीय क्षेत्र में

उसके अतिक्रमणों पर भी नहीं! इस संगठन की स्थापना भारतीय शिक्षा जगत के एक प्रमुख चीन समर्थक व्यक्ति ने की है। इसके अलावा, कुछ प्रमुख पूर्व राजनयिक भी इस संगठन से जुड़े हुए हैं। यह थिंक टैंक हार्वर्ड-येनचिंग इंस्टीट्यूट के साथ साझेदारी के माध्यम से भारतीय छात्रों को चीन में पोस्ट-डॉक्टरेट अध्ययन के लिए 'सिफारिश' भी करता है।
दुआरा ने चीन के पर्यावरणवाद के बारे में बहुत अच्छी बातें कही हैं, और अपनी पुस्तक, द क्राइसिस ऑफ ग्लोबल मॉडर्निटी में, वे कहते हैं: 'सभी विकासशील देशों में, पर्यावरण शिक्षा में चीनी सरकार के प्रयास शायद सबसे महान हैं।'
महिंद्रा ह्यूमैनिटीज सेंटर में अपने प्रवचन में, दुआरा ने पारिस्थितिकी के आधार के रूप में आध्यात्मिकता पर चर्चा की। उन्होंने पारिस्थितिकी में हिंदू धर्म के योगदान को कमतर आंकते हुए ईसाई धर्म को बहुत श्रेय दिया। उन्होंने पारिस्थितिकी के लिए आध्यात्मिकता का उपयोग करने के लिए अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड की प्रशंसा भी की, यह ध्यान में नहीं रखा कि यह एक बौद्ध विचार था जिसे व्हाइटहेड ने आत्मसात किया था। उन्होंने हेनरी थोरो के प्रकृति से प्रेरित होने का भी उल्लेख किया, फिर से यह स्वीकार नहीं किया कि थोरो स्वयं वैदिक विचारों से गहराई से प्रभावित थे। पर्यावरणवाद में अन्य सभी प्रमुख धर्मों के योगदान की प्रशंसा करते हुए, उन्होंने हिंदू धर्म का सबसे कम उल्लेख किया और यह कहने में जल्दबाजी की कि हिंदुत्व के कारण इसकी उपेक्षा की गई है।
न्यूयॉर्क टाइम्स के एक साक्षात्कार में, उन्होंने चीन के पर्यावरणवाद की प्रशंसा की; लेकिन जब उनसे भारत के बारे में टिप्पणी करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ एक पदानुक्रमित समाज है, और यद्यपि पहले पर्यावरण की मदद के लिए आंदोलन हुए थे, अब यहाँ रूसियों और चीनियों की तरह एक शक्तिशाली नेता है।

निष्कर्षतः, हार्वर्ड स्थित महिंद्रा ह्यूमैनिटीज सेंटर के हमारे विश्लेषण में इसके प्रमुख होमी के. भाभा द्वारा प्रस्तुत उत्तरआधुनिकतावाद के दृष्टिकोण और कुछ विद्वानों द्वारा किए गए शोध कार्यों के नमूने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जहाँ तक आनंद महिंद्रा का संबंध है, यद्यपि इन सभी शोध कार्यों का संबंध उनके नाम से है, हम यह स्वीकार करते हैं कि उनके अपने विचार इसमें पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं होते हैं।

12. लक्ष्मी मित्तल और सामाजिक न्याय

अवलोकन

जैसा कि पिछले अध्याय में देखा गया है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय का भारत के प्रति रवैया अक्सर शत्रुतापूर्ण रहा है। इसके द्वारा किए गए अध्ययन भारत को कमजोर करते हैं। यह अध्याय दर्शाता है कि हार्वर्ड, लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान का उपयोग भारत की सभ्यतागत वैधता की आलोचना करने के लिए कैसे करता है। और जैसा कि अपेक्षित है, इसका नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसका भारत के प्रति दृष्टिकोण विरोधाभासी है।

यह संस्थान भारत के अल्पसंख्यकों में असाधारण रूप से रुचि रखता है, चाहे उन्हें धर्म, सामाजिक व्यवस्था, लिंग या किसी अन्य मानदंड के आधार पर परिभाषित किया जाए, और लगातार खुद को इन समूहों के रक्षक के रूप में प्रस्तुत करता है, जो अपनी ही सरकार और साथी नागरिकों के खिलाफ लड़ रहे हैं।

भारत की अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमा बहुत लंबी है और इसकी रक्षा करते

हुए भारत को कई तरह के तनावों का सामना करना पड़ा है, चाहे वह अवैध कब्जा हो, विद्रोह हो या दोनों। मित्तल संस्थान हर जगह मौजूद है और इन समूहों का समर्थन कर रहा है, चाहे वह पश्चिम का भील क्षेत्र हो या पूर्वोत्तर का नागा और मणिपुरी इलाका। यह कश्मीर पर कट्टरपंथी मुस्लिम विचारधारा का भी बचाव कर रहा है। इसका एक उद्देश्य भारत के इतिहास को एक विशेष पूर्वाग्रह के साथ फिर से लिखना भी है, खासकर कुछ खास कालखंडों या घटनाओं (जैसे विभाजन) के संदर्भ में; और इस कहानी के स्रोतों पर अपना अधिकार जताना भी है। हार्वर्ड का नाम ही इसे वर्तमान समय की एकमात्र प्रामाणिक कहानी के रूप में स्थापित करने के लिए काफी है।

इसके विद्वान भारत के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने का लगातार अवसर तलाशते रहते हैं। यहाँ भी विपक्षी दलों को समर्थन देने का प्रयास दिखाई देता है। ये दृष्टिकोण निश्चित रूप से निष्पक्षता की कमी के कारण विद्वतापूर्ण नहीं हैं और इनका उद्देश्य हस्तक्षेपकारी है।

अपनी सभी योजनाओं को सफल बनाने के लिए, हार्वर्ड भारतीय सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है और समय-समय पर सरकारी अधिकारियों और महत्वपूर्ण पदों पर आसीन लोगों की मेजबानी करता है। दरअसल, भारतीयों द्वारा किए गए इस सारे पृष्ठभूमि कार्य और वित्त पोषण के साथ, हार्वर्ड का मानना है कि उसके पास भारत में अधिक प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के लिए एक 'दूतावास' स्थापित करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं।

हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने भारत में अपना 'दूतावास' स्थापित किया।

जब इस्पात उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल ने 2017 में अपना ऐतिहासिक दान

दिया, तो इससे हार्वर्ड में स्थित दक्षिण एशिया संस्थान को नई जान मिली, जो पहले अपनी चरमराहट के दौर से गुजर रहा था। हार्वर्ड स्थित मित्तल संस्थान अब शोध और विद्वानों के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त धन जुटा रहा है और तेजी से विकास कर रहा है। यह संस्थान एक प्रमुख निवेशक भी है जिसने अन्य भारतीय अरबपतियों को हार्वर्ड में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह संस्थान गर्व से कहता है:
लक्ष्मी मित्तल दक्षिण एशिया संस्थान, हार्वर्ड के अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ-साथ इन देशों के प्रवासी समुदायों के साथ जुड़ाव का केंद्र है। वर्तमान में, यह हार्वर्ड और समकक्ष संस्थानों के विभिन्न विषयों के 250 से अधिक संकाय सदस्यों को रोजगार प्रदान करता है; 50 से अधिक छात्रों को अनुसंधान, इंटर्नशिप और गहन भाषा अध्ययन में भाग लेने के लिए वार्षिक रूप से वित्त पोषण प्रदान करता है; पोस्टडॉक्टोरल फेलोशिप का समर्थन करता है; हार्वर्ड में अतिथि कलाकारों की मेजबानी करता है; क्षेत्र और परिसर में व्याख्यान, सम्मेलन और नेतृत्व प्रशिक्षण प्रायोजित करता है; और क्षेत्र में सरकार, शैक्षणिक और नागरिक समाज संगठनों के साथ काम करता है, विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान में अपने स्थानीय कार्यालयों के माध्यम से।
“हम मित्तल परिवार के समर्थन के लिए अत्यंत आभारी हैं, जिससे हमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी के क्षेत्र में सीखने और साझा करने का अवसर मिलेगा, साथ ही उन अनेक लोगों और संस्थानों से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा,” (तरुण) खन्ना ने कहा। “इन संसाधनों से उत्पन्न होने वाले कार्यों से आने वाली पीढ़ियाँ लाभान्वित होंगी।”
स्पष्टतः, मित्तल ने अन्य अरबपतियों की तरह इस दान के पीछे नेक इरादे रखे थे। एक समाचार पत्र की रिपोर्ट में कहा गया है:

विश्व की सबसे बड़ी इस्पात कंपनी आर्सेलरमित्तल के अध्यक्ष और सीईओ, 67 वर्षीय मित्तल ने कहा, “प्रारंभिक सभ्यताओं से ही दक्षिण एशिया ने हमारे विश्व के विकास में एक गतिशील और प्रभावशाली भूमिका निभाई है। इसके बाद उन्होंने कहा, “इसके इतिहास और अनूठी गतिशीलता को पूरी तरह से समझना एक सफल भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।”

लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि संस्थान इस प्रशंसनीय दृष्टिकोण को किस प्रकार आगे बढ़ा रहा है। हम पिछले कुछ वर्षों में इस संस्थान द्वारा अपनाए गए कुछ विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक रुख का विश्लेषण करेंगे ताकि यह पता चल सके कि यह भारत को किस प्रकार शर्मिंदा करता है। हम जाति, योग्यता और भारत के आंतरिक मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप से संबंधित इसके कार्यों से कुछ उदाहरण लेंगे।

वर्ष 2018 में, हार्वर्ड ने घोषणा की कि यह संस्थान भारत में उसका 'दूतावास' है, और इसे दक्षिण एशियाई क्षेत्र के साथ हार्वर्ड की प्रत्यक्ष भागीदारी के एक नए युग के रूप में सराहा।

अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप-प्रोवोस्ट और चीनी एवं आंतरिक एशियाई इतिहास के मार्क श्वार्ट्ज प्रोफेसर मार्क इलियट ने कहा, "हार्वर्ड आज जो कुछ भी है, वह तब नहीं होता जब वह दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने में सक्षम होता। हम संस्थान में एक छोटा दूतावास स्थापित करने का इरादा रखते हैं, जो छात्रों और शोधकर्ताओं को हार्वर्ड में अध्ययन करने में मदद करेगा।"

जिस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, वह यह है कि पश्चिमी उदार कलाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में भारत की अपनी समृद्ध विरासत है। लेकिन चीन के विपरीत, जिसने सैकड़ों कन्फ्यूशियस संस्थानों के माध्यम से अपनी उदार कलाओं का निर्यात किया है और इन

विचारों को घरेलू स्तर पर शिक्षा के सभी स्तरों में शामिल किया है, भारत में ऐसी कोई पहल नहीं है। इसके बजाय, इसके अरबपति पश्चिमी उदार कलाओं के आयात में मदद कर रहे हैं जो भारत की अपनी परंपराओं को नीचा दिखाती हैं।

राजनीतिक हस्तक्षेप

1800 के दशक में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की तरह, हार्वर्ड भी मानवता को बचाने के उद्देश्य से वैश्विक उत्तर और दक्षिण के बीच एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। अपनी प्रतिष्ठा और प्रभाव स्थापित होने के बाद, मित्तल संस्थान ने भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए और अधिक आत्मविश्वास से अपनी ताकत का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया।

इसका एक अच्छा उदाहरण हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के कैर सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स पॉलिसी के वरिष्ठ फेलो सलिल शेट्टी का काम है, जिनकी मित्तल इंस्टीट्यूट नियमित रूप से प्रशंसा करता है। उन्हें 'गरीबी और न्याय के मुद्दों पर एक दीर्घकालिक कार्यकर्ता' के रूप में वर्णित किया गया है और वे एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं।

इंस्टीट्यूट का कहना है कि वे 'भारत में शासन में जवाबदेही और समानता' पर विभिन्न क्षेत्रों में शोध करते हैं। वे भारत में अधिक समावेशी और जवाबदेह शासन के लिए रणनीतियों को समझने का प्रयास करते हैं।

शेट्टी एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता से विद्वान बने व्यक्ति हैं, जिन्हें मित्तल संस्थान द्वारा नियमित रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। उनके एक व्याख्यान का विषय था "कश्मीर: संकट का विश्लेषण", जिसमें जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा:

तथाकथित आतंकवाद विरोधी युद्ध शुरू होने के बाद से, हमने मानवाधिकारों, विशेष रूप से न्याय और लोकतंत्र के क्षेत्र में भारी गिरावट देखी है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के बल पर मुसलमानों, शरणार्थियों, स्वदेशी लोगों, अश्वेतों, महिलाओं आदि के खिलाफ 'अन्यीकरण' की तकनीकों का इस्तेमाल करने वाले निर्वाचित लोकलुभावन अधिनायकवाद के उदय ने एक नई वास्तविकता को जन्म दिया है। मीडिया और इंटरनेट को बंद करना, कर्फ्यू और सभाओं पर प्रतिबंध लगाना, सरकारों द्वारा अभिव्यक्ति और सभा की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मानक कार्यप्रणाली है। इससे कश्मीरी और भी अधिक क्रोधित होंगे, खासकर इसलिए कि हजारों नेताओं और कार्यकर्ताओं को गैरकानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया है और आवागमन की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का मतलब है कि वे अपने पड़ोस में आमने-सामने संवाद भी नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि भारत में वर्तमान सरकार ने मुख्य भूमि भारत में अपने हिंदू राष्ट्रवादी वर्चस्ववादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कश्मीर के लोगों की बलि देने का फैसला किया है।

उनका एजेंडा मित्तल इंस्टीट्यूट के निष्पक्ष और तटस्थ होने के दावे से मेल नहीं खाता। लेकिन वे स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि 'प्रगतिशील दुनिया' भारत में हस्तक्षेप करे। उनका कहना है कि यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि 'प्रगतिशील दृष्टिकोण रखने वाले आम लोग चुप रहेंगे। उम्मीद यहीं टिकी है।'

एक अन्य उदाहरण के रूप में, 2020-21 में जब दिल्ली के किसानों ने भारतीय संसद द्वारा पारित कृषि विधेयकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, तो हार्वर्ड के छात्रों ने मित्तल संस्थान से मानवाधिकार उल्लंघन के आधार पर इन विधेयकों के संबंध में प्रधानमंत्री मोदी की कार्रवाई की निंदा करने की मांग की। हार्वर्ड की कैंपस पत्रिका, द क्रिमसन ने रिपोर्ट

किया:
अंडरग्रेजुएट काउंसिल ने रविवार को एक विधेयक पारित किया जिसमें हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रशासकों और विश्वविद्यालय के लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासन के तहत भारत में प्रदर्शनकारियों की 'गिरफ्तारी और दमन' की निंदा करने का आह्वान किया गया है... सरकार ने इंटरनेट सेंसरशिप और गिरफ्तारियों के माध्यम से विरोध प्रदर्शनों को कुचल दिया है। याचिका में मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों की निंदा की गई है, जिसमें 'गंभीर, अमानवीय और असंवैधानिक' मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।
मोदी सरकार की आलोचना करते हुए एक और राजनीतिक चर्चा का आयोजन मित्तल इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया, जिसमें प्रोफेसरों के एक समूह ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का शीर्षक था, "तानाशाहों के लिए मतदान: ब्राजील और भारत में राष्ट्रवादी और लोकलुभावन नेतृत्व"। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो की तुलना की गई, जिन्हें 'तानाशाही राजनीति के पुनरुत्थान' के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो 'लोकतांत्रिक मानदंडों को दरकिनार करते हुए लोकलुभावन आदर्शों को अपना रही है'। पैनलिस्टों ने राष्ट्रवादी और लोकलुभावन नेतृत्व और वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था पर इसके व्यापक प्रभावों पर चर्चा की।
दक्षिण एशिया की राजनीति पर विभिन्न संयुक्त सेमिनारों का समन्वय मित्तल संस्थान द्वारा किया गया, जिसमें हार्वर्ड, एमआईटी, ब्राउन विश्वविद्यालय के वाटसन संस्थान और वेदरहेड सेंटर फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स ने भाग लिया। इनमें से एक सेमिनार दक्षिण एशिया में 'सशस्त्र राजनीति' पर था।

मित्तल विद्वानों का एक पसंदीदा विषय भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का अध्ययन रहा है, जिसमें विशेष रूप से विद्रोहों और अलगाववादी आंदोलनों को बढ़ावा देने और उनका समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उदाहरण के लिए, समाजशास्त्र के एक प्रोफेसर को भारत के भील बहुल क्षेत्र में विद्रोही नागरिकता की जड़ों की खोज विषय पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। शोध में उन हाशिए के समूहों पर ध्यान केंद्रित किया गया था जिन्हें 'पुनर्वितरण और मान्यता के लिए दावे करने हेतु नागरिकता की सार्वभौमिक शब्दावली का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन वे ऐसा किस आधार पर करते हैं - विशेष रूप से गंभीर दबाव में?' व्याख्यान का विज्ञापन 'पश्चिमी भारत के भील बहुल क्षेत्र में आंदोलन के स्वरूपों की पड़ताल' के रूप में किया गया था, जहाँ आदिवासी समुदायों ने स्थानीय राज्य के अत्याचार के खिलाफ संगठित और लामबंद होकर विरोध प्रदर्शन किया है। यह एक संवेदनशील क्षेत्र है जो विद्रोहों से बुरी तरह प्रभावित है, ठीक उसी तरह का क्षेत्र जहाँ हार्वर्ड को अध्ययन करना पसंद है।

इसके अलावा, पूर्वोत्तर भारत के संवेदनशील क्षेत्र मणिपुर में हाई स्कूल के छात्रों को 'आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान' सिखाने के बहाने, हार्वर्ड से भेजे गए शिक्षकों ने गर्व से घोषणा की कि उनका मकसद भ्रष्टाचार उजागर करना था। पहले ही दिन से, उन्होंने मणिपुर में सामाजिक समस्याओं की एक सूची पर विचार-विमर्श किया। उनके पास महिलाओं के खिलाफ अपराधों से लेकर राज्य में बार-बार होने वाली हड़तालों तक, कई विचार थे।

मित्तल संस्थान द्वारा स्थापित एक अन्य अंतरविषयक परियोजना भारत में नागरिकता के विवादास्पद कानूनी और संवैधानिक मुद्दों का अध्ययन कर रही है। इसमें विभाजन से लेकर विभिन्न प्रति-आंदोलनों तक की अवधि

शामिल होगी। इसका उद्देश्य एक ऐसा ढांचा विकसित करना है जिसमें नागरिकता संबंधी हालिया कानूनों पर चर्चा की जा सके और समस्याओं को उजागर किया जा सके।

मित्तल के विद्वान भारत में राजनीतिक और सामाजिक कार्यप्रणाली से संबंधित विभिन्न मुद्दों का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि भविष्य में उनमें हस्तक्षेप किया जा सके। उदाहरण के लिए, भारत के वन अधिकार अधिनियम 2006 पर मित्तल के एक फेलो द्वारा लिखे गए शोध पत्र में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में निचली जाति के भूमिहीन सदस्यों को उच्च जाति के पुरुषों द्वारा किस प्रकार प्रताड़ित किया जाता था।

यह संस्थान भारत में सामाजिक समस्याओं पर सबसे बड़े डेटाबेस के स्वामी के रूप में हार्वर्ड के प्रभुत्व स्थापित करने के प्रयासों में भी सहयोग कर रहा है। उदाहरण के लिए, मित्तल संस्थान में रघुनाथन परिवार फैलोशिप 'शहरी और आवासीय अलगाव' और 'क्या शहरीकरण जाति और धार्मिक बाधाओं को तोड़ने का समाधान है या नहीं' विषय पर शोध के लिए प्रदान की गई थी। रघुनाथन परिवार सेमिनार में 'आवासीय जाति-विभाजन शहर के आकार से स्वतंत्र कैसे है' विषय पर प्रस्तुति दी गई। इसमें गर्वपूर्वक बताया गया कि पहली बार भारत के 147 सबसे बड़े शहरों से सूक्ष्म विवरणों का एक विशाल डेटाबेस इस्तेमाल किया गया है। इस कार्य को अमेरिका और भारत दोनों में आयोजित वार्ताओं के दौरान प्रदर्शित किया गया।

भारतीय शहरीकरण की प्रमुख पहेलियों में से एक है - पूरे देश में और विभिन्न आकारों के शहरों में जातिगत भेदभाव का निरंतर बने रहना। यह निष्कर्ष भारत के शहरीकरण के एक प्रमुख आदर्श वादे में से एक को उजागर करता है: पारंपरिक जाति-आधारित भेदभाव का धीरे-धीरे समाप्त

होना। यह व्याख्यान शहरी भारत में सबसे अधिक भौगोलिक रूप से हाशिए पर स्थित समूहों - मुसलमानों और दलितों - के अलगाव पर और अधिक विस्तृत प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

इसी प्रकार, पश्चिम बंगाल के एक निम्न जाति समुदाय, पटुआ समुदाय, जिन्होंने तेरहवीं शताब्दी में हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म अपना लिया था, की सामाजिक दुर्दशा पर 'न हिंदू, न मुसलमान: एक बंगाली कारीगर जाति की दुविधा' शीर्षक से एक संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी का दावा था कि निम्न जाति और मुसलमान होने के कारण उन्हें भारतीय समाज द्वारा दोहरे हाशिए पर धकेले जाने की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।

एक अन्य उदाहरण दर्शनशास्त्र में पीएचडी कर रहे एक छात्र को 'दलित मध्यम वर्ग: जाति, वर्ग और बाजार-केंद्रित विमर्श किस प्रकार परस्पर क्रिया करके इसे आकार देते हैं' विषय पर शोध करने के लिए दी गई अनुदान राशि है।

तरुण खन्ना ने एक साक्षात्कार में कहा कि भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 'कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) में अधिक उत्पादक रूप से संलग्न होना चाहिए'। यह एक सरल कथन नहीं है, क्योंकि सीएसआर और ईएसजी का उपयोग कभी-कभी विशिष्ट सामाजिक-राजनीतिक एजेंडों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, खासकर जब इसे पहचान की राजनीति के साथ जोड़ा जाता है।

अमेरिका-भारत संबंधों की व्यापक श्रेणी में अन्य मित्तल शोधकर्ताओं ने भारतीय प्रवासी राजनीति, भ्रष्टाचार और भारत में शासन जैसे मुद्दों को चुना है।

निम्नलिखित समर्थित परियोजनाओं के उदाहरण मित्तल संस्थान की सामाजिक न्याय और राजनीतिक हस्तक्षेपों में रुचि को दर्शाते हैं। इनमें व्यक्तिगत शोध परियोजनाएं और पैनल चर्चाएं शामिल हैं। समर्थित

विद्वानों में से कुछ सुप्रसिद्ध नाम हैं जिनकी सशक्त राजनीतिक विचारधाराएं हैं। निम्नलिखित परियोजनाओं के शीर्षक मित्तल संस्थान द्वारा किए गए व्यापक कार्य का एक नमूना हैं:

रोहिंग्याओं की आवाज़ें

स्वतंत्रता के सपने: पूर्वोत्तर भारत के मिज़ो लोगों के बीच स्थानीय राष्ट्रवाद

आधुनिक भारत में धार्मिक राष्ट्रवाद, जातीय संघर्ष और राज्य आतंक: कश्मीर, पंजाब, गुजरात और नागालैंड के मामले

पूर्वी भारत में नक्सलवादी-माओवादी संघर्ष

नवउदारवाद और धार्मिक कट्टरपंथी आंदोलनों के उदय के बीच संबंध

विचार-विमर्श संबंधी असमानता: तमिलनाडु की ग्राम सभाओं का पाठ-आधारित डेटा अध्ययन

दक्षिण एशिया में लोकतंत्र संकट में है।

श्रीलंका में युद्धोत्तर धार्मिक हिंसा में प्रचार के साधन के रूप में सोशल मीडिया की भूमिका

भारत में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का विश्लेषण

संकट और विश्वसनीयता: भारत और विकासशील लोकतंत्रों में विचारों की राजनीति

बहुमत का निर्माण: भारतीय चुनावों में मतदान पैटर्न का सूक्ष्म-स्तरीय अध्ययन

भावी राज्य: राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद, विऔपनिवेशीकरण

अमेरिका-भारत संबंध, प्रवासी राजनीति, भ्रष्टाचार-विरोधी उपाय और वैश्विक शासन

अमेरिका में जाति का प्रभाव

पश्चिमी हस्तक्षेप का एक सर्वकालिक पसंदीदा विषय सामाजिक मुद्दों की व्यापक श्रृंखला रही है। और इस दायरे में, जाति से अधिक विस्फोटक और प्रभावशाली कोई मुद्दा नहीं है। निम्नलिखित उदाहरण केवल मित्तल संस्थान में प्रचारित विषयवस्तु को दर्शाते हैं।

अमेरिका में जाति व्यवस्था पर एक विशेष श्रृंखला का नेतृत्व टेलीविजन के खोजी पत्रकार ने किया, जिसमें मित्तल इंस्टीट्यूट के तरुण खन्ना, हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के सूरज येंगडे और अन्य शामिल थे। यह उन अनेक गतिविधियों में से एक थी जिनका उद्देश्य हार्वर्ड को इस सिद्धांत में शामिल करना था कि जातिगत दुर्व्यवहार अमेरिकी अश्वेत/श्वेत नस्लवाद के समान है और भारतीय प्रवासियों के माध्यम से अमेरिका में प्रवेश कर चुका है।

एंकर ने शुरुआत में ही इस बात की पुष्टि की कि श्रृंखला का उद्देश्य 'मानव वर्गीकरण की इस प्राचीन पदानुक्रम प्रणाली के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय प्रवासियों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव' का पता लगाना है, जिसमें जाति और नस्ल के बीच संबंध भी शामिल है। येंगडे ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकियों को जाति को समझना चाहिए क्योंकि यह अमेरिका में रहने वाले बड़े भारतीय समुदाय की विशेषता है।

मित्तल इंस्टीट्यूट ने इक्वालिटी लैब्स के साथ मिलकर कार्यक्रमों का सह-प्रायोजन किया है। पिछले अध्यायों में इक्वालिटी लैब्स पर चर्चा की गई थी – जो तथाकथित 'भारत के श्वेत' यानी उच्च जातियों के खिलाफ अश्वेत-दलित आंदोलन का प्रमुख समर्थक थिंकटैंक है। ऐसा ही एक कार्यक्रम 'टाउन हॉल में जाति' पर था, जिसका घोषित उद्देश्य 'अमेरिका के जातिवादी कार्यस्थलों और अमेरिका में जातिवाद को समाप्त करने की

लड़ाई में जाति को एक संरक्षित श्रेणी के रूप में शामिल करने के व्यापक आंदोलन' के खिलाफ गति पैदा करना था। इस कार्यक्रम का संचालन इक्वालिटी लैब्स की कार्यकारी निदेशक थेनमोझी सौंदराजन ने किया। वक्ताओं में अजंता सुब्रमणियन (हार्वर्ड से), जिन पर पहले एक पूरा अध्याय लिखा गया था, साथ ही अंबेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका और अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के प्रतिनिधि शामिल थे।

महिला सशक्तिकरण

महिलाओं और लैंगिक समानता के मुद्दे एक और शक्तिशाली क्षेत्र हैं जिनका उपयोग परंपराओं पर, सामान्य रूप से और विशेष रूप से भारत की परंपराओं पर सवाल उठाने के लिए किया जा रहा है। मित्तल संस्थान ने महिलाओं के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कई गतिविधियाँ की हैं, जैसे कि हार्वर्ड जेंडर वायलेंस प्रोजेक्ट।

हार्वर्ड जेंडर वायलेंस प्रोजेक्ट दक्षिण एशियाई महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाने का काम करता है, ताकि समाज हिंसा को अस्वीकार करे और सभी लोगों के प्रति सम्मान को बढ़ावा दे। हार्वर्ड जेंडर वायलेंस प्रोजेक्ट (एचजीवीपी) एसएआई, एचएलएस, एचबीएस और एफएक्सबी सेंटर फॉर हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स के बीच एक सहयोगात्मक परियोजना है, जिसमें लैंगिक हिंसा की रोकथाम और हस्तक्षेप कार्यक्रमों के क्षेत्र में काम करने वाले क्षेत्रीय विशेषज्ञ शामिल हैं।

हालांकि ये नेक उद्देश्य हैं, समस्या उस तरीके में है जिससे हार्वर्ड भारत की जनता और सरकार के बीच मध्यस्थ के रूप में भारत के शोषित/पीड़ितों, इस मामले में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। मित्तल संस्थान ऐसे मुद्दों पर हार्वर्ड के फ्रांकोइस-जेवियर बैगनोड सेंटर फॉर हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स के साथ भी सहयोग करता है। ऐसी ही एक परियोजना

में निरक्षर माता-पिता की बेटियों के लिए सफल शैक्षिक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत रूपरेखा तैयार करना शामिल था।
भारतीय महिलाओं के अधिकारों की प्रमुख पैरोकारों में से एक हार्वर्ड कैनेडी स्कूल की प्रोफेसर जैकलीन भाभा हैं, जो एक जानी-मानी कानूनी विशेषज्ञ और होमी के. भाभा की पत्नी भी हैं।
महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर आयोजित विभिन्न सम्मेलनों और कार्यशालाओं पर एक नज़र डालने से एक पैटर्न सामने आता है। उदाहरण के लिए, लैंगिक न्याय, आपराधिक कानून और पाठ्यक्रम सुधारों पर आयोजित सम्मेलन का उद्देश्य 'कानून प्रवर्तन, वकालत और पाठ्यक्रम सुधार से संबंधित वर्तमान मुद्दों का पता लगाना' था। इसके बाद 'लैंगिक हिंसा के निवारक उपायों' पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसके बाद 'समकालीन दक्षिण एशिया में लिंग, नागरिक समाज और राज्य: लिंग आधारित हिंसा के निवारक उपाय' शीर्षक से एक और कार्यशाला आयोजित की गई। इसका उद्देश्य भारत में यौन उत्पीड़न और लैंगिक हिंसा से संबंधित प्रासंगिक विधायी और नीतिगत बदलावों को तैयार करना था।
निम्नलिखित विषयों का नमूना अध्ययन किए जा रहे लैंगिक मुद्दों की व्यापक श्रेणी को दर्शाता है:
जैकलीन भाभा ने भारतीय नारीवादियों के साथ 'शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच के मामले में युवा महिलाओं को अभी भी जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, साथ ही सामाजिक अपेक्षाओं के साथ तालमेल बिठाने' पर एक चर्चा का नेतृत्व किया।
कराची स्थित कलाकार नुमैर अब्बासी के शोधपत्र में दक्षिण एशिया में उपनिवेशवाद के परिणामों के रूप में द्विआधारी लिंगों, यौनताओं और उनके सर्वव्यापी व्यवहार के निर्माण और प्रदर्शन की पड़ताल की गई है,

और यह भी कि क्या लिंगों और यौनताओं के स्पेक्ट्रम का अभ्यास, स्वीकृति और दृश्यता उपनिवेशवाद से पूर्व की है।
किशोरावस्था में कम उम्र में विवाह, पारिवारिक हिंसा और यौन उत्पीड़न के जोखिम पर शोध किया जा रहा है।
एक अन्य प्रोफेसर की पुस्तक भारतीय लैंगिक समानता सुधारों की पड़ताल करती है।
वस्त्र उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण पर लिंग और वैश्वीकरण के परस्पर संबंध और प्रभाव का अध्ययन किया गया।
एक सेमिनार में भारत में गरीबी और महिलाओं के अंतर्संबंधों की व्याख्या की गई, जिसमें भारतीय संस्कृति के कारण होने वाले भेदभाव पर विशेष ध्यान दिया गया।
एक वेबिनार में लिंग आधारित हिंसा पर चर्चा की गई और पुलिस प्रशिक्षण की कमी तथा निर्वाचित अधिकारियों की जवाबदेही की जांच की गई। इसमें घरेलू हिंसा को पहचानने के लिए बेहतर नीतियों का प्रस्ताव रखा गया। एक संबंधित वेबिनार में भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा की गई।
भारतीय महिलाओं को अपने आघातों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अनेक गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। लैंगिक चुनौतियों पर निबंधों के तीन खंडों के संग्रह पर एक पैनल चर्चा आयोजित की गई, जिसमें मानक आर्थिक विश्लेषणों और मान्यताओं का खंडन किया गया।
भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर एक फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद प्रश्नोत्तर सत्र हुआ। भारत से आमंत्रित एक महिला ने भारत में एक महिला कलाकार के रूप में अपने सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने एक मध्यमवर्गीय महिला और एक निम्नवर्गीय महिला की तुलना की, जो दोनों कामकाजी होने के साथ-साथ परिवार का पालन-

पोषण भी कर रही थीं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि दोनों ही बुनियादी स्वतंत्रताओं से वंचित हैं।

मित्तल संस्थान एक प्रकार की लेखापरीक्षा और समीक्षा एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है, जो भारत में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखता है, जिसका उद्देश्य राज्य दर राज्य और अंततः अखिल भारतीय स्तर पर समर्थन आधार तैयार करना है। इसकी एक टीम ने महिलाओं के सामाजिक और शैक्षिक सशक्तिकरण की जांच करने के लिए भारत का दौरा किया। इस टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट संस्थान में आगे की कार्यशालाओं का आधार बनी। ऐसी ही एक कार्यशाला में पचास गैर सरकारी संगठनों के पैंसठ नेता एक साथ आए और उसके बाद किए गए क्षेत्रीय दौरों ने जमीनी स्तर पर हार्वर्ड-समर्थक कार्यकर्ताओं का एक नेटवर्क बनाने में मदद की।

एक अन्य संगोष्ठी में सरकारी प्रतिनिधियों, शोधकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों और शिक्षाविदों को एक साथ लाया गया ताकि लैंगिक भेदभाव और हिंसा से निपटने के लिए 'लैंगिक रूढ़ियों और पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को पुनर्परिभाषित करने' के तरीके खोजे जा सकें। इसका उद्देश्य 'पितृसत्तात्मक और दमनकारी मानसिकता' को बदलना था क्योंकि मित्तल संस्थान का मानना था कि भारत में 'व्यापक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम' का अभाव है। हार्वर्ड ने अपने संदेशों के प्रसार के लिए पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएफआई) को एक माध्यम के रूप में शामिल किया।

हार्वर्ड द्वारा अमेरिकी स्कूलों में भारत के बारे में पढ़ाने के तरीकों पर वार्षिक सम्मेलन भी आयोजित किए जाते रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य भारत में लैंगिक हिंसा के बारे में पढ़ाना है। अमेरिकी स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यक्रम में मौजूद पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों को दूर करने

के लिए कई अभियान चलाए गए हैं। यह एक राजनीतिक मुद्दा है और इस संबंध में मुकदमे चल रहे हैं।

हमारा मानना है कि मित्तल संस्थान को अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए भारत के साथ होने वाले व्यवहार पर निष्पक्ष संवाद के लिए ऐसे आयोजनों में सभी पक्षों को आमंत्रित करना चाहिए। बेशक, विश्व स्तर पर महिलाओं के मुद्दों का समाधान करना महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत में बदलाव अमेरिकी स्कूली कक्षाओं में होने वाली चर्चाओं से नहीं होंगे। सवाल यह है कि क्या भारत की शिक्षा प्रणाली को अपनी महिलाओं की सुरक्षा के लिए विधायी और नीतिगत ढांचे प्राप्त करने हेतु हार्वर्ड पर निर्भर रहना चाहिए? क्या हार्वर्ड जैसे संस्थानों पर निर्भरता हार्वर्ड के प्रति दीर्घकालिक लत पैदा करती है, यानी क्या सरकार को किसी विदेशी संस्थान की श्रेष्ठ ब्रांड वैल्यू के कारण उससे निर्देश लेने का इंतजार करना चाहिए? इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत को नीतिगत बदलावों पर उपदेश देने से पहले, क्या हार्वर्ड ने अमेरिकी समाज में, या अपने स्वयं के परिसर में भी, महिलाओं की समस्याओं का समाधान किया है? हार्वर्ड क्रिमसन ने स्वीकार किया कि इस मोर्चे पर हार्वर्ड को अभी बहुत काम करना है और यहां तक कि 2022 में भी, उसके अपने छात्रों ने उस पर एक हार्वर्ड प्रोफेसर द्वारा यौन उत्पीड़न की अनदेखी करने का आरोप लगाया था।

गहरी खुदाई

भारत में सामाजिक न्याय लाने के लिए मित्तल संस्थान में स्थापित एक कार्यक्रम का उदाहरण न्यूयॉर्क के डॉ. मुकेश प्रसाद का विशेष उपहार है। यह विशेष रूप से मित्तल इनिशिएटिव की प्रसाद फैलोशिप के तहत छात्रों

को वित्त पोषित करता है। छात्रों को भारत में विभिन्न मुद्दों पर परियोजनाएं चलाने के लिए वित्त पोषित किया जाता है, जिनमें भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका से लेकर पर्यावरण शासन तक शामिल हैं। इसके अलावा, इसने छात्रों को भारत में स्वास्थ्य सेवा अधिकारों को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए भी भेजा है। छात्रों ने सुझाव दिया कि भारतीय लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए मीडिया को किस प्रकार कार्य करना चाहिए।

यह सोचना स्वाभाविक है कि भारतीयों को स्वास्थ्य सेवा के अधिकार दिलाने, लोकतंत्र में सुधार करने और पर्यावरणवाद को बढ़ावा देने के मामलों में सलाह देने के लिए हार्वर्ड भारतीय संस्थानों की तुलना में अधिक योग्य कैसे है।

प्रमुख विषय

सामाजिक उद्यमिता

मित्तल इंस्टीट्यूट के कार्यक्रमों में से एक युवा भारतीय उद्यमियों को मार्गदर्शन देना और उन्हें प्रेरित करना है। यहाँ पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम मानक है और भारत में आसानी से उपलब्ध है। हार्वर्ड अपने ब्रांड वैल्यू का उपयोग करके उच्च क्षमता वाले युवाओं को आकर्षित करता है और फिर उन्हें अपनी सोच के अनुरूप ढालता है। इसके बदले में, यह उन युवाओं का एक पूर्व छात्र नेटवर्क तैयार करता है जिन्हें भारत के भावी नेताओं के रूप में मार्गदर्शन दिया गया है और जो संस्थान के प्रति वफादार बने रहते हैं।

इसका उदाहरण देने के लिए, टाटा के साथ उनके सहयोग में अठारह महीने की एक शोध परियोजना शामिल थी, जिसका शीर्षक था

"सामाजिक उद्यमिता और कौशल विकास के माध्यम से भारत में आजीविका सृजन"। यह परियोजना तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित थी: ग्रामीण आजीविका सृजन; महिलाओं का शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण; और गरीबी उन्मूलन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप। इस परियोजना का दावा है कि इसने पंद्रह भारतीय राज्यों में सौ से अधिक सामाजिक उद्यमों को प्रभावित किया है। दूसरे चरण में, आठ सामाजिक परियोजनाओं को वित्त पोषित किया गया, जिनमें भारत में कम लागत वाले शौचालयों पर एक परियोजना भी शामिल थी। विकासशील देशों में उद्यमिता को बढ़ावा देने पर नई दिल्ली में एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें कई सरकारी मंत्रियों ने भाग लिया। तरुण खन्ना द्वारा एक विशाल ऑनलाइन ओपन कोर्स पढ़ाया गया, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, शहरीकरण और खाद्य सुरक्षा पर मॉड्यूल शामिल थे। किसी भी प्रमुख देश की अपनी शिक्षा प्रणाली द्वारा आंतरिक रूप से प्रदान की जाने वाली सामग्री की तुलना में, इनमें से कोई भी सामग्री विशेष रूप से उन्नत नहीं लगती है।

हार्वर्ड का एक और प्रत्यक्ष प्रभाव वह पाठ्यक्रम था जो 'विकासशील दुनिया के पांच अरब लोगों की प्रमुख आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के बारे में सोचने के लिए एक ढांचा और कई दृष्टिकोण' प्रदान करता था। गरीब देशों के भावी नेताओं को 'सोचने का तरीका' सिखाने का यह कार्य ही राष्ट्र निर्माण का सार है। क्या भारत ने अपने राष्ट्र निर्माण का कार्य हार्वर्ड को सौंप दिया है?

समस्या कई बार इस बात में नहीं होती कि क्या पढ़ाया जाता है, बल्कि इस बात में होती है कि क्या शामिल नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए, तरुण खन्ना ने एक चीनी सहकर्मी के साथ मिलकर भारत और चीन में योग्यता-आधारित व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए एक परियोजना का

सह-निर्देशन किया। यह इस बात पर चर्चा करने का एक उपयुक्त अवसर था कि चीनी लोग उनके हार्वर्ड सहयोगी अजंता सुब्रमण्यम द्वारा सुझाई गई दिशा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, जिनका कार्य क्रिटिकल रेस थ्योरी का उपयोग करके भारतीय योग्यता-आधारित व्यवस्था पर हमला करता है। मित्तल की परियोजना इस महत्वपूर्ण अंतर को उजागर करने में विफल रही: जहाँ चीन आंतरिक मानवाधिकारों के बारे में अंतरराष्ट्रीय आलोचनाओं के आगे न झुकते हुए, योग्यता को निरंतर बढ़ावा दे रहा है, वहीं विश्व मंच पर भारतीयों से योग्यता-आधारित व्यवस्था पर गर्व करने के बजाय उसके लिए माफी मांगने को कहा जा रहा है।

अर्थशास्त्र और विकास

मित्तल संस्थान द्वारा उठाए गए कई विषय वास्तव में भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं और यह पूरी तरह संभव है कि किया गया कार्य उच्च कोटि का हो। लेकिन सिद्धांत रूप में, भारतीय सरकार के लिए मूलभूत नीतिगत कार्यों को एक ऐसे विदेशी संस्थान को सौंपना समस्याग्रस्त है जो भारतीय जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है और जिसका पिछला रिकॉर्ड भारत के हितों के अनुरूप नहीं है। यहां दिए गए उदाहरणों को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

संस्थान ने एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें उसने अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले लोगों और भारतीय सरकार के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई।[54] इस तरह की भूमिका का एक ठोस उदाहरण बांग्लादेश के वस्त्र निर्माताओं के लिए इसकी वकालत थी। भारत की अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की अपनी भूमिका के तहत, मित्तल संस्थान ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक द्वारा संचालित भारत में वित्तीय समावेशन पर एक सेमिनार का आयोजन

किया।
मित्तल संस्थान भारत में शहरी विकास का व्यापक अध्ययन कर रहा है। इसके द्वारा आयोजित एक सम्मेलन का उद्देश्य सतत विकास प्राप्त करने के तरीके सुझाना था। शहरी नियोजन का विषय सामाजिक मुद्दों के द्वार खोलता है: हार्वर्ड में एक छात्र परियोजना का उद्देश्य 'दिल्ली में स्थानिक शुद्धिकरण, सामाजिक न्याय और परिवर्तन के समकालीन मुद्दों' पर शोध करना था।
मुंबई के विकास में पर्यावरणीय पहलुओं पर एडुआर्डो पेलाएज़ का शोध प्रबंध, "स्लमस्केप्स से सीखना: गीली ज़मीनें, बाढ़ और मुंबई में सामुदायिक पहल", केंद्रित था। इसका उद्देश्य ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास की सामाजिक-राजनीतिक गतिशीलता, गरीबी, बुनियादी ढांचे की कमी, 'कचरे के पहाड़' और अन्य चुनौतियों को समझना था। ये परियोजनाएं ऑस्कर विजेता फिल्म 'स्लमडॉग मिलियनेयर' जैसी फिल्मों में दिखाए गए और चित्रित किए गए स्लम के प्रकारों का गहराई से अध्ययन करती हैं। इसका उद्देश्य विशेषज्ञता और संपर्कों का नेटवर्क बनाना है।
एक अन्य अध्ययन ने नीतिगत दृष्टिकोण से भारत की परिवहन आवश्यकताओं का विश्लेषण किया। इसका उद्देश्य विभिन्न कारकों की जटिलता को ध्यान में रखते हुए परिवहन आवश्यकताओं का मॉडल तैयार करना था। इस प्रकार का कार्य किसी भी देश के योजना आयोग और शहरी नियोजन मंत्रालयों से नियमित रूप से अपेक्षित होता है। हार्वर्ड भारतीय सरकार के साथ अच्छे संबंध बना रहा है और राजमार्ग विकास से लेकर स्वच्छता और आवास परियोजनाओं तक के विषयों पर वार्ता और चर्चा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित कर रहा है।
इस शोध का एक प्रमुख विषय नई दिल्ली में प्रवासी श्रमिकों के अनुभवों,

आकांक्षाओं और विश्वदृष्टिकोण से संबंधित है, जो दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र में धातु श्रमिकों के बीच किए गए क्षेत्रकार्य पर आधारित है।

हार्वर्ड दिल्ली में जल संकट को लेकर काफी चिंतित है और उसने जल समस्याओं में सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ के महत्व को समझने के लिए विशेषज्ञों की मासिक गोलमेज चर्चाओं का आयोजन किया है। उन्होंने जिस प्रमुख संकट की पहचान की है, वह है 'बुनियादी ढांचे की विफलता से प्रभावित आबादी की सामाजिक असुरक्षा'। एक बार फिर, हार्वर्ड के ये नेक अधिकारी दुनिया के दूसरे कोने से भारत के 'दबे-कुचले' लोगों को बचाने की तैयारी कर रहे हैं।

स्वास्थ्य देखभाल

बिल्डिंग भारत-बोस्टन बायोसाइंसेज प्रोग्राम एक महत्वपूर्ण भारतीय सरकारी कार्यक्रम है जिसे मित्तल इंस्टीट्यूट मैसाचुसेट्स के बोस्टन क्षेत्र में संचालित करने में मदद करता है। वास्तव में, हार्वर्ड ने इस कार्यक्रम को तैयार करने और भारतीय सरकार के साथ बातचीत करने में अग्रणी भूमिका निभाई। पंजाब के एक विद्वान को एक वर्षीय फैलोशिप प्रदान की गई, जिन्होंने मानव विज्ञान और राजनीतिक दृष्टिकोणों का उपयोग करते हुए भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अन्याय पर अपने काम को उजागर किया। एक अन्य विद्वान रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में अपने काम के आधार पर हाशिए पर पड़े समूहों के लिए नीतियां विकसित कर रही हैं। भारत में शासन और राज्य तथा समाज के बीच संबंधों का अध्ययन करने के लिए अनुदान दिए जाते हैं। केरल बाढ़ और महाराष्ट्र में आंतरिक प्रवासन के दौरान सामाजिक मुद्दों को उजागर करने के लिए एक परियोजना भी चल रही है।

बर्मा में स्वास्थ्य और मानवाधिकारों पर आयोजित एक सेमिनार में स्वास्थ्य सेवा को म्यांमार में मानवाधिकारों पर चर्चा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया गया।

इसके अलावा, टाटा द्वारा वित्त पोषित टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक्स एंड सोसाइटी, सैन डिएगो, मित्तल इंस्टीट्यूट के माध्यम से हार्वर्ड के साथ सहयोग करता है। इसके शोध में 'वेक्टर-जनित रोगों के लिए वैकल्पिक नियंत्रण विधियों का विकास, उच्च उत्पादकता वाली बेहतर फसलों का विकास और एंटीबायोटिक प्रतिरोध की वैश्विक समस्या को कम करने के लिए तकनीकी उपाय खोजना' शामिल है। मित्तल और टाटा भारत में स्थित अन्य संस्थानों के साथ 'राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नीति निर्माण को प्रभावित करने और प्रशिक्षण देने में सहायता' के लिए सहयोग करते हैं। टाटा ट्रस्ट्स हार्वर्ड की एक परियोजना को भी वित्त पोषित कर रहा है, जिसका उद्देश्य 'लगातार गुणवत्ता वाले मनोसामाजिक हस्तक्षेप प्रदान करने के लिए अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करने हेतु एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण करना' है। इस कार्यक्रम का एक पायलट परीक्षण मध्य प्रदेश स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से किया गया है।

मित्तल संस्थान भारत में चिकित्सा संस्थानों के साथ कई कार्यक्रमों का समन्वय करता है। इनमें शोधकर्ताओं के बीच आदान-प्रदान के साथ-साथ भारत में सरकारी नीतियों को प्रभावित करने वाली परियोजनाएं भी शामिल हैं। भारत में इसकी मानसिक स्वास्थ्य परियोजनाओं में शराब, बाल शोषण, हिंसा, गरीबी और असमानता तथा सामाजिक अलगाव का अध्ययन शामिल है। इसकी बैठकों में नीतियां तैयार की जाती हैं और इनका उपयोग भारतीयों को इस क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता है। कम आय वाले लोगों के लिए उपचार में मौजूद कमियों और

समाज से बहिष्कृत होने की समस्या पर विशेष ध्यान दिया जाता है। लैंगिक समानता और मानवाधिकारों को अक्सर चर्चाओं में शामिल किया जाता है।

कला और संस्कृति

मित्तल संस्थान में एक रोचक विजिटिंग आर्टिस्ट प्रोग्राम है, जिसके तहत भारतीय कलाकारों को लाकर भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने और उसे प्रभावित करने के लिए उन्हें एक माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ विशिष्ट अनुदान और कार्यक्रम सौम्य हैं और पूरी तरह से कला के लिए कला पर केंद्रित हैं। अन्य विशिष्ट सांप्रदायिक पहचानों से संबंधित हैं या विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए कला का उपयोग करते हैं, क्योंकि कला हमेशा से सामाजिक और राजनीतिक संदेश देने का एक प्रभावी माध्यम रही है।

मल्लिका साराभाई, जो एक प्रख्यात नृत्यांगना, विवादास्पद कार्यकर्ता और भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की बेटी हैं, उन कलाकारों का एक उदाहरण हैं जिन्हें बढ़ावा दिया गया है। लिंग और कामुकता का विषय स्वाभाविक रूप से उभर कर सामने आता है।

हार्वर्ड के वामपंथी इतिहासकार सुगाता बोस द्वारा निर्मित फिल्म 'मंदिर, मस्जिद, मंडल और मार्क्स: भारत में लोकतंत्र', जो पश्चिम बंगाल में सक्रिय और सत्ताधारी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ राजनेता भी हैं, ने भारतीय लोकतंत्र को उनके वैचारिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। मित्तल इंस्टीट्यूट द्वारा फिल्म की स्क्रीनिंग और चर्चा का प्रचार इस रूप में किया गया कि यह 'भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में धर्म, जाति और साम्यवाद की भूमिका की एक दुर्लभ झलक' प्रदान करती है।

विभिन्न गतिविधियों के बीच, मुस्लिम कव्वाली प्रदर्शनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेपाल में कला पर आयोजित संगोष्ठी में 'अलगाव के बंधन को चुनौती देने' और आधुनिकता एवं वैश्विकता को अपनाने पर चर्चा हुई। बंगाली ग्रंथों के अनुवाद पर एक अन्य परियोजना धार्मिक और नस्लीय तत्वों की व्याख्या पर केंद्रित है। अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र के लिए हार्वर्ड नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, फिर भी मित्तल संस्थान ने उनकी सामाजिक संदेश पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया, न कि अर्थशास्त्र पर आधारित फिल्म का।

कला को सीधे तौर पर विभाजनकारी तरीकों से भी प्रस्तुत किया जाता है। एक नेपाली आगंतुक ने ऐसा सामाजिक संदेश दिया जिससे हार्वर्ड में उनके मेजबानों से सराहना मिल सके। उन्होंने अपने काम को 'नेपाल भर में जाति, वर्ग, लिंग और क्षेत्रीय असमानताओं की परतों' और 'गहरे ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक सोच' पर केंद्रित बताया।

गायक टी.एम. कृष्णा को कला के माध्यम से सामाजिक आदतों और सीमाओं को तोड़ने की संभावनाओं पर अपने दर्शन पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्होंने भारत के हाशिए पर स्थित समुदायों, जैसे कर्नाटक के ट्रांसजेंडर कलाकारों पर पर्यावरणीय संकटों के प्रभाव पर चर्चा की। कलात्मक मनोरंजन सामाजिक संदेशों को फैलाने का एक बेहतरीन माध्यम बन सकता है, और कृष्णा इस कौशल के लिए जाने जाते हैं। स्वाभाविक रूप से, यह मित्तल संस्थान की भूमिका के प्रति दृष्टिकोण के अनुरूप है। ऐसे संदर्भ होमी के. भाभा जैसे प्रसिद्ध विचारकों के लिए उन जटिल मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आदर्श मंच प्रदान करते हैं जिनमें 'अंतर-सामुदायिक मुठभेड़ों में निहित भेद्यता की परतें' और 'ध्रुवीकृत समुदायों की सूक्ष्म राजनीति' शामिल हैं।

अन्य विविध परियोजनाएँ

कुछ गतिविधियाँ विशुद्ध रूप से 'नेटवर्किंग' के उद्देश्य से आयोजित की जाती हैं, जहाँ भारत और अमेरिका के महत्वपूर्ण लोगों को एक साथ लाया जाता है, जिनमें सरकारी अधिकारी, व्यापारिक नेता और बुद्धिजीवी शामिल होते हैं। एक प्रमुख भूमिका निभाते हुए, हार्वर्ड अपनी प्रतिष्ठा और इस प्रकार अपनी शक्ति का उपयोग करता है। प्रतिभागी हार्वर्ड के नाम से संबद्ध होने और इन प्रतिष्ठित क्लबों में शामिल होने से लाभान्वित होते हैं। अन्य गतिविधियों को विकसित देशों द्वारा विकसित देशों को दी जा रही तकनीकी सहायता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि, हमें उन्नत प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण का कोई ठोस उदाहरण नहीं मिला। शहरी अपशिष्ट जल का अध्ययन या कृषि जल का पुनर्चक्रण जैसे विषय ऐसे नहीं हैं जिनमें भारत को हार्वर्ड में अध्ययन हेतु लोगों को भेजने की आवश्यकता हो। बल्कि, स्थिति इसके विपरीत हो सकती है। लेकिन भारतीय प्रतिभागी हार्वर्ड के शानदार व्यवहार से प्रभावित होकर जीवन भर के लिए हार्वर्ड के प्रति वफादार बन जाते हैं। हार्वर्ड नियमित रूप से टाटा जैसे अन्य भारतीय ब्रांडों को शामिल करके अपनी भूमिका को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, और टाटा जैसी कंपनियों को भी इससे प्रतिष्ठा में वृद्धि मिलती है।

कुछ परियोजनाओं में, हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि भारतीय नवाचारों को हार्वर्ड में भारतीय उद्यमों में मूल्यवर्धन के बहाने प्रदर्शित किया जा रहा है, जबकि वास्तव में ज्ञान का हस्तांतरण भारत से अमेरिका की ओर हो रहा है।

नेपाल अध्ययन कार्यक्रम के तहत, मित्तल संस्थान ने 2015 के भूकंप के बाद की तैयारियों का अध्ययन करने के लिए दो नेपाली सरकारी एजेंसियों और एक विश्वविद्यालय के साथ समन्वय किया। रिपोर्ट पढ़ने पर

यह सवाल उठता है कि हार्वर्ड प्रतिनिधिमंडल अव्यवस्थित, गरीब और असहाय लोगों की तस्वीरें लाने के अलावा और क्या योगदान दे सकता था।

एक अन्य सामान्य विषय भारत के उद्योग के किसी क्षेत्र पर शोध करना है, जिसमें दिल्ली के मंत्रालयों और विभिन्न संबंधित थिंक टैंकों में नियमित रूप से किए जा रहे कार्यों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। जब सभी डेटा और हितधारक भारत में ही मौजूद हैं, तो इस तरह के सीधे-सादे शोध के लिए हार्वर्ड में निवेश करने से भारत को किस प्रकार लाभ होता है?

2020 में, पेटीएम (डिजिटल भुगतान प्रणाली) के प्रमुख विजय शेखर शर्मा भी भारतीय अरबपतियों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गए और उन्होंने लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्यों और अनुसंधान को समर्थन देने के लिए एक अज्ञात राशि दान की।

बजाज परिवार (मोटरसाइकिल और तिपहिया वाहन निर्माता) के वंशज कुशाग्र बजाज ने मित्तल संस्थान को एक अज्ञात राशि दान की है ताकि अग्रणी भारतीय विद्वानों को हार्वर्ड विश्वविद्यालय का दौरा करने और 'विश्वविद्यालय के विशाल संसाधनों का लाभ उठाने' के लिए वित्त पोषित किया जा सके।

मित्तल इंस्टीट्यूट में अपने परिवार के नाम पर कार्यक्रम चलाने वाले धनी भारतीय दानदाताओं के अलावा, प्रभावशाली भारतीयों का एक और वर्ग है जो हार्वर्ड के उच्च स्तरीय पदों पर अपनी जगह बनाना चाहता है। ये लोग मित्तल इंस्टीट्यूट की सलाहकार परिषद में शामिल व्यापारिक नेताओं की सूची में आते हैं। दान की गई धनराशि के आधार पर, इनमें से कुछ को हार्वर्ड के उच्च स्तरीय पदों पर जगह मिलती है। ऐसे परिवारों की

एक नमूना सूची अंत में दी गई है।

पाकिस्तान के गौरव के विपरीत

हार्वर्ड में किए जा रहे कार्यों को लेकर पाकिस्तानी दानदाताओं के दृष्टिकोण में एक दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। हार्वर्ड में कम से कम दो पाकिस्तानी वित्त पोषित फैलोशिप हैं जिन्हें मित्तल संस्थान संचालित करता है। इन फैलोशिप के तहत, संस्थान विद्वानों और पेशेवरों को विशेष रूप से पाकिस्तान पर शोध करने के लिए हार्वर्ड आने के दो अवसर प्रदान करता है। अमन फैलोशिप पाकिस्तान के विकास से संबंधित शोध पर काम कर रहे डॉक्टरेट और उन्नत पेशेवर डिग्री धारकों को सहायता प्रदान करती है। सैयद बाबर अली फैलोशिप पाकिस्तान से संबंधित मुद्दों पर काम कर रहे डॉक्टरेट और उन्नत पेशेवर डिग्री धारकों को सहायता प्रदान करती है।

मित्तल इंस्टीट्यूट में पाकिस्तान का अध्ययन करने वाली प्रमुख शोधकर्ता डॉ. मरियम चुगताई, पाकिस्तान के बारे में पश्चिमी रूढ़ियों और आकलन को चुनौती देती हैं। मित्तल की वेबसाइट बताती है कि मित्तल इंस्टीट्यूट की सैयद बाबर अली फेलो के रूप में, वह एक ऐसी पुस्तक लिख रही हैं जो पाकिस्तान की राजनीति और संस्कृति के बीच तनाव का विश्लेषण करती है, ताकि 'देश को गलत तरीके से सौंपी गई कहानी को फिर से लिखा जा सके'। दूसरे शब्दों में, उनका उद्देश्य पाकिस्तान के बारे में अमेरिकी लोकप्रिय धारणाओं की आलोचना करना है और वह इस पुस्तक को लिखने के लिए अपनी हार्वर्ड फेलोशिप का उपयोग करना चाहती हैं। विशेष रूप से, इसमें कहा गया है:

उनका शोध इस कट्टर पश्चिमी धारणा को चुनौती देता है कि पाकिस्तान में

हिंसा की घटनाओं को पूरी आबादी पर हिंसक प्रकृति के रूप में लागू किया जा सकता है। ... अपनी पुस्तक और जमीनी अनुभव के माध्यम से, चुगताई यह प्रदर्शित करना चाहती हैं कि पाकिस्तान के बारे में प्रचलित धारणा जरूरी नहीं कि सही हो।

कई भारतीय दानदाताओं और उनके द्वारा वित्त पोषित विद्वानों की मानसिकता के विपरीत, चुगताई अमेरिका में पाकिस्तान के बारे में प्रचलित विचारों का खुलकर विरोध करती हैं। वह अपने शोध प्रबंध का उद्देश्य बताती हैं:

... पाकिस्तान को सरल रुझानों और सामान्यीकरणों के रैखिक विश्लेषण से नहीं समझा जा सकता। इसमें कई विरोधाभास और द्वंद्व हैं जिन्हें पाकिस्तान के सूक्ष्म, ऐतिहासिक विश्लेषण के माध्यम से समझना आवश्यक है।

यह परियोजना सैयद बाबर अली द्वारा सौंपी गई थी, जो पाकिस्तान से मित्तल संस्थान के पहले दानदाता और संस्थान की सैयद बाबर अली फेलोशिप के संस्थापक हैं। यह दानदाता के गौरव और साहस को दर्शाता है। किसी फेलो को पाकिस्तान भेजना एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। उनका उद्देश्य लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के शिक्षा संकाय में अपनी तरह का पहला शिक्षा संकाय स्थापित करना था। लाहौर स्थित यह संस्थान पाकिस्तान के हितों के प्रति समर्पित होगा। 'इस संकाय का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान, नीति और व्यवहार के संगम पर कार्य करना है ताकि हमारे छात्र अग्रणी अनुसंधान को समझ सकें और उसे व्यवहार में ला सकें।' वे पाकिस्तान में पहले ही 350 युवा उद्यमियों को अपनी विचारधारा का प्रशिक्षण दे चुके हैं।

पाकिस्तान के बारे में प्रचलित धारणाओं को पलटने का प्रयास दृश्य कलाकार और मित्तल में पाकिस्तानी शोध सहयोगी इमरान चन्ना द्वारा भी

किया गया था। वेबसाइट पर लिखा है:
वह इस बात का अन्वेषण करते हैं कि कैसे गढ़ी गई कथाएँ हमारी सामूहिक स्मृति को प्रभावित करके व्यक्तिगत और सामाजिक चेतना को आकार दे सकती हैं और मानवीय प्रतिक्रियाओं को बदल सकती हैं।
दूसरे शब्दों में कहें तो, पाकिस्तानी भारतीयों की तुलना में कम खर्च करते हैं, लेकिन वे ऐसे विद्वानों और विषयों का चयन करते हैं जिनका पाकिस्तानी परिदृश्य पर सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह कुछ हद तक हार्वर्ड में चीन की परियोजनाओं के समान है, जो देशभक्ति से प्रेरित हैं, न कि उनके देश के हितों के विरुद्ध, जैसा कि भारतीय परियोजनाएं अक्सर होती हैं।
हमारे विश्लेषण में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है जिससे मित्तल परिवार से जुड़ी कोई समस्या सामने आए, जिनके नाम और धन का इस्तेमाल इस तरह के शोध कार्यों के लिए किया जा रहा है। हम केवल कुछ ऐसे संदिग्ध बिंदुओं को उजागर कर रहे हैं जहां एकतरफा शोध कार्य या संवेदनशील मामलों में हस्तक्षेप एक शक्तिशाली विदेशी समूह द्वारा भारतीय संसाधनों का उपयोग करके किया जा रहा है। यह परोपकारियों पर निर्भर है कि वे आगे की जांच करें और यह निर्धारित करें कि क्या कोई सुधार आवश्यक है।

13. पिरामल परिवार: हार्वर्ड विश्वविद्यालय का भारत का प्रवेश द्वार

अवलोकन
हम पहले ही हार्वर्ड और चीन के घनिष्ठ संबंधों का खुलासा कर चुके हैं

और यह भी बता चुके हैं कि हार्वर्ड किस प्रकार अमेरिका और भारत सहित अन्य देशों के हितों की कीमत पर चीन के हितों की रक्षा करता है। यह अध्याय दर्शाता है कि हार्वर्ड टी.एच. चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की जड़ों में एक चीनी सत्ताधारी है जिसके चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध हैं और जो परोपकारी संगठनों के रूप में काम करने वाली फर्जी कंपनियों के माध्यम से इसकी गतिविधियों को वित्त पोषित करता है, और कैसे एक भारतीय अरबपति भी इसमें शामिल हो गया है।

चीन की यह भागीदारी भारत के संदर्भ में विशेष रूप से चिंताजनक है, खासकर उसके शोध कार्यों को देखते हुए। अधिकांश लोग यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि अमेरिका में सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे को भारत में जातिगत मुद्दे से कैसे जोड़ा जा सकता है। लेकिन चान स्कूल ने इस कला में महारत हासिल कर ली है और हार्वर्ड की पसंदीदा श्रेणियों - नस्ल और अंतर्संबंध - के दायरे में स्वास्थ्य के मुद्दे को समेटने में और आगे बढ़ गया है, जिससे हार्वर्ड खुद को निम्न वर्गों का रक्षक घोषित कर रहा है। उदाहरण के लिए, यूरोप के हाशिए पर पड़े रोमा लोगों के लिए वकालत करने का दावा करते हुए भी, हार्वर्ड अभी तक उनके इतिहास या उनके हाशिए पर धकेले जाने के कारणों का सटीक विवरण प्रस्तुत करने में सफल नहीं हुआ है। इसके बजाय, वह सूरज येंगडे को उनके लिए एक 'वैकल्पिक' इतिहास गढ़ने की अनुमति दे रहा है।

भारतीय अरबपति अजय पीरामल, चान स्कूल की भारत में पैठ बनाने के इस अभियान का हिस्सा बन गए हैं। मुंबई में हार्वर्ड चान इंडिया रिसर्च सेंटर, जो पीरामल के अनुदान से स्थापित हुआ है, ने भारतीय अभिजात वर्ग, सरकार, संयुक्त राष्ट्र, यूनिसेफ और अन्य संस्थाओं के सहयोगियों को आकर्षित किया है, साथ ही भारतीय उद्योगपतियों से अतिरिक्त धन भी प्राप्त किया है। और हार्वर्ड द्वारा भारत पर किए जाने वाले इन हमलों

के सामान्य तरीके के अनुसार, इस केंद्र का नेतृत्व ऐसे लोगों द्वारा किया जा रहा है जो जरूरी नहीं कि भारत के हितों के प्रति प्रतिबद्ध हों। इसके अलावा, इसके घोषित लक्ष्य स्पष्ट रूप से पीरामल के संपर्कों का उपयोग करके भारत के अभिजात वर्ग में घुसपैठ करने, आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हर स्तर पर कट्टरपंथी नेतृत्व का निर्माण करने और सामाजिक परिवर्तन लाने के अंतिम लक्ष्य के साथ संवेदनशील डेटा (आनुवंशिक डेटा सहित) एकत्र करने के जोखिम को उजागर करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की उनकी महत्वाकांक्षाओं में चीनी संबंधों का पता लगाया जा सकता है। अन्य भारतीय अरबपतियों के मामलों की तरह, पीरामल परिवार के मामले में भी हमें उनकी ओर से कोई उल्लंघन या चूक नहीं मिली है। किसी भी ऑडिट का उद्देश्य उन क्षेत्रों की पहचान करना होता है जिनके बारे में उद्यम के मालिकों/प्रबंधकों को जानकारी होनी चाहिए, ताकि वे स्पष्टता की दिशा में आगे के कदम उठाने में अपने विवेक का प्रयोग कर सकें। हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि हार्वर्ड में पीरामल की पहल में सकारात्मक पहलू नहीं हैं; यह निश्चित रूप से जन स्वास्थ्य में एक रचनात्मक भूमिका निभाती है।

हार्वर्ड टी.एच. चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में चीन की घुसपैठ
चीन जहां एक ओर सुनियोजित तरीके से अपने स्वयं के आख्यान गढ़ता है, वहीं उसकी विदेश नीति दूसरों में घुसपैठ करके उन्हें बाधित करना है। माइकल पिल्सबरी के अनुसार: 'चीनी कंपनियों ने थिंक टैंकों और विश्वविद्यालयों को बड़ी मात्रा में दान देना शुरू कर दिया है ताकि चीन पर अमेरिकी नीतिगत अध्ययनों को वित्त पोषित किया जा सके जो बीजिंग के विचारों का समर्थन करते हैं।' पिल्सबरी, जिन्होंने रिचर्ड निक्सन (1969-74) से लेकर बराक ओबामा (2009-17) तक अमेरिकी

राष्ट्रपति प्रशासनों में कार्य किया है, थिंक टैंक रैंड कॉर्पोरेशन में पूर्व विश्लेषक थे, रक्षा विभाग में वरिष्ठ पदों पर रहे और चार अमेरिकी सीनेट समितियों के स्टाफ में भी शामिल रहे। उन्हें पूरा विश्वास है कि चीन प्रतिष्ठित अमेरिकी विश्वविद्यालयों में अपनी पैठ बनाने के लिए पैसे का इस्तेमाल कर रहा है।

हम जिस सबसे प्रमुख उदाहरण को उजागर कर रहे हैं, वह है हार्वर्ड टी.एच. चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के माध्यम से चीन का अमेरिका के भीतरी हिस्से में गहरा प्रभाव। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ एक सदी पुराना है और 2014 में 350 मिलियन डॉलर के शुरुआती दान के साथ चीनी प्रभाव में आ गया, जो हार्वर्ड के इतिहास में सबसे बड़ा दान था। इसी समय स्कूल का नाम दानकर्ता टी.एच. चान के नाम पर रखा गया था। इस दान की प्रशंसा 'अप्रतिबंधित' होने के लिए की गई थी, जिससे स्कूल को इसे खर्च करने की पूरी स्वतंत्रता मिल गई थी।

उत्साह इतना अद्भुत था कि किसी ने भी धन के स्रोत की छानबीन करने की जहमत नहीं उठाई, जबकि यह पहली बार था जब हार्वर्ड के एक पूरे स्कूल का नाम किसी दानदाता के नाम पर रखा जा रहा था। प्रेस विज्ञप्तियों और मीडिया कवरेज में अमेरिकी अरबपति जेराल्ड चान को एक व्यक्तिगत दानदाता के रूप में दिखाया गया और उनके भाई रॉनी सी. चान को नजरअंदाज कर दिया गया। दोनों ने मिलकर मॉर्निंगसाइड फाउंडेशन की सह-स्थापना की थी, जो एक अमेरिकी चैरिटी संस्था है जिसमें कोई कर्मचारी नहीं हैं, और इसका उद्देश्य हार्वर्ड के प्रतिष्ठित और रणनीतिक स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ को अपने नाम पर रखना था।

कुछ वर्षों बाद गहन जांच-पड़ताल हुई जिसके परिणामस्वरूप एक घोटाला सामने आया: मॉर्निंगसाइड फाउंडेशन के दो फंडिंग स्रोत अज्ञात संस्थाएं थीं, जिससे उनके फर्जी कंपनियां होने का संदेह पैदा हुआ। मॉर्निंगसाइड

को माध्यम बनाकर फंडिंग करने वाला तीसरा स्रोत हार्वर्ड को दिए गए दान का मुख्य स्रोत था, और पनामा पेपर्स (जानकारी लीक होने से) ने खुलासा किया कि यह मोनाको के गोपनीयता कानूनों की आड़ में छिपी एक संस्था थी।

इस बीच, जनसंपर्क अभियानों ने रॉनी चैन को एक 'परोपकारी' के रूप में पेश किया, इस तथ्य को छिपाते हुए कि वह केवल एक रियल एस्टेट अरबपति नहीं हैं। वह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से घनिष्ठ संबंध रखने वाले एक वैश्विक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उन्होंने एक चीनी सरकारी थिंकटैंक में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्य किया है जो सीधे चीन के सर्वोच्च प्रशासनिक प्राधिकरण को रिपोर्ट करता है।

जब हांगकांग के एक लोकतंत्र समर्थक पत्रकार ने, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था, रोनी चैन को 'चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मोहरा' बताकर बेनकाब किया, तो इस जानकारी को उजागर करने वाला ट्विटर पेज हटा दिया गया। रोनी चैन ने हांगकांग पर बीजिंग के जबरन कब्जे का बचाव किया है और वहां चीन समर्थक नेताओं को चुनाव जिताने में मदद की है। जब वे एशिया सोसाइटी के हांगकांग चैप्टर के सह-अध्यक्ष थे, तब चीन के मानवाधिकार उल्लंघन की आलोचना करने वाली एक फिल्म का प्रदर्शन चीनी दबाव में रद्द कर दिया गया था।

हांगकांग स्थित एक निवेश कंपनी द्वारा फोर्ब्स में बहुमत हिस्सेदारी खरीदने के बाद, रोनी चान की आलोचना करने वाला एक लेख वेबसाइट से हटा दिया गया और लेखक को बर्खास्त कर दिया गया। ऐसा व्यापक रूप से माना जाता है कि वह चीनी सरकार को देश और विदेश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनका प्रभाव विदेशी पत्रकारों को ब्लैकलिस्ट करने और निष्कासित करने से लेकर नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन पर लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों का

समर्थन करने वाले ट्वीट को अस्वीकार करने के लिए दबाव डालने तक फैला हुआ है।

रॉनी चान इन दिनों एक विवादास्पद अरबपति के रूप में विवादों में घिरे हुए हैं, जो रणनीतिक तरीकों से अमेरिकियों को प्रभावित करने के लिए भारी मात्रा में धन दान कर रहे हैं। यह बताया जा रहा है कि वे 'चीन-संयुक्त राज्य अमेरिका एक्सचेंज फाउंडेशन' (CUSEF; अध्याय 8 में उल्लिखित) के प्रमुख हैं, जो आधिकारिक तौर पर अमेरिका में एक विदेशी एजेंट के रूप में पंजीकृत है। इस संगठन ने वाशिंगटन डी.सी. स्थित कई थिंकटैंकों में बड़ी मात्रा में धन का निवेश किया है। इनमें से एक प्रभावशाली पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, जिसके बोर्ड में वे सदस्य भी हैं। द्विदलीय कांग्रेस समिति, यूएस-चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने निष्कर्ष निकाला है कि CUSEF चीन के उस गुप्त नेटवर्क का हिस्सा है जो 'अपनी सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों और सत्ता के संभावित विरोधियों को अपने नियंत्रण में लेने और उन्हें निष्क्रिय करने' का प्रयास करता है। हार्वर्ड के छात्र कार्यकर्ताओं का दावा है कि चान की अमेरिकी कॉलेजों में घुसपैठ चीन के वैश्विक दुष्प्रचार अभियान का समर्थन करती है। रॉनी चान के CUSEF के खिलाफ भी विरोध शुरू हो गया है। उदाहरण के लिए, ऑस्टिन स्थित टेक्सास विश्वविद्यालय ने चीनी दुष्प्रचार फैलाने की आशंका के चलते इसकी फंडिंग अस्वीकार कर दी। लेकिन चान परिवार प्रतिशोध से आसानी से विचलित नहीं होता। मार्च 2022 में, MIT ने घोषणा की कि उसे चान के मॉर्निंगसाइड फाउंडेशन से एक सौ मिलियन डॉलर का दान प्राप्त हुआ है।

हार्वर्ड के अपने अखबार 'द क्रिमसन' ने लिखा: 'इन प्रयासों के पीछे की राजनीति से इतने गहरे रूप से जुड़े एक व्यक्ति को विश्वविद्यालय द्वारा

सम्मानित किया जाना और यहां तक कि उनके दिवंगत पिता के नाम पर एक स्कूल का नाम रखा जाना सरासर अस्वीकार्य है।' लेख में उन्हें 'महत्वपूर्ण मानवीय संकटों के लिए जिम्मेदार सरकार का समर्थक' बताया गया है। हार्वर्ड चीन के बारे में अमेरिकी धारणाओं को आकार देने में बेहद प्रभावशाली है।

न्यूयॉर्क स्थित एशिया सोसाइटी के यूएस-चाइना रिलेशंस सेंटर के प्रमुख ओरविल एच. शेल III का कहना है कि अमेरिका में चीन के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में हार्वर्ड से जुड़ा हुआ है। द क्रिमसन की रिपोर्ट है कि हार्वर्ड द्वारा 'अमीर वर्ग के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने (यहां तक कि छात्रों के प्रतिनिधिमंडलों को उन थिंकटैंकों का दौरा कराने की अनुमति देने, जो कानूनी रूप से विदेशी एजेंटों के रूप में पंजीकृत हैं)' का भविष्य की नीतियों पर ठोस प्रभाव पड़ सकता है।

रॉनी चैन पहले ही भारत में प्रवेश कर चुके हैं और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। चैन एक करिश्माई घुमक्कड़ भी हैं जो ईसाई मिशनरियों का समर्थन करते हैं। धर्मशास्त्र पर विवादास्पद विचार फैलाने के लिए मुख्यधारा के अमेरिकी ईसाइयों द्वारा उनकी आलोचना की गई है। उनका दावा है कि जब वे सोलह वर्ष के थे, तब प्रभु ने उनसे दर्शन किए और वे इसकी तुलना प्रेरित जॉन के अनुभव से करते हैं। उसी समय प्रभु ने चैन को बताया कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना चाहिए।

सार्वजनिक स्वास्थ्य में जाति एक परिप्रेक्ष्य के रूप में

अटलांटा स्थित रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र सार्वजनिक स्वास्थ्य को इस प्रकार परिभाषित करता है:

सार्वजनिक स्वास्थ्य का अर्थ है लोगों और उनके समुदायों के स्वास्थ्य की रक्षा और सुधार करना। यह कार्य स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देकर, रोगों और चोटों की रोकथाम पर शोध करके, और संक्रामक रोगों का पता लगाकर, उनकी रोकथाम करके और उनका उपचार करके किया जाता है। कुल मिलाकर, सार्वजनिक स्वास्थ्य का संबंध संपूर्ण जनसंख्या के स्वास्थ्य की रक्षा से है। ये जनसंख्याएँ किसी स्थानीय मोहल्ले जितनी छोटी या पूरे देश या विश्व के किसी क्षेत्र जितनी बड़ी हो सकती हैं।
इस क्षेत्र में उभरता हुआ एक रुझान हाशिए पर पड़े समुदायों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है, क्योंकि स्वास्थ्य के दायरे को बहुत सीमित नहीं करना चाहिए। किसी भी समुदाय का स्वास्थ्य आस-पड़ोस, नीतियों और इन नीतियों को लागू करने वालों के अवचेतन पूर्वाग्रहों जैसे कारकों पर भी निर्भर करता है। प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो यह एक स्वागत योग्य रुझान है।
दुर्भाग्यवश, कई बार ऐसे विषय और वक्ता होते हैं जिन्हें संदर्भ की पर्याप्त समझ नहीं होती और वे राजनीतिक शुद्धता का सहारा लेते हैं। ऐसी स्थितियों में, आलोचनात्मक नस्ल सिद्धांत और अंतर्संबंधता जैसी अवधारणाओं को पर्याप्त जांच-पड़ताल किए बिना और विरोधी विचारों को जगह दिए बिना ही प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के लिए, अफ्रीकी-दलित गठबंधन नस्ल, पहचान और उत्पीड़न के विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम बन गया है और इसने जातिगत राजनीति को वैश्विक स्तर पर फैलाने का रास्ता खोज निकाला है: अमेरिका में नस्लवाद पर चर्चा शुरू होती है, यह सहजता से दलितों पर चर्चा में बदल जाती है और हिंदू-विरोधी एजेंडा को बढ़ावा दिया जाता है।
हार्वर्ड टी.एच. चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने छह महीने का एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसका शीर्षक था, पब्लिक हेल्थ

स्टोरीटेलर्स – एक स्वस्थ दुनिया के लिए शक्तिशाली कथाएँ। यह कार्यक्रम उसके विविधता और समावेशन कार्यालय का हिस्सा था। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में इसाबेल विल्करसन ने अपनी पुस्तक 'कास्ट' पर चर्चा की। अध्याय 2 में पुस्तक पर चर्चा की गई थी, जहाँ हमने दिखाया कि इस जटिल विषय को उनके काम में पर्याप्त रूप से सूक्ष्मता और संदर्भ के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है। सीएनएन के एंकर डॉन लेमन और प्रोफेसर डेविड विलियम्स इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले वक्ता थे, जिसे नीमन फाउंडेशन का समर्थन प्राप्त था। इस तरह, अश्वेत अमेरिकियों से संबंधित एक सार्वजनिक स्वास्थ्य विषय को जाति के मुद्दे में बदल दिया गया, जबकि इस मुद्दे के जटिल पहलुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कोई अन्य विशेषज्ञ मौजूद नहीं थे।

एक अन्य उदाहरण हार्वर्ड सेंटर फॉर पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट स्टडीज में जातिगत राजनीति पर किया जा रहा कार्य है, जो चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का एक हिस्सा है। क्रिटिकल रेस थ्योरी सार्वजनिक स्वास्थ्य सहित हर विषय में प्रवेश कर चुकी है और क्रिटिकल कास्ट थ्योरी में रूपांतरित हो गई है। भारतीय वामपंथियों का हर कदम पर अमेरिकी वामपंथियों का अनुकरण करना एक प्रवृत्ति बन गई है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि अश्वेतों के लिए मुआवजे का मुद्दा अब भारत में दलितों के लिए मुआवजे की मांग में प्रतिध्वनित हो रहा है। हार्वर्ड अब इस मुद्दे को मुख्यधारा में लाने का केंद्र बन गया है। दिसंबर 2021 में, चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के एक अन्य हिस्से, एफएक्सबी सेंटर फॉर हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स द्वारा "मेकिंग द केस फॉर रिपेरेशन्स" नामक एक सेमिनार का आयोजन किया गया था।

एफएक्सबी में मानवाधिकार निदेशक होमी के. भाभा की पत्नी जैकलीन भाभा हैं। जैकलीन भाभा ने कहा, "फ्रांस से कैलिफोर्निया तक, बेल्जियम

से भारत तक, हर जगह मुआवजे की मांग सुनी जा सकती है।" इससे भारत उन अन्य स्थानों की श्रेणी में आ जाता है जहां मुआवजे की लड़ाई में तेजी आने की उम्मीद है।

हम क्षतिपूर्ति के विरुद्ध नहीं हैं। वास्तव में, हमारा मानना है कि विश्व भर के समाजों के लिए न केवल सत्ता के शोषण की विरासत संरचनाओं को समाप्त करना बल्कि अतीत के पीड़ितों को मुआवजा देना भी महत्वपूर्ण है। हम पश्चिमी सार्वभौमिकता को अन्य देशों पर अंधाधुंध लागू करने के विरुद्ध हैं। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी ऐतिहासिक जटिलताएँ हैं, और किसी एक सिद्धांत को सामूहिक रूप से थोपना और सभी समस्याओं का एक ही कारण मान लेना खतरनाक है। हम विशेष रूप से हार्वर्ड जैसे संस्थानों के हस्तक्षेप के विरुद्ध हैं, जिनके पास अमेरिकी राजनीति को प्रभावित करने और किसी अन्य देश के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रभाव है।

एफएक्सबी सेंटर यूरोप में एक हजार वर्षों से रोमानी लोगों द्वारा झेले जा रहे नस्लवाद और उत्पीड़न को उजागर करने के लिए नियमित कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। दुख की बात है कि हार्वर्ड द्वारा उनके अधिकारों की वकालत करने के एक दशक के दावों के बावजूद, एक भी ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ है जिसमें उनके इतिहास को प्रमाणों के साथ विस्तार से बताया गया हो। और यद्यपि उनके द्वारा सहे गए नस्लवाद के प्रति सहानुभूति दिखाकर उन्हें अपने पक्ष में करने के बहुत प्रयास किए जाते हैं, फिर भी यह कभी स्वीकार नहीं किया जाता कि वे मूल रूप से हिंदू भारतीय हैं। मुसलमानों द्वारा उनकी गुलामी पर चर्चा करना भी राजनीतिक रूप से गलत माना जाता है। हार्वर्ड बस यही कहना पसंद करता है कि वे यूरोप में 'प्रवास' करके आए थे।

इन्फिनिटी फाउंडेशन पिछले पच्चीस वर्षों से रोमानी लोगों के समर्थन में परियोजनाएं चला रहा है। हमारा दृष्टिकोण उनके इतिहास पर आधारित

है। हार्वर्ड चान स्कूल द्वारा रोमानी पहचान का राजनीतिकरण करके अपने एजेंडे को पुष्ट करने के तरीके का मूल्यांकन करने के लिए, हम भारत छोड़ने के समय से लेकर रोमानी लोगों के संक्षिप्त इतिहास का वर्णन करते हैं।

यह सर्वमान्य है कि रोमा लोग मूल रूप से उत्तरी भारत के थे, अधिकतर पंजाब और राजस्थान से, और लगभग एक हजार वर्ष पूर्व भारत छोड़कर चले गए थे। वे स्वयं को रोमानी लोग भी कहते हैं। मुसलमानों द्वारा गुलाम बनाकर ले जाए जाने से पहले, उनके कई समुदाय लंबी दूरी तक माल परिवहन करने वाले व्यापारी थे, जो आमतौर पर बैलों आदि के लंबे काफिलों द्वारा किया जाता था। उनके कुछ समुदाय घुमंतू संगीतकार और मनोरंजनकर्ता भी थे।

विद्वान इस बात पर सर्वसम्मत हैं कि रोमानी लोगों का भारत से पलायन बार-बार हुए मुस्लिम आक्रमणों और लूटपाट के कारण हुआ था। इस विषय पर सबसे प्रसिद्ध और प्रशंसित विद्वानों में से एक टेक्सास विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इयान हैनकॉक हैं, जो रोमानी इतिहास के प्रबल समर्थक हैं। वे कुछ विचारधारावादियों द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत का खंडन करते हैं कि रोमानी लोग निम्न जाति के भारतीयों के वंशज हैं। वे इस बात को सिद्ध करने के लिए व्यापक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि वे उन भारतीय योद्धाओं के वंशज हैं जो ग्यारहवीं शताब्दी में तुर्क महमूद गजनी के भारत आक्रमण में पराजित हुए थे। वे यूरोप भर में रोमानी लोगों के बीच संस्कृत से व्युत्पन्न शब्दों की उपस्थिति का हवाला देते हैं, विशेष रूप से भारत में सैन्य मूल के शब्दों का। वे राजस्थानी लोक कथाओं का भी उल्लेख करते हैं जिनके अनुसार मुस्लिम आक्रमणों के दौरान राजपूतों के समूह हिमालय के रास्ते भारत छोड़कर चले गए थे।

ग़ज़नी ने रोमानी दास योद्धाओं का इस्तेमाल करके भारत के सिंध और

पंजाब के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। कुछ दास आज़ाद हो गए और भारत से बाहर लंबी यात्राएँ करने लगे। 1300 के दशक में, मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी ने उन हिंदुओं को गुलाम बनाने को वैध कर दिया, जिन्होंने गैर-मुसलमानों पर लगाए जाने वाले कर, जिज़्या का भुगतान नहीं किया था। कई लोगों को दास बाज़ारों में बेच दिया गया। उस युग में हिंद महासागर में फलते-फूलते दास व्यापार पर काफी शोध हुआ है, और इस व्यापार पर मुसलमानों का नियंत्रण था। मुसलमान जहाँ भी जाते थे, दासों को अपने साथ ले जाते थे, मध्य यूरोप और उससे भी आगे तक। 2013 में न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में एक प्रदर्शनी में मुस्लिम शासन के दौरान भारत लाए गए अफ्रीकियों के इतिहास को दर्शाया गया था।

एबरडीन विश्वविद्यालय के शोधकर्ता प्रोफेसर क्रिस्टोफ विट्ज़ेनरथ ने भी इस इतिहास पर शोध किया है और इसके बारे में लिखा है। इसमें कहा गया है:

इस्लाम के इतिहास के आरंभिक वर्षों से ही मध्य एशिया और फारस में दक्षिण एशियाई दास बहुतायत में पाए जाते थे। 712-13 में सिंध की विजय से 60,000 दास प्राप्त हुए, और ग्यारहवीं शताब्दी के अफगानिस्तान के ग़ज़नवी शासकों ने भारत से लाखों दासों को अपने देश वापस भेज दिया। पश्चिमी तुर्किस्तान की दास आबादी में कम से कम 1326 से ही कई दक्षिण एशियाई शामिल थे, और भारतीय दासों का नियमित रूप से आंतरिक एशियाई घोड़ों के बदले आदान-प्रदान किया जाता था। चौदहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, समरकंद स्थित तैमूर लंगड़े ने दिल्ली पहुँचने से पहले ही 100,000 भारतीयों को मार डाला, लेकिन फिर भी हजारों को पश्चिमी तुर्किस्तान वापस ले आया। ऐसा माना जाता है कि 1619-20 में लगभग 200,000 भारतीय विद्रोहियों को ईरान में

बेचने के लिए पकड़ा गया था।
सोलहवीं शताब्दी तक यूरेशियाई हृदयभूमि के दक्षिणी पड़ोसी 'बारूद साम्राज्य' बन गए थे, जिससे इस्लामी शक्ति स्थिर हुई। उनकी सेनाओं या उनके सहयोगी तुर्कमेनिस्तान, तातार और मगरेब समुद्री लुटेरे राज्यों की सेनाओं ने भारत से लेकर दक्षिण-पूर्व एशिया तक बड़े पैमाने पर काफिरों को बंदी बनाया। ... मुगलों ने किसी भी पिछली मुस्लिम शक्ति की तुलना में दक्षिण भारत में अधिक विस्तार किया और मध्य एशिया को हिंदू बंदियों से भर दिया। फिर भी, इन प्रगति ने संरचनात्मक खामियों को छिपा दिया: नव-विजित ईसाई और हिंदू अक्सर धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर देते थे।
जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, तो उसने गुलाम हिंदुओं का व्यापार शुरू किया, जिसका विस्तार भारत के बाहर अन्य क्षेत्रों में भी हुआ और यह डचों की एक प्रमुख गतिविधि बन गई।
यूरोप में रहने वाले रोमानी लोग भारत के विभिन्न हिस्सों से अलग-अलग समय पर आए थे और उनकी जातिगत पृष्ठभूमि भी विविध थी। उन्हें बंदी बनाकर गुलाम बनाया गया, अक्सर उनसे मनोरंजन करवाया जाता था और उनसे निम्न स्तर के अन्य काम करवाए जाते थे। यूरोप में ऐसे कई समूह एकजुट हो गए क्योंकि वे उत्पीड़न की एक समान समस्या का सामना कर रहे थे। इसलिए, एक ऐसे शत्रुतापूर्ण क्षेत्र में सुरक्षा के लिए एक साथ रहना उनके लिए जीवित रहने का एक तरीका था, जहाँ उन्हें अक्सर जानवरों की तरह कानूनी रूप से मार डाला जाता था।
भारत में नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई में हार्वर्ड के अगुआ सूरज येंगडे, रोमा समुदाय से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। वे अपने हार्वर्ड ब्रांड और प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए रोमा समुदाय को हिंदू धर्म और भारत में व्याप्त जातिगत अत्याचारों के बारे में 'शिक्षित' करते हैं और

साथ ही उन्हें अपने अंबेडकर दलित आंदोलन में शामिल करना चाहते हैं। वे रोमा समुदाय के इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश करते हैं और उन्हें भारत में दलित बताते हैं, इसलिए उन्हें हिंदू धर्म के खिलाफ उनके अभियान में शामिल होना चाहिए।

भारत पर चान-पिरामल सहयोग

उपरोक्त सभी गतिविधियाँ हार्वर्ड के बोस्टन क्षेत्र परिसर में चल रही थीं, वहीं पीरामल परिवार ने समानांतर रूप से हार्वर्ड को भारत में लाने और इन विचारों को एक आधार प्रदान करने का काम किया। भारतीय विचारकों के बीच जिस बात पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया है, वह यह है कि हार्वर्ड टी.एच. चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ भारत में अपनी पैठ बनाने के लिए पीरामल परिवार का इस्तेमाल कर रहा है। पीरामल परिवार द्वारा अपने हितों को साधने के लिए अपने धन और नाम का उपयोग करने में कोई बुराई नहीं है। हम केवल चान के कथित या संदिग्ध चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधों को लेकर अमेरिका में चल रहे विवाद की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

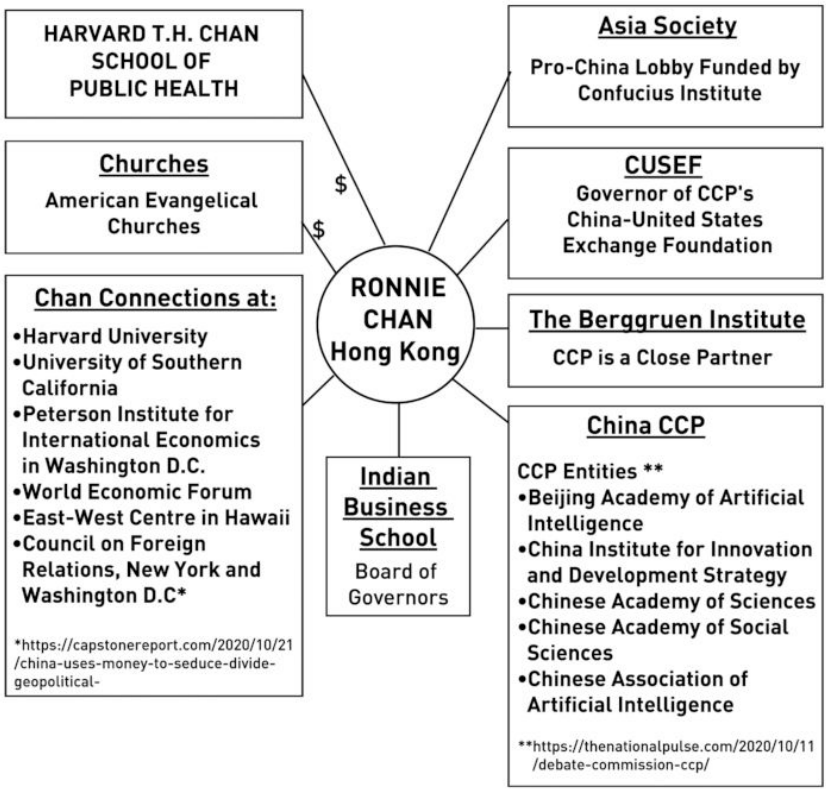

2014 में, चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ को अजय पीरामल और उनकी पत्नी स्वाति से एक उदार दान प्राप्त हुआ, जिससे संस्थान ने मुंबई में, भारत के प्रमुख वित्तीय जिले के ठीक बीच में एक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र खोला। इस केंद्र में लगभग पचास लोगों की क्षमता वाला एक कक्षाकक्ष; पैंतीस लोगों के लिए एक अनौपचारिक लाउंज/भोजन कक्ष; अतिथि शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों के लिए कार्यालय और क्यूबिकल; और एक सम्मेलन कक्ष शामिल हैं।

इसके बदले में, हार्वर्ड ने स्वाति पीरामल को हार्वर्ड बोर्ड ऑफ ओवरसियर्स में एक सीट दी है। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल में इसे 'दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुराने बोर्डों में से एक - हार्वर्ड बोर्ड ऑफ

ओवरसियर्स' के रूप में वर्णित किया गया है। इसके अलावा, उन्हें चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में डीन के सलाहकारों के सदस्य के रूप में भी शामिल किया गया है।

स्वाति पीरामल ने आशा व्यक्त की कि उनके उदार दान और मुंबई के प्रतिष्ठित स्थान पर उपलब्ध कार्यालय स्थान से चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ को भारत में स्वास्थ्य सेवा के उन अनेक क्षेत्रों में सुधार करने में मदद मिलेगी जहाँ यह पिछड़ा हुआ है। उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना करते हुए भावुक अपील की जिसमें

एक माँ को इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ती कि उसका बच्चा जीवित रहेगा या नहीं; जहाँ उसके पास अपने बच्चों की देखभाल करने और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने की शक्ति हो; जहाँ उसे साधारण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने के लिए मीलों पैदल नहीं चलना पड़ता; जहाँ वह अपने परिवार का आकार निर्धारित कर सकती है; जहाँ वह अपने परिवार को बीमारियों से सुरक्षित रख सकती है; जहाँ वह अपने भविष्य के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकती है; और जहाँ वह स्वस्थ और मजबूत होने का सपना देख सकती है।

ये विचार वाकई सराहनीय हैं। लेकिन भारत में विदेशी संगठनों को प्रतिष्ठित स्थान देने का प्रभाव कहीं अधिक जटिल है और इस पर गहन विचार-विमर्श की आवश्यकता है।

स्वाति पीरामल भारत की अग्रणी उद्योगपतियों में से एक हैं। वह पीरामल एंटरप्राइजेज की उपाध्यक्ष हैं, जो स्वास्थ्य सेवा, दवा निर्माण और अनुसंधान उद्योगों में काम करने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। पीरामल फाउंडेशन की निदेशक के रूप में, वह ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में योगदान देती हैं और उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। उनके संपर्क काफी प्रभावशाली हैं:

डॉ. पीरामल के नेतृत्व में, पीरामल फाउंडेशन की पहल केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ नीति आयोग, रॉकफेलर फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसे कई अन्य संगठनों के सहयोग से समन्वित रूप से कार्य करती है।

पिरामल कहते हैं: 'हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ (एचएसपीएच) के पास व्यापक वैश्विक अनुभव है जो भारत की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए नवीन समाधान खोजने हेतु प्रौद्योगिकी और कौशल दोनों प्रदान कर सकता है। एचएसपीएच की मदद से हम न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में लाखों लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकेंगे।

हार्वर्ड चान इंडिया रिसर्च सेंटर के प्रमुख कासिसोमयाजुला 'विश' विश्वनाथ हैं, जो चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में स्वास्थ्य संचार के प्रोफेसर हैं। उन्होंने पीरामल के दान को 'परिवर्तनकारी' बताया। उनका मानना था कि मुंबई स्थित यह केंद्र भारत में और अधिक विस्तार के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होगा।

मुंबई में यह नया स्थान मिलने से एचएसपीएच को मुंबई और पूरे भारत में स्कूल की गतिविधियों को सुगम बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच मिलेगा। ...वहां भौतिक उपस्थिति होने से सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों से संबंधित अनुसंधान, प्रशिक्षण, अनुवाद और संचार सहित कई क्षेत्रों में हमारे काम को समर्थन मिलेगा।

भारत में केंद्र का चल रहा कार्य सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े कई मुद्दों पर परियोजनाओं को शामिल करता है, जिन्हें हर कोई सराहनीय मानेगा। आखिरकार, आवश्यकता इतनी गंभीर है और भारतीय सरकार की वर्तमान क्षमता से कहीं अधिक है। इस स्थिति में, मानवीय सहायता किसी भी स्रोत से आए, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। हालांकि, विश्वनाथ की रणनीतियां भारत की जनता को तत्काल राहत प्रदान करने से कहीं

आगे जाती हैं। उन्हें उम्मीद है कि यह नया केंद्र चान स्कूल द्वारा कई गतिविधियों को बढ़ावा देगा - जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य नेताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य के विभिन्न विषयों पर कार्यशालाएं आयोजित करना और भारत में शोध या इंटर्नशिप कर रहे छात्रों के लिए एक आधार प्रदान करना।

विश्वनाथ, चान स्कूल के एक अन्य केंद्र का नेतृत्व करते हैं। वे चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में ली कुम शेउंग सेंटर फॉर हेल्थ एंड हैप्पीनेस के सह-निदेशक हैं। इस केंद्र की स्थापना एक अन्य चीनी अरबपति परिवार ने की थी, जिसकी चीन में पुरानी जड़ें हैं। इसका मुख्य उद्देश्य खुशी जैसी मानसिक अवस्थाओं के मॉडल विकसित करने के लिए अनुसंधान करना है। यह केंद्र भारत में स्वास्थ्य और आनुवंशिकी से संबंधित संवेदनशील डेटा एकत्र करने के लिए अच्छी स्थिति में है, जो मानसिक व्यवहार पर एल्गोरिदम को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोगी होगा। इससे भविष्य की कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों को यह सिखाया जा सकेगा कि भारतीय लोगों की भावनाओं और मनोदशाओं को विशिष्ट रूप से कैसे प्रभावित किया जाए।

हार्वर्ड टी.एच. चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ इंडिया रिसर्च सेंटर भारत में हार्वर्ड की व्यापक उपस्थिति का एक हिस्सा है। यह हार्वर्ड ग्लोबल रिसर्च सपोर्ट सेंटर इंडिया के साथ मिलकर काम करता है, जिसे 'एक सामाजिक प्रभाव संगठन' के रूप में वर्णित किया गया है, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी और जो मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है। भारत में एक विस्तृत नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है, जिनमें से कुछ सीधे हार्वर्ड के नाम से जुड़े हैं, और अन्य विभिन्न संस्थानों के तत्वावधान में सहयोग के माध्यम से काम कर रहे हैं।

भारत अनुसंधान केंद्र का कहना है कि इसका उद्देश्य भारत भर के

संगठनों के साथ नए रणनीतिक संबंध विकसित करने और मौजूदा संबंधों को मजबूत बनाने में मदद करना है। यह केंद्र भारत में संकाय सदस्यों, छात्रों और उनके सहयोगियों द्वारा पहले से ही किए जा रहे अनुसंधान, शिक्षण, ज्ञान के आदान-प्रदान और संचार के रणनीतिक लक्ष्यों के लिए रसद संबंधी सहायता प्रदान करता है। साथ ही, यह भविष्य में इन गतिविधियों का विस्तार करने और नई परियोजनाएं शुरू करने के अवसर भी प्रदान करता है।

विश्वनाथ के साथ उनकी सहायक निदेशक अनन्या अवस्थी हैं, जिन्होंने हार्वर्ड के चान इंस्टीट्यूट से डिग्री प्राप्त की है। वे अपने कार्यक्षेत्र को 'सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के विकास में सहयोग हेतु सरकार, गैर-सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के अंतर्संबंध' के रूप में वर्णित करती हैं। उन्होंने अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब (जे-पाल) में भी काम किया है, जिसकी 'ब्रेकिंग इंडिया' गतिविधियों पर भाग 3 में चर्चा की जाएगी। केंद्र की सलाहकार परिषद में हार्वर्ड के चान इंस्टीट्यूट, जे-पाल और मैकिन्से जैसे संस्थानों से प्रशिक्षित लोग, साथ ही भारत के गैर-सरकारी संगठन तंत्र और विभिन्न सरकारी विभागों से रणनीतिक संबंध रखने वाले लोग शामिल हैं।

हार्वर्ड चान इंडिया रिसर्च सेंटर ने अपने सहयोगी और विकास साझेदारों में कई प्रभावशाली संगठनों को सूचीबद्ध किया है: टाटा ट्रस्ट्स, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज, नरोत्तम सेखसरिया फाउंडेशन (अंबुजा सीमेंट), यूनिसेफ, यूएन-इंडिया बिजनेस फोरम, इत्यादि। पीरामल परिवार के अलावा, मुंबई के अन्य प्रतिष्ठित उद्योगपतियों ने भी दानदाताओं के रूप में योगदान दिया है।

इसकी विशाल महत्वाकांक्षा और रुचियों के व्यापक दायरे को समझने के लिए, सबसे पहले भारत की वर्तमान स्थिति के इसके विश्लेषण को समझना आवश्यक है। हार्वर्ड चान इंडिया रिसर्च सेंटर बताता है:

गरीब और अमीर राज्यों के बीच स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में असमानताएं हैं, और कई मामलों में अपर्याप्त वित्त पोषण वाली स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियां अक्षमतापूर्वक संचालित और अनियमित हैं। ... सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य प्रणालियां असाधारण स्वास्थ्य नेताओं और पेशेवरों को प्रशिक्षित करने की देश की क्षमता पर भारी दबाव डाल रही हैं। ... हार्वर्ड टी.एच. चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत भर में साझेदारों के साथ सहयोग कर रहा है।

इसमें भारत में अनुसंधान, प्रशिक्षण और ज्ञान प्रसार के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली एक महत्वाकांक्षी रणनीति का उल्लेख किया गया है। इसमें निम्नलिखित गतिविधियों की योजना है:[35]

हार्वर्ड को भारत में उच्चतम स्तर पर स्थानीय संपर्कों तक पहुंच प्रदान करना।

नीतियों को आकार देने के लिए सम्मेलनों और कार्यशालाओं का आयोजन करना।

मानवाधिकार सहित विभिन्न क्षेत्रों में सक्रियता के नेटवर्क स्थापित करना (जिसे हार्वर्ड 'शिक्षा' कहता है)।

राज्य और केंद्र सरकारों के साथ-साथ निजी क्षेत्र में जन स्वास्थ्य नेताओं, शोधकर्ताओं और प्रबंधकों को प्रशिक्षण देना। जन स्वास्थ्य नेताओं की भावी पीढ़ियों को शिक्षित करना।

स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान सहयोग विकसित करने के लिए संपर्क स्थापित करना, तकनीकी मंच उपलब्ध कराना, रसद की सुविधा प्रदान

करना, धनी भारतीयों को संभावित दानदाताओं के रूप में तैयार करना और भारत में हार्वर्ड के क्षेत्र भ्रमण की सुविधा प्रदान करना।
भारत में जनसंख्या और प्राथमिक स्वास्थ्य परियोजनाओं के डेटाबेस विकसित करना।
हार्वर्ड के शोध परिणामों को भारत में लागू करने के लिए उनका अनुवाद करना। हार्वर्ड चान स्कूल द्वारा विकसित नवीनतम तकनीकों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिकित्सकों, शोधकर्ताओं और नेताओं की क्षमता का निर्माण करना।
हार्वर्ड एडएक्स शिक्षा मंच का उपयोग करते हुए, हार्वर्ड चान स्कूल ने भारत के लगभग दो हजार व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं।
केंद्र की वेबसाइट पर इसकी महत्वाकांक्षाओं की घोषणा की गई है और यह बताया गया है कि इसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से धनराशि प्राप्त हुई है:
इस परियोजना का उद्देश्य हार्वर्ड चान स्कूल इंडिया रिसर्च सेंटर को भारत में प्रमुख जन स्वास्थ्य मामलों पर नवीनतम जानकारी एकत्र करने और प्रसारित करने का एक सर्वव्यापी केंद्र बनाना है। इसमें जन स्वास्थ्य विषयों पर जनता, गैर-लाभकारी संगठनों और मीडिया से नवीनतम तथ्य प्राप्त करने के लिए एक डैशबोर्ड सहित एक व्यापक डेटाबेस का निर्माण करना और हार्वर्ड सिस्टम को प्रमुख हितधारकों के रूप में स्थापित करना शामिल है। प्रस्तावित डेटा पोर्टल, जिसे संचार कहा जाता है, पहले ही अपने प्रारंभिक चरण में लॉन्च किया जा चुका है और इसे https://projectsanchar.org/ पर देखा जा सकता है।
अधिक से अधिक डेटा एकत्रित करने के उद्देश्य से, इंडिया सेंटर, हार्वर्ड के जॉन ए. पॉलसन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड एप्लाइड साइंसेज के साथ

मिलकर भारतीय संगठनों को हार्वर्ड के साथ साझेदारी करने में सहयोग कर रहा है। उदाहरण के लिए, वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हार्वर्ड चान सेंटर ने स्वास्थ्य संबंधी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक कार्यशाला का आयोजन किया।
पिरामल हार्वर्ड में अपनी उपस्थिति का उपयोग अन्य अमेरिकी विश्वविद्यालयों में भी विस्तार करने के लिए कर रहा है। 2019 में, पिरामल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन लीडरशिप (पीएफईएल) ने अटलांटा स्थित एमोरी विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और सरकारी अधिकारियों सहित शिक्षाविदों की क्षमता का निर्माण करना है, ताकि भारत भर के सरकारी स्कूलों में 'सामाजिक भावनात्मक नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम' लागू किया जा सके। पिरामल दो वर्षों की अवधि में गुजरात, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र और राजस्थान के पांच हजार सरकारी स्कूलों में इस पाठ्यक्रम का प्रायोगिक परीक्षण करेगा, जिससे पांच लाख बच्चों को लाभ होगा। यह कार्य सराहनीय है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय स्कूलों में 'भावनात्मक और नैतिक शिक्षा' के लिए एक पाठ्यक्रम अमेरिका में विकसित किया जाना चाहिए, जिसकी संस्कृति भारत से बहुत अलग है और जहां भावनात्मक और नैतिक मुद्दे भी भारत से भिन्न हैं।

चिंताएँ

उपरोक्त सारांश से यह स्पष्ट है कि हार्वर्ड स्थित चीनी नियंत्रण वाले चान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ ने भारत के धनी और प्रसिद्ध लोगों की मदद से भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है।
द क्रिमसन ने लिखा कि पिरामल के दान से कई समस्याएं हल हो गईं,

लेकिन फिर भी उसने 'जहां भी संभव हो' और अधिक दान की तलाश जारी रखी।[38] चान-पिरामल इंडिया सेंटर को कई अन्य भारतीय दिग्गजों से भी धन प्राप्त हुआ, जिनमें रति और नादिर गोदरेज, अनुपा और राजीव साहनी, नरोत्तम सेखसरिया फाउंडेशन की पद्मिनी सोमानी, मिंटू भंडारी, टाटा ट्रस्ट्स और अपोलो हॉस्पिटल्स की सुनीता रेड्डी शामिल हैं, जिन्होंने भारत में हार्वर्ड टी.एच. चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ को समर्थन दिया है और बड़ी मात्रा में धन दान किया है।[39]

भारत को किसी भी विदेशी पहल की निरंतर गहन जांच-पड़ताल करने की आवश्यकता है जो ज्ञान और डेटाबेस का दोहन करती है और सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव और निर्भरता लाती है। भारत उचित समझ के बिना ज्ञान का निर्यात कर रहा है, जिसे पश्चिम और चीन आत्मसात कर रहे हैं। यह आयुर्वेद जैसी अपनी स्वदेशी प्रणालियों को जड़ से उखाड़ फेंकने की कीमत पर पश्चिमी शैली की सार्वजनिक स्वास्थ्य पद्धतियों का आयात कर रहा है।

सूचना प्रवाह की इस कड़ी के एक छोर पर चीन है, मध्य में हार्वर्ड टी.एच. चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ है, और दूसरे छोर पर भारत में पीरामल की मौजूदगी है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत ने रॉनी चान के सीसीपी कनेक्शन और हार्वर्ड स्थित अपने संस्थान को भारत में प्रवेश देने के परिणामों की जांच में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि हाल के दिनों में, कुछ हार्वर्ड विद्वानों को चीन से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, और अमेरिकी अधिकारियों और मीडिया ने चीन की उपस्थिति से संबंधित गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों को उजागर किया है। इस पर और अधिक जांच होनी चाहिए।

अगले पृष्ठ पर दिया गया आरेख उन प्रमुख संबंधों का सारांश प्रस्तुत करता है जिन पर हमने चर्चा की है।

अमेरिका ने इन समस्याओं का समाधान करना और अपने हितों की रक्षा करना शुरू कर दिया है। लेकिन भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की उसे क्या परवाह है, जबकि यह मामला तो भारत के ही प्रतिष्ठित व्यक्तियों का है?

भारतीय अरबपतियों का समर्थन हार्वर्ड को भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में पैठ बनाने और अल्पसंख्यकों, सामाजिक न्याय आदि के नाम पर उसकी सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों पर दबाव डालने में मदद करता है। इससे सामाजिक न्याय के एजेंडे को आगे बढ़ाने का रास्ता खुलता है, जिससे भारत को तोड़ने वाली ताकतों को फायदा होता है। भारत हार्वर्ड को विश्व गुरु बनने देने के नकारात्मक पहलुओं के प्रति उदासीन प्रतीत होता है, जो दुनिया को इतने सारे रणनीतिक क्षेत्रों में ज्ञान प्रदान करता है।

जिन नकारात्मक विषयों पर चर्चा हो रही है, उनसे कहीं अधिक चिंताजनक वे बातें हैं जिन पर बात नहीं हो रही है। उदाहरण के लिए, कोविड-19 महामारी ने भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी सफलताओं के प्रति पश्चिमी देशों के पूर्वाग्रह को उजागर कर दिया। प्रति व्यक्ति बहुत कम लागत पर महामारी को नियंत्रित करने में भारत की अभूतपूर्व उपलब्धि को पश्चिम में पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। हार्वर्ड में विभिन्न वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन इसे पश्चिमी और चीनी चिकित्सा प्रणालियों के लिए खतरा माना जाता है। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के प्रबंधन और गरीब देशों को टीके दान करने में भारत की मदद के लिए भी उसे उचित श्रेय नहीं मिला।

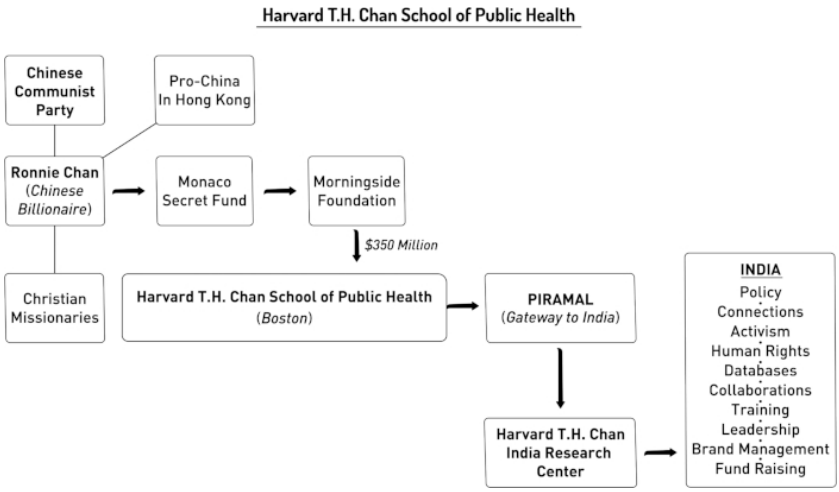

इसके अलावा, भारत का फार्मा उद्योग दवा खोज से पूरी तरह से अलग-थलग रहा है और उसे केवल जेनेरिक विकल्प उपलब्ध कराने तक ही सीमित रखा गया है। पीरामल को सलाह देना हमारा काम नहीं है, लेकिन हम यह बताना चाहते हैं कि वे हार्वर्ड के प्रभाव का इस्तेमाल करके अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से पैरवी कर सकते हैं ताकि भारत को उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल किया जा सके जिनकी मौलिक दवा खोजें विश्व स्तर पर स्वीकार्य हो जाती हैं। इससे भी आगे बढ़कर आयुर्वेद को विश्व मानचित्र पर कम से कम चीनी चिकित्सा के बराबर स्थान दिलाया जा सकता है।
सतह के नीचे देखने पर निम्नलिखित तस्वीर सामने आती है:
चीन अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित करता है और इसे व्यापक रूप से फैलाने के लिए हार्वर्ड का उपयोग करता है, जबकि भारत ने अपने दृष्टिकोण को हार्वर्ड को सौंप दिया है और अपने नेताओं को प्रशिक्षण के लिए वहां भेज रहा है। चीन हार्वर्ड का उपयोग अमेरिका में 'वोके' और 'क्रिटिकल रेस थ्योरी' का समर्थन करने के लिए भी करता है, जिससे अमेरिका में व्यवधान उत्पन्न होता है।

चीन भारत में सांस्कृतिक और बौद्धिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए टी.एच. चान केंद्र का उपयोग कर रहा है।
साथ ही, हार्वर्ड योग, ध्यान और आयुर्वेद जैसी भारतीय चिकित्सा प्रणालियों पर गहन शोध और अध्ययन में संलग्न है। इन्फिनिटी फाउंडेशन इन मामलों का दस्तावेजीकरण कर रहा है, और इस अध्ययन का संक्षिप्त सारांश अध्याय 7 में दिया गया है।
हमारी चिंता यह है कि भारत को तोड़ने वाली ताकतें देश की मदद करने के बहाने सामान्य स्थिति में आ सकती हैं। हम आशा करते हैं कि भारत के उद्योगपति स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भारतीय ज्ञान को आत्मसात करने की उसी तरह जांच करेंगे, जिस तरह चीनी उद्योगपतियों और सरकार ने चीनी चिकित्सा को एक विशाल निर्यात उद्योग में बदल दिया है।

14. भारत में मीडिया व्यवस्था पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय का नियंत्रण

अवलोकन
हार्वर्ड के विद्वानों ने भारत के अध्ययन में विविध भूमिकाएँ निभाई हैं: भारतीय परंपराओं के मूल्यवान पहलुओं को आत्मसात करना; भारत को उन अन्य एशियाई देशों के साथ मिलाकर उसकी स्थिति को कमजोर करना जो उसकी सभ्यतागत विरासत और विश्वदृष्टि को साझा नहीं करते; व्यवस्थित रूप से ऐसे आख्यानों का निर्माण करना जिन्हें केवल अत्याचार साहित्य के रूप में देखा जा सकता है; भारत के इतिहास और परंपराओं की ऐसी व्याख्या करना जो भारत के अपने वृत्तांतों और अनुभवों के अनुरूप नहीं है; हार्वर्ड के नियंत्रण में सूचनाओं के डेटाबेस का निर्माण

करना जिनका उपयोग उसके एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है; और अपने मूल्यों के अनुसार भारत के अभिजात वर्ग को कुशलतापूर्वक गढ़ना।

अपनी सामग्री के वितरण के एजेंडे के तहत, हार्वर्ड का लक्ष्य भारत के मीडिया तंत्र को नियंत्रित करना है। दूसरे शब्दों में, केवल अपने विचार प्रकट करना ही पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त, उन खबरों को दबाने, उनका उपहास उड़ाने, उन्हें हटाने, नियंत्रित करने या पूरी तरह से कुचलने के लिए उपयुक्त तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए जो उसके नियंत्रण से बाहर हैं और उसके विचारों से मेल नहीं खाती हैं। इसके अलावा, भारतीय मीडिया पर नियंत्रण का दोहरा उद्देश्य है। प्रायोजित मीडिया आउटलेट हार्वर्ड के मुखपत्र के रूप में कार्य करते हैं; और पक्षपातपूर्ण/ विभाजनकारी विचारों के विरुद्ध भारतीय सरकार की कार्रवाई का उपयोग 'तानाशाही' के बारे में कहानियां गढ़ने के लिए किया जा सकता है। लेकिन हार्वर्ड इससे कहीं आगे जाता है।

इसके पास इतना प्रभाव है कि यह अपनी चुनी हुई बातों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करवाकर युवा दिमागों को प्रभावित कर सकता है। जब आप इस अकादमिक शक्ति केंद्र में चीन की घुसपैठ पर विचार करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अमेरिका में, यह शक्ति भारतीयों को स्कूलों में बढ़ते भेदभाव का शिकार बना रही है, जहां उन पर जातिगत पहचान थोपी जा रही है। भारत में, इसके अपने कमजोर नागरिक हार्वर्ड के हाथों में खेल रहे हैं, क्योंकि वे सत्ता के बड़े दांव-पेच से अनजान या उन्हें समझ से परे हैं।

हार्वर्ड और उससे संबंधित कई संस्थानों ने भारत के विभिन्न पहलुओं पर सार्वजनिक डेटा एकत्र करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है और इस डेटा को भविष्य की पाठ्यपुस्तकों के लिए सामग्री के रूप में पहले से ही प्रचारित

किया जा रहा है। इन अभिलेखों का आर्थिक महत्व भी बहुत अधिक है और इनमें मौजूद विस्तृत जानकारी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय बनाती है।

हार्वर्ड ने भारत के अरबपतियों की मदद से स्थापित बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए अपने विचारों को प्रसारित और नियंत्रित करने के लिए एक विशाल तंत्र का निर्माण किया है। हार्वर्ड के ऐसे ही वितरण चैनलों में से एक है नीमन फाउंडेशन ऑफ जर्नलिज्म, जिसके पास अन्य गैर-लाभकारी संगठनों का एक व्यापक नेटवर्क है जो पत्रकारिता जगत को नियंत्रित करता है।

नीमन फाउंडेशन की स्थापना 1938 में हुई थी और यह विश्वभर के पत्रकारों को हार्वर्ड में एक वर्ष के अध्ययन, सेमिनार और विशेष कार्यक्रमों के लिए फैलोशिप प्रदान करता है। भारत के संदर्भ में, नीमन फाउंडेशन 2019 के बाद से भारतीय पत्रकारों को अनुदान देने में विशेष रूप से सक्रिय है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारी जीत के साथ मेल खाता है। नीमन फाउंडेशन निम्नलिखित परियोजनाओं का भी संचालन करता है: [1]

नीमन वॉचडॉग प्रोजेक्ट: एक वेबसाइट जो पत्रकारों को सार्वजनिक जीवन में सत्ता का प्रयोग करने वाले सभी लोगों की निगरानी करने और उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए प्रोत्साहित करती है।

नीमन रिपोर्ट्स: यह एक ऐसा मंच है जहां इसके फेलो अपने काम को प्रकाशित कर सकते हैं।

नीमनलैब: डिजिटल युग में प्रभावी पत्रकारिता और सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए अनुसंधान शाखा।

नीमन स्टोरीबोर्ड: कथात्मक शैली की पत्रकारिता के लिए एक वेबसाइट।

नीमन-पुलित्जर सेंटर एलायंस

नीमन फाउंडेशन की पहलों में से एक है संकटकालीन रिपोर्टिंग पर संयुक्त रूप से काम करने के लिए पुलित्जर सेंटर ऑन क्राइसिस रिपोर्टिंग ('पुलित्जर सेंटर') के साथ उसका रणनीतिक गठबंधन। वाशिंगटन डी.सी. स्थित पुलित्जर सेंटर पत्रकारों को दुनिया भर में उन कहानियों को लिखने के लिए अनुदान देता है जिन्हें वह कम रिपोर्ट किया गया मानता है। हालांकि दोनों एक ही परिवार से संबंधित हैं लेकिन अलग-अलग कानूनी संस्थाएं हैं, फिर भी इसे पुलित्जर पुरस्कारों के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। बेशक, कई नीमन फेलो पुलित्जर पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी हैं।

यह पहल हार्वर्ड के उस नियंत्रण को मजबूत करती है जिसके तहत विश्व स्तर पर उन खबरों को प्रकाशित किया जाता है जिन्हें हार्वर्ड 'कम प्रतिनिधित्व वाली अंतरराष्ट्रीय खबरें' मानता है:

नीमन और पुलित्जर सेंटर के बीच यह साझेदारी पुलित्जर सेंटर के पत्रकारों को हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम चर्चित खबरों पर प्रस्तुतियों और चर्चाओं के लिए लाएगी और नीमन फेलो के लिए एक वार्षिक कार्यशाला का आयोजन करेगी जिसमें मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म का प्रभावी ढंग से उपयोग करने, समाचारों को मीडिया में अधिकतम प्रभाव के लिए प्रस्तुत करने और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों में जनता को शामिल करने के लिए सोशल मीडिया, शैक्षिक नेटवर्क और अन्य तकनीकों का उपयोग करने की सेंटर की नवोन्मेषी रणनीतियों का पता लगाया जाएगा।

औपचारिक समझौते की समाप्ति के बाद भी दोनों संगठनों के बीच घनिष्ठ संबंध और मजबूत हुए हैं। उदाहरण के लिए, "अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग को हिंदू राष्ट्रवाद को हिंदू धर्म से अलग करना चाहिए" शीर्षक वाली एक

रिपोर्ट पुलित्जर सेंटर के सहयोग से नीमन रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित हुई थी।

पुलित्जर सेंटर पत्रकारों को विशिष्ट विषयों पर लिखने के लिए वित्तीय सहायता देने के अलावा, उनकी कहानियों को विभिन्न मीडिया आउटलेट्स में प्रकाशित करवाने में भी मदद करता है और यह सुनिश्चित करना चाहता है कि ये कहानियाँ युवा पीढ़ी तक पहुँचें। यह विश्वभर के संस्थानों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करके और कक्षा में चर्चा आयोजित करने वाले शिक्षकों के लिए दिशानिर्देश तैयार करके शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्र निम्नलिखित उपलब्धियों का दावा करता है:

यह सभी प्रकार के पत्रकारों की सहायता करता है: फ्रीलांसर पत्रकार, जिन पर निर्भरता बढ़ती जा रही है और जिनका शोषण भी हो रहा है क्योंकि कई पूर्ण-सेवा वाले विदेशी ब्यूरो गायब हो रहे हैं; और प्रसिद्ध संगठन, जैसे कि द न्यूयॉर्क टाइम्स, द न्यू यॉर्कर और पीबीएस न्यूजऑवर, जिन्हें अपनी सबसे महत्वाकांक्षी पत्रकारिता करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होती है।

इसका अंतिम परिणाम एक प्रभावशाली, 10 वर्षीय विरासत रहा है जिसमें वाशिंगटन स्थित इस गैर-लाभकारी संस्था ने 715 अलग-अलग परियोजनाओं का समर्थन किया है, विभिन्न माध्यमों में कुल 6,168 कहानियों का प्रकाशन किया है और 571 प्रकाशन भागीदारों के साथ काम किया है।

इसका व्यापक प्रसार प्रभावशाली है। इसमें कैंपस कंसोर्टियम के 31 सदस्य हैं, जिनमें शिकागो विश्वविद्यालय और विलियम एंड मैरी कॉलेज जैसे उदार कला संस्थान, नॉर्थवेस्टर्न के मेडिल और अमेरिकन यूनिवर्सिटी जैसे पत्रकारिता स्नातक स्कूल, और जॉन्स हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल

ऑफ पब्लिक हेल्थ और येल स्कूल ऑफ फॉरेस्ट्री एंड एनवायरनमेंटल स्टडीज में जलवायु परिवर्तन जैसे विशिष्ट साझेदार शामिल हैं।
यह सेंट लुइस, शिकागो, वाशिंगटन, फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के साथ-साथ सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र और बोस्टन में भी काम करता है, और उत्तरी कैरोलिना के विंस्टन-सलेम में न्यूज़आर्ट्स पहल (समाचार और कला के अंतर्संबंध की खोज) के माध्यम से भी कार्य करता है। इसके बारे में अधिक जानकारी इसकी वेबसाइट के शिक्षा पृष्ठ पर उपलब्ध है।
पुलित्जर सेंटर अक्सर ऐसी कहानियाँ प्रकाशित करवाता है जिन्हें वह विशिष्ट पत्रकारों को प्रचारित करने के लिए सौंपना चाहता है। ऐसी ही एक कहानी 2014 में नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक चुनावी जीत के बाद नमामि गंगा परियोजना पर थी। यह कहानी द न्यू यॉर्कर द्वारा प्रकाशित करने के लिए तैयार की गई थी। इसका उद्देश्य गंगा सफाई परियोजना को पर्यावरण संबंधी मुद्दों को राजनीति और धर्म की चर्चा में बदलने के लिए एक माध्यम के रूप में उपयोग करना था। इस कहानी पर काम करने वाले पत्रकार जॉर्ज ब्लैक बताते हैं कि इस तरह का एजेंडा कैसे काम करता है:
लगभग एक साल पहले 'द न्यू यॉर्कर' ने मुझसे संपर्क किया और सुझाव दिया कि मैं गंगा नदी पर एक लेख लिखने में रुचि रख सकता हूँ, और मैंने हाँ कह दी। हमने इस बात पर चर्चा की कि लेख किस प्रकार का होना चाहिए। हम चाहते थे कि उसमें बहुत रंग हो क्योंकि यह एक बेहद रंगीन कहानी है - इसमें शानदार स्थान हैं, सशक्त पात्र हैं और... इस रहस्य को सुलझाने का एक अच्छा तरीका है, लोग; फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैं वास्तव में यह हल कर सकता हूँ कि 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन हैं'; ... उनकी छवि एक हिंदू कट्टरपंथी के रूप में रही है, वे गुजरात में कुछ घिनौनी घटनाओं में शामिल रहे हैं, और ... भारत की आर्थिक

समस्याओं को हल करने का वादा करके सत्ता में आए थे। वे सरकार में भ्रष्टाचार को खत्म करने वाले थे, वे एक आर्थिक शक्ति के रूप में चीन से प्रतिस्पर्धा करने वाले थे, वे प्रौद्योगिकी के बहुत समर्थक थे, उन्हें सोशल मीडिया बहुत पसंद था, तो आपके पास ये दो छवियाँ हैं और मुझे याद है कि दो साल पहले चुनाव के समय, 'द इकोनॉमिस्ट' पत्रिका के कवर पर उन्हें (मोदी को) बहुत ही खतरनाक रूप में चित्रित किया गया था। संपादकीय में मूल रूप से कहा गया था कि 'इस आदमी को कभी निर्वाचित नहीं होना चाहिए, यह बहुत खतरनाक है, इसे 10 वर्षों तक अमेरिकी वीजा नहीं दिया गया और फिर उस खबर के छह सप्ताह बाद ही इसने चुनाव जीत लिया...' और फिर वही (मोदी) कवर पेज पर हैं, उन्होंने सफेद कपड़े पहने हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान है और ऐसा लगता है जैसे वे भारत के रक्षक हों। इसलिए, मुझे लगा कि गंगा सफाई अभियान की कहानी इस बात को समझने का एक अच्छा तरीका है। क्या वह एक हैं, क्या वह दूसरे हैं, या क्या वह दोनों हैं? और मुझे लगता है कि अंत में मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह दोनों हैं।

स्पष्ट रूप से, इसे एक सुस्पष्ट पूर्वाग्रह के साथ तैयार करवाया गया था, लेकिन छात्रों के सामने इसे स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

पुलित्जर सेंटर को स्वयं कई वामपंथी धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, जिनमें ओमिडयार नेटवर्क, फेसबुक का मेटा जर्नलिज्म प्रोजेक्ट, रॉकफेलर फाउंडेशन, गेट्स फाउंडेशन और स्टेनली फाउंडेशन शामिल हैं।

पुलित्जर सेंटर को प्राथमिक सहयोग एमिली राउह पुलित्जर, एमिली राउह पुलित्जर फाउंडेशन, डेविड और कैथरीन मूर फैमिली फाउंडेशन, बारबरा और रिचर्ड मूर, न्यूयॉर्क कम्युनिटी ट्रस्ट - डेबोरा डब्ल्यू और

टिमोथी पी मूर फंड, एल्खाना पुलित्जर, जोसेफ पुलित्जर पंचम, माइकल पुलित्जर सीनियर, डिएर्ड्रे और पीटर क्वेसाडा, विलियम बुश, क्रेगलिस्ट चैरिटेबल फंड, जॉन डी और कैथरीन टी मैकआर्थर फाउंडेशन, ट्रेलिस चैरिटेबल फंड, अर्नोल्ड वेंचर्स, ओमिडयार नेटवर्क, ह्यूमैनिटी यूनाइटेड, हेनरी एल किमेलमैन फाउंडेशन, पोक्लोन फाउंडेशन, फोर रिवर फाउंडेशन, हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन (एचएफपीए) और केंडेडा फंड से प्राप्त हुआ है।

पुलित्जर सेंटर के राजनीतिक हस्तक्षेपों को समझने के लिए, न्यूयॉर्क टाइम्स के 1619 प्रोजेक्ट के लिए कक्षा पाठ्यक्रम तैयार करने का यह चर्चित प्रोजेक्ट एक अच्छा उदाहरण है। इस प्रोजेक्ट ने अमेरिका में विवाद खड़ा कर दिया है। इतिहास के इस संशोधित विवरण से सहमत हों या असहमत, यह बात मायने नहीं रखती। हम यहाँ पुलित्जर सेंटर की किसी भी राष्ट्र के बारे में एक व्यापक कथा गढ़ने और उसे शिक्षा प्रणाली में स्थापित करने की शक्ति को उजागर कर रहे हैं। उपरोक्त उदाहरण में, सेंटर ने 1619 प्रोजेक्ट के लिए स्कूल पाठ्यक्रम तैयार किया और पठन मार्गदर्शिकाएँ, पाठ योजनाएँ और अतिरिक्त गतिविधियाँ प्रकाशित कीं। यह पाठ्यक्रम सभी 50 राज्यों के 3,500 से अधिक कक्षाओं में लागू किया जा चुका है। शिकागो और वाशिंगटन डी.सी. सहित पांच स्कूल जिलों ने इसे अनिवार्य कर दिया है। केंद्र ने 1619 प्रोजेक्ट के पत्रिका संस्करण की 5,600 प्रतियां बफ़ेलो पब्लिक स्कूलों को दान कीं, जहां यह अनिवार्य पाठ्यक्रम का हिस्सा है; यह ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के सभी छात्रों को मुफ्त प्रतियां वितरित करने के लिए पर्याप्त है।

अमेरिका के संस्थापक पिताओं पर हमले करने वाले विवादास्पद दावों के बावजूद, बहस का केवल एक पक्ष ही प्रस्तुत किया गया। हालांकि, अमेरिका के मामले में, पुलित्जर सेंटर के काम का मुकाबला करने के

लिए एक सुव्यवस्थित और परिष्कृत तंत्र मौजूद है। भारत में पाठ्यक्रम के आउटसोर्स होने के मामले में ऐसी कोई प्रतिवादिक आवाज नहीं है, जो पुलित्जर के प्रभाव को कहीं अधिक खतरनाक बना देती है।

नीमन इंस्टीट्यूट और पुलित्जर सेंटर द्वारा समर्थित भारतीय संगठन पुलित्जर सेंटर पत्रकारों को भारत में परियोजनाओं पर काम करने के लिए अनुदान देता है और फिर कश्मीर, पर्यावरण, वनवासी/अनुसूचित जनजातियों और भारत में सामाजिक और धार्मिक तनाव जैसे विषयों पर जोर देने वाले भारतीय मीडिया संस्थानों में उनके कार्यों को प्रकाशित करने में उनकी मदद करता है।
भारत में जिन मीडिया संस्थानों के साथ यह साझेदारी करता है, वे अच्छी तरह से वित्तपोषित हैं और उनके पास कई भाषाओं में अत्याधुनिक वेबसाइटें हैं। वे विशिष्ट जनसांख्यिकीय बाजारों और लक्षित मीडिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
सबरंग एक ऐसा ही संगठन है। इसका संचालन तीस्ता सेतलवाद और उनके पति जावेद आनंद करते हैं, जो सरकार की खुलेआम आलोचना करने और एक दशक से अधिक समय से भारतीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ टकराव के लिए जाने जाते हैं। 2010 में, सेतलवाद ने गुजरात और महाराष्ट्र के प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया, जिसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने 'विषाक्त' बताया। इस कार्यक्रम के तहत हजारों बच्चों को पढ़ाया गया।
2018 में, वह एक गबन घोटाले में फंस गईं और उन पर गैर सरकारी संगठन के फंड का अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया। 2021 में, उनके एक ट्रस्ट को कानून का उल्लंघन करते

हुए पाया गया क्योंकि उसने 'भारत में सांप्रदायिकता, जाति-आधारित भेदभाव से निपटने, जिसमें मीडिया रणनीतियाँ भी शामिल हैं' के लिए फोर्ड फाउंडेशन से अनुदान प्राप्त करने के लिए अवैध चैनलों का इस्तेमाल किया था।

केस स्टडी: पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी

पुलित्जर सेंटर से जुड़े मीडिया संस्थानों में से एक विशेष रूप से उल्लेखनीय है और हम इसका केस स्टडी के रूप में विश्लेषण करेंगे। यह है पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया (पीआरआई), जो सुनने में भले ही सौम्य लगे, लेकिन यह डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में व्याप्त असुरक्षा के स्तर को दर्शाता है।

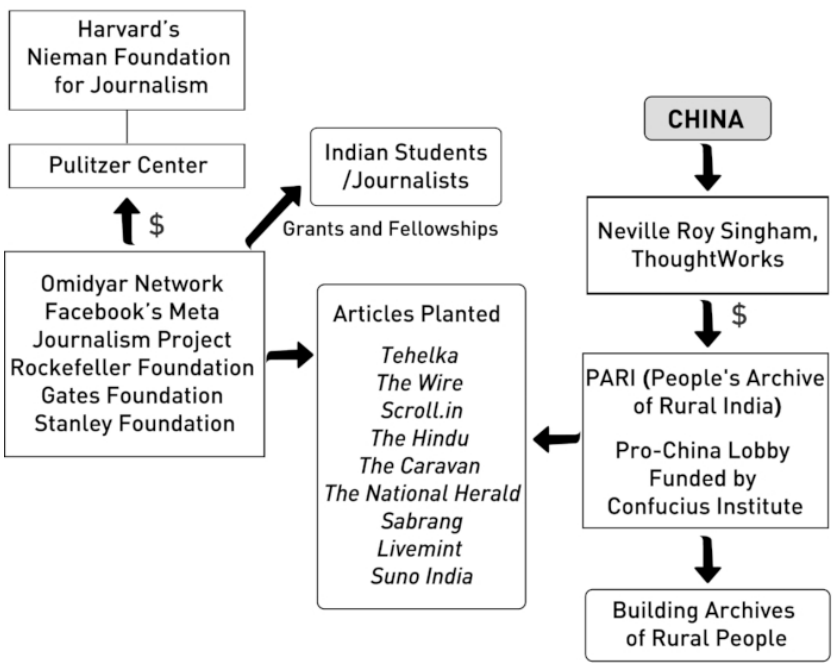

जैसा कि ऊपर दिए गए आरेख में दिखाया गया है, पीपुल्स आर्काइव फॉर रूरल इंडिया को पर्याप्त धन प्राप्त है और यह भारत के विविध लोगों, उनकी संस्कृति और समाज के बारे में फ़ोटो, वीडियो और लेखों के रूप में जानकारी एकत्र करने पर केंद्रित है। यह अभूतपूर्व पैमाने पर भारत के ग्रामीण समाजों का एक डेटाबेस संग्रह है। इसके प्रवक्ता कहते हैं, 'यह एक ऐसी परियोजना है जो कभी पूरी नहीं होगी और न ही कभी पूरी होनी चाहिए।' PARI की वेबसाइट पर लिखा है, 'हमारे लिए लिखें, हमारे लिए शूट करें, हमारे लिए रिकॉर्ड करें - आपकी सामग्री का स्वागत है, बशर्ते वह इस साइट के मानकों को पूरा करती हो और हमारे उद्देश्य के अंतर्गत आती हो: आम लोगों का रोज़मर्रा का जीवन।' आगे लिखा है:

PARI एक जीवंत पत्रिका और एक संग्रह दोनों है। यह ग्रामीण जीवन से संबंधित समसामयिक और वर्तमान खबरों को प्रकाशित और संग्रहित करेगा, साथ ही साथ यथासंभव अधिक से अधिक स्रोतों से प्रकाशित कहानियों, रिपोर्टों, वीडियो और ऑडियो का डेटाबेस भी तैयार करेगा। PARI की सभी सामग्री क्रिएटिव कॉमन्स के अंतर्गत आती है और साइट का उपयोग निःशुल्क है। PARI में कोई भी योगदान दे सकता है।

दान के लिए की गई अपील में कहा गया है:

PARI एक संसाधन अनुभाग भी बना रहा है, जहाँ हमारा उद्देश्य ग्रामीण भारत से संबंधित सभी आधिकारिक (और अनौपचारिक लेकिन विश्वसनीय) रिपोर्टों को (केवल लिंक के माध्यम से नहीं, बल्कि पूर्ण पाठ में) उपलब्ध कराना है। उदाहरण के लिए, असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग की प्रत्येक रिपोर्ट, योजना आयोग (अब NITI आयोग) और मंत्रालयों की रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र और अन्य कई रिपोर्टें। शोधकर्ताओं को महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों और अध्ययनों तक पहुँचने के लिए विभिन्न स्रोतों से कई साइटों पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

इस परियोजना का पैमाना चौंका देने वाला है। अभिलेखागार आम भारतीय नागरिकों के सामाजिक, व्यवहारिक और सांस्कृतिक ज्ञान के आधार की जानकारी प्रदान करेगा, जो कि जैसा कि हमने कई बार समझाया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिदम को प्रशिक्षित करने के लिए मूल्यवान है। यह न केवल एक मूल्यवान आर्थिक संपत्ति है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक खतरा है।

लगभग 60 महीनों के दौरान, PARI देश के हर हिस्से से आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर आधारित टेक्स्ट रिपोर्ट, ऑडियो कहानियां, वीडियो, डॉक्यूमेंट्री फिल्में, तस्वीरें, संगीत और 'टॉकिंग एल्बम' तैयार करेगा। यह डेटाबेस भारतीय जनता, विशेष रूप से 833 मिलियन ग्रामीण नागरिकों का सही प्रतिनिधित्व करेगा। इसमें उनके श्रम, शिल्प, कहानियां, गीत, कविताएं, कला और अन्य चीजें शामिल होंगी। हम जो फेलो नेटवर्क बनाएंगे, वह देश की सामाजिक संरचना को भी प्रतिबिंबित करेगा। लगभग 100 फेलो में से आधे महिलाएं होंगी। दलित पत्रकार, आदिवासी पत्रकार और अल्पसंख्यकों से आने वाले पत्रकारों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। कई कहानियां सीधे आम लोगों द्वारा ही सुनाई जाएंगी। अन्य उपलब्धियों के साथ-साथ, यह छात्रों की पीढ़ियों, हमारे सभी बच्चों को, उनके आसपास की दुनिया पर जीवंत पाठ्यपुस्तकें प्रदान करेगा। और राष्ट्र को एक ऐसा भंडार देगा जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा।

यह थॉटवर्क्स के संस्थापक-अध्यक्ष, व्यवसायी और कार्यकर्ता नेविल रॉय सिंघम का विचार है। थॉटवर्क्स को बेचने के बाद, सिंघम ने पूर्णकालिक रूप से सक्रियता में कदम रखा। हाल ही में, प्रवर्तन निदेशालय की जांच में आरोप लगाया गया है कि सिंघम के सीसीपी और उसके प्रचार विंग के साथ गहरे संबंध हैं। दिलचस्प बात यह है कि सिंघम अन्य मीडिया

कंपनियों में भी पैसा लगाने में रुचि रखते हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मीडिया पोर्टल न्यूजक्लिक और उसके प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में श्रीलंका-क्यूबा मूल के व्यवसायी नेविल रॉय सिंघम के साथ उनके वित्तीय लेन-देन पर ध्यान केंद्रित हुआ है। जांचकर्ताओं ने सिंघम को पीपीके न्यूजक्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड को 2018 से 2021 के बीच विदेश से प्राप्त 38 करोड़ रुपये का मुख्य स्रोत बताया है। एजेंसी के सूत्रों ने, जो मीडिया आउटलेट को प्राप्त धन के प्रवाह का विश्लेषण कर रहे हैं, आरोप लगाया है कि सिंघम का संबंध चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के प्रचार तंत्र से था।
फरवरी 2021 में, प्रवर्तन निदेशालय ने न्यूज़क्लिक से जुड़े कई अधिकारियों और पत्रकारों के परिसरों और आवासों पर छापा मारा था। न्यूज़क्लिक एक समाचार मीडिया पोर्टल है जो फर्जी खबरें फैलाने के लिए कुख्यात है। अधिकारियों ने विदेशी फंडिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्था के घर पर भी छापा मारा था।
सिंघम अमेरिकी निगरानी समूहों की निगरानी में भी हैं, जो दावा करते हैं कि उनके चीन के साथ मजबूत संबंध हैं और वे अमेरिकी राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ लोग उन्हें अमेरिका में चीनी प्रचार तंत्र का हिस्सा और चीन में उइगरों के नरसंहार से इनकार करने वाली गतिविधियों के एक जटिल जाल के केंद्र में मानते हैं।
न्यू लाइन्स द्वारा महीनों तक चली एक जांच से पता चला है कि पिछले पांच वर्षों में लगभग 65 मिलियन डॉलर विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से हस्तांतरित हुए हैं, जिनका संबंध उन लोगों से है जिन्होंने चीनी सरकार का बचाव किया है और बीजिंग द्वारा उइघुर और तुर्क मुस्लिम अल्पसंख्यकों

के खिलाफ किए गए मानवाधिकार उल्लंघनों को कम करके आंका है या उनका खंडन किया है। यह धन मुख्य रूप से कर-कटौती योग्य निवेश फंडों और दान संस्थाओं की एक जटिल श्रृंखला के माध्यम से प्रवाहित हुआ है, जो अपनी शासन संरचनाओं के आधार पर एक ही व्यक्ति से जुड़े हुए हैं: 67 वर्षीय अमेरिकी तकनीकी दिग्गज नेविल रॉय सिंघम। पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया भारत की 'व्यावसायिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता' के अपने डेटाबेस को हाशिए पर पड़े लोगों की मदद करने के लिए एक मानवीय परियोजना के रूप में प्रदर्शित करता है। लेकिन इससे दो बड़ी समस्याएं खड़ी होती हैं। पहली यह कि यह भारत से संबंधित संवेदनशील अभिलेखागार बनाता है जो भारत सरकार के नियंत्रण से बाहर है। दूसरी समस्या सिंघम के चीनी संबंधों से जुड़ी है।

शिक्षा के क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने वाली शक्ति के रूप में PARI PARI द्वारा प्रामाणिक होने का दावा करते हुए प्रकाशित कहानियों के अलावा, यह डेटाबेस को एक शिक्षण उपकरण के रूप में भी प्रस्तुत करता है: 'यह शिक्षकों के उपयोग के लिए एक शिक्षण उपकरण होगा। इसमें जो कुछ भी है, उसका उपयोग शिक्षक पहले से ही कक्षा में कर रहे हैं।' PARI की शिक्षा वेबसाइट बेबाकी से दावा करती है: 'PARI में, हम अपनी असंख्य कहानियों, तस्वीरों और वीडियो के आधार पर भविष्य की पाठ्यपुस्तकें लिख रहे हैं। छात्र और शिक्षक दोनों पाठ्यक्रम सामग्री में योगदान और विकास कर सकते हैं।'
और आगे कहते हैं:
आने वाले कुछ वर्षों में पाठ्यपुस्तकों सहित शिक्षण और अनुसंधान सामग्री तेजी से ऑनलाइन उपलब्ध होगी – यह प्रक्रिया दुनिया के कुछ हिस्सों में पहले से ही चल रही है। PARI का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों,

स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए जानकारीपूर्ण और जीवंत संसाधन बनाने में मदद करना है। सही ढंग से लागू करने पर, इसका अर्थ ऐसी 'पाठ्यपुस्तकें' या शिक्षण सामग्री हो सकती है जिसमें सामग्री जोड़ी जा सकती है, संशोधित की जा सकती है, अद्यतन की जा सकती है या विस्तारित की जा सकती है। ब्रॉडबैंड की पहुंच बढ़ने के साथ, इसका अर्थ कई छात्रों के लिए लागत में कमी भी होना चाहिए, क्योंकि PARI एक सार्वजनिक रूप से निःशुल्क उपलब्ध साइट है।

तीस्ता सेतलवाद के विचारधारा-आधारित शिक्षा पाठ्यक्रम की तरह, जो गुजरात और महाराष्ट्र के स्कूलों में लागू हुआ, और पुलित्जर सेंटर के 1619 प्रोजेक्ट की तरह, जो अमेरिकी स्कूलों में पढ़ाया जाता है, भारतीय शिक्षा प्रणाली में PARI का प्रवेश भी विचारधारा थोपने के उद्देश्य से किया गया है। इसके भारत भर में साठ से अधिक स्कूलों और कॉलेजों के साथ साझेदारी है: फ्लेम, माउंट कार्मेल कॉलेज, IIT जम्मू, JNU, लेडी श्री राम कॉलेज, आदि। भारतीय संस्थानों की लंबी सूची अंत में दिए गए लिंक पर उपलब्ध है।[29]

यह दोतरफा रणनीति है: अपने सक्रियतावाद का प्रसार करना और अपने संग्रह को समृद्ध करने के लिए छात्रों की भर्ती करना। स्कूल और कॉलेज के छात्रों को भेजे गए प्रत्येक संदेश में सक्रियतावाद का आह्वान होता है, जैसा कि निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट होता है:

युवा छात्र के लिए यह असामान्य व्यवसायों के बारे में एक मजेदार और रोमांचक कहानी है, विद्रोह की खोज करने वाले किशोर के लिए यह सत्ता के सामने सच बोलने का एक उदाहरण है, और युवा वयस्क के लिए यह एक जीवंत संग्रह और संसाधन में योगदान करने का अवसर है।

युवा लोग हमारे समय के मुद्दों और प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं: वे किसानों के विरोध प्रदर्शन में जमीनी स्तर पर मौजूद हैं, जौनसार

पहाड़ों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का दस्तावेजीकरण कर रहे हैं, रेलवे विक्रेताओं, निर्माण श्रमिकों और मछुआरों जैसे दिहाड़ी मजदूरों से बात कर रहे हैं, जिनकी आजीविका लॉकडाउन में समाप्त हो गई।

शिक्षकों के रूप में, हम एक ऐसी भारतीय पीढ़ी को तैयार करने के खतरे में हैं जो अपने आस-पास की समस्याओं से बेखबर है, सामाजिक और नैतिक प्रश्नों से अनभिज्ञ है और हमारे चारों ओर बढ़ती असमानताओं से कटी हुई है। यदि हम इसे बदलना चाहते हैं, तो हमें उन्हें रूढ़ियों पर सवाल उठाने और पाठ्यपुस्तकों से परे जाकर आलोचनात्मक रूप से सोचने के लिए आवश्यक उपकरण और जानकारी प्रदान करनी होगी।

PARI द्वारा चुने गए विषय स्पष्ट रूप से बच्चों को अपने सामाजिक न्याय के युद्धों में सैनिकों के रूप में इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं:

अधिकार और लोकतंत्र: क्या हमारे संविधान के अनुसार सभी नागरिकों को समान अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त हैं? सामाजिक और आर्थिक असमानताओं और ऐतिहासिक अन्याय ने कई नागरिकों को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे उनके मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया है। ये कहानियाँ बताती हैं कि कैसे ये असमानताएँ वंचितों के दैनिक जीवन में झलकती हैं। कुछ परियोजनाएँ युवाओं को विचारधारा से प्रभावित करती हैं और इन्हें भारत के इतिहास को पुनर्लेखन की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा सकता है। पुलित्जर सेंटर, PARI के अभिलेखागार में योगदान देने वाले पत्रकारों को अनुदान प्रदान करके इस प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहा है। पुलित्जर सेंटर के साथ जुड़ाव PARI को वैधता भी प्रदान करता है।

डेटा नया हथियार बन गया है और पीएआरआई पत्रकारिता और मानवतावाद के नाम पर भोले-भाले भारतीय नागरिकों का निजी डेटा हासिल कर रहा है। यह भारत की विविधता का इस्तेमाल भारत की

अखंडता को कमजोर करने के लिए कर रहा है।

PARI की सामग्री को व्यापक रूप से 'श्रेणियों' में बांटा गया है: श्रम से संबंधित 'हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य' और कारीगरों, कलाकारों और शिल्पकला से संबंधित 'हमारे द्वारा निर्मित कार्य'। कृषि, खेल, महिलाओं, दलितों और आदिवासियों से संबंधित श्रेणियां भी हैं। यह सूची, हालांकि व्यापक है, अंतिम नहीं है; संस्थापकों का कहना है कि सामग्री उपलब्ध होने पर अन्य श्रेणियां भी जोड़ी जा सकती हैं और जोड़ी जाएंगी।

लेकिन PARI ने पहले ही एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। इसमें 'चेहरे' नाम की एक अनूठी श्रेणी है, जिसमें 40 फोटोग्राफरों ने योगदान दिया है... 'चेहरे' - भारत की चेहरे और पेशे की विविधता का उत्सव - में भारत के हर जिले से एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे की तस्वीर शामिल होगी, साथ ही मेटाडेटा (नाम, पेशा, गांव, जिला और फोटोग्राफर/कैमरे का विवरण) भी होगा। योगदानकर्ताओं के लिए यह समझना एक शानदार अनुभव रहा कि 100 चेहरे और 200 से अधिक पेशे हो सकते हैं, क्योंकि कई ग्रामीण भारतीय जीविका चलाने के लिए एक से अधिक काम करते हैं।

सारी सामग्री... और वेबसाइट खुद भी—स्वेच्छा से तैयार की गई है। थॉटवर्क्स इंडिया, एक वैश्विक सॉफ्टवेयर कंपनी, ने निःशुल्क एक अद्भुत, प्रतिक्रियाशील प्लेटफॉर्म बनाया है... थॉटवर्क्स के संस्थापक-अध्यक्ष नेविल रॉय सिंघम ने टिप्पणी की, 'यह एक अविश्वसनीय परियोजना है, और एक शानदार परियोजना भी।'

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह संग्रह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होने के साथ-साथ आर्थिक महत्व भी रखता है, क्योंकि इसमें लोगों के जीवन, व्यवहार, मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल, धर्म, आयु, जनसांख्यिकी, सामाजिक स्थिति, व्यवसाय, सांस्कृतिक पसंद, गीत,

नृत्य, शिल्प, भाषाएँ, बोलियाँ, यहाँ तक कि चेहरों की तस्वीरें और वीडियो जैसी अद्वितीय जानकारियाँ मौजूद हैं। संवेदनशील ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कमजोर लोगों के ऐसे संग्रह का दुरुपयोग सामाजिक अशांति फैलाने के लिए किया जा सकता है। यह डेटाबेस भारत के स्कूलों और कॉलेजों के भोले-भाले छात्रों से जुटाया जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब तक किसी ने भी इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया है।
जोशुआ प्रोजेक्ट जैसी मिशनरी परियोजनाएं इस डेटाबेस का उपयोग भारत की स्वदेशी संस्कृतियों और परंपराओं पर और अधिक हमले करने के लिए कर सकती हैं। यह पश्चिमी, चीनी और अन्य विदेशी लेखकों के लिए एक डेटाबेस के रूप में काम करेगा, जिससे वे उन लोगों तक पहुंच बनाकर कथा को अपने हिसाब से गढ़ सकें जिन्हें मौजूदा स्थिति की जरा भी जानकारी नहीं है।

केस स्टडी: अमेरिका में हिंदुओं पर हमला
2018 में, पुलित्जर सेंटर ने बोस्टन के डब्ल्यूजीबीएच पब्लिक रेडियो स्टेशन के पत्रकार फिलिप मार्टिन को वित्तीय सहायता प्रदान की, जो नेशनल पब्लिक रेडियो (एनपीआर) और पब्लिक रेडियो इंटरनेशनल (पीआरआई) का सदस्य स्टेशन भी है। यह स्टेशन शिक्षा पर केंद्रित है और एनपीआर और पीआरआई दोनों के समाचार कार्यक्रम प्रसारित करता है। पुलित्जर सेंटर ने हार्वर्ड फेलो सूरज येंगडे को शामिल किया और स्टेशन को "अमेरिका में जातिगत भेदभाव" नामक एक एजेंडा-आधारित श्रृंखला बनाने का काम सौंपा। श्रृंखला की घोषणा इस प्रकार की गई:
‘अमेरिका में जातिगत भेदभाव’ डब्ल्यूजीबीएच/पीआरआई के द वर्ल्ड द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में जातिवाद पर की गई एक

मौलिक, बहु-भाग, बहु-प्लेटफ़ॉर्म पत्रकारिता जांच है।
येंगडे ने 'हार्वर्ड पेडिग्री, कास्ट फॉलोज़ 'लाइक अ शैडो" शीर्षक वाले एपिसोड में मुख्य भूमिका निभाई थी। इसे हार्वर्ड में एक दलित के रूप में उनकी निजी कहानी के तौर पर प्रचारित किया गया था। हार्वर्ड और पुलित्ज़र सेंटर ने रेडियो श्रृंखला, वीडियो और लेखों के माध्यम से इस संदेश को फैलाने के लिए अपने चैनलों का इस्तेमाल किया।
इस परियोजना का उद्देश्य यह दर्शाना है कि जाति, भारतीयों का पीछा करते हुए दुनिया भर में हर जगह जाती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई वायरस हर जगह फैलता है। उत्तरी अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने जाति-आधारित भेदभाव से भरी अपनी कट्टरता को अमेरिकी कार्यस्थल में भी फैला दिया है। इस वृत्तांत को तीस दिनों तक चलने वाले कई मीडिया चैनलों में प्रसारित कहानियों के माध्यम से व्यवस्थित रूप से गढ़ा गया, जिनमें निम्नलिखित प्रसंग शामिल हैं: [39]
सूरज की परछाई: वह जहाँ भी जाता है, उसकी जाति उसका पीछा करती है—अमेरिका में भी।
भारत के ‘अछूतों’ का कहना है, ‘इन किनारों पर जाति से कोई छुटकारा नहीं’ - टिंकू रे द्वारा लिखित।
प्रेम और विवाह: अमेरिका में कायम एक भारतीय परंपरा के खिलाफ विद्रोही - कविता पिल्ले द्वारा लिखित
अमेरिका में जातिगत भेदभाव गैरकानूनी नहीं है। लेकिन यह विश्वविद्यालय इससे लड़ने की कोशिश कर रहा है। - फिलिप मार्टिन
कई लेखकों द्वारा लिखित "अमेरिका जातिगत भेदभाव के आघात से सुरक्षित नहीं है"
हार्वर्ड से ताल्लुक रखने के बावजूद, फिलिप मार्टिन की रचना 'कास्ट' 'परछाई की तरह पीछा करती है'।

डब्ल्यूजीबीएच न्यूज़ के फिलिप मार्टिन जाति व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए भारत की यात्रा पर। फिलिप मार्टिन सूरज येंगडे के साथ भारत में।
अमेरिका में भेदभाव – भाग 1 और 2, फिलिप मार्टिन द्वारा
कॉलेज परिसरों में जातिगत भेदभाव मौजूद है। कुछ स्कूल इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। फिलिप मार्टिन द्वारा लिखित। जसप्रीत महल, ब्रैंडिस विश्वविद्यालय में विविधता और समावेशन (DEI) - जिन्होंने ब्रैंडिस विश्वविद्यालय में जाति को एक संरक्षित श्रेणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और थेनमोझी सौंदराजन, इक्वालिटी लैब्स।
फिलिप मार्टिन अमेरिका में जाति व्यवस्था पर एक पैनल चर्चा की मेजबानी करते हैं।
हिंदू धर्म पर किए गए इस हमले का उद्देश्य जाति को एक व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त श्रेणी बनाना था जिसके कानूनी निहितार्थ हों। पुलित्जर सेंटर ने अपनी सफलता पर गर्व जताया:
प्रवासी भारतीयों में भी, भारत, नेपाल और अन्य जगहों पर 'अछूतों' के दैनिक जीवन की कठोर वास्तविकताओं से दूर, जातिगत पूर्वाग्रह उनका पीछा करता है। विभिन्न अध्ययनों और दलित विद्वानों के अनुसार, और इक्वालिटी लैब्स द्वारा किए गए हालिया अमेरिकी राष्ट्रीय सर्वेक्षण से इसकी पुष्टि होती है। उदाहरणों में ऐसे छात्र शामिल हैं, जिन्हें कथित तौर पर अपना उपनाम बताने के बाद कुछ मामलों में आवास देने से इनकार कर दिया गया। अमेरिका में रहने वाले कई पहली और दूसरी पीढ़ी के दक्षिण एशियाई इस बात से सहमत प्रतीत होते हैं कि भारतीयों में विवाह निर्विवाद रूप से जाति से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, उच्च तकनीक क्षेत्र में कई नौकरियों की भर्ती और नियुक्ति भी जातिगत पूर्वाग्रह से प्रभावित होती है, और अक्सर यह बोस्टन, न्यूयॉर्क या ह्यूस्टन

के भारतीय रेस्तरां की रसोई में काम करने वालों और सिलिकॉन वैली या कैम्ब्रिज के केंडल स्क्वायर में कंपनियों के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों के बीच का अंतर दर्शाती है। दलित, सबसे कम चर्चित तरीके से, कहते हैं कि उन्हें अक्सर जाति-आधारित भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए अमेरिकी संवैधानिक कानून में कोई विशिष्ट सुरक्षा या संदर्भ नहीं है। लेकिन प्रारंभिक साक्षात्कारों के आधार पर, अमेरिका में रहने वाले कई मध्यमवर्गीय भारतीयों का मानना नहीं है कि जाति यहाँ कोई मुद्दा है। इसके विपरीत, ब्रिटेन में जाति को एक प्रमुख चिंता का विषय माना जाता है, हालांकि कानूनी प्रतिबंध लगाने के प्रयास विफल रहे हैं। यह परियोजना ब्रिटेन और कनाडा में चल रहे जमीनी स्तर और संसदीय प्रयासों का गहन अध्ययन करती है, जिनका उद्देश्य ब्रिटेन और ब्रिटेन में कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है, और साथ ही अमेरिका के लिए इससे मिलने वाले सबक का भी विश्लेषण करती है।

मीडिया में चलाए गए व्यापक अभियान ने प्रभावी भूमिका निभाई और पुलित्जर सेंटर तथा हार्वर्ड ने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए: 2022 में, कैलिफोर्निया राज्य विश्वविद्यालयों और हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने जाति को नस्लवाद के एक रूप के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया और इस प्रकार जातिगत उत्पीड़न का शिकार हुए समूहों को अमेरिकी कानून के तहत एक संरक्षित श्रेणी के रूप में मान्यता दी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कैथोलिक चर्च ने इस श्रृंखला को 2020 का गैब्रियल पुरस्कार प्रदान किया।

फिलिप (sic) मार्टिन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में जातिवाद की पड़ताल करने वाली डब्ल्यूजीबीएच की रेडियो श्रृंखला 'कास्ट इन अमेरिका' को कैथोलिक प्रेस एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा द्वारा 2020 का गेब्रियल पुरस्कार प्रदान किया गया।

'कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन द यूएसए: ए पब्लिक रेडियो एंड ऑनलाइन' परियोजना का हिस्सा यह रेडियो श्रृंखला, 'मानव गरिमा - रेडियो - सामान्य उत्कृष्टता' श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुकी है। इस पूरी परियोजना में शामिल रेडियो श्रृंखला, वीडियो और लेखों की टीम में टिंकू रे और कविता पिल्ले शामिल हैं। गेब्रियल पुरस्कार उन कार्यों को मान्यता देते हैं जो गरिमा, करुणा, समुदाय और न्याय के विषयों का समर्थन करते हैं।

फिलिप मार्टिन ने सर्वश्रेष्ठ सहयोगात्मक प्रयास के लिए 2020 पब्लिक मीडिया जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन पुरस्कार भी जीता:

'कास्ट इन अमेरिका' पुलित्जर सेंटर द्वारा समर्थित एक परियोजना है जो जातिवाद, पूर्वाग्रह और जाति के आधार पर भेदभाव के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में वर्तमान समय में इसके निरंतर प्रचलन की पड़ताल करती है।

उपरोक्त उदाहरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हार्वर्ड किस प्रकार पुलित्जर सेंटर जैसे अपने सहयोगियों के माध्यम से एक विद्वान (अर्थात हार्वर्ड के ही सूरज येंगडे) को बढ़ावा देता है, जिसके परिणामस्वरूप अमेरिका में जाति से संबंधित नए कानून बनते हैं। इसका असर भारतीय अमेरिकियों पर पड़ता है। हार्वर्ड और उसके सहयोगियों के हाथों में निहित शक्ति का यही उदाहरण है।

भारत के लिए पुलित्जर सेंटर की वित्तीय सहायता

नीचे पुलित्जर सेंटर द्वारा एक नमूना वर्ष (2021 से फरवरी 2022) के लिए वित्त पोषित कुछ लेख दिए गए हैं। कई मीडिया प्रकाशनों की जानकारी भी दी गई है। कुछ विषय कई अनुदानों और लेखों में दोहराए गए हैं।

PULITZER CENTER FUNDING ON INDIA – PART A (Sample Year – 2021 to February 2022)

POVERTY

- *The Hindu*: Hungry Nation
- Hunger: A Hidden Condition Exacerbated Further by COVID-19 Lockdown
- *The National Herald*: Opinion: What Do the Poorest Eat? Salt, Water and Pepper

TRIBALS IN INDIA

- PARI - We Will Be Kicked Out and No One Will Care
- India's Adivasi Identity in Crisis
- Sabrang: Adivasi Identity At Stake
- *The Wire*: Illegal Detention, Forced Marriage: What Happens After Alleged Naxals 'Surrender' in Bastar?
- *Tehelka*: Rise of Sati Pati Cult in Jharkhand
- *Al Jazeera*: Living in the Shadow of Rebellion: India's Gond Tribe
- The Gond Tribe of Central India
- PARI: We Have Been Pleading for a Bridge in Sautada
- PARI: In Marathwada: Forlorn Farmers, Fatal Fears
- PARI: In Beed: 'It Got Easier To Threaten and Harass Me'(Rape)
- Sabrang: Pathalgadi: Assertion of Adivasi Rights Over Land

COVID MISMANAGEMENT

- The Possibility of a Third Wave Is Frightening
- *LA Times*: A Lost Generation: India's COVID Crisis Reverses Decades of Progress for Children
- Societal Fallouts of COVID-19
- PARI: In Osmanabad: Dodging and Ducking the Virus
- PARI: We Didn't Know Our Situation Could Get Worse
- PARI: 'He Became Irritable ... He Would Snap at Us'
- *South China Morning Post*: China-India Border Dispute: How One Doctor Coped With Conflict and COVID-19 on the Front Lines of a Face-off Between Two World Powers
- Coda: How Healthcare Workers in India Fought a Surveillance Regime and Won

HINDUPHOBIA/RELIGION

- *The Caravan*: Ritual Killings: How Crimes of Superstition Thrive in the New India
- International Reporting Must Distinguish Hindu Nationalism from Hinduism
- Islamophobia and Coronavirus in India
- *The Caravan*: The Republic of Tantric Crimes
- Finding an Old Religion in a New India
- Religion, Populism, and the Media

PULITZER CENTER FUNDING ON INDIA – PART B (Sample Year – 2021 to February 2022)

ENVIRONMENT

- Event: India: Environment Undone
- Liberation: Reforestation compensatoire» en Inde: L'arbre qui gâche la forêt
- *Tehelka*: Unending Despair in India's Magical Land
- The Rise of Citizen Protest in India's Goa
- *Hakai Magazine*: In Goa, The Water Runs Black
- Sabrang: Under the Shadow of Coal Mining
- *The Caravan*: Rocks of Ages: Jharkhand's Millennia-old Megalithic Sites are Under Threat
- *Suno India*: Making Environment Political: The Save Mollem Movement
- Article 14: The Lack Of Evidence To Confirm Obvious Environmental Damage Is Derailing Local Battles For Justice
- Behind the News: India's 'Compensatory' Forests

GENDER

- PARI: Beed's Child Brides: Cutting Cane, Crushing Hopes
- PARI: In Beed: 'It Got Easier To Threaten and Harass Me'

KASHMIR

- In Kashmir: Mourning has Become Contentious
- *Scroll.in*: How Kashmir's Half-Widows Are Denied Their Basic Property Rights
- Years Out of School in Kashmir
- Solace in Spaces: About Kashmir
- Faith and Pandemic in Indian-administered Kashmir
- Sacred Peace Building in Kashmir
- *Haaretz*: Mourning Over Empty Graves
- *The Wire*: Secret Burials in Faraway Places: Slain Kashmiri Militants' Kin Are Denied Right to Grieve
- *Deutsche Welle*: World in Progress: Missing Out on Education in the Kashmir Region
- Islamophobia and Coronavirus in India

POLITICS IN INDIA

- Religion, Populism, and the Media
- Indian Government's Tech Imposition on Healthcare Workers
- *Livemint.com*: Why Childcare Workers Are Suddenly up in Arms

यह सिर्फ एक वर्ष का नमूना है, इसलिए इनके दीर्घकालिक प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है।

यह स्पष्ट है कि इस्तेमाल किए गए कुछ विषय दिखावटी हैं। असली मकसद 'पीड़ित' समुदायों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को दिखाकर सामाजिक अन्याय के समर्थन में सबूत जुटाना लगता है। किसी मीडिया

प्रोजेक्ट को 'पर्यावरण', 'आदिवासी' या 'कोविड' के रूप में वर्गीकृत करना, हार्वर्ड द्वारा भारत के हितों की सेवा करने का एक अच्छा तरीका मात्र है। कड़वी सच्चाई यह है कि उत्पन्न हो रहे इन सभी साक्ष्यों का उपयोग क्रिटिकल रेस थ्योरी के उस लक्ष्य के अनुरूप किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र, हिंदू धर्म और नागरिक समाज की अंतर्निहित संरचनाओं को ध्वस्त करना है - दूसरे शब्दों में, जो भारत को एक साथ बांधे रखता है।

भारत में नीमन-पुलित्जर मीडिया नेटवर्क

समर्थित मीडिया हाउस
पुलित्जर सेंटर द्वारा वित्त पोषित युवा पत्रकारों को निम्नलिखित मीडिया आउटलेट्स को वित्त पोषण करके अपने काम को प्रकाशित करने के लिए भी सहायता मिलती है:
द वायर
कारवां
द नेशनल हेराल्ड
Tehelka
सब्रंग
परी
Livemint.com
सुनो इंडिया (जिसकी सह-स्थापना हिंदू अखबार के पूर्व पत्रकार ने की थी और जिसे इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक-स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन [IPSMF] का समर्थन प्राप्त है)
द हिंदू
Scroll.in

इसके अलावा, अल जज़ीरा जैसे चुनिंदा विदेशी प्रकाशनों को भी भारत पर लिखने के लिए वित्त पोषित किया जा रहा है।

नीमन रिपोर्ट्स

नीमन फाउंडेशन नीमन रिपोर्ट नामक एक वेबसाइट और त्रैमासिक मुद्रित प्रकाशन का संचालन करता है।

… जैसा कि इसकी वेबसाइट पर लिखा है, यह पत्रकारिता में वैचारिक नेतृत्व को कवर करता है। इसका संपादकीय मिशन स्वयं फाउंडेशन के मिशन के समान है: "पत्रकारिता के मानकों को बढ़ावा देना और उन्नत करना।" नीमन रिपोर्ट्स, नीमन वॉचडॉग प्रोजेक्ट का केंद्र है, जो यह बताता है कि पत्रकार किस प्रकार सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहरा सकते हैं। इसकी स्थापना वाशिंगटन पोस्ट के लंबे समय तक पत्रकार रहे और 1950 के नीमन फेलो मुर्रे मार्डर ने की थी।

वित्तीय संसाधनों और उच्च स्तरीय संबंधों के बल पर नीमन भारत में व्यापक स्तर पर काम कर सकता है और चर्चा को नियंत्रित कर सकता है। केवल एक वर्ष का प्रकाशन ही पाठक को नीमन फाउंडेशन के उद्देश्यों की झलक देने के लिए पर्याप्त है। इसके सहयोगी पुलित्जर सेंटर के माध्यम से एक नमूना वर्ष (2021-फरवरी 2022) में वित्त पोषित परियोजनाओं की सूची नीचे दी गई है:

भारत में, स्वतंत्र प्रेस के अंतिम बचे हुए कुछ गढ़ बढ़ते अधिनायकवाद के खिलाफ पहरा दे रहे हैं।

अरुंधति रॉय: ‘हम लघु नरसंहारों के युग में जी रहे हैं’

भारत में पत्रकार इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि सत्य का कोई अर्थ है या नहीं।

मोदी सरकार, द कारवां पत्रिका और भारत में स्वतंत्र प्रेस की स्थिति

नीमन अनुदान प्राप्तकर्ता, पुरस्कार और फेलोशिप

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने विदेशों के उन इक्यावन संगठनों की सूची जारी की है जो विशिष्ट विषयों पर भारतीय पत्रकारों की भर्ती के लिए फैलोशिप और अनुदान प्रदान करते हैं। नीमन फाउंडेशन को शीर्ष वित्तपोषण स्रोत के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

हार्वर्ड विश्वविद्यालय में नीमन फैलोशिप के तहत प्रतिभागियों को एक शैक्षणिक वर्ष के लिए हार्वर्ड में अध्ययन करने का अवसर मिलता है; नाइट विजिटिंग नीमन फैलोशिप, जो 12 सप्ताह या उससे कम अवधि की होती है, परियोजना-आधारित कार्यों के लिए भी उपलब्ध है जो पत्रकारिता को किसी नए तरीके से आगे बढ़ाएगी।

आइए नीमन फाउंडेशन द्वारा हाल ही में दिए गए कुछ पुरस्कारों और छात्रवृत्तियों पर एक नज़र डालते हैं। 2021 में, इसने द कारवां पत्रिका को पत्रकारिता में विवेक और सत्यनिष्ठा के लिए लुई एम. लियोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 'हिंदू वर्चस्ववादी आतंकवाद, राजनीतिक हत्या, जाति और लिंग अन्याय, और भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यक के खिलाफ जातीय हिंसा' की जांच के लिए दिया गया था।

नीमन के अनुसार, 'द कारवां' को भारत में मानवाधिकारों, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के क्षरण की अपनी अनूठी और बेबाक कवरेज के लिए यह मान्यता प्राप्त हुई।[46] आगे इसमें कहा गया है:

… इस प्रकाशन का चयन असाधारण और चिंताजनक परिस्थितियों में हुआ है। द कारवां द्वारा हाल ही में देशव्यापी किसान विरोध प्रदर्शनों की कवरेज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को नाराज कर दिया है, जिसने पत्रिका के सोशल मीडिया खातों को बंद करने का प्रयास किया है

और कारवां के कई कर्मचारियों पर राजद्रोह के आरोप लगाए हैं। ऐसी धमकियों के बीच, द कारवां अंतरात्मा और सत्यनिष्ठा के प्रति एक अत्यावश्यक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। … (इसका) हालिया कार्य दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले लोकतंत्र में अपरिहार्य रिपोर्टिंग की विरासत में एक और अध्याय है। भारत का पहला प्रकाशन जो कथात्मक पत्रकारिता को समर्पित है, द कारवां ने पिछले एक दशक में देश में राजनीतिक हिंदूवाद के उदय का दस्तावेजीकरण करते हुए लगातार सत्ता के सामने सच बोला है। हिंसा और कारावास का जोखिम उठाते हुए, इसके पत्रकारों ने हिंदू वर्चस्ववादी आतंकवाद, राजनीतिक हत्या, जाति और लिंग अन्याय, और भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यक के खिलाफ जातीय हिंसा की जांच की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला लिखी है। द कारवां ने बार-बार यह प्रदर्शित किया है कि यह भारतीय सार्वजनिक जीवन में नैतिक स्पष्टता का प्रतीक है।

2022 बैच के लिए नीमन फाउंडेशन फैलोशिप प्राप्त करने वालों में से एक प्रणव दीक्षित थे, जिनकी आधिकारिक भूमिका भारत के लिए प्रौद्योगिकी को कवर करना है। हालांकि, उन्होंने अपने लेखों के शीर्षकों से स्पष्ट होता है कि उन्होंने सामाजिक न्याय के मुद्दों को कवर करने के लिए 'प्रौद्योगिकी' का उपयोग किया है।

मुझे लगा था कि मेरा काम भारत में प्रौद्योगिकी पर रिपोर्टिंग करना है। लेकिन इसके बजाय, मुझे अपने लोकतंत्र के पतन को करीब से देखने का मौका मिला।

कोई ईमेल नहीं। कोई व्हाट्सएप नहीं। कोई इंटरनेट नहीं। कश्मीर में अब यही सामान्य जीवन है।

कश्मीरी लोग व्हाट्सएप से गायब हो रहे हैं

ट्विटर ने भारत सरकार की आलोचना करने वाले खातों को अनब्लॉक

कर दिया है। अब, इसके कर्मचारियों को धमकी दी जा रही है कि अगर वह इन खातों को दोबारा ब्लॉक नहीं करता है तो उन्हें जेल भेजा जाएगा।
जब दो परमाणु शक्तियां युद्ध के कगार पर थीं, तब ऑनलाइन गलत सूचनाओं का एक भीषण युद्ध चल रहा था।
उन महिलाओं से मिलिए जिन्हें फेसबुक पर छिपकर लॉग इन करना पड़ता है।
जानिए ट्विटर के अधिकारियों और भारतीय कार्यकर्ताओं की एक गुप्त बैठक ने किस तरह जातिगत विवाद को जन्म दिया।
पुराने भारतीय व्हाट्सएप पर मिलेनियल्स को दीवाना बना देते हैं। यही वजह है कि वे उनके प्रति जुनूनी हैं।
भारत की राजनीतिक पार्टियों ने पक्षपातपूर्ण झगड़ों के लिए ट्विटर के ट्रेंडिंग कॉलम को कैसे हथिया लिया
अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियां भारतीयों को नाराज करने से इतना डरती हैं कि वे अपने सभी उत्पादों पर सेंसरशिप लगा रही हैं।
2020 में, द कारवां की विद्या कृष्णन को नीमन फाउंडेशन फेलोशिप से सम्मानित किया गया। 2021 में नीमन फाउंडेशन की रिपोर्ट में मोदी सरकार पर उनके द्वारा लिखा गया एक तीखा लेख प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक था "भारत में, स्वतंत्र प्रेस के अंतिम कुछ गढ़ बढ़ते अधिनायकवाद के खिलाफ पहरा दे रहे हैं"। कृष्णन मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहती हैं, "पत्रकारों को बदनाम करना और परेशान करना मोदी सरकार के संचालन का मुख्य हिस्सा है, जो घोर संदेह और प्रतिशोधी क्रूरता से भरा है।" वह आगे बताती हैं:
पिछले सात वर्षों में, समाचार कक्षों ने मोदी सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए लगातार प्रयास किए हैं... 16 जुलाई को, अफगानिस्तान के कंधार में तालिबान आतंकवादियों ने सिद्दीकी की हत्या कर दी। वह

रॉयटर्स के लिए अफगान विशेष बलों और तालिबान लड़ाकों के बीच हुई झड़प को कवर कर रहे थे। 38 वर्ष की आयु में, उन्होंने 2018 में म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थी संकट को कवर करने के लिए फीचर फोटोग्राफी का पुलित्जर पुरस्कार जीता था। उनके सहयोगियों ने उन्हें 'एक ऐसा व्यक्ति बताया जो उन कहानियों की गहराई से परवाह करता था जिन्हें वह कवर करते थे।' दुनिया भर से शोक संवेदनाएं व्यक्त की गईं, जिनमें अफगान राष्ट्रपति अशरफ घनी, अमेरिकी विदेश विभाग और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस शामिल थे। मोदी ने सिद्दीकी की मौत को स्वीकार नहीं किया… प्रधानमंत्री के समर्थकों ने तालिबान द्वारा मारे गए एक भारतीय मुस्लिम सिद्दीकी को 'जिहादी' कहा।

अन्य उदाहरणों के तौर पर, 2017 में ट्विटर इंडिया और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख राहील खुर्शीद को नाइट विजिटिंग नीमन फेलोशिप से सम्मानित किया गया। 2021 में, पुलित्जर सेंटर की अनुदान प्राप्तकर्ता कल्पना जैन और अमेरिकी इतिहासकार जॉन फी को धर्म और लोकलुभावनवाद के बीच संबंधों पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने समझाया, “यह वी. सावरकर थे, जो एक पूर्व उपनिवेश-विरोधी क्रांतिकारी थे, जिन्होंने हिंदू एकता के इस विचार को साकार रूप दिया और इसे एक अधिक सशक्त प्रतीक बनाया: भारतीय राज्य का प्रतीक। उन्होंने धार्मिक सीमाओं को राष्ट्रीय सीमाओं के रूप में देखा और इस्लामी और ईसाई परंपराओं को अवैध, विदेशी प्रभाव माना।”

पुलित्जर सेंटर ने फीया के उस काम की सराहना की, जिसमें उन्होंने अमेरिका में ईसाई राष्ट्रवाद की तुलना पश्चिम द्वारा हिंदू राष्ट्रवाद के रूप में देखे जाने वाले राष्ट्रवाद से करने का प्रयास किया था।

फीया ने 6 जनवरी, 2021 को अमेरिकी कैपिटल भवन पर हुए हमले में भाग लेने वाले एक व्यक्ति की कहानी पर चर्चा करते हुए, ईसाई राष्ट्रवाद

में इसी तरह की वृद्धि देखी और बताया कि यह उन लोगों के लिए एक मंच प्रदान कर सकता है जो महसूस करते हैं कि समाज में उनकी कोई आवाज नहीं है।

जैन ने समकालीन भारत में हिंदू राष्ट्रवाद के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के महिला संगठन दुर्गा वाहिनी पर विशेष ध्यान केंद्रित किया।

जैन ने बताया, 'दुर्गा वाहिनी की सदस्य भारत भर की आम महिलाएं हैं जो इस संगठन के माध्यम से अपने दैनिक जीवन में अधिक सशक्त बनना चाहती हैं।' उन्होंने आगे कहा, 'वे बहुत ही मजबूत पितृसत्तात्मक नियंत्रण में पली-बढ़ी हैं। उन्हें कभी भी सार्वजनिक रूप से खुलकर बोलने का मौका नहीं मिला।'

जैन ने दुर्गा वाहिनी द्वारा महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा के प्रति अपनाए गए दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा: 'हिंदू संस्कृति के उस प्रशिक्षण में, इतिहास का गलत चित्रण किया गया है, तथ्यों का गलत चित्रण किया गया है, और साथ ही मुसलमानों जैसे बाहरी व्यक्ति के प्रति एक तरह का अलगाव भी पैदा किया गया है।'

2018 से पुलित्जर सेंटर द्वारा वित्त पोषित भारतीय पत्रकारों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। इससे भी उल्लेखनीय बात यह है कि सेंटर कश्मीर में विशेष रुचि दिखा रहा है, जहां कई युवा पत्रकारों को भारतीय सरकार की गतिविधियों के बारे में लिखने के लिए भेजा गया है।

भारतीय शास्त्रीय ग्रंथों की पुनर्व्याख्या

हालांकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस नीमन फाउंडेशन से पूरी तरह स्वतंत्र है, फिर भी प्रकाशक के रूप में इसका प्रभाव नीमन फाउंडेशन के समान ही

है। यह अकादमिक जगत के सबसे शक्तिशाली प्रकाशन गृहों में से एक है और इसके द्वारा प्रकाशित सामग्री का बहुत महत्व होता है। इसलिए, इससे अपेक्षा की जाती है कि वह इस प्रभाव का जिम्मेदारीपूर्वक प्रबंधन करे। लेकिन कई मामलों में, यह भारत की प्राचीन परंपराओं की घोर उपेक्षा करता है। हमारा यह कहना नहीं है कि इसकी सभी पुस्तकें त्रुटिपूर्ण हैं, बल्कि हम यह बताना चाहते हैं कि इसके ब्रांड का कभी-कभी दुरुपयोग किया जाता है।

इसका एक अच्छा उदाहरण इसकी अब तक की सबसे बड़ी परियोजना, मूर्ति क्लासिकल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है। इंफोसिस के सह-संस्थापक और भारतीय अरबपति एन.आर. नारायण मूर्ति द्वारा वित्त पोषित इस परियोजना का उद्देश्य सैकड़ों भारतीय शास्त्रीय ग्रंथों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद और व्याख्या करना है।

भारत की व्यापक साहित्यिक परंपरा को प्रदर्शित करना एक सराहनीय प्रयास है, लेकिन अनुवादों का संपादन कोलंबिया विश्वविद्यालय के शेल्डन पोलॉक ने किया है, जो वैदिक विरासत के प्रति पूर्वाग्रहों के लिए जाने जाते हैं। पुस्तक 'द बैटल फॉर संस्कृत' में इस बात की विस्तृत आलोचना की गई है कि कैसे यह परियोजना भारतीय शास्त्रीय परंपराओं को पश्चिमी सामाजिक विज्ञान के दृष्टिकोण से व्याख्यायित करके और अनुवादों में मनमानी करके विकृत करती है। यह दर्शाती है कि संस्कृत पर पोलॉक के विचार मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण हैं। उनके अनुसार, संस्कृत की सफलता का मुख्य कारण राजनीतिक शोषण और दमन के लिए इसका उपयोग था। वे इसकी आध्यात्मिकता को स्वीकार नहीं करते। वे इसे एक मृत भाषा मानते हैं, जिसे अतीत में हिंदू राजाओं द्वारा नष्ट कर दिया गया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस मूलतः पश्चिमी वैचारिक श्रेणियों को लेकर उन्हें भारतीय मानसिकता में समाहित कर रहा है और दावा कर रहा है कि वह

इन संस्कृत कृतियों के ज्ञान को जनमानस तक पहुंचा रहा है। इससे भारतीयों को अपनी विरासत पर गर्व महसूस होता है।

15. हार्वर्ड कैनेडी स्कूल: भू-राजनीति

अवलोकन
हार्वर्ड कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट निस्संदेह राजनीति विज्ञान, शासन और नीति निर्माण के क्षेत्र में दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और शक्तिशाली शैक्षणिक केंद्र है। यह वर्तमान और भविष्य के विश्व नेताओं को प्रशिक्षित कर रहा है और व्यापक अर्थों में अपनी राजनीतिक विचारधाराओं को प्रतिपादित कर रहा है। इसकी वेबसाइट पर यह घोषणा की गई है:
हार्वर्ड कैनेडी स्कूल का मिशन सार्वजनिक नीति और नेतृत्व में सुधार करना है ताकि लोग अधिक सुरक्षित, स्वतंत्र, न्यायपूर्ण और सतत रूप से समृद्ध समाजों में रह सकें।
यदि सुरक्षा, स्वतंत्रता, न्याय, स्थिरता और समृद्धि की उनकी व्याख्या में कोई पूर्वाग्रह न हो, तो यह मानवता के लिए एक महान सेवा प्रतीत होती है। हम इस अध्याय में भारत के संदर्भ में इन आधारों की जांच करेंगे।
हार्वर्ड के कुल 50 अरब डॉलर से अधिक के अनुदान के अलावा, 1.7 अरब डॉलर के अनुदान के साथ, एचकेएस हार्वर्ड के सबसे बड़े संस्थानों में से एक है। इसके अंतर्गत कई अन्य शक्तिशाली केंद्र भी आते हैं, जैसे कि रॉय और लीला ऐश सेंटर फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड इनोवेशन, बेलफर सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, कैर सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स पॉलिसी, सेंटर फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, सेंटर फॉर पब्लिक

लीडरशिप, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स, शोरेनस्टीन सेंटर ऑन मीडिया, पॉलिटिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी, मैल्कम वीनर सेंटर फॉर सोशल पॉलिसी, मोसावर-रहमान सेंटर फॉर बिजनेस एंड गवर्नमेंट, टॉबमैन सेंटर फॉर स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट और विमेन एंड पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम। इसके अतिरिक्त, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, हार्वर्ड लॉ स्कूल, मित्तल इंस्टीट्यूट, महिंद्रा ह्यूमैनिटीज सेंटर, टी.एच. चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ और हार्वर्ड के विभिन्न अन्य संस्थानों के साथ इसके सहयोगी कार्यक्रम भी हैं।

हार्वर्ड कैनेडी स्कूल की सत्ता संरचनाएं और प्रभाव के नेटवर्क इसे भू-राजनीतिक शक्ति का एक अनूठा केंद्र बनाते हैं। भारत के लिए इस स्कूल का महत्व इसकी उस क्षमता में निहित है जिसके द्वारा यह मुद्दों पर बातचीत कर सकता है, विश्व मंच पर नीतियां निर्धारित कर सकता है और भारत को गंभीर सुरक्षा खतरों से अवगत करा सकता है। इसके अलावा, हम यह भी दिखाएंगे कि चीन ने कैनेडी स्कूल के संसाधनों का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति प्राप्त कर ली है।

हार्वर्ड के सिपाही भारत के खिलाफ गवाही दे रहे हैं

हम एचकेएस द्वारा पोषित पांच विद्वानों - रकीब हमीद नाइक, रशाद हुसैन, अनुरीमा भार्गवा, प्रीता बंसल और आशुतोष वर्शनी - से शुरुआत करते हैं। ये सभी पांचों भारतीय मूल के हैं और एचकेएस द्वारा इन्हें गहन प्रशिक्षण दिया गया है तथा विश्व जनमत को प्रभावित करने के लिए एचकेएस द्वारा इन्हें समर्थन दिया गया है। इनमें से प्रत्येक ने विभिन्न मुद्दों पर अमेरिकी सरकार की सुनवाई में भारत के विरुद्ध विशेषज्ञ गवाही दी है। एचकेएस द्वारा सत्ता का प्रयोग करने के तरीकों में से एक है इन व्यक्तियों का उपयोग करके अमेरिका और अन्य देशों की विदेश नीतियों

को प्रभावित करना।
हम जिस पहले व्यक्ति की चर्चा करेंगे, जिसे एचकेएस ने पाला-पोसा है, वह है रकीब हमीद नाइक। वह एक कार्यकर्ता और स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो अल जज़ीरा और द वायर के लिए लिखते हैं। वह वाशिंगटन डी.सी. में कश्मीर पर अमेरिकी कांग्रेस की ब्रीफिंग में एक विशेषज्ञ गवाह थे, जहां उन्होंने कहा:
घाटी में मानवीय संकट दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन जारी है; और हमें पिछले तीन दशकों से अधिक समय में भारतीय राज्य (कश्मीर में) द्वारा किए गए क्रूर अत्याचारों को नहीं भूलना चाहिए।
हार्वर्ड कैनेडी स्कूल और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस 2020 में नाइक पैनलिस्टों में से एक थे। चर्चा समकालीन भारत में मुस्लिम होने की चुनौतियों पर थी। वे भारत में रोहिंग्या मुस्लिम प्रवासन के प्रति सहानुभूति रखते हैं और उन्होंने "भारत का धुर दक्षिणपंथी रोहिंग्या शरणार्थियों के प्रति शत्रुतापूर्ण हो रहा है" शीर्षक से एक लेख लिखा है। वे अमेरिका में भारत विरोधी पैरवी में इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के एक प्रमुख सहयोगी हैं और भारत की संप्रभुता के खिलाफ लड़ने वाले कश्मीर अलगाववादी के रूप में जाने जाते हैं।
हार्वर्ड इंडिया सम्मेलन में एकतरफा पैनल चर्चा के दौरान, द वायर की वरिष्ठ संपादक अरफा खानम शेरवानी ने नाज़ी जर्मनी की तुलना भारत से की। मानवाधिकार वकील अमन वदूद भी पैनल में शामिल थे, जिन्होंने भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के खिलाफ बात की। एक अन्य पैनलिस्ट लेखक और गीतकार हुसैन हैदरी थे, जिन्होंने राम मंदिर पर अदालत के फैसले पर कड़ी असहमति व्यक्त की और

'प्रगतिशील लोगों' से अयोध्या में अराजकता और अशांति फैलाने तथा भूमि पूजन समारोह को रोकने का आह्वान किया।

भारत पर हार्वर्ड के पैनल चर्चाओं में हमेशा की तरह, उन्होंने किसी भी वैकल्पिक दृष्टिकोण या विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को शामिल नहीं किया। उदाहरण के लिए, हार्वर्ड कश्मीर के आध्यात्मिक और साहित्यिक इतिहास, कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा, इस विवाद में भारतीय पक्ष की कानूनी स्थिति, पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव का उल्लंघन, या चीन द्वारा कश्मीर क्षेत्र पर कब्जे जैसे विषयों पर बोलने के लिए कभी विशेषज्ञों को आमंत्रित नहीं करता है।

यह पूर्वाग्रह यह भी दर्शाता है कि भारतीय अरबपति जो गर्व से ऐसे आयोजनों को प्रायोजित करते हैं, यह सुनिश्चित करने में विफल रहते हैं कि निष्पक्ष और संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाए।

हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से शिक्षित एक और जुझारू कार्यकर्ता रशाद हुसैन हैं, जिनके माता-पिता बिहार से आकर बसे थे। उन्होंने हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और अरबपति जॉर्ज सोरोस के बड़े भाई के नाम पर पॉल और डेज़ी सोरोस फेलोशिप के प्राप्तकर्ता बने। 2010 में, राष्ट्रपति ओबामा ने उन्हें इस्लामिक सहयोग संगठन का विशेष दूत नियुक्त किया। उनके जिहाद समर्थक रुख के कारण कई अमेरिकियों ने उनकी नियुक्ति का विरोध किया। अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है:

हुसैन की नियुक्ति से उपजे विवाद का केंद्र उनके द्वारा कथित तौर पर दोषी आतंकवादी और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के पूर्व नेता सामी अल-अरियन के बचाव में की गई टिप्पणियां हैं। अब, यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि एक आतंकवादी समर्थक राष्ट्रपति के प्रशासन में इतने ऊंचे पद तक कैसे पहुंच गया।

कई वर्षों बाद, जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने, तो हुसैन को अपने करियर में एक और बड़ी सफलता मिली। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया। यह एक शक्तिशाली पद है जो सीधे सरकार के उच्च स्तर को रिपोर्ट करता है और संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।
ओबामा के कार्यकाल के दौरान जब अमेरिकी दक्षिणपंथी उनका विरोध करते थे, उसके विपरीत हुसैन ने हाल ही में इस नए पद पर रहते हुए उनके साथ एकजुटता स्थापित कर ली है। अपने पिछले पद पर रहते हुए, अमेरिकी दक्षिणपंथी उन्हें इस्लाम की ओर झुकाव वाला मानते थे, लेकिन अब उन्होंने धर्मांतरण के विवादास्पद मुद्दे पर भारत को निशाना बनाकर एक साझा मुद्दा बना लिया है। यही कारण है कि क्रिश्चियन पोस्ट और क्रिश्चियनिटी टुडे ने हुसैन के नामांकन के लिए बाइडन की प्रशंसा की। ओपन डोर्स के सीईओ डेविड करी, जिनकी भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की आक्रामक योजनाएँ हैं, ने हुसैन की नियुक्ति की शीघ्र पुष्टि की मांग की।
ओपन डोर्स यूएसए के सीईओ डेविड करी ने क्रिश्चियनिटी टुडे को बताया कि बिडेन प्रशासन द्वारा आईआरएफ के महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति से उन्हें 'उत्साह' मिला है। उन्होंने कहा, 'रशाद हुसैन एक योग्य उम्मीदवार हैं जिन्हें चीन, भारत और अन्य जगहों पर चल रहे कारकों की गहरी समझ है।' उन्होंने आगे कहा, 'हम विश्व स्तर पर धार्मिक उत्पीड़न की बढ़ती लहर का मुकाबला करने के लिए आवश्यक विविध नेतृत्व गठबंधन बनाने के लिए तत्पर हैं।'
नेतृत्व का यह विविध गठबंधन भारत द्वारा ईसाई धर्म में हो रहे व्यापक धर्मांतरण को रोकने के प्रयासों का मुकाबला करने के लिए कुछ मुसलमानों और ईसाइयों को एक साथ लाता है। यह सब 'धार्मिक

स्वतंत्रता' की आड़ में किया जाता है, जो विदेशी वित्त पोषित मिशनरियों का समर्थन करने का एक गुप्त शब्द है। आश्चर्य की बात नहीं है कि 'कर्नाटक हिजाब' विवाद के दौरान, जब भारतीय अदालतें यह तय कर रही थीं कि क्या अलग-अलग संस्थानों को वर्दी अनिवार्य करने का अधिकार है, तो हुसैन ने तुरंत हस्तक्षेप किया और अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से निम्नलिखित ट्वीट किया:

धार्मिक स्वतंत्रता में अपने धार्मिक पहनावे को चुनने की क्षमता शामिल है। कर्नाटक राज्य को धार्मिक वस्त्रों की स्वीकार्यता निर्धारित नहीं करनी चाहिए। स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और महिलाओं और लड़कियों को कलंकित और हाशिए पर धकेल देता है।

दिलचस्प बात यह है कि जब डेनमार्क, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और अन्य पश्चिमी देशों ने बुर्का पर प्रतिबंध लगाया, तब अमेरिका ने हस्तक्षेप नहीं किया। इब्राहीमी धर्मों के बीच तनाव के बावजूद, वे गैर-इब्राहीमी धर्मों, जिनमें हिंदू धर्म सबसे बड़ा है, के खिलाफ एकजुट होकर काम करते हैं और 'धार्मिक स्वतंत्रता' का एक अलग मापदंड लागू होता है।

इससे पता चलता है कि कैसे एचकेएन अपने युवा विद्वान-कार्यकर्ताओं को तैयार करता है और उन्हें वैश्विक स्तर पर एक विशिष्ट एजेंडा फैलाने के लिए रणनीतिक पदों पर तैनात करता है। हुसैन का उदाहरण हार्वर्ड के उस सत्ता नेटवर्क को दर्शाता है जो आइवी लीग की दीवारों से परे तक फैला हुआ है। हार्वर्ड में जो भी विचारधाराएँ गढ़ी जाती हैं, उनका उद्देश्य शेष विश्व को 'शिक्षित' करना होता है। कैनेडी स्कूल एक बार निशाना बन जाने पर किसी भी देश में हस्तक्षेप करने का एक महत्वपूर्ण अड्डा बन जाता है।

हम बाद में भारतीय सिविल सेवा प्रशिक्षण में हार्वर्ड की भूमिका पर चर्चा

करेंगे। वे लगातार अपने संपर्कों का उपयोग करके विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (USCIRF) और अन्य संस्थानों जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अपने लोगों को नियुक्त कर रहे हैं, जो हार्वर्ड को विश्व गुरु के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने में मदद करते हैं।

अनुरीमा भार्गवा यूएससीआईआरएफ में भारत के खिलाफ चल रही कार्यवाही में शामिल एक और जाना-पहचाना चेहरा हैं। हार्वर्ड से उनके घनिष्ठ संबंध हैं, जहां उन्होंने काफी समय बिताया है। 2021 में, हार्वर्ड गजट ने गर्व से हार्वर्ड की छात्रा के रूप में उनके महत्व को रेखांकित किया। उन्हें 'भूरे और अश्वेत छात्रों' को लामबंद करके दबे-कुचले और बेबस लोगों की सेवा करने के लिए तैनात किया गया है।

भार्गवा का विश्वविद्यालय से गहरा जुड़ाव रहा है। उन्होंने फिलिप्स ब्रूक्स हाउस सेंटर फॉर पब्लिक सर्विस एंड एंगेज्ड स्कॉलरशिप द्वारा आयोजित वार्षिक पब्लिक इंटरेस्ट कॉन्फ्रेंस में मुख्य वक्ता के रूप में परिसर में छात्रों और पूर्व छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने हार्वर्ड कॉलेज में नेशनल एडवाइजरी बोर्ड फॉर पब्लिक सर्विस की सह-अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है, हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के कैर सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स में वरिष्ठ फेलो थीं और इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स में भी फेलो रह चुकी हैं। हार्वर्ड के प्रति अपनी सेवा के माध्यम से, उन्हें उम्मीद है कि वे छात्रों को यह दिखा सकेंगी कि सेवा के अनेक रूप होते हैं, जिनमें अपनी कहानी बताना या मौन को एकजुटता और आवाज देना शामिल है, ताकि उन्हें उद्देश्य पर आधारित एक आजीवन समुदाय बनाने या खोजने में मदद मिल सके, विभिन्नताओं के बावजूद एक-दूसरे से जुड़ सकें और विशेष रूप से भूरे और अश्वेत छात्रों को अपनी कहानियाँ साझा करने और समुदाय खोजने के लिए एक मंच प्रदान कर सकें।

हार्वर्ड से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के एक दशक बाद, भार्गवा को एचकेएस में स्थित कैर सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स में एक वरिष्ठ फेलो और इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स में एक फेलो के रूप में चुना गया।
एचकेएस कैर सेंटर में अपनी फेलोशिप के अंत में, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने भार्गवा को यूएससीआईआरएफ में नियुक्त किया, जहां वह वर्तमान में उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।
शक्तिशाली यूएससीआईआरएफ में भार्गवा को 'हिंदू आवाज' के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन भारत में सीएए विधेयक के संबंध में अपने रुख के उदाहरण के रूप में, भार्गवा ने कहा कि 'भारत के विवादास्पद नागरिकता कानून "चिंताजनक" हैं'। इंडिया अब्रॉड ने रिपोर्ट किया कि 'यूएससीआईआरएफ ने सीएए को "गलत दिशा में एक खतरनाक मोड़" बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की और ट्रंप प्रशासन से गृह मंत्री अमित शाह पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया - जो इस कानून के पीछे मुख्य सूत्रधार हैं'।
2021 में, भार्गवा ने यूएससीआईआरएफ में भारत के खिलाफ अपना अभियान जारी रखा:
भारत में इन सुनियोजित और लगातार हो रहे घोर उल्लंघनों के कारण, अमेरिकी समुद्री सुरक्षा परिषद (यूएससीआईआरएफ) ने भारत को विशेष चिंता का देश (सीपीसी) घोषित करने की सिफारिश की है।
यूएससीआईआरएफ आयुक्त अनुरीमा भार्गवा का कहना है कि ऐसी राष्ट्रीय और राज्य नीतियां एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बना रही हैं जो भारत में आमतौर पर देखे जाने वाले बहुलवाद के ऐतिहासिक संरक्षण से भटक रहा है, और कई लोग इस मुद्दे पर बोलने वालों को चुप कराने के सरकार के प्रयासों को लेकर चिंतित हैं।
भारत को 'विशेष चिंता वाले देशों' की सूची में डालना, हार्वर्ड से शिक्षित

उन हिंदू-विरोधी आवाजों का एक विशिष्ट उदाहरण है जो हिंदू होने का ढोंग करते हैं। भार्गव से एक पीढ़ी पहले, एक और महिला यूएससीआईआरएफ में सेवा करने वाली पहली हिंदू बनीं, और उन्होंने भी अपने आधिकारिक पद पर रहते हुए हिंदुओं के अधिकारों से समझौता किया। वह भी हार्वर्ड की एक ऐसी छात्रा थीं जिन पर हार्वर्ड को गर्व था। प्रीता बंसल ने 1986 में हार्वर्ड से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और हार्वर्ड के कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में विजिटिंग फेलो बनीं। एचकेएस फेलोशिप के तुरंत बाद, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने उन्हें 2004 में यूएससीआईआरएफ का अध्यक्ष नियुक्त किया। भारतीय समाचार पत्रों की सुर्खियों में उत्तराखंड राज्य के रुड़की शहर की इस छोटी लड़की की उपलब्धियों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया:

न्यूयॉर्क राज्य की पूर्व सॉलिसिटर जनरल प्रीता बंसल को अमेरिकी आपराधिक प्राधिकरण (USCIRF) का सदस्य नियुक्त किया गया है। यह पहली बार है कि कोई भारतीय अमेरिकी इतने प्रतिष्ठित पद पर आसीन होंगी... जो राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कांग्रेस को अन्य देशों में धार्मिक स्वतंत्रता और इसे बढ़ावा देने के सर्वोत्तम तरीकों पर सलाह देता है।

2004 में, बंसल के नेतृत्व में, यूएससीआईआरएफ ने भारत को विशेष चिंता वाले देशों की सूची में शामिल किया। अपने कार्यों के लिए बंसल को भरपूर पुरस्कार मिले हैं। उन्हें 2006 में नेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ विमेन का 'वुमन ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस अवार्ड' मिला; 2008 में नेशनल लॉ जर्नल द्वारा उन्हें 'अमेरिका के 50 सबसे प्रभावशाली अल्पसंख्यक वकीलों' में से एक नामित किया गया; और नेशनल साउथ एशियन बार एसोसिएशन से 'पायनियर अवार्ड', एस्पेन इंस्टीट्यूट में हेनरी

क्राउन फेलोशिप और एशियन पैसिफिक अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर कांग्रेसनल स्टडीज स्टीवर्डशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया।
हमारा पाँचवाँ और अंतिम उदाहरण आशुतोष वर्शनी का है, जो हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के ऐश सेंटर में फेलो थे। उन्होंने भी यूएससीआईआरएफ के समक्ष भारतीय सरकार के रुख के विरुद्ध गवाही देते हुए कहा था कि सीएए 'मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और राजनीति में मुसलमानों के हाशिए पर धकेलने का अनुकूल माहौल बनाता है'। हालाँकि, उनके शोध से होने वाला नुकसान कहीं अधिक गहरा है, विशेष रूप से हार्वर्ड द्वारा उन्हें अन्यत्र रणनीतिक शैक्षणिक पदों पर नियुक्त किए जाने के बाद। अक्टूबर 2021 में, द इंडियन एक्सप्रेस के एक प्रमुख स्तंभकार के रूप में, उन्होंने 'जिम क्रो हिंदुत्व' शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया। उन्होंने अमेरिकी नस्लवाद के चरम पर रहे जिम क्रो कानूनों को भारत पर थोप दिया। उनका कहना है कि भारत 'जिम क्रो हिंदुत्व' की ओर लौट रहा है, क्योंकि सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को हटा दिया है, जिसने जम्मू और कश्मीर को शेष भारत से अलग रखा था। वे अपने अमेरिकी पाठकों को यह जानकारी नहीं देते कि जम्मू और कश्मीर एक क्षेत्रीय विवाद रहा है, जिसमें हर भारतीय सरकार ने, चाहे वह वामपंथी हो या दक्षिणपंथी विचारधारा की, भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए संघर्ष किया है। यह सवाल उठता है कि क्षेत्रीय मुद्दे को सुलझाने के लिए उठाया गया राजनीतिक कदम जिम क्रो कानून का मुद्दा कैसे बन गया।
अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए, वर्शनी ने जिम क्रो युग के दौरान होने वाली लिंचिंग की प्रथा की तुलना भारत में मवेशी चोरी और बछड़ों की हत्या जैसे मुद्दों से जुड़ी हिंसा की छिटपुट घटनाओं से गलत तरीके से की है। यह एक संदर्भ से लिए गए तथ्यों को दुनिया के दूसरे छोर पर स्थित एक पूरी तरह से असंबंधित संदर्भ पर थोपना है। एक राजनीतिक

वैज्ञानिक के रूप में, उन्होंने चेतावनी दी है कि 'भारत की राजनीति का उदारवाद तेजी से पतन की ओर है'। लेकिन उनके विश्लेषण में वस्तुनिष्ठता का अभाव है और वे जानबूझकर उन महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज करते हैं जो उनके सिद्धांत का खंडन करते हैं। उदाहरण के लिए, वे यह स्वीकार करने में विफल रहते हैं कि अनुच्छेद 370 पर उठाया गया कदम दलितों और महिलाओं को व्यापक अधिकार बहाल करता है, जो पहले जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में उनसे छीन लिए गए थे। ब्राउन विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में, वे इसाबेल विल्करसन के 'जाति = नस्ल' के विचार को नए सिरे से प्रस्तुत करते हैं और इसे भारत में लागू करते हैं। उनका योगदान यह है कि वे भारतीय मुसलमानों को भी इस समीकरण के 'जाति' पक्ष में शामिल करते हैं। उनके अनुसार, भारत के मुसलमान अमेरिका के अश्वेतों के समान हैं, और हिंदुत्व मूलतः श्वेत वर्चस्व का अमेरिकी समकक्ष है। यह दावा करने का एक तरीका है कि मुसलमानों को एक 'संरक्षित वर्ग' के रूप में नामित किया जाना चाहिए जिसकी आलोचना नहीं की जा सकती। जब वर्शनी से पूछा गया कि अमेरिका को भारत के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए, तो उन्होंने अमेरिका के सामने एक रणनीति रखी, जिसमें उपलब्ध विकल्प, इस तरह के हस्तक्षेप के फायदे और नुकसान, और संभावित प्रतिरोध शामिल थे। उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि क्या अमेरिका को भारत पर प्रतिबंध लगाने चाहिए या कूटनीति का सहारा लेना चाहिए; और भारत की संभावित जवाबी कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए, भारत को नियंत्रण में रखने के लिए अमेरिका के पास उपलब्ध विभिन्न हस्तक्षेपों के बारे में बताया। संक्षेप में, वे अमेरिका को सलाह दे रहे थे कि भारत पर मुकदमा चलाने और उसे नियंत्रण में रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है।

वर्षने बार-बार यह दावा करते हैं कि हिंदू राष्ट्र या देश जैसी कोई चीज कभी हो ही नहीं सकती, उनका कहना है, 'जो लोग यह तर्क देते हैं कि भारतीय राष्ट्र 5000 साल पुराना है, लोकतांत्रिक सिद्धांत इस दावे को स्वीकार नहीं करता, यह केवल एक वैचारिक दावा है।' वे कहते हैं कि भारत पांच हजार वर्षों से एक सभ्यता रहा है, न कि एक राष्ट्र। इस प्रकार, भारत एक राजनीतिक संरचना के रूप में स्वतंत्रता के दौरान अस्तित्व में आया।

लेकिन भारत की वैधता का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्र और राजनीतिक संरचना की पश्चिमी परिभाषा को ही मानदंड क्यों बनाया जाना चाहिए? वर्शनी का दृष्टिकोण इतना उपनिवेशवादी है कि वे पश्चिमी राजनीतिक सिद्धांतों से परे सोच ही नहीं सकते। वास्तव में, उनके तर्क को उलट कर यह भी कहा जा सकता है कि वेस्टफेलिया के अनुसार 'राजनीतिक संरचना' द्वारा परिभाषित 'राष्ट्र' की तुलना में भारत परंपरागत रूप से एक सभ्यता के रूप में अधिक समृद्ध था। और यदि वे इस तर्क का खंडन करना चाहें, तो उन्हें यह साबित करने के लिए ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे कि प्राचीन भारत राष्ट्र विफल था। अन्यथा, केवल यह कहने से कुछ भी सिद्ध नहीं होता कि राष्ट्र की अवधारणा पश्चिमी राष्ट्र-राज्य की अवधारणा में फिट नहीं बैठती।

विश्लेषण का बेहतर तरीका यह होगा कि यह प्रश्न उठाया जाए कि क्या राष्ट्र की संरचना, जो एक साझा सभ्यता से एकजुट थी, वास्तव में अपने नागरिकों की सेवा करने में सफल रही? क्या इसने अपने नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान किया, क्या इसने अच्छी शिक्षा दी और क्या इसने प्रगति की? प्राचीन राष्ट्र की तुलना आज के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों से नहीं, बल्कि उस समय की अन्य प्राचीन सभ्यताओं और देशों से करनी होगी। ऐसा दृष्टिकोण वर्शनी के सिद्धांत को गलत साबित कर देगा।

प्राचीन यूनानियों, चीनी लोगों से लेकर हाल ही में यूरोपीय लोगों द्वारा लिखे गए सभी ऐतिहासिक वृत्तांतों से पता चलता है कि भारत राष्ट्र एक उन्नत और सफल समाज माना जाता था।

स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, भारत पश्चिमी मानदंडों के अनुसार एक राष्ट्र राज्य बन गया, जिसका संविधान पश्चिमी शैली की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था। यह आवश्यक था क्योंकि पश्चिम के प्रभुत्व वाली विश्व व्यवस्था ने यह निर्धारित करने के लिए बुनियादी नियम तय किए थे कि किसी उपनिवेश को स्वशासन के लिए कब योग्य माना जाना चाहिए, और यह मानदंड राष्ट्र राज्य की पश्चिमी अवधारणा थी। आधुनिक राष्ट्र बनने की यह अनिवार्यता सभी उपनिवेशों पर उनकी स्वतंत्रता की पूर्व शर्त के रूप में थोपी गई थी। इससे राष्ट्र की अवधारणा किसी भी तरह से अमान्य नहीं हो जाती।

1648 की वेस्टफेलिया संधि द्वारा स्थापित ढाँचों के आधार पर राष्ट्र की अवधारणा का मूल्यांकन किया गया है। आज, राज्य संप्रभुता, राष्ट्रों के बीच मध्यस्थता और कूटनीति की व्यापक रूप से स्थापित अवधारणाओं की उत्पत्ति इसी संधि से हुई है। वेस्टफेलिया के अर्थ में एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के रूप में भारत उपनिवेशवाद की संतान है, और इस बाहरी थोपे गए नियम को भारत के सामने आने वाली कई समस्याओं के संभावित कारण के रूप में देखा जाना चाहिए। एक ओर भारत राष्ट्र एक सभ्यता के रूप में है, और दूसरी ओर आधुनिक भारत पश्चिमी शैली का राष्ट्र बनने का प्रयास कर रहा है, इन दोनों के बीच विरोधाभासों को समझना आवश्यक है। यह स्पष्ट नहीं है कि समस्या सभ्यता में है, न कि आधुनिक ढाँचे में।

हालांकि, यह स्पष्ट है कि स्वयं को उत्तर-औपनिवेशिकवादी घोषित करने वाले वर्शनी, औपनिवेशिक दृष्टिकोण का उपयोग कर रहे हैं, इस प्रकार

राष्ट्र के विचार को उसके अपने गुणों के आधार पर देखने में विफल हो रहे हैं।

वर्षने इतिहासकारों की इस बात के लिए भी आलोचना करते हैं कि वे इस स्थापित तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि मुसलमानों ने बारह सौ साल पहले भारत पर आक्रमण किया था, अपना धर्म थोपा था और भारतीय दरबारों में फारसी भाषा को आधिकारिक भाषा बना दिया था; और यह कि कुछ सबसे पवित्र हिंदू स्थलों को ध्वस्त कर दिया गया और उनकी जगह इस्लामी स्मारक बना दिए गए। नीचे दिए गए अंश में, वे प्रधानमंत्री मोदी की इस बात के लिए निंदा करते हैं कि उन्होंने उस इस्लामी शासन को उपनिवेशवाद का एक रूप बताया है, क्योंकि उनका मानना है कि यह हिंदू राष्ट्रवादियों का एक आम तर्क यह है कि भारत का उपनिवेशीकरण आठवीं शताब्दी में सिंध में मुस्लिम शासकों के आगमन से शुरू हुआ, न कि 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल पर विजय से। इतिहास की किताबों में यही दावा प्रचलित है, और यह भी तर्क दिया जाता है कि यद्यपि भारत के पहले मुसलमान मध्य पूर्व से आए होंगे, वे देश में बस गए, खुद को भारतीय रूप दिया और मध्य पूर्व से संबंध तोड़ लिए, सिवाय जीवन में एक बार मक्का के सबसे पवित्र तीर्थस्थल की यात्रा करने के, जैसा कि इस्लाम में अनिवार्य है। यह ऐतिहासिक दावा हिंदू राष्ट्रवादियों को स्वीकार्य नहीं है। उनके लिए, इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसने बलपूर्वक भारत पर विजय प्राप्त की, और भारत के मूल निवासियों, हिंदुओं को पराजित और अपमानित किया।

उनके तर्क में कई खामियां हैं। सिर्फ इसलिए कि इस्लामी विजय के परिणामस्वरूप उपनिवेशीकरण हुआ, यह विचार 'मानक' नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं कि यह गलत है। आखिर यह 'मानक' किसका है? यह सच है कि विदेशी मुस्लिम शासकों ने स्वयं को भारतीय रूप दिया, लेकिन यह

केवल भारत द्वारा प्रदान की जाने वाली भव्य जीवनशैली का आनंद लेने के उद्देश्य से था, जो उनके मूल देश में उपलब्ध नहीं थी। अमेरिका के श्वेत यूरोपीय विजेताओं ने भी अपने घर छोड़े, नई भूमि में बस गए और यूरोप में न पाई जाने वाली कई प्रथाओं को अपनाकर स्वयं को अमेरिकी रूप दिया। इसी प्रकार, यूरोपीय उपनिवेशवादी भी भारत में बस गए। इसलिए, केवल इसलिए कि विदेशी विजेता विजय के बाद देश में बस जाते हैं और उसे अपना घर बना लेते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि वे उपनिवेशवादी नहीं थे। इनमें से प्रत्येक उदाहरण अंतरमहाद्वीपीय विजय, लूट और पराजित मूल निवासियों पर आक्रमणकारी की संस्कृति, धर्म और भाषा थोपने का कार्य था।

मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अपने साथ लेखकों को भेजा ताकि वे अपनी लूटपाट, हिंदू दासों को पकड़ने और पराजितों के बड़े पैमाने पर नरसंहार का दस्तावेजीकरण कर सकें। फारसी में लिखे गए वीरता के ये ऐतिहासिक अभिलेख न केवल भारत में बल्कि यूरोप और अमेरिका के संग्रहालयों और अभिलेखागारों में भी पाए जाते हैं। मध्य एशिया के दास बाजारों में हिंदुओं की बड़े पैमाने पर बिक्री पूर्व सोवियत संघ के अभिलेखागारों में अच्छी तरह से स्थापित है और स्पष्ट रूप से मिशिगन विश्वविद्यालय में स्कॉट लेवी के पीएचडी शोध प्रबंध का विषय था। भारतीयों द्वारा अपने अतीत के इन पहलुओं पर पहले चर्चा न करने को उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए जिस परिप्रेक्ष्य में महिलाओं, अश्वेतों और LGBTQ+ समुदायों के बारे में चर्चा की जाती है। इन सभी मामलों में, पीड़ित अब जाकर अपने अतीत की पीड़ा पर चर्चा करने के लिए जागरूक हो रहे हैं। ये अतीत का पुनर्मूल्यांकन करने और प्रतिशोध की भावना में परिवर्तित हुए बिना, जिम्मेदारी से उसका सामना करने के उदाहरण हैं।

हम वर्शनी से सहमत हैं कि अतीत में हुए मुस्लिम अत्याचारों के लिए वर्तमान मुसलमानों को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। कोई भी अपने पूर्वजों के आचरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, और लोगों का मूल्यांकन केवल उनके अपने कार्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। लेकिन वह अतीत के इस्लामी अत्याचारों का बचाव कर रहे हैं।

हिंदू राष्ट्रवादियों ने मुस्लिम रियासती सत्ता का इस्तेमाल कुछ मुस्लिम शासकों, विशेषकर बाबर और औरंगजेब, और उनसे पहले ग़ज़नी और गौरी के आक्रमणों के आचरण को एक व्यापक मुस्लिम-विरोधी राजनीतिक कथा में ढालने के लिए किया है। [...] कोई भी गंभीर इतिहासकार मुस्लिम शासन की सदियों में हिंदू-दमन और भारत-विरोध की अटूट श्रृंखला नहीं पाता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि रियासती आचरण में मुस्लिम जनता किस प्रकार संलिप्त है? उन्हें दंडित क्यों किया जाए?

हम इस बात से सहमत हैं कि अतीत की घटनाओं को वर्तमान समय की कटुता में तब्दील नहीं होने देना चाहिए, लेकिन साथ ही, इतिहास की किताबों में हिंदुओं के खिलाफ हुए अत्याचारों को उसी तरह से समझाया जाना चाहिए जिस तरह से अश्वेत अमेरिकी और मूल अमेरिकी अपने खिलाफ अतीत में हुए अत्याचारों के उचित दस्तावेजीकरण की मांग करते हैं।

इस्लामी उत्पीड़न के इतिहास को नकारना न केवल झूठा है, बल्कि इससे उग्र मुस्लिम नेता भारत पर आक्रमण करने और हिंदुओं को जातिवाद और अन्य अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भारत को अपना उपहार बताने के लिए अपने धर्म की श्रेष्ठता का दावा करते हैं। दूसरे शब्दों में, इस्लामी आक्रमणकारियों की प्रतिष्ठा बचाने के लिए, आज के इतिहासकारों और राजनीतिक नेताओं द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि हिंदू विधर्मियों की

निम्न संस्कृति को विदेशी आक्रमण की आवश्यकता थी ताकि मूल निवासियों को उनकी दुर्दशा से बचाया जा सके। यही तर्क अंग्रेजों ने उपनिवेशवाद को सभ्यता का मिशन और तथाकथित 'श्वेत व्यक्ति का बोझ' बताकर उचित ठहराने के लिए भी इस्तेमाल किया था। मुस्लिम अंधराष्ट्रवाद को इस दावे से बल मिला है कि भारत के विधर्मियों को सभ्य बनाना मुसलमानों का बोझ था, जिसके लिए उन्हें मध्य पूर्व से हजारों मील की यात्रा करनी पड़ी।

सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। एक तो यह कि मुस्लिम शासन के दौरान दासों का व्यापार खूब फलता-फूलता था, जिसमें भारतीयों को मध्य एशिया के दास बाजारों में भेजा जाता था और साथ ही अफ्रीकी दासों को भारत में आयात किया जाता था। इतिहास के पाठ्यक्रमों में इन तथ्यों को पढ़ाना, साथ ही हिंदू समाज की अतीत और वर्तमान की कमियों को उजागर करना, राजनीतिक रूप से गलत नहीं माना जाना चाहिए।

दूसरे शब्दों में कहें तो, सच्चाई को राजनेताओं के नियंत्रण में लेकर सौदेबाजी का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो गैर-जिम्मेदाराना हेरफेर अपरिहार्य हो जाएंगे। वर्शनी अपने महत्वपूर्ण पद को देखते हुए आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं और उपयोगी भूमिका निभा सकते हैं।

वर्षने भारतीयों द्वारा ‘राष्ट्रवाद’ की वकालत करने और ‘राष्ट्र-विरोधी’ की निंदा करने की भी आलोचना करते हैं। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा समर्थित तीन वर्षीय परियोजना की एक रिपोर्ट में, वर्षने ‘राष्ट्रवाद’ शब्द के प्रयोग पर तीखी टिप्पणी करते हैं। वे अपने अमेरिकी सरकारी सलाहकारों और प्रायोजकों से बात करते हुए कहते हैं: ‘अमेरिकी विदेश विभाग की धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी रिपोर्टों में भारत की हालिया सरकारों

की अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों को पर्याप्त सहायता—जिसमें शारीरिक सुरक्षा भी शामिल है—प्रदान न करने के लिए आलोचना की गई है।' वे चेतावनी देते हैं कि हिंदू राष्ट्रवाद से भारत का लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन इसे अंग्रेज़ी भाषा की बारीकियों के इस्तेमाल से जुड़ा एक शाब्दिक मुद्दा माना जाना चाहिए। भारतीय अक्सर अंग्रेज़ी शब्दों का इस्तेमाल पश्चिमी विद्वानों से अलग अर्थ में करते हैं। कुछ पीढ़ियों पहले तक पश्चिम में भी देशभक्ति और राष्ट्रवाद शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे के स्थान पर किया जाता था। लेकिन नाज़ियों और अन्य फासीवादियों (जो पश्चिमी सभ्यता की उपज थे) द्वारा इसके इस्तेमाल के कारण राष्ट्रवाद शब्द बदनाम हो गया। परिणामस्वरूप, अब 'देशभक्ति' शब्द का प्रयोग सकारात्मक अर्थ में किया जाता है, जिसका अर्थ है अपनी भूमि और संस्कृति के प्रति प्रेम, बिना इसे किसी पर थोपे, जबकि 'राष्ट्रवाद' एक बुरा शब्द बन गया है, जो तानाशाही और विविधता के प्रति असहिष्णुता को दर्शाता है।

पश्चिमी देशों से प्रशिक्षित लोगों को छोड़कर, भारतीयों ने इस सूक्ष्म अंतर को नहीं समझा है, और न ही उनसे इसकी अपेक्षा की जानी चाहिए। वैसे भी, राष्ट्रवाद और देशभक्ति के बीच का अंतर व्यक्तिपरक है, निरपेक्ष नहीं। वर्शनी अंग्रेजी शब्दों के भारतीय प्रयोग की इस विशिष्टता को समझाने में विफल रहे हैं। किसी भी स्थिति के सार को देखना चाहिए, न कि यह कि अंग्रेजी शब्दावली का सही प्रयोग किया जा रहा है या नहीं। मुख्य बात यह है कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के आरोपी भारतीयों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि भारत के बारे में उनकी धारणा वैदिक तत्वमीमांसा पर आधारित अंतर्निहित विविधता की है।

गलत सूचना युद्ध

एचकेएस में स्थित शोरेनस्टीन सेंटर ऑन मीडिया, पॉलिटिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी अपने चार्टर का वर्णन इस प्रकार करता है:
यह शोध इस बात की समझ बढ़ाने के लिए समर्पित है कि लोग सूचना तक कैसे पहुँचते हैं, उसका निर्माण कैसे करते हैं और उसे कैसे संसाधित करते हैं, विशेष रूप से समाचार और सामाजिक मुद्दों से संबंधित मामलों में, और हमारे सूचना पारिस्थितिकी तंत्र के सामने आने वाली समस्याओं के संभावित समाधानों का वर्णन करने के लिए भी समर्पित है।
हार्वर्ड में सूचनाओं के निर्माण और प्रवाह को नियंत्रित करने वाला यह एक और शक्तिशाली गठजोड़ है। यदि आप हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में भारत के बारे में कुछ भी खोजते हैं, तो आपको संभवतः भारत में मानवाधिकारों, सामाजिक न्याय और यौन हिंसा के प्रति दृष्टिकोण के संदर्भ में हर चीज की भयावहता पर बहुत सारी सामग्री मिलेगी। उदाहरण के लिए, शोरेनस्टीन सेंटर के पास भारत में बलात्कार संस्कृति और प्रेस की भूमिका पर एक शोध पत्र है।
सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों और प्रेस में संपादकीय लेखों के बाद, भारतीय सरकार ने देश के कानूनों और महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण की जांच के लिए एक समिति का गठन किया, जिसने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की – फिर भी मीडिया कवरेज सतही रहा, और सरकार ने अभी तक सुझाए गए सुधारों को लागू नहीं किया है। जॉली [लेखिका] ने सुझाव दिए हैं कि भारतीय मीडिया और सरकार महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए किस प्रकार काम कर सकते हैं, उन समस्याओं का समाधान करते हुए जो पितृसत्तात्मक संरचनाओं में निहित हैं। यह लेख सार्वजनिक राय और नीति को आकार देने में यौन हिंसा की रिपोर्टिंग के महत्व पर भी प्रकाश डालता है।
अपनी सिफ़ारिशों के तहत, लेखिका सुझाव देती हैं कि भारतीय समाचार

संस्थानों को 'विशेष रूप से लैंगिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने वाले पत्रकारों' की नियुक्ति करनी चाहिए ताकि बलात्कार को एक अलग घटना के रूप में नहीं, बल्कि उस सामाजिक संदर्भ में रिपोर्ट किया जाए जिसमें यह घटित होता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बलात्कार, घर के भीतर बलात्कार और संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में बलात्कार जैसी घटनाओं को अधिक कवरेज मिल सकेगी। महिला पत्रकारों की संख्या बढ़ाने और महिलाओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की बात करना निश्चित रूप से एक अच्छा विचार है। लेकिन समस्या यह है कि 'सूचना पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने और स्वस्थ लोकतंत्र का समर्थन करने' के दायित्व से खुद को नैतिक प्रहरी के रूप में स्थापित करके, शोरेनस्टीन सेंटर ने कई बार अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है और गलत सूचनाओं का स्रोत साबित हुआ है।

यह भी चिंताजनक है कि शोरेनस्टीन सेंटर के चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से गहरे संबंध बताए जा रहे हैं। नेशनल पल्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस केंद्र में सीसीपी के कई फेलो रहे हैं और यह पार्टी के अनुरूप विचारों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुष्प्रचार-विरोधी मंच होने का दिखावा करते हुए, शोरेनस्टीन वास्तव में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की उन बातों को खारिज करके उसकी मदद करता है जिन्हें सीसीपी सार्वजनिक नहीं करना चाहती।

इस केंद्र में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सलाहकारों में स्टीवन डोंग जैसे लोग शामिल हैं, जिन्होंने शी जिनपिंग के पूर्व शिक्षण संस्थान, सिंघुआ विश्वविद्यालय में वैश्विक पत्रकारिता संस्थान के निदेशक के रूप में कार्य किया है और जो राज्य द्वारा संचालित समाचार चैनल चाइना सेंट्रल टेलीविजन (सीसीटीवी) के पूर्व प्रस्तुतकर्ता भी रह चुके हैं।

एक अन्य व्यक्ति - ली शिगुआंग - सिंघुआ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं,

चीनी विदेश मंत्रालय की सार्वजनिक कूटनीति संबंधी सलाहकार समिति के सदस्य हैं और राज्य द्वारा संचालित मीडिया आउटलेट शिन्हुआ के पूर्व वरिष्ठ संपादक हैं।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है:

एक अन्य साथी, झेंग्रांग हू, चीन के सरकारी संचार विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय रेडियो और टेलीविजन अध्ययन केंद्र के निदेशक थे। ... झेंग्रांग ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी राज्य परिषद के पत्रकारिता और संचार अनुशासन मूल्यांकन समूह के अध्यक्ष, शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा पर्यवेक्षण समिति के अध्यक्ष, चीन संचार संघ के अध्यक्ष और शिक्षा मंत्रालय में पाठ्यक्रम विकास और अनुशासन स्थापना विशेषज्ञ समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है।

और इसके अलावा,

शोरेनस्टीन सेंटर ने हार्वर्ड के ऐश सेंटर के साथ मिलकर कम से कम 10 कार्यक्रमों की मेजबानी की है, जिसने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी और उसके स्वामित्व वाली कंपनियों से लाखों डॉलर लिए हैं और चीनी सरकारी मीडिया आउटलेट्स द्वारा लोकप्रिय किए गए अध्ययन प्रकाशित किए हैं जिनमें दावा किया गया है कि सरकार को रिकॉर्ड-उच्च समर्थन प्राप्त है।

चीन के इतने अधिक प्रभाव के साथ, शोरेनस्टीन सेंटर किसी भी प्रकार की गलत और भ्रामक सूचनाओं पर मध्यस्थ होने का दावा शायद ही कर सकता है, भारत के बारे में जानकारी के लिए एक ईमानदार मध्यस्थ के रूप में काम करने की तो बात ही दूर है।

चुनावों को प्रभावित करने में सोशल मीडिया की भूमिका में आए विस्फोट के बाद से, हार्वर्ड ने गलत सूचनाओं की निगरानी करने की अपनी स्व-निर्धारित भूमिका के तहत कई पहलें शुरू की हैं। उदाहरण के लिए, कैंपस

रिफॉर्म, एक रूढ़िवादी निगरानी वेबसाइट ने रिपोर्ट किया है कि हार्वर्ड ने कई प्रतिष्ठित रूढ़िवादी और उदारवादी समाचार एजेंसियों को 'फर्जी' समाचार आउटलेट के रूप में ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जबकि उदारवादी समाचार आउटलेट को विश्वसनीय मानकर खुली छूट दे दी है।

हार्वर्ड के फर्जी खबरों पर दिशानिर्देश छात्रों को ब्राउज़र प्लग-इन डाउनलोड करने की सलाह देते हैं जो सैद्धांतिक रूप से उन वेबसाइटों का पता लगा सकते हैं जो "विश्वसनीय स्रोत नहीं हो सकती हैं," और द ड्रज रिपोर्ट, ब्रेइटबार्ट, द डेली सिग्नल जैसे प्रसिद्ध आउटलेट्स को चिह्नित करते हैं, और यहां तक कि लाइफसाइट न्यूज़ को "क्लिकबेट" भी कहते हैं। हालांकि, हार्वर्ड का दावा है कि उसका गाइड केवल "सभी प्रकार की गलत सूचनाओं के प्रसार और उन्हें पहचानने और समाचारों को अधिक जानकारीपूर्ण ढंग से पढ़ने के लिए उपकरणों का संक्षिप्त परिचय प्रदान करता है।"

एचकेएस मिसइन्फॉर्मेशन रिव्यू की शुरुआत 2019 में एचकेएस के शोरेनस्टीन सेंटर में हुई थी। इसकी वेबसाइट खुद का महिमामंडन करते हुए वर्णन करती है।

यह एकमात्र पीयर-रिव्यू जर्नल है जो गलत सूचना और दुष्प्रचार पर बहुविषयक शोध प्रकाशित करने के लिए समर्पित है। यह 'तेज़ पीयर रिव्यू' प्रक्रिया पर काम करता है जो लेखों की अकादमिक कठोरता सुनिश्चित करता है, लेकिन पारंपरिक अकादमिक प्रकाशन की तुलना में बहुत कम समय सीमा में, क्योंकि प्रकाशित किया जा रहा शोध 'समयोचित और दुष्प्रचार और इसके प्रभावों से निपटने के लिए वर्तमान में काम कर रहे विशेषज्ञों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण' है।

हम इस पूर्वाग्रह को स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। 2019 के आम चुनावों में भारत में भाजपा की भारी जीत ने पश्चिम के

उन लोगों को चौंका दिया और निराश किया जो पूर्ववर्ती सरकार के समर्थक थे। हार्वर्ड ने उन तकनीकों का अध्ययन करने का निर्णय लिया जिन्होंने चुनाव परिणामों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया, जिन्हें वह अवांछनीय मानता था। इसकी 'गलत सूचना समीक्षा' वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध पत्र में विभिन्न प्लेटफार्मों पर मौजूद जानकारी का अध्ययन किया गया:

हम भारत में राजनीतिक रूप से प्रेरित व्हाट्सएप समूहों के एक बड़े संग्रह का अध्ययन करते हैं, जिसमें 2019 के भारतीय राष्ट्रीय चुनावों से पहले की अवधि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यादृच्छिक और लोकप्रिय छवियों के नमूनों को वर्गीकृत करके, हम पाते हैं कि साझा की गई छवियों में से लगभग 10% गलत सूचनाएँ हैं और इनमें से अधिकांश तीन प्रकार की छवियों में आती हैं। मशीन लर्निंग विधियों का उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है कि कोई वायरल छवि गलत सूचना है या नहीं... [43]

इस परियोजना का उद्देश्य गलत सूचनाओं को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करना था, ताकि गलत सूचना फैलाने के पीछे के उद्देश्यों का पता लगाया जा सके और अंततः ऐसे एल्गोरिदम विकसित किए जा सकें जो गलत सूचनाओं को फैलाने वाले कारकों के आधार पर उनकी पहचान कर सकें। इसका लक्ष्य यह भी पता लगाना है कि गलत सूचनाओं का उपयोग अशांति और हिंसा भड़काने के लिए कैसे किया जाता है। ऐसी परियोजना में पूर्वाग्रह अंतर्निहित होता है। उदाहरण के लिए, इसने तीन पत्रकारों को 2,500 छवियों पर मैन्युअल रूप से टिप्पणी करने और उनमें से 'फर्जी' और 'पक्षपातपूर्ण' छवियों की पहचान करने के लिए नियुक्त किया, जो अपने आप में पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। उन्होंने भारत में तथ्य-जांच वेबसाइटों को भी मनमाने ढंग से चुना, जो पूर्वाग्रह का एक और स्रोत है। उनकी

विशेष रुचि उन गलत सूचनाओं में थी जिनमें अंधविश्वास, ऐतिहासिक और धार्मिक मिथक, राष्ट्रवाद और राजनीतिक मीम्स शामिल थे - जो हिंदू 'अतिवाद' को निशाना बनाने का एक अच्छा तरीका प्रतीत होता है।

केनेडी स्कूल के एक अन्य शोध पत्र में दावा किया गया कि वैश्विक दक्षिण (अर्थात भारत) में दुष्प्रचार और गलत सूचनाओं की निगरानी के लिए वैश्विक उत्तर में उपयोग की जाने वाली विधियों से भिन्न विधियों की आवश्यकता है, क्योंकि वैश्विक दक्षिण में 'दुष्प्रचार और गलत सूचनाओं की राजनीतिक अर्थव्यवस्था की गहरी समझ की तत्काल आवश्यकता है'। उदाहरण के तौर पर, लेख में दावा किया गया है कि फेसबुक भाजपा से जुड़े लोगों द्वारा संचालित है और इसलिए एक अलग दृष्टिकोण आवश्यक है: 'भारत में, फेसबुक और फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप पर हिंदू राष्ट्रवादी प्रचार के कारण मुसलमानों और निचली जातियों के खिलाफ उत्पीड़न, घृणास्पद भाषण, लिंचिंग और नरसंहार हुए हैं।' हार्वर्ड अपने लोगों को गेटकीपर के रूप में नियुक्त करने में असमर्थ था, इसलिए यह मान लिया गया कि भाजपा ने ही उन्हें नियुक्त किया होगा: 'जब भाजपा से जुड़े लोग फेसबुक इंडिया कार्यालय चलाते हैं तो संस्थागत जवाबदेही की उम्मीद करना मुश्किल है।'

एक अन्य शोध पत्र में भारत में चुनावों के दौरान व्हाट्सएप पर गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए वास्तविक समय में सूचना सहायता केंद्र स्थापित करने पर चर्चा की गई है। जाहिर है, हार्वर्ड के पास ऐसे सूचना सहायता केंद्रों को विकसित करने और वित्त पोषित करने की क्षमता है, जिन्हें निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ स्रोतों के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

हार्वर्ड की गलत सूचना अनुसंधान वेबसाइट इक्वालिटी लैब्स द्वारा किए गए एक अध्ययन को बढ़ावा देती है, जिसका शीर्षक है, क्रिटिकल

डिसइन्फॉर्मेशन स्टडीज: हिस्ट्री, पावर, एंड पॉलिटिक्स। यह अध्ययन हिंदुओं पर इस्लामफोबिया और जातिगत भेदभाव का आरोप लगाता है, जिसे भारत में गलत सूचना फैलाने और म्यांमार में 'रोहिंग्या नरसंहार' का कारण बताया गया है। रिपोर्ट का दावा है कि यह 'इतिहास, संस्कृति और राजनीति पर आधारित है और सत्ता और असमानता के मुद्दों पर केंद्रित है'। यह हार्वर्ड में अनुकूल स्वागत प्राप्त करने के लिए आधार तैयार करती है, जिसमें कहा गया है:

संयुक्त राज्य अमेरिका में, पहचान, विशेष रूप से नस्ल, दुष्प्रचार उत्पादकों के संदेशों और रणनीतियों में और दुष्प्रचार और भ्रामक जानकारी के प्रभाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ... दुष्प्रचार एक प्रमुख मीडिया रणनीति है जिसका उपयोग अमेरिका में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या आर्थिक शक्ति से वंचित आबादी की कीमत पर श्वेत वर्चस्व और सत्ता के पदानुक्रम को पुन: उत्पन्न और सुदृढ़ करने के लिए किया गया है।

इसके बाद यह तर्क भारत पर लागू किया जाता है, जहाँ हजारों रोहिंग्या शरण लेकर आए हैं: ‘फेसबुक इंडिया पर रोहिंग्या समुदायों के खिलाफ मुस्लिम विरोधी षड्यंत्र सिद्धांतों में हिंसा के आह्वान शामिल हैं, जैसे कि म्यांमार में रोहिंग्या नरसंहार को अंजाम देने वाले आह्वान।’ इसमें इस्लामोफोबिया को गलत सूचना बताया गया है जो ‘मौजूदा धार्मिक और जातिगत पदानुक्रमों के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफार्मों पर शक्ति और पहुंच के असमान वितरण का लाभ उठाती है’। हालांकि, इन कथनों पर कभी कोई बहस नहीं हुई और इन्हें बिना सोचे-समझे स्वीकार कर लिया गया।

भारत में सोशल मीडिया जागरूकता को लेकर बढ़ती चिंता हार्वर्ड को परेशान कर रही है। एक लेख में सुझाव दिया गया है कि फेसबुक और

व्हाट्सएप को गलत सूचनाओं को फ़िल्टर करने के अपने तरीके को बदलना चाहिए और उसकी जगह हार्वर्ड की अपनी प्रणाली को अपनाना चाहिए। हार्वर्ड का दावा है कि उसके तथ्य-जांच प्रयासों से गलत सूचनाओं का पता लगाने का उसका तरीका बेहतर है। विडंबना यह है कि चुनावी गलत सूचनाओं की स्व-घोषित पुलिस स्वयं एकतरफा बयानबाजी का स्रोत है।

हार्वर्ड का लक्ष्य विभिन्न देशों में ऐसी सत्ताधारी पार्टियों को स्थापित करना है जो उसके राजनीतिक सिद्धांतों से मेल खाती हों। एक विशेष प्रकार की गलत सूचना को मिटाने में निवेश करके, हार्वर्ड अपने विशाल धन और व्यापक नेटवर्क का उपयोग करके ऐसे दुष्प्रचार अभियान चलाता है जो उसकी विचारधारा का विरोध करने वालों को कुचल देते हैं और उससे जुड़े लोगों को बढ़ावा देते हैं।

एक दिलचस्प उदाहरण यह है कि हार्वर्ड ने एक छोटे अश्वेत ऑनलाइन संगठन, अमेरिकन डिसेंडेंट्स ऑफ स्लेवरी (ADOS) पर किस तरह हमला किया, जिसके विचार हार्वर्ड के राजनीतिक रुख के लिए खतरा थे। एक कठोर दृष्टिकोण अपनाते हुए, हार्वर्ड ने मुख्यधारा के मीडिया में व्यापक रूप से प्रसारित एक लेख में ADOS को बदनाम किया और आरोप लगाया:

हमने पाया है कि एडीओएस नेटवर्क रणनीतिक रूप से ब्रेकिंग न्यूज़ घटनाओं का उपयोग अश्वेत मतदाताओं को डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देने से हतोत्साहित करने के लिए करता है, जिसे हम दुष्प्रचार का प्रसार कहते हैं। इसके विपरीत, एडीओएस नेटवर्क ने अश्वेत समुदायों पर नोवेल कोरोनावायरस के प्रभाव के बारे में काफी हद तक चुप्पी साध रखी है, जिससे अश्वेत अमेरिकियों के हितों में काम करने के उसके दावे कमजोर पड़ते हैं।

ADOS की सीईओ ने पलटवार करते हुए अपने इस दावे को पुष्ट किया कि हार्वर्ड ने उनके संगठन को बदनाम करने के लिए घटिया शोध का इस्तेमाल किया था। उन्होंने इसे
यह रिपोर्ट आइवी लीग संस्थान के प्रतिष्ठित नाम का इस्तेमाल करके (ADOS) आंदोलन के खिलाफ चल रहे दुष्प्रचार अभियान को वैधता प्रदान करने का स्पष्ट प्रयास है। रिपोर्ट हमारे राजनीतिक समर्थन के लिए झूठे उद्देश्यों का एक जाना-पहचाना समूह प्रस्तुत करती है, जिसमें लेखक अक्सर ऐसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के प्रकाशन में अपेक्षित अनुभवजन्य रूप से समर्थित दावों के स्थान पर व्यक्तिपरक दावों, इशारों और सरासर झूठ का इस्तेमाल करते हैं।
हम इस आरोप को पूरी तरह से खारिज करते हैं कि … एडीओएस … ने कभी भी ब्रेकिंग न्यूज़ का इस्तेमाल करके अश्वेत समुदाय को रिपब्लिकन को वोट देने के लिए या 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में मतदान से पूरी तरह से दूर रहने के लिए प्रभावित किया है। और हार्वर्ड रिपोर्ट में इस दावे को साबित करने वाला एक भी सबूत ढूंढना व्यर्थ होगा।
उन्होंने हार्वर्ड की विद्वान मुताले नकोंडे पर हितों के टकराव का खुलासा न करने के लिए भी हमला किया और हार्वर्ड जैसी संस्था द्वारा गलत सूचना फैलाने पर उनके संगठन पर पड़ने वाले गंभीर प्रभाव पर चिंता व्यक्त की।
इस लेख ने हमारी प्रगति पर पानी फेर दिया, और मैं यह सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि क्या यह जानबूझकर किया गया था। एक धनी श्वेत संस्था एक छोटे से अश्वेत समूह को निशाना क्यों बनाएगी? MoveOn को इसमें क्यों शामिल किया गया, जबकि उनके हितों का टकराव स्पष्ट था?
“डिसइन्फॉर्मेशन क्रीप” लेख की प्रमुख लेखिका मुताले नकोंडे थीं। नकोंडे (sic) एआई फॉर द पीपल की संस्थापक सीईओ हैं। इस लेख के कई

सह-लेखक भी थे, जिनमें मीडिया मैटर्स और मूवऑन डॉट ऑर्ग से जुड़े कई लोग शामिल थे, ये दोनों ही प्रगतिशील राजनीतिक संगठन हैं। इस लेख के लिए शोध करते समय मैंने पाया कि एआई फॉर द पीपल की आधिकारिक वेबसाइट पर मुताले नकोंडे (sic) का सीईओ के रूप में कोई उल्लेख नहीं था; केवल बोर्ड और टीम का ही उल्लेख है। वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सामाजिक न्याय की दुनिया में एक स्टार बन चुकी हैं और अक्सर श्वेत बहुल संस्थानों में भाषण देती हैं। उनके संबंध फैशन उद्योग से लेकर व्हाइट हाउस और संयुक्त राष्ट्र तक फैले हुए हैं।

संभवतः मुकदमे के डर से, हार्वर्ड ने अपनी शोधार्थी नकोंडे के शोध पत्र को वापस ले लिया, उनकी लापरवाहीपूर्ण शोध को स्वीकार करते हुए, और निम्नलिखित बयान जारी किया:

बाह्य समीक्षा में पाया गया कि नकोंडे एट अल. का अध्ययन वैधता और विश्वसनीयता के पेशेवर मानकों को पूरा करने में विफल रहा। …

“लेखकों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष मुख्य रूप से एडीओएस नेतृत्व द्वारा किए गए कुछ चुनिंदा ट्वीट्स की उनकी व्याख्या पर आधारित हैं,” और यह कि “मात्रात्मक विश्लेषण शोधपत्र के निष्कर्षों से अपर्याप्त रूप से जुड़ा हुआ है।”

एनकोंडे एट अल. द्वारा प्रकाशित निष्कर्षों की वैधता पर सवाल उठाते हुए (एडीओएस) द्वारा चिंताएं हमारे ध्यान में लाए जाने के बाद, पत्रिका ने एक आंतरिक समीक्षा करवाई, जो हार्वर्ड के एक शोधकर्ता द्वारा की गई थी जिसका पत्रिका से सीधा संबंध नहीं था। आंतरिक समीक्षा में कार्यप्रणाली में खामियां पाई गईं, साथ ही डेटा और लेखकों द्वारा प्रकाशित निष्कर्षों में विसंगतियां भी पाई गईं, जिसके परिणामस्वरूप उनके विश्लेषणों से निराधार निष्कर्ष निकाले गए। इसके बाद हमने प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों को सत्यापित करने के लिए एक बाहरी स्वतंत्र

समीक्षा करवाई।
नि:संदेह, नकोंडे को झूठी और घटिया छात्रवृत्ति के लिए धन की कोई हानि नहीं हुई। वास्तव में, उनके आंदोलन को बढ़ावा मिला:
विडंबना यह है कि एनकोंडे के अब निराधार हो चुके "गलत सूचना का प्रसार" लेख के प्रकाशन से पहले, मैकार्थर फाउंडेशन ने एआई फॉर द पीपल को 2020 और 2021 के बीच 220,000 डॉलर की अनुदान राशि प्रदान की: दो अनुदान, जिनमें से 200,000 डॉलर पत्रकारिता और मीडिया तथा प्रौद्योगिकी के लिए और 20,000 डॉलर सार्वजनिक हित के क्षेत्र में थे। इस धनराशि का उद्देश्य "अश्वेत समुदायों पर प्रौद्योगिकी के डिजाइन और संचालन के प्रभाव के बारे में नया ज्ञान सृजित करना और अधिक अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए उन बाधाओं को दूर करना था जो उन्हें प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी-संबंधित नीतिगत मुद्दों पर सार्वजनिक बहस में भाग लेने में सहायक हों।"

भारतीय लोकतंत्र में हस्तक्षेप
हार्वर्ड कैनेडी स्कूल भारत के राजनीतिक परिदृश्य में स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाता है और उसे प्रभावित करने का इरादा रखता है। 2014 में नरेंद्र मोदी की चुनावी जीत हार्वर्ड कैनेडी स्कूल को स्वीकार्य नहीं थी और तब से इसने भारत पर केंद्रित अनगिनत शोध अध्ययन, सम्मेलन और सेमिनार आयोजित किए हैं। यह भारत में लोकतांत्रिक परिणामों को बदलने के एकतरफा प्रयास को दर्शाता है, जिससे इसके एजेंडे और ऐसे शोध को संभव बनाने वाले वित्तपोषण स्रोतों पर संदेह पैदा होता है। लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने के हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के ये प्रयास हमें उस तरीके की याद दिलाते हैं जिस तरह अमेरिका ने उन जगहों पर सत्ता परिवर्तन किया जहां सरकार ने उसके आदेशों का पालन नहीं

किया। प्रतिष्ठित ब्रांड नाम की अतिरिक्त सहायता से, कैनेडी स्कूल अकादमिक कार्य की आड़ में शक्ति प्रदर्शन के इस वैश्विक प्रयास में एक प्रमुख संस्थान है।

2015 में, कैनेडी स्कूल के बेलफर सेंटर के रोनक देसाई ने नई मोदी सरकार की एक साल की कार्यप्रदर्शन रिपोर्ट जारी की। उन्होंने प्रशासन को 'डी' ग्रेड दिया, उन कार्यों के लिए जिन्हें हार्वर्ड ने घोर उल्लंघन माना: अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के वित्तपोषण पर प्रतिबंधों को कड़ा करना और ग्रीनपीस की जांच करना। इन प्रतिबंधों के कारणों पर कोई चर्चा नहीं हुई, जो विदेशी वित्तपोषण पर भारतीय कानूनों के उल्लंघन और भारत तोड़ने वाली ताकतों द्वारा किए गए अपराधों के कारण आवश्यक हो गए थे।

यह रिपोर्ट विशेष रूप से पाखंडी है क्योंकि हार्वर्ड के चीन पर किए गए बहु-वर्षीय अध्ययन में सीसीपी को उत्कृष्ट अंक दिए गए थे और दावा किया गया था कि उसे अपने नागरिकों का भारी समर्थन प्राप्त है। 2017 में जब चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए गैर सरकारी संगठनों पर कार्रवाई की, तब भी हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में कोई चिंता नहीं जताई गई। चीन ने उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को एक अलग मंत्रालय के अधीन कर दिया।

चीन में काम करने की इच्छुक विदेशी गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के मामलों के प्रबंधन की जिम्मेदारी पूरी तरह से लोक सुरक्षा मंत्रालय (एमपीएस) के पास है। यह पिछले 10 वर्षों की प्रथा से एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जब नागरिक मामलों के मंत्रालय को विदेशी गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों की निगरानी और रिपोर्टिंग का कार्य सौंपा गया था।

2017 में, हार्वर्ड कैनेडी स्कूल की वेबसाइट पर प्रकाशित एक लेख में

दावा किया गया था कि भारत की कांग्रेस पार्टी के पास अर्थव्यवस्था की स्थिति का फायदा उठाकर चुनाव जीतने का एक दुर्लभ अवसर था। हालाँकि, ऐसी योजनाएँ साकार नहीं हुईं। मोदी की 2019 की भारी जीत ने हार्वर्ड कैनेडी स्कूल को चिंतित कर दिया और उसने 'ब्रेकिंग इंडिया' सिद्धांत को बल देने के लिए अत्याचार संबंधी साहित्य का अधिक प्रकाशन शुरू कर दिया। इसका शोध कार्य उन कार्यों का मुकाबला करने के लिए सुनियोजित कार्यक्रमों के साथ प्रस्तुत किया जाता है जिन्हें वह खतरनाक मानता है। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता के रूप में, मोदी को 2019 में दुनिया के सबसे खतरनाक जहरों में से एक के रूप में चित्रित किया गया। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बेलफर सेंटर के प्रोफेसर स्टीफन वॉल्ट ने लिखा:

2019 की 'सबसे महत्वपूर्ण विदेश नीति घटना' की श्रेणी में योग्य उम्मीदवारों के बारे में सोचना मुश्किल नहीं है। आप अपनी पसंद चुन सकते हैं: हांगकांग विरोध प्रदर्शन, व्हिसलब्लोअर के खुलासे जिनके कारण प्रतिनिधि सभा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर महाभियोग चलाने के लिए मतदान किया, अमेज़न और ऑस्ट्रेलिया में लगी आग, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की चुनावी जीत, या भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय राष्ट्रवाद की एक नई और संकीर्ण अवधारणा की ओर अग्रसर होना।

इस प्रकार, हार्वर्ड के पास भारत में जमीनी स्तर पर सक्रियता को बढ़ावा देने और शोध करने के लिए मानव संसाधन प्रशिक्षण का एक संपूर्ण कार्यक्रम है। ऐसा प्रतीत होता है कि 2019 से कैनेडी स्कूल ने भारत में हिंदू पुनर्जागरण को कुचलने के लिए हर संभव प्रयास किया है। उदाहरण के लिए, इसके कई विद्वान व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया संदेशों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि चुनावों पर उनके

प्रभाव का पता लगाया जा सके। इसने मीडिया पुलिस के रूप में अपनी भूमिका के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित उपकरणों का प्रस्ताव दिया है और फेसबुक पर अपने अनुरोधों का पालन करने के लिए भारी दबाव डाला है।

जब विदेशी देशों में आंतरिक आंदोलनों और भारी मतदान के परिणाम हार्वर्ड की योजनाओं के विपरीत आते हैं तो क्या होता है? हम ऐसे उदाहरण दिखाएंगे जिनमें हार्वर्ड, खेल बिगाड़ने वाले की तरह, परिणाम को नियंत्रित करने के अपने प्रयासों में विफल होने पर खेल के नियम बदल देता है। उसका दावा है कि ऐसे देश मरते हुए लोकतंत्र हैं, और यह मृत्यु उन्हीं निर्वाचित नेताओं के कारण हो रही है जिन्हें इस लोकतंत्र ने जन्म दिया है।

चुनाव के प्रतिकूल परिणामों से निपटने के लिए, हार्वर्ड नए राजनीतिक सिद्धांत विकसित करता है। इसके विद्वान यह दावा करने लगते हैं कि चुनाव लोकतंत्र की कई शर्तों में से केवल एक है। वे 'वास्तविक' लोकतंत्र की परिभाषा को फिर से परिभाषित करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, हार्वर्ड के राजनीतिक वैज्ञानिकों स्टीवन लेविट्स्की और डैनियल ज़िबलाट की पुस्तक, हाउ डेमोक्रेसीज़ डाई, में कहा गया है:

हार्वर्ड विश्वविद्यालय में शासनशास्त्र के प्रोफेसर स्टीवन लेविट्स्की ने कहा, “लोकतंत्र अब उस तरह से नहीं मरते जैसे पहले मरते थे... पहले लोकतंत्र बंदूकधारियों के हाथों मरते थे। शीत युद्ध के दौरान, हर चार लोकतांत्रिक पतन में से तीन का कारण सैन्य तख्तापलट होता था... आज लोकतंत्र कहीं अधिक सूक्ष्म तरीके से मरते हैं। वे जनरलों के हाथों नहीं, बल्कि निर्वाचित नेताओं, राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों के हाथों मरते हैं जो लोकतंत्र की संस्थाओं का ही इस्तेमाल करके उसे कमजोर करते हैं...”

उन शासन प्रणालियों में, जो उभर कर सामने आता है वह है "प्रतिस्पर्धी अधिनायकवाद," ... जहाँ "विपक्ष के विरुद्ध परिस्थितियाँ काफी हद तक प्रतिकूल होती हैं। ... हंगरी इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। वेनेजुएला, शायद पोलैंड, शायद भारत, उम्मीद है कि संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं।" जब हार्वर्ड ने प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के इस नए तरीके पर काम शुरू किया, जिसमें भारत को विशेष महत्व दिया गया, तो भारतीय बुद्धिजीवी सिपाहियों ने तुरंत इस सिद्धांत को भारत पर लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया। आशुतोष वर्शनी ने द इंडियन एक्सप्रेस में एक प्रभावशाली लेख में लेविट्स्की और ज़िबलाट द्वारा प्रस्तुत विचारों को और अधिक विस्तार से समझाया।

भारत का लोकतंत्र पतन की ओर जा रहा है, इसका कारण जनरलों और सैनिकों का नहीं, बल्कि निर्वाचित राजनेताओं द्वारा लोकतंत्र को कमजोर करना है। बहुत जल्द, अमेरिका के फ्रीडम हाउस और स्वीडन के वी-डेम इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित दो सबसे अधिक पढ़े जाने वाले वार्षिक लोकतंत्र रिपोर्ट प्रकाशित होने वाली हैं। पिछले वर्ष उन्होंने तर्क दिया था कि भारत अपना लोकतांत्रिक दर्जा खोने की कगार पर है। देखते हैं कि इस वर्ष की रिपोर्ट भारत को अलोकतांत्रिक कहती हैं या केवल "आंशिक रूप से स्वतंत्र"...

लोकतांत्रिक सिद्धांत के लिए चुनाव आवश्यक हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं। केवल चुनावों को ही लोकतंत्र के समान नहीं माना जा सकता। लोकतंत्र का मापन एक समग्र सूचकांक द्वारा किया जाता है। समग्र मूल्यांकन आंशिक रूप से चुनावों पर और आंशिक रूप से निर्वाचित सरकारों द्वारा चुनावों के बीच किए गए कार्यों पर निर्भर करता है।

वर्षनी ने फ्रीडम हाउस की पिछले वर्ष की रिपोर्ट का हवाला दिया:

सदी की शुरुआत से ही, संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी देश

भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के संभावित रणनीतिक साझेदार और लोकतांत्रिक प्रतिसंतुलन के रूप में देखते रहे हैं। ... प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय सरकार द्वारा लोकतांत्रिक मानदंडों से किए गए चिंताजनक विचलन ... बीजिंग और नई दिल्ली के बीच मूल्यों पर आधारित अंतर को धुंधला कर सकते हैं। यद्यपि भारत ने पिछली वसंत ऋतु में सफल चुनाव कराए, भाजपा ने देश की बहुलवाद और व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति मूलभूत प्रतिबद्धता से खुद को दूर कर लिया है, जिसके बिना लोकतंत्र लंबे समय तक टिक नहीं सकता।
फ्रीडम हाउस को अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, और इसके वामपंथी झुकाव के कारण अमेरिकी थिंकटैंकों से इसकी आलोचना का सामना करना पड़ता है।
फ्रीडम हाउस की सभी पांच देशों [संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, इज़राइल, डेनमार्क और पोलैंड] पर रिपोर्ट मुख्यधारा की रूढ़िवादी पार्टियों के खिलाफ पक्षपातपूर्ण रवैये का एक सुसंगत पैटर्न दर्शाती है। ... एक के बाद एक मुद्दे पर, फ्रीडम हाउस प्रगतिशील वामपंथियों के विचारों को नीरस रूप से दोहराता है।
यह उल्लेखनीय है कि आईटी कंपनी विप्रो के पूर्व सीईओ विवेक पॉल फ्रीडम हाउस के बोर्ड में कार्यरत हैं। हार्वर्ड के आत्म-धर्मी विद्वानों, हांगकांग राज्य के भीतर के व्हिसलब्लोअर संस्थानों और मीडिया के बीच के अंतरंग संबंध हार्वर्ड द्वारा गढ़ी गई कहानी को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।
पिछले कई दशकों में हार्वर्ड का रवैया दर्शाता है कि वह उन सरकारों पर हमला करता है जो उसके वर्चस्व का विरोध करती हैं, चाहे वे वामपंथी हों या दक्षिणपंथी। यही कारण है कि भाजपा सरकार के लगभग हर बड़े नीतिगत फैसले की हार्वर्ड द्वारा आलोचना की गई है। जब भारत ने

नोटबंदी लागू की, तो कैनेडी स्कूल के अमर्त्य सेन ने लिखा: 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नोट प्रतिबंध न तो बुद्धिमानी भरा है और न ही मानवीय।' 2019 में, हार्वर्ड से जुड़े 220 से अधिक लोगों ने भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 की निंदा करते हुए और भारतीय विश्वविद्यालयों में छात्र विरोध प्रदर्शनों के कथित दमन के खिलाफ एक याचिका पर हस्ताक्षर किए। हार्वर्ड के कैंपस अखबार ने रिपोर्ट किया: 'यह पत्र हार्वर्ड यूएस-इंडिया इनिशिएटिव, हार्वर्ड इस्लामिक सोसाइटी और हार्वर्ड कॉलेज पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एसोसिएशन सहित समूहों द्वारा प्रायोजित था।'

केनेडी स्कूल के छात्रों को अक्सर भारतीय सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, उदाहरण के लिए जनवरी 2020 में सीएए की निंदा करने के लिए। हार्वर्ड के दलित नेता सूरज येंगडे मुख्य मार्गदर्शक थे।

प्रदर्शनकारी और हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के फेलो सूरज येंगडे ने कहा कि स्क्वायर में प्रदर्शनकारी विशेष रूप से भारत में विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही महिलाओं के साथ एकजुटता दिखाने के लिए खड़े थे, जिनमें दिल्ली के शाहीन बाग इलाके की एक सड़क पर हफ्तों से कब्जा जमाए सैकड़ों महिलाओं का एक समूह भी शामिल है। … “इसका उद्देश्य दो गुना है,” कैनेडी स्कूल की छात्रा और विरोध प्रदर्शन की आयोजकों में से एक रुहा शादाब ने कहा। “पहला तो इस कृत्य के प्रति अपनी असंतोष व्यक्त करना है। और दूसरा, भारत भर में चल रहे सभी छात्र-नेतृत्व वाले आंदोलनों के साथ एकजुटता दिखाना है, जो अब नागरिक आंदोलन बन चुके हैं।”

अगले महीने, हांगकांग कश्मीर के छात्रों ने कश्मीर पर भारत समर्थक बयानों के कारण हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में भारतीय महावाणिज्यदूत के

निमंत्रण का विरोध किया। उन्होंने नारे लगाए और तख्तियां पकड़ीं जिन पर लिखा था, 'कश्मीर को आजादी चाहिए' और 'कश्मीर से फिलिस्तीन तक, कब्जा एक अपराध है!' यह सब इस तथ्य के बावजूद था कि हिंदू कश्मीरी ही थे जिनका नरसंहार किया गया और उन्हें उनकी मातृभूमि से बेदखल कर दिया गया।

भारत में 2019 के आम चुनावों के दौरान, वर्शनी ने कहा था कि भाजपा की बहुमत से जीत हिंदुत्व से प्रभावित होगी, जिसे वे श्वेत वर्चस्व और श्वेत राष्ट्रवाद के बराबर मानते हैं।

यदि भाजपा संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेती है, तो “यह राष्ट्र के हिंदू राष्ट्रवादी स्वरूप की ओर अग्रसर होगी।” … इस बार भाजपा के मंच पर हिंदू राष्ट्रवाद, या हिंदुत्व का अधिक प्रभाव दिखाई देता है। वे इस अवधारणा को “एक राजनीतिक सिद्धांत” के रूप में वर्णित करते हैं, जो यह दावा करता है कि हिंदू राष्ट्र के प्राथमिक स्वामी हैं। वे इसे एक प्रकार का हिंदू वर्चस्ववाद कहते हैं, जिसमें भारत का गैर-हिंदू अल्पसंख्यक हिंदू बहुसंख्यक द्वारा राज्य के नियंत्रण या स्वामित्व को स्वीकार करता है। उन्होंने आगे कहा, “संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेत राष्ट्रवादी भी लगभग इसी तरह का तर्क देते हैं।”

हार्वर्ड में छात्रों द्वारा संचालित पॉलिटिकल रिव्यू भी मोदी विरोधी लेखों से भरा पड़ा है। एक लेख का शीर्षक है, "गायों की रक्षा करना और लोगों को सताना।" एक अन्य लेख, जिसका शीर्षक है "कोविड के दौरान आईपीएल: भारत में क्रिकेट और राजनीति के बीच संबंध", भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा मोदी की चाटुकारिता और प्रशंसा के बारे में बात करता है।

क्रिकेट टीम द्वारा खुलेआम सैन्यवाद का समर्थन करना, पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बाद देश में अति-राष्ट्रवादी भावनाओं

को भड़काने के मोदी सरकार के प्रयासों का समर्थन था, जिसने अंततः मोदी को भारी बहुमत से दोबारा निर्वाचित होने में योगदान दिया।
सचिन तेंदुलकर, … शायद एकमात्र भारतीय खिलाड़ी जो कोहली की लोकप्रियता को टक्कर दे सकते हैं, ने 2019 में मोदी की शानदार जीत के बाद उन्हें बधाई देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक अन्य प्रसिद्ध क्रिकेटर, रवींद्र जडेजा ने भी इस जीत की सराहना करते हुए इसे "नास्तिकों पर विश्वासियों की जीत" बताया। लगभग सभी प्रमुख क्रिकेटर लगातार मोदी की इसी तरह चापलूसी भरी प्रशंसा में लगे रहे हैं, और उनके शासनकाल में देश में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों की बिगड़ती स्थिति को आसानी से नजरअंदाज कर रहे हैं। गौतम गंभीर, जिन्होंने 2011 विश्व कप में भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ने पूर्वी दिल्ली से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव भी जीता और वर्तमान में लोकसभा के सदस्य हैं। …
भारत में राष्ट्रवाद और क्रिकेट आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, और यह खेल राजनीतिक अभिजात वर्ग को जनता के मन पर प्रभाव डालने का एक अद्भुत साधन साबित हुआ है।
हार्वर्ड के हर केंद्र का एक एजेंडा प्रतीत होता है, जिसका उद्देश्य भारत द्वारा अपने स्वयं के मार्ग का चयन करने पर उसकी वैधता को कमजोर करना है। भारतविज्ञानी माइकल विट्ज़ेल ने टिप्पणी की: 'भारत की भाजपा राजनीतिक पार्टी और संघ परिवार से जुड़े संगठनों ने कैलिफोर्निया और भारतीय स्कूली पाठ्यपुस्तकों में हिंदू राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का प्रचार करने के लिए पाठ्यपुस्तकों को मौलिक रूप से और गलत तरीके से संशोधित करने का प्रयास किया है।'
केनेडी स्कूल में लोक नीति के वरिष्ठ व्याख्याता माइकल वाल्टन ने 2020 के एक शोध पत्र में कहा कि भारत में जिसे वे 'समावेशी पूंजीवाद' कहते

हैं, उसका अभाव है।

हालांकि समावेशी पूंजीवाद का मार्ग (अभी भी) कल्पना किया जा सकता है, लेकिन राजनीतिक अर्थव्यवस्था के दबाव और सत्तावादी प्रलोभनों के कारण मध्यम से लंबी अवधि में इसे समर्थन मिलने की संभावना नहीं है। इन परिस्थितियों में, भारत को लैटिन अमेरिकी परिदृश्य का सामना करना पड़ सकता है, जहां असमानता बढ़ती जा रही है, दीर्घकालिक विकास धीमा है और यहां तक कि व्यापक आर्थिक अस्थिरता भी है।

वॉल्टन नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में विजिटिंग फेलो भी हैं और बेंगलुरु स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज में वीकेआरवी राव चेयर प्रोफेसर रह चुके हैं। उन्हें भारत के व्यापार और अर्थव्यवस्था पर एक विशेषज्ञ के रूप में पेश किया जा रहा है। उनका स्पष्ट पूर्वाग्रह उनके कुछ कथनों में झलकता है, जैसे:

व्यापार-समर्थक दृष्टिकोण और कुछ संभावित महत्वपूर्ण नीतिगत बदलावों के बावजूद, मोदी 1.0 पूंजीवाद में सुधार के मामले में एक अधूरा प्रयास साबित हुआ। इससे राज्य और व्यापार के बीच संबंध एक मध्यवर्ती स्थिति में आ गए, जिससे लेन-देन में विश्वसनीयता कम हो गई – केवल सबसे बड़े और प्रभावशाली व्यापारिक घरानों को छोड़कर। मोदी 2.0 के शुरुआती दौर में यह बात और भी स्पष्ट हो गई। उत्पादन और विशेष रूप से निजी निवेश में मंदी आना तो तय था, लेकिन सत्ता परिवर्तन की अनिश्चितताओं और राज्य के साथ व्यापारिक संबंधों को लेकर व्याप्त संशय ने स्थिति को और बिगाड़ दिया – यह सब वित्तीय संकट के साथ परस्पर क्रिया कर रहा था।

मोदी 2.0 के अल्पकालिक उपाय, हालांकि प्रभावशाली हैं, एक सुनियोजित नीतिगत योजना की बजाय हताशा को अधिक दर्शाते हैं, और ये घाटे में वृद्धि और वित्तीय क्षेत्र से निपटने के लिए एक विश्वसनीय

नीतिगत मिश्रण के अभाव से जुड़े हैं।

महिलाएँ और सार्वजनिक नीति कार्यक्रम
हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के तरीके को समर्पित एक केंद्र, महिला और सार्वजनिक नीति कार्यक्रम घोषित करता है:
विश्व में कोई अन्य संगठन हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के महिला एवं सार्वजनिक नीति कार्यक्रम की तरह व्यवहार संबंधी अंतर्दृष्टियों का उपयोग करके साक्ष्य-आधारित संगठनात्मक डिजाइन तैयार नहीं करता है जो महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा दे, लैंगिक पूर्वाग्रह को दूर करे और महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अवसर प्रदान करे।
इसके मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत में भारतीय महिलाओं पर किए जा रहे 'अध्ययनों' के माध्यम से भारतीय महिलाओं के दृष्टिकोण को पश्चिमी महिलाओं के दृष्टिकोण के अनुरूप बदलना है। ये अध्ययन विद्वत्ता के नाम पर हिंदू-विरोधी भावना फैलाने का एक माध्यम भी प्रदान करते हैं।
इसका एक उदाहरण हार्वर्ड का भारतीय महिलाओं और उद्यमिता पर शोध पत्र है, जिसका शीर्षक है "क्या पारंपरिक संस्थाएँ महिला उद्यमिता को बाधित करती हैं? भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण पर एक क्षेत्र प्रयोग"। लेखक इस बात की पड़ताल करते हैं कि क्या गरीब भारतीय महिलाओं को उद्यमिता अपनाने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है और क्या 'पारंपरिक' संरचनाओं की इन महिलाओं को रोकने में कोई भूमिका है। यह अध्ययन अहमदाबाद में एक स्थानीय बैंक के सहयोग से किया गया था। इसमें मुस्लिम, हिंदू अनुसूचित जाति या दलित और हिंदू उच्च जाति की महिलाओं का अध्ययन किया गया। विडंबना यह है कि तीन लेखकों

में से दो उच्च जाति की हिंदू महिलाएं थीं, जो चमत्कारिक रूप से उस दमनकारी हिंदू जाति व्यवस्था से बच निकली थीं जिसका वर्णन उन्होंने अपने शोध पत्र में किया है। उनके अनुसार, उच्च जातियाँ,
यौन संबंध, विवाह और चरम मामलों में निम्न जातियों के साथ संपर्क से बचकर पवित्रता बनाए रखना। पुरुषों को अपवित्रता का स्रोत मानते हुए, महिलाओं पर अपने पतियों के अलावा अन्य पुरुषों से संपर्क सीमित करने के लिए प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ... विवाहित महिला को घूंघट में रहना चाहिए, विधवा होने पर पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए, वृद्ध पुरुषों से बातचीत नहीं करनी चाहिए और घर से बाहर उसकी आवाजाही सीमित होनी चाहिए। ये नियम – विशेष रूप से अंतिम दो – महिला श्रम शक्ति में भागीदारी को काफी हद तक सीमित करते हैं।
हालांकि लेखकों ने पाया कि मुस्लिम महिलाओं पर उच्च जाति की हिंदू महिलाओं की तुलना में अधिक प्रतिबंध हैं, लेकिन वे मुस्लिम प्रतिबंधों के पीछे एक नेक कारण बताते हैं: 'चूंकि मुस्लिम महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में हिस्सेदारी का अधिकार है, इसलिए परिवार के बाहर के पुरुषों के साथ उनके संबंधों को नियंत्रित करना पारिवारिक संपत्ति और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।'
रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि हिंदू उच्च जाति की महिलाओं ने उद्यमिता प्रशिक्षण के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दी क्योंकि इससे उन्हें उन सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने का अवसर मिला जो उनके व्यावसायिक तौर-तरीकों को विकृत कर रहे थे। चूंकि मुस्लिम महिलाओं ने इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए लेखकों को एक ऐसा स्पष्टीकरण देना पड़ा जिसे इस्लाम विरोधी न माना जाए। एक संभावना जो उन्होंने रखी वह यह थी कि स्थानीय बैंक में कार्यरत महिलाएं व्यापक आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं करती होंगी, एक ऐसी परिकल्पना जिसके

लिए उन्हें आवश्यक आंकड़े उपलब्ध नहीं लगे।
एक अन्य संभावना यह बताई गई कि अहमदाबाद में हिंदू मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हैं। इस लेख में यह तर्क दिया गया है कि 'धार्मिक तनाव के इतिहास वाले अहमदाबाद में मुसलमानों को बाज़ार में काफी भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिसे व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दूर नहीं कर सका।' इसके समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया गया, केवल हिंदू धर्म का आरोप लगाना ही काफी था। लेख में इस धारणा को भी खारिज कर दिया गया कि ब्याज वाले ऋणों पर इस्लाम के प्रतिबंध एक संभावित कारण हो सकते हैं कि उद्यमिता प्रशिक्षण से मुसलमानों के बीच ऋण की मांग में वृद्धि नहीं हुई।
महिलाओं को उद्यमिता में शामिल होने से रोकने वाली प्रतिबंधात्मक सांस्कृतिक प्रथाओं के अपने सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए, हार्वर्ड के जनसंख्या और विकास अध्ययन केंद्र के एक अन्य शोधकर्ता भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, लेकिन एक अलग दृष्टिकोण से। आशीष गुप्ता कहते हैं कि भारत में लैंगिक मानदंडों में मौजूद पितृसत्तात्मकता, सरकारी सब्सिडी के बावजूद महिलाओं को खाना पकाने के लिए गैस का उपयोग करने से हतोत्साहित करती है। उनका दावा है कि यदि महिलाएं खाना पकाने के लिए गैस का उपयोग करती भी हैं, तो इसका कारण यह है कि पितृसत्तात्मक संस्कृति उन्हें एकांत में रखना चाहती है, घर तक सीमित रखना चाहती है और उन्हें लकड़ी लाने के लिए बाहर जाने से रोकना चाहती है।
उत्तर भारतीय समाज में महिलाओं को निम्न दर्जा दिया जाता है, उन्हें एकांतवास में रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और घर के बाहर आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी को सीमित किया जाता है। ये मान्यताएँ महिलाओं को गैस बचाने के लिए प्रेरित करती हैं, ठोस ईंधन के

उपयोग को बढ़ावा देने वाले कामों को प्रोत्साहित करती हैं और एलपीजी (द्रवीकृत प्राकृतिक गैस) रिफिल के संबंध में रसोइए और निर्णय लेने वाले के बीच संवाद को बाधित करती हैं। जब ग्रामीण उत्तर भारतीय परिवार गैस का उपयोग करते हैं, तो अक्सर यह एकांतवास के उन मानदंडों का पालन करने के लिए होता है जो महिलाओं को ठोस ईंधन इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर निकलने से रोकते हैं।

एचकेएस की एक अन्य भारतीय टीम ने "भारतीय बच्चे इतने छोटे क्यों हैं?" शीर्षक से एक अध्ययन किया। इस अध्ययन में उन्होंने बताया कि भारत के बच्चे दुनिया में सबसे अधिक बौने हैं, और पाया कि कद में असमानता का कारण यह है कि भारतीय माताएं अपनी बेटियों की तुलना में अपने बेटों को अधिक खिलाती हैं। सीमा जयचंद्रन और रोहिणी पांडे ने भारतीय बच्चों में बौनेपन का सीधा कारण हिंदू संस्कृति में बेटों को प्राथमिकता देना बताया है। हार्वर्ड के प्रामाणिक प्रमाण के साथ, विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला:

प्रथम, भारत में प्रथम संतान के रूप में ऊंचाई का लाभ केवल पुत्रों को ही प्राप्त होता है। द्वितीय, एक भारतीय पुत्र जिसका कोई बड़ा भाई हो, अपने अफ्रीकी समकक्ष से तभी लंबा होता है जब वह सबसे बड़ा पुत्र हो। तृतीय, भारत-अफ्रीका के बीच ऊंचाई का अंतर उन पुत्रियों में सबसे अधिक होता है जिनका कोई बड़ा भाई नहीं होता, जो इस तथ्य को दर्शाता है कि उनके परिवार पुत्र प्राप्ति के लिए अपनी वांछित प्रजनन दर से अधिक प्रजनन करने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं।

टीम द्वारा किए गए एक अन्य शोध का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या अधिक महिला राजनीतिज्ञों के संपर्क में आने से राजनीति में महिलाओं की भूमिका के बारे में नकारात्मक रूढ़िवादिता में बदलाव आता है। उनका निष्कर्ष, आश्चर्यजनक रूप से नहीं, यह दर्शाता है कि हिंदू धर्म

स्त्री-द्वेषी सामाजिक दृष्टिकोण को जन्म देता है: 'दिलचस्प बात यह है कि जहां मतदाता महिलाओं के लिए मतदान करने की अपनी इच्छा को बदलते हैं और अपने अंतर्निहित पूर्वाग्रहों को अपेक्षाकृत तेजी से बदलते हैं, वहीं उनके स्पष्ट दृष्टिकोण (और इसलिए सामाजिक मानदंड) में परिवर्तन बहुत धीमा होता है।'

कैर सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स पॉलिसी

कैर सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स पॉलिसी, एचकेएस का एक और महत्वपूर्ण केंद्र है। इसकी कार्यकारी निदेशक सुषमा रमन, फोर्ड फाउंडेशन और जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ काम कर चुकी हैं। उन्होंने 'सामाजिक न्याय परोपकार और नागरिक समाज को सशक्त बनाने' से संबंधित अनुदानों का प्रबंधन किया और 'लैंगिक न्याय और मानवाधिकार/सामाजिक न्याय' पर केंद्रित नए फाउंडेशनों को शुरू करने में मदद की। वे विश्व गुरु के रूप में हार्वर्ड के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूरी तरह से योग्य हैं, जो विश्व में सामाजिक न्याय का मार्ग प्रशस्त करती हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत में फोर्ड फाउंडेशन में रहते हुए, रमन पर तीस्ता सेतलवाद/जावेद आनंद मामले में भारतीय विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (एफसीआरए) के कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था।

“फोर्ड फाउंडेशन की प्रोग्राम ऑफिसर रमन को सब्रंग से अनुदान प्राप्त करने के लिए पहला प्रस्ताव 2004 में मिला था। जांच में पता चला कि रमन को इस बात की जानकारी थी कि सब्रंग अनुदान प्राप्त करने के योग्य नहीं है क्योंकि यह एफसीआर अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। अनुदान के प्रस्ताव पर कार्रवाई के दौरान उन्होंने जावेद से इस बारे में बात की थी। नियमों का पालन न करने के लिए रमन ने आनंद के

साथ मिलीभगत की, जो अनुदान को परामर्श शुल्क के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा था", आरोप पत्र में यह उल्लेख है।
भारतीय कानूनों की ऐसी अवहेलना किसी व्यक्ति को अमेरिकी अकादमिक जगत में नायक बना सकती है।
एक अन्य उदाहरण कैर सेंटर के वरिष्ठ फेलो सलिल शेट्टी हैं, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल में महासचिव थे, एक ऐसा संगठन जिसका भारत में एफसीआरए उल्लंघन के लिए प्रवर्तन निदेशालय के साथ कई बार विवाद रहा है।[91] 2021 में, शेट्टी को पुरस्कृत किया गया और ओपन सोसाइटी में वैश्विक कार्यक्रम का उपाध्यक्ष बनाया गया।
शेट्टी ने कोविड-19 के दौरान गैर सरकारी संगठनों और मुसलमानों के खिलाफ भारतीय सरकार के 'अनैतिक, आत्ममुग्ध, सत्तावादी और अक्षम नेताओं' के बारे में शिकायत की है।
भारतीय मीडिया और जनता के कुछ वर्गों में अब एक व्यापक अभियान चल रहा है जो भारत में कोविड-19 के प्रसार को इस्लाम से जोड़ता है, जिससे सत्ता में मौजूद हिंदू कट्टरपंथी शासन के मूल एजेंडे को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार की थोड़ी सी भी आलोचना या जवाबदेही की मांग को राष्ट्र-विरोधी माना जाता है! ... दुनिया के कई सबसे बड़े और प्रभावशाली देशों में अनैतिक, आत्ममुग्ध, निरंकुश और अक्षम नेता हैं, जो अल्पसंख्यकों, शरणार्थियों को हाशिए पर रखकर और अतीत के राष्ट्रीय गौरव के बारे में झूठ फैलाकर चुने गए हैं।
हार्वर्ड में एक भाषण में उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों के मामले में दुनिया नेतृत्व की गुणवत्ता को लेकर संघर्ष कर रही है। फिर वे उन नेताओं के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं जिनका मानवाधिकार रिकॉर्ड मानवता को पीछे ले जा रहा है, और मोदी का नाम ट्रंप और चीन के शी जिनपिंग के साथ लिया गया है। एक अन्य लेख में, वे कहते हैं कि आर्थिक और सैन्य

दृष्टि से भारत की तुलना चीन से करना 'थोड़ा भ्रामक' है। हालांकि इसकी क्षमता से इनकार नहीं किया जा सकता, 'घर में इसकी कमजोर होती लोकतंत्र व्यवस्था एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है'। उनका दावा है कि भारत से मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि भारत की सॉफ्ट पावर के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां 'धार्मिक असहिष्णुता और घृणा अपराधों की बढ़ती संख्या' हैं जो इसके पारंपरिक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को नष्ट कर रही हैं। वे लिखते हैं:

वर्तमान शासन के तहत भारत असहमति के किसी भी रूप और किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के मूलभूत नियंत्रण और संतुलन, अर्थात् स्वतंत्र मीडिया, न्यायपालिका, नागरिक समाज आदि के प्रति तेजी से आक्रामक हो गया है। देश द्वारा घरेलू विवादों से निपटने का तरीका – जिसमें जाति आधारित हिंसा, गोमांस के आरोपों पर लिंचिंग, आदिवासियों के अधिकार और कश्मीर का विशेष दर्जा छीनना शामिल है – ने भारत की सॉफ्ट पावर पर गहरा प्रभाव डाला है।

शेट्टी लोकतंत्र को मापने वाले विभिन्न सूचकांकों का हवाला देते हुए तर्क देते हैं कि मोदी के शासन में भारत अब एक अच्छा लोकतंत्र नहीं रह गया है। फ्रीडम हाउस ने उदार लोकतंत्र के रूप में भारत की रैंकिंग को सत्तर से घटाकर पचासी कर दिया है। गैर-सरकारी संगठन, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत को 133वें स्थान से गिराकर 140वें स्थान पर ला दिया है। उनका कहना है कि ये रिपोर्टें एक महत्वपूर्ण चिंता को जन्म देती हैं जिसे कई लोग साझा करते हैं: क्या भारत वास्तव में भावना के रूप में लोकतंत्र बना हुआ है या नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन सबने वैश्विक स्तर पर भारत की सॉफ्ट पावर छवि को नुकसान पहुंचाया है।

शेट्टी के अनुसार, भारत एक प्रकार के संज्ञानात्मक असंगति के साथ

व्यवहार करता है। उनका कहना है कि भारत के 'मानवाधिकार उल्लंघन और हिंसा' से न केवल विश्व मंच पर उसकी प्रतिष्ठा कम होती है, बल्कि इसके परिणामस्वरूप 'प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं'। हालांकि पिछली राजनीतिक पार्टियां भी आलोचकों के प्रति सख्त थीं, लेकिन उनके अनुसार मोदी की वर्तमान सरकार ने ऐसा नहीं किया है।

स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई है। इसे अक्सर अघोषित आपातकाल थोपना बताया जाता है और सभी संकेत यही बताते हैं कि हालात और भी बदतर होंगे। घरेलू लोकतंत्र की कमी बढ़ती जा रही है, वहीं मौजूदा सरकार ने अपने लगभग सभी पड़ोसियों को नाराज़ कर दिया है, कुछ ने स्वेच्छा से तो कुछ ने अपनी गलतियों से। विशेष रूप से संवैधानिक नैतिकता के पतन ने पड़ोसियों की नज़र में भारत की प्रतिष्ठा को काफी कम कर दिया है।

भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर उनका रुख काफी कड़ा है:

भारत की वर्तमान हिंदू राष्ट्रवादी सरकार के लिए, पाकिस्तान को एक मुस्लिम राज्य और ऐतिहासिक शत्रु बताकर उस पर हमला करना उसकी पहचान का एक अभिन्न अंग है। कश्मीर के विशेष दर्जे और कश्मीरी लोगों के अधिकारों को बिना किसी उकसावे के छीनकर, भारत ने जानबूझकर पाकिस्तान और चीन को और अधिक अलग-थलग करने का रास्ता चुना है।

एचकेएस एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया जैसे संगठनों के लिए परामर्श सेवाएं भी प्रदान करता है। ऐसा ही एक विषय था भारतीय संदर्भ में मीडिया हेरफेर: ट्विटर पर कश्मीर से संबंधित चर्चा का विश्लेषण। अध्ययन में कहा गया है कि समस्या का अध्ययन करने के लिए कश्मीर की मीडिया कवरेज का चयन किया गया था।

मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करके जम्मू-कश्मीर को

राज्य का दर्जा छीनने के फैसले ने 2019 के मध्य से इस क्षेत्र को सुर्खियों में ला दिया। इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं, लोगों की आवाजाही और प्रेस की स्वतंत्रता पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों ने जनता को उपलब्ध सूचना की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए।

जांच के लिए ट्विटर को मंच के रूप में चुना गया; दो विशिष्ट प्रकार की हेराफेरी—विभाजन और ध्रुवीकरण को बढ़ावा देना और सरकार समर्थक दुष्प्रचार फैलाना—को मुख्य क्षेत्रों के रूप में चुना गया। उदारवादियों और सरकार के आलोचकों के खिलाफ अपमानजनक शब्दों के प्रयोग के माध्यम से समाज में विभाजन और ध्रुवीकरण को बढ़ावा देना देखा गया। सरकार समर्थक दुष्प्रचार का अध्ययन 2019 के उत्तरार्ध में कश्मीर की स्थिति को "सामान्य" के रूप में चित्रित करने के माध्यम से किया गया (जैसा कि ऊपर वर्णित है, कई प्रतिबंधों के लागू होने के बावजूद)।[100]

यह शोधपत्र राजनीति और मीडिया जगत के शीर्ष एक प्रतिशत प्रभावशाली व्यक्तियों का विश्लेषण करता है, जिन पर सोशल मीडिया पर 'विभिन्न प्रकार की जोड़-तोड़ वाली रणनीति' अपनाने का आरोप है। यह विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी के उन कट्टर समर्थकों की जांच में रुचि रखता है जो विपक्ष की आलोचना करते हुए उनका जमकर बचाव करते हैं। रिपोर्ट में पाया गया है कि इनमें से कई खातों ने गलत जानकारी फैलाई है (हार्वर्ड के सत्यता मानदंडों के अनुसार)। प्रधानमंत्री अपने 'ब्रांड-निर्माण प्रयासों' को अधिकतम करने के लिए सोशल मीडिया पर चतुराई से उन खातों का चयन करते हैं जिन्हें फॉलो किया जा सके। निष्कर्ष यह है:

शोध से पता चलता है कि लोगों के अनुसरण का एक स्तरीय ढांचा हो सकता है, जिसमें मोदी शीर्ष पर होंगे। विभिन्न स्तर उपयोगकर्ताओं के लिए अनुभव को खेलमय बना सकते हैं ताकि उन्हें भाजपा के लिए

ऑनलाइन समर्थन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और वे उच्च स्तर पर पहुंच सकें।
अखबार का दावा है कि नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया कश्मीर मुद्दे पर 'रणनीतिक चुप्पी' का भी इस्तेमाल करता है, जिसके कारण जवाबदेही का अभाव पैदा हुआ है।
चुप्पी भ्रम पैदा करती है और सूचना तंत्र में खामोशी छोड़ देती है। यह मोदी और शाह को उन विवादास्पद चर्चाओं से दूर रखकर उनकी रक्षा करती है जो उनकी छवि को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके बजाय, यह अन्य उपयोगकर्ताओं को चर्चा के केंद्र में ला खड़ा करती है। अन्य विषयों के माध्यम से ध्यान भटकाने से बातचीत महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों से हट जाती है और जवाबदेही की गंभीर कमी हो जाती है। देश के प्रमुख अधिकारियों से स्पष्ट संदेश के अभाव में, कश्मीर की स्थिति जनता के लिए अज्ञात है और एक विषय के रूप में, यह वास्तविकता में जितना महत्वपूर्ण है, उससे कम महत्वपूर्ण प्रतीत हो सकता है।
हार्वर्ड लॉ रिव्यू ने भी सीएए और अनुच्छेद 370 के मुद्दों पर हमले में हिस्सा लिया। "डोमिसाइल से डोमिनियन तक: कश्मीर में भारत का सेटलर कॉलोनियल एजेंडा" शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में, यह कहता है: अनुच्छेद 35ए का निरसन और उसके बाद बने कानून औपनिवेशिक हिंसा के विशिष्ट उदाहरण हैं, लेकिन निरसन से पहले की कानूनी व्यवस्थाएं भी उतनी ही भयावह हैं। कश्मीर के इर्द-गिर्द बढ़ते औपनिवेशिक दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, भारत ने लंबे समय से इस कानून का उपयोग न केवल कश्मीरियों को औपनिवेशिक रूप से उत्पीड़ित करने के लिए किया है, बल्कि उन्हें पूरी तरह से मिटाने के लिए भी किया है।
वैश्विक महामारी के दौरान सामाजिक आंदोलनों और नागरिक प्रतिरोध की पुनर्कल्पना शीर्षक से एक चर्चा की घोषणा इस प्रकार की गई:

कैर सेंटर के संकाय और फेलो यह बताते हैं कि सामाजिक दूरी के इस दौर में सामाजिक आंदोलन और नागरिक प्रतिरोध किस प्रकार आकार ले सकते हैं, और सरकारों को जवाबदेह ठहराने में ये प्रयास पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण क्यों हैं।
कैर सेंटर की स्नातक छात्रा इनायत सबिखी ने छात्र पत्रिका में "एकजुटता में: हार्वर्ड के छात्र नए नागरिकता विधेयक के खिलाफ भारतीय प्रदर्शनों में शामिल हुए" शीर्षक से एक लेख लिखा, जिसमें सीएए के खिलाफ हार्वर्ड के छात्रों की एकजुटता के बारे में बताया गया है। 105

अंतर्राष्ट्रीय विकास केंद्र
हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय विकास केंद्र, हांगकांग केएस का एक और हिस्सा है जो लगातार भारतीयों पर पश्चिमी सांस्कृतिक मानदंडों और प्रथाओं को थोपने का प्रयास कर रहा है। कई समानांतर परियोजनाएं कमजोरियों की तलाश करने, उपयोगी तैनाती के लिए तैयार सिपाहियों की पहचान और प्रशिक्षण देने, और अंततः भारतीय संरचनाओं और प्रणालियों को कमजोर करने के लिए मिलकर काम करती हैं। प्रलोभन और दंड दोनों का मिलाजुला प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, हार्वर्ड के अध्ययनों का एक समूह लक्षित भारतीय घटना का गहन अध्ययन करता है। परियोजनाओं का एक अन्य समूह भारतीय व्यवहार को बदलने के लिए हार्वर्ड या अन्य पश्चिमी शिक्षाविदों द्वारा विकसित विभिन्न उपकरणों का परीक्षण करता है। एक तीसरी शोध परियोजना अत्याचार साहित्य विकसित करती है जो भारत को मानवाधिकारों के दुःस्वप्न के रूप में दर्शाती है, जहां पीड़ित पश्चिम द्वारा बचाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

एचकेएस का शोध इस बात की भी पड़ताल करने का प्रयास करता है कि सदियों से भारतीय सभ्यता इतनी लचीली क्यों रही। इस संबंध में, एचकेएस का एक अध्ययन चल रहा है, जिसका शीर्षक है, भारत में गतिशीलता इतनी कम क्यों है? सामाजिक बीमा, असमानता और विकास। यह अध्ययन भारत में ग्रामीण लोगों की गतिशीलता की कमी के लिए जाति-आधारित नेटवर्क को जिम्मेदार ठहराता है, जो समुदाय के सदस्यों को सहायता प्रणाली प्रदान करते हैं। इसकी तुलना भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर के प्रोफेसर आर. वैद्यनाथन के अग्रणी कार्य से करें, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे जाति समूहों ने सरकारी कार्यक्रमों की तुलना में कम लागत में सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है और कई समुदायों में आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है। हार्वर्ड ने वैद्यनाथन को इस विषय पर अपने किसी भी कार्यक्रम में कभी आमंत्रित नहीं किया है, हालांकि उनका जीवन भर का मौलिक शोध ठीक इसी विषय पर केंद्रित है। वे उनके विचारों से मेल नहीं खाते।

कैर सेंटर की तरह, सेंटर फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट भी कार्यबल में महिलाओं की कम भागीदारी दर का अध्ययन करता है। एक अध्ययन में उन बाधाओं का विश्लेषण किया गया है जो उच्च भागीदारी को रोकती हैं और इस समस्या के समाधान के लिए नीतिगत बदलावों का सुझाव दिया गया है। एक अन्य अध्ययन, जिसका शीर्षक है 'पुरुषों की सामाजिक स्थिति और महिलाओं का कार्य', कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी के प्रति पुरुष जीवनसाथियों और समुदाय के दृष्टिकोण पर 'नवीन डेटा' प्रस्तुत करता है। एक अन्य अध्ययन में महिला नेताओं का उपयोग करके ग्रामीणों के लैंगिक भूमिकाओं के प्रति व्यवहार और दृष्टिकोण में बदलाव लाने का प्रयास किया गया है। एक परियोजना मोबाइल फोन के उपयोग में लैंगिक अंतर की जांच करती है।

हार्वर्ड ऐसे शोध को पुरस्कार देकर विद्वानों को प्रोत्साहित करता है जो इस तरह के विचारों को बल देते हैं, ताकि वे 'जंगली लोगों को बचाओ' जैसी परियोजनाओं में भाग ले सकें। उदाहरण के लिए, सेंटर फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट असमानता अनुसंधान पर मैल्कम वीनर पुरस्कार प्रदान करता है। एक पुरस्कार विजेता ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें कहा गया कि भारत को महिलाओं के रोजगार तक पहुंच बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। एक अन्य पुरस्कार उत्तर प्रदेश के युवाओं में मर्दानगी के लैंगिक मानदंडों को बदलने की परियोजना को दिया गया: 'आंतरिक (पुरुषों के मानसिक मॉडल) और पारस्परिक (सामाजिक/सांस्कृतिक मर्दानगी के मानदंड) स्तरों के बीच एक दुष्चक्र चलता है जो एक दूसरे को मजबूत करता है, प्रतिगामी व्यवहार और हिंसा को बढ़ावा देता है – इसलिए हार्वर्ड पुरुषों के दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास करता है।'

प्रकाशनों

हार्वर्ड कैनेडी स्कूल गौ रक्षकों और हिंदू राष्ट्रवाद के उदय और शादियों के कारण भारत के सबसे गरीब लोगों को बंधुआ मजदूरी की ओर धकेलने जैसे लेख प्रकाशित करता है। इसका उद्देश्य विभिन्न ऐसे विषयों का उपयोग करना है जो सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन उनसे ऐसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो 'उच्च जाति के साहूकारों', शिक्षा के निम्न स्तर, गरीबी, जाति-आधारित भेदभाव, ईंट भट्टों, चावल मिलों, निर्माण स्थलों, खानों, इस्पात कारखानों या मछली फार्मों में काम करने वाले बंधुआ मजदूरों आदि से संबंधित होते हैं।

भारत के अभिजात वर्ग का ब्रेनवॉशिंग

भारत सरकार अपने कई नौकरशाहों को हार्वर्ड में प्रशिक्षित करने के लिए

करदाताओं का पैसा खर्च करती है। हमने यह साबित कर दिया है कि एक के बाद एक केंद्र, एक के बाद एक विद्वान, एक के बाद एक सेमिनार भारत के राष्ट्रीय हित को कमजोर करने पर केंद्रित हैं, जिसका उद्देश्य युवाओं को विचारधारा से प्रभावित करना, कमजोर वर्ग को भर्ती करना और भोले-भाले लोगों पर अपना एजेंडा थोपना है। यह सब करते हुए विषयों के अप्रिय पहलुओं को खुलेआम नजरअंदाज किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 2006 में हुई, जब टाइम्स न्यूज़ ने हार्वर्ड केनेडी स्कूल ऑफ़ गवर्नमेंट द्वारा भारतीय सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के फायदों के बारे में एक लेख प्रकाशित किया। लेख में दावा किया गया था कि हार्वर्ड न केवल प्रशिक्षण देगा, बल्कि इस प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों का चयन भी करेगा। इसमें कहा गया था कि 'लालफीताशाही से निपटने का यह सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठित केनेडी स्कूल ऑफ़ गवर्नमेंट अब भारतीय सिविल सेवकों को सुशासन से संबंधित मुद्दों पर प्रशिक्षण देगा।' तीन महीने और एक साल के कार्यक्रम उपलब्ध हैं। हार्वर्ड के संकाय सदस्य भी इस कार्यक्रम के तहत व्याख्यान देने के लिए भारत आते हैं।

यह चिंताजनक है कि भारत अपने नौकरशाहों को प्रशिक्षित और मार्गदर्शन करने में असमर्थ है। नौकरशाही की शक्ति और कई नीतियों की नाजुक और संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए, यह एक खतरनाक रास्ता है। भले ही भारत को लगता हो कि हांगकांग विश्वविद्यालय (एचकेएस) बेहतर विशेषज्ञता प्रदान करता है, लेकिन क्रोएशिया द्वारा अपनाया गया मॉडल कहीं अधिक उपयुक्त होगा। एचकेएस के साथ क्रोएशिया की साझेदारी का उद्देश्य क्रोएशिया के सामने आने वाले विशिष्ट नीतिगत मुद्दों को हल करने के लिए एक अनुकूलित कार्यक्रम विकसित करना है। समझौते में कहा गया है कि प्रशिक्षण 'क्रोएशिया के प्रधानमंत्री कार्यालय

के साथ परामर्श' के बाद 'सरकार द्वारा पहचाने गए आवश्यक क्षेत्रों' को संबोधित करेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि क्रोएशिया के अग्रणी नीति निर्माता और विशेषज्ञ एचकेएस के संकाय को अपनी आवश्यकताओं के बारे में बताएंगे।

क्रोएशिया जैसा छोटा देश हार्वर्ड से अपने राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से निपटने की समझ और साहस रखता है, जबकि भारत ने अपने अभिजात वर्ग के प्रशिक्षण का जिम्मा पूरी तरह से बाहरी संस्थानों को सौंप दिया है। रोहिंग्याओं के प्रबंधन, कश्मीर में सूफियों से निपटने, भारतीय मुसलमानों के प्रति संवेदनशीलता आदि के बारे में भारतीयों को हार्वर्ड द्वारा प्रशिक्षण देना बेहतर क्यों है? हार्वर्ड को यह तय करने का अधिकार क्यों दिया जा रहा है कि भारतीय अनुच्छेद 370, सीएए, राम मंदिर, सामाजिक न्याय, एलजीबीटीक्यू+ अधिकारों आदि के बारे में कैसा महसूस करते हैं? भारतीय सरकार हार्वर्ड से इतनी प्रभावित है और उसमें इतना तीव्र औपनिवेशिक हीनबोध व्याप्त है कि उसने हार्वर्ड को विश्व गुरु मानकर भारत को अपना शिष्य बना लिया है। भारत जैसे देश के लिए, जो खुद को एक प्रमुख विश्व शक्ति मानता है, यह सरासर अपमानजनक है।

यह कार्यक्रम अब विस्तारित हो चुका है। कई लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय सरकार वास्तव में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए घरेलू निधि योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। विदेशों में विभिन्न विश्वविद्यालयों में अड़तीस अल्पकालिक और सोलह दीर्घकालिक कार्यक्रमों की एक सूची है, जहां भारतीय सिविल सेवकों को प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हार्वर्ड, बर्कले, शिकागो विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भी इन सूचियों में प्रमुखता से शामिल हैं। सरकार भारतीयों के लिए विदेशों में डिग्री कार्यक्रमों के लिए भी धन उपलब्ध कराती है। शीर्ष विश्वविद्यालयों

में पांच चीनी विश्वविद्यालय शामिल हैं, जिसका अर्थ है कि भारतीय नौकरशाह करदाताओं के खर्च पर चीन में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। पाठ्यक्रम और उसकी अवधि के आधार पर, भारतीय सरकार प्रति उम्मीदवार पचपन हजार डॉलर तक का भुगतान करती है।

भारत में विश्वविद्यालय रैंकिंग को लेकर एक तरह का जुनून सा दिखता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल वह अपने नौकरशाहों को प्रशिक्षित करने के लिए विश्वविद्यालय की योग्यता तय करने में करता है। ये रेटिंग व्यक्तिपरक और बेहद संदिग्ध हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले के एक अध्ययन में आरोप लगाया गया है कि इन अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग पर कुछ खास परामर्श फर्मों की नियुक्ति का प्रभाव पड़ता है।

अमेरिका के लिए, लक्षित देशों के अभिजात वर्ग के नेताओं को पश्चिमी विचारधारा से अवगत कराना एक महत्वपूर्ण विदेश नीति रणनीति रही है। अब यह एक नए स्तर पर पहुँच गया है क्योंकि हार्वर्ड ने भारतीय अरबपतियों को अनुदान देने और विश्वसनीयता के लिए अपने नाम का इस्तेमाल करने के लिए लुभाया है। उदाहरण के लिए, भारतीय अरबपति दंपति भरत देसाई और नीरजा सेठी, देसाई-सेठी फाउंडेशन या डीएस फाउंडेशन के पीछे हैं। यह फाउंडेशन हर साल भारतीयों को हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में लोक नीति/लोक प्रशासन/अंतर्राष्ट्रीय विकास में स्नातकोत्तर फेलो के रूप में आने के लिए वित्त पोषित करता है। डीएस फाउंडेशन पब्लिक सर्विस फेलोशिप भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा के सक्रिय अधिकारियों के लिए है। दूसरे शब्दों में, भारतीय नौकरशाहों को हार्वर्ड द्वारा इस विचारधारा से अवगत कराने का खर्च भारत के ही अरबपतियों और करदाताओं द्वारा वहन किया जा रहा है। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल ने इस लोक सेवा फैलोशिप कार्यक्रम की स्थापना की है और भारतीय प्रशासनिक एवं विदेश सेवाएँ अपने अधिकारियों को

इसमें भाग लेने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करती हैं। ऐसे फैलोशिप प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से हार्वर्ड के नियंत्रण में है। इस मामले में न तो भारतीय सरकार और न ही डीएस फाउंडेशन का कोई दखल है।

हार्वर्ड ने किस प्रकार अपने विश्वदृष्टिकोण से भारत के बौद्धिक अभिजात वर्ग में पैठ बनाई है, इसे समझाने के लिए हम मुकुल सक्सेना का उदाहरण लेते हैं, जिन्हें हार्वर्ड ने लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए फैलोशिप प्रदान की थी। यह चयन रणनीतिक था क्योंकि उन्होंने दो दशकों तक भारतीय सेना में सेवा की थी। रोहिंग्या शरणार्थियों के प्रति सहानुभूति रखने और यह मानने के कारण कि भारतीय सेना की कार्रवाई किसी संप्रभु राज्य का आंतरिक मामला नहीं है, सक्सेना हार्वर्ड के लिए उपयुक्त उम्मीदवार थे। उनके कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

उदासीनता और निष्क्रियता: रोहिंग्या मुसलमानों की दुर्दशा (प्रगति में)।

कश्मीर में जिहाद का मानचित्रण: उनका दावा है कि सूफी परंपरा कश्मीर में सहिष्णुता बनाए रखती है, और इसलिए 'यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सभी सैन्य अभियान और गतिविधियां इन धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ की जाएं'।

क्या भारत कानूनी रूप से लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है? भारत और सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम: वह अधिनियम की आलोचना करते हुए कहते हैं कि 'इस तरह के कानूनों का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है'।

फ्रांसीसी हिजाब कानून और धार्मिक आस्था प्रकट करने का अधिकार: वह कुछ मुस्लिम प्रतीकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के खिलाफ फ्रांसीसी कानून की आलोचना करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यह महिलाओं के अधिकारों को प्रभावित करता है और लैंगिक भेदभाव की स्थिति पैदा करता है।

वह भारतीय सेना के लिए लेख भी लिख रहे हैं, जिनमें उन्हें मुस्लिम हिंसा से निपटने में नरम रुख अपनाने की सलाह दी गई है।

हार्वर्ड से स्नातक होने के बाद, सक्सेना हैदराबाद स्थित कौटिल्य लोक नीति विद्यालय में संकाय सदस्य बन गए। इस संस्थान का नाम भ्रामक है क्योंकि इसका कौटिल्य (जो आमतौर पर चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं, एक प्राचीन दार्शनिक और रणनीतिकार) के लोक नीति संबंधी दृष्टिकोण से कोई संबंध नहीं है। यह विद्यालय राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं से जुड़ा हुआ है, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने राहुल गांधी के प्रवक्ता और चुनाव प्रचार प्रबंधक के रूप में कार्य किया है। डीन, सैयद अकबरुद्दीन, भारतीय विदेश सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी और संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि हैं।

हार्वर्ड की वैचारिक उपस्थिति इस तथ्य से स्पष्ट है कि कौटिल्य के बोर्ड में हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के दो पूर्व प्रोफेसर, स्टीव जार्डिंग और मोशिक टेमकिन शामिल हैं। जार्डिंग हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में पूर्व व्याख्याता और राहुल गांधी के राजनीतिक अभियान सलाहकार थे। उन्होंने मोदी के खिलाफ गांधी के 2019 के अभियान में मदद की थी। इससे पहले, जार्डिंग 2017 में समाजवादी पार्टी के अभियान प्रबंधक थे, जो असफल रहा था।

टेमकिन कौटिल्य विश्वविद्यालय में इतिहास और लोक नीति के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वे चीन में उइगरों की स्थिति की तुलना भारत में मुसलमानों की स्थिति से करते हैं। उन्होंने मोदी के नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 की निंदा करने के लिए सीनेटर बर्नी सैंडर्स की प्रशंसा की। उन्होंने (बर्नी सैंडर्स) आज दुनिया के अधिकांश हिस्सों में फैल रहे अधिनायकवाद और फासीवाद के खिलाफ सैद्धांतिक रुख अपनाया; जब भारत के राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के करोड़ों मुस्लिम

नागरिकों के साथ कानूनी रूप से भेदभाव करने का अभियान शुरू किया, तो सैंडर्स एकमात्र प्रमुख अमेरिकी राजनीतिक नेता थे जिन्होंने उनकी निंदा की।

टेमकिन भारतीयों को अमेरिकी भू-राजनीतिक विचारधारा में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता को समझते हैं। भारतीय बुद्धिजीवियों को हार्वर्ड में प्रशिक्षण के लिए लाकर सिपाही बनाना एक धीमी और खर्चीली प्रक्रिया है। कौटिल्य भारत में हार्वर्ड के अकादमिक आधार के रूप में कार्य करके इस समस्या का समाधान करते हैं।

वो दिन अब समाप्त होने चाहिए जब कुछ भाग्यशाली लोग, जो खर्च वहन कर सकते हैं, विदेशों के प्रतिष्ठित संस्थानों में जाते थे; भारत में अब अपना एक उत्कृष्ट लोक नीति विद्यालय है। कौटिल्य लोक नीति विद्यालय का उद्देश्य उन लोगों को शिक्षित और प्रशिक्षित करना है जिनकी भारत को आवश्यकता है, ताकि वह अपने आकार, समृद्धि और क्षमता के अनुरूप वैश्विक नेता के रूप में अपना स्थान प्राप्त कर सके।

कौटिल्य विश्वविद्यालय लोक नीति में स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य भविष्य के ऐसे नेताओं का निर्माण करना है जिनमें 'सही दृष्टिकोण' हो। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कुछ दिखावटी सौंदर्य संबंधी विशेषताओं को भी अपनाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त एंड्रयू फ्लेमिंग ने भी इसकी पुष्टि की, जिन्होंने 'कैनेडी स्कूल से प्रेरित सजावट के साथ उत्कृष्ट सुविधाओं' की सराहना की।

अमेरिका में कई लोगों का मानना है कि हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में कौशल विकास से ज़्यादा राजनीति और नेटवर्किंग पर ज़ोर दिया जाता है, जिसके चलते भारतीय नौकरशाहों को हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में प्रशिक्षित करना करदाताओं के पैसे की भारी बर्बादी है। अमेरिका में कुछ स्वतंत्र

समीक्षाओं में हार्वर्ड कैनेडी स्कूल की शिक्षा को नेतृत्व, नैतिकता, संगठन/लामबंदी और जन प्रबंधन जैसे कौशल क्षेत्रों में सबसे कम प्रभावी बताया गया है। कुछ लोग तो इस बात पर भी संदेह जताते हैं कि क्या किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के क्लासरूम में बैठकर अच्छी नीति निर्माण की कला सिखाई जा सकती है। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के पूर्व छात्र और न्यूयॉर्क के पूर्व सांसद डैनियल बी. मैफेई ने टिप्पणी की कि इन कार्यक्रमों में राजनीति को गौण माना जाता है क्योंकि यह एक विशिष्ट शिक्षा है जो मुख्य रूप से संपर्क बनाने पर केंद्रित है।

हार्वर्ड विश्वविद्यालय के दोहरे मापदंड

अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के कई विश्वविद्यालयों और यहां तक कि कंपनियों ने भी उन मूल निवासियों की भूमि को स्वीकार करना और सम्मान देना शुरू कर दिया है जिन पर उनकी आलीशान इमारतें बनी हैं। ऑस्कर जैसे आयोजनों में, मूल निवासियों की भूमि की घोषणा एक प्रार्थना के रूप में की जाती है। हार्वर्ड में, मूल निवासियों की भूमि की स्वीकृति एक औपचारिक बयान है।

हार्वर्ड विश्वविद्यालय मैसाचुसेट्स जनजाति की पारंपरिक और पैतृक भूमि पर स्थित है, जो बोस्टन और कैम्ब्रिज के मूल निवासी थे। हम मैसाचुसेट्स जनजाति के भूतपूर्व और वर्तमान लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और उस भूमि का आदर करते हैं जो मैसाचुसेट्स लोगों के लिए पवित्र है। इन्हें मूल निवासी भूमि अभिस्वीकृति के रूप में जाना जाता है, और ये ईमेल और इमारतों के साइनबोर्ड पर पसंदीदा सर्वनामों के बगल में ही दिखाई देने लगी हैं। प्रमुख घटनाओं की शुरुआत में, राजनीतिक रूप से सही माने जाने वाले श्वेत लोग अक्सर आत्म-धार्मिकता का प्रदर्शन करते हुए यह स्वीकार करते हैं कि वे 'लूटी हुई भूमि' पर बसे हुए हैं और उस पर

कब्ज़े में 'सहभागी' हैं।
हालांकि यह बात प्रामाणिक लग सकती है, लेकिन इससे एक सवाल उठता है: जब विश्वविद्यालय दावा करते हैं कि वे चोरी की ज़मीन पर बने हैं, तो वे इसे लौटाकर सही काम क्यों नहीं कर रहे हैं? चोरी की संपत्ति के साथ यही किया जाता है। हार्वर्ड को कभी यह ख्याल नहीं आया कि वह अपने तिरपन अरब डॉलर के कोष का इस्तेमाल मूल अमेरिकी लोगों को मुआवज़ा देने के लिए करे।
सामाजिक और व्यवहार विज्ञान विभाग में अकादमिक मामलों और फैलोशिप कार्यक्रमों की सहायक निदेशक एलिजाबेथ सोलोमन को हार्वर्ड टी.एच. चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के 2018 के दीक्षांत समारोह का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्होंने मूल भूमि और लोगों की आधिकारिक स्वीकृति के साथ शुरुआत की। पोंकापोआग में मैसाचुसेट मूल जनजाति की सदस्य होने के नाते, सोलोमन ने इस बात का संदर्भ दिया कि मूल स्थान की स्वीकृति का अभ्यास क्यों किया जाता है:
जब संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वदेशी समुदाय एक साथ एकत्रित होते हैं, तो वे पारंपरिक रूप से उस भूमि के पूर्वजों को स्वीकार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं जिस पर वे मिल रहे हैं।
यह अत्यंत मार्मिक और समझने योग्य है। भूमि के वर्तमान निवासियों को 'भूमि के पूर्वजों' को स्वीकार करना और उनका सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार की सार्वजनिक स्वीकृति हार्वर्ड के लिए भारत में एक आदर्श के रूप में कार्य करने और अपनी नैतिकता के हिस्से के रूप में सिखाने के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। क्या मुंबई में हार्वर्ड चान स्कूल की मेजबानी करने वाले पीरामल सेंटर में होने वाले समारोहों की शुरुआत उस भूमि के मूल निवासियों को सम्मानित करने के अनुष्ठान से होनी चाहिए, जो

पुर्तगालियों के स्वामित्व में आने से पहले उस भूमि के स्वामी थे? इसी प्रकार, हार्वर्ड के नई दिल्ली स्थित कार्यालय गौरवशाली इंद्रप्रस्थ की भूमि पर बने हैं, जिसका सम्मान उनके सभी कार्यक्रमों की शुरुआत में अवश्य किया जाना चाहिए।

हार्वर्ड के सामाजिक न्याय संबंधी सिद्धांतों को कैथोलिक चर्च पर दबाव डालना चाहिए कि वह भारत में अपनी सभी सभाओं की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा छीनी गई और चर्च को विरासत में मिली मूल भूमि को स्वीकार करने और उसका सम्मान करने से करे। हार्वर्ड को इस बात की वकालत करनी चाहिए कि भारतीय मस्जिदों में सभी मुस्लिम प्रार्थनाओं की शुरुआत भूमि के मूल निवासियों को स्वीकार करने से हो। भारत में ये सभी उदाहरण मूल अमेरिकियों से श्वेतों द्वारा की गई भूमि हड़पने की तुलना में हाल ही के लूट के मामले हैं।

इस तरह की बयानबाजी भरी अटकलें महज़ हार्वर्ड विश्वविद्यालय के दोहरे मापदंड को उजागर करने के लिए किए गए विचार प्रयोग हैं।

16. हार्वर्ड बिजनेस स्कूल

अवलोकन

यह एक संक्षिप्त अध्याय है जो बताता है कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल किस प्रकार विश्वभर के प्रबंधन संस्थानों को अपने केस स्टडी संग्रहों का निर्यात करके हार्वर्ड के ब्रांड एंबेसडर की भूमिका निभाता है। यह भी दर्शाता है कि चीन ने इन मुख्यतः अमेरिकी केस स्टडीज़ की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया है और इसके बजाय अपना खुद का ब्रांड बनाने के लिए कदम

उठाए हैं। भारत को भी शायद हार्वर्ड पर अपने झुकाव पर सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि भारतीय सभ्यता और उसकी संपत्तियों को समझने और चित्रित करने में हार्वर्ड बुरी तरह विफल रहा है।

व्यवसाय के नजरिए से सामाजिक न्याय

अधिकांश लोग मानते हैं कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का एकमात्र उद्देश्य व्यवसाय चलाना, निवेश संबंधी निर्णय प्रबंधित करना और इसी तरह की चीजों की शिक्षा देना है। कम ही लोग यह उम्मीद करते हैं कि यह सामाजिक विज्ञान के एजेंडे के साथ पहचान की राजनीति में भी लिप्त है। दुर्भाग्य से, वास्तविकता इसके विपरीत है: हार्वर्ड बिजनेस स्कूल उद्यमिता और व्यवसाय के नाम पर भारत में कई समाजशास्त्रीय अध्ययनों को वित्त पोषित करता है, और ऐसे 'व्यावसायिक विषय' जातिगत भेदभाव के एकतरफा चित्रण को बढ़ावा देने का जरिया बन जाते हैं। हम यह दिखाएंगे कि कैसे हार्वर्ड के विद्वान खुलेआम मान्य प्रमाणों की अनदेखी करते हैं और अपने पूर्वकल्पित विचारों के अनुरूप डेटा का चयन करते हैं। यह सब भारतीय अरबपतियों के वित्त पोषण से खुलेआम होता है।

उदाहरण के तौर पर, लक्ष्मी अय्यर और तरुण खन्ना (दोनों हार्वर्ड स्कूल से) तथा आशुतोष वर्शनी (हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से) द्वारा लिखित एक शोध पत्र में यह निष्कर्ष निकाला गया कि जहाँ कुछ निम्न जाति के सदस्यों ने भारत में राजनीतिक प्रतिनिधित्व में प्रगति की है, वहीं उद्यमिता के क्षेत्र में ऐसा नहीं है। उनका दावा है कि ऐसा श्रमिकों को खोजने के लिए नेटवर्क की कमी और आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के साथ संपर्कों की कमी के कारण होता है। चूंकि यह समस्या 'प्रगतिशील नीतियों' वाले राज्यों में भी बनी हुई है, इसलिए वे समाज के गहरे स्तरों तक जाने वाले आगे के अध्ययनों की अनुशंसा करते हैं। इसका लक्ष्य समाज में काम कर रहे

'गहरे तंत्रों' को उजागर करना होगा।

यह विषय महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पर भारत के अपने सिद्धांतों के आधार पर ही विचार किया जाना चाहिए। हार्वर्ड के ऐसे शोध से विकसित सिद्धांत भारत में अपनी नीतियों को आगे बढ़ाते हैं और वैश्विक शक्ति केंद्रों से अंतरराष्ट्रीय दबाव पैदा करते हैं, जहां हार्वर्ड का दबदबा है। उदाहरण के लिए, यह शोध जाति और उद्यमिता के बीच संबंधों पर प्रोफेसर आर. वैद्यनाथन (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर) के दशकों के शोध को पूरी तरह से अनदेखा करता है। वैद्यनाथन की 2019 में प्रकाशित पुस्तक, 'कास्ट एज़ सोशल कैपिटल', एक व्यापक अध्ययन था, जिसमें व्यवस्थित रूप से दिखाया गया था कि कैसे जातिगत नेटवर्क ने कई समुदायों को व्यावसायिक सफलता प्राप्त करने में मदद की। इस पुस्तक का भारत और अन्य जगहों पर व्यापक प्रचार और चर्चा हुई। फिर भी हार्वर्ड के विद्वानों ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। यह उम्मीद की जाती है कि हार्वर्ड में कार्यरत जिम्मेदार विद्वान अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप कठोर और संतुलित शोध करेंगे।

वैद्यनाथन के अध्ययन में मुस्लिम और दलित समूहों द्वारा स्थापित वाणिज्य मंडलों की उद्यमशीलता में मिली सफलता की एक अलग कहानी सामने आती है। उनके निष्कर्षों की तुलना हार्वर्ड के निष्कर्षों से करना उचित है।

पुस्तक का मुख्य तर्क यह है कि जाति या समुदाय या जाति उद्यमिता में एक प्रमुख भूमिका निभाती है और व्यक्ति विशेष की बजाय पूरी जाति की ऊपर की ओर गतिशीलता को सुगम बनाती है।

यह पुस्तक शिक्षा, उद्यमिता और व्यवसाय को बढ़ावा देने तथा व्यक्तियों के बीच पेशेवर नेटवर्क बनाने में जाति की भूमिका का विश्लेषण करती है। भारत भर में हजारों जाति-आधारित आर्थिक समूह फैले हुए हैं, जो

लाखों रोजगार प्रदान करते हैं और धन सृजित करते हैं। मारवाड़ी, सिंधी, पटेल, बोहरा, कच्छी जैसे पारंपरिक व्यापारिक समुदाय वैश्विक व्यापार नेटवर्क बनाने में अत्यंत सफल रहे हैं। यह पुस्तक इस बात पर प्रकाश डालती है कि किस प्रकार जातियों ने सेवा, व्यापार, निर्माण, अचल संपत्ति, परिवहन, पर्यटन आदि विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। उल्लेखनीय उदाहरणों में तमिलनाडु के तिरुपुर में गौंडर समुदाय द्वारा, गुजरात के सूरत में पटेल समुदाय द्वारा, तमिलनाडु के शिवकाशी में नादार समुदाय द्वारा और गुजरात के जामनगर में जडेजा/पटेल समुदाय द्वारा गठित समूह शामिल हैं। ऐसे समूहों को आम लोग बढ़ावा देते हैं और चलाते हैं, इनके सदस्यों में जोखिम लेने की प्रबल इच्छा होती है, और इनका व्यवसाय औपचारिक अनुबंधों के बजाय संबंधों पर आधारित होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे आर्थिक समूह आमतौर पर स्व-वित्तपोषित होते हैं। वे सहयोग और प्रतिस्पर्धा के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखते हैं।

भारत में दलित जातियाँ व्यापार और उद्यमिता में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। तिरुपुर अब बुनाई उद्योग में विश्व अग्रणी बन चुका है। अहमदाबाद का लगभग 800 करोड़ रुपये का पतंग उद्योग मुस्लिम उद्यमियों के वर्चस्व में है। चमड़े के व्यापार में भी मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या है। दलित भी व्यापार में सक्रिय हो रहे हैं। कुछ दलित उद्यमियों ने बड़े-बड़े व्यापारिक साम्राज्य स्थापित किए हैं। दलितों के लिए भारतीय वाणिज्य और उद्योग का एक चैंबर भी स्थापित किया गया है।

भारत में जाति आरक्षण और राजनीति से गहराई से जुड़ी हुई है। सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में अधिक आरक्षण की मांग बढ़ती जा रही है। अगड़ी जातियां भी आरक्षण चाहती हैं। लेकिन आरक्षण से कितना फायदा होता है? बहुत कम। कुछ जातियों ने आरक्षण के बजाय

अपने वैश्यकरण या उद्यमशीलता कौशल के कारण कहीं अधिक तरक्की की है। तमिलनाडु में कुछ जातियां अनुसूचित जाति समुदाय की सूची से अपना नाम हटवाना चाहती हैं क्योंकि उन्हें इस आधार पर सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

वैद्यनाथन ने लगातार और ठोस तर्क देते हुए कहा है कि जाति एक प्रकार की सामाजिक पूंजी है जिसका उपयोग नीति निर्माता निम्न वर्गों के उत्थान में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए कर सकते हैं।

व्यावसायिक सफलता के संदर्भ में जाति एक जटिल सामाजिक संस्था है जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही निहितार्थ हैं। एक पुस्तक समीक्षा में कहा गया है कि यह 'भारतीय समाज में जाति की भूमिका पर चर्चा को समृद्ध करती है'। उनका कार्य तरुण खन्ना की हार्वर्ड टीम द्वारा किए गए सतही विश्लेषण से कहीं अधिक गहन है, और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने उनका बहिष्कार किया है।

वैद्यनाथन जैसे विषय विशेषज्ञों की अनुपस्थिति में, हार्वर्ड के अनेक सम्मेलन और कार्यक्रम हार्वर्ड के अपने संकीर्ण दृष्टिकोण और वैचारिक पूर्वाग्रह को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र हैं। उदाहरण के लिए, इसाबेल विल्करसन एचबीएस के एक कार्यक्रम, 'विविधता का प्रबंधन: इसाबेल विल्करसन के साथ वार्तालाप, जाति की लेखिका' में मुख्य वक्ता थीं। और कुछ महीनों बाद उन्हें हार्वर्ड के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में आमंत्रित किया गया।

और हार्वर्ड को वित्त पोषित करने वाले भारतीय अरबपति, विविध शोध परिणामों वाले विद्वानों जैसे वैद्यनाथन का बहिष्कार करने वाली 'कैंसल कल्चर' जैसी गतिविधियों के लिए हार्वर्ड को जवाबदेह ठहराने में विफल रहे हैं।

एक अन्य एकतरफा विश्लेषण अभिजीत बनर्जी और अन्य द्वारा एचबीएस

में प्रकाशित एक शोध पत्र था जिसमें कहा गया था कि 'समाज में कुछ समूहों के पास उनकी संख्या के अनुपात से कहीं अधिक शक्ति होती है'। इसके स्पष्ट उदाहरण हैं दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के वर्षों के दौरान श्वेत लोग और भारत में इसके अधिकांश इतिहास में उच्च जातियाँ। यह शोध पत्र भारतीय ईसाइयों जैसे विपरीत उदाहरणों को जानबूझकर अनदेखा करता है, जो जनसंख्या का केवल दो प्रतिशत होने के बावजूद, ब्रिटिशों द्वारा दी गई भूमि और शैक्षिक विशेषाधिकारों के कारण अचल संपत्ति और कॉर्पोरेट नौकरियों के एक बड़े हिस्से के मालिक और नियंत्रक हैं। शोध पत्र में आगे कहा गया है: 'किसी निर्वाचन क्षेत्र में ब्राह्मणों की जनसंख्या हिस्सेदारी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों, डाकघरों तक पहुँच से सकारात्मक रूप से संबंधित है...'

जिस बात को नजरअंदाज किया जा रहा है, वह यह है कि शिक्षा संस्थानों के नियंत्रण में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व अधिक है, जबकि मध्य स्तर पर हिंदू और सबसे निचले स्तर पर मुसलमान हैं। और जब कोई यह बताता है कि भारतीय ईसाई अक्सर शिक्षा के संरक्षक होते हैं, तो अक्सर यह जवाब दिया जाता है कि यह दर्शाता है कि वे एक प्रगतिशील समुदाय हैं। फिर भी, ब्राह्मणों के शिक्षा पर ध्यान को प्रगतिशील के बजाय जातिवादी करार दिया जाता है। कोई भी यह उम्मीद करेगा कि हार्वर्ड के एक विद्वान और भावी नोबेल पुरस्कार विजेता तथ्यों की व्याख्या में सुसंगत होंगे, न कि अपने तर्क को साबित करने के लिए चुनिंदा आंकड़ों का इस्तेमाल करेंगे।

एचबीएस में विविधता प्रबंधन पर दिए गए व्याख्यानों में से एक में, प्रोफेसर मिहिर देसाई ने तुलसा नरसंहार और मुआवजे की मांग पर बात की और अमेरिका में अश्वेतों के लिए मुआवजे पर चर्चा की। उन्होंने इस अवसर का उपयोग भारत में दलितों के मुद्दे पर बात करने के लिए किया।

उन्होंने कहा कि अफ्रीकी अमेरिकियों द्वारा मुआवजे की मांग का उपयोग दलितों के लिए मुआवजे की मांग को प्रेरित करने के लिए किया जाना चाहिए: 'मुझे इस मामले के इस हिस्से पर वास्तव में गर्व है, जो समानताएं तलाशना और इस पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में विचार करना है।'
2017 में, एचबीएस ने विकासशील देशों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लंबे समय से चले आ रहे पैटर्न का अध्ययन किया। भारत पर आधारित अनुभाग में दावा किया गया कि भारतीयों द्वारा गोरी त्वचा को प्राथमिकता देने का मूल कारण जाति व्यवस्था और आर्य आक्रमण है।
1970 के दशक में कुछ पश्चिमी कंपनियों ने उभरते बाजारों के लिए विशेष उत्पाद तैयार करने हेतु उत्पाद नवाचार में निवेश करना शुरू किया। यूनिलीवर की बड़ी भारतीय सहयोगी कंपनी, हिंदुस्तान लीवर, जिसने 1950 के दशक में अपनी खुद की अनुसंधान सुविधाएं स्थापित की थीं, इस क्षेत्र में अग्रणी कंपनियों में से एक थी। इसने अपने विशिष्ट भारतीय शैम्पू और टूथपेस्ट ब्रांडों के साथ-साथ यूनिलीवर के वैश्विक पोर्टफोलियो के ब्रांडों की बिक्री शुरू की। इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह थी कि 1978 में 'फेयर एंड लवली' त्वचा को गोरा करने वाली क्रीम का निर्माण हुआ। यह क्रीम भारत में गोरी त्वचा के प्रति पारंपरिक सम्मान को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। इस तरह की पसंद की जड़ें भारतीय इतिहास में गहराई से निहित हैं, जिसे कुछ लोग ढाई हजार साल पहले की जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से जोड़ते हैं, जब गोरी त्वचा वाले विदेशियों ने एक वर्ग व्यवस्था स्थापित की थी जिसमें स्थानीय, सांवली त्वचा वाली आबादी सबसे निचले पायदान पर थी। ... ब्रिटिश शासन ने गोरी त्वचा वाले शासकों का एक नया समूह पेश किया। अब हिंदुस्तान लीवर ने अपनी वैज्ञानिक और ब्रांडिंग क्षमताओं का उपयोग करते हुए इन सांस्कृतिक प्राथमिकताओं को एक बेहद सफल ब्रांड में तब्दील कर दिया, जो भारत

में सबसे अधिक बिकने वाला स्किन केयर ब्रांड बन गया। 'फेयर एंड लवली' एक पेटेंटकृत फॉर्मूले पर आधारित था जिसमें एक सक्रिय तत्व होता था जो त्वचा में मेलेनिन के फैलाव को नियंत्रित करता था। ब्रांड के विज्ञापन में उत्पाद के उपयोग के छह सप्ताह के भीतर अधिक गोरापन का वादा किया गया था, और गोरी त्वचा वाली महिलाओं के बेहतर वैवाहिक अवसरों पर जोर दिया गया था। बॉलीवुड के नाम से जाने जाने वाले विशाल भारतीय सिनेमा उद्योग की हस्तियों द्वारा इसके प्रचार में काफी योगदान दिया गया, जिसके प्रमुख अभिनेता और अभिनेत्रियाँ अधिकतर गोरे रंग के थे।

हमने अध्याय 2 में पहले ही यह दिखाया है कि गोरी त्वचा के प्रति वरीयता वैदिक संस्कृति के कारण नहीं बल्कि मुस्लिम और यूरोपीय आक्रमणों के परिणामस्वरूप हुए हाल के विकास के कारण है।

एचबीएस की एक रिपोर्ट में इस बात का विश्लेषण किया गया है कि राज्य के विधायकों की धार्मिक पहचान सामाजिक-आर्थिक परिणामों को कैसे प्रभावित करती है, और इस परिकल्पना को संदेह का लाभ दिया गया है कि हिंदू-मुस्लिम संघर्षों को कम करने की इच्छा मुसलमानों की ही है।

हमने पाया है कि जिस जिले से विधायक निर्वाचित होता है, उस जिले में मुसलमानों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि से स्वास्थ्य और शिक्षा के परिणाम बेहतर होते हैं। हमें धार्मिक पक्षपात का कोई प्रमाण नहीं मिला है। … मुस्लिम नेता अन्य (मुख्य रूप से हिंदू) नेताओं की तुलना में बाल स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार लाने में अधिक प्रभावी क्यों हैं? एक संभावित स्पष्टीकरण यह है कि मुसलमान … हिंदू-मुस्लिम संघर्ष को कम करने को प्राथमिकता देते हैं, और सार्वजनिक वस्तुओं का समान प्रावधान इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है।

2018 में, टाटा ने एचबीएस में अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने पर 8.4 मिलियन डॉलर खर्च किए।
हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने टाटा संस, टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा स्टील और जगुआर लैंड रोवर सहित टाटा कंपनियों के एक समूह के साथ छह साल की, 84 लाख डॉलर की अनुसंधान साझेदारी की घोषणा की है। हार्वर्ड के प्रौद्योगिकी विकास कार्यालय द्वारा समन्वित एक समझौते के तहत, यह साझेदारी अत्याधुनिक अनुसंधान का समर्थन करेगी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में टाटा फेलोशिप कार्यक्रम के माध्यम से आने वाले व्यावसायिक नेताओं को पेशेवर विकास कार्यक्रम प्रदान करेगी। इस व्यवस्था के तहत वित्त पोषित प्रत्येक परियोजना के लिए, टाटा के एक अनुभवी कर्मचारी को एचबीएस कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रम में एक वर्ष तक रहने का अवसर मिलेगा।
भारतीय अरबपतियों की इस परंपरा में कई ऐसे भारतीय भी शामिल हो गए हैं जो शीर्ष अरबपतियों की श्रेणी में नहीं आते। वे भी बड़ी रकम दान कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, ज़ेंडर ग्रुप के सिद्धार्थ 'सिड' योग ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी (एचबीएस) को ग्यारह मिलियन डॉलर दान किए, जो किसी भारतीय द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत दान है। योग ने बताया कि यह हार्वर्ड विश्वविद्यालय में उनके प्रोफेसर को दी गई गुरु दक्षिणा थी, जिन्हें वे अपना गुरु मानते हैं। उन्होंने कहा कि वे गुरु-शिष्य परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। अपने प्रोफेसर को दान स्वीकार करने के लिए मनाने के लिए उन्होंने महाभारत के एकलव्य की कहानी सुनाई, जिन्होंने अपना अंगूठा काटकर अपने गुरु द्रोणाचार्य को दक्षिणा के रूप में अर्पित किया था।
योग की मंशा स्पष्ट रूप से अच्छी थी, लेकिन तुलना पर सवाल उठाए जा सकते हैं: उनके हार्वर्ड प्रोफेसर एक द्रोणाचार्य नहीं बल्कि एक रियल

एस्टेट विकास फर्म के धनी मालिक हैं। योग को यह भी नहीं पता था कि हार्वर्ड का मिशन भारत की गुरु-शिष्य परंपराओं को खत्म करना है, क्योंकि वह उन्हें सामाजिक न्याय के लिए खतरा मानता है, और उनकी जगह हार्वर्ड की अपनी परंपराएं स्थापित करना है। बेशक, भारतीय प्रेस ने इस बात पर खुशी जताई कि यह युवा भारतीय उद्यमी अब अंतरराष्ट्रीय उद्योगपतियों के साथ मेलजोल रख रहा है।

हार्वर्ड और कैंसिल कल्चर

हार्वर्ड ने भारत में जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों में राजद्रोह के आरोप में छात्रों की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है, लेकिन अपने ही देश में, जब माहौल उसके अनुकूल नहीं होता, तो वह 'कैंसल कल्चर' का समर्थन करता है, यहाँ तक कि बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्रों के सम्मेलनों में भी। हार्वर्ड अपने पूर्व छात्रों पर स्नातक होने के बाद भी पूर्ण नियंत्रण रखना चाहता है। हाल ही में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल क्लब ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा पश्चिमी समाजों में व्याप्त 'कैंसल कल्चर' पर आयोजित एक कार्यक्रम को विडंबनापूर्ण रूप से रद्द कर दिया गया। यह खबर इस प्रकार है:

‘क्या आपने कभी उन विचारों के बारे में सोचा है जो देश को तबाह कर रहे सांस्कृतिक और राजनीतिक युद्धों के पीछे हैं और पिछले गर्मियों में “कैंसल कल्चर” आंदोलन और देश भर के कई शहरों में हिंसक घटनाओं के रूप में चरम पर पहुंच गए? क्या हम इस आंदोलन में सामाजिक न्याय कार्यकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे भड़काऊ शब्दों को समझते भी हैं?... लेखक जेम्स लिंडसे के साथ पुस्तक की प्रस्तुति और चर्चा के लिए हमसे जुड़ें, जिसके बाद प्रश्नोत्तर सत्र होगा,’ कार्यक्रम का विवरण, जिसे अब बिजनेस स्कूल क्लब की वेबसाइट से हटा दिया गया है, में यह लिखा था।

अमेरिकी सिद्धांतों का निर्यात

शिक्षण क्षमता के आधार पर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल दुनिया के सबसे प्रभावशाली स्कूलों में पहले स्थान पर है, जो इस बात का माप है कि उनके पाठ्यक्रम का उपयोग अन्य स्कूलों द्वारा कितना किया जाता है। एचबीएस की विशिष्ट पद्धति केस स्टडीज़ का उपयोग है, जिन्हें इसके विद्वानों द्वारा तैयार किया जाता है और ये एचबीएस के लिए राजस्व का एक बड़ा स्रोत हैं। ये केस स्टडीज़ विश्व स्तर पर एमबीए शिक्षा का मुख्य आधार बन गई हैं। 2020 में, हार्वर्ड ने दुनिया भर के बिजनेस स्कूलों को केस स्टडीज़ की पंद्रह मिलियन से अधिक प्रतियां बेचीं।

हालांकि, चीन अपने स्वयं के केस स्टडी का संग्रह विकसित कर रहा है जिसे अब दुनिया को उससे खरीदना होगा। उसका दावा है कि एचबीएस केस स्टडी का दृष्टिकोण बहुत ही संकीर्ण और अमेरिकी केंद्रित है। चूंकि चीन कॉर्पोरेट जगत का केंद्र बिंदु बन गया है, इसलिए चीन को समझना आवश्यक है, और इसीलिए उसने शेष विश्व को शिक्षित करने के लिए इन केस स्टडी को विकसित किया है।

बीजिंग स्थित सिंघुआ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र और प्रबंधन विभाग के एसोसिएट डीन युबो चेन का कहना है कि उनके छात्रों की अलग-अलग मांगें इस बात का कारण हैं कि उनका स्कूल एशिया के उन कुछ स्कूलों में से एक है जो अपने स्वयं के - अक्सर छोटे, अधिक व्यावहारिक - शिक्षण केस स्टडी लिख रहे हैं। वे कहते हैं, 'हमारे छात्र हार्वर्ड केस स्टडी से संतुष्ट नहीं हैं। माहौल इतनी तेजी से बदल रहा है, और हमें चीन पर केस स्टडी की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, अमेज़न के बारे में बात करना बहुत मुश्किल है। वे चीन में ई-कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं।'

हार्वर्ड खुद को भारतीय कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रमों से धन

जुटाकर अपनी पसंद के कार्यों में लगाने वाले मध्यस्थ के रूप में स्थापित कर रहा है। यह विश्व बैंक और भारतीय सरकार की मदद से भारतीय व्यापारियों को प्रशिक्षण देने के लिए उच्च स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करता है। इसका लक्ष्य भारतीय व्यापारिक नेताओं को अपनी बौद्धिक सोच के अनुरूप लाना है। ऐसे ही एक कार्यक्रम में कहा गया है:
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निगमों के वरिष्ठ प्रबंधकों के एक समूह की क्षमता को मजबूत करना था। केस स्टडी पद्धति के माध्यम से, सीएसआर विकास में सर्वोत्तम प्रथाओं और रणनीतियों पर प्रकाश डाला गया। यह कार्यशाला हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में विकसित अत्यंत सफल रणनीतिक सीएसआर कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रम के मॉडल पर आधारित थी।
हार्वर्ड, डब्ल्यूईएफ और अन्य व्यावसायिक अभिजात वर्ग द्वारा शुरू किए गए एक आंदोलन को भी बढ़ावा दे रहा है, जिसमें कंपनियों का मूल्यांकन ईएसजी के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए 'अच्छे' कार्यों के आधार पर किया जाता है। 'सामाजिक भलाई' के मानदंड वैश्विक अभिजात वर्ग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और सार्वभौमिक रूप से लागू किए जाते हैं।

चीन का व्यावसायिक नेतृत्व
यह उल्लेखनीय है कि चीन के अपने संस्थान हैं जो उसके अपने व्यावसायिक सिद्धांतों को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए, चाइना यूरोप इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल (CEIBS) यूरोपीय संघ (EU) और चीनी सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। CEIBS की सह-स्थापना चीनी सरकार और EU ने की थी और इसके परिसर शंघाई, बीजिंग, शेन्ज़ेन, घाना के अकरा और स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्थित हैं। यह बिजनेस स्कूल रैंकिंग में तेजी से ऊपर चढ़ रहा है और केवल हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, व्हार्टन, स्टैनफोर्ड के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस और फ्रांस के

INSEAD से पीछे है।
सीईआईबीएस एक ऐसे बिजनेस स्कूल के रूप में अपनी पहचान बनाता है जो चीन को उसके अपने तरीके से समझने का माध्यम है। यह चीन में व्यापार के बारे में दुनिया को सिखाने में माहिर है और चीनी सरकार द्वारा नियंत्रित है।
भारतीय नागरिक शमीम प्रशांतम सीईआईबीएस में एसोसिएट डीन और पूर्णकालिक एमबीए कार्यक्रम के निदेशक हैं। चीनी सरकार इसका उपयोग विश्व भर के कॉर्पोरेट क्षेत्र को चीन को उसके अपने नजरिए से समझने के लिए शिक्षित करने के लिए कर रही है।
कार्यक्रम का चीन के अनुभव पर केंद्रित रहना अपरिवर्तित रहा है। वे कहते हैं, 'हमारे पास कुछ ऐच्छिक पाठ्यक्रम हैं और एक विशाल केस सेंटर है जो दुनिया में सबसे अधिक चीनी केस स्टडीज़ तैयार करता है। डिजिटल चीन यहाँ के कई अनूठे ऐच्छिक पाठ्यक्रमों में से एक है। हम चीन आधारित मॉड्यूल (इमर्शन) के पोर्टफोलियो को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस महीने के अंत में छात्रों को एक ऐसे मॉड्यूल पर ले जाऊंगा जो चीनी कंपनियों के वैश्वीकरण का अध्ययन करता है। एक जर्मन सहकर्मी शंघाई में यूरोपीय कंपनियों और चीन में स्थानीय प्रतिस्पर्धा और डिजिटल कंपनियों के उदय से निपटने के उनके तरीकों पर एक ऐच्छिक पाठ्यक्रम चला रहे हैं।'
प्रशांतम ने कहा: 'हमारे कई अंतरराष्ट्रीय पूर्व छात्र चीन में रहते हैं, और हमारे पास उन संबंधों को और मजबूत करने का अवसर है।'
तरुण खन्ना सीईआईबीएस में अतिथि विचारक के रूप में उपस्थित रहे हैं और नीति आयोग में सलाहकार भी हैं। इससे उन्हें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय सरकार के बीच सेतु का काम करने की शक्ति मिलती है।
यह सवाल मन में उठता है कि भारतीय अरबपतियों ने भारत में कुछ ऐसा

क्यों नहीं बनाया जिससे वे दुनिया को व्यापारिक सफलता के प्रमुख पारंपरिक तरीकों को दिखा सकें: जैसे कि समुदायों का मजबूत नेटवर्क, जो भरोसे और मौखिक समझौतों पर आधारित होता है? यह भी आश्चर्य की बात है कि उन्होंने पारंपरिक व्यापारिक पारिवारिक संरचनाओं और पारिवारिक एवं सामुदायिक अवसंरचनाओं के वित्तपोषण के तरीकों (जैसे कि संघों को वित्तपोषण करना, मंदिरों के आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र को वित्तपोषित करना, वृद्धों और युवाओं के लिए धर्मशालाओं और स्कूलों का दान करना) पर अध्ययन क्यों नहीं कराया?

भाग III. क्या भारतीय उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध हैं?

17. भारत की यात्रा के लिए आइवी लीग का मार्ग

भाग 1 में हमने क्रिटिकल रेस थ्योरी और उसके लोकप्रिय रूप, वोकिज़्म (जागरूकता) पर चर्चा की। हमने दिखाया कि किस प्रकार भारतीय संदर्भ में इसे जाति और नस्ल को एक समान मानकर अपनाया जा रहा है। हमने यह भी दिखाया कि कैसे क्रिटिकल रेस थ्योरी अमेरिकी शिक्षाविदों, कंपनियों और सरकारों की नीति-निर्माण में अपनी अभिव्यक्ति पा रही है और इसका आम भारतीय अमेरिकियों पर कितना विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। अमेरिका में जाति तेजी से एक 'संरक्षित श्रेणी' बनती जा रही है, जिससे यह जातिवादी होने के आरोपी भारतीयों के खिलाफ मुकदमेबाजी का एक हथियार बन गई है। यह पहले से ही हिंदू विरोधी ताकतों के लिए एक प्रभावी साधन बन रहा है, जो भारतीय समाज की संरचनाओं को

ध्वस्त करने के अपने एजेंडे को वैधता प्रदान कर रहा है।
इसके गंभीर परिणाम अमेरिका और भारत दोनों के लिए हैं। अमेरिका में, नस्लवाद के खिलाफ मौजूदा कई कानूनों को जाति पर लागू किया जा रहा है, और कुछ स्थानीय सरकारों ने जाति को नस्लवाद का एक रूप मानने का आदेश दे दिया है। यह सिलसिला अब तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। विश्वविद्यालय और स्कूल भारतीय सामाजिक संगठनों और सामाजिक संरचनाओं पर बिना पर्याप्त तर्क या सबूत पेश किए हमला कर रहे हैं। बड़ी संख्या में भारतीयों को नौकरी देने वाली कंपनियां उपद्रवियों को आर्थिक सहायता देकर, उन्हें अपने फैसलों में मार्गदर्शन देने वाले 'विशेषज्ञ' नियुक्त करके, अपने बोर्ड के संविधान में बदलाव करके, भर्ती प्रक्रिया में हिंदुओं के साथ भेदभाव करके और जाति आधारित 'शिक्षा' शुरू करके उनसे समझौता करना चाहती हैं। अन्यथा, उन्हें सिस्को सिस्टम्स के मामले की तरह जातिगत भेदभाव के लिए अदालत में घसीटे जाने का खतरा है।
हिंदू-विरोधी ताकतें विविधता, समानता और समावेशन (DEI) के नाम पर कॉर्पोरेट जगत में प्रवेश कर रही हैं; और इक्वालिटी लैब्स जैसे अत्यधिक वित्तपोषित 'सलाहकार' 'जाति संवेदनशीलता प्रशिक्षण कार्यक्रमों' के माध्यम से इस स्थिति का फायदा उठा रहे हैं।
परिणामस्वरूप, निर्दोष भारतीयों को अपने 'जन्मजात जातिगत पूर्वाग्रह' को स्वीकार करने और जातिगत विशेषाधिकार विरासत में पाने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कार्यस्थल पर खंडन की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि विरोध करने के किसी भी प्रयास को अपराध का प्रमाण माना जाता है। भारतीयों के लिए एकमात्र रास्ता अपने व्यवस्थित जातिगत पूर्वाग्रह और ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को चुपचाप स्वीकार करना है, जो स्पष्ट रूप से भारतीय समाज

में संस्थागत रूप से स्थापित है, ठीक उसी तरह जैसे अमेरिका में नस्ल का मुद्दा है।

इस आंदोलन की खास बात यह है कि यह अलग-अलग समूहों को एकजुट करता है जिनके अपने मतभेद हैं और समान परिणाम प्राप्त करने के लिए उनके मुद्दों को आपस में जोड़ता है। इस प्रक्रिया में, और क्योंकि यह इसके एजेंडे के अनुकूल है, यह योग्यता के मूल विचार को ही चुनौती देता है। भारत की कोटा प्रणाली वंचितों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, लेकिन योग्यता के सिद्धांत को कमजोर किए बिना। इसके परिणामस्वरूप, भारत IIT जैसे उत्कृष्टता के शैक्षणिक केंद्र विकसित करने में सक्षम रहा है, जिन्होंने विश्व स्तरीय नेताओं को जन्म दिया है। हालांकि, यह नया विमर्श भारतीय सफलता के इस स्तंभ को ध्वस्त करने का प्रयास करता है, जिसके भारत के भविष्य पर दूरगामी परिणाम होंगे।

एक दशक से भी पहले 'ब्रेकिंग इंडिया' में वर्णित अफ्रीकी-दलित आंदोलन, भारत पर इस हमले के प्रायोगिक चरण में था। योजना यह थी कि अश्वेतों और दलितों दोनों के लिए एक समान नस्लीय मूल का दावा किया जाए ताकि अश्वेतों की मुक्ति के लिए इस्तेमाल की गई अकादमिक और कार्यकर्ता मशीनरी को दलित अलगाववाद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सके। यह मशीनरी न केवल कहीं अधिक परिष्कृत हो गई है, बल्कि इसने आलोचनात्मक जाति सिद्धांत और अंतर्संबंधता के माध्यम से दलितों को जोड़कर अश्वेत अमेरिकियों को भारत के विरुद्ध कहीं अधिक बड़े पैमाने पर लामबंद करने में भी सफलता प्राप्त की है।

इसके अतिरिक्त, पहले के 'ब्रेकिंग इंडिया' घटनाक्रम (जिसे हम 'ब्रेकिंग इंडिया 1.0' कहते हैं) में, एक ओर तो मार्क्सवादी विचारों द्वारा ग्रामीण गरीबों को निशाना बनाया जा रहा था, और दूसरी ओर ईसाई धर्म प्रचारक तंत्र द्वारा। लेकिन अब, जिसे हम 'ब्रेकिंग इंडिया 2.0' कहते हैं, उसमें

भारत के शहरी अभिजात वर्ग को, जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सरकारी संस्थानों के उच्चतम स्तर पर हैं, भारतीय समाज को भंग करने के लिए निशाना बनाया जा रहा है और उनका इस्तेमाल हथियार के रूप में किया जा रहा है।

ब्रेकिंग इंडिया 1.0 और ब्रेकिंग इंडिया 2.0 के बीच के मूल अंतर को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बाद वाला संस्करण कहीं अधिक खतरनाक है। इसमें प्रचारित किए जा रहे विचार अधिक जटिल हैं; वित्तपोषण कहीं अधिक व्यापक है, जो भारत और विदेश के कुछ सबसे धनी लोगों से आ रहा है; और प्रौद्योगिकी की भूमिका कपटपूर्ण है। यह अब भारतीय समाज को विघटित करने का एक शीर्ष-स्तरीय अभियान है।

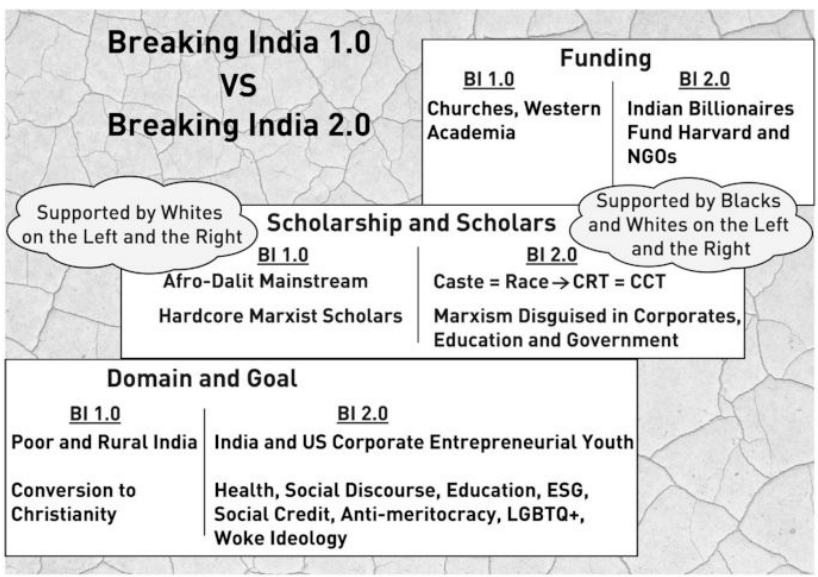

ब्रेकिंग इंडिया 2.0, ब्रेकिंग इंडिया 1.0 का मात्र विस्तार नहीं है। भारत के भीतर और बाहर से कई नए खिलाड़ी इस खेल में शामिल हो गए हैं। इनमें से कुछ विश्वभर के कॉरपोरेट जगत के नेता हैं। विशेष रूप से प्रौद्योगिकी क्षेत्र को शेयर बाजार से भरपूर लाभ मिला है, और कई लोगों

ने अपनी पूंजी निकालकर परोपकार के नाम पर सामाजिक इंजीनियरिंग के लिए अपने विशाल कोष का इस्तेमाल किया है।
परोपकार का यह नया रूप विचारणीय है, और इससे परोपकारियों के लिए और भी अधिक धन और शक्ति उत्पन्न होती है। लेकिन चूंकि इसे एक सौम्य, परोपकारी गतिविधि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए जनता का एक बड़ा हिस्सा (और संभवतः भारत सरकार का भी कुछ हिस्सा!) इसके झांसे में आ रहा है। तकनीक इस योजना को जनता की नजरों से छिपा देती है।
भारत में बड़ी संख्या में कट्टरपंथी कार्यकर्ता तैयार किए जा रहे हैं। 'ब्रेकिंग इंडिया 1.0' में मिशनरियों और मार्क्सवादियों ने भोले-भाले लोगों को अपने विचारों में ढालने के लिए छल और सामाजिक ताने-बाने का सहारा लिया। उन्होंने शुरुआत में विदेशों से धन जुटाने के साधन जुटाए और अत्याचारों से संबंधित कुछ साहित्य भी तैयार किया। लेकिन इसमें नवीनतम एआई-आधारित तकनीकों का उपयोग नहीं किया गया था और न ही यह भारतीय उद्योग जगत और उसके अभिजात वर्ग में पैठ बना पाया था। इसलिए, 'ब्रेकिंग इंडिया 1.0' का पैमाना और दायरा वर्तमान हमले की तुलना में नगण्य था।
भाग 2 में हमने विस्तार से बताया कि कैसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय और उसके लोगों और संस्थानों के विशाल नेटवर्क ने भारतीय समाज के हर पहलू में घुसपैठ कर ली है। भारत को कमजोर करने के इस खेल में कई अन्य विदेशी विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, लेकिन हार्वर्ड वह मुख्य केंद्र है जिसे हमने विश्व गुरु कहा है। यह वह प्रमुख वैश्विक केंद्र है जहां भारत पर क्रिटिकल रेस थ्योरी लागू की जा रही है। हमने इस व्यापक प्रयास के दो प्रकार के परिणाम दिखाए:
भारत में विशिष्ट रूप से प्रचलित सीआरटी-आधारित सिद्धांतों का विकास,

जिनका उपयोग भारत, विशेष रूप से हिंदू धर्म के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अत्याचार साहित्य के रूप में किया जा सकता है।
भारत में इस सामग्री के उपयोग के संबंध में बड़ी संख्या में भारतीय विद्वानों, उद्योगपतियों, तकनीकी उद्यमियों, गैर सरकारी संगठनों के नेताओं और विभिन्न अन्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना।
इसके साथ ही, हमने हार्वर्ड के साथ चीन के गहरे संबंधों और विश्वविद्यालय तथा विभिन्न अमेरिकी थिंक टैंकों के साथ उसके सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के गठबंधनों के जटिल जाल को भी उजागर किया। ये संबंध, हार्वर्ड को मिलने वाले धन प्रवाह के साथ, यह संकेत देते हैं कि इस प्रतिष्ठित संस्थान को चीन ने प्रभावित किया है। भारत के लिए इसके गंभीर परिणाम हैं, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि यह एक असमान आदान-प्रदान है, जिसमें कच्चा डेटा भारत से हार्वर्ड को जाता है, और सामाजिक सिद्धांत, विचारधाराएं और प्रशिक्षित बुद्धिजीवी हार्वर्ड से भारत वापस आते हैं।
अमेरिकी शैक्षणिक संस्थानों की प्रतिष्ठा का लाभ उठाते हुए, कई प्रमुख भारतीय अरबपतियों ने हार्वर्ड में अपने नाम पर केंद्र स्थापित किए हैं। इससे हार्वर्ड और उसके अमेरिकी और चीनी सहयोगियों को सरकारी नीति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, डिजिटल अवसंरचना, उच्च शिक्षा, मीडिया और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत तक पहुंच के पुल बनाने में मदद मिली है।
दूसरे शब्दों में कहें तो, विदेशी शैक्षणिक संस्थान, जिनमें हार्वर्ड प्रमुख है, भारतीय डेटा, भारतीय सरकारी संगठनों, सर्वश्रेष्ठ भारतीय बुद्धिजीवियों और यहां तक कि भारतीय जनता से धन जुटाने का काम कर रहे हैं। ये विदेशी संस्थान भारतीय इतिहास, संस्कृति और सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित अभिलेखागार बनाते और उनका स्वामित्व रखते हैं; भारतीय

साहित्य के अनुवादित ग्रंथों के पुस्तकालय स्थापित करते हैं; कुंभ मेले जैसी बड़े पैमाने की घटनाओं पर डेटा एकत्र करते हैं जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरा पैदा कर सकती हैं; और प्रतिभाशाली युवा भारतीयों को कार्यकर्ता बनने के लिए प्रशिक्षित करने में इनका उपयोग किया जाता है।

हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि इनमें से कोई भी कार्य गैरकानूनी नहीं है। यह अनैतिक है या भारत के राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध है, यह भी व्यक्तिपरक है और व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। भारत, अमेरिका और अन्य जगहों पर ऐसे कई वर्ग हैं जो इन परिवर्तनों का समर्थन करते हैं, क्योंकि वे इन्हें सामाजिक न्याय आंदोलन की प्रगति का मार्ग मानते हैं। वहीं दूसरी ओर, कुछ अन्य लोग पुरानी संरचनाओं के विघटन से उत्पन्न शून्य को लेकर चिंतित हैं। इस पुस्तक में हमारा उद्देश्य निष्पक्ष और तटस्थ रूप से उन उदाहरणों को उजागर करना है जो इस परिवर्तन की ओर इशारा करते हैं। इसके निहितार्थों की व्याख्या अपने स्वयं के मूल्यों के आधार पर करना पाठक का कार्य है।

भारतीय और पश्चिमी व्यापारिक नेता हार्वर्ड द्वारा विकसित नवीनतम कॉर्पोरेट सोशल क्रेडिट प्रणाली (यानी, कंपनियों की रेटिंग के लिए ESG प्रणाली) को अपना रहे हैं, जो पश्चिमी विचारों पर आधारित है। इसके अलावा, उनमें से कुछ भारत में बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह में भी सहयोग कर रहे हैं। जनसंख्या, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अन्य संवेदनशील जानकारियों से संबंधित विशाल डेटा तक पहुँचने के लिए उनके पास कई भारतीय नेटवर्क हैं। वे डिजिटल परिवर्तन के लिए बड़े पैमाने पर पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिससे उन्हें सामाजिक इंजीनियरिंग की रणनीतियों पर प्रयोग करने का अवसर मिलता है। सार्वजनिक और निजी गैर-सरकारी संगठनों के ये गठबंधन अल्पावधि में भारत में आम आदमी के उत्थान में

सहायक प्रतीत होते हैं। लेकिन उनका विशाल तंत्र उन्हें लोगों की स्वायत्तता छीनने और उनकी सहमति में हेरफेर करने की भी अनुमति देता है। इस प्रक्रिया में, भारत की संपत्ति के बाहर जाने का खतरा मंडरा रहा है, जिससे धन और शक्ति का अभूतपूर्व केंद्रीकरण उन कुछ लोगों के हाथों में होने की संभावना है जिनके अपने निजी हित हैं।

भारत को तबाह करने की मुहिम एक शक्तिशाली तंत्र है जिसने भारतीय समाज की जड़ों तक पैठ बना ली है। भारत के कई विश्वविद्यालय (सरकारी और निजी दोनों), मीडिया संस्थान, कॉर्पोरेट घराने, तकनीकी स्टार्टअप और अन्य कई संस्थाएं इसकी चपेट में आ चुकी हैं। यह सवाल उठता है कि क्या भारत सरकार भी अपनी सभी समस्याओं के समाधान के लिए हार्वर्ड को विश्व गुरु मानकर चल रही है? उदाहरण के लिए, भारतीय सरकार अपने नौकरशाहों को हार्वर्ड और अन्य प्रतिष्ठित विदेशी संस्थानों में प्रशिक्षित करती है। कई शीर्ष भारतीय बुद्धिजीवियों के पश्चिमी अभिजात वर्ग से संबंधों को लेकर पर्याप्त चिंता नहीं दिखाई जा रही है। भारत को तबाह करने की मुहिम 1.0 का दायरा, जनसांख्यिकी, इसमें शामिल लोग और संसाधन सीमित थे। लेकिन भारत को तबाह करने की मुहिम 2.0 हमारी आने वाली पीढ़ियों, हमारे रीति-रिवाजों, हमारे इतिहास, हमारी विरासत और हमारे जीवन शैली का व्यापक विश्वासघात है।

नीचे दी गई तालिका ब्रेकिंग इंडिया 1.0 और ब्रेकिंग इंडिया 2.0 के बीच प्रमुख अंतरों का सारांश प्रस्तुत करती है।

	Feature	Breaking India 1.0	Breaking India 2.0
1	Funding	Marxists NGOs, Missionaries/Churches	Billionaires: Indians and foreign
2	Narrative	Afro-Dalit, Postmodernism Supported by • Left: White Liberal Americans • Right: White evangelical Americans	• Critical Race Theory ➔ Critical Caste Theory • Hindutva = White supremacy • Dalits + Black Americans ➔ Afro-Dalit Movement • Anti-meritocracy in academics and employment • LBGTQ+/Gender as victim categories • Corporate ESG, Social Credit Supported by: • Left: White and Black Liberal Americans • Right: White and Black evangelical Americans
3	Focus areas	• Religion, poverty	• Religion • Public health: big data on public health, children's health, nutrition • Cultural/Heritage: Kumbh Mela, religion and economics, archives on lived experience of victims • Digital infrastructure: digital ID, currency, Internet access, digital projects for public works • Education: NCERT – elementary through secondary • Education: public and private universities, research, training students and scholars • Corporates: frameworks for assessment, metrics using ESG • Administration: government policymaking
4	Target Demographic	Rural India, Poor, Dalits, Tribals: • Religious conversion • Atrocity literature • Cultural appropriation	• Urban middle class Hindu youth become Woke • Young entrepreneurs in corporates: incentivized by venture capital • Corporates pushing ESG: punishing businesses for non-compliance; Diversity, Equity, Inclusion • Media pushing Woke narrative: promoting gender fluidity and Woke activism • Universities: using academic talent to shape Woke-friendly government policy, grooming sepoys • Government: installing infrastructure for social credit system, shaping policy on philanthropy, skill development and public infrastructure. Big data at risk, foreign control of culture/history archives • Bureaucrats: trained by West resulting in deep colonization • In US: caste as a protected category like race in universities, US government and corporations
5	Infrastructure	• Bibles in native languages • Funding pipelines for missionaries • Media/TV channels acquisition • Instituting tithing • Local seminary training	• Infrastructure for archives: real-time updated archives • Infrastructure for big data: collection and monitoring systems • Digital infrastructure • Infrastructure for public health monitoring and data collection • Infrastructure alliances with global organizations like WEF, UN, WHO & NGOs • Infrastructure for scholarship: university conferences on Woke topics, preparation of students/scholars
6	Vulnerability	• India's discourse	• National security risks • Youth: social engineering • Indian way of life, religion, heritage, culture

इस तीसरे भाग में, हम चर्चा करेंगे कि पहले जिस आंदोलन की बात की गई थी, वह किस प्रकार भारत में प्रवेश कर रहा है। हाल के वर्षों में संगठनों का एक विशाल नेटवर्क उभरा है। चूंकि इस पुस्तक से पहले किसी ने भी इस घटनाक्रम का व्यवस्थित अध्ययन नहीं किया है और इसे समझने के लिए कोई ढांचा विकसित नहीं किया है, इसलिए भारतीयों में

इस विकास के बारे में अंतर्दृष्टि का अभाव है। हमारा मुख्य उद्देश्य राजनीतिक विचारधाराओं के व्यापक दायरे में स्वस्थ बहसों को प्रोत्साहित करना है ताकि अधिक जानकारी प्राप्त हो सके और उस पर खुलकर चर्चा की जा सके।

हम उन भारतीय संस्थानों पर नज़र डालेंगे जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय, एमआईटी, येल विश्वविद्यालय और संबद्ध संगठनों के साथ मिलकर अग्रिम पंक्ति में काम कर रहे हैं। भारत के भीतर घरेलू रूप से स्थापित ये ताकतें एक नए प्रकार की सिपाही सेना का निर्माण कर रही हैं। 'ब्रेकिंग इंडिया 2.0' का संचालन भारत के अभिजात वर्ग द्वारा किया जा रहा है, ठीक उसी तरह जैसे भारतीय राजाओं और जमींदारों ने स्थानीय अभिजात वर्ग का दर्जा पाने के बदले अंग्रेजों के लिए काम किया था। कुछ व्यवसायी, सरकारी अधिकारी, शिक्षाविद, मीडियाकर्मी, कार्यकर्ता आदि और शिक्षित युवा वर्ग को सभ्यतागत विरासत को नष्ट करने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

हम सबसे पहले आंध्र प्रदेश स्थित क्रिया विश्वविद्यालय और एमआईटी के जे-पाल (सऊदी अरब द्वारा वित्त पोषित परियोजना) तथा येल विश्वविद्यालय के साथ इसके संबंधों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद अशोका विश्वविद्यालय का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। इससे भारतीय शिक्षा जगत की दिशा स्पष्ट रूप से सामने आएगी। क्रिया और अशोका विश्वविद्यालय स्वयं को 'भारत का हार्वर्ड' बताते हुए गर्व से कहते हैं कि वे अमेरिकी उदार कलाओं को भारत में ला रहे हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में, हार्वर्ड की तरह, वे अनजाने में भारत की कई परंपराओं को नष्ट कर रहे हैं।

अशोका और क्रेया दोनों के बोर्ड में भारत और विदेशों के विश्व स्तरीय विद्वानों का एक समूह शामिल है, जिनके आइवी लीग विश्वविद्यालयों से गहरे संबंध हैं। वे भारत के भीतर और बाहर बुनियादी ढांचा तैयार कर रहे

हैं, और उनके द्वारा बनाई जा रही निर्बाध पाइपलाइन का उपयोग युवा भारतीय छात्रों के दिमाग में विचारों का हेरफेर करने और बड़े पैमाने पर डेटा निकालने के लिए किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य तथ्य प्रस्तुत करना है, निर्णय देना नहीं। निष्कर्ष निकालना और गहराई से जांच करना पाठक का काम है। सरकार कुछ विदेशी प्रोफेसरों को सलाहकार के रूप में नियुक्त करती है और भारतीय उद्योग, थिंक टैंक और अनुसंधान संगठनों में उनके सहयोग को बढ़ावा देती है। मीडिया को भी एक ऐसे गठबंधन द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है जो प्रतिभागियों की प्रत्यक्ष भागीदारी को कम करता है।

उदाहरण के तौर पर, सिलिकॉन वैली के एक अरबपति द्वारा संचालित ओमिडयार फाउंडेशन, निजी और सार्वजनिक गठबंधनों के माध्यम से भारत में एक बड़ा खिलाड़ी बन गया है। इसी प्रकार, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे अन्य गैर-सरकारी संगठन, जिन्हें हार्वर्ड का समर्थन प्राप्त है, भी भारतीय सरकार के साथ साझेदारी कर रहे हैं। वे अशोका और अन्य विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी नीतियां उनकी विचारधाराओं के अनुकूल हों। भारतीयों को पश्चिमी वर्चस्व का समर्थन करने वाले विभिन्न सिद्धांतों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जबकि पश्चिम भारतीय विशाल डेटा तक पहुंच बना रहा है और भारत पर अभिलेखागार तैयार कर रहा है।

18. सऊदी अरब, अमेरिका और भारत के अरबपतियों का गठजोड़

अवलोकन

मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी परंपरागत रूप से प्रौद्योगिकी का स्रोत रहा है, लेकिन अब यह अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप और 'गरीबी उन्मूलन' के लिए भारत में तेजी से साझेदारी बना रहा है। एमआईटी के नोम चोम्स्की, जो संभवतः जीवित सबसे प्रभावशाली अमेरिकी बुद्धिजीवियों में से एक हैं, ने अपने संस्थान के हिंदू-विरोधी रवैये को संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त किया:

पश्चिमी देशों में इस्लामोफोबिया की समस्या बढ़ती जा रही है। भारत में यह अपने सबसे घातक रूप में सामने आ रही है, जहां मोदी सरकार भारतीय धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर रही है और देश को एक हिंदू जातीय शासन में बदल रही है, जिसके चलते लगभग 25 करोड़ मुसलमान उत्पीड़ित अल्पसंख्यक बन गए हैं। यह हमला अन्य रूपों में भी सामने आ रहा है, जिसमें स्वतंत्र विचार और शिक्षा प्रणाली पर व्यापक हमले शामिल हैं, जो मुख्य रूप से मुस्लिम पीड़ितों को निशाना बनाते हैं, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। यह कश्मीर में भारत के भयानक अपराधों से अलग है। इन अपराधों का एक लंबा इतिहास है। मोदी की दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी सरकार ने इन्हें और भी बढ़ा दिया है। कश्मीर अब क्रूर सैन्य नियंत्रण में एक क्रूरतापूर्वक कब्जे वाला क्षेत्र है, जो कुछ मायनों में कब्जे वाले फिलिस्तीन जैसा है।

इसके बाद, चोम्स्की ने अमेरिकी सरकार पर भारत को 'नव-फासीवादी' कहने के लिए उसका समर्थन करने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला।

... संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय सरकार का भरपूर समर्थन करता है। भारत में नव-फासीवादी सरकार है। मोदी सरकार भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने, भारत को नस्लवादी, हिंदू भ्रष्ट शासन में बदलने, मुसलमानों

पर हमला करने, कश्मीर पर कब्जा करने, कश्मीर को कुचलने के लिए जी-तोड़ मेहनत कर रही है – लेकिन इस बारे में कोई कुछ नहीं कहता। संयुक्त राज्य अमेरिका इन सबका समर्थन करता है। वह बेहद समर्थक है। वह एक करीबी सहयोगी है, इज़राइल का करीबी सहयोगी – दूसरे शब्दों में, हमारे जैसा ही आदमी।

मानवाधिकारों पर पाखंड

अपने पड़ोसी हार्वर्ड की तरह, एमआईटी भी विदेशी संस्थाओं के प्रभाव में आ रहा है, जिससे अमेरिकी सरकार चिंतित है। इसके सऊदी शाही परिवार के साथ गहरे संबंध हैं, जो उदारतापूर्वक कई शोध परियोजनाओं को वित्त पोषित करता है और संस्थान में सऊदी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

2018 की अपनी यात्रा के दौरान, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एमआईटी को तेईस मिलियन डॉलर का दान दिया। कुछ महीनों बाद, वाशिंगटन पोस्ट के लिए काम करने वाले सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की इस्तांबुल स्थित सऊदी दूतावास में बेरहमी से हत्या कर दी गई और उनके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए गए। एमआईटी में क्राउन प्रिंस के दल के एक सदस्य (जिनकी यात्रा के दौरान प्रिंस के साथ तस्वीर ली गई थी) का खशोगी की क्रूर हत्या के मुख्य दोषियों में से एक के रूप में सीधा संबंध पाया गया और उनकी पहचान की गई। इस घोटाले के परिणामस्वरूप, एमआईटी को क्राउन प्रिंस से प्राप्त धन को लेकर भारी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अमेरिकी सरकार के सूत्रों के अनुसार, खशोगी की हत्या का व्यक्तिगत रूप से आदेश दिया था। अमेरिका में आलोचकों ने अमेरिकी संस्थानों में सऊदी फंडिंग और प्रभाव पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। हालांकि कई लोगों ने विरोध

किया, एमआईटी की एक रिपोर्ट में सऊदी अरब से संबंध तोड़ने का कोई ठोस कारण नहीं पाया गया।
अमेरिकी विश्वविद्यालयों के दोहरे मापदंड का यही स्वरूप है: एक ओर वे भारत को फासीवादी देश बताकर निंदा करते हैं, वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब के वास्तविक युवराज के लिए लाल कालीन बिछाते हैं, जिनका मानवाधिकारों के मामले में बेहद खराब रिकॉर्ड है, जिसमें यमन में नागरिकों पर बमबारी और घरेलू असहमति को पूरी तरह कुचलना शामिल है। न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में नाम न छापने की शर्त पर एक सऊदी छात्र ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की स्थिति वास्तव में और खराब हो गई है। [6]
मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जेफरी एपस्टीन के साथ भी घनिष्ठ संबंध थे, जो अमीर और मशहूर हस्तियों को यौन सुख के लिए युवा लड़कियों की आपूर्ति करने वाले एक बाल यौन शोषण गिरोह का संचालन करता था। एपस्टीन के इतिहास से पूरी तरह अवगत होने के बावजूद, एमआईटी ने कम से कम 9 बार उसकी मेजबानी की और उससे 850,000 डॉलर का दान स्वीकार किया।
फिर भी, एमआईटी की हिंदू विरोधी मशीनरी भारतीय प्रतिष्ठान पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ती, भले ही इसके पीछे बहुत ही हल्के कारण क्यों न हों।

सऊदी अरब द्वारा अमेरिकी संस्थानों को दी जाने वाली धनराशि
चीन की तरह ही, सऊदी अरब कम से कम बासठ अमेरिकी संस्थानों को वित्त पोषित करता है, या तो सऊदी राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों जैसे अरामको के माध्यम से, क्राउन प्रिंस के व्यक्तिगत परोपकारी ट्रस्टों के माध्यम से, या मोहम्मद अब्दुल लतीफ जमील जैसे प्रभावशाली सऊदी

व्यापारियों के माध्यम से, जो एमआईटी में पॉवर्टी एक्शन लैब को वित्त पोषित करते हैं, जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया:

इससे पता चलता है कि सऊदी अरब का पैसा सभी प्रकार के अमेरिकी स्कूलों में जाता है: एमआईटी के प्रतिष्ठित समकक्ष, जिनमें हार्वर्ड, येल, नॉर्थवेस्टर्न, स्टैनफोर्ड और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शामिल हैं; मिशिगन और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले जैसे प्रमुख सार्वजनिक विश्वविद्यालय; टेक्सास ए एंड एम जैसे तेल उत्पादक क्षेत्रों के संस्थान; और ईस्टर्न वाशिंगटन यूनिवर्सिटी और बॉल स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे राज्य स्तरीय स्कूल।

2012 और 2018 के बीच, सऊदी सरकार ने अमेरिकी विश्वविद्यालयों को 650 मिलियन डॉलर का दान दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि कैसे अमेरिकी क्राउन प्रिंस की एक सेलिब्रिटी की तरह मेजबानी करते हैं और ऐसे संबंधों के माध्यम से सऊदी छवि के सफल पुनर्निर्माण की व्याख्या की। असल में, यह सऊदी की सॉफ्ट पावर का निर्माण कर रहा है।

इन संबंधों से सऊदी अरब को होने वाले लाभ स्पष्ट हैं। अपनी अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के प्रयासों में, जिसे राजकुमार मोहम्मद ने विज़न 2030 नाम दिया है, सऊदी अरब को अमेरिका के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों के बुद्धिजीवियों तक पहुंच प्राप्त होती है। एमआईटी जैसे संस्थानों में प्रवेश से सऊदी अरब की छवि में कुछ सुधार होता है। सऊदी अरब एक निरंकुश राजशाही है, जो महिलाओं और एलजीबीटीक्यू अधिकारों के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखता है और जहां स्वतंत्र प्रेस या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, लेकिन देश की सीमाओं से परे इसके संबंध इसे लगभग एक मानद पश्चिमी राष्ट्र जैसा

बना देते हैं। अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ सऊदी अरब के संबंधों को ब्रांडिंग के रूप में भी देखा जा सकता है; हाल ही में प्रमुख खेल आयोजनों को प्रायोजित करने के उसके कदम भी इसी उद्देश्य को पूरा करते हैं। पूर्व राजदूत जॉर्डन कहते हैं, "यह 'सॉफ्ट पावर' फैलाने का एक तरीका है, ठीक उसी तरह जैसे अमेरिका वर्षों से दुनिया भर में करता आ रहा है।"
... प्रिंस मोहम्मद ने अपना पूरा दिन उस दो मील लंबे गलियारे में बिताया, जिसे अमेरिका का सबसे पवित्र शैक्षणिक स्थल माना जाता है। एमआईटी में सुबह बिताने के बाद, वे अपने काफिले से हार्वर्ड के लिए रवाना हुए, जहाँ उन्होंने एक फैकल्टी राउंड टेबल में भाग लिया, जिसके बाद स्थानीय कॉलेज अध्यक्षों के साथ एक स्वागत समारोह हुआ। किसी ने भी उनसे यमन या किसी अन्य विषय के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा।

मोहम्मद अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब, एमआईटी
भारतीय अरबपतियों के विपरीत, जो हार्वर्ड में ऐसे कार्यों को प्रायोजित करते प्रतीत होते हैं जो उनके अपने देश को कमजोर करते हैं, सऊदी अरब के उद्योगपति अधिक रणनीतिक और देशभक्तिपूर्ण तरीके से धन देते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण एमआईटी में अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब (जे-पाल) को सऊदी अरब द्वारा दिया गया धन है। एमआईटी के पूर्व छात्र मोहम्मद अब्दुल लतीफ जमील ने इसका नाम अपने पिता अब्दुल लतीफ जमील के नाम पर रखा है। पॉवर्टी एक्शन लैब नाम से ही स्पष्ट है कि यह एक परोपकारी संस्था है जो महिलाओं और अल्पसंख्यकों की दुर्दशा को उजागर करती है और कई देशों, विशेष रूप से भारत में लोकतंत्र की कमी को सामने लाती है।
विडंबना यह है कि जे-पाल सऊदी अरब में सामाजिक मुद्दों या लोकतंत्र की कमी पर शोध नहीं करता है। सऊदी अरब के प्रमुख निवेशक होने के

कारण, जे-पाल को विभिन्न स्रोतों से दान भी मिलता है। इनमें से कुछ धनराशि भारत के आंतरिक मामलों से संबंधित परियोजनाओं पर खर्च की जाती है। जे-पाल को वित्तपोषित करके, सऊदी अरब अमेरिकी वामपंथी बुद्धिजीवी हलकों से मित्रता स्थापित करता है और खुद को विश्व स्तर पर दबे-कुचले लोगों के मसीहा के रूप में पेश करता है। यह एक चालाकी भरा तरीका है, मानो वामपंथी निगरानी संस्थाओं को खरीद लिया गया हो ताकि वे सऊदी अरब में व्याप्त सामाजिक मुद्दों पर ध्यान न दें।
पॉवर्टी एक्शन लैब को सऊदी अरब के सबसे प्रभावशाली व्यवसायी मोहम्मद अब्दुल लतीफ जमील से कम से कम 73 मिलियन डॉलर प्राप्त हुए हैं, जिनके बारे में एमआईटी का दावा है कि वे 'दुनिया भर में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एमआईटी में अनुसंधान पहलों के समर्पित समर्थक' हैं। जमील ने 2005 में जे-पाल (J-PAL) निधि की शुरुआत की, जिसके बाद 2009 में इसके काम को व्यापक रूप से विस्तारित करने के लिए एक और महत्वपूर्ण योगदान दिया। आलोचकों ने बताया है कि जमील और क्राउन प्रिंस दोनों ही सऊदी अरब के उस घनिष्ठ कुलीनतंत्र का हिस्सा हैं जो देश का संचालन करता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख में बताया गया है कि 'यह विशाल तेल कंपनी ही यमन में युद्ध, असंतुषों की गिरफ्तारी और राज्य में होने वाली हर चीज को वित्त पोषित करती है', और यह बात सामने रखी गई है कि 'वे सभी शासन का हिस्सा हैं, सरकार का हिस्सा हैं'।
ओमिडयार नेटवर्क (अध्याय 22 का मुख्य विषय) और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, अन्य संस्थाओं के साथ, जे-पाल को वित्त पोषित करते हैं। इसे औपचारिक रूप से एमआईटी के अर्थशास्त्र विभाग में एक अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता पति-पत्नी अर्थशास्त्री, अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो, इसके

संस्थापक सदस्यों में से हैं, जिससे इसे काफी प्रभाव प्राप्त होता है। जे-पाल के कार्यकारी निदेशक इकबाल सिंह धालीवाल हैं, जो गीता गोपीनाथ के पति हैं। गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मुख्य अर्थशास्त्री थीं और बाद में उन्हें प्रथम उप प्रबंध निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया। ये दोनों प्रभावशाली अभिजात वर्ग के लोग हैं जो विश्व सत्ता के शीर्ष हलकों में सक्रिय हैं। धालीवाल और डुफ्लो जे-पाल के दक्षिण एशिया कार्यालय के सह-वैज्ञानिक निदेशक हैं, जहां से उन्होंने भारत में प्रवेश किया है।
भारत का क्रेया विश्वविद्यालय उनका लॉन्चपैड है, क्योंकि इसकी आकांक्षा भारत का एमआईटी बनने की है (इंजीनियरिंग क्षेत्र को छोड़कर)। मानवाधिकारों को सामने लाने के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र का उपयोग करना एक दिलचस्प दृष्टिकोण है।

भारतीय सहयोगी
मामला और भी पेचीदा हो जाता है क्योंकि इसमें कई और पक्ष शामिल हैं। पॉवर्टी एक्शन लैब का दक्षिण एशिया कार्यालय इंस्टीट्यूट फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसर्च (आईएफएमआर) द्वारा संचालित है, जो कि क्रेया विश्वविद्यालय की मूल संस्था है। आईएफएमआर की प्रमुख शोभिनी मुखर्जी हैं, जो केयर इंडिया के निदेशक मंडल में भी हैं। केयर इंडिया एक गैर-सरकारी संगठन है जिसे यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार, केयर इंडिया केरल में ईसाई मिशनरियों को वित्त पोषित करता है।
पॉवर्टी एक्शन लैब संयुक्त रूप से अंतर-क्षेत्रीय सतत विकास लक्ष्यों (एक्सएसडीजी) सम्मेलन की मेजबानी करता है। इसका संचालन

वाशिंगटन डी.सी. स्थित डालबर्ग एडवाइजर्स और उनके भारतीय गैर-सरकारी संगठन, बिलॉन्ग रिसर्च कलेक्टिव के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अध्याय 1 में वर्णित अंतर-क्षेत्रीयता के परिप्रेक्ष्य का उपयोग करते हुए, बिलॉन्ग पहचान के आधार पर भेदभाव से संबंधित भारतीय डेटा का संग्रहण करता है। यह अभी प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन इसका दायरा व्यापक है और इसके पास पर्याप्त संसाधन हैं। बिलॉन्ग का लक्ष्य भारत में विविधता से संबंधित सभी मुद्दों का विशेषज्ञ बनना है। यह 'विशेषज्ञों' का एक डेटाबेस तैयार कर रहा है, जिन्हें कॉर्पोरेट कंपनियां भेदभाव पर प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए नियुक्त कर सकती हैं, जैसा कि अमेरिका में इक्वालिटी लैब्स बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए कर रहा है। यह विज्ञापन देता है कि यह 'ऐसे विशेषज्ञ प्रदान करता है जिन्हें आप विकास तक पहुंच के संदर्भ में धर्म-आधारित भेदभाव को समझने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं'।

इसके प्रयासों में चुनिंदा विषयों पर शोध पत्र जुटाना, एक साहित्यिक उत्सव आयोजित करना और पहचान की राजनीति पर आधारित पुस्तकालय बनाना शामिल है, जिसमें अल्पसंख्यकों के वीडियो साक्षात्कार भी शामिल हैं ताकि उनकी शिकायतों को उजागर किया जा सके। हालांकि इसके कई उद्देश्य सराहनीय प्रतीत होते हैं, लेकिन बेलॉन्ग के अंतर्संबंध सिद्धांत के दृष्टिकोण से कई पहलों का वर्णन असंतुलित हो जाता है। उदाहरण के लिए:

इसमें मुसलमानों और इस्लाम के बारे में फैली रूढ़ियों को दूर करने के लिए कई 'भ्रम तोड़ने वाले' वीडियो हैं। हालांकि, स्कूलों और कार्यस्थलों में मौजूद हिंदू-विरोधी भावना को उजागर करने के लिए ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि यह संगठन समावेशी शिक्षा की आड़ में भारतीय

स्कूलों में बच्चों के 'यौन शोषण' के लिए अमेरिकी वामपंथियों द्वारा अपनाए गए तरीकों को बढ़ावा दे रहा है। भारतीय स्कूलों में LGBTQ+ मुद्दों पर इसके प्रचार-प्रसार और प्रशिक्षण कार्यक्रम लोगों को पीड़ित महसूस कराने के उद्देश्य से चलाए जा रहे हैं। भारतीय सरकारी अधिकारी भी Belongg के 'समावेशी' शिक्षा सेमिनारों में भाग लेते हैं।

बेलॉन्ग का साहित्यिक उत्सव पेरुमल मुरुगन जैसे हिंदू विरोधी लेखकों की आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास करता है, जिनके विचारों का कोई प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं किया गया है।

बेलॉन्ग शोध पत्रों को आमंत्रित करता है और अंतर-क्षेत्रीयता और भेदभाव के परिप्रेक्ष्य से भारतीय जीवन का विश्लेषण करने वाले शोध कार्यों के लिए भारी अनुदान प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, एक शोध पत्र को इस बात का आकलन करने के लिए वित्त पोषित किया गया था कि 'जाति, वर्ग और लिंग आधारित बहिष्कार को दूर करके' घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के उपयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसके शोध में कहा गया है कि सरकार की एलपीजी योजना 'अपने दृष्टिकोण में लिंग-परिवर्तनकारी नहीं है'। एक अन्य शोध अध्ययन में पाया गया है कि दिल्ली में मकान मालिक दलितों और मुसलमानों के प्रति पूर्वाग्रही हैं। जे-पाल के साथ संयुक्त रूप से आयोजित एक्सएसडीजी सम्मेलन में बेलॉन्ग की भागीदारी का एक विशिष्ट लक्ष्य है: 'बेलॉन्ग का मानना है कि लिंग, जाति, विकलांगता, धर्म आदि से जुड़ी अंतर-क्षेत्रीय सोच को समग्र एसडीजी दृष्टिकोण में और अधिक गहराई से एकीकृत करने की आवश्यकता है'।

xSDG वेबसाइट पर इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट (IXR) नामक एक रिपोर्ट का संदर्भ दिया गया है। यह रिपोर्ट जनवरी 2021 और उससे पहले के वर्षों में सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज (CES) नामक एक प्रमुख

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के संगठन द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसका नेतृत्व लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को टाटा ट्रस्ट से वित्तीय सहायता और समर्थन प्राप्त हुआ। अमेरिका से, ब्राउन विश्वविद्यालय के वाटसन इंस्टीट्यूट के प्रमुख आशुतोष वार्ष्णेय ने भी इसका समर्थन किया। सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा सालाना (लगभग दो से तीन करोड़ रुपये) का अनुदान प्राप्त होता है, इसके अलावा अन्य विदेशी अनुदान स्रोत भी हैं। मंदर अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में अक्सर वक्ता के रूप में शामिल होते हैं। कानूनी अधिकार निगरानी समूह, लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी के अनुसार, सीईएस को फ्रांसीसी और डेनिश ईसाई मिशनरी संगठनों से भी करोड़ों रुपये प्राप्त होते हैं। भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान सीईएस को दान देने वाले अन्य दानदाताओं में एक्शन फॉर होप (एक प्रमुख अखिल-अरब सांस्कृतिक संगठन), अमेरिका स्थित इंडियन मुस्लिम्स रिलीफ एंड चैरिटी और ब्रिटेन स्थित माइनॉरिटी राइट्स शामिल हैं।

हर्ष मंदर को जॉर्ज सोरोस जैसे भारत को तबाह करने वाले दिग्गजों का समर्थन भी प्राप्त है, जिन्होंने उन्हें 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। सोरोस द्वारा वित्त पोषित ओस्लो शांति अनुसंधान संस्थान, जो पुरस्कार के लिए नामांकन करता है, ने निम्नलिखित घोषणा की:

नरेंद्र मोदी के हिंदू राष्ट्रवादी प्रशासन के तहत, भारत में मुसलमानों की स्थिति लगातार कठिन होती जा रही है, और देश में धार्मिक हिंसा की कई घटनाएं देखने को मिली हैं। इस हिंसा के जवाब में, लेखक, कार्यकर्ता और नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज के निदेशक हर्ष मंदर ने कारवां-ए-मोहब्बत नामक अभियान शुरू किया है, जो घृणा अपराधों के

पीड़ितों के प्रति समर्थन और एकजुटता दर्शाता है।
दरअसल, मंदर सोरोस के शिष्यों में से एक हैं, जिन्हें सोरोस ने लंबे समय तक प्रशिक्षित किया है। वे वर्तमान में जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से संबंधित मानवाधिकार पहल के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इस संबंध के महत्व को बेहतर ढंग से समझने के लिए, आइए संक्षेप में देखें कि सोरोस कौन हैं।
जॉर्ज सोरोस एक हंगेरियन-अमेरिकी हैं जो राष्ट्रवादियों और रूढ़िवादी सरकारों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिन्हें वे सत्तावादी मानते हैं। भारत में उनके प्रमुख संगठन ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के तहत, उन्होंने अध्ययन और अनुसंधान के लिए छात्रवृत्ति और फैलोशिप प्रदान करके शुरुआत की, लेकिन तेजी से पूरे भारत में पत्रकारों और मीडिया संस्थानों का एक विशाल नेटवर्क बनाया जो भारत विरोधी हैं।
दावोस 2020 में आयोजित विश्व आर्थिक मंच पर सोरोस ने कहा:
राष्ट्रवाद को पलटने के बजाय, और अधिक बढ़ावा मिला। सबसे बड़ा और सबसे भयावह झटका भारत में लगा, जहाँ लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नरेंद्र मोदी एक हिंदू राष्ट्रवादी राज्य का निर्माण कर रहे हैं, कश्मीर (एक अर्ध-स्वायत्त मुस्लिम क्षेत्र) पर दंडात्मक उपाय लागू कर रहे हैं, और लाखों मुसलमानों को उनकी नागरिकता से वंचित करने की धमकी दे रहे हैं।
अपने भाषण में उन्होंने राष्ट्रवाद के प्रसार, विशेष रूप से भारत में, से निपटने के लिए एक नए विश्वविद्यालय नेटवर्क को वित्त पोषित करने के लिए एक अरब डॉलर देने का वादा किया।
दिल्ली में किसानों के दंगों के दौरान, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जस्टिस फॉर माइग्रेंट वुमेन द्वारा प्रायोजित और 76 संगठनों द्वारा हस्ताक्षरित एक पूर्ण पृष्ठ का विज्ञापन प्रकाशित किया, जिसमें खुद को चिंतित किसान,

कार्यकर्ता और विश्व नागरिक बताया गया था। शीर्षक था: 'हम - किसान, कार्यकर्ता और विश्व नागरिक - भारत में अपनी आजीविका की रक्षा के लिए विरोध कर रहे किसानों के साथ एकजुटता से खड़े हैं।' समर्थकों के रूप में सूचीबद्ध किसानों, कार्यकर्ताओं और नागरिकों में काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस (सीएआईआर) भी शामिल था, जो पूरे अमेरिका में बिलबोर्ड लगाकर कश्मीर के अलगाववादियों का समर्थन कर रहा है। यह अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के भारतीय सरकार के फैसले की आलोचना करता है और मुसलमानों के खिलाफ अत्याचारों के लिए भारतीय सेना को दोषी ठहराता है। सोरोस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन सीएआईआर के लिए एक प्रमुख निधि स्रोत है।
सोरोस के ओपन सोसाइटी फ़ाउंडेशन्स द्वारा शामिल किए गए एक अन्य व्यक्ति अमरदीप सिंह हैं, जो अमेरिका स्थित गैर सरकारी संगठन सिख कोएलिशन के सह-संस्थापक हैं। उन्हें राष्ट्रपति ओबामा द्वारा एशियाई अमेरिकियों और प्रशांत द्वीपवासियों (एएपीआई) पर अपने सलाहकार आयोग में नियुक्त किया गया था। 2014 से, वे ओपन सोसाइटी फ़ाउंडेशन्स में वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। सिख कोएलिशन की वेबसाइट ने दंगाइयों का समर्थन करते हुए कहा: 'इस कार्रवाई में आंसू गैस, पानी की बौछारें, लाठीचार्ज, इंटरनेट और संसाधनों को बंद करना, पत्रकारों पर सेंसरशिप, कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और हिरासत, और सरकारी नेताओं और राज्य-समर्थित मीडिया द्वारा प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी के रूप में चित्रित करने के समन्वित प्रयास शामिल थे।' इसमें आगे कहा गया कि
सिख गठबंधन ने इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने और कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रयास किए, जिनमें निर्वाचित और नियुक्त नीति निर्माताओं से सीधे संपर्क करना, जागरूकता बढ़ाने के लिए संगत की

पहलों का समर्थन करना और इस ऐतिहासिक आंदोलन की कवरेज को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेस के साथ जुड़ना शामिल था। हमने देश भर में 6,700 से अधिक समुदाय के सदस्यों और सहयोगियों को संगठित किया ताकि वे कांग्रेस में अपने निर्वाचित अधिकारियों को लगभग 20,000 संदेश भेजकर किसानों के शांतिपूर्ण विरोध करने के अधिकार का समर्थन करें और भारतीय सरकार के अलोकतांत्रिक व्यवहार की निंदा करें। हमने संगत को प्रस्ताव का मसौदा उपलब्ध कराया ताकि वे इस मुद्दे पर स्थानीय सांसदों से संपर्क कर सकें। हमने कांग्रेस के सदस्यों और बाइडेन प्रशासन को कई पत्र भेजे।

अनुसंधान परिणाम

समानता अध्ययन केंद्र (सीईएस) के कार्यक्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा, नागरिकता, लिंगभेद, श्रम एवं प्रवासन, सामाजिक न्याय और बेघरता जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। हालांकि इसका उद्देश्य नेक प्रतीत होता है, लेकिन इसकी 'भारत बहिष्करण रिपोर्ट' केवल मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार मुद्दों को ही उजागर करती है। हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा का इसमें स्पष्ट अभाव है और उन्हें हिंसा के दोषी के रूप में चित्रित करना अंतरराष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थानों द्वारा प्रतिपादित कथनों के अनुरूप साक्ष्य प्रस्तुत करने का एक स्पष्ट प्रयास है। 308 पृष्ठों की यह 'भारत बहिष्करण रिपोर्ट', जो विभिन्न लेखों का संकलन है, सरकार को मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के प्रति नीतिगत बदलावों का सुझाव देती है। सीईएस ने नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के विरुद्ध सबसे संगठित और वित्तपोषित संघर्षों में से एक का संचालन किया है।

मंदर की इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट को प्रदर्शित करने वाले xSDG

सम्मेलन का संचालन MIT J-PAL के अधिकारियों द्वारा किया गया। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि J-PAL का उद्देश्य सरकारी नीति में बदलाव लाना और इसके लिए स्थानीय भारतीय विद्वानों को प्रशिक्षित करना है। अशोका विश्वविद्यालय, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय और क्रिया विश्वविद्यालय के विद्वान इसमें अच्छी संख्या में उपस्थित थे। उनकी गतिविधियों के गहन विश्लेषण से स्पष्ट है कि J-PAL, Belongg, CES, क्रिया विश्वविद्यालय और अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय भारत में एक ऐसा व्यापक तंत्र बनाने की दिशा में अग्रसर हैं जो विशिष्ट विचारधारा वाले शोध को बढ़ावा देता है और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करता है। पॉवर्टी एक्शन लैब जाति व्यवस्था को लेकर बेहद जुनूनी प्रतीत होती है और उसने इस विषय पर पश्चिमी 'विशेषज्ञों' को नियुक्त किया है। उदाहरण के लिए:

जे-पाल की कार्यकारी समिति और बोर्ड सदस्य मैरिएन बर्ट्रेंड शिकागो विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर हैं, जिनका शोध अमेरिका में नस्लीय भेदभाव को वंचित जातियों के लिए सकारात्मक कार्रवाई और भारत में भ्रष्टाचार के साथ जोड़ता है।

जे-पाल में एक अन्य संकाय सदस्य जीन लाफोर्ट्यून हैं, जो चिली के पोंटिफिकल कैथोलिक विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्री हैं, जिनका ध्यान 'विवाह बाजार की स्थितियों और मानव पूंजी संचय के बीच संबंध, भारतीय विवाह बाजार में जाति की भूमिका...' पर केंद्रित है।

प्रियाल पाटिल जाति, नस्लीय/लैंगिक भेदभाव, स्वास्थ्य और शिक्षा में शोध रुचि रखने वाली एक विद्वान हैं। अंकित अग्रवाल एक अन्य विद्वान हैं जिनकी शोध रुचियां लिंग, जाति, धर्म और शिक्षा के अर्थशास्त्र के रूप में बताई गई हैं।

जे-पाल भारत में डेटा संग्रह, सामाजिक मानचित्रण, गहन साक्षात्कार और

ग्राम स्तरीय बैठकों के आयोजन के लिए अपने स्वयं के बुनियादी ढांचे के निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल है।

पॉवर्टी एक्शन लैब किसी भी विषय को विभाजनकारी मुद्दे का अध्ययन करने के अवसर के रूप में उपयोग करने में बहुत ही रचनात्मक है। उदाहरण के लिए, क्रिकेट का उपयोग विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच पूर्वाग्रह का अध्ययन करने और भारत में अंतर-समूह गतिशीलता के लिए रणनीतियाँ तैयार करने के लिए किया गया था। एक अन्य अध्ययन में यह देखा गया कि जातिगत स्थिति छात्रों को दिए गए ग्रेड से कैसे संबंधित है। एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि बाढ़-सहिष्णु बीजों को भारतीय किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक बीजों पर स्पष्ट लाभ था, जिससे पारंपरिक कृषि तकनीकों को नुकसान पहुंचा और विदेशी बीजों पर निर्भरता बढ़ी। एक अध्ययन में जाति और धार्मिक मानदंडों का भी अध्ययन किया गया जो आर्थिक विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।

पॉवर्टी एक्शन लैब के लैंगिक अध्ययन बेहद दिलचस्प हैं। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के साथ मिलकर इसने सूक्ष्म उद्यमशीलता में लैंगिक अंतर का अध्ययन किया है और जाति से जुड़े ऐसे सहसंबंध पाए हैं जो महिलाओं की गतिशीलता को सीमित करते हैं। ऐसे अध्ययनों में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह सवाल उठता है कि सऊदी अरब द्वारा वित्त पोषित जे-पाल सऊदी अरब में ऐसा शोध क्यों नहीं करता, जहां महिलाओं को मौलिक अधिकारों से वंचित किया जाता है। सऊदी अरब अपने ही देश में लाखों डॉलर खर्च करने के लिए विवश क्यों नहीं है, जहां स्वतंत्रता और मानवाधिकार गंभीर चिंता का विषय हैं?

सामाजिक मुद्दों के अलावा, जे-पाल भारत में मतदान और चुनावी परिणामों का भी गहन अध्ययन कर रहा है। एक अध्ययन में उम्मीदवारों

के आपराधिक पृष्ठभूमि के चुनाव परिणामों पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया गया। एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि उम्मीदवारों की नीतियों और प्रदर्शन के बारे में अधिक पारदर्शी जानकारी से कम भ्रष्ट उम्मीदवारों को मदद मिलती है। हैरानी की बात यह है कि तानाशाही सऊदी अरब भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया और भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों को लेकर इतना चिंतित है कि वह इस स्थिति को सुधारने के लिए लाखों डॉलर खर्च कर रहा है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि एमआईटी, डालबर्ग एडवाइजर्स, आईएफएमआर, क्रेया यूनिवर्सिटी, सीईएस, बिलॉन्ग डॉट नेट और अन्य संस्थाएं यह सवाल नहीं उठातीं कि सऊदी अरब अपने देश में इस स्थिति को सुधारने के लिए ऐसा क्यों नहीं करता।

जमील-पॉवर्टी एक्शन लैब की भारत में शाखाएं: वित्तीय प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान और क्रेया विश्वविद्यालय
आईएमएफएमआर की स्थापना 1970 के दशक में आईसीआईसीआई बैंक, कोठारी समूह और अन्य व्यवसायों द्वारा वित्त पोषित की गई थी। आज, यह कई संगठनों का संचालन करता है, जिनमें शामिल हैं:
क्रेया विश्वविद्यालय
आईएफएमआर लीड
जे-पाल दक्षिण एशिया
डिजिटल वित्तीय समावेशन केंद्र
अर्थव्यवस्था में महिलाओं और लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए कारगर उपायों की पहल
समावेशी अर्थशास्त्र भारत केंद्र
मोतुरी सत्यनारायण मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उन्नत अध्ययन

केंद्र

IFMR के हार्वर्ड और येल विश्वविद्यालयों के साथ गहरे संबंध रहे हैं और हाल ही में इसने Krea विश्वविद्यालय के अंतर्गत MIT के J-PAL को भी शामिल किया है। जहाँ तक हमें पता चला है, यह अब व्यावहारिक रूप से Krea का पर्याय बन चुका है, और एक छत्र संगठन के रूप में कार्य करता है जो Krea के माध्यम से विदेशी एजेंसियों के लिए अनुसंधान का समर्थन करता है।

कई दिग्गज कंपनियों ने Krea को वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिनमें आनंद महिंद्रा, बायोकॉन की किरण मजूमदार शॉ, आर्सेलरमित्तल के आदित्य मित्तल, अशोक लेलैंड के धीरज हिंदुजा, जेएसडब्ल्यू स्टील के सज्जन जिंदल और थर्मैक्स की अनु आगा शामिल हैं। शासी परिषद में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, प्रिंसटन के गणित प्रोफेसर मंजुल भार्गव और स्टैनफोर्ड के पूर्व प्रोवोस्ट जॉन डब्ल्यू एचेमेंडी जैसे प्रतिष्ठित शिक्षाविद शामिल हैं, जो इंफोसिस के बोर्ड में भी कार्यरत हैं। कॉग्निजेंट के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रामकुमार राममूर्ति प्रो-वाइस-चांसलर के रूप में शामिल हुए हैं। Krea को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से भी महिला मुद्दों पर शोध के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। इनमें से कुछ IFMR संगठनों को अमेरिका स्थित डालबर्ग एडवाइजर्स से भी वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।

चुपचाप, भारत क्रिटिकल रेस थ्योरी के आयात के लिए एक उपजाऊ ज़मीन बन गया है। क्रेया के पास वामपंथी विद्वानों का एक प्रतिष्ठित पैनल है और अमेरिकी अकादमिक जगत का भरपूर समर्थन प्राप्त है। पश्चिम से उदार कलाओं को लाने के नाम पर, यह अकादमिक रूप से और प्रशासनिक नियंत्रण के मामले में तेजी से विकसित होकर वोक एक्टिविज़्म का एक प्रमुख केंद्र बन रहा है।

भारत में जे-पाल के कार्यों के लिए क्रेया एक चौकी के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि एमआईटी भारत में अपना नेटवर्क स्थापित करना शुरू कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि एमआईटी की उत्कृष्ट प्रतिष्ठा मुख्य रूप से एक प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र के रूप में है, लेकिन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए भारत में एमआईटी समर्थित इंजीनियरिंग केंद्रों की स्पष्ट कमी है। देशभक्त भारतीयों के लिए एमआईटी जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का उपयोग करना स्वाभाविक विकल्प होना चाहिए। इसके विपरीत, जे-पाल के माध्यम से एमआईटी द्वारा किए गए सभी निवेश सामाजिक विज्ञान में हैं, जिनमें जाति को मुख्य विषय बनाया गया है।

अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो (माइकल क्रेमर के साथ) ने प्रायोगिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण करके 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता, ठीक उसी तरह जैसे फार्मा कंपनियां किसी दवा की प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिए यादृच्छिक नैदानिक परीक्षणों का उपयोग करती हैं। क्रेया विश्वविद्यालय (आईएफएमआर के माध्यम से) ने बनर्जी और डुफ्लो को जे-पाल के लिए ये प्रयोग करने में सहायता की। डुफ्लो को 2021 में क्रेया की शासी परिषद में शामिल किया गया और उन्होंने नोबेल पुरस्कार तक पहुंचने वाले अपने शोध में सहायता के लिए विश्वविद्यालय को धन्यवाद दिया। यह कहना उचित होगा कि यदि भारत में किए गए हमारे सभी शोध कार्य न होते, तो हमें नोबेल पुरस्कार न मिलता, और यह सब 2008 से क्रेया विश्वविद्यालय के प्रायोजक निकाय से प्राप्त समर्थन के कारण ही संभव हो पाया।

क्रेया की जे-पाल के साथ साझेदारी सऊदी अरब को गरीबी उन्मूलन जैसे मुद्दों की आड़ में भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने की अपार शक्ति

प्रदान करती है। हस्तक्षेप के एक उदाहरण के रूप में, अमेरिकी रॉक सुपरस्टार रिहाना ने अचानक ट्विटर पर भारत के विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को अपना समर्थन दिया, जिससे किसानों का विरोध वैश्विक मुद्दा बन गया। उन्होंने अपने 10.6 करोड़ ट्विटर फॉलोअर्स का इस्तेमाल विरोध प्रदर्शन को और अधिक बल देने के लिए किया। (रिहाना पहले जे-पाल के संस्थापक मोहम्मद अब्दुल लतीफ जमील के बेटे हसन मोहम्मद अब्दुल लतीफ जमील के साथ प्रेम संबंध में थीं।)

क्रेया जैसे विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान प्रणालियों की अपर्याप्त समझ है और वे प्रतिष्ठित संस्थानों के रूप में विश्वसनीयता हासिल करने के लिए पश्चिमी शिक्षाविदों को अपने साथ जोड़ते हैं। ये संबंध मुफ्त में नहीं मिलते: क्रेया को इसके लिए भारत पर व्यापक डेटा उपलब्ध कराना पड़ता है। यह भारतीय विद्वानों को पश्चिमी वामपंथी शिक्षाविदों और भारत में उनके राजनीतिक हस्तक्षेपों के शिष्य बनने के लिए प्रशिक्षित करने में मदद करता है।

Krea, MIT, येल विश्वविद्यालय, सऊदी अरब, फ्रांस और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसे विदेशी गैर-सरकारी संगठनों के लिए एक प्रवेश द्वार बन गया है। Krea ने अर्थशास्त्र, लिंग, पर्यावरण और गरीबी पर शोध कार्य करने के लिए विदेशी संस्थाओं के साथ साझेदारी की है। ये परियोजनाएं पश्चिमी मूल्यों को लागू करती हैं, चाहे वे अपने देशों में सफल हों या असफल, और भारतीय संदर्भ का जरा भी ध्यान नहीं रखतीं। यह जनता की मानसिकता को बदलने के लिए एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन अभियान है।

पृष्ठ 512 और 513 पर दिए गए चार्ट भारत में जे-पाल के व्यापक नेटवर्क और उसके शोध परिणामों को दर्शाते हैं।

क्रेआ के विद्वान और उनके शोध परिणाम इसके नेतृत्व की विचारधाराओं

को दर्शाते हैं। सुमित मिश्रा जैसे इसके अर्थशास्त्र के प्रोफेसरों ने हार्वर्ड और कॉर्नेल के विद्वानों के साथ मिलकर अर्थशास्त्र में ऐसे शोध पत्र तैयार किए हैं जो यह दर्शाते हैं कि भारत में जाति-आधारित भेदभाव किस प्रकार व्याप्त है। लेकिन वे इस परिप्रेक्ष्य को शामिल करने में विफल रहते हैं कि जाति-आधारित नेटवर्क भी कई समुदायों की सफलता में योगदान देते हैं, जैसा कि आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर आर. वैद्यनाथन ने विस्तार से स्थापित किया है।

एक अन्य उदाहरण सायंतन दत्ता हैं, जिनके पास संज्ञानात्मक विज्ञान में एमएससी की डिग्री है, लेकिन वे क्रेया में लेखन और मौखिक संचार पढ़ाते हैं। दत्ता को 2021 में नेशनल एसोसिएशन ऑफ साइंस राइटर्स, एक अमेरिकी संगठन, से 'विविधता रिपोर्टिंग' अनुदान प्राप्त हुआ, जिसका दावा है कि यह 'स्वदेशी लोगों, न्यूरोडाइवर्स व्यक्तियों और ट्रांसजेंडर/नॉनबाइनरी समुदाय को प्रभावित करने वाले मुद्दों की एक प्रभावशाली श्रृंखला का पता लगाएगा'। उन्होंने अध्याय 1 में चर्चा की गई अंतर्संबंधता की पूरी प्रणाली को आयात किया है और इसे भारत की जाति, लिंग और यौन पहचान पर लागू किया है, जिसे उत्पीड़ित 'संरक्षित वर्ग' के रूप में देखा जाता है। भारत में विज्ञान का अध्ययन भी इसी दृष्टिकोण से देखा जाता है।

जब आईआईटी प्रमुख ने टिप्पणी की कि उनके संस्थान में कोई भेदभाव नहीं है और 'हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर ऐसा होता है तो हम इससे सख्ती से निपटेंगे', तब दत्ता ने ट्वीट किया:

यह वाकई बेहद परेशान करने वाला है। इस बात के पर्याप्त से अधिक प्रमाण मौजूद हैं कि सभी IIT, और IIT मद्रास भी, जातिवादी भेदभाव का गढ़ हैं। वास्तव में, IIT जातिवाद पर ही टिके हुए हैं; IIT योग्यता के मिथक को कायम रखने के लिए जाति का *उत्पादन* करते हैं।

आयुर्वेद पर दत्ता के विचार इस प्रकार हैं: ‘आयुर्वेद का कोई भी विश्लेषण, यह समझे बिना कि यह जाति और जातिवाद से किस प्रकार अटूट रूप से जुड़ा हुआ है, अधिकतर बकवास है। आयुर्वेद को बढ़ावा देना = जाति को बढ़ावा देना।’

क्रिया और डेटा माइनिंग

हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के एविडेंस फॉर पॉलिसी डिज़ाइन कार्यक्रम ने भारतीय श्रम अर्थशास्त्र पर अध्ययन और डेटा एकत्र करने के लिए 2013 में IFMR को नियुक्त किया था। इस कार्यक्रम को येल विश्वविद्यालय के इंक्लूजन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आर्थिक विकास केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया। अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य येल विश्वविद्यालय में एक विशाल डेटा भंडार बनाने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर डेटा का संकलन करना है। कुछ मामलों में, भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज से संबंधित डेटा तक पहुँचने के लिए येल विश्वविद्यालय से विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। IFMR/Krea द्वारा येल विश्वविद्यालय के लिए इतना मूल्यवान डेटा संकलित किए जाने के बावजूद, यह विडंबनापूर्ण है कि IFMR/Krea को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 'राष्ट्रीय महत्व की संस्था' के रूप में मान्यता प्राप्त है।

येल विश्वविद्यालय श्रम अर्थशास्त्र, आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक अर्थशास्त्र और पर्यावरण अर्थशास्त्र से संबंधित लिंग संबंधी विषयों पर डेटा संग्रह और विश्लेषण के लिए कई विद्वानों को नियुक्त करता है। इसका उद्देश्य नीतिगत हस्तक्षेपों को समर्थन देने के लिए डेटा एकत्र करना है। एक अन्य लक्ष्य येल की समावेशिता संबंधी विचारधारा के अनुरूप परिवर्तन लाने के लिए आम जनता और नीति निर्माताओं के बीच

इस विचार को बढ़ावा देना है। येल की वेबसाइट पर भारत में इस प्रकार के डेटा-आधारित शोध करने के लिए एक दर्जन से अधिक फैलोशिप पद उपलब्ध हैं। क्रेया येल को भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और सामाजिक नेटवर्क पर भारी मात्रा में डेटा एकत्र करने में मदद कर रही हैं। हम यह दावा नहीं कर रहे हैं कि किसी कानून का उल्लंघन हो रहा है। हमारी पिछली पुस्तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर में प्रस्तुत तर्कों के आधार पर, हम केवल उन अनेक उदाहरणों की ओर इशारा कर रहे हैं जिनमें संवेदनशील डेटा को आवश्यक सरकारी निगरानी के बिना एकत्र और निर्यात किया जा रहा है।

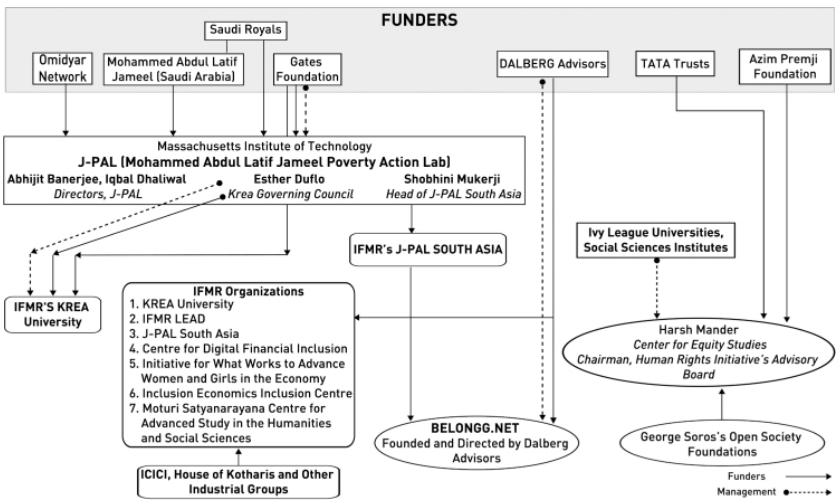

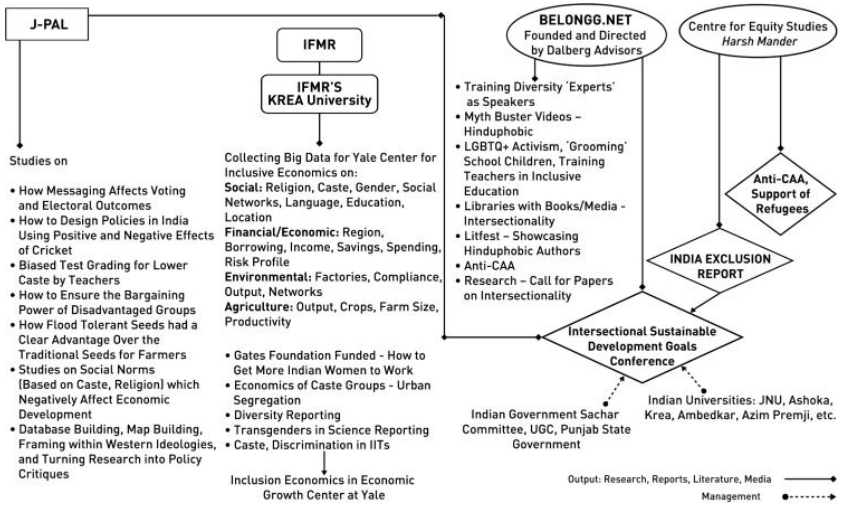

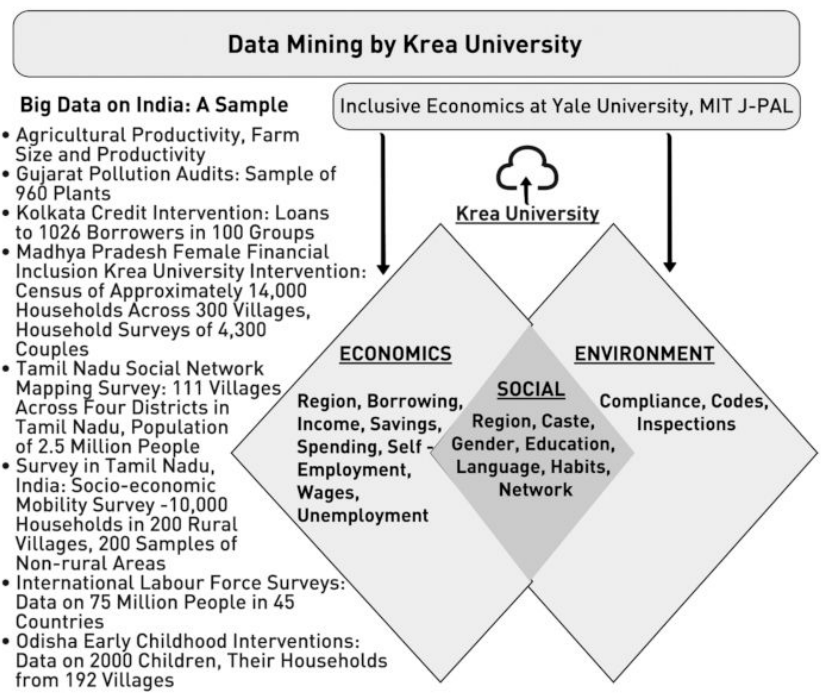

ऊपर दिया गया आरेख डेटा संकलन परियोजनाओं की एक नमूना सूची दर्शाता है।

इसका एक उदाहरण क्रेया और येल के आर्थिक विकास केंद्र द्वारा किया गया सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता का व्यापक सर्वेक्षण है, जिसमें दक्षिणी भारतीय राज्य तमिलनाडु के दो सौ ग्रामीण गांवों के दस हजार परिवारों और गैर-ग्रामीण क्षेत्रों के दो सौ परिवारों को शामिल किया गया था। इसमें प्रत्येक परिवार के सदस्य की आय, भूमि स्वामित्व, आवास की स्थिति, आयु, जाति, प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय, परिवार का आकार और परिवार के मुखिया की शिक्षा और व्यवसाय पर गांव-दर-गांव जनगणना शामिल थी। परिवार और व्यक्तिगत स्तर पर प्रश्नावली का उपयोग किया गया था, जिसमें सभी विवाहित महिलाओं को वैवाहिक और प्रजनन इतिहास से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए एक विशेष प्रश्नावली दी गई थी।

एक अन्य उदाहरण ओडिशा अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशन डेटासेट है, जिसमें पूर्वी राज्य ओडिशा के 192 गांवों के 2000 बच्चों और उनके परिवारों का डेटा शामिल है। येल का दावा है:

इसमें परिवारों के जनसांख्यिकीय और आर्थिक आंकड़ों के साथ-साथ बच्चों के कौशल पर विस्तृत और उन्नत माप भी शामिल हैं। इसमें नेटवर्क और सामुदायिक स्तर की जानकारी भी शामिल है। इस डेटासेट का आकार और दायरा मूल शोध से कहीं आगे गरीब समुदायों पर शोध करने की अनुमति देता है। यह एक ऐसे समूह का आधार भी बनता है जिसमें बच्चों और उनके परिवारों का भविष्य में कई शोध उद्देश्यों के साथ अनुसरण करने की क्षमता है, जिसमें उन हस्तक्षेपों के प्रभावों का अनुवर्ती अध्ययन भी शामिल है जिन्होंने इसे मूल रूप से प्रेरित किया था।

तमिलनाडु सोशल नेटवर्क मैपिंग सर्वे तमिलनाडु के 25 लाख लोगों का एक विशाल डेटाबेस है जो वित्तीय और सामाजिक नेटवर्क का मानचित्रण करता है। येल के स्वामित्व वाले इस डेटासेट में व्यक्तिगत गांवों के बाहर

के सामाजिक नेटवर्क का भी सावधानीपूर्वक मानचित्रण किया गया है। वेबसाइट का दावा है कि,

प्रत्येक गाँव के लगभग सभी परिवारों के वित्तीय और सामाजिक संबंधों से संबंधित संपूर्ण नेटवर्क डेटा उपलब्ध है। ... गाँव के भीतर और गाँव के बाहर दोनों तरह के संपर्कों का डेटा मौजूद है, जो कि बहुत दुर्लभ है। अंत में, इस डेटासेट में सभी परिवारों द्वारा स्वयं-मूल्यांकित खुशहाली, आय और संपत्ति, सार्वजनिक सुविधाओं के प्रावधान और सामुदायिक भागीदारी से संबंधित विस्तृत माप शामिल हैं, जो नेटवर्क मैपिंग डेटासेट के संदर्भ में अद्वितीय है।[64]

पर्यावरण संबंधी डेटा संग्रह में वायु प्रदूषण, नियामक अनुपालन और कारखाने के निरीक्षण पर सर्वेक्षण शामिल हैं। Krea को अपने पर्यावरण डेटा माइनिंग परियोजनाओं के लिए भारत सरकार, हार्वर्ड विश्वविद्यालय जलवायु परिवर्तन समाधान कोष, हार्वर्ड विश्वविद्यालय सततता विज्ञान कार्यक्रम, मैकार्थर फाउंडेशन और USAID से वित्त पोषण प्राप्त होता है। येल इंक्लूजन इकोनॉमिक्स सेंटर ने कृषि उत्पादकता और खेत के आकार के साथ-साथ कृषि इनपुट और फसल पैदावार में बीमा की भूमिका का अध्ययन करने के लिए भारतीय कृषि के बारे में डेटा एकत्र किया है। भारत के ऊर्जा अवसंरचना के विस्तार की लागत और लाभों का अध्ययन करने के लिए विद्युत अवसंरचना डेटा का उपयोग किया गया है। इसमें अवसंरचना से संबंधित संवेदनशील जानकारी शामिल है जिसका संभावित रूप से साइबर हमलों के लिए उपयोग किया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण के बहाने, येल इंक्लूजन इकोनॉमिक्स सेंटर मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को प्रशिक्षण देता है; और यह रिपोर्ट करता है कि भारतीय महिलाएं गृहिणी बनना पसंद करती हैं, जिसे वे एक सांस्कृतिक दोष मानती हैं जिसे वे दूर करना चाहती हैं।

हालांकि क्रेया की गतिविधियां वैध प्रतीत होती हैं, लेकिन डेटा सुरक्षा पर हालिया भारतीय नीतियों से गहन जांच की आवश्यकता महसूस होती है। हमने एक पश्चिमी विश्वविद्यालय से एक भारतीय विश्वविद्यालय तक सामाजिक न्याय के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख माध्यमों में से एक को उजागर किया है, और यह सब विदेशी और भारतीय व्यापारियों द्वारा वित्त पोषित है।

19. अशोका विश्वविद्यालय: हार्वर्ड विश्वविद्यालय का कनिष्ठ भागीदार

अवलोकन

अशोका विश्वविद्यालय उन ताकतों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है जिन्हें कई देशभक्त भारतीय भारत को तोड़ने वाली ताकतों के रूप में देखते हैं। यहीं पर भारतीयों से संबंधित महत्वपूर्ण डेटाबेस एकत्र और विश्लेषण किए जाते हैं, भारत को तोड़ने के सिद्धांतों को अवधारणाबद्ध किया जाता है और हस्तक्षेप रणनीतियों को विकसित, परखा और परिष्कृत किया जाता है। यहीं पर कई छात्रों को वैचारिक आख्यानों और रणनीतियों का प्रशिक्षण दिया जाता है और फिर उन्हें संगठित किया जाता है। नए पीड़ित समूहों की पहचान की जाती है और उन्हें पोषित किया जाता है। निहित स्वार्थों वाले पश्चिमी देशों के साथ-साथ भारतीयों द्वारा भारी समर्थन प्राप्त यह विश्वविद्यालय जिस तरह से व्यवहार करता है, उससे राष्ट्र के प्रति इसकी निष्ठा पर सवाल उठ सकते हैं। हम भारत में लोगों, बुनियादी ढांचे और संस्थानों के वैश्विक संबंधों के एक जटिल नेटवर्क की ओर इशारा करते हैं, जो चिंताजनक है। हम किसी भी प्रकार के उल्लंघन का न्याय

नहीं करना चाहते हैं, और यहां हमारा उद्देश्य केवल कच्चा डेटा प्रस्तुत करना है जिसका निर्णय लेने से पहले गहन विश्लेषण की आवश्यकता होगी।

भारत भर में उभर रहे अन्य उदार कला विश्वविद्यालय भले ही इसी तरह की भूमिका निभा रहे हों, लेकिन अशोका विश्वविद्यालय सबसे प्रमुख है। हालांकि इसके संस्थापकों की कल्पना इस प्रकार नहीं थी। वे नेक इरादों वाले, सफल IIT/IIM और अमेरिका से शिक्षित उद्यमियों का एक समूह थे, जो शीर्ष पश्चिमी विश्वविद्यालयों की तर्ज पर उदार कला शिक्षा पर केंद्रित एक विश्वविद्यालय बनाना चाहते थे। उनमें से अधिकांश की तकनीकी पृष्ठभूमि थी, लेकिन उन्हें पश्चिमी उदार कलाओं और भारतीय परंपराओं से उनके अंतर की पर्याप्त समझ नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वे वैश्विक अभिजात वर्ग के साथ मेलजोल करके अपनी हाल ही में अर्जित संपत्ति का प्रदर्शन करने की लालसा से प्रेरित थे। कुछ बड़े नामों द्वारा पहल शुरू करने के बाद, कई और धनी भारतीय भी इस राह पर चल पड़े।

उन्होंने भारत के अध्ययन में हार्वर्ड जैसे संस्थानों के रिकॉर्ड की गहराई से जांच नहीं की। यह उम्मीद की जा सकती है कि रणनीतिक योजनाएँ बनाने से पहले उन्होंने भाग 1 और 2 में प्रस्तुत किए गए विश्लेषण को अवश्य किया होगा। सफल व्यवसायी होने के नाते, वे रणनीतिक निवेश करने से पहले उचित जांच-पड़ताल के महत्व को जानते हैं।

2014 में, Naukri.com के संस्थापक और अशोका विश्वविद्यालय के शुरुआती संस्थापकों और वित्तपोषकों में से एक संजीव बिखचंदानी ने कहा:

लेकिन मुझे असल में तब झटका लगा जब सेंट स्टीफंस कॉलेज ने 2007 में घोषणा की कि वे सामान्य वर्ग और आरक्षित वर्ग के बीच कट-

ऑफ अंकों में 35% के अंतर के साथ 50% आरक्षण लागू करेंगे। इससे सेंट स्टीफंस के सभी पूर्व छात्र भड़क उठे और कहने लगे कि 'देखिए, 35% के अंतर से बात आरक्षण की नहीं, बल्कि अंतर की है।' लेकिन 35% के इतने बड़े अंतर से तो कॉलेज का शैक्षणिक स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। इसलिए, कुछ पूर्व छात्र एक साथ आए और उन्होंने कहा कि चलो एक नया कॉलेज शुरू करते हैं। बिखचंदानी ने आईआईटी और आईआईएम द्वारा प्रदर्शित योग्यता और कड़ी मेहनत की प्रशंसा की। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि हार्वर्ड के स्वयं के प्रोफेसर भारत-विरोधी रुख अपना रहे हैं, जिसमें आईआईटी पर योग्यता की आड़ में जातिवादी संस्था होने का आरोप लगाना भी शामिल है।

अशोक के संस्थापक सिद्धांतों के पतन का एक संभावित कारण यह हो सकता है कि अनुदान देने वालों को उदार कला विश्वविद्यालयों में पनपी, पोषित और प्रचारित विचारधाराओं की जानकारी नहीं थी। उन्हें इस बात का गर्व था कि उनके द्वारा प्रशिक्षित पश्चिमी और भारतीय लोग अशोक के मूल्यों, संरचनाओं और गठबंधनों को परिभाषित करने का दायित्व सहर्ष ग्रहण कर रहे थे।

सोनीपत कैंपस के लिए ही इन व्यापारियों ने 1,000 करोड़ रुपये (125 मिलियन डॉलर) से अधिक का निवेश किया। दूसरे कैंपस के लिए, जिसके लिए धन जुटाने का अभियान 2021 में शुरू हुआ था, लक्ष्य और भी अधिक था - 1,500 करोड़ रुपये। IIT/IIM नेटवर्क को सक्रिय किया गया और अशोका के 160 से अधिक सह-संस्थापक हैं, जिनमें व्यवसायी, अनिवासी भारतीय और यूके, अमेरिका और सिंगापुर के उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्ति शामिल हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और ओमिडयार समूह ने भी अशोका की कुछ परियोजनाओं को समर्थन

देने के लिए अनुदान दिया।
आगे दिया गया आरेख अशोक के भीतर के प्रमुख केंद्रों को दर्शाता है, जिन पर हम अलग-अलग चर्चा करेंगे, और यह भी कि ये केंद्र किस प्रकार एक ऐसी प्रणाली के रूप में संगठित हैं जो भारत को तोड़ने वाली ताकतों की एक नई पीढ़ी का निर्माण करती है।

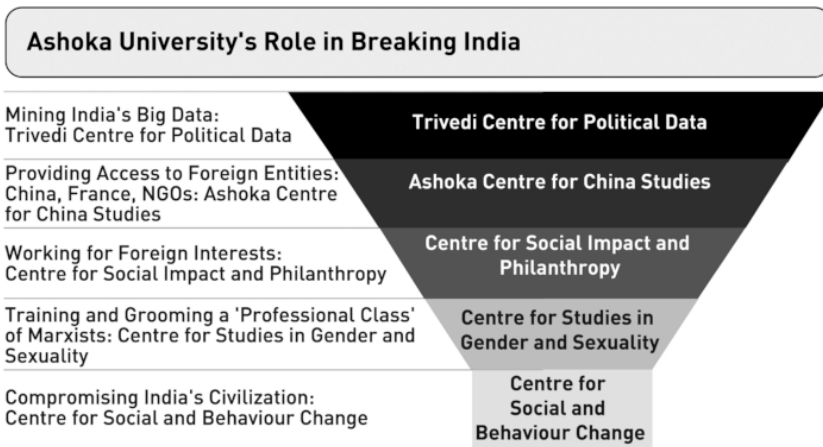

भारत के पारिस्थितिकी तंत्र को तोड़ना: ईंट दर ईंट निर्माण
वित्तीय निवेशक आशीष धवन ने अन्य संस्थापकों के साथ मिलकर एक अकादमिक परिषद नियुक्त की, जिसमें वामपंथी विद्वान प्रताप भानु मेहता (जो 2021 तक कुलपति रहे), रामचंद्र गुहा, आंद्रे बेटेल, कौशिक बसु और अन्य शामिल थे। इस प्रकार उन्होंने पश्चिमी अकादमिक अभिजात वर्ग के हाथों में खेल खेला, जिसकी हमने भाग 2 में आलोचना की है। यही कारण है कि अशोक की मूल अवधारणा शुरू से ही त्रुटिपूर्ण रही है। धवन और उनकी टीम ने पश्चिमी सामाजिक विज्ञानों की संरचना का गहन अध्ययन नहीं किया था, जिसका संक्षिप्त विवरण हमने अध्याय 1 में परिचयात्मक स्तर पर दिया था। वे भारतीय शास्त्रीय अध्ययन में पारंगत

नहीं थे। अमेरिका के हार्वर्ड और येल जैसे विश्वविद्यालयों से सीखने के उनके निर्णय ने उन विश्वविद्यालयों को विश्व गुरुओं के समान माना, जिनमें अशोक प्रमुख शिष्य थे।

अशोका विश्वविद्यालय भारत को तोड़ने वाले संस्थानों में से एक बन चुका है, जिसे अमीरों का जेएनयू कहा जा सकता है। यह उन विशेषाधिकार प्राप्त भारतीय बच्चों के लिए है जिनके माता-पिता तीस लाख रुपये खर्च करके स्नातक की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, जो उन्हें उस विरासत को अपमानित और नष्ट करना सिखाती है जिसे उनके पूर्वजों ने सदियों से अथक परिश्रम से बनाया है।

हम युवाओं में आलोचनात्मक सोच का पूरा समर्थन करते हैं, जिसमें सभ्यताओं, धर्मों, सरकारों और सभी प्रकार की संस्थाओं की आलोचना शामिल है। लेकिन इसमें हमेशा अनेक दृष्टिकोणों का समावेश होना चाहिए। अशोका विश्वविद्यालय में हमें ऐसा नहीं दिखता। हमारा उद्देश्य किसी भी निवेशक की व्यक्तिगत रूप से आलोचना करना नहीं है, बल्कि विद्वानों के बौद्धिक योगदान पर ध्यान केंद्रित करना है। हम अशोका विश्वविद्यालय से जुड़े व्यक्तियों, कुलपति से लेकर नियमित संकाय सदस्यों और छात्रों तक, के कार्यों का सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हैं। इन व्यक्तियों ने अपने उद्देश्यों को सार्वजनिक रूप से उजागर किया है। उदाहरण के लिए, 2016 में, जब जेएनयू में अफजल गुरु (2001 में भारतीय संसद पर आतंकवादी हमले में शामिल कश्मीरी अलगाववादी, जिसे बाद में मौत की सजा दी गई) के समर्थन में हुए विरोध प्रदर्शन में भारत विरोधी नारे गूंजे, जिसके कारण कई लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया, तब अशोका विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति प्रताप भानु मेहता ने लिखा था कि 'हम एक ऐसी सरकार के अधीन रह रहे हैं जो घोर दुर्भावनापूर्ण और राजनीतिक रूप से अक्षम दोनों है'।

उसने जारी रखा:
यह राष्ट्रवाद का इस्तेमाल संवैधानिक देशभक्ति को कुचलने के लिए, कानूनी तानाशाही का इस्तेमाल असहमति को दबाने के लिए, राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल छोटे-मोटे हिसाब-किताब निपटाने के लिए और प्रशासनिक सत्ता का इस्तेमाल संस्थाओं को नष्ट करने के लिए कर रहा है। इस दमनकारी कार्रवाई की वजह जेएनयू में कथित तौर पर कुछ राष्ट्रविरोधी नारे लगाना और अफजल गुरु की पुण्यतिथि मनाने के लिए आयोजित एक बैठक थी। लेकिन सरकार की यह असंतुलित प्रतिक्रिया घोर तानाशाही की बू देती है।
मेहता ने कहा, 'राष्ट्र-विरोधी होना अपराध नहीं है।' यह सच है कि भारत जैसे स्वतंत्र देश में, अधिकारियों की नीतियों पर मौखिक हमला करना अपराध नहीं है। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या निवेशकों और संस्थापकों ने जानबूझकर उचित संतुलन के बिना एक राष्ट्र-विरोधी विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहा था? मेहता ने सीएए पारित होने के बाद हुई तोड़फोड़ का खुलेआम समर्थन किया। उनके हवाले से कहा गया है, 'दिशा भीड़ द्वारा, क्रूर बल द्वारा, लामबंदी द्वारा तय की जाएगी, जबकि कानूनी और दार्शनिक कार्य आवश्यक है, उन पर भरोसा न करें।'
योग्यता और मेहनत को बढ़ावा देने के उच्च उद्देश्यों से स्थापित एक अग्रणी विश्वविद्यालय के कुलपति का परिसरों और सड़कों पर ईमानदार बहसों के बजाय गुंडागर्दी को बढ़ावा देना चिंताजनक है। अशोका के छात्र हार्वर्ड जैसे संस्थानों में अपने साथियों की नकल करते हुए भारतीय व्यापक विचारधारा के विरुद्ध मार्क्सवादी प्रतिवाद को अपना रहे हैं।

अशोक: हिंदूफोबिया का एक इनक्यूबेटर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर आलोचक मेहता का मानना है कि भारतीय

जनता पार्टी के उदय का एकमात्र कारण लोकलुभावनवाद है। वे हिंदुओं के उत्पीड़न की भावना को एक मनगढ़ंत कहानी में पिरोते हैं, जिसके अनुसार हिंदू विभिन्न अल्पसंख्यकों और उनके समर्थकों के खिलाफ साजिश रचते हैं। उनका मानना है कि इसी वजह से उन्हें उनकी चिंताओं को खारिज करने का अधिकार मिल जाता है। द प्रिंट को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा:

इस क्षण को लेकर बहुत शेखी बघारी जा रही है – आधिकारिक कथा के अनुसार, पिछले 70 वर्षों की व्यर्थ स्वतंत्रता की राख से एक नया भारत उभर रहा है। लेकिन... अगर आप इस सत्तावादी विचारधारा, इस अधिनायकवाद और सांप्रदायिकता के मिश्रण को गहराई से देखें, तो आप पाएंगे कि यह किस प्रकार असुरक्षाओं से भरी है – यह एक ऐसी विचारधारा है जो काफी हद तक चिंता और आक्रोश पर आधारित है। ... इसे कायम रखने के लिए एक उत्पीड़नकारी मानसिकता की आवश्यकता है, यह विचार कि भारत के बहुसंख्यक [हिंदू] ... इतिहास में लगातार उत्पीड़ित होते रहे हैं और यह उनका समय है, ... अपने उचित ऐतिहासिक अधिकार का दावा करने का। ... यह जितनी वास्तविक है, उतनी ही गढ़ी हुई चिंता भी है। ... इसे अपनी संतुष्टि के लिए हमेशा एक दुश्मन की आवश्यकता होगी। आज लुटियंस दिल्ली है, परसों बुद्धिजीवी, आज मुसलमान हैं, कल ईसाई, कल अयोध्या थी, और कल कृष्ण जन्मभूमि। ... इस विचारधारा के साथ आने वाला इतिहास का दर्शन अपेक्षाकृत सरल है: 'आइए हम अपने इतिहास की जटिलताओं, इस अविश्वसनीय रूप से जटिल ताने-बाने से परेशान न हों जिसने भारत को वह बनाया है जो वह आज है; इतिहास अपेक्षाकृत सरल है – अतीत कुछ चुनिंदा अभिजात वर्ग की साजिश है – शुरुआत में इस्लामी अभिजात वर्ग, बाद में धर्मनिरपेक्ष अभिजात वर्ग और भविष्य का उद्धार एक ऐसे नेता द्वारा

होगा जो जनता का साक्षात रूप होगा। भाजपा की राजनीति की सोच में एक प्रकार की साजिश रचने वाली राजनीति निहित है। इसलिए, इसे हमेशा साजिशकर्ताओं की तलाश करनी होगी – अल्पसंख्यक, उदार धर्मनिरपेक्षतावादी, वामपंथी, शहरी नक्सलवादी, अब तो बॉलीवुड भी। और उन्हें निशाना बनाना राजनीति के सामान्य गणित पर आधारित नहीं होगा, क्योंकि जब आप दुश्मनों को गढ़कर खुद को पूरी तरह से वैध ठहराते हैं, तो सच्चाई का कोई महत्व नहीं रह जाता, सभ्यता के सामान्य नियम और नियंत्रण और संतुलन मायने नहीं रखते।

सच्चाई यह है कि भारतीय स्कूली पाठ्यक्रम में इतिहास की पुस्तकों पर विदेशी वामपंथी इतिहासकारों का गहरा प्रभाव रहा है। दुर्भाग्यवश, इतिहास को पुनः स्थापित करने का कोई भी भारतीय प्रयास उत्पीड़न की मानसिकता के रूप में निंदा का पात्र बन जाता है। यह रवैया कुलपति कार्यालय से लेकर छात्रों तक, अशोका विश्वविद्यालय में व्याप्त है। अशोका के संकाय में इतिहास के प्रोफेसर दिलीप सिमियन जैसे जाने-माने विध्वंसक शामिल हैं, जो एक पूर्व नक्सली हैं और जिन्होंने 'भारतीय राज्य के खिलाफ पहले नक्सलबाड़ी युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था'। वे अमन पंचायत के अध्यक्ष और न्यासी भी हैं, जो एक गैर-लाभकारी संस्था है और कई गैर-सरकारी संगठनों और भारत-विरोधी गतिविधियों में शामिल संगठनों से वित्त पोषण प्राप्त करती है। इनमें से कुछ के विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत लाइसेंस उल्लंघन के कारण रद्द कर दिए गए हैं।

एक अन्य उदाहरण समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के प्रोफेसर मितुल बरुआ का है, जिन पर 2016 में छात्रा राया सरकार की #MeToo सूची में 'शिक्षा जगत में यौन उत्पीड़न करने वालों' के रूप में यौन उत्पीड़न और बलात्कार का आरोप लगाया गया था। इस मामले में अशोका की

जांच डेढ़ साल तक चली, जिसके बाद बरुआ को यौन उत्पीड़न के बजाय 'पेशेवर कदाचार' के मामूली आरोप में छोड़ दिया गया, जिससे महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए लड़ने में उनकी भूमिका असंभव हो जाती। वामपंथी अखबार ग्रेटर कश्मीर ने इस मुद्दे को उठाया था।
2017 में, बरुआ ने 'नमामि ब्रह्मपुत्र' शीर्षक से एक तीखा लेख लिखा, जिसमें उन्होंने दावा किया कि नदी से संबंधित हिंदू प्रथाएं इसे 'हिंदुत्व की कल्पना में शामिल करने' का प्रयास हैं। उनका कहना है कि 'स्थानीय समुदाय ब्रह्मपुत्र को 'पवित्र' नहीं मानते...'। एक अन्य लेख में वे लिखते हैं कि हालांकि ब्रह्मपुत्र की पूजा की जाती है, लेकिन यह केवल कुछ लोगों द्वारा ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के ढांचे के भीतर और वह भी हताशा में की जाती है।
माजुली के लोगों के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पवित्रता का प्रतीक नहीं है। ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब कुछ सत्राधिकारियों (वैष्णव मठ के धार्मिक और प्रशासनिक प्रमुख) ने द्वीप को कटाव से बचाने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी को भोग अर्पित किया है। हालांकि, ऐसे अनुष्ठान केवल द्वीप पर तीव्र कटाव के समय ही किए गए हैं। इसलिए, ये हताशा भरे कार्य हैं, सामान्य प्रथा नहीं... ऐसे कार्य हमेशा सत्राधिकारियों द्वारा ही किए जाते हैं, न कि द्वीप के आम निवासियों द्वारा। इन्हें ब्राह्मणवादी अनुष्ठान कहा जा सकता है जो शायद सत्राधिकारियों के प्रति जनता की श्रद्धा को बढ़ाने में सहायक होते हैं। ये स्थानीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा नहीं हैं।
बरुआ उन लोगों में भी शामिल थे जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति से मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के दोषी आतंकवादी याकूब मेमन की फांसी के खिलाफ दया याचिका पर विचार करने का अनुरोध किया था, जिसमें 257 लोग मारे गए थे।
एक और उदाहरण अशोका विश्वविद्यालय में समकालीन इतिहास के

प्रोफेसर श्रीनाथ राघवन का है, जिन्होंने ट्वीट किया: 'यह दावा कि किसी ने भी बांग्लादेश की आजादी के लिए सत्याग्रह किया और गिरफ्तार हुआ, इतना हास्यास्पद है कि इसका खंडन करने की आवश्यकता ही नहीं है।' ट्विटर यूजर्स ने तुरंत उनके ऐतिहासिक दावों को गलत साबित करने वाले वीडियो ढूंढ निकाले। 2021 में, अशोका विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के सहायक प्रोफेसर नीलंजन सिरकार ने ट्विटर पर भारत के राष्ट्रपति को ट्रोल किया और भगवान राम का मजाक उड़ाते हुए हिंदू विरोधी बयान दिया। बाद में आलोचना के बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया।

अपने सार्वजनिक बयानों के अलावा, संकाय सदस्य ऐसे पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं और अध्ययन सामग्री की अनुशंसा करते हैं जो हिंदू-विरोधी एजेंडा को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए, इतिहास की प्रोफेसर अपर्णा वैदिक अपने ग्रेट बुक्स फाउंडेशन पाठ्यक्रम के लिए जांच के दायरे में आईं, जिसमें उन्होंने श्रीविद्या नटराजन द्वारा लिखित 'ए गार्डनर इन द वेस्टलैंड: जोतिबा फुले की स्वतंत्रता की लड़ाई' को पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया था। हिंदू-विरोधी प्रकाशनों के लिए जाने जाने वाले प्रकाशक नवयान ने स्वीकार किया है कि यह पुस्तक 'ब्राह्मणवाद और भारत की निम्न जातियों की गुलामी पर एक तीखा और व्यंग्यात्मक हमला है'। यह पुस्तक आदि शंकराचार्य को एक ‘धूर्त ब्राह्मण’ और ‘विकृत बुद्धि’ वाले व्यक्ति के रूप में चित्रित करती है। नटराजन के अनुसार, ब्राह्मणों ने एक-दूसरे को पहचानने के लिए जनेऊ और ऋग्वेद के अत्यंत पूजनीय गायत्री मंत्र जैसे चिह्नों का आविष्कार किया और ‘गाय के मूत्र का सेवन’ करके स्वयं को शुद्ध किया। सार्वजनिक विरोध के जवाब में, अशोक ने संकाय का बचाव करते हुए कहा: ‘विश्वविद्यालय के संकाय चिंतन को उत्प्रेरित करने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का उपयोग करने के

लिए स्वतंत्र हैं’। यह तब ठीक होता जब उल्लिखित ‘विविध प्रकार की सामग्रियां’ वास्तव में विविध होतीं और पूरी तरह से एकतरफा न होतीं, जैसा कि वे हैं। अशोक ने आदि शंकराचार्य के योगदान या गायत्री मंत्र के महत्व को समझाकर छात्रों के चिंतन को ‘उत्प्रेरित’ करने का कोई प्रयास नहीं किया है ताकि वे इस मुद्दे पर बहस कर सकें। हमारा मुद्दा एक बार फिर, विमर्श में संतुलन का अभाव है।

वैदिक को 2018 में एंड्रयू डब्ल्यू. मेलन फाउंडेशन से एक बड़ी ग्रांट मिली, जो उत्तर-औपनिवेशिक दुनिया में 'यौनिकता, लिंग और राज्य' पर शोध करने और 'वैश्विक दक्षिण में लैंगिक असमानताओं की निरंतरता' को उजागर करने की परियोजना का हिस्सा थी। 2020 में, वैदिक को ब्रिटेन की ब्रिटिश अकादमी से पचास हजार पाउंड की एक और ग्रांट मिली। अकादमिक सहायता प्रदान करने के लिए अशोका और फ्लेम विश्वविद्यालयों को चुना गया। लक्ष्यों में से एक 'अनुभवात्मक ज्ञान' के अभिलेखागार का निर्माण करना है, जो उन समूहों के दृष्टिकोण से है जिन्हें वैदिक 'सबआल्टर्न' के रूप में वर्गीकृत करती हैं। वह इसे 'सार्वजनिक इतिहास' कहती हैं। इसका उद्देश्य इस 'उत्पीड़क बनाम उत्पीड़ित' इतिहास को अकादमिक जगत में शामिल करना और फिर इसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करना है।

वहीं दूसरी ओर, ग्रामीण लोगों के पौधों, औषधियों और अन्य मूल्यवान चीजों के बारे में उपयोगी ज्ञान और अनुभव का ऐसे शोध में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि इससे वे शोषितों की बजाय नायक बन जाएंगे। इसके अलावा, इससे पश्चिमी फार्मा कंपनियों द्वारा जैविक बौद्धिक संपदा की चोरी का पर्दाफाश भी होगा।

ब्रिटिश अकादमी के अनुसार:

यह शोध परियोजना अकादमिक इतिहासकारों और भारत के स्वदेशी

लोगों के सामुदायिक प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है और संयुक्त रूप से संचालित की जाएगी, जिसका उद्देश्य हाशिए पर स्थित ज्ञान प्रणालियों और ज्ञान को स्कूल और विश्वविद्यालय की शिक्षाशास्त्र में लाना है। शोध दल भारत में सामुदायिक सार्वजनिक इतिहास पहलों और शैक्षणिक संसाधनों का पहला डेटाबेस बनाकर यह कार्य करेगा। यह परियोजना बहुभाषी और बहुजातीय स्रोतों पर निर्भर होकर तथा सामुदायिक परंपराओं, मौखिक परंपरा और अनुभवात्मक ज्ञान को केंद्र में रखकर पारंपरिक ऐतिहासिक प्रथाओं को चुनौती देती है। अपनी अवधारणा, डिजाइन और प्रसार में, परियोजना का लक्ष्य हाशिए पर स्थित समुदायों के सामुदायिक शोधकर्ताओं को, जो भारतीयों में सबसे कम अनुपात में हैं, औपचारिक शिक्षा से जोड़कर उनकी आवाज़ को शैक्षिक परिवेश में लाना है। इससे स्थानीय समुदाय के विकास और उनके ज्ञान संसाधनों के पुनर्मूल्यांकन को लाभ होगा। यह शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न दर्शकों को सामूहिक सार्वजनिक इतिहास की एक नई समझ विकसित करने में भी सक्षम बनाएगा।

विदेशी वित्तपोषण स्रोतों के अलावा शायद ही किसी की निगरानी हो रही है। इसलिए, विश्वविद्यालय का उपयोग गरीब, कमजोर लोगों के लिए अपनी शिकायतें व्यक्त करने के मंच के रूप में किया जा सकता है, और ऐसी कहानियों का उपयोग अंतरराष्ट्रीय मंचों पर समुदायों के बीच अविश्वास और अशांति को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। परियोजना की देखरेख करने वाले ब्रिटिश विश्वविद्यालय का कहना है: यह परियोजना हाशिए पर पड़े समुदायों के बीच इतिहास और स्मृति के प्रति जागरूकता बढ़ाएगी और उच्च शिक्षा संस्थानों को भारतीय विश्वविद्यालयों के शिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों में गैर-मानक सामुदायिक ज्ञान को एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

Ashoka's website quotes Vaidik:
बहुत से ऐतिहासिक शोध राज्यों और निगम संस्थाओं द्वारा बनाए गए संस्थागत अभिलेखागारों पर आधारित हैं। ...हम अभिलेखागारों को उपनिवेशवाद से मुक्त कैसे करें? लोगों और समुदायों के विश्वदृष्टिकोण को अभिलेखागारों में कैसे समाहित करें? वे कौन सी पारंपरिक अभिलेखागार प्रथाएं हैं जिन्हें समाप्त करने की आवश्यकता है?
सार्वजनिक इतिहास का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना दृष्टिकोण सामुदायिक अभिलेखागारों की ओर मोड़ना होगा - ऐसे अभिलेखागार जो समुदाय द्वारा निर्मित हों, न कि समुदायों के लिए बनाए गए अभिलेखागार। ... जनस्तु ... पट्टाचित्र कथाकारों की कहानियों को उनके द्वारा बटन वाले रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड किए गए रूप में दर्ज करता है। यह ... रायका समुदाय के बारे में भी जानकारी देता है, जहाँ उन्होंने चरवाहों के लिए अपने स्थान का पता लगाने हेतु एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया है। इससे साझा संसाधनों की रक्षा करने और समुदाय द्वारा स्वयं जैव-सांस्कृतिक प्रोटोकॉल संकलित करने में सहायता मिलती है। पारंपरिक अभिलेखागार हिंसा और विलोपन के स्थान हैं, जो औपनिवेशिक प्रशासन, राज्य और सत्ता में बैठे लोगों द्वारा निर्मित हैं। इनमें नरसंहार, सामूहिक हत्याओं और भूमि हड़पने की घटनाओं का वर्णन है। ... सामुदायिक ज्ञान का संग्रह और अभिलेखन हमारे इतिहास की पुनर्कल्पना में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इतिहास का एक बड़ा हिस्सा वास्तव में राज्य, शासकों और बड़े राजनेताओं का इतिहास है। उन्हें इतिहास में 'कर्ता' के रूप में देखा जाता है... फिर आए अधीनस्थ इतिहासकार जिन्होंने इतिहास के हाशिये पर रहने वाले लोगों - श्रमिक वर्ग, किसानों और महिलाओं - पर ध्यान केंद्रित किया और उन्हें इतिहास के कर्ता के रूप में प्रस्तुत किया।

सार्वजनिक इतिहास... इतिहास के विश्लेषण और लेखन की शैली में इतिहास की 'घुमंतू आवाज़' को शामिल करने का प्रयास करता है। यहाँ सावधानी बरतनी आवश्यक है क्योंकि सार्वजनिक इतिहास की अवधारणा 'वास्तविक' इतिहास (जो इतिहासकारों द्वारा अपने साथियों के लिए किया जाता है) और उस इतिहास (जो वे जनता के लिए और जनता के साथ मिलकर लिखते हैं) के बीच अलगाव पैदा कर सकती है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।

यह देखना रोचक है कि ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के मन में उपनिवेशित लोगों के लिए कितनी सहानुभूति थी, यहाँ तक कि उन्होंने उपनिवेशित लोगों के इतिहास को अपने 'दृष्टिकोण' से फिर से लिखने के लिए लोगों को नियुक्त किया। यह बात विशेष रूप से आश्चर्यजनक है क्योंकि वे भारत से लूटे गए संसाधनों और कलाकृतियों को वापस करने से इनकार करते हैं, जबकि वे भली-भांति जानते हैं कि ये उस काल के इतिहास को निष्पक्ष रूप से लिखने में सहायक होंगे।

वैदिक के विश्लेषण में स्पष्ट रूप से क्रिटिकल रेस थ्योरी का अप्रत्यक्ष अनुप्रयोग झलकता है, जिसमें वे कहती हैं कि भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाएँ हिंसा से भरी हुई हैं, और 'उच्च जाति के विशेषाधिकार लोगों की इस हिंसा को पहचानने में असमर्थता में प्रमुख भूमिका निभाते हैं'। जब उनसे पूछा गया कि 'हिंदू राष्ट्रवाद जैसी श्रेष्ठतावादी विचारधाराओं' से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, तो उन्होंने अपनी पुस्तक 'माई सन्स इनहेरिटेंस: ए सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ लिंचिंग एंड ब्लड जस्टिस इन इंडिया' में दिए गए संदेश को समझाया।

हमारे ऐतिहासिक हिंसा का परिणाम... एक रहस्य के रूप में हमारे सामने आता है, एक ऐसा रहस्य जो सबके सामने होते हुए भी छिपा हुआ है। यह दिखाई देता है, फिर भी हम इसे नहीं देख पाते। जब यह रहस्य

उजागर हो जाएगा, तभी प्रायश्चित या मुक्ति का प्रश्न उठेगा: हम स्वयं को कैसे मुक्त करें? हम कैसे प्रायश्चित करें?... प्रायश्चित तभी संभव है जब भारतीय सबसे पहले अपने हिंसा के इतिहास को स्वीकार करें। हमारे पास दो विकल्प हैं: या तो अपनी शर्म को छुपाकर और भी हिंसा को बढ़ावा दें, या फिर अपने ऐतिहासिक शर्म को स्वीकार करके हिंसा पर चुप्पी तोड़ें। क्योंकि विशेषाधिकार से उपजी हमारी यही चुप्पी हिंसा को कायम रखती है।

इस प्रश्न के उत्तर में कि, 'आपको क्या लगता है कि भारत में उच्च जाति और मध्यम वर्ग अल्पसंख्यकों और शोषितों के प्रति सहानुभूति क्यों नहीं रखते?' वह कहती हैं:

'गरीब ब्राह्मण' की मिथक को समझना होगा। यहाँ ब्राह्मण शब्द एक ऐसे सवर्ण के लिए रूपक है जिसकी सामाजिक पूंजी अपर्याप्त आर्थिक पूंजी से संतुलित हो जाती है और ... जीवन निर्वाह की रेखा से नीचे गिरने का खतरा रहता है। जन्म के कारण उसे एक असमान परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, जिसे उसे कड़ी मेहनत, ईमानदारी और अपनी जन्मजात योग्यता से पार करना होता है – और वह भी बिना हिंसा का सहारा लिए। स्वतंत्र भारत में जाति आधारित आरक्षण और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के प्रावधानों ने उसके जीवन को और भी बदतर बना दिया। उसे सामाजिक सम्मान प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, जबकि अन्य लोग जाति आधारित आरक्षण की सहायता से तेजी से आगे बढ़ गए। ... सबसे गरीब ब्राह्मण को कभी भी सिर पर मल ढोना, सीवेज साफ करना, पशुओं के शव हटाना या गाँव के बाहरी इलाकों में रहना नहीं पड़ा। उसे कभी भी गाँव के कुएँ से पानी लेने से नहीं रोका गया। ... उसकी परछाई ने कभी किसी दूसरे इंसान को अपवित्र नहीं किया। यह मिथक गरीब ब्राह्मण के जातिगत विशेषाधिकार को अनदेखा कर देता है और उसे

ऐतिहासिक पीड़ित होने की भावना को कायम रखता है। भारत के बहुसंख्यक समुदाय के सामूहिक अचेतन के रूप में यह मिथक उन्हें उत्पीड़न को अनदेखा करने के लिए मजबूर करता है।

भारतीय इतिहास को फिर से लिखने की उनकी इस परियोजना के पीछे की प्रेरणा को देखते हुए, यह उम्मीद की जा सकती है कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों को उनके ही साथी नागरिकों के खिलाफ विभाजनकारी आख्यान परोसा जाएगा।

हमारा अगला उदाहरण अशोका की विकास अर्थशास्त्र की फेलो दुर्बा चट्टराज का है, जिन्होंने हाल ही में "भारत खुले में शौच मुक्त होने के लिए संघर्ष क्यों कर रहा है" विषय पर लेख लिखा है, और इसका दोष हिंदू धर्म में अनुष्ठानिक पवित्रता की मान्यताओं और सभी बुराइयों की जड़ - जाति व्यवस्था पर डाला है। वह इस बात पर पश्चिमी शोध का हवाला देती हैं कि हिंदू कैसे और क्यों शौच करते हैं:

कई विद्वानों ने हिंदू जाति व्यवस्था के अनुसार खुले में शौच करने की प्रथाओं का विश्लेषण किया है... डीन स्पीयर्स और माइकल गेरुसो द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि भारत में हिंदू, मुसलमानों की तुलना में शौचालयों का उपयोग बहुत कम करते हैं। हिंदुओं और मुसलमानों की शौचालयों की मांग में यह अंतर धन के सभी स्तरों पर देखा गया। ये निष्कर्ष 5% स्तर पर महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा, हिंदुओं में घर से दूर शौच करने को पवित्र मानने की संभावना अधिक थी।

2021 में, अशोका के राष्ट्रीय कोविड-19 पैनल के वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक संपादकीय लेख लिखकर भारत में महामारी के लिए मोदी सरकार की आलोचना की। हालांकि, अन्यत्र यह बताया गया है कि उनकी भविष्यवाणियां त्रुटिपूर्ण थीं और वे भारत के स्वदेशी टीके की विश्वसनीयता को कम करना चाहते थे।

अशोका के योगदान का एक अन्य उदाहरण पत्रकार माया मिर्चांदानी का लेख है, जो अब अशोका विश्वविद्यालय में मीडिया अध्ययन विभाग की प्रमुख हैं, जिसमें उन्होंने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल द्वारा नागरिक समाज पर युद्ध छेड़ने की निंदा की है।
अब हम अशोका विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर और आर्थिक डेटा एवं विश्लेषण केंद्र की निदेशक अश्विनी देशपांडे के कार्यों का अध्ययन करेंगे। यह उदाहरण अशोका विश्वविद्यालय की भारत का हार्वर्ड बनने की चाहत में निहित समस्या को दर्शाता है। देशपांडे कहती हैं कि वह भारत में भेदभाव के अर्थशास्त्र पर काम कर रही हैं, जिसमें जाति, लिंग और सकारात्मक कार्रवाई नीतियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। वह कार्यबल में महिलाओं की कम भागीदारी दर को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करती हैं और इसका कारण पारंपरिक लिंग भूमिकाओं और उपयुक्त नौकरियों की अनुपलब्धता को मानती हैं।
हमारा कहना है कि अमेरिका में महिलाओं को कार्यस्थल पर धकेलने के ऐसे प्रयोगों के परिणामस्वरूप टूटे हुए परिवार, अवसाद की उच्च दर, आत्महत्याएं, तलाक, बलात्कार और एकल माता-पिता द्वारा बच्चों का पालन-पोषण जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। पश्चिमी देशों को महिलाओं के कल्याण के मामले में आदर्श नहीं माना जा सकता। इसलिए, भारत द्वारा महिलाओं के लिए पश्चिमी मानदंडों को किस हद तक अपनाया जाए, यह व्यक्तिगत पसंद का विषय होना चाहिए। सांस्कृतिक भिन्नताओं को देखते हुए सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है। अमेरिकियों को मानदंड निर्धारित करने, परिणामों का आकलन करने और निर्णय सुनाने की अनुमति देना अनुचित है। हम इसे एक ऐसा मुद्दा मानते हैं जिसे भारतीय समाज को अपने तरीके से हल करना होगा। यदि महिलाएं काम करना चाहती हैं तो उन्हें काम करने से रोकने वाला कोई कानून नहीं है।

आजीविका कमाने के लिए काम करने वाली गरीब महिलाओं का प्रतिशत इस बात का प्रमाण है कि महिलाओं को अपनी इच्छा अनुसार इस विकल्प का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है।

भारतीय समाज ने यह सिद्ध कर दिया है कि उसमें वह संरचना, बुद्धिमत्ता, लय और संतुलन है जो बाहरी हस्तक्षेप के बिना परिवर्तन को सुगम बनाता है। व्यवस्था थोपने पर आधारित पश्चिमी संस्कृतियाँ विकल्पों को सीमित करने की प्रवृत्ति रखती हैं और परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में कम सक्षम होती हैं। भारतीय संस्कृति संयुक्त परिवार संरचना, बुजुर्गों की देखभाल, छोटे बच्चों की देखभाल, पारिवारिक परंपराओं और संस्कृति का पालन, पारिवारिक व्यवसाय में श्रम विभाजन, जिम्मेदारियों का विभाजन जहाँ एक व्यक्ति कमाने वाला होता है और दूसरा गृहिणी, जैसे कारकों को अधिक सहजता से अपनाती है। ये सभी वैध कारण हैं जिनकी वजह से महिलाएं कार्यबल में शामिल न होने का विकल्प चुन सकती हैं। भारतीय संस्कृति अलग है, और भारत को अपनी इस विशिष्टता पर गर्व करने का पूरा अधिकार है।

भारतीय महिलाओं के मामलों में इस तरह का हस्तक्षेप उनकी परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यह उनकी बुद्धिमत्ता का अपमान करता है और जीवनशैली चुनने के उनके अधिकार का उल्लंघन करता है। लेकिन यह विशेष रूप से चिंता का विषय तब बन जाता है जब विदेशी वित्त पोषित एजेंसियां, जिनका कोई नैतिक आधार या जवाबदेही नहीं है, भारत पर चर्चा को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ऐसे प्रयोग करती हैं। एक बार जब उनकी प्रणालियां और मानक स्थापित हो जाते हैं, तो वे दुनिया में कहीं से भी नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं और भारत के सुदूरतम गांवों तक इसके प्रभावों की निगरानी और प्रबंधन कर सकते हैं। और वे तुरंत मूल्यांकन

करके निर्णय सुना सकते हैं।
अश्विनी देशपांडे उन जमीनी कार्यकर्ताओं का एक उदाहरण हैं जो भारत को बाहरी ताकतों के प्रति संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देशपांडे 'द वायर' पत्रिका में जातिगत मुद्दों पर नियमित रूप से लिखती हैं और ब्रिटेन में कानून के तहत जाति को भेदभाव की श्रेणी के रूप में मान्यता देने का समर्थन करती हैं। वह भारतीय प्रवासियों पर भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव का आरोप लगाती हैं, जिसे वह नस्लवाद का एक रूप मानती हैं।
उन्हें हार्वर्ड द्वारा चीन के हार्वर्ड शंघाई सेंटर में भारत और योग्यतावाद पर बोलने के लिए भी आमंत्रित किया गया था। लेकिन शंघाई में उनके भारत-विरोधी योगदानों पर चर्चा करने से पहले, हम हार्वर्ड की चीन अध्ययन पहल के साथ अशोका के जुड़ाव की थोड़ी पृष्ठभूमि प्रस्तुत करेंगे।

चीन अध्ययन केंद्र
चीन ने विश्व मंच पर अपनी प्रमुखता का इस्तेमाल भारतीय शिक्षण संस्थानों को कमजोर करने और उन्हें खरीदने के प्रयासों को तेज करने के लिए किया है, ठीक वैसे ही जैसे वह अमेरिका में कर रहा है। हम उन भारतीयों पर कोई व्यापक फैसला नहीं सुनाना चाहते जो किसी न किसी तरह से इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से अनजाने में हो सकता है या भारत-चीन मित्रता के अतीत का अवशेष हो सकता है। हम केवल उन जोखिमों की ओर इशारा कर रहे हैं जिनका वर्तमान भू-राजनीतिक संदर्भ में मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। हमारी चिंता यह है कि अशोका का इस्तेमाल चीन द्वारा भारत में प्रवेश करने के लिए किया जा सकता है:

भारत में युवा चीन अध्ययन विद्वानों को प्रशिक्षित करना;
भारत भर के विश्वविद्यालयों में चीन अध्ययन विभाग स्थापित करें; और
भारत में चीन अध्ययन के विमर्श को नियंत्रित करें
सतही तौर पर, अशोका के सेंटर फॉर चाइना स्टडीज (ACCS) के लक्ष्य नेक इरादे वाले प्रतीत होते हैं:
यह केंद्र चीन अध्ययन के लिए अकादमिक अनुसंधान फोकस और रणनीति निर्धारित करेगा, पाठ्यक्रम और डिग्री कार्यक्रम विकसित करेगा, और संकाय और छात्रों के लिए शैक्षिक आदान-प्रदान को सुगम बनाएगा, और अशोका में एक केंद्र की स्थापना के माध्यम से भारत के प्रमुख संस्थानों में चीन अध्ययन के विकास में सहयोग करेगा।
लेकिन चीन जैसी समस्याग्रस्त स्थिति के संबंध में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, विदेशी प्रभावों से इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए अधिक सावधानी बरतनी चाहिए।
चीन मौजूदा संस्थागत ढांचे का फायदा उठाकर भारत में घुसपैठ कर सकता है, जिसकी व्याख्या भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन की भूमिका से की जा सकती है, जो ACCS के अध्यक्ष हैं। पिछले वर्षों में यह सामान्य बात होती, लेकिन चीन से संबंधित हाल की भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण इस पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। मेनन ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन में विदेश नीति के एक प्रतिष्ठित फेलो हैं। ब्रूकिंग्स चीन की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) से प्रभावित है, और जैसा कि अध्याय 8 में बताया गया है, अमेरिकी भी अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभावों को लेकर चिंतित हैं।
सेवानिवृत्ति के बाद, मेनन को हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में फिशर फैमिली फेलो बनाया गया, जो सरकारी निर्णयों और नीति निर्माण को प्रभावित करता है। वे नई दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज (ICS) के

सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, जिसे भारतीय विदेश मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है। इनमें से कोई भी बात मेनन या अन्य लोगों की ओर से किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि का संकेत नहीं देती है। इसके अलावा, प्रताप भानु मेहता ने अशोका विश्वविद्यालय के कुलपति पद से इस्तीफा देने से पहले, आईसीएस में गवर्निंग काउंसिल के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था, और वे अभी भी इस पद पर बने हुए हैं। यह निष्कर्ष निकालना शायद गलत नहीं होगा कि आईसीएस का अशोका के चीनी अध्ययन केंद्र से निकलने वाले शोध पर कुछ हद तक नियंत्रण है, क्योंकि यह उनके कई विद्वानों को नियमित रूप से अतिथि शोध सहयोगी के रूप में सहायता प्रदान करता है।

हार्वर्ड-येनचिंग इंस्टीट्यूट (HYI) का संबंध प्रभाव का एक और माध्यम है। इस संस्थान की शुरुआत एक ईसाई मिशनरी संगठन के रूप में हुई थी, जिसकी स्थापना 1928 में चार्ल्स एम. हॉल की संपत्ति से हुई थी। हॉल एक व्यवसायी थे जिन्होंने एशिया में अमेरिकी प्रोटेस्टेंट मिशनरी कॉलेजों की स्थापना की थी। 1940 के दशक के उत्तरार्ध से लेकर 1950 के दशक तक, चीनी कम्युनिस्ट सरकार ने चीनी शैक्षणिक संस्थानों पर विदेशी नियंत्रण समाप्त कर दिया था। लेकिन हॉल के ईसाई मिशन के कारण, HYI के कम से कम तीन ट्रस्टी अभी भी यूनाइटेड बोर्ड फॉर क्रिश्चियन हायर एजुकेशन इन एशिया से हैं, जो एक गैर-लाभकारी संस्था है और दावा करती है कि वह 'अपनी ईसाई पहचान और मूल्यों और एशियाई कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के साथ अपने सहयोग से शक्ति प्राप्त करती है'। यूनाइटेड बोर्ड ने एशिया के पंद्रह देशों में अस्सी कॉलेजों को वित्त पोषित किया है।

आज, HYI में भारत अध्ययन और चीन अध्ययन दोनों के लिए छात्रवृत्तियाँ चीन सरकार के नियंत्रण में स्थित प्रमुख चीनी विश्वविद्यालयों

द्वारा 'सहायता' प्रदान की जाती हैं। HYI में भारतीय छात्रों और विद्वानों के लिए दो कार्यक्रम हैं: एक डॉक्टरेट छात्रवृत्ति और एक पोस्टडॉक्टरेट छात्रवृत्ति। यह अशोका विश्वविद्यालय से सीधे पोस्टडॉक्टरेट उम्मीदवारों की भर्ती करता है, जबकि डॉक्टरेट छात्रवृत्ति हार्वर्ड-येनचिंग संस्थान और दिल्ली स्थित चीनी अध्ययन संस्थान के बीच एक साझेदारी है जिसका उद्देश्य 'भारत में चीनी अध्ययन को प्रोत्साहित करना' है।

चीन के आठ भागीदार संस्थानों की भागीदारी से संचालित यह कार्यक्रम, हार्वर्ड-येनचिंग संस्थान में भारतीय अध्ययन के विद्वानों को लाकर एक अंतर-राष्ट्रीय नेटवर्क को बढ़ावा देना चाहता है। HYI में, HYI के 'चीनी अध्ययन भारत कार्यक्रम' (दिल्ली स्थित चीनी अध्ययन संस्थान के साथ संयुक्त डॉक्टरेट फेलोशिप कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य भारत में चीनी अध्ययन को प्रोत्साहित करना है) के चयनित उम्मीदवार भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के मेजबान चीनी संस्थानों (बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी, ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी, फुदान यूनिवर्सिटी, पेकिंग यूनिवर्सिटी, सिचुआन यूनिवर्सिटी और युन्नान यूनिवर्सिटी) को भारतीय अध्ययन के क्षेत्र में कुछ उत्कृष्ट डॉक्टरेट छात्रों या युवा संकाय सदस्यों को HYI में विजिटिंग फेलो या विजिटिंग स्कॉलर के रूप में आमंत्रित करने का अनुरोध किया जाएगा। चयनित उम्मीदवार एक वर्ष के प्रवास के लिए हार्वर्ड-येनचिंग संस्थान में अपने भारतीय समकक्षों के साथ जुड़ेंगे।

HYI कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए, अशोका ने नोएडा स्थित शिव नादर विश्वविद्यालय, बेंगलुरु स्थित क्राइस्ट विश्वविद्यालय (यूनाइटेड बोर्ड ऑफ क्रिश्चियन हायर एजुकेशन द्वारा समर्थित), आईआईएम शिलांग, मुंबई स्थित सोमैया विद्याविहार विश्वविद्यालय, अहमदाबाद विश्वविद्यालय और कोलकाता स्थित जादवपुर विश्वविद्यालय को अपने साथ जोड़ा है।

अशोका और HYI दो वर्षीय पोस्टडॉक्टोरल फैलोशिप प्रदान करते हैं। यह सब अपने आप में कोई समस्या नहीं है और हम केवल भारत की उच्च शिक्षा में चीन की व्यापक उपस्थिति को दर्शाना चाहते हैं। चीन के अधिकारियों से कई संबंध अप्रत्यक्ष हैं, लेकिन उन पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है।

शंघाई मेरिटोक्रेसी कार्यशाला

अशोका-हार्वर्ड संबंध से उभरने वाली विद्वत्ता का एक उदाहरण यह है कि हार्वर्ड ने चीन और भारत में योग्यता के महत्व पर चर्चा करने के लिए शंघाई, चीन में एक कार्यशाला का आयोजन किया। अशोका विश्वविद्यालय की अश्विनी देशपांडे, हार्वर्ड के अजंता सुब्रमणियन, हार्वर्ड के पूर्व कैनेडी फेलो आशुतोष वर्शनी, पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के देवेश कपूर और मदन लाल सोबती सहित कई भारतीय विद्वानों ने इसमें भाग लिया। भारतीय और चीनी विशेषज्ञों के बीच का अंतर स्पष्ट था। जहां चीनी विशेषज्ञों ने चीन की महानता और गौरव के निर्माण में योग्यता की भूमिका पर गर्व व्यक्त किया, वहीं भारतीय प्रतिभागियों ने भारत के संदर्भ में योग्यता को शर्मनाक बताकर उसे बदनाम करने का प्रयास किया।

चीन के विशेषज्ञों ने बताया कि योग्यता पर आधारित चीनी परीक्षा प्रणाली अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध थी, जिसे बाकी दुनिया अनुकरण करना चाहती थी। उन्होंने योग्यता प्रणाली के इतिहास पर शोध पत्र प्रस्तुत किए और बताया कि चीनी सम्राटों द्वारा नौकरशाहों का चयन पूरी तरह से प्रदर्शन-आधारित था। एक शोध पत्र में योग्यता के आधार पर वैश्विक स्तर पर चीनी विश्वविद्यालयों के हालिया उत्थान पर चर्चा की गई। एक अन्य शोध पत्र में 'पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना से

लेकर वर्तमान समय तक की प्रमुख शिक्षा नीति और योजना दस्तावेजों' का विश्लेषण किया गया। एक अन्य शोध पत्र तांग राजवंश पर केंद्रित चीन में योग्यता प्रणाली के इतिहास पर था।

भारतीय पक्ष का दृष्टिकोण बिल्कुल विपरीत था। भारतीय विद्वान शंघाई गए और उन्होंने चीनी विद्वानों को बताया कि भारतीय संदर्भ में योग्यता प्रणाली कितनी अनुचित है, उन्होंने जाति आधारित उत्पीड़न का हवाला देते हुए बताया कि यह हिंदू समाज का एक व्यवस्थित उत्पीड़न है। यह अध्याय 4 में विश्लेषित अजंता सुब्रमण्यम के कार्यों से मेल खाता है। आशुतोष वार्ष्णेय ने योग्यता को एक सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में समर्थन देते हुए कहा: 'समावेशी सिद्धांतों को लागू करने पर भी, योग्य व्यक्तियों को उनका उचित महत्व दिया जाना चाहिए।' शिक्षा जगत में, उन्होंने यह सवाल उठाया कि क्या योग्यता का अर्थ 'शैक्षणिक प्रदर्शन' होना चाहिए, या 'शैक्षणिक उपलब्धि की परवाह किए बिना प्रदर्शन करने और परिणाम देने की क्षमता', और क्या शैक्षणिक उत्कृष्टता को सामाजिक बुद्धिमत्ता से पूरक करने की आवश्यकता है। इन विरोधाभासों के समाधान के अभाव में, उन्होंने स्वीकार किया कि शैक्षणिक उपलब्धि ही योग्यता मापने का एकमात्र मापदंड है।

वर्षने ने आगे बताया कि यह सामान्य नियम भारत पर लागू नहीं होता। उन्होंने भारत में जाति व्यवस्था का मुद्दा उठाया, जिसे उन्होंने सच्ची योग्यता प्राप्त करने में एक बाधा बताया। दूसरे शब्दों में, भारत के मामले में, योग्य व्यक्तियों को महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि ऐतिहासिक रूप से, जाति-आधारित श्रम विभाजन ने लोगों को ऐसे व्यवसायों में धकेल दिया जो उनकी आकांक्षाओं या क्षमताओं को प्रतिबिंबित नहीं करते थे। उन्होंने कहा: 'भारत में योग्यता का मूल अर्थ वंशानुगत सामाजिक पदानुक्रमों का पुनरुत्पादन हो गया है, एक ऐसा विचार जिसे लोकतंत्र

बर्दाश्त नहीं कर सकता।'
इसके बाद उन्होंने जातिगत उत्पीड़न की तुलना अमेरिका में नस्लवाद से की। श्रम विभाजन को 'सख्ती से विनियमित' किया गया था और हिंसा के बल पर लागू किया गया था: 'यदि इसका उल्लंघन किया जाता था, तो सामाजिक व्यवस्था, जिसे अक्सर कानूनी रूप से समर्थन प्राप्त होता था, हिंसा के बल पर लागू की जाती थी, जो अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद के जिम क्रो अमेरिकी दक्षिण के समान थी।' [51]
उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं में उच्च जाति के वर्चस्व की समस्या से निपटने की क्षमता पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने टिप्पणी की, 'क्या केवल उच्च जातियां ही मेधावी हैं?'
वर्षने ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में समावेशन और निजी क्षेत्र में योग्यता के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए कहा: 'समावेशनकारी परियोजनाएं मूल रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के कामकाज की विशेषता हैं, जबकि योग्यता का विचार, सिद्धांत रूप में, निजी क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया है।'
अश्विनी देशपांडे ने दावा किया कि निजी क्षेत्र कुछ जातियों के साथ भेदभाव करता है:
इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि आर्थिक परिणामों और व्यावसायिक उपलब्धियों में जातिगत असमानताएँ न तो मुख्य रूप से अतीत की विरासत हैं और न ही मुख्य रूप से शिक्षा या कौशल की कमी का परिणाम हैं। इसलिए, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों को रोजगार के मामले में खराब स्थिति का सामना करना पड़ेगा, भले ही वे उच्च जातियों के समान ही योग्य हों, क्योंकि श्रम (रोजगार) बाजारों में भेदभाव मौजूद है।
क्रिटिकल रेस थ्योरी के सिद्धांतों के अनुरूप, देशपांडे ने कहा कि परिणामों में अंतर का कारण केवल अंतर्निहित पक्षपातपूर्ण व्यवस्था ही हो सकती

है। इसे साबित करने के लिए, उन्होंने दावा किया कि 'शिक्षक निम्न जाति और महिला द्वारा चिह्नित उत्तरपत्रों को उच्च जाति और पुरुष द्वारा चिह्नित उत्तरपत्रों की तुलना में कम अंक देते थे।' उन्होंने आगे सुझाव दिया कि आवेदकों की 'पारिवारिक पृष्ठभूमि' की जाँच के बहाने, नियोक्ता जाति-आधारित भेदभाव करते हैं।

यह तथ्य कि दोनों समूह श्रम बाजार में "क्षमता" या "योग्यता" में पर्याप्त अंतर के साथ प्रवेश करते हैं, "बाजार-पूर्व भेदभाव" को इंगित करता है, जिसका अर्थ है कि प्रारंभिक बचपन के विकास में भेदभावपूर्ण कारक कार्यरत हैं।

देशपांडे का मानना है कि योग्यता कोई 'तटस्थ, वस्तुनिष्ठ विशेषता नहीं है, जो इसे मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक से स्वतंत्र हो, जैसे कि ऊंचाई, वजन या दांतों की संख्या'। इसलिए उन्होंने परीक्षा की अवधारणा पर ही संदेह जताते हुए इस धारणा पर सवाल उठाया कि परीक्षा में प्रदर्शन योग्यता का सूचक है।

निम्न जातियों के लिए आरक्षित कोटा का उपयोग करके विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने वाले छात्रों पर चर्चा करते हुए, उन्होंने कहा कि उनके कम प्रदर्शन का कारण 'सूक्ष्म आक्रामकता' से निपटने में असमर्थता के कारण होने वाला मनोवैज्ञानिक आघात है। उनका अंतिम निष्कर्ष यह था कि...

"पारिवारिक पृष्ठभूमि", एक व्यापक शब्द है जो वर्ग, जाति, माता-पिता की पृष्ठभूमि और सामाजिक नेटवर्क के परस्पर जुड़े प्रभाव को समाहित करने के लिए बनाया गया है, और यह व्यक्तिगत योग्यता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक बना हुआ है, जिससे अवसर की समानता या निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का माहौल स्थापित करना - योग्यता-आधारित व्यवस्था की बुनियादी शर्तें - हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है।

वर्षने और देशपांडे दोनों ने भारतीय संदर्भ में योग्यता को दिखावा माना

और निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए आरक्षण का प्रस्ताव रखा। हम निम्न जाति के छात्रों की योग्यता पर कोई निर्णय नहीं दे रहे हैं, बल्कि शिक्षा जगत में जाति-नस्ल-लिंग के पैरोकारों के गुट द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ही सामने रख रहे हैं।

हम एक ऐसी वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रक्रिया के पक्षधर हैं जो सभी छात्रों को, उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, अपनी योग्यता साबित करने का अवसर प्रदान करे। हमारा यह भी मानना है कि यद्यपि सकारात्मक कार्रवाई कुछ वर्षों के लिए असंतुलन को दूर करने में लाभकारी हो सकती है, लेकिन अनिश्चित काल तक जारी रहने पर इसका लाभ कम हो जाता है, क्योंकि इससे युवाओं में विशेषाधिकार की भावना पैदा होती है जो उन्हें परिश्रम और मेहनत के महत्व को कम आंकने के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा, जनसंख्या के एक वर्ग को विस्तारित संरक्षण वास्तव में उन्हें कमजोर बनाता है क्योंकि इस प्रक्रिया में कई कौशल नष्ट हो जाते हैं और वे आत्मनिर्भर बनने में असमर्थ हो जाते हैं। अध्याय 6 में, हमने भारत के निम्न जाति समूहों के कई उदाहरण दिए हैं जिन्होंने अच्छे नेताओं और आंतरिक प्रयासों के बल पर सामाजिक-आर्थिक सीढ़ी पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की है। इनमें से कोई भी उदाहरण अशोक के जाति संबंधी विवेचनाओं में शामिल नहीं है।

हार्वर्ड की अजंता सुब्रमणियन ने 'योग्यता और जाति' शीर्षक से एक शोधपत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने अपनी पुस्तक के उस सिद्धांत को दोहराया जिसकी हमने अध्याय 4 में आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि योग्यता 'जातिगत भेदभाव के उन रूपों को संदर्भित करती है जिनका सामाजिक अस्तित्व कहीं अधिक लंबा है'। उनका प्रस्तुतीकरण इस तर्क पर केंद्रित था कि तकनीकी विज्ञान शिक्षा में जाति का पुनर्गठन होता है और योग्यता-आधारित व्यवस्था विशेषाधिकार पर आधारित असमानता

को जन्म देती है।
अंत में, देवेश कपूर का विषय था "पदानुक्रमित और असमान समाज में चयन तंत्र और योग्यता-आधारित व्यवस्था: भारतीय उच्च शिक्षा"। उन्होंने कहा कि योग्यता-आधारित व्यवस्था सुनने में तो बहुत अच्छी और निष्पक्ष लगती है, लेकिन भारतीय संदर्भ में जाति व्यवस्था के कारण यह असमानताओं को और बढ़ा देती है। उन्होंने कोई नए विचार प्रस्तुत नहीं किए, बल्कि विशेषाधिकार, असमानता और जाति से संबंधित उन्हीं पुराने विचारों को दोहराया। उन्होंने कहा कि योग्यता-आधारित व्यवस्था का निष्पक्ष होना एक मिथक है, क्योंकि इससे समान परिणाम नहीं मिलते। वास्तव में, उनका मानना था कि "लोकतंत्रों में असमानता के प्रति जो उच्च स्तर की सहनशीलता है, उसका कुछ कारण योग्यता-आधारित व्यवस्था के इस मिथक का औचित्य सिद्ध करना भी हो सकता है।" अशोका विश्वविद्यालय आईआईटी, आईआईएम, द इंडस एंटरप्रेन्योर्स और कई अन्य संस्थानों से योग्यता-समर्थक विचारकों को शामिल करके भारतीय पैनल को आसानी से संतुलित कर सकता था, जो भारत की योग्यता-आधारित प्रणाली पर गर्व करते हैं।
भारत और चीन में योग्यता-आधारित व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। चीनी तिब्बत या उइगरों जैसे सामाजिक मुद्दों का ज़िक्र तक नहीं करते, जबकि भारतीय अपने देश में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को उजागर करने में लगे रहते हैं। हम ठोस उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे भारत को अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय, अपने ही उदार कला विश्वविद्यालयों और चीन जैसे देशों में तब निशाना बनाया जाता है जब भारतीयों को बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

त्रिवेदी सेंटर फॉर पॉलिटिकल डेटा

विदेशी संस्थाओं के सहयोग से, अशोका का त्रिवेदी सेंटर फॉर पॉलिटिकल डेटा (टीसीपीडी) भारत से संबंधित संवेदनशील डेटाबेस तैयार करता है, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। यह राजनीतिक और कंप्यूटर वैज्ञानिकों की एक संयुक्त परियोजना है। इसके कार्यकारी बोर्ड में अशोका के संस्थापक आशीष धवन और अशोक त्रिवेदी, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी, राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर गाइल्स वर्नियर्स (फ्रांस से) और कंप्यूटर विज्ञान के प्रोफेसर सुधींद्र हंगल शामिल हैं।

त्रिवेदी केंद्र का वैज्ञानिक बोर्ड परियोजना की परिकल्पना, अकादमिक मार्गदर्शन और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इसमें विदेशी विद्वानों (मुख्यतः फ्रांसीसी और अमेरिकी) और कुरैशी विद्वानों का वर्चस्व है। लंदन के किंग्स कॉलेज के क्रिस्टोफ़ जैफ्रेलॉट इस प्रयास का नेतृत्व करते हैं। नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स की फ्रांसेस्का आर. जेन्सिनियस, कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के मिलान वैष्णव, नोट्रे डेम विश्वविद्यालय की सुसान एल. ओस्टरमैन, यूपीएन के तारिक थाचिल और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की मुकुलिका बनर्जी वैज्ञानिक बोर्ड के सदस्य हैं।

पेरिस इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल स्टडीज (साइंसेज पो) और फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एलआईए स्पिनपर जैसे फ्रांसीसी संस्थान, यूपीएन, मिशिगन विश्वविद्यालय, नोट्रे डेम विश्वविद्यालय जैसे अमेरिकी विश्वविद्यालयों और कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल पीस जैसे थिंकटैंक के साथ मिलकर टीसीपीडी में अनुसंधान को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख भागीदार हैं। त्रिवेदी केंद्र भारत में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च और द हिंदुस्तान टाइम्स जैसे संगठनों के साथ घरेलू साझेदारी भी विकसित कर रहा है। इसके शोध पत्र नियमित रूप से वामपंथी प्रकाशनों में प्रकाशित

होते हैं।
त्रिवेदी केंद्र भाजपा के उदय का अध्ययन करने के लिए बिग डेटा/मशीन लर्निंग और एआई तकनीक का उपयोग कर रहा है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि डेटाबेस का उपयोग भारत में चुनावी परिणामों को प्रभावित करने के प्रयासों में किया जा सकता है, जिसमें संभावित रूप से विदेशी प्रभाव भी शामिल हैं।
यह संस्थान 1962 से लेकर अब तक के चुनावी प्रणाली और शासन में भाग लेने वाले लोगों, परिणामों और उम्मीदवारों से संबंधित व्यापक डेटा एकत्र कर रहा है। 'विधायकों का सामाजिक प्रोफाइलिंग' परियोजना के तहत, धर्म, जाति, लिंग, भाषा, शिक्षा, व्यवसाय और अन्य जनसांख्यिकीय आंकड़ों का विस्तृत संग्रह और सत्यापन किया जा रहा है। इससे उन्हें भारतीय राजनीतिक परिदृश्य को समझने और वांछित दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिलती है। बड़ी मात्रा में भिन्न-भिन्न डेटा को साफ-सुथरा और व्यवस्थित करके भारतीय और विदेशी शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराया जाता है। वेबसाइट के अनुसार, संस्थान
इसका उद्देश्य भारत के राजनीतिक जीवन पर डेटा-आधारित अनुसंधान, नीतिगत कार्य और पत्रकारिता को बढ़ावा देना है, जिसके लिए वैज्ञानिक रूप से एकत्रित और संसाधित राजनीतिक डेटा को सार्वजनिक पहुंच में उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही, भारतीय डेटा के अनुकूल वेब-आधारित उपकरण विकसित करके और उनकी पहुंच प्रदान करके मौजूदा सार्वजनिक डेटा की गुणवत्ता में सुधार करना भी इसका लक्ष्य है।

त्रिवेदी केंद्र के पीछे के लोग और संस्थाएँ
हम त्रिवेदी केंद्र चलाने वाले कुछ प्रमुख सदस्यों की पृष्ठभूमि का संक्षेप में

पता लगाएंगे ताकि यह दिखाया जा सके कि इसके डेटाबेस माइनिंग गतिविधियों को संचालित करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण और परिप्रेक्ष्य काम करता है।

क्रिस्टोफ़ जैफ़्रेलॉट

त्रिवेदी केंद्र के अध्यक्ष, फ्रांसीसी मूल के क्रिस्टोफ़ जैफ़्रेलॉट, कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में अनिवासी फेलो भी हैं, साथ ही मिलान वैष्णव, जो कार्नेगी एंडोमेंट के दक्षिण एशिया कार्यक्रम में निदेशक और वरिष्ठ फेलो हैं। कार्नेगी एंडोमेंट पर सीसीपी के साथ घनिष्ठ संबंध होने का आरोप है।

कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस - जिसका नेतृत्व पहले जो बाइडेन की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के निदेशक बिल बर्न्स करते थे - ने बर्न्स द्वारा अमेरिकी सीनेट के समक्ष शपथपूर्वक दिए गए बयान के विपरीत दावों के बावजूद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभावशाली समूहों के साथ अपने संबंध जारी रखे हैं।

टीसीपीडी के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका के अलावा, जैफ़्रेलॉट पेरिस स्थित इसके वर्तमान फ्रांसीसी सहयोगी सीईआरआई-साइंसेज पो/सीएनआरएस में भारत के डेटाबेस का विश्लेषण करने वाले फेलो और लंदन स्थित किंग्स इंडिया इंस्टीट्यूट में भारतीय राजनीति और समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं। आरएसएस पर हमले करने का उनका एक सुप्रसिद्ध इतिहास है और उन्होंने भारत में हिंदू राष्ट्रवाद और जाति-आधारित आंदोलनों पर कई पुस्तकें लिखी हैं। वे 'वैश्विक हिंदुत्व विघटन' सम्मेलन में एक प्रमुख प्रतिभागी थे। उन्होंने लिखा: 'बेरोजगार आम लोग बजरंग दल और इसी तरह के अन्य गुंडा संगठनों में शामिल हो गए और गाय के लिए लड़कर अपनी पहचान बनाने लगे।' उनके कुछ कार्यों की सूची अंत टिप्पणी में दी गई है।

इंडियन एक्सप्रेस ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि वे 'दक्षिण एशियाई राजनीति, विशेष रूप से भारत में हिंदू दक्षिणपंथियों के तौर-तरीकों और प्रेरणाओं पर बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं'।[69] इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे खुद को भारतीय मुसलमानों की आवाज के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

कार्नेगी के भारत विशेषज्ञ मिलान वैष्णव ने कई ऐसे लेख लिखे हैं जो उनके राजनीतिक पूर्वाग्रह को उजागर करते हैं। (अंत में दी गई सूची देखें।)

गिल्स वर्नियर्स

फ्रांसीसी नागरिक गाइल्स वर्नियर्स, जैफ्रेलॉट के छात्र और अशोका के टीसीपीडी में राजनीति विज्ञान के सहायक प्रोफेसर हैं। अशोका से पहले, वर्नियर्स ने भारत में साइंसेज पो के डेटा माइनिंग कार्य के लिए सभी स्तरों पर भारतीय छात्रों की भर्ती की थी। उन्होंने भारतीय सिविल सेवकों के लिए कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रम भी विकसित किए हैं और थिंकटैंक, कॉरपोरेट और मीडिया के लिए काम किया है।

S.Y. Quraishi

भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी, त्रिवेदी केंद्र के कार्यकारी और वैज्ञानिक बोर्ड के सदस्य हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान (IDEA) में लोकतंत्र के राजदूत भी हैं, जो एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसका मिशन 'विश्व स्तर पर सतत लोकतंत्र का समर्थन करना' है। वे त्रिवेदी केंद्र को विश्वसनीयता के साथ-साथ बड़े डेटा संग्रह के लिए संपर्क भी प्रदान करते हैं।

अपनी पुस्तक, 'द पॉपुलेशन मिथ: इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया' पर चर्चा करते हुए, कुरैशी ने अपने कुछ विवादास्पद विचार खुलकर व्यक्त किए, जैसे कि 'मुसलमान हिंदुओं की

तुलना में परिवार नियोजन को तेजी से अपना रहे हैं' और 'यह एक मिथक है कि भारत में बहुविवाह व्यापक रूप से प्रचलित है'। मुसलमानों के समर्थक के रूप में, वे कहते हैं कि मुसलमानों में बहुविवाह हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और आदिवासियों की तुलना में बहुत कम है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय के हिजाब संबंधी फैसले पर कुरैशी ने कहा कि हिजाब के बारे में फैसला न्यायाधीश नहीं बल्कि मौलाना करेंगे। कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा, 'कश्मीर फाइल्स आतंकवादियों की तरह ही जनता को बांट रही है।'
हम उनकी राजनीतिक विचारधाराओं पर किसी भी तरह से कोई निर्णय नहीं देते हैं, लेकिन यह बताना चाहते हैं कि इस केंद्र में वरिष्ठ पदों पर आसीन कई लोगों में एक विशिष्ट झुकाव है।

त्रिवेदी राजनीतिक डेटा केंद्र से प्राप्त परिणाम
अध्याय 10 में बताए अनुसार, अभिलेखागार निर्माण और डेटाबेस मैपिंग भारत की विमर्श को नियंत्रित करने की क्षमता को कमजोर करने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। त्रिवेदी केंद्र द्वारा ऐसे कई डेटाबेस तैयार किए जा रहे हैं।
उदाहरण के लिए, TCPD–IAS 1951 से 2020 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का एक डेटासेट है। इसी प्रकार, TCPD ने 1962 से 2021 के बीच भारतीय राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों और उनके चुनावी इतिहास का एक डेटासेट भी बनाया है। इस डेटा को व्यवस्थित और सत्यापित किया गया है। एक अन्य डेटासेट भारत में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारों की सामाजिक संरचना से संबंधित है। इसका उद्देश्य कैबिनेट मंत्रियों की जनसांख्यिकी का विस्तार से अध्ययन करना है।

भारत में प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के अध्ययन पर बहुत जोर दिया जाता है, शायद कार्यपालिका में सत्ता के केंद्रीकरण की परंपरा के कारण। हम मंत्रिमंडल की संरचना के बारे में कम जानते हैं। भारत के मंत्री कौन हैं? वे कहाँ से आते हैं? उनकी राजनीतिक प्रोफ़ाइल और सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है? पार्टियाँ अपनी सरकारें कैसे बनाती हैं? वे कितनी बार अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हैं? और राज्यों और समय के साथ-साथ कौन से रुझान स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं?

टीसीपीडी ने राज्यपालों और न्यायपालिका का भी इसी तरह का डेटाबेस विकसित किया है। यह अपने प्रभावशाली 'लोकधबा' प्रोजेक्ट पर गर्व करता है, जिसमें 1962 से लेकर अब तक राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर सभी भारतीय चुनावी परिणामों को आसान पहुंच के लिए विज़ुअलाइज़ेशन के साथ प्रदर्शित किया गया है। जैसे-जैसे सोशल मीडिया चुनावों में एक हथियार बनता जा रहा है, अशोका विश्वविद्यालय फेसबुक और ट्विटर का उपयोग करके चुनावी प्रचार से संबंधित भारी मात्रा में डेटा एकत्र करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग कर रहा है। फेसबुक इंडिया टीसीपीडी का भागीदार है।

उद्देश्य... चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के स्तर पर सोशल मीडिया पर राजनीतिक प्रचार का विश्लेषण करना है। व्यक्तिगत उम्मीदवारों पर ध्यान केंद्रित करके यह विश्लेषण और भी विस्तृत होगा, जिससे सभी स्तरों पर अंतर्दृष्टि प्राप्त की जा सकेगी, जैसे कि निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर और उनके बीच, पार्टियों के भीतर और उनके बीच आदि के रुझान। हम गुणात्मक विश्लेषण के लिए आवश्यक डेटा तैयार करने हेतु मशीन लर्निंग (एमएल) समर्थित मानव एनोटेशन और मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग करते हुए मिश्रित पद्धति का दृष्टिकोण अपनाते हैं। फेसबुक विज्ञापनों के अध्ययन के लिए यह विशेष रूप से आवश्यक है, क्योंकि सामग्री मुख्य

रूप से दृश्य होती है, जिससे सामग्री को वर्गीकृत करने के लिए स्वचालित एमएल विधियों को चलाना मुश्किल हो जाता है। हमने फेसबुक के टीटीसी लैब्स (ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड कंट्रोल लैब्स) के साथ उनके विज्ञापन लक्ष्यीकरण पारदर्शिता डिजाइन जैम कार्यशाला के दौरान भी भाग लिया, जिसका उद्देश्य फेसबुक पर राजनीतिक विज्ञापनों को डिजाइन और चलाने के तरीके में बेहतर पारदर्शिता लाना था।

टीसीपीडी की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, इसने एक पॉलिटिकल करियर ट्रैकर टूल जारी किया है, जो उपयोगकर्ताओं को 1962 से लेकर अब तक चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के राजनीतिक करियर को देखने में सक्षम बनाता है। यह राज्य चुनावों और संबंधित विषयों का व्यापक विश्लेषण करता है। इसने विभिन्न मीडिया में तैंतीस लेख प्रकाशित किए हैं और मिशिगन विश्वविद्यालय के साथ एक डेटा साझेदारी शुरू की है।

इस प्रकार के डेटा संग्रह से टीसीपीडी को प्रत्येक राजनीतिक दल के वास्तविक समय के संचालन की जानकारी मिलती है, जिससे उसके एल्गोरिदम को यह सीखने में मदद मिलती है कि चुनाव अभियान कैसे बनाए और चलाए जाते हैं, व्यक्तिगत उम्मीदवारों की लोकप्रियता का स्तर क्या है, विशिष्ट उम्मीदवारों के प्रभावित होने की संभावना कितनी है, और न्यायिक प्रणाली को प्रभावित करने के तरीके क्या हैं। भारत सरकार ने घोषणा की है कि अगली जनगणना ई-जनगणना होगी, जो जन्म और मृत्यु पंजीकरण से भी सहज रूप से जुड़ेगी और अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लोगों को स्वचालित रूप से मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। लोग अपने मोबाइल फोन से विवरण भरेंगे। यह अगले पच्चीस वर्षों के आर्थिक विकास की नींव बनने की उम्मीद है। टीसीपीडी डेटा को अन्य डेटासेट के साथ पढ़ने से उन स्थानों के बारे में भी जानकारी

मिलेगी जहां जनसांख्यिकी को बदलने के लिए पुनर्जनसंख्या की जा सकती है, या उन स्थानों के बारे में जहां मतदाताओं के कुछ वर्गों को डरा-धमकाकर चुनावी परिणामों को प्रभावित किया जा सकता है। डेटाबेस बनाना, प्रक्रियाओं और परिणामों का अध्ययन करना, वर्तमान चुनावी कार्यवाही की निगरानी करना और मीडिया संबंधों का लाभ उठाना टीसीपीडी को चुनावी परिणामों में बदलाव लाने में सक्षम बनाता है। क्रिस्टोफ़ जैफ़्रेलॉट ने टीसीपीडी के डेटा का उपयोग करने और इसके फ्रांसीसी सहयोगी सीएनआरएस के समर्थन का दावा किया है। उन्होंने आरएसएस की जातिगत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए डेटाबेस के अपने उपयोग को ऐसे शब्दों में दर्शाया है जिनका राजनीतिक रूप से दुरुपयोग किया जा सकता है:
परंपरागत रूप से, संघ परिवार को उच्च जातियों का समर्थन प्राप्त रहा है। आरएसएस मुख्य रूप से एक ब्राह्मण संगठन था और जनसंघ को "बनिया-ब्राह्मण" पार्टी के रूप में जाना जाता था। भाजपा ने इस विशेषता को बरकरार रखा है, लेकिन निम्न जाति के मतदाताओं को भी आकर्षित करने में सक्षम रही है। इसके मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की जातिगत पृष्ठभूमि से स्पष्ट है कि इसने अपनी उच्च जाति की विरासत को बरकरार रखा है - यह बात सीएनआरएस समर्थित डेटाबेस से भी स्पष्ट है, जिसे अशोका विश्वविद्यालय और साइंसेज पो ने स्पिनपर नाम से बनाया है।

द फ्रेंच कनेक्शन: लिया स्पिनर
भारत के राष्ट्रीय और प्रांतीय निर्वाचित प्रतिनिधियों की सामाजिक प्रोफ़ाइल या SPINPER परियोजना, LIA SPINPER नामक फ्रांस स्थित एक संस्थान द्वारा बनाई गई है, जो भारतीय राजनीति के डेटा को एकत्रित करने के लिए समर्पित है। इसमें कई फ्रांसीसी संस्थान शामिल

हैं, जिनमें साइंसेज पो और उसकी अनुसंधान इकाइयाँ, CERI, CDSP और मेडियालैब शामिल हैं। फेसबुक इंडिया LIA SPINPER सम्मेलनों का भागीदार है। ये सभी संस्थान भारतीय चुनावी परिदृश्य पर संवेदनशील जानकारी एकत्रित करने के लिए अशोका विश्वविद्यालय के त्रिवेदी केंद्र का उपयोग करते हैं। हार्वर्ड की तरह, वामपंथी फ्रांसीसी शिक्षाविद भी भाजपा के उदय से चिंतित प्रतीत होते हैं। LIA SPINPER का मूल उद्देश्य भारत में वर्तमान सत्ता संरचना को कमजोर करना प्रतीत होता है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में विधानसभाओं में निम्न जाति के सदस्यों के चुनाव के साथ शुरू हुई अधिक समावेशिता की प्रवृत्ति पूरे देश में उलट गई है। ग्रामीण निम्न जाति, महिला और मुस्लिम प्रतिनिधियों की कीमत पर शहरी "मध्यम वर्ग" के हिंदू पुरुषों की वापसी भाजपा के सत्ता में आने से और भी तेज हो गई है, जिसकी हिंदू जातीय-धार्मिक लोकलुभावनवाद ने अभिजात वर्ग को सत्ता पुनः प्राप्त करने में मदद की है। ... यह विश्लेषण लगभग 70,000 निर्वाचित प्रतिनिधियों के जीवनी संबंधी आंकड़ों पर आधारित है। डेटा संग्रह चरण, जिसमें ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी के लिए डेटा स्क्रैपिंग और वेब माइनिंग तथा अन्य जानकारी के लिए व्यवस्थित क्षेत्र कार्य शामिल हैं, और डेटा प्रसंस्करण चरण, दोनों में साइंसेज पो-आधारित अनुसंधान इकाइयों ... और अशोक विश्वविद्यालय-आधारित त्रिवेदी सेंटर (राजनीतिक डेटा) का सहयोग लिया गया है। डेटा विश्लेषण चरण के परिणामस्वरूप कई प्रकाशन होंगे ...[90]

भारतीय डेटा स्रोत भारतीय भाषाओं में या मुद्रित रूप में उपलब्ध हैं, जिसके कारण वे फ्रांसीसियों के लिए अपात्र हैं। यही कारण है कि भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यापक डेटासेट प्रोफाइलिंग का निर्माण अशोका के त्रिवेदी केंद्र की सहायता से किया जा रहा है, जिसमें जैफ्रेलॉट और वर्नियर्स फ्रांसीसी नियंत्रण सुनिश्चित करने के प्रयास का नेतृत्व कर

रहे हैं। योजना अशोका के विशाल डेटाबेस को अन्य डेटासेट से जोड़ने की है।

एकत्रित डेटा (TCPD) द्वारा भारतीय चुनाव परिणामों पर संकलित डेटासेट में जोड़ा जाएगा। सामाजिक प्रोफाइल के अध्ययन को उम्मीदवारों और पार्टियों के प्रदर्शन के विस्तृत विश्लेषण के साथ-साथ चुनावी परिणामों के व्यापक विश्लेषण द्वारा पूरक बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा, उप-क्षेत्रों, जिलों या प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के शहरीकरण की डिग्री जैसे भौगोलिक चरों की कोडिंग विभिन्न स्तरों पर विश्लेषण करने में सहायक होगी। इस प्रकार, SPINPER डेटासेट को अन्य मौजूदा डेटासेट से जोड़ा जाएगा, जिसमें एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा संकलित शपथ पत्र डेटासेट भी शामिल है। ADR ने 2004 से भारतीय चुनावों में सभी उम्मीदवारों द्वारा दिए गए शपथ पत्रों को डिजिटाइज़ किया है, जिससे व्यवसाय, संपत्ति और देनदारियों के साथ-साथ चुनाव उम्मीदवारों के आपराधिक प्रोफाइल पर भी डेटा उपलब्ध होता है।

अशोका पत्रिका ने जैफ्रेलॉट और वर्नियर्स दोनों को ख्याति दिलाई है, जिन्हें अब हिंदुत्व और भारतीय राजनीति के विशेषज्ञ माना जाता है। 2018 में, उन्होंने यूसी बर्कले में साथी शिक्षाविदों को 'भारत में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की सीमाएं - मुसलमानों और महिलाओं का मामला' विषय पर प्रशिक्षण देने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की। एलआईए स्पिनपर को फ्रांस-बर्कले फंड द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, जो बर्कले विश्वविद्यालय और फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय की साझेदारी है। हालांकि फ्रांसीसी सरकार और थिंकटैंक को भारत के संवेदनशील डेटा तक आसानी से पहुंच प्राप्त है, लेकिन इससे भारत में कोई चिंता नहीं जताई गई है।

एलआईए स्पिनपर त्रिवेदी केंद्र द्वारा उत्पादित आंकड़ों पर चर्चा करने के लिए वार्षिक सम्मेलन आयोजित करता है। जिन विषयों में इसकी रुचि है, उन्हें अगले पृष्ठ पर दिए गए आरेख में दिखाए गए 2018 के सम्मेलन के दौरान चर्चा किए गए कुछ मुद्दों से स्पष्ट किया जा सकता है।
इन विषयों से हिंदू-विरोधी एजेंडा स्पष्ट रूप से सामने आता है। उदाहरण के लिए, जब टीसीपीडी ने भारत में भूमि कानूनों पर "एक हजार भूमि कानून: भारत में भूमि विनियमन की भूलभुलैया का मानचित्रण" शीर्षक से एक कार्यशाला आयोजित की, तो उसने हिंदू मंदिरों पर सरकारी कब्जे और मंदिर की जमीनों के दुरुपयोग के मुद्दे पर शोध नहीं किया।
त्रिवेदी केंद्र हार्वर्ड के मित्तल संस्थान के साथ भी अपना काम साझा करता है। उदाहरण के लिए, वर्नियर्स ने हार्वर्ड मित्तल संस्थान के एक कार्यक्रम में टीसीपीडी डेटा प्रस्तुत किया, जिसका संचालन आशुतोष वार्ष्णेय ने किया था। यह कार्यक्रम भारत में चुनावों के कुछ हफ्तों बाद आयोजित 2022 के विधानसभा चुनावों पर आधारित था। संस्थान ने भारत के चुनावों की निगरानी के महत्व पर जोर दिया।
उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर सहित पांच भारतीय राज्यों में 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक सात चरणों में चुनाव हुए। उत्तर प्रदेश और पंजाब में हुए ये चुनाव दोनों राज्यों में विधानसभा चुनावों की 70वीं वर्षगांठ के साथ हुए। इन चुनावों के परिणाम भारत के राजनीतिक भविष्य को आकार देने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि हम 2024 के लोकसभा चुनावों की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे जीवंत पैनल में शामिल हों, जो इन चुनावों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका और देश के भविष्य के लिए परिणामों के निहितार्थों पर चर्चा करेंगे।
पृष्ठ 544 पर दिया गया आरेख अशोक में स्थित त्रिवेदी केंद्र से जुड़े जटिल संबंधों को दर्शाता है।

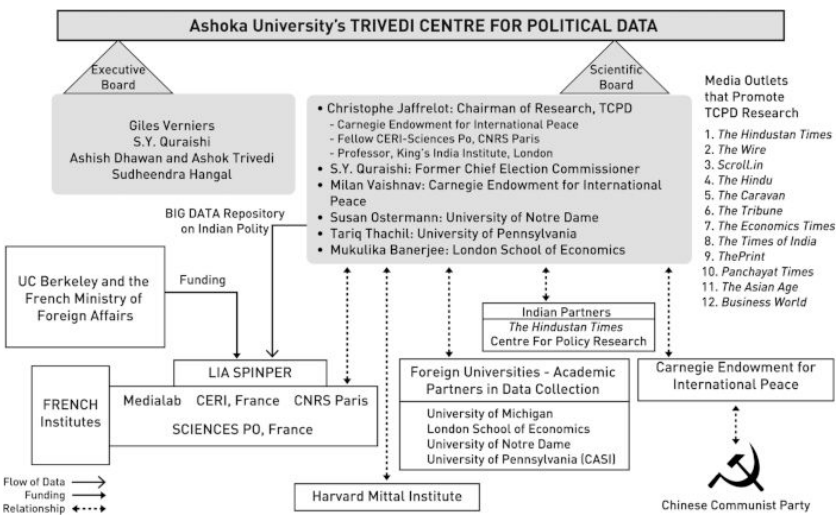

क्रेया और अशोका जैसी संस्थाओं के माध्यम से, भारतीय जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित व्यापक डेटा एकत्र किया जा रहा है और भारत के बाहर के डेटाबेस में संग्रहीत किया जा रहा है। भारतीय अरबपतियों और विदेशी गैर सरकारी संगठनों से प्राप्त धन और भारत के आंतरिक राजनीतिक परिदृश्य पर सुप्रसिद्ध विचारधाराओं वाले विदेशी

शिक्षाविदों के मार्गदर्शन और देखरेख में, उच्च पदस्थ पूर्व नौकरशाह इन प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं। विदेशी सामाजिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग में प्रशिक्षित पेशेवरों का एक पूरा दल भारतीय धरती पर ही तैयार किया जा रहा है।

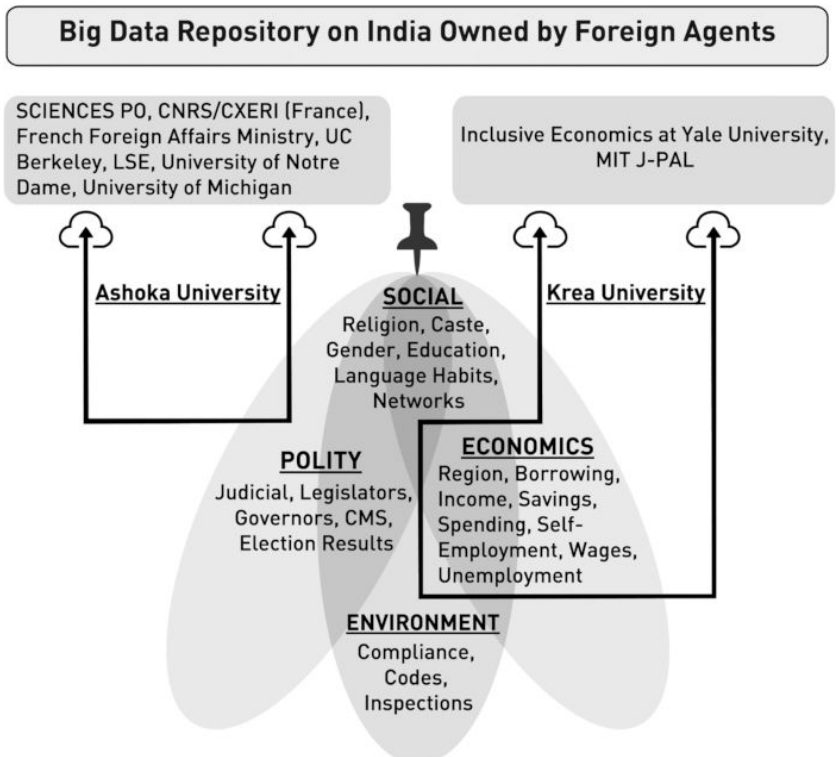

लिंग और यौनिकता अध्ययन केंद्र

लैंगिक पूर्वाग्रह, असमानता और संबंधित मुद्दे अध्ययन के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, लेकिन हम इन्हें स्वदेशी संदर्भ में अध्ययन करने की सलाह देते हैं। हालांकि, शिक्षा जगत में आज मौजूद लैंगिक अध्ययन, लिंग और यौनिकता पर उत्पीड़क और उत्पीड़ित के मार्क्सवादी विचार को थोपता है

और समाज की स्थापित संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए एक प्रतिवाद प्रस्तुत करता है। इसका स्पष्टीकरण अध्याय 1 में दिया गया है।
अशोका विश्वविद्यालय के लिंग और यौनिकता अध्ययन केंद्र (सीएसजीएस) में अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य जैसे विभिन्न विभागों के संकाय सदस्यों का एक मिलाजुला समूह है, जो 'वोके' विचारों का प्रचार करने और छात्रों को सक्रियता के लिए प्रशिक्षित और भर्ती करने के लिए एकजुट हुए हैं। विमर्श पर एकाधिकार जमाने के लिए, वे मधु किश्वर जैसे कई सम्मानित भारतीय विद्वानों का बहिष्कार करते हैं, जिन्होंने भारत में महिलाओं के मुद्दों और नारीवाद पर दशकों तक काम किया है। भारतीय सिद्धांतों के बजाय पश्चिमी सिद्धांतों और वास्तविक विद्वानों के बजाय कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली यह प्राथमिकता हमें विभाग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करती है।
अमेरिका स्थित वेलेस्ली सेंटर्स फॉर विमेन अपने ढांचे पर आधारित पाठ्यक्रम के विकास के लिए धन दे रहा है, और यह पाठ्यक्रम अशोका के माध्यम से सीएसजीएस के छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। अशोका लिंग संबंधी पश्चिमी विचारों के प्रसार का एक प्रभावी माध्यम है, और इसका स्वाभाविक परिणाम युवा दिमागों का राजनीतिक रूप से प्रभावित होना है।
अशोका की संस्थापक सदस्यों में से एक हर्षबीना साहनी ज़ावेरी हैं, जो एनआरबी बेयरिंग्स की प्रबंध निदेशक हैं। वेलेस्ली कॉलेज से मानवविज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद, उन्होंने सीएसजीएस के लिए इस सौदे को संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका लक्ष्य 'विशेषाधिकार की बाधाओं' को तोड़ना है, जो कि एक ऐसी शख्सियत के लिए हास्यास्पद है, जिनकी सफलता का बहुत बड़ा श्रेय उनके पिता के

व्यवसाय को विरासत में मिलने के विशेषाधिकार को जाता है। 2016 में, अशोका ने वेलेस्ली कॉलेज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

अशोका विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों में अमेरिका से आयातित क्रिटिकल रेस थ्योरी का व्यापक उपयोग होता है। उदाहरण के लिए, एंड्रयू डब्ल्यू. मेलन फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित पांच वर्षीय शोध परियोजना 'गवर्निंग इंटिमेसीज' के अंतर्गत, अंतरंगता, कामुकता और क्वीरनेस जैसी विभिन्न अवधारणाओं को जाति और जातीयता के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। स्वाभाविक रूप से, उत्पीड़न के लिए 'हिंदू-सर्वोच्चतावादी राजनीति' को दोषी ठहराया जाता है। लिंग और कामुकता की श्रेणियों को 'नस्लीय' रूप दिया गया है। तीन तलाक (इस्लामी प्रथा जिसके तहत पति केवल तीन बार 'तलाक' कहकर एकतरफा तलाक दे सकता है) पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को 'भाजपा और संघ द्वारा संगठित इस्लामोफोबिया और नारीवाद-विरोधी' बताया जाता है। घोषित लक्ष्य उत्पीड़न के पीड़ितों के बीच 'राजनीतिक एकजुटता का निर्माण' करना है।

पश्चिम में, ऐसे ‘शिकायत’ आधारित अध्ययनों की आलोचना बनावटी अकादमिक क्षेत्रों के रूप में की जा रही है, जो वामपंथी प्रचार यंत्रों के रूप में काम करते हैं। कई फर्जी शोध पत्रों के माध्यम से इन ‘अध्ययन’ विभागों का पर्दाफाश हो चुका है। इन बेकार की डिग्रियों की भारी कीमत न केवल युवाओं को भावनात्मक रूप से नष्ट कर रही है, बल्कि उन्हें रोजगार योग्य कौशल से भी वंचित कर रही है। कुछ देश लैंगिक अध्ययन को बंद कर रहे हैं, और इस क्षेत्र के शिक्षाविद इस विरोध को एक विषमलैंगिक पितृसत्तात्मक समाज के लिए दक्षिणपंथी साजिश बता रहे हैं।

अमेरिकी रूढ़िवादी इस तरह की सक्रियता को 'ग्रूमिंग' कहते हैं, जिसमें युवाओं को सक्रियता के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जिसमें वास्तव में 'ट्रांस' जीवन जीना भी शामिल हो सकता है। उनका आरोप है कि ये रुझान शिक्षा, हॉलीवुड आदि में संगठित शीर्ष-स्तरीय आंदोलनों के कारण हैं। वे ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं जिनसे पता चलता है कि कई युवा अपनी यौनिकता को लेकर भ्रमित हो जाते हैं, या ध्यान आकर्षित करने की बेताब ज़रूरत के चलते, इस तरह की ग्रूमिंग का शिकार हो जाते हैं और लिंग परिवर्तन की सर्जरी करवा लेते हैं, जिसका उन्हें बाद में पछतावा होता है।

पश्चिम में, दोनों पक्षों के बीच स्वस्थ बहस चल रही है, जिसमें दोनों पक्ष अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हैं और अपने-अपने दृष्टिकोण के समर्थन में शोध आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। हालांकि, भारत में गंभीर स्तर पर कोई बहस नहीं है। अमेरिका में क्रिटिकल रेस थ्योरीज़ के स्रोतों से अशोक के संबंध, और भारतीयों के समर्थन ने इसे एकतरफा सक्रियता में बदल दिया है। यह जेएनयू से भी कहीं अधिक परिष्कृत स्तर की सामाजिक इंजीनियरिंग है।

समर्थकों की संख्या बढ़ाने के लिए इन मुद्दों को अन्य ज्वलंत मुद्दों के साथ जोड़ा जा रहा है। उदाहरण के लिए, अशोका का सीएसजीएस अपनी कश्मीरी शोधकर्ता समरीन मुश्ताक को प्रोत्साहित करता है, जो कश्मीर में भारत के 'अत्याचार' के बारे में लिखती हैं और अलगाववादी प्रचार को बढ़ावा देती हैं। (कश्मीर मुद्दे पर सीएसजीएस द्वारा प्रायोजित शोध पत्रों की सूची के लिए फुटनोट देखें।) जेंडर एंड सेक्सुअलिटी सेंटर इन असंबंधित मुद्दों को इस तरह से जोड़ता है जिसे युवा पीढ़ी के बीच लोकप्रिय और चलनशील माना जाता है।

अमेरिका में लैंगिक अध्ययन विभागों और भारत में उनके अनुयायियों का

लक्ष्य विद्यालयों में एक विशेष प्रकार की यौन शिक्षा शुरू करना है। यह शिक्षा बच्चों को दुर्व्यवहार या गर्भावस्था से बचाने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें कम उम्र में ही यौन संबंधों के लिए तैयार करने के लिए है ताकि उनकी बचपन की मासूमियत को नष्ट किया जा सके। जैसा कि हमने अध्याय 1 में देखा, बचपन की मासूमियत को श्वेत विषमलैंगिक पुरुषों द्वारा निर्मित एक सामाजिक अवधारणा माना जाता है, जिन्होंने बच्चों का मस्तिष्क इस विश्वास में धो डाला कि विभिन्न लिंगों के बीच यौन संबंध सामान्य और वांछनीय हैं। इस थोपे गए विश्वास को एक प्रकार का उत्पीड़न कहा जाता है। इसलिए, इसका मुकाबला करने के लिए बच्चों को बहुत कम उम्र में ही समलैंगिकता से परिचित कराना आवश्यक है। इस पद्धति के परिणामस्वरूप बच्चे विद्रोही बन जाते हैं और उनके माता-पिता, परंपराओं, संस्कृति और समाज से अलगाव पैदा हो जाता है। दूसरे शब्दों में, बच्चों को उनके माता-पिता से दूर करना, स्थापित व्यवस्था से लड़ने के लिए विकसित मार्क्सवादी प्रतिवाद का एक हिस्सा है।
अशोका विश्वविद्यालय का सीएसजीएस अपने परिसर में एलजीबीटीक्यू + सक्रियता के लिए पश्चिमी मॉडल को धड़ल्ले से अपना रहा है। कक्षा शिक्षण के हिस्से के रूप में, यह वीडियो, अध्ययन समूहों और अन्य तरीकों के माध्यम से इस विचारधारा को व्यवस्थित रूप से प्रसारित कर रहा है। और अमेरिका से आयातित 'कैंसल कल्चर' की भावना में, किसी भी विरोधी विचार या स्वतंत्र आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है।
स्वयं को ‘उत्कृष्टता केंद्र’ घोषित करने वाले CSGS का एक ऐसा संगठन भी है जो भारत में ‘वोकेवाद’ लाने वाले प्रमुख केंद्रों को आपस में जोड़ता है, ताकि ऐसे नए काल्पनिक अल्पसंख्यकों का निर्माण किया जा सके जो खुद को राष्ट्र-राज्य के शिकार के रूप में देखते हैं। प्रत्येक नए

अल्पसंख्यक को शिकायतों के एक नए समूह द्वारा परिभाषित किया जाता है।

सीएसजीएस और उसके अमेरिकी सहयोगी वेलेस्ली कॉलेज द्वारा आयोजित यौन शिक्षा पर एक सम्मेलन में, लक्ष्य सीधे अमेरिका से लिया गया था: यौन संबंधी विचारों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे भारतीय बच्चों और उनके माता-पिता के बीच मतभेद पैदा हो सके। यह प्रतिवाद उनकी पहचान और पैतृक संस्कृति से चली आ रही वर्चस्ववादी धारणा को पराजित करेगा। इसके परिणामस्वरूप, पारिवारिक संरचना नष्ट हो जाएगी और समाज अस्थिर हो जाएगा, जिससे एक नए समाज के निर्माण में सहायता मिलेगी। सम्मेलन में अमेरिका और भारत के शिक्षाविद, कार्यकर्ता, कलाकार और प्रदर्शनकारी शामिल थे। चर्चा किए गए विषयों के लिए अंत नोट देखें।

ऐसा लगता है कि अशोका विश्वविद्यालय भारतीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को प्रभावित करने की यही प्रक्रिया अपना रहा है। सरकारी एनसीईआरटी, जो स्कूली पाठ्यपुस्तकों के निर्माण के लिए ज़िम्मेदार है, ने 2021 में स्कूलों के लिए लैंगिक विविधता पर एक शिक्षक प्रशिक्षण नियमावली (जिसे बाद में वापस ले लिया गया) जारी करके इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस नियमावली में यौवन अवरोधकों के बारे में जानकारी शामिल थी और जातिगत पितृसत्ता को ट्रांसफोबिया का कारण बताया गया था। एनसीईआरटी द्वारा आमंत्रित एक बाहरी विशेषज्ञ विक्रमादित्य सहाय थे, जो सीएसजीएस में अक्सर वक्ता के रूप में आते हैं और लिंग, विवाह और एकविवाह की उन अवधारणाओं को नष्ट करने के अपने अंतर्निहित एजेंडे को खुलकर सामने रखते हैं जिन्हें वे 'हिंसक' मानते हैं। अशोका में सहाय के व्याख्यानों के कुछ अंश इस प्रकार हैं:

यह सिर्फ विवाह की संस्था ही नहीं है, बल्कि मुझे एकविवाह की संस्थाएँ और प्रेम की परिभाषा से संबंधित सांस्कृतिक विचार भी दमनकारी संस्थाएँ लगती हैं। ये ऐसी संस्थाएँ हैं जो कुछ खास तरह की संरचनाओं को कायम रखती हैं - पितृसत्ता का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है; और ये ऐसी संरचनाएँ हैं जो गहन विचार-विमर्श की अनुमति नहीं देतीं। मैं मानती हूँ कि लिंगभेद एक गंभीर हिंसा है, लेकिन यह मुझे लिंगभेद के आधार पर संगठित होने से नहीं रोकता; यानी जो हिंसात्मक है, वही प्रतिरोध की नई संभावनाओं और दुनिया को सही ढंग से पुनर्कल्पना करने का आधार भी बन सकता है।

एक तरह से विवाह पर मेरी आलोचना यह है कि मुझे विवाह संस्था में कुछ भी ऐसा नहीं दिखता जिसे बचाया जा सके। विवाह का एक इतिहास रहा है जहाँ यह दमनकारी रहा है; यह भीतर से भी दमनकारी है और दूसरों को इससे बाहर रखकर भी, लेकिन इसके अलावा मैं यह भी मानता हूँ कि हिंसा ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं पूरी तरह से त्याग सकता हूँ।

अशोका विश्वविद्यालय की बिट्टू कावेरी राजारामन एनसीईआरटी की एक अन्य सलाहकार थीं। हार्वर्ड से शिक्षित ट्रांसजेंडर, अशोका विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान की प्रोफेसर और सीएसजीएस की फैकल्टी सदस्य हैं। उनके भाषणों का सार ब्राह्मणवादी पितृसत्ता, पुरुष प्रधानता और हिंदू विरोधी बयानबाजी पर आक्रमण है, जिसमें जातिगत उत्पीड़न का भी भरपूर तड़का लगता है। वे जेएनयू के बिरसा अंबेडकर फुले छात्र संघ (बीएपीएसए) और हैदराबाद विश्वविद्यालय के 'जस्टिस फॉर रोहित' कार्यक्रम में भी एक लोकप्रिय वक्ता हैं।

जीव विज्ञान की प्रोफेसर होने के बावजूद, वह इस बात को बढ़ावा देती हैं कि लिंग एक सामाजिक संरचना है, और कहती हैं कि 'हमें लिंग का जैविकरण नहीं करना चाहिए'। वह आगे कहती हैं:

आयोजकों ने मुझसे लिंग तरलता के प्रश्न पर विचार करने का अनुरोध किया है, जैसा कि उन्होंने कहा है। मूल रूप से, समग्र प्रश्न स्वयं लिंग का है क्योंकि लिंग एक सामाजिक संरचना है जो जैविक श्रेणी 'सेक्स' के साथ जुड़ाव से वैधता प्राप्त करती है।
अशोका के सीएसजीएस द्वारा पोषित एक अन्य 'पीड़ित' समूह बॉन्डेज-डोमिनेशन-सैडो-मैसोकिज़्म (बीडीएसएम) समुदाय है, जिसे यह भी बताया जाता है कि वह 'जाति और वर्ग संरचनाओं' के उत्पीड़न के तहत 'संघर्ष' कर रहा है। इसमें भारत में विकृत यौन प्रथाओं के बारे में शिक्षा देना भी शामिल है। सीएसजीएस द्वारा प्रायोजित व्याख्यान आयोजित करने वाले किंकी कलेक्टिव की सदस्य जया शर्मा ने आनंद को परिभाषित करने और इस धारणा को बदलने के अधिकार के बारे में बात की है कि केवल सुखद ही आनंददायक होता है। उन्होंने कहा है कि अपमान सहित सभी इच्छाएं और बलात्कार सहित सभी कल्पनाएं तब तक स्वीकार्य हैं जब तक सहमति हो। कोई भी असामान्य चीज़ वांछनीय है क्योंकि यह उन मौजूदा विचारों को चुनौती देती है जिन्हें 'लिंग, जाति, वर्ग, धर्म, निजी संपत्ति और बाकी सभी की मौजूदा शक्ति संरचनाओं और शक्ति पदानुक्रमों' द्वारा बढ़ावा दिया गया है।

सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन केंद्र
बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने अशोका में सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज (सीएसबीसी) की स्थापना की है और ओमिडयार नेटवर्क के साथ मिलकर इसे वित्त पोषित करता है। इसका स्पष्ट लक्ष्य निम्न-आय और हाशिए पर रहने वाली आबादी में 'प्रभावशाली व्यवहार परिवर्तन हस्तक्षेप' करना है।
सीएसबीसी का उद्देश्य भारत में एक ऐसी संस्था स्थापित करना है जो

निम्न आय वर्ग और हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए प्रभावी व्यवहार परिवर्तन हस्तक्षेपों में वैचारिक नेतृत्व और उत्कृष्टता के लिए विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित हो।

सीएसबीसी कई कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय सरकार में विदेशी प्रभाव बढ़ा रहा है। यह एक त्रिपक्षीय साझेदारी है जिसमें सरकार, नीति आयोग के माध्यम से, समस्या का विवरण प्रस्तुत करती है, अशोका उस समस्या के समाधान के लिए शोध करता है और गेट्स फाउंडेशन अपने हितों के अनुरूप अशोका को वित्त पोषित करता है। इसके बाद सरकार उस समाधान को अपना लेती है। इस प्रकार के सहयोग में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारें शामिल हैं।

उदाहरण के लिए, नीति आयोग ने सीएसबीसी के साथ मिलकर संचार और सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेशों के 'फ्रेमिंग' के माध्यम से व्यवहार संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए काम किया।

भारत में व्यवहार-आधारित नीति निर्माण के एक नए प्रतिमान को प्रस्तुत करने के लिए, नीति आयोग ने 2019 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) और सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज (सीएसबीसी) के साथ साझेदारी करके भारत की पहली बिहेवियरल इनसाइट्स यूनिट (बीआईयू) की स्थापना की।

डॉ. पवन मामिडी सीएसबीसी के निदेशक हैं और मोबाइल प्रयोगशालाओं और टेंटों की सहायता से व्यवहार परिवर्तनकारी प्रयोगों को डिजाइन करने का दायित्व उन पर है। 'समस्याग्रस्त' व्यवहार के आधार पर, टीम समाधान प्रस्तुत करती है। अभियान या उद्देश्य के अनुसार, केंद्र कहानियों, लोक संगीत और फिल्मों के माध्यम से उपयुक्त कथानक तैयार करता है। यह प्रारूप जनता को अधिक स्वीकार्य है और इसलिए व्यवहार परिवर्तन में अधिक प्रभावी है। लेकिन जनमानस के मस्तिष्क को

प्रभावित करने वाले शोध का दुरुपयोग भी हो सकता है।
सीएसबीसी प्रोत्साहन के रूप में गाजर और छड़ी का उपयोग करके व्यवहार परिवर्तन के तरीके सुझाता है और निम्नलिखित का समर्थन करता है:
औपचारिक संस्थानों के माध्यम से नीतिगत परिवर्तन;
बाजारों में व्यवहारिक बदलाव लाने के लिए मूल्य निर्धारण; और
व्यवहार में परिवर्तन लाने वाले सामाजिक मानदंड (अनौपचारिक संस्थाएँ) [123]
उदाहरण के लिए, कोविड-19 संकट के दौरान समाज में प्रचलित मानदंडों को बदलने के लिए ऐसे प्रयोग किए गए थे:
मास्क पहनने के नियम को लागू करना; [124]
भारतीय समाज में व्याप्त 'भाग्यवाद' की धारणाओं को तोड़ना; और
यह उन सूचनाओं से निपटता है जिन्हें यह गलत/भ्रामक मानता है।
बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित गतिविधियों में से एक भारत में टीकाकरण के प्रति झिझक को कम करना और टीकों पर गेट्स के दृष्टिकोण का प्रचार करना है। इसे 'भाग्यवाद' कहकर, गेट्स/अशोका परियोजना उन लाखों भोले-भाले भारतीयों की सांस्कृतिक सोच को बदलने का औचित्य साबित कर रही है जो कर्म में विश्वास करते हैं। भोले-भाले लोगों का इस तरह शोषण करना अनैतिक है और इससे सभ्यता के मूल्यों को भी ठेस पहुँच सकती है। और जब लोगों को यह नहीं पता होता कि किस पर विश्वास करें, तो वे नक्सलियों, मार्क्सवादियों और मिशनरियों के प्रभाव में आसानी से आ जाते हैं। हम इस विषय पर कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि केवल इस तथ्य की ओर ध्यान दिला रहे हैं कि बिल गेट्स जैसे लोग अशोका का उपयोग करके जनता के व्यवहार को बदलने का प्रयास कर सकते हैं।

अशोका के माध्यम से, गेट्स फाउंडेशन को विश्व बैंक द्वारा समर्थित बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना (स्थानीय रूप से जीविका ट्रस्ट के नाम से जानी जाती है) तक पहुंच प्राप्त होती है। इस पहल का उद्देश्य व्यवहार परिवर्तनकारी समाधान प्रदान करके बिहार में टीकाकरण को बढ़ाना है। सीएसबीसी और गेट्स फाउंडेशन दोनों उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं।
उत्तर प्रदेश में, हम उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग, एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) विभाग, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम), सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) विभाग और यूपी तकनीकी सहायता इकाई (टीएसयू) के साथ मिलकर काम करेंगे।
कई भारतीयों को इस बात की जानकारी नहीं है कि अमेरिका में गेट्स फाउंडेशन और उसके इरादों पर जनता के भरोसे पर सवाल उठ रहे हैं।

सामाजिक प्रभाव और परोपकार केंद्र
अध्याय 22 में ओमिडयार नेटवर्क की भारत को तोड़ने से संबंधित गतिविधियों पर चर्चा की गई है। अशोका विश्वविद्यालय के सामाजिक प्रभाव और परोपकार केंद्र (सीएसआईपी) को ओमिडयार नेटवर्क से धनराशि प्राप्त होती है। सीएसआईपी का उद्देश्य विदेशी संबंधों वाले शक्तिशाली भारतीय गैर सरकारी संगठनों के लिए अनुसंधान को सुगम बनाना है। अशोका विश्वविद्यालय का बुनियादी ढांचा, संकाय और छात्र सरकार के साथ नीतिगत परिवर्तनों के लिए सलाहकार और पैरवीकार की भूमिका निभाते हैं।
सीएसआईपी को वित्त पोषण के पीछे के उद्देश्यों को समझने के लिए, 2015 में वापस जाना आवश्यक है, जब गैर-सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा दिल्ली उच्च

न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें नए एफसीआरए नियमों को लागू करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय के गठन की मांग की गई थी। यह एक विदेशी हित याचिका है क्योंकि एडीआर को फोर्ड फाउंडेशन, ओमिडयार नेटवर्क, गूगल और हिवोस (एक डच गैर-सरकारी संगठन) से भारी मात्रा में धन प्राप्त होता है। सीएसआईपी की वर्तमान प्रमुख इंग्रीड श्रीनाथ, पहले भारत में हिवोस की सीईओ थीं, जो जनहित याचिका दायर करने वाले पक्षों में से एक थी। स्पष्ट रूप से, संबंध काफी गहरे हैं। 2014 की शुरुआत में ही, भारत में निगरानी संस्थाओं ने हिवोस द्वारा किए जा रहे कार्यों पर ध्यान देना शुरू कर दिया था।
हिवोस को फोर्ड फाउंडेशन से उदार अनुदान प्राप्त होते हैं। नीदरलैंड्स स्थित स्टिचिंग हिवोस भी एक दाता है, जिसका भारत में एक पूर्ण विकसित कार्यालय है और उसे 1.2 मिलियन डॉलर (2014) प्राप्त हुए हैं। हिवोस नीदरलैंड्स सरकार की सह-वित्तपोषित एजेंसियों में से एक है, जिसका दूतावास केजरीवाल और सिसोदिया की फिल्म कबीर को वित्तपोषित करता है। हिवोस सीसीडी को भी सह-वित्तपोषित करता है। यह आईआईएम बैंगलोर के डीन त्रिलोचन शास्त्री के फोर्ड फाउंडेशन द्वारा वित्तपोषित दो गैर सरकारी संगठनों में से एक को भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो एडीआर भी चलाते हैं। फोर्ड फाउंडेशन की पैरवी के बदौलत उन्हें ब्रेटन वुड्स कमेटी की सदस्यता भी प्रदान की गई है।
हिवोस ने अशोका के सीएसआईपी के साथ मिलकर "वकालत, अधिकार और नागरिक समाज: भारतीय परोपकार के लिए अवसर" नामक एक परियोजना पर काम किया है, जिसे ओमिडयार और अजीम प्रेमजी परोपकारी पहलों से वित्त पोषित किया गया है। इसके साझेदारों में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, गेट्स फाउंडेशन, एटीई चंद्र फाउंडेशन (अमित चंद्र और अर्चना चंद्र), रोहिणी नीलेकानी परोपकार संस्थाएं और ऑक्सफैम

शामिल हैं। यह परियोजना भारत के एफसीआरए कानूनों का उल्लंघन करने वाले विदेशी गैर सरकारी संगठनों पर पड़ने वाले विनाशकारी प्रभाव की जांच कर रही है। इसकी रिपोर्ट में गैर-अनुपालन के लिए विदेशी गैर सरकारी संगठनों पर भारतीय सरकार की कार्रवाई के प्रति समाधान प्रस्तावित किए गए हैं।

रिपोर्ट में सरकार द्वारा 'वित्तीय स्रोतों से आने वाले धन पर बढ़ती नज़र' के कानूनी और नियामक ढाँचे और भारत में सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों को बनाए रखने के बहाने काम करने वाले विदेशी गैर-सरकारी संगठनों पर इसके प्रभाव की जाँच की गई है। यह रिपोर्ट अशोका द्वारा चयनित गैर-सरकारी संगठनों से एकत्रित शिकायतों पर आधारित है। इनमें ग्रीनपीस, हिवोस, पीपुल्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑक्सफैम, फोर्ड फाउंडेशन, सीआरवाई, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, मैकार्थर फाउंडेशन, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, माइकल और सुसान डेल फाउंडेशन के साथ-साथ आशीष धवन, अजीम प्रेमजी और अन्य के फाउंडेशन शामिल हैं। सीएसआईपी की रिपोर्ट में कुछ बड़े गैर-सरकारी संगठनों की पहचान गुप्त रखी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है:

भारतीय परोपकारियों के लिए गैर-लाभकारी क्षेत्र में एक बड़ी सहायक भूमिका निभाने के अवसर पहचाने गए हैं, विशेष रूप से कुछ प्रकार के अधिकारों और वकालत के कार्यों का समर्थन करके जिनका संरचनात्मक, दीर्घकालिक प्रभाव होता है।

यह शोध स्वयं सीएसआईपी द्वारा स्वीकार किए गए उपाख्यानात्मक साक्ष्यों और वृत्तांतों पर आधारित है। सीएसआईपी ने बीस हजार एफसीआरए लाइसेंसों के रद्द होने को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की। सीएसआईपी ने अपने शोध साझेदारों हाउ इंडिया लिव्स और ल्यूमेन कंसल्टिंग के साथ मिलकर कई महीनों तक सरकारी डेटाबेस का अध्ययन

किया और भारत में गैर-लाभकारी संस्थाओं को मिलने वाले वित्तपोषण पर गहन शोध करने के लिए विभिन्न लोगों से बातचीत की। उन्होंने यह भी देखा कि एफसीआरए अधिनियम में किए गए कुछ बदलावों ने हमारे क्षेत्र को कैसे प्रभावित किया है; और... परोपकार किस प्रकार लगभग 20,000 एफसीआरए लाइसेंस रद्द होने से उत्पन्न हुए अंतर को भरने में सहायक हो सकता है।

रिपोर्ट में गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए गए उल्लंघनों की जांच करने की जहमत ही नहीं उठाई गई। इसके बजाय, इसने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि कैसे:

भारतीय सरकार पर मुकदमा दायर करें, जिसमें कानूनी रक्षा कोष का गठन भी शामिल हो;

उन गैर सरकारी संगठनों को निधि प्रदान करें जिन्होंने एफसीआरए रद्द होने के कारण अपने वित्तपोषण स्रोत खो दिए हैं;

भारतीय कानून का उल्लंघन करने वाले गैर सरकारी संगठनों को अस्थायी रूप से अंतरिम सहायता प्रदान करना, जिसमें 'ब्रिज फंडिंग' के रूप में अंतरिम उपाय शामिल हैं; और

भारतीय कॉरपोरेट घरानों पर दबाव डालें कि वे भारत में 'सामाजिक न्याय' और 'मानवाधिकार' के कार्यों के लिए धन जुटाएं, जिससे विदेशी निधियों पर निर्भरता कम हो सके।

अशोका सीएसआईपी परियोजना 2015-16 से 2016-17 तक एफसीआरए फंडिंग में आई गिरावट को लेकर चिंतित थी। अशोका के सीएसआईपी की इंग्रीड श्रीनाथ, जो पहले हिवोस की कार्यकारी थीं, ने कहा:

भारतीय परोपकार संस्थाएं एफसीआरए रद्द होने से प्रभावित गैर-लाभकारी संस्थाओं की सहायता के लिए तीन मुख्य कार्य कर सकती हैं।

पहला, इन निर्णयों को चुनौती देने के लिए एक कानूनी रक्षा कोष बनाकर ऐसी संस्थाओं का समर्थन करना। दूसरा, उन संस्थाओं को सहायता प्रदान करना जिन्होंने अपने निधि प्रदाता के निगरानी सूची में शामिल होने के अलावा किसी विशेष कारण के बिना वित्तपोषण खो दिया है। और तीसरा, एक प्रकार का ब्रिज फंड बनाने पर विचार करना... जो एफसीआरए खोने वाली संस्थाओं को अल्पावधि में वैकल्पिक व्यवस्था मिलने तक अपना खर्च चलाने में मदद करेगा।

भारत में अधिकांश अधिकार एवं वकालत संगठन विदेशी वित्त पोषित हैं, जबकि जमीनी स्तर पर सेवा प्रदान करने वाले गैर-सरकारी संगठन सीएसआर योगदान और घरेलू परोपकार से वित्त पोषित होते हैं। 2009 से भारत में परोपकार में धनी व्यक्तियों, कॉर्पोरेट सीएसआर और छोटे दानदाताओं से अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। भारतीय और भारतीय कंपनियां अभी भी सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाले गैर-सरकारी संगठनों की तुलना में सेवा एवं कार्यान्वयन करने वाले गैर-सरकारी संगठनों को वित्त पोषित करना अधिक पसंद करते हैं। यह रिपोर्ट इस संतुलन को बदलने के तरीके बताती है और निगमों एवं धनी व्यक्तियों को अधिकार एवं वकालत संगठनों को वित्त पोषित करने के लिए प्रोत्साहित करने के सुझाव देती है।

हालांकि कुछ भारतीय परोपकारियों ने मानवाधिकार और सामाजिक हितैषी कार्यों के लिए विश्वविद्यालय, विचार-मंथन केंद्र और सामाजिक संगठन स्थापित किए हैं, लेकिन इस तरह की अधिकांश धनराशि विदेशी स्रोतों से आती है। कार्यक्षेत्र में शासन, लोकतंत्र, मानवाधिकार आदि शामिल हैं। उदाहरण के लिए, हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क, सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ सोशल कंसर्न्स, लॉयर्स कलेक्टिव आदि जैसे कई प्रतिष्ठित संगठनों के बजट का बड़ा हिस्सा विदेशी दानदाताओं से प्राप्त

होता है।
रिपोर्ट में प्रस्तुत कुछ केस स्टडी के पीछे जिन संगठनों का हाथ है, उनमें विदेशी वित्त पोषित संगठन इंडियन सोशल एक्शन फोरम भी शामिल है, जिसका लाइसेंस तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के बाद सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था।
अशोका की सीएसआईपी रिपोर्ट विदेशी वित्तपोषण एजेंसियों को सरकार से होने वाली परेशानियों से बचने के तरीके बताती है। उदाहरण के लिए, इसने अपने अनुदान प्राप्तकर्ताओं को निर्देश दिया है कि 'यह सुनिश्चित करें कि हमारे द्वारा वित्तपोषित किसी भी परियोजना में "अधिकार" शब्द का प्रयोग न हो।' एक अन्य शानदार रणनीति जो इसने अपनाई, वह थी गैर-लाभकारी संगठनों से बचना क्योंकि वे एफसीआरए के दायरे में आते हैं और इसके बजाय लाभ कमाने वाले संगठनों की स्थापना करना जो बिना किसी एफसीआरए प्रतिबंध के विदेशी निधियों का उपयोग करके वही सक्रियतावादी कार्य कर सकते हैं।
सीएसआईपी यह भी सुझाव देता है कि कॉरपोरेट कंपनियां अकेले काम करने के बजाय दूसरों के साथ सहयोग करके जोखिम को कम कर सकती हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक-स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन है, जो वामपंथी मीडिया संस्थानों को वित्त पोषित करता है और कभी-कभार स्वराज्य जैसी तटस्थ पत्रिकाओं को भी थोड़ी-बहुत धनराशि देता है। इसका विस्तृत विवरण अध्याय 20 में दिया गया है।
सीएसआईपी की रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है:
जो भारतीय वित्तदाता अधिक जोखिम उठाने में असमर्थ हैं, वे अपने उन समकक्षों के पोर्टफोलियो से कम जोखिम वाले अनुदानों को लेने का वचन

दे सकते हैं जिनकी जोखिम लेने की क्षमता अधिक है। इससे बाद वाले की पूंजी अधिक अधिकार और वकालत संबंधी कार्यों के लिए मुक्त हो जाएगी। … विदेशी वित्तदाता जो FCRA के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हैं, वे भारतीय वित्तदाताओं से कम जोखिम वाले अनुदान ले सकते हैं और उन अधिकार और वकालत संबंधी कार्यों को सौंप सकते हैं जिनका समर्थन भारतीय वित्तदाता FCRA के प्रतिबंधों के बिना कर सकते हैं।

अशोका विश्वविद्यालय की शैक्षणिक साझेदारियाँ

हार्वर्ड का अशोका के साथ प्रारंभिक संबंध प्रोफेसरों को अपने साथ शामिल करने और हार्वर्ड-येनचिंग संस्थान के माध्यम से सहयोग करने से जुड़ा था। पिछले कुछ वर्षों से, हार्वर्ड अशोका के साथ अधिक प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने की तैयारी कर रहा है।

उदाहरण के लिए, 2015 में, हार्वर्ड ने अशोका के छात्रों को अठारह सौ डॉलर में व्यवसाय में एक वर्षीय ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रम की पेशकश की। 2017 में, अशोका ने भारतीय गैर-लाभकारी क्षेत्र में 'सार्थक सामाजिक परिवर्तन लाने' के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के साथ साझेदारी की। हार्वर्ड के प्रोफेसरों ने दक्षिण या दक्षिणपूर्व एशिया में कार्यरत गैर-लाभकारी संगठनों के वरिष्ठ नेतृत्व, न्यासियों और बोर्ड सदस्यों को कक्षाएं दीं। इसके अलावा, अशोका के छात्रों ने भारत के बारे में भारत में सम्मेलनों के आयोजन में हार्वर्ड यूएस-इंडिया इनिशिएटिव (HUII) के साथ साझेदारी की।

हार्वर्ड और अन्य विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी का एक दुष्प्रभाव यह है कि वे ऐसी सामग्री तैयार करते हैं जिसका उपयोग विदेशी विद्वान भारत के बारे में अत्याचार साहित्य लिखने के लिए कर सकते हैं।

इसका उद्देश्य भारतीय छात्रों को इतिहास, समाज विज्ञान और इसी तरह के विषयों के पक्षपातपूर्ण संस्करण परोसकर उन्हें अपने पक्ष में करना है। इन प्रयासों का उद्देश्य उन्हें भारत को देखने का पश्चिमी दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करना है।

उदाहरण के लिए, 2016 में, अशोका विश्वविद्यालय द्वारा भारत में रूढ़िवाद पर आयोजित सम्मेलन ने निम्नलिखित प्रकार के शोध को जन्म दिया:

स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की विद्वान शारिका थिरनागामा ने 'मुक्ति की धीमी प्रक्रिया? केरल में साम्यवाद और दलित जीवन' विषय पर अपना शोधपत्र प्रस्तुत किया और राजनीतिक परिवर्तनों के माध्यम से उभरने वाली नई पहचानों के समावेशन की समस्याओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने पूछा कि क्या जातिगत प्रथाओं में परिवर्तन वास्तव में परिवर्तन का संकेत है, या आज लागू की जा रही नीतियां केवल समायोजन का संकेत हैं, इसलिए इन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।

अशोका विश्वविद्यालय में क्रिकेट के इतिहास पर आधारित 'क्रिकेट का वैश्विक इतिहास' नामक पाठ्यक्रम भी इस बात की पड़ताल करता है कि 'किस प्रकार नस्लीय, वर्गीय और जातिगत इतिहास क्रिकेट के खेल से परस्पर जुड़े हुए थे'।

बेशक, किसी विदेशी विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी हमेशा छात्र के विकास के लिए हानिकारक नहीं होती। लेकिन जैसा कि ऊपर देखा गया है, विदेशी साझेदार अक्सर सार्थक चीजों के निर्माण के बजाय, 'वोके' छात्रवृत्ति, शिकायत अध्ययन या भारत की संस्कृति, विरासत और इतिहास को नष्ट करने के तरीकों पर शोध करने में रुचि रखते हैं।

अशोका ने 2015 में येल विश्वविद्यालय सहित कई पश्चिमी संस्थानों के साथ साझेदारी की, यह आशा व्यक्त करते हुए कि इससे 'अनुसंधान में

सहयोग को आगे बढ़ाने के रास्ते' खुलेंगे।
सैलोवे ने कहा, 'भारत में हुई मेरी चर्चाओं के दौरान, भारतीय नेताओं ने मुझे बार-बार बताया कि भारत में उदार कला शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है।' उन्होंने आगे कहा, 'अशोका के संस्थापकों और शिक्षकों द्वारा प्रदर्शित उद्देश्य की गंभीरता से मैं बहुत प्रभावित हुई।' अशोका में मानवविज्ञान की प्रोफेसर दुर्बा चट्टराज ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि येल और अशोका संकाय और छात्रों के आदान-प्रदान के साथ-साथ अनुसंधान सहयोग के माध्यम से एक-दूसरे के मानवविज्ञान और समाजशास्त्र विभागों को समृद्ध कर सकेंगे।
अशोका के संस्थापक और वित्तपोषक पश्चिमी विश्वविद्यालयों से मिल रही प्रशंसा से इतने मुग्ध हैं कि उन्होंने येल-नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर साझेदारी के टूटने जैसी हालिया घटनाओं का मूल्यांकन करने की जहमत ही नहीं उठाई। इस साझेदारी के खिलाफ सिंगापुर के साहसिक रुख को देखते हुए इन भारतीय समाजसेवी लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए था। इसके विपरीत, नई नीति पारित होने के बाद, अशोका ने यूपीएन, कार्लटन विश्वविद्यालय, मिशिगन विश्वविद्यालय, येल, यूसी बर्कले, किंग्स कॉलेज, लंदन और फ्रांस में साइंसेज पो के साथ साझेदारी पर हस्ताक्षर करने की होड़ लगा दी है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल अब भारतीय छात्रों को यह सिखाने के लिए अशोका का दौरा करता है कि योग्यता स्वयं ब्राह्मणवादी पितृसत्ता है।

पश्चिमी अकादमिक जगत द्वारा अशोका विश्वविद्यालय को धमकाने का प्रयास

2021 के अंत में, अशोका विश्वविद्यालय के कुलपति प्रताप भानु मेहता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद की घटनाओं से पता चलता

है कि हार्वर्ड और येल जैसे संस्थान अशोका को अपने 'अनुसंधान' के वितरण चैनल के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं और इस वितरण चैनल पर उनका नियंत्रण किस हद तक है। मेहता के इस्तीफे पत्र में कहा गया था कि अशोका उन्हें एक राजनीतिक बोझ मानती है। पश्चिमी विश्वविद्यालयों के वामपंथी आकाओं ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। आख़िरकार, अशोका को तभी इस विशिष्ट क्लब में शामिल होने की अनुमति मिल सकती थी जब वह उनकी बात मानती। कोलंबिया विश्वविद्यालय के शेल्डन पोलॉक ने तुरंत तीखा हमला बोला: ट्रस्टियों को उन सभी नीतियों या दबावों का पूर्ण और सार्वजनिक लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होगा जिनके कारण प्रताप भानु मेहता को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा... अशोका विश्वविद्यालय के प्रति मेरा सम्मान गंभीर रूप से परखा गया है... मैंने उसी वर्ष बाद में विश्वविद्यालय को जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अशोका 'क्रॉसओवर' श्रृंखला का पहला व्याख्यान दिया; मैंने 2018 के अशोका दीक्षांत समारोह में दीक्षांत भाषण दिया; मैंने 2019 में इसके पुस्तकालय को अपने और अपनी दिवंगत पत्नी के पुस्तकों का संपूर्ण संग्रह दान किया। और मैं प्रोफेसर मेहता को लगभग 30 वर्षों से जानता हूं और उनसे 30 वर्षों तक सीखा है।

पोलॉक ने उल्लेख किया कि वे 2013 में अशोक विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में प्रमाथ राज सिन्हा के सलाहकार थे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अशोक ने उनकी मांगों का पालन नहीं किया, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे: 'यदि ऐसा नहीं किया गया, और जल्द ही नहीं किया गया,' उन्होंने कहा, 'तो विश्वविद्यालय पर लगा कलंक अमिट हो जाएगा, और इसके सबसे उत्साही प्रशंसकों का समर्थन हमेशा के लिए खो जाएगा।' हार्वर्ड के पूर्व फेलो और ब्राउन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, आशुतोष वर्शनी

(जिन्होंने 2020 में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग के समक्ष भारत के सीएए के खिलाफ गवाही देते हुए कहा था कि यह मुस्लिम प्रवासियों को निशाना बनाता है) ने एक धमकी भरा ट्वीट पोस्ट किया:

अगर अशोका के संस्थापकों को लगता है कि उन्होंने इसमें इतना पैसा लगाया है, इसलिए यह एक कंपनी बन गई है, तो चलिए अब व्यापार की बात करते हैं। अमेरिका के कई प्रमुख विश्वविद्यालय अशोका के साथ साझेदारी विकसित करने के बारे में सोच रहे थे और एक प्रमुख संस्थापक ब्राउन विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी के लिए मेरे पास आए थे। अब यह संभव नहीं है।

जल्द ही पश्चिमी शिक्षा जगत के प्रतिष्ठित लोगों ने हमेशा की तरह उन्हीं दोषियों के हस्ताक्षरों के साथ एक पत्र लिखा। इसका शीर्षक था: "शैक्षणिक स्वतंत्रता पर एक खतरनाक हमला" में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के होमी के भाभा, बर्कले स्कूल ऑफ लॉ के इरविन चेमेरिंस्की, पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के रोजर्स स्मिथ, कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के मिलान वैष्णव और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की केट ओ'रेगन शामिल हैं।

इस दबाव के आगे अशोक झुक गया और उसने अपने अमेरिकी आकाओं से माफी मांग ली:

अशोका विश्वविद्यालय ने "संस्थागत प्रक्रियाओं में कुछ कमियों" को स्वीकार किया है, जिन्हें "सभी हितधारकों के परामर्श से दूर करने का प्रयास किया जाएगा", और साथ ही विश्वविद्यालय छोड़ने वाले दोनों प्रोफेसरों की प्रशंसा भी की है। प्रशासन के सदस्यों ने यह भी कहा है कि वे "शैक्षणिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं, जो हमेशा से अशोका विश्वविद्यालय के आदर्शों का मूल रही है"।

पश्चिमी शिक्षाविदों द्वारा असहमति को बढ़ावा देने के आंदोलन भारत में राजद्रोह को भड़काने का एक बहाना मात्र हैं। वे उन विद्वानों का करियर बर्बाद करने के लिए जाने जाते हैं जिनका दृष्टिकोण उनके द्वारा निर्धारित दृष्टिकोण से भिन्न होता है। स्वतंत्र रूप से सोचने वाले विद्वान अक्सर स्थायी पद पर होने के बावजूद भी अपनी राय व्यक्त करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें वित्तपोषण, अपने पाठ्यक्रमों में छात्रों की भर्ती और अपने शोध के प्रकाशन को लेकर चिंता रहती है।

अशोका एक तकनीकी मौलिकता के लिए प्रसिद्ध शोध संस्थान नहीं है, इसलिए यह अपनी पहचान बनाने के लिए पूरी तरह से विदेशी फ्रेंचाइजी पर निर्भर है। विदेशी समर्थन वापस लेने का अर्थ होगा इसकी अब तक बनी छवि और प्रतिष्ठा का नुकसान। पश्चिमी अकादमिक गुट इस बात को भली-भांति जानता है और अपनी सत्ता और विशेषाधिकार को खतरे में पड़ने से बचाने के लिए तुरंत सक्रिय हो जाता है। अंग्रेजों ने भारत में जमींदारों और राजाओं के साथ ठीक यही किया था, उन्हें अधीनता के बदले सत्ता, रुतबा, गौरव और संरक्षण का आनंद लेने दिया था।

अशोका विश्वविद्यालय की स्थापना सिलिकॉन वैली के उन अरबपतियों ने की थी जिनका अमेरिकी पारिस्थितिकी तंत्र में व्यापक प्रभाव है। उन्होंने भारतीय सरकार को यह विश्वास दिला दिया है कि आयातित उदार कलाएँ भारत के आधुनिकीकरण का हिस्सा हैं। इस विचार को भोलापन से स्वीकार करना भारत की मूर्खता है। प्रताप भानु मेहता का इस्तीफा इस बात की पुष्टि करता है। नीचे दिया गया आरेख अशोका विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित विशाल पारिस्थितिकी तंत्र का सारांश प्रस्तुत करता है।

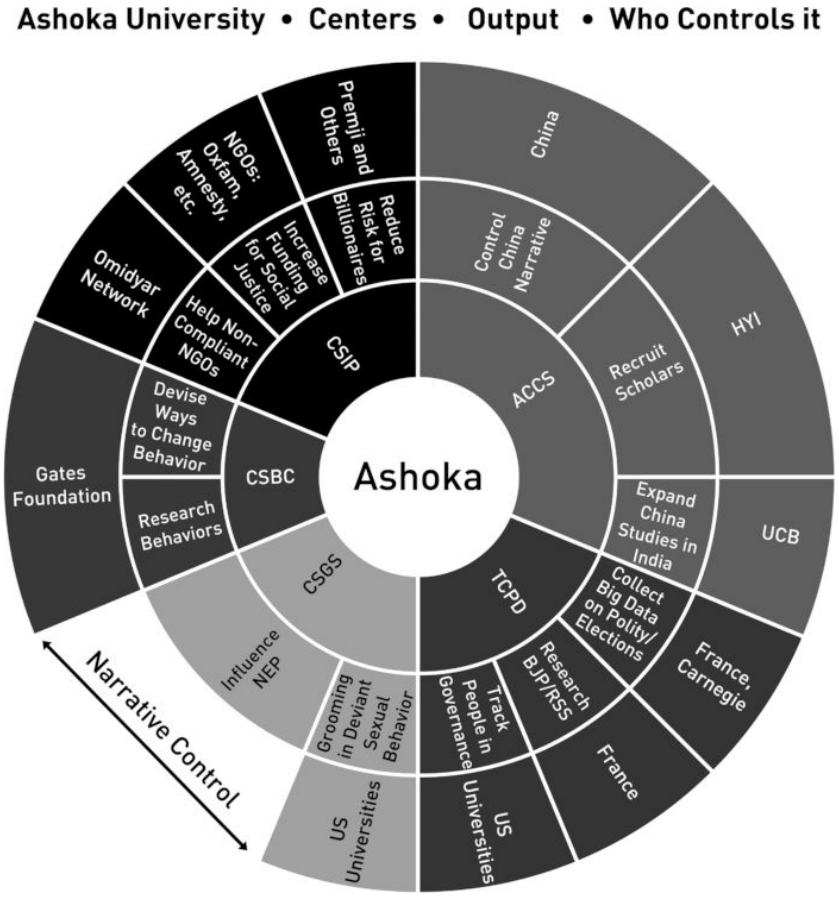

अशोका में छात्रों का वैचारिक प्रशिक्षण

विश्वविद्यालय की रणनीति ने इसे हार्वर्ड और अन्य पश्चिमी विश्वविद्यालयों के लिए ज्ञान आपूर्ति और वितरण का एक तंत्र बनाने का माध्यम बना दिया है। अशोका विश्वविद्यालय मार्क्सवादियों द्वारा नियमित प्रचार वार्ता आयोजित करता है। इनमें से कुछ प्रमुख वक्ताओं में कविता कृष्णन (तीन तलाक को अपराध घोषित करने के 'हिंदू-सर्वोच्चतावादी' अभियानों पर) और संगीतकार टी.एम. कृष्णा (अपनी संगीतमय प्रस्तुतियों में

समानता, न्याय और शासन के विचारों पर) शामिल हैं। इक्वालिटी लैब्स की थेनमोझी सौंदराजन (जिनकी चर्चा अध्याय 3 में की गई है) को जाति का लैंगिकरण और नस्ल का यौनिकरण विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था।

सौंदराजन ने यौन हिंसा और लैंगिक नियंत्रण के माध्यम से लाखों लोगों का शोषण करने के लिए गठित हिंसक 'ब्राह्मणवादी व्यवस्था' को दोषी ठहराया। उन्होंने ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के खिलाफ लड़ाई में भारत के दलित, क्वीर, ट्रांस और नारीवादी आंदोलनों की एकता को समझाया और अमेरिकी अश्वेत, नारीवादी, क्वीर, ट्रांस और संबंधित सक्रियता से इसकी तुलना की। उन्होंने श्वेत अमेरिकी विषमलैंगिक पितृसत्ता की तुलना ब्राह्मणों से की और दावा किया कि जातिगत वर्चस्व बलात्कार पर आधारित है, हालांकि उन्होंने अपने इस बेतुके दावे के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया।

अशोका द्वारा समर्थित विचारधारा-आधारित शिक्षा के खतरे अब स्पष्ट होने लगे हैं। अशोका के दो स्नातकों (ज़ैनब फ़िरदौसी और स्पर्श अग्रवाल) ने आज़ाद इंडिया कलेक्टिव (एआईसी) की स्थापना की, जिस पर सीएए विरोधी प्रदर्शनों का आयोजन करके भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। यह संगठन रटगर्स विश्वविद्यालय की कुख्यात ऑड्रे ट्रुश्के द्वारा स्थापित स्टूडेंट्स अगेंस्ट हिंदुत्व आइडियोलॉजी (एसएएचआई) नामक संगठन से संबद्ध है। यह संगठन अमेरिकी परिसरों में होली के त्योहार को हिंदुत्व-विरोधी बताकर बढ़ावा देता है। एसएएचआई के सोशल मीडिया पर घोषित उद्देश्यों में से एक है 'कश्मीर में उपनिवेशवाद का अंत, सैन्यीकरण का अंत और आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग'।

2020 में जब चीन के साथ झड़प में भारतीय सेना का एक जवान शहीद

हो गया, तो अशोका विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त छात्रों की सोशल मीडिया चैट से उनके प्रबल राष्ट्र-विरोधी भावों का पता चला। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है कि अशोका को वित्त पोषित करने वाले अरबपति अपने निवेश के इन परिणामों को चिंताजनक नहीं मानते।
2016 में, अशोका विश्वविद्यालय के अस्सी-आठ छात्रों, पूर्व छात्रों और संकाय सदस्यों ने एक याचिका तैयार की और उस पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कश्मीर में भारतीय राज्य के अत्याचारों का विरोध कर रहे विद्वानों के साथ एकजुटता का आह्वान किया गया था, कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग की गई थी और बुरहान वानी (कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी कमांडर, जो गोलीबारी में मारा गया था) की मौत को 'न्यायेतर हत्या' बताया गया था। इस मुद्दे पर पूछे जाने पर, अशोका के संस्थापक विनीत गुप्ता ने जिम्मेदारी लेने से बचते हुए और मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा: 'कश्मीर याचिका के मुद्दे पर, विश्वविद्यालय की आपत्ति याचिका या उस पर हस्ताक्षर करने वाले छात्रों से नहीं थी, बल्कि विश्वविद्यालय के नाम के दुरुपयोग से थी।'
अशोका कॉलेज 'वोकेवाद' का गढ़ है। यूट्यूब पर कुछ छात्रों के रोचक बयान मौजूद हैं जो स्थिति की गंभीरता को उजागर करते हैं। अर्थशास्त्र के एक छात्र ने कहा कि अशोका कॉलेज का माहौल सिर्फ नाम का ही विविधतापूर्ण है क्योंकि विभिन्न पहचान वाले छात्र आपस में घुलते-मिलते नहीं हैं; अमीर बच्चे एक साथ रहते हैं, पूर्वोत्तर के छात्र या विदेशी छात्र सभी अपने-अपने समूह बनाते हैं। विचारों की विविधता भी यहाँ नदारद है। इसके अलावा, कॉलेज में मुद्दों पर एक निर्धारित दृष्टिकोण है और उससे अलग हटकर बात करना अस्वीकार्य है।
एक ग्रामीण गांव के भौतिकी के छात्र ने कहा कि अशोका में वामपंथी विचारधारा वाले अमीर बच्चों की भरमार है, जिन्हें जमीनी हकीकत की

कोई समझ नहीं है। उन्होंने कहा कि अशोका के छात्र उन्हीं मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे जिन पर जेएनयू के छात्र करते हैं, लेकिन फर्क यह है कि जेएनयू के छात्र अपने मुद्दों के प्रति समर्पित रहते हैं और पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, जबकि अशोका के छात्र, क्योंकि वे समृद्ध और प्रभावशाली परिवारों से आते हैं, विरोध प्रदर्शन के बाद आलीशान बस में घर लौटते हैं। उन्होंने अशोका के विशेषाधिकार प्राप्त छात्रों के विचारों की एकरूपता पर भी शिकायत की।

इतिहास के एक छात्र ने कहा कि अशोक संस्कृति विषैली है, जहाँ छात्र जन्मस्थान के आधार पर एक-दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं, और भारत के दूरदराज के इलाकों से आए छात्र खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं। धनी छात्र ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के बोलने और पहनावे का उपहास उड़ाते हैं। अत्यधिक सहपाठी दबाव के कारण कमजोर छात्र अपने मूल्यों को भुलाकर नए मूल्य सीखने पर मजबूर हो जाते हैं, ताकि वे समाज में घुल-मिल सकें। राजनीतिक रूप से भी, विपरीत विचारों वाले छात्रों को बहिष्कृत माना जाता है। धनी छात्रों को निम्न सामाजिक-आर्थिक वर्गों के लोगों के साथ बातचीत करने का तरीका नहीं पता होता। न ही उन्हें यह पता होता है कि मौलिक रचना करने के लिए क्या आवश्यक है।

एक छात्रा द्वारा यह पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया कि गैर-वामपंथी छात्रों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार किया जाता है। उनके निष्कर्षों का सारांश प्रस्तुत करने वाले एक लेख में कहा गया है:

दक्षिणपंथी विचारधारा वाले लोगों को समलैंगिक विरोधी और लिंगभेदी मानकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और करीबी दोस्त भी उन्हें 'दफा हो जाओ' कह देते हैं। एक छात्रा ने कहा कि 'कैंपस में राजनीतिक चर्चा की अनुमति नहीं है, जब तक कि आप एक विशेष तरीके से न सोचते हों, जो मेरी राय में बहुत ही अभिजात्य वर्ग से प्रेरित है।' उसे

लगता है कि इससे अशोका कॉलेज एक तरह से अभिजात्य वर्ग की विचारधारा का गढ़ बन जाता है। एक अन्य छात्र ने कहा कि उसके कई दोस्त खुद को 'घिरा हुआ' महसूस करते हैं और अपने विचार व्यक्त करने में सहज महसूस नहीं करते।

यह दिलचस्प बात है कि अशोका में तर्कसंगतता और विचारों की विविधता की कमी पर सवाल उठाने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र अधिक प्रतीत होते हैं, न कि विशेषाधिकार प्राप्त शहरी महानगर के बच्चे।

ब्रेकिंग इंडिया 1.0 पर हमारे पहले के काम की तुलना में, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) अब विश्वविद्यालयों की तुलना में कम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिन पर पहले उतनी कड़ी निगरानी नहीं रखी गई है। साथ ही, विश्वविद्यालयों को हार्वर्ड जैसे वैश्विक ब्रांडों का संरक्षण प्राप्त है, जिन्हें भारतीय अरबपतियों का समर्थन प्राप्त है। भारत में असहमति को वित्त पोषित करने के लिए एफसीआरए के दुरुपयोग पर लगाम लगाने का प्रयास अब अप्रचलित हो गया है, क्योंकि जिन वित्तपोषण तंत्रों का हमने वर्णन किया है, वे एफसीआरए कानूनों के दायरे में नहीं आते हैं।

अशोका विश्वविद्यालय पश्चिमी उदार कलाओं के जवाब में भारत का एक प्रमुख संस्थान बन सकता था। यह भारतीय सभ्यता को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का एक अग्रणी केंद्र हो सकता था। लेकिन संस्थान को वित्त पोषित करने वाले कुलीन व्यापारियों और उससे सलाह लेने वाली सरकार, दोनों ने ही बुनियादी जांच-पड़ताल करने की जहमत नहीं उठाई। इसका अंतिम परिणाम यह है कि एक महत्वपूर्ण भारतीय संस्थान पश्चिमी अकादमिक जगत की छाया बनकर रह गया है, और निश्चित रूप से पश्चिम से प्रतिभाओं को वापस आकर्षित करने में सफल नहीं हो रहा है जैसा कि इसका उद्देश्य था, बल्कि इसके बजाय विदेशी संस्थानों को अपना प्रभाव बढ़ाने में मदद कर रहा है।

ये परिणाम तब सामने आते हैं जब भारतीय अपने स्वयं के नालंदा का पुनर्निर्माण करने के बजाय हार्वर्ड की नकल करने का निर्णय लेते हैं।

20. अजीम प्रेमजी का मीडिया और शिक्षा पर प्रभाव

अवलोकन

यह प्रशंसनीय है कि कई अरबपति अपने परोपकार के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और भारत के गरीब और वंचित वर्गों को शिक्षित करने के नेक इरादे से काम कर रहे हैं। जहां सफल सरकारें विफल रही हैं, वहां भारतीय अभिजात वर्ग ने बड़ी संख्या में आगे बढ़कर इस कमी को पूरा किया है, बिना किसी अपेक्षा के। हालांकि, हम एक ऐसा मुद्दा उठाना चाहते हैं जो विचारणीय है: ये उदार कला विश्वविद्यालय क्या पैदा कर रहे हैं और क्या यह भारत के लिए अच्छा है? यह मुद्दा परोपकारियों के आचरण या इरादों के बारे में नहीं है, बल्कि उन विद्वानों के प्रदर्शन के बारे में है जिन्हें उनका संरक्षण प्राप्त है।

अशोका विश्वविद्यालय के अलावा, भारत के अन्य प्रमुख उदार कला विश्वविद्यालयों में महाराष्ट्र का टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, कर्नाटक का अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश का शिव नादर विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र का फ्लेम विश्वविद्यालय और हरियाणा का ओ.पी. जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय शामिल हैं। ये सभी विश्वविद्यालय पश्चिमी सामाजिक विज्ञान और मानविकी पर आधारित हैं, और इन्हीं क्षेत्रों में भारत की समृद्ध बौद्धिक परंपराओं की अनदेखी करते हैं। इसलिए, इन संस्थानों के प्रदर्शन का हमारा मूल्यांकन काफी हद तक पश्चिमी उदार

कला की प्रकृति से प्रभावित होता है, जिस पर ये संस्थान आधारित हैं। ये निजी विश्वविद्यालय हार्वर्ड और अन्य पश्चिमी विश्वविद्यालयों के साथ विश्व गुरु के रूप में जुड़े हुए हैं। इनके बीच आदान-प्रदान दो प्रकार का है: भारतीय संस्थान अपने पश्चिमी संस्थानों को डेटा प्रदान करते हैं, और बदले में वे पश्चिमी सिद्धांतों को अपनाकर उन्हें भारतीय संदर्भ में ढालते हैं। आज, जाति, अल्पसंख्यक धर्म, महिलाएं आदि जैसे विषयों का अध्ययन करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्रिटिकल रेस थ्योरी का प्रयोग किया जा रहा है। मार्क्सवाद से प्रेरित उत्पीड़क/उत्पीड़ित और सिद्धांत/विरोधी अवधारणाएं मूलभूत हैं।

संक्षेप में, वही सिद्धांत, उपकरण और दृष्टिकोण जिन्हें हमने हार्वर्ड में तैयार करने के भाग 2 में समझाया था, इन विश्वविद्यालयों द्वारा, उनके फ्रेंचाइजी/एजेंटों के रूप में, भारतीय सरकार, थिंकटैंक, कॉर्पोरेट अभिजात वर्ग, उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र, मीडिया और आम जनता को वितरित किए जाते हैं।

इस तरह का पारिस्थितिकी तंत्र भारत में औपनिवेशिक काल से ही मौजूद था। हालांकि, हाल ही में इसमें ज़बरदस्त तेज़ी आई है क्योंकि पहली बार इसे भारतीय अभिजात वर्ग द्वारा वित्त पोषित और समर्थित किया जा रहा है।

इस अध्याय में हम उस तंत्र का विश्लेषण करेंगे जिसमें अजीम प्रेमजी एक विशिष्ट प्रकार के विचारों को प्रसारित करने वाले मीडिया संस्थानों को वित्त पोषित करने के लिए धनी दानदाताओं का गठबंधन बनाने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। ऐसा करने में कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि किसी भी विचारधारा को अपनाना और उसका खुले तौर पर प्रचार करना व्यक्ति की स्वतंत्रता है।

हम भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विकास में उनके कुछ

सहयोगियों द्वारा निभाई गई भूमिका पर भी चर्चा करते हैं। हमारी आलोचना केवल प्रेमजी के एनईपी 2020 में योगदान तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत में उदार कलाओं के अमेरिकीकरण पर एक व्यापक टिप्पणी है। एनईपी के तहत, अमेरिकी सिद्धांतों को स्कूलों, कॉलेजों, सरकार, कानून और नागरिक समाज के लगभग हर पहलू में आयात, अनुकूलित और स्थापित किया जा रहा है।

अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय

अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय (एपीयू) में संगोष्ठी श्रृंखला आयोजित की जाती है जिसमें छात्रों को हर्ष मंदर जैसे वक्ताओं के चुनिंदा विचारों से अवगत कराया जाता है, जो मानवाधिकारों पर बोलते हैं, कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज श्रम संघों पर बात करती हैं, संगीतकार टी.एम. कृष्णा शास्त्रीय संगीत के परिवेश में ब्राह्मणवादी पितृसत्ता पर चर्चा करते हैं, और पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन यह सवाल उठाते हैं कि 'भारतीय मीडिया में क्या गड़बड़ हो गई है?' कार्यकर्ता तीस्ता सेतलवाद को इतिहास पर विशेषज्ञ वक्ता के रूप में आमंत्रित किया जाता है। अरबपति जॉर्ज सोरोस भी अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में अतिथि वक्ता रह चुके हैं।

इनमें से कोई भी बात किसी कानून का उल्लंघन नहीं करती और न ही इसे रद्द करने की आवश्यकता है। लेकिन छात्रों को संतुलित दृष्टिकोण का अधिकार है, जिसमें विरोधी विचारों को समान स्थान मिले, और यही कमी हमें नज़र आती है।

एपीयू में शोध और चर्चा के प्रमुख विषय हिंदुत्व, आरएसएस और हिंदू राष्ट्रवाद हैं। इन विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, वे मिशनरी-आधारित गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों, विश्व में भारत के सांस्कृतिक और वैज्ञानिक योगदान, भारतीय ज्ञान का पश्चिमी ढाँचे में समाहित होना आदि

जैसे मुद्दों पर शोध या चर्चा करने से बचते हैं।
रूढ़िबद्ध विद्वानों के एक उदाहरण के रूप में, राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर मालिनी भट्टाचार्य बताती हैं कि आरएसएस की सेवा की अवधारणा के माध्यम से किस प्रकार एक 'हिंदू राष्ट्र' या राज्य का निर्माण किया जा रहा है। वे सेवा को 'रचनात्मक और अधिक गुप्त प्रकार की लामबंदी' के रूप में वर्णित करती हैं जो देखने में सौम्य और गैर-धमकी भरी लगती है। सेवा की रणनीति इस प्रकार की राजनीतिक लामबंदी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वे चिंता व्यक्त करती हैं कि 'आरएसएस नेताओं के हाथों में, इसे [सेवा] जानबूझकर दान और परोपकार की पश्चिमी अवधारणाओं की तुलना में एक विशिष्ट और "श्रेष्ठ" श्रेणी के रूप में महत्व दिया गया था।' उनका निष्कर्ष है कि 'इस प्रकार सेवा पहचान प्रदर्शन की एक प्रक्रिया बन जाती है।'
अध्याय 1 में चर्चा किए गए अनुसार, अमेरिकी विश्वविद्यालयों में एक नया चलन यह है कि विद्वत्ता और सक्रियता के बीच की सीमाएं धुंधली हो रही हैं, और कठोरता और वस्तुनिष्ठता को व्यक्तिगत किस्सों से प्रतिस्थापित किया जा रहा है जो उनके पसंदीदा सिद्धांतों का समर्थन करते हैं। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के संकाय और छात्र, कई बार, छात्रों को राष्ट्र-विरोधी गुंडागर्दी की ओर धकेलते हैं। उदाहरण के लिए:
जब भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की एक घातक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो विश्वविद्यालय के मानविकी विभाग के एक स्नातक ने उन्हें 'युद्ध अपराधी' कहा।
संकाय के कम से कम छह सदस्यों ने जेएनयू छात्रों द्वारा दायर उन याचिकाओं का समर्थन किया है, जो परिसर की राजनीति को साफ करने और इसे एक गंभीर शिक्षा संस्थान में बदलने के प्रयासों में बाधा डाल रही हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर को नक्सलवादी (आतंकवादी) गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के विरोध में कम से कम चार एपीयू प्रोफेसरों ने प्रदर्शन किया।
कई संकाय सदस्यों ने पुलवामा में हुए आतंकी हमलों पर भारत की प्रतिक्रिया की आलोचना की।
एपीयू के कई सदस्यों ने सरकार द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 का विरोध किया। उन्होंने दिल्ली दंगों से निपटने के सरकार के तरीके का भी विरोध किया।
शिक्षकों और छात्रों द्वारा की जाने वाली ऐसी गतिविधियाँ उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे में आती हैं और वित्तपोषण स्रोत पर कोई प्रभाव नहीं डालतीं। लेकिन हम आशा करते हैं कि एक अधिक खुला शैक्षणिक वातावरण बनेगा जहाँ परस्पर विरोधी विचारों पर आपसी सम्मान के साथ बहस हो सकेगी।

स्वतंत्र और जनहितैषी मीडिया फाउंडेशन
अज़ीम प्रेमजी ने इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक-स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन (IPSMF) नामक एक अलग गैर-लाभकारी संस्था भी शुरू की है, जो विशेष रूप से मीडिया और पत्रकारिता को वित्तपोषण प्रदान करती है। इसके दानदाताओं में शामिल हैं: अज़ीम प्रेमजी फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव्स, पिरोजशा गोदरेज फाउंडेशन, साइरस गुज़दर, रोहिणी नीलेकानी फिलैंथ्रोपीज़, किरण मजूमदार शॉ, अनु आगा परिवार, आरडीए होल्डिंग्स, लाल फैमिली फाउंडेशन, श्री नटराज ट्रस्ट, मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप, तेजस्किरण फार्माकेम, विदिति इन्वेस्टमेंट, यूनिमेड टेक्नोलॉजीज, क्वालिटी इन्वेस्टमेंट और पिरामल एंटरप्राइजेज।
यह संस्था कुछ मीडिया संस्थानों को वित्त पोषित करती है, जिनमें से कुछ

सरकार-विरोधी विचारधाराओं का घोर विरोध करते हैं और अति-वामपंथी विचारधाराओं की ओर झुकाव रखते हैं। इनमें द वायर, द कारवां, मोजो स्टोरी (बरखा दत्त द्वारा संचालित), इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, ऑल्ट न्यूज और फेमिनिज्म इन इंडिया शामिल हैं। ये संस्थान सीएए, किसान आंदोलन, जेएनयू आंदोलन जैसे मुद्दों पर विवादास्पद रुख अपनाते हैं और अमेरिका स्थित डिसमेंटलिंग हिंदुत्व सम्मेलन का समर्थन करते हैं।

आईपीएसएमएफ का दावा है कि उसके अनुदान और छात्रवृत्तियां 'स्वतंत्र और प्रभावशाली डिजिटल मीडिया संस्थाओं' के लिए हैं, ताकि डिजिटल मीडिया उद्यमों को जनहित के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। पत्रकारों को सामाजिक रूप से प्रभावशाली सामग्री तैयार करने के लिए प्रेरित किया जा सके...

बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने ग्लोबल मीडिया फिलैंथ्रोपी (IPSMF) की एक रिपोर्ट को वित्त पोषित किया, जिसमें हिंदू राष्ट्रवाद द्वारा निर्मित पत्रकारिता के लिए भारत के 'प्रतिकूल माहौल' में इन नए मीडिया स्टार्टअप्स की मदद करने के लिए IPSMF की प्रशंसा की गई थी। रिपोर्ट में इस बात का हवाला दिया गया कि हिंदू चरमपंथियों द्वारा पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा था, जिन्हें अक्सर 'धमकाया, हिरासत में लिया या गिरफ्तार' किया जा रहा था। हमारा मानना है कि पत्रकारों के अधिकारों और जनहित के बीच संतुलन स्थापित करना भारतीय न्यायालयों का काम है।

अशोका विश्वविद्यालय के सामाजिक प्रभाव और परोपकार केंद्र ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें इस सहयोगात्मक मॉडल की सराहना की गई है। चूंकि व्यक्तियों की तुलना में समूहों को लक्षित करना अधिक कठिन होता है, इसलिए रिपोर्ट में इसे उन अनेक रणनीतियों में से एक के रूप में

अनुशंसित किया गया है जिनका उपयोग गैर-लाभकारी संगठनों को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 और अन्य भारतीय कानूनों के उल्लंघन के जोखिम से बचने के लिए करना चाहिए।
अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन भारत में स्थित कुछ ईसाई मिशनरी संस्थानों को भी वित्त पोषित करता है, जिनमें रोंगमेई बैपटिस्ट एसोसिएशन नागालैंड; रोंगमेई नागा बैपटिस्ट एसोसिएशन, इम्फाल, (जिसे जर्मन मिशनरी संस्था ब्रोट फर डाई वेल्ट (ब्रेड फॉर द वर्ल्ड) द्वारा भी वित्त पोषित किया जाता है, जो जर्मनी में प्रोटेस्टेंट चर्चों की एक एजेंसी है); और क्रिश्चियन हॉस्पिटल, बिसमकुट्टक शामिल हैं। फिर से, वित्त पोषण के संबंध में अपनी पसंद का चुनाव करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन साथ ही, हमारे जैसे पर्यवेक्षकों के लिए इस तरह के वित्त पोषण पैटर्न में वैचारिक झुकाव को इंगित करना भी उचित है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की भूमिका
अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन के वर्तमान कुलपति अनुराग बेहार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने वाले पैनल में शामिल थे। विप्रो के पूर्व कार्यकारी बेहार, उस वामपंथी/मार्क्सवादी उदार कला शिक्षा का समर्थन करते हैं जिसकी हम आलोचना करते रहे हैं। बेहार उदार कला शिक्षा के लिए एनईपी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि यह
…उदार शिक्षा के प्रति इस दृढ़ प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है, …मीडिया में इसकी खूब चर्चा होती है; और उदार शिक्षा के प्रति यह दृढ़ प्रतिबद्धता केवल स्नातक स्तर की शिक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कक्षा 9, 10, 11 और 12 की संरचना का तरीका भी उदार शिक्षा के मूल सिद्धांतों पर आधारित है।
वे इस बात की भी प्रशंसा करते हैं कि नई नीति (एनईपी) इन संस्थानों

को 'किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप' से स्वायत्तता प्रदान करती है। यह स्वायत्तता किसी भी सरकारी या अन्य नियमन को हमारे शैक्षणिक संस्थानों की रक्षा करने से रोकती है। इससे देश की शिक्षा पर विदेशी आकाओं द्वारा चयनित और उनके हितों की पूर्ति करने वाले शासी बोर्डों के नियंत्रण में आने का खतरा मंडराता है। विदेशी वित्तपोषण स्रोत पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, पठन सामग्री, अनुसंधान के क्षेत्र और हमारे युवाओं के समग्र वैचारिकरण को अपने भू-राजनीतिक हितों के अनुरूप ढाल सकते हैं।

असल में, एनईपी भारतीय शिक्षा क्षेत्र को विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए खोल देती है, जिससे उन्हें राजस्व उत्पन्न करने वाले एक विशाल बाजार तक पहुंच मिल जाती है। यह राजस्व उन शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अर्जित किया जा सकता था जो भारतीयों द्वारा और भारतीयों के लिए स्थापित किए गए थे, और महत्वपूर्ण कमियों को पूरा करने के लिए चुनिंदा विदेशी शिक्षकों को आमंत्रित किया जा सकता था।

इसका नतीजा यह हुआ कि भारत समर्थक विचारधारा वाला कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जिससे शक्तिशाली पश्चिमी संस्थानों को ही सारी व्यवस्था चलाने का अधिकार मिल गया। एक बार फिर, भारत पश्चिमी शिक्षा का मात्र उपभोक्ता बनकर रह गया है।

एनईपी के नुकसान – धन, डेटा और प्रतिभा का बहिर्वाह

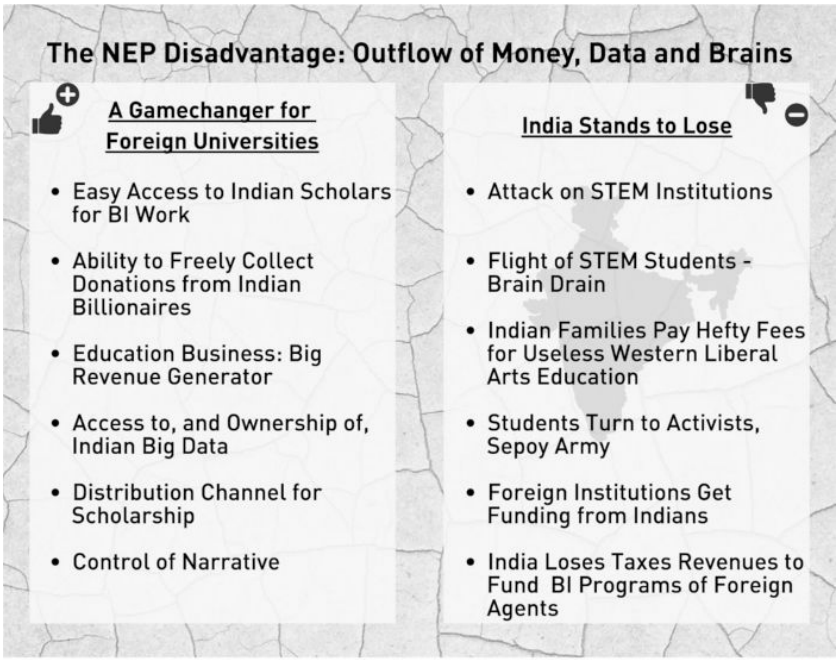

हालांकि यह विचार देखने में अच्छा लग सकता है कि भारतीय छात्रों को विदेश यात्रा किए बिना 'विश्व स्तरीय' शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले, लेकिन हमें इस वास्तविकता को समझना होगा कि पाठ्यक्रम और विषयवस्तु भारत के नियंत्रण में नहीं हैं। भारतीय और वैश्विक संस्थानों के बीच अनुसंधान सहयोग केवल दिखावटी तौर पर बराबरी के संबंधों का प्रतीक है। लेकिन नीचे दिया गया कथन इस तथ्य को उजागर करता है कि इन सहयोगों में कनिष्ठ भागीदार होने के नाते, भारतीय संस्थान मूलतः 'वैश्विक' दिखने के लिए पश्चिमी विषयवस्तु और शिक्षण पद्धति को अपनाएंगे।

अंतर्राष्ट्रीय मानकों से सुसज्जित प्रयोगशालाओं और अनुसंधान केंद्रों वाले विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। विदेशी साझेदारियों से स्थानीय संस्थानों को वैश्विक शिक्षण मानकों के अनुरूप अपना पाठ्यक्रम

तैयार करने और छात्रों को विषयों और विशेषज्ञताओं का विविध पोर्टफोलियो प्रदान करने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा, यह स्पष्ट नहीं है कि शोध कौन करेगा और किन क्षेत्रों में करेगा; भारत को किन संसाधनों का योगदान देना होगा, एकत्रित किए गए डेटाबेस को कौन संग्रहित करेगा, नियंत्रित करेगा और उसका स्वामित्व किसके पास होगा, और इसका प्रभाव क्या होगा, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में। दूसरे शब्दों में, ऐसी परियोजनाओं के अल्पकालिक, मध्यवर्ती और दीर्घकालिक परिणाम क्या होंगे?

पिछले अध्यायों में पश्चिमी अकादमिक जगत के पक्षपातपूर्ण शोध हितों पर चर्चा की गई थी। अध्याय 4 में हमने IIT और अन्य भारतीय STEM संस्थानों पर हमले के लिए इस्तेमाल की जा रही योग्यता-विरोधी विचारधारा पर भी बात की थी। इसलिए, जबकि विदेशी उदार कलाएँ और उनकी विचारधाराएँ हमारे युवाओं का मस्तिष्क धो रही हैं, STEM स्नातक बेहतर शिक्षा और करियर के अवसरों के लिए विदेश जाते रहेंगे। यह रणनीति पहले से ही दिखाई दे रही है, क्योंकि MIT STEM सहयोग लाने के बजाय J-PAL को भारत ला रहा है। स्पष्ट रूप से, भारत STEM पर ध्यान केंद्रित करने और पश्चिमी उदार कला शिक्षा को देश में प्रवेश करने से रोकने की चीन की रणनीति से सीखने में विफल रहा है। इसका स्पष्टीकरण अध्याय 8 में दिया गया था।

विदेशी संस्थान राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उपयोग करके भारत में गैर-लाभकारी संस्थाएँ स्थापित कर रहे हैं जो कर छूट का लाभ उठाकर भारतीयों से दान मांगती हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण मुंबई स्थित हार्वर्ड ग्लोबल रिसर्च सपोर्ट सेंटर इंडिया है, जिसे यह विशेष कर दर्जा प्राप्त है और यह अमेरिकी मूल संस्था के लिए काम करता है। हार्वर्ड न केवल अपनी विचारधारा से भारतीयों का उपनिवेशीकरण कर रहा है और

बहुमूल्य और संवेदनशील बड़े डेटा का दोहन कर रहा है, बल्कि वह यह सब भारतीय करदाताओं के पैसे का उपयोग करके कर रहा है।
हमारी स्थानीय संस्था, हार्वर्ड ग्लोबल रिसर्च सपोर्ट सेंटर इंडिया, धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी कंपनी है, जो हमें हार्वर्ड के कई स्कूलों और केंद्रों की ओर से भारत भर में गतिविधियों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करने में सक्षम बनाती है।
अध्याय 13 में वर्णित हार्वर्ड टी.एच. चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने भारत में डेटाबेस संकलन और उच्च स्तरीय नीतिगत कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एचएसपीएच-इंडिया हेल्थ पार्टनरशिप नामक एक औपचारिक पहल शुरू की है। हार्वर्ड ग्लोबल रिसर्च सेंटर, हार्वर्ड चान स्कूल को पूरे भारत में अनुसंधान, शिक्षण और नीतिगत कार्य करने के लिए एक महत्वपूर्ण परिचालन आधार प्रदान करता है। मुंबई में स्थित अपने कर्मचारियों के साथ, यह हार्वर्ड चान स्कूल की भौतिक उपस्थिति के रूप में कार्य करता है और निम्नलिखित गतिविधियों को सुगम बनाता है: जन स्वास्थ्य अनुसंधान; साक्ष्य-आधारित नीतियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान का अनुवाद और संचार; क्षेत्र भ्रमण और प्लेसमेंट के माध्यम से वकालत और सार्वजनिक सेवा में नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए जन स्वास्थ्य विद्वानों और चिकित्सकों की अगली पीढ़ी को प्रशिक्षण देना; कार्यशालाएँ; और विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक कार्यक्रम।
एनईपी पर हमारी मुख्य चिंता यह है: हालांकि भारत ने मिशनरी कार्यों और मार्क्सवादी/माओवादी विचारधारा से प्रेरित भारत तोड़ने की गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले गैर-सरकारी संगठनों के विदेशी वित्तपोषण पर रोक लगा दी है, फिर भी एनईपी 'शिक्षा' और 'अनुसंधान' के नाम पर हर तरह के वित्तपोषण के द्वार खोल देती है। और कई उद्यमी

भारतीयों ने विदेशी गठजोड़ों की मदद करने वाले बिचौलिए बनकर इस होड़ में हिस्सा लिया है। सन्नम एस4 ग्रुप इसका एक अच्छा उदाहरण है। नई शिक्षा नीति (एनईपी) के लागू होने से भारतीय विशाल डेटा और प्रतिभाओं का पलायन तेज हो गया है। इसने भारत को तोड़ने की ताकतों के लिए द्वार खोल दिए हैं, जो युवा छात्रों को ऐसे सिपाही बनाना चाहती हैं जो भारतीय राज्य को नष्ट कर दें। ऐसा लगता है मानो भारत को तोड़ने की ताकतों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वयं ही इस तरह तैयार किया है ताकि उनके अभियान सुचारू रूप से चल सकें। यह प्रेमजी या किसी अन्य भारतीय अरबपति की गलती नहीं है, बल्कि सरकार की नीति की आलोचना है।

21. गोदरेज और क्वीयरिंग

अवलोकन
उद्योगपति गोदरेज परिवार ने एक महत्वपूर्ण संगठन की स्थापना की है जो भारत में समलैंगिक आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। भारत में सभी लिंगों और यौन अभिविन्यासों के व्यक्तियों के लिए सम्मानजनक स्थान है, लेकिन गोदरेज विभाजनकारी और भारतीय परंपराओं के विपरीत पश्चिमी मॉडल को आयात कर रहा है। हमें उम्मीद है कि यह अध्याय ऐसे संभावित खतरों पर प्रकाश डालेगा।
वैदिक दृष्टिकोण में, एक ही परम सत्ता सर्वस्वरूप अस्तित्व में है। इसी प्रकार हम समस्त अस्तित्व का उत्सव मना सकते हैं। प्रत्येक विशिष्ट प्रकार का अनुभव विश्व के प्रति हमारे सामूहिक अनुभव को समृद्ध करता

है। LGBTQ+ समुदाय अपनी विविधता के माध्यम से समाज में हमेशा से योगदान देता रहा है। LGBTQ+ व्यक्तियों और संपूर्ण समुदाय का सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें सार्थक जीवन जीने के लिए सभी संसाधनों तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए।
हमारी चिंता इस बात से है कि LGBTQ+ आंदोलन को पश्चिम से भारत में किस औपनिवेशिक तरीके से लाया जा रहा है, जिसे पूरी तरह से पश्चिमी दृष्टिकोण में ढाला गया है। हालांकि हमारी रुचि भारत पर इसके प्रभाव पर चर्चा करने में है, लेकिन हम पहले अमेरिका में इस आंदोलन की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करेंगे, जहां से यह विश्व स्तर पर फैल रहा है।

मार्क्सवादी नींव
अध्याय 1 में, हमने मार्क्सवाद की उन प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या की, जो वोकवाद और एलजीबीटीक्यू+ आंदोलन सहित विभिन्न अमेरिकी सामाजिक आंदोलनों की नींव रही हैं। वामपंथी सामाजिक चिंतन की कुछ विशेषताओं को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है:
समाज को उत्पीड़क और उत्पीड़ित के द्वंद्व के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए।
हाशिए पर पड़ी सभी प्रकार की पहचानों को खोजना और उन्हें यह सिखाना आवश्यक है कि वे लंबे समय से उत्पीड़न का शिकार रही हैं। इस प्रकार के उत्पीड़न का इतिहास पुराना है, और उत्पीड़न की संरचनाएं सतह के नीचे दबी हुई हैं। जब तक इन संरचनाओं को पूरी तरह से उजागर करके नष्ट नहीं कर दिया जाता, तब तक उत्पीड़न जारी रहेगा, भले ही वह निष्क्रिय और छिपा हुआ हो।
समाज के आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता प्रचलित विचारधारा का मुकाबला करने के लिए एक प्रति-प्रसिद्धि विकसित करना है। यह

विचारधारा प्रभुत्वशाली समूहों द्वारा विकसित विमर्श है और यह उनके दमन का अभिन्न अंग है।

विरोधी सिद्धांत और प्रचलित सिद्धांत के बीच का संघर्ष एक पूर्ण युद्ध होना चाहिए जो पूर्ण विनाश की ओर ले जाए। इसमें किसी प्रकार के समझौते या पारस्परिक लाभ के लिए कोई गुंजाइश नहीं है।

इस प्रकार की व्यापक क्रांति की सफलता के लिए, वर्चस्ववादी विमर्श कहे जाने वाले झूठे विमर्श को नष्ट करना आवश्यक है। यह शिक्षा, मीडिया, विज्ञापन, सरकारी नीतियों और वास्तव में नागरिक समाज के सभी अंगों में व्याप्त मूलभूत कथा है। इस सर्वव्यापी बुराई से लड़ने के लिए, एक प्रति-वर्चस्ववादी विमर्श विकसित करना होगा।

इसके लिए उत्पीड़कों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाना और केवल पीड़ितों को ही अपनी बात कहने की अनुमति देना आवश्यक है। उत्पीड़कों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी तर्क, विवेक और अनुभवजन्य साक्ष्यों को अवरुद्ध करना और पूरी तरह से खारिज करना होगा, क्योंकि ये दमन की उस संरचना का हिस्सा हैं जिसे ध्वस्त किया जा रहा है।

शिक्षा, मीडिया और नीति निर्माण में केवल शोषित समुदायों के वास्तविक अनुभवों को ही सुना जाना चाहिए। यह उत्पीड़कों की 'कैंसल कल्चर' के समान है।

चूंकि किसी एक पीड़ित समूह के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत होना संभव नहीं है, इसलिए उन सभी को एकजुट होकर स्थापित व्यवस्था को हराना होगा।

इन सभी समस्याओं के लिए जिम्मेदार उत्पीड़कों का एकमात्र समूह पश्चिम में श्वेत और भारतीय समाज में ब्राह्मण हैं। इन समूहों को अपने उत्पीड़न को स्वीकार करने और माफी मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिया जाना चाहिए, और उन्हें सामाजिक क्रांति की मांगों का पालन

करके क्षतिपूर्ति करनी चाहिए।
प्रमुख मांगों में से एक निष्पक्षता की मांग होनी चाहिए, जो समानता के समानार्थक नहीं है। समानता का अर्थ है कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, चुनौतियों और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का हो, के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए और उसे सफल होने के लिए समान संसाधन और अवसर दिए जाएं। दूसरी ओर, निष्पक्षता यह मानती है कि प्रत्येक व्यक्ति में किसी विशेष क्षेत्र में समान प्रतिभा, कौशल और सफलता के अन्य कारक होते हैं; और परिणामों में कोई भी भिन्नता श्वेत वर्चस्व, पितृसत्ता, जातिवाद, ट्रांसफोबिया, नस्लवाद आदि द्वारा निर्मित एक धांधली वाली व्यवस्था के कारण होती है। योग्यता की अवधारणा ही धांधली वाली है। मुख्य लक्ष्य परिणामों को समान बनाना होना चाहिए। मार्क्सवादी विचारधारा की कई पीढ़ियों में समाहित यह सिद्धांत, इतिहास में बहुत पहले स्थापित प्रमुख पहचानों द्वारा बनाई गई संरचनाओं को ध्वस्त करने का एक कठोर और आक्रामक तरीका है। चूंकि नस्ल को नए बाहरी लोगों को शामिल करने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है, इसलिए युवाओं के बीच नए अल्पसंख्यक समूह और उपसमूह बन रहे हैं, जैसे कि अमेरिका में अश्वेत, मुस्लिम, LGBTQ+ और महिलाएं।

अमेरिका में क्वीर आंदोलन
अरबपतियों और कॉरपोरेट जगत की मदद से, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए जागरूकता का प्रसार कार्यस्थलों, विश्वविद्यालयों, प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रमों और रोजमर्रा की भाषा में गहराई तक समा गया है। कुछ साल पहले तक, विभिन्न व्यक्तिगत सर्वनामों का विचार अनसुना था। आज, यह कॉरपोरेट ईमेल का एक अभिन्न अंग है।
जागरूक अमेरिकी युवा चिंतित हैं, आसानी से उत्तेजित हो जाते हैं और

अपनी पहचान, लिंग और यौनिकता को लेकर भ्रमित हैं। उन्हें लगातार समर्थन की ज़रूरत होती है और सोशल मीडिया एक ऐसा मंच है जो उन्हें भावनात्मक रूप से मज़बूत करता है। TikTok और युवाओं के लिए बने अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे वीडियो से भरे पड़े हैं जिनमें युवा अपनी यौनिकता और लिंग के बदलते स्वरूप में अपनी स्थिति का बखान करते नज़र आते हैं। यही आजकल का जुनून है। यौनिकता, लिंग और व्यक्तिगत सर्वनामों की नई श्रेणियां रोज़ाना उभर रही हैं। अमेरिकी युवा स्पष्ट रूप से एक मनोवैज्ञानिक संकट से गुज़र रहे हैं।

पिछले दशक में, LGBTQ+ के रूप में पहचान करने वाले अमेरिकियों की संख्या में अचानक और नाटकीय रूप से भारी वृद्धि हुई है।[1] साथ ही, 2021 तक 'लिंग' को 'यौनिकता' से अलग कर दिया गया। और मीडिया ने इस विचार को बढ़ावा दिया है कि अमेरिका को विषमलैंगिक बनाने के लिए श्वेत वर्चस्व ही ज़िम्मेदार है। नवीनतम सिद्धांतों के अनुसार, सच्चाई यह है कि लिंग, जैसा कि हम सदियों से जानते आए हैं, वास्तव में एक स्पेक्ट्रम है। यह गैर-द्विआधारी है और इसका यौनिकता से कोई लेना-देना नहीं है। पिछले दशक में, LGBTQ+ यौन समूह में उप-श्रेणियों की संख्या बढ़ी है और अब इसमें शामिल हैं: लेस्बियन, गे, बाईसेक्सुअल, क्वीर, एसेक्सुअल, डेमीसेक्सुअल, ग्रेसेक्सुअल, पैनसेक्सुअल, क्वेश्चनिंग, क्वीर और ट्रांससेक्सुअल। इसके अलावा, चूंकि लिंग को स्वयं एक 'तरल, सामाजिक संरचना' माना जा रहा है, इसलिए लिंग की श्रेणियां भी बढ़ गई हैं।[2]

2021 में, न्यूज़वीक ने कुछ चौंकाने वाले आँकड़े प्रकाशित किए: तीस प्रतिशत मिलेनियल्स और उनतीस प्रतिशत जेनरेशन Z (अठारह से चौबीस वर्ष की आयु के) के बच्चों ने खुद को LGBTQ+ के रूप में पहचाना। यह संख्या बड़ी उम्र के लोगों की तुलना में तीन गुना अधिक है,

जो एक पीढ़ीगत बदलाव का संकेत देती है। क्या इस नाटकीय वृद्धि का अर्थ यह है कि अब अधिक लोग इन क्वीर श्रेणियों में खुद को पहचानने में सहज महसूस करते हैं? या यह वोकिज़्म के कारण हुआ एक सामाजिक परिवर्तन है?

कुछ लोगों का मानना है कि लैंगिक पहचान और यौनिकता के प्रति यह जुनून ध्यान आकर्षित करने वाले उन युवाओं की मनोवैज्ञानिक स्थिति को दर्शाता है जो सुरक्षा के लिए ऐसी पहचानों का सहारा ले रहे हैं। यह अमेरिकी संस्कृति के हालिया संकट का परिणाम हो सकता है। उदाहरण के लिए, न्यूज़वीक के सर्वेक्षणकर्ता और समाजशास्त्री जॉर्ज बार्ना इस प्रवृत्ति का कारण सामाजिक और समाचार कवरेज को मानते हैं, जो युवा अमेरिकियों के लिए LGBTQ+ के रूप में पहचान बनाना 'सुरक्षित और कूल' बना देता है। उनका कहना है कि यह एक खोई हुई पीढ़ी है जो जीवन में अर्थ की तलाश कर रही है और LGBTQ+ पहचान उन्हें एक सहारा देती है। यह उन्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने का एक कारण भी प्रदान करती है, जिसके चलते वे अपनी सभी समस्याओं का दोष श्वेत विषमलैंगिक पुरुषों जैसे कुछ बलि के बकरों पर डाल देते हैं।

नेशनल पब्लिक रेडियो ने रिपोर्ट किया कि अमेरिका के एक प्रतिष्ठित लिबरल आर्ट्स कॉलेज में आधे से अधिक छात्र LGBTQ+ के रूप में अपनी पहचान बताते हैं। मुख्यधारा मीडिया से युवाओं को भरपूर समर्थन मिलता है और यहां तक कि अधिकांश अमेरिकी कॉलेज आवेदन पत्रों में भी छात्रों से उनकी यौन प्राथमिकताओं और लैंगिक पहचान के बारे में बात करने को कहा जाता है। इसके अलावा, अपनी भावनाओं के अनुरूप अपने शरीर को बदलने के लिए क्रूर और कई शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं से गुजरने वाले लोगों की संख्या में भी अचानक वृद्धि हुई है।

अमेरिका में समलैंगिक जीवनशैली को प्राथमिक विद्यालय स्तर से ही

बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे छोटे बच्चों के मन में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। अपनी अस्थिरता और उद्देश्यहीनता के कारण, युवा तेजी से क्रोधी और आत्ममुग्ध होते जा रहे हैं, और उन्हें किसी भी विपरीत दृष्टिकोण को 'सूक्ष्म आक्रामकता' के रूप में आरोपित करना सिखाया जा रहा है।

यह सर्वमान्य है कि लैंगिक पहचान और यौन वरीयता के आधार पर भेदभाव और उत्पीड़न अस्वीकार्य है। हालांकि, वोकवाद समाज की मूलभूत संरचनाओं को ध्वस्त करने की मांग कर रहा है। यह भाषा को बदल रहा है, विज्ञान को नकार रहा है, दूसरों पर अपने विचार थोप रहा है, अपने पक्ष में विपरीत भेदभाव की मांग कर रहा है और युवाओं में विशेषाधिकार की भावना पैदा कर रहा है।

ट्रांसजेंडर अधिकारों की प्राप्ति महिलाओं के अधिकारों की कीमत पर हुई है, जिन्हें हासिल करने में दशकों लग गए। पुरुषों द्वारा महिला बनने और ट्रांसजेंडर महिला के रूप में प्रतिस्पर्धा करने से महिलाओं के खेल जगत को नुकसान पहुँच रहा है। यूपीएन में एक ट्रांसजेंडर तैराक कॉलेज चैंपियनशिप में लगातार जीत हासिल कर रहा है और कई रिकॉर्ड तोड़ रहा है। टीम के साथी ट्रांसजेंडर तैराक के साथ लॉकर रूम में कपड़े बदलने में असहज महसूस करते हैं। समावेशिता के नाम पर शौचालयों, स्पा और यहाँ तक कि जेलों जैसी विशेष सुविधाओं को विपरीत लिंग के लिए खोले जाने पर यौन उत्पीड़न की आशंकाएँ भी हैं। जे.के. हैरी पॉटर श्रृंखला की लेखिका जे.के. रोलिंग को ट्विटर पर ट्रांसजेंडर कार्यकर्ताओं द्वारा ट्रोल किया गया और 'बहिष्कृत' कर दिया गया, जब उन्होंने कहा कि 'महिला' शब्द को 'मासिक धर्म वाली महिलाएं' शब्द से प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा: 'यदि सेक्स वास्तविक नहीं है, तो विश्व स्तर पर महिलाओं की वास्तविक जीवन की वास्तविकता मिट जाएगी।'

लैंगिक तरलता का अर्थ होगा कि पारंपरिक अर्थों में 'महिला' जैसी कोई चीज नहीं है।
हम उन अमेरिकी सामाजिक रुझानों का विरोध नहीं कर रहे हैं जिनमें लोग स्वतंत्र रूप से चुनाव करते हैं और अपनी पसंद को प्रचारित करते हैं। हालांकि, हम इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं कि किस प्रकार पश्चिमी सामाजिक इंजीनियरिंग के इस स्वरूप को भारत के लिए अनुकूलित किया गया है और यह अशोका जैसे उदार कला विश्वविद्यालयों के साथ-साथ गोदरेज इंडिया कल्चर लैब जैसी पहलों में भी प्रवेश कर चुका है।

ट्रांस-क्वीर और भारत
पश्चिमी सभ्यता के विपरीत, भारतीय सभ्यता में ऐतिहासिक रूप से समलैंगिकता और ट्रांसजेंडर लोगों के विचार को लेकर कोई आपत्ति नहीं रही है। भारतीय मानसिकता में यह अंतर्निहित स्वीकृति है कि यह एक निजी मामला है जिसमें समाज को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और भारतीय धार्मिक ग्रंथों में भी इनके विरुद्ध कोई निषेध नहीं है।
इसके विपरीत, पारंपरिक भारतीय कथाओं में लोकप्रिय देवता अर्धनारीश्वर में पुरुष और स्त्री दोनों सिद्धांतों के संयुक्त चित्रण मिलते हैं। इस देवता की प्रतिमा में स्त्री और पुरुष शरीर का मेल है, जो लिंग भेद से परे जाकर साधक को असीम जगत की ओर ले जाता है। लिंग परिवर्तन करने वाले लोगों की पवित्र कथाएँ भी प्रचलित हैं। औपनिवेशिक काल से लेकर आज तक, भारत में ट्रांसजेंडरों को जन्म, विवाह और अन्य शुभ अवसरों पर परिवारों को आशीर्वाद देने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है।
लेकिन मुगल और ब्रिटिश शासन के दौरान, यौनिकता पर इब्राहीमी दृष्टिकोण थोपे गए, और समलैंगिक समुदाय को हाशिए पर धकेल दिया

गया और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। यहां तक कि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अनिच्छा से इस तथ्य को स्वीकार किया है, हालांकि उसने केवल अंग्रेजों को दोषी ठहराया और मुसलमानों की भूमिका पर चुप्पी साधे रखी।

सैकड़ों वर्ष पूर्व, परंपरागत हिंदू संस्कृति में, हिजड़ों को एक निश्चित स्तर का सम्मान प्राप्त था। लेकिन विक्टोरियन युग के इंग्लैंड ने इसे बदल दिया। जब अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत को उपनिवेश बनाया, तो उन्होंने यौन नैतिकता के प्रति कठोर नीति अपनाई और "प्रकृति के विरुद्ध यौन संबंध" को अपराध घोषित कर दिया। विद्वानों का कहना है कि यहीं से भारत में समलैंगिकता, ट्रांसजेंडर लोगों और हिजड़ों के प्रति मुख्यधारा की असुविधा की शुरुआत हुई।

हालांकि, अशोका विश्वविद्यालय की ट्रांसजेंडर प्रोफेसर बिट्टू कावेरी राजारामन ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा झेले जाने वाले कलंक के लिए ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को दोषी ठहराती हैं। यह उसी तरह की हूबहू नकल है जिस तरह से अमेरिकी श्वेतों को दोषी ठहराया जाता रहा है, हालांकि भारत में ब्राह्मणों ने पश्चिम के श्वेतों के समान सामाजिक भूमिकाएँ नहीं निभाई हैं। वह लिखती हैं:

हिजड़ा और किन्नर समुदायों में पारंपरिक रूप से रहने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के तहत ऐसे श्रम के प्रकार सौंपे जाते हैं जिन्हें मुख्यधारा के समाज द्वारा कलंकित माना जाता है, और लॉकडाउन के दौरान बधाई तोली/मांगती और नृत्य से लेकर यौन कार्य तक के ये सभी श्रम के प्रकार बंद हो गए हैं।

2018 में, ट्रांसजेंडर समुदाय को अंततः औपनिवेशिक काल के दौरान लागू की गई उनकी अवैध स्थिति से मुक्ति मिल गई। अब वे धीरे-धीरे हिंदू समाज में अपना खोया हुआ स्थान प्राप्त कर रहे हैं, यहां तक कि कुंभ

मेले के उपलक्ष्य में एक ट्रांस-अखाड़ा (एक प्रकार का आध्यात्मिक समूह) भी बना रहे हैं।

मंगलवार को, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी (ट्रांसजेंडर महिला) के धार्मिक आंदोलन, किन्नर अखाड़ा ने प्राचीन त्योहार के पहले दिन पवित्र गंगा और यमुना नदियों के संगम पर स्नान करने वाला पहला ट्रांसजेंडर समूह बनकर इतिहास रच दिया। यह त्योहार परंपरागत रूप से एकांतप्रिय हिंदू पुजारियों के लिए आरक्षित है, जिनमें से लगभग सभी पुरुष हैं। "सदियों बाद, आखिरकार इस समुदाय को उसका हक मिला," त्रिपाठी ने रॉयटर्स को बताया, जो अपने माइकल कोर्स बैग के बगल में एक चबूतरे पर बैठी थीं और आईफोन पर फोन कॉल का जवाब दे रही थीं। त्योहार में कई लोग त्रिपाठी की सराहना कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने भारत के "तीसरे लिंग" यानी हिजरा समुदाय के लिए हिंदू धर्म में खोए हुए स्थान को पुनः प्राप्त किया है। हजारों वर्षों से हिजरा समुदाय को अर्ध-देवताओं के रूप में पूजा जाता रहा है, लेकिन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान उनका उपहास किया गया और उन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया।

2021 में, भारत सरकार ने लोक कला में उनके योगदान को मान्यता देते हुए ट्रांसजेंडर कलाकार माता मंजम्मा जोगथी को पद्म श्री से सम्मानित किया। पूरे भारत ने इसका स्वागत किया। आयुष्मान भारत योजना या स्वस्थ भारत योजना अब ट्रांसजेंडरों के लिए लिंग परिवर्तन सर्जरी का खर्च वहन करती है। विभिन्न राज्य सरकारें ट्रांसजेंडरों को रोजगार दे रही हैं। सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण, कौशल विकास, आवास और आजीविका के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु एक योजना शुरू की है। उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक नया कानून पारित किया गया। इस प्रगति के बावजूद, इस समुदाय के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, जो कलंक, उत्पीड़न, यौन शोषण

और गरीबी का सामना करता रहता है।
हमें यह समझना होगा कि पश्चिमी समलैंगिक/ट्रांस आंदोलन, अब्राहमिक धर्मों की यौनिकता संबंधी कट्टरता के विरुद्ध एक विद्रोह है। यदि किसी पुरानी संरचना को ध्वस्त करने की आवश्यकता है, तो वह अब्राहमिक धर्मों की संरचना ही है। यह सच है कि भारत को ट्रांस समुदाय के उत्थान के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, लेकिन पश्चिमी मार्क्सवादी दृष्टिकोण इसके विपरीत परिणाम देगा।
जैसा कि हमने अध्याय 1 में देखा, क्वीर थ्योरी का दायरा सभी द्वंद्वों और मानक चिंतन को विखंडित करने और उनसे लड़ने के लिए व्यापक है, क्योंकि यह सभी मानक चिंतन को शक्ति में निहित मानती है। हमने इसकी तुलना वेदांत के उस केंद्रीय विचार से भी की, जो द्वंद्वों को ध्वस्त करने और द्वैत को मिथक के रूप में पहचानने पर केंद्रित है। क्वीर थ्योरी ने इन विचारों को उसी प्रकार अपनाया और आत्मसात किया है, जिस प्रकार उत्तरआधुनिकतावाद ने भारतीय चिंतन से बहुत कुछ लिया है। हालांकि, वेदांत में, आत्म की अवधारणा को अभिन्न एकता द्वारा मजबूती से बांधा गया है। दुर्भाग्य से, पश्चिमी क्वीर थ्योरी इस पहलू को समझने में विफल रहती है क्योंकि यह अहंकार के स्तर पर है और उच्च चेतना की समझ का अभाव है। वेदांत के अनुसार, वास्तविक ट्रांस का अर्थ है अहंकार से परे जाना।
पश्चिमी प्रश्नवादियों ने इस बात पर गहराई से विचार नहीं किया है कि पीड़ित अहंकार को किससे प्रतिस्थापित किया जाए। इसीलिए वे अंततः शून्यवाद की ओर अग्रसर होते हैं। यही कारण है कि उनका मनमाना और व्यक्तिपरक अनुभव ही सत्य का आधार बन गया है। उत्पीड़क का अहंकार पीड़ित के अहंकार से प्रतिस्थापित हो जाता है। भारतीय मार्ग व्यापक स्तर पर स्वतंत्रता प्रदान करता है, न केवल लिंग और यौनिकता

से मुक्ति, बल्कि अन्य प्रकार की अहंकार-आधारित पहचानों से भी मुक्ति। दूसरी ओर, जागरूक कार्यकर्ता यह मांग करते हैं कि उनके आंदोलन में शामिल होने के लिए व्यक्ति को दूसरों को नीचा दिखाने के जुनून में डूबा हुआ कार्यकर्ता होना चाहिए।

गोदरेज इंडिया कल्चर लैब

अशोका विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर स्टडीज इन जेंडर एंड सेक्सुअलिटी के अलावा, जो सक्रियता को बढ़ावा देने के लिए पश्चिमी क्वीर थ्योरी को आयात करने पर ध्यान केंद्रित करता है, इस क्षेत्र में दूसरा प्रमुख खिलाड़ी गोदरेज इंडिया कल्चर लैब है। इन दोनों का भारत की संस्कृति से बहुत कम संबंध है।

गोदरेज कंपनी में निसाबा 'निसा' गोदरेज, गोदरेज इंडिया कल्चर लैब (जीआईसीएल) की प्रायोजक हैं, जो परिवार द्वारा भारत में उभरते और तेजी से बढ़ते क्वीर/ट्रांस आंदोलन को बढ़ावा देकर विविधता पर अपने प्रगतिशील विचारों को प्रदर्शित करने के लिए शुरू की गई एक पहल है। भारत में अधिकांश समझदार लोग इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि लिंग या जाति के आधार पर भेदभाव बिल्कुल अस्वीकार्य है। कॉर्पोरेट जगत विशेष रूप से संवेदनशील है क्योंकि बिना भेदभाव के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को नियुक्त करना व्यवसाय के लिए लाभकारी होता है। अधिकांश भारतीय इस बात से सहमत हैं कि ट्रांसजेंडरों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें उत्पीड़न का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए, ठीक उसी गंभीरता से जैसे महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न को गंभीरता से लिया जाता है।

परमेश शाहानी, येल विश्वविद्यालय के विश्व फेलो और विश्व आर्थिक मंच के युवा वैश्विक नेता, ने 2011 से शुरू होकर एक दशक से अधिक समय

तक गोदरेज इंडिया कल्चर लैब का नेतृत्व किया। स्वयं एक क्वीर कार्यकर्ता होने के नाते, शाहानी ने LGBTQ+ मुद्दों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए और कार्यकर्ताओं को जाति, नारीवाद, लिंग और उत्पीड़न के अन्य रूपों पर अपनी शिकायतें व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान किया। वे भारतीय व्यापारिक घरानों के लिए एक सफल DEI सलाहकार हैं।

शाहानी येल समेत दुनिया भर के छात्रों के बीच एक लोकप्रिय वक्ता बन गए। उनके नेतृत्व में, गोदरेज ने भारतीय समाज में समकालीन मुद्दों, विशेष रूप से पहचान की राजनीति पर केंद्रित अध्ययन के लिए छात्रों को फैलोशिप प्रदान करना भी शुरू किया। गोदरेज इंडिया कल्चर लैब मानविकी के छात्रों के लिए फैलोशिप प्रदान करती है और इसे 'कला के प्रति कॉर्पोरेट प्रतिबद्धता' के लिए इंडिया टुडे पुरस्कार प्राप्त हुआ है। गोदरेज द्वारा प्रोत्साहित किए जाने वाले कार्यकर्ताओं का एक उदाहरण अनीश गावंडे हैं, जो गोदरेज इंडिया कल्चर लैब के ब्रांड एंबेसडर हैं। शाहानी के करीबी सहयोगी, गावंडे कोलंबिया विश्वविद्यालय में मानविकी के छात्र थे जब उन्होंने गोदरेज इंडिया कल्चर लैब में फैलोशिप पर समय बिताया और इस अनुभव से काफी प्रभावित हुए। वे स्वयं को राष्ट्र-विरोधी बताते हैं, पिंक लिस्ट इंडिया के संस्थापक हैं और दारा शिकोह फैलोशिप कार्यक्रम के निदेशक हैं, जो हार्वर्ड यूएस-इंडिया इनिशिएटिव के साथ एक साझेदारी है।

गोदरेज इंडिया कल्चर लैब को बढ़ावा देने के लिए दिए गए अपने भाषण में, गावंडे ने कश्मीर अलगाववादी आंदोलन को और तेज़ करने का आह्वान करते हुए अपना भाषण समाप्त किया। उन्होंने कहा कि जीआईसीएल डिजिटल मानविकी को कश्मीर मुद्दे से जोड़कर सक्रियता के बारे में अधिक जानने का एक मंच है। नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019

के खिलाफ रैलियों का समर्थन करने का उनका पुराना इतिहास भी है। भारत के खिलाफ लिखे उनके एक लेख का हवाला कश्मीर पर दक्षिण एशिया मानवाधिकार पर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति की सुनवाई में दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंसा भड़काने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ-साथ भारत को तोड़ने की इच्छा रखने वालों का भी उन्होंने खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने भारतीय सेना के खिलाफ भी आवाज उठाई है।

गवांडे उन LGBTQ+ कार्यकर्ताओं को शर्मिंदा करते हैं जो देशभक्त भारतीय हैं और उनके 'ब्रेकिंग इंडिया' आंदोलन से सहमत नहीं हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे GICL चुनिंदा रूप से उन LGBTQ+ कार्यकर्ताओं को मंच से हटा देता है और उनका बहिष्कार करता है जो हिंदू-विरोधी और भारत-विरोधी विचारों का समर्थन नहीं करते। ऐसे ही एक ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता गोपी शंकर मदुरै हैं, जिन्हें गोदरेज द्वारा प्रायोजित एक बड़े कार्यक्रम से मंच से हटा दिया गया था। यह सब तब हुआ जब गोदरेज गर्व से समावेशिता और प्रगतिशील नीतियों का समर्थन करने का दावा करता है।

जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी आलोचना LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि इस समुदाय का राजनीतिक रूप से कश्मीर, CAA आदि जैसे असंबंधित एजेंडों को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है।

मानव संसाधन नीतियां

गोदरेज की रणनीति यह है कि कॉर्पोरेट सिस्टम में घुसपैठ करने के बाद LGBTQ+ कार्यकर्ता आक्रामक हो जाएं। परमेश शाहानी कॉर्पोरेट जगत में LGBTQ+ घुसपैठिए के रूप में अपनी सफलता पर गर्व करते

हैं। गोदरेज ने LGBTQ+ मुद्दों पर अपनी मानव संसाधन नीतियां बनाई हैं और कॉर्पोरेट ESG रेटिंग का उपयोग करके अन्य कंपनियों पर इन्हें अपनाने के लिए दबाव डालता है। LGBTQ+ समुदाय के लिए आक्रामक मांगों को शामिल करके, उनकी रणनीति कंपनियों पर गोदरेज का अनुसरण करने के लिए दबाव डालना है।

शाहानी ने भारतीय कार्यस्थल में ट्रांसजेंडर समावेशन के लिए एक घोषणापत्र तैयार किया है, जिसमें उन्होंने कई मांगें रखी हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की महंगी प्लास्टिक सर्जरी शामिल हैं जिन्हें कंपनी बीमा द्वारा कवर किया जाना चाहिए, ताकि ट्रांसजेंडर लोगों के लिए समावेशी माना जा सके। उन्होंने स्त्रीत्व और पुरुषत्व प्रदान करने वाली शल्य चिकित्सा और गैर-शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं की भी मांग रखी है। शाहानी स्पष्ट रूप से एक कार्यकर्ता हैं जब वे कहते हैं: 'यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जब कोई व्यक्ति संक्रमण का विकल्प चुनता है, तो संगठन भी उसके साथ संक्रमण करता है।' वे कंपनियों पर ट्रांसफोबिया का आरोप लगाते हैं यदि वे उनके दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करती हैं। घोषणापत्र में कहा गया है कि कंपनियों को 'लिंग-आधारित भाषा' (जैसे 'वह/वह') से बचना चाहिए। उनका मानना है कि लिंग-आधारित भाषा का उपयोग करना अनजाने पूर्वाग्रह को दर्शाता है और इस तथ्य की पुष्टि करता है कि कंपनी ट्रांस-अनुकूल कार्यस्थल नहीं है।

शाहानी भारतीय कॉरपोरेट्स को नवीनतम अमेरिकी तौर-तरीकों के बारे में सिखाती हैं, जिनमें भाषा, कार्यस्थल का पुनर्गठन और ट्रांसजेंडर मुद्दों पर कर्मचारियों का निरंतर पुनर्प्रशिक्षण शामिल है। घोषणापत्र में एक कॉरपोरेट मानक की भी वकालत की गई है कि 'नए कर्मचारियों के लिए लैंगिक पहचान पर एक अनिवार्य प्रशिक्षण मॉड्यूल होना चाहिए'। इसमें यह भी कहा गया है कि 'ड्रेस कोड लैंगिक रूप से तटस्थ होना चाहिए',

यानी यह लैंगिक भेदभाव पर आधारित नहीं होना चाहिए (जैसे महिलाओं के लिए स्कर्ट, पुरुषों के लिए टाई)।
हम इस बात से सहमत हैं कि ट्रांसजेंडरों को ऐसे शौचालयों की आवश्यकता है जिनका उपयोग वे सहजता से कर सकें, लेकिन शाहानी एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं कि महिलाओं को ट्रांसजेंडरों (जिनके जननांग आमतौर पर पुरुष जननांग होते हैं) द्वारा महिलाओं के शौचालयों का उपयोग करने में सहजता महसूस करनी चाहिए। वे लिखते हैं:
लिंग-तटस्थ शौचालय 'तीसरे लिंग' या 'ट्रांसजेंडर' के बजाय बेहतर हैं, क्योंकि ऐसे शौचालय स्पष्ट रूप से भेदभाव पैदा करेंगे। ट्रांसजेंडर कर्मचारी जो अभी तक खुलकर सामने नहीं आए हैं, वे शायद 'तीसरे लिंग' वाले शौचालय का उपयोग नहीं करना चाहेंगे, जबकि लिंग-तटस्थ शौचालय सभी के लिए खुले हैं।
इसके अलावा, वह चाहते हैं कि प्रत्येक कंपनी ट्रांसजेंडर समावेशन के लिए विशेष परिवहन विकल्पों पर विचार करे और उन्हें सुरक्षित आवास खोजने में मदद करे। कॉर्पोरेट भर्ती के संबंध में, शाहानी कहते हैं कि ट्रांसजेंडर-अनुकूल होने के लिए, कंपनियों को 'अपने मानदंडों में ढील देनी चाहिए और संचार और प्रस्तुति जैसे कौशल का मूल्यांकन करना चाहिए यदि वे वास्तव में कंपनी में समावेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं'।

अमेरिकी वोकवाद से असहिष्णुता का आयात
येल विश्वविद्यालय में एक भाषण के दौरान, शाहानी ने अपने से असहमत होने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति अपनी असहिष्णुता प्रदर्शित की। यह अमेरिकी वोकिज़्म की असहमति के खिलाफ़ 'कैंसल कल्चर' की नकल है। उनके भाषण पर एक रिपोर्ट कहती है कि वह चाहते हैं कि...
संदेह करने वालों के लिए कोई जगह न छोड़ें। "जब कमरे में कोई खड़ा

होकर कहे, 'मुझे थोड़ी देर के लिए विरोधी पक्ष की भूमिका निभाने दीजिए,' तो कहिए 'नहीं।' अगर कमरे में कोई आशा का दूत या समझदारी का दूत नहीं बन सकता, तो नहीं। नकारात्मक बातें करने वालों को चुप कराओ," शाहानी ने मुस्कुराते हुए लेकिन गंभीरता से कहा। "हमें इस समय आपकी ज़रूरत नहीं है। हमें आपकी कभी ज़रूरत नहीं होगी।"
जागरूकता, समान अवसर की नीतियां और उत्पीड़न न करना सराहनीय प्रयास हैं, लेकिन शाहानी गोदरेज में आक्रामक रूप से अपना एजेंडा आगे बढ़ाते हैं और फिर 'गोदरेज के प्रभाव' का इस्तेमाल करके अन्य निगमों में भी अपनी सक्रियता को बढ़ावा देते हैं। उनकी मांगें बहुत कठोर हैं और यदि कोई कार्यकारी अधिकारी विरोध करता है या निगम के भीतर LGBTQ+ से संबंधित प्रस्तावों पर बहस करना चाहता है, तो उसे चुप करा दिया जाता है। शाहानी हर जगह बढ़ती हुई तीव्रता के साथ उन्हीं बातों को दोहराते हैं।
किसी भी बैठक में हमेशा कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता है, जो आपके किसी भी क्रांतिकारी या नवोन्मेषी सुझाव को अस्वीकार कर देता है, और यह व्यक्ति आमतौर पर पुरुष होता है, और मेरे अनुभव में तो वह अक्सर उम्रदराज पुरुष होता है। ... ऐसे व्यक्ति से सामना होने पर सबसे पहले आपको हाथ उठाकर कहना चाहिए, 'नहीं', बस 'नहीं!' शायद आपको कुछ समय के लिए शैतान का वकील बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि शैतान के कई वकील होते हैं... यह मेरा हल्का जवाब है... क्योंकि इस शैतान के वकील वाली बकवास की वेदी पर कई अच्छे विचार बलिदान हो चुके हैं, और यह बकवास हमेशा किसी डरे हुए व्यक्ति से आती है, किसी उम्रदराज व्यक्ति से, जो डरा हुआ है, जिसके आसपास दुनिया बदल रही है, उसे पता नहीं है, इसलिए वह अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहता है।

जैसा कि अध्याय 1 में चर्चा की गई है, यह वही रणनीति है जिसका इस्तेमाल अमेरिका में क्रिटिकल रेस थ्योरी के समर्थक रॉबिन डिएन्जेलो और इबराम एक्स. केंडी करते हैं। उनका कहना है कि किसी भी विरोधी को खारिज कर देना चाहिए, चाहे इसका मतलब उस व्यक्ति को बहिष्कृत करना हो या उसे चुप करा देना हो। अगर हम डिएन्जेलो और केंडी के लेखन में नस्लवाद शब्द को ट्रांसफोबिया से बदल दें, तो शाहानी ठीक यही रणनीति अपना रहे हैं। वोकिज़्म के तौर-तरीके सिखाते हैं कि शिकायत करने वाले समूहों को संदेह करने वालों को तब तक धमकाना चाहिए जब तक वे हार न मान लें।

शाहानी मानव संसाधन नीति पर बहस करने का अधिकार और दायित्व रखने वाले अधिकारियों के सवालों का भी जवाब देने से इनकार करते हैं। हमें उनकी मांगें अनुचित लगती हैं: कार्यस्थल पर सभी को समान अवसर मिलना और उत्पीड़न से मुक्त होना एक बात है, लेकिन LGBTQ+ समुदाय का व्यवसाय में भारी संख्या में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना बिलकुल अलग बात है। शाहानी तो व्यावसायिक नेताओं के वेतन को उनके द्वारा नियुक्त किए गए समलैंगिक और ट्रांसजेंडर लोगों की संख्या से जोड़ना चाहते हैं।

अनजाने में ही, गोदरेज राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मंच प्रदान करके भारत को तोड़ने वाली ताकतों का समर्थन कर रहा है। उदाहरण के लिए, वामपंथी कलाकारों को बढ़ावा देने वाली एक गैर-सरकारी संस्था, इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स (IFA), गोदरेज इंडिया कल्चर लैब के मंच पर कला के माध्यम से असहमतिपूर्ण विचारों को वित्तपोषित करने के महत्व के बारे में बात करने के लिए उपस्थित थी। IFA की अरुंधति घोष ने खुले तौर पर कहा कि वे राजनीतिक कला के लिए अनुदान देते हैं: 'हम ऐसे कई कार्यों का समर्थन करते हैं जो अनछुए क्षेत्रों में हैं और जाति, लिंग,

यौनिकता जैसे मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं...'
इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स के संरक्षकों की सूची में धनी कॉरपोरेट दानदाता और व्यापारिक नेता शामिल हैं और अनुदान एवं कार्यक्रमों के लिए इसका वार्षिक बजट तीन से पांच करोड़ रुपये है। कई अमेरिकी और भारतीय कॉरपोरेट भी दानदाताओं के रूप में सूचीबद्ध हैं।
निष्कर्षत:, हमारा मानना है कि गोदरेज ने भारतीय व्यवसायों को LGBTQ+ संवेदनशीलता से परिचित कराने में अग्रणी भूमिका निभाई है। लेकिन जिस तरह से उनके प्रमुख प्रतिनिधियों ने इस दृष्टिकोण को लागू किया है, उससे यह उन मुद्दों (जैसे कश्मीर, सीएए आदि) पर पक्षपातपूर्ण राजनीति में तब्दील हो गया है जिनका LGBTQ+ समुदाय की जरूरतों से कोई संबंध नहीं है। हमारे विचार में, एक बेहतर दृष्टिकोण वह होगा जो विभाजनकारी राजनीति में हस्तक्षेप किए बिना, LGBTQ+ व्यक्तियों का सम्मान करते हुए भारतीय पारंपरिक विचारों पर आधारित हो।

22. ओमिडयार नेटवर्क: भारत में ट्रोजन हॉर्स

अवलोकन
मुंबई स्थित ओमिडयार नेटवर्क इंडिया (ONI) ईबे के संस्थापक पियरे मोराद ओमिडयार की भारतीय पहल है, जिनकी कुल संपत्ति लगभग बीस अरब डॉलर है। वे समाज और राजनीति की मूलभूत कार्यप्रणाली को बदलने की इच्छा रखने वाले एक परोपकारी व्यक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उनका परिचय देने का एक उपयुक्त तरीका यह होगा कि उन्हें एक

अन्य अरबपति, जॉर्ज सोरोस के युवा संस्करण के रूप में देखा जाए। दोनों ही बेहद धनी और स्व-निर्मित हैं और अपनी संपत्ति का उपयोग अपने आदर्श समाज के अनुरूप विश्व स्तर पर सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए करना चाहते हैं।

दोनों को मानवतावादी के रूप में चित्रित किया गया है जो 'लोकतंत्र की रक्षा' कर रहे हैं। वे समाजों को अधिनायकवाद से लड़ने में मदद करना चाहते हैं। दोनों ही तथाकथित 'अच्छे पुलिस वाले' हैं जो वैश्विक मोर्चे पर काम कर रहे हैं, जहाँ असभ्य लोगों (अर्थात, जो उनके विश्वदृष्टिकोण से असहमत हैं) और उनकी संस्कृतियों को सभ्य बनाने की आवश्यकता है।

इन दोनों में से, ओमिडयार तकनीकी रूप से कहीं अधिक कुशल और सामाजिक इंजीनियरिंग के प्रति रणनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं। उनके 'निवेश' सावधानीपूर्वक चुनी गई शब्दावली में व्यक्त किए जाते हैं, और सतह के नीचे छिपी सामाजिक-राजनीतिक उथल-पुथल को समझने के लिए गहराई से छानबीन करनी पड़ती है। फोर्ब्स के एक लेख में ओमिडयार को 'हमले के तहत लोकतंत्रों' के रक्षक के रूप में चित्रित किया गया है। जब वे 'डेटा सुरक्षा और गोपनीयता अधिकार' प्रदान करने वाले उद्यमों में निवेश करते हैं, तो उनका दीर्घकालिक उद्देश्य नागरिकों को उनकी अपनी सरकारों से बचाना होता है जो निगरानी और नियंत्रण के लिए नई तकनीकों का उपयोग कर सकती हैं। विडंबना यह है कि उनके कई उद्यम विशेष रूप से डेटा संग्रह, व्यवहार विश्लेषण और विभिन्न प्रकार के एआई अनुप्रयोगों के क्षेत्र में हैं।

एक विदेशी संस्था होने के नाते, ओमिडयार की खासियत यह है कि भारत में उसका अपना वितरण चैनल है, जो सरकार के उच्चतम स्तर से लेकर व्यवसायों और व्यक्तिगत नागरिकों के स्तर तक भारतीय मामलों में गहराई से जुड़ा हुआ है।

केंद्र और राज्य सरकारों तथा उनके विभिन्न विभागों के साथ तकनीकी साझेदारी के जाल का उपयोग करते हुए, ओमिडयार नेटवर्क इंडिया ने खुद को भारतीय जनता और उनकी सरकारों के बीच स्थापित कर लिया है। पहला, इससे उसे भारतीयों पर बहुमूल्य डेटा एकत्र करने और भविष्य में सामाजिक इंजीनियरिंग के उद्देश्य से समाज और व्यवहार के मॉडल विकसित करने और उनका अध्ययन करने में मदद मिलती है। दूसरा, यह इसे प्रभावी रूप से एक समानांतर शासन संरचना के रूप में स्थापित करता है, जो विडंबना यह है कि स्वयं भारतीय सरकार की मदद से ही निर्मित हो रही है। हम ओमिडयार द्वारा इन उद्देश्यों की प्राप्ति को सुगम बनाने के लिए अपनाई गई विभिन्न रणनीतियों को प्रदर्शित करेंगे। तुलनात्मक रूप से, पश्चिम से पहले के सभ्यतागत अभियान कम परिष्कृत थे, जिनमें अधिक समय, संसाधन और जनशक्ति की आवश्यकता होती थी। ओमिडयार का दृष्टिकोण कहीं अधिक कुशल है क्योंकि भारतीय स्वयं काम करते हैं, राजस्व उत्पन्न करते हैं और वास्तविक समय की निगरानी के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। वे अक्सर युवा, अनुभवहीन और प्रतिभाशाली होते हैं, और उन्हें सावधानीपूर्वक ऐसे नेताओं के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है जो उनके मिशन को पूरा कर सकें। इसके अतिरिक्त, ओमिडयार ने रणनीतिक महत्व के संगठनों में निवेश किया है जो डेटासेट प्रदान कर सकते हैं या वांछित मीडिया कवरेज उपलब्ध करा सकते हैं।

पृष्ठभूमि: द अमेरिकन पेरेंट

हालांकि यहां हमारी रुचि ओमिडयार के भारतीय उपक्रमों में है जिन्हें ओमिडयार नेटवर्क इंडिया के तहत कार्यान्वित किया गया है, लेकिन हम पहले उनकी अमेरिका स्थित गतिविधियों के बारे में बताएंगे ताकि उनके

संचालन के वैश्विक दृष्टिकोण को समझा जा सके।
प्रारंभ में हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमें उनके द्वारा किए गए किसी भी गैरकानूनी कार्य की जानकारी नहीं है। उन्हें अपनी विचारधारा के अनुसार समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपने धन का उपयोग करने का पूरा अधिकार है। वास्तव में, भारत में उनके द्वारा वित्तपोषित कई परियोजनाएं उन उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक हैं जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, और जिन उद्यमियों का वे समर्थन करते हैं वे प्रतिभाशाली युवा पुरुष और महिलाएं हैं जो प्रोत्साहन के पात्र हैं।
हम व्यापक परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए ओमिडयार की अमेरिकी गतिविधियों पर एक खोजी रिपोर्ट का संदर्भ लेंगे। "द बिलियनेयर टेकओवर ऑफ सिविल सोसाइटी" शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में, कनाडाई लेखिका रोज़लिन फुलर ओमिडयार को एक और भी बड़े 'एनजीओ-औद्योगिक परिसर' का हिस्सा बताती हैं, जिसमें राजनीतिक वित्तपोषण का एक संपूर्ण जाल शामिल है। वह लिखती हैं:
यदि हम ओमिडयार जैसे ‘दानदाताओं’ की बातों को स्वीकार करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जरूरतमंदों के लिए अस्पताल की स्थापना जैसे पारंपरिक परोपकारी कार्यों में भाग लेने के बजाय, वे ‘सामाजिक इंजीनियरिंग’ में संलग्न होने का प्रयास कर रहे हैं – अर्थात्, अपने संसाधनों का उपयोग करके समाज की संरचना को कृत्रिम रूप से उस रूप में बदलने का प्रयास कर रहे हैं जैसा वे चाहते हैं। यदि वे सफल होते हैं, तो यह लोकतंत्र का घोर उल्लंघन होगा, जिसमें धन का उपयोग न केवल चुनाव जीतने के लिए किया जाएगा, बल्कि वास्तविक समर्थन के स्थान पर सशुल्क या रियायती सामग्री का उपयोग करके, कुछ आवाजों को बुलंद करके और दूसरों को दबाकर, पूरी राजनीतिक संस्कृति को एक अलग दिशा में मोड़ दिया जाएगा।

सामने दिया गया आरेख दर्शाता है कि निधियों का एक सघन जाल है, और ये निधियां अन्य निधियों को धन देती हैं, जो आगे चलकर अन्य निधियों को धन देती हैं, और यह सिलसिला चलता रहता है। इससे निधियों के स्रोत और गंतव्य के बारे में पारदर्शिता अस्पष्ट हो जाती है। यह विडंबनापूर्ण है, क्योंकि ओमिडयार के परोपकार का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक पसंदीदा शब्द विश्व स्तर पर शासन में 'पारदर्शिता' है।

आरेख की ऊपरी पंक्ति में दर्शाए गए सभी फंड ओमिडयार के स्वामित्व वाले संगठनों से हैं। नीचे के संगठन अन्य अरबपतियों के हैं जो समान उद्देश्यों के लिए सहयोग कर रहे हैं। यहाँ उद्देश्य यह दर्शाना है कि ये समूह परस्पर संबंधित उद्देश्यों वाले एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं।

आइए फंडिंग स्रोतों में से एक, ल्यूमिनेट पर गौर करें, जो ओमिडयार समूह का हिस्सा है और जिसकी अध्यक्षता पियरे ओमिडयार करते हैं। ल्यूमिनेट जिन संगठनों को फंड देता है उनमें से एक है न्यू मीडिया वेंचर्स: इनोवेशन फंड (NMV)□ ल्यूमिनेट के एक लेख के अनुसार: 'न्यू मीडिया वेंचर्स अमेरिका में लोकतंत्र की रक्षा के लिए व्यापक प्रयास कर रहा है।' इसे मीडिया और तकनीकी स्टार्टअप्स को समर्थन देने वाले एक सीड फंड के रूप में वर्णित किया गया है जो 'राजनीति में बदलाव लाते हैं और प्रगतिशील परिवर्तन को गति देते हैं'। उन्हें गर्व है कि उनके स्टार्टअप 'नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देते हैं', 'संस्कृति को बदलते हैं' और 'आंदोलनों का निर्माण करते हैं'। लक्ष्य 'उद्यमियों और कार्यकर्ताओं में निवेश करना है जो हमारे लोकतंत्र के सामने आने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों से जूझ रहे हैं'। ये सभी आदर्श दुनिया को बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में, ये निष्पक्ष नहीं हैं और

सामाजिक विज्ञान से प्रेरित वैचारिक पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं।
उदाहरण के लिए, हमने पिछले अध्याय में उल्लेख किया था कि एनएमवी, इक्वालिटी लैब्स का मुख्य वित्त पोषण स्रोत है, जो अमेरिकी उद्योग, नागरिक समाज और कॉलेज परिसरों में जाति को औपचारिक रूप से नस्लवाद के रूप में वर्गीकृत करने के आंदोलन का नेतृत्व करता है। ओमिडयार से प्राप्त धन का प्रवाह इस प्रकार है:

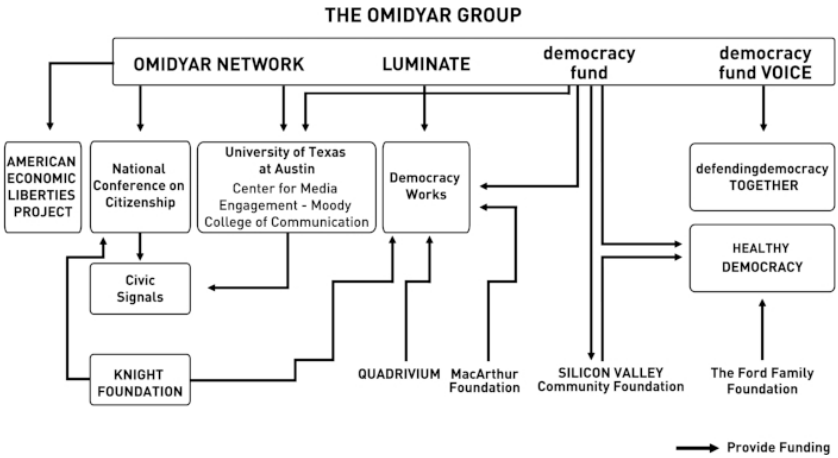

ओमिडयार → ल्यूमिनेट → न्यू मीडिया वेंचर्स → इक्वालिटी लैब्स[7]
निम्नलिखित आरेख अमेरिका में ल्यूमिनेट द्वारा प्रदान की गई फंडिंग के एक नमूने को ज़ूम करके दिखाता है। इससे पता चलता है कि ओमिडयार के फंडिंग तंत्रों में से केवल एक का प्रभाव कितना व्यापक है।
ओमिडयार की गतिविधियों का वर्णन अत्यंत सटीकता से किया गया है – ठीक किसी इंजीनियरिंग परियोजना की तरह। इसमें एक अत्यंत अनुशासित, औपचारिक प्रक्रिया का आभास होता है। युवा टेक्नोक्रेट्स उस शब्दावली से प्रभावित होते हैं जो उन्हें 'तथ्यों', 'विज्ञान', 'सबूत-आधारित निर्णय लेने' और विभिन्न प्रकार के 'टूलकिट' द्वारा संचालित एक आंदोलन के गौरवान्वित सदस्य होने का एहसास कराती है।

ओमिडयार 'अनुसंधान' संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क में भी निवेश करता है जो जानकारी संकलित करते हैं और वकालत के लिए स्थिति पत्र तैयार करते हैं। यह तथाकथित 'अभूतपूर्व अनुसंधान' उस जटिल जाल का हिस्सा है जो उनकी विचारधारा का समर्थन करता है।

रोस्लिन फुलर को ओमिडयार के बारे में जो बात झूठी लगती है, वह यह है कि युवा प्रतिभागियों को सशक्त बनाने के बजाय उनका एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिरकार, वे एक निवेश कोष के पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं जो उनका उपयोग 'सत्ता परिवर्तन' के लिए कर रहा है। इसमें शामिल लगभग सभी लोग युवा और अनुभवहीन हैं, लेकिन उन्हें बहुत अधिक वेतन मिलता है। वे एक ऐसी सेना की तरह हैं जो लगातार गश्त पर रहती है, अपने उद्देश्य की रक्षा करती है और उसका विस्तार करती है। यह व्यवस्था आपस में मिलीभगत वाली है। परस्पर संबंधित संगठन एक-दूसरे के काम का हवाला देते हैं और आपस में साझेदारी करते हैं। वही कर्मचारी और नेता बार-बार चुने जाते हैं।

स्टार्ट-अप्स, परियोजनाओं और सहयोगों का यह जटिल जाल कुलीनतंत्र की सत्ता की भूख को बढ़ावा देता है। ग्लेन ग्रीनवाल्ड, जिन्होंने 'द इंटरसेप्ट' की सह-स्थापना मुख्यधारा के कॉर्पोरेट आउटलेट्स के लिए 'बहुत अधिक सत्ता-विरोधी और कट्टरपंथी आवाजों के लिए एक मंच' के रूप में की थी, इस बारे में बात करते हैं कि 'यह अपरिहार्य है कि एक अरबपति फंडदाता की विचारधारा, विचार और राजनीतिक एजेंडा अंततः किसी भी परियोजना को दूषित और हावी कर देगा जिसके लिए वे एकमात्र या प्राथमिक फंडदाता हैं'।

यह बात तब और भी सच हो जाती है जब संबंधित अरबपति-संस्थापक अपनी विचारधारा के अनुसार दुनिया को बदलने के मिशन पर होता है। ऐसे में, उसके लिए निम्न वर्गों का उत्थान करना ही काफी नहीं होता, जो

कि वह दिखावटी तौर पर करने की कोशिश करता है और अपनी गतिविधियों को इसी तरह पेश करता है। उसे विमर्श को नियंत्रित करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ना होगा। ग्रीनवाल्ड कहते हैं:

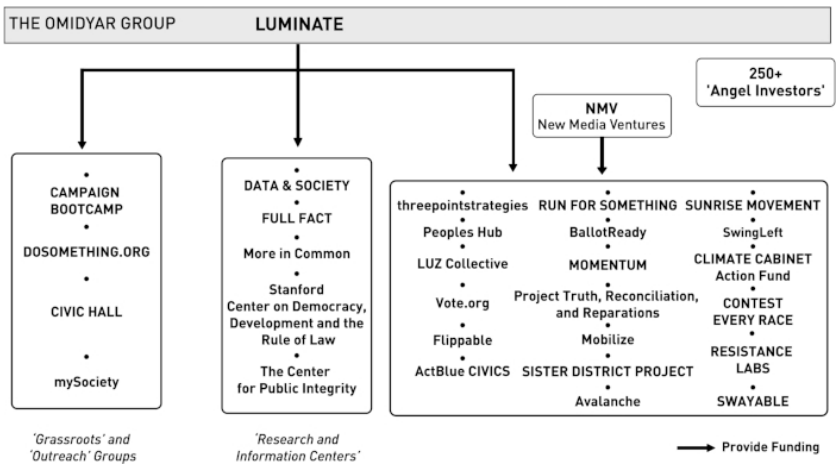

ओमिडयार कोई गैर-राजनीतिक या तटस्थ इंटरनेट प्रशासन का संरक्षक नहीं है; वह समाज के सबसे चर्चित मुद्दों पर बेहद मुखर विचार रखने वाला एक अत्यधिक राजनीतिक और वैचारिक व्यक्तित्व है। और यही कारण है कि इंटरनेट को नियंत्रित करने और उस पर निगरानी रखने का अभियान —ऑनलाइन क्या कहा जा सकता है और क्या नहीं, इस पर नियंत्रण को और अधिक केंद्रीकृत करने के लिए दबाव अभियान चलाना, और स्वीकार्य माने जाने वाले विचारों की सीमा को और अधिक प्रतिबंधित करना—लगभग पूरी तरह से ओमिडयार जैसे मुट्ठी भर अरबपतियों द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है, यह बेहद खतरनाक है। चाहे वे कितने भी परोपकारी और नेक इरादे वाले हों, वे जिस शक्ति और नियंत्रण का प्रयोग करेंगे, वह अपरिहार्य होगा, भले ही वे ऐसा न करने का प्रयास करें। और जब एक स्वतंत्र इंटरनेट की बात आती है, तो मुट्ठी भर समान विचारधारा वाले अरबपतियों को अपनी विशाल संपत्ति का उपयोग करके

स्वीकार्य अभिव्यक्ति की सीमाओं को नियंत्रित करने की अनुमति देने से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं है।

इसका अंतिम परिणाम यह है कि अरबपतियों और करोड़पतियों के लाभ के लिए नागरिक समाज के मानदंडों का व्यवसायीकरण हो जाता है। वे एक पवित्र मिशन पर निकले हुए महापुजारी हैं।

द इंटरसेप्ट के सह-संस्थापक होने के बावजूद, ग्रीनवाल्ड को अंततः बाहर कर दिया गया। ओमिडयार को वरिष्ठ संपादकीय टीम को भारी वेतन देने और अपने वामपंथी विचारों को सार्वजनिक करने के अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। ग्रीनवाल्ड संपादकीय टीम की स्थिति स्पष्ट करते हैं:

ओमिडयार द्वारा संपादकीय स्वतंत्रता के स्पष्ट दावे के बावजूद, वे पूरी तरह से ओमिडयार की मनमानी और पसंद के गुलाम और भयभीत रहते हैं। ... द इंटरसेप्ट के संपादकों और वरिष्ठ लेखकों को बाजार दर से कहीं अधिक भारी वेतन मिलता है। चूंकि यह वेबसाइट लगभग पूरी तरह से ओमिडयार की असीमित संपत्ति पर निर्भर है, इसलिए यह कोई सदस्यता या विज्ञापन नहीं बेचती है और इसलिए राजस्व उत्पन्न करने के लिए इस पर कोई दबाव नहीं है। ... भारी वेतन, अंतहीन खर्च खाते, नौकरी की आवश्यकताओं का पूर्ण अभाव, और यहां तक कि दर्शकों को आकर्षित करने की भी कोई आवश्यकता नहीं... ओमिडयार से पैसा लगातार आता रहता है।

वे एक ऐसे उद्योग में काम करते हैं जहाँ नौकरियाँ आश्चर्यजनक रूप से तेज़ी से गायब होती हैं, जहाँ छंटनी आम बात है, जहाँ अधिकांश संगठनों का अस्तित्व ही अनिश्चित है, और जहाँ उदारवादी रूढ़ियों से ज़रा सा भी असहमति किसी को हमेशा के लिए बेरोज़गार बना सकती है। अरबपतियों द्वारा वित्तपोषित संस्थानों में काम करने वालों ने एक तरह की लॉटरी जीत

ली है... बहुत कम लोग जीतने वाली लॉटरी का टिकट खोने का जोखिम उठाना चाहते हैं, खासकर तब जब उन्हें पता हो कि उनकी सुरक्षा छिन जाने की स्थिति में उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है...
वरिष्ठ संपादकीय प्रबंधन को यह बात भलीभांति पता है कि उनका एकमात्र वास्तविक कार्य ओमिडयार को प्रसन्न रखने वाला माहौल बनाना है, जिसका अर्थ है केवल उन्हीं लोगों को नियुक्त करना या प्रकाशित करना जो उन्हें नाराज न करें, यह सुनिश्चित करना कि द इंटरसेप्ट का राजनीतिक और पत्रकारिता संबंधी रुख उनके वैचारिक दृष्टिकोण के अनुरूप हो और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी व्यक्ति या पत्रकारिता को द इंटरसेप्ट में रहने से रोकना यदि वह ओमिडयार की राजनीतिक परियोजना से बहुत दूर भटक जाती है।
यह कानूनी सीमाओं के भीतर रहते हुए लोगों को खरीदने और उनकी निष्ठाओं को स्थानांतरित करने का एक बहुत ही स्पष्ट तरीका है।
लोकतंत्र को बचाने का शोर मचाते हुए, ये अरबपति असल में स्थापित ढांचों को दरकिनार और कमजोर कर रहे हैं और उनकी जगह समाज के कामकाज के अपने नए मॉडल को लागू कर रहे हैं। यह सारा सामाजिक हेरफेर 'व्यापक हित' के लिए एक क्रांति है।

कर योग्य कंपनियां पारंपरिक कर-मुक्त गैर-लाभकारी संस्थाओं का स्थान ले रही हैं।
अरबपतियों की दुनिया पर राज करने की महत्वाकांक्षा बढ़ने के साथ, वे पारंपरिक गैर-लाभकारी ढांचे के बजाय 'परोपकार' के लिए लाभ कमाने वाली कंपनियों की स्थापना को एक नए ढांचे के रूप में चुन रहे हैं।
हालांकि गैर-लाभकारी ढांचे कर मुक्त होते हैं, लेकिन इसकी कमी यह है कि उनके कर संबंधी विवरण सार्वजनिक होते हैं। वे चर्चा को नियंत्रित

करने और खुद को भगवान समझने की अपनी बड़ी महत्वाकांक्षाओं को गोपनीय रखना चाहते हैं। इसलिए, अरबपति 'इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग' नामक एक ढांचे का उपयोग करते हैं जो लाभ कमाने वाला होता है और कर का भुगतान करता है, लेकिन वित्तीय विवरण गोपनीय होते हैं। उदाहरण के लिए, मेटा प्लेटफॉर्म्स के मार्क ज़करबर्ग अपने चैन ज़करबर्ग इनिशिएटिव के लिए कर छूट छोड़ रहे हैं, जैसा कि फोर्ब्स के एक हालिया लेख में बताया गया है।

“पारंपरिक फाउंडेशन के बजाय एलएलसी का उपयोग करके, हमें अपने शेयरों को चैन ज़करबर्ग इनिशिएटिव को हस्तांतरित करने से कोई कर लाभ नहीं मिलता है, लेकिन हमें अपने मिशन को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने में लचीलापन मिलता है,” ज़करबर्ग ने लिखा। … एलएलसी संरचना उन्हें और प्रिसिला चैन को निजी (लाभ कमाने वाली कंपनियों सहित) कंपनियों में निवेश करने के साथ-साथ नीतिगत बहसों में शामिल होने में सक्षम बनाती है—जिसे लॉबिंग के रूप में भी जाना जाता है।

लेख में पियरे ओमिडयार की ओर भी इशारा किया गया है, जो प्रभाव निवेश में अपने 'निवेश' के तरीके में गोपनीयता और लचीलेपन को प्राथमिकता देते हैं। यही कारण है कि उनके पास इतने सारे फर्जी संगठन हैं जिन्हें वे निजी धन से वित्त पोषित करते हैं। विवरणों को सार्वजनिक जांच से छिपाकर रखा जाता है। इसमें कहा गया है:

कुछ अन्य अरबपतियों ने भी इसी तरह की रणनीति अपनाई है। ईबे के संस्थापक पियरे ओमिडयार शायद लाभ कमाने वाली कंपनियों में निवेश और अपने ओमिडयार नेटवर्क के माध्यम से गैर-लाभकारी संस्थाओं को दान देने के मिश्रण के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं।

इन अरबपतियों के पास FCRA नियमों को दरकिनार करने और लाभ कमाने वाले व्यवसाय के रूप में भारत में प्रवेश करके अपनी 'ब्रेकिंग

इंडिया' गतिविधियों को अंजाम देने की वित्तीय क्षमता है। इसलिए भारत को व्यापार के बहाने भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी उद्यमों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। सही और गलत में फर्क करना एक चुनौती होगी, लेकिन यही समय की मांग है।

ओमिडयार नेटवर्क इंडिया

भारत में, ओमिडयार का निवेश राजनीतिक प्रक्रिया के हर पहलू को प्रभावित करता है। यहाँ धन, प्रभाव और बड़े डेटा का लेन-देन अमेरिका की तुलना में कहीं अधिक जटिल और अस्पष्ट है, और यह अधिकारियों के साथ अच्छे जनसंपर्क और समाज के निचले तबकों की मदद करने के बारे में चतुराई भरी बयानबाजी के पीछे छिपा रहता है। वास्तव में, ओएनआई द्वारा नियंत्रित विभिन्न उद्यमों और परियोजनाओं में महत्वपूर्ण 'इनसाइडर ट्रेडिंग' होती है।

ओमिडयार नेटवर्क इंडिया खुद को तीन रूपों में प्रस्तुत करता है: वेंचर कैपिटलिस्ट, सामाजिक लामबंदी समूह और तकनीक-प्रेमी युवा भारतीयों के लिए मेंटर।

यह भारत की आधी आबादी (अगली आधी आबादी) को अपना मुख्य लक्ष्य मानते हुए 'नेक्स्ट हाफ बिलियन' (एनएचबी) शब्द का इस्तेमाल करता है। जोशुआ प्रोजेक्ट के मिशनरियों की तरह, जो सुसमाचार को उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं जिन तक यह अभी तक नहीं पहुँचा है, ओएनआई उन लोगों को लक्षित करता है जिन तक प्रौद्योगिकी का पर्याप्त प्रभाव नहीं पड़ा है ताकि सामाजिक परिवर्तन लाया जा सके। इस प्रक्रिया में, ओएनआई ऐसे डेटाबेस बनाता है जिनके वित्तीय और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी निहितार्थ हैं। ओएनआई चार तरीकों से भारतीय समाज को बदलना चाहता है:

ऐसे तकनीकी समाधानों को लागू करने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करें जो समाज को बदल देंगे और इसे ओएनआई की विचारधारा के अनुरूप बनाएंगे।

नवीनतम तकनीक, पहलों और अवसरों का उपयोग करने वाले नवोन्मेषी उद्यमियों और नेताओं, विशेष रूप से युवाओं में निवेश करें। उन्हें ओमिडयार के वफादार युवा नेताओं की सेना में बदलें और उनके करियर को आगे बढ़ाने में सहायता करें।

ऐसी तकनीकी स्टार्टअप कंपनियों का नेटवर्क बनाएं जिनमें इक्विटी हो, ताकि यह सोशल इंजीनियरिंग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके।

भारत सरकार की नीतियों को प्रभावित करने के लिए विभिन्न संगठनों को वित्तपोषण प्रदान करना, जिनमें उसके अपने स्टार्ट-अप, उद्योग संगठन और स्थापित संस्थान शामिल हैं।

यह चार-सूत्रीय रणनीति भारत में ओएनआई की उपस्थिति को तेजी से बढ़ा रही है। यह बहुआयामी रणनीति के बारे में बहुत पारदर्शी है और इसकी वेबसाइटें और सोशल मीडिया प्रचार बहुत जानकारीपूर्ण हैं।

निम्नलिखित आरेख में चार प्रकार के निवेश दर्शाए गए हैं, जबकि केंद्र में स्थित वृत्त परिणामी उत्तोलन को दर्शाता है।

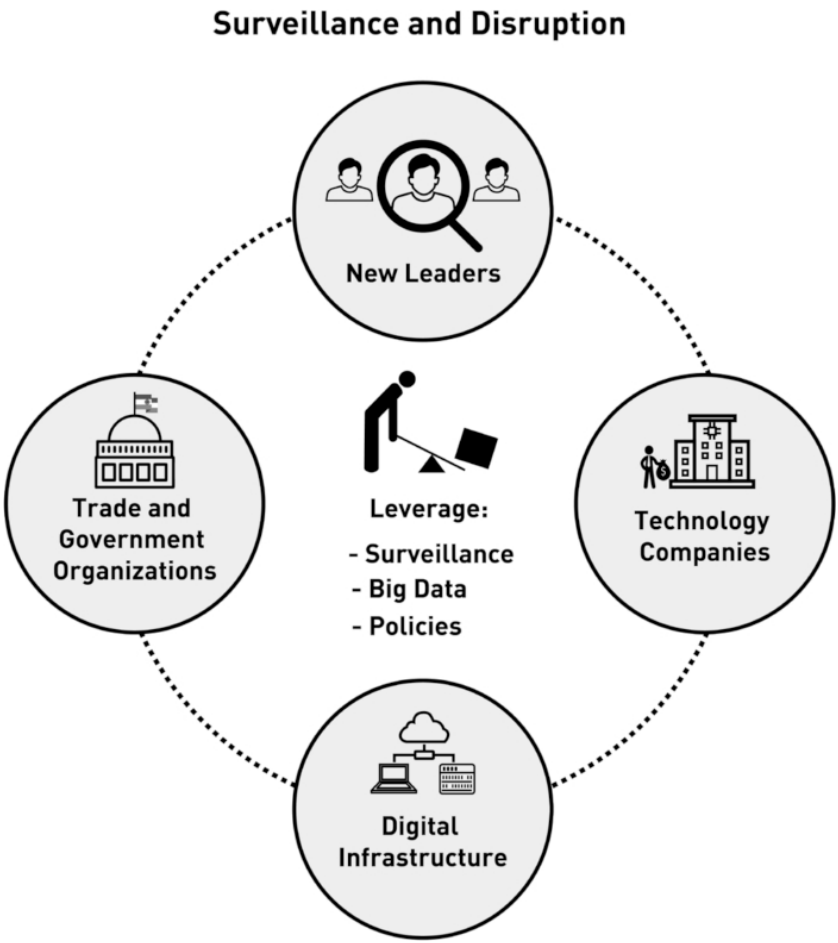

यह आसानी से समझा जा सकता है कि ओमिडयार की वैश्विक रणनीति भारत में भी कारगर साबित हो रही है। यह उन तकनीकी प्लेटफार्मों पर आधारित है जो दिखावटी तौर पर भारतीय जनता की सेवा करते हैं। दृष्टिकोण और विशिष्ट लक्ष्यों को राजनीतिक रूप से सही शब्दों में सावधानीपूर्वक व्यक्त किया गया है, जैसे कि 'समावेश', 'सामाजिक गतिशीलता', 'निम्न वर्ग की सहायता', 'जनता को अधिकार दिलाना', 'सरकार से नागरिकों का संबंध', 'पारदर्शिता बढ़ाना' आदि, जो इस तथ्य से ध्यान हटाते हैं कि उनका डेटा लीक हो रहा है।

गहन विश्लेषण करने पर पता चलता है कि यह ओएनआई को भारतीयों की सोच, उनकी सौंदर्यबोध और मूल्यों, उनके पसंद के उत्पादों, उनके प्रति वफादार रहने वाले नेताओं आदि को फिर से परिभाषित करने की स्थिति में लाता है।

जोशुआ परियोजना का पुनर्जन्म

जोशुआ प्रोजेक्ट से परिचित पाठकों को याद होगा कि जब हमारी पुस्तक, ब्रेकिंग इंडिया, ने चर्च के वैश्विक मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे इस भयावह प्रोजेक्ट का पर्दाफाश किया, जिसमें भारत के हर जिले का धार्मिक नेताओं, संबद्धताओं और सामाजिक-जनसांख्यिकीय विवरणों से युक्त एक व्यापक डेटाबेस विकसित करने का प्रयास किया गया था, तो भारत में कितना हंगामा मच गया था। इसका घोषित उद्देश्य मिशनरी कार्य के लिए व्यक्तिगत समुदायों को सूक्ष्म स्तर पर लक्षित करना था।

यह परियोजना धर्म प्रचार के लिए भारतीय समुदायों की व्यक्तिगत प्रोफाइल तैयार करती है और इस डेटा को पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के साथ साझा करती है। इससे अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को भारतीय समुदायों में अपने हस्तक्षेपों को दूर से प्रबंधित करने में सुविधा मिलती है, जिसमें सामाजिक न्याय की शिक्षा के बहाने सामाजिक अशांति पैदा करना भी शामिल हो सकता है। 'ब्रेकिंग इंडिया' नामक पुस्तक में इस परियोजना का सारांश इस प्रकार दिया गया है:

भारत में ऐसे संस्थान हैं जो धर्म प्रचार के उद्देश्य से भारत का अकादमिक अध्ययन करते हैं और भारतीय ईसाई धर्म प्रचारक संस्थानों के साथ औपचारिक संबंध रखते हैं। ये सभी कारक भारत में एक मजबूत जनसंख्या आधार का निर्माण करते हैं जो आर्थिक, संस्थागत और भावनात्मक रूप से पश्चिम के दक्षिणपंथी समूहों पर निर्भर होगा। राज्य

और गैर-राज्य दोनों ही संगठन सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर प्रभावी नियंत्रण के लिए भारत में संस्थागत अवसंरचनात्मक व्यवस्था के निर्माण में निवेश करते हैं। ईसाई धर्म प्रचारक संगठनों के माध्यम से भारत में पश्चिमी वर्चस्व का आधार प्रभावी ढंग से तैयार किया जा रहा है। इसका लक्ष्य कट्टरपंथी ईसाई धर्म का प्रसार करना और पश्चिम के साथ मजबूत भावनात्मक जुड़ाव और निर्भरता रखने वाले विश्वासियों की आबादी का निर्माण करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ईसाई दक्षिणपंथी समूह इस संबंध में विशेष रूप से सक्रिय और महत्वाकांक्षी हैं।
हमने खुलासा किया कि कई डेटा संग्रह समूहों में से केवल एक, गॉस्पेल फॉर एशिया ने, जोशुआ प्रोजेक्ट की ईसाई धर्म के संदर्भ में सबसे अधिक 'अपरिचित लोगों' की सूची में शामिल सौ समुदायों में टीमें तैनात की थीं। प्रत्येक टीम में कम से कम तीस प्रचारक थे। हमारी रिपोर्ट में कहा गया है: 'यह ईसाई बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उस प्रकार का बाजार अनुसंधान प्रदान करता है जिसकी अपेक्षा कोका-कोला या आईबीएम जैसी व्यावसायिक कंपनियों से की जाती है।'
एक जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि
यह योजना सैन्य मॉडल पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य आक्रमण करना, कब्जा करना, नियंत्रण करना या आबादी को अपने अधीन करना था। यह जमीनी स्तर से प्राप्त ठोस खुफिया जानकारी और चुनिंदा जनसमूहों के विभिन्न पहलुओं पर गहन शोध पर आधारित थी। इसका उद्देश्य जासूसी मिशन भेजकर धर्म और संस्कृति के बारे में सूक्ष्म जानकारी जुटाना था। विभिन्न भारतीय समुदायों में मौजूद सामाजिक और आर्थिक विभाजनों का गहन अध्ययन किया गया।
इस प्रकार का बहुराष्ट्रीय नेटवर्क अमेरिकी मुख्यालय को भारत स्थित इकाइयों के समन्वय से भारत में स्थानीय कार्रवाइयों को कुशलतापूर्वक

निर्देशित करने की शक्ति प्रदान करता है:
अमेरिका स्थित एक एजेंसी को लिखा गया पत्र तुरंत बेंगलुरु भेज दिया जाता है और बेंगलुरु स्थित एजेंसी निकटतम प्रचारक का पता लगाती है और उसे नए जिज्ञासु व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने का कार्य सौंपती है। मिशन का लक्ष्य है: 'हमें साइकिल से पहुँचने योग्य दूरी के भीतर, फिर पैदल चलकर पहुँचने योग्य दूरी के भीतर और अंत में सुनने योग्य दूरी के भीतर एक चर्च की आवश्यकता है।'
जोशुआ प्रोजेक्ट के पास स्थानीय संघर्षों को भड़काने या नियंत्रित करने की शक्ति है, जिन्हें सनसनीखेज खबरों और आगे के राजनीतिक हस्तक्षेपों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया जा सकता है। इसका उद्देश्य सबसे अधिक जरूरतमंद और संवेदनशील जनसमूहों, उनकी संवेदनशील समस्याओं और उनसे संपर्क करने के लिए उपयुक्त नेताओं और संपर्कों की पहचान करना और उन्हें उजागर करना है।
उद्धृत रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जोशुआ प्रोजेक्ट भारतीय सरकार के डेटाबेस, जैसे कि आधिकारिक जनगणना और भारतीय मानवविज्ञान सोसायटी द्वारा संचालित 'पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट', का दुरुपयोग कर रहा था। विश्व सुसमाचार प्रचार पर वैश्विक परामर्श के निदेशक लुइस बुश ने गर्व से दावा किया:
भारत के बारे में इस प्रकार की जानकारी का पहले कभी भी इतनी सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण, संकलन, प्रकाशन और वितरण नहीं किया गया है। ... हमें विश्वास नहीं है कि यह संयोग है। ईश्वर हमें इस भूमि का अन्वेषण करने की अनुमति दे रहा है ताकि हम इसमें प्रवेश कर सकें और इस पर और इसके निवासियों पर अपना अधिकार जता सकें।
नीचे जोशुआ प्रोजेक्ट और भारत में ओमिडयार के प्रोजेक्ट के बीच के अंतर दिए गए हैं:

ओमिडयार वैश्विक वामपंथियों की ओर से हस्तक्षेप करने के लिए डेटाबेस और बुनियादी ढांचा विकसित कर रहा है, न कि चर्च की ओर से।
जहां जोशुआ प्रोजेक्ट को मैन्युअल रूप से अंजाम दिया गया था, वहीं ओएनआई स्वचालित रूप से कहीं अधिक सटीक डेटा एकत्र करता है और उसे संसाधित करके वास्तविक समय में वितरित करता है।
जोशुआ प्रोजेक्ट को निरंतर आधार पर भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होती थी, जबकि ओएनआई भारत में अत्याधुनिक स्टार्टअप्स की इक्विटी में निवेश करके लाभ कमाता है; उत्पन्न डेटा एक उप-उत्पाद है।
जोशुआ प्रोजेक्ट अपने एजेंडे को लेकर पारदर्शी था, जबकि ओएनआई भारतीयों, विशेष रूप से दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों तक प्रौद्योगिकी और सामाजिक न्याय पहुंचाने के दिखावे के पीछे छिपा रहता है।
जोशुआ प्रोजेक्ट केवल इंजीलवादी जगत तक ही सीमित था, जबकि ओएनआई को निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और शिक्षा जगत में एक सम्मानित भागीदार के रूप में व्यापक स्वीकृति प्राप्त है।

ओमिडयार अनुदान हार्वर्ड के मित्तल संस्थान के माध्यम से प्राप्त हुए। 2012 की शुरुआत में, मित्तल संस्थान ने भारत में कुछ परियोजनाओं पर काम करने के लिए विद्वानों को अनुदान प्रदान करके ओमिडयार के लिए भारत में प्रवेश का द्वार खोला। ओमिडयार ने भारत में 'मोबिलाइज़! डिजिटल लाइब्रेरीज़' परियोजना को वित्त पोषित किया, जो स्व-निर्देशित शिक्षा के लिए विकसित की गई प्रौद्योगिकी (स्मार्ट स्क्रीन) का उपयोग करती है। इसका लक्ष्य 'सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन को गति देना' था।
हम शिक्षा, प्रौद्योगिकी और गतिशीलता के संगम पर काम करते हैं, छात्रों

को सोचने के नए तरीकों के लिए प्रेरित करने और स्वयं के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार के लिए अधिक रुचि पैदा करने के लिए सर्वोत्तम सामग्री और प्रथाओं का उपयोग करते हैं।
एक अन्य परियोजना चेन्नई में महिलाओं को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने पर केंद्रित थी।
इस पहल का लक्ष्य मध्यम आय वर्ग की कामकाजी महिलाएं हैं, और इसके तहत इंटरनेट की सुविधा, प्रिंटिंग प्रेस, कॉफी, नियमित शैक्षिक सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दक्षिण एशिया में उद्यमिता के लिए ओमिडयार अनुदान से प्राप्त धनराशि का उपयोग करते हुए, आईस्पेस चेन्नई में एक पायलट साइबर कैफे स्थापित करेगा और इसे कई साइबर कैफे श्रृंखलाओं में विस्तारित करने की उम्मीद करता है।
एक दशक पहले मित्तल इंस्टीट्यूट के माध्यम से छोटे-छोटे कदम उठाने के बाद, ओमिडयार ने पूरी तरह से अपने स्वयं के संगठनों के माध्यम से बड़ी सफलता हासिल की।

ओमिडयार नेटवर्क इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और बिग डेटा
कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस युग में, व्यक्तियों और समुदायों की गतिविधियों, घटनाओं और व्यवहारों से संबंधित जानकारी विश्लेषण और भविष्यवाणी के लिए एक शक्तिशाली डेटाबेस बन जाती है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक, "कृत्रिम बुद्धिमत्ता और शक्ति का भविष्य", राजनीतिक रणनीति, सामाजिक व्यवहार को समझने और उसमें हेरफेर करने, और सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए बड़े डेटा के उपयोग के उदाहरण प्रस्तुत करती है। ओमिडयार नेटवर्क इंडिया के निवेश को व्यापक स्तर पर, विशेष रूप से संवेदनशील समुदायों में, खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र के रूप में

बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। यह डेटा गहन विश्लेषण और सभी प्रकार के सामाजिक हस्तक्षेपों, चाहे वे रचनात्मक हों या विघटनकारी, के लिए उपयुक्त है। किसी समाज की कार्यप्रणाली का मॉडल बनाना एक जटिल कार्य है जिसके लिए डेटा संग्रह और विश्लेषण के विस्तृत तंत्र की आवश्यकता होती है। ओमिडयार की तकनीकी पृष्ठभूमि उन्हें इस प्रकार के बुनियादी ढांचे के विकास और संचालन में महारत हासिल करने के लिए उपयुक्त बनाती है।

जब इसे बिग डेटा के संदर्भ में देखा जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ओएनआई ऐसा क्यों करता है। बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले एप्लिकेशन और सेवाएं व्यवहार संबंधी डेटा से भरपूर हैं। भारत के संवेदनशील समूहों के साथ जुड़ते समय, सामाजिक न्याय के नाम पर सामाजिक बदलाव लाने के लिए ऐसे डेटा विश्लेषण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। अपने सभी प्रयासों में, ओएनआई डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करने की कोशिश करता है।

इस रणनीति के केंद्र में ई-गवर्नमेंट्स फाउंडेशन (ई-गव) है, जिसमें ओमिडयार ने शुरुआत में 2014 में दस लाख डॉलर का निवेश किया था। प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दिग्गज नंदन नीलेकानी और श्रीकांत नाधामुनी द्वारा स्थापित ई-गव का उद्देश्य अर्थव्यवस्था, समाज और सरकार को जोड़ने वाले एक ओपन-सोर्स प्रौद्योगिकी आधार के माध्यम से डेटा-संचालित शासन स्थापित करना है। इस सॉफ्टवेयर स्टैक को डिजिट नाम दिया गया है, जो इसका ओपन डिजिटल इकोसिस्टम (ओडीई) है। इसे व्यवसायों और नागरिकों को अनुमोदन, कराधान, सेवा वितरण और शिकायत निवारण के लिए सरकार के साथ संवाद करने में सहायता करने की रणनीति पर बनाया गया था। इसलिए, इस प्रक्रिया को निर्बाध रूप से करने की क्षमता एक ओर सरकार की परिचालन दक्षता, संसाधनों के

प्रभावी उपयोग, सेवाओं के वितरण में सुविधा और राजस्व संग्रह में सुधार लाएगी। दूसरी ओर, यह व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए प्रक्रियाओं को गति प्रदान करेगी।

यह अल्पकालिक रूप से भारतीयों के लिए अच्छा है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से ओएनआई ही उस तकनीक पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है जिस पर यह पारिस्थितिकी तंत्र संचालित होता है, जिससे उसे उत्पन्न होने वाले सभी मूल्यवान डेटा को हासिल करने की शक्ति मिलती है। इससे ओमिडयार नागरिक-सरकारी अंत:क्रियाओं की निगरानी और मार्गदर्शन करने वाले द्वारपाल बन जाते हैं।

भारत में चीजों के काम करने के तरीकों को समझने और मॉडल विकसित करने के लिए इस इकोसिस्टम के प्रसार को बढ़ावा देना फायदेमंद है, ताकि बाद में इसे फिर से डिज़ाइन किया जा सके। इसे 'ओपन सोर्स' बनाने से सिस्टम का व्यापक प्रसार होता है। जितना अधिक इसे अपनाया जाएगा, सरकार, उद्यम और व्यक्ति उतने ही इस पर निर्भर होते जाएंगे, जिससे इस पर स्विच करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए, ई-गवर्नेंस ने वाणिज्यिक उद्यमों और उद्यमियों के साथ साझेदारी की है ताकि प्लेटफॉर्म पर आधारित और उससे एकीकृत स्थानीय समाधान तैयार किए जा सकें। यह नागरिक समाज संगठनों के साथ भी साझेदारी करता है ताकि उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके, जिससे इसे सामाजिक घटनाओं को समझने और उनका विश्लेषण करने में मदद मिलती है। ओमिडयार पहले से ही भारतीय सरकार, अधिकांश राज्यों और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय तथा राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान जैसे महत्वपूर्ण सरकारी निकायों के साथ साझेदारी कर रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय मानकों के निर्धारण और ऐसी नीतियों एवं कार्यक्रमों के विकास को प्रभावित करना है जो सरकार द्वारा इसके डिजिटल सिस्टम को

अपनाने की प्रक्रिया को गति प्रदान कर सकें। इसका एक उदाहरण महामारी के दौरान इसकी तकनीक को अपनाना है।

सरकार ने घोषणा की है कि सरकार के टीकाकरण पोर्टल COWIN पर ई-गवर्नेंस के DIVOC सॉफ्टवेयर का उपयोग करके 1 अरब से अधिक कोविड वैक्सीन प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। DIVOC एक मॉड्यूलर डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो देशों को अंतिम छोर तक टीकाकरण कार्यक्रमों के बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन को प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है। इसने क्यूआर कोड तकनीक का उपयोग करके डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित और ऑफ़लाइन सत्यापन योग्य प्रमाणपत्रों की सुविधा प्रदान करके लाखों लोगों के लिए वैक्सीन प्रमाणपत्र को साथ रखना और सुरक्षित रखना सुविधाजनक बना दिया है।

ओएनआई की वेबसाइट पर यह घोषणा की गई है:

'व्यापक प्रभाव' यह अतिप्रचलित वाक्यांश पिछले पांच वर्षों में संगठन द्वारा हासिल की गई उपलब्धि का सटीक वर्णन करता है: ई-गवर्नेंस अब 14 राज्यों के 2,421 शहरों (653 चालू, 1858 कार्यान्वयन के अधीन) में प्लेटफॉर्म को तैनात कर रहा है, जिससे 160 मिलियन से अधिक भारतीय नागरिक प्रभावित हुए हैं... डिजिट ने 2.5 बिलियन डॉलर से अधिक का राजस्व संग्रह सक्षम किया है।

यह गर्वपूर्वक घोषणा करता है: 'यह उन निवेशों में से एक रहा है जो हमारी परिकल्पना के लगभग हर आयाम पर खरा उतरता है और वह भी अभूतपूर्व पैमाने पर।' दूसरे शब्दों में, यह प्रणाली भारी मात्रा में डेटा और प्रभाव उत्पन्न कर रही है जिसका उपयोग ओएनआई अपने सामाजिक मॉडल बनाने के लिए कर रहा है, जो उसके हस्तक्षेपों की नींव हैं। भारत के शासन में सभी स्तरों पर निभाई जा रही केंद्रीय भूमिका को देखते हुए, ओएनआई ने अपने आर्थिक, सामाजिक और सरकारी विषयों के अनुरूप

भविष्य के लिए निम्नलिखित विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं।
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की साझेदारियों को आगे बढ़ाते हुए 'कई शहरों में प्लेटफॉर्म का सह-स्वामित्व, सुधार, अनुकूलन, तैनाती और सेवा प्रदान करना' जारी रखना।
सबसे वंचित नागरिकों तक पहुंचने के लिए अंतिम चरण में "ऑफ़लाइन संरचनाएं" या मध्यस्थ (जैसे, समुदाय-आधारित संगठन, स्थानीय राजनेता आदि) बनाना और उन्हें शामिल करना। यह बात तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम इस दावे पर विचार करते हैं कि यह प्रणाली "बढ़ी हुई पारदर्शिता के माध्यम से सरकारों को जवाबदेह बना रही है"।
राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के माध्यम से सरकार के राष्ट्रीय शहरी शासन मंच का विस्तार करना, सेवाओं के वितरण के लिए क्लाउड का लाभ उठाना और इस प्रक्रिया में राज्यों और शहरों में डिजिटल डिजिटलीकरण (DIGIT) को अपनाने को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य 'विभिन्न नगरपालिका सेवाओं को एक साझा मंच पर एकीकृत करना है ताकि सभी राज्य/शहर अपनी आवश्यकताओं को तेजी से और व्यापक रूप से पूरा करने के लिए अनुकूलित समाधानों का उपयोग कर सकें'। नौ संदर्भ सेवा अनुप्रयोग हैं: संपत्ति कर निर्धारण/भुगतान, भवन योजना अनुमोदन, नगरपालिका शिकायत निवारण, व्यापार लाइसेंस जारी करना और भुगतान, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना, जल और सीवरेज कनेक्शन प्रबंधन, नगरपालिका लेखांकन और वित्त, जन्म और मृत्यु पंजीकरण और जल, बिजली आदि जैसी सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए उपयोगकर्ता शुल्क।
ओमिडयार नेटवर्क इंडिया का डेटा नीति और डेटा गवर्नेंस को प्रभावित करने वाली परियोजनाओं और संगठनों के प्रति जुनून अब समझ में आता

है। इसका मुख्य उद्देश्य अपना खुद का ओपन डिजिटल इकोसिस्टम बनाना है। यह डिजिटल इकोसिस्टम एक समानांतर गवर्नेंस और ट्रैफिक के जाल की तरह काम करता है, जिसमें ओएनआई के नामित नेता ट्रैफिक पुलिस और गेटकीपर की भूमिका निभाते हैं।

ईबे के संस्थापक के रूप में, ओमिडयार डिजिटल बाज़ार बनाने में माहिर हैं जो खरीदारों और विक्रेताओं को एक मंच पर लाते हैं और इस गतिविधि से डेटाबेस बनाने की तकनीकों से भली-भांति परिचित हैं। वे अपनी इस विशेषज्ञता का उपयोग निम्नलिखित उद्यमों में कर रहे हैं, इस बार भारत के सुदूरतम समुदायों में डिजिटल गेटकीपर के रूप में।

बिजाक भारत के अट्ठाईस से अधिक राज्यों और एक हजार से अधिक क्षेत्रों में किसानों के लिए एक डिजिटल आपूर्ति श्रृंखला है, जो खरीदारों और विक्रेताओं को उनके 'विश्वसनीय डिजिटल बाज़ार' के रूप में जोड़ती है। स्पष्ट रूप से, यह ग्रामीण खेतों से प्राप्त समृद्ध वास्तविक समय डेटा का स्रोत है।

इंटरसिटी सौ से अधिक शहरों में ट्रेन या बस द्वारा यात्रा आरक्षण करती है, जिससे ओएनआई को लोगों की आवाजाही और वास्तविक समय में रुझानों का डेटाबेस मिलता है।

CredR प्रयुक्त मोटरसाइकिलों के बाजार को व्यवस्थित करता है, और इस प्रक्रिया में जीपीएस के माध्यम से उनकी गतिविधियों पर नज़र रखता है और उपयोगकर्ताओं के व्यवहार संबंधी डेटा एकत्र करता है।

इंडिफी छोटे व्यवसायों को डिजिटल ऋण प्रदान करता है, जिससे उन्हें वित्तीय डेटा और व्यवहार मॉडलिंग तक पहुंच मिलती है, और छोटे पैमाने के उद्यमियों के बीच उनका प्रभाव बढ़ता है।

सितारा संस्था वर्तमान में साठ हजार से अधिक गरीब महिलाओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान करती है। इससे ओएनआई को परिवारों और उनकी वित्तीय

स्थिति के साथ-साथ व्यवहार संबंधी आंकड़े प्राप्त होते हैं।
डाउटनट के-12 विद्यार्थियों के लिए एक लोकप्रिय बहुभाषी शिक्षा मंच है। यह प्रतिदिन 20 लाख से अधिक प्रश्नों के उत्तर देता है, जिससे उत्तरों के प्रकार पर इसका प्रभाव पड़ता है। यह बच्चों वाले परिवारों का डेटा भी एकत्र करता है, उनके करियर और वयस्कता में संक्रमण पर नज़र रखता है, और उनकी आकांक्षाओं को समझने और व्यवहार को प्रभावित करने के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान कर सकता है।
वेदांतु एक और लाइव ऑनलाइन के-12 शिक्षा मंच प्रदान करता है। इसने चालीस मिलियन से अधिक युवाओं और शिक्षकों का डेटाबेस बनाया है, जिसकी मदद से व्यक्तिगत स्तर पर करियर को प्रभावित करने, भर्ती करने और व्यवहार संबंधी कारकों का पता लगाने की क्षमता है।
ट्रांसर्व ऐसे भू-जनसांख्यिकीय डेटाबेस का निर्माण कर रहा है जो समुदायों, ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों और शहरी क्षेत्रों के लिए उपयोगी हैं और जिनका क्षेत्रफल 23 मिलियन से अधिक लोगों तक फैला हुआ है।
ओमिडयार नेटवर्क इंडिया की परियोजना कावेरी इन्वेस्टमेंट ने प्रतिष्ठित भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु में प्रवेश कर लिया है, जहां इसे उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। इसका मिशन 'डेटा के विशाल अप्रयुक्त सामाजिक और आर्थिक मूल्य को उजागर करना' है। मूल्यवान डेटा और प्रतिभाशाली मानव संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने के साथ-साथ, यह इस प्रतिष्ठित संस्थान के साथ जुड़कर अपनी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ा रहा है।
ओमिडयार नेटवर्क इंडिया की यह भी योजना है कि जनगणना के आंकड़ों को अधिक आसानी से सुलभ बनाने के बहाने विश्व बैंक के साथ मिलकर उन तक पहुंच प्राप्त की जाए।

आर्थिक प्रभाव और नेतृत्व निर्माण

पिछले कई वर्षों में, ओएनआई ने कुल 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर के 128 सक्रिय निवेश किए हैं। कंपनी का दावा है कि उसने 55 करोड़ भारतीयों के जीवन को प्रभावित किया है। इसके पोर्टफोलियो में कम से कम 4 यूनिकॉर्न सहित कुल 106 कंपनियां शामिल हैं। यह सब तेजी से विस्तार कर रहा है।

ओमिडयार नेटवर्क इंडिया (ONI) की रणनीति युवा भारतीय उद्यमियों को रोमांचक तकनीकी परियोजनाओं में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना और इन परियोजनाओं का उपयोग ग्रामीण भारत में बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए करना है। हम ONI के कुछ निवेशों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम इन अनुदानों को प्राप्त करने वाले संगठनों का विरोध नहीं कर रहे हैं। कई मामलों में, उनका कार्य (उदाहरण के लिए fes.org) अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा तर्क यह है कि ONI ने इन संगठनों का चयन केवल वित्तीय दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक व्यापक योजना के तहत किया है। हम इसी अंतर्निहित उद्देश्य को उजागर करना चाहते हैं।

मूल सिद्धांत सुव्यवस्थित रूप से प्रतिपादित हैं और सतही तौर पर देखने पर विवादरहित हैं:

डिजिटल समाज: समावेशिता, गोपनीयता, सुरक्षा, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। 'अगली आधी अरब' आबादी के सबसे संवेदनशील वर्ग के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य।

शिक्षा: पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यक्रम को प्रभावित करना और शिक्षकों को छात्रों के प्रति सहानुभूति रखते हुए 'पढ़ाई जाने वाली सामग्री की

पुनर्कल्पना' करने के लिए प्रशिक्षित करना, अर्थात् मूल्यों और विचारधारा को प्रभावित करना।

वित्तीय समावेशन: वित्तीय समावेशन में मौजूद संरचनात्मक बाधाओं पर शोध करना और उन्हें दूर करना। इससे भारत के लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) में, विशेषकर संवेदनशील ग्रामीण क्षेत्रों में, वित्तीय समावेशन को गहराई से शामिल किया जा सकेगा।

सुशासन: नागरिकों और सरकार के बीच संबंधों में भूमिका निभाएं। ओएनआई का कहना है: 'हम नागरिकों को जागरूक बनाते हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनकी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करते हैं और उनके राजनीतिक नेताओं को जवाबदेह ठहराते हैं।' नागरिकों द्वारा राजनीति और शासन में बदलाव लाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करना, स्वतंत्र मीडिया (यानी ओएनआई के अनुरूप) को बढ़ावा देना और राजनेताओं और सरकार के लिए सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को परिभाषित और लागू करना हमारा लक्ष्य है।

दरअसल, ओएनआई की वेबसाइट और प्रचार सामग्री आकर्षक तकनीकी शब्दावली से भरी हुई है। ओपन डिजिटल इकोसिस्टम पहल को एक ऐसे इंजन के रूप में वर्णित किया गया है जिसमें डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना शामिल है जो 'लाभदायक प्रौद्योगिकी' का समर्थन करती है। यह 'एक मजबूत शासन ढांचे के आधार पर समाज के लिए परिवर्तनकारी समाधान खोजने के लिए हितधारकों के एक समुदाय को सक्षम बनाती है'। ओमिडयार नेटवर्क इंडिया का कहना है कि भारत की डिजिटल प्रणालियाँ अलग-थलग हैं, और वह अंतर्संचालनीयता का इंजन बनना चाहता है।

इसका सीधा सा मतलब है कि यह विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच आवागमन के केंद्र में एक रक्षक और निगरानी तंत्र के रूप में कार्य करना

चाहता है। इस तरह के महत्वाकांक्षी पारिस्थितिकी तंत्र का विकास काफी जटिल है और इसमें सरकारों, व्यवसायों और नागरिकों की नीतियों, प्रथाओं और व्यवहार में बदलाव शामिल हैं। नैतिकता, गोपनीयता, डेटा तक पहुंच, संवेदनशीलता और राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों से संबंधित चिंताएं व्यापक रूप से मौजूद हैं।

गहराई से देखने पर, एक प्रकार की समानांतर सरकार का एजेंडा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, या कम से कम लोगों, प्रौद्योगिकियों और डेटाबेस का एक नेटवर्क जो ओएनआई से जुड़ा हुआ है और उसके नियंत्रण में है। वास्तव में, ओएनआई बार-बार कहता है कि उसके निवेश दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करते हैं (जिसे वह अपना 'दोहरा चेकबुक' दृष्टिकोण कहता है): एक ओर अच्छे वित्तीय निवेश और दूसरी ओर अच्छे सामाजिक इंजीनियरिंग हस्तक्षेप।

उदाहरण के लिए, आइए इसकी समूह कंपनी iMerit के कामकाज को देखें। iMerit का कहना है कि वह 'मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी प्रमुख तकनीकों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है', जिनका उपयोग स्वायत्त वाहन, मेडिकल एआई, कृषि प्रौद्योगिकी, भू-स्थानिक और अन्य रोबोटिक्स-आधारित प्रौद्योगिकी उद्योगों, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण के साथ-साथ 'सामाजिक अनुप्रयोगों' में भी किया जाता है। आईमेरिट का काम क्षेत्र का सर्वेक्षण करने से शुरू होता है: 'हालांकि, भारतीय कार्यबल का दो-तिहाई हिस्सा अभी भी कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों में कार्यरत है, और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवा क्षेत्र में काम करने वाली आबादी के एक-तिहाई हिस्से के केवल एक अंश को ही रोजगार प्रदान करती है।'

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के संचालन में संलग्न होने के कारण, इसे मशीन लर्निंग के लिए आवश्यक डेटा लेबलिंग जैसे कार्यों के लिए बड़ी

मात्रा में सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है (यह परिवार की आय से तीन से दस गुना अधिक भुगतान करता है, जो जीवन निर्वाह स्तर है)। इसके लिए यह भारत के उन 'वंचित क्षेत्रों' में सीधे जाता है, जहां पारंपरिक डिग्री न रखने वाले लोगों को 'विकास के अधिक अवसरों' की आवश्यकता है। इसने इन क्षेत्रों से 5,500 लोगों को भर्ती किया है, जिनमें से 50% महिलाएं हैं।

आईमेरिट, अनुदीप फाउंडेशन के साथ मिलकर काम करता है, जो एक कौशल विकास गैर-लाभकारी संस्था है जिसकी स्थापना आईमेरिट ने की थी। यह संस्था भारत में स्थित अपने छह केंद्रों और न्यू ऑरलियन्स में स्थित एक केंद्र के माध्यम से इन क्षेत्रों के लोगों को प्रशिक्षित करती है। भारतीय केंद्रों से प्राप्त प्रशिक्षण न्यू ऑरलियन्स केंद्र को भी मिलता है। कौशल विकास कार्यक्रम के विभिन्न चरणों में नौकरी के दौरान प्रशिक्षण, अंग्रेजी सुधार कार्यक्रम, प्रासंगिक समझ, क्षेत्र विशेषज्ञता और नेतृत्व विकास शामिल हैं, ताकि उन्हें धीरे-धीरे उच्च स्तर पर पहुंचाया जा सके। आईमेरिट की संस्थापक राधा बसु ने पहले ऑनवर्ड टॉक शो में सामाजिक प्रभाव के बारे में बात की। उनका कहना है कि अगर आप इन लोगों से बात करेंगे, तो वे कहेंगे, 'हमारे परिवार हमारी राय को बहुत गंभीरता से लेते हैं, खासकर पारिवारिक और गांव से जुड़े फैसलों में।'

इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह संगठन कम सौदेबाजी शक्ति वाले लोगों का चयन करने और उस धन का उपयोग जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को विकसित करने के लिए करने में कितना कुशल है, जिनका उपयोग बाद में समुदाय और ग्राम स्तर पर वांछित विचारधाराओं को स्थापित करने के लिए किया जाता है।

स्पष्ट है कि iMerit जनता के लिए बेहतरीन काम कर रहा है। हमारी चिंता विदेशी नियंत्रण को लेकर है क्योंकि इस तरह के हस्तक्षेप भारत

की जनता की सामाजिक एकता के लिए संभावित खतरा पैदा कर सकते हैं। इनमें से कई अनुदान और निवेश भारतीय राज्य के कामकाज का अध्ययन करने और उसे प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हैं। इनमें से कुछ का उद्देश्य अपने नीति निर्माताओं को नियुक्त करना या मौजूदा नीति निर्माताओं को प्रभावित करना है। ओमिडयार नेटवर्क इंडिया की लिंक्डइन उपस्थिति से यह स्पष्ट है कि यह जिन युवाओं को वित्त पोषित करता है, उन्हें साहसी, नवोन्मेषी और महत्वाकांक्षी राजनीतिक नेताओं के रूप में स्थापित करने के लिए बेहद उत्सुक है। नेताओं की एक नई पीढ़ी को तैयार करना और नेतृत्व तंत्र को प्रभावित करना महत्वपूर्ण कदम हैं।

ओमिडयार ने आईडीएफसी इंस्टीट्यूट और आईडीएफसी फाउंडेशन का समर्थन किया।
हम दो गैर-लाभकारी संगठनों का अध्ययन करते हैं: आईडीएफसी फाउंडेशन और आईडीएफसी इंस्टीट्यूट। ये भारत की अवसंरचना विकास वित्त कंपनी लिमिटेड (आईडीएफसी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं, जो एक वित्त कंपनी और आईडीएफसी बैंक की मूल कंपनी है, जिसकी स्थापना सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के तहत की गई है। आईडीएफसी फाउंडेशन की स्थापना 2011 में क्षमता निर्माण, नीति परामर्श और स्थिरता पहलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए की गई थी। यह आईडीएफसी समूह द्वारा संचालित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों की देखरेख करता है। यह आईडीएफसी संस्थान को भी वित्त पोषित करता है और फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और ओमिडयार नेटवर्क जैसे विदेशी गैर-सरकारी संगठनों से धन प्राप्त करता है, जो भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए जाने जाते हैं। आईडीएफसी संस्थान की वेबसाइट पर लिखा है:

आईडीएफसी संस्थान की स्थापना एक स्वतंत्र, आर्थिक विकास-केंद्रित विचार-विमर्श और कार्य-संचालन मंच के रूप में की गई है, जिसका उद्देश्य भारत के निम्न-आय वाले, राज्य-प्रधान देश से समृद्ध बाजार-आधारित अर्थव्यवस्था में चल रहे परिवर्तन के राजनीतिक, आर्थिक और स्थानिक आयामों का अध्ययन करना है। हम क्रियान्वयन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था की प्रासंगिक समझ पर आधारित गहन, व्यावहारिक शोध और सिफारिशें प्रदान करते हैं।

आगे दिया गया आरेख आईडीएफसी से जुड़े जटिल संबंधों के जाल को दर्शाता है।

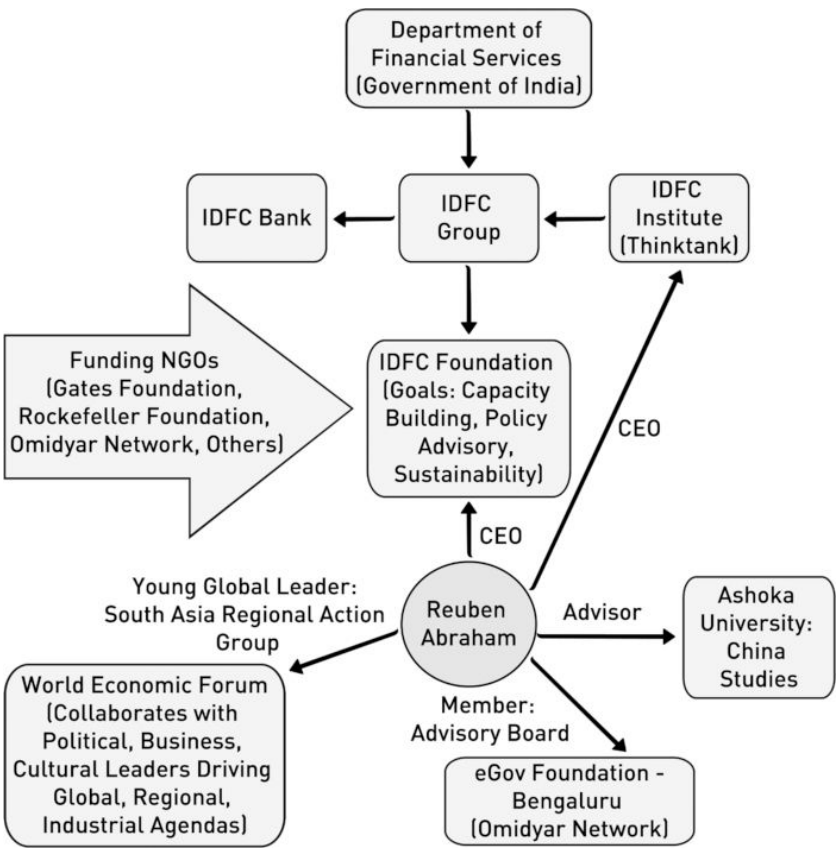

बुनियादी ढांचे के निर्माण में आईडीएफसी की भूमिका और ग्रामीण विकास पर इसके विशेष ध्यान को देखते हुए, पियरे ओमिडयार की इस संगठन में पैठ बनाने में रुचि होना स्वाभाविक था। और आईडीएफसी इंस्टीट्यूट, जिसके संस्थापक-सीईओ रूबेन अब्राहम हैं, ने उन्हें यह अवसर प्रदान किया। अब्राहम बेंगलुरु स्थित ई-गवर्नमेंट फाउंडेशन के सलाहकार मंडल के सदस्य हैं, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि ओमिडयार की प्रभाव निवेश शैली और डेटा जुटाने के लिए डिजिटल तकनीक का उनका उपयोग संस्थान की गतिविधियों में परिलक्षित होता है।
यह सब आसान हो गया क्योंकि रूबेन अब्राहम आईडीएफसी फाउंडेशन और थिंकटैंक आईडीएफसी इंस्टीट्यूट दोनों के सीईओ हैं। वर्तमान में, वह अशोका के सेंटर फॉर चाइना स्टडीज में सलाहकार, डब्ल्यूईएफ के यंग ग्लोबल लीडर भी हैं और अभी भी वहां विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं।
उन्हें [रूबेन अब्राहम] को विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) द्वारा 2009 के लिए एक युवा वैश्विक नेता के रूप में चुना गया था, जहां वे वर्तमान में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्य समूह के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले, वे डब्ल्यूईएफ की उभरते बाजार बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर वैश्विक एजेंडा परिषद के उपाध्यक्ष, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय बोर्ड के उपाध्यक्ष और शहरों और शहरीकरण पर वैश्विक भविष्य परिषद के सदस्य रह चुके हैं। एक दशक तक उन्होंने न्यूयॉर्क स्थित सोरोस इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड (एसईडीएफ) में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य किया, जो वैश्विक स्तर पर प्रभाव निवेश का अग्रणी संस्थान है। 2008 में, एसईडीएफ के तत्वावधान में, उन्होंने सोरोस, ओमिडयार नेटवर्क और गूगल के साथ सह-निवेशकों के रूप में SONG की स्थापना में मदद की, जो शुरुआती प्रभाव निवेश कोषों में से एक है।
विश्व आर्थिक मंच (ईआईडीएफसी) स्वयं को एक 'सार्वजनिक-निजी

सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन' के रूप में वर्णित करता है, जो 'वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग संबंधी एजेंडा तय करने के लिए समाज के अग्रणी राजनीतिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक और अन्य नेताओं को शामिल करता है'। इसलिए रूबेन अब्राहम का इससे, साथ ही ओमिडयार और एसईडीएफ से संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है; वह मूल रूप से उनका आदमी है, जो भारतीय सरकार के एक महत्वपूर्ण संगठन में बैठकर उनके एजेंडा को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने अपनी विचारधारा के नेता के रूप में उसे स्थापित करने के लिए उसमें धन और संसाधन लगाए हैं। और अब प्रतिफल का समय आ गया है, क्योंकि वह आईडीएफसी के भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ओमिडयार नेटवर्क, आईडीएफसी द्वारा निर्मित डिजिटल बुनियादी ढांचे में निस्संदेह एक बड़ा हितधारक है, क्योंकि इसने आईडीएफसी फाउंडेशन को तीन वर्षों में दस लाख डॉलर से अधिक का दान दिया है। फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन और गेट्स फाउंडेशन जैसे समान उद्देश्यों वाले अन्य विदेशी दानदाताओं के साथ मिलकर, आईडीएफसी फाउंडेशन को लगभग तीन मिलियन डॉलर प्राप्त हुए हैं।

आईडीएफसी इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित डिजिटल अवसंरचना एक सामाजिक क्रेडिट प्रणाली का आधार है, जिसे डब्ल्यूईएफ 'ग्रेट रीसेट' नामक एक नई विश्व व्यवस्था की खोज में समर्थन देता है। ओमिडयार के लिए, यह उन्हें अधिक डेटा प्राप्त करने और अपने प्रभाव को और बढ़ाने में मदद करता है। जैसा कि एक रिपोर्टर ने उनके बारे में टिप्पणी की:

[ओमिडयार] के अनुसार, इसका उद्देश्य तकनीकी विशेषज्ञों, व्यापारिक अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों को दुनिया का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए चीजों को एकीकृत करना है—ताकि वे समाज का अधिक कुशलता से प्रबंधन और नियंत्रण कर सकें। — याशा

लेविन, 'सर्विलांस वैली: द मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट' के लेखक। [49]

आईडीएफसी संस्थान की परियोजनाएं

संस्थान में पच्चीस से अधिक परियोजनाएं चल रही हैं, जिन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डेटा, अर्थमितीय अध्ययन और मशीन लर्निंग में उच्च कुशल टीमों द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह एक डेटा गवर्नेंस नेटवर्क भी संचालित करता है, जो पेशेवरों का एक बहुविषयक समुदाय है, जो 'सुशासन प्रथाओं और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है'।

संस्थान ने कई अत्याधुनिक डिजिटल उपकरण विकसित किए हैं जो उपग्रह चित्रों, सर्वेक्षणों और रेलवे तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त विशाल डेटा के आधार पर निर्णय लेने में सहायक हो सकते हैं। आईडीएफसी संस्थान की प्रमुख परियोजनाओं में भारत के शहरीकरण, सकल घरेलू उत्पाद, आंतरिक प्रवासन, शहरी गतिशीलता, क्षेत्रीय भिन्नताओं और बुनियादी ढांचे तथा शहरी विस्तार का मानचित्रण जैसी अवसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं।

यह संस्थान आर्थिक नीति संबंधी मुद्दों पर सरकार को सलाह देने के लिए उपग्रह इमेजिंग से प्राप्त बड़े डेटा का उपयोग करता है, जो परंपरागत रूप से संख्यात्मक विश्लेषण द्वारा प्राप्त किया जाता था। यह उपग्रह इमेजरी के एआई-आधारित विश्लेषण का उपयोग करके शहरीकरण और उसे प्रभावित करने वाले कारकों की निगरानी करता है और नीति विश्लेषण के लिए बड़े डेटा का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, यह आंतरिक प्रवासन का अध्ययन करता है, जिसमें 'रोजगार की तलाश में प्रवासन के लिए पांच वर्षों के अनारक्षित रेल यात्री यात्रा के मासिक डेटा का उपयोग एक संकेतक के रूप में किया जाता है। भारत में रेलवे स्टेशनों के प्रत्येक

जोड़े के लिए डेटा संकलित किया गया था।' बड़े डेटा का उपयोग जिला स्तर तक श्रम प्रवाह को समझने के लिए भी किया गया था। अंतर-राज्यीय व्यापार की जानकारी प्राप्त करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क डेटा और केंद्रीय बिक्री कर चालानों का विश्लेषण किया गया था। आईडीएफसी संस्थान इंटरैक्टिव मानचित्रों का उपयोग करके पूरे भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं के मानचित्र बना रहा है। इस तर्क के साथ कि ये मानचित्र संकट के समय बहुत उपयोगी होते हैं, इनमें भारी मात्रा में डेटा एकत्र किया जा रहा है।

स्वास्थ्य सुविधाओं के स्थान जैसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को जियोटैग किया जाना चाहिए और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इससे नवाचार के लिए डेटा के पुन: उपयोग को प्रोत्साहन मिलता है, जैसे कि अनुसंधान, नई सेवाओं और उपकरणों का विकास, या साक्ष्य-आधारित नीतियों में सुधार। ... इसका उपयोग निर्णय निर्माताओं और मानवीय एजेंसियों को सुविधाओं तक पहुंच मापने, स्वास्थ्य क्षेत्र की समग्र सेवा वितरण में सुधार करने और/या आपातकालीन प्रतिक्रिया की योजना बनाने में मदद करने के लिए किया जा सकता है। सड़क अवसंरचना में सुधार के लिए चल रहे सरकारी कार्यक्रमों और कोविड-19 के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया के सकारात्मक प्रभावों के रूप में, भारतीय स्वास्थ्य सुविधाओं के स्थानों वाली दो नई डेटासेट अब सार्वजनिक क्षेत्र में जोड़ दी गई हैं। इनमें शामिल हैं: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तीसरे चरण के अंतर्गत ग्रामीण सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का सर्वेक्षण किया गया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के अंतर्गत सूचीबद्ध निजी सुविधाएं (कोविड-19 टीकाकरण केंद्र या सीवीसी के रूप में कार्यरत) [52]

आईडीएफसी संस्थान बृहन्मुंबई नगर निगम के मृत्यु दर, नियंत्रण क्षेत्र, बिस्तर क्षमता, टीकाकरण आदि जैसे विस्तृत संकेतकों के आंकड़ों का उपयोग करता है। आईडीएफसी का कहना है: 'जैसा कि अनुमान लगाया जा सकता है, ऐसे आंकड़े न केवल अल्पकालिक नीतिगत उपायों को तैयार करने में बल्कि दीर्घकालिक अकादमिक अनुसंधान में सहायता करने में भी अत्यंत उपयोगी हैं।'

… हमने जुलाई 2020 से लेकर अब तक की सभी पीडीएफ फाइलें एकत्र कर ली हैं। हम सभी प्रासंगिक संकेतकों को मशीन-पठनीय प्रारूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में हैं और इन्हें जल्द ही सार्वजनिक डेटाबेस के रूप में उपलब्ध कराएंगे। … हम संबंधित डेटासेट के साथ इनका संक्षिप्त विश्लेषण भी प्रकाशित करेंगे। हमने समय के साथ सभी मृत्यु दर आंकड़ों को संकलित और विश्लेषण करके शुरुआत की है, जैसा कि नीचे बताया गया है।[54]

आईडीएफसी ने कोविड-19 टीकाकरण दर, महामारी के दौरान आईसीयू बेड की उपलब्धता, मृत्यु दर, आईसीयू बेड की उपयोग दर, गंभीर कोविड-19 मामलों, विभिन्न जनसांख्यिकीय समूहों को दी गई खुराक आदि से संबंधित आंकड़े भी एकत्र किए। विदेशी वित्त पोषित निजी संस्थान के पास यह बहुमूल्य डेटा है।

इसके अलावा, इसने भारत में महामारी के दौरान टीकाकरण की स्वीकार्यता के लिए व्यवहार परिवर्तन हेतु एक टूलकिट भी तैयार किया: 'हमने महसूस किया कि टीकाकरण की मांग को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन को सुगम बनाने हेतु सरल, सहानुभूतिपूर्ण और प्रभावी संचार की आवश्यकता है।'

आईडीएफसी के पास नीति आयोग के विनिर्माण फर्मों के डेटा तक पहुंच है और वह इसके लिए सर्वेक्षण आयोजित करता है:

नीति आयोग-आईडीएफसी संस्थान उद्यम सर्वेक्षण में राज्यों में व्यावसायिक नियामक वातावरण का आकलन करने के लिए लगभग 3200 विनिर्माण फर्मों को शामिल किया गया है, जिनमें विनिर्माण स्टार्टअप भी शामिल हैं। यह सर्वेक्षण व्यवसाय करने के 9 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जैसे कि व्यवसाय शुरू करना, भूमि और निर्माण संबंधी परमिट, पर्यावरण परमिट, श्रम नियम, बुनियादी ढांचा संबंधी उपयोगिताएँ जैसे बिजली, पानी और सीवरेज, कर और सीमा शुल्क, कानूनी मुद्दे, वित्त तक पहुंच और व्यवसाय से बाहर निकलना। फर्मों से पूछा जाता है कि क्या उन्होंने अनुपालन प्रक्रियाएँ ऑनलाइन पूरी कर ली हैं, प्रक्रियाओं को पूरा करने में कितना समय लगा और उन्हें इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में किन बाधाओं का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, सर्वेक्षण में उद्योग संघों और विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है ताकि राज्यों में व्यावसायिक नियामक वातावरण के संबंध में उनके विचार जाने जा सकें।
निम्नलिखित तालिका उनके कुछ प्रोजेक्टों के उदाहरण दर्शाती है।[57]

MAPPING INDIA'S URBANIZATION	Satellite imagery and machine learning techniques to analyze level and form of urbanization across India over the last four decades.
DEVELOPING INFRASTRUCTURE TO CREATE EMPLOYMENT	Study focuses on eighteen districts across states that show potential for growth. The project will involve conducting a firm-level survey of districts to understand infrastructural constraints enterprises face in operating, scaling, and hiring.
MAPPING INDIA'S GDP	New 3D web tool developed to assess the spatial distribution of India's GDP. This tool is based on 2006 GDP and population data (recent data will be added) and be used to understand variation in economic activity across the country at a higher resolution than administrative data, and at a granular level. Users can search for specific cities to view economic output at a one sq. km. cell level and population.
INDIA INFRASTRUCTURE REPORT	Government should focus on areas where market does not operate like providing mass public transit and public services, and facilitate effective functioning of land and housing markets. This will make housing affordable for low-income groups. IDFC Institute has developed a new web tool that illustrates the supply-side constraints that hinder access to affordable housing in India.

URBAN DEFINITIONS	Providing alternate definitions
COVID STUDIES: KARNATAKA	Seroprevalence studies conducted in random population-representative studies are essential for measuring the spread of COVID-19. To fill this critical evidence gap, researchers from IDFC Foundation undertook a study in Karnataka in collaboration with the Centre for Monitoring Indian Economy.
INDEX FOR LAND GOVERNANCE	The current government's interest in improving the existing land title system across all states presents a great opportunity to speed up implementation of the Digital India Land Records Modernisation Programme as a prerequisite to moving towards a system of conclusive titles. This is an opportunity to track states' performances in modernizing land records. IDFC Institute, in collaboration with World Bank, is involved in creating a state-level land governance index. Such an indicator will capture policymakers' attention at a high level, improve ability to regularly report on progress and possibly also allocate funds, support DILRMP management/implementation by allowing Department of Land Resources, GOI, to drill down to sub-registrar office/village level, and make it possible to assess the impact of modernization by correlating it with other sources of socio-economic data.

ओमिडयार कर्नाटक में डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए IDFC का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह IDFC, HDFC और कर्नाटक सरकार के बीच एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी के रूप में स्थापित किया गया है, जिसे iDeck इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (कर्नाटक) लिमिटेड कहा जाता है। iDeck सरकारों को नीति निर्माण, कानून बनाने और क्षमता निर्माण गतिविधियों में भी सहायता प्रदान करता है। IDFC

फाउंडेशन की वेबसाइट के अनुसार:
आईडीएफसी फाउंडेशन, कर्नाटक सरकार (जीओके) और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचडीएफसी) के संयुक्त उद्यम, आईडेक को एक गतिशील सरकारी विभाग की स्थिरता और अवसंरचना रणनीति में अग्रणी रहे विशेषज्ञों की प्रेरणा से बनाया गया है। वर्ष 2000 से, आईडेक परिवहन, पर्यटन, शहरी विकास, सामाजिक अवसंरचना, औद्योगिक अवसंरचना और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अवसंरचना के विकास के लिए दुनिया भर की सरकारों, उनके विभागों और एजेंसियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के ग्राहकों के साथ मिलकर काम कर रहा है।
एक अन्य परियोजना नई दिल्ली में है, जो आईडीएफसी फाउंडेशन और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के बीच एक गठबंधन है, जिसे दिल्ली एकीकृत मल्टी-मोडल ट्रांजिट सिस्टम लिमिटेड कहा जाता है। ओमिडयार, गेट्स और रॉकफेलर द्वारा समर्थित आईडीएफसी परिवहन नीति पर सरकार को सलाह दे रही है।
आईडीएफसी फाउंडेशन और (जीएनसीटीडी) के संयुक्त उद्यम, डीआईएमटीएस परिवहन क्षेत्र में नीतिगत, तकनीकी और लेनदेन संबंधी सलाहकारी समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। यह भारत के कई शहरों और विकासशील देशों में सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के विकास और सुधार में सरकार और निजी ग्राहकों की सहायता करता है। यह परिवहन योजना, बुद्धिमान परिवहन प्रणाली, अवसंरचना इंजीनियरिंग, रेलवे, परिवहन प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, लेनदेन सलाहकारी और संचालन जैसी कई सेवाएं प्रदान करता है। इन एजेंसियों की भागीदारी ने भारत में अवसंरचना के विकास के लिए पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) के उपयोग के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है।

ओमिडयार-चीन गठजोड़

ओमिडयार का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध और पार्टी के साथ 'सहयोग' में काम करने का उनका दावा भारत के लिए प्रत्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा है। सवाल यह है कि क्या इस 'सहयोग' का मतलब भारत में चीनी हितों के लिए काम करना है। 2017 की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि चीन राष्ट्रपति जो बाइडेन की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहा था और उसमें ओमिडयार समेत कई लोगों का नाम लिया गया था।

2017 की एक रिपोर्ट में प्रभावी रूप से सीसीपी की ओर से दावा किया गया है कि सीएनएन के होस्ट फरीद ज़कारिया, ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी, फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड की सदस्य हेले थॉर्निंग-श्मिट, नेवरट्रम्प के परोपकारी पियरे ओमिडयार और कई अन्य लोग सीसीपी और उसके लक्ष्यों के साथ "सहयोग" करते हैं।

इसी बात को ध्यान में रखते हुए, सीएसी विदेशी दर्शकों के लिए 10,000 से अधिक प्रचार सामग्री को बढ़ावा देने का दावा करता है और महत्वपूर्ण रूप से, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में पश्चिमी थिंक-टैंकों के साथ अपने काम का बखान करता है: 'संयुक्त राज्य अमेरिका में बर्गग्रुएन इंस्टीट्यूट, कैनेडियन सेंटर फॉर इंटरनेशनल गवर्नेंस इनोवेशन और ऑस्ट्रेलिया में लोवी इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी जैसे थिंक-टैंकों के साथ सहयोग के माध्यम से, हमने चाइना डेली में विशेष टिप्पणीकार के रूप में लगभग 200 विदेशी थिंक-टैंकरों को आकर्षित किया है। एक वर्ष में, इसने उनके हस्ताक्षर वाले 300 से अधिक लेख प्रकाशित किए, जिससे इन प्रभावशाली लोगों को अधिक विदेशी दर्शकों को प्रभावित करने और चीन की कहानियों को अच्छी तरह से बताने में मदद मिली।' अमेरिका में मीडिया जगत की सोच को बदलने के लिए ओमिडयार

मीडिया कंपनियों में निवेश करने के लिए जाने जाते हैं और अब भारत में भी वे यही कर रहे हैं। ओमिडयार ने बेंगलुरु स्थित स्व-प्रकाशन प्लेटफॉर्म 'प्रतिलिपि' में निवेश किया है, जिसने हाल ही में चीन स्थित किमिंग वेंचर पार्टनर्स से भी निवेश प्राप्त किया है। ओमिडयार 'प्रतिलिपि' के माध्यम से अगले पांच करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जो भारत का सबसे बड़ा स्व-प्रकाशन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। 'प्रतिलिपि' बारह भारतीय भाषाओं में पाठकों और लेखकों को जोड़ता है। विदेशी पूंजी से युक्त इस साइट के पास पहले से ही '2.5 करोड़ से अधिक पाठक, 27 लाख से अधिक कहानियां, 2.7 लाख से अधिक लेखक और 12 भाषाएं' का विशाल संग्रह है। एक बार 'प्रतिलिपि' को पर्याप्त लोकप्रियता मिल जाने पर, इसके लिए कुछ आवाजों को दबाना और दूसरों को बुलंद करना आसान हो जाएगा। चूंकि प्रतिलिपि 'भारत में क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य को बढ़ावा देने वाला एकमात्र ऑनलाइन मंच है', ऐसा प्रतीत होता है कि भारत अपना समकालीन साहित्य ओमिडयार और चीनी निवेशकों को सौंप रहा है।

सामाजिक प्रभाव

ओएनआई की एक प्रभावशाली परियोजना उन क्षेत्रों में नवीनतम तकनीक ला रही है जो पहले से ही मिशनरियों और अलगाववादी आंदोलनों से भरे पड़े हैं। रीसॉल्व इनिशिएटिव परियोजना उन गैर-सरकारी संगठनों को सशक्त बना रही है जिनसे हम पिछले कई दशकों से लड़ रहे हैं और जो भारत की ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाली आबादी का शोषण करते हैं। इसका लक्ष्य उन 11 करोड़ भारतीयों को है जो सूक्ष्म और लघु व्यवसायों को चलाने में मदद करते हैं और साथ ही उन प्रवासी श्रमिकों को भी है जिनकी संख्या 80 से 13 करोड़ के बीच होने का

अनुमान है।
ओएनआई ने जिस अवसर का लाभ उठाया है, वह यह है कि इन छोटे व्यवसायों और प्रवासी कामगारों की सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को 'व्यवस्थित रूप से संबोधित नहीं किया गया है'। इस भेद्यता को इस प्रकार पहचाना गया है: 'महिलाओं और बालिकाओं के प्रति लैंगिक पूर्वाग्रह प्रवासी महिलाओं और बच्चों के बीच कैसे प्रकट होते हैं? उनमें से कितनों को पर्याप्त भोजन, पोषण और शिक्षा मिलती है?' यह परियोजना उद्यमियों, विचारकों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाती है। अब तक ओएनआई ने सत्रह राज्यों में सड़सठ ग्रामीण परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है, जिनमें से इक्कीस का दावा है कि उनका राष्ट्रव्यापी प्रभाव है। कम से कम 32 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं; ओएनआई की सामाजिक न्याय गतिविधियों से 48 करोड़ अन्य भारतीयों को भी लाभ होगा।
ओमिडयार नेटवर्क इंडिया, अशोका विश्वविद्यालय के सामाजिक प्रभाव और परोपकार केंद्र में निवेश कर रहा है, जो दावा करता है कि यह भारत का पहला शैक्षणिक केंद्र है जो व्यापक सामाजिक प्रभाव के लिए रणनीतिक और सशक्त परोपकार को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ओएनआई का कहना है: 'केंद्र का उद्देश्य क्षेत्र की रणनीति और कार्रवाई को सूचित करने वाले ज्ञान उत्पाद विकसित करके, और क्षेत्र की दृष्टि, आवाज और मानदंडों का निर्माण करने वाले स्वतंत्र, निष्पक्ष मंच प्रदान करके इसे प्राप्त करना है।' इस पर अध्याय 19 में अधिक विस्तार से चर्चा की गई है।
पिछले अध्याय में हमने एमआईटी स्थित सऊदी अरब द्वारा वित्त पोषित अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब (जे-पाल) के कार्यों में व्याप्त दोहरेपन की व्याख्या की थी। ओमिडयार नेटवर्क इंडिया जे-पाल को वित्त

पोषित करता है और उसके साथ सक्रिय रूप से काम करता है। यह मानते हुए कि भारतीय जे-पाल की निंदनीय गतिविधियों से अनभिज्ञ होंगे, ओएनआई का दावा है कि उसका मिशन 'वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित नीतियों को सुनिश्चित करके गरीबी कम करना' है। हम यह शोध, नीतिगत जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण के माध्यम से करते हैं।

जनअग्रहा एक अन्य गैर-सरकारी संगठन है जिसे ओएनआई द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और यह भारत के शहरों और कस्बों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने का दावा करता है। यह स्थानीय राजनीतिक मुद्दों पर जनता को शिक्षित करने और वकालत करने के अपने सक्रिय प्रयासों के माध्यम से शहरी प्रशासन में सुधार लाने का दावा करता है। यह परियोजना ओएनआई को भारत भर के चार हजार से अधिक शहरों में स्थानीय, राज्य और केंद्र सरकारों में पैठ बनाने में मदद करती है। यह कुछ हद तक वैसी ही भूमिका है जैसी ओमिडयार ने अमेरिकी स्थानीय राजनीति में मतदाताओं को संगठित करने, विशिष्ट नीतियों को बढ़ावा देने और राजनेताओं पर दबाव डालने में निभाई है।

फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी (एफईएस) ग्रामीण नागरिकों के साझा भूमि पर अधिकार, स्वशासन और संरक्षण के कानूनी अधिकार सुनिश्चित करता है। यह जमीनी स्तर पर भूमिहीन समुदायों का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे यह पारंपरिक गैर सरकारी संगठनों का एक उन्नत संस्करण बन जाता है जो समाज के सबसे निचले तबके तक मानवाधिकारों को पहुंचाते हैं। अपने डेटाबेस में पहले से ही नौ मिलियन एकड़ से अधिक भारतीय भूमि का डेटा होने के कारण, यह समुदायों पर प्रभाव डालता है, उनकी सामाजिक-राजनीतिक-धार्मिक संरचना पर डेटा एकत्र करता है और व्यवहार के मॉडल विकसित करता है। निस्संदेह, एफईएस सुदूर क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, लेकिन हमारी चिंता

केवल विदेशी निर्भरता, डेटा के बहिर्वाह और वैचारिक प्रभावों के अंतर्वाह को लेकर है।

जन साहस एक गैर-सरकारी संगठन है जो भारत के सबसे वंचित समुदायों के लिए काम करता है और उन्हें परामर्श, कानूनी सहायता, रोजगार कौशल, भूमि और संपत्ति अधिकार, सामाजिक सहयोग, सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन, जागरूकता अभियान आदि सेवाएं प्रदान करता है। यह दावा करता है कि यह बेहतर नीतियों को प्रभावित करने के लिए स्थानीय सरकार, पुलिस और राज्य तंत्र के साथ मिलकर काम करता है। इससे जन साहस एक महत्वपूर्ण जमीनी स्तर का कार्यकर्ता बन जाता है जो पांच मिलियन से अधिक लोगों तक एक प्रकार का अप्रत्यक्ष शासन पहुंचाता है।

ओमिडयार नेटवर्क इंडिया, मैकार्थर और रॉकफेलर फाउंडेशन के साथ मिलकर कैटेलिटिक कैपिटल कंसोर्टियम (C3) का संचालन करता है। इसका सामाजिक प्रभाव अफ्रीका और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण कारीगरों पर पड़ता है।

ओमिडयार नेटवर्क इंडिया का विविधता, समानता और समावेशन कार्य लिंग, जाति, धर्म और यौन अभिविन्यास के आधार पर सामाजिक न्याय दिलाने के लिए कानूनी सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सक्रियता उत्पन्न करना है। यह विभिन्न हाशिए पर पड़े समूहों से युवा नेताओं का निर्माण करता है और उन्हें सामाजिक, सामाजिक, सामाजिक और सामाजिक विकास (ESG) गतिविधियों से जोड़ता है। यह ओमिडयार सांस्कृतिक ढांचे को भारत के मध्य भाग में लाता है। यह महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को हल करने के लिए विघटनकारी, विशिष्ट सोच को बढ़ावा देने हेतु बुनियादी ढांचा तैयार करके नड्ज फाउंडेशन के सामाजिक नवाचार केंद्र को भी वित्त पोषित करता है।

ओएनआई ने इस क्षेत्र पर केंद्रित उद्यमियों के साथ एक दशक से अधिक समय बिताया है, जिसमें से पिछले तीन वर्षों का उपयोग 'आंतरिक संवाद, आत्मनिरीक्षण और विविधता एवं समावेशन पर जागरूकता' के लिए किया गया था। अब, विविधता परियोजना अगले स्तर पर पहुंच रही है। अपने द्विवार्षिक न्यूज़लेटर, विविधता के पहले अंक में, इसने अपनी अंतर्दृष्टि और लक्ष्यों को रेखांकित किया है:

अब समय आ गया है कि सामान्य चर्चा से हटकर संगठनों को विशिष्ट लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने के लिए प्रेरित किया जाए।

इसका उद्देश्य विविधता, समावेशन और समावेशन (DEI) को मूल व्यवसाय और संगठनात्मक रणनीति में समाहित करना है ताकि सफलता और प्रभाव को गति मिल सके।

जमीनी स्तर पर काम करने वाले सैनिकों को 'असुविधाजनक सच्चाइयों का सामना करने', 'कठिन बातचीत करने' और अपने 'अचेतन पूर्वाग्रहों' को पहचानने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 'दृढ़, लचीले और खुले विचारों वाले बनें क्योंकि कई समाधान अप्रभावी या अप्रत्याशित रूप से लागू करने में कठिन साबित हो सकते हैं'।

डेटा माइनिंग निरंतर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और वांछित समाधान बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनी हुई है।

वेंचर कैपिटलिस्टों द्वारा फंडिंग में विविधता लाने के लिए दबाव बनाना अब एक लक्ष्य बन गया है।

ओपन डिजिटल इकोसिस्टम पहल, समुदाय और सुदृढ़ शासन के गैर-तकनीकी स्तर प्रदान करती है, जिसे 'फिजीटल' (भौतिक + डिजिटल) भी कहा जाता है। यह आमतौर पर वह बिंदु है जहां सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना समाप्त होती है और 'अंतिम मील' यानी दूरस्थ क्षेत्रों में रहने

वाले लोगों का नेटवर्क शुरू होता है। यह ओएनआई को सबसे कमजोर और संवेदनशील आबादी के लिए डिजिटल गेटकीपर के रूप में स्थापित करता है।

प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन (PRADAN) वन-आधारित हाशिए पर स्थित समुदायों में हस्तक्षेप कर रहा है। ये पारंपरिक वनवासी हैं (जिन्हें अनुचित रूप से 'आदिवासी' कहा जाता है)। यह एक और संवेदनशील क्षेत्र है जहाँ से ओएनआई सक्रियता के लिए जमीनी कार्यकर्ताओं की भर्ती और प्रशिक्षण करना चाहता है।

नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया को सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए ओएनआई से अनुदान प्राप्त होता है। यहां ओएनआई अपने नेटवर्क के उपयोग के बारे में खुलकर बताता है: 'राज्य स्तरीय साझेदारियों और नागरिक सहभागिता के माध्यम से हमने 26,000 दलित और आदिवासी परिवारों, 14,000 से अधिक अल्पसंख्यकों, 30,000 महिलाओं, 3,000 युवाओं और 158 विधानसभा सदस्यों तक पहुंच बनाई है।'

भारत के लिए इसके निहितार्थ स्पष्ट हैं। इसके साथ ही ओएनआई का लीगल टेक सिद्धांत भी जुड़ा हुआ है: देश के डिजिटलीकरण ने ऐसे सुधारों के अवसर खोले हैं जो 'न्यायालय-केंद्रित न्यायिक सुधारों से परे' हैं। यह तकनीक-आधारित कानूनी हस्तक्षेप ओएनआई को अपनी सक्रियता को बढ़ाने की क्षमता प्रदान करता है।

ओएनआई की एक और पहल जिस पर उसे गर्व है, वह है सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने और सामाजिक न्याय के युवा नेताओं का मार्गदर्शन करने के लिए उसका 'पुरस्कार विजेता कार्यक्रम पाठ्यक्रम'। यह भूमिका जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और सरकार के बीच मध्यस्थ और संपर्क सूत्र के रूप में रणनीतिक रूप से स्थापित है।

ओमिडयार नेटवर्क इंडिया का गिवइंडिया के साथ एक रणनीतिक

समझौता भी है, जो दानदाताओं और गैर-लाभकारी संगठनों को जोड़ने वाला एक क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म है। ओमिडयार नेटवर्क इंडिया अपनी ब्रांड वैल्यू और विश्वसनीयता के दम पर दानदाताओं की मदद करता है। ओएनआई के अनुसार, यह 'दानदाताओं और गैर-लाभकारी संगठनों के बीच विश्वास की कमी को दूर कर रहा है और विश्वसनीय गैर-लाभकारी संगठनों को काफी कम लागत पर खुदरा दान प्राप्त करने में सहायता कर रहा है'। दूसरे शब्दों में, यह दानदाताओं और गैर-सरकारी संगठनों के बीच एक शक्तिशाली मध्यस्थ की भूमिका निभाता है और अपनी भूमिका को इस प्रकार समझाता है:

गिवइंडिया गैर-सरकारी संगठनों को उनके कर्मचारियों, स्वयंसेवकों और दानदाताओं के माध्यम से आपसी सहयोग से धन जुटाने की शक्ति का लाभ उठाने में मदद करता है। व्यक्ति (कर्मचारी, स्वयंसेवक, दानदाता आदि) गिवइंडिया के ऑनलाइन क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म पर किसी गैर-सरकारी संगठन के लिए धन जुटाने के अभियान बना सकते हैं।

इसमें आगे बताया गया है कि यह सीएसआर कार्यक्रमों से कैसे जुड़ा हुआ है।

ओमिडयार नेटवर्क इंडिया ने ग्रामीण ई-कॉमर्स पर एक शोध-प्रबंध विकसित किया है, जिसका उद्देश्य अगली पीढ़ी के आधे अरब लोगों की आकांक्षाओं के बारे में लगातार अधिक जानकारी प्राप्त करना और उनके जीवन में प्रवेश करने के तरीके खोजना है।

अपने अमेरिकी मूल संगठन की तरह, ओएनआई भी राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर मीडिया को प्रभावित करने के तरीके खोजता रहता है। उदाहरण के लिए, इसने न्यूजलॉन्ड्री और स्क्रॉल में इक्विटी निवेश किया है। स्वराज्या को दिया गया इसका अनुदान संदेह पैदा करता है। यह सवाल उठता है कि क्या यह 'संतुलन' का सार्वजनिक प्रदर्शन है या द

इंडिपेंडेंट की तरह संपादकीय नीति को प्रभावित करने की दीर्घकालिक रणनीतियों का एक प्रवेश बिंदु है।

नीति अनुसंधान और सरकार पर इसका प्रभाव
ईस्ट इंडिया कंपनी से परिचित भारतीय, राजनीतिक और सरकारी मामलों में विदेशी हस्तक्षेप के जोखिमों और अनिश्चितताओं को भली-भांति जानते हैं। मैत्रीपूर्ण सहयोग से शुरू हुआ संबंध वैचारिक या व्यावसायिक हितों के टकराव की स्थिति में आसानी से शत्रुतापूर्ण हो सकता है। ओमिडयार के मामले में, अन्य देशों में भी इसके उदाहरण मौजूद हैं। एक उदाहरण ओमिडयार द्वारा वित्तपोषित आंदोलन हैं, जिन्होंने कथित तौर पर यूक्रेन की पिछली सरकार को गिराने में मदद की थी। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार, यह बताया गया है कि ओमिडयार, जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर एक ऐसे संगठन के प्रमुख वित्तपोषक थे, जिसने यूक्रेन में विद्रोह भड़काने में मदद की। इसके चलते 2014 में यूक्रेनी राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को सत्ता से बेदखल कर दिया गया क्योंकि उन्होंने यूरोपीय संघ के बजाय रूस के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए थे। आरोप यह है कि अमेरिकी अरबपतियों ने सीआईए के साथ गठबंधन किया क्योंकि देशों को रूस के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकालने से अमेरिकी निगमों के लिए अवसर पैदा होंगे।
नीचे ओमिडयार द्वारा भारतीय शासन में शामिल व्यक्तियों और संगठनों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से की गई पैठ के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। शुरुआत से ही, पियरे ओमिडयार ने भारत के कुछ सबसे प्रभावशाली राजनीतिक नेताओं से संपर्क साधा, जिससे उन्हें भारत की सत्ता संरचना के प्रमुख लोगों तक पहुँच प्राप्त हुई। इनमें से एक थे सी.वी. मधुकर, जिन्होंने ओमिडयार नेटवर्क के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया है।

ओमिडयार नेटवर्क डिजिटल पहचान और डेटा गोपनीयता से संबंधित मुद्दों में रणनीतिक हस्तक्षेपों का नेतृत्व करने के लिए मधुकर की सराहना करता है। उन्होंने भारत में विदेशी ई-कॉमर्स प्रवेश, सुशासन और पारदर्शिता पर गठित कार्यबल और अन्य महत्वपूर्ण संगठनों से संबंधित नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और विश्व बैंक के साथ भी काम किया है, हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से डिग्री प्राप्त की है और विश्व आर्थिक मंच में यंग ग्लोबल लीडर के रूप में नामित हुए हैं।

ओमिडयार द्वारा भारत में अपने प्रमुख नेताओं में से एक के रूप में मधुकर को चुनने का एक कारण यह था कि मधुकर नई दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च स्टडीज (पीआरएस) के सह-संस्थापक थे। पीआरएस के महत्व को समझने के लिए, हम इसकी वेबसाइट का संदर्भ लेते हैं, जो इसके लक्ष्यों को इस प्रकार वर्णित करती है: 'विधायकों को विभिन्न मुद्दों की बारीकियों को समझने और विभिन्न नीतिगत विकल्पों के निहितार्थों का आकलन करने के लिए डेटा और साक्ष्य का उपयोग करने में मदद करना'। इससे संबंधित इसका एक और लक्ष्य है 'विधानमंडलों की पारदर्शिता में सुधार करना', जिसका अर्थ है कि यह स्वयं को एक निगरानी संस्था के रूप में देखता है जो यह सुनिश्चित करती है कि विधायकों में योग्यता और ईमानदारी हो। यह संस्थान राजनीति में प्रवेश करने वाले युवा भारतीयों को संसद सदस्यों के साथ जोड़कर उनका मार्गदर्शन भी कर रहा है।

संक्षेप में: 'पीआरएस का विज़न विधायिकाओं को अधिक प्रभावी बनाकर भारत के लोकतंत्र को मजबूत करना है। पीआरएस का मिशन विधायी प्रक्रिया को अधिक जानकारीपूर्ण, अधिक पारदर्शी और सहभागी बनाना है।' यह उल्लेखनीय है कि पीआरएस के अन्य बोर्ड सदस्यों में तरुण

खन्ना (जिनके बारे में पहले हार्वर्ड मित्तल इंस्टीट्यूट के प्रमुख के रूप में चर्चा की गई थी) और प्रताप भानु मेहता (जिनके बारे में अशोका विश्वविद्यालय के पूर्व प्रमुख के रूप में चर्चा की गई थी) शामिल हैं।
भारत में ओमिडयार जैसी विदेशी संस्था की भूमिका को देखते हुए, पीआरएस को सर्वोच्च स्तर पर अपने नियंत्रण में लेना वाकई एक सराहनीय उपलब्धि है। ओमिडयार नेटवर्क थिंकटैंक में इस तरह की पैठ बनाने में इसलिए सफल रहा है क्योंकि यह अपनी रणनीतिक पहलों पर इस तरह से चर्चा करता है जिससे सरकार को लगता है कि वह उसका 'सहयोगी' है। इससे नौकरशाहों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने और उन्हें दीर्घकालिक प्रभाव के लिए मार्गदर्शन देने तथा सूचनाओं तक पहुंच प्राप्त करने में भी मदद मिलती है।
ऊपर वर्णित डिजिटल मध्यस्थ ई-गवर्नमेंट फाउंडेशन, नगरपालिका संचालन, निर्णय लेने और वित्तीय पारदर्शिता में अपनी भूमिका के साथ, केंद्र सरकार में शीर्ष-स्तरीय नीति निर्माण और स्थानीय स्तर पर निचले-स्तरीय कार्यान्वयन को सुगम बनाता है। इसका प्रभाव भारत में पहले से ही 16 करोड़ से अधिक लोगों पर है। यह नीति निर्माण संबंधी बहसों, दृष्टिकोणों और नीतिगत परिवर्तनों की प्रत्याशाओं का एक बड़ा भंडार बन जाएगा।
डेटा गवर्नेंस नेटवर्क एक अन्य शोध पहल है। इसे इस प्रकार वर्णित किया गया है:
पेशेवरों का एक आत्मनिर्भर, बहुविषयक समुदाय जो सुशासन प्रथाओं और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा को दिशा देने में सहायक हो। हमारा लक्ष्य संस्थागत और व्यक्तिगत विशेषज्ञों को एक साथ लाना, उद्योग, सरकार और शिक्षा जगत के हितधारकों को एकत्रित करना और कार्यान्वयन योग्य नीति अनुसंधान को गति प्रदान करना है।

इससे ओएनआई को नीति निर्माण करने वाले सरकारी निकायों में अग्रणी भूमिका निभाने, हमेशा एक कदम आगे रहने और अपने शोध दल, रिपोर्टों, सेमिनारों और अन्य गतिविधियों के माध्यम से सोच को आकार देने का अवसर मिलता है। इसके अलावा, यह अन्य स्टार्टअप्स के लाभ के लिए नीतियों की अग्रिम जानकारी प्रदान करने में भी उपयोगी है।
एक अन्य शोध कार्य में ओमिडयार नेटवर्क इंडिया की भागीदारी डेटा सुरक्षा परिषद (डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया) के साथ है, जो डेटा संरक्षण से संबंधित उद्योग निकाय है। ओमिडयार नेटवर्क इंडिया स्वीकार करता है कि इससे उसे 'केंद्र और राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों, नियामकों, उद्योग क्षेत्रों, उद्योग संघों और थिंक टैंकों तक नीतिगत वकालत, विचार नेतृत्व, क्षमता निर्माण और आउटरीच गतिविधियों के लिए पहुंच' मिलती है। इस तरह के सहयोग से उसे नीति निर्माताओं तक पहुंच मिलती है और भारत की डेटा नीति की दिशा के बारे में अग्रिम जानकारी प्राप्त होती है।
इसका बेंगलुरु स्थित शोध संगठन सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी के साथ एक महत्वपूर्ण संबंध है, जो 'इंटरनेट और डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर अंतःविषयक शोध' पर काम करता है, जिसमें गोपनीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, साइबर सुरक्षा, डिजिटल पहचान, ज्ञान तक पहुंच, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल श्रम और सुलभता जैसे विषयों को नीतिगत और अकादमिक दृष्टिकोण से शामिल किया जाता है। इससे ओएनआई को नीति निर्माताओं के विचारों तक विशेष पहुंच मिलती है और साथ ही अपने स्वयं के प्रभाव डालने का मार्ग भी प्रशस्त होता है।
ओमिडयार नेटवर्क इंडिया ने भारत भर में 'सेवा वितरण और स्थानीय सरकार में मौजूद कई कमियों' को दूर करने के एक बड़े अवसर की ओर इशारा किया है। इसमें कहा गया है:

बड़े महानगरों से लेकर छोटे गांवों तक, अपारदर्शी सरकारी प्रक्रियाओं, सार्वजनिक सेवाओं के आसपास कमजोर बुनियादी ढांचे और नागरिक भागीदारी के अपर्याप्त अवसरों के कारण नागरिकों के हित अक्सर प्रासंगिक सार्वजनिक कार्रवाई में तब्दील नहीं हो पाते हैं। ... विलेज कैपिटल और ओमिडयार नेटवर्क सरकारी प्रणालियों और समुदायों में नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने वाले स्टार्टअप उद्यमों को समर्थन देने के इच्छुक हैं। यह कार्यक्रम उद्यमियों को पुरस्कार विजेता पाठ्यक्रम, क्षेत्र के नेताओं के साथ व्यक्तिगत मार्गदर्शन और रणनीतिक साझेदारों और निवेशकों के साथ अनुकूलित जुड़ाव के माध्यम से सहायता प्रदान करेगा। असल में, ओमिडयार एक समानांतर डिजिटल नागरिक-शासन ढांचा तैयार कर रहा है जो पारंपरिक भौतिक ढांचे को दरकिनार करता है। वह खुले तौर पर इसका औचित्य यह बता रहा है कि मौजूदा ढांचा 'अपर्याप्त' है।

भारत की संप्रभुता खतरे में है

भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर विदेशी स्वामित्व और उस पर सूचना प्रवाह को विदेशी नियंत्रण की अनुमति देने के खतरों को कम करके नहीं आंका जा सकता। विशेष रूप से तब जब विदेशी ताकतों का गृहयुद्धों और सत्ता परिवर्तन को बढ़ावा देने का इतिहास रहा हो। और विशेष रूप से तब जब वे देश के हर स्तर पर प्रभाव डालने, निम्न वर्गों की वकालत करने और सरकार से जवाबदेही की मांग करने का अपना इरादा स्पष्ट रूप से व्यक्त करती हों। और जब महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर अपने नियंत्रण के बल पर वे सरकार की प्रतिक्रिया का अनुमान लगा सकती हों।

सरकार और देश की जनता के बीच फूट डालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी

है। इसकी नींव रखी जा चुकी है और ढांचा तेजी से तैयार किया जा रहा है। भारत की संप्रभुता और लोकतंत्र के लिए खतरा अभूतपूर्व प्रतीत होता है।

23. निष्कर्ष: दावोस के देवता और डिजिटल जाति व्यवस्था

पुस्तक की प्रस्तावना में चार प्रमुख कहानियों का उल्लेख किया गया है जो भारत को कमजोर करने वाले विमर्श को आकार देती हैं। हमने समझाया कि कैसे 'वोकेवाद' सामाजिक उत्पीड़न के विभिन्न प्रकार के पीड़ितों की पहचान कर उन्हें एक एकीकृत आंदोलन में संगठित कर रहा है, और कैसे इस आंदोलन का उपयोग समाज की संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए एक हथियार के रूप में किया जा रहा है। हमने भारत और पश्चिम में मौजूद उस विशाल तंत्र का पर्दाफाश किया जो इस तबाही को अंजाम दे रहा है, और हमने इस गतिविधि में भारतीय अरबपतियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष ध्यान केंद्रित किया।

वोकवाद का मूल सिद्धांत यह है कि उन सभी संरचनाओं को ध्वस्त किया जाना चाहिए जो किसी भी तरह से किसी भी समूह के उत्पीड़न से जुड़ी हैं और जिनका निर्माण उत्पीड़कों द्वारा किया गया था। हम सैद्धांतिक रूप से इसका समर्थन करते हैं क्योंकि यह अतीत की गलतियों को सुधारने और मानवता के लिए एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने का एक तरीका है। लेकिन हम यह बताना चाहते हैं कि:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बिग डेटा जैसी तकनीकों का उपयोग करके दमन की बिल्कुल नई संरचनाएं खड़ी की जा रही हैं, जिनमें उत्पीड़क ही नए अभिजात वर्ग बन गए हैं। नस्ल, जातीयता, धर्म, लिंग और यौन

अभिविन्यास जैसी पहचानों की जगह उत्पीड़क/उत्पीड़ित की बिल्कुल नई श्रेणियां स्थापित हो जाएंगी।

पुरानी संरचनाओं को ध्वस्त करने से दमन की नई प्रौद्योगिकी-आधारित संरचनाओं को सत्ता के शून्य को भरने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। हम एक डिजिटल जाति व्यवस्था की बात कर रहे हैं।

ऐसे परिदृश्य को देखते हुए मानवता के सभी शुभचिंतकों को यह जांच करनी चाहिए: इन दो प्रमुख प्रवृत्तियों के बीच क्या संबंध है: विघटनकारी शक्ति के रूप में वोकवाद और नए तकनीकी अभिजात वर्ग का उदय? पूरी स्थिति को समझने के लिए, हमें यह स्वीकार करना होगा कि कोविड-19 महामारी, युद्धों, जलवायु परिवर्तन और तकनीकी क्रांति जैसी चुनौतियों के कारण हमारी मौजूदा वैश्विक व्यवस्था बिखर रही है। प्रौद्योगिकी पहले से कहीं अधिक तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जिसके परिणामस्वरूप अति-अमीर और बाकी आम जनता के बीच धन का अंतर और भी गहराता जा रहा है। बड़ी तकनीकी कंपनियों का बाज़ार मूल्य कई संप्रभु देशों के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से भी अधिक है। तकनीकी अभिजात वर्ग द्वारा नियंत्रित प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म उन्हें बड़े डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके व्यवहार की भविष्यवाणी और परिवर्तन करने, और विशिष्ट आवाजों को या तो दबाने या बढ़ाने में सक्षम बनाते हैं। वे अपने नियंत्रण वाले बड़े प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके चुनावों को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त प्रभावशाली हैं। प्लेटफॉर्मों और बड़े डेटा पर उनका स्वामित्व उन्हें कथाओं पर नियंत्रण प्रदान करता है; सरकारें असहमति की आवाजों को दबाने या सरकार द्वारा गलत मानी जाने वाली जानकारी को सेंसर करने के लिए उनके साथ गठबंधन करती रही हैं। कथाओं को नियंत्रित करने का एक उदाहरण बड़े मीडिया समूहों का ट्रस्टेड न्यूज इनिशिएटिव (TNI) के तहत एकजुट होना है। TNI की

शुरुआत BBC ने की थी और इसमें भारत का द हिंदू मीडिया समूह भी शामिल है। तकनीकी कंपनियां और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी TNI का हिस्सा हैं। यह समूह स्वयं को सूचना का रक्षक मानता है।

पिछले अध्यायों में यह बताया गया था कि मार्क्सवादी तर्क (हर्बर्ट मारक्यूज़ द्वारा प्रतिपादित) का उपयोग करते हुए वोकवाद द्वारा कैंसिल कल्चर को उचित ठहराया जा रहा है, जिसके अनुसार उत्पीड़क को प्रति-वर्चस्व द्वारा चुप कराया जाना चाहिए। एक उत्पीड़न का मुकाबला दूसरे उत्पीड़न से किया जाना चाहिए। क्या हम कैंसिल कल्चर और डी-प्लेटफ़ॉर्मिंग को रंगभेद और अस्पृश्यता का वोक संस्करण नहीं मान सकते?

प्रौद्योगिकी को एक शक्ति गुणक के रूप में उपयोग करने की क्षमता ने वैश्विक कुलीन वर्गों को सरकारों को प्रभावित करने में सक्षम बनाया है और वे राजनीतिक हस्तक्षेप करने में जरा भी समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से इसका परिणाम सत्ता में बढ़ते अंतर के रूप में सामने आएगा।

यह पहली बार नहीं है जब सभ्यताओं का बड़े पैमाने पर विनाश होगा। लेकिन इस बार हथियार और सैनिक अलग हैं। अरबपतियों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वे इस गतिविधि का सक्रिय रूप से समर्थन करेंगे जो उस विश्व व्यवस्था को नष्ट कर रही है जिसमें वे शीर्ष पर हैं। हां, अगर वे इसे किसी और बड़ी चीज के निर्माण के अवसर के रूप में देखते हैं जिससे उनकी शक्ति और भी अधिक बढ़ जाएगी, तो बात अलग है।

एक संकेत वैश्विक वामपंथियों के 'वोकेवाद' और वैश्विक अरबपतियों की साझेदारी में निहित विचित्र विडंबना है: अरबपतियों ने पुरानी व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम वामपंथियों को सौंप दिया है और उन्हें मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। यह गठबंधन अस्थायी होगा जिसमें एक पक्ष दूसरे

का इस्तेमाल गंदा काम करवाने के लिए कर रहा है। एक बार व्यवस्था ध्वस्त करने का काम पूरा हो जाने पर, 'वोकेवाद' वामपंथी बेकार हो जाएंगे और एक नई व्यवस्था उभर कर सामने आएगी, जिसके शीर्ष पर अरबपति होंगे।

अध्याय 1 में मार्क्सवाद के मुख्य सिद्धांत की व्याख्या की गई थी कि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था अपनी विपरीत शक्ति को जन्म देती है, जिसे प्रतिवाद कहा जाता है। ये दोनों शक्तियाँ परस्पर विनाश की स्थिति तक लड़ेंगी, और मलबे से एक नया संश्लेषण उभरेगा जो हमें आगे ले जाएगा। लेकिन इस बार मार्क्सवादियों के लिए एक बड़ा आश्चर्य और निराशा इंतजार कर रही है!

वामपंथियों को यह जानकर झटका लगेगा कि यह क्रांति (मार्क्सवाद द्वारा परिकल्पित जनतंत्र की तानाशाही की ओर नहीं, बल्कि अभिजात वर्ग की तानाशाही की ओर ले जाएगी।

इस नए प्रकार की तानाशाही नवीनतम तकनीकों पर आधारित होगी और उन दमनकारी ढांचों से कहीं अधिक भयावह होगी जिन्हें उखाड़ फेंका जा रहा है। इसका परिणाम एक समतावादी समाज नहीं बल्कि एक नई पदानुक्रमित जाति व्यवस्था होगी। मार्क्सवादी पद्धतियों का उपयोग एक ऐसा परिणाम उत्पन्न करने के लिए किया जा रहा है जो मार्क्सवाद की इच्छाओं के बिल्कुल विपरीत है। क्या ब्लॉकचेन तकनीक गुलामी की नई जंजीरों में तब्दील हो जाएगी?

इस बात पर बहस हो सकती है कि कौन किसका इस्तेमाल कर रहा है। क्या अरबपतियों के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया के कारण वोकिज़्म (जागरूकतावादी विचारधारा) आगे बढ़ रहा है? या फिर क्या वामपंथी एक आत्मघाती क्रांति में उलझे हुए हैं क्योंकि अभिजात वर्ग का एक नया गुट सत्ता में उभर आएगा?

और नए विश्व व्यवस्था को चलाने वाले नए विजेता कौन हो सकते हैं? व्यवस्थागत गड़बड़ी और अराजकता के किसी भी अस्थाई दौर की तरह, जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो शीर्ष पर आने के लिए कई दावेदार होड़ में होंगे। हर खेमा मौजूदा उथल-पुथल को अपने आप को फिर से स्थापित करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहता है। कुछ प्रमुख दावेदार ये हैं:

पश्चिमी देशों में स्थित वैश्विक वामपंथ – यही हमारा मुख्य विषय है।

वैश्विक ईसाई दक्षिणपंथी

चीन

पैन-इस्लाम

इसलिए, नई विश्व व्यवस्था और उसमें भारत की भूमिका कई अलग-अलग रास्तों से गुजर सकती है। इस उथल-पुथल के बाद उभरने वाले इन सभी वैकल्पिक परिदृश्यों पर चर्चा आवश्यक है। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर भविष्य में एक पुस्तक लिखी जाएगी।

इस संक्षिप्त निष्कर्ष में, हम उस पक्ष का विश्लेषण करेंगे जिसे हम प्रमुख दावेदार मानते हैं। अगले पृष्ठ पर दिया गया आरेख भारत को केस स्टडी के रूप में लेते हुए समग्र स्थिति को दर्शाता है। यह आरेख अति-अमीरों को द्वार पर खड़े बर्बरों के रूप में चित्रित करता है, जो भारत को विखंडित करने के लिए 'वोकेवाद' का उपयोग एक उपयोगी उपकरण के रूप में कर रहे हैं। हम उस परिदृश्य की व्याख्या करेंगे जिसमें वैश्विक अभिजात वर्ग नई सत्ता संरचनाओं का संचालन करेगा और भारतीय अरबपति उसके कनिष्ठ साझेदार होंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा करते थे। वैश्विक अभिजात वर्ग ने अपनी रणनीतियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है, और अब तक की घटनाओं से संकेत मिलता है कि उन्होंने काफी गति प्राप्त कर ली है।

नई विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ते हुए प्रमुख घटनाक्रमों में से एक है व्यापार और सरकार के बीच के पृथक्करण का उन्मूलन, जिससे सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है जो मूलतः एक वैश्विक कुलीनतंत्र है। इस नए प्रतिमान को इसके प्रमुख समर्थक, विश्व आर्थिक मंच द्वारा हितधारक पूंजीवाद का नाम दिया गया है। इसका मुख्य सिद्धांत यह है कि निगमों को सरकारों द्वारा निभाई जाने वाली कई भूमिकाओं को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। यह सामाजिक न्याय और प्रभाव निवेश के बहाने किया जा रहा है। हितधारक पूंजीवाद व्यापार और राजनीति के विलय द्वारा पूंजीपतियों को कुलीनतंत्र में परिवर्तित कर देगा।

वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में, यह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्गों को मिलाकर एक प्रकार का एकीकृत कुलीनवर्गीय वर्ग बना देता है! इससे उन्हें शेयरधारक पूंजीवाद नामक पूंजीवाद के मूल स्वरूप की तुलना में कहीं अधिक धन और शक्ति प्राप्त होती है। यही कारण है कि उनमें से कई लोग वर्तमान व्यवस्था को, जिसमें वे सफल हैं, समाप्त करके इस नई व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें वे सत्ता का अभूतपूर्व केंद्रीकरण करना चाहते हैं।

शेयरधारकों के लाभ के लिए बनाई गई सीमित देयता कंपनी को अब सामाजिक कार्यों के लिए एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल उठता है कि वे दान के लिए बनी स्वतंत्र गैर-लाभकारी संस्थाओं की संरचना का उपयोग क्यों नहीं करते? इसका उत्तर यह है कि सार्वजनिक दान संस्थाएं कानूनों के तहत सार्वजनिक जांच के दायरे में आती हैं। सीमित देयता वाली निजी कंपनियां अपने सामाजिक प्रभाव के लिए सार्वजनिक दान संस्थाओं की तरह जवाबदेह नहीं होतीं।

उदाहरण के लिए, भारत के FCRA कानून गैर-लाभकारी संस्थाओं में आने वाले विदेशी धन पर निगरानी रखते हैं। लेकिन FCRA कानून

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर लागू नहीं होते, क्योंकि यह व्यावसायिक निवेश के रूप में आता है, न कि परोपकार के रूप में। सामाजिक-राजनीतिक हस्तक्षेपों में व्यावसायिक संस्थाओं का उपयोग उद्देश्यों और गतिविधियों को गुप्त रखने की एक चाल है। अध्याय 22 में हमने देखा कि कैसे ओमिडयार ने चतुराई से वेंचर कैपिटल का उपयोग एक विशाल बुनियादी ढांचा स्थापित करने के साधन के रूप में किया है, जो भारत के सामाजिक और राजनीतिक ताने-बाने को प्रभावित करता है। इनमें से कोई भी गतिविधि FCRA व्यवस्था के दायरे में नहीं आती।

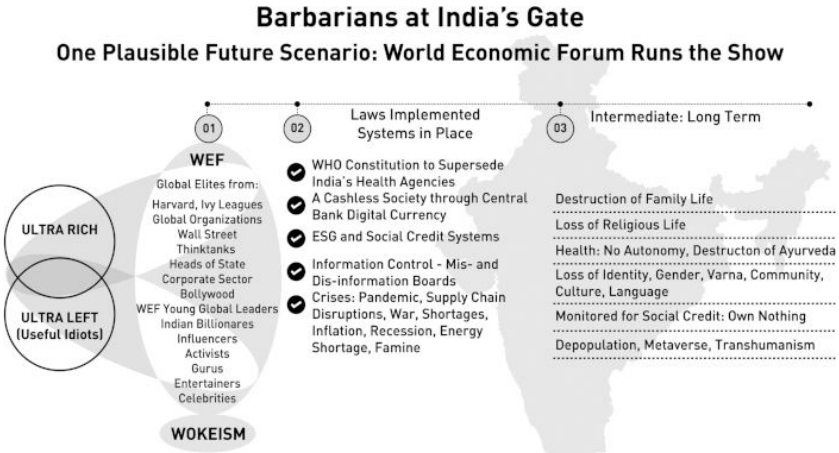

जनता को इस भ्रम में डाला जा रहा है कि वैश्विक अभिजात वर्ग अचानक उदार और निस्वार्थ हो गया है। सच्चाई यह है कि वे धन और शक्ति के और भी अधिक केंद्रीकरण के लिए खुद को पुनर्गठित कर रहे हैं। सरकार और सामाजिक निगरानी से बचने के लक्ष्य के अलावा, विदेशी गठबंधन एक और बाधा को दूर करना चाहते हैं, जो कि समाज की पुरानी संरचनाएं हैं जो विश्व भर के हर समाज में गहराई से जड़ें जमा चुकी हैं। हमने समझाया कि किसी भी नई व्यवस्था के लिए जगह बनाने के लिए इन्हें ध्वस्त करना आवश्यक है। यहीं पर वोकिज़्म एक विनाशकारी शक्ति

के रूप में उपयोगी साबित होता है, और इसीलिए कई अरबपतियों का समर्थन प्राप्त है। हमारा तर्क है कि सत्ता और दमन के पदानुक्रम को हटाने के बजाय, नई विश्व व्यवस्था अपनी ही तरह की डिजिटल जाति व्यवस्था लागू करेगी।

वोकिज़्म जनमानस के गुस्से को लक्षित उत्पीड़कों की सूची के विरुद्ध मोड़ रहा है, और उत्पीड़ितों को आकर्षक रोज़गार, धन का पुनर्वितरण और यहाँ तक कि मुआवज़े का वादा किया जा रहा है। कुछ कार्यकर्ता बिचौलिए के रूप में सफल हो जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कुछ अफ़्रीकी दास व्यापार में शामिल होकर अपने साथी अफ़्रीकियों को बेच देते थे, और जैसे भारतीय ज़मींदार, बाबू और सिपाही बनकर अंग्रेजों को अपना साम्राज्य बनाए रखने में मदद करते थे। पीड़ितों के रूप में लामबंद किए गए लोगों का एक बड़ा हिस्सा एक ऐसे खेल में महज़ मोहरे हैं जिसे वे पूरी तरह से समझ नहीं पाते। अगले पृष्ठ पर दिया गया चित्र वोकिज़्म की विनाशकारी भूमिका को दर्शाता है।

यह चित्र नई पदानुक्रमित संरचनाओं के निर्माण के लिए निम्नलिखित दो प्रक्रियाओं को भी दर्शाता है:

कंपनियों के स्तर पर, पर्यावरण, समाज और शासन पर पड़ने वाले प्रभाव के मापदंड के आधार पर अच्छे कॉर्पोरेट नागरिक व्यवहार को पुरस्कृत करने की एक नई प्रणाली लागू की गई है। यह वैश्विक व्यवस्था के रणनीतिकारों द्वारा स्थापित किए जा रहे नए नियमों के अनुरूप कंपनियों के लिए एक सामाजिक ऋण प्रणाली के समान है।

व्यक्तिगत स्तर पर, प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार की निगरानी डिजिटल पहचान और निगरानी के माध्यम से की जाएगी, और व्यक्तियों के लिए एक सामाजिक क्रेडिट प्रणाली का उपयोग करके लगातार प्रबंधित किया जाएगा।

संगठनात्मक और व्यक्तिगत दबाव डालने के तरीकों का यह संयोजन समाज के व्यवहार को नियंत्रित करेगा, जिससे कुछ व्यक्तियों और कंपनियों को इस नए खेल में प्रतिस्पर्धा करने और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

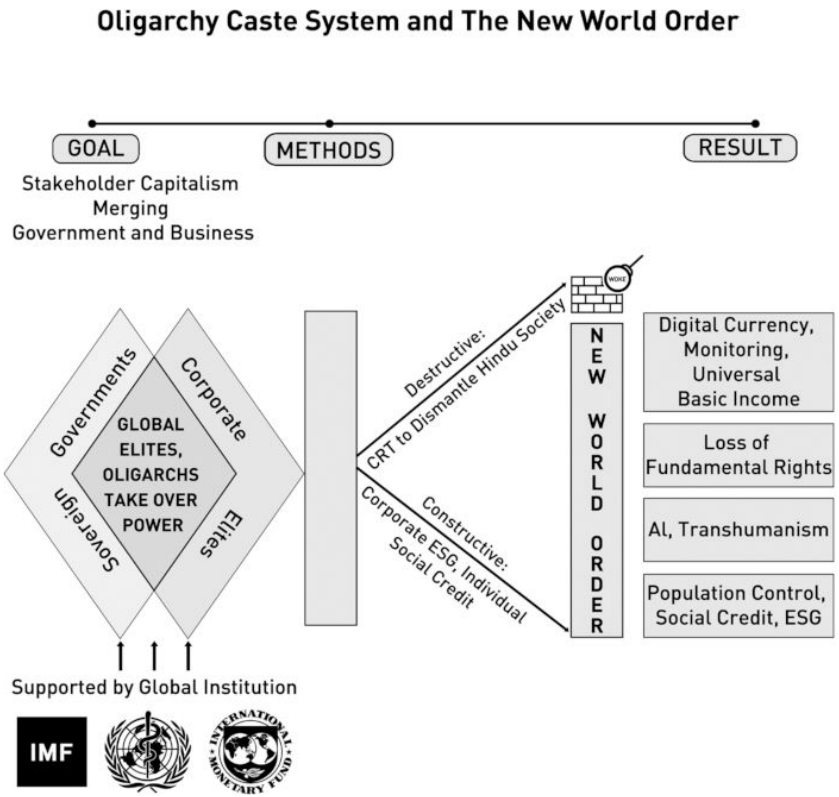

हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि ये वैश्विक अभिजात वर्ग कौन हैं और उनके अपने शब्दों और कार्यों का उपयोग करके चल रही क्रांति को समझाएंगे। भाग 2 में, हमने दिखाया कि कैसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय एक सुनियोजित योजना के साथ एक कुशल कठपुतली नचाने वाले की तरह काम करने के लिए विद्वता का विकास कर रहा है। यह सत्य की खोज से नहीं, बल्कि सत्ता की खोज से प्रेरित है। हमने यह भी देखा कि कुछ

भारतीय अरबपति हार्वर्ड के कनिष्ठ साझेदार के रूप में मिलीभगत कर रहे हैं। इस पुस्तक का एक प्रमुख उद्देश्य इस साझेदारी के पाखंड को उजागर करना है।

पहले से ही, वैश्विक अभिजात वर्ग का एक समूह अपनी विशाल संपत्ति का उपयोग केंद्रीय बैंकों, कई सरकारी निकायों और कॉरपोरेट क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए कर रहा है। वे अपने स्वामित्व वाले मीडिया संस्थानों के माध्यम से सार्वजनिक चर्चा और चुनाव परिणामों को नियंत्रित कर सकते हैं। यहां तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी वैश्विक संस्थाएं भी बिल गेट्स जैसे कुलीन वर्ग से प्रभावित हैं। निम्नलिखित चित्र सत्ता के इस केंद्रीकरण की सीमा को दर्शाता है।

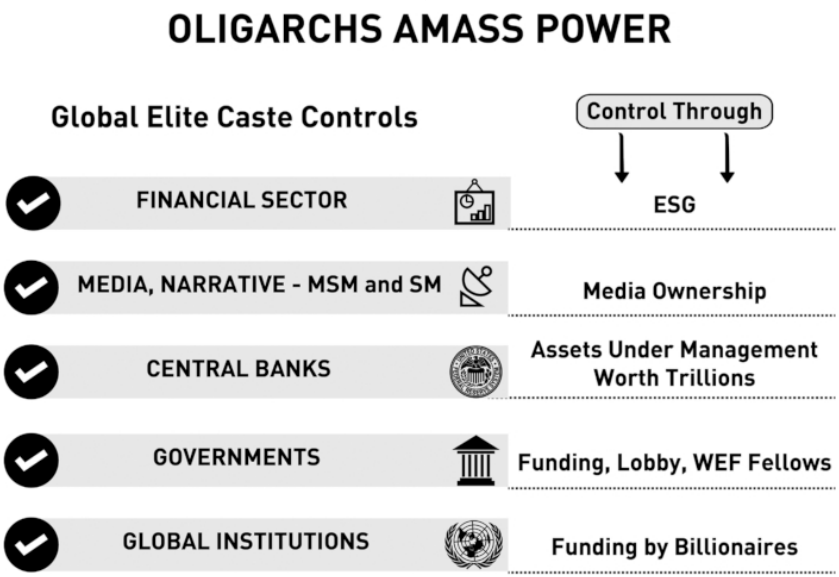

दावोस देवतस: क्लाउस श्वाब और विश्व आर्थिक मंच

हार्वर्ड विश्वविद्यालय का प्रभाव और शक्ति उसके अकादमिक परिसरों से कहीं अधिक व्यापक है। हम इसे हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के पूर्व छात्र और पूर्व

अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर के शिष्य, टेक्नोक्रेट क्लाउस श्वाब के नेतृत्व में डब्ल्यूईएफ द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका को समझाकर प्रदर्शित करेंगे। श्वाब निक्सन और फोर्ड के कार्यकाल में सेवा दे चुके हैं। डब्ल्यूईएफ कई मायनों में हार्वर्ड का ही एक हिस्सा है जो सभी नियंत्रणों से परे काम करता है और किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। संयुक्त राष्ट्र, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, विश्व बैंक और डब्ल्यूएचओ जैसे अन्य बहुपक्षीय संगठनों की तरह इसकी निगरानी नहीं की जाती है, न ही यह रेड क्रॉस, एमनेस्टी इंटरनेशनल आदि की तरह सार्वजनिक दान संस्थाओं की तरह जांच के दायरे में आता है।

क्लाउस श्वाब की ताकत उनके द्वारा स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होने वाले भव्य वैश्विक शिखर सम्मेलन से आती है, जिसमें केवल आमंत्रित लोग ही शामिल हो सकते हैं। यह शिखर सम्मेलन शिक्षाविदों, निगमों, सरकारों, कलाकारों, राजपरिवार के सदस्यों, मशहूर हस्तियों, कार्यकर्ताओं और हर तरह की सार्वजनिक हस्तियों को एक सुविचारित विश्वदृष्टि में शामिल होने के लिए एक साथ लाता है। इस नेटवर्किंग प्रभाव के माध्यम से, WEF ने अधिकांश सरकारों, व्यवसायों और गैर-सरकारी संगठनों में अपनी पैठ बना ली है।

आज, श्वाब का विश्व आर्थिक मंच दुनिया भर के सबसे धनी और सबसे शक्तिशाली लोगों का एक समूह है। उनके समूह के सदस्यों और भागीदारों में कुछ समानताएं हैं:

इनमें से अधिकांश बेहद धनी हैं और/या शक्तिशाली पदों पर आसीन हैं। ये सभी अपने-अपने तरीके से विश्व प्रभुत्व स्थापित करने का सपना देखते हैं।

‘सतत विकास’ की खोज में बाकी सभी लोग उपेक्षित हैं।

मार्क्सवादी क्रांति, सामाजिक न्याय के आवरण में छिपी हुई, उनके

परिवर्तन की विधि है।
एक विश्व व्यवस्था उनका लक्ष्य है।
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी तरीके का इस्तेमाल जायज है।
महत्वपूर्ण बात यह है: भले ही लोग विविध हों, लेकिन विचार-विमर्श एक जैसा है। सभी विचार पश्चिमी सार्वभौमिक मूल्यों के ढांचे में समाहित हैं। इसमें पर्यावरणवाद पर मूल अमेरिकी दृष्टिकोण, समाज पर इस्लामी दृष्टिकोण, शासन पर कन्फ्यूशियस दृष्टिकोण या नैतिकता पर हिंदू दृष्टिकोण नहीं मिलता।
श्वाब लंबे समय से डब्ल्यूईएफ मिशन पर काम कर रहे हैं:
श्वाब ने हार्वर्ड के जॉन एफ. कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट (1966-67) में अध्ययन किया, जहाँ उन्होंने लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री प्राप्त की। उन्होंने कई प्रख्यात हस्तियों से मित्रता विकसित की, जिनमें अर्थशास्त्री जॉन केनेथ गैलब्रेथ और रियलपॉलिटिक के जनक हेनरी किसिंजर शामिल थे। निक्सन और फोर्ड प्रशासन में आक्रामक विदेश मंत्री रहे किसिंजर के साथ श्वाब का रिश्ता मात्र अनौपचारिक नहीं था। श्वाब ने इसे "50 साल लंबी मेंटरशिप" बताया, जिससे आज भी उन्हें लाभ मिल रहा है।
जैसा कि पत्रकार अन्र्स्ट वोल्फ बताते हैं, "हार्वर्ड बिजनेस स्कूल अपने स्वयं के एक प्रबंधन मंच की योजना बना रहा था, और यह संभव है कि हार्वर्ड ने अंततः इसे आयोजित करने का कार्य उन्हें [अर्थात, श्वाब को] सौंप दिया हो।"
अब जबकि क्लाउस श्वाब और डब्ल्यूईएफ ने अपने बहुप्रतीक्षित तकनीकी राज्य की रूपरेखा तैयार कर ली है, एक महत्वपूर्ण बात अभी भी बाकी है, और वह यह सुनिश्चित करना है कि इस संदेश के प्रति सहानुभूति रखने वाले नेता सत्ता में हों ताकि इसे साकार किया जा सके।
दावोस को सफलतापूर्वक एक ऐसे मंच में बदल दिया गया है जो एक

विशिष्ट मूलभूत विश्वदृष्टि को सुदृढ़ करता है। विश्व आर्थिक संगठन (WEF) द्वारा गढ़े गए वाक्यांशों को लोकप्रिय बनाने के लिए सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्राध्यक्ष 'बिल्ड रिबैक बेटर' और 'प्राइवेट-पब्लिक पार्टनरशिप' जैसी WEF शब्दावली का उपयोग करते हैं, और ब्लैक रॉक जैसे कॉर्पोरेट सीईओ 'स्टेकहोल्डर कैपिटलिज्म' का समर्थन करते हैं।

क्लाउस श्वाब वैश्विक स्तर पर जीवन की परिभाषा को बदलने के अपने विचार को छिपाते नहीं हैं। वैश्विक शासन, जनसंख्या और पर्यावरण को नियंत्रित करने के लिए सामाजिक ऋण प्रणाली के उपयोग पर उनके विचार स्पष्ट हैं। यहाँ तक कि वे प्रौद्योगिकी के उपयोग को लेकर भी विचार रखते हैं, जिसे ट्रांसह्यूमनिज़्म कहा जा रहा है।

उनकी सबसे साहसिक अवधारणाओं में से एक यह है कि 'आपके पास कुछ भी नहीं होगा और आप खुश रहेंगे'। दूसरे शब्दों में, आपका जीवन एक सदस्यता मॉडल होगा जिसमें आपकी भागीदारी के स्तर के आधार पर आपको एक निश्चित जीवनशैली पूरी तरह से उपलब्ध कराई जाएगी। इसे एक नए प्रकार की डिजिटल गुलामी के रूप में देखा जा सकता है। मुख्य एजेंडा शेयरधारक पूंजीवाद की जगह हितधारक पूंजीवाद को बढ़ावा देना है, जैसा कि तकनीकी उद्यमी विवेक रामास्वामी ने अध्याय 1 में उद्धृत किया है। क्लाउस श्वाब ने अपनी नई विश्व व्यवस्था पर कोविड-19: द ग्रेट रीसेट नामक पुस्तक में चर्चा की है। उनका कहना है कि 'महामारी ने हमारी दुनिया को फिर से स्थापित करने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान किया है'। ब्रिटिश पत्रकार जेम्स डेलिंगपोल के अनुसार:

जैसा कि अब हर जानकार व्यक्ति जानता है, 'ग्रेट रीसेट' विश्व आर्थिक मंच (और अन्य) की एक भयावह योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य दुनिया को एक विशाल गुलाम राज्य में बदलना है, जहाँ हम सब उनके

अधीन होंगे ('तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा और तुम खुश रहोगे') और दावोस के अभिजात वर्ग हम पर फिरौन या बेबीलोन के राजाओं की तरह शासन करेंगे। लेकिन किसी अजीब कारण से, इस अभिजात वर्ग के आदेशों का पालन करने वाली कठपुतली सरकारें इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करना चाहतीं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WEF) द्वारा प्रशिक्षित कई विश्व नेताओं ने ग्रेट रीसेट के सिद्धांत का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया है। 2020 में WEF की वार्षिक बैठक के दौरान ग्रेट रीसेट परियोजना के शुभारंभ समारोह में, प्रिंस चार्ल्स ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा:

हमारे पास इस संकट से कुछ सकारात्मक हासिल करने का सुनहरा अवसर है। इसके अभूतपूर्व प्रभाव से लोग बदलाव की बड़ी योजनाओं के प्रति अधिक ग्रहणशील हो सकते हैं।

2020 में संयुक्त राष्ट्र के एक सम्मेलन में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा:

इस महामारी ने नए सिरे से शुरुआत करने का अवसर प्रदान किया है। यह हमारे लिए महामारी से पहले किए गए प्रयासों को गति देने, आर्थिक प्रणालियों की पुनर्कल्पना करने का मौका है जो वास्तव में अत्यधिक गरीबी, असमानता और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करती हैं।

मुख्य रणनीति संकटों को अवसरों के रूप में उपयोग करना है ताकि जनता को ऐसे व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए प्रेरित किया जा सके जो सामान्यतः अलोकप्रिय होते हैं, जिससे नई प्रौद्योगिकियों और नई पदानुक्रमित संरचनाओं पर उनकी निर्भरता बढ़ जाती है।

विघटन प्रक्रिया

एक नई व्यवस्था बनाने के लिए, क्रिटिकल रेस थ्योरी और इसके लोकप्रिय संस्करण, वोकिज़्म जैसे विचारों का उपयोग मौजूदा संरचनाओं, प्रणालियों और संस्थानों को नष्ट करने के लिए किया जा रहा है। फरवरी 2022 में, WEF ने "क्रिटिकल रेस थ्योरी के बारे में आपको यह जानना चाहिए" शीर्षक से एक प्रचार वीडियो जारी किया। WEF का लक्ष्य क्रिटिकल रेस थ्योरी का उपयोग करके समाज में दरारें बढ़ाना और दुनिया को स्टेकहोल्डर कैपिटलिज़्म और द ग्रेट रीसेट की ओर ले जाना है।
विश्व आर्थिक संगठन (WEF) वोकिज़्म के मूल सिद्धांत, समानता के बजाय निष्पक्षता को बढ़ावा दे रहा है। निष्पक्षता से मेहनत और योग्यता का हनन होगा और इस प्रकार एक औसत दर्जे का समाज बनेगा। इससे प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी और विशेषाधिकार प्राप्त कुलीन वर्ग के लिए शासन करना आसान हो जाएगा। निष्पक्षता का वादा करके जनता की पीड़ित भावना का फायदा उठाया जाता है और उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि अतीत में हुए अन्याय के मुआवजे के रूप में वे हर तरह के लाभ के हकदार हैं। निष्पक्षता एक मार्क्सवादी हथियार है जिसका इस्तेमाल जनता को एक समरूप गुलामों के समूह में बदलने के लिए किया जा रहा है। हमने पिछले अध्यायों में देखा कि वोकिज़्म पारिवारिक संरचनाओं और सामाजिक संबंधों को भी तोड़ना चाहता है - कुलीन वर्ग को इससे फायदा होता है क्योंकि ऐसी संरचनाओं को नष्ट करने से समाज कमजोर हो जाता है और इसलिए उनके लिए शासन करना आसान हो जाता है।
महामारी के दौरान धन के पुनर्वितरण की एक झलक हमें देखने को मिली, जब बड़ी तकनीकी कंपनियाँ और भी अधिक समृद्ध हो गईं। जनता ने डर के मारे कई बदलावों को स्वीकार कर लिया – जैसे कि डिजिटल आईडी, निजी डेटा का उपयोग आदि। इसी तरह, हम विश्वव्यापी

बेरोजगारी में अचानक वृद्धि देख सकते हैं, जो सार्वभौमिक बुनियादी आय (यूबीआई) को लागू करने का एक अवसर बन जाएगी, जो जनता को नियंत्रित करने का एक और तंत्र है। इसे मानवता के प्रति वास्तविक चिंता के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूईएफ) की वेबसाइट बताती है कि वह यूबीआई को किस प्रकार प्रस्तुत करता है:
… इस संकट से एक नए सामाजिक अनुबंध का उदय होना चाहिए जो समाजों में व्याप्त गहरी असमानताओं को संतुलित करे। … सवाल अब यह नहीं होना चाहिए कि प्रभावी सामाजिक सुरक्षा के लिए संसाधन मिल सकते हैं या नहीं, बल्कि यह होना चाहिए कि वे कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। सार्वभौमिक बुनियादी ढांचा (UBI) इस तरह के ढांचे का एक उपयोगी तत्व साबित हो सकता है।
लेकिन इस अचानक दिखाई गई उदारता का असली कारण यह है कि विश्व आर्थिक प्रोत्साहन (डब्ल्यूईएफ) को सार्वभौमिक बुनियादी ढांचे (यूबीआई) के अभाव में बड़े पैमाने पर सामाजिक अशांति का डर है। इसलिए, यूबीआई का उद्देश्य एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करना है जो लोगों को भविष्य में होने वाली वित्तीय विपत्ति से राहत प्रदान करे। सार्वभौमिक बुनियादी ढांचा (UBI) न होने का विकल्प और भी बुरा है – सामाजिक अशांति, संघर्ष, अनियंत्रित जनप्रवासन और चरमपंथी समूहों के प्रसार की बढ़ती संभावना, जो सामाजिक निराशा का फायदा उठाते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं। … हमें एक सुनियोजित UBI को लागू करने पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, ताकि झटके लगें, लेकिन वे विनाशकारी न हों।
यहाँ निर्णायक सबूत है: प्रस्तावित सार्वभौमिक बुनियादी ढांचा (यूबीआई) कुछ शर्तों के साथ आएगा, और इसी तरह अधिक नियंत्रण और शक्ति आम जनता से अभिजात वर्ग के हाथों में स्थानांतरित हो जाएगी। श्वाब

यूबीआई प्राप्त करने के बदले में आम जनता से बिना कहे आज्ञापालन की अपेक्षा करता है:

सार्वभौमिक बुनियादी आय के लिए कुछ चुनिंदा शर्तें रखने के पक्ष में अच्छे तर्क दिए जा सकते हैं – जैसे कि सार्वजनिक हित से संबंधित शर्तें, जैसे सभी बच्चों का टीकाकरण और उनकी स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करना। ऐसी चुनिंदा शर्तें गरीबी उन्मूलन के मुख्य उद्देश्य को कमजोर नहीं करेंगी और कम आय वाले लोगों को सोच-समझकर जोखिम उठाने और गरीबी से बाहर निकलने का प्रयास करने की अनुमति देंगी।

धीरे-धीरे, आम जनता जीवित रहने के लिए सार्वभौमिक बुनियादी ढांचे (UBI) पर निर्भर हो जाएगी, जिससे वे आज्ञाकारी बन जाएंगे, जबकि वैश्विक अभिजात वर्ग कुलीनतंत्र में परिवर्तित हो जाएगा।

एक बार आय पर केंद्रीय नियंत्रण स्थापित हो जाने पर, इसका उपयोग व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। कंपनियां हितधारक पूंजीवाद के माध्यम से इसमें भूमिका निभाएंगी, जो कंपनियों का मूल्यांकन केवल लाभ के आधार पर नहीं बल्कि उनके सामाजिक प्रभाव (अर्थात ESG रेटिंग) के आधार पर करने का एक तरीका है। विश्व आर्थिक संगठन (WEF) इसे दुनिया को पुनर्गठित करने और धन के पुनर्वितरण के एक तरीके के रूप में बढ़ावा दे रहा है। पर्यावरण, सामाजिक न्याय और शासन हितधारक पूंजीवाद के स्तंभ हैं, और कंपनियों की रेटिंग यह निर्धारित करेगी कि व्यवसाय कैसे संचालित होंगे और किसे वित्त पोषण मिलेगा।

लेकिन सवाल यह है कि ESG प्रणाली के तहत रेटिंग के मानदंड कौन तय कर रहा है? जवाब: बड़े बैंक, बड़ी परामर्श और वित्तीय संस्थाएं, कुछ निगम, सरकारें और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी – ये सभी विश्व आर्थिक मंच के टास्क फोर्स के तत्वावधान में काम कर रहे हैं। लेकिन इससे हितों

का गंभीर टकराव पैदा होता है क्योंकि वैश्विक अभिजात वर्ग ही उस मूल्य प्रणाली को निर्धारित कर रहा है जिसके आधार पर कॉर्पोरेट सामाजिक ऋण का प्रबंधन किया जाएगा।

हितों के टकराव के बावजूद, ESG हितधारक पूंजीवाद प्रणाली लोकप्रिय हो गई है क्योंकि केंद्रीय बैंकों, सरकारों और धनी निवेशकों ने ESG फंडिंग में खरबों डॉलर का निवेश किया है। जो बाइडेन की अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी सरकार द्वारा समर्थित समूह, ग्लासगो फाइनेंशियल एलायंस फॉर नेट ज़ीरो (GFANZ) का दावा है कि उसके सदस्यों में 'दर्जनों देशों के 450 से अधिक बैंक, बीमा कंपनियां और अन्य परिसंपत्ति प्रबंधक' शामिल हैं। GFANZ के सदस्यों ने मिलकर 130 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति का निवेश करने का वादा किया है।

इससे WEF और उसके सहयोगी नए तानाशाह बन गए हैं। नियमों का पालन न करने वाले किसी भी व्यक्ति पर बहिष्कार की नीतियां लागू की जाएंगी – यह संस्थानों पर लागू की गई एक प्रकार की 'कैंसल कल्चर' है। इसलिए, हर कंपनी नियमों का पालन करने के लिए तैयार हो रही है।

श्वाब के अनुसार, दुनिया को एक तकनीकी अभिजात वर्ग की योजनाओं के अनुसार तेजी से रूपांतरित किया जाना चाहिए, और "हमें" पुस्तक के लिए साक्षात्कार किए गए 50 चुनिंदा "कथाकारों" के विचारों और नीतिगत प्राथमिकताओं को अपनाना चाहिए, जिन्हें वे "वैश्विक विचारक और सार्वजनिक बुद्धिजीवी" के रूप में वर्णित करते हैं।

क्लाउस श्वाब में एक अविश्वसनीय ईश्वर-प्रेम की भावना है, और वह अक्सर पाठक को अपनी असीमित तकनीकी क्षमताओं की याद दिलाता रहता है। वह नियमित रूप से यह प्रकट करता है कि उसका मानना है कि उसके सहयोगियों के समूह में ईश्वरीय शक्तियां हैं, और एक बार जब वे अपनी समग्र विशेषज्ञता को एकजुट कर लेंगे, तो ये प्रौद्योगिकीविद, हम

सभी के प्रभारी बनने पर, अभूतपूर्व सुख और व्यवस्था ला सकते हैं। ईएसजी प्रणाली को गरीबी उन्मूलन, असमानता को दूर करने और नियंत्रण और प्रौद्योगिकी के माध्यम से पहुंच में सुधार करने के एक तरीके के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है।

क्लाउस श्वाब एक कॉमिक बुक खलनायक हैं, और अपनी पुस्तक "द ग्रेट नैरेटिव" में वे विश्व आर्थिक मंच के सचमुच पागलपन भरे, चरमपंथी एजेंडे का पर्दाफाश करते हैं, जो अपने दावोस मंच के माध्यम से शासक वर्ग के लिए नीति और विचारों का प्रमुख स्रोत है। इस पुस्तक को पढ़ना इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि आप उन "महान कथाओं" से अवगत हो सकें जो जल्द ही वैश्विक अभिजात वर्ग से उभरेंगी। इस दुनिया में शायद ही कभी आपको इतनी वास्तविक, स्पष्ट बुराई देखने को मिलती है। क्लाउस और विश्व आर्थिक मंच, "जलवायु आपातकाल" के बहाने हमारी स्वतंत्रता को ट्रोजन हॉर्स की तरह छीनने के प्रयास के माध्यम से, इस श्रेणी में पूरी तरह फिट बैठते हैं।

इसका उद्देश्य स्थापित ढाँचों को ध्वस्त करने के लिए वोकिज़्म को एक उपकरण के रूप में उपयोग करना और हितधारक पूंजीवाद के लिए जन समर्थन प्राप्त करने हेतु यूबीआई जैसे प्रलोभनों का इस्तेमाल करना है। ईएसजी रेटिंग कंपनियों को नियंत्रित और निगरानी करेंगी। डब्ल्यूईएफ ने महामारी में कॉर्पोरेट ईएसजी रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाने का अवसर देखा और अपने ईएसजी ढांचे को बढ़ावा देने, लागू करने और अंततः अनिवार्य करने के लिए डेलॉइट, ईवाई, केपीएमजी और पीडब्ल्यूसी जैसी प्रमुख लेखा फर्मों के साथ साझेदारी की है।

एक मजबूत व्यवसाय का निर्माण तेजी से गैर-वित्तीय कारकों के प्रभाव के लिए तैयारी पर निर्भर करता है, जिसमें ESG से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं। जैसा कि हम COVID-19 के वर्तमान व्यावसायिक प्रभावों

से देख रहे हैं, कंपनियां पहले से ही वित्तीय रूप से महत्वपूर्ण व्यावसायिक कारकों से निपट रही हैं जो अचानक उत्पन्न हो सकते हैं। आने वाले दशक में सफल होने के लिए, निवेशकों और कंपनियों को महत्वपूर्णता के प्रति दूरदर्शी और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना होगा।

वैनगार्ड ग्रुप, स्टेट स्ट्रीट और ब्लैक रॉक तीन सबसे बड़े संस्थागत निवेशक हैं जो लगभग सभी उद्योगों की सभी प्रमुख कंपनियों के मालिक हैं: फार्मास्युटिकल, उपभोक्ता वस्तुएं, कृषि, खनन, ऑटोमोटिव, ऊर्जा, रक्षा और निश्चित रूप से, बड़ी टेक कंपनियां। ब्लूमबर्ग ने "ब्लैक रॉक और वैनगार्ड 20 ट्रिलियन डॉलर का प्रबंधन करने से एक दशक से भी कम दूर हैं - निवेश के भविष्य पर दो शक्तिशाली दिग्गज हावी हो रहे हैं" शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। [19]

ब्लूमबर्ग तो यहाँ तक कहता है कि ब्लैक रॉक सरकार की चौथी शाखा है जिसके अमेरिकी और यूरोपीय संघ के केंद्रीय बैंकों से मजबूत संबंध हैं। फिंक के पास एक ऐसी शक्ति है जो अधिक तकनीकी है। ब्लैक रॉक, दुनिया की सबसे बड़ी मुद्रा प्रबंधक कंपनी, सरकारों को अभी जिन चीजों की आवश्यकता है, उन्हें कर सकती है।

ब्लैकरॉक द्वारा व्यापार जगत में वोकवाद का प्रसार गंभीर है क्योंकि ब्लैकरॉक और उससे जुड़े कुछ गिने-चुने कुलीन वर्ग लगभग सभी प्रमुख कंपनियों के मालिक हैं। ब्लैकरॉक वर्ल्ड इकोनॉमिक फाउंडेशन (WEF) का भागीदार है और उसने ईएसजी को अनिवार्य बनाने के अभियान के तहत एक स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म सेंटर की स्थापना की है, जिसके लिए वह अपने दस ट्रिलियन डॉलर के परिसंपत्ति आधार का व्यापक रूप से उपयोग कर रहा है।

हालांकि ब्लैक रॉक अपने इंडेक्स फंड में शामिल कंपनियों से विनिवेश नहीं कर सकता, लेकिन फिंक ने स्पष्ट किया है कि जब कंपनियां स्थिरता

संबंधी खुलासों और उनसे संबंधित व्यावसायिक प्रथाओं और योजनाओं में पर्याप्त प्रगति नहीं कर रही होंगी, तो वे प्रबंधन और बोर्ड निदेशकों के खिलाफ मतदान करने के लिए अधिक तत्पर होंगे।

विश्व आर्थिक मंच वेंचर कैपिटल जगत में भी ESG को ला रहा है, जिससे कंपनियों को केवल उन्हीं स्टार्ट-अप्स में निवेश करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जो ESG के अनुरूप हैं। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि यह वेंचर कैपिटलिस्टों से मानवाधिकार रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों का उपयोग करने की अपेक्षा करता है। यह कहता है कि

एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में मानवाधिकार संबंधी उचित परिश्रम में वेंचर कैपिटल फर्मों की विफलता को उजागर किया गया है, जो यह दर्शाता है कि निवेश प्रक्रियाओं में [ESG] संबंधी विचारों को शामिल करने के मामले में वेंचर कैपिटल पिछड़ गया है।

इस तरह, जागरूक वर्ग एक सहयोगी बन जाता है क्योंकि उसे पूंजीवादी उद्यमों के मूल्यांकन के लिए निर्णायक की भूमिका निभाने का अधिकार मिल जाता है। यह मानना सुरक्षित है कि ESG कार्यक्रम के माध्यम से कंपनियों पर लागू मानदंड और व्यक्तियों पर लागू सामाजिक साख प्रणाली स्कोरकार्ड, सामाजिक न्याय, पर्यावरण अनुपालन और शासन के संबंध में पश्चिमी सामाजिक विज्ञान के विचारों पर आधारित होंगे।

दिलचस्प बात यह है कि जब ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक को स्टेकहोल्डर कैपिटलिज्म अपनाने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा, तो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित सामाजिक प्रभाव परामर्श फर्म के एक लेखक के लेख के माध्यम से तुरंत उनका बचाव किया। इसमें कहा गया है:

फिंक जैसे नेताओं को उनके व्यवसायों पर व्यक्तिगत एजेंडा थोपने के

लिए दोषी ठहराने के बजाय, हमें उन सीईओ की निंदा करनी चाहिए जो सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखने में विफल रहते हैं और परिणामस्वरूप, अपने शेयरधारकों के रिटर्न को नुकसान पहुंचाते हैं। धन और राजनीति के मेल से सत्ता का यह केंद्रीकरण, विभिन्न संस्कृतियों में विचारों और मूल्यों की विविधता को नकारता है। उदाहरण के लिए, भारत की संस्कृति, डब्ल्यूईएफ और उसके सहयोगियों द्वारा प्रतिपादित हितधारकों की अच्छी मूल्यों की परिभाषाओं के साथ मेल नहीं खा सकती है।

व्यक्तियों के लिए नियंत्रण तंत्र के रूप में डिजिटल पहचान
जैसा कि हम देख रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WEF) ने प्रौद्योगिकी की मदद से कठोर उपायों का इस्तेमाल करते हुए मानवता को अभूतपूर्व पैमाने पर नियंत्रित करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। जिस प्रकार ESG निगमों के व्यवहार को नियंत्रित करने का एक तरीका है, उसी प्रकार व्यक्तियों को डिजिटल आईडी और डिजिटल मुद्रा के माध्यम से नियंत्रित किया जाएगा, जो उन्हें अभिजात वर्ग द्वारा निर्धारित 'अच्छे व्यवहार' के लिए अर्जित सामाजिक साख के आधार पर पुरस्कृत करेगी। हमने महामारी के दौरान इसका उदाहरण देखा, जब गरीबों को टीकाकरण से इनकार करने पर राशन नहीं दिया गया। यह तो बस शुरुआत है!
विश्व वित्तीय आयोग (WEF) लेन-देन को सुगम बनाने के स्पष्ट उद्देश्य से डिजिटल आईडी अवसंरचना को बढ़ावा दे रहा है। इसने इस संबंध में कई श्वेत पत्र प्रकाशित किए हैं, उदाहरण के लिए, "कोविड-19 के बाद की दुनिया में डिजिटल पहचान कैसे जीवन को बेहतर बना सकती है" और "डिजिटल पहचान समावेशी वित्तीय सेवाओं को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है"। यह भारत द्वारा इस दिशा में कदम उठाने की सराहना करता

है।

भारत की आधार प्रणाली 12 लाख से अधिक भारतीयों के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ाती है। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री पॉल रोमर इसे दुनिया की सबसे परिष्कृत डिजिटल पहचान प्रणाली कहते हैं। चूंकि वैश्विक स्तर पर एक अरब लोग वर्तमान में पहचान के औपचारिक प्रमाण से वंचित हैं, इसलिए अन्य सरकारों को सेवाओं और भुगतानों की सुगमता बढ़ाने और वित्तीय समावेशन को व्यापक रूप से बढ़ाने के लिए ऐसी प्रणाली का उपयोग करना चाहिए।

भारत आधार कार्ड आईडी में निर्मित निगरानी प्रणाली का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। आधार दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक आईडी प्रणाली है, जिसमें 1.1 अरब लोग रेटिना स्कैन और फिंगरप्रिंट डेटा के साथ पंजीकृत हैं। बिल गेट्स ने इसकी प्रशंसा की है। आधार एक सरकारी आईडी के रूप में कार्य करता है जिसे सरकारी सेवाओं, यात्रा, बैंकिंग आदि के लिए स्वीकार किया जाता है। कोविड-19 टीकों के लॉन्च के साथ, आधार प्रदान करने वाले रोगियों को सरकार द्वारा निर्मित और अनुरक्षित एक विशिष्ट स्वास्थ्य आईडी दी गई थी। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि यह सूचित सहमति से किया गया था या नहीं। अक्टूबर 2021 में, इस कार्यक्रम को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से अनुदान प्राप्त हुआ।

भारत की बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल आईडी वाली सामाजिक क्रेडिट प्रणाली की तरह, पश्चिमी दुनिया भी वैक्सीन पासपोर्ट को डिजिटल आईडी के रूप में इस्तेमाल करने पर काम कर रही है। विश्व बैंक और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने इंफोसिस के सह-संस्थापक और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के पूर्व अध्यक्ष नंदन नीलेकानी के साथ मिलकर अन्य देशों में भी इसी तरह की डिजिटल आईडी विकसित

करने के लिए साझेदारी की है। यह दिलचस्प बात है कि नीलेकानी पिछले बीस वर्षों से विश्व आर्थिक आंदोलन (WEF) के आयोजनों में एजेंडा तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं। हम मानव जाति के भविष्य के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम ऐसी प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमारे जीवन पर 'बिग ब्रदर' जैसे नियंत्रण पर सवाल उठाते हैं।

डिजिटल आईडी को साइबर सुरक्षा और लेन-देन के प्रमाणीकरण में सुधार के एक तरीके के रूप में उचित ठहराया जाएगा। हालांकि, इस प्रणाली का इस्तेमाल असहमति या विचारों की अभिव्यक्ति को दबाने के लिए भी किया जा सकता है। ट्रक चालकों के काफिले का समर्थन करने वाले नागरिकों के बैंक खातों का पता लगाने और उन्हें फ्रीज करने के लिए कनाडा सरकार द्वारा की गई दंडात्मक कार्रवाई में यह स्पष्ट हो गया। "एडवांसिंग डिजिटल एजेंसी: द पावर ऑफ डेटा इंटरमीडियरीज" शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में, विश्व वित्तीय मंत्रालय (WEF) ने क्रेडिट, चिकित्सा इतिहास, सोशल मीडिया और ऑनलाइन खरीदारी व्यवहार जैसे रोजमर्रा के लेन-देन पर डेटा एकत्र करने के लिए डिजिटल आईडी के उपयोग का प्रस्ताव दिया, और इस डेटा का उपयोग "प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं, प्रोफाइल और इतिहास के आधार पर निर्णय लेने (जैसे कि एक बैंक किसी व्यक्ति के लिए ऋण की उपयुक्तता का निर्णय करता है)" या "यात्राएं बुक करने, देशों या क्षेत्रों के बीच सीमा नियंत्रण से गुजरने, मतदान करने और कर दाखिल करने" के लिए किया जा सकता है।

संकट की स्थिति में, जीवित रहने के लिए लोग बिना सवाल पूछे कठोर उपायों का आसानी से पालन कर लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूईएफ) ऐसे अवसरों का फायदा उठा रहा है।

कोविड-19 महामारी ने चिकित्सा डेटा, विशेष रूप से तथाकथित वैक्सीन

पासपोर्ट की शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया है। ये पासपोर्ट स्वाभाविक रूप से डिजिटल पहचान के एक रूप के रूप में कार्य करते हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूईएफ) संवेदनशील डेटा एकत्र करने के लिए वैक्सीन पासपोर्ट के उपयोग की सराहना करता है और सुझाव देता है कि इस डेटा का पुन: उपयोग सहमति के साथ या बिना सहमति के किया जा सकता है। यह स्पष्ट रूप से आक्रामक डिजिटल आईडी को साधन के रूप में उपयोग करके दुनिया भर में एक सामाजिक क्रेडिट प्रणाली का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। यह 'सूचना और सहमति की सीमाओं को दूर करने के लिए डेटा मध्यस्थ का उपयोग' करने का सुझाव देता है। यह प्रस्ताव करता है कि एकत्रित डेटा का उपयोग ऋण पात्रता जैसी चीजों के लिए निर्णय लेने में किया जा सकता है।

भारतीय व्यवसाय एक नए धर्म के प्रचारक बन रहे हैं
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WEF) ने एक और बड़ी पहल को जन्म दिया है जिसे धार्मिक स्वतंत्रता और व्यापार फाउंडेशन (RFBF) कहा जाता है, जिसका नेतृत्व WEF के एक पूर्व अधिकारी कर रहे हैं। यह संगठन व्यापार में आस्था और मानवाधिकारों से संबंधित मामलों से निपटता है और इसने प्रमुख बहुराष्ट्रीय निगमों के भीतर आस्था-आधारित शाखाओं का एक नेटवर्क स्थापित किया है। इसने समान विचारधारा वाले संगठनों के एक बड़े समूह से धन और समर्थन प्राप्त किया है।
आरएफबीएफ भारत द्वारा विदेशी धर्म प्रचार प्रयासों पर लगाए जा रहे कड़े प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए व्यवसायों को आड़ के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) के साथ मिलकर काम करते हुए, आरएफबीएफ ने धार्मिक स्वतंत्रता पर 2021 की एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत

को धर्म पर सरकारी प्रतिबंधों के लिए 0 से 10 के पैमाने पर 5.12 अंक दिए गए हैं। भारत को धर्म से संबंधित सामाजिक शत्रुता के लिए भी 0 से 7 के पैमाने पर (उच्चतम से निम्नतम) 5.74 अंक मिले हैं, जबकि पाकिस्तान को 6.06 और चीन को मात्र 1.70 अंक मिले हैं। यह स्पष्ट है कि डब्ल्यूईएफ और उसके सहयोगी संगठन एक ऐसी समस्या खड़ी कर रहे हैं जो वास्तव में मौजूद ही नहीं है।

आरएफबीएफ धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति प्रत्येक व्यावसायिक इकाई की प्रतिबद्धता को मापने के लिए अपना स्वयं का सूचकांक विकसित कर रहा है। रणनीति यह है कि इस सूचकांक को एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत रेटिंग प्रणाली के रूप में स्थापित किया जाए, जिसका उपयोग ईएसजी रेटिंग के पूरक के रूप में किया जा सके।

कॉर्पोरेट धार्मिक समानता, विविधता और समावेशन (REDI) सूचकांक, किसी कंपनी की समग्र विविधता पहलों में धर्म को शामिल करने की प्रतिबद्धता का एक मानक माप है।

स्पष्ट है कि ऐसे सूचकांक को नियंत्रित करने में बहुत शक्ति निहित है।

भविष्य के विश्व नेताओं का प्रशिक्षण

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) निजी-सार्वजनिक साझेदारी को बढ़ावा दे रहा है जिसमें निगम दक्षता के नाम पर सरकार के कई कार्यों को अपने हाथ में ले लेते हैं। सरकारों में घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए, डब्ल्यूईएफ दुनिया भर में व्यापारिक नेताओं और राजनेताओं को प्रशिक्षित कर रहा है। श्वाब इस पर गर्व करता है:

अब हमें जिस बात पर सबसे ज्यादा गर्व है, वह यह है कि प्रधानमंत्री ट्रूडो, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति आदि जैसी युवा पीढ़ी मंत्रिमंडलों में अपनी जगह बना रही है। कल मैं प्रधानमंत्री ट्रूडो के स्वागत समारोह में था और मुझे

पता है कि उनके मंत्रिमंडल के आधे से भी ज्यादा सदस्य हमारे, दरअसल, WEF के युवा वैश्विक नेताओं में से हैं। [...] यह अर्जेंटीना में सच है, अब फ्रांस में भी सच है, जहां राष्ट्रपति [मैक्रोन] एक युवा वैश्विक नेता हैं... [46]

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूईएफ) का यंग ग्लोबल लीडर्स प्रोग्राम चालीस वर्ष से कम आयु के उच्च क्षमता वाले व्यक्तियों की भर्ती करके अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए बनाया गया है। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल दानदाताओं में से एक है। चयन प्रक्रिया बहुत कठिन है, और इस विशिष्ट क्लब में नामांकित होना नेताओं के लिए सम्मान की बात है। इस सूची में शाही परिवार के सदस्य, राजनेता, कार्यकर्ता, व्यापारिक नेता और पत्रकार शामिल हैं। द हिल ने हाल ही में रिपोर्ट किया:

ये युवा नेता नामांकित होने पर रोमांचित और भयभीत दोनों हैं, और अलग न दिखने के लिए अंततः विचारों का समर्थन करने लगते हैं। अगर हर कोई कह रहा है कि यही सही है, तो हम सब इस पर सहमत हो जाते हैं, भले ही वे सहमत न हों। लोग सिर्फ इसलिए समर्थन करते हैं ताकि वे अकेले विपरीत राय रखने वाले न हों। इसलिए समूह सोच इस समूह का कम से कम एक परिणाम है। ... यह अधिक संभावना है कि नेतृत्व इस समूह को एक निश्चित तरीके से सोचने के लिए ढाल रहा है, ताकि जब वे अंततः मंत्रिमंडल में प्रवेश करें तो वे एक निश्चित तरीके से शासन करें। यह समझ में आता है क्योंकि यही विश्व आर्थिक मंच और उसके ग्रेट रीसेट का घोषित लक्ष्य है। एक घोषित एजेंडा है और निश्चित रूप से उनका ग्लोबल यंग लीडर्स कार्यक्रम इस एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए नेताओं को सत्ता के पदों तक पहुंचाने का एक प्रशिक्षण मैदान है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूईएफ) इस कार्यक्रम के तहत कई विश्व नेताओं को प्रशिक्षित कर रहा है, जिनमें महत्वपूर्ण पदों पर आसीन बड़ी

संख्या में भारतीय नेता (जैसे कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी) शामिल हैं। इसके अलावा, तीस वर्ष से कम आयु के युवाओं के लिए भी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है।

2012 में, श्वाब और डब्ल्यूईएफ ने एक और संस्था, "ग्लोबल शेपर्स कम्युनिटी" की स्थापना की, जो दुनिया भर से 30 वर्ष से कम आयु के उन लोगों को एक साथ लाती है जिन्हें उन्होंने नेतृत्व क्षमता से संपन्न माना है। अब तक लगभग 10,000 प्रतिभागी इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, और वे नियमित रूप से 400 शहरों में बैठकें आयोजित करते हैं। वोल्फ का मानना है कि यह एक और ऐसा मंच है जहां भावी राजनीतिक नेताओं का चयन, जांच-पड़ताल और प्रशिक्षण किया जाता है, इससे पहले कि उन्हें विश्व के राजनीतिक तंत्र में स्थान दिया जाए।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन रेड्डी पहले से ही विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूईएफ) के साथ काम कर रहे हैं। श्री श्री रवि शंकर और सद्गुरु जग्गी वासुदेव जैसे आधुनिक लोकप्रिय हिंदू गुरु भी डब्ल्यूईएफ से जुड़े हुए हैं। भारतीय फिल्म उद्योग के कई अभिनेता भी डब्ल्यूईएफ के राजदूत हैं।

पेप्सिको की पूर्व अध्यक्ष, इंदिरा नूयी, डब्ल्यूईएफ टैलेंट फॉर बोर्ड्स की ट्रस्टी हैं। डब्ल्यूईएफ ने मुंबई में एक कार्यालय भी स्थापित किया है, जिसे वह चौथी औद्योगिक क्रांति कहता है। सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंडिया का घोषित लक्ष्य प्रौद्योगिकियों और सार्वजनिक सेवाओं के व्यापक क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में कार्य करना है।

भारत सरकार के नीति आयोग ने सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंडिया के साथ साझेदारी की है और डेटा आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा विकसित किया है, जिसमें 'खुले, स्केलेबल

आर्किटेक्चर और पारदर्शी एवं न्यायसंगत शासन मॉडल' शामिल हैं, जो ठोस प्रोत्साहन सिद्धांतों द्वारा समर्थित हैं। विश्व आर्थिक संगठन (WEF) के पिछले रिकॉर्ड और उद्देश्यों को देखते हुए, यह सवाल उठता है कि ये 'प्रोत्साहन' क्या हैं और 'न्यायसंगत' की परिभाषा क्या है। नीति आयोग WEF के साथ मिलकर विचार विकसित कर रहा है और सार्वजनिक-निजी भागीदारी की वकालत कर रहा है। निम्नलिखित कथन WEF के ढांचे को प्रतिध्वनित करता है:

नीति आयोग द्वारा iSPIRT के सहयोग से जारी किया गया डेटा सशक्तिकरण और संरक्षण ढांचा (DEPA) वास्तव में भविष्योन्मुखी है, जो आम नागरिक को सबसे व्यापक और पारदर्शी तरीके से डेटा सशक्तिकरण प्रदान करता है। डेटा को अलग-अलग स्रोतों से निकालकर सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से डेटा प्लेटफॉर्म विकसित करने का ऐसा ही दृष्टिकोण संगठनों के लिए डेटा-आधारित निर्णय लेने और सरकार के लिए डेटा-आधारित नीति निर्माण में सहायक होगा। नीति आयोग ने लचीले डेटा गवर्नेंस ढांचे के लिए डेटा एक्सचेंज (DEx), तकनीकी और वाणिज्यिक सहायक कारकों पर यह शोधपत्र तैयार करने के लिए (WEF) के साथ सहयोग किया है। डेटा एक्सचेंज से डेटा का उपयोग व्यापक सामाजिक परिणामों के लिए किया जा सकता है और यह डेटा अर्थव्यवस्था की क्षमता को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह डेटा-आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और नागरिक सेवाओं के लिए सरकार के नेतृत्व वाले डेटा एक्सचेंजों की खोज पर संवाद को आमंत्रित करता है। क्षेत्र-विशिष्ट मॉडल और उपयोग के मामलों को डिजाइन और विकसित करने की आवश्यकता है। नीति आयोग और विश्व आर्थिक मंच, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के डेटा के आदान-प्रदान के लिए एक

ढांचा, लॉजिस्टिक्स डेटा एक्सचेंज (एलडीएक्स) विकसित करने के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम इस श्वेत पत्र को तैयार करने में उनकी पहल और प्रयासों के लिए विश्व आर्थिक मंच की टीम और नीति आयोग के सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। भारतीय सरकार को डब्ल्यूईएफ की नीतियों का अनुपालन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, इसने भारत के डिजिटल रीसेट की प्रशंसा की है:
13 लाख लोगों के देश का यह डिजिटल-प्रथम पुनरुद्धार न केवल तकनीकी प्रगति है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह शासन के माध्यम से सुविधाओं के वितरण के लिए एक नए तंत्र की नींव है। … यह संयुक्त जन-निजी प्रयास भारत को एक डिजिटल-प्रथम देश बना रहा है, जिससे एक अरब से अधिक लोगों के बुनियादी जीवन अनुभव और आकांक्षाओं का पुनर्मूल्यांकन हो रहा है।

दावोस के देवता
इब्राहीमी धर्मों को अब धर्म परिवर्तन के लिए मिशनरियों या तलवार का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। दावोस में मौजूद विश्व आर्थिक संगठन (डब्ल्यूईएफ) के प्रभावशाली नेताओं का समूह उद्योगपतियों और राजनेताओं को अपनी कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर सकता है। इसके सिद्धांत पश्चिमी सार्वभौमिकता पर आधारित हैं और इनमें मार्क्सवादी विचारधारा का भी समावेश है, जिसका उद्देश्य मौजूदा ढाँचों को ध्वस्त करना है। विश्व गुरु माने जाने वाले हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने इस विषय पर दशकों तक शोध कार्य किया है। प्रौद्योगिकी की सहायता से इन ज्ञान प्रणालियों का अभूतपूर्व पैमाने पर उपयोग भारत को कमजोर करने और डब्ल्यूईएफ के 'ग्रेट रीसेट' के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए किया

जाएगा।

हम एक ऐसी प्रणाली की ओर भी बढ़ सकते हैं जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता वैश्विक कुलीन वर्ग के मूल्यों को समाहित कर देगी और न्याय प्रणाली एल्गोरिथम पर आधारित होगी। विश्व आर्थिक मंच के देवता सामाजिक साख प्रणाली द्वारा निर्धारित 'पापों' के लिए विधर्मियों को दंडित करेंगे। सामाजिक साख यह निर्धारित करेगी कि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा, भोजन, बीमा, आवास और यात्रा/गतिशीलता जैसी सेवाओं के लिए पात्र है या नहीं। डिजिटल आईडी और व्यक्तिगत डेटा असंतुष्टों को वस्तुओं और सेवाओं का लाभ उठाने से रोकेंगे। कॉर्पोरेट ईएसजी रेटिंग गैर-अनुपालन करने वाले छोटे व्यवसायों को प्रभावी रूप से बंद कर देगी। रेटिंग विविधता, समानता और समावेशन की 'वोके' परिभाषा पर आधारित होगी। उदाहरण के लिए, एक हिंदू को वैदिक अनुष्ठान करने, दीपक जलाने, दिवाली पर पटाखे फोड़ने, दूध से बने उत्पादों का सेवन करने, हिंदू प्रार्थना करने और पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए दंडित किया जा सकता है। सामाजिक क्रेडिट प्रणाली की नई नैतिकता एक धर्म की तरह बन जाएगी।

इस नए खेल की विडंबना यह है कि इसे मानवता को विभिन्न समस्याओं से बचाने के नाम पर खेला जा रहा है। दुख की बात है कि कई भारतीय अभिजात वर्ग के लोग नए जमींदारों, सिपाहियों और शिष्यों के रूप में इसमें शामिल हैं। भारत को सचमुच उसके अपने ही अभिजात वर्ग ने बेच दिया है!

स्वीकृतियाँ

इतनी विशाल और व्यापक पुस्तक का निर्माण एक सक्षम टीम की सहायता से ही संभव है। लेखक विभिन्न विशिष्ट क्षमताओं में कार्यरत अनेक व्यक्तियों द्वारा दी गई सहायता के लिए आभार व्यक्त करते हैं। टी.एन. सुदर्शन ने इस विशाल पुस्तक को संकलित करने के लिए आवश्यक व्यापक शोध में सहायता की है। सेजुती बनर्जी ने लेखन के दौरान प्रत्येक अध्याय का समानांतर संपादन किया, साथ ही अंत में संपूर्ण पांडुलिपि का संपादन करके प्रवाह, निरंतरता और स्पष्टता में सुधार किया। अनुराग शर्मा और दिव्या शर्मा ने आरेखों में उल्लेखनीय सुधार किया। अनुराग ने अध्याय 6 के लिए व्यापक शोध सहायता भी प्रदान की। सुभोदीप मुखोपाध्याय ने मानक प्रारूप में बहुत ही व्यवस्थित ढंग से ग्रंथसूची तैयार की। दिव्या रेड्डी ने इस पुस्तक के पाठ के संकलन में प्रयुक्त ऑडियो फाइलों और वीडियो के प्रतिलेखन में सहायता की। जेराल्ड सूर्या ने उद्धरणों के सत्यापन और मूल यूआरएल के निष्क्रिय होने पर वैकल्पिक यूआरएल खोजने के प्रयास का नेतृत्व किया। आदित्य पाई ने सभी संदर्भों को डाउनलोड किया और उन्हें भविष्य के शोध के लिए एक संग्रह में व्यवस्थित किया, साथ ही उद्धरणों के सत्यापन में भी सहायता की। हमारी अत्यंत अनुभवी संपादक संजना रॉय चौधरी ने भाषा और विशेष शब्दों के सही और सुसंगत प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए पांडुलिपि की कई बार गहन समीक्षा की। बिस्वजीत मलाकर पुस्तक की वेबसाइट और इसके विमोचन एवं विपणन से संबंधित सभी वीडियो निर्माण के लिए जिम्मेदार रहे हैं। अदिति बनर्जी ने कई अध्यायों की समीक्षा की और उपयोगी टिप्पणियाँ एवं प्रतिक्रियाएँ दीं। दीप्ति राव ने LGBTQ+ विषयों से संबंधित अनुभागों की समीक्षा की और उनकी विस्तृत प्रतिक्रिया प्रस्तावना में उद्धृत की गई है। राजीव राव ने इक्वालिटी लैब्स के प्रारंभिक सुझावों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रतीक उनियाल ने

लेखकों द्वारा दिए गए कुछ कथनों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने में सहायता की। मनोग्ना शास्त्री ने पुस्तक के सफल प्रकाशन का समन्वय और पर्यवेक्षण किया।

ग्रन्थसूची

अबेलव, हेनरी, मिशेल ऐना बराले, और डेविड एम हैलपेरिन। 1993. द लेस्बियन एंड गे स्टडीज रीडर। न्यूयॉर्क: रूटलेज।

अभिषेक, अमन। 2021. “प्रचार पर शोध में राजनीतिक अर्थव्यवस्था की अनदेखी।” हार्वर्ड कैनेडी स्कूल, मिसइन्फॉर्मेशन रिव्यू। 1 अप्रैल। 31 मार्च, 2022 को देखा गया। https://misinforeview.hks.harvard.edu/wp-content/uploads/2021/03/abhishek-_political_economy_research_propaganda_20210401.pdf

अग्रवाल, सी.बी. 1934. विद्रोह में हरिजन। बॉम्बे: तारापोरेवाला एंड संस।

अग्रवाल, रिजू. 2017. भारत की कांग्रेस पार्टी के लिए एक दुर्लभ अवसर. 10 अक्टूबर. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://ksr.hkspublications.org/2017/10/10/a-rare-opportunity-for-india-and-the-congress-party/.

अहमद, क़यामुद्दीन। 1988। अल-बिरूनी द्वारा भारत। दूसरा संस्करण। नई दिल्ली: राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट।

अहुजा, राम. 1993. भारतीय सामाजिक व्यवस्था. जयपुर: रावत पब्लिशर्स.

अय्यंगार, के.वी. रंगास्वामी। 1934. प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन के पहलू। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय: बनारस।
ऐयर, स्वामीनाथन एस. अंकलेसरिया। 2019. दृष्टिकोण: प्रायोगिक अर्थशास्त्र परिपूर्ण नहीं है, लेकिन इसमें क्षमता है। 20 अक्टूबर। 15 मई, 2022 को देखा गया। https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/view-experimental-economics-not-perfect-but-has-potential/articleshow/71670694.cms
अल जज़ीरा. 2021. किसान विरोध प्रदर्शनों पर ट्वीट करके रिहाना ने भारत में हलचल मचा दी। 3 फरवरी। 15 मई, 2022 को देखा गया। https://www.aljazeera.com/news/2021/2/3/rihanna-creates-flutter-in-india-with-tweet-on-farmer-protests
अमन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। 2018. दानदाता एवं भागीदार। 15 मई, 2022 को देखा गया। http://amanpanchayat.org/about/donors-partners/
अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर (एआईसी)। 2021. सिस्को जातिगत भेदभाव: एआईसी प्रेस विज्ञप्ति। 2 मार्च। 15 फरवरी, 2022 को एक्सेस किया गया। https://ambedkarinternationalcenter.org/2021/03/cisco-caste-discrimination-aic-press-release/
अंबेडकर किंग स्टडी सर्कल, यूएसए। 2020. अमेरिका में जाति का प्रचलन - जाति कैसे फैलती है? डॉ. अजंता सुब्रमणियन, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, यूएसए द्वारा। 25 जुलाई। 15 फरवरी, 2022 को देखा गया। https://www.youtube.com/watch?

v=gVweqgyGvKM
——. 2021. जातिगत भेदभाव पर सांता क्लारा काउंटी मानवाधिकार परिषद। 30 अप्रैल। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया। https://akscusa.org/santa-clara-county-hrc-on-caste-discrimination/
Ambedkar, Bhimrao Ramji. 2015. 'Buddha or Karl Marx? CreateSpace Independent Publishing Platform. https://www.baiae.org/index.php/ja/downloads-baiae.html?download=12:buddha-or-karl-marx-pdf.
1936. जाति का नाश, महात्मा गांधी को उत्तर सहित। लाहौर: स्वयं प्रकाशित। http://www.ambedkar.org/ambcd/02.Annihilation%20of%20Caste.htm
——. 1990. पाकिस्तान: भारत का विभाजन। मुंबई: शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार। https://mea.gov.in/Images/attach/amb/Volume_08.pdf
——. 1979. शूद्र कौन थे? नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय, भारत सरकार। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त किया गया। https://www.mea.gov.in/Images/attach/amb/Volume_07.pdf
——. 1989ए. लेखन और भाषण. खंड 3. बॉम्बे: महाराष्ट्र सरकार.
——. 1989बी. लेखन और भाषण. खंड 5. बॉम्बे: महाराष्ट्र सरकार.
एम्स, मार्क। 2014b. जैसा कि हमने भविष्यवाणी की थी, भारत का नया नेता पियरे ओमिडयार को और भी अमीर बनाने वाला है। 5 जून। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया। https://pandodaily.com/2014/06/04/just-as-we-predicted-indias-new-leader-is-about-to-make-pierre-omidyar-a-

lot-richer/
——. 2014a. पियरे ओमिडयार के भारत में नियुक्त व्यक्ति को मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। 9 नवंबर। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया। https://pandodaily.com/2014/11/09/pierre-omidyars-man-in-india-is-named-to-modis-cabinet
आनंद, अभिषेक। 2020. “रोजगार पर कोविड-19 लॉकडाउन का लैंगिक प्रभाव: भारत का मामला।” हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय विकास केंद्र। 24 मार्च। 31 मार्च, 2022 को प्राप्त किया गया। https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/cid/files/publications/CID_Wiener_Inequality%20Award%20Research/Policy%20Briefs/Abhishek%20Anand%20(1-A).pdf.
एंडरसन, बेनेडिक्ट। 1983. कल्पित समुदाय: राष्ट्रवाद की उत्पत्ति और प्रसार पर विचार। लंदन: वर्सो।
एएनआई. 2021ए. डिजिट अब शहरी शासन के लिए राष्ट्रीय मंच है, जो शहरी परिदृश्य को बदल रहा है। 30 अक्टूबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.aninews.in/news/business/business/digit-now-the-national-platform-for-urban-governance-transforming-urban-landscape20211030124256/.
——. 2021b. गृह मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से ट्रांसजेंडरों की सुरक्षा और पुनर्वास करने का आग्रह किया। 23 जनवरी। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.livemint.com/politics/policy/mha-asks-states-uts-to-protect-

rehabilitate-transgenders-11611378131197.html.
एनेनबर्ग पब्लिक पॉलिसी सेंटर। 2021. “एनेनबर्ग पब्लिक पॉलिसी सेंटर 2021 नागरिक शास्त्र ज्ञान सर्वेक्षण।” सितंबर। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://cdn.annenbergpublicpolicycenter.org/wp-content/uploads/2021/10/APPC_2021_Civics_SCOTUS_Appendix.pdf.
एपलबाउम, इवान पी., माइकल आई. नॉर्टन, और सैमुअल आर. सोमर्स। 2012. नस्लीय रंगभेद: उद्भव, अभ्यास और निहितार्थ। जून। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=41856.
अपूर्वानंद. 2018. अशोका विश्वविद्यालय ने वह कर दिखाया जो प्रसिद्ध दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं कर सका - अपने शिक्षकों का साथ दिया. 19 दिसंबर. 15 मई, 2022 को देखा गया. https://theprint.in/opinion/ashoka-university-did-what-famed-delhi-university-could-not-stand-by-its-teachers/165093/.
एप्पलबाउम, बारबरा। 2010. श्वेत होना, अच्छा होना: श्वेत मिलीभगत, श्वेत नैतिक उत्तरदायित्व और सामाजिक न्याय शिक्षाशास्त्र। न्यूयॉर्क: लेक्सिंगटन बुक्स।
एरेनास, जे. सी. 2010. जिहाद समर्थक रशाद हुसैन: ओबामा द्वारा नियुक्त व्यक्ति का सोरोस से संबंध। 18 फरवरी। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.americanthinker.com/blog/2010/02/projihadist_rashad_hussain_oba.html.
आर्किटेक्ट इंडिया. 2021. एनईपी- नई शिक्षा नीति 2020 क्या है? - प्रो. अनुराग बेहार, कुलपति, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय. 2 फरवरी. 15

मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.youtube.com/watch?v=2CWOCnkknlw.
आर्मर-जोन्स, सारा, जेसिका क्लार्क, और लौरा श्वार्ट्ज-हेंडरसन। 2019. "ग्लोबल मीडिया फिलैंथ्रोपी।" मीडिया इम्पैक्ट फंडर्स। मार्च। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://mediaimpactfunders.org/wp-content/uploads/2019/03/Gates-Report-Final-3-25-19-2.pdf.
अर्थन. 2021. नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. एस्थर डुफ्लो, क्रेया विश्वविद्यालय की शासी परिषद में शामिल हुईं. 28 दिसंबर. 15 मई, 2022 को देखा गया. https://blog.arthancareers.com/nobel-laureate-dr-esther-duflo-joins-krea-universitys-governing-council/.
असानी, अली एस. 2007. बहुलवाद और इस्लाम पर विचार। 30 अप्रैल। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। http://worldmuslimcongress.blogspot.com/2007/04/pluralism-and-islam-asani.html.
अशोका विश्वविद्यालय। 2019. हमारे बारे में। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। http://csgs.ashoka.edu.in/about-us/
——. 2022a. अशोका सेंटर फॉर चाइना स्टडीज (ACCS). 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.ashoka.edu.in/centres_list/centre-for-china-studies/.
——. 2020a. अशोका इतिहास संकाय की अपर्णा वैदिक को ब्रिटिश अकादमी, यूके द्वारा शोध के लिए £50,000 (लगभग 50 लाख रुपये) का अनुदान प्रदान किया गया। 29 दिसंबर। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया। https://www.ashoka.edu.in/ashoka-history-

faculty-aparna-vaidik-awarded-50000-about-rs-50-lacs-grant-for-research-by-the-british-academy-uk/.
——. 2016a. अशोका विश्वविद्यालय ने 'भारत में रूढ़िवाद' विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। 14 दिसंबर। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया। https://www.ashoka.edu.in/ashoka-university-hosts-a-conference-on-conservatism-in-india/.
——. 2018a. अशोका विश्वविद्यालय ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के साथ साझेदारी में भारत में सामरिक गैर-लाभकारी प्रबंधन पर कार्यकारी कार्यक्रम के पहले बैच की मेजबानी की। 3 अगस्त। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.ashoka.edu.in/ashoka-university-in-partnership-with-harvard-business-school-hosted-the-first-batch-of-the-executive-programme-on-strategic-nonprofit-management-in-india/.
——. 2017a. अशोका विश्वविद्यालय के छात्रों ने हार्वर्ड यूएस इंडिया इनिशिएटिव के साथ साझेदारी की। 4 जनवरी। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.ashoka.edu.in/ashoka-university-students-partner-with-harvard-us-india-initiative/.
——. 2019a. अशोका विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर सौरव पाल का स्वागत किया। 21 मई। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.ashoka.edu.in/ashoka-university-welcomes-professor-sourav-pal/.
——. 2021a. भारत की व्यवहार संबंधी अंतर्दृष्टि इकाई, नीति

आयोग। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://csbc.org.in/niti-biu.php.
——. 2022बी. सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज (सीएसबीसी). 4 जनवरी. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.compendium.ashoka.edu.in/post/centre-for-social-and-behaviour-change-csbc-1.
——. 2019b. फैकल्टी@अशोका: प्रो. अश्विनी देशपांडे. 25 मार्च. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.youtube.com/watch?v=txohUgHF49o.
——. 2020b. अंतरंग संबंधों का संचालन। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया। http://csgs.ashoka.edu.in/governing-intimacies-a-research-meeting/
——. 2021. इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय संबंध कार्यक्रम। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.ashoka.edu.in/courses/history-and-international-relations-b-a-hons/.
——. 2017b. जया शर्मा ऑन बीडीएसएम. 18 जनवरी. 15 मई, 2022 को देखा गया. https://www.youtube.com/watch?v=mPKybSZyOvI
——. 2018. हमारे भागीदार। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://csip.ashoka.edu.in/partnerships/
——. 2021बी. राज्य व्यवहार अंतर्दृष्टि इकाइयाँ. 15 मई, 2022 को अभिगमित. https://csbc.org.in/state-biu.php.
——. 2016b. विक्रम आदित्य सहाय - सीएसजीएस के साथ पूरा साक्षात्कार। 10 मई। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया।

https://www.youtube.com/watch?v=kyJ4FdLR4jU.
एशिया नाउ. 2020. मेरे बेटे की विरासत: भारत की अदृश्य हिंसा. 27 अगस्त. 15 मई, 2022 को देखा गया. https://www.asianstudies.org/my-sons-inheritance-indias-invisible-violence/.
एशिया सेंटिनल. 2017. फोर्ब्स पत्रिका ने हांगकांग के एक प्रभावशाली उद्योगपति पर लेख प्रकाशित किया. 20 जुलाई. 30 अप्रैल, 2022 को देखा गया. https://www.asiasentinel.com/p/forbes-magazine-dumps-article-ronnie-chan.
अशोका टीवी चैनल. 2017. डॉ. सूरज येंगडे, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका: भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा पर. 16 सितंबर. 15 फरवरी, 2022 को देखा गया. https://www.youtube.com/watch?v=IEIMtnG7jTY.
लोकतांत्रिक सुधार संघ। 2016. एफसीआरए घोषणाएँ। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://adrindia.org/content/fcra-declarations.
Auti, V. M. 1970. Varkari Sampradaya Ke Kaviyon Ki Hindi Rachnaon Ka Anushilan. Pune: Pune University.
अजीम प्रेमजी फाउंडेशन. 2021. क्रिश्चियन हॉस्पिटल बिस्समकटक, रायगड़ा, ओडिशा। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://azimpremjifoundation.org/content/christian-hospital-bissamcuttack-rayagada-odesha
——. 2020. संगोष्ठी श्रृंखला: हम संगीत निर्माता हैं। 9 अक्टूबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://

azimpremjifoundation.org/content/colloquium-series-we-are-music-makers.
——. 2021a. रोंगमेई नागा बैपटिस्ट एसोसिएशन (आरएनबीए), इंफाल। 10 अप्रैल. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://azimpremjifoundation.org/content/rongmei-naga-baptist-association-rnba-imfal
——. 2021बी. रोंगमीन बैपटिस्ट एसोसिएशन नागालैंड, नागालैंड। 10 अप्रैल. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://azimpremjifoundation.org/content/rongmein-baptist-association-nagaland-nagaland
अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय. 2012. 'जॉर्ज सोरोस के साथ एक बातचीत,' अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में. 12 जनवरी. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.youtube.com/watch?v=epjGg_dO3oQ.
——. 2016. 'अदालतों और सड़कों पर लड़ाई...' सुधा भारद्वाज द्वारा। 23 सितंबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.youtube.com/watch?v=g4v_lWyYZzo.
——. 2014. एक आधुनिक स्वदेशी ऐतिहासिक ढाँचे की ओर। 12 फ़रवरी। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.youtube.com/watch?v=82Fmf6s231o.
——. 2020. हम संगीत निर्माता हैं, टी एम कृष्णा द्वारा। 27 अक्टूबर। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.youtube.com/watch?v=eIatArSxTNc.
बद्रीनाथन, सुमित्रा, देवेश कपूर, जोनाथन के और मिलन वैष्णव। 2021. भारतीय अमेरिकियों की सामाजिक वास्तविकताएँ: 2020 भारतीय

अमेरिकी दृष्टिकोण सर्वेक्षण के परिणाम। 9 जून। 15 फरवरी 2022 को एक्सेस किया गया। https://carnegieendowment.org/2021/06/09/social-realities-of-indian-americans-results-from-2020-indian-american-attitudes-survey-pub-84667.
बैग, ए.के. 1997. भारत में प्रौद्योगिकी का इतिहास। खंड I. नई दिल्ली: भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी।
बेली, एलिसन। 2017. "फेमिनिस्ट और क्रिटिकल रेस फिलॉसफी कक्षाओं में विशेषाधिकार-संरक्षण ज्ञानमीमांसीय पुशबैक को ट्रैक करना।" हाइपेटिया: ए जर्नल ऑफ फेमिनिस्ट फिलॉसफी 32 (4): 876-892. doi:https://doi.org/10.1111/hypa.12354 .
बैकर, पीटर, और जॉन एल्किंगटन। 2020. बेहतर पुनर्निर्माण के लिए, हमें पूंजीवाद को फिर से परिभाषित करना होगा। यहाँ बताया गया है कि कैसे। 13 जुलाई। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.weforum.org/agenda/2020/07/to-build-back-better-we-must-reinvent-capitalism-heres-how/.
बालकृष्ण, संदीप। 2020. ऑक्सफैम की भूलभुलैया को सुलझाना: जॉर्ज सोरोस, हर्ष मंदर और अशोका विश्वविद्यालय को क्या एकजुट करता है? 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.dharmadispatch.in/commentary/untangling-the-oxfam-labyrinth-what-unites-george-soros-harsh-mander-and-ashoka-university.
बनर्जी, अभिजीत, लक्ष्मी अय्यर, और रोहिणी सोमनाथन। 2006. "सार्वजनिक वस्तुओं के लिए सार्वजनिक कार्रवाई।" हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। सितंबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://

www.hbs.edu/ris/Publication%20Files/07-061.pdf.
बैंगलोर इंटरनेशनल सेंटर. 2019. जाति मायने रखती है: सूरज येंगडे की 21वीं सदी में जाति पर पुस्तक. 21 अगस्त. 15 फरवरी, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.youtube.com/watch?v=k6PMii3sdNg.
बीएपीएसए (बिरसा अंबेडकर फुले छात्र संघ), जेएनयू। 2016. कार्तिक बिट्टू कोंडैया का भाषण 'सभ्यता विहीन समाज' - भाग 2. 21 नवंबर। 15 मई, 2022 को देखा गया। https://www.youtube.com/watch?v=J4mZtpL705A.
बारबोनी, जियोर्जिया, एरिका फील्ड, रोहिणी पांडे, नतालिया रिगोल और सिमोन शैनर। 2018. “एक कठिन चुनौती: भारत में महिलाओं द्वारा मोबाइल फोन अपनाने में आने वाली बाधाओं और प्रभावों को समझना।” हार्वर्ड कैनेडी स्कूल, नीति निर्माण के लिए साक्ष्य। अक्टूबर। 31 मार्च, 2022 को देखा गया। https://epod.cid.harvard.edu/sites/default/files/2018-10/A_Tough_Call.pdf.
बार्न्स, जूलियन ई., मैथ्यू रोसेनबर्ग और गार्डिनर हैरिस। 2018. अमेरिकी जासूसी एजेंसियां पत्रकार के लापता होने से सऊदी राजकुमार के संबंधों को लेकर तेजी से आश्वस्त हो रही हैं। 17 अक्टूबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.nytimes.com/2018/10/17/world/middleeast/pompeo-khashoggi-murder.html.
बार्नेट, इयान, तरुण खन्ना, और जुक्का-पेक्का ओनेला। 2016. “मानवता के सबसे बड़े जमावड़े में लोगों का सामाजिक और स्थानिक समूहीकरण।” पीएलओएस वन। 3 जून। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://journals.plos.org/plosone/article?

id=10.1371/journal.pone.0156794.
बर्राबी, थॉमस। 2022. ब्लैक रॉक के सीईओ का कहना है कि स्टेकहोल्डर कैपिटलिज्म 'वोके' नहीं है, बल्कि अच्छा व्यवसाय है। 18 जनवरी। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://nypost.com/2022/01/18/larry-fink-says-stakeholder-capitalism-isnt-woke-just-good-business/.
बार्थ, फ्रेडरिक. 1956. “स्वात, उत्तरी पाकिस्तान में जातीय समूहों के पारिस्थितिक संबंध.” अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट 58 (6): 1079-1089. https://www.jstor.org/stable/666295.
बरुआ, मितुल. 2017बी. “नमामी ब्रह्मपुत्र” ब्रह्मपुत्र घाटी के लोगों के लिए एक अपमान है. 4 अप्रैल. 15 मई, 2022 को अभिगम किया गया. https://raiot.in/namami-brahmaputra-is-a-disservice-to-the-people-of-the-brahmaputra-valley/.
——. 2017a. “नमामि ब्रह्मपुत्र”: नदी की पूजा करना, उसकी भौतिकता को अनदेखा करना। 27 अप्रैल। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://entitleblogdotorg3.wordpress.com/2017/04/27/namami-brahmaputra-worshipping-a-river-ignoring-its-materialities/.
बाशा, सादिक. 2020. एनईपी विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए द्वार खोलता है और कई सपनों को पूरा करता है. 16 सितंबर. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://bloncampus.thehindubusinessline.com/b-learn/nep-opens-doors-to-foreign-universities-and-fulfils-many-dreams/article32622859.ece.

बशम, ए.एल. 2004. द वंडर दैट वाज़ इंडिया. तीसरा संस्करण. लंदन: पिकाडोर.
बेसलर, रॉय पी. 1953. अब्राहम लिंकन के एकत्रित कार्य। न्यू ब्रंसविक, एनजे: रटगर्स यूनिवर्सिटी प्रेस।
बीबीसी न्यूज़. 2020. हानिकारक कोविड वैक्सीन मिथकों से निपटने के लिए मीडिया और तकनीकी कंपनियाँ एकजुट हुईं. 10 दिसंबर. 15 मई, 2022 को देखा गया. https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-55257814.
बीमन, लोरी, राघबेंद्र चट्टोपाध्याय, एस्थर डुफ्लो, रोहिणी पांडे और पेटिया टोपालोवा। 2008. "शक्तिशाली महिलाएं: क्या प्रदर्शन पूर्वाग्रह को कम करता है?" हार्वर्ड में छात्रवृत्ति तक डिजिटल पहुंच। जुलाई। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/37366185/175.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
बीमन, लोरी, रोहिणी पांडे और एलेक्जेंड्रा सिरोन। 2012. "भारत में पुरुष प्रधान राजनीति और सशक्तिकरण।" महिला एवं लोक नीति कार्यक्रम, हार्वर्ड कैनेडी स्कूल। 31 मार्च, 2022 को प्राप्त किया गया। https://wappp.hks.harvard.edu/files/wappp/files/14._politics_as_a_male_domain_and_empowerment_in_i
बेहल, रिया। 2021. अधिकार और लोकतंत्र। 6 अक्टूबर। 31 मार्च, 2022 को देखा गया। https://pari.education/learning-resource/rights-and-democracy/
बेल, डेरिक ए. 1995. "क्रिटिकल रेस थ्योरी से कौन डरता है?" इलिनोइस विश्वविद्यालय विधि समीक्षा (4)।
Belongg. 2019. About. 4 नवंबर. 15 मई, 2022 को एक्सेस

किया गया. https://belongg.net/about/
BelonggCircle.2022. विकास तक पहुंच के संदर्भ में धर्म-आधारित भेदभाव को समझने के लिए आप 7 विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकते हैं। 15 मई, 2022 को प्रकाशित। https://belonggcircle.com/collections/0f06d411-05d1-45ff-84f9-6dd471f2d6a9
बेलॉन्ग मेंटल हेल्थ कलेक्टिव। 2021. बेलॉन्ग स्टूडेंट एंबेसडर प्रोग्राम 2021. 22 मार्च। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://belonggmentalhealth.com/initiatives/belongg-student-ambassador-program/
बर्कले सेंटर. 2021. धर्म और लोकलुभावनवाद को समझना. 12 मार्च. 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.youtube.com/watch?v=DPUF-Pjtjgk.
बर्नहार्ड्ट, एरिएल, एरिका फील्ड, रोहिणी पांडे, नतालिया रिगोल और सिमोन शैनर। 2018. "पुरुषों की सामाजिक स्थिति और महिलाओं का कार्य।" हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। मई। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.hbs.edu/ris/Publication%20Files/pandp.20181086_5907afa6-2831-43f0-a7bb-d2fd848e3e14.pdf.
बेशारा, रॉबर्ट। 2019. डीकोलोनियल मनोविश्लेषण: एक आलोचनात्मक इस्लामोफोबिया की ओर। लंदन: रूटलेज।
बेथम, आर.एम. 1908. मराठा और देखनी मुसलमान। कलकत्ता: सरकारी मुद्रण अधीक्षक।
बेयरर, जैक। 2021. आइवी लीग कॉलेज सैन्य से जुड़े चीनी स्वास्थ्य संस्थानों के साथ साझेदारी करते हैं। 10 मार्च। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://freebeacon.com/national-

security/ivy-league-colleges-partner-with-chinese-health-institutions-tied-to-military/
भाभा, होमी के. 1994. संस्कृति का स्थान. लंदन, न्यूयॉर्क: रूटलेज.
भालोत्रा, सोनिया, गिलहेम कैसन, इरमा क्लॉट्स फिगुएरस और लक्ष्मी अय्यर। 2013. “धर्म, राजनीतिज्ञ पहचान और विकास परिणाम: भारत से साक्ष्य।” हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। 21 जून। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.hbs.edu/ris/Publication%20Files/13-102_ef340026-34b1-4b90-af4f-dc022a137e9a.pdf.
भारती, नवीन, दीपक मलघन, सुमित मिश्रा और अंदलीब रहमान। 2020. “फ्रैक्टल अर्बनिज़्म: भारत में शहर का आकार और आवासीय अलगाव।” डायसन स्कूल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, कॉर्नेल विश्वविद्यालय। जून। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://dyson.cornell.edu/wp-content/uploads/sites/5/2020/07/WP_2020_06-VD.pdf.
भट्टाचार्जी, के. 2021. एनसीईआरटी का 'वोके' रुख, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग शौचालयों को समस्या बताना, यौवन अवरोधकों का सुझाव देना, और कलंक के लिए 'जातिगत पितृसत्ता' को दोषी ठहराना। 1 नवंबर। 15 मई, 2022 को प्राप्त। https://www.opindia.com/2021/11/ncert-training-manual-teachers-gender-identity-transgender-woke-puberty-blockers/.
——. 2020. वे ‘विरोध प्रदर्शन’ जिन्होंने देश को जला दिया: अमेरिकी नागरिक सिद्धार्थ वरदराजन की ‘द वायर’ ने सीएए विरोधी ‘प्रदर्शनकारियों’ के साथ कैसे सहयोग किया। 13 जून। 15 मई, 2022

को एक्सेस किया गया। https://www.opindia.com/2020/06/azaad-india-collective-siddharth-varadarajan-the-wire-anti-caa-protests/.
भट्टाचार्जी, मालिनी। 2021. 'सेवा' के माध्यम से 'हिंदू राष्ट्र' का निर्माण। 14 जनवरी। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.epw.in/engage/article/building-hindu-rashtra-through-seva.
भट्टाचार्य, सौम्या। 2015. हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डिजिटल प्लेटफॉर्म एचबीएक्स ने भारत में अशोका विश्वविद्यालय के साथ पहला समझौता किया। 20 अक्टूबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://economictimes.indiatimes.com/industry/services/education/harvard-business-schools-digital-platform-hbx-enters-into-first-tie-up-in-india-with-ashoka-university/articleshow/49460004.cms.
——. 2012. ज़ेंडर ग्रुप के संस्थापक सिद्धार्थ योग ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को 11 मिलियन डॉलर का दान दिया। 28 जनवरी। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://economictimes.indiatimes.com/news/company/corporate-trends/xander-group-founder-siddharth-yog-gifts-11-million-to-harvard-business-school/articleshow/11655935.cms.
बिंकले, कॉलिन। 2022. 'हमारे अतीत की गलतियों को सुधारने की सच्ची लालसा': आइवी लीग स्कूलों में विरासत प्रवेश को समाप्त करने की लड़ाई। 13 फरवरी। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.boston.com/news/

politics/2022/02/13/ending-legacy-admissions-harvard-yale-brown/.
——. 2018. एमआईटी रिपोर्ट सऊदी अरब के साथ संबंध तोड़ने के खिलाफ सिफारिश करती है। 7 दिसंबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://apnews.com/article/edee57a4171f406694f57eb16f26dd0e.
बिस्वास, सौतिक। 2016. कई भारतीय मुसलमानों को अछूत क्यों माना जाता है? 10 मई। 15 फरवरी, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.bbc.com/news/world-asia-india-36220329.
बिट्टू, कार्तिक. 2021. कोविड-19 महामारी के समय में गौरव माह. 20 जुलाई. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://gaurilankeshnews.com/pride-month-in-times-of-covid-19-pandemic-community/?fbclid=IwAR1lNLJmLy7GH5b2U3q3JVbhzAH_LDh2FnaSZz
ब्लैंडिंग, माइकल। 2021. क्षतिपूर्ति के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करना। 14 दिसंबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.hsph.harvard.edu/news/features/making-the-case-for-reparations/.
स्पष्ट रूप से ईमानदार। 2021a. 'अशोका विश्वविद्यालय में अकादमिक शिक्षा बहुत कठिन है,' गणित के एक छात्र ने अपनी यात्रा के बारे में बताया। 31 दिसंबर। 15 मई, 2022 को देखा गया। https://www.youtube.com/watch?v=zJMmOt4WO7Q.
——. 2022. अत्याधुनिक शिक्षण पद्धति के बावजूद, अशोका के अधिकांश छात्र अभी भी सीबीएसई की मानसिकता में फंसे हुए हैं। 6

जनवरी। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.youtube.com/watch?v=8A6qOUMKtQ8.
——. 2021b. 'अशोका विश्वविद्यालय में टिके रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है,' एक छात्र ने वहाँ बिताए अपने समय को याद करते हुए कहा। 29 दिसंबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.youtube.com/watch?v=QjqJCTW7Wb4.
बोगोसियन, पीटर, और जेम्स ए. लिंडसे। 2019. असंभव बातचीत कैसे करें: एक बहुत ही व्यावहारिक मार्गदर्शिका। दा कैपो लाइफलोंग बुक्स।
बॉन्ड, पॉल। 2021. एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि अमेरिका में लगभग 40 प्रतिशत जेन जेड और 30 प्रतिशत युवा ईसाई खुद को एलजीबीटीक्यू के रूप में पहचानते हैं। 20 अक्टूबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.newsweek.com/nearly-40-percent-us-gen-zs-30-percent-christians-identify-lgbtq-poll-shows-1641085.
बोनिला-सिल्वा, एडुआर्डो। 2003. नस्लवादियों के बिना नस्लवाद: रंग-अंधा नस्लवाद और अमेरिका में नस्लीय असमानता की निरंतरता। लैनहैम: रोवमैन एंड लिटिलफील्ड पब्लिशर्स।
बोनिला-सिल्वा, एडुआर्डो, और डेविड डायट्रिच। 2011. "ओबामा के अमेरिका में रंग-अंध नस्लवाद का मधुर आकर्षण।" अमेरिकन एकेडमी ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल साइंस के इतिहास (सेज पब्लिकेशन्स, इंक.) 190-206। http://www.jstor.org/stable/29779402
बूम, डैनियल वैन। 2021. जॉन सीना की चीन से माफी: आपको क्या जानना चाहिए। 26 मई। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.cnet.com/news/john-cenas-apology-to-

china-everything-you-need-to-know/
बोर्गोंजोन, डेविड. 2017. कलाकार साक्षात्कार: थेनमोझी सौंदराजन. 20 अप्रैल. 15 फरवरी, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.eyebeam.org/five-questions-around-technology-and-stories-for-social-change/.
बोवर, जेरी. 2021. सिलिकॉन वैली से एक अप्रत्याशित संदेश. 19 अक्टूबर. 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया. https://wng.org/opinions/an-unexpected-message-from-silicon-valley-1634728806.
बॉयड, जॉर्डन। 2021. कम्युनिस्ट चीन ने प्रचार सामग्री में क्रिटिकल रेस थ्योरी को बढ़ावा देने वाला वीडियो जोड़ा। 18 अगस्त। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://thefederalist.com/2021/08/18/communist-china-adds-video-promoting-critical-race-theory-to-propaganda-lineup/
ब्रूकिंग्स. 2015. राजदूत शिवशंकर मेनन ने विदेश नीति में विशिष्ट फेलो के रूप में ब्रूकिंग्स में कार्यभार संभाला। 16 जून। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया। https://www.brookings.edu/research/ambassador-shivshankar-menon-joins-brookings-as-distinguished-fellow-in-foreign-policy/.
ब्रेड फॉर द वर्ल्ड। 2020. हमारे बारे में: ब्रेड फॉर द वर्ल्ड। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.brot-fuer-die-welt.de/en/bread-for-the-world/about-us/
बर्नली, मैल्कम। 2017. हार्वर्ड कैनेडी स्कूल ने अमेरिका को कैसे त्याग दिया। 22 जनवरी। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया।

https://www.bostonmagazine.com/news/2017/01/22/harvard-kennedy-school-america/2/
बर्न्स, निकोलस। 2020. भारत का बदलता क्षितिज: राहुल गांधी के साथ एक वार्तालाप। 8 अक्टूबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.belfercenter.org/publication/indias-transforming-horizon-conversation-rahul-gandhi.
बर्न्स, निकोलस, और अंजा मैनुअल। 2020. भारत पर, अमेरिका को व्यापक सोच रखनी चाहिए। 16 अक्टूबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.belfercenter.org/publication/india-us-must-think-bigger.
बिजनेस फ्रांस. 2021. स्वाति पीरामल. 12 अक्टूबर. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://events-export.businessfrance.fr/ambition-india/swati-piramal/.
बुचर, जोनाथन, और माइक गोंजालेज। 2020. क्रिटिकल रेस थ्योरी, नई असहिष्णुता, और अमेरिका पर इसकी पकड़। 7 दिसंबर। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.heritage.org/civil-rights/report/critical-race-theory-the-new-intolerance-and-its-grip-america.
बटलर, जूडिथ। 1993. बॉडीज़ दैट मैटर: ऑन द डिस्क्रसिव लिमिट्स ऑफ़ “सेक्स”। लंदन: रूटलेज।
बीडब्ल्यू एजुकेशन. 2020. हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और आईआईएम के पूर्व छात्रों ने मिलकर हैदराबाद में कौटिल्य स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी की

स्थापना की। 11 नवंबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। http://bweducation.businessworld.in/article/Harvard-Stanford-IIM-Alumni-Together-Establishes-The-Kautilya-School-Of-Public-Policy-In-Hyderabad/11-11-2020-341653/.
बायरन, जॉन ए. 2021. सीईआईबीएस के नए एमबीए निदेशक चीन में एमबीए प्राप्त करने पर। 1 दिसंबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://poetsandquants.com/2021/12/01/ceibs-new-mba-director-on-getting-an-mba-in-china/?pq-category=b-schools.
कैडेल, पैट्रिक। 1938. बॉम्बे सेना का इतिहास। लंदन: लॉन्गमैन्स।
कैपस्टोन रिपोर्ट. 2020a. चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े अरबपति ने इवेंजेलिकल ईसाईयों सहित अमेरिकियों को व्यापक रूप से दान दिया है. 16 दिसंबर. 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया. https://capstonereport.com/2020/12/16/billionaire-linked-to-chinese-communist-party-has-given-extensively-to-americans-including-to-evangelical-christians/35257/.
——. 2020b. चीन भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को लुभाने और विभाजित करने के लिए पैसे का उपयोग करता है। 21 अक्टूबर। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://capstonereport.com/2020/10/21/china-uses-money-to-seduce-divide-geopolitical-rivals/35077/.
कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस। 2016. मिलान वैष्णव। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://

carnegieendowment.org/experts/714.
कार्नी, लियो। 2022. हार्वर्ड कैनेडी स्कूल मिसइन्फॉर्मेशन रिव्यू ने ADOS के खिलाफ लिखे गए लेख को वापस लिया। 7 जनवरी। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.mississippifreepress.org/19539/harvard-kennedy-school-misinformation-review-retracts-hit-piece-against-ados/
सीईआईबीएस. 2016. सीईआईबीएस स्थापना. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.ceibs.edu/ceibs-establishment.
सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज। 2021. “सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज: 31 मार्च 2019 तक का बैलेंस शीट।” सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज। फरवरी। 15 मई 2022 को एक्सेस किया गया। http://centreforequitystudies.org/wp-content/uploads/2021/02/Balance-Sheet-F.Y-18-19.pdf
सामाजिक प्रभाव और परोपकार केंद्र। 2019. “वकालत, अधिकार और नागरिक समाज: भारतीय परोपकार के लिए अवसर।” एसडीजी परोपकार मंच। जनवरी। 15 मई, 2022 को देखा गया। https://www.sdgphilanthropy.org/system/files/2019-01/Advocacy%2C%20Rights%20%26%20Civil%20Society%3A%20The%20Opportunity%20for%20Indian%20Philanthropy.pdf.
चक्रबोर्ती, हरिपाड़ा। 1960. प्राचीन भारत का व्यापार और वाणिज्य। कलकत्ता: अकादमिक प्रकाशक।
चक्रवर्ती, संजय। 2019. दृष्टिकोण: अंग्रेजों ने भारत की जाति व्यवस्था

को कैसे नया रूप दिया। 19 जून। 15 फरवरी, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.bbc.com/news/world-asia-india-48619734.
चंद्र, अभिमन्यु। 2020. विशेषाधिकार कई लोगों को भारत में हिंसा देखने से रोकता है: इतिहासकार अपर्णा वैदिक। 4 अक्टूबर। 15 मई, 2022 को प्राप्त। https://caravanmagazine.in/interview/privelege-keeps-many-from-seeing-the-violence-in-india-historian-aparna-vaidik.
चंद्र, रोहित वाल्टन, और माइकल। 2020. बड़ी क्षमता, बड़े जोखिम? भाजपा युग में भारतीय पूंजीवाद, आर्थिक सुधार और लोकलुभावनवाद। 19 मई। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14736489.2020.1744997.
चार्स्ले, साइमन. 1996. "'अछूत': नाम में क्या है?" रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का जर्नल (ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड का रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट) 2 (1): 1-23.
चट्टोपाध्याय, ब्रजदुलाल। 2014. प्राचीन भारतीय आर्थिक इतिहास पर निबंध। द्वितीय संस्करण। दिल्ली: भारतीय इतिहास कांग्रेस और प्राइमस बुक्स।
Chauhan, G.S. 2014. Bani of Bhagats Part 2. Amritsar: All India Pingalwara Charitable Society.
चेनोवेथ, एरिका, मैथ्यू स्मिथ और सलिल शेट्टी। 2020. "वैश्विक महामारी के दौरान सामाजिक आंदोलनों और नागरिक प्रतिरोध की पुनर्कल्पना।" हार्वर्ड कैनेडी स्कूल, कैर सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स पॉलिसी। 17 अप्रैल। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://

carrcenter.hks.harvard.edu/files/cchr/files/200416_covid_discussion_paper.pdf.
महाद के बच्चे। 2020. जातिगत उत्पीड़न महिलाओं के उत्पीड़न पर पनपता है - सूरज येंगडे। 22 जुलाई। 15 फरवरी, 2022 को देखा गया। https://www.youtube.com/watch?v=LGf-MjCH5eg.
चाइनीज स्टडीज एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। 2021. चाइना स्टडीज पोस्टडॉक्टोरल फेलोशिप। 13 अगस्त। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.csaa.org.au/2021/08/china-studies-postdoctoral-fellowship/
क्रिस्टेंसन, जोश। 2021. डब्ल्यूएचओ निदेशक जिन्होंने चीन का बचाव किया, हार्वर्ड दीक्षांत समारोह में वक्ता बने। 28 जनवरी। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://freebeacon.com/coronavirus/who-director-who-covered-for-china-to-be-harvard-commencement-speaker/
चुआंग, कैलिया ए., ल्यूक ए. विलियम्स, और मैटियो एन. वोंग। 2019. सैकड़ों हार्वर्ड संबद्ध व्यक्तियों ने भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में पत्र पर हस्ताक्षर किए। 20 दिसंबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.thecrimson.com/article/2019/12/20/indian-citizenship-act-letter/
चुगताई, मरियम। 2015. “इतिहास की पाठ्यपुस्तक कैसे बनती है?” हार्वर्ड में छात्रवृत्ति तक डिजिटल पहुँच। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/16461056/CHUGHTAI-DISSERTATION-2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

क्लेरिडा, मैथ्यू क्यू. 2014. स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का नाम 350 मिलियन डॉलर के दान से बदला गया, हार्वर्ड के इतिहास में सबसे बड़ा दान। 8 सितंबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.thecrimson.com/article/2014/9/8/chan-gift-public-health/.
सीएनआरएस. 1997. सीएनआरएस. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.cnrs.fr.
कोट्स, ता-नेहिसी. 2015. रंग-अंधा नीति, रंग-जागरूक नैतिकता. 13 मई. 30 अप्रैल, 2022 को अभिगमित. https://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/05/color-blind-policy-color-conscious-morality/393227/.
कोगिटो 137. 2020. डॉ. बिट्टू लिंग तरलता के विज्ञान की व्याख्या करते हैं। 24 अक्टूबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.youtube.com/watch?v=h1TsrL7QgoI.
कोहेन, रिक. 2014. यूक्रेन में पियरे ओमिडयार और बड़ी चैरिटी की भूमिका. 4 मार्च. 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया. https://nonprofitquarterly.org/the-role-of-pierre-omidyar-and-big-charity-in-the-ukraine/.
कॉलिन्स, पेट्रीसिया हिल। 1990. ब्लैक फेमिनिस्ट थॉट: नॉलेज, कॉन्शियसनेस, एंड द पॉलिटिक्स ऑफ एम्पावरमेंट। न्यूयॉर्क और लंदन: रूटलेज।
कॉलिन्स, पेट्रीसिया हिल, और सिरमा बिल्गे। 2016. अंतर्संबंधता। माल्डेन, एमए: पॉलिटी प्रेस।
कॉनरॉन, केरिथ जे., और शोशाना के. गोल्डबर्ग। 2020. “संयुक्त राज्य अमेरिका में वयस्क एलजीबीटी आबादी।” विलियम्स इंस्टीट्यूट स्कूल

ऑफ लॉ। जुलाई। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/LGBT-Adult-US-Pop-Jul-2020.pdf.
कॉन्स्टेबल, फिलिप. 2001. "उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध और बीसवीं सदी के आरंभिक पश्चिमी भारत में दलित मार्शल जाति का हाशिए पर जाना।" जर्नल ऑफ एशियन स्टडीज 60 (2): 439-478. doi:https://doi.org/10.2307/2659700.
कॉर्नेल लॉ स्कूल। दिनांक अज्ञात। महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.law.cornell.edu/wex/critical_legal_theory.
कॉस्ट, बेन. 2021. जे.के. राउलिंग ने सोशल मीडिया पर पता साझा करने के लिए ट्रांसजेंडर कार्यकर्ताओं की आलोचना की. 22 नवंबर. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://nypost.com/2021/11/22/j-k-rowling-slams-trans-activists-for-sharing-address-on-twitter/.
काउंटरकरंट्स. 2020. दिल्ली में मुस्लिम विरोधी नरसंहार पर 350 से अधिक शिक्षाविदों ने बयान जारी किया। 2 मार्च। 15 मई, 2022 को देखा गया। https://countercurrents.org/2020/03/over-350-acadamics-issue-statement-on-the-anti-muslim-pogrom-in-delhi/.*
सांता क्लारा काउंटी। 2020। सिलिकॉन वैली में जातिगत भेदभाव से संबंधित इक्विटी लैब्स से रिपोर्ट प्राप्त करें और यदि कोई सिफारिशें हों तो उन्हें अनुमोदित करें। 12 नवंबर। 15 फरवरी, 2022 को देखा गया। http://sccgov.iqm2.com/Citizens/Detail_LegiFile.aspx?

ID=103782&highlightTerms=Caste.*
क्रॉफर्ड, अबिजाह। 2021. भारत में धार्मिक स्वतंत्रता संकट में है। 2 अगस्त। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://providencemag.com/2021/08/religious-freedom-india-trouble/
क्रेमर, लूसी। 2020. चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हार्वर्ड और प्रिंसटन के कक्षाओं तक पहुँच गया है। 19 अगस्त। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.wsj.com/articles/chinas-national-security-law-reaches-into-harvard-princeton-classrooms-11597829402?page=1.
क्रेंशॉ, किम्बर्ले। 1989. नस्ल और लिंग के अंतर्संबंध को हाशिए से हटाना: भेदभाव-विरोधी सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत और नस्ल-विरोधी राजनीति की एक अश्वेत नारीवादी आलोचना। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8/
क्रेंशॉ, किम्बर्ले विलियम्स, ल्यूक चार्ल्स हैरिस, डैनियल मार्टिनेज होसांग और जॉर्ज लिप्सिट्ज़। 2019. सीइंग रेस अगेन। ओकलैंड, कैलिफोर्निया: यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस।
सीएसजीएस@अशोका. 2019. गवर्निंग इंटिमेसीज़ | मुख्य भाषण | कविता कृष्णन. 11 दिसंबर. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.youtube.com/watch?v=8mFepS-OuPg.
——. 2020. सिद्धांत और व्यवहार | जाति का निर्माण, नस्ल का यौनिकरण। 12 नवंबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.youtube.com/watch?v=YcIX4Ph5tMw.

कनिंघम, एडवर्ड, टोनी सैच, और जेसी ट्यूरिएल। 2020. सीसीपी के लचीलेपन को समझना: समय के साथ चीनी जनमत का सर्वेक्षण। जुलाई। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://ash.harvard.edu/publications/understanding-ccp-resilience-surveying-chinese-public-opinion-through-time.
दा अल्टरनेटिव. 2022. क्लाउस श्वाब 2017 यंग ग्लोबल लीडर्स. 3 फरवरी. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.youtube.com/watch?v=PbVD4tB4cVQ.
डैलमेयर, मैककेना। 2021. हार्वर्ड बिजनेस स्कूल क्लब ऑफ न्यूयॉर्क ने कैंसल कल्चर टॉक से वक्ता को रद्द किया: रिपोर्ट। 26 फरवरी। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.campusreform.org/article?id=16920.
डी'अमोर-मैककिम स्कूल ऑफ बिजनेस। 2019. भारत में लोकतंत्र: उपलब्धियां और कमियां | आशुतोष वर्शनी | भारत व्याख्यान श्रृंखला। 26 अक्टूबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.youtube.com/watch?v=uZyEnOMEjxA.
दास, वीना. 2003. द ऑक्सफोर्ड कम्पेनियन टू सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
डेटा गवर्नेंस नेटवर्क. 2020. परिचय | डेटा गवर्नेंस नेटवर्क. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://datagovernance.org/about.
——. 2013. डेटा गवर्नेंस नेटवर्क. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://datagovernance.org/.
दत्ता, अवेक. 2014. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सीएसआर में अधिक

उत्पादक रूप से संलग्न हो सकते हैं: तरुण खन्ना. 6 फरवरी. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.livemint.com/Companies/NVQioMXAzDgPYweaoS22lM/PSUs-could-be-engaged-in-CSR-more-productively-Tarun-Khanna.html.
दत्ता, भूपेंद्रनाथ। 1944. भारतीय सामाजिक राजनीति में अध्ययन। कलकत्ता: पुरबी पब्लिशर्स।
दत्ता, सायंतन. 2021. भारतीय विज्ञान अभ्यास में अंतर्संबंध और विशेषाधिकार. 28 अप्रैल. 15 मई, 2022 को अभिगमित. https://thelifeofscience.com/2021/04/28/intersectionality-and-privilege-in-indian-science-practice/.
डेविडसन, हेलेन। 2020. हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक नेता जोशुआ वोंग गिरफ्तार। 24 सितंबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.theguardian.com/world/2020/sep/24/pro-democracy-leader-joshua-wong-arrested-in-hong-kong.
डेविस, जिम. 2012. अकादमिक अस्पष्टताएँ: उत्तर आधुनिक बकवास का मनोवैज्ञानिक आकर्षण - दस्तावेज़ - गेल अकादमिक वनफाइल. ग्रीष्मकालीन. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA313159923&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linka%7Ef3ce69b3.
डॉसन, जूली, और क्रिस्टियन डुडा। 2021. कोविड-19 के बाद की दुनिया में डिजिटल पहचान कैसे जीवन को बेहतर बना सकती है। 14 जनवरी। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://

www.weforum.org/agenda/2021/01/davos-agenda-digital-identity-frameworks/
डीन, पॉल. 2013. ओबामा और रंगभेद. 16 दिसंबर. 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.thesociologicalcinema.com/videos/obama-and-color-blindness.
डीबेनेडिक्टिस, जूलिया ई. 2016. एचबीएस में लैंगिक असमानता से निपटना: एक केस स्टडी। 4 मई। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.thecrimson.com/article/2016/5/4/tacking-gender-inequality-at-hbs/.
Defence.Capital. 2021. लॉ एंड सोसाइटी एलायंस की अध्ययन रिपोर्ट में भारत में कम्युनिस्ट चीन के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव अभियानों का खुलासा हुआ। 4 सितंबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://defence.capital/2021/09/04/law-and-society-alliance-study-report-exposes-communist-chinas-overt-covert-influence-operations-in-india.
डेल्गाडो, रिचर्ड, और जीन स्टेफेंसिक। 2017. क्रिटिकल रेस थ्योरी: एक परिचय। न्यूयॉर्क और लंदन: न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी प्रेस।
डेलिंगपोल, जेम्स। 2021. डेलिंगपोल: देखें कैसे बहादुर डच सांसद ने क्लाउस 'एनाल' श्वाब के ग्रेट रीसेट पर कटाक्ष किया। 23 जुलाई। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.breitbart.com/europe/2021/07/23/delingpole-watch-brave-dutch-mp-skewer-klaus-anal-schwabs-great-reset/.
डेलाचेरी, ओलिवियर। 2017. विश्व आर्थिक मंच ने क्लाउस श्वाब के

साथ बोर्गे ब्रेंडे को अध्यक्ष के नए पद पर नियुक्त करने की घोषणा की। 15 सितंबर। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया। https://talent4boards.com/world-economic-forum-announces-borge-brende-new-role-president-alongside-klaus-schwab-executive-chairman/
देसाई, रोनक डी. 2015. प्रधानमंत्री मोदी का कार्यालय में पहला वर्ष: एक रिपोर्ट कार्ड. 26 मई. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.belfercenter.org/publication/prime-minister-modis-first-year-office-report-card.
देशपांडे, अश्विनी. 2018a. यूके में जाति: भेदभाव से इनकार करना समाधान नहीं है. 5 अगस्त. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://thewire.in/caste/caste-discrimination-uk-denial-equality.
——. 2018. “भारत में योग्यतावाद और सकारात्मक कार्रवाई।” हार्वर्ड चाइना फंड। 8 मई। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://hcf.fas.harvard.edu/wp-content/uploads/2018/05/Deshpande_Shanghai.pdf.
धर्मपाल. 2003. भारत की पुनर्खोज: निबंध और भाषणों का संग्रह, 1956-1998. मसूरी: हिमालय के एकीकृत विकास के लिए सोसायटी।
1983. सुंदर वृक्ष: अठारहवीं शताब्दी में स्वदेशी भारतीय शिक्षा। मापुसा: गोवा।
धर्मसिरी, गुनापाला। 1988. ईश्वर की ईसाई अवधारणा की बौद्ध आलोचना। एंटिओक, कैलिफोर्निया: गोल्डन लीव्स पब्लिशिंग।
धवन, हिमांशी। 2021. ‘परिवार नियोजन की अवधारणा का प्रवर्तक इस्लाम है… और यह एक मिथक है कि भारत में बहुविवाह व्यापक रूप

से प्रचलित है'। 25 फरवरी। 15 मई, 2022 को प्राप्त। https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/the-interviews-blog/islam-is-the-pioneer-of-the-concept-of-family-planning-and-it-is-a-myth-that-polygamy-is-rampant-in-india/.
ढिल्लों, दिलशेर। 2018. बिल गेट्स ने लोगों के उंगलियों के निशान और आंखों की पुतलियों को स्कैन करके प्रत्येक नागरिक का डेटाबेस बनाने की भारत की योजना का समर्थन किया। 4 मई। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.insider.com/bill-gates-denies-biometric-id-breaches-human-rights-2018-5.
डायमंड, लैरी, और ओरविल शेल। 2018. चीन का प्रभाव और अमेरिकी हित: रचनात्मक सतर्कता को बढ़ावा देना। स्टैनफोर्ड, कैलिफोर्निया: हूवर इंस्टीट्यूशन प्रेस। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/00_diamond-schell_fullreport_2ndprinting_web-compressed.pdf.
डिएन्जेलो, रॉबिन। 2018. श्वेत नाजुकता। बोस्टन: बीकन प्रेस।
डिएन्जेलो, रॉबिन। 2011. "श्वेत नाजुकता।" इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी 3 (3): 54-70।
दीया टीवी. 2021. एक्सक्लूसिव: सांता क्लारा काउंटी मानवाधिकार आयोग में जाति पर बहस | दीया टीवी. 30 अप्रैल. https://www.youtube.com/watch?v=9b6KJptrArU.
डिज़िक्स, पीटर. 2020. क्या लोकतंत्र संकट में है? 30 अक्टूबर. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://news.mit.edu/2020/democracy-distress-starr-1030.

डोलन, केरी ए. 2015. मार्क ज़करबर्ग बताते हैं कि चैन ज़करबर्ग इनिशिएटिव एक धर्मार्थ संस्था क्यों नहीं है। 4 दिसंबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.forbes.com/sites/kerryadolan/2015/12/04/mark-zuckerberg-explains-why-the-chan-zuckerberg-initiative-isnt-a-charitable-foundation/?sh=19fc033370c5.
डोनोवन, जोन, और जेनिफर निल्सन। 2021. छिपा हुआ विज्ञान: यान रिपोर्ट। 3 जनवरी। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://mediamanipulation.org/case-studies/cloaked-science-yan-reports.
डफ़र्टी, माइकल ब्रेंडन। 2018. द चर्च ऑफ़ ग्रीवेंस। 14 मई। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.nationalreview.com/magazine/2018/05/14/victim-mentality-identity-politics-dominate-modern-left/.
डी'सूज़ा, फेय. 2020. पास द माइक - सूरज येंगडे जाति क्यों मायने रखती है इस पर | फेय डी'सूज़ा. 6 अक्टूबर. 15 फरवरी, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.youtube.com/watch?v=nhBAV1XbDL8.
दुबे, आशुतोष जे. 2020. यह घटना दिल्ली के अशोका विश्वविद्यालय में घटी | अशोका विश्वविद्यालय का पर्दाफाश। 25 सितंबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.naradasbuzz.com/this-incident-happened-at-ashoka-university-in-delhi-ashoka-university-exposed.
डफी, एविटा। 2021. स्नैपचैट एक ट्रांसजेंडर प्रचार और ग्रूमिंग मशीन

है। 27 फरवरी। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://thefederalist.com/2021/02/27/snapchat-is-a-transgender-propaganda-and-grooming-machine/
ईकिन, एमिली। 2001. हार्वर्ड का प्राइज़ कैच, एक डेल्फ़िक पोस्टकोलोनियलिस्ट। 17 नवंबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.nytimes.com/2001/11/17/arts/harvard-s-prize-catch-a-delphic-postcolonialist.html.
एबरहार्ट, क्रिस्टोफर। 2021. नस्लवाद-विरोधी लेखिका ने अमेरिका में जागरूकता बढ़ने के साथ ही अपने भाषणों की फीस दोगुनी कर दी: 'श्वेत नाजुकता' की लेखिका रॉबिन डिएन्जेलो प्रति भाषण औसतन 14,000 डॉलर लेती हैं और सालाना 728,000 डॉलर कमाती हैं। 2 जुलाई। 30 अप्रैल, 2022 को देखा गया। https://www.dailymail.co.uk/news/article-9749517/An-anti-racist-author-Robin-DiAngelo-makes-728K-year-speaking-engagements.html.
एगेलिंग, जूलियस। 1900. शतपथ ब्राह्मण भाग V. ऑक्सफोर्ड: क्लेरेंडन प्रेस।
एलिसी पैलेस, 2020. अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई - गणतंत्र की सक्रियता: गणतंत्र के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन का अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई पर भाषण। 2 अक्टूबर। 30 अप्रैल, 2022 को देखा गया। https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/10/02/fight-against-separatism-the-republic-in-action-speech-by-emmanuel-macron-president-of-the-republic-on-the-fight-against-separatism.en.

जबरन मध्यस्थता समाप्त करो। 2022. थेनमोझी सौंदराजन के साथ जातिगत भेदभाव पर एक वार्तालाप। 19 अप्रैल। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.youtube.com/watch?v=rXyzbWAuPWQ.
इक्वालिटी लैब्स. 2018बी. संयुक्त राज्य अमेरिका में जाति - समीक्षाएँ. 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.equalitylabs.org/castesurvey/#reviews.
——. 2018a. मिशन. 15 फरवरी, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.equalitylabs.org/mission.
——. 2020. हम होली को क्यों ना कहते हैं? जातिवाद को चुनौती देने के लिए एक मार्गदर्शिका। https://www.equalitylabs.org/mission पर उपलब्ध।
——. 2020. हम होली को क्यों नकारते हैं? जातिवाद को चुनौती देने के लिए एक मार्गदर्शिका। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.kractivist.org/why-do-we-say-no-to-holi-a-guide-to-challenge-casteism/.
एराली, अब्राहम। 2007. द मुगल वर्ल्ड। नई दिल्ली: पेंगुइन बुक्स।
ईटी ब्यूरो. 2020. असम एनआरसी डेटा: विप्रो का कहना है कि अक्टूबर 2019 के बाद आईटी सेवाओं का अनुबंध नवीनीकृत नहीं किया गया। 13 फरवरी। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://economictimes.indiatimes.com/tech/ites/assam-nrc-data-wipro-says-it-services-contract-not-renewed-after-october-2019/articleshow/74100062.cms.
इवान. 2015. एल, जी, बी, टी, क्यू, क्यू, आई, ए... इन सभी अक्षरों का क्या अर्थ है? 8 जुलाई. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया.

http://queergrace.com/letters/.
इवांस, राहेल, सबरीना विलमर, निक बेकर और ब्रैंडन कोचकोडिन। 2017. ब्लैक रॉक और वैनगार्ड 20 ट्रिलियन डॉलर का प्रबंधन करने से एक दशक से भी कम दूर हैं। 4 दिसंबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.bloomberg.com/news/features/2017-12-04/blackrock-and-vanguard-s-20-trillion-future-is-closer-than-you-think.
ईडब्ल्यूटीएन ग्लोबल कैथोलिक नेटवर्क। 2003. बिशप्स कॉन्फ्रेंस इंडिया - 6. 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.ewtn.com/catholicism/library/bishops-conference-india--6-8243.
FCCED. 2020. अमेरिकी शिक्षा विभाग हार्वर्ड और येल को मिले लाखों डॉलर के विदेशी दान की जांच कर रहा है। 17 मार्च। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://fcced.com/doj-probes-foreign-donations-harvard-yale-173201632/
फेल्डशर, करेन। 2014. पूर्व छात्रा स्वाति पिरामल और परिवार के उपहार ने एचएसपीएच-भारत के नए सहयोग को प्रेरित किया। 31 मार्च, 2022 को प्राप्त किया गया। https://www.hsph.harvard.edu/magazine/magazine_article/gift-from-alumna-swati-piramal-and-family-inspires-new-hsph-india-collaborations/.
फेरलाज़ो, लैरी। 2019. जब लोग कहते हैं कि वे नस्ल नहीं देखते, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या वे मुझे नहीं देखते। 17 सितंबर। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.edweek.org/teaching-learning/opinion-when-people-say-they-

dont-see-race-i-ask-them-if-they-dont-see-me/2019/09.
फील्ड, ऐनी। 2019. ओमिडयार नेटवर्क की ल्यूमिनेट स्पिनऑफ कंपनी, हमले के तहत लोकतंत्रों की रक्षा करना चाहती है। 31 जनवरी। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.forbes.com/sites/annefield/2019/01/31/omidyar-networks-luminate-spinoff-seeks-to-protect-democracies-under-attack/?sh=580d917164dc.
फील्ड, एरिका, रोहिणी पांडे, नतालिया रिगोल, सिमोन शैनर और चैरिटी ट्रायर मूर। 2021c. अपने दम पर: महिलाओं के वित्तीय नियंत्रण को मजबूत करने से श्रम आपूर्ति और लैंगिक मानदंडों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जुलाई। 15 मई, 2022 को देखा गया। https://egc.yale.edu/her-account.
एरिका फील्ड, सीमा जयचंद्रन और रोहिणी पांडे। 2010. "क्या पारंपरिक संस्थाएँ महिला उद्यमिता को बाधित करती हैं? भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण पर एक क्षेत्रीय प्रयोग।" महिला एवं सार्वजनिक नीति कार्यक्रम, हार्वर्ड कैनेडी स्कूल। मई। 31 मार्च, 2022 को प्राप्त किया गया। https://wappp.hks.harvard.edu/files/wappp/files/entrepreneur.pdf.
फाइनेंशियल एक्सप्रेस. 2018. टाटा ट्रस्ट्स द्वारा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को दिए गए 50 मिलियन डॉलर के उपहार की जांच चल रही है. 26 मई. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.financialexpress.com/industry/50-million-gift-from-tata-trusts-to-harvard-business-school-under-scrutiny/1181574/.

फिश, इसहाक स्टोन। 2018. ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन से हुआवेई के आश्चर्यजनक संबंध। 7 दिसंबर। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.washingtonpost.com/opinions/2018/12/08/chinese-companys-surprising-ties-brookings-institution/.
——. 2019. बीजिंग की वीज़ा 'व्हाइटलिस्ट' में शामिल होने के लिए चीन विशेषज्ञों को क्या करना होगा। 5 सितंबर। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/09/05/what-china-experts-have-do-get-beijings-visa-whitelist/.
फ्लेचर, एरिन के., रोहिणी पांडे, और चैरिटी ट्रायर मूर। 2017. “भारत में महिलाएं और काम: वर्णनात्मक साक्ष्य और संभावित नीतियों की समीक्षा।” हार्वर्ड कैनेडी स्कूल। 30 दिसंबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://research.hks.harvard.edu/publications/getFile.aspx?Id=1624.
फुलर, रोज़लिन। 2021. नागरिक समाज पर अरबपतियों का कब्ज़ा। 29 जनवरी। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.spiked-online.com/2021/01/29/the-billionaire-takeover-of-civil-society/
गणेश एन. 2015बी. कुंभ मेले में कंडोम विवाद छाया हुआ है, पवित्र त्योहार के दौरान 'मांग पूरी करने' के लिए 5.40 लाख कंडोम मंगवाने का दावा किया गया है। 8 जुलाई। 31 मार्च, 2022 को प्राप्त किया गया। http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-3154032/AIDS-prevention-activists-deny-condom-supply-surge-linked-Kumbh-Mela.html.

——. 2015a. कंडोम की आपूर्ति में अचानक हुई वृद्धि की खबरों से कुंभ मेला आयोजक परेशान। 9 जुलाई। 31 मार्च, 2022 को देखा गया। http://indiatoday.intoday.in/story/condom-supply-surge-vexes-kumbh-planners-mela/1/450131.html
गांगुली, श्रेया। 2019. चीन स्थित किमिंग वेंचर पार्टनर्स ने प्रतिलिपी में 15 मिलियन डॉलर के फंडिंग राउंड का नेतृत्व किया। 6 जून। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://inc42.com/buzz/china-based-qiming-venture-partners-invests-in-pratilipi/
गरिमेला, किरण और डीन एक्लेस। 2020. राजनीतिक समूहों में चित्र और गलत सूचना: भारत में व्हाट्सएप से साक्ष्य। 7 जुलाई। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://misinforeview.hks.harvard.edu/article/images-and-misinformation-in-political-groups-evidence-from-whatsapp-in-india/
गार्लेन, जूली सी. 2018. “निर्दोषता पर सवाल उठाना: “बचपन” एक बहिष्करणकारी सामाजिक प्रथा के रूप में।” 22 नवंबर। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0907568218811484.
गेट्स, गैरी जे. 2011. कितने लोग लेस्बियन, गे, बाईसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर हैं? अप्रैल। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://williamsinstitute.law.ucla.edu/publications/how-many-people-lgbt/.

गेटलमैन, जेफ़री, और ईव लियोन्स। 2018बी। भारत में तीसरे लिंग की विचित्र स्थिति। 17 फ़रवरी। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.nytimes.com/2018/02/17/style/india-third-gender-hijras-transgender.html.
घोरपड़े, अर्जुन. 2011. चोखामेला. औरंगाबाद: बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय।
घुरये, जी.एस. 1959. अनुसूचित जनजातियाँ। द्वितीय संस्करण। बॉम्बे: पॉपुलर बुक डिपो। गिब्सन, एबिगेल, जॉन फी, कल्पना जैन और ऐन पीटर्स। 2021. धर्म, लोकलुभावनवाद और मीडिया। 15 मार्च। 31 मार्च, 2022 को प्राप्त किया गया। https://pulitzercenter.org/blog/religion-populism-and-media.
ग्लोबल न्यूज़. 2020. कोरोनावायरस: ट्रूडो ने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में कहा कि महामारी ने "पुनर्स्थापन का अवसर" प्रदान किया। 30 सितंबर। 30 अप्रैल, 2022 को देखा गया। https://www.youtube.com/watch?v=n2fp0Jeyjvw.
गोकोव्स्की, एंथोनी। 2017. हार्वर्ड ने रूढ़िवादी वेबसाइटों को 'फर्जी समाचार' कहते हुए सूची जारी की। 10 मार्च। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.campusreform.org/?ID=8895.
गोदरेज इंडिया कल्चर लैब. 2019a. इंडिया कल्चर लैब: LGBTQ. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://indiaculturelab.org/lgbtq.
——. 2019b. द इंडिया कल्चर लैब नेशनल फेलोशिप. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://indiaculturelab.org/nationalfellowship.

गोलेमैन, डैनियल। 1976. “ध्यान और चेतना: मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक एशियाई दृष्टिकोण।” अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकोथेरेपी 30 (1): 41–54.
——. 1971. “मेटा-थेरेपी के रूप में ध्यान: चेतना की प्रस्तावित पाँचवीं अवस्था की ओर परिकल्पनाएँ।” ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी एसोसिएशन। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.atpweb.org/jtparchive/trps-03-71-01-001.pdf.
——. 1972a. “बुद्ध ध्यान और चेतना की अवस्थाओं पर, भाग 1: शिक्षाएँ।” ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी एसोसिएशन। 31 मार्च, 2022 को प्राप्त किया गया।
——. 1972b. “बुद्ध ध्यान और चेतना की अवस्थाओं पर, भाग II: ध्यान तकनीकों का एक वर्गीकरण।” ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी एसोसिएशन। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.atpweb.org/jtparchive/trps-04-72-02-151.pdf.
गोलिकेरी, प्रियंका, और सतीश जॉन। 2011. यदि आपके पास मानविकी नहीं है, तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, वित्त में मूल्यों का एक मजबूत ढांचा नहीं होगा। 31 जनवरी। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.dnaindia.com/business/interview-if-you-don-t-have-humanities-the-sciences-tech-finance-won-t-have-a-strong-framework-of-values-1501124.
गॉर्डन, रॉबर्ट सी. 2007. एमर्सन और भारत का प्रकाश। नई दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट।
गोस्वामी, देविका। 2020. क्या अशोक राजनीतिक विमर्श के लिए एक सुरक्षित स्थान है? 1 फरवरी। 15 मई, 2022 को देखा गया। http://

edictarchive.the-edict.in/index.php/2020/02/01/why-ashoka-needs-to-be-more-inclusive-of-its-political-right/
गोयल, एस.आर. 1987. भारतीय बौद्ध धर्म का इतिहास। मेरठ: कुसुमांजलि प्रकाशन। गुरुत्वाकर्षण। 2017. सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करने वाली भीड़ ने येल प्रोफेसर से गिड़गिड़ाकर माफी मांगने की मांग की। 6 मार्च। 30 अप्रैल, 2022 को देखा गया। https://www.youtube.com/watch?v=iAr6LYC-xpE.
ग्रीनवाल्ड, ग्लेन। 2021. पियरे ओमिडयार द्वारा फेसबुक "व्हिसलब्लोअर" अभियान के वित्तपोषण से बहुत कुछ पता चलता है। 25 अक्टूबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://greenwald.substack.com/p/pierre-omidyars-financing-of-the.
ग्रे, सैंड्रा जे. 2013. “सक्रिय शिक्षाविद: भविष्य क्या?” पॉलिसी फ्यूचर्स इन एजुकेशन 11 (6): 700-711. doi:https://doi.org/10.2304/pfie.2013.11.6.701.
ग्रॉसमैन, रॉन। 1999. इस लेखन प्रतियोगिता में, बुरा होना अच्छा है। 28 जनवरी। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.chicagotribune.com/news/ct-xpm-1999-01-28-9901280242-story.html.
गल्फ न्यूज. 2017. लक्ष्मी मित्तल ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय को 25 मिलियन डॉलर दान किए. 17 अक्टूबर. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://gulfnews.com/world/asia/india/lakshmi-mittal-donates-25m-to-harvard-university-1.2107905.

Gupt, Harihara Prasad. 1986. Vaishnava Kabir. Allahabad: Bhasha Sahitya Samsthan. Gupta, Arvind. 2015. Book Review : Prof R Vaidyanathan, Caste as Social Capital, Westland Books, 2019, Chennai, PP. 131. 15 April. Accessed March 31, 2022. https://www.vifindia.org/bookreview/2019/april/15/caste-as-social-capital.
गुप्ता, दीपांकर। 2000. जाति का विश्लेषण - भारतीय समाज में पदानुक्रम और अंतर को समझना। नई दिल्ली: सेज।
गुप्ता, सुरभि। 2020. 'यह पुस्तक मेरी बेचैनी का परिणाम है... मेरी शोक की पुस्तक'। 11 नवंबर। 15 मई, 2022 को देखा गया। https://indianexpress.com/article/books-and-literature/aparna-vaidik-interview-7047876/
हैबरमैन, डेविड एल. 2003. रूपा गोस्वामी की भक्तिरसमृतसिंधु। नई दिल्ली: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र।
हैनकॉक, इयान एफ. 1987. परिया सिंड्रोम: जिप्सी गुलामी और उत्पीड़न का एक विवरण। एन आर्बर, एमआई: कारोमा पब्लिशर्स।
हनीफा, अजीज। 2020. भारत के विवादास्पद नागरिकता कानून 'चिंताजनक' हैं, हिंदू अमेरिकी आयुक्त कहते हैं। 11 मार्च। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.indiaabroad.com/india/india-s-controversial-citizenship-laws-are-troubling-says-hindu-american-commissioner/article_865fadb8-63fa-11ea-99dd-27ca3a74507c.html.
हैनसन, मेलानी। 2022. छात्र ऋण ऋण सांख्यिकी। 1 मार्च। 31 मार्च,

2022 को एक्सेस किया गया। https://educationdata.org/student-loan-debt-statistics.
हार्डग्रेव जूनियर, रॉबर्ट एल. 1969. तमिलनाडु के नाडार: परिवर्तन में एक समुदाय की राजनीतिक संस्कृति। बर्कले और लॉस एंजिल्स: कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय प्रेस।
हारमोन, ग्रेस। 2020. एवरग्रीन में आधे से अधिक छात्र LGBTQ या प्रश्न करने वाले के रूप में पहचान रखते हैं। 18 फरवरी। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.knkx.org/youth-education/2020-02-18/more-than-half-of-the-student-body-at-evergreen-identifies-as-lgbtq-or-questioning.
हर्षा, दान. 2019. राष्ट्रीय चुनावों में भारत की बहुलवादी राजनीतिक व्यवस्था दांव पर. 13 मई. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.hks.harvard.edu/faculty-research/policy-topics/politics/indias-pluralistic-political-system-stake-national.
हार्टोकॉलिस, एनेमोना। 2022. एक मुकदमे में हार्वर्ड पर एक प्रोफेसर द्वारा यौन उत्पीड़न की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया। 8 फरवरी। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.nytimes.com/2022/02/08/us/harvard-sexual-harassment-lawsuit.html.
हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। 2021. क्या ऐतिहासिक सामाजिक अन्याय को क्षतिपूर्ति के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है? 2 मार्च। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://hbswk.hbs.edu/item/cold-call-can-historic-social-injustices-be-addressed-

through-reparations.
हार्वर्ड सेंटर फॉर पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट स्टडीज। 2021. ग्रामीण उत्तर भारत में लैंगिक मानदंड, खाना पकाने के लिए स्वच्छ, सरकार द्वारा अनुमोदित ईंधन स्रोतों को अपनाने की धीमी गति में भूमिका निभा सकते हैं। 27 अक्टूबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.hsph.harvard.edu/population-development/2021/10/27/gender-norms-in-rural-north-india-may-play-role-in-slow-adoption-of-cleaner-government-endorsed-fuel-sources-for-cooking/.
हार्वर्ड ग्लोबल. 2017a. भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.harvardglobal.org/our-projects/public-health-center-india.
——. 2017b. वेयर वी ऑपरेट : इंडिया. एक्सेस किया गया मई 15, 2022. https://www.harvardglobal.org/where-we-operate/india.
हार्वर्ड कैनेडी स्कूल - महिला एवं सार्वजनिक नीति कार्यक्रम। 2014. WAPP के बारे में। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://wappp.hks.harvard.edu/about-wappp.
हार्वर्ड कैनेडी स्कूल। 2021ए। बे एरिया डेवलपमेंट एंड इनोवेशन रिसर्च प्रोजेक्ट। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://ash.harvard.edu/bay-area-development-and-innovation-research-project.
——. 2016बी. चीन परोपकार. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया

गया. https://ash.harvard.edu/china-philanthropy-project.
——. 2015a. चीन कार्यक्रम. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://ash.harvard.edu/china-programs.
——. 2021b. सीआईडी/मैल्कम वीनर सेंटर असमानता अनुसंधान पर संयुक्त पुरस्कार। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.hks.harvard.edu/centers/cid/about-cid/news-announcements/joint-award-inequality-research.
——. 2015b. सम्मेलन. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://ash.harvard.edu/china-conferences.
——. 2016a. डैलियो छात्रवृत्ति. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://ash.harvard.edu/dalio-fellowship.
——. 2017a. गाइड टू सेंटर एंड प्रोग्राम फेलो। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.hks.harvard.edu/research-insights/library-knowledge-services/research-services-policies/research-policies/guide-hks.
——. 2019b. हार्वर्ड कैनेडी स्कूल प्रवेश ब्लॉग. 16 दिसंबर. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://hksadmissionblog.tumblr.com/post/189701921903/fellowshipscholarship-series-public-service.
——. 2019a. हार्वर्ड कैनेडी स्कूल ने क्रोएशिया में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण और विकास के लिए नए कोष की स्थापना की। 17 जनवरी। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://

www.hks.harvard.edu/announcements/harvard-kennedy-school-new-fund-support-training-civil-servants.
——. 2016c. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नोट प्रतिबंध न तो बुद्धिमानी भरा है और न ही मानवीय: अमर्त्य सेन ने एनडीटीवी को बताया। 30 नवंबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.hks.harvard.edu/centers/mrcbg/programs/growthpolicy/pm-narendra-modis-notes-ban-neither-intelligent-nor-humane.
——. 2018. सलिल शेट्टी. 15 अक्टूबर. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://carrcenter.hks.harvard.edu/people/salil-shetty.
——. 2017b. श्वाब का विएनर व्याख्यान नई औद्योगिक क्रांति की चुनौतियों और अवसरों की ओर इशारा करता है। 2 अक्टूबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.hks.harvard.edu/more/alumni/alumni-stories/collaboration-fractured-world-klaus-schwab-mcmpa-speaks-harvard-kennedy.
——. 2017c. Shivshankar Menon. 6 January. Accessed May 15, 2022. https://www.belfercenter.org/person/shivshankar-menon-0.
——. 2019c. “छात्र वित्तीय सेवाएँ: आपकी शिक्षा का वित्तपोषण।” हार्वर्ड कैनेडी स्कूल, छात्र वित्तीय सेवाएँ। जुलाई। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/student%20financial%20services/

files/282548%20HKS%20Finance%20Education_WEB.pdf.
——. 2015सी. शिक्षण. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://ash.harvard.edu/china-programs-executive-education.
हार्वर्ड लॉ रिव्यू. 2021. अधिवास से प्रभुत्व तक: कश्मीर में भारत का उपनिवेशवादी एजेंडा. 10 मई. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://harvardlawreview.org/2021/05/from-domicile-to-dominion-indias-settler-colonial-agenda-in-kashmir/.
हार्वर्ड लॉ स्कूल। 2018. “पूर्व छात्राओं के 65 वर्ष पूरे होने का जश्न, 14-16 सितंबर, 2018, वक्ताओं की जीवनियाँ।” हार्वर्ड लॉ स्कूल। 31 मार्च, 2022 को प्राप्त किया गया। https://hls.harvard.edu/content/uploads/2018/08/Speaker-Bios-8.31.pdf.
हार्वर्ड स्क्वायर लाइब्रेरी। 2017. राल्फ वाल्डो एमर्सन की जीवंत विरासत। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.harvardsquarelibrary.org/collection/living-legacy-ralph-waldo-emerson/
हार्वर्ड टी.एच. चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ। 2021ए। 'मानवता के लिए एक उत्प्रेरक' इसाबेल विल्करसन के साथ एक वार्तालाप। 1 फरवरी। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://theforum.sph.harvard.edu/events/catalyst-for-humanity/
——. 2018. मूल निवासी भूमि और लोगों की स्वीकृति। 24 मई। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://

www.hsph.harvard.edu/social-and-behavioral-sciences/2018/05/24/acknowledgment-of-native-land-and-peoples/.
——. 2019b. इंडिया रिसर्च सेंटर - साक्ष्य-आधारित सार्वजनिक नीति और अभ्यास। 16 जनवरी। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.hsph.harvard.edu/india-center/research/initiative-on-evidence-based-public-policy-and-practice/.
——. 2017. भारत अनुसंधान केंद्र - भारत में स्वास्थ्य में सुधार। 15 दिसंबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.hsph.harvard.edu/india-center/improving-health-in-india/.
——. 2019a. इंडिया रिसर्च सेंटर - हमारे दाता। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.hsph.harvard.edu/india-center/press-releases/.
——. 2016. भारत अनुसंधान केंद्र. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.hsph.harvard.edu/india-center/.
——. 2021b. भारत का कोविड-19 संकट: प्रकार, टीके और उछाल। 13 मई। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://theforum.sph.harvard.edu/events/indias-covid-19-crisis/.
हार्वर्ड विश्वविद्यालय। 2017b. “एक कलाकार का सामाजिक ताना-बाना” – 2017 साईं महिंद्रा व्याख्यान पर चिंतन। 13 अप्रैल। 31 मार्च, 2022 को प्राप्त किया गया। https://

mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/2017/04/the-social-texture-of-an-artist-reflections-on-the-2017-sai-mahindra-lecture/.
——. 2015b. “जल, वन और भूमि हमारी है”: भारतीय वन में सामूहिक कार्रवाई और संपत्ति। 14 जनवरी। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/event/south-asia-without-border-seminar-2/.
——. 2013a. 2013 प्रसाद फेलोशिप लंचियन. 1 अक्टूबर. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/2013/10/2013-prasad-fellowship-luncheon/.
——. 2014डी. 2014 प्रसाद फेलोशिप. 16 मई. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/2014/05/2014-prasad-fellowships/.
——. 2019e. हार्वर्ड की एक टीम ने भारत के मणिपुर में एक शैक्षिक आउटरीच कार्यक्रम को साकार किया। 20 फरवरी। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/2019/02/harvard-educational-outreach-manipur-india/.
——. 2018j. “फरवरी मेरिटोक्रेसी कार्यशाला के लिए सार।” हार्वर्ड विश्वविद्यालय। मई। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://hcf.fas.harvard.edu/wp-content/uploads/2018/05/Abstracts-for-Feb-Meritocracy-

Workshop.pdf.
——. 2020h. भूमि और लोगों की स्वीकृति। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://hunap.harvard.edu/land-acknowledgement.
——. 2022ए. सलाहकार परिषद. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/mittalinstitute-advisory-council/.
——. 2012a. एंथनी साइच अमेरिकी-चीनी संबंधों पर || अमेरिकी वार्तालाप अनिवार्य। 12 जून। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.youtube.com/watch?v=GaqIXrpVZBU.
——. 2022बी. विधानसभा चुनाव और उसके बाद. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/event/assembly-elections-and-after/.
——. 2020e. ब्रेकिंग द मोल्ड: समकालीन भारत में नारी शक्ति और उससे आगे। 2 जनवरी। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/event/breaking-the-mould-girl-power-and-beyond-in-contemporary-india/.
——. 2021a. बौद्ध भिक्षुणियाँ और जैव विविधता: शीतकालीन छात्र अनुदान रिपोर्ट। 13 मई। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/2021/05/buddhist-nuns-and-biodiversity-winter-student-grant-

report/.
——. 2020डी. टेक टाउन हॉल में जाति. 14 अगस्त. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/event/caste-in-tech-town-hall/.
——. 2020c. शहर और बस्तियाँ: उपमहाद्वीप में शहरीकरण पर विभाजन का प्रभाव। 28 जुलाई। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/partition-cities-and-settlements/.
——. 2020b. क्राउडसोर्सिंग मेमोरीज. 4 अगस्त. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/partition-crowdsourcing-memories/.
——. 2016a. भारतीय लोकतंत्र में विकास और राजनीति। 1 दिसंबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/event/armed-politics-violence-order-and-the-state-in-southern-asia/.
——. 2018i. फॉल क्लास: समकालीन विकासशील देश: दुर्गम सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के लिए उद्यमशीलता समाधान (SW47). 14 अगस्त. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/2018/08/fall-class-contemporary-developing-countries-entrepreneurial-solutions-to-intractable-social-and-

economic-problems-sw47/.
——. 2017d. फिल्म स्क्रीनिंग और दीपा मेहता के साथ प्रश्नोत्तर सत्र: हिंसा की संरचना। 1 फरवरी। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/event/film-screening-and-qa-with-deepa-mehta-anatomy-of-violence/.
——. 2013बी. वित्तीय समावेशन: इसकी चुनौतियाँ और संभावनाएँ। 5 दिसंबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/event/social-enterprise-seminar-2/.
——. 2021g. “वित्तीय रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2021.” हार्वर्ड विश्वविद्यालय. अक्टूबर. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://finance.harvard.edu/files/fad/files/fy21_harvard_financial_report.pdf.
——. 2019f. फ्रैक्टल शहरीकरण: उदारीकरण वाले भारत में स्थानिक अलगाव। 12 नवंबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/event/fractal-urbanization-spatial-segregation-in-liberalizing-india/.
——. 2018h. निःशुल्क ऑनलाइन edX पाठ्यक्रम: “उभरती अर्थव्यवस्थाओं में उद्यमिता”. 27 फ़रवरी. 31 मार्च, 2022 को देखा गया. https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/2018/02/entrepreneurship-emerging-economies/.
——. 2016बी. लिंग चुनौतियाँ. 14 सितंबर. 31 मार्च, 2022 को

एक्सेस किया गया. https://
mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/event/gender-
challenges/.
——. 2018e. भारत में किशोरों की लिंग, हिंसा और भेद्यताएँ। 17
सितंबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://
mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/event/gender-
violence-and-vulnerabilities-of-adolescents-in-india/.
——. 2019j. मानवता की सेवा के लिए विज्ञान का उपयोग: टाटा
इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक्स एंड सोसाइटी का विजन। 25 फरवरी। 31
मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://
mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/event/
harnessing-science-serve-humanity/.
——. 2014f. हार्वर्ड के संकाय सदस्यों ने मुंबई के नेताओं के साथ
कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के सबक साझा किए। 12 फरवरी। 31
मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://
mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/2014/02/
harvard-faculty-share-corporate-social-responsibility-
lessons-with-leaders-in-mumbai/.
——. 2013डी. हार्वर्ड जेंडर वायलेंस प्रोजेक्ट: जेंडर जस्टिस और
क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस. 10 जून. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस
किया गया. https://
mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/gender-
violence-project_delhi-event/.
——. 2018d. भारत में हार्वर्ड का नया “दूतावास”. 22 मार्च. 31
मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://

mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/2018/03/harvards-new-embassy-in-india/.
——. 2015सी. बर्मा में स्वास्थ्य और मानवाधिकार। 16 जनवरी। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/event/burma-panel/.
——. 2019g. अमेरिका पर जाति का प्रभाव कैसे पड़ता है? 27 मार्च। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/2019/03/caste-impact-america/.
——. 2018a. इंडिया इंटरनेशनल सेंटर: एनेक्स बिल्डिंग: लेक्चर रूम-I. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/events/venue/india-international-center-annexe-building-lecture-room-i.
——. 2018b. भारत सेमिनार श्रृंखला: भारत में कोयले का अतीत, वर्तमान और संभावित भविष्य। 1 अगस्त। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/2018/08/the-past-present-and-future-of-coal-in-india/.
——. 2014e. अनौपचारिक श्रमिक, उद्यम और शहर: दक्षिण एशिया में अनौपचारिकता का समाधान। 3 मार्च। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/sai-symposium-2014-informal-economy/.

——. 2021b. दक्षिण एशियाई राजनीति पर संयुक्त सेमिनार अभिलेखागार। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/events/topic/joint-seminar-on-south-asian-politics/.
——. 2015a. दिल्ली में कुंभ मेला पुस्तक विमोचन. 20 अगस्त. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. http://southasiainstitute.harvard.edu/kumbh-mela/post/kumbh-mela-book-launch-in-delhi/7.
——. 2021f. कुशाग्र नयन बजाज का एलएमएसएआई को दिया गया नया उपहार दक्षिण एशियाई विद्वानों के लिए अवसरों को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाता है। 13 अक्टूबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/2021/10/bajaj-fellowship/.
——. 2020a. पीछे मुड़कर देखना, भविष्य को सूचित करना: ब्रिटिश भारत का 1947 का विभाजन। 4 अगस्त। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/partition-home/.
——. 2012बी. भारत के कुंभ मेले का मानचित्रण. 21 सितंबर. 30 अप्रैल, 2022 को अभिगमित. http://southasiainstitute.harvard.edu/kumbh-mela/.
——. 2019i. मेरिटोक्रेसी: चीन के अतीत और वर्तमान से परिप्रेक्ष्य। 10 दिसंबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/event/

meritocracy-perspectives-from-china-past-and-present/.
——. 2013c. हिंदू, मुसलमान: एक बंगाली कारीगर जाति की दुविधा। 3 सितंबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/event/na-hindu-na-musalman-the-dilemma-of-a-bengali-artisan-caste/.
——. 2019. ओमिडयार ग्रांट फॉर इनोवेटिव सॉल्यूशंस। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/omidyar-grant-for-innovative-solutions/.
——. 2019k. भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुधार: प्रारंभिक कार्यान्वयन से प्राप्त जमीनी सबक। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/event/primary-health-care-reforms-in-india-field-lessons-from-early-implementation/.
——. 2019h. संपत्ति, शक्ति और महिलाएं: लैंगिक समानता के लिए भारतीय सुधारों के सकारात्मक और विकृत परिणाम। 25 अक्टूबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/event/womens-representation-and-resistance-rachel-brule/.
——. 2014a. धर्म और संस्कृति: भारत के कुंभ मेले का मानचित्रण। 10 मार्च। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://web.archive.org/web/20140310060958/http://southasiainstitute.harvard.edu/kumbh-mela/page/

religion-and-culture/.
——. 2016c. एसएआई ने महिला सशक्तिकरण कार्यशाला का आयोजन किया। 3 फरवरी। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/2016/02/womens-empowerment-educational-social-and-economic-solutions/.
——. 2014बी. एसएआई रिसर्च एफिलिएट्स, 2014-2015. 12 अक्टूबर. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/2014/10/sai-research-affiliates-2014-2015/.
——. 2017a. एसएआई ब्रिटिश भारत के विभाजन पर साप्ताहिक सेमिनार श्रृंखला की मेजबानी करेगा। 13 फरवरी। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/2017/02/sai-to-host-weekly-seminar-series-on-partition/.
——. 2019b. सलिल शेट्टी: कश्मीर संकट का विश्लेषण। 12 सितंबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/2019/09/salil-shetty-decoding-kashmir-crisis/.
——. 2017c. आध्यात्मिक पारिस्थितिकी: समकालीन एशिया में स्थिरता और पारगमन। 16 नवंबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://mahindrahumanities.fas.harvard.edu/event/spiritual-ecologies-sustainability-and-transcendence-contemporary-asia.

——. 2019d. डर दूर हो गए हैं: भारत के भील बहुल क्षेत्र में विद्रोही नागरिकता की जड़ों की खोज। 22 अगस्त। 31 मार्च, 2022 को प्राप्त किया गया। https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/event/exploring-roots-insurgent-citizenship-bhil-heartland/.
——. 2018f. मित्तल इंस्टीट्यूट और टाटा ट्रस्ट्स ने भारत में सामाजिक उद्यम साझेदारी शुरू की। 13 फरवरी। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/2018/02/sai-tata-trusts-begin-social-enterprise-partnership-india/.
——. 2021d. मित्तल संस्थान के शीतकालीन 2020 छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता। 7 जनवरी। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/2021/01/the-mittal-institutes-winter-2020-student-grant-recipients/.
——. 2018सी. रोमा कार्यक्रम. 21 फरवरी. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://fxb.harvard.edu/the-roma-program/.
——. 2018g. विश्वास और रचनात्मकता: विकासशील देशों में उद्यमिता को बढ़ावा देना। 15 मार्च। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/event/trust-and-creativity-fostering-entrepreneurship-in-developing-countries/.
——. 2021e. वीएएफ स्पॉटलाइट: कला और कलात्मक अभिव्यक्ति

में लिंग मानदंडों पर बूनु धुंगना। 1 दिसंबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/2021/12/bunu/.
——. 2020f. विजय शेखर शर्मा ने मित्तल संस्थान के लिए नया कोष प्रदान किया। 7 दिसंबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/2020/12/vijay-shekhar-sharma-provides-new-fund/.
——. 2021c. विजिटिंग आर्टिस्ट फेलो प्रगति जैन आज के भारत में एक अभ्यासी कलाकार और महिला होने पर विचार करती हैं। 17 नवंबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/2021/11/pragati-jain/.
——. 2019a. विजिटिंग आर्टिस्ट फेलो प्रदर्शनी स्वागत समारोह: विभाजन परिप्रेक्ष्य। 22 फरवरी। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/event/visiting-artist-fellows-exhibition-2019/.
——. 2019c. सत्ताधारी नेताओं के लिए मतदान: ब्राजील और भारत में राष्ट्रवादी और लोकलुभावन नेतृत्व। 9 सितंबर। 31 मार्च, 2022 को प्राप्त किया गया। https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/event/voting-for-strongmen/.
——. 2020g. वेबिनार: दक्षिण एशिया में कोविड-19 की प्रतिक्रिया। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://

mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/event/webinar-is-the-response-to-covid-19-in-south-asia-adequate-and-proportionate.
——. 2014सी. राजनीति में महिलाएं: भारत का मामला. 15 मई. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/2014/05/women-in-politics-the-case-of-india/.
हार्वर्ड-येनचिंग इंस्टीट्यूट। 2020बी। भारत में चीनी अध्ययन। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.harvard-yenching.org/programs/chinese-studies-in-india/
——. 2020a. हार्वर्ड-येनचिंग संस्थान का इतिहास। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.harvard-yenching.org/history-of-the-harvard-yenching-institute/.
——. 2020सी. चीन में भारतीय अध्ययन। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.harvard-yenching.org/programs/south-asian-studies-in-china-program/.
हावा, गुइलेर्मो एस. 2020ए. चीन में, हार्वर्ड जानबूझकर अनदेखी कर रहा है। 12 फरवरी। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.thecrimson.com/article/2020/2/12/hava-harvard-china-ties/.
——. 2020b. द अदर चान: स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में दान स्वच्छता। 19 अक्टूबर। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.thecrimson.com/column/for-sale/article/2020/10/19/hava-the-other-chan/.

हिगिंस, माइकल। 2021. अल्पसंख्यक प्रोफेसर को योग्यता के आधार पर नियुक्तियाँ करने के कारण अनुदान से वंचित किया गया: 'लोग सोचने से डरते हैं'। 24 नवंबर। 15 फरवरी, 2022 को एक्सेस किया गया। https://nationalpost.com/news/canada/minority-professor-denied-grants-because-he-hires-on-merit-people-are-afraid-to-think.
हिगिंस, रिचर्ड। 2017. थोरो में हार्वर्ड। 29 जून। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://news.harvard.edu/gazette/story/2017/06/near-the-bicentennial-of-thoreaus-birth-a-look-at-his-harvard-years/.
हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन. 2019. डब्ल्यूजीबीएच न्यूज़ “अमेरिका में जाति” पैनल चर्चा, भाग 1. 2 अप्रैल. 15 फरवरी, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.youtube.com/watch?v=NEjfA47QcG0.
हिन्दू जनजागृति समिति. 2014. फोर्ड फाउंडेशन का कांग्रेस, एनएसी, आप के साथ संबंध। 3 मई. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.hindjagruti.org/news/19538.html
हिंदू छात्र परिषद. 2021. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हिंदूफोबिया। 2 फरवरी. 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.hindustudentscouncil.org/open-letter-to-harvard-signatories/
एचकेएस मिसइन्फॉर्मेशन रिव्यू संपादकीय स्टाफ। 2021. खंडन नोट: दुष्प्रचार का प्रसार: एडीओएस और ब्रेकिंग न्यूज़ का रणनीतिक हथियारकरण। 20 दिसंबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। doi:https://doi.org/10.37016/mr-2020-86.

होगलैंड, केट। 2012. ऐश सेंटर: दो वरिष्ठ चीनी अधिकारियों ने ऐश सेंटर में महत्वपूर्ण शोध कार्य किया। 3 फरवरी। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://ash.harvard.edu/news/ash-center-two-senior-chinese-officials-perform-key-research-ash-center.
हॉकिंग, विलियम अर्नेस्ट। 1963. "व्हाइटहेड जैसा कि मैं उन्हें जानता था।" अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड: उनके दर्शन पर निबंध, जॉर्ज एल. क्लाइन द्वारा, 7-17। न्यू जर्सी।
होडर, एलन डी. 2001. थोरो का परमानंद साक्षी। न्यू हेवन, कनेक्टिकट: येल यूनिवर्सिटी प्रेस।
होर्खाइमर, मैक्स। 1982. क्रिटिकल थ्योरी सिलेक्टेड एसेज। न्यूयॉर्क: कंटीन्यूम पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन।
होर्खाइमर, मैक्स, और थियोडोर डब्ल्यू. एडोर्नो। 2002. ज्ञानोदय का द्वंद्व: दार्शनिक अंश। स्टैनफोर्ड, कैलिफोर्निया: स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
होरविट्ज़, जोश। 2017. दलाई लामा की यात्रा एक अमेरिकी कैंपस को विभाजित कर रही है जहाँ 14% छात्र चीन से हैं। 15 जून। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://qz.com/1004386/the-uproar-over-the-dalais-lamas-ucsd-visit-has-unveiled-chinas-meddling-influence-over-foreign-campuses/.
हाउस ऑफ बिलॉन्ग। 2021. बिलॉन्ग समावेशी स्कूल महोत्सव: समावेशी स्कूल क्या है? 21 जुलाई। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.youtube.com/watch?v=UGgIFnDoSSs.
ह्सू, टिफ़नी, डेविड याफ़े-बेलानी और मार्क ट्रेसी। 2020. जेफ़री एपस्टीन ने एमआईटी को 850,000 डॉलर दिए और प्रशासकों को

इसकी जानकारी थी। 10 जनवरी। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.nytimes.com/2020/01/10/business/mit-jeffrey-epstein-joi-ito.html.
आईएएमसी आधिकारिक चैनल। 2022. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में इस्लामोफोबिया की विकृति सबसे घातक रूप ले रही है: प्रो. नोम चोम्स्की। 10 फरवरी। 15 मई, 2022 को देखा गया। https://www.youtube.com/watch?v=hRrPBvWQmq4.
——. 2020. रकीब हमीद नाइक द्वारा 12 दिसंबर, 2019 को संयुक्त राज्य कांग्रेस के समक्ष कश्मीर पर दी गई ब्रीफिंग। 5 मार्च। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.youtube.com/watch?v=ZZZOrzU6pAs.
आईडीएफसी फाउंडेशन. 2016ए. आईडीएफसी फाउंडेशन: अनुदान. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. http://idfcfoundation.com/#grants.
——. 2016b. संयुक्त उद्यम। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। http://idfcfoundation.com/. IDFC संस्थान। 2015. हमारे बारे में - IDFC संस्थान। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.idfcinstitute.org/about/.
——. 2017c. परियोजनाएँ। 15 मई, 2022 को अभिगमित। https://www.idfcinstitute.org/projects/
——. 2017बी. रूबेन अब्राहम - आईडीएफसी संस्थान. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.https://www.idfcinstitute.org/projects/.
——. 2017b. रूबेन अब्राहम - आईडीएफसी संस्थान। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://

www.idfcinstitute.org/about/people/team/reuben-abraham/.
——. 2017a. रूबेन अब्राहम - आईडीएफसी संस्थान। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.idfcinstitute.org/about/people/executive-council/reuben-abraham/
इमाद, सोफिया, हर्ष वर्धन पचीसिया, श्रीधर गणपति, राजेश्वरी परसा और मानवी मेहता। 2021बी. मुंबई के लिए कोविड-19 मृत्यु दर डेटा। 26 मई. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.idfcinstitute.org/blog/2021/may/covid-19-mortality-data-for-mumbai/
स्वतंत्र और जनहितैषी मीडिया फाउंडेशन। 2019a. अनुदान प्राप्तकर्ता पोर्टफोलियो – आईपीएसएमएफ। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://ipsmf.org/grantee-portfolio/
——. 2019सी. दानदाताओं का परिचय। 15 मई, 2022 को अभिगमित।
——. 2019बी. जनादेश. 15 मई, 2022 को अभिगमित. https://ipsmf.org/about-us/the-mandate/.
इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स. 2014. आईएफए के बारे में. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://indiaifa.org/about-us/about-ifa.html.
——. 2021. “इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स: वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021.” इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://indiaifa.org/website/about_ifa/ifa_ar/AnnualReport2020-2021.pdf.

इंडियाकल्चरलैब. 2019. गोदरेज इंडिया कल्चर लैब में फेलोशिप - अभी हमसे जुड़ें! 26 नवंबर. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.youtube.com/watch?v=rEo2WUIe7xI.
——. 2020a. निसाबा गोदरेज और परमेश शाहानी कंपनियों के लिए समावेशी होने की अनिवार्यता पर। 8 जुलाई। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.youtube.com/watch?v=qFV7OiPcRzg.
——. 2020b. द मनी क्वेश्चन | भारत में कलाओं के वित्तपोषण के लिए रणनीतियाँ और मॉडल। 13 जुलाई। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.youtube.com/watch?v=Oeb3Dv5RiZo.
इंडियन एक्सप्रेस. 2015. पार्टी फंडिंग: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार से एफसीआरए लागू करने के लिए लागू प्रणाली के बारे में पूछा. 25 नवंबर. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://indianexpress.com/article/india/india-news-india/party-funding-delhi-hc-asks-govt-about-system-in-place-to-enforce-fcra/.
इन्फिनिटी फाउंडेशन. 2002बी. संगमानी: भारत अध्ययन के लिए एक सम्मेलन. 7 दिसंबर. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.infinityfoundation.com/mandala/s_pr/s_pr_sangamani_frameset.htm.
——. 2002ए. हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इन्फिनिटी फाउंडेशन विजिटिंग प्रोफेसर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://infinityfoundation.com/harvard/.
InfluenceWatch. 2020. Pulitzer Center on Crisis

Reporting. Accessed March 31, 2022. https://www.influencewatch.org/non-profit/pulitzer-center-on-crisis-reporting/.
इंफोसिस. 2020. नंदन नीलेकानी डब्ल्यूईएफ 2020 में. 22 जनवरी. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.youtube.com/watch?v=njqLhi0Ukfc.
चीनी अध्ययन संस्थान। 2021. बरनाली चंदा। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.icsin.org/faculty/barnali-chanda.
——. 2020. प्रताप भानु मेहता. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.icsin.org/faculty/pratap-bhanu-mehta.
इंस्टीट्यूट ऑफ नोएटिक साइंसेज (आईओएनएस)। 2010. ध्यान का शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव। 9 नवंबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.psychologyofjoy.com/the-physical-and-psychological-effect-of-meditation/
आईपीएसएमएफ न्यूज़. 2021. “अनुदान प्राप्तकर्ता वीडियो के माध्यम से सशक्त उपस्थिति बनाते हैं।” आईपीएसएमएफ न्यूज़. मई. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://ipsmf.org/wp-content/uploads/2021/05/IPSMF-Quarterly-Newsletter-April202134121.pdf.
अय्यर, लक्ष्मी, तरुण खन्ना, और आशुतोष वर्शनी। 2011. “भारत में जाति और उद्यमिता।” हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। 18 अक्टूबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। http://www.hbs.edu/

research/pdf/12-028.pdf.
जैक, एंड्रयू। 2021. हार्वर्ड की 'शिक्षण शक्ति' बिजनेस स्कूल को प्रभाव के मामले में अग्रणी बनाती है। 31 मई। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.ft.com/content/beb77be1-f735-45e9-82cb-ec834eb39565.
——. 2018. हार्वर्ड के केस स्टडीज़ आलोचनाओं के घेरे में क्यों हैं. 29 अक्टूबर. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.ft.com/content/0b1aeb22-d765-11e8-a854-33d6f82e62f8.
जैफ्रेलॉट, क्रिस्टोफ़। 2021. नरेंद्र मोदी और हिंदू राष्ट्रवाद। 13 जुलाई। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://carnegieendowment.org/publications/84978.
जैफ्रेलॉट, क्रिस्टोफ़, और शारिक लालीवाला। 2018b. अहमदाबाद के जुहापुरा के अंदर: मुसलमानों के लिए एक बस्ती में रहना कैसा होता है। 12 सितंबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://thewire.in/communalism/juhapura-ahmedabad-ghetto-muslims.
——. 2018. अलग-थलग शहर. 26 मई. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://indianexpress.com/article/opinion/columns/muslims-in-india-hindus-jains-gujarat-love-jihad-5191304/.
जैन, दिनेन्द्र चंद्र। 1980. जैन प्रामाणिक साहित्य में चित्रित प्राचीन भारत का आर्थिक जीवन। वैशाली, बिहार: प्राकृत, जैन विज्ञान और अहिंसा अनुसंधान संस्थान।
जैन, कल्पना। 2019. गौ रक्षक और हिंदू राष्ट्रवाद का उदय। 3 मई।

31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://ksr.hkspublications.org/2019/05/03/cow-vigilantes-and-the-rise-of-hindu-nationalism/.
——. 2019. अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग को हिंदू राष्ट्रवाद को हिंदू धर्म से अलग करना चाहिए। 3 दिसंबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://niemanreports.org/articles/international-reporting-must-distinguish-hindu-nationalism-from-hinduism/.
जैसवाल, सुवीरा। 1998. जाति: उत्पत्ति, कार्य और परिवर्तन का आयाम। नई दिल्ली: मनोहर पब्लिशर्स।
जमील, शाहिद। 2021. भारत वायरस से कैसे बच सकता है। 13 मई। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.nytimes.com/2021/05/13/opinion/india-coronavirus-vaccination.html मजूमदार, आर.सी. 1971. इतिहास।
जैशचिक, स्कॉट। 2021. रैंकिंग में प्रगति खरीदना? 27 अप्रैल। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.insidehighered.com/admissions/article/2021/04/27/study-charges-qs-conflicts-interest-international-rankings.
जे, मार्टिन. 1996. द डायलेक्टिकल इमेजिनेशन. बर्कले, लॉस एंजिल्स और लंदन: यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस.
जयचंद्रन, सीमा, और रोहिणी पांडे। 2015. भारतीय बच्चे इतने छोटे क्यों होते हैं? | सीआईडी फैकल्टी वर्किंग पेपर संख्या 292. अप्रैल। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://

www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/cid/files/publications/faculty-working-papers/Indian_Children_Short_Pande_293.pdf.
जयसवाल, के.पी. 1934. संस्कृत पाठ में भारत का एक शाही इतिहास। लाहौर: मोतीलाल बनारसीदास.
जीन लाफॉर्च्यून का मुखपृष्ठ। 2022. जीन लाफॉर्च्यून: पाठ्यक्रम जीवन। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://sites.google.com/site/jeannelafortune/curriculum-vitae
जीदीगुंटा, सत्यनारायण, नादिया हेवेट, पुरूषोत्तम कौशिक और आरुषि गोयल। 2021. "डेटा अर्थव्यवस्था की ओर: एक सक्षम ढांचा।" विश्व आर्थिक मंच। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www3.weforum.org/docs/WEF_Towards_a_Data_Economy_2021.pdf
जीलानी, गुलाम. 2021. मुसलमान हिंदुओं की तुलना में परिवार नियोजन को तेजी से अपना रहे हैं; बहुविवाह एक मिथक है: पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी. 20 मार्च. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.moneycontrol.com/news/politics/muslims-taking-to-family-planning-faster-than-hindus-polygamy-a-myth-former-cec-sy-quraishi-6669901.html/amp.
झारगॉव टीवी. 2021. हार्वर्ड में भारत सम्मेलन - 20-02-2021. 20 फरवरी. 15 फरवरी, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.youtube.com/watch?v=MJ4yqgc_gkM.
जॉनसन, आयन. 2016. पर्यावरण संरक्षण में चीनी धर्म की भूमिका पर.

17 अक्टूबर. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.nytimes.com/2016/10/18/world/asia/china-religion-prasenjit-duara.html.
जोलिवेट, एंड्रयू जे. 2015. रिसर्च जस्टिस: मेथोडोलॉजीज़ फॉर सोशल चेंज. ब्रिस्टल, यूके: पॉलिटी प्रेस.
जॉली, जोआना। 2016. भारत में बलात्कार संस्कृति: अंग्रेजी भाषा के प्रेस की भूमिका। 20 जुलाई। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://shorensteincenter.org/rape-culture-india-english-language-press/
जोन्स, जेफ्री। 2017. “अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उभरते बाजार: एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य।” हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। 29 सितंबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.hbs.edu/ris/Publication%20Files/18-020_0da6ca17-091e-4491-8ec1-974156463cb
जोन्स, जेफरी एम. 2021. नवीनतम अमेरिकी अनुमान में एलजीबीटी पहचान बढ़कर 5.6% हो गई है। 24 फरवरी। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://news.gallup.com/poll/329708/lgbt-identification-rises-latest-estimate.aspx.
जोशी, मोहित. 2021. डिजिटल पहचान समावेशी वित्तीय सेवाओं को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है. 30 अप्रैल. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.weforum.org/agenda/2021/04/digital-id-is-the-catalyst-of-our-digital-future/.
जे-पाल. 2010. हमारे बारे में - अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन

लैब (जे-पाल). 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.povertyactionlab.org/about-j-pal.
——. 2020d. अंकित अग्रवाल. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.povertyactionlab.org/person/agarwal.
——. 2014बी. अहमदाबाद, भारत में महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.povertyactionlab.org/evaluation/business-training-women-ahmedabad-india.
——. 2014a. भारत में ग्रेडिंग में भेदभाव। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.povertyactionlab.org/evaluation/discrimination-grading-india.
——. 2020e. एच.वाई. गौराम्मा. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.povertyactionlab.org/person/gowramma.
——. 2020b. जीन लाफोर्ट्यून. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.povertyactionlab.org/person/lafortune.
——. 2020a. मैरिएन बर्ट्रेंड. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.povertyactionlab.org/person/Bertrand.
——. 2020सी. प्रियाल पाटिल. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.povertyactionlab.org/person/patil.
——. 2020f. भारत में बाढ़-सहनशील चावल के माध्यम से किसानों के जोखिम को कम करना। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.povertyactionlab.org/evaluation/

reducing-farmers-risk-through-flood-tolerant-rice-india.
——. 2021. भारत में क्रॉस-कास्ट क्रिकेट टीमों के माध्यम से पूर्वाग्रह को कम करना। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.povertyactionlab.org/evaluation/reducing-prejudice-through-cross-caste-cricket-teams-india.
जे-पाल दक्षिण एशिया। 2021. एक्सएसडीजी अनकॉन्फ्रेंस: वैश्विक विकास को समावेशी बनाना। अगस्त। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.povertyactionlab.org/event/xsdg-unconference-making-global-development-inclusive.
जे-पाल. 2003. अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब (जे-पाल). 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.povertyactionlab.org/.
रोहित के लिए न्याय, हैदराबाद विश्वविद्यालय। 2016. महा धरना - कार्तिक बिट्टू कोंडैया का भाषण - रोहित के लिए न्याय। 30 अगस्त। 15 मई, 2022 को देखा गया। https://www.youtube.com/watch?v=b9U_-Jz1Hes.
काकुतानी, युइचिरो। 2020b. पूर्व चीनी अधिकारी डी.सी. थिंक टैंक के शीर्ष दानदाता। 13 जुलाई। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://freebeacon.com/national-security/ex-china-official-a-top-donor-to-d-c-think-tank/.
——. 2020a. हार्वर्ड ने चीन में जनमत सर्वेक्षण कराने के लिए पूर्व सीसीपी अधिकारी को नियुक्त किया। 31 जुलाई। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://freebeacon.com/coronavirus/harvard-hires-ex-regime-official-to-poll-china/.

Kane, Pandurang Vaman. 1941. History of Dharmashastra. Vol. II. Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute.
——. 1990. धर्मशास्त्रों का इतिहास: भारत में प्राचीन और मध्यकालीन धर्म और नागरिक कानून खंड II. भाग 1. पुणे: भंडारकर प्राच्य अनुसंधान संस्थान।
कपूर, कमलेश। 2010. एक राष्ट्र के चित्र: प्राचीन भारत का इतिहास। नई दिल्ली: स्टर्लिंग पब्लिशर्स।
कार्तिकेयन, अपर्णा। 2014. रोजमर्रा की जिंदगी, रोजमर्रा के लोग। 13 दिसंबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.thehindu.com/features/magazine/everyday-lives-everyday-people/article10945235.ece.
काज़ेमी, अश्कन, किरण गरिमेला, गौतम किशोर शाही, डेविन गैफनी और स्कॉट ए हेल। 2022. “शोध नोट: गलत सूचना का पर्दाफाश करने के लिए टिपलाइन।” हार्वर्ड कैनेडी स्कूल, गलत सूचना समीक्षा। 31 जनवरी। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://misinforeview.hks.harvard.edu/wpcontent/uploads/2022/01/kazemi_tiplines_whatsapp_20220131.pdf.
केर्न्स, क्लियो मैकनेली। 1987. टी. एस. एलियट और भारतीय परंपराएँ। कैम्ब्रिज [कैम्ब्रिजशायर]; न्यूयॉर्क: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
की, एफ.ई. 1918. प्राचीन भारतीय शिक्षा। लंदन: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
कीले विश्वविद्यालय। 2020. कीले के शोधकर्ता को भारत में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए धनराशि से सम्मानित किया गया। 15

दिसंबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.keele.ac.uk/about/news/2020/december/funding-inclusive/education-india.php.
केंडी, इबराम एक्स. 2019. नस्लवाद-विरोधी कैसे बनें. न्यूयॉर्क: वन वर्ल्ड. केनलेज. 2022. विश्व आर्थिक मंच. 4 मार्च. 15 मई, 2022 को देखा गया. https://www.dinardaily.net/t103534-world-economic-forum.*
केनेडी, डंकन, और कार्ल ई. क्लेयर। 1984. “क्रिटिकल लीगल स्टडीज की एक ग्रंथ सूची।” येल लॉ जर्नल 94 (461)।
खारे, पल्लवी, अगस्त्य देव, भव्य झा, दीया अग्रवाल और निव्या रघु। 2021. “भारत में वंचित किशोर बच्चों में लैंगिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए चैटबॉट की प्रभावशीलता का मापन।” हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय विकास केंद्र। 31 मार्च, 2022 को प्राप्त किया गया। https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/cid/files/publications/CID_Wiener_Inequality%20Award%20Research/Pallavi%20Khare%20(1-A).pdf.
किंग, रूथ. 2018. माइंडफुल ऑफ रेस: ट्रांसफॉर्मिंग रेसिज्म फ्रॉम द इनसाइड आउट. बोल्डर, कोलोराडो: साउंड्स ट्रू.
क्लाइन, जॉर्ज एल. 1963. अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड: उनके दर्शन पर निबंध। न्यू जर्सी: एंगलवुड क्लिफ्स।
कोडाइकनाल इंटरनेशनल स्कूल। 2021. क्वाड टॉक्स I योग्यतावाद की राजनीति, प्रो. अजंथा सुब्रमणियन '86 के साथ। 17 मार्च। 15 फरवरी, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.youtube.com/watch?v=xNDM6aYx7uM.

कूप, चाकौर। 2020. स्मिथसोनियन संग्रहालय ने कड़ी मेहनत और तर्कसंगत विचार को 'श्वेत संस्कृति' कहने के लिए माफी मांगी। 17 जुलाई। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.miamiherald.com/news/nation-world/national/article244309587.html.
कोशी, जैकब। 2021. कोरोनावायरस | टीका तो टीका ही होता है... नियामक कभी बैकअप को मंजूरी नहीं देते, वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील कहते हैं। 9 जनवरी। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.thehindu.com/sci-tech/health/a-vaccine-is-a-vaccineregulators-never-approve-a-backup-says-virologist-shahid-jameel/article33537424.ece.
क्रेमर, मार्क आर. 2020. लैरी फिंक आपकी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट नहीं पढ़ने वाले हैं। 20 जनवरी। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://hbr.org/2020/01/larry-fink-isnt-going-to-read-your-sustainability-report.
——. 2019. लैरी फिंक के पत्र पर हुई प्रतिक्रिया से पता चलता है कि सामाजिक जिम्मेदारी के मामले में व्यवसायों को अभी कितना आगे जाना है। 31 जनवरी। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://hbr.org/2019/01/the-backlash-to-larry-finks-letter-shows-how-far-business-has-to-go-on-social-responsibility.
कृष्णम, उज्जवल. 2021. भारतीय उदारवाद का पितृसत्तात्मक बोझ। 2 अक्टूबर. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.greaterkashmir.com/op-ed-2/the-patriarchal-

burden-of-भारतीय-उदारवाद।
कृष्णा, विद्या। 2021. भारत में, स्वतंत्र प्रेस के अंतिम कुछ गढ़ बढ़ते अधिनायकवाद के खिलाफ पहरा दे रहे हैं। 20 सितंबर। 31 मार्च, 2022 को प्राप्त। https://niemanreports.org/articles/in-india-the-last-few-bastions-of-the-free-press-stand-guard-against-rising-authoritarianism/.
कुडवा, रूपा। 2021. विविधता, समानता और समावेशन: हमारी टीम और हमारे भागीदारों के प्रति हमारा वादा। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.omidyarnetwork.in/diversity-equity-inclusion.
कुमार, अवंतास। 2020. अकादमिक जगत में हिंदूफोबिया। 15 दिसंबर। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://indiacurrents.com/hinduphobia-in-the-academy/
कुमार, शिल्पा, तारिक मुस्तफा और आस्था कामरा। 2021a. हमारी लीगलटेक थीसिस: भारत में संविदात्मक विश्वास का निर्माण। 16 दिसंबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.omidyarnetwork.in/insights/our-legaltech-thesis.
कुंदू, प्रेरणा। 2020. क्या सूचना बेहतर मतदान निर्णयों की ओर ले जा सकती है? भारत में सूचना अभियानों से साक्ष्य। 30 मार्च। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.povertyactionlab.org/blog/3-30-20/can-information-lead-better-voting-decisions-evidence-information-campaigns-india.
कुन्हप्पा, मुरकोट। 1988. श्री नारायण गुरु। नई दिल्ली: नेशनल बुक

ट्रस्ट। कुओ, राहेल, और एलिस मारविक। 2021. क्रिटिकल डिसइन्फॉर्मेशन स्टडीज: हिस्ट्री, पावर, एंड पॉलिटिक्स। 12 अगस्त। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। doi:https://doi.org/10.37016/mr-2020-76.
किंग, जेम्स। 2021. हार्वर्ड में अध्ययन किए गए नजरबंदी शिविरों की देखरेख करने वाले शिनजियांग अधिकारी। 19 अक्टूबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.ft.com/content/39404813-472c-455d-98d6-60aa865033d0.
लैम, जेफ़ी, और किम्मी चुंग। 2018. ऑस्टिन स्थित टेक्सास विश्वविद्यालय ने हांगकांग स्थित फाउंडेशन से कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधों का हवाला देते हुए फंडिंग को अस्वीकार कर दिया। 15 जनवरी। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.scmp.com/news/hong-kong/education/article/2128338/university-texas-austin-rejects-funding-hong-kong-based.
कानून और समाज गठबंधन। 2021. “भारत में चीनी पदचिह्न और प्रभाव संचालन का मानचित्रण।” डिफेंस कैपिटल। अगस्त। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://defence.capital/wp-content/uploads/2021/09/MAPPING-CHINESE-FOOTPRINTS-AND-INFLUENCE-OPERATIONS-IN-INDIA2.pdf.
लॉ, बिमल चूर्ण। 1943. प्राचीन भारत में जनजातियाँ। प्रथम संस्करण। पूना: भंडारकर प्राच्य अनुसंधान संस्थान।
लियुंग, रसेल। 2021. हार्वर्ड शोधकर्ता और एनयू प्रोफेसरों ने अश्वेत और दलित समुदाय एकजुटता पर चर्चा की। 6 मई। 15 फरवरी, 2022 को एक्सेस किया गया। https://

dailynorthwestern.com/2021/05/07/campus/harvard-researcher-and-nu-profs-discuss-black-and-dalit-community-solidarity/
लेवी, स्कॉट सी. 2002. “हिंदू कुश से परे हिंदू: मध्य एशियाई दास व्यापार में भारतीय।” जर्नल ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी 12 (3): 277-288.
लिया स्पिनर. 2019ए. के बारे में: स्पिनर. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. http://liaspinper.com/.
——. 2019c. परियोजना के बारे में। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। http://liaspinper.com/about-the-project/.
——. 2019e. बर्कले, अक्टूबर 2018. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. http://liaspinper.com/berkeley-october-2018/.
——. 2019डी. डेटा. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. http://liaspinper.com/data/.
——. 2019b. पेरिस, 24-25 जून – LIASPINPER. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. http://liaspinper.com/paris-24-25th-june/.
——. 2019f. सोनीपत, 21 दिसंबर 2018. 15 मई 2022 को एक्सेस किया गया. http://liaspinper.com/sonipat-21-december-2018/.
लिंडा हॉल लाइब्रेरी. 2022. आइरिस येल्लम (ट्रैवल फेलो, 2020-21). 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.lindahall.org/fellow-iris-yellum/.
लियू, रेबेका। 2019. होमी के भाभा: हमें मानवाधिकारों की एक नई,

भावनात्मक भाषा की आवश्यकता क्यों है। 5 नवंबर। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.prospectmagazine.co.uk/arts-and-books/homi-k-bhabha-interview-degradation-populism-immigration-postcolonialism-ica.
लियू, सिक़ी, और हेलरी वाई. झांग। 2016. स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने मुंबई में अनुसंधान केंद्र खोला। 16 जनवरी। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.thecrimson.com/article/2016/1/16/public-health-center-mumbai/
लोक ढाबा. 2022. 2022 विधानसभा चुनाव एक नज़र में. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://lokdhaba.ashoka.edu.in/dash.
लॉन्गर, विक्टर। 1981. फोरफ्रंट फॉरएवर: महार रेजिमेंट का इतिहास। सागर: महार रेजिमेंट केंद्र।
लॉर्ड माइकल. 2021. खुलासा: क्लाउस श्वाब का कोविड तानाशाहों का स्कूल, 'ग्रेट रीसेट' की योजना (वीडियो). 10 नवंबर. 15 मई, 2022 को देखा गया. https://rairfoundation.com/exposed-klaus-schwabs-school-for-covid-dictators-plan-for-great-reset-videos/.
लूसे, डैन डे. 2021. नई रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी विश्वविद्यालय बीजिंग के सैन्य निर्माण का समर्थन करने वाले चीनी विश्वविद्यालयों से संबंध बनाए रखते हैं। 10 दिसंबर। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.nbcnews.com/politics/national-security/us-universities-retain-ties-chinese-schools-support-chinas-military-bu-rcna8249.

ल्यूमिनेट. 2019. न्यू मीडिया वेंचर्स ने अमेरिका में लोकतंत्र की रक्षा के लिए व्यापक प्रयास किए। 8 मई। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://luminategroup.com/posts/blog/new-media-ventures-casts-a-wide-net-to-defend-democracy-in-the-us.
मैकआर्थर फाउंडेशन. 2022. पुलित्जर सेंटर ऑन क्राइसिस रिपोर्टिंग. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.macfound.org/grantee/pulitzer-center-on-crisis-reporting-41986/.
मैक्रोपोलिस. 2015. मोहम्मद अब्दुल लतीफ जमील. 5 मई. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://marcopolis.net/mohammed-abdul-latif-jameel.htm.
महाप्रशस्ता, अजय आशीर्वाद। 2020. 'हिंदू राष्ट्रवाद नहीं, बल्कि बदला हुआ समाज': क्रिस्टोफ़ जैफ्रेलॉट। 25 जनवरी। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://thewire.in/religion/christophe-jaffrelot-rss-narendra-modi.
Mahavir. 2001. Vaidik Arthvyavastha. New Delhi: Samaanantar Prakashan.
महिंद्रा ह्यूमैनिटीज सेंटर। 2020. भारतीय यौन जीवन: दुर्बा मित्रा, लिसा लोवे और शेरोन मार्कस के साथ बातचीत में। 17 मार्च। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.youtube.com/watch?v=PQ7-_pOSpAA.
मजूमदार, आर.सी. 1971. प्राचीन बंगाल का इतिहास। कलकत्ता: जी. भारद्वाज एंड कंपनी।
——. 2001. साम्राज्यवादी एकता का युग - भारतीय लोगों का

इतिहास और संस्कृति। 7वां। खंड 2. भारतीय विद्या भवन।
माल्होत्रा, राजीव। 2021. कृत्रिम बुद्धिमत्ता और शक्ति का भविष्य: 5 युद्धक्षेत्र। नई दिल्ली: रूपा पब्लिकेशन्स इंडिया।
——. 2022a. सीनेटर कोरी बुकर को खुला पत्र। 1 जनवरी। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.linkedin.com/posts/rajivmalhotra2007_open-letter-to-senator-cory-booker-11-activity-6883190755465154560-yXhe/.
——. 2016. संस्कृत के लिए लड़ाई। नोएडा: हार्परकॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया।
——. 2022बी. पीयर-रिव्यू कार्टेल. 3 फरवरी. 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.outlookindia.com/website/story/the-peer-review-cartel/222822.
माल्होत्रा, राजीव, और अरविंदन नीलकांतन। 2011. ब्रेकिंग इंडिया: द्रविड़ और दलित विभाजन रेखाओं में पश्चिमी हस्तक्षेप। नई दिल्ली: एमरिलिस।
माल्होत्रा, राजीव, और सत्यनारायण दास बाबाजी। 2020. संस्कृत गैर-अनुवाद्य: अंग्रेजी का संस्कृतीकरण करने का महत्व। नई दिल्ली: एमरिलिस।
मकबूल, माजिद और रकीब हमीद नाइक। 2017. भारत का धुर दक्षिणपंथी रोहिंग्या शरणार्थियों के प्रति शत्रुतापूर्ण हो गया। 28 जून. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.trtworld.com/magazine/india-s-far-right-turns-hostile-toward-rohingya-refugees-8327
मार्कस, एडम। 2021. हार्वर्ड जर्नल ने चुनावों में अश्वेतों की वकालत पर

अपना शोधपत्र वापस लिया। 22 दिसंबर। 31 मार्च, 2022 को देखा गया। https://retractionwatch.com/2021/12/22/harvard-journal-retracts-paper-on-black-advocacy-in-elections/
मार्क्यूज़, हर्बर्ट। 1964. एक-आयामी मनुष्य: उन्नत औद्योगिक समाज की विचारधारा में अध्ययन। बोस्टन: बीकन प्रेस।
मार्टिन, फिलिप, टिंकू रे और कविता पिल्ले। 2019. अमेरिका में जातिगत भेदभाव: एक सार्वजनिक रेडियो और ऑनलाइन श्रृंखला। 25 फरवरी। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://pulitzercenter.org/projects/caste-discrimination-usa-public-radio-and-online-series.
मार्टिन, फिलिप, टिंकू रे, कविता पिल्ले और कायला एडवर्ड्स। 2020. 'कास्ट इन अमेरिका' को 2020 गेब्रियल पुरस्कार मिला। 27 मई। 31 मार्च, 2022 को देखा गया। https://pulitzercenter.org/blog/caste-america-receives-2020-gabriel-award.
मासा, एनी, और कालेब मेल्बी। 2020. इन फिंक वी ट्रस्ट: ब्लैक रॉक अब 'सरकार की चौथी शाखा' है। 21 मई। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-21/how-larry-fink-s-blackrock-is-helping-the-fed-with-bond-buying.
मैक्लेश, मार्क, और पैट्रिक ओलिवेल। 2012. अर्थशास्त्र: राज्य-प्रबंधन पर क्लासिक भारतीय कृति से चयनित अंश। इंडियानापोलिस: हैकेट पब्लिशिंग कंपनी इंक।
संस्थापकों से मिलें। 2017. संजीव बिखचंदानी और आशीष धवन | संस्थापकों से मिलें, अशोका विश्वविद्यालय। 29 नवंबर। 15 मई, 2022

को एक्सेस किया गया। https://www.youtube.com/watch?v=eE0eLYrbJWo.
मेहता, मलिका नूर। 2016. कैसे शादियाँ भारत के सबसे गरीब लोगों को बंधुआ मजदूरी की ओर धकेलती हैं। 8 अगस्त। 31 मार्च, 2022 को देखा गया। https://ksr.hkspublications.org/2016/08/08/how-weddings-condemn-indias-poorest-to-bonded-labor/
मेहता, प्रताप भानु। 2016. अत्याचार का एक कृत्य: 'मोदी सरकार ने लोकतंत्र को खतरा पहुँचाया; यह सभी कृत्यों में सबसे राष्ट्रविरोधी है'। 16 फरवरी। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया। https://indianexpress.com/article/opinion/columns/jnu-sedition-case-kanhaiya-kumar-arrest-afzal-guru-event/.
मेनन, ए. श्रीधर। 2011. केरल का इतिहास और इसके निर्माता। नई दिल्ली: डीसी बुक्स।
मेरिगन, तारा डब्ल्यू. 2010. अंतर्राष्ट्रीय दान में वृद्धि, विशेष रूप से भारत के टाटा से। 28 अक्टूबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.thecrimson.com/article/2010/10/28/business-school-harvard-donations/.
मेटकाफ, हिलेरी, और हीदर रोल्फ़। 2010. “ग्रेट ब्रिटेन में जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न।” राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक अनुसंधान संस्थान। दिसंबर। https://www.niesr.ac.uk/wp-content/uploads/2021/10/caste-discrimination.pdf.
मिंट. 2021. कल के नेताओं का मार्गदर्शन. 2 जुलाई. 31 मार्च, 2022

को एक्सेस किया गया. https://www.livemint.com/brand-stories/mentoring-the-leaders-of-tomorrow-11625201641694.html.
मिश्रा, पंकज. 2014. नंदन नीलेकानी ने ई-गवर्नमेंट्स फाउंडेशन को पुनर्जीवित किया. 20 नवंबर. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://economictimes.indiatimes.com/industry/services/education/nandan-nilekani-reboots-egovernments-foundation/articleshow/45199769.cms.
मिशन काली. 2020. रोनेन सेन ने भारत में ईसाई मिशनरियों को वीजा देने के लिए अपने पद का दुरुपयोग कैसे किया. 9 अप्रैल. 31 मार्च, 2022 को देखा गया. https://missionkaali.org/how-ronen-sen-misused-his-position-to-grant-visas-for-christian-missionaries-in-india/.
एमआईटी न्यूज़ ऑफिस। 2014. एमआईटी के पूर्व छात्र मोहम्मद अब्दुल लतीफ जमील ने विश्व खाद्य और जल सुरक्षा की तात्कालिक चुनौतियों के समाधान के लिए बड़ा दान दिया। 6 मई। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://news.mit.edu/2014/mohammed-abdul-latif-jameel-gives-major-gift-to-solve-food-water-issues-0506.
मिचेल, जोशुआ। 2019. मृत रूढ़िवादी मीम्स पहचान की राजनीति के कुष्ठ रोगियों को पराजित नहीं कर सकते। 6 जून। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://americanmind.org/salvo/dead-conservative-memes-cant-defeat-the-identity-politics-clerisy/

मित्तल इंस्टीट्यूट. 2013. हार्वर्ड विदाउट बॉर्डर्स: मैपिंग द कुंभ मेला. 1 मई. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.youtube.com/watch?v=8T1boAZX-8M2.
——. 2016. ब्रिटिश भारत का 1947 विभाजन: जनसांख्यिकीय और मानवीय परिणाम। 13 मई। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.youtube.com/watch?v=fTAddznUy-w.
मोहन, मौलश्री और अन्ना रेगो। 2020. प्रभाव मूल्यांकन में सामाजिक दृष्टिकोण और मानदंडों का मापन: भारत से उदाहरण। 13 मार्च। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.povertyactionlab.org/blog/3-13-20/measuring-social-attitudes-and-norms-impact-evaluations-examples-india.
मोहंती, सच्चिदानंद। 2005. वैश्विक सांस्कृतिक नागरिकता की ओर। 3 जुलाई। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://web.archive.org/web/20050706092138/http://www.hindu.com/lr/2005/07/03/stories/2005070300020100.htm.
मोजो स्टोरी. 2020. संयुक्त राज्य आयोग की सुनवाई में भारत में सीएए और धार्मिक स्वतंत्रता पर गवाही. 8 मार्च. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.youtube.com/watch?v=pmDbrooDvck.
मुखर्जी, राधा कुमुद. 1969. प्राचीन भारतीय शिक्षा। चौथा. नई दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास.
मोशिक टेमकिन (@moshik_temkin). 2020. याद दिलाने के लिए धन्यवाद। इसका बाइडन के विदेशियों के प्रति नफरत फैलाने वाले

विज्ञापन से कोई लेना-देना नहीं है, जिसमें इसका ज़िक्र तक नहीं था। उइगरों की स्थिति - फ़िलिस्तीनियों की स्थिति या भारत में मुसलमानों की स्थिति की तरह - डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व को ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। 20 अप्रैल। 31 मार्च, 2022 को देखा गया। https://twitter.com/moshik_temkin/status/1252036147066347522.

मुखर्जी, शुभम। 2010. महिंद्रा ने अपने पूर्व शिक्षण संस्थान हार्वर्ड को 10 मिलियन डॉलर का उपहार दिया। 4 अक्टूबर। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/Mahindra-gifts-alma-mater-Harvard-10-m/articleshow/6680909.cms.

मुखर्जी, अनाहिता। 2021. ऐतिहासिक सिस्को मामले में जातिगत भेदभाव से लड़ने में कैलिफोर्निया का कानूनी आधार केंद्र में आया। 10 मार्च। 15 फरवरी, 2022 को एक्सेस किया गया। https://thewire.in/caste/cisco-case-caste-discrimination-silicon-valley-ambedkar-organisations.

मुंशी, कैवन, और मार्क आर. रोज़ेनज़्वेग। 2005. "भारत में गतिशीलता इतनी कम क्यों है? सामाजिक बीमा, असमानता और विकास।" हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय विकास केंद्र। जुलाई। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/cid/files/publications/faculty-working-papers/121.pdf.

मुस्तफा, तारिक, शिल्पा कुमार और नंदन शरलय। 2022a. शहरी भारत के लिए डिजिटल रेल का निर्माण - हमने ई-गवर्नमेंट्स फाउंडेशन में निवेश क्यों किया। 2 फरवरी। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया।

https://www.omidyarnetwork.in/blog/why-we-invested-in-egovernments-foundation.
नाडकर्णी, एम. वी. 2003. “क्या जाति व्यवस्था हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है? एक मिथक का भंडाफोड़।” आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक (आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक) 38 (45): 4783-4793. 15 फरवरी, 2022 को अभिगमित।
नजर, निदा। 2017. भारत ने राम नाथ कोविंद को राष्ट्रपति चुना, जो कभी 'अछूत' कहलाने वाली जाति से आते हैं। 20 जुलाई। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त। https://www.nytimes.com/2017/07/20/world/asia/india-dalit-president-ram-nath-kovind.html.
नाम्बियार, नयनिका, और परमेश शाहानी। 2018. “भारतीय कार्यस्थल में ट्रांसजेंडर समावेशन के लिए एक घोषणापत्र।” गोदरेज इंडिया कल्चर लैब। दिसंबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://indiaculturelab.org/assets/Uploads/Godrej-India-Culture-Lab-Trans-Inclusion-Manifesto-Paper3.pdf.
नंदा, मीरा. 2001. “हम सब अब संकर हैं: उत्तर-औपनिवेशिक लोकलुभावनवाद का खतरनाक ज्ञानमीमांसा।” जर्नल ऑफ पीजेंट स्टडीज 28 (2): 162-186. doi:https://doi.org/10.1080/03066150108438770.
नंदा, प्रशांत के. 2021. अशोका विश्वविद्यालय विस्तार के लिए 1.5 हजार करोड़ रुपये जुटाएगा। 8 सितंबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.livemint.com/education/news/ashoka-university-to-raise-1-5k-crore-for-expansion-11631121634731.html.

नेशनल एसोसिएशन ऑफ साइंस राइटर्स। 2021. NASW डायवर्सिटी रिपोर्टिंग ग्रांट के 2021 के प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की गई। 2 दिसंबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.nasw.org/article/nasw-diversity-reporting-grant-recipients-2021-announced.
नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया. 2019. हम कौन हैं | नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया. 20 जुलाई. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.nfi.org.in/who-we-are/#link-115.
नवयाना. 2012. बंजर भूमि में एक माली. 10 अक्टूबर. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://navayana.org/books/2012/10/10/a-gardener-in-the-wasteland-2/?v=7516fd43adaa.
एनबीसी न्यूज़@एनबीसीन्यूज़. 2021. मैरीलैंड विश्वविद्यालय को प्रशासनिक ग्राफ़िक द्वारा छात्रों को दो श्रेणियों में विभाजित करने के बाद आलोचना का सामना करना पड़ रहा है — “रंगीन छात्र, एशियाई छात्रों को छोड़कर” और “श्वेत या एशियाई छात्र”। 20 नवंबर। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया। https://twitter.com/NBCNews/status/1461844255027175425.
नीलोत्पल, एस. 2013. मीरा पदावली। दिल्ली: प्रभात प्रकाशन.
न्यूमैन, स्कॉट, और कोरी टर्नर। 2020. हार्वर्ड, येल पर विदेशी दान में करोड़ों डॉलर की जानकारी न देने का आरोप। 13 फरवरी। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.npr.org/2020/02/13/805548681/harvard-yale-targets-of-education-department-probe-into-foreign-donations.

नेवराडाकिस, माइकल। 2022. एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से 23 वर्षीय युवक की मौत के आरोप में बिल गेट्स और भारतीय सरकार पर मुकदमा। 20 जनवरी। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://childrenshealthdefense.org/defender/bill-gates-indian-government-lawsuit-astrazeneca-vaccine-killed-shri-hitesh-kadve/
न्यू डिस्कोर्स। 2021. ग्रूमर स्कूल्स 2: क्वीर फ्यूचरिटी और आपके बच्चों का यौन शोषण। 25 नवंबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.youtube.com/watch?v=-OQL1Jja3p4.
——. 2022. पाउलो फ्रेयर की शिक्षा की राजनीति और एक नई आशा। 18 जनवरी। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.youtube.com/watch?v=v2aGMCpgpjU.
न्यू वेंचर फंड. 2021. कैटालिटिक कैपिटल कंसोर्टियम ने 14 अनुसंधान परियोजनाओं को पुरस्कारों की घोषणा की. 13 अक्टूबर. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://newventurefund.org/for-grant-seekers/c3grantmaking/catalytic-capital-consortium-announces-awards/.
नेक्स्टशार्क - संपादकीय स्टाफ। 2019. 2017 से अब तक कम से कम 25 वैश्विक ब्रांडों ने चीन से माफी मांगी है। 14 अक्टूबर। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://nextshark.com/global-brands-apologize-to-china/
एनएफआई. 2019. प्रभाव. 20 जुलाई. 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.nfi.org.in/impact.
हार्वर्ड में नीमन फाउंडेशन फॉर जर्नलिज्म। 2021a. भारत की कारवां

पत्रिका ने पत्रकारिता में विवेक और सत्यनिष्ठा के लिए लुई एम. लियोन्स पुरस्कार जीता। 8 फरवरी। 31 मार्च, 2022 को देखा गया। https://nieman.harvard.edu/news/2021/02/indias-caravan-magazine-wins-louis-lyons-award-for-conscience-integrity-journalism/

——. 2017. नीमन फाउंडेशन ने 2017 नाइट विजिटिंग नीमन फेलो की घोषणा की। 7 फरवरी। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://nieman.harvard.edu/news/2017/02/nieman-foundation-announces-2017-knight-visiting-nieman-fellows/.

——. 2021बी. नीमन फाउंडेशन फॉर जर्नलिज्म - क्लास ऑफ 2022. 25 मई. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://nieman.harvard.edu/alumni/class-of-2022/.

——. 2020. हार्वर्ड में नीमन फाउंडेशन फॉर जर्नलिज्म ने 2020-2021 बैच के फेलो की घोषणा की। 22 जुलाई। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://nieman.harvard.edu/news/2020/07/nieman-foundation-for-journalism-announces-2021-fellows/.

——. 2010. नीमन फाउंडेशन, पुलित्जर सेंटर ने वैश्विक स्वास्थ्य रिपोर्टिंग को मजबूत करने के लिए मिलकर काम किया। 7 सितंबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://nieman.harvard.edu/news/2010/09/nieman-foundation-pulitzer-center-join-forces-to-strengthen-global-health-reporting/.

नीमनलैब. 2021. भारत की कारवां पत्रिका ने पत्रकारिता में विवेक और

सत्यनिष्ठा के लिए लुई एम. लियोन्स पुरस्कार जीता. 10 फरवरी. 31 मार्च, 2022 को देखा गया. https://www.niemanlab.org/reading/indias-caravan-magazine-wins-the-louis-m-lyons-award-for-conscience-and-integrity-in-journalism/.
नीमन रिपोर्ट्स. 2014. नीमन रिपोर्ट्स के बारे में. 8 जनवरी. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://niemanreports.org/about-nieman-reports/.
नीट्ज़ेल, माइकल टी. 2022. एमआईटी को नए बहुविषयक डिज़ाइन केंद्र के गठन के लिए 100 मिलियन डॉलर का उपहार प्राप्त हुआ। 17 मार्च। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.forbes.com/sites/michaeltnietzel/2022/03/17/mit-receives-100-million-gift-to-form-new-multidisciplinary-design-center/?sh=5a9ed7193526.
नितनवारे, हिमांशु। 2015. कंडोम की कमी: कुंभ से पहले नासिक में घबराहट | इंडिया न्यूज़ - टाइम्स ऑफ इंडिया। 4 जुलाई। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। http://timesofindia.indiatimes.com/india/Condom-shortage-Jitters-in-Nashik-ahead-of-Kumbh/articleshow/47932804.cms.
नॉर्थ स्टार फंड. 2017. नॉर्थ स्टार फंड रैपिड रिस्पांस ग्रांट्स 2016-17. 8 नवंबर. 15 फरवरी, 2022 को एक्सेस किया गया. https://northstarfund.org/2017/11/north-star-fund-rapid-response-grants-2016-17/.
नुस्बाम, मार्था सी. 2009. द क्लैश विद इन: डेमोक्रेसी, रिलीजियस

वायलेंस, एंड इंडियाज फ्यूचर. हार्वर्ड: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। 2020. जयंत सिन्हा: अध्यक्ष, वित्त संबंधी स्थायी समिति और संसद सदस्य, भारत। 1 अप्रैल। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.orfonline.org/about/jayant-sinha/
विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय। 2022. प्रतिबंध सूची खोज। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34119.
ओल्डमीडो, हैरी। 2004. पूर्व की यात्राएँ: 20वीं सदी में पूर्वी धार्मिक परंपराओं के साथ पश्चिमी मुठभेड़। ब्लूमिंगटन, इंडियाना: वर्ल्ड विजडम।
Olivelle, Patrick. 2000. Dharmasutras. New Delhi: Motilal Banarsidass.
——. 2005. मनु की विधि संहिता। न्यूयॉर्क: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
ओमिडयार नेटवर्क. 2020. सी.वी. मधुकर: प्रबंध निदेशक, लाभकारी प्रौद्योगिकी. 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया. https://omidyar-network.jjzizzr3-liquidwebsites.com/omidyar-team/cv-madhukar/.
ओमिडयार नेटवर्क इंडिया. 2021b. बिजाक | भारत के 28+ राज्यों और 1000+ क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ाना. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.omidyarnetwork.in/theboldones/bijak.
——. 2020b. सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज (सीएसबीसी). 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://

www.omidyarnetwork.in/investees/centre-for-social-and-behaviour-change.
——. 2021a. सेंटर फॉर सोशल इम्पैक्ट एंड फिलैंथ्रोपी (सीएसआईपी). 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.omidyarnetwork.in/centre-for-social-impact-philanthropy-ashoka-university.
——. 2021f. CredR | प्रयुक्त मोटरसाइकिलों के माध्यम से स्वतंत्रता और यात्रा में सुगमता प्रदान करना। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.omidyarnetwork.in/theboldones/credr.
——. 2020डी. डेटा सुरक्षा परिषद ऑफ इंडिया. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.omidyarnetwork.in/data-security-council-of-india.
——. 2021c. डाउटनट | भारत का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला शिक्षा मंच। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.omidyarnetwork.in/theboldones/doubtnut.
——. 2021d. ईजीओवी | बेहतर शहरी शासन के लिए प्रौद्योगिकी समाधान। 16 नवंबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.omidyarnetwork.in/theboldones/egov.
——. 2021e. FES | स्थानीय ग्रामीणों को 9 मिलियन एकड़ में संपत्ति अधिकार देना। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.omidyarnetwork.in/theboldones/fes.
——. 2020c. गिवइंडिया. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.omidyarnetwork.in/giveindia.

——. 2021जी. भारतीय विज्ञान संस्थान. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.omidyarnetwork.in/indian-institute-of-science.
——. 2019a. बड़े पैमाने पर सशक्तिकरण और सामाजिक प्रभाव को बढ़ावा देने वाले निवेश। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.omidyarnetwork.in/.
——. 2021h. जन साहस | भारत के सबसे हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए काम करना। 16 नवंबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.omidyarnetwork.in/theboldones/jan-sahas.
——. 2019b. जनअग्रहा सेंटर फॉर सिटिजनशिप एंड डेमोक्रेसी. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.omidyarnetwork.in/investees/janaagraha.
——. 2019सी. न्यूजलॉन्ड्री. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.omidyarnetwork.in/investees/newslaundry.
——. 2022a. ओमिडयार नेटवर्क इंडिया की पोस्ट - द इंडियन एक्सप्रेस थिंक माइग्रेशन सीरीज़। 20 जनवरी। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.linkedin.com/posts/omidyar-network-india_migration-migrationinindia-migrants-activity-6889827276704366592-v6n1.
——. 2020a. ओमिडयार नेटवर्क इंडिया की रीसॉल्व पहल: कोविड-19 के प्रति प्रतिक्रिया का अगला चरण प्रवासन और MSMEs पर केंद्रित है। 22 जुलाई। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.omidyarnetwork.in/blog/omidyar-

network-indias-resolve-initiative-next-phase-of-response-to-covid-19-focusses-on-migration-and-msme.
——. 2021i. सितारा | कम आय वाली महिला उधारकर्ताओं के लिए किफायती आवास ऋण। 17 नवंबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.omidyarnetwork.in/theboldones/sitara.
——. 2021जे. पारस्परिक सहायता के लिए सामुदायिक अवसंरचना कोष। 15 मई, 2022 को अभिगमित। https://omidyar.com/the-community-infrastructure-fund-for-mutual-aid/.
——. 2022c. वेदांतु | भारत का पहला लाइव ऑनलाइन इंटरैक्टिव के-12 शिक्षा मंच। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.omidyarnetwork.in/theboldones/vedantu.
——. 2020e. ग्राम राजधानी. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.omidyarnetwork.in/investees/village-capital-c.
——. 2022b. विविधता: विविधता, समता और समावेशन (DEI) पर एक द्विवार्षिक समाचार पत्र। 27 जनवरी। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.omidyarnetwork.in/blog/vividh-bi-annual-newsletter-on-diversity-equity-inclusion-dei.
ओमवेद्ट, गेल. 2003. भारत में बौद्ध धर्म: ब्राह्मणवाद और जाति को चुनौती. नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन्स.
ऑनलाइन बर्मा/म्यांमार लाइब्रेरी। 1998. हार्वर्ड: उत्कृष्टता की कीमत। 1 जून। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://

www.burmalibrary.org/reg.burma/archives/199806/msg00033.html.
ओपइंडिया. 2020ए. क्या दिल्ली दंगों की रिपोर्ट के कारण एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को बंद करना पड़ा? 29 सितंबर. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.opindia.com/2020/09/fact-check-amnesty-international-shut-operations-india-report-delhi-riots/.
——. 2021a. ईडी की जांच में न्यूज़क्लिक को चीनी फंडिंग का खुलासा, एल्गर परिषद मामले के आरोपी गौतम नवलखा भी लाभार्थियों में से एक: विवरण। 18 जुलाई। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.opindia.com/2021/07/ed-newsclick-china-funding-gautam-navlakha-prabir-purkayastha/.
——. 2020b. हुसैन हैदरी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के विरोध में प्रदर्शन न करने के लिए 'प्रगतिशील गैर-मुसलमानों' की निष्क्रियता पर खेद व्यक्त किया। 4 अगस्त। 31 मार्च, 2022 को प्राप्त। https://www.opindia.com/2020/08/hussain-haidry-progressive-non-muslims-construction-of-ram-mandir-in-ayodhya/.
ओपइंडिया स्टाफ। 2022. 'हिजाब पर फैसला मौलाना करेंगे, जज नहीं': पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ. एस.वाई. कुरैशी ने लव जिहाद, हिजाब और कश्मीरी पंडितों पर क्या कहा। 26 मार्च। 15 मई, 2022 को देखा गया। https://www.opindia.com/2022/03/former-chief-election-commissioner-sy-quraishi-love-jihad-hijab-

yogi-adityanath-kashmiri-pandits/
——. 2021a. अशोका विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर ने झूठे आरोपों पर भारत के राष्ट्रपति को ट्रोल करने की कोशिश करते हुए भगवान राम का उपहास किया। 25 जनवरी। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया। https://www.opindia.com/2021/01/neelanjan-sircar-ashoka-university-mocks-lord-ram-president-kovind-netaji-portrait/.
——. 2021. जॉर्ज सोरोस किस प्रकार मीडिया और 'नागरिक समाज' के माध्यम से भारत विरोधी खतरनाक कथा को हवा दे रहे हैं। 18 जुलाई। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया। https://www.opindia.com/2021/07/how-george-soros-fund-open-society-foundation-anti-india-narrative-media-ngos/.
——. 2020. केयर इंडिया का पर्दाफाश: बोर्ड के एक सदस्य पर धोखाधड़ी में संलिप्तता, भारत सरकार के नाम पर धन की याचना और ईसाई धर्म प्रचारक संगठनों को वित्तपोषण करने के आरोप। 29 जून। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया। https://www.opindia.com/2020/06/care-india-evangelical-organisations-fcra-neera-saggi-mani-shankar-aiyer-daughter/.
ओपइंडिया. 2021b. द वायर की पत्रकार अरफा खानम शेरवानी ने 2020 में नाज़ी जर्मनी की तुलना भारत से की, नेटिज़न्स ने अंतर समझाया। 17 जनवरी। 31 मार्च, 2022 को देखा गया। https://www.opindia.com/2020/01/arfa-khanum-sherwani-nazi-germany-india-2020-compare/.

——. 2021c. जब 'कार्यकर्ता' तीस्ता सेतलवाद पर गोधरा दंगा पीड़ितों के लिए आवंटित धन की धोखाधड़ी और गबन का आरोप लगा। 30 मई। 31 मार्च, 2022 को देखा गया। https://www.opindia.com/2021/05/teesta-setalvad-was-accused-of-fraud-in-the-name-of-gujarat-riot-victims/.*
आउटलुक वेब डेस्क. 2021. हार्वर्ड की सबसे बड़ी दलित आवाज़ अपनी नई जाति संवेदनशील नीति से नाखुश, जानिए क्यों. 4 दिसंबर. 15 फरवरी, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.outlookindia.com/website/story/harvards-biggest-dalit-voice-unhappy-after-new-caste-sensitive-policy-heres-why-suraj-yengde-instagram/403707.
पांडे, अल्पना। 2015. मध्यकालीन आंध्र: एक सामाजिक-ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। पार्ट्रिज इंडिया।
पांडुरंगी, के.टी. 1999. मानवीय मूल्यों पर भारतीय विचार। दूसरा. बैंगलोर: भारतीय विद्या भवन।
परेड. 2020. मिलिए मिस्टर माइंडफुलनेस से: कैसे जॉन काबाट-ज़िन ने माइंडफुलनेस को आम लोगों तक पहुँचाया. 22 अप्रैल. 30 अप्रैल, 2022 को देखा गया. https://parade.com/717983/parade/meet-mr-mindfulness-how-jon-kabat-zinn-brought-mindfulness-to-the-masses/amp/.
परासा, राजेश्वरी. 2021ए. भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं के स्थानिक डेटासेट की यथास्थिति. 29 अप्रैल. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.idfcinstitute.org/blog/2021/april/status-quo-of-spatial-datasets-of-health-facilities-in-

india/.
PARI - ग्रामीण भारत का जन अभिलेखागार। 2021b. 2014-15 में, मुख्य पृष्ठ की खबरों का केवल 0.24% हिस्सा ग्रामीण भारत से आया था। हम इसे बदलना चाहते हैं। 31 मार्च, 2022 को देखा गया। https://ruralindiaonline.org/en/pages/donate/
——. 2021a. ग्रामीण भारत: एक जीवंत जर्नल, एक सक्रिय संग्रह। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://ruralindiaonline.org/en/pages/about/.
PARI Education - People's Archive of Rural India. 2020a. छात्रों और शिक्षकों के लिए एक ही स्थान पर सभी संसाधन उपलब्ध। 22 जून। 31 मार्च, 2022 को देखा गया। https://pari.education/p-sainath/.
——. 2020बी. सहभागी संगठन. 31 मार्च, 2022 को अभिगमित. https://pari.education/participating-institutions/.
PARI शिक्षा टीम। 2021. PARI शिक्षा वर्ष 1, 2 और 3. 27 अगस्त। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://pari.education/articles/pari-education-years-1-2-3/
PARI शिक्षा. 2020. PARI शिक्षा क्या है. 17 जून. 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया. https://pari.education/what-is-a-pari-education/.
पार्किन, सिओधभ्रा. 2019. चीन विदेशी गैर-सरकारी संगठनों को कैसे नियंत्रित करता है. 27 अगस्त. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.chinafile.com/ngo/latest/how-china-regulates-foreign-non-governmental-organizations.
पाठक, प्रिया. 2019a. एनआरसी विरोध प्रदर्शन: विप्रो ने असम में

एनआरसी परियोजना में कंपनी की भूमिका का जश्न मनाया, पहले पेज डिलीट किया फिर उसे पुनर्स्थापित किया. 23 दिसंबर. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.indiatoday.in/technology/news/story/wipro-celebrates-its-role-in-nrc-project-in-assam-first-deletes-page-then-restores-it-1630865-2019-12-23.
पटनायक, सस्मिता, और शैली झा। 2020. ऊर्जा तक पहुंच निर्धारित करने में जाति, वर्ग और लिंग। जून। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.ceew.in/publications/caste-class-and-gender-determining-access-energy.
पैट्रिक, जिम। 2021. अमेरिका में घुसपैठ: चीन ने डीसी स्थित रेडियो स्टेशन को चीनी प्रचार प्रसारित करने के लिए लाखों डॉलर का भुगतान किया। 24 दिसंबर। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.lawenforcementtoday.com/infiltrating-america-china-paid-dc-based-radio-station-millions-to-air-chinese-propaganda/
पेलाएज़, एडुआर्डो। 2019. अनुकूलन के (स्लम) परिदृश्य: कमजोर आधार, जोखिम पारिस्थितिकी, सामुदायिक पहल। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.gsd.harvard.edu/project/slumscapes-of-adaptation-weak-grounds-risk-ecologies-community-initiatives/
पर्ना, लौरा डब्ल्यू. 2018. टेकिंग इट टू द स्ट्रीट्स: द रोल ऑफ स्कॉलरशिप इन एडवोकेसी एंड एडवोकेसी इन स्कॉलरशिप. बाल्टीमोर: जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस.
पीटर्स, एन. 2010. वैश्विक स्वास्थ्य रिपोर्टिंग को मजबूत करने के लिए

नीमन फाउंडेशन और पुलित्जर सेंटर ने हाथ मिलाया। 7 सितंबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://pulitzercenter.org/blog/nieman-foundation-and-pulitzer-center-join-forces-strengthen-global-health-reporting.
फिलैंथ्रोपी न्यूज़ डाइजेस्ट। 2016. हार्वर्ड और टाटा कंपनियों ने 8.4 मिलियन डॉलर की अनुसंधान साझेदारी की घोषणा की। 30 अगस्त। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://philanthropynewsdigest.org/news/harvard-tata-companies-announce-8.4-million-research-partnership.
फिलिप, स्नेहा। 2018. आईडीआर शॉर्ट्स | अधिकार-आधारित वकालत में परोपकार की भूमिका। 19 दिसंबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://idronline.org/idr-shorts-philanthropys-role-in-rights-based-advocacy/
पीआईबी दिल्ली। 2020. नीति आयोग ने 'नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल' नामक व्यवहार परिवर्तन अभियान और वेबसाइट का शुभारंभ किया (सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य)। 15 जून। 15 मई, 2022 को देखा गया। https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1634328
प्लकरोज़, हेलेन, और जेम्स ए. लिंडसे। 2020. सनकी सिद्धांत: कैसे कार्यकर्ता विद्वत्ता ने हर चीज़ को नस्ल, लिंग और पहचान से जोड़ दिया —और यह सबको क्यों नुकसान पहुँचाता है। डरहम: पिचस्टोन पब्लिशिंग।
पॉकेट न्यूज अलर्ट। 2016. अशोका विश्वविद्यालय, वेलेस्ली कॉलेज की

साझेदारी छात्र विनिमय कार्यक्रम के साथ शुरू हुई। 1 अप्रैल। 15 मई, 2022 को देखा गया। https://www.pocketnewsalert.com/2016/04/Ashoka-University-Wellesley-College-partnership-commences-with-student-exchange-programme.html.
पोरायौ, विलियम। 2022. वैश्विक अनुसंधान विस्तार के साथ येल भारत और दक्षिण एशिया की ओर देख रहा है। 17 फरवरी। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://yaledailynews.com/blog/2022/02/17/yale-looks-to-india-and-south-asia-as-global-research-expands/
पॉइंटर. 2017. दुनिया की सबसे महत्वाकांक्षी पत्रकारिता के पीछे मौजूद छोटे गैर-लाभकारी संगठन से मिलें. 21 मार्च. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.poynter.org/reporting-editing/2017/the-tiny-nonprofit-behind-the-worlds-most-ambitious-journalism/.
प्रताप, रश्मी. 2017. 'अब हमारे पास जैसे को तैसा लोकतंत्र है'. 8 सितंबर. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.thehindubusinessline.com/blink/know/now-we-have-a-titfortat-democracy/article9850190.ece.
प्रतिलिपि. 2014. के बारे में | प्रतिलिपि. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.pratilipi.com/about
विकास कार्यों के लिए व्यावसायिक सहायता। 2021. PRADAN - विकास कार्यों के लिए व्यावसायिक सहायता। 10 फरवरी। 15 मई, 2022 को देखा गया। https://www.pradan.net/
पुलित्जर सेंटर. 2016. पत्रकार से मिलें: जॉर्ज ब्लैक. 18 जुलाई. 31

मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.youtube.com/watch?v=GVnaiBdIjdE.
पुलानूर, हरीश। 2021. खतरनाक हमला: प्रताप भानु मेहता के अशोक विश्वविद्यालय से बाहर निकलने पर येल, एमआईटी, हार्वर्ड के शिक्षाविदों की प्रतिक्रिया। 20 मार्च। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.ndtv.com/india-news/yale-mit-harvard-academics-on-pratap-bhanu-mehtas-ashoka-university-exit-2394968.
पर्सेर, रॉन. 2017. माइंडफुलनेस की ब्रांडिंग. 16 दिसंबर. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.huffpost.com/entry/the-branding-of-mindfulness_b_5a35a283e4b02bd1c8c60750.
राधाकृष्णन, एस. 1953. प्रधान उपनिषद। नई दिल्ली: हार्पर कॉलिन्स।
राय, सिद्धार्थ। 2018. राहुल गांधी ने 2019 के चुनावों में मोदी को मात देने के लिए हार्वर्ड के प्रोफेसर स्टीव जार्डिंग की सेवाएं बरकरार रखीं। 1 सितंबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.mynation.com/news/rahul-gandhi-congress-bjp-steve-jarding-narendra-modi-bjp-samajwadi-party-pedtx6.
राज्याध्यक्ष, निरंजन। 2017. बिग डेटा भारतीय नीति में प्रवेश करता है। 16 अगस्त। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.livemint.com/Opinion/qSvFZxqhXBgWTmw0AARdeP/Big-Data-enters-Indian-policy.html.
राजन, कल्याणी, शिल्पा राव, सोफिया इमाद और अनुष्का भंसाली।

2021सी। कोविड-19 वैक्सीन स्वीकृति संचार अभियान। 27 सितंबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.idfcinstitute.org/projects/state-capacity/covid-vaccine-acceptance/
राजगढ़िया, संजना। 2020. “भारतीय संदर्भ में मीडिया हेरफेर: ट्विटर पर कश्मीर से संबंधित प्रवचन का विश्लेषण।” हार्वर्ड कैनेडी स्कूल, मोसावर-रहमान सेंटर फॉर बिजनेस एंड गवर्नमेंट। जून। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/mrcbg/files/Final_AWP_147.pdf.
रमन, ए. रघु. 2022. ‘ग्रामीण प्रतिभाओं तक पहुंच, स्वदेशी प्रौद्योगिकी आई.टी.आई. मद्रास की प्राथमिकता होगी’. 21 जनवरी. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://timesofindia.indiatimes.com/city/chennai/reaching-out-to-rural-talent-homegrown-technology-to-be-priority-of-iit-madras/articleshow/89034539.cms.
रामास्वामी, विवेक। 2021. वोक, इंक.: कॉर्पोरेट अमेरिका के सामाजिक न्याय घोटाले के अंदर। न्यूयॉर्क: हैचेट बुक ग्रुप।
रामटेके, डी.एल. 1983. आधुनिक भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार। नई दिल्ली: दीप एंड दीप।
रामज़ी, ऑस्टिन। 2017. एशिया सोसाइटी ने हांगकांग कार्यकर्ता के भाषण पर रोक लगाने के लिए कर्मचारियों को दोषी ठहराया। 7 जुलाई। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.nytimes.com/2017/07/07/world/asia/hong-kong-joshua-wong-censorship.html.

राव, सी. हयवदना। 1936. श्रीकार भाष्य: श्रीपति द्वारा वेदांत सूत्र पर वीरशैव भाष्य होना। बैंगलोर: बैंगलोर प्रेस.
राव, राज. 2021. एक्सक्लूसिव: सांता क्लारा काउंटी मानवाधिकार आयोग जाति पर सुनवाई करेगा. 29 अप्रैल. 15 फरवरी, 2022 को एक्सेस किया गया. https://diyatvusa.com/2021/04/29/exclusive-santa-clara-county-human-rights-commission-to-hold-hearing-on-caste/.
राव, सुनीता आर. 2021. टीकाकरण के लिए आधार देने वाले लोगों के लिए सरकार द्वारा विशिष्ट स्वास्थ्य आईडी जारी की जाएगी। 11 जनवरी। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://timesofindia.indiatimes.com/india/govt-to-generate-unique-health-ids-for-people-giving-aadhaar-for-vaccination/articleshow/80205336.cms.
राठौर, आकाश सिंह, और अजय वर्मा। 2011. बी.आर. अंबेडकर: बुद्ध और उनका धम्म - एक आलोचनात्मक संस्करण। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
रे, रजत कांता। 2003. द फेल्ट कम्युनिटी। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। रेमन, नोआ एस., और एलिसा ए. एल. स्पिट्जर। 2010. अंतःविषयक कार्य के उद्देश्य से संस्कृत विभाग का नाम परिवर्तन। 27 मई। 31 मार्च, 2022 को देखा गया। https://www.thecrimson.com/article/2010/5/27/department-witzel-sanskrit-current/
रेडडेन, एलिजाबेथ। 2018. जेंडर स्टडीज पर वैश्विक हमला। 5 दिसंबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.insidehighered.com/news/2018/12/05/gender-

studies-scholars-say-field-coming-under-attack-many-countries-around-globe.
——. 2017. क्या चीन दलाई लामा की मेजबानी करने के लिए अमेरिकी विश्वविद्यालय को दंडित कर रहा है? 20 सितंबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.insidehighered.com/news/2017/09/20/china-punishing-american-university-hosting-dalai-lama.
रेली, पैट्रिक। 2022. टीम के साथियों का कहना है कि वे यूपीएन की ट्रांसजेंडर तैराक लिया थॉमस के साथ लॉकर रूम में कपड़े बदलने में असहज महसूस करते हैं। 27 जनवरी। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://nypost.com/2022/01/27/teammates-are-uneasy-changing-in-locker-room-with-trans-upenn-swimmer-lia-thomas/.
रीस, जूलियो सी.एस., फिलिप मेलो, किरण गरिमेला और फैब्रिसियो बेनेवेनुटो। 2020. “क्या गलत सूचनाओं को कम करने के लिए तथ्यों की जाँच करके सत्यापित की गई गलत सूचनाओं से व्हाट्सएप को लाभ हो सकता है?” हार्वर्ड कैनेडी स्कूल, गलत सूचना समीक्षा। 20 अगस्त। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://misinforeview.hks.harvard.edu/wp-content/uploads/2020/08/WhatsApp_India_Brazil_Copyedited.pdf.
धार्मिक स्वतंत्रता एवं व्यापार फाउंडेशन। 2021. “नई दिशाएँ: धार्मिक स्वतंत्रता पहलों के विस्तार और समन्वय के लिए वैश्विक अवसर।” धार्मिक स्वतंत्रता एवं व्यापार फाउंडेशन। जुलाई। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया। https://

religiousfreedomandbusiness.org/wp-content/uploads/2021/07/IRF-Global-Survey-2021-FINAL.pdf.
——. 2019. टेम्पलटन रिलीजन ट्रस्ट अनुदान से आरएफबीएफ एशिया की सहभागिता बढ़ाने में मदद मिली। 3 अक्टूबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://religiousfreedomandbusiness.org/2/post/2019/10/templeton-religion-trust-grant-helps-expand-rfbf-asia-engagement.html.
अर्थशास्त्र पर पुनर्विचार, जेएनयू। 2021. डॉ. पवन मामिडी के साथ व्यवहार अनुसंधान पर संवादात्मक सत्र। 3 अगस्त। 15 मई, 2022 को देखा गया। https://www.youtube.com/watch?v=fNq5aGbBH2s.
रॉयटर्स. 2019. बहिष्कृत से देवी-देवता तक: ट्रांसजेंडर लक्ष्मी कुंभ मेले में अपने किन्नर अखाड़े के साथ स्टार बन गईं. 20 जनवरी. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.indiatoday.in/india/story/transgender-laxmi-narayan-tripathi-kumbh-mela-kinnar-akhara-1435168-2019-01-20.
राइडर, रेम. 2014. राइडर: पियरे ओमिडयार का यूक्रेनी कनेक्शन। 2 मार्च. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.usatoday.com/story/money/columnist/rider/2014/03/02/flap-over-omidyar-support-for-ukrainian-group/5948821/
राइली, डोना। 2008. इंजीनियरिंग और सामाजिक न्याय। सैन राफेल, कैलिफोर्निया: मॉर्गन एंड क्लेपूल पब्लिशर्स।

सोनाली के साथ उदय। 2020. भारत का जातिगत भेदभाव अमेरिका तक कैसे पहुँचा। 21 जुलाई। 15 फरवरी, 2022 को देखा गया। https://vimeo.com/440440045.
आरएनबीए मणिपुर. 2020. दानकर्ता - आरएनबीए मणिपुर. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://rnba.in/about-rnba/donors/.
रोडमैन, मेलिसा सी., और येहोंग झू. 2015. विनिवेश के लिए आह्वान: एक पूर्वव्यापी. 27 मई. 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.thecrimson.com/article/2015/5/27/divest-retrospective-reunion-1990/.
रोड्रिग्स, शॉनना। 2020. दलित नया राजनीतिक और ज्ञानमीमांसीय क्षितिज है: सूरज येंगडे के साथ एक साक्षात्कार। 23 नवंबर। 15 फरवरी, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.borderlines-cssaame.org/posts/2020/11/23/dalit-is-the-new-political-and-epistemic-horizon-an-interview-with-suraj-yengde.
रोसारियो, केनिथ. 2017. 'एक लोकलुभावन राष्ट्रवाद अब जीवित है'. 16 सितंबर. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.thehindu.com/opinion/interview/a-populist-nationalism-is-now-alive/article19697534.ece.
रोसेनबाम, आर्थर लुईस। 2012. येनचिंग विश्वविद्यालय 1916-1952 पर नए परिप्रेक्ष्य: एक नए चीन के लिए उदार शिक्षा। लीडेन, नीदरलैंड: ब्रिल एकेडमिक पब्लिशर्स।
रॉस, अलेक्जेंडर रीड, और कर्टनी डॉब्सन। 2022. उइघुर नरसंहार इनकार का बड़ा कारोबार। 18 जनवरी। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस

किया गया। https://newlinesmag.com/reportage/the-big-business-of-uyghur-genocide-denial/
रॉस, चक। 2021बी। ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन ने बोर्ड सदस्य से जुड़ी चीन पहलों को बढ़ावा दिया। 1 नवंबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://freebeacon.com/national-security/brookings-institution-boosts-china-initiatives-linked-to-board-member/
——. 2021a. शीर्ष कैलिफ़ोर्निया डेमोक्रेट और थिंक-टैंक दिग्गज चीनी कम्युनिस्ट कूटनीति कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। 13 मई। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://freebeacon.com/national-security/top-california-democrat-and-think-tank-titans-slated-to-attend-chinese-communist-diplomacy-event/.
रॉय, प्रताप चंद्रा. 1923. कृष्ण द्वैपायन व्यास का महाभारत खंड VIII कलकत्ता: ओरिएंटल पब्लिशिंग कंपनी.
रोजारियो, एंथोनी एस. 2020. एनईपी: भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति देने के फैसले का अमेरिका ने स्वागत किया। 4 अगस्त। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.thequint.com/news/education/nep-us-welcomes-decision-to-allow-foreign-universities-in-india.
रुबिनस्टीन, अलेक्जेंडर, और मैक्स ब्लुमेंथल। 2019. पियरे ओमिडयार_ सर्विलांस वैली के सुल्तान और दुनिया भर में सीआईए शासन परिवर्तन के लिए फंडिंग एजेंट। 11 मार्च। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://themillenniumreport.com/2019/03/pierre-

omidyar-sultan-of-surveillance-valley-and-funding-agent-for-cia-regime-changes-worldwide/.
रुडोल्फ, लॉयड आई., और सुज़ैन होएबर रुडोल्फ। 1967. परंपरा की आधुनिकता: भारत में राजनीतिक विकास। शिकागो: शिकागो विश्वविद्यालय प्रेस।
रसेल, आर.वी. 1916. भारत के मध्य प्रांतों की जनजातियाँ और जातियाँ। खंड IV. लंदन: मैकमिलन।
साथी रे. 2017. हार्वर्ड ग्लोबल रिसर्च सपोर्ट सेंटर इंडिया. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.saathire.com/TTQ/harvard-global-research-support-centre-india/.
सबिखी, इनायत. 2019. एकजुटता में: हार्वर्ड के छात्र नए नागरिकता विधेयक के खिलाफ भारतीय प्रदर्शनों में शामिल हुए. 20 दिसंबर. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://citizen.hkspublications.org/2019/12/20/in-solidarity-harvard-students-join-indian-demonstrations-against-new-citizenship-bill/.
सफीकुल हसन. 2018. पलागुम्मी साईनाथ की ग्रामीण भारत पर अद्भुत चर्चा। 25 अक्टूबर. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.youtube.com/watch?v=-aSlKpLhfVg
साहा, शर्मिष्ठा. 2020. इतिहास का पुनर्पाठ: अंबेडकर की पुस्तक “अछूत: वे कौन थे और वे अछूत क्यों बने” पर. 17 अक्टूबर. 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त. https://www.allaboutambedkaronline.com/post/an-outline-of-the-untouchables-who-were-they-and-why-they-became-untouchables.

संबारा, श्राव्या। 2021. उपमहाद्वीप से परे जाति और उपनिवेशवाद: अजंता सुब्रमणियन के साथ एक साक्षात्कार। 1 सितंबर। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त किया गया। https://harvardpolitics.com/caste-and-colonialism-beyond-the-subcontinent-an-interview-with-ajantha-subramanian/
सम्यक चेतना, 2021। अजान सुजान द्वारा डॉ. सूरज येंगडे के साथ अंबेडकरवाद, संघर्ष और बौद्ध धर्म पर विशेष चर्चा। 25 जून। https://www.youtube.com/watch?v=Zj1_t7slNzU.*
सैंचेज़, लुइस। 2018. ताइवान को छोड़कर नक्शे वाली टी-शर्ट बेचने के लिए गैप ने चीन से माफी मांगी। 16 मई। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/387984-gap-apologizes-to-china-for-selling-t-shirt-with-map-that-omitted.
सैंडेल, माइकल जे. 2020. योग्यता का अत्याचार: आम भलाई का क्या हुआ? फरार, स्ट्रॉस और गिरौक्स।
संघमित्रा. 2018. कांग्रेस द्वारा स्वीकृत और बच्चों के प्रति घृणास्पद हिंदू विरोधी विचारधारा के प्रचार की घिनौनी कहानी, तीस्ता सेतलवाद द्वारा। 29 मई। 31 मार्च, 2022 को प्राप्त। https://www.opindia.com/2018/05/sordid-tale-of-congress-sanction-and-hateful-anti-hindu-brainwashing-of-children-by-teesta-setalvad/.
सन्नम एस4 ग्रुप. 2008. सन्नम एस4 ग्रुप. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://sannams4.com/.
शर्मा, अजय। 2020. गायों की रक्षा करना और लोगों को सताना। 4 फरवरी। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://

harvardpolitics.com/protecting-cows/
शास्त्री, के. ए. नीलाकांता. 1987. भारत का व्यापक इतिहास खंड 2. नई दिल्ली: पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस.
सत्याग्रह. 2022. जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन द्वारा वित्तपोषित इंस्टीट्यूट पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो (पीआरआईओ) ने ओपन सोसाइटी के पदाधिकारी हर्ष मंदर को नोबेल पुरस्कार के लिए अनौपचारिक सूची में शामिल किया। 4 फरवरी। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://satyaagrah.com/global/global-news/1231-george-soros%E2%80%99s-open-society-foundation-funded-institute-peace-research-institute-oslo-prio-names-open-society-functionar-y-harsh-mander-in-unofficial-shortlist-for-nobel-prize.
शाचटेल, जॉर्डन। 2022. द ग्रेट रीसेट, भाग दो: विश्व आर्थिक मंच की महान कथा परियोजना। फरवरी। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://dossier.substack.com/p/the-great-reset-part-two-the-world.
श्नाइडर, क्रिश्चियन। 2020. वैश्विक मानवाधिकारों को बढ़ावा देते हुए स्टैनफोर्ड ने चीन से 58 मिलियन डॉलर नकद स्वीकार किए। 2 जुलाई। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.thecollegefix.com/stanford-accepts-58-million-in-chinese-cash-while-pushing-global-human-rights/
स्कोफील्ड, ह्यूग। 2021. फ्रांस अपने मूल्यों के लिए अमेरिकी चुनौती का प्रतिरोध करता है। 13 दिसंबर। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.bbc.com/news/world-europe-59584125.

श्वाब, क्लाउस, और पीटर वैनहैम। 2021. स्टेकहोल्डर कैपिटलिज़्म क्या है? 22 जनवरी। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.weforum.org/agenda/2021/01/klaus-schwab-on-what-is-stakeholder-capitalism-history-relevance/.
श्वार्ट्ज, नताली। 2018. एमआईटी रिपोर्ट में सऊदी अरब से संबंध तोड़ने का कोई 'मजबूत आधार' नहीं मिला। 10 दिसंबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.highereddive.com/news/mit-report-finds-no-compelling-case-to-cut-saudi-ties/543938/
श्वेज़र, पीटर. 2021. चीन के अमेरिकी समर्थक. 19 दिसंबर. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.gatestoneinstitute.org/18035/china-us-enablers.
साइंसेज पो. 2017. क्रिस्टोफ़ जैफ़्रेलॉट. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.sciencespo.fr/ceri/en/cerispire-user/7143/586.
सेनसोय, ओज़लेम, और रॉबिन डिएन्जेलो। 2017. क्या वास्तव में सभी समान हैं? न्यूयॉर्क: टीचर्स कॉलेज प्रेस।
शेफर, लिआह. 2016. इस्लामफोबिया को खत्म करना. 23 नवंबर. 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.gse.harvard.edu/news/uk/16/11/dismantling-islamophobia.
शर्मा, अनन्या। 2021a. जानिए भारत खुले में शौच मुक्त होने के लिए संघर्ष क्यों कर रहा है। 28 अक्टूबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://thewire.in/government/heres-why-india-

is-struggling-to-be-truly-open-defecation-free.
शर्मा, अंकिता, और हिंदोल सेनगुप्ता। 2020. कोविड-19 ने भारत के डिजिटल रीसेट को गति दी है। 5 अगस्त। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.weforum.org/agenda/2020/08/covid-19-has-accelerated-india-s-digital-reset/
शर्मा, अरविंद। 2000। शास्त्रीय हिंदू विचार। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस: नई दिल्ली।
——. 1996. हमारे समय के लिए हिंदू धर्म। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
शर्मा, अरविंद. 2015. “रूपा विश्वनाथ द्वारा लिखित ‘द परिया प्रॉब्लम: कास्ट, रिलीजन, एंड द सोशल इन मॉडर्न इंडिया’ की समीक्षा।” इंटरनेशनल जर्नल ऑफ धर्म स्टडीज 3 (8): 1-2. doi:https://doi.org/10.1186/s40613-015-0018-0.
शर्मा, कृतिका। 2017. अशोका विश्वविद्यालय का कहना है कि समस्या कश्मीर याचिका से नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय के नाम के दुरुपयोग से है। 27 मार्च। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.dnaindia.com/india/report-ashoka-university-says-problem-with-misuse-of-university-name-not-kashmir-petition-2369645.
——. 2021. भारतीय विश्वविद्यालयों को हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की तरह धन जुटाने का तरीका सिखाया जा रहा है। 21 अगस्त। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://theprint.in/india/education/indian-universities-are-being-taught-how-to-generate-funds-like-harvard-cambridge/719113/.

शर्मा, नूपुर जे. 2020c. गोदरेज, हिंदू-विरोधी, भारत-विरोधी तत्वों के साथ एक बेहद समस्याग्रस्त जुड़ाव और एक धार्मिक LGBTQIA + कार्यकर्ता की चुप्पी। 19 फरवरी। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.opindia.com/2020/02/lgbtqia-event-rise-pride-circle-godrej-de-platform-gopi-shankar-madurai-pressure-anti-india-elements/.
शर्मा, राम शरण। 1998. भारत के सामाजिक और आर्थिक इतिहास में परिप्रेक्ष्य। नई दिल्ली: मुंशीराम मनोहरलाल पब्लिशर्स।
——. 1958. प्राचीन भारत में शूद्र। नई दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास। शर्मा, रवींद्र नाथ। 1977. श्रौत सूत्रों में प्रकट संस्कृति और सभ्यता। दिल्ली: नाग पब्लिशर्स।
शशिकुमार, वी. के. 2004. “भारत के लिए बुश का रूपांतरण एजेंडा: फसल की तैयारी...” तेहलका। फरवरी। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://baixardoc.com/preview/bush39s-conversion-agenda-for-india-preparing-for-the-harvest-tehelka-5cf8268d22593.
शॉ, जोनाथन। 2022. जलवायु-समाधान निवेश बंदोबस्ती परिसंपत्तियों के लगभग 1 प्रतिशत के करीब। 3 फरवरी। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.harvardmagazine.com/2022/02/endowment-climate-solution-investment.
शेखर, दिव्या जे. 2021. यह जोड़ी प्रारंभिक चरण के गैर-लाभकारी संगठनों को बढ़ावा देती है। उनका लक्ष्य: 2025 तक 1 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकालना। 29 अक्टूबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.forbesindia.com/article/

innovation-nation-2021/this-duo-incubates-earlystage-nonprofits-their-goal-bring-1-crore-indians-out-of-poverty-by-2025/71259/1.
शेठ, श्रीनाल. 2022. ईएसजी वेंचर कैपिटल में आ रहा है। स्टार्टअप संस्थापक इस क्षेत्र में कैसे आगे रह सकते हैं? 5 जनवरी। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.weforum.org/agenda/2022/01/esg-is-coming-to-venture-capital-here-s-how-early-stage-startup-founders-can-stay-ahead-of-the-curve/.
शेट्टी, सलिल, और तारा सहगल। 2019. “भारत की सॉफ्ट पावर: चुनौतियाँ और अवसर।” राजीव गांधी समकालीन अध्ययन संस्थान। दिसंबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.rgics.org/wp-content/uploads/RGICS-Paper-Indias-Soft-Power-Challenges-Opportunities.pdf.
शिमर, डेविड। 2015. येल और अशोका आगे बढ़ते हैं। 26 अक्टूबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://yaledailynews.com/blog/2015/10/26/yale-and-ashoka-engage-further/
शिरीन, राबिया। 2021. दिल्ली दंगे: अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के छात्रों ने यूएपीए की आरोपी गुलफिशा फातिमा की कैद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। 15 अक्टूबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://thehindustangazette.com/national/new-delhi/delhi-riots-azim-premji-university-students-protest-the-incarceration-of-uapa-accused-gulfisha-fatima-5792.

श्रियर, अबीगैल। 2020. किशोर लड़कियों के संक्रमण में वृद्धि में 'सहकर्मी संक्रमण' की क्या भूमिका हो सकती है। 27 जून। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://nypost.com/2020/06/27/how-peer-contagion-plays-into-the-rise-of-teens-transitioning/
सिद्दीकी, इक्तिदार हुसैन। 2014. दिल्ली सल्तनत: शहरीकरण और सामाजिक परिवर्तन। द्वितीय संस्करण। नई दिल्ली: विवा बुक्स।
सिकोरा, क्रिसिया। 2021. धर्म और लोकलुभावनवाद विश्व स्तर पर मीडिया के लिए गंभीर चुनौतियाँ हैं, विद्वान जॉन फी और पत्रकार कल्पना जैन कहते हैं। 10 मार्च। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://berkleycenter.georgetown.edu/features/religion-and-populism-are-critical-challenges-for-media-worldwide-scholar-john-fea-and-journalist-kalpana-jain-say.
साइलस, करेन. 2019. रिहाना के बॉयफ्रेंड हसन जमील कौन हैं? 13 सितंबर. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.hola.com/us/celebrities/gallery/2019091328003/who-is-rihanna-boyfriend-hassan-jameel/1/.
सिंधवानी, प्रेरणा। 2020. भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) में महिला स्नातकों के उत्पादन में विश्व में शीर्ष पर है, लेकिन उन्हें रोजगार देने में 19वें स्थान पर है। 28 फरवरी। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.businessinsider.in/careers/news/india-tops-the-world-in-producing-female-graduates-in-stem-but-

ranks-19th-in-employing-them/
articleshow/74117413.cms.
सिंह, अभिनव. 2021a. “क्या हम इस सत्याग्रह की तस्वीर देख सकते हैं?” प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष में भाग लेने की बात कहने के बाद उदारवादियों का ज़बरदस्त पतन हुआ। 27 मार्च। 15 मई, 2022 को प्राप्त। https://tfipost.com/2021/03/can-we-see-a-photograph-of-this-satyagraha-liberals-suffer-a-glorious-meltdown-after-pm-modi-talks-about-participating-in-bangladesh-liberation-struggle/.
——. 2021b. सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मृत्यु का उपहास करने वालों की तलाश में राज्यों भर में बड़े पैमाने पर अभियान शुरू हो गया है। 10 दिसंबर। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया। https://tfipost.com/2021/12/a-massive-hunt-for-people-who-mocked-cds-gen-bipin-rawats-death-has-begun-across-states/.
सिंह, के.एस. 1993. अनुसूचित जातियाँ। नई दिल्ली: भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस।
1994. अनुसूचित जनजातियाँ। नई दिल्ली: भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस।
सिंह, उपिंदर। 2013. प्रारंभिक मध्यकालीन भारत पर पुनर्विचार। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
स्मिथ, वारेन डब्ल्यू. 2009. चीन का तिब्बत: स्वायत्तता या आत्मसात्करण? लैनहैम, मैरीलैंड: रोवमैन एंड लिटिलफील्ड पब्लिशर्स।
सोवे, रॉबी। 2020. यूकॉन स्कूल प्रशासकों को प्रशिक्षित करने के लिए व्हाइट फ्रजिलिटी की लेखिका रॉबिन डिएन्जेलो को 20,000 डॉलर का

भुगतान करेगा। 14 अगस्त। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://reason.com/2020/08/14/uconn-will-pay-white-fragility-author-robin-diangelo-20000-to-train-school-administrators/.
सोकोलोव, माइकल। 2019. अमेरिकी विश्वविद्यालयों में इतना अधिक सऊदी धन क्यों है? 3 जुलाई। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.nytimes.com/2019/07/03/magazine/saudi-arabia-american-universities.html.
जॉर्ज सोरोस। 2020. भारत में भयावह झटका, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित मोदी हिंदू राज्य का निर्माण कर रहे हैं: जॉर्ज सोरोस। 24 जनवरी। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया। https://theprint.in/world/frightening-setback-in-india-democratically-elected-modi-creating-hindu-state-george-soros/353960/
सोशी, मायेशा आर, और लुकास जे. वाल्श। 2021. यूसी ने भारत में विरोध प्रदर्शनों के दौरान कथित मानवाधिकार उल्लंघनों की निंदा करने के लिए हार्वर्ड से की गई अपीलों का समर्थन किया। 8 मार्च। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.thecrimson.com/article/2021/3/8/uc-condemns-indian-protest-crackdown/
स्क्वॉक बॉक्स (@SquawkCNBC) 2021 “उनके पास एक निरंकुश व्यवस्था है और एक नेता ने इसका वर्णन करते हुए कहा कि अमेरिका व्यक्तियों और व्यक्तिवाद का देश है... चीन में यह परिवार का ही विस्तार है,” @RayDalio कहते हैं। “एक शीर्ष-तटस्थ राष्ट्र होने के नाते वे एक सख्त अभिभावक की तरह व्यवहार करते हैं।” 30 नवंबर।

31 मार्च, 2022 को देखा गया। https://twitter.com/SquawkCNBC/status/1465660719756681218
श्रीनिवास, एम. एन. 1971. आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन। नई दिल्ली: ओरिएंट लॉन्गमैन। श्रीनिवासन, रागिनी थारूर। 2020. वह राष्ट्र जिसे हम जानते थे: होमी भाभा के “डिसेमिनेशन” के बाद। 19 मई। 31 मार्च, 2022 को प्राप्त। https://post45.org/2020/05/the-nation-we-knew-after-homi-bhabhas-dissemination/
श्रीवास्तव, ए.आर.एन. 1986. भारत के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी। नई दिल्ली: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन प्रभाग।
Srivastava, Badrinarayan. 1957. Ramanand Sampradaya Tatha Hindi Sahitya Par Unka Prabhaav. Prayag: Hindi Parishad, Prayag Vishvidyalaya.
Srivastava, Surabhi. 2008. Socio-economic History of the Gurjara Pratihara Times. Lucknow: New Royal Book Company.
स्टीन, जेफ़। 2021. वित्तीय फर्मों ने जलवायु परिवर्तन के लिए 130 ट्रिलियन डॉलर की प्रतिबद्धताओं की घोषणा की, लेकिन व्यावहारिक प्रश्न अभी भी बने हुए हैं। 3 नवंबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.washingtonpost.com/us-policy/2021/11/03/climate-glasgow-bloomberg-carney/
स्टॉप हिंदू हेट एडवोकेसी नेटवर्क। 2020. द वायर। 14 जुलाई। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://

stophinduhate.org/hindu-haters-2/media/the-wire/
सुब्रमणियन, अजंता। 2019. योग्यता की जाति। कैम्ब्रिज, एमए: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
सुब्रमणियन, बालाजी। 2020. हर्ष मंदर द्वारा संचालित गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज को ईसाई और इस्लामी दानदाताओं से करोड़ों रुपये प्राप्त हुए। 25 सितंबर। 15 मई, 2022 को देखा गया। https://thecommunemag.com/centre-for-equity-studies-ngo-run-by-harsh-mander-received-crores-from-christians-and-islamic-donors/
स्वराज्य स्टाफ. 2021. क्या प्रताप भानु मेहता ने सही काम किया? 18 मार्च. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://swarajyamag.com/ideas/did-pratap-bhanu-mehta-do-the-right-thing.
साइमंड्स, रिचर्ड। 1986. ऑक्सफ़ोर्ड और साम्राज्य: अंतिम खोया हुआ कारण? न्यूयॉर्क: सेंट मार्टिन प्रेस।
तमारी, ताल. 2009. “पश्चिम अफ्रीका में जाति व्यवस्था का विकास.” जर्नल ऑफ अफ्रीकन हिस्ट्री (कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस) 32 (2): 221-250. https://doi.org/10.1017/S0021853700025718 .
टैन, रेबेका। 2021. चीन में, अमेरिकी शिक्षा का सपना अपनी चमक कुछ हद तक खो देता है। 13 अगस्त। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/chinese-students-america-university/2021/08/13/6f38368a-ef47-11eb-81b2-9b7061a582d8_story.html.

टंडन, माधव, सिद्धार्थ नौटियाल, और रूपा कुडवा। 2019a. ई-कॉमर्स 2.0: भारत के अगले आधे अरब के लिए डिज़ाइन किया गया। 29 नवंबर. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.omidyarnetwork.in/insights/e-commerce-2-0
——. 2019. “ई-कॉमर्स 2.0: भारत के अगले आधे अरब लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया।” ओमिडयार नेटवर्क इंडिया। 29 नवंबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://uploads-ssl.webflow.com/61b9a0d531bc5e31aa66a38d/6245a663e commerce-2.0-26_09.pdf.
टंडेल, वैदेही, शमिका रवि, विवेक देहजिया और कादंबरी शाह। 2017a. नीति आयोग - आईडीएफसी इंस्टीट्यूट एंटरप्राइज सर्वे। 1 सितम्बर. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.idfcinstitute.org/projects/state-capacity/nitiaayog-idfcinstitute_enterprise-survey/
तांग, वेनफैंग, और किंग यांग। 2008. “संक्रमण में चीनी शहरी जाति व्यवस्था।” द चाइना क्वार्टरली (कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस) (196): 759-779. http://www.jstor.org/stable/20192266.
तारिक, वरीशा। 2020. प्रोफेसर बिट्टू के साथ वार्तालाप: एक न्यूरोसाइंटिस्ट और एक क्वीर एक्टिविस्ट। 6 मार्च। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://feminisminindia.com/2020/03/06/professor-bittu-a-neuroscientist-and-an-anti-caste-queer-activist/
टेलर, क्लोई। 2020. प्रिंस चार्ल्स का कहना है कि कोरोनावायरस संकट अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का एक 'सुनहरा अवसर' प्रस्तुत करता है। 3 जून। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://

www.cnbc.com/2020/06/03/prince-charles-covid-19-a-golden-opportunity-to-reboot-the-economy.html.
तेजेडा, अमांडा, और मनमीत सिंह चहल। 2021. “संकल्प संख्या 21-01: कैलिफ़ोर्निया पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी और कैलिफ़ोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी (सीएसयू) से भेदभाव-विरोधी नीति में जाति को शामिल करने का आह्वान करने वाला संकल्प।” कैलपॉलि। 4 मार्च। 15 फरवरी, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.asi.calpoly.edu/wp-content/uploads/2021/03/21-01-Resolution-Call-for-CP-and-CSU-to-Include-Caste-in-the-Anti-Discriminatory-Policy_BODappr.pdf.
टेमकिन, मोशिक। 2020. बर्नी ने हमें भविष्य का वादा किया था। वह असफल क्यों हुए—और हमने क्या खोया? 14 अप्रैल। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.belfercenter.org/publication/bernie-offered-us-future-why-did-he-fail-and-what-did-we-forfeit.
ठाकुर, प्रदीप. 2021. ईडी ने चीन शासन से 'जुड़े' व्यवसायी से मीडिया पोर्टल के वित्तपोषण की जांच की. 18 जुलाई. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/84514212.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst.
अमेरिकन बाज़ार। 2018. भारतीय अमेरिकी प्रीता बंसल को APAICS समारोह में सम्मानित किया गया। 16 मई। 31 मार्च, 2022 को देखा गया। https://

www.americanbazaaronline.com/2018/05/16/indian-american-preeta-bansal-honored-at-apaics-gala/
ब्रिटिश अकादमी। 2020. भारत में सार्वजनिक इतिहास का स्वामित्व (TOPHI) 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.thebritishacademy.ac.uk/projects/humanities-social-sciences-tackling-global-challenges-ownership-public-history-india/
सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी। 2008। सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://cis-india.org/
द डेली वायर. 2022. चीन: भीतर का दुश्मन. एपिसोड 3. शिक्षा. 18 फरवरी. 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.dailywire.com/episode/3-education.
द इकोनॉमिस्ट. 2020. चीनी प्रबंधन स्कूल फल-फूल रहे हैं. 15 फरवरी. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.economist.com/business/2020/02/13/chinese-management-schools-are-thriving.
फ्लेचर स्कूल। 2021. ब्राह्मणवादी वर्चस्व और श्वेत वर्चस्व को तोड़ना। 5 मार्च। 15 फरवरी, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.youtube.com/watch?v=3KQf9E8fKMM.
युवा वैश्विक नेताओं का मंच। 2020. समर्थक। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.younggloballeaders.org/supporters.
हार्बस. 2020. हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस 2020 में “भारत: दूरदर्शिता” पर

चर्चा। 7 मार्च। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://harbus.org/2020/harvard-india-conference-2020-discusses-india-foresight/.
हार्वर्ड गजेट। 2021. भार्गव को 1996 बैच के मुख्य मार्शल पद के लिए चुना गया। 10 मार्च। 31 मार्च, 2022 को देखा गया। https://news.harvard.edu/gazette/story/2021/03/harvard-alumni-association-announces-chief-marshal-for-2021/
——. 2008. भारत सरकार ने स्नातकोत्तर छात्रों के समर्थन के लिए 4.5 मिलियन डॉलर दिए। 18 दिसंबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://news.harvard.edu/gazette/story/2008/12/government-of-india-gives-4-5m-to-support-grad-students/.
——. 2017. दक्षिण एशिया से हार्वर्ड के संबंधों को मजबूत करना: मित्तल परिवार के दान से दक्षिण एशिया के साथ जुड़ाव के अवसर बढ़े। 11 अक्टूबर। 31 मार्च, 2022 को प्राप्त किया गया। https://news.harvard.edu/gazette/story/2017/10/mittal-family-gift-expands-opportunities-for-south-asia-engagement/.
हेरिटेज फाउंडेशन। 2018. फ्रीडम हाउस पक्षपातपूर्ण हो गया। 16 फरवरी। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.heritage.org/global-politics/commentary/freedom-house-turns-partisan.
द हिल. 2022. किम इवर्सन: ग्रेट रीसेट ने ट्रूडो जैसे युवा नेताओं के साथ दुनिया भर के मंत्रिमंडलों में घुसपैठ कर ली है। 23 फरवरी। 15

मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.youtube.com/watch?v=-p1_8-jLQkI.
द हिंदू. 2019. भारत-पाकिस्तान तनाव पर 600 से अधिक चिंतित नागरिकों की ओर से कारण बताने की अपील. 1 मार्च. 15 मई, 2022 को प्राप्त. https://www.thehindu.com/news/national/appeal-for-reason-from-over-600-concerned-citizens-on-indo-pak-tension/article26410066.ece.
——. 2016. प्रख्यात व्यक्तियों ने राष्ट्रपति से याकूब मेमन की दया याचिका पर विचार करने का अनुरोध किया। 2 अप्रैल। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया। https://www.thehindu.com/news/national/Eminent-persons-request-President-to-consider-Yakubs-mercy-plea/article60329906.ece.
——. 2021. राहुल गांधी ने भारत में हो रही घटनाओं पर अमेरिका की चुप्पी पर सवाल उठाए। 3 अप्रैल। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.thehindu.com/news/national/rahul-gandhi-questions-us-silence-on-happenings-in-india/article34226862.ece.
हिंदुस्तान टाइम्स. 2017. फ़ोर्ड फ़ाउंडेशन के अधिकारी ने तीस्ता सेतलवाड की कंपनी के साथ फंड अनुदान के लिए मिलीभगत की: सीबीआई. 4 फ़रवरी. 31 मार्च, 2022 को देखा गया. https://www.hindustantimes.com/india-news/ford-foundation-officer-sushma-raman-connived-with-teesta-setalvad-s-company-sabrang-for-fund-grant-cbi/story-Msc2TQzKPNmXKigysB7X9J.html.
——. 2022. पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी बताते हैं कि

भारतीय चुनावों में धार्मिक ध्रुवीकरण कैसे लाभ दे रहा है। 18 जनवरी। 15 मई, 2022 को देखा गया। https://www.youtube.com/watch?v=yuIjUsNhfRM.
——. 2004. प्रीता बंसल. 8 जनवरी. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.hindustantimes.com/india/preeta-bansal/story-m6puAx3G4JGAVWTSueHi1I.html.
द इंडियन एक्सप्रेस. 2015. क्रिस्टोफ़ जैफ़्रेलॉट. 29 अप्रैल. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://indianexpress.com/profile/columnist/christophe-jaffrelot/.
द इंटरसेप्ट. 2022. नोआम चोम्स्की और जेरेमी स्कैहिल रूस-यूक्रेन युद्ध, मीडिया, प्रचार और जवाबदेही पर. 15 अप्रैल. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.youtube.com/watch?v=8Jr0PCU4m7M.
अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान। 1998. हमारे बारे में। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.idea.int/
जर्नल ऑफ द अब्राहम लिंकन एसोसिएशन। 1984. हमारी राजनीतिक संस्थाओं का संरक्षण (स्प्रिंगफील्ड के यंग मेन्स लाइसेम के समक्ष अब्राहम लिंकन द्वारा दिया गया भाषण, 27 जनवरी, 1838)। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://quod.lib.umich.edu/j/jala/2629860.0006.103/--perpetuation-of-our-political-institutionsaddress?rgn=main;view=fulltext.
हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान।

2018a. सूरज येंगडे के साथ प्रश्नोत्तर: जाति, रंगभेद और एक चौथी दुनिया का थिंक टैंक। 1 अगस्त। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त किया गया। https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/2018/08/q-a-with-suraj-yengde-caste-apartheid-and-a-fourth-world-think-tank/.

——. 2012. “एसएआई फैकल्टी ग्रांट प्रोफाइल: द चैंपियंस प्रोजेक्ट।” हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/wp-content/uploads/2012/10/Jacuqeline-Bhabha-Champions-Project-Report.pdf.

——. 2018b. “द मित्तल इंस्टीट्यूट ईयर इन रिव्यू 2017-2018.” issuu. 25 अप्रैल. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://issuu.com/sainit/docs/the_mittal_institute_year_in_review_74f9ee41f07a9c.

——. 2019. “द मित्तल इंस्टीट्यूट ईयर इन रिव्यू 2018-2019.” issuu. 28 मई. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://issuu.com/sainit/docs/yir_mittalinstitute_5.7.

——. 2020. “द मित्तल इंस्टीट्यूट ईयर इन रिव्यू 2019-2020.” issuu. 19 मई. 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया. https://issuu.com/sainit/docs/mittal_institute_2019-20_year_in_review.

——. 2021. “द मित्तल इंस्टीट्यूट ईयर इन रिव्यू 2020-21.” issuu. 24 जून. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://

issuu.com/sainit/docs/mittal_institute_yir_2020-21.
——. 2014. “वर्ष की समीक्षा 2013-2014.” issuu. 6 मई. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://issuu.com/sainit/docs/sai_year_in_review_final_1_.
——. 2015. “वर्ष की समीक्षा 2014-2015.” issuu. 22 अप्रैल. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://issuu.com/sainit/docs/sai_year_in_review_1415.
——. 2016. “वर्ष की समीक्षा 2015-2016.” issuu. 13 मई. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://issuu.com/sainit/docs/year_in_review_2015_2016.
——. 2017. “वर्ष की समीक्षा 2016-2017.” issuu. 23 जून. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://issuu.com/sainit/docs/yir_2016-17/1.
लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान। 2019a. चीन और भारत में प्रतिभा और योग्यता। 16 अप्रैल। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/talent-and-meritocracy-in-india-and-china-february-2018-workshop/
द लेट शो विद स्टीफन कोलबर्ट। 2021. यहाँ जॉन सीना की चीन से पूरी माफी है। 27 मई। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.youtube.com/watch?v=XI2IkPNteO4.
द नेशनल पल्स। 2021. चीन समर्थित हार्वर्ड सेंटर फेलो ल्यूक ओ'ब्रायन ने द नेशनल पल्स के खिलाफ लक्षित उत्पीड़न में भाग लिया। 27 जुलाई। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://

thenationalpulse.com/2021/07/27/china-backed-harvard-center-fellow-luke-obrien-engages-in-targeted-harassment-against-the-national-pulse/.
न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी। 2013. भारत में अफ्रीकी: गुलामों से लेकर सेनापतियों और शासकों तक। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.nypl.org/events/exhibitions/africans-india-slaves-generals-and-rulers.
——. 2020. अमेरिका में जाति: जॉन डिकर्सन के साथ इसाबेल विल्करसन | एनवाईपीएल से लाइव। 6 अगस्त। 15 फरवरी, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.youtube.com/watch?v=FxpouTYfJKY.
ओस्लो शांति अनुसंधान संस्थान (पीआरआईओ)। 2021. नोबेल शांति पुरस्कार 2022: पीआरआईओ निदेशक की शॉर्टलिस्ट। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.prio.org/nobelshortlist
सिख गठबंधन। 2021. किसानों का विरोध कार्य। 28 जून। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.sikhcoalition.org/our-work/empowering-the-community/farmers-protest-work/
टाइम्स ऑफ इंडिया। 2010। टाटा समूह से हार्वर्ड को 102 वर्षों में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दान मिला। 15 अक्टूबर। 31 मार्च, 2022 को देखा गया। https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/Harvard-gets-biggest-international-donation-in-102-yrs-from-Tata-Group/articleshow/6752185.cms.

——. 2006. हार्वर्ड देसी आईएएस अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। 15 अप्रैल। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/1491724.cms.
प्रशिक्षण प्रभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार। 2018. "एफ. संख्या 12037/41/2018-एफटीसी।" केंद्रीकृत परिपत्र सूचना प्रणाली, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग। 9 नवंबर। 31 मार्च, 2022 को अभिगमित। http://documents.doptcirculars.nic.in/D2/D02trn/DFFT%20Circular%202019-207z2n1.pdf.
——. 2018. "एफ. संख्या 12038/01/2018-एफटीसी." केंद्रीकृत परिपत्र सूचना प्रणाली, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग। 9 नवंबर। 31 मार्च, 2022 को अभिगमित। http://documents.doptcirculars.nic.in/D2/D02trn/Partial%20Funding%20Circular%20091118dLTpe.pdf.
द वायर. 2021. उच्च जाति के सवालों का जवाब: सूरज येंगडे ने जाति के बारे में विशेषाधिकार प्राप्त लोगों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले सवालों का जवाब दिया। 11 जून। 15 फरवरी, 2022 को देखा गया। https://www.youtube.com/watch?v=nhBAV1XbDL8.
द वायर स्टाफ. 2021b. अशोका विश्वविद्यालय ने 'कुछ चूक' स्वीकार की लेकिन प्रताप भानु मेहता आगे बढ़ने पर जोर देते हैं. 21 मार्च. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://thewire.in/education/ashoka-university-pratap-bhanu-mehta-lapses-protests.
——. 2018. जेएनयू प्रशासन द्वारा असहमति की आवाज़ों के विरुद्ध

चलाए जा रहे 'चुड़ैल-शिकार' के विरुद्ध एकजुटता में। 29 मार्च। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://thewire.in/education/in-solidarity-against-jnu-administrations-witch-hunt-against-dissenting-voices.
——. 2019. ‘ज्ञान को राज्य के विरुद्ध अपराध माना गया’: छात्र, प्रोफेसर हनी बाबू के साथ खड़े हैं। 15 सितंबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://thewire.in/rights/hany-babu-solidarity-statements-delhi-university.
——. 2021a. शेल्डन पोलॉक: ‘अशोका विश्वविद्यालय के प्रति मेरा सम्मान गंभीर रूप से परखा गया है’। 19 मार्च। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://thewire.in/education/sheldon-pollock-my-respect-for-ashoka-university-has-been-seriously-tested.
द प्रिंट. 2020. प्रताप भानु मेहता कहते हैं कि भारत अंधकार के युग से गुजर रहा है जहाँ संविधान एक दिखावा मात्र है। 19 अक्टूबर। 15 मई, 2022 को देखा गया। https://www.youtube.com/watch?v=6F3YKnduUDI.
थेरा, न्यानापोनिका। 1999. चेतना का विश्लेषण। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। http://www.buddhanet.net/abhidh05.htm.
थोराट, सुखदेव, अनुराधा बनर्जी, विनोद के मिश्रा और फिरदौस रिज़वी। 2015. "शहरी किराया आवास बाजार: पहुंच में जाति और धर्म के मामले।" जे.एस.टी.ओ.आर. 27 जून. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.jstor.org/stable/24482557?seq=1

थोरो, हेनरी डेविड। 1932. सात ब्राह्मणों का पुनर्जन्म। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.sacred-texts.com/hin/tsb/tsb03.htm.
तिमल्सिना, तरुण नेहमे और मिशेल। 2021. कोविड के दौरान आईपीएल: भारत में क्रिकेट और राजनीति के बीच संबंध। 7 मई। 31 मार्च, 2022 को देखा गया। https://harvardpolitics.com/ipl-during-covid/
टीएनएम स्टाफ. 2020. 'प्रतिशोधी राज्य दमन बेहद चिंताजनक': सीएए-एनआरसी पर अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर. 16 जनवरी. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.thenewsminute.com/article/vengeful-state-repression-deeply-concerning-azim-premji-uni-profs-caa-nrc-116239.
हमारी जानकारी के अनुसार। 2014. भावनात्मक बुद्धिमत्ता - डैनियल गोलेमैन का प्रतिलेख। 28 फरवरी। 30 अप्रैल, 2022 को देखा गया। http://archive.ttbook.org/book/ transcript/emotional-intelligence-daniel-goleman.
टॉकविले, एलेक्सिस डी. 2004. एलेक्सिस डी टॉकविले: अमेरिका में लोकतंत्र. न्यूयॉर्क: लाइब्रेरी ऑफ अमेरिका.
ToHim89 लाइव. 2019. संदेश 1 यंग वर्किंग सेंट्स कॉन्फ्रेंस एसपीएस चर्च बेलमोपन में -- रॉनी चैन. 14 अक्टूबर. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.youtube.com/watch?v=HYAEzmLRWwY.
Tripathi, Rama Shankar. 1989. History of Kanauj. New Delhi: Motilal Banarsidass.

त्रिवेदी सेंटर फॉर पॉलिटिकल डेटा. 2020c. परिचय: त्रिवेदी सेंटर फॉर पॉलिटिकल डेटा. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://tcpd.ashoka.edu.in/about-the-centre/.
——. 2021ए. भारत के नौकरशाह. 1 दिसंबर. 15 मई, 2022 को अभिगमित. https://tcpd.ashoka.edu.in/bureaucrats-of-india/.
——. 2021बी. भारत के मुख्यमंत्री. 30 जून. 15 मई, 2022 को अभिगमित. https://tcpd.ashoka.edu.in/chief-ministers-of-india/.
——. 2020b. भारतीय मंत्रिपरिषद. 10 अगस्त. 15 मई, 2022 को अभिगमित. https://tcpd.ashoka.edu.in/indian-council-of-ministers/.
——. 2021e. एक हजार भूमि कानून: भारत में भूमि विनियमन की भूलभुलैया का मानचित्रण। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://tcpd.ashoka.edu.in/event/one-thousand-land-laws-mapping-the-maze-of-land-regulation-in-india/.
——. 2022. पॉलिटिकल करियर ट्रैकर. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://lokdhaba.ashoka.edu.in/pct/.
——. 2021सी. सोशल मीडिया और चुनाव. 11 नवंबर. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://tcpd.ashoka.edu.in/social-media-and-elections/.
——. 2018. विधायकों का सामाजिक प्रोफाइलिंग। 10 अगस्त। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://tcpd.ashoka.edu.in/social-profiling-of-legislators/.
——. 2021d. “TCPD वार्षिक रिपोर्ट: 2020-21.” त्रिवेदी सेंटर

फॉर पॉलिटिकल डेटा. अगस्त. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://tcpd.ashoka.edu.in/wp-content/uploads/2021/08/TCPD-Annual-Report-2020-2021.pdf.
त्शुरेनेव, जाना। 2019. साम्राज्य, नागरिक समाज और भारत में औपनिवेशिक शिक्षा की शुरुआत। नई दिल्ली: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
अमेरिकी राजदूत रशाद हुसैन (@IRF_Ambassador) 2022. धार्मिक स्वतंत्रता में अपने धार्मिक पहनावे को चुनने की क्षमता शामिल है। कर्नाटक राज्य को धार्मिक वस्त्रों की स्वीकार्यता निर्धारित नहीं करनी चाहिए। स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है और महिलाओं और लड़कियों को कलंकित और हाशिए पर धकेलता है। 11 फरवरी। 30 अप्रैल, 2022 को देखा गया। https://twitter.com/IRF_Ambassador/status/1492153532350402564
यूनाइटेड बोर्ड. 2019. मिशन और पहचान - यूनाइटेड बोर्ड. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://unitedboard.org/about-us/about-united-board/mission-vision/.
संयुक्त राज्य अमेरिका का राजकोष विभाग। 2022. विशेष रूप से नामित नागरिक और प्रतिबंधित व्यक्तियों की सूची (एसडीएन) मानव पठनीय सूचियाँ। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists.
-उपाध्याय, बलदेव। 1954. भागवत संप्रदाय। वाराणसी: काशी नागरी प्रचारिणी सभा.

यूएससीआईआरएफ. 2004. प्रीता डी. बंसल, अध्यक्ष द्वारा गवाही. 6 अक्टूबर. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.uscirf.gov/resources/testimony-preeta-d-bansal-chair-0.
——. 2020. यूएससीआईआरएफ - नागरिकता कानून और धार्मिक स्वतंत्रता। 5 मार्च। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.youtube.com/watch?v=IcGgWJG5qxA.
वैद्यनाथन, आर. 2019. जाति एक सामाजिक पूंजी के रूप में। चेन्नई: वेस्टलैंड पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड।
वैलेंटाइन, डगलस। 2017. संगठित अपराध के रूप में सीआईए: अवैध संचालन अमेरिका और दुनिया को कैसे भ्रष्ट करते हैं। अटलांटा, जॉर्जिया: क्लैरिटी प्रेस।
वरदराजन, सिद्धार्थ। 2014. सिद्धार्थ वरदराजन: भारतीय मीडिया के साथ क्या गलत हुआ है? 14 अगस्त। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://azimpremjifoundation.org/author/siddharth-varadarajan.
वर्षने, आशुतोष। 2018. “लोकतंत्र और योग्यतातंत्र।” हार्वर्ड चाइना फंड। 8 मई। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://hcf.fas.harvard.edu/wp-content/uploads/2018/05/Varshney-Abstract-Shanghai.pdf.
——. 2020b. हिंदू राष्ट्रवाद, श्वेत वर्चस्ववाद दो लोकतंत्रों को नैतिक रूप से कमजोर करने की धमकी देते हैं। 6 जुलाई। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://indianexpress.com/article/opinion/columns/the-same-shrinking-6491627/.
——. 2021. भारत की लोकतांत्रिक विशिष्टता अब क्षीण हो रही है।

इसका प्रभाव बाहरी भी है। 23 फरवरी। 31 मार्च, 2022 को प्राप्त किया गया। https://indianexpress.com/article/opinion/columns/elected-government-death-of-democracy-india-7200030/.
——. 2021ए. जिम क्रो हिंदुत्व. 20 अक्टूबर. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://indianexpress.com/article/opinion/columns/jim-crow-hindutva-7577159/.
वार्ष्णेय, आशुतोष, श्रीकृष्ण अयंगर, और सिद्धार्थ स्वामीनाथन। 2021. "भारत में लोकलुभावनवाद और हिंदू राष्ट्रवाद।" स्प्रिंगर. 3 जुलाई. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12116-021-09335-8.pdf
वेणु, एम. के., और माया मिर्चंदानी। 2021बी। डोवाल के नागरिक समाज में पेगासस का पता लगाना युद्ध की नई सीमा के रूप में। 29 नवंबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://thewire.in/government/locating-pegasus-in-dovals-civil-society-as-new-frontier-of-war.
वेरहोवेन, मार्टिन जे. 2001. “बौद्ध धर्म और विज्ञान: आस्था और तर्क की सीमाओं की जाँच।” धर्म पूर्व और पश्चिम (1): 77-97.
VI-Control. 2007. सेल्मा, अलबामा में बराक ओबामा के भाषण से उद्धरण। 5 मार्च। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://vi-control.net/community/threads/quotes-from-barack-obama-speech-in-selma-alabama.6237/.
विकासपीडिया. 2019. अटल नवाचार मिशन. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://vikaspedia.in/education/

policies-and-schemes/atal-innovation-mission.
विश्वेश्वरन, कमला, माइकल ई.जे. विट्ज़ेल, नंदिनी मांजरेकर, दिप्ता भोग, और उमा चक्रवर्ती। 2009. “इतिहास का हिंदुत्व दृष्टिकोण: भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में पाठ्यपुस्तकों को फिर से लिखना।” जॉर्जटाउन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स 10 (1): 101-112।
वॉन फ्यूरर हैमेंडॉर्फ, क्रिस्टोफ़, और एलिजाबेथ वॉन फ्यूरर हैमेंडॉर्फ। 2022. आंध्र प्रदेश के गोंड। न्यूयॉर्क: रूटलेज.
व्यास, संगीता, आशीष गुप्ता और नज़र खालिद। 2021. ग्रामीण उत्तर भारत में सरकारी हस्तक्षेप के बाद लिंग और एलपीजी उपयोग। 6 सितंबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X21002977?via%3Dihub.
वॉकर, जोनाथन। 2021. सीसीपी से जुड़ा हार्वर्ड सेंटर कोविड-19 की उत्पत्ति को छुपा रहा हो सकता है - विजन टाइम्स। 24 फरवरी। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.visiontimes.com/2021/02/24/ccp-linked-harvard-center-could-be-covering-up-covid-19-origin.html.
वॉल्ट, स्टीफन। 2019. 2019 में दुनिया में ज्यादा बदलाव नहीं आया। यह 2020 के लिए बुरी खबर है। 31 दिसंबर। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://foreignpolicy.com/2019/12/31/united-states-world-changes-2019/
वेबर, जेरेमी। 2021. बाइडन ने पहले मुस्लिम धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत का नाम घोषित किया। 30 जुलाई। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया

गया। https://www.christianitytoday.com/news/2021/july/rashad-hussain-irf-ambassador-religious-freedom-uscirf-khan.html.
वेबर, मैक्स। 1905. प्रोटेस्टेंट नैतिकता और पूंजीवाद की भावना। पैंटियानोस क्लासिक्स। वेलेस्ली सेंटर्स फॉर विमेन। 2020. सेक्स/एड: अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने अमेरिका, भारत और अन्य देशों के दृष्टिकोणों को एक साथ लाया। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.wcwonline.org/News-Events/sex-ed-international-conference-india.
वेलेस्ली कॉलेज. 2016a. वेलेस्ली ने भारत के पहले निजी आइवी लीग-स्तरीय संस्थान अशोका विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की. 27 जनवरी. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.wellesley.edu/news/2016/january/node/82096.
व्हेरी, आरोन। 2020. 'ग्रेट रीसेट' कुछ कथानक खामियों के साथ एक वैश्विक साजिश की तरह लगता है। 27 नवंबर। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.cbc.ca/news/politics/great-reset-trudeau-poilievre-otoole-pandemic-covid-1.5817973.
विग्नराजा, कन्नी, और बालाज़ होर्वाथ। 2020. कोविड-19 द्वारा उजागर असमानताओं का समाधान सार्वभौमिक बुनियादी आय है। 17 अप्रैल। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.weforum.org/agenda/2020/04/covid-19-universal-basic-income-social-inequality/
विल्करसन, इसाबेल। 2020. जाति: हमारी असंतोष की उत्पत्ति।

न्यूयॉर्क: रैंडम हाउस।
विलियम्स, ल्यूक ए. 2020. हार्वर्ड इंडिया सम्मेलन में भारतीय महावाणिज्यदूत के समक्ष चालीस लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। 18 फरवरी। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.thecrimson.com/article/2020/2/18/harvard-india-conference-protest/
विलियम्स, ल्यूक ए., और मैटियो एन. वोंग। 2020. हार्वर्ड से संबद्ध लोगों ने भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ 24 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया। 27 जनवरी। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.thecrimson.com/article/2020/1/27/indian-citizenship-act-protest/
विल्सन, जेफ़. 2014. माइंडफुल अमेरिका: बौद्ध ध्यान और अमेरिकी संस्कृति का पारस्परिक परिवर्तन. ऑक्सफ़ोर्ड और न्यूयॉर्क: ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
विंटर्स, नताली। 2021a. “हमें चीन की ज़रूरत है” – बाइडन के चीन राजदूत ने सीसीपी से जुड़ी एक परामर्श फर्म और चीन की सेना को सलाह देने वाले हार्वर्ड समूह में काम किया। 17 अप्रैल। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://thenationalpulse.com/2021/04/17/bidens-china-ambassador-former-ccp-consultant/.
——. 2021b. समझौता: हार्वर्ड ने छात्रों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी प्रचार मोर्चे द्वारा लिखित यात्राओं और शोध पत्रों के अधीन किया। 21 मई। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://thenationalpulse.com/2021/05/21/harvard-kennedy-school-takes-ccp-trips/.

——. 2020d. EXC: हार्वर्ड चाइना कॉन्फ्रेंस ने टिकटॉक की मूल कंपनी और चीनी सैन्य प्रॉक्सी के साथ सहयोग किया। 16 अगस्त। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://thenationalpulse.com/2020/08/16/harvard-ccp-forum/.
——. 2020a. एक्सक्लूसिव: हार्वर्ड सेंटर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की लोकप्रियता को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है जबकि चीनी सरकार और सीसीपी से जुड़ी कंपनियों से लाखों डॉलर प्राप्त करता है। 23 जुलाई। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://thenationalpulse.com/2020/07/23/harvard-chinese-funding/.
——. 2020b. चौंकाने वाला: सभी प्रमुख पश्चिमी मीडिया आउटलेट चीनी कम्युनिस्ट प्रचार मोर्चे से 'निजी रात्रिभोज', 'प्रायोजित यात्राएँ' लेते हैं। 29 दिसंबर। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://thenationalpulse.com/2020/12/29/media-private-ccp-dinners-trips/.
विंटर्स, नताली, और रहीम जे. कसम। 2021. EXC: कोविड लैब सिद्धांत पर हमला करने वाले हार्वर्ड सेंटर के चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ व्यापक वित्तीय और कार्मिक संबंध हैं। 13 फरवरी। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://thenationalpulse.com/2021/02/13/harvard-shorenstein-center-ccp-ties/
——. 2022. EXC: जो बाइडेन के सीआईए निदेशक ने कांग्रेस को बताया कि उन्होंने एक चीनी कम्युनिस्ट प्रभाव समूह के साथ संबंध समाप्त कर दिया था - नए सबूत बताते हैं कि यह झूठ था। 30 मार्च।

15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://thenationalpulse.com/2022/03/30/cia-directors-think-tank-continues-cusef-relationship/.
विंटर्स, नताली, और रहीम कसम। 2021बी। खुलासा: चीन का सरकारी प्रचार समूह पश्चिमी थिंक टैंक, 'चुनाव अखंडता' समूहों और यहां तक कि जो बाइडेन की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम पर नियंत्रण का दावा करता है। 1 अप्रैल। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://thenationalpulse.com/2021/04/01/exc-china-state-propaganda-boasts-control-over-think-tanks/
विट्ज़ेनरथ, क्रिस्टोफ़। 2015. विश्व इतिहास में यूरेशियन दासता, फिरौती और उन्मूलन, 1200-1860। सरेरी, इंग्लैंड: एशगेट पब्लिशिंग लिमिटेड।
वोल्फ, रॉबर्ट पॉल, बैरिंगटन मूर, जूनियर, और हर्बर्ट मार्क्यूज़। 1969. शुद्ध सहिष्णुता की एक आलोचना। बोस्टन: बीकन प्रेस।
वोल्टर्स, लुकास, और निकोलस डुमास। 2018. राष्ट्रपति रीफ, सऊदी अरब से एमआईटी के संबंध अभी तोड़ें! 25 अक्टूबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://thetech.com/2018/10/25/reif-cut-ties-saudi-arabia.
वोंग, मैटियो एन. 2020. हार्वर्ड सदी का अंत. 23 अप्रैल. 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.thecrimson.com/article/2020/4/23/harvard-china-scrutiny/.
विश्व आर्थिक मंच। 2022b. “डिजिटल एजेंसी को आगे बढ़ाना: डेटा मध्यस्थों की शक्ति।” विश्व आर्थिक मंच। फरवरी। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www3.weforum.org/docs/

WEF_Advancing_towards_Digital_Agency_2022.pdf.
——. 2022a. ब्लैक रॉक के लैरी फिंक ने स्टेकहोल्डर कैपिटलिज्म सेंटर के लॉन्च पर टिप्पणी की। 18 जनवरी। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.weforum.org/partners/live-updates/davos-agenda-2022#blackrocks-larry-fink-calls-on-ceos-to-step-up.
——. 2020a. “चौथी औद्योगिक क्रांति नेटवर्क के लिए केंद्र।” विश्व आर्थिक मंच। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://weforum.ent.box.com/v/C4IR-India.
——. 2016. हमारा मिशन | विश्व आर्थिक मंच। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.weforum.org/about/world-economic-forum.
——. 2020b. विश्व आर्थिक मंच ने दीर्घकालिक लचीलेपन के लिए ESG कारकों की पहचान करने में व्यवसायों की मदद के लिए ढांचा जारी किया। 19 मार्च। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.weforum.org/press/2020/03/world-economic-forum-releases-framework-to-help-business-identify-esg-factors-for-long-term-resilience.
wzgrl. 2008. ओबामा का राइट को जवाब: नस्ल-मुक्त अमेरिका का समय। 15 मार्च। 30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.youtube.com/watch?v=9_6aLDQTleU.
ज़ि, स्टेला यिफ़ान। 2018. ब्रिजवाटर को चीन में निवेश उत्पाद बेचने का लाइसेंस मिला। 4 जुलाई। 31 मार्च, 2022 को एक्सेस किया गया। https://www.wsj.com/articles/bridgewater-wins-license-to-sell-investment-products-in-

china-1530707031.
xSDG. 2021b. हमारे बारे में. 1 मार्च. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://xsdg.dev/about-us/#rakesh-basant.
——. 2021c. xSDG by Belongg: A Knowledge Platform For SDGs and Intersectionality. 6 April. Accessed May 15, 2022. https://xsdg.dev/xsdg-by-belongg-a-knowledge-platform-for-sdgs-and-intersectionality/.
येल आर्थिक विकास केंद्र। 2020a. तमिलनाडु, भारत में ईजीसी-सीएमएफ सर्वेक्षण। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://egc.yale.edu/data/egc-cmf-survey-tamil-nadu-india.
——. 2022b. औद्योगिक वायु प्रदूषण को कम करना: डेटा सिस्टम और नीति नवाचार। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://egc.yale.edu/ie/projects/reducing-industrial-air-pollution.
——. 2021a. प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास पर अध्ययन। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://egc.yale.edu/data/studies-early-childhood-development.
——. 2021बी. तमिलनाडु सोशल नेटवर्क मैपिंग सर्वे. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://egc.yale.edu/data/tamil-nadu-social-network-mapping-survey.
——. 2022a. TNSMS उपयोगकर्ता संदर्भ. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://egc.yale.edu/tnsms-users-reference.
येल मैकमिलन सेंटर. 2022. पोस्ट-डॉक्टोरल रिसर्च फेलो (2) -

आईएफएमआर/क्रेया विश्वविद्यालय में समावेशन अर्थशास्त्र भारत केंद्र. 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया. https://southasia.macmillan.yale.edu/post-doctoral-research-fellow-2-inclusion-economics-india-centre-ifmrkrea-university.
येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। 2014. गोदरेज के लिए केवल पागल लोग ही उपयुक्त हैं। 11 दिसंबर। 15 मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://som.yale.edu/blog/the-only-people-for-godrej-are-the-mad-ones.
येम्मा, जॉन, और डैनियल गोल्डन। 1998. हार्वर्ड के साम्राज्य पर सूरज कभी नहीं डूबता। https://web.archive.org/web/20091015101243/http://www.harvard60.org/china.html.
येंगदे, सूरज. 2020. ब्राह्मणवादी पितृसत्ता - यूपीएन | सूरज येंगड़े. 28 फरवरी. https://www.youtube.com/watch?v=SApNw5FuLSM.
——. 2021. कास्ट्स ऑफ माइंड. 24 मार्च. 15 फरवरी, 2022 को एक्सेस किया गया. https://thebaffler.com/latest/castes-of-mind.
——. 2019. अछूतों की चौथी दुनिया. 3 जनवरी. 15 फरवरी, 2022 को एक्सेस किया गया. https://www.aljazeera.com/opinions/2019/1/3/the-fourth-world-of-the-untouchables.
येउंग, बर्नार्ड। 2018. “योग्यतावाद पर टिप्पणियाँ: तांग की सिविल सेवक परीक्षा और कविता से अंतर्दृष्टि।” हार्वर्ड चाइना फंड। 1 मई। 15

मई, 2022 को एक्सेस किया गया। https://
hcf.fas.harvard.edu/wp-content/uploads/2018/05/
Yeung-Bernie-For-May-2018-b.pdf.
यंग, रॉबर्ट। 1990. श्वेत मिथक: इतिहास लेखन और पश्चिम। लंदन,
न्यूयॉर्क: रूटलेज।
यंग, सारा और स्टीफन एडिसन। 2020. ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स का कहना
है कि कोरोनावायरस रीसेट स्थिरता के लिए एक नया अवसर है। 3 जून।
30 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया। https://
www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-
britain-royals-idUSKBN23A2AC.
ज़ी मीडिया ब्यूरो। 2022। अमित शाह ने घोषणा की कि अगली
जनगणना ई-जनगणना होगी और कहा, 'यह 100 प्रतिशत सटीक होगी'।
10 मई। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया। https://
zeenews.india.com/india/next-census-to-be-e-census-
announces-amit-shah-says-it-will-be-100-per-cent-
perfect-2461986.html
*नोट: लिंक, लेख, ट्वीट आदि में कोई भी त्रुटि होने पर, उन्हें मूल रूप में ही प्रस्तुत किया गया है।

1. साक्ष्य जटिल है क्योंकि इसमें पुरातत्व, भाषाविज्ञान, कला इतिहास, लिखित साक्ष्य (मुख्यतः मौखिक) आदि जैसे कई विषय शामिल हैं। कई विद्वानों ने भाषाई और पुरातात्विक आधार पर आर्य आक्रमण सिद्धांत के विरुद्ध तर्क दिए हैं। कुछ ने तो यह भी प्रस्तावित किया है कि इंडो-यूरोपीय

भाषा परिवार का उद्गम स्थल भारत है, जिसे 'भारत से बाहर' सिद्धांत के नाम से जाना जाता है।

2. (मालहोत्रा 2016, 20)

3. उनकी पृष्ठभूमि के लिए: 'दीप्ति राव'। लिंक्डइन। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.linkedin.com/in/deepthirao05)

4. उनकी पृष्ठभूमि के लिए: 'दीप्ति राव'। लिंक्डइन। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.linkedin.com/in/deepthirao05)

5. (शेफर 2016)

6. (कुमार 2020)

7. (हिंदू छात्र परिषद 2021)

8. देखें: 'महासभा ने सर्वसम्मति से इस्लामोफोबिया से निपटने, चारागाहों की रक्षा करने, विधवाओं की कठिनाइयों का समाधान करने और सार्वजनिक परिवहन के रूप में साइकिल के उपयोग पर विधेयकों को अपनाया'। संयुक्त राष्ट्र। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.un.org/press/en/2022/ga12408.doc.htm)

1. लेखक इस अध्याय में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए निम्नलिखित दो पुस्तकों के आभारी हैं: 1) (प्लकरोज़ और लिंडसे 2020); 2) (बोगोसियन और लिंडसे 2019)।

2. मार्क्सवादी ढांचे में ग्राम्स्की ने सांस्कृतिक वर्चस्व की अवधारणा प्रस्तुत की। इसका तात्पर्य एक विविधतापूर्ण समाज पर शासक वर्ग के प्रभुत्व से है, जो उस समाज की संस्कृति—मान्यताओं, व्याख्याओं, धारणाओं, मूल्यों और रीति-रिवाजों—में हेरफेर करके उसे इस प्रकार स्थापित करता है कि शासक वर्ग का विश्वदृष्टिकोण स्वीकृत सांस्कृतिक मानदंड बन जाता है। इस प्रकार, सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक यथास्थिति को स्वाभाविक, अपरिहार्य और सभी वर्गों के लिए लाभकारी के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जबकि वास्तव में यह केवल शासक वर्ग के लाभ के लिए बनाई गई होती है।

3. ग्राम्स्की ने दो प्रकार के युद्धों के बीच रणनीतिक अंतर प्रस्तावित किया। स्थिति का युद्ध एक बौद्धिक और सांस्कृतिक संघर्ष है जिसका उद्देश्य एक सर्वहारा संस्कृति का निर्माण करना है जिसकी मूल मूल्य प्रणाली पूंजीपति वर्ग के सांस्कृतिक वर्चस्व का प्रतिकार करती है। इसमें वर्ग भेदों पर जोर दिया जाता है, जिससे अकादमिक विमर्श और क्रांतिकारी संगठन में परिवर्तन आता है। दूसरी ओर, पैंतरेबाजी के युद्ध में, सामाजिक क्रांति के लिए जन और राजनीतिक समर्थन जुटाया जाता है।

4. (हॉर्कहाइमर, क्रिटिकल थ्योरी सिलेक्टेड एसेज 1982, 244)

5. (मार्क्यूस 1964, 8)

6. (मार्क्यूस 1964)

7. (बुचर और गोंजालेज 2020)

8. (मार्क्यूस 1964, 256–57) और (हॉर्कहाइमर और एडोर्नो 2002, 106)

9. उत्तरआधुनिकतावादी विखंडन और वेदांत या बौद्ध धर्म के बीच एक बड़ा अंतर यह है कि वेदांत और बौद्ध धर्म भी द्वैत, अहंकार, सत्य के बारे में हमारे अपने अहंकार और हमारी अपनी भाषा पर आधारित धारणाओं आदि का विखंडन करते हैं। अंतर यह है कि वेदांत में सापेक्ष वास्तविकता से परे जाकर एक गहन परम वास्तविकता का विचार आता है। अतः नाम रूप की सापेक्ष वास्तविकता झूठी है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि इससे उच्च स्तर की कोई वास्तविकता नहीं है, जबकि उत्तरआधुनिकतावाद के मामले में, कोई उच्च वास्तविकता नहीं है, कोई परम, परम वास्तविकता नहीं है, और एक बार जब आप मानवीय शक्ति और सामाजिक विमर्श द्वारा निर्मित वास्तविकता का विखंडन कर देते हैं, तो कोई अन्य उच्च वास्तविकता नहीं रह जाती जो सार्वभौमिक प्रकार की हो। अंततः व्यक्ति अलग-अलग वास्तविकताओं वाली पहचानों के साथ एक-दूसरे से लड़ता हुआ और एक वर्चस्व को दूसरे वर्चस्व से प्रतिस्थापित करता हुआ प्रतीत होता है।

10 देखें: 'क्रिटिकल लीगल थ्योरी'। कॉर्नेल लॉ स्कूल। 30 अप्रैल,

2022 को प्राप्त किया गया (https://www.law.cornell.edu/wex/critical_legal_theory); (केनेडी और क्लेयर 1984)

11. (बुचर और गोंजालेज 2020)

12. (डेल्गाडो और स्टेफेंसिक 2017, 3)

13. रिचर्ड डेलगाडो और जीन स्टेफेंसिक जैसा कि (प्लकरोज़ और लिंडसे 2020, 115) में उद्धृत है।

14. (के. क्रेंशॉ 1989)

15. (कॉलिन्स 1990)

16. (कॉलिन्स और बिल्गे 2016, 2)

17. (Beshara 2019)

18. (मालहोत्रा, सीनेटर कोरी बुकर को खुला पत्र, 2022a)

19. (एनबीसी न्यूज़@एनबीसीन्यूज़ 2021)

20. (तमारी 2009)

21. (बोयर 2021)

22. (एबेलोव, बराले और हैलपेरिन 1993, 149) गेल रुबिन ने बाल यौन शोषण पर एक चरम रुख अपनाया है। वह बाल यौन शोषण को इन 'आवश्यक श्रेणियों' में से एक मानती हैं और नैतिक सापेक्षवाद का दृष्टिकोण अपनाती हैं। वह चाहती हैं कि हम बाल यौन शोषण करने वालों के प्रति सहानुभूति रखें, और लिखती हैं: 'अधिकांश लोगों के लिए लड़कों से प्रेम करने वालों के प्रति सहानुभूति रखना वास्तव में कठिन है। 1950 के दशक में कम्युनिस्टों और समलैंगिकों की तरह, लड़कों से प्रेम करने वालों को इतना कलंकित किया जाता है कि उनकी नागरिक स्वतंत्रता के रक्षक मिलना मुश्किल है, उनकी कामुक प्रवृत्ति के रक्षक मिलना तो दूर की बात है।' (एबेलोव, बराले और हैलपेरिन 1993, 147)

23. (बटलर 1993, 2)

24. बचपन की मासूमियत का विघटन: जूली सी. गार्लेन समझाती हैं: '...बचपन की मासूमियत की अवधारणा एक शक्तिशाली सामाजिक मिथक है जो बच्चों के सामाजिक संबंधों और संस्कृति को आकार देती है और समाज में उनके अधिकारों और स्थिति को निर्धारित करती है। ...बचपन की अवधारणाओं को आकार देने वाले भावनात्मक निवेशों और सामाजिक तनावों की जांच करके, जो यह परिभाषित करते हैं कि मासूमियत का हकदार कौन है और बचपन से जुड़ाव का क्या अर्थ है, मैं यह उजागर करती हूं कि कैसे मासूमियत के सिद्धांत ने श्वेत वर्चस्व को बनाए रखने में भूमिका निभाई है।' वह बचपन की मासूमियत को अप्राकृतिक मानती हैं और इसके लिए श्वेत वर्चस्व को दोषी ठहराती हैं। यह मासूमियत माता-पिता द्वारा उन 'जादुई बचपन के पलों' के माध्यम से

निर्मित की जाती है जिन्हें वे चाहते हैं कि बच्चा हमेशा के लिए याद रखे, जैसे कि 'सोने से पहले के गीत और कहानियां, लंच बॉक्स में प्यार भरे संदेश, चुंबन, किले बनाना, कीड़े और जुगनू पकड़ना, अलाव जलाना, बर्फ के गोले से खेलना, कंधे पर बिठाकर घुमाना, बागवानी करना, खाना बनाना, संगठित रोमांच और आसानी से उपलब्ध कला, संगीत और सांस्कृतिक अनुभव'। माता-पिता का लक्ष्य बच्चों में एक खुशहाल बचपन की यादें बसाना है, जो संगीत, हंसी, खोज और धूप से भरपूर हो। वे कहती हैं कि छुट्टियां 'खुशी के सहारे' का काम करती हैं, जो बाद में 'वयस्कता के बोझ को हल्का करती हैं'। उनका मानना है कि यह पालन-पोषण बनावटी है, क्योंकि इसका उद्देश्य 'बच्चों के लिए असाधारण वयस्क यादें संजोना' है, जिसके लिए वे एक काल्पनिक, विस्मयकारी और जादुई पलों से भरे दौर का निर्माण करते हैं। माता-पिता यौनिकता, मृत्यु, हिंसा और गरीबी जैसे विषयों पर रोक लगाकर बच्चों को दुख और तनाव जैसी स्वाभाविक चीजों से बचाते हैं। वे एक विशेष प्रकार का 'बचपन' बनाकर 'बच्चों की यौन स्वतंत्रता' के साथ-साथ नस्लीय संबंधों को भी नियंत्रित करना चाहते हैं, जो श्वेत वर्चस्व को कायम रखता है। गार्लेन कहती हैं कि यह 'मासूमियत को रूढ़िवादी ईसाई मूल्यों के साथ मिलाना' है। उनका मानना है कि हिंसा दर्शाने वाले खिलौने, खेल, वीडियो गेम और टीवी शो मासूमियत के लिए खतरा हैं, क्योंकि वे ईसाई मूल्यों पर सीधा हमला हैं। लैंगिक तरलता बचपन की मासूमियत पैदा करने के माता-पिता के एजेंडे के लिए खतरा है। मासूमियत की परिभाषा गलत है, क्योंकि इसमें बच्चों को वयस्कों के यौन इच्छा, उपभोग, हिंसा और अनैतिकता के ज्ञान से बचाने की आवश्यकता बताई गई है। यह इस धारणा पर आधारित है कि वयस्क संस्कृति भ्रष्ट है और बच्चों को इससे बचाने की आवश्यकता है। गार्लेन वयस्क-बच्चे के द्वंद्व को चुनौती देती हैं।

वह संरचनात्मक समस्या को समझाती हैं: 'बचपन की मासूमियत को प्राथमिकता देने से श्वेत अभिजात वर्ग की श्रेष्ठता मजबूत हुई, जो नए ईसाई धर्मनिष्ठा के आदर्श के रूप में कार्य करते थे और अच्छे ईसाई बच्चों के प्राथमिक पालन-पोषणकर्ता के रूप में महिलाओं की भूमिका पर जोर देते थे। ऐसे समय में जब मानव दासता की नैतिकता को अब उचित नहीं ठहराया जा सकता था, बचपन की मासूमियत का सिद्धांत श्वेत अमेरिकियों के लिए एक प्रकार का परोक्ष क्षमादान भी प्रदान करता था।' उनका घोषित लक्ष्य 'सामाजिक न्याय की स्थितियों को आगे बढ़ाने' के लिए मासूमियत की पारंपरिक धारणाओं को समाप्त करना है। (सभी उद्धरण: (गार्लेन 2018))।

25. (रामास्वामी 2021, 216)

26. (रामास्वामी 2021, 231)

27. (मिशेल 2019)

28. (मिशेल 2019)

29. (रामास्वामी 2021, 258-59)

30. (डफर्टी 2018)

31. इसका एक उदाहरण 2015 में एक सार्वजनिक प्रांगण में येल के प्रोफेसर निकोलस क्रिस्टाकिस और छात्रों के बीच हुई मुठभेड़ थी। यह

वीडियो स्वतंत्र सोच की हठधर्मिता और गिरोह-जैसी धमकियों को दर्शाता है: (ग्रेविटाहन 2017)

32. (जय 1996, 69)

33. (जोलीवेट 2015, 5)

34. (नंदा 2001, 165)

35. (राइली 2008, 109)

36. देखें: 'प्रोफेसर ने "सत्य और ज्ञान" के विरुद्ध तर्क दिया; कहा गणित = श्वेत विशेषाधिकार'। द न्यू अमेरिकन। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया (https://thenewamerican.com/professor-argues-against-truths-and-knowledge-says-math-white-privilege)

37. (डफर्टी 2018)

38. हर्बर्ट मार्क्यूज़, 'दमनकारी सहिष्णुता', (वोल्फ, मूर, जूनियर और मार्क्यूज़ 1969, 110)

39. (बेल 1995, 893, 902) इसके अलावा, (बुचर और गोंजालेज 2020) में उद्धृत।

40. (डियांगेलो, व्हाइट फ्रैजिलिटी 2011)

41 (सोवे 2020)। 2020 में वह प्रति भाषण चौदह हजार डॉलर लेती थीं और अब उन्होंने अपनी फीस बढ़ाकर तीस हजार से चालीस हजार डॉलर कर दी है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अपनी बेस्टसेलर पुस्तक से मिलने वाली 7.5 प्रतिशत रॉयल्टी के अलावा, उनकी सालाना आय $728,000 थी। देखें: (एबरहार्ट 2021)

42. (सेनसोय और डिएन्जेलो 2017, 20,23,24)

43. (सेनसोय और डिएन्जेलो 2017, 15)

44. (सेनसोय और डिएन्जेलो 2017, 84-85)

45. (डियांगेलो 2011, 55-56)। वह श्वेत संवेदनशीलता का एक विशिष्ट उदाहरण देती हैं: 'श्वेत संवेदनशीलता का एक ठोस उदाहरण हाल ही में कार्यस्थल पर नस्लवाद-विरोधी प्रशिक्षण के दौरान सामने आया, जिसका संचालन मैंने एक अंतर-नस्लीय टीम के साथ मिलकर किया था। श्वेत प्रतिभागियों में से एक सत्र छोड़कर अपनी डेस्क पर वापस चली गई, क्योंकि उसे (प्रशिक्षण टीम को जो संवेदनशील और कूटनीतिक प्रतिक्रिया प्रतीत हुई) इस बात पर आपत्ति थी कि उसके कुछ कथनों ने कमरे में मौजूद कई अश्वेत लोगों को कैसे प्रभावित किया था। विराम के दौरान, कई अन्य श्वेत प्रतिभागी हमारे (प्रशिक्षकों) पास आए और बताया कि उन्होंने डेस्क पर बैठी उस महिला से बात की थी, और वह अपने कथनों पर सवाल उठाए जाने से बहुत परेशान थी। वे हमें यह बताना चाहते थे

कि उसे सचमुच "दिल का दौरा पड़ सकता है"। हमारे पूछने पर, उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मतलब सचमुच यही था। ये सहकर्मी अपने इस डर में गंभीर थे कि प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप वह युवती वास्तव में शारीरिक रूप से मर सकती है।' बेशक, जब महिला की संभावित रूप से जानलेवा स्थिति की खबर बाकी प्रतिभागियों तक पहुंची, तो सारा ध्यान तुरंत उस पर केंद्रित हो गया और अश्वेत लोगों पर उसके प्रभाव से ध्यान हट गया। (डियांगेलो 2011, 64-65)

46. (एप्पलबाउम 2010, 108)

47. (एप्पलबाउम 2010, 188-89)

48. (बेली 2017, 880)

49. (ग्रे 2013)

50. (पेर्ना 2018)

51 विडंबना यह है कि मनुस्मृति पर हमला करते समय यही तर्क लागू नहीं होता। सुसंगत रहने के लिए, उन्हें यह कहना होगा कि जाति को समझने के लिए मनुस्मृति को एक विश्वसनीय स्रोत नहीं माना जा सकता।

52. (स्कोलफील्ड 2021)

53. (स्कोलफील्ड 2021)

54. (एलिसी 2020)

55. (एलिसी 2020)

56. (wzgrl 2008, 00:02:08)

57. (बोनीला-सिल्वा और डायट्रिच 2011)

58. “हमारा संविधान रंगभेद नहीं करता, और नागरिकों के बीच किसी भी वर्ग को न तो मानता है और न ही सहन करता है। नागरिक अधिकारों के मामले में, सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं।” देखें: ‘प्लेसी बनाम फर्ग्यूसन, 163 यू.एस. 537 (1896)’। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त (https://supreme.justia.com/cases/federal/us/163/537) यह भी देखें: ‘कम्युनिटी स्कूलों में शामिल माता-पिता बनाम सिएटल स्कूल डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 (28/06/07)’। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त (https://www.supremecourt.gov/opinions/06pdf/05-908.pdf)

59. (एफ़ेलबाउम, नॉर्टन और सोमरस 2012)

60. देखें: ‘इबराम एक्स. केंडी ने नस्लवाद-विरोधी होने का अर्थ समझाया है’। पेंगुइन। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.penguin.co.uk/articles/2020/june/

ibram-x-kendi-definition-of-antiracist.htm)

61. (VI-कंट्रोल 2007)

62. (बोनीला-सिल्वा और डायट्रिच 2011)

63. (बोनीला-सिल्वा और डायट्रिच 2011)

64. (कोट्स 2015)

65. (बोनीला-सिल्वा 2003)

66. (डीन 2013)

67. (बोनीला-सिल्वा और डायट्रिच 2011)

68. (बोनीला-सिल्वा और डायट्रिच 2011)

69. (बोनीला-सिल्वा और डायट्रिच 2011)

70. (क्रेंशॉ, एट अल. 2019, 128)

71. (क्रेंशॉ, एट अल. 2019, 128)

72. (फेरलाज़ो, 2019)

73. ‘सीआरटी उदारवाद की बुनियाद पर ही सवाल उठाता है, जिसमें समानता का सिद्धांत, कानूनी तर्क, ज्ञानोदय का तर्कवाद और संवैधानिक कानून के तटस्थ सिद्धांत शामिल हैं।’ (डेल्गाडो और स्टेफेंसिक 2017, 3)

74. (रामास्वामी 2021)

75. (एनेनबर्ग पब्लिक पॉलिसी सेंटर 2021)

76. स्प्रिंगफील्ड, इलिनोइस के यंग मेन्स लाइसेम के समक्ष अब्राहम लिंकन द्वारा दिया गया भाषण, जैसा कि संगामो जर्नल में 3 फरवरी, 1838 को प्रकाशित हुआ था। (बेसलर 1953) से पुनर्मुद्रित। (द जर्नल ऑफ द अब्राहम लिंकन एसोसिएशन 1984) भी देखें।

77. (2020 में खरीदें)

78. देखें: ‘एसएचआरएम के बारे में’। एसएचआरएम। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.shrm.org/about-shrm/pages/default.aspx)

79. (डियांगेलो, व्हाइट फ्रैजिलिटी 2018, xiv)

80. (स्वयं द्वारा रिकॉर्ड किया गया, 2019, 163)

81. (रामास्वामी 2021, 2)

82. (रामास्वामी 2021, 3)

83. (रामास्वामी 2021, 135)

84. (रामास्वामी 2021, 139)

85. (रामास्वामी 2021, 143)

86. (रामास्वामी 2021, 19)

1. (Malhotra and Neelakandan 2011, 11)

2. (विल्करसन 2020)

3. (विल्करसन 2020, 273)

4. (न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी 2020)

5. देखें: 'इसाबेल विल्करसन'। इसाबेल विल्करसन। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.isabelwilkerson.com)

6. देखें: 'जाति और डरबन सम्मेलन'। विदेश मंत्रालय: भारत सरकार। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त किया गया (https://

www.mea.gov.in/articles-in-indian-media.htm?dtl/18479/Caste+and+the+Durban+conference)

7. (विल्करसन 2020, 176)

8. (विल्करसन 2020, 17)

9. (विल्करसन 2020, 24)

10. (विल्करसन 2020, 18)

11. (विल्करसन 2020, 19)

12. (विल्करसन 2020, 19)

13. (विल्करसन 2020, 26)

14. (विल्करसन 2020, 29)

15. (विल्करसन 2020, 25)

16. (विल्करसन 2020, 29)

17. (विल्करसन 2020, 74)

18. (विल्करसन 2020, 104)

19. (विल्करसन 2020, 268)

20. देखें: ‘भारत में अफ़्रीकी: दासों से लेकर सेनापतियों और शासकों तक’। न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी। 15 फ़रवरी, 2022 को प्राप्त (https://www.nypl.org/blog/2013/01/31/africans-india-slaves-generals-and-rulers) यह भी देखें: ‘हिंद महासागर और मध्य पूर्वी दास व्यापार’। ऑक्सफ़ोर्ड बिब्लियोग्राफ़ीज़। 15 फ़रवरी, 2022 को प्राप्त (https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199846733/obo-9780199846733-0051.xml) और ‘अटलांटिक दास व्यापार में पूर्वी अफ्रीका की भूमिका की कहानी’। द कन्वर्सेशन। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त किया गया (https://theconversation.com/the-story-of-east-africas-role-in-the-transatlantic-slave-trade-43194)

21. (लेवी 2002) जब मैंने पहली बार विस्कॉन्सिन-मैडिसन विश्वविद्यालय में स्कॉट लेवी के पीएचडी शोध प्रबंध को देखा, तो मुझे उसमें मुसलमानों से पहले भारत में दास प्रथा का कोई ज़िक्र नहीं मिला। यह शोध प्रबंध भारत में इस्लाम के समय की दास प्रथा पर था और यह पूर्व सोवियत संघ में उपलब्ध उस काल के अभिलेखागारों पर आधारित था। लेकिन फिर अकादमिक विद्वानों ने चेतावनी जारी की कि उनका काम मेरे जैसे "हिंदू कार्यकर्ताओं" के हाथों में खेल सकता है। प्रकाशित

संस्करण में एक प्रस्तावना जोड़ी गई जिसमें कहा गया कि भारत में दास प्रथा इस्लाम से पहले की है क्योंकि इसका उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। हालाँकि, यह दावा गलत है क्योंकि यह वैदिक संस्कृत शब्द "दास" का "दास" के रूप में गलत अनुवाद पर आधारित है, जो कि एक गलत अनुवाद है।

22. देखें: 'भारतीय मुसलमानों में जाति एक वास्तविक मुद्दा है। तो उन्हें आरक्षण से वंचित क्यों किया जाए?' द वायर। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त (https://thewire.in/caste/caste-among-indian-muslims-real-why-deny-reservation) और साथ ही 'भारतीय मुसलमानों में इस्लाम और जातिगत असमानता'। इंडियन दलित मुस्लिम्स वॉयस। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त (https://dalitmuslims.wordpress.com/2009/07/13/islam-and-caste-inequality-among-indian-muslims)

23. देखें: 'उत्तर भारत और पाकिस्तान में मुस्लिम जाति पर बहस: औपनिवेशिक नृवंशविज्ञान से पस्मंदा लामबंदी तक'। एचएएल ओपन साइंस। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त (https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02697381) और साथ ही 'भारत का मुस्लिम समुदाय उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है: 85% पिछड़े पस्मंदा बनाम 15% अशरफ'। द प्रिंट। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त (https://theprint.in/opinion/indias-muslim-community-under-a-churn-85-backward-pasmandas-up-against-15-ashrafs/234599)

24. स्पेनिश जाति व्यवस्था: 'स्पेनिश जाति व्यवस्था'। नुएस्ट्रा वेरदाद पब्लिकेशियन। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त (https://www.nuestraverdad.com/post/spanish-caste-system); लैटिन अमेरिकी जाति व्यवस्था: 'चित्र 1 - हेक्टर वाई एडम्स द्वारा अपलोड किया गया'। रिसर्चगेट। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त (https://www.researchgate.net/figure/Latin-American-Social-Caste-Pyramid-LASCP_fig1_262107699); पाकिस्तान की जाति व्यवस्था: (बार्थ 1956); चीन की शहरी जाति व्यवस्था: (टैंग और यांग 2008); जापान की जाति व्यवस्था: "जापान की अछूतों की गुप्त जाति।" बीबीसी न्यूज़। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त (https://www.bbc.com/news/world-asia-34615972)

25. (विल्करसन 2020, 76)

26. उदाहरण के लिए, कॉक्स की 1948 की पुस्तक देखें जिसमें कहा गया है कि जाति नस्ल नहीं है। 'जाति, वर्ग और नस्ल'। ग्लोबल सोशल थ्योरी। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त किया गया (https://globalsocialtheory.org/concepts/caste-class-and-race)

27. (विल्करसन 2020, 106)

1. (इक्वालिटी लैब्स 2018a)

2. (नॉर्थ स्टार फंड 2017)

3. देखें: ‘डॉ. टी.एस.एस. राजन एमडी’। यू.एस. न्यूज़। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया (https://health.usnews.com/doctors/tss-rajan-1225010)

4. देखें: 'थेनमोझी सुंदरराजन'। वर्जीनिया टेक. 30 अप्रैल, 2022 को पुनःप्राप्त (https://ccc.ipg.vt.edu/Programs/forum/Thenmozhi.html)

5. (इक्वालिटी लैब्स 2018a)

6. (इक्वालिटी लैब्स 2018बी)। पूर्ण रिपोर्ट के पृष्ठ 39 देखें।

7. (Badrinathan, et al. 2021)

8. (Badrinathan, et al. 2021)

9. (मेटकाफ और रोल्फ़ 2010)

10. (इक्वालिटी लैब्स 2018बी)

11. देखें: ‘अमेरिका में जाति पर एक ऐतिहासिक कांग्रेसी सुनवाई’। द वायर। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त किया गया (https://thewire.in/caste/a-historic-congressional-hearing-on-caste-in-the-us)

12. (आर. राव 2021)

13. देखें: 'हम किनमें निवेश करते हैं'। न्यू मीडिया वेंचर्स। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त (https://www.newmediaventures.org/investments) यह भी देखें: 'इक्वालिटी लैब्स का 1 निवेशक, न्यू मीडिया वेंचर्स'। क्रंचबेस। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त (https://www.crunchbase.com/search/principal.investors/field/organizations/num_investors/equality-labs) और: https://mobile.twitter.com/by2kaafi/status/1247926029319987206 इस ट्वीट में, जिसे हटा दिया गया है, कहा गया था: 'न्यू मीडिया वेंचर्स (NMV) इक्वालिटी लैब्स में एक एंजेल निवेशक है। NMV के कई निवेशक हैं जिनमें से एक नाम जाना-पहचाना है - ओमिडयार नेटवर्क'।

14. (इक्वालिटी लैब्स 2018बी)

15. देखें: 'थेनमोझी सौंदराजन'। अटलांटिक फेलो। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त (https://racialequity.atlanticfellows.org/fellow/thenmozhi-soundararajan); यह भी देखें: 'द अटलांटिक इंस्टीट्यूट'। रोड्स ट्रस्ट। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त (https://www.rhodeshouse.ox.ac.uk/about/the-atlantic-institute)

16. देखें: 'दमनकारी व्यवस्था का वर्णन करना अपशब्द नहीं है'।

Scroll.in. 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त किया गया (https://scroll.in/article/902949/describing-a-system-of-oppression-is-not-a-slur-creator-of-smash-brahmanical-patriarchy-poster)

17. देखें: 'एचएएफ की कानूनी टीम ने सीडीई को हमले के आरोपों की जांच करने के लिए पत्र लिखा'। एचएएफ। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.hinduamerican.org/press/haf-legal-team-writes-cde-investigate-assault-allegations)

18. देखें: 'हमें जातिगत उत्पीड़न क्यों समाप्त करना चाहिए'। रीएप्रोप्रिएट। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त किया गया (http://reappropriate.co/2018/05/why-we-must-end-caste-oppression/)

19. देखें: '2020.06.30 DFEH बनाम सिस्को सिस्टम्स, एट अल. दीवानी शिकायत – दायर'। स्क्रिब्ड। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.scribd.com/document/467774912/2020-06-30-DFEH-v-Cisco-Systems-Et-Al-Civil-Complaint-FILED)

20. (राइजिंग अप विद सोनाली 2020). समय: 8:01

21. (राइजिंग अप विद सोनाली 2020). समय: 9:05-9:41

22 देखें: 'Protecting Our People'□ सिस्को। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त (https://blogs.cisco.com/news/protecting-our-people)□ मामला अक्टूबर 2020 में खारिज कर दिया गया था। लेकिन सिस्को के बचाव में ऐसे बयान शामिल थे कि कानून यह नहीं कहता कि आप जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते! देखें: 'कैलिफोर्निया विभाग ने सिस्को के खिलाफ कर्मचारी उत्पीड़न का मामला खारिज किया'। द टाइम्स ऑफ इंडिया। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त (https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/california-dept-dismisses-employee-harassment-case-against-cisco/articleshow/78760768.cms)

23. (Mukherji 2021)

24 देखें: 'भारत के इंजीनियरों ने सिलिकॉन वैली में खूब तरक्की की है। साथ ही, यहाँ की जाति व्यवस्था भी फली-फूली है।' द वाशिंगटन पोस्ट। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.washingtonpost.com/technology/2020/10/27/indian-caste-bias-silicon-valley/)

25. BAPS stands for Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha.

26. देखें: 'अमेरिका में जातिगत असमानता अभी भी कानूनी क्यों है?' द न्यूयॉर्क टाइम्स। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त किया गया (https://

www.nytimes.com/2021/05/25/opinion/caste-discrimination-us-federal-protection.html)

27. देखें: 'अमेरिकी कॉलेज जाति को एक संरक्षित वर्ग के रूप में मान्यता देना शुरू कर रहे हैं'। क्वार्ट्ज इंडिया। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त किया गया (https://qz.com/india/2081765/us-universities-like-uc-davis-ban-indian-caste-system-on-campus/)

28. देखें: 'कंपनियों ने नस्लीय समानता के लिए 35 अरब डॉलर देने का वादा किया है। पैसा कहाँ जा रहा है?' द वॉल स्ट्रीट जर्नल। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.wsj.com/articles/companies-have-promised-billions-toward-racial-equity-where-is-the-money-going-11608570864)

29. देखें: 'कार्यालय विविधता प्रशिक्षण का अधूरा काम'। द वॉल स्ट्रीट जर्नल। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.wsj.com/articles/the-unfinished-business-of-office-diversity-training-11608512401)

30. देखें: 'विविधता एक फलता-फूलता व्यवसाय बन गया है। तो परिणाम कहाँ हैं?' टाइम पत्रिका। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त किया गया (https://time.com/5696943/diversity-business)

31. देखें: 'ईईओ डेटा संग्रह'। अमेरिकी समान रोजगार अवसर आयोग।

15 फरवरी, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.eeoc.gov/employers/eeo-data-collections)

32. देखें: 'ब्रैंडिस गैर-भेदभाव नीति के अंतर्गत जाति की व्याख्या पर वक्तव्य'। ब्रैंडिस विश्वविद्यालय। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.brandeis.edu/human-resources/policies/discrimination/caste-statement.html)

33. देखें: 'यूसी डेविस ने चुपचाप अपनी भेदभाव-विरोधी नीति में जाति को शामिल कर लिया है। क्या इससे अन्य विश्वविद्यालय भी ऐसा ही करेंगे?' सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त (https://www.sfchronicle.com/california/article/UC-Davis-quietly-added-caste-to-its-16626845.php) यह भी देखें: 'कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बोर्ड ने जातिगत भेदभाव से सुरक्षा को मान्यता देने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया'। द हिंदू। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त (https://www.thehindu.com/news/international/california-varsity-board-unanimously-votes-to-recognise-protection-from-caste-discrimination/article38328354.ece)

34. कोल्बी कॉलेज के लिए देखें: 'मेन के कोल्बी कॉलेज ने जाति के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया'। एपी। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त किया गया (https://apnews.com/article/asia-education-discrimination-maine-south-asia-a4934667f35e70733e4986474a5021b0)

35. (Tejeda and Chahal 2021)

36. (Tejeda and Chahal 2021)

37. (Tejeda and Chahal 2021)

38. (Tejeda and Chahal 2021)

39. (Tejeda and Chahal 2021)

40. (आर. राव 2021)

41. (सांता क्लारा काउंटी 2020)

42. (सांता क्लारा काउंटी 2020)

43. देखें: 'कार्यवाही'। सांता क्लारा काउंटी मानवाधिकार आयोग। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त किया गया (http://sccgov.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=12&ID=8723&Inline=True)

44. (दीया टीवी 2021). टाइमस्टैम्प: 05:28:20. वक्ता ने अपनी पहचान निखिला लक्ष्मण के रूप में बताई।

45. (अंबेडकर किंग स्टडी सर्कल यूएसए 2021)

46. देखें: 'विषय: संयुक्त राज्य अमेरिका में जाति आधारित भेदभाव'। सांता क्लारा काउंटी। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त किया गया (http://sccgov.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=4&ID=213125)

47. (बोर्गोग्नियन 2017)

48. (इक्वालिटी लैब्स 2020)

49. देखें: 'अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज में एक मुस्लिम छात्र ने तीन प्रोफेसरों पर सिर्फ इसलिए झूठे आरोप लगाए क्योंकि वे हिंदू हैं: विवरण'। ओपइंडिया। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.opindia.com/2021/10/muslim-student-made-false-allegations-against-hindu-professors-in-usa)

50. (अनिवार्य मध्यस्थता 2022 समाप्त). समय: 30:43-32:11.

51. (किंग 2018)

1. देखें: 'दक्षिण एशिया सीमा-रहित सेमिनार श्रृंखला'। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया (https://

mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/event/south-asia-without-borders-seminar-series)

2. (सुब्रमणियन 2019, 23)

3. (वेबर 1905)

4. देखें: 'ईसाई धर्म की योग्यतावादी दुविधा: सैंडेल की 'द टायरेनी ऑफ मेरिट' पर चिंतन'। प्रोविडेंस पत्रिका। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त किया गया (https://providencemag.com/2021/11/christianitys-meritocratic-dilemma-reflections-michael-sandel-tyranny-of-merit/)

5. (सैंडेल 2020)

6. देखें: 'माइकल सैंडेल: "लोकप्रियतावादी प्रतिक्रिया योग्यता के अत्याचार के विरुद्ध एक विद्रोह रही है"'। द गार्जियन। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.theguardian.com/books/2020/sep/06/michael-sandel-the-populist-backlash-has-been-a-revolt-against-the-tyranny-of-merit)

7. (सुब्रमणियन 2019, 27)

8. (सुब्रमणियन 2019, 28)

9. (सुब्रमण्यन 2019, 31)

10 ब्रिटेन के विपरीत, जर्मनी में तकनीकी कार्य के मानसिक और शारीरिक पहलू एकीकृत हैं, और छात्रों से बढ़ईगिरी और धातु के काम जैसे शारीरिक कार्यों के साथ-साथ बौद्धिक, वैचारिक और अमूर्त कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। वास्तव में, जर्मन इंजीनियरिंग में सिद्धांत की तुलना में तकनीक को प्राथमिकता दी जाती है। इंजीनियर को सबसे पहले एक कुशल तकनीशियन के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है।

11. (सुब्रमण्यन 2019, 26)

12. (मालहोत्रा, द पीयर-रिव्यू कार्टेल 2022बी)

13. यह लेख का थोड़ा संपादित संस्करण है: (मालहोत्रा 2022बी)

14. (साम्बारा 2021)

15. हार्वर्ड के अध्यक्ष लैरी समर्स उस समय विवादों में घिर गए जब उन्होंने कहा कि पुरुषों और महिलाओं की योग्यताएं अलग-अलग प्रकार की होती हैं। देखें: 'हार्वर्ड अध्यक्ष द्वारा लिखित 'विज्ञान में महिलाएं कमजोर क्यों होती हैं'। द गार्जियन। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.theguardian.com/science/2005/jan/18/educationsgendergap.genderissues)

16. (सिंधवानी 2020)

17. (सुब्रमण्यन 2019, 260)

18. (सुब्रमण्यन 2019, 268)

19. (सुब्रमण्यन 2019, 293)

20. (सुब्रमण्यन 2019, 299)

21. (साम्बारा 2021)

22. (अंबेडकर किंग स्टडी सर्कल यूएसए 2020). समय: 03:54 और 9:54.

23. (साम्बारा 2021)

24. (अंबेडकर किंग स्टडी सर्कल यूएसए 2020). समय: 20:28.

25. (अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर (एआईसी) 2021)

26. (अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर (एआईसी) 2021)

27. (अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर (एआईसी) 2021)

28. (साम्बारा 2021)

29. (सुब्रमण्यन 2019, 304)

30. (सुब्रमण्यन 2019, 305)

31. (कोडाइकनाल इंटरनेशनल स्कूल 2021). टाइमस्टैम्प: 00:00:43-00:00:51.

32. (सुब्रमण्यन 2019, 314)

33. (सुब्रमण्यन 2019, 303)

34. सुब्रमणियन का असली रंग तब सामने आता है जब वह कश्मीर के अलगाववादियों, मकबूल भट्ट और अफजल गुरु का समर्थन करना शुरू करती हैं, जिन पर 2001 में भारतीय संसद पर हुए आतंकवादी हमले का आरोप लगाया गया था। यह दिलचस्प है कि उनकी आलोचना अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की उन रिपोर्टों में भी झलकती है जिनमें भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के कथित दमन के कारण 'चिंताजनक देश' बताया गया है। खुद को यूएससीआईआरएफ के साथ खड़ा करते हुए, वह मोदी पर मुसलमानों और दलितों पर हिंसक हमलों, नागरिक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और पत्रकारों की हत्या का आरोप लगाती हैं। उनका मानना है कि पिछली सरकारों के शासनकाल में ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुईं। वह मोदी सरकार की संस्कृत का जश्न मनाने और शाकाहारियों और मांसाहारियों के लिए अलग-अलग सुविधाएं

स्थापित करने की भी आलोचना करती हैं, मानो यह निचली जाति के हितों के विपरीत हो।

35. (सुब्रमणियन 2019, 321)

36. (साम्बारा 2021)

37. (साम्बारा 2021)

38. (हिगिंस 2021)

1. देखें: 'सूरज येंगडे - अमेरिका और भारत में नस्ल और जाति पर परिप्रेक्ष्य, वैश्विक नस्लवाद पर वक्ता श्रृंखला'। लोयोला यूनिवर्सिटी शिकागो। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.luc.edu/asianstudies/events)

2. देखें: 'जैसे-जैसे हम फ्लॉयड और व्यवस्थागत पूर्वाग्रह पर बहस कर रहे हैं, इस तरह की नैतिक शक्ति की आवश्यकता और महत्व आज के समय में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है'। द इंडियन एक्सप्रेस। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त किया गया (https://indianexpress.com/article/opinion/columns/george-floyd-us-india-dalit-advisasi-6479505)

3. (लेउंग 2021)

4. (द वायर 2021). टाइमस्टैम्प: 30:57.

5. देखें: 'अफ्रीका में भारतीय प्रवासी समुदाय में जाति'। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.epw.in/journal/2015/37/notes/caste-among-indian-diaspora-africa.html)

6. (आंटी 2019)

7. (डी'सूजा 2020). समय: 19:36-21:20.

8. (हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन 2019). समय: 01:19:26.

9. (हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन 2019). समय: 01:14:05.

10. (हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन 2019). समय: 01:07:29.

11. (आंटी 2021)

12. (सम्यक चेतना 2021)। टाइमस्टैम्प: 24:19.

13. (सम्यक चेतना 2021)। टाइमस्टैम्प: 26:25.

14. (Samyak Chetna 2021)

15. (सम्यक चेतना 2021)। टाइमस्टैम्प: 07:08.

16. (बैंगलोर इंटरनेशनल सेंटर 2019). टाइमस्टैम्प: 01:07:29.

17. (झारगॉव टीवी 2021)

18. देखें: 'आदिवासी कभी हिंदू नहीं थे, वे कभी नहीं होंगे: झारखंड के मुख्यमंत्री'। द इंडियन एक्सप्रेस। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त किया गया (https://indianexpress.com/article/india/adivasis-were-never-hindus-they-never-will-be-jharkhand-cm-7199096)

19. (सम्यक चेतना 2021)। टाइमस्टैम्प: 35:58

20. देखिए: 'यह बदसूरत सिर वाला कूड़ेदान—शंकराचार्य इस तरह के अपराधों के लिए जिम्मेदार है। भारत में आतंकवादी जातिगत आतंकवाद फैला रहे हैं। अभी तक ऐसे गर्वित ब्राह्मण और हिंदू देखने को नहीं मिले हैं जो अंतरजातीय विवाहों के माध्यम से सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देते हों। युवाओं को चुनाव करना होगा।' ट्विटर। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त (https://twitter.com/surajyengde/status/1368201526028697601)

21. (सम्यक चेतना 2021)। टाइमस्टैम्प: 36:22.

22. (हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन 2019). टाइमस्टैम्प: 01:20:23.

23. (सम्यक चेतना 2021)। टाइमस्टैम्प: 43:06.

24. (सम्यक चेतना 2021)। टाइमस्टैम्प: 43:48.

25. (सम्यक चेतना 2021)। टाइमस्टैम्प: 45:14.

26. (सम्यक चेतना 2021)। टाइमस्टैम्प: 37:13.

27. (सम्यक चेतना 2021)। टाइमस्टैम्प: 35:00।

28. (सम्यक चेतना 2021)। टाइमस्टैम्प: 40:51.

29. (द वायर 2021). टाइमस्टैम्प: 06:05.

30. (द वायर 2021). टाइमस्टैम्प: 03:50.

31. (द वायर 2021). समय: 21:30.

32. (द वायर 2021). टाइमस्टैम्प: 25:50.

33. (द वायर 2021). टाइमस्टैम्प: 07:25.

34. (द वायर 2021). टाइमस्टैम्प: 13:55.

35. (बैंगलोर इंटरनेशनल सेंटर 2019). समय: 09:18.

36. (द वायर 2021). समय: 20:00.

37. (बैंगलोर इंटरनेशनल सेंटर 2019). समय: 22:27.

38. (बैंगलोर इंटरनेशनल सेंटर 2019). समय: 09:00.

39. (डी'सूजा 2020). समय: 26:30.

40. (डी'सूजा 2020). टाइमस्टैम्प: 26:50.

41. (अशोका टीवी चैनल 2017). समय: 21:20.

42. (डी'सूजा 2020). टाइमस्टैम्प: 36:24.

43. (बैंगलोर इंटरनेशनल सेंटर 2019). टाइमस्टैम्प: 01:22:00.

44. (बैंगलोर इंटरनेशनल सेंटर 2019). टाइमस्टैम्प: 01:22:05.

45. (बैंगलोर इंटरनेशनल सेंटर 2019). टाइमस्टैम्प: 01:28:01.

46. (डी'सूजा 2020). टाइमस्टैम्प: 45:40.

47. (द वायर 2021). टाइमस्टैम्प: 09:40.

48. (द वायर 2021). समय: 16:30.

49. (रोड्रिग्स 2020)

50. (बैंगलोर इंटरनेशनल सेंटर 2019). समय: 01:20:25.

51. (बैंगलोर इंटरनेशनल सेंटर 2019). टाइमस्टैम्प: 01:25:20.

52. (अशोका टीवी चैनल 2017). टाइमस्टैम्प: 42:33.

53. (बैंगलोर इंटरनेशनल सेंटर 2019). टाइमस्टैम्प: 00:39:00.

54. देखें: 'सूरज मिलिंद येंगडे का कथन: हर सेमेस्टर में 10,000 दलित छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों में भेजें'। द इकोनॉमिक टाइम्स। 14 अगस्त, 2016। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त किया गया (https://economictimes.indiatimes.com/opinion/interviews/send-10000-dalit-students-every-semester-to-foreign-universities-suraj-milind-yengde/articleshow/53690113.cms)

55. देखें: 'आरक्षण हमारी सबसे महत्वपूर्ण राज्य नीति है और हम इसे छोड़ नहीं सकते'। द काठमांडू पोस्ट। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त (https://kathmandupost.com/interviews/2019/07/09/reservation-is-the-most-

important-state-policy-we-have-and-we-can-t-give-up-on-that)

56. (हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन 2019). टाइमस्टैम्प: 01:25:10.

57. देखें: 'आरएसएस = ब्राह्मण वर्चस्व। आप = बनिया वर्चस्व। ब्राह्मण-बनिया राज में आपका स्वागत है'। ट्विटर। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया (https://twitter.com/surajyengde/status/1506530077412151300)

58. (Najar 2017)

59. (रोड्रिग्स 2020)

60. देखें: 'ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय जाति के शिक्षाविदों को अपनी जाति और उपजातियों के बारे में शोध करने में निवेश करना चाहिए। दलितों को संग्रहालय की वस्तुओं की तरह मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखना और उनके जीवन पर विनाशकारी निर्णय देना बंद करें। गैर-दलितों द्वारा किए गए दलित अध्ययनों की गहन जांच की आवश्यकता है।' ट्विटर। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त (https://twitter.com/surajyengde/status/1377266791513198598)

61. (डी'सूजा 2020). टाइमस्टैम्प: 08:42.

62. (डी'सूजा 2020). टाइमस्टैम्प: 10:39.

63. (येंगडे 2020). समय: 00:05:31.

64. (येंगडे 2020). समय: 00:49:35.

65. (येंगडे 2020). समय: 00:57:42.

66. (येंगडे 2020). समय: 00:49:20.

67. (महाद के बच्चे 2020)

68. (येंगडे 2020). समय: 00:21:54.

69. (येंगडे 2020). समय: 00:11:46.

70. (येंगडे 2020). समय: 00:11:05.

71. (येंगडे 2020). समय: 00:16:03.

72. (येंगडे 2020). समय: 00:47:05.

73. (येंगडे 2020). समय: 00:19:00-00:20:30.

74. (येंगडे 2020). समय: 00:07:40.

75. (येंगडे 2020). समय: 00:14:40.

76. (येंगडे 2020). समय: 00:21:17.

77. (महाद के बच्चे 2020)

78. (येंगडे 2020). समय: 00:55:48.

79. (येंगडे 2020). समय: 01:04:30.

80. (येंगडे 2020). समय: 00:17:11.

81. (येंगडे 2020). समय: 00:24:42.

82. (फ्लेचर स्कूल 2021). समय: 49:20.

83. देखिए: 'माता-पिता ही पहले जातिवादी शिक्षक होते हैं। वे अपने बच्चे के मन को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब युवा मुझसे पूछते हैं कि जाति से कैसे छुटकारा पाया जाए, तो मैं उन्हें अपने जातिवादी माता-पिता को त्यागने की सलाह देता हूं। अगर वे ऐसा कर सकते हैं, तो हम आगे के कदमों के बारे में बात कर सकते हैं।' ट्विटर। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त (https://twitter.com/surajyengde/status/1366737360646524930)

84. (डी'सूजा 2020). समय: 35:00.

85. (आंटी 2020)

86. (येंगडे 2020). समय: 00:36:38.

87. (येंगडे 2020). समय: 00:06:50.

88. (महाद के बच्चे 2020)

89. (येंगडे 2020). समय: 00:59:28.

90. (येंगडे 2020). समय: 00:38:40.

91. (येंगडे 2020). समय: 00:46:30.

92. (हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन 2019). टाइमस्टैम्प: 00:06:35.

93. (आंटी 2021)

94. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2018a)

95. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2018a)

96. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2018a)

97. (आंटी 2021)

98. (आंटी 2021)

99. (फ्लेचर स्कूल 2021). समय: 54:00-56:30.

100. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2018a)

101. (येंग्डे 2019)

102. (येंग्डे 2019)

103. (येंग्डे 2019)

104. (आंटी 2021)

105. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2018a)

106. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2018a)

107. (लेउंग 2021)

108. (फ्लेचर स्कूल 2021). समय: 38:57.

109. देखें: 'चेतना एसोसिएशन ऑफ कनाडा'। chetna.ca 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त किया गया (https://chetna.ca)

110. (आउटलुक वेब डेस्क 2021)

111. (आउटलुक वेब डेस्क 2021)

1. (अहुजा 1993, 287)

2. (अहुजा 1993, 286)

3. (अहुजा 1993, 287)

4. (अहुजा 1993, 288)

5. (अहुजा 1993, 288)

6. (अहुजा 1993, 292)

7. Examples are Kavasa of Rig Veda and Mahidasa of

Aitreya Aranyaka.

8. (मजूमदार 2001, 546-47)

9. (Aiyangar 1934, 55)

10. (कानून 1943, 350)

11. (जैसवाल 1998, 15)

12. (आर. एस. शर्मा 1998, 58)

13. (मजूमदार 2001, 548)

14. (यू. सिंह 2013, 168-69)

15. (एराली 2007, 166)

16. (एराली 2007, 166)

17. (अंबेडकर, शूद्र कौन थे? 1979, 22)

18. शर्मा, आर.एस. प्राचीन भारत में शूद्र, पृ. 29, मोतीलाल बनारसीदास, नई दिल्ली, 1958 जैसा कि (ए. शर्मा 2000, 142) में उद्धृत है।

19. देखें: 'बृहदारण्यक उपनिषद |' स्वामी कृष्णानंद'. 15 फरवरी, 2022 को पुनःप्राप्त (https://www.swami-krishnananda.org/brdup/Brihadaranyaka_Upanishad.pdf पृष्ठ 39)

20. (ए. शर्मा 1996)

21. ऋग्वेद V 60.5. द्वारा अनुवादित (पांडुरंगी 1999, 3)

22. (राधाकृष्णन 1953)

23. (ए. शर्मा 2000, 136)

24. जैसा कि उद्धृत है: (ए. शर्मा 2000, 165)

25. (गुप्ता 2000, 190)

26. (साहा 2020)

27. (साहा 2020)

28. अनेक उदाहरणों के लिए देखें: (ए. शर्मा 2000, 132-80)।

29. अपस्तम्भ धर्मसूत्र में छुआछीद का समर्थन किया गया होगा, लेकिन

इसे अभ्यास करने वाले हिंदू शायद ही कभी पढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि इसे मुख्य रूप से वे लोग पढ़ते हैं जो हिंदू धर्म पर आक्रमण करने के तरीके खोज रहे हैं। अधिकांश हिंदुओं ने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं है। और कई अन्य प्रसिद्ध धर्मशास्त्रों में इससे असहमति है, जैसे 'बदरी ने शूद्रों का पक्ष लिया और यह मत प्रतिपादित किया कि सभी (शूद्रों सहित) वैदिक यज्ञ करने के हकदार हैं।' देखें: 'धर्मशास्त्र का इतिहास (भारत में प्राचीन और मध्यकालीन धर्म और नागरिक कानून)। खंड I-V'□ भंडारकर प्राच्य अनुसंधान संस्थान, पुणे। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त (https://indianculture.gov.in/indian-culture-repository?search_api_fulltext=History%20of%20Dharmasastra&f%5B0%5D=parent_library_ic_repository%3AArchaeological%20Survey%20of%20India)□ अंबेडकर बताते हैं कि यद्यपि धर्मशास्त्रों में एक स्थान पर कहा गया है कि शूद्र उपनयन संस्कार के पात्र नहीं हैं, वहीं संस्कार गणपति ग्रंथ में स्पष्ट रूप से शूद्रों को इसके लिए योग्य बताया गया है। वे यह भी दर्शाते हैं कि पूर्व मीमांसा के रचयिता जैमिनी ने कहा है कि शूद्र वैदिक अनुष्ठान कर सकते हैं। अंबेडकर भारद्वाज श्रौत सूत्र (श्लोक 28) और कात्यायन श्रौत सूत्र (1 और 5) का हवाला देते हुए शूद्रों की वैदिक अनुष्ठान करने की योग्यता को दर्शाते हैं। देखें: 'शूद्र और प्रति-क्रांति' (अंबेडकर, लेखन और भाषण, खंड 3, 1989ए, 423)

30. (ओलिवेल 2005, 124)

31. (ओलिवेल 2005, 185)

32. (ओलिवेल 2000, 359)

33. (चट्टोपाध्याय 2014, 95)

34. (ओलिवेल 2000, 361)

35. (अहमद 1988, 236)

36. (ओलिवेल 2000, 69)

37. (ओलिवेल 2005, 103)

38. (केन 1941, 161)

39. (केन 1941, 170)

40. (केन 1941, 170)

41. (केन 1941, 168)

42. (केन 1941, 173-76)। इसी प्रकार, स्मृतिअर्थसार में कहा गया है कि बाजार की ओर जाने वाली सार्वजनिक सड़कों पर, धार्मिक जुलूसों में, मंदिरों में, त्योहारों के दौरान, यज्ञों में, पवित्र स्थानों पर, देश पर विपत्तियों या आक्रमणों के दौरान, बड़े जल निकायों के किनारों पर, बड़े

व्यक्तियों की उपस्थिति में, या आग या अन्य आपदा के समय शारीरिक संपर्क होने पर कोई समस्या नहीं होती है।

43. इसके अलावा, आपस्तम्भ धर्मसूत्र कहता है कि शूद्र उच्च जातियों के स्वामियों के लिए भोजन पका सकते हैं। (दत्ता 1944, 27)

44. (आर. एन. शर्मा 1977, 55)

45. ऋग्वेद (X.45.6) इनमें प्रत्येक वर्ण से चार और पाँचवाँ वर्ण से बाहर का, अर्थात् दलित, शामिल थे। यास्क ने अपने निरुक्त (VI.7) में यह कहा है। देखें (मूकरजी 1969, 52)।

46. (आर. एस. शर्मा 1958, 63)

47. (आर. एस. शर्मा 1958, 68)

48. (मैकक्लिश और ओलिवेल 2012, lxiv)

49. (दत्ता 1944, 30)

50. उदाहरण के लिए, बैजवाप गृह्य सूत्र कहता है कि शूद्रों को गर्भाधान से चौला तक सात संस्कार करने की अनुमति है। विधिकार अपारार्क का मत यह प्रतीत होता है कि गर्भाधान से चौला तक के आठ संस्कार शूद्रों सहित सभी वर्णों के लिए थे। मदनारत्न, रूपनारायण और हरिहर के भाष्य के अनुसार, जैसा कि निर्णयसिंधु में उद्धृत है, शूद्रों को छह संस्कार

और पांच दैनिक महायज्ञ करने का अधिकार था। (केन, धर्मशास्त्र का इतिहास 1941, 198)

51. देखें: 'लिंगायत अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कहलाने का स्वागत नहीं कर सकते'। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.newindianexpress.com/states/karnataka/2018/mar/23/lingayat-scs-obcs-may-not-welcome-minority-tag-1791248.html)

52. उदाहरण के लिए: सिगाला जातक में, बुद्ध एक निम्न वर्ण के व्यक्ति की क्षत्रिय कन्या से विवाह की इच्छा रखने के लिए निंदा करते हैं। सिंहकोत्थुक जातक में, निम्न कुल का एक भिक्षु उच्च वर्णों में जन्मे भिक्षुओं द्वारा पढ़े जाने वाले धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना चाहता है, लेकिन बुद्ध उसे फटकारते हुए कहते हैं कि उच्च वर्णों में जन्मे भिक्षु सिंह के समान हैं जबकि वह सियार की संतान के समान है। उसकी तुलना उस गधे से की गई है जो सिंह की खाल पहनकर सिंह का दर्जा प्राप्त करना चाहता है। (गोयल 1987, 283)
इसके अलावा, कन्नकथालसुत्त में बुद्ध कहते हैं, 'ये चार वर्ण हैं - क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों में से दो - क्षत्रिय और ब्राह्मण - को प्रणाम, सम्मान और आदर में प्राथमिकता दी जाती है।' (दत्ता 1944, 177)

53. (गोयल 1987, 285)

54. उदाहरण के लिए: सारिपुत्र, मौद्गल्यायन और महाकश्यप जैसे बौद्ध गुरु सभी ब्राह्मण थे। बाद के बौद्ध संप्रदाय में, दर्शन, तर्कशास्त्र, नैतिकता, कविता और नाटक के क्षेत्र में विख्यात विद्वान लगभग पूरी तरह से ब्राह्मण वर्ण से थे। अश्वघोष, नागार्जुन, आर्यदेव, असंग, वसुबंधु, दिग्नगा, धर्मकीर्ति और धर्मोत्तर जैसे बौद्ध आदर्श ब्राह्मण परिवारों में जन्मे, वैदिक ज्ञान प्राप्त किया और रूढ़िवादी वैदिक परंपरा में पले-बढ़े। वे विख्यात विद्वान थे जिन्होंने तर्कशास्त्र और तर्कशास्त्र पर विद्वतापूर्ण रचनाएँ कीं, जिन्होंने बौद्ध दर्शन के कई मूल सिद्धांतों की स्थापना की। (गोयल 1987, 271-72)

55. (गोयल 1987, 392)

56. (गोयल 1987, 392)

57. (गोयल 1987, 419)

58. (गोयल 1987, 392)

59. (गोयल 1987, 397)

60. (सिद्दीकी 2014, 80)

61. (सिद्दीकी 2014, 80)

62. (कपूर 2010, 195)

63. (बिस्वास 2016)

64. (बिस्वास 2016)

65. (बिस्वास 2016)

66. (बिस्वास 2016)

67. (ईडब्ल्यूटीएन ग्लोबल कैथोलिक नेटवर्क 2003)

68. देखें: 'मनीषा पंचकम"। (https://sanskritdocuments.org/sites/snsastri/Manishapanchakam.pdf)

69. देखें: (श्रीनिवास 1971) में 'संस्कृतीकरण'

70. उदाहरण के लिए, सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथों में से एक, शतपथ ब्राह्मण, एक शूद्र राजा द्वारा एक महत्वपूर्ण वैदिक यज्ञ करने का उल्लेख करता है। (एगेलिंग 1900, 397); शतपथ ब्राह्मण (XIII.5.4.6), (ओलिवेल 2000, 131)

71. (अंबेडकर, शूद्र कौन थे? 1979, 114)

72. (रॉय 1923, 137)

73. (अंबेडकर 1979, 119-22)

74. (आर. एस. शर्मा 1958, 241)

75. देखें (जयसवाल 1934, 3) और (जयसवाल 1934, 45)

76. (मजूमदार, प्राचीन बंगाल का इतिहास, 1971, 99)

77. देखें (रे 2003, 98)

78. (ए. शर्मा 2015)

79. (आर. एस. शर्मा 1958, 54)

80. (आर. एस. शर्मा 1958, 48-49)

81. (आर. एस. शर्मा 1958, 242)

82. (आर. एस. शर्मा 1958, 53)

83. छत्रपति शिवाजी के समय में, महार, मांग और रामोशी सैनिक मराठा किलों की ढलानों और पहुँच मार्गों की रक्षा करते थे (कॉन्स्टेबल 2001, 447)। रामोशी सैनिक पहाड़ी किलों की सुरक्षा करते थे, जबकि महार और मांग सैनिक तोपखाने और सैन्य चौकियों में सेवा करते थे। (कैडेल 1938, 12) वे खुफिया एजेंट भी थे, जो निगरानी करते थे और

दुश्मनों को गुमराह करते थे। (बेथम 1908, 141)

84. उदाहरण के लिए, सूबेदार गोपाल बाबा वलंगकर (उन्नीसवीं बॉम्बे इन्फैंट्री), जो 1880 के दशक के उत्तरार्ध में दापोली में महार नेता थे और सामाजिक कार्यकर्ता ज्योतिराव फुले के सहयोगी थे, ने महारों को 'दूषित क्षत्रिय' कहा था। (कांस्टेबल 2001, 446-47)

85. देखें: 'भारतीय सेना की महार रेजिमेंट: दो सेना प्रमुखों और एक परमवीर चक्र का घर'। द प्रिंट। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त किया गया (https://theprint.in/report/indian-armys-mahar-regiment-home-to-two-army-chiefs-and-a-param-vir-chakra/26313)

86. (के. सिंह 1993, 6)

87. उत्तर प्रदेश का जाटव समुदाय खुद को चमार कहलाना पसंद नहीं करता। नेपाल में पाए जाने वाले लोमश रामायण के अनुसार, जाटव अपना वंश भगवान शिव से जोड़ते हैं। जाटव जीवन (1924) और यदुवंश का इतिहास (1942) में जाटवों को क्षत्रिय जाति के रूप में उल्लेख किया गया है। डबगर (जिन्हें अक्सर चमार माना जाता है) गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैला एक दलित समुदाय है। उनकी मौखिक परंपरा के अनुसार, उनकी उत्पत्ति राजपूतों से हुई है, जिन्हें मृत पशुओं की खाल का काम करने के कारण निम्न श्रेणी में रखा गया था। मेघवाल अनुसूचित जाति समुदाय कई बहिर्विवाही समुदायों में विभाजित है, जैसे चौहान, परमार, सोलंकी आदि। इनमें से कई नाम

राजपूत मूल के हैं। माधोपुर (उत्तर प्रदेश) के चमार भी खुद को निम्न श्रेणी के क्षत्रिय मानते हैं (के. सिंह 1993, 326, 387, 939, 304)।

88. (अग्रवाल 1934, 69). इसके अलावा (लॉन्गर 1981, 4)

89. (कांस्टेबल 2001, 448-49)

90. यजुर्वेद के कुछ अध्याय पूरी तरह से उनके द्वारा किए जाने वाले विभिन्न उद्योगों के विवरण के लिए समर्पित हैं। उदाहरण के लिए: यजुर्वेद 30.15 में चमड़े के कामगारों (चर्मकार या वर्तमान समय के चमार) का उल्लेख है, यजुर्वेद 16.27 और 30.7 में वस्त्र कामगारों (जुला) का उल्लेख है, यजुर्वेद 16.27 और 30.7 में लोहे के कामगारों (लोहार या लोहार) का उल्लेख है, यजुर्वेद 16.27 और 30.6 में रथकार या रथ निर्माता का उल्लेख है, यजुर्वेद 16.46 और 30.6 में धनुष और बाण बनाने वालों का उल्लेख है, यजुर्वेद 30.8 में कील और सुई बनाने वालों का उल्लेख है, यजुर्वेद 30.12 में मूर्तिकारों या मूर्ति निर्माताओं का उल्लेख है (महावीर 2001, 116)। इसके अलावा, अथर्ववेद में उल्लेख है कि शिल्पकारों के पास बहुत बड़े आवास और कारखाने थे (अथर्ववेद 7.73.1 देखें। (महावीर 2001, 113) भी देखें)।

91. (महावीर 2001, 228)

92. (महावीर 2001, 114)

93. उदाहरण के लिए, ऋग्वेद 1.31.8, 1.31.9 और 8.46.3 देखें।

पृष्ठ 112, वैदिक अर्थव्यवस्था, डॉ. महावीर, समांतर प्रकाशन, नई दिल्ली, 2001 भी देखें। वैदिक मंत्रों में शूद्र कारीगरों का उल्लेख है जो अपने कारखानों में राजा के लिए लोहे के हथियार बनाते थे और बदले में राजा उनकी रक्षा करता था, जो उनके सामंजस्यपूर्ण और सहजीवी संबंध का संकेत है। (ऋग्वेद 10.92.7 और ऋग्वेद 10.48.3 देखें।) शूद्रों की इंजीनियर और वास्तुकार के रूप में भूमिका बाद के काल में भी जारी रही। मौर्य काल के दौरान, राजमहल के पश्चिम का क्षेत्र उन्हें ऊनी और सूती सामान और कवच बनाने के लिए आवंटित किया गया था (शास्त्री 1987, 79)। आंध्र प्रदेश के शूद्र कारीगर समुदाय का दावा था कि उनकी उत्पत्ति विश्वकर्मा (हिंदू धर्म में दिव्य वास्तुकार माने जाने वाले) से हुई है। उन्होंने मंदिरों, रथों, मंदिर के आभूषणों, धार्मिक पात्रों और मूर्तियों के निर्माण और मरम्मत में सहायता की। विजयनगर के राजाओं (चौदहवीं-सत्रहवीं शताब्दी) ने उन्हें कुछ विशेष मंदिरीय सम्मान और विशेषाधिकार दिए, जैसे रथों के आगे चलना और पारंपरिक पोशाक में रथों पर खड़े होकर पूजा करना। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश में कंचारा या पीतल के कारीगर शूद्र थे, और 1645 ईस्वी के एक शिलालेख में कहा गया है कि शासक ने उनके महत्व के कारण उनके सभी करों और शुल्कों को माफ कर दिया था। उप्पारा शूद्र समुदाय ने कुएँ खोदने और घर बनाने जैसे सिविल इंजीनियरिंग कार्य किए। वे नदियों से गाद हटाने में भी शामिल थे ताकि उन्हें नौकायन के लिए उपयुक्त बनाया जा सके। एक अन्य शूद्र समुदाय कम्मारा थे, जो लोहे के औजार, उपकरण और सामान बनाते थे (पांडे 2015, अध्याय 2)।

94. उदाहरण के लिए, सत्रहवीं-अठारहवीं शताब्दी में आंध्र क्षेत्र में, कई ब्राह्मण और क्षत्रिय गाँव के शूद्र मुखिया के अधीन काम करते थे (पांडे

2015, अध्याय 2)।

95. (Kunhappa 1988, 2)

96. (मेनन 2011, 133)। दिलचस्प बात यह है कि महाभारत में, देवताओं के चिकित्सक जुड़वां अश्विन शूद्र हैं (आर. एस. शर्मा 1958, 74)।

97. (दत्ता 1944, 25)

98. गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के इंदौर ताम्रपत्र शिलालेख (465-466 ईस्वी) में एक दान का उल्लेख है, जिसके ब्याज का उपयोग सूर्य मंदिर में दीपक के रखरखाव के लिए किया गया था। यह दान इंद्रपुरा के तेल व्यापारियों के संघ के पास जमा किया गया था, जिन्होंने इसे अपने व्यवसाय में निवेश किया या ब्याज कमाने के लिए दूसरों को उधार दिया। तीसरी शताब्दी ईस्वी के राजा ईश्वरसेन के शासनकाल के नासिक के एक शिलालेख में कुम्हारों, तेल मिल मालिकों और अन्य संघों के पास दान के निवेश का उल्लेख है। जूनार के एक शिलालेख (लगभग 1165 ईस्वी) में बांस के कामगारों और अंगीठी कारीगरों के संघों के पास दान के निवेश का उल्लेख है (चक्रबोर्ती 1960, 316-18)। बारहवीं शताब्दी के कुछ अभिलेखों में उल्लेख है कि शूद्र वैश्यों के लिए वर्जित वस्तुओं, जैसे नमक, शराब, दही, हथियार, विष आदि का व्यापार करते थे, जबकि बृहस्पति स्मृति में कहा गया है कि शूद्र सभी वस्तुओं का व्यापार करते थे। इसके अलावा, आठवीं शताब्दी ईस्वी के जैन ग्रंथ कुवलयमाला में शूद्रों को व्यापारिक कारवां का नेता बताया गया है। (एस. श्रीवास्तव 2008,

51)

99. (एस. श्रीवास्तव 2008, 53)

100. (दत्ता 1944, 27)

101. (दत्ता 1944, 148)

102. (चक्रवर्ती 1960, 326)

103. उदाहरण के लिए, मौर्य काल में राज्य द्वारा ऐसे संघों को विभिन्न प्रकार की रियायतें दी गई थीं। आंध्र-कुषाण काल (लगभग 200-300 ईस्वी) और आंध्रवृत्त काल में बुनकरों, औषधि विक्रेताओं, अनाज व्यापारियों, तेल निर्माताओं आदि के संघ थे। गुप्त काल (लगभग 320-500 ईस्वी) में तेल व्यापारियों, रेशम बुनकरों और वास्तुकारों के संघ थे (दत्ता 1944, 147-48)। कर्नाटक में सम्राट विक्रमादित्य द्वितीय (लगभग 733-44 ईस्वी) के एक शिलालेख से पता चलता है कि राज्य ने पीतल के कारीगरों के संघ को जनता से कर वसूलने का अधिकार दिया था (चक्रबोर्ती 1960, 318)। प्रतिहारा सम्राट महेंद्रपाल प्रथम के सियादोनी शिलालेख (903 ईस्वी) में कुम्हारों, शराब बनाने वालों, चीनी उबालने वालों, पान विक्रेताओं, तेल बनाने वालों और पत्थर तराशने वालों के संघों का उल्लेख है। ऐसे संघों ने सरकार के कार्यों को सुगम बनाया और समाज को संगठित करने तथा आंतरिक मामलों में न्याय प्रशासन में उपयोगी सेवाएँ प्रदान कीं (त्रिपाठी 1989, 345-46)।

104. कृष्ण यजुर्वेद और सामवेद में धनी शूद्रों के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है। अलिनाचित्त जातक में बनारस के पास बुनकरों के एक समृद्ध संघ का जिक्र है। बौद्ध जातक कथाओं में बताया गया है कि लोहारों का विवाह धनी जौहरियों से होता था। (दत्ता 1944, 29) और (चक्रबोर्ती 1960, 314, 319) देखें।

105. (दत्ता 1944, 151, 155)

106. उदाहरण के लिए, कुषाण काल (प्रथम शताब्दी ईस्वी) के मथुरा शिलालेखों में कई समृद्ध शूद्र दानदाताओं के नाम दर्ज हैं, जो लोहार, नाई, धोबी आदि थे। उन्होंने मंदिरों, सड़कों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण के लिए धन दान किया। शिलालेख में सिंह के पुत्र गोवा नामक एक लोहार द्वारा सरस्वती की एक मूर्ति समर्पित करने का भी उल्लेख है। इसी प्रकार, कन्हेरी शिलालेख में कल्याणा के लोहार नादा द्वारा सड़क निर्माण के लिए धन दान करने का उल्लेख मिलता है। कुषाण काल (प्रथम शताब्दी ईस्वी) के एक शिलालेख में 'राजनपिता' शब्द का उल्लेख है, जिसका अर्थ है नाइयों के संघ का मुखिया। कुषाण काल के मथुरा शिलालेख में 'रायगिनी' नामक एक दानदाता का नाम दर्ज है, जिसका अर्थ है रंगसाज़ या धोबी की पत्नी। जातक कथाओं में भी रंगसाज़ों या धोबी (धोबी) के संघों का उल्लेख है। सम्राट कनिष्क (प्रथम-द्वितीय शताब्दी ईस्वी) के तक्षशिला शिलालेख में एक वास्तुकार द्वारा किए गए धार्मिक दान का उल्लेख है। उस काल के अनेक अभिलेखों में नवकर्मिक (वास्तुकारों) के एक शिल्प संघ का उल्लेख मिलता है, जो विश्वविद्यालयों और मंदिरों का निर्माण करते थे और उनकी मरम्मत भी करते थे। गुप्त सम्राटों के मंदसर शिलालेख (लगभग 437-38 ईस्वी) में एक ऐसे संघ

का जिक्र है जिसने 'शिल्प से अर्जित धन से सूर्य के एक भव्य और अद्वितीय मंदिर' का निर्माण किया था। गुप्त काल में राजाओं द्वारा कारीगरों को उच्च सम्मान दिया जाता था, जैसा कि करितालाई (लगभग 493-4 ईस्वी) और खोह (लगभग 497-512 ईस्वी) के शिलालेखों से स्पष्ट होता है। उत्तर भारत के गुर्जर प्रतिहार (आठवीं शताब्दी के मध्य से ग्यारहवीं शताब्दी तक) शासकों के शिलालेख भी दर्शाते हैं कि एक ही व्यवसाय से जुड़े लोग आमतौर पर अपने व्यवसाय को विनियमित करने के लिए संगठन बनाते थे (चक्रबोर्ती 1960, 318-25)।

107. इनमें भारत के धनी शूद्र मछुआरों का उल्लेख है जो नदियों में मछली पकड़ने के लिए कई मजदूरों को काम पर रखते थे। एक अन्य उदाहरण में, एक शूद्र को मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए पाँच सौ झोपड़ियों का मालिक बताया गया है, जो स्पष्ट रूप से समृद्ध उद्यमियों का संकेत है। एक अन्य शूद्र महिला को मिट्टी के बर्तनों के व्यवसाय की समृद्ध मालकिन के रूप में उल्लेख किया गया है, और जैन भिक्षु अक्सर ऐसी मिट्टी के बर्तनों की दुकानों में शरण लेते थे और उन्हें बहुत सम्मान देते थे। जैन ग्रंथों में कई समृद्ध शहरों का वर्णन है जिनमें सुंदर इमारतें, मंदिर, उद्यान, सड़कें आदि थीं, जहाँ शूद्र शिल्पकार रहते और काम करते थे। इनमें यह भी बताया गया है कि चमड़ा उद्योग फलता-फूलता था और शूद्र समुदाय जूते, थैले, ढोल, रज्जु आदि जैसे वाद्य यंत्र बनाते थे। (जैन 1980, 29, 56, 58)

108. (एस. श्रीवास्तव 2008, 51)

109. (बशम 2004, 146)

110. (बशम 2004, 146). उदाहरण के लिए, ब्रिटिश काल में, 1821 में एक मदरसा स्थापित करने की योजना विफल हो गई क्योंकि शूद्र छात्रों ने शानार और परैयाओं के साथ बैठने से इनकार कर दिया, जिन्हें वे अपने से नीचा मानते थे। यह एक बोर्डिंग स्कूल होना था, और विभिन्न जातियों के छात्रों से एक साथ भोजन करने की अपेक्षा की जाती थी। शूद्र छात्रों के लिए, यह एक भावनात्मक रूप से तनावपूर्ण स्थिति थी। परिणामस्वरूप, माता-पिता ने अपने बच्चों को वापस ले लिया। (त्शुरेनेव 2019, 304)

111. (के. सिंह 1993, 11)

112. (के. सिंह 1993, 11)

113. (के. सिंह 1993, 29)

114. (के. सिंह 1993, 6)

115. (Dharampal 1983, 21)

116. (Dharampal 1983, 29)

117. (Dharampal 1983, 29)

118. (Dharampal 1983, 29)

119. (Dharampal 1983, 35)

120. (त्शुरेनेव 2019, 41)

121. (की 1918, 148)

122. (के. सिंह 1993, 10)

123. (के. सिंह 1993, 11)

124. (के. सिंह 1993, 4)

125. (के. सिंह 1993, 5)

126. (के. सिंह 1993, 3)

127. (के. सिंह 1993, 302)

128. (के. सिंह 1993, 307)

129. (के. सिंह 1993, 314)

130. (के. सिंह 1993, 314)

131. (के. सिंह 1993, 318)

132. (के. सिंह 1993, 3)

133. (के. सिंह 1993, 25)

134. (के. सिंह 1993, 27)

135. (के. सिंह 1993, 29)

136. (के. सिंह 1993, 1070)

137. (के. सिंह 1993, 1072)

138. (के. सिंह 1993, 1072)

139. (रसेल 1916, 380-81)

140. (के. सिंह 1993, 105-12)

141. (दास 2003, 378-79)

142. (Ghurye 1959, 4)

143. (के. सिंह 1994, 10)

144. (के. सिंह 1994, 12)

145. (के. सिंह 1994, 3)

146. (के. सिंह 1994, 293)

147. (के. सिंह 1994, 293)

148. (के. सिंह 1994, 295, 324, 336)। यह भी देखें: (वॉन फ्यूरर हैमेंडोर्फ और वॉन फ्यूरर हैमेंडॉर्फ 2022, 436, 439)

149. (के. सिंह 1994, 118, 119, 127, 122)

150. (के. सिंह 1994, 3, 773)

151. (के. सिंह 1994, 774)

152. (के. सिंह 1994, 776)

153. (के. सिंह 1994, 776)

154. (बैग 1997, 106)

155. (के. सिंह 1994, 842)

156. (ए. श्रीवास्तव 1986, 18)

157. (ए. श्रीवास्तव 1986, 18)

158. (ए. श्रीवास्तव 1986, 20)

159. उदाहरण के लिए, हिमाचल प्रदेश की गद्दी राजपूत अनुसूचित जनजाति का दावा है कि वे मध्यकाल में मुस्लिम शासकों के आक्रमण से बचने के लिए लाहौर से पलायन कर गए थे (के. सिंह 1994, 272-74)।

160. (के. सिंह 1994, 436-38)

161. (के. सिंह 1994, 436, 441-42)

162. उदाहरण के लिए, महान वीरशैव आचार्य और विद्वान श्रीपति पंडितचार्य (तेरहवीं शताब्दी ईस्वी) ने वेदांत सूत्रों पर श्रीकर भाष्य नामक एक अद्भुत टीका लिखी। ग्रंथ की शुरुआत इस प्रकार होती है: 'मैंने इसे वीरशैवों के लाभ के लिए रचा है। वीरशैव वे हैं जिन्हें वेदों और आगमों का ज्ञान है और उनके आंतरिक आध्यात्मिक अर्थों का ज्ञान है; जो मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र इच्छा से प्रेरित हैं; जो वैदिक मार्ग के अनुयायी हैं; और जो शुद्ध शैव धर्म के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करते हैं।' (सी. एच. राव 1936, 24) सोलहवीं शताब्दी ईस्वी के महान वैष्णव विद्वान रूप गोस्वामी ने भी भक्ति-रस पर अपने विशाल ग्रंथ भक्तिरस्मृतसिंधु में यही

बात कही है। उन्होंने कहा कि भगवान के प्रति भक्ति शास्त्रों, श्रुति और स्मृति के अनुसार होनी चाहिए। (हैबरमैन 2003, 41)

163. (बी. श्रीवास्तव 1957, 87)

164. (नीलोत्पल 2013, 20-21)

165. (चौहान 2014, 59-61)

166. (Gupt 1986, 48)

167. (घोरपड़े 2011, 196)

168. (उपाध्याय 1954, 583)

169. (ऑटी 1970, 16)

170. (Kunhappa 1988, 34)

171. (कुन्हप्पा 1988, viii)

172. (कुन्हप्पा 1988, ix)

173. देखें: (हार्डग्रेव जूनियर 1969) और (रुडॉल्फ और रुडॉल्फ 1967)

174. देखें: 'जाति व्यवस्था के पतन से व्यावसायिक वर्ग का उदय'। द न्यूयॉर्क टाइम्स। 15 फरवरी, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.nytimes.com/2010/09/11/world/asia/11caste.html)

175. (चार्स्ले 1996)

176. (चार्स्ले 1996)

177. ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल ने कहा, 'प्रथा का स्पष्ट प्रमाण, कानून के लिखित पाठ से अधिक महत्वपूर्ण है।' 1833 में, ब्रिटिश संसद ने प्रिवी काउंसिल की स्थापना की, जो भारत सहित ब्रिटिश उपनिवेशों के विभिन्न न्यायालयों से अपीलें सुनने वाली न्यायिक संस्था थी।

178. (Dharampal 2003, 12)

179. जैसा कि उद्धृत किया गया है: (चक्रवर्ती 2019)।

180. जैसा कि उद्धृत किया गया है: (चक्रवर्ती 2019)

181. (चार्स्ले 1996)

182. (चार्स्ले 1996)

183. (चार्स्ले 1996)

184. ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो दर्शाते हैं कि अंतर्विवाह प्रथा का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता था। पुराणों और महाभारत में वर्णित अनेक महान ऋषियों की माताएँ शूद्र थीं, जैसे विष्णु पुराण के रचयिता माने जाने वाले पराशर मुनि, जिनका जन्म एक श्वपाक (शाब्दिक अर्थ: कुत्ते का मांस पकाने वाली) स्त्री से हुआ था। (आर. एस. शर्मा 1958, 63) धर्मशास्त्रों में ब्राह्मण और शूद्र पुत्र के उदाहरण का वर्णन है और यह सुझाव दिया गया है कि यदि पिता ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य हो, तो पुत्र को आधी संपत्ति विरासत में मिलनी चाहिए। (आर. एस. शर्मा 1958, 247) इससे पता चलता है कि ऐसे मामले काफी आम थे। गुप्त काल में भी विभिन्न वर्णों के लोगों के बीच विवाह के उल्लेख मिलते हैं। बौद्ध ग्रंथ भी विभिन्न वर्णों के लोगों के बीच अंतर्विवाह के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए, मतंग जातक में एक व्यापारी की पुत्री का उल्लेख है, जिसने एक चांडाल से विवाह किया था। (दत्ता 1944, 178)

185. जैसा कि उद्धृत है: (चक्रवर्ती 2019)

186. जैसा कि उद्धृत है: (चक्रवर्ती 2019)

187. (चार्स्ले 1996)

188. (चार्स्ले 1996)

189. (चार्स्ले 1996)

190. (चार्स्ले 1996)

191. (चार्स्ले 1996)

192. (चार्स्ले 1996)

193. (चार्स्ले 1996)

194. (चार्स्ले 1996)

195. (चार्स्ले 1996)

196. (चार्स्ले 1996)

197. (चार्स्ले 1996)

198. (चार्स्ले 1996)

199. (चार्स्ले 1996)

200. (अंबेडकर 1936)

201. (अंबेडकर 1990)

202. देखें: (राठौर और वर्मा 2011) की प्रस्तावना

203. (अंबेडकर 2015)

204. (अंबेडकर 1936), प्रस्तावना

205. (अंबेडकर 1936, 5)

206. (अंबेडकर 1936, 5)

207. (अंबेडकर 1936, 5)

208. (अंबेडकर 1936, 24)

209. (अंबेडकर 1936, 26)

210. (अंबेडकर 1936, 3)

211. (अंबेडकर 1936)

212. (अंबेडकर 1936, 14)

213. (अंबेडकर 1936, 20)

214. (अंबेडकर 1936, 21)

215. (अंबेडकर 1936, 23)

216. (अंबेडकर 1936, 23)

217. (अंबेडकर 1936, 24)

218. (अंबेडकर 1990)

219. (अंबेडकर 1990), अध्याय X-I

220. (अंबेडकर 1990), अध्याय X-I

221. (अंबेडकर 1990), अध्याय X-I

222. (अंबेडकर 1990), अध्याय X-I

223. (अंबेडकर 1990), अध्याय X-I

224. (अंबेडकर 1990), अध्याय X-I

225. (अंबेडकर 1990), अध्याय X-I

226. (अंबेडकर 1990), अध्याय X-II

227. (अंबेडकर 1990), अध्याय XII-III

228. (अंबेडकर 1990), अध्याय XII-III

229. (अंबेडकर 1990), अध्याय XII-III

230. (अंबेडकर 1990), अध्याय XII-III

231. (अंबेडकर 1990), अध्याय XII-V

232. (अंबेडकर 1990), अध्याय X-II

233. (अंबेडकर 1990), अध्याय X-II

234. (अंबेडकर 1990), अध्याय X-II

235. (अंबेडकर 1990), अध्याय VII-III

236. (अंबेडकर 1990), अध्याय VII-III

237. (अंबेडकर 1990), अध्याय VII-III

238. (राठौर और वर्मा 2011, xxix-xxx)

239. (राठौर और वर्मा 2011, 50)

240. (ओमवेड्ट 2003, 262)

241. (अंबेडकर 1989ए, 23)

242. (अंबेडकर 1989बी, 416-17)

243. जैसा कि (रामटेके 1983, 127) में उल्लेख किया गया है।

244. (अंबेडकर 2015)

245. (अंबेडकर 2015, 5)

246. (अंबेडकर 2015, 7)

247. (अंबेडकर 2015, 7)

248. (अंबेडकर 2015, 8)

249. (अंबेडकर 2015, 6)

250. (अंबेडकर 2015, 6)

251. (अंबेडकर 2015, 8)

252. (अंबेडकर 2015, 8)

253. (अंबेडकर 2015, 8)

254. (अंबेडकर 2015, 8)

255. इस खंड में कई विचार (नाडकर्णी 2003) से लिए गए हैं।

256. (केन 1990, 531)

257. (केन 1990, 66-67, 121)

258. (अहुजा 1993, 322)

259. (अहुजा 1993, 322)

260. (अहुजा 1993, 322)

261. (अहुजा 1993, 323)

262. (अहुजा 1993, 324)

263. (अहुजा 1993, 325)

264. (अहुजा 1993, 326) हेरोल्ड गोल्ड ने 1954-5 में उत्तर प्रदेश

के फैजाबाद जिले के शेरपुर गांव में जजमानी प्रणाली के अपने अध्ययन में पाया कि भुगतान मुफ्त निवास स्थल, परिवार के लिए मुफ्त भोजन, मुफ्त कपड़े, जानवरों के लिए मुफ्त भोजन, मुफ्त लकड़ी, मुफ्त गोबर, किराया मुक्त भूमि, ऋण सुविधाएं, पूरक रोजगार का अवसर, औजारों का मुफ्त उपयोग, मुकदमेबाजी में सहायता आदि के रूप में किया जाता था।

265. (अहुजा 1993, 324)

266. (अंबेडकर 1936, 11)

1. देखें: 'इनफिनिटी फाउंडेशन में आपका स्वागत है'। इनफिनिटी फाउंडेशन। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया (https://infinityfoundation.com)

2. देखें: 'राजीव मल्होत्रा द्वारा 'यू-टर्न थ्योरी'। स्पॉटिफाई। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त (https://open.spotify.com/episode/50PZhCEtJihTO2B3IzA7fr) और 'द यू-टर्न थ्योरी: कैसे भारतीय विचारों को पश्चिम द्वारा चुराया और छुपाया जाता है'। यूट्यूब। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त (https://www.youtube.com/watch?v=tR6QGe-a8gM)

3. (विल्सन 2014, 82)

4. देखें: 'न्यूयॉर्क राज्य अभिलेखागार द्वारा रखे गए तंबाकू उद्योग के

रिकॉर्ड'। न्यूयॉर्क राज्य अभिलेखागार। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया (https://web.archive.org/web/20141212180722/http://www.archives.nysed.gov/a/research/res_topics_bus_tobacco.shtml) मूल लिंक, जो अंतिम बार 30 जनवरी, 2013 को प्राप्त किया गया था, अब सक्रिय नहीं है (http://www.archives.nysed.gov/a/research/res_topics_bus_tobacco.shtml)

5. (बेन्सन, अलेक्जेंडर और फेल्डमैन 1975) यह भी देखें: (बेन्सन, मार्ज़ेटा, एट अल. 1974)

6. (विल्सन 2014, 80-82)

7. (गोलेमैन 1971, 1-25)

8. (हमारी जानकारी के अनुसार, 2014)

9. (हमारी जानकारी के अनुसार, 2014)

10. (गोलेमैन 1971, 1-25)

11. (गोलेमैन 1971, 1-25)

12. (गोलेमैन 1971, 1-25)

13. देखें: (गोलेमैन 1972a) और (गोलेमैन 1972b)

14. देखें: (गोलेमैन 1972a) और (गोलेमैन 1972b)

15. (विल्सन 2014, 80-82)

16. (गोलेमैन 1976)

17. (विल्सन 2014, 80-82)

18. (हमारी जानकारी के अनुसार, 2014)

19. (परेड 2020)

20. (परेड 2020)

21. (पुर्सर 2017)

22. (पुर्सर 2017)

23. (पुर्सर 2017)

24. (वेरहोवेन 2001) में उद्धृत।

25. (क्लाइन 1963, 25)

26. यह अभी तक अप्रकाशित है और भारतीय ज्ञान के आत्मसात्करण पर श्रृंखला का हिस्सा होगा।

27. (थेरा 1999)

28. (थेरा 1999)

29. हार्वर्ड में व्हाइटहेड के कार्यकाल (1924-37) के दौरान दर्शनशास्त्र विभाग में विलियम अर्नेस्ट हॉकिंग्स जैसे कई पेशेवर दार्शनिक मौजूद थे, जो भारतीय दर्शन में कुछ हद तक संलग्न थे। उन्होंने हार्वर्ड के पूर्व के दार्शनिकों जैसे विलियम जेम्स, सी.एस. पीयर्स, जॉर्ज सैंटायना की विरासत को आगे बढ़ाया था, जिनके दर्शन भारतीय चिंतन से व्यापक रूप से प्रभावित थे। हार्वर्ड में व्हाइटहेड के समय में संस्कृत और भारतीय अध्ययन विभाग के साथ-साथ बौद्ध अध्ययन विभाग भी फला-फूला। पिछले दो दशकों की तरह, भारतीय अध्ययन और विशेष रूप से बौद्ध अध्ययन का दर्शनशास्त्र विभाग से घनिष्ठ संबंध बना रहा। इस संदर्भ में हॉकिंग्स एक प्रमुख उदाहरण हैं। व्हाइटहेड के बारे में अपने व्यक्तिगत संस्मरणों पर आधारित निबंध, व्हाइटहेड जैसा कि मैं उन्हें जानता था (हॉकिंग 1963), में हॉकिंग्स हार्वर्ड में व्हाइटहेड के कार्यकाल को स्नेहपूर्वक याद करते हैं और बताते हैं कि कैसे वे जोशिया रॉयस दर्शन क्लब के सदस्य थे, जिसके सदस्यों में विलियम जेम्स और हार्वर्ड के वे अन्य लोग शामिल थे जिनकी भारतीय चिंतन में रुचि थी। इसी खंड में एक अन्य निबंध ("व्हाइटहेड का नवीन अंतर्ज्ञान", पृष्ठ 18-26) में,

व्हाइटहेड के शिष्य और आगे चलकर एक प्रख्यात दार्शनिक एवं धर्मशास्त्री बने चार्ल्स हार्टशोर्न ने व्हाइटहेड के प्रक्रिया दर्शन और बौद्ध धर्म के बीच समानता का उल्लेख किया है, और विशेष रूप से व्हाइटहेड की पूर्वधारणा की अवधारणा पर ध्यान आकर्षित किया है (पृष्ठ 2-26)। जैसा कि हमने ऊपर तर्क दिया है, व्हाइटहेड का पूर्वधारणा का सिद्धांत संभवतः बौद्ध अभिधर्म की प्राप्ति की अवधारणा के आधार पर विकसित हुआ था (ऊपर दी गई तालिका देखें (नीचे से तीसरा बिंदु)। हार्टशोर्न ने स्वयं प्रक्रिया दर्शन (जिसके वे व्हाइटहेड के बाद अग्रणी सिद्धांतकार बने) और बौद्ध धर्म दोनों को अपनाया और विकास के दर्शन या प्रक्रिया दर्शन को 'बौद्ध-व्हाइटहेडियन सिद्धांत' कहा, इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से व्हाइटहेड के प्रक्रिया दर्शन की बौद्ध पृष्ठभूमि की पुष्टि की।

30. ईश्वर, चाहे वह आदिम प्रकृति में हो या परिणामी प्रकृति में, एक स्वतः-संगठित, निरंतर परिवर्तनशील ब्रह्मांड पर एक विचित्र आक्षेप है। कई बौद्धों और अन्य वैज्ञानिकों के लिए, विज्ञान और धर्मशास्त्र का यह विचित्र मिश्रण, विशेषकर विकासवादी सिद्धांत का, एक असंगत ईसाई धर्मशास्त्रीय ढांचे पर थोपा जाना अत्यंत समस्याग्रस्त है। ईसाई धर्मशास्त्रियों द्वारा विकासवाद को एक असंगत ईसाई धर्मशास्त्रीय ढांचे पर थोपने के प्रयासों की तीखी आलोचना के लिए, देखें (धर्मासिरी 1988)।

31. (हार्वर्ड स्क्वायर लाइब्रेरी 2017)

32. (गॉर्डन 2007)33 (ओल्डमीडो 2004, 27)

33 (ओल्डमीडो 2004, 27)

34. (थोरो 1932)

35. (थोरो 1932)

36. (थोरो 1932)

37. (इंस्टीट्यूट ऑफ नोएटिक साइंसेज (आईओएनएस) 2010)

38. (हॉडर 2001)

39. (आर. हिगिंस 2017)

40. टी.एस. एलियट की आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स जैसा कि (केर्न्स 1987, 13) में उद्धृत है।

41. (केर्न्स 1987, 13)

42. निम्नलिखित पुस्तक एलियट द्वारा सामना किए गए इस आंतरिक संघर्ष को समर्पित है: (केर्न्स 1987)

43. उदाहरण के लिए, उनका विस्तृत लेख यहाँ देखें: (असानी 2007)

44. देखें: (इनफिनिटी फाउंडेशन 2002ए)

45. (इनफिनिटी फाउंडेशन 2002बी)

46. (नुस्बाम 2009, 214-215, 246-261)

1. (येम्मा और गोल्डन 1998) और (ऑनलाइन बर्मा/म्यांमार लाइब्रेरी 1998)

2. (येम्मा और गोल्डन 1998) और (ऑनलाइन बर्मा/म्यांमार लाइब्रेरी 1998)

3. (डायमंड और शेल 2018)

4. (वोंग 2020)

5. (वोंग 2020)

* http://english.www.gov.cn/news/top_news/2019/03/20/content_281476571167688.htm

6. (रोडमैन और झू 2015)

7. (मौसम 2020a)

8. (होरविट्ज़ 2017)

9. (रेडडेन 2017)

10. देखें: 'बीजिंग विभाग में दलाई लामा के दूतों से संबंधित कर्मियों में परिवर्तन'। वर्ल्ड तिब्बत नेटवर्क न्यूज़। 30 जनवरी, 2004। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया। (https://web.archive.org/web/20040408192139/http://www.tibet.ca/en/wtnarchive/2004/1/30_2.html) वैकल्पिक स्रोत: (स्मिथ 2009, 232)

11. देखें: 'चीन पर अमेरिकी विशेषज्ञों के साथ तिब्बती मुद्दे पर चर्चा'। चाइना न्यूज एंड रिपोर्ट। 17 सितंबर 2002। 30 अप्रैल 2022 को प्राप्त किया गया (https://web.archive.org/web/20040225014441/http://www.china.org.cn/baodao/english/newsandreport/2002sep/17-1.htm)

12. (किंग 2021)

13. (किंग 2021)

14. (किंग 2021)

15. (होगलैंड 2012)

16. (विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय 2022)

17. (संयुक्त राज्य अमेरिका का वित्त विभाग, 2022)

18. (शीतकालीन 2020a)

19. (शीतकालीन 2020a)

20. (श्नाइडर 2020)

21. इसने चीनी संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने परिसर में चीनी सरकार द्वारा वित्त पोषित कन्फ्यूशियस संस्थान खोलने के लिए एक अनुबंध किया। और 2012 में, स्टैनफोर्ड के अध्यक्ष जॉन हेनेसी के नेतृत्व में, चीन में स्टैनफोर्ड के छात्रों के लिए पेकिंग विश्वविद्यालय में स्टैनफोर्ड सेंटर भी खोला गया। 2014 में, स्टैनफोर्ड को 'अमेरिका-चीन संबंधों में उन्नति' के लिए चीन स्थित उपहारों और अनुबंधों के रूप में 58.1 मिलियन डॉलर प्राप्त हुए। देखें: (श्नाइडर 2020)

22. (एफसीसीईडी 2020)

23. (न्यूमैन और टर्नर 2020)

24. (न्यूमैन और टर्नर 2020)

25. (न्यूमैन और टर्नर 2020)

26. (न्यूमैन और टर्नर 2020)

27. (टैन 2021) चीन में, अमेरिकी शिक्षा का सपना कुछ हद तक फीका पड़ गया है।

28. (रामास्वामी 2021, 161)

29. (रामास्वामी 2021, 165)

30. (रामास्वामी 2021, 168)

31. (रामास्वामी 2021, 178)

32. (रामास्वामी 2021, 175). देखें: (क्रेमर 2020)

33. (रामास्वामी 2021, 194)

34. (हार्वर्ड कैनेडी स्कूल 2015सी)

35. (ज़ि 2018)

36. (स्क्वॉक बॉक्स @SquawkCNBC 2021)

37. (स्क्वॉक बॉक्स @SquawkCNBC 2021)

38. (हार्वर्ड कैनेडी स्कूल 2016a)

39. (पी. श्विज़ेर 2021)

40. देखें: (फिश, बीजिंग की वीजा 'श्वेत सूची' में शामिल होने के लिए चीन के विशेषज्ञों को क्या करना होगा, 2019)

41. (पैट्रिक 2021)

42. उदाहरण: जॉन सीना की माफी (बूम 2021); (द लेट शो विद स्टीफन कोलबर्ट 2021); चीन के नक्शे के लिए गैप की माफी: (सांचेज़ 2018); चीन से माफी मांगने वाली अमेरिकी कंपनियां। (नेक्स्टशार्क - संपादकीय स्टाफ 2019)

43. देखें: 'चीन द्वारा प्रौद्योगिकी की चोरी अमेरिका के लिए सबसे बड़ा कानून प्रवर्तन खतरा है, एफबीआई का कहना है'। द गार्जियन। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त (https://www.theguardian.com/world/2020/feb/06/china-technology-theft-fbi-biggest-threat) और 'मध्य साम्राज्य उच्च शिक्षा से मिलता है'। एफडीडी। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त (https://www.fdd.org/analysis/2021/12/09/the-middle-kingdom-meets-higher-education/)

44. देखें: '5 में से 1 कंपनी का कहना है कि चीन ने पिछले एक साल में

उनकी बौद्धिक संपदा (आईपी) चुराई है: सीएनबीसी सीएफओ सर्वेक्षण'। सीएनबीसी। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.cnbc.com/2019/02/28/1-in-5-companies-say-china-stole-their-ip-within-the-last-year-cnbc.html)

45. (हार्वर्ड कैनेडी स्कूल 2016बी)

46. (हार्वर्ड कैनेडी स्कूल 2016बी)

47. (हार्वर्ड कैनेडी स्कूल 2015बी)

48. (हार्वर्ड कैनेडी स्कूल 2021ए)

49. (हार्वर्ड कैनेडी स्कूल 2021ए)

50. (हार्वर्ड कैनेडी स्कूल 2015सी)

51. (हार्वर्ड कैनेडी स्कूल 2015सी)

52. (डायमंड और शेल 2018)

53. (शीतकालीन 2020बी)

54. (शीतकालीन 2021बी)

55. (डायमंड और शेल 2018, 45-46)

56. (शीतकालीन 2021बी)

57. (शीतकालीन 2021बी)

58. (शीतकालीन 2021बी)

59. (शीतकालीन 2020बी)

60. (शीतकालीन 2020बी)

61. (शीतकालीन 2020बी)

62. (डायमंड और शेल 2018, 46)

63. (कनिंघम, सैच और ट्यूरियल 2020)

64. (शीतकालीन 2020a)

65. (काकुतानी 2020ए)

66. (काकुतानी 2020ए)

67. (काकुतानी 2020ए)

68. (काकुतानी 2020ए)

69. (शीतकालीन 2020a)

70. (शीतकालीन, 2020ए)

71. (शीतकालीन, 2020ए)

72. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2012ए). समयबिंदु: 00:15-01:50.

73. (शीतकालीन 2021a)

74. (शीतकालीन 2021a)

75. (शीतकालीन 2021a)

76. (शीतकालीन 2021a)

77. (शीतकालीन 2021a)

78. (बर्न्स और मैनुअल 2020)

79. (बर्न्स 2020). समय: 08:20.

80. (द हिंदू 2021)

81. (बर्न्स 2020). टाइमस्टैम्प: 23:37.

82. (बर्न्स 2020). टाइमस्टैम्प: 25:08.

83. देखें: 'भविष्य में एचबीएस की विफलता पर केस स्टडी: 1. कोविड-19. 2. नोटबंदी. 3. जीएसटी कार्यान्वयन'। ट्विटर। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया (https://twitter.com/RahulGandhi/status/1279963844027183105)

84. (लूसे 2021)

85. (शीतकालीन 2020d)

86. (शीतकालीन 2020d)

87. (बेयरर 2021)

88. (हार्वर्ड टी.एच. चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ 2019ए)

89. (डोनोवन और निल्सन 2021)

90. (वॉकर 2021)

91. (वॉकर 2021)

92. (विंटर्स और कसम 2021)

93. (क्रिस्टेंसन 2021)

94. (क्रिस्टेंसन 2021)

95. (क्रिस्टेंसन 2021)

96. (हार्वर्ड टी.एच. चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ 2021बी)

97. (हार्वर्ड टी.एच. चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ 2021बी)

98. (सी. रॉस 2021ए)

99. (सी. रॉस 2021ए)

100. (सी. रॉस 2021बी)

101. (सी. रॉस 2021बी)

102. (सी. रॉस 2021बी)

103. (फिश, ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन से हुआवेई के आश्चर्यजनक संबंध,

2018)

104. (फिश, ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन से हुआवेई के आश्चर्यजनक संबंध, 2018)

105. (द डेली वायर 2022)

106. (द डेली वायर 2022). टाइमस्टैम्प: 0:00.

107. (द डेली वायर 2022). टाइमस्टैम्प: 0:32.

108. (द डेली वायर 2022). टाइमस्टैम्प: 1:19.

109. देखें: 'टैग आर्काइव्स: चीन'। लॉ एंड सोसाइटी एलायंस। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया। (https://lawandsocietyalliance.in/tag/china) पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए देखें: 'भारत में चीनी पदचिह्नों और प्रभाव अभियानों का मानचित्रण'। लॉ एंड सोसाइटी एलायंस। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया। (https://defence.capital/wp-content/uploads/2021/09/MAPPING-CHINESE-FOOTPRINTS-AND-INFLUENCE-OPERATIONS-IN-INDIA2.pdf)

1. (टोकविले 2004)

2. विंस्टन चर्चिल, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भाषण, 6 सितंबर, 1943।

3. (बिंकले 2022)

4. (हैनसन 2022)

5. (हार्वर्ड गजेट 2008)

6. (हार्वर्ड गजेट 2008)

7. (मिशन कैबेज 2020)

8. (द टाइम्स ऑफ इंडिया 2010)

9. (फाइनेंशियल एक्सप्रेस 2018)

10. (फाइनेंशियल एक्सप्रेस 2018)

11. (फाइनेंशियल एक्सप्रेस 2018)

12. (विकासपीडिया 2019)

13. (हार्वर्ड ग्लोबल 2017ए)

14. (बॉयड 2021)

1. (माल्होत्रा 2021)

2. (एंडर्सन 1983)

3. (एंडर्सन 1983, 168)

4. (एंडर्सन 1983, 177-78)

5. (एंडर्सन 1983, 188)

6. भारत के संदर्भ में एक अन्य प्रासंगिक धारणा यह है कि विदेशी आर्यों ने मूल द्रविड़ लोगों पर प्रभुत्व स्थापित किया था। जैसा कि अध्याय 3 में चर्चा की गई है, हार्वर्ड में इसे तीन-स्तरीय मॉडल में विकसित किया गया है: मुंडा भाषा बोलने वालों को भारत का मूल निवासी माना जाता है (जिन्हें अब 'आदिवासी' या दलित कहा जाता है)। उनसे ऊपर द्रविड़ हैं जो मध्य पूर्व से आकर सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया और उन्होंने मुंडाओं पर अत्याचार किया। सबसे ऊपर आर्य हैं जो मध्य एशिया से आए और उन्होंने इन दोनों स्तरों पर अत्याचार किया।

7. (मालहोत्रा और बाबाजी 2020)

8. (साइमंड्स 1986)

9. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2012b) यह भी देखें: ‘कुंभ मेले का मानचित्रण’। कुंभ मेले का मानचित्रण। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त

किया गया (https://mappingthemela.wordpress.com)

10. (मित्तल संस्थान 2013). समय: 01:17:33; (नितनावारे 2015)

11. (गणेश एन 2015ए)

12. (गणेश एन 2015बी)

13. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2014a)

14. (बार्नेट, खन्ना और ओन्नेला 2016)

15. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2016, 24)

16. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2016, 8)

17. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2015a)

18. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2016, 9)

19. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2016, 17)

20. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2016, 17)

21. (मित्तल संस्थान 2016)

22. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2020a)

23. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2020बी)

24. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2020सी)

25. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2019a)

26. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2017a)

27. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2021, 38)

28. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2019, 67)

29. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2019, 67-68)

30. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2017, 24)

31. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2017, 24)

32. देखें: 'प्रोजेक्ट प्रकाश'। प्रोजेक्ट प्रकाश। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.projectprakash.org)

33. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2020, 27)

34. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2018बी, 74)

35. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2021ए)

36. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2021ए)

37. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान 2020, 37); (लिंडा हॉल लाइब्रेरी 2022)

38. उदाहरण के लिए देखें: (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2018a); (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2019k); (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2020g);

39. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2021, 65)

40. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2019, 15-16)

41. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2020, 28)

42. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2021, 28)

43. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2013ए)

44. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2014, 22)

45. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2019, 43)

46. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2020, 39)

1. (मुखर्जी 2010)

2. (मेरिगन 2010)

3. (मेरिगन 2010)

4. (मुखर्जी 2010)

5. (मुखर्जी 2010)

6. देखें: (ईकिन 2001)

7. देखें: 'इंफोसिस पुरस्कार | निर्णायक मंडल'। इंफोसिस साइंस फाउंडेशन। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.infosys-science-foundation.com/prize/jury/jury-2017.asp)

8. (गोलिकेरी और जॉन 2011)

9. (गोलिकेरी और जॉन 2011)

10. (रेमन और स्पिट्जर 2010)

11. (ग्रॉसमैन 1999)

12. (ग्रॉसमैन 1999) में उद्धृत

13. (ईकिन 2001)

14. (ईकिन 2001)

15 देखें: 'ग्राहक समीक्षा | डेविड श्वित्ज़र'। अमेज़न। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया। (https://www.amazon.com/gp/customer-reviews/R1Q3POGMK3H1F6)

16. (यंग 1990, 186)

17. देखें: (डेविस 2012)। इस कहानी के अन्य संस्करण भी हैं जिनमें फौकॉल्ट ने पच्चीस प्रतिशत के बजाय दस प्रतिशत कहा है, लेकिन निहितार्थ अभी भी वही है।

18. (मोहंती 2005)

19. (भाभा 1994)

20. जैक्स लैकन, 'द लाइन एंड लाइट', ऑफ द गेज़, उद्धृत (भाभा 1994, 121)

21. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2017बी)

22. (रोसारियो 2017)

23. (रोसारियो 2017)

24. (प्रताप 2017)

25. (प्रताप 2017)

26. (आर. लियू 2019)

27. (श्रीनिवासन 2020)

28. इस खंड में सभी संदर्भ और उद्धरण (महिंद्रा ह्यूमैनिटीज सेंटर 2020) से लिए गए हैं।

29. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2017सी)

30 देखें: 'प्रसेनजीत दुआरा'। चीनी अध्ययन संस्थान। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया। (https://www.icsin.org/faculty/prasenjit-duara)

31. (कानून और समाज गठबंधन 2021, 15)। संयोगवश, इस संस्थान को निम्नलिखित संस्थाओं का समर्थन प्राप्त है: भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद; भारत का विदेश मंत्रालय; गार्गी और विद्या प्रकाश दत्त मेमोरियल; टाटा ट्रस्ट्स; जमनालाल बजाज फाउंडेशन; पिरोजशा गोदरेज फाउंडेशन।

32. (महिंद्रा ह्यूमैनिटीज सेंटर 2020). टाइमस्टैम्प: 01:01:15.

33. (जॉनसन 2016)

1. (हार्वर्ड गजेट 2017)

2. (गल्फ न्यूज 2017)

3. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2018डी)

4. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2020, 55)

5. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2019बी)

6. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2019बी)

7. (सोशी और वाल्श 2021)

8. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2019सी)

9. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2021बी)

10. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2016a)

11. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2019d)

12. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2019e)

13. देखें: 'एसएआई इवेंट टाइप: लेक्चर'। लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया (https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/events/types/lecture/page/2/)

14. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2015बी)

15. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2020, 51)

16. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2019f)

17. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2013सी)

18. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2021, 47)

19. (ए. दत्ता 2014)

20. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2020, 54)

21. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2019जी)

22. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2020डी)

23. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2014, 13)

24. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2012)

25. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2012)

26. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2014, 13)

27. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2015, 15)

28. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2013डी)

29. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2020ई)

30. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया

संस्थान, 2020, 52)

31. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2018e)

32. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2019h)

33. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2014बी)

34. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2014, 31)

35. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2014, 45)

36. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2014सी)

37. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2016बी)

38. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2017डी)

39. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2021सी)

40. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2016सी)

41. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया

संस्थान, 2015, 49)

42. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2014, 49)

43. (डीबेनेडिक्टिस 2016)

44. (हार्टोकॉलिस 2022)

45. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2014डी)

46. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2013ए)

47. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2014डी)

48. देखें: 'आजीविका सृजन परियोजना'। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया। (https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/about-livelihood-creation-project)

49. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2018f)

50. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2018जी)

51. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2018h)

52. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2018i)

53. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2019i)

54. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2014 संस्करण)

55. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2013बी)

56. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2016, 15)

57. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2020, 16-17)

58. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2019, 49)

59. (पेलाएज़ 2019)

60. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2017, 32)

61. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया

संस्थान, 2018बी, 74, 77)

62. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2014, 33)

63. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2016, 21)

64. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2020, 55)

65. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2020, 55)

66. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2020, 55)

67. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2020, 55)

68. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2015सी)

69. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2019j)

70. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया

संस्थान, 2019, 68)

71. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2020, 29)

72. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2017, 16)

73. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2017, 29)

74. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2020, 17)

75. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2021d)

76. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2017, 29)

77. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2021e)

78. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2017, 25)

79. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया

संस्थान, 2017, 25)

80. उदाहरण के लिए, चूल्हों का आविष्कार और उनके डेटा को मूल्यांकन के लिए बर्कले तक भेजना, ऐसा काम भारत में IIT से संबंधित कोई स्टार्टअप आसानी से कर सकता था। देखें: (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2019, 71)

81. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2017, 20)

82. उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन वार्ता के दौरान भारत पर दबाव डालने में अमेरिका को सशक्त बनाने के अलावा, हार्वर्ड केनेडी स्कूल भारत के कोयला उद्योग के अध्ययन में क्या योगदान देता है? देखें: (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2018b)

83. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2020f)

84. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2021f)

85. मित्तल इंस्टीट्यूट के सलाहकार मंडल में कई प्रभावशाली भारतीय शामिल हैं: 1) के.पी. बालाराज, बेंगलुरु, भारत; वे वेस्टब्रिज कैपिटल के सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक हैं। 2) कुशाग्र बजाज, बजाज समूह के अध्यक्ष, बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, और बजाज कॉर्प लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। 3) कुंतला दास (न्यूयॉर्क) और भरत

दास। 4) मीरा गांधी, द गिविंग बैक फाउंडेशन की सीईओ और संस्थापक हैं, जिसकी स्थापना उन्होंने 2010 में महिलाओं और बच्चों की सहायता करने, नेताओं और विचारकों की एक नई पीढ़ी तैयार करने के लिए की थी। 5) विक्रम गांधी, आशा इम्पैक्ट के संस्थापक हैं, जो एक प्रभाव निवेश और वकालत मंच है, और वीएसजी कैपिटल एडवाइजर्स के संस्थापक हैं, जो कैनेडियन पेंशन प्लान और ग्रीनहिल एंड कंपनी के वरिष्ठ सलाहकार हैं। 6) माला गांवकर हारमन, छह अरब डॉलर के एक निजी निवेश साझेदारी कोष में भागीदार और प्रबंध निदेशक हैं, जिसमें तीन इक्विटी हेज फंड शामिल हैं। वह फंड के मीडिया, प्रौद्योगिकी और दूरसंचार निवेश पोर्टफोलियो की देखरेख करती हैं। 7) डॉ. दीप्ति माथुर ने आधुनिक और समकालीन दक्षिण एशियाई कला का एक प्रतिष्ठित संग्रह तैयार किया है। उन्होंने न्यूयॉर्क स्थित एशिया सोसाइटी संग्रहालय की संग्रह समिति, सैन फ्रांसिस्को स्थित एशियाई कला संग्रहालय के समकालीन कला सलाहकार पैनल और सिएटल कला संग्रहालय के न्यासी मंडल में अपनी सेवाएं दी हैं। 8) संजीव मेहरा, न्यूयॉर्क, गोल्डमैन सैक्स के प्रबंध निदेशक और भागीदार हैं, जहां वे इसके प्रमुख निवेश क्षेत्र के लिए व्यावसायिक व्यवहार समिति और संचालन समिति का नेतृत्व करते हैं और इसकी निवेश समिति में भी कार्यरत हैं। 9) विक्टर मेनेजेस (पीए; न्यूयॉर्क) एक अंतरराष्ट्रीय निजी इक्विटी फर्म, न्यू सिल्क रूट पार्टनर्स एलएलसी में वरिष्ठ सलाहकार हैं। वे पूर्व में सिटीग्रुप इंक. के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे और कंपनी में बत्तीस वर्षों के वैश्विक करियर के बाद जनवरी 2005 में सेवानिवृत्त हुए। वे अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और कैथोलिक चैरिटीज के उपाध्यक्ष हैं। 10) गौरव और पारुल स्वरूप (कोलकाता) - कोलकाता में पहारपुर कूलिंग टावर्स लिमिटेड के प्रमुख। पहारपुर एक सुस्थापित व्यावसायिक समूह है जिसके

औद्योगिक प्रक्रिया शीतलन उपकरण, लचीली पैकेजिंग, आरा मिलिंग और वानिकी, रियल एस्टेट और निवेश में हित हैं। 11) राजीव और अनुपा साहनी (मुंबई)। राजीव न्यू वर्नोन कैपिटल, एलएलसी के संस्थापक और प्रबंध भागीदार हैं, जो एक निजी इक्विटी फर्म है जिसने सितंबर 2008 तक 2.1 बिलियन डॉलर की संपत्ति का प्रबंधन किया था। न्यू वर्नोन कैपिटल की स्थापना से पहले, वे मेडुसिंड के संस्थापक और सीईओ थे, जो एक स्वास्थ्य सेवा आउटसोर्सिंग कंपनी है। 12) श्रीबाला सुब्रमणियन और अरविंद रघुनाथन। अरविंद रोक कैपिटल मैनेजमेंट के सीईओ और सीआईओ हैं। 13) दलीप और चंद्रिका पाठक। दलीप वारबर्ग पिंकस के वरिष्ठ सलाहकार हैं। उन्होंने 1994 में वारबर्ग पिंकस में कार्यभार संभाला और इससे पहले वे फर्म के भारत और यूरोप दोनों के प्रमुख रह चुके हैं। 14) मुकेश (एबी '93) और चांदनी प्रसाद (न्यूयॉर्क)। मुकेश ने जॉन्स हॉपकिंस मेडिकल कॉलेज से एमडी की उपाधि प्राप्त की है और कोलंबिया विश्वविद्यालय में ओटोलैरिंगोलॉजी और सिर एवं गर्दन की सर्जरी में प्रशिक्षण पूरा किया है। 15) टॉम वर्गी (न्यूयॉर्क) 2001 में फर्म में शामिल होने के बाद से स्टोनहिल पोर्टफोलियो के प्रबंधन में भाग ले रहे हैं और 2004 से भागीदार हैं। देखें: (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2022a)

86. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2021, 56)

87. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2019, 27)

88. (Chughtai 2015, 203)

89. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2018बी, 22)

1. (कैपस्टोन रिपोर्ट 2020बी)

2. (क्लारिडा 2014)

3. (एयर 2020बी)

4. (काकुतानी 2020बी)

5. देखें: '@jimmylaiapple | यह खाता मौजूद नहीं है'। ट्विटर। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया (https://twitter.com/jimmylaiapple)

6. देखें: (रामज़ी 2017) और: (डेविडसन 2020)

7. (एशिया सेंटिनल 2017)

8. उदाहरण के लिए, देखें: (कैपस्टोन रिपोर्ट 2020a)

9. (काकुतानी 2020बी)

10. (मौसम 2020बी)

11. (लाम और चुंग 2018)

12. (नीतज़ेल 2022)

13. (मौसम 2020बी)

14. (मौसम 2020बी)

15. देखें: 'आईएसबी गवर्निंग बोर्ड'। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी)। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.isb.edu/en/about-isb/leadership/governing-board.html)

16. (ToHim89 लाइव 2019)

17 देखें: 'सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या है?' सीडीसी फाउंडेशन। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया। (https://www.cdcfoundation.org/what-public-health)

18. (हार्वर्ड टी.एच. चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ 2021ए)

19. देखें: 'हार्वर्ड सेंटर फॉर पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट स्टडीज'। हार्वर्ड टी.एच. चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त

किया गया (https://www.hsph.harvard.edu/population-development/tag/caste/)

20. (ब्लैंडिंग 2021)

21. (ब्लैंडिंग 2021)

22. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2018सी)

23. (हैनकॉक 1987)

24. (न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी 2013)

25. (विट्ज़ेनरथ 2015) एक अन्य पुस्तक जो विस्तृत जानकारी देती है वह है: (लेवी 2002)

26. (फेल्डशर 2014)

27. (फेल्डशर 2014)

28. (बिजनेस फ्रांस 2021)

29. (फेल्डशर 2014)

30. (फेल्डशर 2014)

31. (फेल्डशर 2014)

32. (Saathi Re 2017)

33. (हार्वर्ड टी.एच. चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ 2016)

34. (हार्वर्ड टी.एच. चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ 2017)

35. (हार्वर्ड टी.एच. चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ 2016)

36. (हार्वर्ड टी.एच. चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ 2019बी)

37. देखें: 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तपेदिक'। हार्वर्ड टी.एच. चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.hsph.harvard.edu/india-center/research/artificial-intelligence-and-tuberculosis/)

38. (लियू और झांग 2016)

39. (हार्वर्ड टी.एच. चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ 2019ए)

1. (पीटर्स 2010)

2. (पीटर्स 2010)

3. (मैकआर्थर फाउंडेशन 2022)

4. (हार्वर्ड में नीमन फाउंडेशन फॉर जर्नलिज्म 2010)

5. (के. जैन, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग को हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदू धर्म में अंतर करना चाहिए, 2019)

6. (मैकआर्थर फाउंडेशन 2022)

7. (पॉयंटर 2017)

8. (पॉयंटर 2017)

9. (पॉयंटर 2017)

10. (पॉइंटर 2017)

11. (पुलित्जर सेंटर 2016). समय: 00:00:00-00:01:42

12. देखें: 'पुलित्जर सेंटर ऑन क्राइसिस रिपोर्टिंग अपने समर्थकों और दानदाताओं के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है'। पुलित्जर सेंटर। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया (https://pulitzercenter.org/about/donors)

13. (इन्फ्लुएंसवॉच 2020)

14. (संघमित्र 2018)

15. (संघमित्र 2018)

16. (ऑप इंडिया 2021सी)

17. (सफीकुल हसन 2018). टाइमस्टैम्प: 47:51. 1 अप्रैल, 2022 को एक्सेस और डाउनलोड किया गया. लिंक अब सक्रिय नहीं है.

18. (पीएआरआई - पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया 2021ए)

19. (पीएआरआई - पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया 2021ए)

20. (पीएआरआई - पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया 2021ए)

21. (पीएआरआई - पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया 2021बी)

22. देखें: 'धन्यवाद'। पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया (https://ruralindiaonline.org/en/pages/acknowledgements/)

23. (ठाकुर 2021)

24. (ऑप इंडिया 2021ए)

25. (रॉस और डोबसन 2022)

26. (सफीकुल हसन 2018). टाइमस्टैम्प: 46:56. 1 अप्रैल, 2022 को एक्सेस और डाउनलोड किया गया. लिंक अब सक्रिय नहीं है.

27. (पीएआरआई एजुकेशन - पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया 2020ए)

28. (पीएआरआई एजुकेशन - पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया 2020ए)

29. (पीएआरआई एजुकेशन - पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया 2020बी)

30. (पीएआरआई शिक्षा टीम 2021)

31. (पीएआरआई शिक्षा टीम 2021)

32. (पीएआरआई एजुकेशन 2020)

33. (Behl 2021)

34. (कार्तिकेयन 2014)

35. (कार्तिकेयन 2014). यह भी देखें: 'चेहरे'. PARI - ग्रामीण भारत का जन अभिलेखागार. 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया (https://ruralindiaonline.org/en/categories/faces/)

36. (कार्तिकेयन 2014)

37 देखें: 'डिजिटल सदी में नेतृत्व'। जीबीएच। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया। (https://www.wgbh.org/foundation)

38. (मार्टिन, रे और पिल्ले, अमेरिका में जातिगत भेदभाव: एक सार्वजनिक रेडियो और ऑनलाइन श्रृंखला 2019)

39. (मार्टिन, रे और पिल्ले, अमेरिका में जातिगत भेदभाव: एक सार्वजनिक रेडियो और ऑनलाइन श्रृंखला 2019)

40. (मार्टिन, रे और पिल्ले, अमेरिका में जातिगत भेदभाव: एक सार्वजनिक रेडियो और ऑनलाइन श्रृंखला 2019)

41. (मार्टिन, रे, एट अल., 'अमेरिका में जाति' को 2020 का गैब्रियल पुरस्कार प्राप्त हुआ)

42. देखें: 'लेख'। पुलित्जर सेंटर। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया (https://pulitzercenter.org/article)

43. (नीमन रिपोर्ट्स 2014)

44. देखें: 'पत्रकारिता में फैलोशिप'। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया (https://editorsguild.in/awards-fellowships/)

45. (नीमनलैब 2021)

46. (हार्वर्ड में नीमन फाउंडेशन फॉर जर्नलिज्म 2021ए)

47. (हार्वर्ड में नीमन फाउंडेशन फॉर जर्नलिज्म 2021ए)

48. (हार्वर्ड में नीमन फाउंडेशन फॉर जर्नलिज्म 2021बी)

49. (हार्वर्ड में नीमन फाउंडेशन फॉर जर्नलिज्म 2020)

50. (कृष्णन 2021)

51. (कृष्णन 2021)

52. (हार्वर्ड में नीमन फाउंडेशन फॉर जर्नलिज्म 2017)

53. (गिप्सन, एट अल. 2021)

54. (सिकोरा 2021)

55. (गिप्सन, एट अल. 2021)

56. (सिकोरा 2021)

57. (सिकोरा 2021). यूट्यूब में मूल लिंक यह है: (बर्कले सेंटर 2021). टाइमस्टैम्प: 00:08:12.

58. (मालहोत्रा 2016)

1. देखें: 'सीखो। नेतृत्व करो। सेवा करो'। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.hks.harvard.edu/more/about)

2. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2021जी)

3. (हार्वर्ड कैनेडी स्कूल 2017a)

4. (आईएएमसी आधिकारिक चैनल 2020). समय: 00:07:00-00:07:15

5. (हारबस 2020)

6. (Maqbool and Naik 2017)

7. (आईएएमसी आधिकारिक चैनल 2020)

8. (ऑप इंडिया 2021बी)

9. (ऑप इंडिया 2020बी)

10. देखें: 'रशाद हुसैन, 2003'। पॉल और डेज़ी सोरोस फेलोशिप फॉर न्यू अमेरिकन्स। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.pdsoros.org/meet-the-fellows/rashad-hussain)

11. (एरेनास 2010)

12. (जे. वेबर 2021)

13. देखें: 'धार्मिक स्वतंत्रता में अपने धार्मिक पहनावे को चुनने की क्षमता शामिल है। कर्नाटक राज्य को धार्मिक वस्त्रों की स्वीकार्यता निर्धारित नहीं करनी चाहिए। स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और महिलाओं और लड़कियों को कलंकित और हाशिए पर धकेल देता है।' ट्विटर। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त (https://twitter.com/IRF_Ambassador/status/1492153532350402564)

14. (हार्वर्ड गजेट 2021)

15. (हनीफा 2020)

16. (हनीफा 2020)

17. (क्रॉफर्ड 2021)

18. (हिंदुस्तान टाइम्स, 2004)

19. (यूएससीआईआरएफ 2004)

20. (हार्वर्ड लॉ स्कूल 2018)

21. (द अमेरिकन बाज़ार 2018)

22. (यूएससीआईआरएफ 2020)

23. (मोजो स्टोरी 2020)

24. (Varshney 2021a)

25. (Varshney 2020b)

26. (डी'अमोर-मैककिम स्कूल ऑफ बिजनेस 2019). टाइमस्टैम्प: 29:20.

27. (Varshney, Ayyangar and Swaminathan 2021)

28. (लेवी 2002)

29. (Varshney 2020b)

30. देखें: 'शोरेनस्टीन सेंटर ऑन मीडिया, पॉलिटिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी'। शोरेनस्टीन सेंटर। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया (https://shorensteincenter.org/about-us/)

31. (जॉली 2016)

32. (जॉली 2016)

33. (राष्ट्रीय पल्स 2021)

34. (राष्ट्रीय पल्स 2021)

35. (राष्ट्रीय पल्स 2021)

36. (राष्ट्रीय पल्स 2021)

37. (राष्ट्रीय पल्स 2021)

38. (राष्ट्रीय पल्स 2021)

39. (गॉकोव्स्की 2017)

40. (गॉकोव्स्की 2017)

41. देखें: 'एचकेएस गलत सूचना समीक्षा'। शोरेनस्टीन सेंटर। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया (https://shorensteincenter.org/programs/misinformation/)

42. (कार्नी 2022)

43. (गरिमेला और एक्लेस 2020)

44. (अभिषेक 2021)

45. (अभिषेक 2021)

46. (अभिषेक 2021)

47. (काज़ेमी, एट अल. 2022)

48. (कुओ और मारविक 2021)

49. (कुओ और मारविक 2021)

50. (कुओ और मारविक 2021)

51. (रीस, एट अल. 2020)

52. (मार्कस 2021)

53. (मार्कस 2021)

54. (कार्नी 2022)

55. (कार्नी 2022)

56. (एचकेएस गलत सूचना समीक्षा संपादकीय स्टाफ 2021)

57. (एचकेएस गलत सूचना समीक्षा संपादकीय स्टाफ 2021)

58. (एचकेएस गलत सूचना समीक्षा संपादकीय स्टाफ 2021)

59. (कार्नी 2022)

60. (देसाई 2015)

61. (पार्किन 2019)

62. (अग्रवाल 2017)

63. (वाल्ट 2019)

64. (डिज़िक्स 2020)

65. (Varshney 2021)

66. (Varshney 2021)

67. (द हेरिटेज फाउंडेशन 2018)

68. देखें: 'बोर्ड और नेतृत्व'। फ्रीडम हाउस। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया (https://freedomhouse.org/about-us/board-leadership)

69. (हार्वर्ड कैनेडी स्कूल 2016सी)

70. (चुंग, विलियम्स और वोंग 2019)

71. (विलियम्स और वोंग 2020)

72. (विलियम्स 2020)

73. (हर्ष 2019)

74. (शर्मा 2020)

75. (तिमल्सिना और मिशेल 2021)

76. (के. विश्वेश्वरन, एम. ई. विट्ज़ेल, एट अल. 2009)

77. (चंद्र और माइकल 2020)

78. (चंद्र और माइकल 2020)

79. (हार्वर्ड कैनेडी स्कूल - महिला एवं सार्वजनिक नीति कार्यक्रम 2014)

80. (फील्ड, जयचंद्रन और पांडे 2010)

81. (फील्ड, जयचंद्रन और पांडे 2010)

82. (फील्ड, जयचंद्रन और पांडे 2010)

83. (फील्ड, जयचंद्रन और पांडे 2010)

84. (हार्वर्ड सेंटर फॉर पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट स्टडीज 2021)

85. (व्यास, गुप्ता और खालिद 2021)

86. (जयचंद्रन और पांडे 2015)

87. (जयचंद्रन और पांडे 2015)

88. (बीमन, पांडे और सिरोन, भारत में राजनीति एक पुरुष प्रधान क्षेत्र और सशक्तिकरण 2012)

89. देखें: 'सुषमा रमन - सामाजिक परिवर्तन रणनीतिकार | लेखिका | गठबंधन निर्माता'। लिंक्डइन। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.linkedin.com/in/sushmaraman/details/experience)

90. (हिंदुस्तान टाइम्स 2017)

91. (ऑप इंडिया 2020ए)

92. (चेनोवेथ, स्मिथ और शेट्टी 2020)

93. (हार्वर्ड कैनेडी स्कूल 2018). समय: 00:03:37.

94. (शेट्टी और सहगल 2019)

95. (शेट्टी और सहगल 2019)

96. (शेट्टी और सहगल 2019)

97. (शेट्टी और सहगल 2019)

98. (शेट्टी और सहगल 2019)

99. (Rajgarhia 2020)

100. (Rajgarhia 2020)

101. (Rajgarhia 2020)

102. (Rajgarhia 2020)

103. (हार्वर्ड लॉ रिव्यू 2021)

104. (चेनोवेथ, स्मिथ और शेट्टी 2020)

105. (Sabhikhi 2019)

106. रिपोर्ट में कहा गया है: 'यह शोधपत्र इस परिकल्पना की जाँच करता है कि हाल के वर्षों में बढ़ती विकास दर और बढ़ती असमानता के बावजूद ग्रामीण भारत में कम स्थानिक और वैवाहिक गतिशीलता का बने रहना, उप-जाति नेटवर्क के अस्तित्व के कारण है जो अपने सदस्यों को पारस्परिक बीमा प्रदान करते हैं। जातिगत ऋण और उप-जाति पहचान पर जानकारी प्रदान करने वाले विशिष्ट पैनल डेटा का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया गया है कि जो परिवार दूसरे देश में विवाह करते हैं या

पलायन करते हैं, वे इन नेटवर्क की सेवाओं से वंचित हो जाते हैं, जिससे गतिशीलता कम हो जाती है जब तुलनीय गुणवत्ता के बीमा या वित्त के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध नहीं होते हैं। समग्र स्तर पर, ऐसा प्रतीत होता है कि इन नेटवर्क ने हरित क्रांति के साथ उप-जातियों के भीतर बढ़ती असमानता का सफलतापूर्वक सामना किया है। वास्तव में, असमानता में इस वृद्धि ने समग्र गतिशीलता को और भी कम कर दिया, जो पहले से ही कम थी। परिणाम बताते हैं कि जातिगत नेटवर्क सदियों से ग्रामीण भारत में उपभोग को सुचारू बनाए रखने में सहायक रहे हैं।' देखें: (मुंशी और रोज़ेनज़्वेग 2005)।

107. रिपोर्ट में कहा गया है: '1990 के दशक की शुरुआत से निरंतर उच्च आर्थिक विकास ने भारतीय महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं, फिर भी महिला श्रम बल भागीदारी 30% से नीचे ही स्थिर बनी हुई है, और हाल के श्रम सर्वेक्षणों से 2005 के बाद से इसमें कुछ गिरावट का भी संकेत मिलता है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि घरेलू सर्वेक्षण का उपयोग करते हुए, हम भारत में महिला श्रम बल भागीदारी के बारे में पाँच वर्णनात्मक तथ्य प्रस्तुत करते हैं जो उच्च भागीदारी में बाधाओं को पहचानने में सहायक हैं। पहला, वर्तमान में श्रम बल में शामिल न होने वाली महिलाओं द्वारा नौकरियों की काफी मांग है। दूसरा, काम करने की इच्छुक गैर-कामगार महिलाओं को नौकरियों के लिए उपयुक्त नौकरी मिलने में कठिनाई होती है। तीसरा, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करना महिलाओं में काम करने की अधिक संभावना से संबंधित है। चौथा, महिलाओं के उन क्षेत्रों में काम करने की अधिक संभावना है जहाँ लैंगिक वेतन अंतर और अस्पष्टीकृत वेतन अंतर, जिसे आमतौर पर भेदभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, अधिक है। अंत

में, कोटा सहित महिला-हितैषी नीतियां, कुछ प्रमुख क्षेत्रों में उच्च महिला भागीदारी से संबंधित हैं।' इन तथ्यों को साहित्य की समीक्षा के साथ मिलाकर, हम भविष्य में अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार करते हैं और इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि रोजगार कोटा और कौशल विकास एवं विनिर्माण पर केंद्रित सरकारी पहलों जैसी नीतियों की बेहतर जांच और उनका लाभ उठाकर महिलाओं की आर्थिक गतिविधि को कैसे बढ़ाया जा सकता है। (फ्लेचर, पांडे और मूर 2017)

108. रिपोर्ट में कहा गया है: 'आर्थिक विकास के समान स्तर वाले देशों में भी महिला श्रम बल भागीदारी में काफी भिन्नता पाई जाती है। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि लैंगिक मानदंड महिलाओं के काम में इन अंतरों को समझाने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन वे माध्यम जिनके द्वारा मानदंड महिलाओं के रोजगार संबंधी निर्णयों को प्रभावित करते हैं, अच्छी तरह से समझ में नहीं आए हैं। हम ग्रामीण भारत में महिला श्रम के बारे में सामुदायिक दृष्टिकोण के संबंध में पतियों की प्राथमिकताओं और धारणाओं पर नए आंकड़े प्रस्तुत करते हैं और महिला कार्य के साथ संबंधों का दस्तावेजीकरण करते हैं। हम पाते हैं कि महिलाओं के काम की कथित सामाजिक लागत पुरुषों पर पड़ती है और महिला श्रम के प्रति पतियों का विरोध उनकी पत्नियों द्वारा रोजगार ग्रहण करने की कम दर से जुड़ा हुआ है।' (बर्नहार्ड्ट, एट अल. 2018)

109. रिपोर्ट में कहा गया है: 'हमने भारतीय ग्राम परिषदों में लिंग कोटा के यादृच्छिक आवंटन का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया कि क्या महिला मुख्य पार्षद होने से महिला नेताओं के प्रति जनमत प्रभावित होता है। जिन ग्रामीणों को कभी भी महिला नेता रखने की आवश्यकता नहीं

पड़ी है, वे पुरुष नेताओं को प्राथमिकता देते हैं और समान प्रदर्शन होने पर भी काल्पनिक महिला नेताओं को उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में कम प्रभावी मानते हैं। महिला नेता के संपर्क में आने से पुरुष नेताओं के प्रति ग्रामीणों की पसंद में कोई बदलाव नहीं आता है। हालांकि, यह सार्वजनिक और घरेलू क्षेत्रों में लिंग भूमिकाओं के बारे में रूढ़ियों को कमजोर करता है और पुरुष ग्रामीणों के बीच महिला नेताओं की प्रभावशीलता के बारे में नकारात्मक पूर्वाग्रह को समाप्त करता है। महिला ग्रामीणों में पूर्व पूर्वाग्रह कम होता है, लेकिन स्थानीय राजनीति के बारे में जानने या उसमें भाग लेने की संभावना भी कम होती है; परिणामस्वरूप, उनके दृष्टिकोण काफी हद तक अप्रभावित रहते हैं। हमारे प्रायोगिक निष्कर्षों के अनुरूप, ग्रामीण अपनी महिला नेताओं को पहली बार संपर्क में आने पर कम प्रभावी मानते हैं, लेकिन दूसरी बार संपर्क में आने पर नहीं।' दृष्टिकोण में ये बदलाव चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं: कोटा नीति के 10 वर्षों के बाद, जिन गांवों में लगातार महिला मुख्य पार्षद का होना अनिवार्य रहा है, वहां महिलाओं के मुफ्त सीटों पर चुनाव लड़ने और जीतने की संभावना अधिक है। (बीमन, चट्टोपाध्याय, एट अल. 2008)।

110. (बारबोनी, एट अल. 2018)

111. (हार्वर्ड कैनेडी स्कूल 2021बी)

112. (आनंद 2020)

113. (खारे, एट अल. 2021)

114. (के. जैन, गौ रक्षक और हिंदू राष्ट्रवाद का उदय, 2019)

115. (मेहता 2016)

116. (मेहता 2016)

117. (द टाइम्स ऑफ इंडिया 2006)

118. (हार्वर्ड कैनेडी स्कूल 2019a)

119. (प्रशिक्षण प्रभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, 2018)

120. (प्रशिक्षण प्रभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, 2018)

121. (जैशिक 2021)

122. (हार्वर्ड कैनेडी स्कूल 2019बी)

123. (हार्वर्ड कैनेडी स्कूल 2019सी)

124. देखें: 'मुकुल सक्सेना | कौटिल्य स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के संस्थापक प्रोफेसर'। लिंक्डइन। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.linkedin.com/in/mukul-saxena)

125. (बीडब्ल्यू एजुकेशन 2020)

126. (राय 2018)

127. (मोशिक टेमकिन @moshik_temkin 2020)

128. (सावधानी 2020)

129. (मिंट 2021)

130. देखें: 'आपकी मेहमाननवाज़ी के लिए @AkbaruddinIndia और @KautilyaSPP की पूरी टीम को धन्यवाद। @DavidWhiteDelhi और मैं दोनों ही छात्रों और @Kennedy_School से प्रेरित सजावट वाली उत्कृष्ट सुविधाओं से बहुत प्रभावित हुए – हम आशा करते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन के संस्थानों के साथ ठोस सहयोग कैसे विकसित हो सकता है, इस पर विचार करेंगे।' ट्विटर। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया (https://twitter.com/Andrew007Uk/status/1466337552386781189)

131. (बर्नले 2017)

132. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2020h)

133. (हार्वर्ड टी.एच. चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ 2018)

1. (Iyer, Khanna and Varshney 2011)

2. (ए. गुप्ता 2015)

3. (ए. गुप्ता 2015)

4. देखें: 'कार्यक्रम - नस्लीय समानता को बढ़ावा देना | विविधता प्रबंधन वक्ता श्रृंखला'। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.hbs.edu/racialequity/news-commentary/Pages/events.aspx)

5. (बनर्जी, अय्यर और सोमनाथन 2006)

6. (बनर्जी, अय्यर और सोमनाथन 2006)

7. (हार्वर्ड बिजनेस स्कूल 2021)

8. (जोन्स 2017)

9. (Bhalotra, et al. 2013)

10. (परोपकार समाचार डाइजेस्ट 2016)

11. (भट्टाचार्य 2012)

12. (डालमेयर 2021)

13. (जैक, हार्वर्ड की 'शिक्षण क्षमता' ने 2021 में प्रभाव के मामले में बिजनेस स्कूल को अग्रणी स्थान पर पहुँचाया)

14. (जैक, हार्वर्ड की 'शिक्षण क्षमता' ने 2021 में प्रभाव के मामले में बिजनेस स्कूल को अग्रणी स्थान पर पहुँचाया)

15. (जैक, हार्वर्ड के केस स्टडीज़ आलोचनाओं के घेरे में क्यों हैं, 2018)

16. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान, 2014, 47)

17. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2014f)

18. (शॉ 2022)

19. (सीईआईबीएस 2016)

20. (द इकोनॉमिस्ट 2020)

21. (बर्न 2021)

22. (बर्न 2021)

23. (बर्न 2021)

1. (आईएएमसी आधिकारिक चैनल 2022). समय: 0:00-1:20

2. (द इंटरसेप्ट 2022). समय: 42:10-42:50

3. (बार्न्स, रोसेनबर्ग और हैरिस 2018)

4. (वोल्टर्स और डुमास 2018)

5. (श्वार्ट्ज 2018)

6. न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया: 'अमेरिका में एक सऊदी छात्र, जिससे मैंने साक्षात्कार करने का अनुरोध किया था, ने कहा कि वह तभी भाग लेगा जब मैं उसकी पहचान गुप्त रखूँ। उसने मुझे ईमेल में लिखा, "संपर्क करने के लिए धन्यवाद, कृपया मेरे नाम, संबद्धता या किसी भी प्रकार की जानकारी का किसी भी प्रकाशित रचना में उपयोग न करें।" जब हम मिले, तो उसने कहा कि सरकार द्वारा किए गए कुछ प्रगतिशील आर्थिक सुधारों के विपरीत, "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विपरीत दिशा में जा रही है। आप मामूली आलोचना करने का जोखिम भी नहीं उठा सकते। और यदि आप खुलकर आलोचना करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप जेल में जा सकते हैं।"' (सोकोलोव 2019)

7. (ह्सू, याफे-बेलानी और ट्रेसी 2020)

8. (सोकोलोव 2019)

9. (सोकोलोव 2019)

10. (सोकोलोव 2019)

11. (सोकोलोव 2019)

12. (बिंकले 2018)

13. (मैक्रोपोलिस 2015)

14. (एमआईटी न्यूज़ ऑफिस 2014)

15. (सोकोलोव 2019)

16. इसकी वेबसाइट पर लिखा है: 'हमारे काम को दूरदर्शी संस्थाओं, सरकारों और व्यक्तियों का भरपूर समर्थन प्राप्त है। प्रमुख दानदाताओं में अर्नोल्ड वेंचर्स, को-इम्पैक्ट, कम्युनिटी जमील, इकिडना गिविंग, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, गूगल डॉट ऑर्ग, विलियम एंड फ्लोरा हेवलेट फाउंडेशन, किंग फिलैंथ्रोपीज़, जॉन डी. एंड कैथरीन टी. मैकआर्थर फाउंडेशन, डगलस बी. मार्शल जूनियर फैमिली फाउंडेशन, ओमिडयार

नेटवर्क, अल्फ्रेड पी. स्लोअन फाउंडेशन, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मामलों और व्यापार विभाग और यूके अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग शामिल हैं।' (जे-पाल 2010)

17. (ऑपइंडिया स्टाफ 2020)

18. (जे-पाल दक्षिण एशिया 2021)

19. देखें: (xSDG 2021b) और (Belongg 2019)

20. (बिलॉन्ग सर्कल 2022)

21. (बिलॉन्ग मेंटल हेल्थ कलेक्टिव 2021)

22. (हाउस ऑफ बिलॉन्ग 2021). टाइमस्टैम्प: 15:52

23. (पटनायक और झा 2020)

24. (पटनायक और झा 2020)

25. (Thorat, et al. 2015)

26. (एक्सएसडीजी 2021सी)

27. देखें: 'भारत बहिष्करण रिपोर्ट 2019-2020'। इक्विटी अध्ययन

केंद्र। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया (http://centreforequitystudies.org/wp-content/uploads/2021/01/India-Exclusion-Report-2019-20-e-copy.pdf)

28. (सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज 2021)

29. देखें: 'अमेरिका स्थित इंडियन मुस्लिम्स रिलीफ एंड चैरिटी, जो ब्रिटेन स्थित एक अल्पसंख्यक अधिकार समूह है, ने CAA-NRC विरोधी प्रदर्शनों के चरम काल में हर्ष मंदर के CES को धन दिया, जो आम भारतीयों को आहत करता है। दानदाताओं का मकसद और ज़मीनी स्तर पर गैर सरकारी संगठन की कार्रवाई दिल्ली दंगों में उसकी भूमिका को देखते हुए बहुत कुछ बयां करती है (जारी)'। ट्विटर। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया (https://twitter.com/legallro/status/1308969510968479751)

30. (सुब्रमण्यम 2020)

31. (द पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो (PRIO) 2021) यह भी देखें: (सत्याग्रह 2022)

32. (ऑपइंडिया स्टाफ 2021)

33. (सोरोस 2020)

34. (सिख गठबंधन 2021)

35. (सिख गठबंधन 2021)

36. (जे-पाल 2020ए)

37. (जीन लाफोर्ट्यून का होमपेज 2022)। यह भी देखें: (जे-पाल 2020बी)

38. (जे-पाल 2020सी)

39. (जे-पाल 2020डी)

40. (जे-पाल 2020ई)

41. (जे-पाल 2021)

42. (जे-पाल 2014ए)

43. (जे-पाल 2020एफ)

44. (मोहन और रेगो 2020)

45. (जे-पाल 2014बी)

46. (कुंदू 2020)

47. (कुंडू 2020)

48. (ऐयर 2019)

49. (अर्थन 2021)

50. (अल जज़ीरा 2021)

51. (साइलस 2019)

52. (भारती, एट अल. 2020)

53. (वैद्यनाथन 2019)

54. (नेशनल एसोसिएशन ऑफ साइंस राइटर्स 2021)

55. (दत्ता 2021)

56. (रमन 2022)

57. देखिए: 'यह वाकई बेहद परेशान करने वाला है। इस बात के पर्याप्त से अधिक प्रमाण मौजूद हैं कि सभी IIT, और IIT मद्रास भी, जातिवादी भेदभाव का गढ़ हैं। वास्तव में, IIT जातिवाद पर ही टिके हैं; IIT योग्यता

के मिथक को कायम रखने के लिए जाति का *उत्पादन* करते हैं।' ट्विटर। 15 मई, 2022 को प्राप्त (https://twitter.com/queersprings/status/1485216011666157572)

58. देखें: 'आयुर्वेद का जाति और जातिवाद से अटूट संबंध समझे बिना उसका विश्लेषण करना, अधिकतर बकवास है। आयुर्वेद को बढ़ावा देना = जातिवाद को बढ़ावा देना।' ट्विटर। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया (https://twitter.com/queersprings/status/1502551645569564672)

59. (येल मैकमिलन सेंटर 2022)

60. (येल मैकमिलन सेंटर 2022)

61. (येल आर्थिक विकास केंद्र 2020a)

62. (येल आर्थिक विकास केंद्र 2022ए)

63. (येल आर्थिक विकास केंद्र 2021ए)

64. (येल आर्थिक विकास केंद्र 2021बी)

65. (येल आर्थिक विकास केंद्र 2022बी)

66. (फील्ड, पांडे, एट अल. 2021सी)

1. (मीट द फाउंडर्स 2017) (8:53 – 9:29)

2. (नंदा 2021)

3. (मेहता 2016)

4. (मेहता 2016)

5. (स्वराज्य स्टाफ 2021)

6. (द प्रिंट 2020). समय: 06:37-09:30

7. (बालकृष्ण 2020)

8. (नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया 2019)। (अमन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट 2018) दानदाता थे ऑक्सफैम, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, फोर्ड फाउंडेशन, नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया (जिसे स्वयं ऑक्सफैम, फोर्ड फाउंडेशन, गेट्स फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से धन प्राप्त होता है)।

9. (कृष्णम 2021)
प्रकाशन ने रिपोर्ट किया: 'ये तथाकथित उदारवादी स्थान उन अन्य स्थानों या संस्थानों से बिल्कुल भिन्न नहीं हैं जिन्हें हम पितृसत्तात्मक मान सकते हैं। अशोका ने अपराधी को बचाने के लिए अपनी पूरी क्षमता से प्रयास

किया। कोई सोच सकता है कि बिहार या उत्तर प्रदेश का कोई विश्वविद्यालय इस तरह से व्यवहार कर सकता है, न कि अशोका जैसा कोई स्थान, जहाँ मेरी शिकायत के समय प्रसिद्ध सार्वजनिक बुद्धिजीवी प्रताप भानु मेहता कुलपति थे।' यह अशोका विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले में पीड़िता के पहले अप्रकाशित साक्षात्कार का एक अंश है।

10. (बरुआ 2017ए)

11. (बरुआ 2017बी)

12. (द हिंदू 2016)

13. (ए. सिंह 2021ए)

14. (ऑपइंडिया स्टाफ 2021ए)

15. (Navayana 2012)

16. (Apoorvanand 2018)

17. (अशोका विश्वविद्यालय 2019a)

18. (अशोका विश्वविद्यालय 2020a)

19. (ब्रिटिश अकादमी 2020a)

20. (भाषा विश्वविद्यालय 2020)

21. (अशोका विश्वविद्यालय 2020ए)

22. (चंद्र 2020)

23. (एशिया नाउ 2020)

24. (एस. गुप्ता 2020)

25. (एस. गुप्ता 2020)

26. (ए. शर्मा 2021ए)

27. (जमील 2021)

28. (कोशी 2021)

29. (Venu and Mirchandani 2021b)

30. (अशोका विश्वविद्यालय 2019बी)
वह एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, जिसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि भारत में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी लगातार इतनी कम क्यों है। इसके पीछे क्या मुद्दे हैं और यह वर्तमान में एक बड़ा नीतिगत

प्रश्न है। हम पाते हैं कि महिलाओं को घरेलू काम करने पड़ते हैं - मेरा मतलब खाना पकाने, सफाई आदि से नहीं है, बल्कि घर की देखभाल, कपड़े धोने आदि जैसे काम भी शामिल हैं। हर अतिरिक्त घरेलू काम के साथ, अन्य सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी कम हो जाती है। यह एक बात है जो हमने पाई है और दूसरी बात जो हमने पाई है वह यह है कि महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हो रही है, लेकिन उपयुक्त नौकरियों की उपलब्धता नहीं बढ़ रही है। मुझे उम्मीद है कि यह साक्ष्य-आधारित शोध इन लगातार बनी रहने वाली समस्याओं से निपटने के लिए सार्थक नीति बनाने में योगदान देगा।

31. (अशोका विश्वविद्यालय 2019बी)

32. (देशपांडे 2018ए)

33. (अशोका विश्वविद्यालय 2022ए)

34. (अशोका विश्वविद्यालय 2022ए)

35. (ब्रूकिंग्स 2015)

36. (हार्वर्ड कैनेडी स्कूल 2017सी)

37. (चीनी अध्ययन संस्थान 2020)

38. (चीनी अध्ययन संस्थान 2021)

39. (हार्वर्ड-येनचिंग संस्थान 2020a)

40. (रोसेनबाम 2012)

41. (यूनाइटेड बोर्ड 2019)

42. देखें: “हमारा नेटवर्क”। यूनाइटेड बोर्ड। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया (https://unitedboard.org/about-us/our-network/) भारत में, यह बैंगलोर में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सी.एस.आई., एवार्ट महिला क्रिश्चियन कॉलेज, फातिमा कॉलेज, होली क्रॉस कॉलेज, त्रिची, लेडी डोक कॉलेज, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, मैरिस स्टेला कॉलेज, नेसमोनी मेमोरियल क्रिश्चियन कॉलेज, यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज, केरल, यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज, शिलांग और चेन्नई में महिला क्रिश्चियन कॉलेज आदि को सहायता प्रदान करता है।

43. (हार्वर्ड-येनचिंग संस्थान 2020बी)

44. (ऑस्ट्रेलियाई चीनी अध्ययन संघ 2021)

45. (हार्वर्ड-येनचिंग संस्थान 2020सी)

46. (हार्वर्ड-येनचिंग संस्थान 2020सी)

47. (ऑस्ट्रेलियाई चीनी अध्ययन संघ 2021)

48. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2018j)

49. (यंग 2018)

50. (Varshney 2018)

51. (Varshney 2018)

52. (Varshney 2018)

53. (Varshney 2018)

54. (Varshney 2018)

55. (देशपांडे, भारत में योग्यतावाद और सकारात्मक कार्रवाई, 2018)

56. (देशपांडे, भारत में योग्यतावाद और सकारात्मक कार्रवाई, 2018)

57. (देशपांडे, भारत में योग्यतावाद और सकारात्मक कार्रवाई, 2018)

58. (देशपांडे, भारत में योग्यतावाद और सकारात्मक कार्रवाई 2018)

59. (देशपांडे, भारत में योग्यतावाद और सकारात्मक कार्रवाई, 2018)

60. (देशपांडे, भारत में योग्यतावाद और सकारात्मक कार्रवाई, 2018)

61. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2018j, 9) ‘पहला बिंदु जाति निर्माण में तकनीकी शिक्षा की भूमिका है। सार्वभौमिक ज्ञान के उस क्षेत्र के बजाय जहाँ जाति का कोई महत्व नहीं रह गया है, हम तकनीकी विज्ञानों के भीतर और उनके माध्यम से जाति का पुनर्गठन देख रहे हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि जाति आधुनिकतम, स्पष्ट रूप से पहचान-मुक्त संस्थानों के भीतर भी लचीली है और उनकी संरचना का आधार भी है। दूसरा बिंदु योग्यतावाद और लोकतंत्र के बीच संबंध को समझना है। ऐतिहासिक रूप से संचित लाभों और हानियों को दरकिनार करते हुए, योग्यतावाद की अवधारणा, रंगभेद-मुक्त समाज की तरह, असमानता के पुनरुत्पादन को बढ़ावा देने लगी है। बेशक, ऐतिहासिक विशेषाधिकारों को दूर करने वाली प्रणाली के रूप में योग्यतावाद का आदर्श अर्थ अभी भी मौजूद है। हालाँकि, इसके आदर्श अर्थ और इसके सामाजिक जीवन के बीच का अंतर इस सरल धारणा पर सवाल उठाता है कि योग्यतावाद वास्तव में अवसरों की समानता लाने वाला है।’

62. (लक्ष्मी मित्तल और परिवार दक्षिण एशिया संस्थान 2019a); (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2018j, 15)

63. (त्रिवेदी सेंटर फॉर पॉलिटिकल डेटा 2018)

64. (त्रिवेदी सेंटर फॉर पॉलिटिकल डेटा 2020सी)

65. (साइंसेज पो 2017)

66. (विंटर्स और कसम, EXC: जो बाइडेन के सीआईए निदेशक ने कांग्रेस को बताया कि उन्होंने एक चीनी कम्युनिस्ट प्रभाव समूह के साथ संबंध समाप्त कर दिया था - नए सबूत बताते हैं कि यह झूठ था, 2022)

67. (Mahaprashasta 2020)

68. (जैफ्रेलॉट और लालीवाला, द सेग्रेगेटेड सिटी 2018)। 'द सेग्रेगेटेड सिटी - घेटोइज़ेशन और डिस्टर्बड एरिया एक्ट गुजरात में शहरी क्षेत्रों को विभाजित कर रहे हैं, मुसलमानों को हाशिए पर धकेल रहे हैं'; (जैफ्रेलॉट और लालीवाला 2018b) 'अहमदाबाद के जुहापुरा के अंदर: मुसलमानों के लिए एक घेटो में रहना कैसा है - यदि घेटो रूढ़िवादिता, सांप्रदायिकता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हैं, तो हिंदुत्व के उदय ने व्यापक नागरिक समाज तक पहुँचने के प्रयासों को भी प्रेरित किया है'; (जैफ्रेलॉट 2021) 'नरेंद्र मोदी और हिंदू राष्ट्रवाद - पुलिस अल्पसंख्यकों के खिलाफ सीधे तौर पर कार्रवाई कर रही है और 2020 के दिल्ली दंगों ने दिखाया कि पुलिस सड़कों पर उनके दंगा गतिविधियों में उनका साथ दे सकती है'।

69. (द इंडियन एक्सप्रेस 2015)

70. (कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस 2016) उनके शोध पत्र हैं: राष्ट्रवाद, हिंदुत्व नहीं, 2019 का प्रमुख विषय होगा; भाजपा युवाओं के वोट को लेकर असुरक्षित है; एनआरसी 21वीं सदी की राम जन्मभूमि हो सकती है; भारतीय राज्यों में लोकतंत्र का दयनीय कामकाज; क्या भारत

की 'कमजोर राज्य व्यवस्था' उलट-पुलट हो गई है?; ई-संगोष्ठी का परिचय: उत्तर भारत में शहरीकरण, लिंग और सामाजिक परिवर्तन; शहरीकरण, लिंग और सामाजिक परिवर्तन: क्या कामकाजी महिलाओं को अधिक स्वायत्तता प्राप्त है?

71. देखें: 'गिल्स वर्नियर्स'। लिंक्डइन। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.linkedin.com/in/gillesverniers/?originalSubdomain=in)

72. देखें: 'डॉ. एस.वाई. क़ुरैशी'. लिंक्डइन. 15 मई, 2022 को पुनःप्राप्त (https://www.linkedin.com/in/dr-s-y-quraishi-bab17365/)

73. (अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनावी सहायता संस्थान, 1998)

74. (जल्द ही आ रहा है, 2021)

75. (जीलानी 2021)

76. (ऑपइंडिया स्टाफ 2022)

77. (हिंदुस्तान टाइम्स 2022). समय: 2:00

78. (ऑपइंडिया स्टाफ 2022)

79. (ऑपइंडिया स्टाफ 2022)

80. (त्रिवेदी सेंटर फॉर पॉलिटिकल डेटा 2021a)

81. (त्रिवेदी सेंटर फॉर पॉलिटिकल डेटा 2021बी)

82. (त्रिवेदी सेंटर फॉर पॉलिटिकल डेटा 2020बी)

83. (त्रिवेदी सेंटर फॉर पॉलिटिकल डेटा 2022)

84. (त्रिवेदी सेंटर फॉर पॉलिटिकल डेटा 2021सी)

85. (त्रिवेदी सेंटर फॉर पॉलिटिकल डेटा 2021डी)

86. (ज़ी मीडिया ब्यूरो 2022); यह भी देखें: 'ई-जनगणना अगले 25 वर्षों के विकास को आकार देगी, हर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण होगा: अमित शाह'। टाइम्स नाउ। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.timesnownews.com/india/e-census-will-shape-development-of-next-25-years-every-birth-and-death-will-be-registered-amit-shah-article-91444323)

87. (सीएनआरएस 1997) और (महाप्रशास्ता 2020)

88. (एलआईए स्पिनर 2019ए)

89. (एलआईए स्पिनर 2019बी)

90. (एलआईए स्पिनर 2019ए)

91. (एलआईए स्पिनर 2019सी)

92. (एलआईए स्पिनर 2019डी)

93. (एलआईए स्पिनर 2019ई)

94. (एलआईए स्पिनर 2019एफ)

95. (त्रिवेदी सेंटर फॉर पॉलिटिकल डेटा 2021ई)

96. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2022बी)

97. (वेलेस्ली कॉलेज 2016a) ‘हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन पाँच वर्ष के समझौते का प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तावित शैक्षणिक कार्यक्रम के मुख्य घटकों में शामिल हैं: नवीन पाठ्यक्रम सामग्री का संयुक्त विकास; पारस्परिक हित के क्षेत्रों में संकाय सदस्यों और छात्रों के बीच अनुसंधान; संकाय विनिमय; और शीतकालीन सत्र कार्यक्रम, छात्र विनिमय और विदेश में अध्ययन कार्यक्रमों की संभावना। इसके अलावा, समझौते के हिस्से के रूप में, वेलेस्ली सेंटर्स फॉर विमेन ने लिंग और कामुकता पर अनुसंधान केंद्र के विकास में सहयोग करने के लिए अशोका के साथ

सहयोग करने का प्रस्ताव दिया है, और अल्ब्राइट इंस्टीट्यूट ने अपने पाठ्यचर्या और शिक्षण संबंधी वैश्विक मामलों के मॉडल को साझा करने का प्रस्ताव दिया है। अशोका के छात्रों का एक छोटा समूह 2016 अल्ब्राइट इंस्टीट्यूट के शीतकालीन सत्र का अवलोकन करने के लिए परिसर में उपस्थित था।'

98. (पॉकेट न्यूज़ अलर्ट 2016)

99. (वेलेस्ली कॉलेज 2016a)

100. (अशोका विश्वविद्यालय 2020बी)

101. ब्राजील, रोमानिया और रूस ऐसे उदाहरण हैं जहां सरकारों द्वारा लैंगिक अध्ययन पर हमले किए जा रहे हैं। देखें: (रेडडेन 2018बी)

102. (डफी 2021)। 'छात्रों से यौन संबंध शुरू करने के बारे में नकली चर्चाओं के दौरान खुद को ट्रांस या नॉन-बाइनरी होने का नाटक करने को कहा जा रहा है। यह संघीय रूप से वित्त पोषित यौन शिक्षा कार्यक्रम का हिस्सा है।' किशोरों में जेंडर डिस्फोरिया में अचानक हुई वृद्धि का कारण ट्रांस एक्टिविज्म को माना जाता है और कुछ लोग इसे अमेरिका के अकादमिक जगत के मार्क्सवादियों द्वारा 'सोशल इंजीनियरिंग' तक कहते हैं। ट्रांस एक्टिविज्म के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट पर भी ट्रांस एजेंडा को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने का आरोप है और जेंडर ट्रांजिशन एक अरबों डॉलर का उद्योग बन गया है।

103. (जोन्स 2021); देखें: 'एलजीबीटी के रूप में पहचान करने वाले बच्चों की संख्या, विशेष रूप से ट्रांस और उभयलिंगी बच्चों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अगर आपको लगता है कि यह एक स्वाभाविक या सहज विकास है, तो आप भ्रम में हैं। मीडिया, हॉलीवुड और स्कूल प्रणाली सक्रिय रूप से बच्चों को एलजीबीटी समुदाय में भर्ती कर रहे हैं।' ट्विटर। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया (https://twitter.com/MattWalshBlog/status/1364639405605027840)

104. सीएसजीएस द्वारा प्रायोजित कश्मीर संबंधी लेख: कश्मीरी महिलाओं के प्रतिरोध गीतों पर, एलएसई एंगेन्डरिंग्स; कश्मीरी जिंदगियां मायने नहीं रखतीं तो कश्मीर का इंटरनेट क्यों मायने रखता है? मिडिल ईस्ट आई; कश्मीरी महिलाओं के प्रतिरोध पर, एशिया डायलॉग पोस्ट, नॉटिंघम विश्वविद्यालय; सशक्तिकरण का मिथक: कश्मीर में लिंग, संघर्ष और 'विकास', अल्पसंख्यक और लोकलुभावनवाद - दक्षिण एशिया और यूरोप से महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य (वोल्कर कौल और अनन्या वाजपेयी द्वारा संपादित), स्प्रिंगर; एकजुटता पर: कश्मीर में प्रेम, हानि और लालसा को पढ़ना, आइडेंटिटीज जर्नल; कश्मीर में प्रतिरोध मुख्यधारा है, हिमालय साउथ एशियन; कश्मीर: कोरोनावायरस भारत के लिए हमें दबाने का एक नया हथियार है, मिडिल ईस्ट आई; कश्मीर में अंतिम संस्कार से इनकार करके भारत ने इजरायल की रणनीति अपनाई, मिडिल ईस्ट आई; कश्मीर और एकजुटता की राजनीति, आइडेंटिटीज जर्नल ब्लॉग; कश्मीर में भारत का उपनिवेशवाद अभी शुरू नहीं हो रहा है, मूल निवासियों का उन्मूलन एक लंबी प्रक्रिया है, द पोलिस प्रोजेक्ट; होम एज़ द फ्रंटियर, कैन यू हियर कश्मीरी विमेन स्पीक? में, निताशा कौल और अथर ज़िया द्वारा

संपादित, विमेन अनलिमिटेड; कश्मीर में, फ़िलिस्तीन की तरह, पर्यटन कब्जे की वास्तविकता को छिपाता है, मिडिल ईस्ट आई।

105. (नए प्रवचन 2021)

106. (अशोका विश्वविद्यालय 2019)

107. (वेलेस्ली सेंटर्स फॉर विमेन 2020)। विषय थे: क्या भय, पीड़ित होने की भावना और आघात की संस्कृति में यौन शिक्षा दी जा सकती है?; लिंग और कामुकता के बीच अंतर्संबंध, शैक्षिक नीति और सिद्धांत पर चर्चा; इतिहास, कला, साहित्य, कानून और संस्कृति में यौन संबंध और शिक्षा; भारतीय संदर्भ में यौन संबंध और शिक्षा; यौन संबंध, शिक्षा, इतिहास और संस्कृति के बीच संबंध; शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों में 'इच्छा' को नियंत्रित करने वाले कानून; यौन संबंध, शिक्षा और कक्षा।

108. (के. भट्टाचार्य 2021)

109. (अशोका विश्वविद्यालय 2016बी). समय: 31:48

110. (अशोका विश्वविद्यालय 2016बी). समय: 34:23

111. (तारिक 2020)

112. (BAPSA (बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन), जेएनयू

2016)

113. (रोहित के लिए न्याय, हैदराबाद विश्वविद्यालय 2016)

114. (कोगिटो 137 2020)। टाइमस्टैम्प: 1:40

115 (कोगिटो 137 2020)। टाइमस्टैम्प: 0:23

116. (अशोका विश्वविद्यालय 2017बी). समय: 9:17

117. (अशोका विश्वविद्यालय 2017बी). समय: 13:24

118. (अशोका विश्वविद्यालय 2017बी). समय: 08:53

119. (ओमिडयार नेटवर्क इंडिया 2020बी)

120. (ओमिडयार नेटवर्क इंडिया 2020बी)

121. (अशोका विश्वविद्यालय 2021ए)

122. (ओमिडयार नेटवर्क इंडिया 2020बी)

123. (अर्थशास्त्र पर पुनर्विचार, जेएनयू 2021)। समय: 14:45

124. (पीआईबी दिल्ली 2020)

125. (अशोका विश्वविद्यालय 2022बी)

126. (अशोका विश्वविद्यालय 2021बी)

127. (ओमिडयार नेटवर्क इंडिया 2021ए)

128. (द इंडियन एक्सप्रेस 2015)

129. (लोकतांत्रिक सुधार संघ 2016)

130. देखें: 'इंग्रिड श्रीनाथ'। लिंक्डइन। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.linkedin.com/in/ingrid-srinath-355552)

131. (हिन्दू जनजागृति समिति 2014)

132. (अशोका विश्वविद्यालय 2018)

133. (सेंटर फॉर सोशल इम्पैक्ट एंड फिलैंथ्रोपी 2019)

134 (सेंटर फॉर सोशल इम्पैक्ट एंड फिलैंथ्रोपी 2019, 5)

135. (सेंटर फॉर सोशल इम्पैक्ट एंड फिलैंथ्रोपी 2019)

136. (फिलिप 2018)

137. (फिलिप 2018)

138. (सेंटर फॉर सोशल इम्पैक्ट एंड फिलैंथ्रोपी 2019, 10)

139. (सेंटर फॉर सोशल इम्पैक्ट एंड फिलैंथ्रोपी 2019, 17)

140. (सेंटर फॉर सोशल इम्पैक्ट एंड फिलैंथ्रोपी 2019, 24)

141. (सेंटर फॉर सोशल इम्पैक्ट एंड फिलैंथ्रोपी 2019, 25)

142. (स्वतंत्र और जनहितैषी मीडिया फाउंडेशन 2019a)

143. (सेंटर फॉर सोशल इम्पैक्ट एंड फिलैंथ्रोपी 2019, 40)

144. (भट्टाचार्य 2015)

145. (अशोका विश्वविद्यालय 2018ए)

146. (अशोका विश्वविद्यालय 2018ए)

147. (अशोका विश्वविद्यालय 2017ए)

148. (अशोका विश्वविद्यालय 2016ए)

149. (अशोका विश्वविद्यालय 2021)

150. (शिमर 2015)

151. (शिमर 2015)

152. (वेलेस्ली कॉलेज 2016ए)

153. (द वायर स्टाफ 2021ए)

154 (द वायर स्टाफ 2021ए)

155. देखें: 'यदि अशोका के संस्थापकों को लगता है कि यह एक कंपनी थी क्योंकि उन्होंने इसमें इतना पैसा लगाया था, तो चलिए अब व्यापार की बात करते हैं। अमेरिका के कई प्रमुख विश्वविद्यालय अशोका के साथ साझेदारी विकसित करने के बारे में सोच रहे थे और एक प्रमुख संस्थापक ब्राउन विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी के लिए मेरे पास आए थे। अब यह संभव नहीं है।' ट्विटर। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया (https://twitter.com/profvarshney/status/1372747919242235904)

156. (पुल्लानूर 2021)

157. (द वायर स्टाफ 2021बी)

158. (सीएसजीएस@अशोका 2019)

159. (सीएसजीएस@अशोका 2020). समय:
00:03:45-00:07:45

160. (स्टॉप हिंदू हेट एडवोकेसी नेटवर्क 2020)

161. (के. भट्टाचार्य 2020)

162. देखें: 'स्टूडेंट्स अगेंस्ट हिंदुत्व आइडियोलॉजी'। इंस्टाग्राम। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.instagram.com/studentsagainsthindutva)

163. (दुबे 2020)

164. (के. शर्मा 2017)

165. (स्पष्टतः ईमानदार 2021बी)

166. (स्पष्टतः ईमानदार 2021ए)

167. (स्पष्टतः ईमानदार 2022)

168. (गोस्वामी 2020)

1. (अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी 2016)

2. (अजीम प्रेमजी फाउंडेशन 2020); (अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी 2020)

3. (Varadarajan 2014)

4. (अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी 2014)

5. (अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी 2012)

6. (एम. भट्टाचार्य 2021)

7. (एम. भट्टाचार्य 2021)

8. (एम. भट्टाचार्य 2021)

9. (ए. सिंह 2021बी)

10. (द वायर स्टाफ 2018)

11. (द वायर स्टाफ 2019)

12. (द हिंदू 2019)

13. (काउंटरकरंट्स 2020)

14. (शिरीन 2021)

15. (स्वतंत्र और जनहितैषी मीडिया फाउंडेशन 2019सी)

16. 2016 से अब तक उन्होंने 79 करोड़ रुपये तक के अनुदान दिए हैं। अनुदान प्राप्तकर्ताओं की सूची इस प्रकार है: कश्मीर ऑब्जर्वर, द वायर, द प्रिंट (शेखर गुप्ता का), द कारवां, मोजो स्टोरी (बरखा दत्त का), इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, जंजवार, द बैस्टियन, डाउन टू अर्थ, फेमिनिज्म इन इंडिया, द सिटिजन, ऑल्ट न्यूज, इंडिया स्पेंड, मैक्स महाराष्ट्र, इंडिया डेवलपमेंट रिव्यू, लाइव हिस्ट्री इंडिया, साप्ताहिक साधना, द न्यूज मिनट, स्वराज, थिंक प्रगति, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर, आर्टिकल 14, द केन, द बेटर इंडिया, अज़ीमुखम, लाइव लॉ, डूल न्यूज, यूट्यूब, एशियाविल, द इंडिया फोरम, सुनो इंडिया, सीजीनेट स्वरा, इम्फाल फ्री प्रेस, ईस्ट मोजो, सिक्किम क्रॉनिकल, खबर लहरिया और गांव कनेक्शन। देखें: (IPSMF न्यूज 2021)। आईपीएसएमएफ की वेबसाइट के अनुसार, जनवरी 2022 तक, निम्नलिखित प्रकाशन अभी भी उनके सक्रिय अनुदान प्राप्तकर्ता पोर्टफोलियो में हैं: आर्टिकल 14, द सिटिजन, मोजो स्टोरी, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर, द इंडिया फोरम, इम्फाल फ्री प्रेस, कश्मीर ऑब्जर्वर, फेमिनिज्म इन इंडिया, एशियाविले, जंजवार, लाइव हिस्ट्री इंडिया, इंडिया डेवलपमेंट रिव्यू, द बैस्टियन, सुनो इंडिया, सिक्किम क्रॉनिकल, साप्ताहिक साधना, मैक्स महाराष्ट्र, ईस्ट मोजो, ऑल्ट न्यूज, खबर लहरिया, द कारवां, डाउन टू अर्थ, द प्रिंट, स्वराज,

थिंक प्रगति, द न्यूज मिनट और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली।

17. (स्वतंत्र और जनहितैषी मीडिया फाउंडेशन 2019बी)

18. (आर्मर-जोन्स, क्लार्क और श्वार्ट्ज-हेंडरसन 2019)

19. (आर्मर-जोन्स, क्लार्क और श्वार्ट्ज-हेंडरसन 2019, 39)

20. (सेंटर फॉर सोशल इम्पैक्ट एंड फिलैंथ्रोपी 2019, 30)

21. (अजीम प्रेमजी फाउंडेशन 2021a); (अजीम प्रेमजी फाउंडेशन 2021बी)

22. (ब्रेड फॉर द वर्ल्ड 2020)

23. (आरएनबीए मणिपुर 2020)

24. (अजीम प्रेमजी फाउंडेशन 2021)

25. (आर्किटेक्ट इंडिया 2021)

26. (आर्किटेक्ट इंडिया 2021). समय: 09:40

27. (आर्किटेक्ट इंडिया 2021). समय: 11:36

28. (माला 2020)

29. (बाशा 2020)

30. (के. शर्मा 2021)

31. (हार्वर्ड ग्लोबल 2017बी)

32. (हार्वर्ड ग्लोबल 2017ए)

33. (सन्नाम एस4 ग्रुप 2008)

1. यूसीएलए विलियम्स इंस्टीट्यूट द्वारा 2011 में किए गए एक अध्ययन में अमेरिका और चार अन्य देशों में LGBTQ+ आबादी के आकार का अनुमान लगाया गया था। अध्ययन में पाया गया कि 3.5% लोग खुद को LGBTQ+ के रूप में पहचानते हैं, 0.3% लोग खुद को ट्रांसजेंडर के रूप में पहचानते हैं, और 8.2% अमेरिकियों ने समलैंगिक यौन व्यवहार में शामिल होने की बात कही। (गेट्स 2011) देखें। 2020 में, यह संख्या बढ़ गई: इसी शोध समूह द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि अमेरिकी आबादी का 4.5% LGBTQ+ है। (कॉनरॉन और गोल्डबर्ग 2020) देखें।

2. आज की कुछ मुख्य श्रेणियाँ इस प्रकार हैं: एजेंडर: किसी भी लिंग से पहचान नहीं रखता; बाइजेंडर: दो लिंगों के रूप में पहचान रखता है, चाहे एक साथ या अलग-अलग समय पर; सिसजेंडर: जन्म के समय निर्धारित

जैविक लिंग के रूप में पहचान रखता है; जेंडरफ्लुइड: लिंग पहचान में बदलाव होता रहता है या अलग-अलग समय पर अलग-अलग पहचान रखता है; जेंडरक्वीर: लिंग पहचान अपने निर्धारित जैविक लिंग के सामाजिक मानदंडों से भिन्न होती है; न्यूट्रोइस: तटस्थ लिंग; ट्रांसजेंडर: जन्म के समय निर्धारित लिंग से भिन्न लिंग के रूप में पहचान रखता है। कभी-कभी ट्रांस लोग एमटीएफ (पुरुष से महिला) या एफटीएम (महिला से पुरुष) के रूप में पहचान रखते हैं। एक ट्रांस पुरुष वह व्यक्ति है जिसे जन्म के समय महिला निर्धारित किया गया था और वह पुरुष के रूप में पहचान रखता है। एक ट्रांस महिला वह व्यक्ति है जिसे जन्म के समय पुरुष निर्धारित किया गया था और वह महिला के रूप में पहचान रखती है। देखें: (इवान 2015)

3. (बॉन्ड 2021)

4. (बॉन्ड 2021)

5. (हार्मोन 2020)

6. (शियर 2020)

7. (नए प्रवचन 2022). समय: 02:15:20 – 02:16:00

8. (रेली 2022)

9. (लागत 2021)

10. (लागत 2021)

11. उदाहरण के लिए, विष्णु का मोहिनी रूप धारण करना। यह एक वार्षिक उत्सव है जिसे ट्रांसजेंडर लोग मना सकते हैं।

12. (गेटलमैन और लियोन्स 2018बी)

13. (बिट्टू 2021)

14. (रॉयटर्स 2019)

15. (2021b वर्ष)

16. (गोदरेज इंडिया कल्चर लैब 2019a)

17. (गोदरेज इंडिया कल्चर लैब 2019बी)

18. (एन. जे. शर्मा 2020सी)

19. (एन. जे. शर्मा 2020सी)

20. (इंडियाकल्चरलैब 2019). समय: 02:00

21. (एन. जे. शर्मा 2020सी)

22. (एन. जे. शर्मा 2020सी)

23. (एन. जे. शर्मा 2020सी)

24. (एन. जे. शर्मा 2020सी)

25. (एन. जे. शर्मा 2020सी)

26. (इंडियाकल्चरलैब 2020ए). समय: 19:22

27. (Nambiar and Shahani 2018)

28. उदाहरण के लिए, स्त्रीत्व को निखारने में निम्नलिखित शल्य चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं: सिर के बालों का पुनर्निर्माण (जिसमें मुकुट और हेयरलाइन पुनर्निर्माण दोनों शामिल हैं); सिर की लंबाई बढ़ाना/हेयरलाइन को नीचे करना; माथे की आकृति को निखारना/भौंहों को चमकाना; भौंहों को ऊपर उठाना; ब्लेफेरोप्लास्टी; राइनोप्लास्टी; नाक की सर्जरी; गालों को उभारना/कम करना; ऊपरी होंठ को कम करना/उभारना; जेनियोप्लास्टी, स्त्रीत्व को निखारना; जबड़े की आकृति को निखारना; गर्दन का लाइपोसेक्शन; श्वासनली की शेविंग; स्तन वृद्धि/मैमोग्राफी; सक्शन-सहायता प्राप्त लाइपेक्टोमी/शरीर की आकृति को निखारना; पेनेक्टोमी; ऑर्किक्टोमी; वैजिनोप्लास्टी; क्लिटोरोप्लास्टी; वल्वोप्लास्टी; लेबियाप्लास्टी। पुरुषत्व को निखारने में निम्नलिखित सर्जरी शामिल हैं: माथे को लंबा करना; माथे को उभारना; गालों को उभारना;

नाक को उभारना; जेनियोप्लास्टी, पुरुषत्व को निखारना; थायरॉइड उपास्थि को निखारना। मास्टेक्टॉमी; सक्शन-असिस्टेड लाइपेक्टॉमी/बॉडी कंटूरिंग; हिस्टेरेक्टॉमी/ओफोरेक्टॉमी; मूत्रमार्ग के स्थिर भाग का पुनर्निर्माण; मेटोइडियोप्लास्टी; फैलोप्लास्टी; वैजिनेक्टॉमी; स्क्रोटोप्लास्टी; इरेक्टाइल या टेस्टिकुलर प्रोस्थेसिस का प्रत्यारोपण। (नांबियार और शाहानी 2018)

29. (Nambiar and Shahani 2018, 37)

30. (Nambiar and Shahani 2018, 41)

31. (Nambiar and Shahani 2018, 39)

32. (Nambiar and Shahani 2018, 42)

33. (Nambiar and Shahani 2018, 51)

34. (Nambiar and Shahani 2018, 51)

35. (येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट 2014)

36. (इंडियाकल्चरलैब 2020ए). समय: 24:08

37. (इंडियाकल्चरलैब 2020ए). समय: 22:33

38. (इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स 2014); देखें: 'कहानी सुनाने का विशेष कार्यक्रम | 14, 15, 27 और 28 जून, 2013 | मुंबई'। इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया (http://indiaifa.org/events/storytelling-special-june-14-15-27-28-2013-mumbai.html)

39. (इंडियाकल्चरलैब 2020बी). समय: 07:50

40. (इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स 2021)

1. देखें: (ए. फील्ड 2019)

2. देखें: (फुलर 2021)। हम फुलर के खोजी कार्य के ऋणी हैं जिसने हमें गहराई से छानबीन करने में सक्षम बनाया।

3. देखें: (फुलर 2021)

4. फुलर की जांच से निम्नलिखित बातें सामने आती हैं: 'ओमिडयार, जिसका ओमिडयार नेटवर्क एईएलपी को वित्त पोषित करता है, वह डेमोक्रेसी फंड को भी वित्त पोषित करता है जो अब ओमिडयार ग्रुप (1) का हिस्सा है। डेमोक्रेसी फंड, बदले में, नाइट फाउंडेशन, क्वाड्रीवियम, मैकआर्थर फाउंडेशन और ल्यूमिनेट (जिसे ओमिडयार द्वारा भी वित्त पोषित किया जाता है) के साथ मिलकर डेमोक्रेसी वर्क्स (2) को वित्त पोषित करता है। ओमिडयार डेमोक्रेसी फंड वॉयस को भी वित्त पोषित करता है, जो बदले में डिफेंडिंग डेमोक्रेसी टुगेदर (3) में योगदान देता है।

फिर हेल्दी डेमोक्रेसी है जिसे डेमोक्रेसी फंड, सिलिकॉन वैली कम्युनिटी फाउंडेशन (जिसे डेमोक्रेसी फंड से भी धन प्राप्त होता है) (4) और फोर्ड फैमिली फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। ओमिडयार नेटवर्क नाइट फाउंडेशन, वन प्रोजेक्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सिटिजनशिप और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन, सेंटर फॉर मीडिया एंगेजमेंट के साथ मिलकर सिविक सिग्नल्स द्वारा संचालित न्यू पब्लिक को भी सह-वित्त पोषित करता है। बेशक, ऑस्टिन स्थित टेक्सास विश्वविद्यालय का मीडिया एंगेजमेंट सेंटर भी ओमिडयार नेटवर्क, डेमोक्रेसी फंड (ओमिडयार द्वारा वित्तपोषित), नाइट फाउंडेशन, रॉबर्ट मैककॉर्मिक फाउंडेशन और गूगल द्वारा वित्तपोषित है। कुछ अन्य संस्थाओं के नाम लें तो, एडा लवलेस इंस्टीट्यूट को भी ल्यूमिनेट, वेलकम ट्रस्ट और नफिल्ड फाउंडेशन से फंडिंग मिलती है, जबकि 'सिविक टेक' पर आधारित माईसोसाइटी का एक कार्यक्रम टिकटेक, फेसबुक, ल्यूमिनेट और गूगल आदि द्वारा वित्तपोषित है।

5. (लाइट्स 2019)

6. देखें: ‘एनएमवी’। न्यू मीडिया वेंचर्स। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.newmediaventures.org)

7. इक्वालिटी लैब्स को भी सीधा सहयोग मिलता है। इक्विटी इनिशिएटिव ओमिडयार की वेबसाइट पर लिखा है: ‘इक्वालिटी लैब्स दक्षिण एशियाई और व्यापक नस्लीय न्याय समुदायों के लिए सूचना, सेवाओं और त्वरित प्रतिक्रिया का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ओमिडयार नेटवर्क से मिले अनुदान से हम अपने समुदाय को दी जाने वाली सीधी

सेवाओं में वृद्धि करेंगे, अपनी पारस्परिक सहायता संसाधन किट को अद्यतन करेंगे, कोविड-19 जन स्वास्थ्य मार्गदर्शिका का विस्तार करेंगे और अधिक सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील सामग्री तैयार करेंगे; साथ ही एक नए डिजिटल सुरक्षा ठेकेदार को नियुक्त करेंगे।' देखें: (ओमिडयार नेटवर्क इंडिया 2021j)

8. (ग्रीनवाल्ड 2021)

9. (ग्रीनवाल्ड 2021)

10. (डोलन 2015)

11. (डोलन 2015)

12. (Malhotra and Neelakandan 2011)

13. (Malhotra and Neelakandan 2011, 336-37)

14. (Malhotra and Neelakandan 2011, 363-64)

15. (Shashikumar 2004)

16. (Shashikumar 2004)

17. (Shashikumar 2004)

18. देखें: 'ग्रीष्मकालीन 2012, पायलट प्रोजेक्ट'। हार्वर्ड विश्वविद्यालय। 30 अप्रैल, 2022 को प्राप्त किया गया (https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/wp-content/uploads/2012/08/Final-Report-MOBILIZE-Digital-Libraries-2012-Pilot3.pdf)

19. (हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2019)

20. (मालहोत्रा 2021)

21. (मिश्रा 2014)

22. शासन, प्रभाव और परिवर्तन के लिए डिजिटल अवसंरचना। देखें: 'ई-गवर्नेंस फाउंडेशन द्वारा डिजिट'। digit.org 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.digit.org/)

23. (मुस्तफा, कुमार और शरालय 2022ए)

24. (मुस्तफा, कुमार और शरालय 2022a)

25. (मुस्तफा, कुमार और शरालय 2022a)

26. (मुस्तफा, कुमार और शरालय 2022ए); (एएनआई 2021ए)

27. (ओमिडयार नेटवर्क इंडिया 2021बी)

28. देखें: 'इंट्रासिटी स्मार्ट बसों के साथ इंट्रासिटी मोबिलिटी में आए बदलाव'। ओमिडयार नेटवर्क इंडिया। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.omidyarnetwork.in/theboldones/intrcity)

29. (ओमिडयार नेटवर्क इंडिया 2021f)

30. देखें: 'आसान ऋणों के माध्यम से लघु व्यवसायों को विकास में सहायता'। ओमिडयार नेटवर्क इंडिया। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.omidyarnetwork.in/theboldones/indifi)

31. (ओमिडयार नेटवर्क इंडिया 2021i)

32. (ओमिडयार नेटवर्क इंडिया 2021c)

33. (ओमिडयार नेटवर्क इंडिया 2022सी)

34. देखें: 'डेटा संचालित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भारत का रूपांतरण – ट्रांसवर्स'। ओमिडयार नेटवर्क इंडिया। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.omidyarnetwork.in/theboldones/transerve)

35. (ओमिडयार नेटवर्क इंडिया 2021g)

36. (ओमिडयार नेटवर्क इंडिया 2019a) नवीनतम निवेश ट्रैकर के लिए होमपेज देखें

37. ये निवेश इक्विटी, अनुदान, परियोजना सहायता और अनुसंधान श्रेणियों में हैं।

38. देखें: 'ओमिडयार नेटवर्क इंडिया'। लिंक्डइन। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया (https://in.linkedin.com/company/omidyar-network-india)

39. देखें: 'द बोल्ड वन्स'। लिंक्डइन। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.linkedin.com/posts/omidyar-network-india_the-bold-ones-activity-6868452932489121792-v6AO)

40. (आईडीएफसी फाउंडेशन 2016ए)

41. (आईडीएफसी संस्थान 2015)

42. (आईडीएफसी संस्थान 2015)

43. (आईडीएफसी संस्थान 2017ए)

44. (आईडीएफसी संस्थान 2017बी)

45. (आईडीएफसी संस्थान 2017बी)

46. (विश्व आर्थिक मंच 2016)

47. (आईडीएफसी फाउंडेशन 2016ए)

48. (आईडीएफसी फाउंडेशन 2016ए)

49. (रुबिनस्टीन और ब्लुमेंथल 2019)

50. (डेटा गवर्नेंस नेटवर्क 2020)

51. (Rajadhyaksha 2017)

52. (परसा 2021ए)

53. (इमाद, एट अल. 2021बी)

54. (इमाद, एट अल. 2021बी)

55. (राजन, एट अल. 2021सी)

56. (टंडेल, एट अल. 2017ए)

57. तालिका में दिए गए आंकड़े (IDFC इंस्टीट्यूट 2017c) से लिए गए हैं।

58. (आईडीएफसी फाउंडेशन 2016बी)

59. (आईडीएफसी फाउंडेशन 2016बी)

60. (विंटर्स और कसम 2021बी)

61. (विंटर्स और कसम 2021बी)

62. (गंगुली 2019)

63. (Pratilipi 2014)

64. (Pratilipi 2014)

65. (ओमिडयार नेटवर्क इंडिया 2022ए)

66. (ओमिडयार नेटवर्क इंडिया 2020a)

67. (ओमिडयार नेटवर्क इंडिया 2021ए)

68. (जे-पाल 2003)

69. (ओमिडयार नेटवर्क इंडिया 2019बी)

70. (ओमिडयार नेटवर्क इंडिया 2021ई)

71. (ओमिडयार नेटवर्क इंडिया 2021h)

72. देखें: 'कैटलिटिक कैपिटल कंसोर्टियम ने 14 अनुसंधान परियोजनाओं को पुरस्कारों की घोषणा की'। लिंक्डइन। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.linkedin.com/posts/omidyar-network_catalytic-capital-consortium-announces-awards-activity-6856272421377458177-8iLe) और (न्यू वेंचर फंड 2021)

73. देखें: '#NextHalfBillion: विविधता, समानता और समावेशन'। लिंक्डइन। 15 मई, 2022 को प्राप्त (https://www.linkedin.com/posts/omidyar-network-india_nexthalfbillion-diversity-equity-activity-6853955345090441216-JV0e) और (कुडवा 2021)

74 देखें: 'यह जोड़ी प्रारंभिक चरण के गैर-लाभकारी संगठनों को बढ़ावा देती है। उनका लक्ष्य: 2025 तक 1 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकालना'। लिंक्डइन। 15 मई, 2022 को प्राप्त (https://

www.linkedin.com/posts/omidyar-network-india_forbes-india-this-duo-incubates-early-stage-activity-6863754490013614081-atzY) और (शेखर 2021)

75. (ओमिडयार नेटवर्क इंडिया 2022बी)

76. देखें: 'भारत के डिजिटल राजमार्गों का विस्तार: ओपन डिजिटल इकोसिस्टम (ओडीई) के लिए अगली सीमाएँ'। लिंक्डइन। 15 मई, 2022 को प्राप्त (https://www.linkedin.com/posts/omidyar-network-india_odes-opendigitalecosystems-digitalindia-activity-6859007168834760704-Xpd1) और यह भी देखें: "ओडीई के लिए अगली सीमाएँ"। लिंक्डइन। 15 मई, 2022 को प्राप्त (https://www.linkedin.com/posts/omidyar-network-india_the-next-frontiers-for-odes-activity-6859736951080140800-0ULs)

77. (प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन 2021); देखें: 'आदिवासी भूमि अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: हमने प्रधान में निवेश क्यों किया'। लिंक्डइन। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.linkedin.com/posts/omidyar-network-india_leveraging-technology-to-secure-tribal-land-activity-6851831041959710720-PEdZ/); देखें: 'प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन (प्रदान): अवलोकन'।

लिंक्डइन। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.linkedin.com/company/professional-assistance-for-development-action)

78. (एनएफआई 2019)

79. (कुमार, मुस्तफा और कामरा 2021a)

80. (ओमिडयार नेटवर्क इंडिया 2020सी)

81. (Tandan, Nautiyal and Kudva 2019)

82. (ओमिडयार नेटवर्क इंडिया 2019c)

83. देखें: 'Scroll.in' ओमिडयार नेटवर्क इंडिया। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.omidyarnetwork.in/investees/scroll)

84. (राइडर 2014)

85. जैसा कि रिपोर्ट किया गया है: (वैलेंटाइन 2017, 130-131)। यह भी देखें: (कोहेन 2014)

86. देखें: 'पीआरएस विधायी अनुसंधान'। पीआरएस। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया (https://prsindia.org) और (ओमिडयार

नेटवर्क 2020)

87. देखें: 'सरकारी क्षेत्र में उद्यमिता_ भाग I डॉ. के.पी. कृष्णन और वरद पांडे के साथ'। लिंक्डइन। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.linkedin.com/posts/omidyar-network-india_entrepreneurship-in-government-part-i-with-activity-6838355897102807040-L1ts)

88. (ओमिडयार नेटवर्क इंडिया 2021डी)

89. (डेटा गवर्नेंस नेटवर्क 2020)

90. (डेटा गवर्नेंस नेटवर्क 2013)

91. (ओमिडयार नेटवर्क इंडिया 2020डी)

92. (इंटरनेट और समाज केंद्र 2008); और देखें: 'इंटरनेट और समाज केंद्र'। लिंक्डइन। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया (https://in.linkedin.com/company/centre-for-internet-and-society)

93. ग्राम राजधानी: (ओमिडयार नेटवर्क इंडिया 2020ई)

1. (बीबीसी न्यूज़ 2020)

2. (श्वाब और वैनहैम 2021); (बक्कर और एल्किंगटन 2020)

3. (हार्वर्ड कैनेडी स्कूल 2017बी)

4. (kenlej 2022)

5. (kenlej 2022)

6. (kenlej 2022)

7. (शेयरिंग पोल 2021)

8. (यंग और एडिसन 2020); (टेलर 2020)

9. (व्हेरी 2020); (ग्लोबल न्यूज़ 2020). समय: 2:05.

10. देखें: 'क्रिटिकल रेस थ्योरी के बारे में आपको यह जानना आवश्यक है। नस्लीय समानता के बारे में अधिक जानें: http://ow.ly/PUbR50HPGga'□ ट्विटर। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया (https://twitter.com/wef/status/1491094355444219906)

11. (विग्नराजा और होर्वाथ 2020)

12. (विग्नराजा और होर्वाथ 2020)

13. (विग्नराजा और होर्वाथ 2020)

14. (स्टीन 2021)

15. (बॉक्स 2022)

16. (बॉक्स 2022)

17. (बॉक्स 2022)

18. (विश्व आर्थिक मंच 2020बी)

19. (इवांस, एट अल. 2017)

20. (मासा और मेल्बी 2020)

21. (मासा और मेल्बी 2020)

22. (विश्व आर्थिक मंच 2022a); देखें: 'ब्लैकरॉक'। विश्व आर्थिक मंच। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.weforum.org/organizations/blackrock-inc)

23. (क्रेमर 2020)

24. (शेठ 2022)

25. (बर्राबी 2022)

26. (क्रेमर 2019)

27. (डॉसन और डुडा 2021)

28. (जोशी 2021)

29. (जोशी 2021)

30. (ढिल्लों 2018)

31. (राव 2021)

32. (नेवराडाकिस 2022)

33. (नेवराडाकिस 2022)

34. (नेवराडाकिस 2022)

35. (इंफोसिस 2020). समय: 01:05

36. (विश्व आर्थिक मंच 2022बी, 22)

37. (विश्व आर्थिक मंच 2022बी, 22)

38. (विश्व आर्थिक मंच 2022बी, 22)

39. (विश्व आर्थिक मंच 2022बी, 24)

40. (विश्व आर्थिक मंच 2022बी, 24)

41. (विश्व आर्थिक मंच 2022बी, 29)

42. देखें: 'ब्रायन जे. ग्रिम | आस्था और व्यवसाय एक बेहतर दुनिया का निर्माण करते हैं'। लिंक्डइन। 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया (https://www.linkedin.com/in/briangrim)

43. उदाहरण के लिए, ईसाई पहलों के वित्तपोषण में अपने व्यापक अनुभव के साथ टेम्पलटन फाउंडेशन, आरएफबीएफ के एशियाई विस्तार कार्यक्रम का प्रायोजक है। देखें: (धार्मिक स्वतंत्रता और व्यापार फाउंडेशन 2019)

44. उदाहरण के लिए, उनके फोकस समूह के एक प्रतिभागी ने कहा: 'वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भारत में बहुत सक्रिय हैं। उनका एक बहुत मजबूत कारोबारी समुदाय है। अब पूरे भारत में उनके लगभग 40 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हैं। मैं बोर्ड के कई लोगों को जानता हूँ और पिछले कुछ दशकों से सक्रिय रहा हूँ। यह मुद्दा [धार्मिक स्वतंत्रता] वहाँ कभी नहीं उठा... लेकिन

गोलमेज सम्मेलनों के माध्यम से, मैं उनसे जुड़ा। तब मुझे एहसास हुआ कि यह मुद्दा कितना गंभीर है। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। कारोबारी समुदाय में यह मुद्दा मेरी समझ से परे था।' (धार्मिक स्वतंत्रता और व्यापार फाउंडेशन 2021, 7)

45. देखें: 'कॉर्पोरेट धार्मिक समानता, विविधता और समावेशन (REDI) सूचकांक'। REDI 15 मई, 2022 को प्राप्त किया गया (https://religiousfreedomandbusiness.org/redi)

46. (दा अल्टरनेटिव 2022)

47. (युवा वैश्विक नेताओं का मंच 2020)

48. (द हिल 2022). समय: 05:38-06:23

49. (प्रभु 2021)

50. (डेलाचेरी 2017)

51. (विश्व आर्थिक मंच 2020a)

52. (जीडिगुंटा, एट अल. 2021, 4)

53. (शर्मा और सेनगुप्ता 2020)